



# अन्तर्राष्ट्रीय विधि

[ शान्ति, युद्ध तथा तटस्थता की विधियों का विश्लेषण ]

लेखक

महेश प्रसाद टण्डन

एम० ए० एल० एल० बी०

( परिशोधित एवं परिष्कृत )

तृतीय संस्करण

इलाहाबाद लॉ एजेन्सी

लॉ पब्लिशर्स

६, यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद

प्रमाण  
इलाहाबाद लॉ एजेन्सो,  
इलाहाबाद ।

## समर्पण

अपने उस परम पूज्य भ्राता की स्मृति में जिसके स्नेह की  
दक्षिमर्त्य मेरे मानस-पटल पर चल-चित्र की भाँति दीर्घ  
जाया करती हैं और जिसकी आत्मा भगवान् में  
ही आकर मेरे रोम-रोम में निरन्तर आगे  
बढ़ते रहने का आत्म-विश्वास  
पैदा कर जाती है !





## तृतीय संस्करण की भूमिका

मुझे 'अन्तर्राष्ट्रीय विधि' के तीसरे संस्करण को राष्ट्रभाषा के माध्यम से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने में हर्ष का अनुभव हो रहा है। वस्तुतः इस पुस्तक के प्रथम और द्वितीय संस्करण को पाठकों ने जिस उदारता के साथ अपनाया उससे मेरा उत्साह बढ़ा है और युग की बदलती हुई परिस्थितियों का पुनः समावेश करते हुये पुस्तक के तीसरे संस्करण को प्रस्तुत करने की शीघ्र आवश्यकता का अनुभव हुआ है।

सत्तार के रगमच पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली घटनायें तीव्रता से घटती जा रही हैं और उन सबका अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर आनुपातिक प्रभाव पड़ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि उनमें से प्रत्येक को दृष्टि में रखते हुये अन्तर्राष्ट्रीय विधि का पुनरीक्षण किया जाय और सावदेशिक सिद्धान्तों को मान्यता दी जाय।

भारतीय दर्शन के 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सूत्र को आज के प्रगतिशील विज्ञान ने सार्थक कर दिया है और आज का विश्व पृथक् पृथक् राष्ट्रों का एक विश्रुल्लित समूह नहीं, एक सश्रुत परिवार है। प्रत्येक राष्ट्र उस बृहत्तर परिवार का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्र ही क्यों, आज की परिभाषा में व्यक्ति भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्ति का अन्तर्राष्ट्रीय विधि में कुछ कर्तव्य है, कुछ दायित्व है और निस्संदेह प्रत्येक राष्ट्र किंवा व्यक्ति का उस विधि के अन्तर्गत कुछ अधिकार है, कुछ अस्तित्व है। आज कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर निरकुश रूप में हावी नहीं हो सकता। बड़ा से बड़ा और शक्तिशाली राज्य भी आज की परिस्थितियों में छोटे से छोटे और निर्बल राज्य की तुलना में समान है। विद्यतनाम जैसे छोटे राज्य और अमेरिका जैसे बड़े और शक्तिशाली राज्य का लम्बे समय तक का चलने वाला सशस्त्र संघर्ष इस बात के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व उसकी विशालता और साधन-सम्पन्नता पर नहीं निर्भर करता।

विज्ञान की आधुनिकतम प्रगति ने मानव-मानव के सम्बन्धों के लिये एक नया क्षेत्र खोल दिया है। आज मनुष्य चन्द्रलोक तक की खोज कर ले रहा है और

है कि निकट भविष्य में उसके चरण उस लोक तक भी पहुँच जायेंगे। उस लोक से जब मनुष्य इस पृथ्वी की ओर देखेगा, तब सम्भवतः आज की रही-सही दूरी भी समाप्त हो जायेगी और मानव के नये-नये अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का श्रीगणेश होगा।

आज विश्व को ऐसी विधियों की अधिक आवश्यकता है जो सार्वदेशिक हों, अन्तर्राष्ट्रीय हों। विश्व में एक ओर निर्माण हो रहा है, किन्तु दूसरी ओर विध्वंस का ताड़व नर्तन भी होता जा रहा है। न्यूट्रि के प्रयोगों और मानव-विनाश के यन्त्रों की ओर भी बृद्धि हुई है, या यों कहें कि निर्माण का तुलना में आज हम विध्वंस के अधिक निकट हैं ता इसमें कोई अयुक्ति नहीं है। अभी तक सोवियत सङ्घ और संयुक्त राज्य द्वारा 'परस्पर आतंक-संतुलन' बनाये रखने के आश्वासनों पर विश्व को अपने अस्तित्व के प्रति कुछ भरोसा भी था किन्तु पिछले वर्षों में साम्यवादी चीन के मुविलपर-शिविर में प्रवेश कर जाने तथा विश्व के मध्य राष्ट्रों द्वारा निरंतर विरोध प्रकट किये जाने के उपरान्त भी निरंकुश रूप में विस्फोटक प्रयोगों को करत रहने के कारण विश्व को एक नये खतरे की अशंका हो गयी है। आज के विश्व का अस्तित्व कल के विश्व के अस्तित्व और शान्ति की अपेक्षा अधिक खतरे में है। जहाँ एक ओर मनुष्य को भूख, बीमारी, अशिक्षा, अस्वास्थ्य, असमानता, दासत्व आदि को दूर करते हुये सहअस्तित्व को बनाये रखने का प्रयत्न करना है, वहाँ दूसरी ओर मानव-विनाश के उपक्रमों को स्थगित करते हुये विश्व में शान्ति स्थापित करने और युद्ध के बढ़ते हुये तनाव को रोकने के प्रयत्न भी करना है।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ घन तिमिर के बीच एक ज्योति-रेखा के सगन है। उस ज्योति-रेखा को प्रस्फुटित करने के लिए राष्ट्रों के परस्पर सौजन्य और स्नेह के तेल की आवश्यकता है। इस तेल के अभाव में वह कभी-कभी बुझता-सा प्रतीत होने लगता है, किन्तु फिर, किसी कोने से कुछ स्निग्धता मिल जाने के कारण ज्योतिर्मान हो उठता है।

भारत सदैव से 'पंचशील' और 'विश्वशान्ति' और 'सह-अस्तित्व' का पोषक रहा है और इस बात के समर्थकों में अग्रणी रहा है कि बिना किसी गुटबन्दी या भेदभाव के विश्व के सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सदस्य हों। लाल चीन के प्रति भी भारत की उदारता और संयुक्त राष्ट्र में उसका समर्थन सर्व-विदित है। फिर भी, १९६२ में चीन द्वारा भारत की उत्तरी सीमा पर बर्बर आक्रमण किये गये। चीन और पाकिस्तान ने दुरमसिधि में प्रविष्ट होकर भारतीय क्षेत्रों को हड़प लेने का कुचक्र बिछा, किन्तु आज भी भारत विश्व के परिवार में चीन की सदस्यता का पोषक है। यद्यपि साधारण सभा के बीसवें अविवेशन में भी चीन इस सदस्यता के लिये निर्धारित तीन-चौथाई बहुमत नहीं प्राप्त कर सका, फिर भी विश्व के राष्ट्र

ने यह अनुभव कर लिया है कि चीन की निरंकुशता को रोकने के लिये उसे अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ के नियन्त्रण में लाना ही विश्व-शान्ति की दृष्टि से उपयोगी होगा ।

सितम्बर १९६५ में पाकिस्तान ने अप्रत्याशित रूप में भारत के ऊपर बहुत बड़ा सशस्त्र आक्रमण कर दिया । यह आक्रमण संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उन उपबन्धों के सर्वथा अतिरिक्त-स्वरूप था जिनमें कि यह स्थापित किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा अवश्य ही शान्तिपूर्ण उपायों से किया जाना चाहिये । ब्रिटेन से जो कि कामनवेल्थ का प्रस्तावक सदस्य है, अपेक्षा की जाती थी कि वह पाकिस्तान के ऐसे अनियन्त्रित कार्य को भर्त्सना करेगा, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो कम से कम तटस्थ अवस्था रहेगा । किन्तु वह परोक्षतः पाकिस्तान के पक्ष का ही समर्थन करता रहा । संयुक्त राज्य अमेरिका की भी लगभग यही स्थिति थी । वह अपने गुट में सम्मिलित होने के कारण पाकिस्तान की निन्दा न कर सका और उसने आक्रामक और आक्रमित दोनों को समान तुलना पर तोलते हुये दोनों की सैनिक सहायता तथा पुनश्च, नागरिक और खाद्यान्न-महायन्ता भी बन्द करने की घोषणा की । पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध उन भयावह और अजेय हमलों की शृङ्खला का प्रयोग किया, जिन्हें कि अपने साम्यवादी देशों से अपनी रक्षा के बहाने प्राप्त किया था । अमेरिका इसको भी भर्त्सना न कर पाया । विश्व के किसी भी शान्तिप्रिय और सम्प्रदेश के लिए यह विन्ता और निराशा की बात थी । भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध किये गये युद्ध में कभी भी शान्त नगरी, अस्पतालों या नागरिक जीवन के महत्वपूर्ण स्थलों पर बमबर्षा नहीं की, किन्तु पाकिस्तान औपचारिक युद्ध की घोषणा न की जाने के उपरान्त भी भारत के शान्त नगरी, अस्पतालों, गिरजाघरों और मस्जिदों पर भयंकर रूप से बमबर्षा करता रहा ।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत के ऐसे संकट के समय संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बहुत-कुछ दौड़ धून करने के उद्योग भी केवल युद्ध-विराम के प्रस्ताव पारित करता रहा, और यहाँ तक कि वास्तविक आक्रामक कौन है, इसकी भी स्पष्ट घोषणा न कर पाया । यहाँ तक कि नाशकन्द-घोषणा के उपरान्त भी पाकिस्तान हठधर्मी और युद्ध-उत्प्रेरणा के कार्य करता रहा । पूरे शान्ति के समय भी १९६७ में उसका एक युद्ध-धन्येपक यान भारत के क्षेत्र में भीतर उड़ान मरता हुआ पाया गया और भारतीय नभ-शक्ति का शिकार हुआ । प्रश्न है, ऐसी कार्यवाहियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोकें कौन ?

विपतनाम पर अमेरिकी बमबर्षा निरन्तर जारी है । मसार के मन्त्र कहे जाने वाले बहुराष्ट्रों ने इस कार्यवाही को निन्दा की है और बमबर्षा तत्काल

रोक देने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की ओर से भी ऐसे ही। प्रस्ताव प्राये हैं। किन्तु शक्ति सम्पन्न संयुक्त राज्य पर ऐसी अपीलें ओर ऐसे प्रस्तावों का कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं दिखायी पड़ता।

१९६५ में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किये जाने के प्रश्न पर विचार के समय पाकिस्तान के तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री श्री भुट्टो ने स्पष्ट धमकी दी कि यदि काश्मीर प्रश्न का निर्णय पाकिस्तान के पक्ष में नहीं किया जाता तो वह संयुक्त राष्ट्र सङ्घ छोड़ देगा। इसी प्रकार इन्डोनेशिया ने सुरक्षा परिषद् में मलायोेशिया की सदस्यता के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ से अपना सबंध विच्छेद कर देने की घोषणा कर दी। कालान्तर में वह साधारण सभा के बीचवर्ष अधिवेशन में पुनः सम्मिलित हो गया। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ इन दोनों कार्यवाहियों पर कोई प्रभावकारी प्रतिक्रिया न उपबन्धित कर पाया।

दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे के प्रश्न के निपटारे और मानव-मान को भेद-रहित समानता प्रदान करने के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के उल्लेखनीय प्रयत्नों के उपरान्त भी व्यावहारिक मान्यता नहीं मिल सकी है।

पूरब से लेकर पश्चिम तक विश्व के रंगमंच पर पिछले वर्षों में कुछ और भी घटनाएँ घटित हुई हैं जिनसे इस बात पर पुनः विचार होना लगा है कि क्या संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रवर्तन में पूर्णतया सफल नहीं हो पा रहा है? यदि उसकी यह असफलता बढ़ती रही तो क्या उसे भी लोग आफ नेशनस के ही भाग्य का सामना करना होगा? आदि। इधर नये स्वतन्त्र होने वाले देश लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था की अपेक्षा सैन्य तन्त्र की ओर अधिक झुक रहे हैं। यह एक और भी चिन्तनीय बात है। अस्तु, आज इस बात की आवश्यकता और भी बढ़ गई है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का गहनतम अध्ययन किया जाय।

इन्हीं दृष्टियों से इस संस्करण में यथाप्रसंग और भी प्रकरण बढ़ा दिये गये हैं। उदाहरणार्थ निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं —

अध्याय ८ में राज्यों की मान्यता के साथ ही इस प्रश्न पर भी प्रकरण बढ़ा दिये गये हैं कि क्या मान्यता एक वैध या राजनीतिक समस्या है। इसके साथ ही मान्यता के भेद, एवं मान्यता सम्बन्धित अन्य वाञ्छित प्रकरण भी संयुक्त कर दिये गये हैं।

अध्याय ९ में राज्य के उत्तराधिकार के प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में उत्तराधिकार, यू० ए० धार० और यू० ए० ए० के गठन की वैध समस्या, संयुक्त प्रारम्भ गणराज्य, संयुक्त प्रारम्भ राज्य, आदि व प्रसंग बढ़ाये गये हैं।

अध्याय १३ में राज्य क्षेत्र का अर्जन तथा अपहरण, काश्मीर समस्या की आधुनिकतम प्रगति फारमूसा (तैवान) की वैध स्थिति, चन्द्र और ग्रहों पर मानव-विजय, आदि के प्रसङ्ग समस्याओं के स्पष्ट विवेचन सहित समुक्त कर दिये गये हैं ।

इसी प्रकार अध्याय १६ में समुद्री डाका के लिए आवश्यक तथ्य, अध्याय २० में राजनयिक अभिकर्ता, राजाधिक उन्मुक्तियाँ तथा जनता स्वभाव और प्रवर्तन, आन्तराधिक सत्ताधिकार से उन्मुक्ति, आदि के प्रसंग जोड़े गये हैं ।

अध्याय २६ समुक्त राष्ट्र सङ्घ के प्रवरण में चीन का भारत आक्रमण, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का प्रश्न, १९५० में न्यायालय की सम्मति, इथियोपिया और लाइबेरिया का मामला, अफ्रीका में राजनीतिक जागृति, चार्टर के अनुच्छेदों में सशोधन, आदि का भी विवेचन कर दिया गया है ।

अध्याय ३३ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, के प्रकरण में ऐंग्लो-ईरानियन तेल की कम्पनी का मामला, भारत के कतिपय क्षेत्रों पर पुर्तगालियों के आधिपत्य के अधिकार का मामला, मशरूफा परामर्श, आदि के प्रसंग बढ़ाये गये हैं ।

इसी प्रकार अध्याय ४२ में हवाई युद्ध की विधियाँ और अनुक्रम प्रयोग की नैतिकता पर विचार, अध्याय ४३ में युद्ध सम्बन्धी अपराध, बन्धा व्यक्तिों का वध एक युद्धापराध, युद्ध अपराधिया, निवर्जनिष्ठ और राजद्रोहियों के लिए शरण-स्थान, अध्याय ४८ में सरोध या नाकाबन्दी, और नाकाबन्दी के प्रकार और अध्याय ४९ में विनिषिद्ध, विनिषिद्ध और नाकाबन्दी में सम्बन्ध तथा निम्नतर समुद्र यात्रा के बाद, आदि के प्रसंग और भी बढ़ाये गये हैं ।

इस प्रकार प्रस्तुत संस्करण को और भी पूर्ण आधुनिकतम और प्रामाणिक बनाने के प्रयत्न किये गये हैं । भाषा को और भी प्राञ्जल, सुद्ध और सरल करने की ओर भी यत्न किये गये हैं । विश्वास है कि यह संस्करण छात्रों, प्रतियोगियों और जिज्ञासुओं के लिये और भी उपयोगी हो सकेगा ।

‘शरीश’ भवन,  
इलाहाबाद ।

महेश प्रसाद टण्डन

# विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ संख्या

## भाग १—प्रारम्भिक

### १—अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्वरूप (Nature of International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का महत्व हमकी उत्पत्ति, परिभाषा, मार्वाजनिक और वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि, क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि यवार्थ मे विधि है ? अन्तर्राष्ट्रीय विधि के दोष, अन्तर्राष्ट्रीय विधि का नया कृतव, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार—मूल अधिकारों का सिद्धान्त, सहमति सिद्धान्त, वास्तविक आधार ।

### २—अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत (Sources of International Law)

प्रकट सहमति, परोक्ष सहमति, सन्धियाँ, रुढियाँ—रुढि तथा प्रथा—विधि के सामान्य सिद्धान्त, न्यायिक निर्णय, न्यायाधिकरण, समुद्र मे अभिप्रेहीत सम्पत्ति सम्बन्धी समुद्री सेना विभाग के नौजितमाल न्यायालय, राष्ट्र-न्यायालयों के निर्णय तथा प्राइज कोर्ट्स, मूल-पाठों के लेखक, विवि-वेत्ताओं के कार्यों और टीकाकार, अन्तर्राष्ट्रीय सीजन्य, सन्धियों के अतिरिक्त अन्य अन्तर्राष्ट्रीय राज-पत्र, अपने अधिकारियों के निर्देश क लिये राष्ट्रों के अनुदेश, आधुनिक विधि-व्यवस्था मे तर्क का स्थान ।

### ३—अन्तर्राष्ट्रीय विधि का इतिहास (History of International Law)

हिन्दू, मुसलमान, यहूदी, यूनानी, रोमन, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इतिहास का तीन युगों मे विभाजन, ओशस, जाउवे, तीन सम्प्रदाय—प्रकृति-वादी, स्थिर व्यवहारवादी तथा ओशस मतावलम्बी, उन्नीसवी तथा बीसवी शताब्दी, हेग सम्मेलन, लीग आफ नेशन्स की प्रतिज्ञा,

लोकानों की सन्धि, केलोग-विमोड सम्झौता, १९२६ की जेनेवा का सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण, द्वितीय विश्व युद्ध ।

४—प्रकृति-विधि और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास पर उसका प्रभाव (Law of Nature and its Influence on the Development of International Law)

४१

जस्टोनियन, हुकर, यूनानी विचारगारा, रामन विचारधारा, सिसरो, प्राकृतिक नियम पर मेन, शासक के पूर्व प्राकृतिक नियम, शासन, रिचर्ड लाउचे, हान्न तथा पफे डाफ, वैकरशाक, आधुनिक युग में प्राकृतिक विधि ।

५—राष्ट्रों की विधि का संहिताकरण (Codification of the Law of Nations)

४७

परिभाषा, साम, सक्षित इतिहास, हेग सम्मेलन, लंदन की घोषणा, लीग ऑफ नेशन्स, संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकार-पत्र तथा संहिताकरण, अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग, राज्यों के अधिकार तथा वर्तव्यता की घोषणा का मसौदा, नूरम्बर्ग सिद्धान्तों का निरूपण, प्रचालित अन्तर्राष्ट्रीय विधि, अग्रपर्वण की परिभाषा मनुष्य जाति की शान्ति तथा सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की संहिता का मसौदा, प्रधान समुद्रों की शासन पद्धति, सन्धिया की विधि, अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक क्षेत्राधिकार, मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, अन्य अभिसमय ।

६—अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि में परस्पर सम्बन्ध (Monistic Theory), द्वैतात्मक सिद्धान्त (Dualistic Theory), रूपान्तर सिद्धान्त (Transformation Theory), अन्तर्राष्ट्रीय विधि का राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करने के सम्बन्ध में राज्यों की रीति—ब्रेट वितेन, अमेरिका महादीप वाला की रीति ।

५६

## भाग २—शान्ति की विधि

७—अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय (Subjects of International Law)

राज्य की परिभाषा, सर्वोच्चसत्ता तथा राज्या की स्वतन्त्रता, राज्या का वर्गीकरण—स्वतन्त्र राज्य तथा परतन्त्र राज्य—, राज्या की

६३



समानता, असंपूर्ण प्रभुताधारी राज्य तथा राज्यों का सङ्घ—राज्य-मंडल, वास्तविक सङ्घ, व्यक्तिगत सङ्घ, सङ्घ राज्य, स्तराज्य, राष्ट्रमंडल, भारत की स्थिति, सामंत राज्य—तिब्बत, नेपाल, भारतीय रियासत, संरक्षित राज्य—इजिप्ट, सिक्किम, भूटान, ब्रिटिश संरक्षित राज्य फ्रांसीसी संरक्षित राज्य, प्रादेशित तथा व्याप्त प्रदेश—प्रादेशित क्षेत्र नियमित प्रदेश—स्विटजरलैंड तटस्थीकृत तथा तटस्थ राज्या में भेद, होली सी ।

### ८—राज्यों की मान्यता (Recognition of States)

२१

इसका लक्षण, मान्यता के सिद्धांत आपेनहेन का मत, समन्वित विचार, मान्यता क्या एक वैध या राजनीतिक समस्या है ? मान्यता के भेद, प्रतिबंध युक्त मान्यता, सामूहिक अमान्यता, तथ्यत और विधित मान्यता, वैदेशिक कार्यालय से सूचना, तथ्यत और विधित मान्यता में भेद, राज्य के नये अध्यक्षा की मान्यता, निर्वासित सरकार की मान्यता, राज्यों की मान्यता, स्टिमसन का अमान्यता सिद्धान्त स्ट्राडा का सिद्धान्त, मान्यता की पूर्ण अभाव, मान्यता के प्रकार तथा परिणाम, अमान्य राज्यों की अनहतायें, मान्यता और लीग, मान्यता तथा संयुक्त राष्ट्र सच, युद्ध सलसलता की दशा में मान्यता, राज्य प्रतिरोध, सह युद्ध सलसलता ।

### ९—राज्य उत्तराधिकार (State Succession)

११२

मावदेशिक उत्तराधिकार, आंशिक उत्तराधिकार, राज्य उत्तराधिकार के परिणाम, सधि अधिकार और वक्तव्य विधि नियामक सधियों के मध्य में राज्य उत्तराधिकार, सदस्यता भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन, किसी राज्य के सविधान या राज्य की सीमा के बदल जाने का प्रभाव लोक सन्मति और लोक अधिकार, वैयक्तिक संपत्ति वैयक्तिक अधिकार, सविदात्मक दायित्व, लोक श्रृंखला, दुष्टति, विधिर्षा, राष्ट्रीयता, विद्रोह के दबा दिये जाने के बाद उत्तराधिकार, असदस्यता की स्थिति में उत्तराधिकार अंतराष्ट्रीय संगठन में उत्तराधिकार, यू० ए० आर० और यू० ए० एस० के गठन की वैध समस्या, संयुक्त अरब गणतंत्र, संयुक्त अरब राज्य, वैध परीक्षण, संयुक्त अरब गणतंत्र या मोरिया तथा ईमेन का विश्रुद्धन ।

## १०—हस्तक्षेप (Intervention)

१२७

हस्तक्षेप क्या है, हस्तक्षेप के प्रकार—भ्रान्तरिक, बाह्य तथा दाडिग—हस्तक्षेप के मूल कारण—आत्मसंरक्षण, सधि अधिकारों का लागू करना, हगरी के मामले में सोवियत रूस का हस्तक्षेप, मानवता के कारण, चार्टर के अनुसार व्यवस्था, शक्ति-संतुलन, व्यक्तियों तथा सम्पत्ति का संरक्षण, गृहयुद्धों में हस्तक्षेप, अन्य कारण, हस्तक्षेप के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न विद्वानों के सिद्धान्त, मुनरो सिद्धान्त, डैगो-सिद्धान्त, नेहरू सिद्धान्त ।

## ११—आवश्यकता तथा आत्म-संरक्षण का सिद्धान्त (Doctrine of Necessity and Self-Preservation)

१३७

किसी प्रदेश के अतिक्रमण का न्यायोचित होना, अन्तर्निहित अधिकार, प्रथम विश्वयुद्ध, मचूरिया का ऋगडा, रूम का फिनलैंड पर आक्रमण, अमेरिका वालो की तटस्थता, कोरिया का मामला तिब्बत पर आक्रमण, चार्टर के उपबन्ध, निष्कर्ष ।

## १२—राज्य-क्षेत्र (State Territory) ✓

१४२

क्षेत्रीय प्रभुपत्ता की सीमाएँ, क्षत्र, सीमाएँ, नदियाँ, नहरें, स्वेज नहर, कील नहर, पनामा नहर, जलडमरूमध्य, साप्ताहिक पेट्रो, तटीय व्यापार, खाडियाँ तथा आखात, बन्दरगाह, तीव्र पीछा का सिद्धान्त जेनेवा कन्फ्रेंस, १९५८, नम पर सर्वोच्चसत्ता—पेरिस, हवाना, बारासा तथा सिकागो का-वेशन अथवा वायु-परिवहन की पौव स्वतन्त्रताएँ, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सन्ध, बेतार की खबरें, किसी राज्य की ऊपरी आकाशीय सीमा की मान्यता और 'यू-२' का दृष्टान्त, सुविधा-भार, या अधिसेविता-स्वीकारात्मक तथा निषेधात्मक सुविधा-भार, सैनिक और आर्थिक सुविधा-भार, राज्य अधिसेविता (सुविधा-भार) की वैधता, सुविधा-भार का अन्त ।

## १३—राज्य-क्षेत्र का अर्जन तथा अपहरण (Acquiring and Losing State Territory)

१५६

बच्चा या दलाल, जर्मनी की वैध स्थिति, फारपूर्मा (तैवान) की वैध स्थिति, चन्द्र और ग्रहों पर मानव विजय, भोगाधिकार, शोधबुद्धि, परित्याग, अनमत संग्रह, काश्मीर समस्या और उसका अन्तर्राष्ट्रीय,

वैध रूप, जारिन रिपोर्ट, डा० ग्राहम रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संधि में १९६४ का कश्मीर वाद-विवाद, जम्मू और काश्मीर राज्य भारत का अविभाज्य अंग, विजय तथा परामर्श, गोघा की स्वतन्त्रता (मुक्ति), मूल तथा उप-रीतियाँ, न्याय निर्णय और पञ्चाट, पट्टे, राष्ट्रीय क्षेत्र की हानि ।

### + १४—क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) १८४

खुले हुये समुद्र पर क्षेत्राधिकार, सामुद्रिक मार्ग स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में वैध धारणाएँ, सार्वजनिक जहाज, समुद्री डकैती, खुले हुये समुद्र में मरस्य-क्षेत्र, समुद्र की सतह, खुले समुद्र पर ऋण-परीक्षण, तीन मील के सामुद्रिक क्षेत्राधिकार का प्रश्न, दीवानी तथा आपराधिक क्षेत्राधिकार, विदेशी राज्यों में विदेशियों की स्थिति, अपर-देशीयता ।

### ✓ १५—सार्वजनिक तथा वैयक्तिक जहाजों पर क्षेत्राधिकार (Jurisdiction over Public and Private Vessels) १८३

सार्वजनिक पोत क्या है ? सार्वजनिक जलयानों की खुले हुए समुद्र पर तथा विदेशीय क्षेत्रीय जलभागों पर वैध स्थिति, टक्कर के मामले, सार्वजनिक सशस्त्र पोत, उन्मुक्तियाँ, वैयक्तिक पोत क्या है ? बड़े समुद्री पर वैयक्तिक पोत की वैध स्थिति ।

### ✓ १६—समुद्री डाका (Piracy) १८६

समुद्री डाका के लिये आवश्यक तथ्य, किसी सरकार द्वारा प्राधिकृत समुद्री डकैती के कार्य, वैयक्तिक समुद्री डकैती सम्बन्धी जहाजों को गिरफ्तार करना, समुद्री डकैती के प्रसंग में सम्पत्ति का स्वामित्व, समुद्री डकैती और राष्ट्र विधि ।

### ✍ १७—राष्ट्रीयता (Nationality) १८८

राष्ट्रीयता क्या है ? राष्ट्रियता का निर्धारण, राष्ट्रियता तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रियता तथा स्थायी निवास, राष्ट्रियता प्राप्त करने का ढंग, ब्रिटिश राष्ट्रियता अधिनियम, अमेरिका का राष्ट्रियता अधिनियम, दुहरी राष्ट्रियता, भारत में राष्ट्रियता, राष्ट्रियता का

लोप होना—विमुक्ति, वचित करना, समाप्ति, त्याग, प्रतिस्थापन, राष्ट्रहीनता, देश निकाला ।

१८—क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित प्रत्यर्पण (Extradition connected with Jurisdiction)

२०३

इसकी आवश्यकता, परिभाषा, कठिनाइयाँ, आवश्यक शर्तें, अटैलाट खड, प्रमुख मामले तथा सिद्धान्त, सावरकर का मामला, गोडफ्रे का मामला, मुबारक अली का मामला, ईस्लर का मामला, ह्या डे ला टोरे का मामला ।

१९—अन्तर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति का स्थान (Place of the Individual in International Law)

२१५

पारम्परिक मत, चरम मत, राज्य तथा व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय, रूस वालो का मत, सन्धि अनुबन्ध, नूरेम्बर्ग परीक्षण, जनवध अभिसमय, अटलांटिक चार्टर, संयुक्त राष्ट्र, मानवीय अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा, मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिये यूरोपीय अभिसमय, विदेशियों के अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण, खुले समुद्र की स्वतन्त्रता व्यक्ति की है अथवा राज्य की, व्यक्ति और अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ ।

२०—राजनयिक अभिकर्ता (Diplomatic Agents)

२२६

दूतकर्म का अधिकार, राजनयिक प्रतिनिधियों की श्रेणियाँ—राजदूत, पोपदूत तथा नसियो, पूर्ण सक्षम मंत्री तथा असाधारण दूत, निवासी मंत्री, कार्यदूत या निस्पृष्ट दूत, निमुक्ति, पहुँचने की विज्ञप्ति, किन दशाओं में राज्य इन दूत सम्बन्धों को अस्वीकार कर सकते हैं, राजनयिक अभिकर्ताओं की पदसंज्ञा, राजनयिक अभिकर्ता के कार्य, राजनयिक उन्मुक्तियाँ तथा उनका स्वभाव और प्रवर्तन, आपराधिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति, राजनयिक मुविधायें तथा उन्मुक्तियाँ प्रदान करने के तीन सर्वव्यापी सिद्धान्त, दीवानी क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति, दूतों के कर्मचारीवर्ग की उन्मुक्ति, निवास-स्थान के सम्बन्ध में उन्मुक्ति, करो (टैक्सो) से छूट, माल के अभिग्रहण होने से छूट, उपासना का अधिकार, यातायात की स्वतन्त्रता, उन्मुक्तियों का आरम्भ और उनकी परिसमाप्ति, निष्पट गमन का अधिकार, अस्थायी राजदूत,

राजनयिक मिशन की समाप्ति, दूतकर्म की समाप्ति पर भी प्रचारिकतायें ।

### २१—वाणिज्य दूत (Consuls)

२४४

परिभाषा, उनकी उत्पत्ति, वाणिज्य दूत की श्रेणियाँ, कीसलों की नियुक्ति, उनके कार्य, विशेषाधिकार, वाणिज्य दूत के पद का अन्त ।

## अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार

### २२—सन्धियाँ (Treaties)

२४८

संधि क्या है ? संधि के प्रकार, संधि में प्रविष्ट होने की शक्ति, अधिराज्यों (डोमिनियनो) की संधि करने की शक्ति, समुक्त राष्ट्र संधि की संधि करने की शक्ति, सविदाकारा में पारस्परिक सहमति सविदाय तथा संधियाँ, चार्टर से असम्बद्ध तथा अनैतिक संधियाँ सवैधानिक आवश्यकताय, संधियों को करने में भिन्न भिन्न कार्यवाही—प्रतिनिधियों का प्रत्यापन, वार्ता, हस्ताक्षर, सत्यापन, अधिमिलन तथा ससक्ति (आसजन) संधियों का प्रवर्तन, पञ्जीकरण, सन्धि का राज्य विधि में निगमन, अवैध संधियाँ, संधियों की समाप्ति, संधियों का पुनरीक्षण, भाग्य मिश्रीय (ब्रिटेन तथा इजिप्ट के मध्य की) सन् १९३६ की संधि, संधियों की व्याख्या ।

### २३—सैन्य और व्यापारिक संधियाँ (Alliances and Commercial Treaties)

२६४

मैत्रियाँ, सङ्घ कारण, गारंटी सन्धियाँ, व्यापारिक सन्धियाँ, परम मित्र राष्ट्र धारा ।

### २४—अन्तर्राष्ट्रीय दुष्कृतियाँ और क्षतिपूर्ति (International Torts and Damages)

२६६

अन्तर्राष्ट्रीय दुष्कृतियों के प्रकार, राष्ट्रीयता का दावा, स्थानीय उपचारों की परिसमाप्ति, सामूहिक कार्यों का दायित्व ।

## अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ

### २५—१ लीग ऑफ नेशन्स (League of Nations)

२६८

इसकी उत्पत्ति, सदस्य, उद्देश्य, संविधान, सभा, परिषद्, सचिवालय

विश्वशान्ति का स्थापना, प्रत्याहरण, लीग की स्थिति, लीग की असफलता के कारण ।

## २६—२. संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organization)

२७५

इसकी उत्पत्ति—लन्दन की घोषणा, अटलांटिक चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की घोषणा, मास्को तथा तेहरान सम्मेलन, डब्लुवर्न ओब्स सम्मेलन, सैन फ्रान्सिस्को सम्मेलन, इसके उद्देश्य तथा सिद्धान्त, सदस्यता, चीन का प्रतिनिधित्व, चीन का भारत आक्रमण, चीनियों का भारतीय सीमा पर दावा आधार रहित, संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान—(१) साधारण सभा, कार्य तथा शक्तियाँ, मतदान प्रक्रिया, सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्रों से प्रत्याहरण, शान्ति के लिए संगठित होने का सकल, कार्यों का सिद्धान्तलोकन, (२) सुरक्षा परिषद्, अगुआ का शान्तिपूर्ण तथा अनुरोधपूर्वक समझौता, सुरक्षा परिषद् में मतदान की प्रक्रिया, निषेधाधिकार, दुश्मन निषेधाधिकार, आत्म रक्षा, सैन्य की वैध स्थिति, संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा तथा सुरक्षा परिषद् का सम्बन्ध, राष्ट्र संघ में विधि, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा लीग, लीग और संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सुरक्षा परिषद् में अन्तर, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के कार्यों में प्रतिबन्ध, (३) सचिवालय, (४) न्याय परिषद्, शक्तियाँ तथा कार्य, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका का प्रश्न, १९५० में न्यायालय का सम्मति, ईथियोपिया और लाइबेरिया का मामला, (५) आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, प्रादेशिक तथा सुरक्षा-प्रबन्ध, अफ्रीका में राजनीतिक जागृति, चार्टर के अनुच्छेदों में सङ्गठन, चार्टर का पुनरीक्षण, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम चरण के कार्यों की समीक्षा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ का महत्व, पक्षशील ।

## २७—सुरक्षा परिषद् के कार्य का सिद्धान्तलोकन (Survey of Security Council at Work)

२४१

इटाली, ग्रीस, बर्लिन की नाकाबन्दी, फिनलैंड, सीरिया-लेबानोन, आग्न ईरानी तेल का अगुआ, कार्फू चैनल अगुआ, कोरिया, कोरिया-युद्ध में वैध प्रश्न, ऐजोर्निया का प्रश्न, काश्मीर, स्वेडन नहर, हंगरी, टुनिसिया, दक्षिण अफ्रीका में जातीय रक्तपात, कांगो का संकट, १९६५ का भारत-पाक सङ्घर्ष-संघर्ष, परिणाम ।

## २८—सामूहिक सुरक्षा (Collective Security)

३७२

लीग प्रतिज्ञा-पत्र, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ का चार्टर, सामूहिक सुरक्षा की असफलता, शक्ति-संतुलन, क्षेत्रीय समझौते—नाटो या उत्तरीय अटलांटिक सन्धि सङ्गठन, सन् १९४७ का रियो पैक्ट, इनकॉर्पो सन्धि, सन् १९४८ की ब्रसेल्स की सन्धि, योरोपीय सुरक्षा समुदाय, ऐन्जु पैक्ट, दक्षिण-पूर्वी एशिया सामूहिक प्रतिरक्षा सन्धि अथवा मनीला पैक्ट, अमेरिका-जापान पैक्ट, बाल्कन पैक्ट, फ्रान तथा सीबिया के मध्य मैत्री सन्धि, इजिप्ट-सीरिया प्रतिरक्षा पैक्ट, सामूहिक सुरक्षा की सोवियत पद्धति, मित्रता सम्बन्ध तथा पारस्परिक सहायता की सन्धि, वारसा सन्धि अथवा पूर्वीय यूरोपीय सन्धि सभ, अमेरिका-फिलिपाइन्स पारस्परिक प्रतिरक्षा सन्धि, अरब लीग, बगदाद पैक्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका और टर्की तथा ईरान और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता समझौता, आर्थिक और राजनैतिक सहकारिता—वेनेलकस, यूरोपीय आर्थिक सहकारिता सङ्घ, अमेरिकी राज्यों का सङ्घ, शुमन प्लान या योरोपीय कोयला व सोदा समुदाय, कोलम्बो योजना, पश्चिम।

## २९—निःशस्त्रीकरण (Disarmament)

३८१

लीग आफ नेशन्स, जेनेवा सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, आणविक शक्ति आयोग, शस्त्रों का नियमन तथा न्यूनीकरण, रूस की शिल्लर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के लिये पुकार, रपाकी योजना, पुनरीक्षित रपाकी योजना, निःशस्त्रीकरण आयोग, शान्ति के लिए अणु, नभक्षेत्र का शान्तिपूर्ण उपयोग, एटम शक्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग, १९६०-६१ की संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा, संयुक्त मेमोरेण्डम, संयुक्त राष्ट्र के साधारण सभा का १७वाँ अधिवेशन, न्यायिक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (१९६३), निष्कर्ष।

## ३०—विशिष्ट अभिकरण

४०१

(१) अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सङ्घ, (२) संयुक्त राष्ट्र का स्वास्थ्य तथा वृषि सम्बन्धी सङ्घ, (३) संयुक्त राष्ट्र सङ्घ का शिक्षा सम्बन्धी, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्घ, (४) अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सङ्घ, (५) पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, (६) अन्तर्राष्ट्रीय

घन कोप, (७) विश्व स्वास्थ्य सङ्घ, (८) अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी सङ्घ  
(९) सार्वदेशिक डाक सङ्घ, (१०) अन्तर्राष्ट्रीय तार मंडलवहन सङ्घ,  
(११) विश्व-अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी सङ्घ ।

### अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विधि

३१—१. विवाचन का स्थायी न्यायालय (The Permanent Court of Arbitration)

४०८

उत्पत्ति, इसका ढाँचा, पेंनेल के सदस्य, प्रशासकीय परिषद्, ब्यूरो (कार्यालय); अर्थ व्यवस्था, न्यायानय का प्रकार, विभाजक निर्णय, न्यायाधिकरण के समक्ष के कुछ मामले—(१) उत्तरीय अटलांटिक महासागरों का मामला (१९१०), (२) सावरकर का मामला (१९११), (३) रूस का दलितपूर्ति का मामला (१९१२) ।

३२—२. अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय (The Permanent Court of International Justice)

४११

न्यायालय की उत्पत्ति, न्यायालय के सदस्यगण, राजनैतिक विशेषाधिकार, विवाचन न्यायालय पर सुधार, न्यायानय की पहुँच, न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली विधियाँ, स्थायी न्यायानय के प्रमुख निर्णय—(१) एस० एस० विम्बेल्डन, (२) पोलैंड में जर्मन निवासी, (३) पोलैंड प्रवर सिलेशिया का मामला, (४) एस० एस० लोटस, (५) कोरजो वी फैक्ट्री से सम्बन्धित मामला ।

३३—३. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (The International Court of Justice)

४१६

इसकी उत्पत्ति, न्यायालय का संगठन, न्यायालय की क्षमता, न्यायालय का क्षेत्राधिकार—ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार तथा मन्त्रणा क्षेत्राधिकार, सलाह क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में प्रक्रिया, न्यायापीठों की अनुमक्तियाँ, न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली विधि, न्यायालय की प्रक्रिया, अन्तरिम भववा अन्तःकालीन उपाय, अंग्ल-ईरानी तेल कम्पनी का मामला, न्यायिक निर्णयों का निष्पादन,



न्यायालय के समक्ष मामले—(१) कोर्फू चैनल वाला मामला, (२) ह्या डे ला टोरे का मामला, (३) ऐम्बो-ईरानियन तेल की कम्पनी का मामला, (४) भारत के कतिपय क्षेत्रों पर पुर्नगालियों के प्राधिपत्य के अधिकार का मामला, मंत्रालय परामर्श—(१) संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की मददस्वता के लिये किसी राष्ट्र का प्रवेश, (२) किसी राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र सङ्घ में प्रवेश करने के लिये साधारण सभा की क्षमता, (३) संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की सेवा में प्राप्त हानि के लिये क्षतिपूर्ति ।

### भाग ३—युद्ध की विधियाँ (The Laws of War)

#### ३४—मसगड़ों का निवटारा (Settlement of Disputes)

४३५

शान्तिपूर्ण रीतियाँ, वार्ता, मदभावना, मध्यस्थता, समाधान, प्रन्तरेद्रोप जांच आयोग, विवाचन, बाध्यकारी रीतियाँ, शिकायतें, प्रतिकार, प्रत्यपकार (प्रतिज्ञा), शत्रुतापूर्ण अविरोध, शान्तिपूर्ण सरोध (नाकाबन्दी), हस्तक्षेप, चाटर द्वारा बन्धनकारी रीतियों की अनुशास्ति ।

#### ३५—युद्ध तथा इसका प्रभाव (War and its Effects)

४४६

परिभाषा, युद्ध के प्रकार, पूर्ण युद्ध, क्या यह आवश्यक है कि युद्ध के पूर्व युद्ध की घोषणा की जाय ? युद्ध का तात्कालिक प्रभाव, राजनयिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी नियम, वाणिज्य सम्पर्क, सविशेष, सम्भेदारी वाले फर्म, शत्रुता का भुगतान, शत्रु के देश में प्राप्त सम्पत्ति, तटस्थ राज्यों में युद्ध स्थित सम्पत्ति, युद्ध का सन्धियों पर पारिणाम, सन्धियाँ जिनमें युद्ध संलग्न तथा अन्य शक्तियाँ पक्षकार हैं, सन्धियाँ जिनमें केवल युद्ध-सलग्न राज्य ही पक्षकार हैं ।

#### ३६—शत्रु लक्षण (Enemy Character)

४५४

व्यक्तियों का शत्रु स्वभाव, स्थायी निवास, शत्रु पोत, जहाजों का हस्तान्तरण, गोमार, तटस्थों का माल युद्ध में मलग्न वापारिक जहाजों पर तथा इनो का विरोध, शत्रु सम्पत्ति, निगम, दबस तथा विजय का प्रभाव ।

- ३७—युद्ध की नई समस्याएँ (New Problems of Warfare) ४६२  
युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की नई पद्धतियाँ, लीग, १९२८ का वेरिस वेक्ट, समुदाय राष्ट्र सङ्घ ।
- ३८—स्थल युद्ध की विधियाँ (Laws of Land Warfare) ४६५  
१८६४ का जेनेवा अभिसमय, सेट पीटर्सवर्ग का घोषणा, युद्ध की रीतियाँ, सन् १९०७ का हेग अभिसमय, स्थल युद्ध की विधियों का विकास, सन् १९४९ का जेनेवा अभिसमय, युद्धबन्दी, अस्वस्थ तथा घायल, युद्ध-छल, युद्ध-भेदिये और घाघेबाज ।
- ३९—युद्धस्थित के दखल (Belligerent Occupation) ४७२  
दखल का अर्थ, इसके परिणाम, उपासना के लिये मम पत सस्थाप्ये, अचल सम्पत्ति, लड़ाई न लड़ने वालों की चल सम्पत्ति, सार्वजनिक चल सम्पत्ति, व्यक्तिगत सम्पत्ति, युद्ध-कार्य, सामूहिक दण्ड, न्यायालय, अधिग्रहण, अनादान तथा अन्य दण्ड, सन् १९४९ का जेनेवा अभिसमय ।
- ४०—समुद्री युद्ध की विधियाँ (Laws of Maritime Warfare) ४७७  
उद्देश्य, वेरिस की घोषणा, शत्रु के सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत पोत पर आक्रमण, अपवाद, शत्रु की सेना में सलग्न तटस्थ व्यापारी जहाज, तटस्थ व्यापारी जहाज शत्रु के पररक्षक जहाजों के साथ, तटीय नगरों पर बम बरसाना, सुरंग, पनडुब्बियाँ, डाक द्वारा पत्र-व्यवहार, शत्रु के जहाजों का पकड़ने वाले जहाज, समुद्री युद्ध में छल, सन् १९४९ का जेनेवा अभिसमय, अस्पताली जहाज, कर्मचारी वर्ग ।
- ४१—नौजितमाल न्यायालय (Prize Courts) ४८५  
नौजितमाल का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्राधिकार, निर्णय का प्रभाव, प्रक्रिया, नौजितमाल न्यायालयों के कर्तव्य, नौजितमाल न्यायालय की स्थापना, अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा उनके द्वारा प्रदत्त किये जाने वाली विधि में उनकी स्थिति, नौजितमाल का विनाश, जर्मन नौजितमाल न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रीय नौजितमाल न्यायालय की आवश्यकता ।

४०—हवाई युद्ध की विधियाँ (Laws of Air Warfare) X ✓ ४६३

ब्रसेल्स सम्मेलन, हेग सम्मेलन, प्रथम महायुद्ध, वाशिंगटन सम्मेलन, अयोधिया की स्थिति, द्वितीय विश्वयुद्ध, अणुबम प्रयोग की नैतिकता पर विचार, अणुशक्ति आयाग, शत्रु के नागरिक जहाज पर आक्रमण ।

४३—युद्ध सम्बन्धी अपराध (War Crimes) ✓ ५००

युद्ध अपराध किम प्रकार से स्थापित होता है, नूरम्बर्ग परीक्षण—इसकी उत्पत्ति नूरम्बर्ग परीक्षण का भौतिक, अपराध की श्रेणियाँ—शान्ति के विरुद्ध अपराध युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध—प्रतिरक्षा न्यायाधिकरण का निरूपण, परीक्षण की आलोचना, टोकियो परीक्षण—शान्ति के विरुद्ध अपराध, हत्याएँ, अन्य अभिसमयात्मक युद्धापराध और मानवता के विरुद्ध अपराध—मनभेद प्रकट करने वाला निर्णय, जनवध, अन्तर्राष्ट्रीय दण्ड न्यायालय, बन्धक व्यक्तियों का वध एक युद्धापराध, युद्ध-अपराधियों, विश्वजलियन और राज्यद्रोहियों के लिये क्षरण स्थान, युद्धापराध परीक्षण और युद्धविधियाँ ।

४४—पराधर्तन तथा पुनर्ग्रहण या पुन बन्दोकरण का सिद्धान्त (The Doctrine of Postliminium and Recapture) ५१६

पृष्ठभूमि, अभिप्राय तथा प्रयोग, तटस्थ प्रदेशों में इसके प्रवर्तन की सम्भावनाएँ—चल सम्पत्ति पर प्रभाव, अचल सम्पत्ति पर प्रभाव, ऋण शोधन (चुकाना), इसका प्रभाव, सिद्धान्त की परीक्षा, हेसे केसल मामला ।

४५—युद्ध का समापन (The Termination of War) X ✓ ५२१

युद्ध समापन की रीतियाँ, शान्ति सन्धि का प्रभाव, अवाधुत, युद्ध विराम सन्धि तथा युद्ध विघाति सन्धि, प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध ।

भाग ४—तटस्थता की विधि

४६—तटस्थता (Neutrality) ✓ ✓ ५२५

परिभाषा, तटस्थता के भेद, तटस्थता तथा तटस्थीकरण, तटस्थता सम्बन्धी आधुनिक धारणा, हेग का द्वितीय सम्मेलन, लन्दन की

घोषणा, प्रथम विश्वयुद्ध, लीग ऑफ नेशन्स के अधीन तटस्थता, तटस्थता तथा केलोग-ब्रिग्हाड पैक्ट, स्पेन का गृह-युद्ध, पनामा की घोषणा, पनामा की घोषणा का महत्व, द्वितीय विश्वयुद्ध, चार्टर के अन्तर्गत तटस्थता, तटस्थता और आवश्यकता का सिद्धान्त, तटस्थों के अधिकार तथा कर्त्तव्य, तटस्थ राज्य के अधिकार अथवा युद्धस्थित राज्य का तटस्थ राज्य के प्रति कर्त्तव्य, तटस्थ राज्यों का युद्धस्थित राज्यों के प्रति कर्त्तव्य अथवा युद्धस्थित राज्यों के अधिकार, परहेज (अलग रहन व कर्त्तव्य), रोकन का कर्त्तव्य, युद्धपोतो का ठहरना तथा उनकी मरम्मत, उपमति के कर्त्तव्य, पुन स्थापन या वापसी के कर्त्तव्य, क्षति-पूर्ति के कर्त्तव्य, निर्णय विधि ।

#### ✓ ४७—संकटाधिकार (Right of Angary)

५४३

संकटाधिकार, इसकी उत्पत्ति, ओपेनहेम का मत, पिट कोबेट का मत, फिलीमार का मत, सन् १८७० का फ्राय तथा जर्मनी का युद्ध, परि-सीमन, जमारा ।

#### ✓ ४८—संरोध या नाकाबन्दी (Blockade) X

५४७

परिभाषा, संरोध या नाकाबन्दी के लक्षण, पेरिस की घोषणा (१८५६), लन्दन की घोषणा (१९६), नाकाबन्दी के प्रकार, वास्तविक तथा बन्धनकारी नाकाबन्दी के आवश्यक अंग—उचित संस्थापन, प्रभाविकता, निरन्तर बनाये रखना, निष्पक्षता—नाकाबन्दी का भंग, नाकाबन्दी की समाप्ति, नाकाबन्दी भंग करने के लिए दण्ड, निर्णय वाद, सम्बन्धी दूरी की नाकाबन्दी—प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध, निकट नाकाबन्दी ।

#### ✓ ४९—विनिपिद्ध (Contraband) X

५५७

परिभाषा, इसका आधार, परम का विभाजन, निरपेक्ष विनिपिद्ध, सप्रतिबन्ध विनिपिद्ध, अनिपिद्ध, पीटरहोफ वाला मामला, अपराध के आवश्यक अंग, विनिपिद्ध वस्तु वहन करने के लिये दण्ड, वैध आगम-ग्रहण के लिये मुभाबजा, विनिपिद्ध और नाकाबन्दी से सम्बन्ध, अद्वैत यात्रा का सिद्धान्त, अद्वैत यात्रा के सिद्धान्त की नाकाबन्दी, विनिपेध तथा अतटस्थ सेवा में उपयोगिता, निरन्तर समुद्र यात्रा के महत्वपूर्ण वाद, सन् १७५६ का युद्ध का नियम ।

परस्पर समाज में जीवन-यापन नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक राष्ट्र भी अपने आचरण को नियमित करने वाली परम्पराओं और रूढ़ियों के बिना परस्पर संसर्ग स्थापित नहीं कर सकता। जहाँ व्यक्तियों तथा राष्ट्र की जनता का आचरण नागरिक विधि द्वारा शासित होता है, वहाँ राष्ट्रों का, या राष्ट्रों के कुटुम्ब के सदस्यों, या राष्ट्रों के समाज का परस्पर आचरण अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा नियमित होता है।

इसकी उत्पत्ति:—अन्तर्राष्ट्रीय विधि ( International Law ) का यह शब्द सर्वप्रथम जेरेमी बेन्थम ( Jeremy Bentham ) द्वारा १७८० में रचा गया। यह राष्ट्रों की विधि ( Law of Nations ) का पर्यायवाची है और इसके समानार्थक फ्रांसीसी तथा जर्मन भाषा में क्रमशः 'droit des gens' 'Volkerrecht' शब्द प्रचलित हैं। बिकरशूक ( Bynkershoek ) ने राष्ट्रों की विधि की उत्पत्ति को तर्क और प्रथा ( reason और usage ) अथवा *ex ratione et usu* के कारण माना है और प्रथा को संधियों और अध्यादेशों ( *pacta et edicta* ) पर आधारित कहा है। दूसरे प्रसंग में उनका कहना है कि—

“Reason commands me to be equally friendly to two of my friends who are enemies to each other; and hence it follows that I am not to prefer either in war”.

तार्पर्य यह है कि तर्क यही कहता है कि हम अपने ऐसे दो दोस्तों से बराबर दोस्ती का सम्बन्ध बनाये रखें जो आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं और परिणामतः हम दोनों के बीच किसी को युद्ध में प्राथमिकता न दें।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि ( International Law ) की यथार्थता पर विचार करने के पूर्व यह अधिक उपयोगी होगा कि कुछ प्रसिद्ध लेखकों, विधि-शास्त्रियों और प्रकाशकों तथा इस विषय पर कुछ प्रसिद्ध कानूनी नज़ीरों या मुकदमों के दृष्टान्तों में दी हुई परिभाषाओं पर विचार कर लिया जाय।

### परिभाषायें

लॉरेंस ( Lawrence )—अंग्रेजी के प्रसिद्ध विधि-शास्त्री लॉरेंस ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि की इस प्रकार परिभाषा की है :—“वे नियम जो सम्य राज्यों के सामान्य और मामूहिक आचरण को उनके पारस्परिक व्यवहार में निर्धारित करते हैं, उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधिकांश भाग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में पृथक् युद्ध के प्रबन्ध के नियम सम्निहित हैं। स्वतंत्र संप्रभु राज्यों के बीच असमानता उनके पारस्परिक व्यवहार में बाधा उत्पन्न करती है; उनका अनियंत्रित सम्बन्ध मानवीय समाज में एक ऐसा कारण है जिससे युद्ध का भूतपात हो जाता है।

अतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार में उनके आचरण को नियमित करती है चाहे वे शत्रु-रूप में हो अथवा शान्त की स्थिति में हो ।

आपेनहेम ( Oppenheim )—राष्ट्रों की विधि या अन्तर्राष्ट्रीय विधि परंपरागत तथा संधियों से उत्पन्न नियम हैं जो कि सम्य राज्यो द्वारा परस्पर के व्यवहार में वैध रूप में एक-दूसरे पर बाधित माने जाते हैं ।

हॉल (Hall)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि आचरण के उन कतिपय नियमों में निहित है जो कि वर्तमान सम्य राज्य एक-दूसरे के सम्बन्ध में अपने ऊपर उसी शक्ति और मात्रा में बाधित मानते हैं जितनी कि अपने देश के कानूनों को मानने की बाध्यता सचेतन व्यक्तियों पर मानी जाती है और यह भी मानते हैं कि यदि उन नियमों का उल्लंघन किया गया तो उपयुक्त माध्यम द्वारा उनका प्रवर्तन अवश्य किया जायेगा ।

ह्यूज्स ( Hughes )—अन्तर्राष्ट्रीय विधि उन सिद्धान्तों और नियमों का समूह है जिन्हें सम्य राज्य परस्पर के सम्बन्ध में अपने ऊपर बाधित मानते हैं, और ये संप्रभु राज्यों की सहमति पर आधारित होते हैं ।

हन्स केल्सन (Hans Kelsen)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि या राष्ट्रों की विधि उन नियमों के समूह का नाम है जो कि साधारण परिभाषा के अनुसार राज्यों के व्यवहारों को एक-दूसरे के सम्पर्क में नियमित करते हैं । (International Law or the Law of Nations is the name of a body of rules which—according to the usual definition—regulate the conduct of two states in their intercourse with one another)

कैंपट (Kent)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि सार्वजनिक निर्देशों की वह संहिता है जो अधिकारों की व्याख्या करती है और राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों के प्रसंग में उनके कर्तव्यों का निर्धारण करती है ।

सर सेसिल हर्स्ट (Sir Cecil Hurst)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों का समुदाय है जो उन अधिकारों का निर्धारण करते हैं जिन्हें एक राज्य दूसरे राज्य से अपने अथवा अपने नागरिकों की ओर से माँगने का अधिकारी है । (International Law is the aggregate of the rules which determine the rights which one State is entitled to claim on behalf of itself or its nationals against another State)

ब्लैकस्टोन (Blackstone)—राष्ट्रों की विधि नियमों की एक व्यवस्था है जो प्राकृतिक तर्क द्वारा अनुमानित है और विश्व के सम्य नागरिकों की सार्वभौमिक सहमति से प्रपतित है । इसका उद्देश्य सभी अंगुष्ठों को तय करना, सभी नागरिक भौपचारिकताओं को नियमित करना और अपने उस व्यवहार में जिसे दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्यों के बीच निरन्तर होना चाहिए, न्याय और सद्भावना को अधिक

सुनिश्चित करना और दोनों के व्यक्तियों के बीच न्याय और सद्भावना उत्पन्न करना हुमा करता है ।

गाउल्ड (Gould)—“अन्तर्राष्ट्रीय विधि यहाँ तक कि व्यक्तियों से सम्बन्धित प्रसंगों में भी सार्वजनिक विधि है ।”

ब्रायरले (Brierly)—राष्ट्रो की विधि या अन्तर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि यह उन नियमों तथा कार्यों के सिद्धान्तों का समूह है जो कि सम्य राज्यों पर उनके एक दूसरे के सम्बन्ध में बाधित हैं ।

पिट कोबेट (Pitt Cobbett)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि इस प्रकार वर्णित की जा सकती है कि यह उन नियमों का योग है जो कि सम्य राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति तथा एक दूसरे की अनुराधा के प्रति अपना आचरण निर्धारित करने के लिए स्वीकार किए गए हैं ।

सर हैनरी मैने (Sir Henry Maine)—राष्ट्रो की विधि भिन्न-भिन्न अंशों से रचित एक मिश्रित व्यवस्था है । इसमें नैसर्गिक प्रकार से निष्पक्ष राष्ट्र के व्यक्तियों के आचरण के लिये तथा राष्ट्रों के सम्बन्ध और आचरण के लिए सामान्यतया उपयुक्त अधिकार तथा न्याय के सामान्य सिद्धान्त, प्रथाओं, लोकरीतियों और सम्मतियों का समूह, सम्पत्ति तथा व्यापार की वृद्धि और निश्चित अथवा पोजिटिव विधि (Positive Law) की संहिता सम्मिलित हैं ।

स्टार्क (Stark)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि को यो परिभाषित किया जा सकता है कि यह उन विधियों का समूह है जिनका अधिकांश भाग उन आचरण के सिद्धान्तों तथा नियमों का बना हुआ है जिनको राज्य अपने परस्पर सम्बन्धों में पालन करने के लिये अपने को बाध्य समझते हैं, अतः साधारणतया पालन करते हैं, और जिनमें कि निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं :

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं या सगठनों के सञ्चालन-सम्बन्धी विधि के नियम, उनके एक-दूसरे के प्रति सम्बन्ध तथा उनके राज्यों और व्यक्तियों के प्रति सम्बन्ध, और

(ग) व्यक्तियों से सम्बन्धित कुछ विधि-नियम जो कि ऐसे व्यक्तियों के अधिकार या कर्तव्य को निर्धारित करते हों जो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के विषय हों ।

स्टार्क की उपरोक्त परिभाषाओं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर अमेरिका के प्रमाण पुरुष प्रोफेसर चार्ल्स हेनरी हाईड (Professor Charles Cheney Hyde) द्वारा दी हुई परिभाषा का ही रूपान्तर है, हमारे समक्ष एक नया दृष्टिकोण उपस्थित करती है । परम्परागत परिभाषाओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि वह पद्धति है जिसमें राज्यों के परस्पर सम्बन्ध को निश्चित करने वाले नियम ही आते हैं ; युद्धोत्तर प्रगतियों को देखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाया तथा सगठनों की आयातक आवश्यकता और भी बढ़

गई है, और संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तराष्ट्रीय श्रमिक संघ, विश्व-स्वास्थ्यसंघ आदि प्रकट हो गए हैं। इनका अन्तराष्ट्रीय वैध व्यक्तित्व मान लिया गया है और ये संस्थायें एक दूसरे से तथा राज्यों से सम्बन्ध स्थापित करती तथा मानवीय अधिकारों की रक्षा करने और व्यक्तियों की मौलिक स्वतन्त्रता की सुरक्षा हेतु कार्यवाही करती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अन्तराष्ट्रीय विधि की पुरानी परिभाषाएँ अब प्रचलित नहीं हैं तथापि सामान्यतः अन्तराष्ट्रीय विधि की पुरानी परिभाषाओं में भी सत्य का एक अंश है। अन्तराष्ट्रीय विधि प्रमुख रूप से एक व्यवस्था है जिसके द्वारा राज्यों के अधिकार तथा कर्तव्य परस्पर नियमित किये जाते हैं और इसी कारण यह राष्ट्रों की विधि (Law of Nations) भी कही जाती है।

**फ्रैंकोनिया-विवाद—R. v. Keyn ( The Franconia ) (१८७६)**  
 में लार्ड कॉलरिज ( Lord Coleridge ), मुख्य न्यायाधीश, का कथन है कि राष्ट्रों की विधि उन रूढ़ियों या परम्पराओं का समूह है, जिनको कि सम्य राज्यों ने एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहारों में मानना स्वीकार कर लिया है। ये रूढ़ियाँ क्या हैं, कोई विशेष रूढ़ि स्वीकृत की गई है अथवा नहीं, ये बातें अवश्य साक्ष्य पर निर्भर होनी चाहिये।

**वेस्ट रैंड गोल्ड माइनिंग कम्पनी लिमिटेड सम्बन्धित विवाद (West Rand Gold Mining Co. Ltd. v. The King) (१९०५)** वाले प्रसिद्ध विवाद में लार्ड अल्वेस्टोन ( Lord Alverstone ) मुख्य न्यायाधीश ने किलोवन के लार्ड रसेल ( Lord Russell of Killowen ) द्वारा सन् १८६६ में सेराटोगा में दिये गये भाषण में दी गई परिभाषा को इस कथन द्वारा स्वीकार किया था, कि वह इससे उपयुक्त अन्तराष्ट्रीय विधि की परिभाषा नहीं जानते कि "यह उन नियमों तथा रूढ़ियों का योग है जो कि सम्य राज्यों द्वारा एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहारों में अपने ऊपर बाध्य मान लिये गये हैं।"

**एस० एस० लोटस विवाद ( S. S. Lotus )—एस० एस० लोटस (१९२७)** सम्बन्धित विवाद में जो कि फ्रांस और टर्की के बीच में हुआ, अन्तराष्ट्रीय स्थायी न्यायालय ( Permanent Court of International Justice ) ने अन्तराष्ट्रीय विधि की परिभाषा निम्न रूप से दी थी :—

"International Law was defined as meaning the principles which are in force between all independent nations" तात्पर्य यह है कि ये वे सिद्धान्त हैं जो सभी स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच प्रवर्तित हैं।

यह परिभाषा अन्तराष्ट्रीय विधि के दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर बल देती है—  
 एक तो इसकी सार्वभौमिकता पर और दूसरे इसकी अनन्यता पर। इसमें अधिक बल



‘स्वतन्त्र राष्ट्रों’ शब्द पर है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय के अनुसार वही सिद्धान्त प्रवर्तित किये जाते हैं, जिनका सम्बन्ध सभी राष्ट्रों से नहीं, अपितु सभी स्वतन्त्र राष्ट्रों से हुआ करता है।

पैकट हबाना विवाद (The Paquete Habana Case) - न्यायाधीश ग्रे (Gray, J.) ने यह अवलोकन किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि समुक्त राज्य (अमेरिका) की विधि का भाग है और उचित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों द्वारा प्रशासित होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उस अवस्था में, जहाँ कि कोई सन्धि अथवा कोई शासकीय अथवा विधायनिक अधिनियम (Act) या न्यायिक निर्णय न हो, सम्म राष्ट्रों की ऐसी रीतियों तथा रूढ़ियों का साक्ष्य रूप में सहारा लेना चाहिये जिन्हें न्याय-प्रवीणों तथा भाष्यकारों ने वर्षों के परिश्रम, अनुसन्धान और अनुभव के आधार पर अपने ग्रन्थों में इस विषय पर लिखा है।

ऊपर दी गई बहुत-सी परिभाषाएँ यह व्यक्त करती हैं कि भिन्न-भिन्न लेखकों ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों की विविधता पर किस प्रकार बल दिया है। पारम्भिक विद्वान् प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक तर्क और न्याय के सिद्धान्त पर बल देते थे जब कि आधुनिक लेखक विधि के नियमों की सीमा को व्यक्तियों और राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अधिकारों और कर्तव्यों के निर्धारण तक फैला हुआ मानते हैं। आधुनिक विद्वान् रूढ़ियों (रीतियों) और सन्धियों को विधि का मुख्य स्रोत मानते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि को आज हम विधि-शास्त्र का असहाय शिशु नहीं कह सकते। इसका एक न्यायिक आधार है और इसका उद्देश्य समन्वयिक और न्याय-पूर्ण ढंग से विश्व समुदाय के अन्तर्युनिट सम्बन्धों (equitable and just regulation of inter-unit relations within the world community) को नियमित करना है।

सार्वजनिक और वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Public International Law and Private International Law):—ऊपर दी गई परिभाषाएँ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि से साधारणतया सम्बन्धित हैं। “व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि” उन सिद्धान्तों का समूह है जो क्षेत्राधिकार और उपयुक्त विधि के चुनाव सम्बन्धी प्रश्नों का निर्धारण करते हैं। ये प्रश्न नागरिक विवाद के होते हैं जो निर्णय हेतु किसी एक राज्य या देश के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, किन्तु जिनमें कोई न कोई विदेशी तत्व (foreign element) अवश्य सम्मिलित होता है। तदर्थ यह है कि वह प्रश्न विदेशी व्यक्तियों, वस्तुओं या आसक्ति या पूर्ण रूप से किये गये विदेशी व्यापारों, या किसी विदेशी कानून-व्यवस्था आदि पर प्रभाव अवश्य डालते हैं।” (Pitt Cobbett's Leading Cases on International Law).

“वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उद्देश्य निम्नलिखित हैं — ”

“प्रथम—उन शर्तों को निश्चित करना जिनके अनुसार न्यायालय को कोई वाद प्रतिग्रहण करने के लिए उचित क्षेत्राधिकार प्राप्त हो ,

“द्वितीय—प्रत्येक घेसो के वाद के लिए विशिष्ट वैधानिक व्यवस्था निर्धारित करना जिसके अनुसार पक्षकारों के अधिकारों का पता लगाया जा सके ; और

“तृतीय—उन परिस्थितियों का विस्तारपूर्वक वर्णन करना जिनमें कि (अ) कोई विदेशी निर्णय किसी विवादास्पद प्रश्न के निश्चित करने के लिए प्रमाण मान लिया जाय । और (आ) किसी महाजन को किसी विदेशीय निर्णय द्वारा दिये गये अधिकार को कार्यवाही द्वारा इंग्लैंड में प्रवर्तित कराया जा सके ।”

वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्रत्येक देश में भिन्न होती है, मत वैयक्तिक और सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में कोई सादृश्य नहीं है ।

हाइसी महोदय (Dicey) इसे ‘विधि-सर्प’ (Conflict of Laws) कहते हैं क्योंकि यह उन मामलों से सम्बन्धित नियमों की व्यवस्था करता है जिनमें भिन्न-भिन्न राष्ट्रों की नागरिक विधियाँ (Municipal Laws) एक दूसरे के विरोध रूप में उपस्थित होती हैं । ऐसे विधि-सर्प नागरीकरण, विवाह, तलाक, इच्छापत्र और सविदाओं की वैधता आदि के प्रसंग में उठ सकते हैं । इसको ‘अन्तर-नागरिक राष्ट्रीय विधि’ (Inter-Municipal Laws), ‘अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य’ (International Comity) इत्यादि भी कहते हैं ।

उपरोक्त स्पष्ट होगा कि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि मुख्य रूप से एक शान्ति वा कानून है जो कि राज्यों के एक-दूसरे के व्यवहारों और सम्बन्धों को नियंत्रित करता है । जबस दो राष्ट्रों में सर्प छिड़ जाने अथवा युद्ध की घोषणा हो जाने व पश्चात् ही युद्ध के कानूनों और युद्ध में लगे हुये और तत्काल राष्ट्रों के अधिकारों और भावनाओं का आरम्भ होता है । वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों वा समूह है जो क्षेत्राधिकार के प्रश्नों के निर्णय करने के लिये हैं जो कि किसी राष्ट्र अथवा देश के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले व्यवहार-वादों में जिनमें कोई विदेशीय तत्त्व भी सम्मिलित हो, उचित विधि चुनने के सम्बन्ध में उपस्थित होते हैं । क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि यथार्थ में विधि (Law) है ?

‘राष्ट्रों की विधि’ के विज्ञान के विकास के आरम्भिक काल से ही यह प्रश्न कि क्या ‘अन्तर्राष्ट्रीय विधि’ यथार्थ में विधि है एक विवादास्पद विषय रहा है । क्या हममें बाध्यता की शक्ति है , इस प्रश्न पर विभिन्न सम्मतियाँ हैं । विधिशास्त्र (Jurisprudence) पर प्रमुख अंग्रेजी लेखक जॉन ओस्टिन (John Austin) ने यह प्रतिपादन किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि यथार्थ में विधि नहीं है बल्कि यह आचरण सम्बन्धी नियमों की संहिता है जिनका बल केवल नैतिक है । हाब्स (Hobbes) तथा

पफेन्डोर्फ (Pufendorf) ने भी इस प्रश्न का निपेधात्मक उत्तर दिया है और कहा है कि राष्ट्रों की कोई ऐसी विधि नहीं है जो कि उचित रूप से सच्चे और वैध बल से युक्त हो और अपने से वरिष्ठ की आज्ञा के समान बाधित हो। वाटेल (Vattel) के अनुसार 'राष्ट्रों की विधि' (Law of Nations) मूल में और कुछ नहीं बरद केवल प्रकृति के नियम है जो राष्ट्रों पर लगाये गये हैं। हाल्लैंड (Holland) ने यह समर्थन किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि साधारण विधि से इस बात में भिन्न है कि इसे राज्य की प्राधिकार शक्ति का समर्थन नहीं प्राप्त है। उनके अनुसार यह केवल वैयक्तिक विधि है जिसे विस्मृत रूप में लिख दिया गया है। इस दृष्टिकोण से देखने पर उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को विधि-शास्त्र को लोप करने वाला बिन्दु (vanishing point of Jurisprudence) कह कर वर्णन किया है। बेन्थम (Bentham) ने भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि को उचित रूप से विधि मानने के सम्बन्ध में आपत्ति की है।

इसके विपरीत हाल (Hall) तथा लॉरेन्स (Lawrence) जैसे प्रसिद्ध विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि न केवल विधि के समान कार्य ही करती है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता से अपने नियमों तथा अनुशास्ति दोनों रूपों द्वारा स्पष्टतया पूर्ण रूप से भिन्न है। हाल महोदय यह कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्वभावतः विधि मानी जाती है और जो कुछ इस समय विधि के रूप में स्वीकृत है उसका कुछ भाग प्रकृति से ही उमसे पृथक् नहीं किया जा सकता। लॉरेन्स महोदय इस बात पर विशेष महत्व देते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि साधारणतः राज्यों द्वारा व्यवहृत की जाती है, यद्यपि यत्र-तत्र अन्य विधियों के समान ही इसके भी कुछ भादशों की उपेक्षा की जाती है और यदा-बदा की इस उपेक्षा से हम उसे प्रकृति या अस्तित्वहीनता की सीमा तक नहीं कह सकते।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रश्न को हल करना कानून की उस परिभाषा पर निर्भर करता है, जिसे हम अपना लें।

ऑस्टिन (Austin) का यह मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि कोई विधि ही नहीं है क्योंकि यह किसी ऐसे प्राधिकारी से उत्पन्न नहीं होती जो विधि सृजित करता हो और इसके पीछे कोई अनुशास्ति (sanction) नहीं है। उनका कथन है कि वह विधि जो राष्ट्रों के बीच में मानी जाती है निश्चयात्मक विधि नहीं है क्योंकि प्रत्येक निश्चयात्मक विधि एक संप्रभु द्वारा अपने अधीन राज्य के व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए निर्धारित की जाती है। उनसे अनुसार राष्ट्रों के बीच प्रवर्तित कानून केवल सामान्य सम्मति के आधार पर निर्धारित विधि है और जिन कर्तव्यों को वह आरोपित करता है वह दैविक शक्ति द्वारा लागू किये जाते हैं। कोई अपपूर्वक कार्य बनाने वाली शक्ति जो कि वरिष्ठ मण्ड से प्राप्त हो यही संसन् नहीं है, क्योंकि विवाद करने वाले राष्ट्रों के ऊपर कोई संप्रभु शक्ति नहीं है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को 'निश्चित अन्तर्राष्ट्रीय

नैतिकता' (positive international morality) कहा है जिसमें सम्मतियाँ या भाव जो कि राष्ट्रों के बीच साधारणतः प्रचलित हैं (opinions or sentiments current among nations generally) सम्मिलित हैं ।

हालैंड जैसा कि ऊपर कहा गया है ग्रॉस्टिन की सम्मति से सहमत हैं । उनका कथन है कि ऐसे नियम जो कि स्वेच्छासे, यद्यपि स्वभावतः, प्रत्येक राष्ट्र, अन्य के साथ व्यवहार करने में पालन करते हैं, केवल शिष्टाचार के नाते ही विधि कहे जा सकते हैं—

Such rules as are voluntarily, though habitually, observed by every State in its dealings with the rest can be called law only by courtesy " ये किसी राज्य के प्राधिकार द्वारा समर्थित नहीं होते । उनके अनुसार यह विधि-शास्त्र का लोप-विन्दु है, क्योंकि इसमें किसी सघर्ष की स्थिति में जनता की राय के प्रतिरिक्त अन्य कोई विवाचक नहीं होता ।

लार्ड सैलिसबरी (Lord Salisbury) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि किसी न्यायाधिकरण द्वारा प्रवर्तित नहीं होती, इसलिये उसे साधारण अर्थों में कानून या विधि कहना भ्रमात्मक है ।

भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की गणना सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञों में है । वे भी इसी सम्मति से सहमत हैं । अन्तर्राष्ट्रीय-विधि-परिषद् की भारतीय शाखा की बैठक में जो कि दिल्ली में मार्च ३१ सन् १९५१ को हुई थी, भाषण करने हुये उन्होंने कहा था कि विश्लेषण के द्वारा अन्त में हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कोई अन्तर्राष्ट्रीय विधि नहीं है । किसी प्रकार एकमत होने के लिये उद्योग किया गया था, परन्तु व्यवहारतः दखा गया है कि अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय विधि अथवा उस विषय में कोई विधि इस प्रकार की एक वस्तु हो जाती है जिसमें किसी शक्तिशाली अथवा अधिक शक्ति रखने वाले किसी समुदाय द्वारा शास्ति का प्रवर्तन होने लगता है । उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा कि जब कोई सकट, जैसे कि युद्ध, उत्पन्न होता है तो सब विधियाँ समाप्त हो जाती हैं, और अनुमानतः वे केवल वकीलों के वाद-विवाद का विषय मात्र बनकर रह जाती हैं ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि से कम शास्ति-सूचक तथा कम स्पष्ट है, तथापि यह विधि है । विधि वे पीछे केवल दबाव ही शास्ति नहीं है । इसकी प्रवृत्ति के अन्तर्गत जितना ही अधिक बल महत्वपूर्ण है उतना ही अधिक न्याय भी । इसमें भय की मात्रा भी अनुपस्थित नहीं है । राष्ट्रों को यह भय रहता है कि यदि वे अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के नियमों का प्रकट उल्लंघन करेंगे तो इसका परिणाम उनके लिये अनुचित होगा । साधारण विधि के समान अन्तर्राष्ट्रीय विधि की भी कभी-कभी अपेक्षा की जाती है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि विधि का अस्तित्व ही नहीं है, या विधि सर्वथा प्रकृति तक पहुँच गई है ।

सर हेनरी मेन ने ऑस्टिन के विधि-सम्बन्धी विचारों की समालोचना करते हुये कहा है कि मनुष्य अवश्य कभी-कभी नियमों को दड के भय से मानता है परन्तु प्रत्येक समाज के अधिकांश मनुष्यों के साथ ऐसे मनुष्यों की तुलना करने पर यह प्रकट होता है कि इस श्रेणी के मनुष्यों की संख्या कम होती है और सभ्यत उन्हीं लोगों की श्रेणी तक सीमित है जिन्हें हम अपराधी जाति के कहते हैं। अधिकतर नियमों का पालन मनुष्यों द्वारा अनजान में ही मानसिक स्वभाव के कारण होता है।

स्टार्क (Starke) ने ऑस्टिन (Austin) के सिद्धान्त का निम्नलिखित आधार पर विरोध किया है —

(क) आधुनिक विधि-शास्त्र ने विधि के सामान्य सिद्धान्त को कम कर दिया है। यह देखा जाता है कि बहुत से समुदाय ऐसे होते हैं जहाँ कोई प्राधिकारिक वैध शक्ति नहीं होती, फिर भी विधि की एक रीति प्रचलित रही है, और उसका पालन पूर्ण रूप से होता रहा है और ऐसी विधि की बाध्यता में किसी वैध शक्ति-सम्पन्न राज्य की वैधता में कोई अन्तर नहीं रहा है।

(ख) ऑस्टिन के विचार अने ही उन दिनों ठीक रहे हों, किन्तु उन्हें हम आज की परिस्थितियों में लागू नहीं कर सकते।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्नों को उन लोगों द्वारा सदैव वैय प्रश्नों के रूप में माना गया है जो वैदेशिक पदा 'foreign offices' पर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों को करते रहे हैं।

फिलोवेन के लॉर्ड रसेल (Lord Russel of Killowen) भी इस विचार से सहमत हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन समाजों में भी, जिनमें ऑस्टिन (Austin) द्वारा दिये गये अर्थ के अनुसार विधि बनाने की व्यवस्था उपस्थित है ऐसे नियम और ऐसी रूढ़ियाँ विकसित होती हैं जो यथार्थ में 'विधि' हैं। अधिकांशतः जनमत पर निर्भर रहते हुये ज्यों-ज्यों शासन व्यवस्थाये स्पष्टतया अधिकाधिक लोकतन्त्रात्मक होती जाती हैं त्यों-त्यों विधियाँ क्रूर सत्ता द्वारा प्रतिष्ठापित अनुज्ञाया व रूप को छोड़ती जाती हैं और अधिकतया स्वभावतः स्वीकृति पर निर्भर प्रचलित विधि (customary law) का रूप धारण करती हैं और इस विचार उ उन नियमों के योग का, जिन पर अपना आचरण निर्भर करने के लिये राष्ट्र एक दूसरे के प्रति सहमत हैं उचित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विधि कहा जा सकता है।

आधुनिक लेखक जैसे हॉल और सरिन्स, अन्तर्राष्ट्रीय विधि को यथार्थ विधि मानते हैं। उनसे अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्वभावतः विधि रूप में मानी

तथा प्रवर्तित समझी जाती है । कुछ निश्चित विधियों के समान यह भी रूढ़ि से उत्पन्न हुई है । पूर्ववर्ती दृष्टान्त अन्तर्राष्ट्रीय विधि का भी उतना ही स्रोत माना जाता है जितना कि यह निश्चयात्मक (positive) नियम का और इसके नियमों का पालन करना अनिवार्य है ।

इसके अनन्तर अन्तर्राष्ट्रीय नियम अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा लागू किये जाते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध में अनुशास्ति (sanction) का विचार एक सस्था अर्थात् संयुक्त राष्ट्र-संघ में एक निश्चित रूप ग्रहण कर रहा है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ियों, संधियों और मध्यस्थ निर्णय के करार (agreements) ने कई ऐसे सुनिश्चित सिद्धांतों को जन्म दिया है जो कि राष्ट्रों के प्राकृतिक और पादस्पर्शिक सम्बन्धों में उनके कार्यों को उसी प्रकार सीमित कर देते हैं जिस प्रकार कि इंग्लैंड की विधियाँ उनके नागरिकों के कार्यों को सीमित कर देती हैं ।

प्रोफेसर ओपेनहेम (Professor Oppenheim) विधि को इस प्रकार परिभाषित करते हैं—यह किसी समाज के भीतर मनुष्यों के आचरण के लिये उन नियमों का समूह है जो कि उस समाज की सर्वमान्य सम्मति से एक बाह्य शक्ति द्वारा प्रवर्तित किये जायेंगे—“a body of rules for human conduct within a community which by common consent of this community shall be enforced by external power” इस परिभाषा में विधि के अस्तित्व के लिए निम्नलिखित अभिधारणाएँ मानी गई हैं:—प्रथम एक समुदाय (community), द्वितीय, उनमें मनुष्यों के आचरण के लिए नियमों का एक समूह, तृतीय उन नियमों को एक बाह्य शक्ति द्वारा प्रवर्तित करने के लिए उस समाज की सर्वमान्य सम्मति । ओपेनहेम महोदय का कथन है कि “एक समुदाय कई व्यक्तियों का समूह है जो कि आपसमें ऐसे सर्वमान्य हितों से कुछ न कुछ सम्बद्ध हों जो कि उन प्रत्येक व्यक्तियों के बीच में निरन्तर तथा बहुविध ससर्ग उत्पन्न करते हों ।” इस परिभाषा में ‘समुदाय’ शब्द में केवल व्यक्तिगत मनुष्य द्वारा बना हुआ समाज ही सम्मिलित नहीं है वरन् इसमें व्यक्तिगत समाज के समूह भी सम्मिलित हैं जैसे व्यक्तिगत राष्ट्र । अब राष्ट्रों के कुटुम्ब को अन्तर्राष्ट्रीय समाज समझ लिया जाय जिसमें कि उसके सदस्य राष्ट्रों के आचरण के लिये नियम विकसित हो गये हैं जिनका आधार अथवा रूढ़ियों और अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकार-पत्र (करार) जैसे पेरिस की उद्घोषणा, १८६४, (Declaration of Paris, 1856) भूमि-युद्ध सम्बन्धी हेग अभिसमय १८६६ और १९०७ (Hague Conventions relating to Land Warfare, 1899 and 1907), पेरिस की सन्धि, १९२८ (Pact of Paris, 1928) तथा संयुक्त राष्ट्रों का अधिकार-पत्र १९४५ (Charter of the United Nations, 1945) हैं । इन नियमों के प्रवर्तन की अनुशास्ति अन्त-

राष्ट्रीय समाज की सहमति द्वारा दी गई है। सुरक्षा परिषद् (Security Council) को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह वायु, जल तथा स्थल सेना से ऐसा कार्य ले जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने अथवा पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक हो; और इस प्रयोजन के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे सुरक्षा-परिषद् की माँग पर सेना, सहायता तथा सुविधायें, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये उपस्थित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कर्त्तव्य है कि वह आक्रमण तथा शांति-भङ्ग के विरुद्ध प्रभावकारी सामूहिक शक्ति का उपयोग करे।

सुरक्षा-परिषद् के जून २७ और जुलाई ७, १९५०, के प्रस्तावों से जिनके द्वारा यह संस्तुति की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य गणतन्त्र कोरिया को ऐसी सहायता दे जो कि सशस्त्र आक्रमण को पीछे हटाने के उपयुक्त हो और वे उस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को पुनः स्थापित करें, और यह कि सभी सदस्य-राष्ट्र अपनी सहायता एवं सेना संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौमिक नियन्त्रण में कोरिया की सहायता हेतु प्रस्तुत करें; विश्व के इतिहास में सबसे पहला एक दृष्टान्त उपस्थित हुआ जिसमें किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने सामूहिक सैनिक कार्यवाही का प्रयोग किया था। इस दृष्टान्त ने सर्वप्रथम इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण उपस्थित किया कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में अपने सही अर्थों में विधि है।

इस अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रवर्तन भी ठीक निर्मित और निश्चयात्मक विधि के रूप में किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने १६ राष्ट्रों द्वारा दी गई सैनिक सहायता का कोरिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से नेतृत्व किया और ४० राष्ट्रों ने इसी प्रसंग में आर्थिक सहायता पहुँचायी। यही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने १२ दिसम्बर १९५० को अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ियों का खंडन करने वाले व्यक्तियों को दंड निर्धारित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) की स्थापना की भी सहमति दे दी, और १७ राष्ट्रों की समिति ने इसके प्रारूप को तैयार किया जो कि आगे चलकर १९५३ में पुन. 'इंटरनेशनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन' अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक क्षेत्राधिकार की समिति की बैठक के समय पुनः परिशोधित किया गया।

इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रों के बीच ऐसी अनेक घटनाएँ घटी हैं, और आज भी घट रही हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा प्रवर्तित विधियों को पूर्ण रूप से निश्चयात्मक विधि के रूप में माना गया है।

इस विषय पर स्टीमशिप प्रोमैथ्यूस (S. S. Prometheus) में विचार किया गया। सर हेनरी बर्कले, प्रधान न्यायाधीश, ने कहा, "भेरी सम्मति में विधि स्थापित

की जा सकती है और वह अन्तर्राष्ट्रीय हो सकती है, अर्थात् सब राष्ट्रों पर बाध्य हो सकती है, यदि वे राष्ट्र जो अपने को उससे बाध्य करना चाहें आपस में सहमत हो, यद्यपि उसकी आज्ञा का पालन कराना किसी राष्ट्र द्वारा जो कि उस स्वीकारपत्र पर पक्षकार रहा हो सम्भव न होगा। किसी राष्ट्र का अवरोध उस विधि के लिए जिसके लिये कि वह सहमत हो गया है विधि की अधिकार शक्ति को लघु नहीं करता क्योंकि वह अवरोध सम्भवतः विजित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का अवरोध केवल उस अवरोधक राष्ट्र को उस विधि का भगकर्ता बनाता है जिसके लिए वह अपनी मान्यता प्रदान कर चुका था, पर वह विधि जिसके स्थापित करने में अवरोध करने वाला राष्ट्र पक्षकार रहा है, उसी प्रकार बनी रहती है। क्या यह सफलतापूर्वक प्रतिपादित किया जा सकता है कि चूंकि कोई मान्य व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह तत्समय के लिये किसी स्थापित नागरिक विधि को अवरोध करने की शक्ति रखे तो ऐसी दशा में विधि का अस्तित्व ही नहीं है ? इस प्रतिपादन का उत्तर यही होगा कि विधि का अब भी अस्तित्व है भले ही तत्समय इसकी आज्ञापालन का प्रवर्तन कराना सम्भव न हो।

जे० एल० ब्रायरले (J. L. Brierly) के मतानुसार "किसी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय विधि का अस्तित्व केवल इस बात का अवश्यभावी परिणाम है कि इस संसार में बहुत से राष्ट्र हैं और वे अनिवार्यतः एक दूसरे के सम्बन्ध में आते हैं और एक साथ रहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अस्तित्व का सर्वोत्तम साक्ष्य यह है कि प्रत्येक राष्ट्र, जो वास्तव में अस्तित्व रखता है यह मानता है कि इसका (अन्तर्राष्ट्रीय विधि का) अस्तित्व है, और वह अपने को इसके पालन के लिए बाध्य समझता है। राष्ट्र बहुधा अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उत्सर्जन कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार जैसे कि व्यक्ति बहुधा नागरिक विधियों का उत्सर्जन करते हैं। परन्तु वे भी अपनी प्रति-रक्षा इस आधार पर नहीं करते कि वे कानून के बन्धन से परे हैं।"

इस प्रसंग में सर फ्रेडरिक पोलॉक (Sir Frederick Pollock) का निम्न-लिखित कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है —

"यदि अन्तर्राष्ट्रीय विधि केवल एक प्रकार की नैतिकता होती तो राज्य की वैदेशिक नीति को बनाने वाले लोगों ने अपने तर्क बहुधा नैतिकता पर ही आधारित रखे होते। बल्कि वास्तव में वे ऐसा नहीं करते।" (They appeal not to the general feeling of moral rightness, but to precedents, to treaties, and to opinions of specialists. They assume the existence among statesmen and publicists of a series of legal as distinguished from moral obligations in the affairs of nations)—Pollock, Oxford Lectures, 1890, p. 18). अर्थात् वे किसी भी धर्म के लिए नैतिकता की सामान्य



भावनाओं का सहारा नहीं लेते बल्कि राष्ट्रों के प्रसंग में पूर्व दृष्टान्तों, सविय और विशेषज्ञों की सम्मतियों का आश्रय ग्रहण करते हैं ।

सर सेसिल हर्स्ट (Sir Cecil Hurst) का भी कहना है कि कोई राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विधि की अधीनता से परे नहीं हो सकता—“A state cannot escape from subjection to International Law .”

पुनः ओपेनहेम के शब्दों में—“विज्ञान और कला ने जो कि स्वभावतः अधिक सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय हैं, भिन्न-भिन्न राज्यों की प्रजाओं के बीच विचारों तथा सम्मतियों का निरन्तर आदान-प्रदान स्थापित कर दिया है । इनमें सबसे अधिक महत्त्व के कृषि-उद्योग और विशेषतः व्यापार हैं । यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ही था जिसने कि भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के मध्य से प्रवाहित होने वाले महासागरी तथा नदियों पर यातायात स्थापित कर दिया । सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा मानवीय हितों ने अन्तर्राष्ट्रीय एकाकरण तथा संगठन की भाग का है । लीग ऑफ नेशन्स (राष्ट्रसंघ), संयुक्त राष्ट्र सभ और अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के स्थायी समूहों तथा समस्याओं के अतिरिक्त बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय और अन्तर्राष्ट्रीय आयोग (कमीशन) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकाशन के लिए स्थापित कर दिये गये हैं और हेग में एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित कर दिया गया है । यद्यपि राज्य व्यक्तिगत रूप से सार्वभौम सत्ता रखते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और उनके ऊपर कोई अन्तर्राष्ट्रीय शासन नहीं है तथापि उन्हें एकता के सूत्र में बाँधने वाले कुछ समान हित अवश्य हैं जिनमें वे बँधे रहते हैं ।”

यह बात सत्य है कि फंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब कोई संकट जैसे युद्ध, उपस्थित होता है, सब विधियाँ समाप्त हो जाती हैं और अनुमानतः वे केवल वकीलों के वाद-विवाद में रह जाती हैं । ओपेनहेम ने इस विषय पर समुचित प्रकाश डाला है । उनका कथन है कि “अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उत्लघन अवश्यमेव प्रायः किया जाता है, विशेषतः युद्ध के बीच में । परन्तु अपराधी सर्वदा यह सिद्ध करने का यत्न करते हैं कि उनके कार्य उत्लघन की सीमा तक नहीं पहुँचते, और उनको राज्यों की विधि द्वारा इस प्रकार कार्य करने का अधिकार है, अथवा राज्यों की विधि का कोई नियम उनके कार्यों के विरुद्ध नहीं जाता । वास्तव में यह बात है कि राज्य जब ‘राष्ट्रों की विधि’ को भग्न करते हैं तो वे इसके अस्तित्व को कभी अस्वीकार नहीं करते, बल्कि वे ‘राष्ट्रों की विधि’ की इस प्रकार व्याख्या करने का प्रयास करते हैं कि जिससे उनका आचरण न्याय्य ठहरे और ऐसा करने में उसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का पुनः-पुनः उत्लघन इसके वैध प्रभाव को प्रायः गमाता हो कर देता है तथापि यह साधारणतः बहुधा चिढ़ पैदा करने वाला—कथन है कि इसका प्रभाव बाध्यात्मक है, निरर्थक नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के दोष—इसमें सन्देह नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि एक कमजोर विधि है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधान-व्यवस्था ऐसी शक्ति-सम्पन्न नहीं है जैसी कि किसी राज्य की विधान-व्यवस्था हुआ करती है। नियमित अर्थ में अन्तर्राष्ट्रीय-विधि का न तो कोई विधान-मंडल है और न कोई अधिशासीवर्ग। अन्तर्राष्ट्रीय न्याया-लय जो कि इसके न्यायाधिकारी वर्ग का प्रतिनिधि स्वरूप है, का न तो कोई ऐसा अधि-कार-क्षेत्र है जो सम्पूर्ण विश्व में प्रभावशाली हो और न उसके निर्णय ही राष्ट्रों के बीच के झगड़ों को पूर्णरूप से निपटाने के लिए निश्चित मान जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि कोई अन्तर्राष्ट्रीय विधान-मंडल की बनाई हुई विधि नहीं है बल्कि यह उन रूढ़ियों का समूह है जिनको सम्य राष्ट्रों ने अपने एक दूसरे से व्यवहार में पालन करने के लिए स्वीकार कर लिया है। पिट कॉबेट (Pitt Cobbett) महोदय ने तो यहाँ तक लिखा है कि "It is not only less imperative and less explicit than State Law, but it also lacks the coercive force of State Law." अर्थात् यह राज्यों द्वारा निमित्त विधियों से केवल कम प्रभावकारी या बाधित ही नहीं है बल्कि यह राज्य-निमित्त विधि की अवपीडक शक्ति (coercive force) में भी पीछे रह जाती है। पेटन साहब के कथनानुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि सम्बन्धी पक्ष बहुत ही बलहीन है—कोई विधान-मंडल नहीं है और यद्यपि एक न्यायालय वर्तमान है तथापि यह पक्षकारों की सम्मति से ही कार्य कर सकता है और इसमें अपने निर्णयों के प्रवर्तन की वास्तविक शक्ति नहीं है। यह बात सत्य है कि शान्ति के समय अन्तर्राष्ट्रीय विधि कदाचित् ही भग की जाती हो। परन्तु ज्योंही गंभीर स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं हम देखते हैं कि स्वीकृत नियमों की स्पष्ट रूप से उपेक्षा की जाने लगती है। सत्कार का लोचमत् एव ऐसा विषय हो सकता है जिसकी हम सहज ही उपेक्षा न कर सकें। तथापि किसी नियम भग करने वाले राष्ट्र से व्यवहार करना एक असम्भ पुष्ट को उसके समुदाय से बहिष्कृत करने से ही कहीं अधिक कठिन है। अतः यद्यपि आदिकालीन तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि दोनों में विधि सम्बन्धी व्यवस्था का अभाव है तथापि आदिकालीन विधि की अनुशास्तियाँ वस्तुतः अधिक प्रभावपूर्ण होती हैं क्योंकि ये व्यक्ति पर प्रवर्तित की जाती हैं न कि राष्ट्र पर। अन्तर्राष्ट्रीय विधि की बलहीनता प्रवान न्यायाधीश लार्ड कॉलरिज (Lord Coleridge) द्वारा भी फ्रैंकोनिया विवाद (R. v. Keyn : The Franconia) में इस प्रकार उल्लिखित की गई है :

"अपने कथन को नियमित करने पर 'अन्तर्राष्ट्रीय विधि' एक यथार्थरहित कथन हो जाता है और यदि हम इसकी निर्मूलता को ध्यान में न रखें तो हम धोखे में पड़ सकते हैं। 'विधि' शब्द से विधि का दाता और एक न्यायाधिकरण जो कि

इसे प्रवृत्त कराने तथा इसके उल्लंघन करने वालों को दंडित करने में समर्थ हो, लक्षित होते हैं। सप्रभु राष्ट्रों के लिये न तो कोई समान विधि का दाता है और न कोई ऐसा न्यायाधिकरण है जो ऐसी शक्ति रखता हो कि अपनी डिगरियों द्वारा उन्हें बाध्य कर सके, या यदि कोई उल्लंघन करे तो उसे दंडित कर सके। राष्ट्रों की विधि उन रूढ़ियों का समूह है जिसको सभ्य राष्ट्रों ने अपने एक दूसरे के प्रति व्यवहारों में पालन करना स्वीकार कर लिया है। ये रूढ़ियाँ क्या हैं अथवा कोई विशेष प्रथा स्वीकृत की गई है या नहीं यह साक्ष्य का विषय होना चाहिए। सन्धियों तथा राष्ट्र के अधिनियम कवल राष्ट्रों की स्वीकृति के साक्ष्य हैं और कम से कम इस देश में स्वयं न्यायाधिकरणों पर बाध्य नहीं हैं।”

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विधि की निर्बलता इस बात से भी प्रकट होती है कि यह “राष्ट्रों के कुटुम्ब” को अथवा उसके अनुकूल किसी अन्तर्राष्ट्रीय सघ को उन विषयों में हस्तक्षेप करने को अधिकृत नहीं करती जो कि प्रथमतः किसी राष्ट्र के घरेलू क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हो और इस प्रकार इसका अधिकार क्षेत्र तथा प्रभाव सीमित हो जाता है। संयुक्तराष्ट्र-सघ को अन्तर्राष्ट्रीय विधि अधिशासन करने वाली सर्वोच्च सस्था के रूप में अधिकार होना चाहिये कि वह किसी राज्य के घरेलू अधिकार क्षेत्र में भी उस दशा में हस्तक्षेप कर सके जबकि कोई राज्य ऐसी बातों का उल्लंघन करे जिससे मनुष्य का गौरव न्यून होता हो अथवा उसकी सामाजिक स्थिति के घटने की संभावना हो। इसके पश्चात् बहुत से विषय जैसे शुल्कदर (tariffs), अधिदान (bounties), व्यापार और बाजार इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय विधि की सीमा के बाहर पड़ते हैं और इसके स्वाभाविक कार्यों में रुकावट डालते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त कुछ लोग, राज्यों की राष्ट्रीयता की प्रबल भावना के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय विधि को स्वीकार करने को अब भी उद्यत नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि की असफलता का कारण विशेषतः यह भी है कि मनुष्य तथा राष्ट्रों में, जिनके विचार अभी प्रादेशिक हैं एक अन्तर्राष्ट्रीय नमूने का जीवन साधने का प्रयत्न किया जा रहा है। स्वर्जन्बर्गर (Schwarzenberger) महोदय का कथन है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीनस्थ लोग अत्यधिक स्वार्थ-केन्द्रित हैं और अन्तर्राष्ट्रीय समाज को कर्तव्यों को सोचने के लिए वे उद्यत नहीं हैं, या वे उनको उचित रूप से पालन करने में समर्थ न हैं। उनका अन्त में अपनी ही शक्ति पर निर्भर रहना एक सर्वांगीण अथवा प्रभावशाली वैध व्यवस्था (legal system) के विनाश के लिए बाधक है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का नया झुकाव (New Trend in International Law)—एक नई अन्तर्राष्ट्रीय विधि तीव्रता से विकसित हो रही है। इसकी

जीव १९वीं शताब्दी के मध्य से पड़ी। इस काल को हम एक दूसरे पर आघित रहने की प्रवृत्ति का काल कह सकते हैं। इस सुझाव की स्थिति की बहुत ही उप-युक्त व्याख्या अल्वरेज (M Alvarez) महोदय द्वारा की गई है। यह व्याख्या उन्होंने अपने मतभेद जो कि 'Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the United Nations' 'किमी राज्य को संयुक्त राष्ट्रों में प्रविष्टि के संबंध में साधारण सभा के सामर्थ्य' में प्रकट किया था, में की गई है। उनका कथन है—

'पहले विधि के नियम हड़ स्थापित अभिसमय (conventions) तथा रूढ़ियों (customs) के अनुसार धीरे-धीरे विकसित किये गये अथवा ये नियम विधिकुशलो (jurists) द्वारा धीरे-धीरे विकसित किये गये। आजकल सामाजिक उलट-फेर के कारण जिसको हमने अभी पार किया है तथा लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तनशीलता के कारण तथा नये अन्तर्राष्ट्रीय सघ तथा उसके द्वारा बनायी गई संस्थाओं और उनके अगो के कारण और अन्त में लोगों की आकांक्षायें तथा आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के कारण इन नियमों का विस्तार तीव्र गति से किया जा रहा है तथा कभी-कभी यह आकस्मिक भी हो जाता है। इस विस्तार के साधन पूर्ववालीन साधनों से भिन्न हैं और इस रीति में वे कारण जिनका कि हमने अभी उल्लेख किया है अपना प्रभाव डालते हैं।

"यह साधारण सम्मति कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि केवल राज्यों द्वारा ही बनाई जानी चाहिये, आज वैध नहीं है और न यह कभी वैध रही है।" उन्हीं के शब्दों में—  
"The common view that the International Law must be created solely by States is, therefore, not valid to-day—nor indeed has it ever been."

"वास्तव में अभिसमयात्मक विधि (conventional law) के साथ-साथ रूढ़ि विधि (customary law) भी है और इन सब के ऊपर उन विधि-वेत्ताओं के सिद्धान्त हैं, जिनको न केवल रूढ़ियों वे ही प्रतिपादन का अवसर है बल्कि जिन्होंने वे नियम बनाये हैं जिनको राष्ट्रों ने मान्यता दी है।

"अविषय में नये अन्तर्राष्ट्रीय विधि के लिये हम किसी और से अधिक संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा विधि-वेत्ताओं की ओर देखेंगे।"

## अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार

(Basis of International Law)

परम्परा से दो प्रतिद्वन्द्वी सिद्धान्त हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के आधार की विवेचना करते हैं। ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :—

(१) मूल अधिकारों का सिद्धान्त (Theory of Fundamental Rights)—ब्रायली (Brierly) का कथन है कि मूल अधिकारों का सिद्धान्त प्राकृतिक अवस्था (state of nature) के सिद्धान्त के साम्य में है। इस सिद्धान्त में स्वीकार किया गया है कि मनुष्य बिना किसी राजनीतिक समुदाय या राज्य के निर्माण के पूर्व भी भलीभाँति जीवन-निर्वाह किया करता था और उस समय भी मनुष्य की यही स्थिति थी जब कि राज्यों के ऊपर किसी बड़े राज्य की कल्पना नहीं की गई थी। अतः प्रत्येक राज्य के स्वरूप में कुछ मूल, जन्मजात या प्राकृतिक अधिकार हुआ करते हैं—जैसे आत्म-रक्षा, स्वतन्त्रता, समानता, सम्मान और पारस्परिक सम्बन्ध।

ब्रायली ने इस सिद्धान्त पर निम्नलिखित आधार पर अभ्याक्रमण किया है :—

(क) इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि मनुष्य या राज्य समाज में अपने साथ कुछ स्वामाधिक अधिकार लेकर उत्पन्न होते हैं, जो कि समाज की सदस्यता के कारण उन्हें नहीं प्राप्त होते अपितु वे अधिकार उनके व्यक्तित्व में निहित होते हैं और इन्हीं अधिकारों के द्वारा एक वैध व्यवस्था का निर्माण होता है; जब कि सत्य यह है कि वैध अधिकार (legal right) या वैध-व्यवस्था उस समय तक एक अर्थहीन शब्द है जब तक कि हम पहले उस वैध-व्यवस्था के अस्तित्व की कल्पना न कर ले जहाँ से इन्हीं वैधता प्राप्त होती है।

(ख) राज्यों के समाज में व्यक्ति-राज्य की स्वतन्त्रता की उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी कि उनमें एक सामाजिक संबंध को मजबूत करने की आवश्यकता है।

(ग) यह सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अस्तित्व ही समाप्त कर देता है, क्योंकि इसक अन्तर्गत राज्यों की प्रकृति में ही स्वतन्त्रता की कल्पना की जाती है और इस बात की अवज्ञा हो जाती है कि राज्यों का मिलन केवल ऐतिहासिक विकास की अवस्था का परिणाम है।

(२) सहमति सिद्धान्त (Consent Theory)—प्रोफेसर हेम कुछ अन्य विधि-वेत्ताओं के विचारों के अनुकूल यह विचार प्रकट करते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के रुढ़ि नियम राष्ट्रों की सहमति से विकसित हुए हैं अर्थात् भिन्न-भिन्न राज्यों ने इस रूप में कार्य किया है कि उससे उनकी प्रकट सहमति इन नियमों के तत्वे प्रकट होती है। वे कहते हैं कि नये राज्य जिनका जन्म हुआ और जो प्रकट प्रथा परोक्ष रूप से स्वीकृति द्वारा राष्ट्रों के मुद्रुम्न में प्रविष्ट किये गये उन्होंने अपने प्रदेश के समग्र अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के समूह की स्वीकृति कर लिया।

राज्यों की समान सहमति पर स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर कई कारणों से अभ्यासक्रमण हो सकता है। सर्वप्रथम जैसा कि फेनविक (Fenwick) महोदय ने कहा है कि यह सिद्धान्त उन सहमतियों की विवेचना के लिये पर्याप्त नहीं है जिन पर कि सरकारें अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आरम्भ से ही कार्य करती हुई प्रतीत होती हैं। लेखको ने चाहे किसी भी स्थिति स्वीकार की हो, लेकिन सरकारों ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि को सर्वदा बाह्य विषयक प्रकृति के रूप में देखा है और इसे बाध्य इसलिए स्वीकृत किया है कि यह 'विधि' थी; उन्होंने इसलिए नहीं स्वीकार किया कि इसके पालन करने में उन्हें सुविधा मिली।

दूसरा यह कि समान सहमति का सिद्धान्त वास्तविक सहमति को एक प्रकार की कल्पना पर स्थित है। केलसन (Kelsen) महोदय का कथन है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि से अपनी इच्छा के बिना या अपनी इच्छा के विरुद्ध भी बाध्य हैं। उदाहरण के लिए ज्यों ही किसी नये राज्य का जन्म होता है त्यों ही उसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा नियत सब अधिकार तथा कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं और उस राज्य के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्वीकृतसूचक कोई कार्य करे। जिस प्रकार एक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी राज्य की विधि के अधीन नहीं होता, वह तो उसकी इच्छा के न रहते हुए भी, उसकी इच्छा के विरुद्ध, उस पर बाध्य हो जाती है उसी प्रकार राज्य भी स्वेच्छापूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन नहीं होता, वह तो उस पर स्वयम् बाध्य हो जाती है, चाहे वह उसको स्वीकार करे अथवा नहीं।

तीसरा यह तर्क है कि किसी राज्य की जिसे मान्यता दी गई है प्रकट अथवा परोक्ष स्वीकृति द्वारा राष्ट्रों के कुटुम्ब में प्रवेश करना यह व्यक्त करता है कि उस राज्य ने उस समय के प्रवर्तित सब नियमों के अधीन रहना स्वीकार कर लिया है, भ्रमोत्पादक है। कारण स्पष्ट है कि "मान्यता प्रदान करने का कार्य अन्य राज्यों का कार्य है न कि उस राज्य का जिसे मान्यता प्रदान की जा रही है।" मान्यता के प्रदान करने में राजनीति तथा राजनैतिक आवश्यकता का विचार अन्य बातों से अधिक प्रबल रहता है और इन्हीं के आधार पर यह प्रदत्त की जाती है। मान्यता-प्रदत्त राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की अन्य राष्ट्रों द्वारा नियमानुसार स्वीकृति यह प्रबल नहीं करती कि उस राष्ट्र ने सहमति दे दी है।

चौथा तर्क यह कि जैसा कि स्टार्क (Stark) महोदय ने कहा है "प्रयोग में जब कभी अन्तर्राष्ट्रीय विधि का कोई विशिष्ट नियम विशिष्ट राज्य के विरुद्ध लगाये जाने की मांग की जाती है तो यह आवश्यक नहीं होता कि यह दिखलाना पड़े

कि उस राज्य ने उस नियम को राजनैतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। परीक्षण करने की कसौटी यह है कि क्या वह नियम एक ऐसा नियम है जिसे राष्ट्रों के समाज ने साधारणतः स्वीकृत कर लिया है ?" स्मिथ (Smith) महोदय के शब्दों में "अन्तर्राष्ट्रीय विधि रूप से सब सम्य राज्यो पर उनकी व्यक्तिगत स्वीकृति की अपेक्षा बिना ही बाधित है।" ("International Law as a whole is binding upon all civilised states irrespective of their individual consent. No state can by its own act release itself from the obligation either of the general law or of any well-established rule.")

अन्तिम रूप में ब्रायली के शब्दों में कहा जाता है कि सहमति के द्वारा आभार नहीं उत्पन्न किये जा सकते, यह वेदल वहाँ तक बाध्य हो सकते हैं, जहाँ तक कि पक्षकार ने संधि या संबिदा के रूप में अपनी बाध्यता की सहमति प्रकट की है।

**वास्तविक आधार :—**अन्तर्राष्ट्रीय विधि का वास्तविक आधार जैसा कि ऊपर लिखा गया है यह है कि ससार की वर्तमान घटनाओं की स्थिति में जब कि राजनैतिक विचारों, कला, साहित्य तथा वैज्ञानिक आविष्कारों में अत्यधिक उन्नति हो गई है, कोई आधुनिक राज्य सबसे सम्बन्ध-विच्छेद करके अलग जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। यातायात के साधनों में असाधारण उन्नति तथा स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के स्थापित होने के कारण सारा विश्व एक कुटुम्ब के रूप में बँध गया है ; और इस पृथ्वी के किसी कोने में होने वाली घटना का प्रभाव ससार के दूसरे भागों में अवश्य पड़ता है। इसका परिणाम सर सिसिल हर्स्ट (Sir Cecil Hurst) महोदय के कथनानुसार यह होता है कि कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन से मुक्त नहीं हो सकता। इसी बात को कुछ भेद से हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि राज्यों पर बाधित इसलिए है कि वे राज्य हैं। बदाबिज यह एक विचित्र स्थिति नहीं है जिस पर कि हम पहुँच जाते हैं, क्योंकि यह स्मरण रखना चाहिये कि राज्य के बारे में हमारी आधुनिक धारणा ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि की उत्पत्ति को हुई है और वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के ही नियम हैं जिनके द्वारा राज्यों के अधिकार तथा कर्तव्य परिभाषित किये जाते हैं।

## अध्याय २

### अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत

#### (Sources of International Law)

सारेन्स के अनुसार यदि हम विधि के स्रोत का अर्थ विधि के आरंभ से लें और उसे संपूर्ण बाध्यता की दृष्टि से प्राधिकृत मानें तो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में विधि का केवल एक ही स्रोत है और वह है राष्ट्रों की सहमति। यह सहमति या तो प्रकट हो सकती है अथवा परोक्ष। सहमति रूढ़ि द्वारा व्यक्त होती है अर्थात् आचरण के कुछ नियत नियम ऐसे हैं जिनको राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में स्वभावतः प्रयोग करते हैं, भले ही उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने को प्रतिज्ञा द्वारा दृष्टि में धारण न किया हो। प्रकट सहमति सन्धियों द्वारा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रलेखों (international documents) द्वारा जिनका प्रभाव सन्धियों के ही समान होता है दी जाती है। परोक्ष सहमति अन्तर्राष्ट्रीय आचरण में सन्निहित होती है।

विधि के स्रोत के सम्बन्ध में ओपेनहेम महोदय की सम्मति भी वही है जो सारेन्स महोदय की है। वह कहते हैं कि कोई राज्य ठीक एक व्यक्ति के समान अपनी सहमति या तो सीधे प्रकट रूप में घोषणा द्वारा व्यक्त कर सकता है अथवा अप्रकट रूप में ऐसे आचरण द्वारा जिसे कि वह यदि सहमत न होता तो न करता। अतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत निम्नलिखित दो हैं :—

(१) प्रकट सहमति—यह उस अवस्था में दी जाती है जब कि राज्यों के बीच में कोई सन्धि होती है जिसमें पक्षकारों के भविष्य में आचरण सम्बन्धी कुछ नियम निर्धारित किये जाते हैं।

(२) परोक्ष सहमति—अर्थात् उपलक्षित सहमति अथवा आचरण द्वारा सहमति। यह उस दशा में दी जाती है जब राज्य अन्तर्राष्ट्रीय आचरण सम्बन्धी कुछ नियमों के अधीन रहने की रूढ़ि को अंगीकार कर लेते हैं।

ओपेनहेम महोदय के मतानुसार राज्यों की विधि के स्रोत केवल सन्धियाँ (treaties) तथा रूढ़ियाँ (customs) ही मानी जानी चाहिये।

प्रोफेसर ब्रायरले (Brierly) रूढ़ियों तथा युक्तियों (reasons) को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत बताते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (संयुक्तराष्ट्र मंडल के अधिपत्य द्वारा स्थापित) की सविधि के अनुच्छेद ३८ (१) में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है :—



१. अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (international conventions) चाहे सामान्य हो अथवा विशिष्ट; किन्तु जिनके द्वारा वे नियम स्थापित किये जायें उनको प्रतिस्पर्धी राज्यों ने प्रकट रूप से स्वीकर कर लिया हो ( वे शुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप हैं ) ।

२. अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ियाँ (international customs) विधि के समान स्वीकृत सामान्य रीति के साक्ष्य के रूप में ।

३. सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धान्त ।

४. अनुच्छेद ५६ के उपबन्धों के अधीन न्यायिक निर्णय और भिन्न-भिन्न राज्यों के उत्कृष्ट योग्यता वाले लेख-कुशलों की शिक्षाये, विधि के नियमों के निर्धारण करने के लिये सहायक साधनों के रूप में ।

अनुच्छेद ५६ में यह उपबन्धित है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय पक्षकारों के मध्य में तथा किसी विशिष्ट मामले में ही बाध्यकारी प्रभाव रखता है, इनको छोड़कर और किसी में नहीं ।

उपर्युक्त कथन के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्य स्रोत जिनका कि उल्लेख किया जा सकता है वे यह हैं :—

अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार, संधियों के अतिरिक्त राज्यों के प्रलेख (documents), राज्यों के अपने पदाधिकारियों तथा न्यायाधिकरणों के मार्गप्रदर्शन के लिए प्रादेश, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रस्ताव, पार्लियामेंटों के नागरिक अधिनियम, नागरिक न्यायालयों के निर्णय और न्याय-परामर्शदाताओं या सिद्धान्त-विषयक पुस्तक-लेखकों की सम्मतियाँ ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मुख्य स्रोत की यथाक्रम गणना के उपरान्त यह उचित होगा कि उनमें से प्रत्येक की कुछ विस्तारपूर्वक व्याख्या कर ली जाय ।

१. सन्धियाँ (Treaties)—ये अन्तर्राष्ट्रीय विधि की सबसे मुख्य स्रोत हैं । अन्तर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में, एक राज्य के भीतरी विधान-मंडलों के समान, कोई ऐसा विधायी अंग नहीं है जिसके बनाये अधिनियम सब राष्ट्रों पर बाध्य हो सकें । तथापि पक्षकार सन्धि द्वारा सविदा करके कोई ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित कर सकते हैं और उसे प्राधिकृत कर सकते हैं कि उसके प्रस्ताव उन पर बाध्य हों अथवा वे अपने पारस्परिक आचरण के लिये नियम भी निर्धारित कर सकते हैं । इस अर्थ में बहुपक्षी सन्धियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधान के लिये एक बहुत ही दुर्बल साधन हैं ।

सन्धियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है — (१) विधि-विधायक सन्धियाँ जो ऐसे सामान्य नियम निर्धारित करती हैं जो राज्यों पर बाध्य

होते हैं अथवा राज्यों को भविष्य में मार्गदर्शन के लिये या उनके भावी अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के लिये नये सामान्य नियम घोषित करती हैं ।

(२) सन्धि संविदाये जो सविदा करने वाले राज्यों के बीच किसी विशेष विषय का ही निपटारा करती हैं ।

केवल विधि निर्मित करने वाली सन्धियाँ ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि की स्रोत हैं और अन्य प्रकार की द्विपक्षी सन्धियाँ नहीं ।

विधि निर्मित करने वाली सन्धि में स्पष्ट रूप से दो भिन्न क्रियायें होती हैं :—

(अ) एक वैधानिक कार्य जिसके द्वारा नियम निर्धारित किये जाते हैं; और

(आ) उन नियमों के अनुरूप कार्य करने के सविदाकर्ता पक्षकारों के बचन ।

विधि निर्मित करने वाली सन्धियों के उदाहरण निम्नलिखित हैं :—

(क) भिन्न-भिन्न शान्ति-सन्धियाँ, उदाहरणार्थ वेस्टफेलिया की सन्धि (१६४८), पेरिस की सन्धि (१८१५) और वर्सलोज की सन्धि (१९१९); जिन्होंने वैधानिक चार्टर को जन्म दिया ।

(ख) पेरिस की घोषणा (१८५६), जेनेवा कन्वेंशन, १८६४, १९०६, १९२९ और १९४९, स्वेज नहर की प्रतिज्ञा, (१८८८), हेग कन्वेंशन १८६९ तथा १९०७, सीग्राफ नेशन का प्रसविदा (१९२०), पोत-बालन योग्य जल-मार्ग तथा सक्रमण स्वतन्त्रता सम्बन्धी बार्सिलोना की प्रतिज्ञाये (१९२१), केलोग-ब्रिग्गाउन्ड पैक्ट (१९२८), मुद्र-स्पागार्थ सामान्य सन्धि तथा स्ट्रेट्स सम्बन्धी मैट्रो प्रतिज्ञायें (१९३६) तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का शासपत्र (Charter) (१९४५); जो कि शुद्ध रूप में विधि निर्मित करने वाली संधियाँ हैं ।

इस विषय में कोई सन्देह नहीं है कि सन्धि की शर्तें अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ि विधि के नियमों से बड़ी अधिक मान्य हैं । रूढ़ि विधि के नियम संधि की शर्तों की तुलना नहीं कर सकते हैं । यह बात विम्बेडन (S. S. Wimbledon) सम्बन्धी निर्णय में स्वीकार की गई है । उस निर्णय में अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने यह राय प्रकट की है कि रूढ़ि-विहित विधि के आगे सन्धिविहित विधि की प्रधानता है ।

२. रूढ़ियाँ (Customs)—ये विधि के प्राचीन और मौलिक स्रोत हैं, यद्यपि गत शताब्दी के मध्यसे रूढ़ियों ने अपनी प्रधानता अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के समक्ष खो दी है । ऐसी दशा में भी ये अन्तर्राष्ट्रीय विधि के द्वितीय मुख्य स्रोत उस सीमा तक हैं जहाँ तक कि ये विधि रूप में स्वीकृत किसी सामान्य रीति के साक्ष्य हों । सन्धियों की व्याख्या में जो सदिग्धतावस्था में रूढ़ियों का बहुधा निर्देश किया जाता

है। रूढ़ियाँ इस प्रकार के नियम सदृश हैं जो कि एक दीर्घकालीन ऐतिहासिक क्रम के उपरान्त विकसित हुए हैं और जिनको अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय समाज ने स्वीकार करके विधि का स्थान दिया है।

**रूढ़ि तथा प्रथा ( Custom and Usage )**—दो शब्द 'रूढ़ि' तथा 'प्रथा' प्रायः एक दूसरे के बदले प्रयोग में लाये जाते हैं परन्तु इन दोनों के बीच एक स्पष्ट पारिभाषिक अन्तर है। जिस प्रकार प्रातः सूर्योदय से पहिले का धुंधला प्रकाश दिन के प्रकाश में तथा सन्ध्या का धुंधला प्रकाश रात्रि के अन्धकार में विलीन हो जाता है उसी प्रकार प्रथा रूढ़ि में विलीन हो जाती है। प्रथा का अन्त रूढ़ि का आरम्भ है। प्रथा अन्तर्राष्ट्रीय आचरण की एक प्रकृति है जिसे अन्तः पूर्णवैध साक्ष्यकन या प्रमाणन (attestation) न मिला हो। प्रथाये परस्पर विरोधी हो सकती हैं किन्तु रूढ़ि एकरूप तथा आत्मसंगत होनी चाहिए। ओपेनहेम महोदय भी रूढ़ि तथा प्रथा के भेद को इन्हीं शब्दों में वर्णन करते हैं। वे कहते हैं—“अन्तर्राष्ट्रीय विधि-वेत्ता कहते हैं कि जब कुछ कार्यों को करने की एक स्पष्ट तथा अप्रतिहत प्रवृत्ति इस दृढ़ विश्वास की छत्रछाया में विकसित हो जाती है कि वे कार्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार बाध्य हैं अथवा उचित हैं तो इसे रूढ़ि कहते हैं।” (International jurists speak of a *custom* when a clear and continuous habit of doing certain actions has grown up under the aegis of the conviction that these actions are, according to International Law, obligatory or right.) “इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय विधि-वेत्ता कहते हैं कि जब कुछ कार्यों को करने की प्रवृत्ति इस दृढ़ विश्वास के बिना विकसित होती है कि वे कार्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार बाध्य हैं अथवा उचित हैं तो इसे प्रथा कहा जा सकता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र की भाषा में ‘रूढ़ि’ शब्द से जो अर्थ प्रकट होता है वह ‘प्रथा’ शब्द द्वारा प्रकटित भाव से अधिक संकुचित है क्योंकि कोई दो हुई आचरण विधि (तरीका) रूढ़ि हुए बिना भी सामान्यतया व्यवहृत की जा सकती है।”

आज इस प्रकार की विचारधारा बढ़ती जा रही है कि रूढ़ि की प्रवृत्ति केवल घातनात्मक है न कि सगठनात्मक। यह दृष्टिकोण भी अपना अधिक प्रभाव रखता है और यह प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान के अनुच्छेद ३८ के उपबन्ध से और भी अधिक बढ़ जाता है। उसमें विधि के एक स्रोत की परिभाषा दी गई है—“अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ि, विधि-रूप में अंगीकृत किसी सामान्य रीति व साध्य के रूप में।”

किसी अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ि को राज्य पर बाध्य बनाने के लिए आवश्यक नहीं है कि वह राज्य उस रूढ़ि के विकास का एक पक्षकार रहा हो। जब कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का स्वेच्छया सदस्य बन जाता है, तो वह अनन-प्राप्त राष्ट्रों व रूढ़ि-बानूनों के अधीनस्थ बन देना है। किन्तु, यदि परिस्थिति-विशेष में कोई राज्य

अन्य राज्यों द्वारा निमित्त रूढ़ियों का पालन न करना चाहे, या उसके विरुद्ध करना चाहे, तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

३. विधि के सामान्य सिद्धांत ( The General Principles of Law )—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि (statute) न्यायालय को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के दो मुख्य स्रोत 'अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय लोकरीतियों तथा रूढ़ियों' के प्रतिरिक्त, सम्म राश्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धान्त भी लागू करने को प्राधिकृत करता है । अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इस सहायक स्रोत से उन दशावरो में, जहाँ कि सन्धिवा का प्रमाण देना अथवा इस बात का साक्ष्य देना कठिन होता है कि विधि का कोई सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ि-विधि का अंग बन जाता है, न्यायालय का मुख्य दृष्टान्त के रूप में सम्बद्ध की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विधि के शुद्ध अर्थ तथा विकास की पूर्णतया विचार में रखते हुए, न्याय तथा समता के सिद्धान्तों पर विश्वास करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान में इस खड के समावेश से स्थिर नियम द्वारा लगाये हुए अर्थ का खडन हो जाता है जिसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों को अपने निर्णय निर्धारित कर सकने के लिए केवल सन्धियाँ तथा रूढ़ियाँ ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मान्य स्रोत हैं । यह बात इस पक्ष के भी विरुद्ध पडती है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में अन्तर्राष्ट्रीय भूगडा को मौलिक वैध सिद्धान्तों के अनुसार निर्णय करने व लिये सचीलापन नहीं है ।

फिलिमूर (Phillimore) महोदय द्वारा रेग० बनाम केईन (Reg v. Keyn) में यह मत प्रकट किया गया है कि "राश्ट्रों की विधि न्याय, साम्या, सुविधा तथा विषय-हेतु पर स्थापित की गई है और दीर्घकालीन प्रथा द्वारा पुष्टीकृत कही जाती है" । (The law of nations is said to be founded upon justice, equity, convenience and the reason of the thing, and confirmed by long usage.)

४. न्यायिक निर्णय, न्यायाधिकरण, समुद्र में अभिगृहीत सम्पत्ति सम्बन्धी समुद्री सेना विभाग के नौ-जितमाल न्यायालय (Prize Courts)—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि विधान के अनुच्छेद ३८ में यह निर्देशित किया गया है कि विधि के नियमों को निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरणों के न्यायिक निर्णय सहायक साधनों के रूप में हैं । तर्क-वितर्क में तथा निर्णय में अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ि के साक्ष्य के रूप में उनपर बहुधा विश्वास किया जाता है और तथ्यतः उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय विधि की उन्नति में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की है । परस्पर विरोधी राज्यों की समुक्त सहमति द्वारा नियुक्त मिश्रित न्यायाधिकरणों के निर्णयों को केवल एक राज्य द्वारा नियुक्त समुद्री सेना-विभाग के न्यायालयों के निर्णयों से अधिक गौरव (मान्यता) प्रदान किया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि के ५६वें अनुच्छेद

मे जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यह उपबन्धित है कि न्यायालय के निर्णय पक्षकारों तथा उस विशिष्ट विषय को छोड़कर अन्यत्र बाध्य नहीं हैं, तथापि अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के प्रथम स्थायी न्यायालय तथा उसके उत्तराधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, दोनों में ससार की मुख्य विधायी पद्धतियों का विस्तृत प्रदर्शन किया गया है तथा न्यायालयों के न्यायाधीशों की उच्चकोटि की ख्याति एवं निष्पक्षता की दृष्टि से उनके निर्णयों को न्यायिक पूर्व दृष्टान्त के वास्तविक गुणों से युक्त माना गया है ।

**राष्ट्र-न्यायालयों के निर्णय (Decisions of Municipal Courts)**—विधि के स्रोत के रूप में राष्ट्र-न्यायालयों (Municipal Courts) के निर्णयों को वैसी ही मान्यता नहीं प्रदान की जाती जैसी कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के तथा न्यायाधिकरणों के निर्णयों को । ऐसे न्यायालय सामान्यतया लिखित सविधान के स्पष्ट उपबन्धों के विरुद्ध पड़ने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विधि को लागू नहीं करते । ब्रिटिश न्यायालयों की यह रीति है कि वे सरकार तथा विदेशीय राज्यों के बीच में हुई, परन्तु पार्लियामेंट से अप्राप्त स्वीकृत सन्धियों को यदि उनके द्वारा सामान्य अथवा वैधानिक विधि का रूपभेद होता हो, तो स्वतः लागू नहीं करते । बहुत से देशों में जहाँ न्यायालयों के समक्ष राजनीति विषयक प्रश्न उपस्थित होते हैं, कार्यपालिका को बहुत बड़े अधिकार होते हैं ।

थर्टी हॉग्सहेड्स बनाम बॉयल (Thirty Hogsheads v. Boyle) वाले वाद में मुख्य न्यायाधीश मार्शल (Chief Justice Marshall) द्वारा यह मत प्रकट किया गया था कि “प्रत्येक देश के न्यायालयों के निर्णय जहाँ तक वे एक ऐसी विधि पर स्थापित हैं जो कि प्रत्येक देश के लिए समान है प्रमाण रूप में नहीं, बल्कि सम्मान की दृष्टि पर स्वीकार किये जायेंगे ।”

**प्राइज कोर्ट्स (Prize Courts)**—इन्हें नीजित माल न्यायालय या समुद्री लूट न्यायालय भी कह सकते हैं । ये न्यायालय बोद्धा-राष्ट्रों द्वारा अपने क्रूजरो के अभिग्रहण की वैधता को निर्णय करने के प्रयोजन से स्थापित किये जाते हैं । वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि को किसी विशिष्ट राज्य द्वारा निर्धारित विधि के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी विधि के रूप में प्रयुक्त और कार्यान्वित करते हैं जिसका कि प्रारम्भ मध्य-राष्ट्रों द्वारा अपने पारस्परिक व्यवहारों में दीर्घकाल तक पालित रीति-रिवाजों अथवा प्रकट अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृतियों में होता है । इसमें सन्देह नहीं है कि वे पार्लियामेंट के अधिनियमों से बाध्य हैं, परन्तु यदि वे (अधिनियम) राष्ट्रों की विधि से असंगत हो तो ऐसे अनुबन्धों को प्रभावयुक्त करने में प्राइज कोर्ट्स के तत्समय अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग समाप्त हो जायेगा । ऐसे उपबन्धों से व्याप्त क्षेत्र में उनका प्राइज-कोर्ट के रूप में अधिकार अपहृत हो जायेगा । लॉरेंस महोदय का मत है कि

सोभाग्यवश राष्ट्रों द्वारा ऐसी सधियाँ कदाचित् ही की जाती हैं। अतः प्राइज कोर्ट्स वे निर्णय, उनके न्यायाधीशों की विद्वत्ता, योग्यता तथा निष्पक्षता की स्थािति के अनुसार मान्य किये जाते हैं। लॉर्ड स्टॉवेल, डॉ० लुशिंगटन, केन्ट तथा स्टोरी (Lord Stowell, Dr. Lushington, Kent and Story) के समान प्रमुख विद्वानों द्वारा दिये गये निर्णयों की जिनसे उत्कृष्ट योग्यता प्रकट होती है अंग्रेजी तथा अमरीकी विधि-दृष्टान्त-पुस्तिकाओं ने मुक्तकठ से प्रशंसा की है।

५. मूल पाठ के लेखक (Text-writers), विधि-वेत्ताओं के कार्य (Acts of Jurists) और टीकाकार (Commentators) — अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि अनुच्छेद ३८ न्यायालय की विधि के नियम निर्धारण करने के लिए इस विषय पर भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के सर्वोत्कृष्ट योग्यता रखने वाले प्रवीण लेखकों की शिक्षाओं को सहायक साधन के रूप में लागू करने की प्राधिकृत करती है। पहली बात तो यह है कि लेखकों की कृतियों का अन्तर्राष्ट्रीय विधियों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है। “वैज्ञानिक महत्त्व, निष्पक्षता और राज्यों के कार्यों की वैध सिद्धान्तों पर आलोचना करने का उनका दृढ निश्चय,” इस महत्त्व को और भी बड़ा देता है। दूसरी बात यह है कि लेखकों की रचनाएँ स्वतन्त्र रूप से विधि के लिए स्रोत नहीं हैं। यह सही है कि वे कालान्तर में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के रूप-निर्धारण में सहायक होती हैं क्योंकि उनके द्वारा ऐसे साक्ष्य उपस्थित किये जाते हैं कि वस्तुतः विधि क्या है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्र सम्बन्धी लेखकों के महत्त्व पर संयुक्त राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस ग्रे द्वारा पैकीट हबाना (The Paquete Habana) वाले मामले में निम्नलिखित शब्दों में बल दिया गया।

“उन स्थानों में जहाँ कोई सन्धि नहीं है और कोई नियन्त्रक अधिवासकीय अथवा वैधानिक अधिनियम या न्यायिक निर्णय नहीं है, उन दशाओं में इनके साक्ष्य के रूप में सभ्य राष्ट्रों की रूढ़ियों तथा प्रथाओं और विधिशास्त्र-विशारदों और टीकाकारों की कृतियों का जिन्होंने वर्षों के परिश्रम, अनुसन्धान और अनुभव द्वारा अपने लेख्य विषयों का विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आश्रय लिया गया होगा। न्यायाधिकरणों द्वारा उनका आश्रय, विधि क्या होनी चाहिये इस सम्बन्ध में उनके लेखकों की कल्पना के लिए नहीं बल्कि विधि वास्तव में क्या है इसके विश्वासनीय साक्ष्य के लिये लिया जाता है।”

जुडिशल कमेटी के न्यायाधीशों ने भी पायरेसी जूरे जेरिडियम (Re. Piracy Jure Gentium) वाले मामले में यह निर्धारित किया कि मूलपाठ लेखकों के

वृत्तिरव अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतो मे से सबसे अन्तिम स्रोत हैं लेकिन उनका महत्व किसी से कम नहीं है ।

अयाला, जेटिलिम, ग्रोशस, वेटस, केन्ट, जाउचे (Ayala, Gentius, Grotius, Vattel, Kent, Zouche) इत्यादि वे लेखको ने कम समय मे ही प्रथा का भुक्ताव रुढि को प्रोर कर दिया है, और रुढि ने विधि के एकीकरण मे प्रबल साधक का काम किया है ।

लॉरेन्स महोदय को यह सम्मति है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का लेखक एक अर्थ मे स्वयं विधि-निर्माता है क्योंकि वह उस सम्मति को जन्म देता है जो वास्तव मे श्रेष्ठ है । उसके तर्कों की प्रबलता के कारण कोई नियम समय आने पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि का भाग हो सकता है, परन्तु जब तक उसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त न हो और वह राज्यों की प्रथाओ मे सम्मिलित न कर लिया जाय लेखक को यह नहीं कहना चाहिये कि यह विधि है ।

क्वीन बनाम केयन (Queen v Keyn) म ब्रेट् (Brett J A) ने यह प्रश्न उठाया कि विधि-वेत्ताओं की समान सहमति अथवा मौन स्वीकृति का प्राधिकार क्या है—“What is the authority of a common agreement or acquiescence of jurists ?” इस प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा गया है कि लेखको तथा राजनीतिज्ञों का प्रमाण राष्ट्रों की विधि के सिद्धान्तों के रूप तथा लक्षण वर्णन करने मे ग्रहण करना चाहिये और यदि ऐसे लेखक और राजनीतिज्ञ विभिन्न राष्ट्रों के और भिन्न भिन्न समय के हो और वे किसी सामान्य सिद्धान्त पर सहमत हो जो अनुचित न हो तो ऐसी सहमति राष्ट्रों की समान सहमति के साक्ष्य के रूप मे ग्रहण की जा सकती है और उसके द्वारा राष्ट्रों की विधि बनती है ।”

ग्रोशस ने राष्ट्रों की विधि का विकास दार्शनिकों, इतिहासकारों, कवियों और यहाँ तक कि वक्ताओं का भी प्रमाण दे कर किया, इसलिए नहीं कि उन पर बिना विवेक के भरोसा किया जाय, बल्कि इसलिए कि जहाँ भिन्न-भिन्न युगों तथा देशों के व्यक्ति एक ही कथन मे सहमत हुये हो तो ऐसा भाव अथवा कर्त्तव्य निर्देश किसी सामान्य हित के लिए कहा जा सकता है ।

व्हीटन (Wheaton) का तो यहाँ तक कहना है कि “Without wishing to exaggerate the importance of these writers, or to substitute, in any case, their authority for the principles of reason, it may be affirmed that they are generally impartial in their judgment They are witnesses of the sentiments and usages of civilised nations, and the weight of their testimony increases every time that their authority is invoked by statesmen, and every year that passes without the rules laid down in their works being impugned by the avowal of contrary principles”

६. अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य (International Comity)—ओपेनहेम का मत है कि एक विशेष प्रकार का तत्व जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि को प्रभावित करता है वह तयाकथित सौजन्य है। अपने पारस्परिक सहयोग में राज्य केवल ऐसे ही नियमों का पालन नहीं करते जिससे वे वैध रूप से बाध्य हो अथवा प्रथाओं का लक्षण रखते हो, किन्तु ऐसे नियमों का भी जिनसे विनय (Politeness), सुविधा (Convenience) और कीर्तिस्व या सद्भावना (Goodwill) प्रकट होती हो। अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के ऐसे नियम विधि के नियम नहीं हैं बल्कि वे सौजन्य के नियम हैं। राष्ट्रों का सौजन्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत नहीं है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य क बहुत से पहले के नियम आजकल अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम हैं।

७. सन्धियों के अतिरिक्त अन्य अन्तर्राष्ट्रीय राजपत्र (State Papers)—राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की सरकारी न्याय-विचारदो द्वारा उत्कृष्ट विद्वत्ता तथा योग्यता से राज-पत्रों (State Papers) में प्रायः विवेचना की जाती है। वे अपनी लिखित सम्मतियाँ अपनी-अपनी सरकारों की गुप्त रीति से देते हैं। कभी कभी अन्तर्राष्ट्रीय विवाद किसी विवादग्रस्त वैध विषय को स्पष्ट कर देता है अथवा उन सिद्धान्तों का उपयोग बढ़ा देता है जिनको पहिले एक अव्यावहारिक स्वीकृति से अधिक और कुछ न मिला हो। प्रत्येक देश के विदेशीय कारोबार विभाग के गन्यरखागृहों में विशेषज्ञों की असूच्य सम्मति का डेर पड़ा है जो यदि प्रकाशित किया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य में विशेष रूप से वृद्धि हो सके।

८. अपने अधिकारियों के निर्देश के लिए राष्ट्रों के अनुदेश—विद्वानों द्वारा की गई घोषणाएँ या उनके कार्य, राज्य सरकारों की दी गई वैध सलाह और राज्य की सरकार द्वारा किये गये विवादों के सम्बन्ध में विधि-अधिकारियों के परामर्श अथवा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य राज्यात्मक पत्रों, इन सबके द्वारा उन प्रथाओं का साक्ष्य मिलता है जो समयानुसार वे अन्य राज्यों द्वारा ज्यों-ज्यों अंगीकृत होती गई रूढ़ि में परिणत हो जाती हैं।

९. आधुनिक विधि व्यवस्था में तर्क का स्थान (Place of 'Reason' in the modern system)—न्यायिक तर्क जो कि "पूर्ववर्ती दृष्टान्तों, विवेचनान्तरों के परिणामों, और प्रवर्तित कानूनों के भीतर पाये जाने वाले सिद्धान्तों की आकस्मिक उपेक्षा" आदि पर निर्भर है, "वैध माने जाते हैं और राज्यों में अनवरत-रूप से व्यवहृत होते हैं—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णयों में और वैदेशिक कार्यालयों द्वारा एक दूसरे के प्रसंग में दिये गये तर्कों में दोनों रूपों में ये मान्य हैं।" यदि कोई ऐसा विवाद उठ खड़ा होता है जिसके नियन्त्रण करने के नियम नहीं हैं, तो फिर यह कार्य विधि-शास्त्र का हो जाता है कि वह सामान्य सिद्धान्तों और उपस्थित प्रसंग के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विवादग्रस्त अधिकारों और हितों का निपटारा करे।



## अध्याय ३

## अन्तर्राष्ट्रीय विधि का इतिहास

## (History of International Law)

अन्तर्राष्ट्रीय विधि किसी न किसी रूप में प्रायः सब देशों और सब युगों में विद्यमान रही है। ऐसी दशा में इसकी उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन है। यह सत्य है कि 'राष्ट्रों के कुटुम्ब' अथवा 'एक ससार' की धारणा प्राचीन जगत के लिये विदेशी थी किन्तु राष्ट्र एक-दूसरे के संपर्क में आये और इस संपर्क के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगे तथा सन्धियाँ, युद्ध की घोषणाएँ तथा उनके संचालन सम्बन्धी नियम, सन्धियाँ तथा राजनैतिक विशेषाधिकार उत्पन्न हुए। भारतीयों, यहूदियों, यूनानियों, तथा रोम देशवासियों का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। ज्यों-ज्यों सम्प्रदाय में उन्नति होती गई त्यों त्यों सम्प्रदायों के पारस्परिक व्यवहारों को नियंत्रित करने वाले नियम अधिकाधिक स्पष्ट होते गये, यहाँ तक कि अब राष्ट्रों के लिये चाहे वे बड़े हो या छोटे, सत्रसे सम्बन्ध-विच्छेद करके एकाकी रहना असम्भव हो गया है।

हिन्दू—अन्तर्राष्ट्रीय विधि के चिह्न, राजदूतों के विशेषाधिकार, सन्धियाँ तथा युद्ध की घोषणाएँ और उनके संचालन-सम्बन्धी नियमों के रूप में प्राचीन भारत के इतिहास में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। रामायण तथा महाभारत के महाकाव्यों में यद्यपि प्रधानरूप से धार्मिक विवेचन प्रधान विषय है तथापि उनमें युद्ध, शान्ति तथा सटस्पता के नियमों और प्रथाओं को लक्ष्य करके बारबार निर्देश किया गया है। वे राजदूतों अथवा युद्ध के मध्य में सदेशवाहक दूतों की अवाप्त्यता को उचित महत्त्व देते हैं। हिन्दुओं की धर्म-पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता में जिसकी शिक्षाओं को भारत से बहुत दूर के देशों में भी ग्रहण कर लिया है धर्म तथा अधर्म-युद्धों का पूर्ण रूप से वर्णन है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से, जो कातरतावश कर्तव्य-च्युत हो रहे थे, कहा है—'क्षत्रिय के लिये धर्मयुक्त से अधिक और कोई वस्तु अभिमत नहीं है और क्षत्रियों में कोई विरले ही ऐसे होते हैं जिनको युद्ध के लिये, जो कि स्वर्गप्राप्ति का खुला द्वार है ऐसा अवसर बिना मंगे प्राप्त हो जाता है। यदि तुम यह धर्मयुद्ध न करोगे तो तुम कर्तव्य-च्युत हो जाओगे, अपनी कीर्ति को खो दोगे और तुम्हें पाप लगेगा (अध्याय २. श्लोक ३१—३३)।' इसी स्थान पर इस बात की आवश्यकता पर भी महत्त्व दिया गया है कि युद्ध की घोषणा पहले उमय पक्ष में मोढ़ाओं द्वारा संसद बजाकर होनी चाहिये।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा वामनदकीय नीतिशास्त्र में सरकारी तथा विदेशी कार्यों के संचालनार्थ विस्तृत नियम निर्धारित किये गये हैं। कौटिल्य इस पक्ष के समर्थक हैं कि युद्ध में नीति के सिद्धान्त अथवा धर्म का पालन त्याग देना चाहिये।

मनु ने धर्मयुद्ध तथा अधर्मयुद्ध के भेद का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि एक वीर क्षत्रिय के लिये धर्मयुद्ध में प्राण देने से अधिक और कोई पुरस्कार का कार्य नहीं है। उन्होंने युद्ध में गुप्त अथवा विपरीत शस्त्रों का उपयोग, शत्रु की सम्पत्ति का मर्यादाहीन विनाश तथा घायल योद्धा का वध वर्जित किया है। आत्म-समर्पण करने वाले शत्रुपक्षीय व्यक्तियों का वध करना अथवा उनको घायल करना वर्जित था। उन्होंने मन्दिरों की अभ्यन्तता स्वीकार की है तथा युद्धबन्धियों और लड़ाई में भाग न लेने वालों को उन्मुक्ति प्रदान की है। प्राचीन हिन्दू सन्धियों को बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे।

मुसलमान—भारत के मुसलमान-बादशाहों ने भी कुछ विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्ध स्थापित किया था। उन्होंने यूरोपीय देशों के राजदूतों का सत्कार किया और सन्धियाँ भी की परन्तु उनके अन्तर्राष्ट्रीय विधि-सम्बन्धी विचार अविकसित थे। उनके यहाँ केवल वे ही नियम परिभाषित हैं जिनमें मुसलमान राज्यों का तथा जनता का सम्बन्ध उन राज्यों से तथा जनता से जो मुसलमान नहीं हैं कैसा होना चाहिये परन्तु उनका भी आधार कोई अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था अथवा सौजन्य नहीं है। मुसलमानों का राज्यकाल ऐसे उदाहरणों से परिपूर्ण है जब इस्लाम की रक्षा के लिये किसी विदेशी अथवा शत्रु अमुसलमान राष्ट्र में लड़ाई लड़ी गई जिसे जेहाद कह कर पुकारा जाता है। परन्तु यदि अमुसलमान विदेशी राज्य अथवा उसकी प्रजा इस्लाम ग्रहण कर लेती थी तो कोई लड़ाई नहीं की जाती थी।

यहूदी—यहूदी लोगों की विधियाँ उनके राज्य में रहने वाले विदेशियों के लिये भी वही थी जो अपने लिये थी, यथा “विदेशियों से प्रेम करो क्योंकि मित्र देश में तुम भी विदेशी थे।” *Love...the stranger for ye were strangers in the land of Egypt.* (Deuteronomy अध्याय १०, श्लोक १९)। तथापि बाइबिल को एक बार पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहूदी लोग एकेश्वरवाद के कारण दूसरे लोगों को, जो कि अनेक देवताओं में विश्वास रखते थे अपने बराबर का नहीं स्वीकार करते थे। युद्ध के सब नियमों को धूल में फेर कर उन्होंने उनके साथ निर्दयता से लड़ाईयाँ लड़ीं। यहूदी लोग मित्र-राष्ट्रों से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध रखते थे। उन्होंने सन्धियों का निष्कपटता से पालन किया और राजदूतों को पवित्र आत्मा के समान सम्मान।

**यूनानी—**यूनानी लोग अपने पड़ोसियों से अधिक सम्य थे और वे जगली जातियों के समान समझते थे। अहंकार के कारण उनको अपने पड़ोसियों के साथ पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने में बाधा पड़ती थी। यूनानी लोग असह्य छोटे नगर-राज्यों में रहते थे जो कि एक दूसरे से स्वतन्त्र थे। इन राज्यों के निवासी एक ही जाति, रक्त तथा धर्म के थे। इस घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण समय की गति में इन स्वतन्त्र इकाइयों को राज्या के एक समुदाय में जोड़ दिया जो कि युद्ध तथा शान्ति के समय परस्पर कुछ नियमों का पालन करते थे। अपने भगवों को निपटाने के लिये वे प्रायः पञ्चायनों का आश्रय लेते थे, सदेशवाहक दूतों तथा पवित्र अग्नि ले जाने वाले पुरोहिता को पूज्य मानते थे, बिना पहले घोषणा किए कोई युद्ध आरम्भ नहीं करते थे, युद्धक्षेत्र में मरे हुये योद्धाओं के शवों को गाड़ते थे, युद्धबंदियों का विनिमय करते थे, अपालो देवता के मंदिर को स्थायी रूप से अनुत्लघनीय मानते थे और राजदूतों को असाधारण विशेषाधिकार देते थे तथा उनके शरीर को अनुत्लघनीय मानते थे।

भाषेनहेम का मत है कि यूनानी लोगों ने इतिहास के लिये यह उदाहरण रक्खा कि स्वतन्त्र सर्वोच्चसत्ताधारी राज्य एक ऐसे समुदाय में रह सकते हैं जो कि अपने सदस्य राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिये विधि निर्धारित करता हो परन्तु अनुबन्ध यह है कि इन राज्यों को एक सूत्र में बाँधने वाले कोई समान हित तथा लक्ष्य विद्यमान हो।

**रोमन—**रोम देशवासियों के विचार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सम्बन्ध में अधिक प्रगतिशील थे। उनके यहाँ २० पुरोहितों की एक श्रेणी होती थी जिनको फिटायल्स (Fetiales) कहा जाता था। वे विदेशी राज्यों के सम्बन्धों की व्यवस्था उन विधियों के अनुसार करते थे जिनको जम फिटायल्स (Jus fetiales) प्रपवा जस सैक्रेल (Jus sacrale) कहा जाता था। रोम देशवासियों की विधि दो श्रेणियों में विभाजित थी एक अर्थात् दीवानी विधि (Jus civile) यह जो केवल उन्हीं लोगों में लागू होनी थी और दूसरी अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Jus gentium) जो विदेशियों के लिये भी और वह ऐसी विधि थी जो उनके और अन्य राष्ट्रों के बीच समान थी। अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Jus gentium) बाद में प्राकृतिक विधि (Jus naturale) में प्रोत्त बनकर और भी दृढ़ बन दी गई। यह वह विधि थी जो उन युक्तियों पर स्थापित थी जिनसे प्रकृति तथा मनुष्य में समानता प्रकट होती थी। अन्त में इसी विधि अर्थात् जम फिटायल्स (Jus fetiales) के अनुसार रोम-देशवासियों ने सम्बन्ध विदेशों के साथ शान्ति और युद्ध के समय में तथा उनके साथ मित्रता की गति स्थापित करने के समय में निर्धारित होने लगे। ऐसी ही विधि

तीन प्रकार की होती थी अर्थात् मित्रता सन्धि (amicitia), आतिथ्य-सन्धि (hospitium) और सहयोग-सन्धि (foedus) ।

रोम-देशवासियों की विधि के अन्तर्गत लड़ाई के चार उचित कारण माने जाते थे :—(अ) रूमो राज्य का उल्लंघन, (आ) राजदूत सम्बन्धी विशेषाधिकारों का उल्लंघन, (इ) सन्धियों का उल्लंघन और (ई) मित्र-राष्ट्र का युद्ध के समय किसी विपक्षी को महायुता प्रदान करना । रोम-देशवासियों के अनुसार लड़ाई की समाप्ति (१) दान्ति-स्थापन सन्धि द्वारा, (२) आत्मसमर्पण (deditio) द्वारा अथवा (३) शत्रु के देश की विजय-प्राप्ति द्वारा हो सकती थी ।

सन्धियाँ तीन वर्गों में विभाजित थी —(१) मित्रता-सन्धि, (२) सहयोग-सन्धि और (३) आतिथ्य-सन्धि । रोम-देशवासी सन्धियों की बड़ी प्रतिष्ठा करते थे और वे सूचना द्वारा समाप्त की जा सकती थी ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इतिहास का तीन युगों में विभाजन—स्थूल दृष्टि से लॉरेन्स अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इतिहास को तीन युगों में विभाजित करते हैं । प्रथम युग का मान आदिकाल से सीज़रो के अर्धिन रोम राज्य के स्थापन तक है । इस युग का विशिष्ट लक्षण यह विश्वास है कि राष्ट्रों के एक-दूसरे के प्रति कर्तव्य उसी दशा में होते हैं जब वे एक ही जाति न हो अन्यथा नहीं । अन्तर्राष्ट्रीय विधि का मूलभूत सिद्धान्त, यथा किसी बन्धन द्वारा एक सूत्र में सम्बद्ध होना ग्रीस-देशवासियों में विद्यमान था, क्योंकि एक ही जाति तथा धर्म के सब यूनानी लोगों का आपस में ऐसा सम्बन्ध था जैसा उनका शेष संसार के अन्य लोगों के साथ नहीं । इस युग की विशेष बात रोडियावासियों की समुद्रीय संहिता (Maritime Code of Rhodians) का विकास है । इसी से ग्रीस-देशवासियों का व्यापार नियन्त्रित होता था और यही वह आधार था जिस पर मध्ययुग की बड़ी समुद्रीय संहिता अर्थात् कॉन्सोलेटो डेल मेयर (Consolato del Mare) स्थापित है ।

द्वितीय युग—यह युग सीज़रो के अर्धिन रोमराज्य की स्थापना होने से सोलहवीं शताब्दी के धार्मिक विप्लव तक विस्तृत है । लॉरेन्स का कथन है कि इस युग की विशेषता इस धारणा में थी कि कहीं न कहीं सर्वसामान्य प्रवर सत्ता-प्राप्त हो जाती है जो साधारण राजनैतिक समुदायों के पारस्परिक व्यवहारों को नियन्त्रित करती है । रोमन-साम्राज्य यूरोप के बड़े हुये भाग पर तथा एशिया और अफ्रीका के अधिकांश भाग पर विस्तृत था । सीज़र अपने अर्धिनस्थ बहुत से राजाओं का राजनैतिक श्रेष्ठ पुरुष था और उनके झगड़ों का निपटारा अपील के आधार पर होता था । उसने अपने साम्राज्य के लोगों से कर्तव्य का पालन पूर्णरूप

से कराया और वे यह विश्वास करने लगे कि सब राज्यों के ऊपर एक सर्वसामान्य प्रभुसत्ता का अस्तित्व भी संसार की प्राकृतिक व्यवस्था का एक भंग है। ऑस्टिन की विचारधारा के अनुसार 'अन्तर्राष्ट्रीय विधि' का आधार वास्तव में एक सप्रभुसत्ता की आज्ञायें ही हैं। रोमन विधि विदेशी राज्यों के माल तथा सम्पत्ति के सरक्षण की गारंटी उस दशा में लेती थी जब कि रोम तथा उस विदेशी राज्य के बीच मित्रता की सन्धि रहती थी परन्तु यदि इस प्रकार की सन्धि नहीं रहती थी तो माल का बन्दीकरण किया जा सकता था और व्यक्तियों को दास बनाया जा सकता था।

पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी में रोम की सम्पत्ता का प्रभाव प्राचीन समूचे सम्य देशों पर पड़ा और व्यक्तिगत राजाओं के भिन्न-भिन्न प्रभाव साम्राज्य पर पड़ते रहे। शासक और पोप अपने को राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रधान के रूप में मानते रहे। परिणामतः मध्य युग में राष्ट्रों के कानून की आवश्यकता न रही। यह स्थिति उस समय तक रही जब तक कि छोटे-छोटे राज्य उत्पन्न होने लगे और अधिकार-विवेचन की प्रतिद्वन्द्विता शासक और पोप में अत्यन्त गहरी नहीं हो गई।

तीसरा युग—इसके अनन्तर हम तीसरे युग में पहुँचते हैं। यह युग सोलहवीं शताब्दी के धर्म-सुधार (Reformation) से वर्तमान काल तक माना जाता है। लॉरेन्स का कथन है कि इस युग में हमें वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय विधि मिलती है जिसका आधार यह सिद्धान्त है कि राज्य एक बड़े समाज के पृथक् और स्वतन्त्र सदस्य हैं और यद्यपि वे किसी सामान्य वरिष्ठ सत्ता द्वारा नियन्त्रित नहीं किये जाते तथापि वे स्वेच्छाचारी नहीं हैं बल्कि आचरण के ऐसे नियमों से शासित हैं जो सब सदस्यों पर बाधित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आधुनिक अर्थ में आरम्भ ग्रीशस (Grotius) के समय से (१५८३-१६४५) मानना चाहिये जिसने अपना ग्रन्थ 'डी जूरे बेली ऐक् वेसिस' (De Jure Belli ac Pacis) सन् १६२५ में पेरिस में प्रकाशित किया। उसके पूर्वकालीन थे—(१) बल्येजार अयाला (Balthazar Ayala) जिसने अपनी पुस्तक 'डी जूरे एट् आफिसिस बेलिसिस' (De Jure et Officiis Bellicis) सन् १५८२ में 'दो आई' में प्रकाशित की और इस सामान्य मत का खडन किया कि लड़ाई कोई नियम नहीं जानती। (२) 'अल्बेरिकस जेंटिलिस' (Albericus Gentilis) (१५५२-१६०८) जिसको अपने धार्मिक विचारों के परिणामस्वरूप अपनी जन्मभूमि इटली छोड़नी पड़ी। वह सन् १५८७ में ऑक्सफोर्ड में विधि-शास्त्र का प्रोफेसर था और उसने सन् १५६८ में अपना महाव् ग्रन्थ 'डी जूरे बेली लिब्री ट्रेस' (De Jure Belli Libri Tres) प्रकाशित किया और इस पदा का समर्थन किया कि लड़ाई का एक

नियम होता है जिसका आधार प्राकृतिक युक्ति है। यद्यपि ग्रीशस ने जेस्टिलस की उसके लोपो, दोली तथा रचना के लिये समालोचना की तथापि अपने ग्रन्थ का अधिकांश उसने उसी जेस्टिलस (Gentilis) से ही लिया है। (३) फ्रांसिस सुवारेज (Francis Suarez) (१५४८-१६१७) स्पेन का एक पादरी था जिसने अपनी पुस्तक 'ट्रेक्टेटस डी लेजिबस एट् डिभो लेजिस्लेटोर' (Tractatus de Legibus et Deo Legislatore) सन् १६१२ में प्रकाशित की जिसमें उसने मनुष्य जाति के नैतिक ऐक्य पर महत्व दिया।

ग्रीशस (Grotius)—हूग वैन गूट (Hug Van Groot), जो कि हूगो ग्रीशस (Hugo Grotius) के नाम से प्रसिद्ध है सन् १० सन् १५८३ ई० में हॉलेड में डेलफ्ट (Delft) में पैदा हुआ था। शीघ्र ही उसने ग्रन्थकार, विधिवेत्ता और कवि के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। प्रथम उसने बकासत धारम्भ की परन्तु शीघ्र ही उसने राजनैतिक भ्रमणों में भाग लिया जिसके परिणामस्वरूप वह १६१८ में गिरफ्तार किया गया और उसे भाजन्म कारावास का दण्ड मिला। सन् १६२१ ई० में वह अपनी स्त्री की सहायता से एक सन्दूक में, जो कि उसके द्वारा अपने मित्रों से उधार ली हुई पुस्तकों को रखने के उद्देश्य से बना था, निकल भागा। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है उसका सब से प्रसिद्ध 'ग्रन्थ डी जूरे बेली एक् पेसिस' (De Jure Belli ac Pacis) (शान्ति तथा युद्ध की विधि) पेरिस में सन् १६२५ में प्रकाशित हुई थी। उसने अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Jus Gentium) अर्थात् राष्ट्रों की व्यावहारिक विधि तथा प्राकृतिक विधि (Jus Naturale) अर्थात् राज्यों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से समुक्त विधि को पृथक् किया और राज्यों के प्राकृतिक विधि-सम्बन्धी नियमों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया। उसने कहा कि अधिकार जो सब के लिये समान हैं वे किसी विशेष राज्य के लिखित विधियों अथवा मन्त्र्यादेशों द्वारा नहीं प्रदत्त किये जा सकते। वे प्राकृतिक विधि बुद्धि की आज्ञायें हैं। उसके अनुसार प्राकृतिक समाज केवल ईश्वर को ही अपनी प्रभुसत्ता करके जानता है और मनुष्य के हृदय में केवल ईश्वरीय विधि ही अधिक शक्ति है। वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि राज्य परस्पर इस अम्योन्याश्रित दशा में रहते हुये उसी विधि का अनुसरण करते हैं। उसने राज्यों के स्थिर नियम का आधार यह माना कि राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में कुछ निश्चित नियमों के संग्रह को पालन करने के लिये इच्छा-पूर्वक सहमति देते हैं।

उसने 'युद्ध से घृणा' इस कथन द्वारा प्रकट किया है कि वह देखता है कि संपूर्ण ईसाई ससार में इस प्रकार के युद्ध करने की अनुमति है जिसकी देख कर जगली जातियाँ भी अपना सर सज्जा से नीचा कर लेती हैं। उसका कहना है कि

मनुष्य बहुत ही छोटे कारणों पर युद्ध के लिए दौड़ पड़ता है, और जब हाथ में एक बार ले लिये जाते हैं, तब कानून के प्रति कोई सम्मान नहीं रह जाता, मने हो वह कानून देवी हो भयवा मनुष्यवृत्त । वह प्रभुसत्ता को प्रादेशिक रूप में मानता था । उसकी सफलता की कुंजी यह रही कि उसने पहिले से ही स्वीकृत विधियों तथा सिद्धान्तों का विवेकपूर्ण प्रयोग किया ।

उसके पुस्तक की ख्याति धीरे-धीरे दूर-दूर तक फैल गई और उसके कुछ सिद्धान्तों का ही यूरोप के कांग्रेस ने अपने विचारों में अनुसरण किया । परिणाम स्वरूप सन् १६५८ में वेस्टफालिया की शांति सन्धि हुई और तीस वर्ष के युद्ध का अन्त हुआ ।

जाउचे (Zouche) — अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में थोड़ा सा था Richard Zouche (१५६०-१६६०) का भी है । वह भाक्सफोर्ड में दीवानी विधि का प्रोफेसर था और नौ-प्रधिकरण न्यायालय (Admiralty Court) का ब्र था । उसने अपने महाग्रन्थ 'ऑरिस एंड् जुडिसी फिसियालिस, सिवि ऑरिस्ट इटर् जेण्टिस' (Juris et Judicij fecialis, sive Juris inter Gentes) १६५० ई० में प्रकाशित किया । इस पुस्तक को राष्ट्रों के स्थिर नियमों की प्रथम पुस्तक कहा गया है । उसमें और घोषित है कि उसने राज्यों की शान्ति-विधि पर अधिक महत्व दिया यद्यपि उसने राज्यों की प्राकृतिक विधि के अस्तित्व को मानी कार नहीं किया ।

तीन सम्प्रदाय (Three Schools) — सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर तीन विभिन्न सम्प्रदायों के खेलकों को जन्म दिया, अर्थात् प्राकृतिवादी (Naturalists), स्थिर व्यवहारवादी (Positivists) और गोट्टोव मतावलम्बी (Grotians) ।

प्राकृतिवादी यह नहीं मानते कि कूटियों अथवा सन्धियों के आधार पर स्थापित राष्ट्रों की कोई निश्चयात्मक विधि (Positive Laws) हैं, बरन्, उनकी धारणा यह है कि वे प्राकृतिक नियमों के एक अंश हैं सेमुएल पफेन्डोर्फ (Samuel Pufendorf) (१६३२-१६९४) इस सम्प्रदाय का अनुयायी था । उसने यह प्रतिपादन किया कि राष्ट्र अपने पारस्परिक आचरण को प्राकृतिक नियमों के अनुसार नियंत्रित करते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई सामान्य प्रभुसत्ता नहीं है । जर्मन दार्शनिक Christian Thomasius (१६५५-१७२८) पफेन्डोर्फ (Pufendorf) का परम अनुयायी था । इसी प्रकार उसके अन्य अनुयायी अग्रेजी दार्शनिक फ्रान्सिस हचिंसन (Francis Hutcheson) और टामस ह्यूरफोर्ड (Thomas Rutherford), फ्रांसीसी

दायनिक जीन बरबेयरेक (Jean Barbeyrac) (१६७४-१७४४) तथा जेनेवा का दार्शनिक जीन जैक्स बरलेमाकी (Jean Jacques Burlamaqui) भा थे ।

निश्चयात्मक विधि वालो का प्राकृतिक सिद्धान्त वालो से मूलरूप मे ही अन्तर या और वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास का कारण रूढ़ि तथा अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को बताते थे । वे प्राकृतिक नियम पर कोई महत्व नहीं देते थे लेकिन संधियों तथा रूढ़ियों पर आधारित रूढ़ि विधि को निश्चयात्मक अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Positive International Law) मानते हैं और इसे सबसे अधिक महत्व देते हैं । इनका प्रभाव अठारहवीं शताब्दी मे बढ गया । इस सम्प्रदाय के प्रमुख टीकाकार डेनमार्क के विधिवेत्ता बिनकरशोक (Bynkorshoek) (१६७३-१७४३), जर्मन लक्षक जॉन जैकब मूसोर (John Jacob Moser) (१७०१-१७८५) और जीर्ज फ्रेडरिक डी मार्टेन्स (George Friedrich de Martens) (१७५६-१८२१) थे । यह सम्प्रदाय अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर आधुनिक विचारो को प्रवृत्त करता है ।

ग्रोशस (Grotius) बतावलम्बी प्राकृतिक सिद्धान्तवादियो तथा निश्चयात्मक नियमवादियों के बीच का स्थान ग्रहण करते थे । उन्होंने ग्रोशस (Grotius) द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रों की प्राकृतिक तथा ऐच्छिक विधि के अन्तर को स्वीकार किया और दोनों को विधि का स्रोत माना परन्तु ग्रोशस (Grotius) के विपरीत उनकी यह धारणा थी कि राज्यों के स्थिर अथवा ऐच्छिक नियम भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना राष्ट्रों के प्राकृतिक नियम । सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दियों में उनका महत्व बहुत ही बढ गया । इस सम्प्रदाय के दो प्रभावशाली प्रतिपादक क्रिस्चियन वुल्फ (Christian Wolff) (१६७९-१७५४) और वेटेल (Emerich de Vattel) (१७१४-१७६७) थे । पहला एक जर्मन दार्शनिक था और दूसरा एक स्विटजरलैंड का विधिवेत्ता था जिसने कि अपना महान् ग्रन्थ 'ली ड्रॉयट डी जेन्स' (Les droit des gens) १७५८ मे प्रकाशित किया और यह प्रतिपादन किया कि राष्ट्रों की विधि प्रकृति के नियम हैं जो राष्ट्रों पर लागू किये गये हैं ।

उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी — उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दियों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास के कई कारण बताये जा सकते हैं । प्रथम—वियना (Vienna) की कांग्रेस के उपरान्त राष्ट्रों की ओर से यह प्रयत्न किया गया कि राष्ट्रों की विधि के नियमों का पालन किया जाय । यह कांग्रेस यूरोप की पहली अन्तर्राष्ट्रीय सभा थी जिसने अन्तर्राष्ट्रीय नदियों में नौचालन सम्बन्धी नियम बनाये और राजदूतों की कोटि (rank) तथा उनकी पूर्ववर्तिता (precedence) निश्चित की । द्वितीय—यह काल बहुत-सी विधिकारी सन्धियों के होने के कारण अधिक महत्व रखता है, यर्थात् पेरिस की घोषणा (१८५६) जिसमे राष्ट्रों के लिये समुद्री



युद्ध में मार्ग-प्रदर्शनार्थ नियमों का समावेश किया गया है, जेनेवा का अभिसमय (१८६४) भूमियुद्ध में रण्यो तथा घायलों की दशा सुधारने के लिये, सेंट पीटर्सबर्ग की घोषणा (१८६८) युद्ध में विस्फोटक गोलियों का प्रयोग निषेध करने के लिये, सन् १९०६ का जेनेवा का अभिसमय (Convention) जिसके द्वारा भूमियुद्ध के बीमारों तथा घायलों वाली व्यवस्था समुद्री लड़ाई वाली के लिये भी लागू कर दी गई । अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के निश्चित (Positive) सिद्धान्तों पर डी मार्टेन्स, हेफ्टर, फिलिमूर, मेन तथा वेस्टलेक (De Martens, Heffter, Phillimore, Maine तथा Westlake) जैसे लेखकों द्वारा अधिक महत्व दिया । हॉल, ओपेन-हेम, लॉरेन्स, हाइड, ह्यूटन और ब्लन्त्स्ली (Hall, Oppenheim, Lawrence, Hyde, Wheaton और Bluntschli) ऐसे अन्य लेखकों ने भी घोषणात्मक (Declaratory) ग्रन्थकारों के रूप में अपने लेखों द्वारा अधिकांश में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में सहायता प्रदान की ।

यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रों का समाज क्रिस्तानी देशों की सीमाओं को पार करके सभ्यता के साथ समानरूप से विस्तृत हो गया, और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियम राष्ट्रों की सहमति से विकसित हुये ।

हेग सम्मेलन—हेग सम्मेलन १८६६ और १९०७ में जिन अन्तर्राष्ट्रीय महान सभाओं का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को शान्तिपूर्वक निपटाने का था, उन्होंने राष्ट्रों के कुटुम्ब के लिये सम्पूर्ण रूप से नियमों को बनाने का प्रयत्न किया । १८६६ के पहले हेग-सम्मेलन में भूमियुद्ध के लिये एक संहिता निकाली । सन् १९०७ के दूसरे हेग-सम्मेलन में बमवर्षा-निषेध-सम्बन्धी प्रतिज्ञायें स्वीकृत की—अरक्षित ग्रहों पर बम बरसाने का निषेध, सम्पर्क विस्फोटक सुरङ्गों का बिछाना, समुद्री-युद्ध में तटस्थों के अधिकार तथा कर्तव्य, व्यापारी जहाजों का जङ्गी जहाजों में परिवर्तन, समुद्री-युद्ध, सैनिक अस्पताली जहाज, युद्धविश्राम-सन्धि के भूदे इत्यादि । इन सम्मेलनों के परिणाम-स्वरूप पञ्चायत का स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) स्थापित हुआ ।

लीग ऑफ नेशन्स की प्रतिज्ञा—मित्र तथा सम्बद्ध राष्ट्रों और अर्जन्ती के बीच वार्सलीज की सन्धि प्रथम महायुद्ध के बाद जून २८, सन् १९१९ को हुई । इसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास के लिये लीग ऑफ नेशन्स की नींव पड़ी । पहले तो यह प्रतीत हुआ कि लीग अपने भिन्न-भिन्न अंगों द्वारा एक सच्चे अन्तर्राष्ट्रीय सच का रूप धारण करेगी और राष्ट्रों के बीच की भिन्नताओं को हटा कर शान्ति तथा मित्रता का युग लायगी परन्तु ये सब आशाएँ शीघ्र ही मिट्टी में मिल गई ।

लीग आफ नेशन्स के प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १४ के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय सन् १९२१ में स्थापित किया गया ।

लोकार्नो की सन्धि—यह सन्धि नवम्बर १६ सन् १९२५ को फ्रांस, ग्रेट-ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और बेलजियम के बीच हुई और इसके द्वारा जर्मनी, फ्रांस और बेलजियम ने अपने पारस्परिक सीमाओं को बनाये रखने का तथा एक-दूसरे के विरुद्ध बलप्रयोग न करने का प्रण किया । ब्रिटेन तथा इटली ने इस समझौते (Pact) की गारंटी ली और विश्वास दिलाया कि उल्लंघन की स्थिति में वे एक-दूसरे की सहायता करेंगे । इस सन्धि ने राष्ट्रों के इस विश्वास को दृढ़ किया कि वे अपने झगड़ों का लीग आफ नेशन्स के प्रतिज्ञा के अनुसार शान्तिपूर्वक निपटारा कर लेंगे । १९३६ में जर्मनी ने इस सन्धि को इस कथन पर त्थाप दिया कि फ्रांस और सोवियत रूस के बीच पारस्परिक सहायता का पैक्ट लोकार्नो के पैक्ट के साथ असंगत है ।

केलोग-ब्रिअंड-समझौता (Kellogg-Briand Pact)—लोकार्नो की सन्धि के थोड़े समय बाद ही संयुक्त राज्य अमेरिका के परराष्ट्रसचिव फ्रैंक बी० केलॉग (Frank B. Kellogg) के आगे बढ़ने पर एक अन्तर्राष्ट्रीय इकरारनामे पर हस्ताक्षर किये गये जिसके द्वारा संसार के प्रायः सभी राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के निर्णय के लिये युद्ध को साधन बनाने की निन्दा की और प्रण किया कि वे अपने झगड़ों को तय करने के लिये शान्तिपूर्ण उपायों का सहारा लेंगे ।

१९२६ की जेनेवा का अभिसमय—स्विटजरलैंड की सरकार की प्रेरणा पर ४७ सरकारों के प्रतिनिधियों ने जेनेवा में युद्धबन्धियों से व्यवहार-सम्बन्धी तथा रणक्षेत्र में घायल और बीमार सैनिकों की इलाज सुधारने की प्रतिज्ञायें कीं । युद्ध-बन्धियों के प्रति व्यवहार वाली प्रतिज्ञा द्वारा प्रतिकार, बन्धियों से अनमानुषिक व्यवहार तथा कुछ व्यक्तियों के कार्य के निमित्त औरों पर सामूहिक दंड निषिद्ध किये गये । दूसरी प्रतिज्ञा द्वारा डाक्टरी दलों (units) तथा बीमारों और घायलों की सेवा में लगे हुये व्यक्तियों को उन्मुक्ति प्रदान की गई ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण (Codification of International Law)—प्रथम विश्वयुद्ध के अन्त तथा लीग आफ नेशन्स के स्थापन के उपरान्त हम देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण के लिये सच्चे प्रयत्न किये गये । उसका विस्तारपूर्वक वर्णन संहिताकरण के अगले अध्याय में किया गया है ।

द्वितीय विश्व युद्ध—द्वितीय विश्वव्यापी महामुद्ध के अन्त में एक-दूसरे राष्ट्रीय गंध भर्पाव संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organisation) का जन्म हुआ । इसके चार्टर पर पचास राष्ट्रों द्वारा सैन फ्रान्सिस्को में २६ जून सन्

१९४५ को हस्ताक्षर किये गये। संयुक्त राष्ट्र का जन्म २४ अक्टूबर, १९४५ को हुआ जब इसका चार्टर पाँच मूल सदस्यों तथा बहुसंख्यक अन्य हस्ताक्षर करने वालों द्वारा सत्याकित (ratified) किया गया। इस विश्व-संघ पर मानव-मात्र की भाशा सही हुई है और इसमें संसार की व्यवस्था के वह बीज निहित हैं जो “एक संसार” (One World) की भावना पर स्थापित हैं। यह वह आधार है जिस पर एक ऐसे नये संसार का निर्माण किया जाता है जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखे और मनुष्य-जाति के कल्याण की वृद्धि करे।

राष्ट्रों को अपने पारस्परिक सम्बन्धों में बाधित करने वाले विधि के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के महत्त्व को इन दो विश्वव्यापी युद्धों द्वारा बहुत ही घनका लगा, परन्तु शान्ति-स्थापन के अनन्तर इसका महत्त्व पुनः पहले की अवस्था को प्राप्त हो गया क्योंकि पराजित राष्ट्रों और युद्ध के अपराधियों ने अपने कार्यों को न्यायोचित ठहराने तथा दोषों से मुक्त होने के लिये बार-बार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों की शरण ली। फिर भी, हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, सम्मिलित राष्ट्रों के अपने पारस्परिक व्यवहारों को नियन्त्रण करनेवाली अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में, एक कीर्तिस्तम्भ है।

मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (१९४८), मानवीय अधिकारों तथा मूलमूल स्वतन्त्रताओं की रक्षा हेतु यूरोपीय अभिसमय (European Convention for the Protection of Human Rights) (१९५०), जनवध (Genocide) तथा शरणार्थियों की सामाजिक स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा अंगीकृत विभिन्न अभिसमय वास्तव में सन्धियाँ हैं जो विधि द्वारा नियन्त्रित अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के नियमों के समूह में वृद्धि करते हैं।

अभिसमय (Conventions), निर्णयों, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमाणित व्याख्याओं तथा सहिताकरण द्वारा एक विश्व विधि-व्यवस्था बनाने के दीर्घकालीन कार्य के लिये संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा क्रमानुसार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

## अध्याय ४

प्रकृति-विधि और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास पर इसका प्रभाव

### Law of Nature and Its Influence on the Development of International Law

प्रकृति-विधि नीतिशास्त्र का वह भाग है जिससे मनुष्य जाति को अपने प्रकट कार्यों को अनुशासित करने के लिये अधिक आवश्यक तथा सार्वभौमिक नियम प्राप्त होते हैं। यह प्रकृति की अनुसंधानों द्वारा मनुष्य के हृदय-पट पर लिखा गया है। इसमें वे नियम सम्मिलित हैं जिनके सम्बन्ध में यह विश्वास किया जाता है कि उनको प्रकृति ने पथ-प्रदर्शक के रूप में प्रकट कर उन पर चलने की आज्ञा दी। ऐसे नियम प्राकृत भौतिक एव दार्शनिक सिद्धान्त होते हैं या अपने व्यापक अर्थ में न्याय के सिद्धान्त होते हैं। यूनानी दार्शनिकों का विचार था कि ससार के भौतिक तथा नैतिक विषयों को कुछ साधारण तथा सामान्य नियमों में स्थिर किया जा सकता है और इनको वे प्रकृति के नियम कहते थे।

प्रकृति-विधि को देवी विधि ( Divine Law ) भी कहते हैं ( क्योंकि यह मनुष्यों पर लगाई गई ईश्वर की आज्ञा है ) तथा अलिखित विधि ( Unwritten Law ) ( क्योंकि यह ताम्रपत्रों अथवा स्तम्भों पर नहीं लिखी हुई है ), सार्वभौमिक अथवा सामान्य विधि ( क्योंकि यह सब लोगों के लिये समान रूप से न्याय है ), तर्क-विधि ( Law of Reason ) ( क्योंकि यह उस युक्ति पर स्थापित है जिससे सारा ससार अनुशासित होता है ) और शाश्वत विधि ( Eternal Law ) ( क्योंकि यह किसी की बनाई हुई नहीं है और अचल है ) भी कहते हैं। "प्रकृति-विधि" का वास्तविक अर्थ नीचे लिखे श्रेष्ठ विचारों की सम्मतियों से प्रकट होगा।

जस्टीनियन ( Justinian )—प्रकृति विधि, जिसे जूरा नेचुरैलिया ( *jura naturalia* ) भी कहते हैं और जिसका पालन समान रूप से सभी राष्ट्रों में होता है, देवी शक्ति द्वारा लागू किये जाने के पश्चात् सदा के लिए निश्चित हो जाती है और फिर बहुत ही दृढ़ हो जाती है, किन्तु वह विधि जिसे प्रत्येक राज्य ने अपने लिए स्थिर किया है वे प्रायः या तो विधायन अथवा लोकमत द्वारा परिवर्तित होती रहती हैं।

हूकर ( Hooker )—हूकर महोदय का कहना है कि "The law of reason or human nature is that which men by discourse of natural reason

have rightly found out themselves to be all for ever bound unto in their actions." अर्थात् तर्क-विधि या मानव-प्रकृति उसे कहते हैं जिसे मनुष्यों ने प्राकृत तर्क द्वारा अपने लिए सदैव के लिए उचित पाया है और सदा के लिए उनमें अपने कार्यों को बाँध दिया है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राष्ट्रों की विधि के विकास के आदिकाल में प्रकृति के नियम का उस पर अधिक प्रभाव रहा है। यूनानियों के समय से सत्रहवीं शताब्दी तक व्यक्तिगत रूप में राष्ट्रों के सम्बन्ध अधिकतर प्राकृतिक नियम द्वारा अनुशासित होते थे। यह नियम उचित-अनुचित के तर्क पर स्थापित था और उसको शक्ति-राष्ट्रों के बीच में हुए किसी विशिष्ट स्वीकार-पत्रों से नहीं बरदा, उचित तथा अनुचित सम्बन्धी उन सार्वभौमिक सिद्धान्तों से प्राप्त होता था जिसका उद्गम मनुष्य के हृदय में भीतर से होता है और जो अबस तथा सनातन हैं। इसमें सन्देह नहीं कि नीति तथा अनीति के नियम स्पष्ट नहीं थे और न वे ऐसे सारभूत सिद्धान्तों में परिणित किये जा सकते थे जो कठिनाई के बिना हमेशा प्रयोग किये जा सकते थे, तथापि ऐसे शाश्वत न्याय का अस्तित्व सामान्यतः स्वीकृत किया जाता था और अन्ततः इसी से आधुनिक राष्ट्रों की विधि के विकास का बीज बोया गया।

यूनानी विचारधारा—यूनानी लोग अपने पड़ोसियों से जिन्हें वे जंगली समझते थे अधिक सम्म्य थे। इन्होंने यूनानी मंडल (Hellenic Circle) के तथा उससे बाहर के राज्यों में अन्तर रक्खा। उनका विश्वास था कि म-यूनानी लोग प्रकृति द्वारा ही यूनानी लोगों की दासता के लिये रचे गये हैं। यूनानियों की विधियाँ तर्क के नियम अर्थात् देवी नियम से प्राप्त की गई थी और उनको मनुष्य जाति की प्रकृति के अनुसार, जो कि स्वभावतः विवेकपूर्ण होती है, कार्य करने को बाध्य करती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप में यूनानी नगर-राष्ट्रों ने इतिहास के लिए एक ऐसे सामुदायिक जीवन का उदाहरण रक्खा जो एक समान जाति, धर्म, रुढ़ियाँ तथा भाषा पर स्थापित था। उन्होंने प्राकृतिक विधि (Jus naturale) की भावना को और दृढ़ किया और सारे विश्व को एक मौलिक सिद्धांत से, जिसे वे प्रकृति का नियम कहते थे, अनुशासित देखा। सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine) का कहना है कि "मसार के भौतिक तथा नैतिक तत्व कुछ साधारण तथा सामान्य नियमों में स्थिर किये जा सकते हैं और इनको वे प्रकृति के नियम कहते थे। ये वे नियम हैं जिनको प्रकृति ने पथ-निर्देशक दृष्टि के रूप में प्रकट किया और उन पर चलने की आज्ञा दी।"

"They thought that the material and moral phenomena of the world could be resolved into simple and general rules and they called

them the Laws of Nature They are the rules which Nature, personified as a guiding power, is deemed to have evolved and prescribed "

**रोमन विचार-धारा**—रोम-वासियों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के लिये एक बहुत ही प्रगतिशील धारणा थी जिसका विकास उन्होंने प्राकृतिक नियम की सहायता से किया। उनके यहाँ दो प्रकार की विधियाँ थी —

(१) **जस सिविली (Jus Civile)** अथवा दीवानी विधि जो इस प्रकार की विधि तथा रूढ़ियाँ थी जो रोमन निवासियों पर लागू होती थी, तथा

(२) **जस जेन्टियम (Jus Gentium)** अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विधि वह विधि थी जो उनमें और अन्य राष्ट्रों में समान थी। वह विधि प्राकृतिक तर्क पर आधारित थी और मनुष्यमात्र के लिए बनाई गई थी। इसी जस जेन्टियम को आगे चलकर जस नेचुरेल (Jus Naturale) अर्थात् प्राकृतिक विधि कहने लगे।

**सिसरो (Cicero)**—सिसरो महोदय का कथन है कि सच्चा कानून (lex) वह होता है जिसमें उचित तर्क और प्रकृति का साम्य हो जाता है और जो मनुष्य-मात्र में परिवर्तित रूप से निरन्तर के लिए व्याप्त हो जाता है। न तो इस कानून का परिवर्तन हो सकता है, न इसका महत्व कम किया जा सकता है और न कोई इसकी उपेक्षा ही कर सकता है।

**प्राकृतिक नियम पर मेन (Maine) महोदय का मत**—सर हेनरी मेन प्राधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में प्राकृतिक नियम के विचार की महत्ता पर जोर देते हुये अपने 'ऐंशियेंट लॉ' "Ancient Law" में कहते हैं कि प्राकृतिक नियम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्राधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा प्राधुनिक युद्ध-विधि को जन्म देने में पूर्ण हुआ। जैसा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मूल निर्माताओं ने लिखा है, उन स्वयं-सिद्ध प्रमाणों में से, जो इसकी अभिधारणा है, तीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। वह अभिधारणा जो कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आधार है, प्रथम यह है कि निर्धारित किये जाने वाला एक प्राकृतिक नियम ग्रोशस (Grotius) महोदय तथा उनके अनुयायियों ने सीधे रोम निवासियों से लिया, परन्तु उनके निर्धारित करने की रीति के विषय में उनके विचार आपस में एक दूसरे से तथा रोम के विधि-वेत्ताओं से बिल्कुल भिन्न थे। इन्हीं ग्रोशस महोदय को प्राधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रवर्तक माना जाता है।

**द्वितीय अभिधारणा** यह है कि राष्ट्रीय विधि राज्यों पर आपस में बाध्य है। प्रकृति के राज्य में राष्ट्र मगल एक दूसरे से सम्बद्ध हैं, अतः प्राकृतिक नियम राज्यों पर परस्पर बाध्य हैं। वास्तव में सत्य यह है कि प्राधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि

यद्यपि रोमन विधि (Roman Law) की वसाज है तथापि यह उससे उल्टे ढंग से सम्बद्ध है। उपरोक्त से जो साध्य निवसता है वह यह है कि स्वतन्त्र जातियाँ प्राकार तथा शक्ति में चाहे कितनी ही भिन्न हो विन्तु राष्ट्रों की विधि की दृष्टि में सब समान हैं।

तीसरी अभिधारणा यह है कि प्रभुसत्ता (sovereignty) प्रादेशिक होती है और सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न व्यक्तियों (sovereigns) को परस्पर सार्वभौमिकता (paramount) पर विचार न किया जाय वरन् उन्हें राष्ट्र रूपी प्रदेश का निरंकुश स्वामी समझा जाय।

प्रोशास के पूर्व प्राकृतिक नियम—इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पवित्र रोमन साम्राज्य का टुकड़ो-टुकड़ो में विभाजन तथा पोप-समूह ने प्रभुत्व के धीरे-धीरे कम होने का प्रभाव प्राकृतिक नियम पर बहुत अधिक पड़ा परन्तु प्राकृतिक नियम के अक्रूर जो अपनी जड़ जमा चुके थे पूर्णतः मुरझा नहीं गये। पन्द्रहवीं शताब्दी में हम देखते हैं कि कला तथा साहित्य का पुनरुत्थान हुआ। यह एव मध्य युग से प्राधुनिक ससार में प्रवेश करने का लक्षण था। नई दुनिया का भी अन्वेषण हो गया था। इन सब तथ्यों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सह-संबंध का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो गया। स्पेन के अख्यात्मवादी विटोरिया (१४८०-१५४६) ने स्पष्ट शब्दों में यह सिद्धान्त घोषित किया कि ससार के राष्ट्र मिलकर एक समुदाय बनाते हैं जो प्राकृतिक तर्क तथा सामाजिक सह-संबंध पर आधारित हैं। १५८२ में बल्येजार अयाला (Balthazar Ayala) (१५४८-१५८४) ने दोभाई (Douai) में अपनी पुस्तक 'De Jure et Officiis Bellicis' प्रकाशित की और समान सहमति द्वारा स्थापित 'Jus Naturale' और 'Jus Gentium' के पक्ष का समर्थन किया। उसका अनुवर्ती अल्बेरिकस जेटिलिस (Albericus Gentilis) (१५५२-१६०८) एक इटली निवासी प्रोटेस्टेन्ट था। उसे अपने प्रोटेस्टेन्ट विचारों के कारण इंग्लैंड भागना पड़ा था। उसने अपना ग्रन्थ 'De Jure Belli Libri Tres' सन् १५६८ में प्रकाशित किया और प्राकृतिक तर्क तथा सहमति पर आधारित युद्ध के अस्तित्व पर बल दिया। सबसे अन्त में स्पेन-निवासी सुमारेज (Jesuit Francis Suarez) (१५४८-१६१७) आता है। उसने अपना ग्रन्थ 'Tractatus de Legibus et Deo Legislatore' १६१२ में प्रकाशित किया। उसने इस बात पर महत्व दिया कि 'Jus Gentium' नैतिक रूप से बाध्य है और यह कहा कि भिन्न-भिन्न राज्य यद्यपि स्वतन्त्र हैं फिर भी वे मनुष्य जाति के सदस्य हैं, अतः प्राकृतिक तर्क तथा रूढ़ि पर आधारित आचरण की विधि से बाध्य हैं। उसने मनुष्य जाति के नैतिक ऐक्य तथा प्राकृतिक तर्क और साधारण रूढ़ि द्वारा अनुशासित राष्ट्रों के समाज पर महत्व दिया जो अन्तिम विस्लेषण के आधार पर ईश्वरेच्छा पर निर्भर माना गया है।

ग्रोशस (Grotius) (१५८३-१६४५)—ह्विग वैन गूट (Hug van Groot) जो जनसाधारण में ह्यूगो ग्रोशस (Hugo Grotius) के नाम से प्रसिद्ध है, का जन्म हाल्लैंड में डेलफ (Delft) नामक स्थान में १५८३ में हुआ। उसको 'राष्ट्रों की विधि का पिता' (Father of the Law of Nations) की उपाधि दी जाती है। उसका सबसे प्रमुख 'ग्रन्थ डी जूरे वेली ऐक् पेसिस' (De Jure Belli ac Pacis) फ्रांस में प्रकाशित हुआ। व्हीटन (Wheaton) कहते हैं कि "ग्रोशस (Grotius) तथा उसके निकटवर्ती शिष्यों तथा अनुयायियों का उस विज्ञान में जिसका वह संस्थापक था, प्रमुख उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि, प्रथम तो न्याय के उन नियमों को निर्धारित किया जाय जिससे सामाजिक स्थिति में रहने वाले अथवा जैसा साधारण रूप से कहा जाता है 'प्राकृतिक अवस्था में साथ रहने वाले' मनुष्य पर मानवीय संस्थाओं के स्थिर नियमों से स्वतंत्र रूप से बाध्य हो, तथा दूसरे यह कि उन नियमों को, प्राकृतिक नियम के नाम में भिन्न-भिन्न समुदायों के जो कि आपस में समान दशा में रहते हैं, पारस्परिक सम्बन्धों में लागू करना किया जाय।"

ग्रोशस ने राष्ट्रों की विधि तथा प्राकृतिक विधि में यह भेद बतलाया कि उनकी उत्पत्ति पृथक् है और राष्ट्रों की विधि का यह गुण बतलाया कि इसमें राष्ट्रों की सामान्य सहमति है। उसने दार्शनिकों, इतिहासकारों, कवियों तथा व्यक्तियों के साक्ष्य का भी प्रयोग अपने द्वारा प्रतिपादित विधि के पक्ष में किया, इसलिए नहीं कि उस पर निष्पक्ष प्रमाण के रूप में विश्वास कर लिया जाय, क्योंकि वे अपने-अपने सम्प्रदाय के पक्षपात में अपने तर्कों अथवा अपने उद्देश्यों के लक्ष्य को मोड़ देते थे, परन्तु इसलिए, कि जहाँ भिन्न-भिन्न युगों के तथा देशों के लोग एक ही बात पर सहमत हो वहाँ पर यह कहा जा सकता है कि अवश्य ही कोई सामान्य कारण है जिसके कारण सभी उन्हें विधि-रूप में मानते हैं।

रिचर्ड ज़ाउचे (Richard Zouche) (१५६०-१६६०)—एक और अंग्रेजी विद्वान ज़ाउचे (Richard Zouche) हैं, जिनको 'राष्ट्रों की विधि का द्वितीय संस्थापक' (Second Founder of the Law of Nations) की उपाधि दी जाती है। उसने राष्ट्रों की रूढ़-विधि के पक्ष का समर्थन किया और ऐसा करने में उसका ग्रोशस से अत्यन्त मतभेद हो गया, परन्तु उसने राष्ट्रों के प्राकृतिक नियम का पूर्णतया परित्याग नहीं किया।

हॉब्स और पफेनडॉर्फ (Hobbes and Pufendorf)—हॉब्स (Hobbes) ने प्राकृतिक नियम को दो भागों में विभाजित किया—(१) मनुष्यों का प्राकृतिक नियम और (२) राज्यों का प्राकृतिक नियम, जिसे सामान्यतः राष्ट्रों की



विधि कहते हैं। उनका कथन है कि 'दोनो की धारणाएँ एक ही हैं, परन्तु राज्य ज्यों ही स्थापित होता है मनुष्य के व्यक्तिगत गुणों का समावेश कर लेता है। यह वह विधि जो व्यक्तिगत मनुष्यों के सम्बन्ध में 'प्राकृतिक नियम' कह कर सम्बोधित की जाती है जब सम्पूर्ण राज्यों, जातियों तथा लोगों में लागू की जाती है तो 'राष्ट्रों की विधि' के नाम से सम्बोधित होने लगती है। पफेनडॉर्फ (Pufendorf) (१६३२-१६९६) ने हॉब्स (Hobbes) के मत को स्वीकार किया और इतना और कहा कि "वरिष्ठ शक्ति की आज्ञाओं में जितनी बाध्यता है, उतनी अन्य किसी भी राष्ट्र की ऐच्छिक भयवा निश्चयात्मक विधि में, जिसे कि हम सही और वैध रूप में प्रवर्तित कह सकें, नहीं पायी जाती।" "There is no other voluntary or positive law of nations properly invested with a true and legal force, and binding as the command of a superior power" उन्होंने राष्ट्रों की व्यवहारिकता को बाध्यता की शक्ति से सम्पन्न कहापि स्वीकार नहीं किया।

बिंकरशोके (Bynkershoek)—इन्होंने राष्ट्रों की विधि का आधार तर्क तथा रीतियों को माना और सन्धियों तथा अध्यादेशों (प्रोविनन्सो) के साथ ही रीतियों का उद्भव बताया।

वेटेल (Vattel)—इनका कथन है कि राष्ट्रों की विधि मूल में राष्ट्रों में लागू किये गये प्रकृति के नियमों के प्रतिरिक्त अन्य कुछ नहीं थी। उन्होंने कहा कि सब नागरिक समाजों (civitas) का यह स्वत्व है कि उसका प्रत्येक सदस्य अपने अधिकारों का कुछ भाग समाज के समुदाय को त्याग दे और एक ऐसी बरिष्ठ सत्ता विधान रहे जो अपने सब सदस्यों को आज्ञा देने में समर्थ हो, उनको विधि दे सके तथा जो आज्ञा न मानें उनको दंडित कर सके। राष्ट्रों के बीच में ऐसी किसी बात का अस्तित्व न तो बिचारा जा सकता है न उनकी कल्पना की जा सकती है। प्रत्येक प्रभुसत्ता-धारी राष्ट्र अपने को पूर्णतः स्वतन्त्र दिखाते हैं और वास्तव में ऐसा है भी।

आधुनिक युग में प्राकृतिक विधि—ओपेनहेम (Oppenheim) ने ठीक ही कहा है कि प्रकृति के नियम में वह बैसाखी (crutches) दी जिनकी सहायता से इतिहास न मनुष्य-जाति को मध्ययुग की सत्ताओं से निकाल कर आधुनिक युग की सत्ताओं में आना सिखाया। आधुनिक राष्ट्रों की विधि अपने अस्तित्व के लिये ही प्राकृतिक विधि के सिद्धान्त की ऋणी है। प्रोपस ने प्राकृतिक नियम को असांख्य-वाकिक बनाने तथा इसके शुद्ध धार्मिक पथ से मुक्त करने का दृढ़ कदम उठाया।

यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि यद्यपि प्राकृतिक विधि का अन्तर-राष्ट्रीय विधि के विकास में बहुत बड़ा हाथ है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता

कि यह सिद्धान्त आलोचना से रहित है। ओशेस ने 'क्या होना चाहिये' इस आदर्श विचार को 'यह वास्तव में क्या है' इसको साथ मिला कर स्वयं भ्रम में पड़ गया। लारेस कहते हैं कि "यदि उसका विचार ठीक होता तो प्राकृतिक नियम के मूलभूत सिद्धान्तों तथा अधिक प्रमुख नियमों के सम्बन्ध में सर्वदा सामान्य सहमति रही होती। परन्तु इस प्रकार की किसी वस्तु का कभी अस्तित्व ही नहीं रहा है। विधि-वेत्ताओं तथा दार्शनिकों में आपस में बहुत मतभेद रहा है क्योंकि मनुष्यजाति के विशाल जनसमूह ने मिथ्या रूप से भी यह नहीं दर्शाया कि वे इस विषय को समझते हैं।" जैसा कि ब्रियरली (Brierly) महोदय ने कहा है कि मध्ययुग के लेखकों ने यह घोषणा करके कि विरोध की दशा में प्राकृतिक विधि निश्चयात्मक नियमों को रद्द कर सकती है, एक प्रतिकूल सिद्धान्त को प्रवृत्त कर दिया है, जो भयानक है। उन्होंने विधान के कार्य को वर्तमान विधि क्या है इसे ढूँढने के कार्य के साथ मिलाकर गड़बड़ी उत्पन्न कर दी जब कि उनका यह मत था कि विधि के नियम का युक्तिसंगत न होना उसको अवैध कर सकता है।

## अध्याय ५

### राष्ट्रों की विधि का संहिताकरण

#### (Codification of the Law of Nations)

परिभाषा :—संहिता सविधियों का एक संकलित रूप है (A code is a consolidation of the statute law.); अथवा यह एक संग्रह है जिसमें किसी विशेष विषय सम्बन्धी सभी सविधियों का संग्रह है। संहिताकरण यह क्रिया है जिसके द्वारा सविधियों (statutes), अभिसमय (conventions) रूढ़-विधि (customary laws) अथवा न्यायाधिकरणों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले नियम स्वल्प अथवा बिना किसी परिवर्तन के लेखबद्ध विधियों के रूप में बदल दिये जाते हैं। यह सामान्य अभिसमय द्वारा राज्यों के बीच में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषयों के बारे में करार प्राप्त करता है तथा एक अकुल के समान कार्य करता है जिससे किसी विशेष विधि का निर्णय केवल न्यायाधीशों के मन पर ही न छोड़ दिया जाय। यह विरोधी विचारों को समाधान करने की प्रवृत्ति रखता है और भिन्न-भिन्न राज्यों के बीच में सहमति या सौहार्द संभव करना है।

लाभ—सहिताकरण द्वारा किसी विशेष विषय में क्या विधि है इसका शीघ्र ही पता लगाया जा सकता है और एक विशाल क्षेत्र में एकता लाई जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि का दोष यह है कि यह अनिश्चित है। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मशीन इतनी कुशल नहीं है जितनी राज्य की विधानकारी मशीन। सहिताकरण विभिन्न राज्यों के बीच के विरोधी विचारों का समाधान करके उन विभिन्न इकाइयों को विधि के एक बड़े भाग को एक सूत्र में बाँध देता है जो कि अन्यथा विभिन्न तथा विरोधी सम्मतियों के विषय बने रहते हैं।

यत्नपूर्वक सकलित सहिता न्यायाधीश को न्याय करने में बड़ी सहायता पहुँचाती है। न्यायाधीश लोग व्याख्या की क्रिया द्वारा बहुत से दोषों का समाधान कर सकते हैं जिनका प्रायः सहिताकरण में समावेश हो जाता है।

रुढ़ि द्वारा विधि के विकास की गति बहुत ही मन्द रहती है। समय का विकास, नये हितों का प्रादुर्भाव तथा नये अविवेकारों के साथ समाज का ढाँचा दिन प्रतिदिन जटिल होता जा रहा है। स्थितियों तथा वातावरण में प्रायः इतनी शीघ्रता से परिवर्तन हो रहा है कि किसी राष्ट्र की निश्चयारमक विधि को उनके साथ चलना कठिन हो जाता है। अतः सहिताकरण इन उन्नतियों तथा विकाशों से उत्पन्न हुई समस्याओं को सुलझाने के लिये आवश्यक हो जाता है और विधि के विज्ञान को प्रोत्साहित करता है।

बहुत से आवश्यक विषयों के सम्बन्ध में जो मतभेद तथा गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है विधि के सहिताकरण से नुस्त हो जावेगी।

विभिन्न विधि के सहिता में एक सकलित रूप में उपस्थित होने पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा अन्य न्यायाधिकरणों को, प्रस्तुत विवादों का निर्णय करने में अत्यन्त सहायता पहुँचेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सहिताकरण इसकी स्पष्टता तथा प्रामाणिकता में वृद्धि करता है और इसके फलस्वरूप राष्ट्रों को अपने को न्यायिक अथवा पचासती निर्णयों के अधीनस्थ करने को कुछ सीमा तक बाध्य करता है।

संक्षिप्त इतिहास—राष्ट्रों की विधियों के सहिताकरण के विचार पर सब से प्रथम अठारहवीं शताब्दी के अन्त में वेनियम द्वारा तर्क-वितर्क किया गया। उसने एव ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि की कल्पना की जो सम्य राष्ट्रों के बीच निरन्तर शान्ति का आधार हो सकती थी।

वास्तविक सहिताकरण का प्रयत्न पेरिस की घोषणा पर सन् १८५६ में किया गया। क्रीमिया के युद्ध के अन्त में इस घोषणा पर ग्रेट-ब्रिटेन, फ्रान्स, प्रुशिया,

रूप, प्रशा, सादोनिमा तथा टर्की द्वारा हस्ताक्षर किये गये । चार सिद्धान्त निर्धारित हुये :—

(१) शत्रुओं के जहाजों का चूटना बन्द कर दिया जाय ;

(२) तटस्थ भूदे के आवरणमें शत्रु के माल का संरक्षण, युद्ध सम्बन्धी प्रतिपिद्ध पदार्थों को छोड़कर, रहता है ।

(३) शत्रु के भूदे के नीचे तटस्थ राष्ट्रों का युद्ध सम्बन्धी प्रतिपिद्ध पदार्थों को छोड़कर अन्य माल उन्त न किया जाय ।

(४) नाकाबन्दी वास्तविक तथा बाध्य होने के लिये कार्य के साधन के रूप में की जानी चाहिये ।

वाशिंगटन की सन्धि जो ८ मई सन् १८७१ को संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन के मध्य में हुई उसमें उनके मतभेदों को तय करने के अतिरिक्त तटस्थ राष्ट्र के समुद्र में जहाजों को सुरक्षित करने तथा उसके बन्दरगाहों के उपयोग करने पर उसके क्या कर्तव्य हैं इस सम्बन्ध में भी निर्णय किया गया ।

सन् १८७२ में डडलेफील्ड (Dudley Field) ने “अन्तर्राष्ट्रीय विधि की रूपरेखा का मसौदा” (Draft Outlines of an International Code) प्रकाशित किया ।

सन् १८७४ में रूस के अलेक्जेंडर द्वितीय (Alexander II) की प्रेरणा पर ब्रसेल्स सम्मेलन (Brussels Conference) ने साठ अनुच्छेदों के समूह का मसौदा ‘ब्रसेल्स की घोषणा’ के नाम से किया परन्तु वे अनुच्छेद शक्तियों द्वारा सरपाकित नहीं किये गये ।

हेग सम्मेलन—सन् १८६६ में हेग सम्मेलन न जो रूस के निकोलस द्वितीय के अभिमन्त्रण पर बुलाई गई थी, दो प्रमुख अभिसमय संहिता के रूप में बनाये गये :—

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का दान्तिपूर्वक निपटारा करने के लिये अभिसमय (Convention for the Pacific Settlement of International Disputes), और

(आ) भूमियुद्ध सबंधी विधि तथा उसके रूढ़ि सम्बन्धी अभिसमय (Convention with respect to the Laws and Customs of War on Land) ।

सम्मेलन में २६ शक्तियों ने भाग लिया । इनकी प्रतिज्ञाएँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण की सीमाचिह्न हैं ।

१९०७ के हेग सम्मेलन ने तेरह अभिसमय निमित्त किये जिनमें से कुछ समुद्री विधि के भागों के संहिताकरण हैं । उनमें भूमि तथा समुद्र पर युद्ध और तटस्थता

सम्बन्धी नियमों को भी व्यवस्था की गई है। सम्मेलन में ४४ स्वतन्त्र प्रभु सत्तावादी राष्ट्रों ने भाग लिया।

लंदन की घोषणा (Declaration of London) — सन् १९०६ के लंदन के समुद्रीय सम्मेलन में प्रतिषिद्ध करने के प्रयोजन से वस्तुओं की एक संमत सूची बनाने का प्रयत्न किया गया। इसके निर्णय लंदन की घोषणा (१९०६) में सम्मिलित किये गये, परन्तु घोषणा पुष्टीकृत न होने के कारण लागू नहीं हुई। प्रथम विश्वव्यापी महायुद्ध सन् १९१४, और तदनन्तर १९३९, के सघात ने लंदन की घोषणा को प्राधिकार के शेष अंश से भी वंचित कर दिया।

लीग ऑफ नेशन्स (The League of Nations) : — दि लीग ऑफ नेशन्स ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण में तीव्र रुचि दिखाई। सन् १९२४ में लीग की परिषद् (Council) ने सभा (Assembly) के क्रम में विशेषज्ञों की एक समिति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण पर प्रतिवेदन करने के लिये तथा संहिताकरण के लिये परिपक्व विषयों को छांटने के लिये नियुक्त की। सन् १९२७ में अपने प्रतिवेदन में समिति ने निम्नलिखित विषयों को संहिताकरण के योग्य मान कर प्रस्तुत किया : (१) राष्ट्रिकता, (२) प्रादेशिक समुद्र, (३) किसी राष्ट्र की उसके प्रदेश में विदेशियों के शरीर अथवा सम्पत्ति को पहुँचाई गई हानि के लिये उत्तरदायित्व, (४) राजनैतिक विशेषाधिकार तथा अनुभूतियाँ, (५) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा सन्धिओं का सौदा तैयार करने की प्रक्रिया, (६) समुद्री डकैती, तथा (७) समुद्र के उत्पन्न पदार्थों का उपयोग।

सितम्बर १९२७, में सभा (Assembly) ने समिति द्वारा परिषद् (Council) को दिये गये प्रतिवेदन तथा परिषद् के उस पर कथन का परीक्षण किया और निम्नलिखित तीन विषयों पर विधि के संहिताकरण के प्रयोजन के लिये हेग में एक सम्मेलन बुलाया :—

(१) राष्ट्रिकता,

(२) प्रादेशिक समुद्र,

(३) किसी राष्ट्र की उसके प्रदेश में विदेशियों के शरीर तथा सम्पत्ति को पहुँचाई गई हानि के लिये उत्तरदायित्व।

इसमें अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उत्तरोत्तर संहिताकरण के लिए पहला सम्मेलन हेग में सन् १९३० में मार्च १३ से अप्रैल १२ तक हुआ। इसमें तीन सत्रियाँ उद्घाटित तीन विषयों में से प्रत्येक के लिये एक-एक बनी। राष्ट्रिकता सम्बन्धी प्रथम समिति के विचारों के परिणामस्वरूप परिषद् ने निम्नलिखित बातों को स्वीकृत किया :

(प्र) राष्ट्रिक विधियो (Nationality Laws) के संघर्ष सम्बन्धी कुछ प्रश्नो व सम्बन्ध मे एक अभिसमय ।

(भा) दाहरी राष्ट्रिकता के (Double Nationality) कुछ मामलो मे सैनिक आभार सम्बन्धी सलेख (Protocol) ।

(इ) ऐसा कोई मामला जिसमे कोई राष्ट्रियता ही न हो तत्सम्बन्धी सलेख (Protocol) ।

(ई) राष्ट्रिकतारहित मामला सम्बन्धी एक विशेष सलेख (Protocol) ।

बाद में ये अभिसमय कई राष्ट्रों द्वारा सर्याकित किये गये । प्रादेशिक समुद्रों के बारे में कोई अभिसमय उस समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा सका जिसको यह कार्यभार सौंपा गया था क्योंकि प्रादेशिक समुद्रों की चौड़ाई के प्रश्न के सम्बन्ध में तथा उसके निकटवर्ती मिले हुए भूमण्डल की समस्या के सम्बन्ध में कोई सविदा नहीं हो सकी । सम्मेलन में राष्ट्रीय उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में विशेषतः अन्य देशीय निवासियों के साथ व्यवहार के सम्बन्ध में भी कोई सहमति न हो सकी ।

लीग के संरक्षण में युद्ध की विधि के क्षेत्र में भी बहुत से अभिसमय बनाये गये । वर्साई की संधि के अनुच्छेद १७१ द्वारा दम घोटने वाली विपैली अथवा अन्य गैसों का उपयोग निषिद्ध किया गया और जर्मनी में इसका निर्माण रोक दिया गया । १९२१-१९२२ के वाशिंगटन सम्मेलन में यह यदन किया गया कि शस्त्रीकरण की परिसीमन पर एक सविदा हो जाय परन्तु सम्मेलन अपने प्रारम्भिक कार्य से दूर चला गया और उसने युद्ध सम्बन्धी नियमों को बनाया जिनके द्वारा विपैली गैसों के प्रयोग को रोकता और पनडुब्बी जहाजों की युद्ध की रीतियों को निर्धारित किया । इन क्षेत्रों में हमके परिश्रम को वर्तमान विधि की संहिताकरण की श्रेणी में नहीं बरन् एक नये विधान की श्रेणी में रक्खा जाना चाहिये ।

सन् १९२३ में न्यायविशारदों के एक आयोग ने वायु-युद्ध सम्बन्धी नियमों को बनाया ।

सन् १९२५ में लीग की परिषद् के निमन्त्रण पर कई राष्ट्रों का एक विशेष अधिवेशन हुआ जिन्होंने दम घोटनेवाली विपैली अथवा अन्य गैसों को निषिद्ध करने वाले एक सलेख (protocol) पर हस्ताक्षर किये । जुलाई १९२६ में स्विटजरलैंड की सरकार के निमन्त्रण पर ४७ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने युद्ध-क्षेत्र में पड़े हुए सैनिकों के बीमारों तथा घायलों और युद्धबन्दीयों के प्रबन्ध सम्बन्धी संशोधित अभिसमय को बनाया ।

संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिकार-पत्र (Charter) तथा संहिताकरण :—  
संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार-पत्र के अनुच्छेद १३ में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण के लिये पर्याप्त अवसर दिया गया है । उसमें कहा गया है कि—

(१) सामान्य सभा निम्नलिखित प्रयोजन के लिये अध्ययन प्रारम्भ करावेगी तथा प्रतिवेदन करेगी,

(अ) राजनैतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि और इसके संहिताकरण का उत्तरोत्तर विकास ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग ( The International Law Commission ) :-

संयुक्त राष्ट्र संघ का अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग सामान्य सभा के दिनांक नवम्बर २१, सन् १९४७, के प्रस्ताव द्वारा अधिपत्र (चार्टर) के अनुच्छेद १३ (१) (घ) को पूर्ण करने के लिये नियुक्त किया गया जिसके द्वारा सामान्य सभा को यह भार सौंपा गया है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा इसके संहिताकरण के उत्तरोत्तर विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अध्ययन प्रारम्भ करावे और सिफारिश करे ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग की सविधि (Statute) के अनुच्छेद १ में यह व्यवस्था की गई है कि कमिशन का लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि की उत्तरोत्तर वृद्धि तथा इसका संहिताकरण होगा । यह मुख्यतः सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि से सम्बन्धित है परन्तु इसके लिये वैयक्तिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में प्रवेश करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

संविधि (Statute) :- आयोग (Commission) १५ सदस्यों का बना है जिसमें अनुच्छेद २ के अनुसार ऐसे व्यक्ति होने चाहिये जिनको अन्तर्राष्ट्रीय विधि में योग्यता के लिये मान्यता प्रदान की गई हो । आयोग के कोई भी दो सदस्य एक ही राज्य के न होने चाहिये । आयोग के सदस्य सामान्य सभा द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की सरकारों द्वारा नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों की सूची में से निर्वाचित होते हैं । (अनुच्छेद ३)

अनुच्छेद १८ के अन्तर्गत आयोग को इस कार्य का भार सौंपा गया है कि वह संहिताकरण के विषयों का सकलन करने के उद्देश्य से वर्तमान मसौदों (Drafts) को, चाहे वे सरकारी हों अथवा नहीं, ध्यान में रखते हुये अन्तर्राष्ट्रीय विधि के संपूर्ण क्षेत्र का पर्यवेक्षण करे । जब आयोग समझता है कि किसी विशिष्ट विषय का संहिताकरण आवश्यक है अथवा वांछनीय है तो इसे अपनी सिफारिशों को सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है ।

नवम्बर २१, सन् १९४७ को सामान्य सभा ने आयोग को यह निर्देश दिया कि (घ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि जिसका विनूरम्बर्ग न्यायाधिकरण के चार्टर तथा उक्त निर्णय में मान्यता प्रदान की गई है, उसके सिद्धान्तों को सूचित करे, (घा) अनुसूचित जाति की शांति तथा सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की संहिता का मसौदा तैयार

और उसमें यह स्पष्ट रूप से दिसतावे कि उपरोक्त उप-अनुच्छेद (घ) में कथित सिद्धान्तों को क्या स्थान दिया जाय । आयोग से यह भी कहा गया कि यह राष्ट्रों के अधिकार तथा कर्तव्यों की घोषणा का मसौदा तैयार करे और जनवध (genocide) तथा कुछ अन्य अपराधों के परीक्षण के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्था के स्थापन की संभावनाओं का अध्ययन करे ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सर्वेक्षण तथा संहिताकरण के लिए विषयों का चुनाव :—  
आयोग ने निम्नलिखित तीन विषयों का प्राथमिकता देने का निर्णय किया :—

(१) सन्धियों की विधि (Law of Treaties), (२) पंचायती प्रक्रिया (Arbitral Procedure), (३) समुद्रों की शासन-पद्धति (Regime of the High Seas) ।

राज्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की घोषणा का मसौदा (Draft Declaration on Rights and Duties of States) :—

आयोग ने राज्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की घोषणा का मसौदा तैयार करने का कार्यभार अपने ऊपर लिया और इसकी विवेचना का आधार पनामा द्वारा प्रस्तुत किये गये राज्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की घोषणा का मसौदा रखता और इसके साथ ही इस विषय पर अन्य लेखों तथा मसौदों को भी ध्यान में रखा गया । इसने न कि बंधनकारी नियमों (binding rules) को पद्धति के रूप में वस्तु-भाचरण के स्तर के रूप में सामान्य सभा द्वारा ग्रहण तथा घोषित किये जाने के लिये एक घोषणा तैयार की । भिन्न-भिन्न धाराओं के द्वारा जो कि संस्था में १४ ये राष्ट्रों के चार अधिकारी घोषित किये—स्वतन्त्रता के अधिकार, राष्ट्रीय प्रदेश के ऊपर क्षेत्राधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा स्वीकृत उन्मुक्तियों के अधीन व्यक्तियों तथा वस्तुओं के ऊपर अधिकार, समानता के अधिकार और सैनिक भाग-मण होने पर व्यक्तिगत तथा सामूहिक-सुरक्षा के अधिकार ।

अक्टूबर १९५२ तक १८ सदस्य राष्ट्रों ने अपनी-अपनी टिप्पणियाँ भेज दी । सभा के पाँचवें अधिवेशन की छठी विधिक समिति ने यह निर्णय किया कि राज्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों की घोषणा के मसौदा पर विचार करने के पूर्व अन्तिम प्रतिवेदनों (रिपोर्टों) की प्रतीक्षा की जाय ।

नूरम्बर्ग सिद्धान्तों का निरूपण (Formulation of Nuremberg Principles) :—अपने दूसरे अधिवेशन में (जून ५-जुलाई २६, १९५०) आयोग ने उन अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सात सिद्धान्तों की एक धोखी बनाई जो कि



न्यायाधिकरण के चार्टर तथा उसके निर्णय में स्वीकृत किये गये थे। वे निम्न-लिखित हैं :—

(१) कोई व्यक्ति जो ऐसा कार्य करता है जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत एक अपराध है वह उसके लिये उत्तरदायी है और दंड का भागी है।

(२) यदि कोई कार्य जिसकी गणना अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अपराध में है, पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत दंडनीय नहीं है, किसी व्यक्ति द्वारा किया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत वह व्यक्ति उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होता।

(३) यदि कोई कार्य जिसकी गणना अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अपराध में है, किसी व्यक्ति द्वारा राज्य के अध्यक्ष अथवा उत्तरदायी सरकारी पदाधिकारी के रूप में किया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत वह व्यक्ति उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होता।

(४) यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा अपनी सरकार अथवा अपने से सर्वोच्च के आदेशानुसार किया जाय तो वह व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत इस अनुबन्ध के साथ कि उस व्यक्ति के लिये नैतिक विकल्प (moral choice) सभ्य रहा हो, दायित्व से मुक्त नहीं होता।

(५) अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अपराध के लिये आरोपित किसी व्यक्ति को तथ्य तथा न्यायानुसार उचित विचारण (trial) का अधिकार है।

(६) यथाक्रम रखे हुये अपराध अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अपराधों के रूप में दंडनीय हैं (अ) शान्ति के विरुद्ध अपराध, (घा) युद्धापराध, (ङ) मानवता के विरुद्ध अपराध।

(७) सिद्धान्त ६ में यथोल्लिखित शान्ति के विरुद्ध अपराध, युद्धापराध अथवा मानवता के विरुद्ध अपराध में भाग लेना भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अपराध है।

सभा ने अपने १९५० के अधिवेशन में प्रायोग की सिफारिशों को सार्व-राष्ट्रों की सरकारों के पास उनकी टिप्पणी के लिए भेजा।

प्रथागत अन्तर्राष्ट्रीय विधि (Customary International Law) — प्रायोग ने अपने दूसरे अधिवेशन में यह प्रतिवेदित किया कि संयुक्तराष्ट्रों के प्रती द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सम्बन्ध में किये गये प्रवक्तव्यों का यथासंभव विस्तृत रूप में वितरण किया जाय, और यह कि सभा अपने सचिवालय (secretary) को यह अधिकृत करे कि वह प्रवक्तव्यों का आठ मसूदा बनावे और उनको विस्तृत रूप में वितरण करे जिससे प्रथागत अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सादर अधिक गुणवत्ता के

प्राप्त हो सके और यह कि सभा सरकारों का ध्यान अपने राजनैतिक पत्र-व्यवहार के सक्षिप्त संग्रह के प्रकाशन की उपादेयता की ओर आकर्षित करे ।

**अग्रघर्षण ( Aggression ) की परिभाषा :—**यद्यपि आयोग ने अपने तीसरे अधिवेशन में जेनेवा में (मई १६ से जुलाई २७ सन् १९५१ तक) प्रयत्न अग्रघर्षण को परिभाषित नहीं किया था क्योंकि इसकी परिगणना करना कठिन था तथापि इसने पुनर्विचार पर यह निश्चित किया कि अग्रघर्षण की सामान्य परिभाषा का समावेश मनुष्यजाति की शांति तथा सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की संहिता के मसौदे में कर दिया जाय । शब्द 'अग्रघर्षण' में कोई अग्रघर्षण का कार्य जिसमें किसी राष्ट्र के अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय अथवा सामूहिक आत्मरक्षा में अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सक्षम अंग के निर्णय अथवा सिफारिश (recommendation) के अनुसार किये गये बलप्रयोग से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध सैनिक बल का उपयोग भी सम्मिलित था ।

**मनुष्य जाति की शांति तथा सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की संहिता का मसौदा (Draft Code of Offences against the Peace and Security of Mankind) :—**आयोग ने अपने दूसरे अधिवेशन में इस विषय पर एक मसौदा तैयार किया जो सभा के समक्ष उसके १९५० के अधिवेशन में उद्घोषित किया गया । सभा ने अपने सदस्य-राज्यों से टिप्पणियाँ माँगी ।

अपने तीसरे अधिवेशन में आयोग ने एक संहिता का मसौदा तैयार किया और अपना तत्पर्य उन्हीं अपराधों तक सीमित रखता जिनमें कोई राजनैतिक तत्व सम्मिलित था तथा जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के अनुपालन में संकट और बाधा उत्पन्न होती थी । संहिता में परिगणित अपराधों को 'अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अपराध' के रूप में परिभाषित किया गया । आयोग ने निश्चय किया कि केवल व्यक्तियों को ही ऐसे अपराधों के लिये दण्डित किया जाना चाहिये और भाव-वाचक नामों से सूचित अपराधों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई ।

संहिता के मसौदे में अन्य अपराधों के अतिरिक्त निम्नलिखित अपराध भी सम्मिलित थे, अर्थात् अग्रघर्षण का कार्य, अग्रघर्षण की धमकी, किसी राज्य के अधिकारियों द्वारा किसी अन्य राज्य के विरुद्ध बल-प्रयोग की तैयारी, आत्म-संरक्षण में अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सक्षम अंग के निर्णय अथवा सिफारिशों के अनुसार या किसी अन्य प्रयोजन से किसी और प्रयोजन के लिये किसी राज्य का सैन्यदल द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से दूसरे राज्य के प्रदेश में आक्रमण, किसी राज्य के अधिकारियों का किसी अन्य राज्य में राजनैतिक भूखंडों के मड़काने अथवा भय

उत्पन्न करने वाले कार्य करने से सम्बन्धित कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रतिक्रमण करके किसी प्रदेश का समामेलन (annexation), राज्य के अधिकारियों द्वारा अथवा वैयक्तिक रूप में जनवश, नागरिक जनता के विरुद्ध अमानुषिक कार्य, युद्ध-नियमों के प्रतिक्रमण में कार्य । प्रायाग ने यह मत प्रकट किया कि किसी व्यक्ति का किसी राज्य के अध्यक्ष के रूप में अथवा एक उत्तरदायी सरकारी पदाधिकारी के रूप में कार्य करना उसको उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करता । यदि कोई व्यक्ति अपने सरकार अथवा प्रवर के आदेशानुसार कार्य करे तो केवल उसी देश में उत्तरदायी माना जा सकता है जब उसके लिये नैतिक विकल्प वास्तव में सम्भव रहा हो ।

एक अन्तर्राष्ट्रीय दण्ड न्यायालय के स्थापन के आलम्बित रहने तक प्रायों ने कोई लेख-पत्र संहिता के कार्यान्वित करने के लिये नहीं बनाया और प्रत्येक अग्र राध के लिये एक निश्चित दण्ड की व्यवस्था किये बिना उसका प्रयोग राष्ट्रीय न्यायालयों के ऊपर छोड़ दिया ।

प्रधान समुद्रों की शासन-पद्धति (Regime of the High Seas) किनारे का राज्य समुद्र से बलुई किनारे तथा उमरे हुये चट्टान पर (shelf) प्राकृतिक साधनों को उपयोग करने का नियन्त्रण तथा क्षेत्राधिकार रख सकेगा किन्तु निकटवर्ती ऊपर के समुद्र की तथा वायुमण्डल की वैधिक स्थिति पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा ।

सन्धियों की विधि (Law of Treaties) :—यह विषय आयोग के प्रथम अधिवेशन में संहिताकरण के लिये चुना गया । सन्धियों की तैयारी, सन्धि करने की योग्यता, सत्याकन, स्वीकृति तथा सन्धियों में प्रवेश सम्बन्धी बहुत सी धारामों के मसौदे आयोग के विचाराधीन थे ।

अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक क्षेत्राधिकार (International Criminal Jurisdiction) :—आयोग ने अपने दूसरे अधिवेशन में जनवश तथा कुछ अन्य अपराधों के विचार के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक अंग के स्थापना की आवश्यकता की परीक्षा की । इसके विचार में एक पृथक अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना सम्भव तथा वाञ्छनीय दोनों थी, पर वह ऐसे न्यायालय के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को चैम्बर (chamber) के रूप में स्थापित किये जाने में विरुद्ध था ।

अपने पाँचवें अधिवेशन में सभा (Assembly) ने एक अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के स्थापन तथा सविधि (statute) सम्बन्धी अभिसमय का मसौदा

तैयार करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की। समिति की बैठक जेनेवा में अगस्त सन् १९५१ में हुई और इसने अन्तर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक न्यायालय के लिये संविधि (statute) का मसौदा तैयार किया।

समिति की रिपोर्ट संविधि (statute) के सहित सरकारों की टिप्पणी तथा अवलोकन के लिये भेजी गई।

मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा :—सन् १९४८ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनुष्य के अधिकारों का पहला अन्तर्राष्ट्रीय वक्तव्य अर्थात् 'मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' घोषित की। अप्रैल ६ सन् १९५० को मानवीय अधिकारों के आयोग ने प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का विधि द्वारा संरक्षण तथा इसके एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (Convention) में सम्मेलन के सिद्धान्त को स्वीकृत किया।

अन्य अभिसमय ( Other Conventions ) :—संयुक्त राष्ट्र संघ ने जन-वध (genocide) पर एक अभिसमय तैयार किया है जिसके अनुसार किसी प्रकार के राष्ट्रीय, जातीय अथवा वर्गीय समूहों के विनाश के उपलक्ष्य में किये गये अन्तर्राष्ट्रीय अपराध के कार्य दंडनीय माने गये हैं, उनके लिये उत्तरदायी व्यक्ति पाहे राजा हो, राष्ट्र हों, सरकारी पदाधिकारी हो अथवा सामान्य व्यक्ति हो, सभी माने गये हैं। ३१ जनवरी, १९५६, तक ५६ राज्यों ने इसका अनुसमर्थन किया।

एक अभिसमय का मसौदा सूचना की स्वतन्त्रता तथा समाचारों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रेषण (भेजने) के सम्बन्ध में भी तैयार किया गया है जिस पर साधारण सभा की सामाजिक समिति द्वारा विवेचना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के एक समुदाय ने एक नीति-सहिता का मसौदा तैयार किया।

संयुक्त राष्ट्र संघ के भिन्न-भिन्न दल विश्व के सामाजिक समस्याओं के सुलझाने में लगे हुये हैं जिनमें बलात् श्रम, दामता, श्रमिक सघों के अधिकारों का संरक्षण, जनसंख्या का अध्ययन, इत्यादि सम्मिलित हैं।

जुलाई सन् १९५१ में शरणार्थियों की प्राप्ति (status) पर एक अभिसमय संयुक्तराष्ट्र संघ की अध्यक्षता में स्वीकृत की गई जो शरणार्थियों के अधिकारों पर सबसे अधिक विस्तृत लिखित अधिकारपत्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक आयोग जिसमें विधिवेत्ता प्रमाणिक व्यक्ति हैं, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सहिताकरण तथा विकास के प्रयत्न में लगा हुआ है।

## अध्याय ८

अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्र-विधि में  
परस्पर सम्बन्ध( Relation between International Law and  
Municipal Law)

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार-भूत सिद्धान्तों के अध्ययन करने के पूर्व यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्र-विधि में क्या सम्बन्ध है इसका संक्षेप में अध्ययन किया जाय। हमने इससे पूर्व यह देख लिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि प्रभु-सत्ताधारी स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को अनुशासित करती है। राष्ट्र-विधि (Municipal Law), राज्य-विधि (State Law) अथवा राष्ट्रीय-विधि (National Law) किसी राष्ट्र अथवा देश की विधि है और इस सम्बन्ध में वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध है। केससेन का कहना है कि राष्ट्रीय विधि व्यक्तियों के व्यवहार को नियमित करती है और अन्तर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के व्यवहार को, अथवा जैसा कहा जाता है कि राष्ट्रीय विधि के नियम राज्य के 'भान्तरिक सम्बन्ध' अथवा तदाकथित 'घरेलू मामले' हैं। और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय राज्यों के 'बाह्य' सम्बन्ध अर्थात् उनके 'विदेशीय मामले' हैं।

क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्र-विधि या विभिन्न राष्ट्रीय विधियों को एक ही वस्तु, अर्थात् विधि के ही एक विचार के भिन्न-भिन्न रूप कहा जा सकता है अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विधि विधि की एक स्वतन्त्र पद्धति है जो राष्ट्र-विधि से प्रधानतः भिन्न है। इस प्रश्न पर बहुत-सा साहित्य निकल चुका है। प्रथम सिद्धान्त को एकात्मक (Monistic) और द्वितीय सिद्धान्त को द्वैतात्मक (Dualistic) कहा जाता है।

एकात्मक सिद्धान्त (Monistic Theory):—एकात्मक सिद्धान्त के विचार वाले यह प्रतिपादित करते हैं कि विधि की दोनों पद्धतियों अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्र-विधि के विषय प्रधानतः एक ही है क्योंकि पहला राज्यों के आचरण को निरूपित करता है और दूसरा व्यक्तियों के आचरण को। इस मत के अनुसार विधि प्रधानरूप में एक आज्ञा है जो इसके (विधि के) अधीनस्थ विषयों पर उनकी स्वतन्त्र इच्छा से बधनकारी है जो (अधीनस्थ विषय) एक दशा में राज्य है और दूसरी दशा में व्यक्ति। इस मत के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्र-विधि एक ही वस्तु के दो रूप हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि यद्यपि सीधे राज्यों को निगम (corporate bodies) के रूप में सम्बोधित है, तथापि वह व्यक्तियों पर भी लागू है क्योंकि राज्य अन्तर्-तो-

गया केवल व्यक्तियों के ही संगठन है। इस सिद्धान्त (doctrine) के पक्ष का समर्थन वियेना स्कूल के केल्सन (Kelsen) महोदय द्वारा किया गया है जिनके मतानुसार राष्ट्र-विधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि में एकरूपता है और इसके विरुद्ध कोई विचार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के वैध सङ्गण का ही उत्सर्जन करता है। डूगू (Duguit) महोदय एक पक्ष और आगे बढ़ गये और उन्होंने इस मत का व्यवलम्बन किया कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन राष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य है। (The subjects of International Law are not States but the individual members of States.—Duguit).

**द्वैतात्मक सिद्धान्त (Dualistic Theory) :**—द्वैतात्मक सिद्धान्त के विचारों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्र-विधि की पद्धतियाँ महाँ तक पृथक् तथा स्वयं परिपूर्ण हैं जहाँ तक एक के नियम दूसरे में ग्रहण नहीं किये जाते। ओपेनहेम का कथन है कि इस विचार के अनुसार राष्ट्रों की विधि (Law of Nations) तथा राष्ट्र-विधि (Municipal Laws) प्रधानतः एक दूसरे से भिन्न हैं। सब से प्रथम तो उनके स्रोतों में ही अन्तर है। राष्ट्र विधि के स्रोत सम्बन्धित राष्ट्रों की सीमाओं के भीतर विकसित रुढ़ियाँ तथा उनमें बनायी गई सविधियाँ (statute) हैं और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत राष्ट्रों के कुटुम्ब के भीतर विकसित रुढ़ियाँ तथा इसके सदस्यों द्वारा की गई विधि-विधायक सन्धियाँ हैं। दूसरे यह कि, राष्ट्र-विधि राज्य के प्रभुत्व के अधीन व्यक्तियों के अथवा व्यक्तियों तथा राज्य के बीच के सम्बन्धों को नियमित करती है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के कुटुम्ब के सदस्य-राष्ट्रों के बीच के सम्बन्धों को नियमित करती है। अन्त में विधि के सार के सम्बन्ध में भेद है क्योंकि राष्ट्र-विधि व्यक्तियों के ऊपर एक सर्वोच्च सत्ता की विधि है जब कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि सर्वोच्चसत्ताधारी राज्यों के बीच की विधि है जो उनके मध्य होने से बनी है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि निर्बल विधि है। इस सिद्धान्त का पक्ष का समर्थन प्रधानतः ट्रिपेल (Triepel), (जर्मनी) तथा अंजिलोटी (Anzilotti) (इटली) द्वारा किया गया है।

**रूपान्तर सिद्धान्त (Transformation Theory) :**—उपरोक्त दो सिद्धान्तों के प्रतिरिक्त स्टार्क (Starke) महोदय एक अन्य सिद्धान्त को निर्देशित करते हैं जिसे हम रूपान्तर सिद्धान्त (Transformation Theory) के नाम से पुकारते हैं।

इस सिद्धान्त के अनुसार "यह सन्धि का राष्ट्रीय विधान में रूपान्तर ही है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय सविधानों में उल्लिखित नियमों का विस्तार व्यक्तियों के लिये भी वैध होता है। रूपान्तर एक केवल नियमानुसार ही नहीं बल्कि एक वास्तविक सारपूर्ण आवश्यकता है। इस सिद्धान्त के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय अथवा

राष्ट्र-विधि में तब तक स्थान नहीं पा सकती जब तक वे अपने यन्त्र उस प्रयोजन के लिये उपयोग में लाये जाने के लिये न दें। अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि का राष्ट्रीय विधान में रूपान्तर का उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन द्वारा की गई प्रत्यर्पण (extradition) सन्धियों से मिलता है। अंग्रेजी विधि में प्रत्यर्पण कार्यवाहियों द्वारा भागे हुए अपराधी को प्रकट सविधिक प्राधिकार (express statutory authority) बिना विदेशी देश को समर्पण करने की शक्ति नहीं है। ऐसा प्राधिकार प्रत्यर्पण अधिनियमों के अधीन परिषद् आदेशों (Orders-in Council) द्वारा दिया जाता है और केवल उन्हीं में निर्दिष्ट अपराधों से सम्बद्ध होता है। इसी प्रकार अन्य सन्धियों तथा अभियमों को लागू करने के लिये भी राष्ट्रीय विधान अपेक्षित है।

यह सिद्धान्त कई बातों में भ्रान्तिपूर्ण है। प्रथम तो इसका यह पक्ष कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्र विधि दो स्पष्टतया भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ हैं, प्रशुद्ध है। दूसरे यह पक्ष कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि केवल राज्यों के लिए बंधनकारी है और राष्ट्र-विधि व्यक्तियों को लागू होती है यह भी सही नहीं है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों का समूह है जो सम्मेलन राज्यों द्वारा अपने पारस्परिक आचरण तथा एक दूसरे की प्रजा के प्रति आचरण को निर्धारित करने के लिये स्वीकार किये गये हैं। तीसरे यह कि इस सिद्धान्त द्वारा सन्धियों के लागू होने के लिये राष्ट्रीय विधि में रूपान्तर अपेक्षित है। यह बात विधि-विधायक सन्धियों की दशा में निश्चय ही असत्य है। कुछ सन्धियाँ तो स्वयं ही लागू होती हैं और रूपान्तर की अपेक्षा नहीं करती। उन सन्धियों के सम्बन्ध में जो अपने पूर्ण होने के लिये वैध कार्य की अपेक्षा करती हैं यह पूर्ण होने का कार्य रूपान्तर नहीं कहा जा सकता जब तक कि हम इस पूर्ण होने के कार्य को ही रूपान्तर न मान लें।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रिक क्षेत्र में लागू करने के सम्बन्ध में राज्यों के प्रचलन — परस्पर विरोधी सिद्धान्तों को जिनको विवेचना ऊपर की गई है दृष्टि में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय विधि को राष्ट्रिक क्षेत्र में लागू करने के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रचलनों को अब परीक्षा की जावेगी।

ग्रेट ब्रिटेन (Great Britain). — ग्रेट-ब्रिटेन में अन्तर्राष्ट्रीय विधि को प्रमाणित अन्तर्राष्ट्रीय विधियों तथा सन्धि द्वारा निर्धारित विधियों में उनको प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भेद मानत हैं। प्रमाणित अन्तर्राष्ट्रीय विधि के ऐसे नियम जिनकी स्वीकृति सार्वभौमिक मान ली गई है, और जिनको देश की सम्मति प्राप्त हो गई है, देश की विधि के अंग समझे जाते हैं। न्यायाचार्य Blackstone के विचार त्रिनदी द्वारा उन्होंने सन् १७६१ में यह स्थापित किया कि राज्यों की विधि "यहाँ पूर्णतया सामान्य विधि द्वारा अङ्गीकृत की गई है और देश की विधि का भाग मानी जाती

है" (Law of Nations 'is here adopted in its full extent by the common law and is held to be a part of the law of the land') यह आजकल भी ठीक मानी जाती है। इससे पूर्व १७६४ के त्रिकेट बनाम बाथ (Triquet v. Bath) में लॉर्ड मैन्सफील्ड Lord Mansfield ने अनुमोदन सहित लॉर्ड तालबॉट (Lord Talbot) की सम्मति को एक इससे पूर्व के बारबून (Bar mit) के मामले से उद्धृत करते हुए कहा है कि "राष्ट्रों की विधि पूर्णतया इंग्लैंड की विधि का भाग है।"

यह परम्परागत विचार वेस्ट रैंड सेण्ट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम किंग (West Rand Central Gold Mining Co Ltd v. The King) वाले मामले में पक्का करके कहा गया था। उसमें मुख्याधीश सॉर्ड अल्वेस्टोन (Lord Alverstone, C. J.) द्वारा यह मत प्रकट किया गया कि जिस किसी बात को सभ्य राज्यों की सामान्य सम्मति प्राप्त हो गई हो उसे हमारे देश की भी सम्मति अवश्य प्राप्त हो गई होगी और जिस किसी बात में हम सामान्यतः अन्य राज्यों से सहमत हो गये हो वह उचित रीति से अन्तर्राष्ट्रीय विधि कही जा सकती है। ऐसी दशा में वह हमारे नागरिक न्यायाधिकरणों द्वारा जब कभी उनको ऐसे प्रश्नों का निर्णय करने के लिये यथायोग्य अवसर प्राप्त हो जिनमें कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्त सगत हो स्वीकृत तथा लागू की जावेगी। चुंग ची च्वांग बनाम किंग (Chung Chi Cheung v. The King) वाले मामले में सॉर्ड अटकिन (Lord Atkin) ने यह कहा कि न्यायालय नियमों के एक समूह के अस्तित्व को मानते हैं जिनको कि राज्यों ने परस्पर स्वीकृत कर लिया है। किसी न्यायिक विवाद-प्रश्न में वे अपेक्षित नियम का पता लगाने का यत्न करते हैं और उसको या जाने पर ये उसे घरेलू विधि में समावेशित मानेंगे जहाँ तक कि यह सिफारिशों (recommendations) द्वारा अधिनियमित अथवा उनके न्यायाधिकरणों द्वारा घोषित नियमों से प्रसंगत न हो।

अमेरिका (America) —संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सिद्धान्त को कि "अन्तर्राष्ट्रीय विधि देश की विधि का भाग है" ("International Law is part of the law of the land") बिना किसी सदिग्धता के लागू किया है। सब अन्तर्राष्ट्रीय विधियाँ जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सत्यापित की गई हैं तथा ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़िविधि जिसे संयुक्त राज्य की स्वीकृति प्राप्त हो गई है अमेरिका के न्यायालयों पर बंधनकारी हैं चाहे वे सविधियाँ के अनुबन्धों के प्रतिबल ही क्यों न हों। जिन मामलों में झगडा रहता है उन मामलों में यह मान लिया जाता है कि संयुक्त राज्य की कांग्रेस या यह आक्षेप बढ़ाए न रहा होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि को नष्ट



कर दिया जाय । अतः इस सम्बन्ध में अमेरिका तथा ब्रिटेन द्वारा प्रयुक्त प्रवक्तव्यों में घनिष्ठ समता है ।

संयुक्त राज्य अमेरिका का सविधान सन्धियों को सबसे अधिक महत्व देता है । उसके अनुच्छेद ६ में से यह विशेष रूप से व्यवस्थित है कि "संयुक्त राज्य के प्राधिकार के अधीन की गईं सब सन्धियाँ अथवा जो भविष्य में की जावेगी देश की सबसे श्रेष्ठ विधि होगी और प्रत्येक राज्य (State) का न्यायाधीश उनसे बाध्य होगा चाहे किसी राज्य के सविधान में अथवा विधियों में उसके विरुद्ध कुछ भी हो ।" इसका परिणाम यह होता है कि जो भी प्रेसीडेंट किसी सन्धि को सत्याकृत करता है, वह हमेशा की विधि में परिवर्तित हो जाती है । यदि सन्धियाँ स्वयं निरपादित होने वाली होती हैं तो वे न्यायालयों पर देश की विधि के अंश के रूप में बन्धनकारी होती हैं । यदि वे ऐसी हुईं कि उनको प्रवृत्त करने के लिये क्षमता प्रदान करने वाले विधान की आवश्यकता हो तो वे देश की विधि तब तक नहीं होती जब तक कि वे आवश्यक विधान द्वारा प्रवर्तित न की जायें ।

महाद्वीप वालों की रीति .—फ्रांस में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रथागत विधि, उस समय तक राष्ट्र विधि का अंश मानी जाती है जब तक वे देश के विधान के विरुद्ध न आती हो । सन्धियों के सम्बन्ध में फ्रांस ने न्यायालयों के निर्णयों में कोई एकता नहीं है । कभी-कभी तो न्यायालयों ने सन्धि को सविधियों से प्रबल माना है और प्रायः उन्होंने इसके विपरीत अपना दृष्टिकोण रखा है । सन्धियों के लागू करने के सम्बन्ध में भी फ्रांस में स्थिति अस्थिर है । कुछ सन्धियों में विधियों के समान घोषणा अपेक्षित है और कुछ केवल प्रकाशित की जाती हैं । बेल्जियम तथा पोलैंड में यह आवश्यक है कि सन्धियों को लागू होने के लिए पार्लियामेंट की स्वीकृति लेनी चाहिए । डेनमार्क की विधि भी सामान्यतः स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय विधि को मान्यता प्रदान करती है और इसके विरुद्ध कार्य अवैध माने जाते हैं ।

स्पेन ने सविधान (१९३१) के अनुच्छेद में यह उपबन्धित है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि देश की विधि का अंश है ।

जर्मनी ने वीमर सविधान (१९१९) के अनुच्छेद ४ में यह निर्धारित किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सार्वभौमिक मान्य नियम जर्मन सब के बाध्यकारी प्रभागों के समान वैध हैं, परन्तु इस अनुच्छेद के स्पष्ट व्यवस्थाओं के हाव पर भी जर्मन न्यायालयों ने इस अनुच्छेद का बहुत सक्रिय अर्थ ग्रहण किया है । सन् १९२८ में जर्मन Reichsgericht ने यह मत ग्रहण किया कि वह *lex posterior derogat priori* (उत्तरवर्ती अधिनियम पूर्ववर्ती को रद्द कर देता है) सिद्धान्त के अनु-

सार कार्य करने को बाध्य है और एक उत्तरवर्ती सविधि (statute) को बर्साई की सन्धि की व्यवस्थाओं के विरुद्ध लागू कर दिया। एक दूसरे मामले में जर्मनी के सर्वोच्च न्यायालय ने सन् १९३३ में यह मत प्रकट किया कि केवल जर्मनी ही अपनी अन्तरिक बातों में सर्वोच्च सत्ता होने के कारण यह निर्णय कर सकता है कि सविधान के अनुच्छेद ४ के अर्थ के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्यतः मान्य नियमों में क्या-क्या आता है, अतः यह उसकी इच्छा पर निर्भर है कि ऐसा विधान बनाव जो सन्धि की व्यवस्था के विरुद्ध जाता हो। संक्षेप में न्यायालयों की प्रवृत्ति सविधान के अनुच्छेद को केवल उन्हीं नियमों में लागू करने की रही है जिनका कि जर्मनी का विशेष सम्मति प्राप्त हो गई हो।

## भाग २

### शान्ति की विधि

#### अध्याय ७

#### अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय

#### ( Subjects of International Law )

“विधि के विषय” क्या हैं ? वे वस्तुतः वह विषय हैं जिन पर विधि के नियम ‘Rules of Law’ लागू किये जाते हैं, अथवा यों कह लें कि वे सीधे विधि के नियमों से बाधित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधिकारों और कर्तव्यों से युक्त होते हैं, और अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारण के सक्षम अपने अधिकारों के अतिक्रमण का दावा कर सकते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख विषय राज्य हैं। उन्हीं को केवल राष्ट्रों की विधि में प्रवेश करने का अधिकार है और वे ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का रूप धारण किये हुये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्येक सम्यक् राज्य राष्ट्रों के कुटुम्ब का सदस्य है और वैध परिभाषा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के नाम से सम्बोधित किया जाता है। राज्य वे व्यक्ति हैं जिनको विधि के अनुसार अधिकार तथा कर्तव्य प्रदान किये जाते हैं यद्यपि यह सत्य है कि वे स्वभावतः पृथक्-पृथक् विभागों से निर्मित होने के कारण एक व्यक्ति की इवाइ के रूप में कार्य नहीं कर सकते और उनको इसके लिये नियुक्त कार्य-कर्त्ताओं अथवा लोकसेवकों द्वारा कार्य करना पड़ता है।

कट्टर व्यवहारवादियों (Orthodox Positivists) के मतानुसार, केवल राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय बन सकते हैं और वैयक्तिक रूप से व्यक्ति उसके आधार हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि राष्ट्रों की विधि को ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति का कोई वैध अस्तित्व नहीं हुआ करता, उसका अस्तित्व तो केवल उसके राज्य के द्वारा ही सिद्ध होता है।

किन्तु आज इस सिद्धान्त पर अनेक तर्क किये जाते हैं। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के परिणाम-स्वरूप और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रतिफल-रूप में व्यक्तियों को भी वैध अस्तित्व प्राप्त हो गया है। अब व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के समक्ष "an object of international compassion a subject of international right" का रूपान्तर हो गया है, और वह केवल अन्तर्राष्ट्रीय अनुकम्पा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि उसे स्वतन्त्र अस्तित्व भी प्राप्त हो चुका है। व्यक्ति के आधार-भूत अधिकारों को स्वीकार करके उसे राज्यों के अस्तित्व से पृथक् रूप से व्यक्तित्व प्रदान किया गया है और सीधे व्यक्ति पर अधिकारों और कर्तव्यों का दायित्व सौंपा गया है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एवं अन्य विधि-नियामक संधियों के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों को स्वीकार करने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। इससे व्यक्ति सीधे अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय बन गया है।

**राज्य की परिभाषायें (Definitions of State) :—**राज्य (State) की परिभाषा भिन्न-भिन्न लेखकों ने अपने-अपने मत के अनुसार निर्धारित की है। राज्य की विशेषताओं को भली प्रकार समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ प्रमुख लेखकों के विचारों को जान लें :—

**लॉरेंस :—**लॉरेंस के मतानुसार राज्य एक राजनैतिक समाज (a political community) है जिसके सदस्य किसी केन्द्रीय सत्ता के समानरूप से अधीनस्थ होने के नाते आपस में बंधे हुए हैं और उनमें से अधिकतर उसकी आज्ञाओं का पालन स्वभावतः करते हैं।

**सॉमंड :—**सॉमंड की परिभाषानुसार राज्य मनुष्यों का एक समाज (a society of men) है जो कुछ उद्देश्यों की पूर्ति जैसे आन्तरिक सुव्यवस्था तथा बाह्य सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है।

**हॉल्लैंड :—**हॉल्लैंड के कथनानुसार राज्य मनुष्यों का एक अनेक जन समूह (a numerous assemblage of human beings organized for law, generally occupying a certain territory) है जो कानून के लिए संगठित हुए हैं और जो साधारणतः एक विशिष्ट प्रदेश में बसे हैं।

हॉलैंड के मतानुसार राष्ट्र के पाँच लक्षण ये हैं—(१) बहुत से मनुष्य, (२) एक ऐसा स्थायी राजनैतिक संगठन कि जिसके द्वारा नागरिकों का स्वाभाविक भ्राजा-पालन सुरक्षित रह सके, (३) एक प्रदेश जिसकी सीमा स्थिर हो, (४) स्वतन्त्रता और (५) सम्पत्ता का वह स्तर जिससे कि इसका प्रवेश राष्ट्रों के कुटुम्ब में हो सके।

**ओपनहेम** —ओपनहेम के मतानुसार उपनिवेशों तथा अधिराज्यों के विपरीत दशा में एक राज्य का अस्तित्व तभी होता है जब कि किसी जाति अथवा समाज के लोग किसी देश में अपनी ही सर्वोच्चसत्ताधारी सरकार की अधीनता में बस गये हों।

राज्य के अस्तित्व के लिए चार बातें होनी चाहिये —

(१) लोगों का एक समुदाय होना चाहिए। लोगों का समुदाय व्यक्तियों (पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों) की एक समष्टि है जो एक जाति के समान साथ में रहते हो चाहे वे भिन्न-भिन्न वंश, धर्म अथवा रंग के क्यों न हों।

(२) एक देश होना चाहिये जिसमें लोगों का समुदाय बस गया हो।

(३) एक सरकार होनी चाहिये अर्थात् एक या अधिक व्यक्ति जो उन लोगों के समुदाय के प्रतिनिधि हो और देश की विधि के अनुसार शासन करते हों, अराजक-जाति-राज्य नहीं।

(४) एक सर्वोच्चसत्ताधारी सरकार होनी चाहिये। सर्वोच्चसत्ता सर्वोच्च प्राधिकार है—अर्थात् ऐसा प्राधिकार कि जो सत्तार के किसी भी अन्य प्रभाव से स्वतन्त्र हो।

**मोंटेविडो अभिसमय (Montevideo Convention)** —राज्यों के अधिकार तथा कर्तव्यों के सम्बन्ध में सन् १९३३ में किया गया मोंटेविडो अभिसमय (जिस पर संयुक्तराज्य अमेरिका तथा कुछ लैटिन अमेरिकीय देशों ने हस्ताक्षर किए हैं) के अनुच्छेद १ में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के व्यक्ति के रूप में राज्य के निम्नलिखित लक्षण हैं —

(अ) एक स्थायी जनसमुदाय (a permanent population), (आ) एक प्रदेश जिसकी सीमा स्थिर हो (a defined territory), (इ) एक सरकार (a government), (ई) अन्य राज्यों से सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता (capacity to enter into relations with other states)।

**सर्वोच्चसत्ता तथा राज्यों की स्वतन्त्रता** —सर्वोच्चसत्ता एक वेध शब्द है जिसका द्वारा वह सर्वोच्च अधिकार व्यक्त होता है जिससे कोई राज्य सम्पत्ति होता है। साधारण दोलचाल में यह एक राज्य द्वारा बाह्य तथा आन्तरिक मामलों में आत्म-

निश्चय करने का असीमित अधिकार है। जॉन डॉस्टिन ने सर्वोच्चसत्ता को आवश्यक, अविभाज्य तथा अपरिमित कहा है। सर्वोच्चसत्ताधिकार के प्रयोग के परिणाम-स्वरूप दो धैर्य बल्पनाये अन्तर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में आती हैं अर्थात् प्रत्येक सर्वोच्चसत्ताधारी राज्य की विधि के समान स्वतन्त्रता तथा समानता और प्रत्येक स्वतन्त्र राज्य की बाह्य तथा आन्तरिक सर्वोच्चसत्ता में बाधा डालने का नियम।

परम्परागत प्रभुसत्ता की विचारधारा में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गये हैं। सर्वोच्चसत्ताधारी राज्य के परमाधिकारों में से यह भी एक अधिकार है कि वह अन्य राज्यों से पारस्परिक लाभ तथा सामान्य हितों के लिये सन्धि करे। किन्तु, विपक्ष सम्बन्ध अथवा क्षमान्तदारों स्थापित करने वाली सन्धियों के परिणामस्वरूप सर्वोच्चसत्ताधिकार का प्रयोग निर्वल पक्ष पर एकपक्षीय भार डालने के कारण संमित हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र सच यद्यपि अपने सब सदस्यों की सर्वोच्चसत्ता की समानता के सिद्धान्त पर स्थापित हुआ है तथापि इसमें महत्व राज्यों की स्वतन्त्रता से उनके अभ्योयाश्रय में बदल दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सब लोगों ने अपनी शक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाये रखने में तथा अपनी मशीन को सब जातियों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की उत्तरोत्तर वृद्धि में लगाये रहने को संयुक्त कर दिया है।

स्वतन्त्र राज्यों का अपने पारस्परिक आवरण में अपने राष्ट्र-विधि की अपेक्षा के बिना अन्तर्राष्ट्रीय विधि से बाध्य होने का विचार ही उनके सीमारहित सर्वोच्चसत्ता के विपरीत है। जैसा ओपनहेम कहते हैं “यह धीरे-धीरे अनुभव किया जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि की उन्नति, अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा इसके साथ ही स्वतन्त्र जातीय राज्यों का बनाये रखना अन्त में राज्यों द्वारा अपने सर्वोच्चसत्ताधिकार के आंशिक आत्मसमर्पण पर प्रतिबन्धित है जिससे कि एक सीमित क्षेत्र के भीतर अन्तर्राष्ट्रीय विधान की क्रिया तथा एक आवश्यकीय असीमित क्षेत्र के भीतर बाध्यकारी क्षेत्राधिकार से सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों द्वारा मर्यादित विधि का शासन प्राप्त होना सम्भव हो सके।”

संसार के दो शक्तिशाली गुटों में, एक संयुक्तराज्य अमेरिका के नेतृत्व में तथा दूसरा रूसी सामाजिक गणतन्त्रवादी सब के नेतृत्व में विभाजन के कारण, जिसे सामान्यतः शीतयुद्ध (cold war) कहा जाता है, राज्यों का व्यक्तित्व लुप्त होता जा रहा है और प्रत्येक पश्चिमीय तथा पूर्वीय गुटों के भीतर पारस्परिक आर्थिक, सैनिक तथा राजनैतिक सहयोग की उन्नति होती जा रही है। प्रत्येक गुट अपने-अपने प्रभाव के क्षेत्र को बढ़ाने का यत्न कर रहा है।

**राज्यों का वर्गीकरण ( Classification of States )** — अन्तर्राष्ट्रीय विधि क प्रयाजना के लिये राज्यों का दो भागो म विभाजित किया जा सकता है (१) स्वतन्त्र राष्ट्र, और (२) अधीनस्थ राज्य ।

**स्वतन्त्र राज्य ( Independent States )** — स्वतन्त्र राज्य राष्ट्रों के कुटुम्ब के पूर्णत प्रभुताधारी सदस्य हैं । अन्तर्राष्ट्रीय विधि मे वे प्रभुताधारी राज्य कह जात हैं । वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि क प्रसामान्य विषय हैं और अपनी सीमाओं म भीतर स्थित सब व्यक्तिओ तथा सम्पत्तियो पर अनन्य अधिकार का प्रयोग करते हैं । वे किसी अन्य व्यक्ति क प्रत्यक्ष नियन्त्रण से स्वतन्त्र ह । अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार प्रभुताधारी राज्य कुछ विशेषाधिकारो तथा उन्मुक्तियों के अधिकारी हैं । उनको अन्य राज्यों को कूटनीतिज्ञ मन्त्रियों को भेजने का तथा अपने स्थान मे उनके प्रतिनिधियों को अपने यहाँ लेने का विशेषाधिकार प्राप्त है । वे अन्य राज्यों से अपने ही नाम म सन्धियाँ करते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो मे पूर्ण समानता के आधार पर मिलते हैं । सक्षम मे उनके अन्य राज्यों से सम्बन्धों के बीच म हस्तक्षेप करने वाला कोई तीसरा पक्षकार नहीं है । अपने घरेलू मामलो मे भी उन्हें पूर्ण क्षमता प्राप्त है ।

**परतन्त्र राज्य ( Dependent States )** — परतन्त्र राज्य निस्संदेह वैदेशिक सम्बन्धो मे सीमित क्षमता रखते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अपूर्ण विषय है । उनकी पयार्थ स्थिति का लक्ष्य केवल सन्धियों के प्रसंग तथा इस बात का पता लगाने से हा सकता है कि अन्य राज्यों द्वारा उनकी अधीनता की स्थिति किस सीमा तक स्वीकृत की गई है । अन्य शब्दो मे, वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय उनके स्वराज्यक्षेत्र की सीमा के भीतर हैं ।

केवल राष्ट्रीयता ही राज्यों के कुटुम्ब की सदस्यता का चिह्न नहीं है और ऐसे गुण के अभाव के कारण यह आवश्यक नहीं है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि क क्षेत्र के बाहर पड जाय ।

**राज्यों की समानता ( Equality of States )** — यद्यपि राज्य विस्तार, जनसंख्या, शक्ति, सम्यता की दशा, मात्रा, सम्पत्ति तथा अन्य गुणो मे असमान होते हैं तथापि राष्ट्रों के कुटुम्ब मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के रूप मे व समान ही हाते हैं । मोपनहेम के कथनानुसार इस वैध समानता के चार परिणाम निम्नलिखित हैं —

(१) जब कभी कोई ऐसा प्रश्न उठता है जिसका निर्णय सम्पत्ति द्वारा करना हो तो प्रत्येक राज्यों को केवल एक मत का अधिकार होता है ।

(२) नियमानुसार सबसे निर्बल तथा सबसे छोटे राज्यों के मत का उतना ही प्रभाव होता है जितना कि सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली राज्य का, भने ही राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली राज्यों के समक्ष उनके मत का उतना प्रभाव न माना जाय ।

(३) कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर क्षेत्राधिकार नहीं रख सकता है। अतः यद्यपि राज्य विदेशी न्यायालयों में दावा कर सकते हैं तथापि उन पर नियमानुसार वहाँ दावा नहीं किया जा सकता जब तक कि वे अपने को सम्बंधित विदेशी न्यायालय के क्षेत्राधिकारों के अधीन स्वेच्छापूर्वक न कर लें : [Mighell v Sultan of Johore, The Parlement Belge and Duff Development Co Ltd v Government of Kelantan] ।

(४) एक राज्य के न्यायालय अन्य प्रभुसत्ताधारी राज्य के सरकारी कार्यों अथवा उसके नागरिकों के सरकारी अथवा सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों की रक्षण पर, कम से कम इस परिणाम तक प्रश्न नहीं उठाते जहाँ तक उन कार्यों का प्राप्ति उस राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर हो ।

यद्यपि सिद्धान्त के अनुसार राज्यों के समान अधिकार हैं और प्रत्येक राज्य को एक मत का अधिकार है तथापि व्यावहारिक रूप में यह बड़ी ही शक्तियों के मत होते हैं जो अन्ततः प्रभावकारी होते हैं । वे साराजू के पलड़ों को इधर उधर फुटते देते हैं । वास्तविक व्यवहार में राज्यों की असमानता का ज्वलन्त उदाहरण इस बात से प्रकट है कि पाँच बड़ी शक्तियाँ अर्थात् चीन का प्रजातन्त्र, फ्रान्स, रूसी समाजवादी गणतन्त्रीय सभ, ब्रिटिश तथा संयुक्तराज्य अमेरिका सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य हैं और उनको यह अधिकार है कि सारभूत विषयों में सुरक्षा परिषद् के किसी भी निर्णय को अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करके अस्वीकृत कर दें । साम्यवादी चीन की संयुक्तराष्ट्र सभ की सदस्यता का प्रश्न इसी प्रकार के प्रभावों के कारण एक सदस्यता का रूप ले चुका है ।

### असंपूर्ण प्रभुसत्ताधारी राज्यों, तथा राज्यों का सभ (Non Sovereign and Union of Stats)

असंपूर्ण प्रभुसत्ताधारी के मुख्य लक्षणों की विवेचना के उपरान्त अब हम कुछ विशेष प्रकार के राज्यों का बखान करेंगे जो यद्यपि पूर्णरूप से प्रभुसत्ताधारी नहीं हैं तथापि उनमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बहुत से लक्षण विद्यमान हैं —

संविदा (Compact) द्वारा परस्पर स्थायी रूप से संयुक्त प्रभुसत्ताधारी राज्य या एक राज्यमंडल (Confederation) का स्थापना कर सकते हैं ।

अथवा एक सर्वोच्च सघीय सरकार का, जिसे प्रायः समष्टिक (Composite) राज्य कहा जाता है ।

**राज्यमंडल (Confederation).—**राज्यमंडल अथवा (Staatenbund) (राज्यों का बन्धन) कई पूर्ण प्रभुसत्ताधारी राज्यों के एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि द्वारा परस्पर एक सघ में बंध जाने से बनता है जिसमें सरकारी अंगों की प्रवृत्ति सदस्य राज्यों के ऊपर तो होती है परन्तु उनकी प्रजा के ऊपर नहीं । वे एक सविदा (Compact) द्वारा पारस्परिक सहयोग अथवा रक्षा के लिये संयुक्त होते हैं और इसका प्रत्येक मौलिक अंश अर्थात् सदस्य अपनी-अपनी प्रभुसत्ता तथा मित्र सारूप्य बनाये रखता है । इस प्रकार का राज्यमंडल राज्य नहीं है । राज्यमंडल के उदाहरण हमको १५८० से १७६५ तक नीदरलैंड्स में, १७७८ से १७८७ तक संयुक्तराज्य अमेरिका में, १२६१ से १७६८ तथा १८१५ से १८४८ तक स्विटजरलैंड में और १८१५ से १८६६ तक जर्मनी में प्राप्त होते हैं । वर्तमान युग में मंडलित राज्य विद्यमान नहीं हैं ।

**वास्तविक संघ (Real Union):—**एक विशेष प्रकार का संगठन 'वास्तविक संघ' है जिसका अस्तित्व उस दशा में होता है जब दो या अधिक विभिन्न पूर्ण प्रभुसत्ताधारी राज्यों का एक ही सम्राट होता है और वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिये तथा बाह्य सम्बन्धों के लिये एक राज्य के समान कार्य करते हैं यद्यपि उसके मौलिक अंश घरेलू विषयों में अपनी-अपनी भिन्नता बनाये रखते हैं । "वास्तविक संघ" स्वयं एक राज्य नहीं है किन्तु यह केवल दो पूर्ण प्रभुसत्ताधारी राज्यों का संघ है जो मिलकर पृथक् भागों से निमित्त एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति बनाते हैं । वर्तमान काल में कोई वास्तविक संघ विद्यमान नहीं है । आस्ट्रिया तथा हंगरी का "वास्तविक संघ" जो सन् १८६७ में बनाया गया था सन् १९१८ में युद्ध में पराजय के कारण विघटित कर दिया गया । डेनमार्क तथा आइसलैंड का संघ भी सन् १९४४ में समाप्त हो गया । इसका अन्य उदाहरण सन् १८१४ तथा १९०५ के मध्य में नॉर्वे तथा स्वीडन ॥ ।

**व्यक्ति संघ (Personal Union):—**व्यक्ति संघ का अस्तित्व उस समय होता है जब दो संपूर्ण प्रभुसत्ताधारी राज्य तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति केवल इस आकस्मिक बात के कारण परस्पर संयुक्त हो जाते हैं कि उनका एक ही व्यक्ति सम्राट है । ये राज्य बाह्य प्रयोजनों के लिये अपना-अपना भिन्न-भिन्न स्वरूप बनाये रखते हैं । इस प्रकार का व्यक्ति संघ १७१४ से १८३७ तक ग्रेट ब्रिटेन तथा हैनोवर के मध्य में, १८१५ से १८६० तक नीदरलैंड्स तथा सक्सनबर्ग के



मध्य में तथा १८८५ से १९०८ तक बेल्जियम तथा कोंगो स्वतन्त्र राष्ट्र के मध्य में विद्यमान था ।

**सघराज्य (Federal State) :—**सघराज्य अथवा 'Bundesstaat' बहुत से संपूर्ण प्रभुसत्ताधारी राज्यों का स्थायी सघ है जिसके अपने अंग होते हैं और जिसको अधिकार न केवल अपने सदस्य-राज्यों पर ही वरन् उनके नागरिकों पर भी होता है । प्रभुसत्ता की साधारण शक्तियाँ अशत सघीय सरकार में तथा अलग-अलग राज्यों में विभक्त होती हैं और दोनों प्राधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र में निरन्तर कार्य करते हैं । इसको दी गई शक्तियाँ के क्षेत्र के भीतर यह एक वास्तविक तथा प्रभुसत्ताधारी राज्य है और राज्यमण्डल के असदृश इसे केवल सदस्य-राज्यों के ऊपर ही नहीं, वरन् उन राज्यों के नागरिकों पर भी सीधे अधिकार है । प्रभुसत्ता जैसा कि ऊपर कहा गया है सदस्य राज्यों तथा सघराज्य के मध्य में विभाजित है । सघ सरकार को युद्ध की घोषणा करने, सुलह करने का तथा सन्धि करने का अधिकार होता है और सदस्य-राज्य अपने-अपने सूक्ष्म क्षेत्रों के भीतर अधिकार का प्रयोग करते हैं तथा नियन्त्रण रखते हैं, और स्वायत्तता (Autonomy) पर्याप्त मात्रा में बनाये रखते हैं ।

मुख्य सघराज्य निम्नलिखित हैं :—संयुक्त राज्य अमेरिका सन् १७८७ से स्विटजरलैंड १८४८ से, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, कनाडा, ब्राजील, वेनेजुएला, ओस्ट्रेलिया, रूसी सोवियत गणतन्त्र-वर्ग, जर्मनी, भारतवर्ष, पाकिस्तान तथा इथियोपिया १९४९ से ।

भारतीय संविधान अपने सब सामान्य लक्षणों से सघीय है यद्यपि यह सघीय सरकार अर्थात् केन्द्रीय सघ सरकार को अनुमति देता है कि सकलकालीन अवस्था में यह अनुच्छेद ३५२ के अधीन राष्ट्रपति द्वारा घोषित किये जाने पर अपने को एकात्मक (unitary) में परिवर्तित कर ले ।

**सहसहस्य (Condominium) :—**यह दो या अधिक राज्यों का किसी एक प्रदेश में समान राज्य है । इसमें यद्यपि जनता पर संयुक्त प्रभुसत्ताधिकार है तथापि संयुक्त प्रकार से शासन करने वाले राज्यों में से प्रत्येक राज्य अपनी प्रजा के ऊपर भिन्न क्षेत्राधिकार रखता है । एंग्लो-इजिप्शियन सूडान (Anglo-Egyptian Sudan) दक्षिणी समुद्र (South Sea\*) में फीनिक्स द्वीप (Phoenix Island\*) जो अंग्रेजों तथा अमेरिका वालों के समान प्रशासन में रहे तथा न्यू हेब्रिड्स (New Hebrides) जो अंग्रेज तथा फ्रांसवालों के समान प्रशासन में रहे, सहसहस्य के उदाहरण हैं ।

**राष्ट्रमंडल (Commonwealth) :—**राष्ट्रो की कामनवेल्थ के सदस्यों की स्थिति में द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त एक तीव्र परिवर्तन हो गया है। प्रथम महायुद्ध के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य में उपनिवेश तथा अधीनस्थ राज्य थे और उस साम्राज्य के अंग कोई अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का दावा नहीं करते थे। उसके बाद उनको स्वराज्य वाले उपनिवेशों की पदवी प्राप्त हो गई और अन्त में वे स्वराज्य वाले अधिराज्य हो गये।

कामनवेल्थ के सदस्य भव्य प्रभुसत्ताधारी राष्ट्र हैं और उनमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व पूर्ण रूप से उपस्थित है। उनको बाह्य मामलों में असीमित स्वायत्तता प्राप्त है। उनको सन्धि करने तथा दूतों को भी नियुक्त करने का अतिरिक्त अधिकार है। भारत, पाकिस्तान, लंका तथा मलेशिया सच को छोड़कर अन्य सब सदस्य राष्ट्र नियमानुसार एक समान अध्यक्ष अर्थात् ब्रिटिश सम्राट् के अधीन हैं।

**भारत की स्थिति :—**अप्रैल १९४६, में कामनवेल्थ सरकारों के प्रधान मंत्री सदन में उस समस्या का विचार करने को एकत्रित हुए जो भारत के अपने को सम्पूर्ण प्रभुसत्ताधारी स्वतन्त्र प्रजातन्त्र घोषित करने के निर्णय तथा कामनवेल्थ की सदस्यता जारी रखने की उसकी इच्छा से उत्पन्न हुई थी। उस सम्मेलन में जो निर्णय हुए थे, निम्नलिखित है :—

(१) अन्य राज्यों ने जिनके कामनवेल्थ की सदस्यता के आधार में परिवर्तन नहीं हुआ था इस बात को अंगीकृत तथा स्वीकार किया कि भारत कामनवेल्थ का सदस्य बना रहे।

(२) भारत ने अपनी ओर से सम्राट् को स्वतन्त्र सदस्य राष्ट्रों के स्वतन्त्र सम्मेलन का प्रतीक तथा इस रूप में कामनवेल्थ का प्रधान अंगीकार किया। सब सदस्य देशों ने यह घोषणा की कि वे राष्ट्रों के कामनवेल्थ के स्वतन्त्र तथा समान सदस्यों के रूप में संयुक्त रहेंगे तथा शान्ति, स्वतन्त्रता और उन्नति के कार्यों में स्वेच्छापूर्वक सहयोग करेंगे।

(३) भारत के साम्राज्यिक अधिमान (Imperial preferences) पूर्णतः जारी रहे।

(४) अधिराज्य या डोमिनियन (Dominion) शब्द का प्रयोग बन्द कर दिया गया।

(५) कामनवेल्थ के भीतर भारतीय नागरिकों का उन सब अधिरारों का उपभोग करना जारी रहा जिनका वे पहले उपभोग करते थे।

(६) गवर्नर-जनरल का पद जो सम्राट् का प्रतिनिधि हुआ करता था समाप्त हो गया ।

### सामन्त और संरक्षित राज्य (Vassal and Protectorates)

**सामन्त राज्य (Vassal State) .**—सामन्त राज्य वह है जिस पर दूसरे राज्य का पूर्ण रूप से आधिपत्य हो । अन्तर्राष्ट्रीय विधि में इसका कोई स्थान नहीं है । सामन्त राज्य के सब अधिकारों का समावेश अधिपति में हो जाता है । तो भी ऐसे उदाहरण उपस्थित हैं जहाँ सामन्त राज्यों ने कुछ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाये रखे हैं । प्रथमस्थ राज्यों के उदाहरण १८७८ के पूर्व रूमानिया तथा सर्बिया, १८७८ तथा १९०८ के बीच में बल्गेरिया, इजिप्ट, ट्रान्सवाल, श्रीलंका की स्टेट्स, तिब्बत तथा बाहरी मंगोलिया रहे हैं ।

**तिब्बत** —कई शताब्दियों तक भारत का सम्बन्ध तिब्बत के साथ अस्थिर दशा में रहा । अन्त में सन् १९१४ में शिमला में एक सम्मेलन सर हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में हुआ जिसमें सुप्रसिद्ध शिमला के अभिसमय का मसौदा तैयार किया गया । इस अभिसमय द्वारा तिब्बत की स्वायत्तता चीन के प्राधिकार के अधीन स्वीकृत की गई । सिक्किम में स्थित ब्रिटिश एजेंट तथा राजनैतिक पदाधिकारी भारत की ओर से तिब्बत सम्बन्धी कार्यों का संचालन करता था । परन्तु १९३६ में चीन तथा तिब्बत के बीच जो घटनाय घटी और जिनके अनुसार चीन का आधिपत्य व्यावहारिकता से अधिक सिद्धान्त में ही रह गया, उनका दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने तिब्बत से प्रत्यक्ष सत्ता स्थापित किया ।

चीन तथा तिब्बत की सन्धि पर पेकिंग में २३ मई सन् १९५१ को हस्ताक्षर किये गये जिसके अनुसार तिब्बत में एक चीनी सैनिक तथा प्रशासकीय आयोग तथा सैनिक-क्षेत्र का प्रधान कार्यालय स्थापित करने की व्यवस्था की गई तथा यह निर्धारित किया गया कि चीनी केन्द्रीय जनता की सरकार में तिब्बत के क्षेत्र के सम्पूर्ण बाह्य कार्यों का प्रबन्ध केन्द्रित होगा ।

सितम्बर १९५२ में भारत तथा चीन की सरकारों ने यह घोषणा प्रकाशित की कि वे इन बातों पर सहमत हो गये हैं कि ल्हासा मिशन जो ल्हासा में सोपह वर्षों से स्थित है, उसको अब ल्हासा मिशन के स्थान में कोन्सुलेट जनरल कहा जाय । भारतीय मिशन की प्रास्थिति में यह परिवर्तन ल्हासा की ही राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन का परिणाम था । इसके अनुसार तिब्बत के बाह्य सम्बन्धों का पूर्ण नियन्त्रण अब चीनी सरकार ने हाथ में है । इससे भारत का बाह्य मामलों में तिब्बत से प्रत्यक्ष सम्बन्ध समाप्त हो गया । तिब्बत के बाह्य सम्बन्धों का चीन द्वारा नियन्त्रण

स्वीकृत हो गया और उसी ने अनुसार सहायता में भी स्थिति बदल दी गई। तिब्बत की सामान्य जनता के विरोध के उपरान्त भी इस समय तिब्बत चीन का एक अन्तर्गत समझा जाता है और उसी द्वारा प्रशासित है।

**नेपाल** — ब्रिटिश सरकार तथा नेपाल के बीच हुई सन् १८१५ की सन्धि द्वारा नेपाल को प्रास्थिति एक सामंत राज्य में परिणत कर दी गई। उसके अनुसार नेपाल के बाह्य मामले ब्रिटिश सरकार को हस्तान्तरित कर दिये गये। प्रथम महायुद्ध के उपरान्त ब्रिटिश सरकार ने नेपाल की स्वतंत्रता उसको विदेशों में राजदूत नियुक्त करने का अधिकार देकर स्वीकृत कर ली। उसको अब पूर्णतः प्रभुसत्ताधारी राज्य के अधिकार प्राप्त हैं और उसने भारत तथा तिब्बत से सन्धि-सम्बन्ध स्थापित किये हैं। चीन द्वारा भारत पर किये गये १९६२ के आक्रमण के समय नेपाल ने चीन तथा भारत दोनों से मैत्री सन्धि बनाये रखने का प्रयास किया।

**भारतीय रियासतें (Indian States)** — ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय रियासतें इंग्लैंड के सम्राट के अन्तर्गत सामन राज्य मात्र थीं। वे केवल आंतरिक बाता में ही प्रभुसत्ता का प्रयोग कर सकती थीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७ के पारित होने के उपरान्त भारतीय रियासतों के ऊपर सम्राट का आधिपत्य समाप्त हो गया। भारत सरकार के लिये इन प्रादेशिक इकाइयों को जिनकी संख्या ५५० से कम न थी ऐसे विस्तार का इकाइयों में परिणत करना पड़ा जो एक समान विधि तथा सरकार के अन्तर्गत रह सकें। यह एक कठिन समस्या थी, किन्तु रियासती विभाग ने सरदार बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कुछ रियासतों को पारस्परिकता प्राप्त करने में मिलाकर, कुछ को रियासतों के साथ में मिलाकर करके और कुछ को केन्द्रीय प्रशासन में लेकर तथा उनके शासकों द्वारा प्रवेश-पत्र प्राप्त करके इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली। ऐसी रियासतों ने अपना भिन्न व्यक्तित्व खो दिया है और वे अब भारतीय सङ्घ की अभिन्न अङ्ग हैं।

काश्मीर के सम्बन्ध में एक जटिल समस्या उत्पन्न हो गई। काश्मीर की सरकार ने पाकिस्तान के साथ आर्थिक तथा प्रशासकीय सम्बन्ध तथा यातायात, रसद, डाक तथा सार-व्यवस्था जिस प्रकार भारत के विभाजन के पूर्व थी, वैसे ही बनाये रखने की दशा में लिये गयी स्थिति करार (standstill agreement) कर ली। तो भी कुछ दिन के बाद पाकिस्तान ने काश्मीर पर आर्थिक दबाव डालना आरम्भ कर दिया जो कि बढ़ते-बढ़ते रियासत के विरुद्ध नाकाबंदी में परिणत हो गया और बाद में कबालियों के दलों के सामूहिक आक्रमण आरम्भ हो गये। २७

अक्टूबर, १९४७ को काश्मीर के महाराजा की प्रार्थना पर भारत की सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर का प्रवेश (accession) स्वीकार किया परन्तु भारत के प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा की कि यह प्रवेश इस प्रतिबन्ध के साथ था कि रियासत की स्थिति में सुधार होने के उपरान्त वहाँ जनमत संग्रह (plebiscite) भी किया जाय। यह बात ध्यान रखने के योग्य है कि जनमत संग्रह के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मन्त्री की घोषणा प्रवेश की स्वीकृति के उपरान्त की गई और प्रवेश इस प्रतिबन्ध के अधीन नहीं था तथा यह प्रतिज्ञा एकपक्षीय थी। रियासत के भारत में प्रवेश करने पर भी आक्रमणकारी अपने पाकिस्तानी अड़ो से हमले करते ही रहे। ३ दिसम्बर १९४७ को भारत की सरकार ने इस झगड़े को सुरक्षा-परिषद् के सामने प्रस्तुत किया। इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत प्रयत्न हुये हैं, किन्तु कोई ऐसा सुझाव अभी तक उपस्थित नहीं हो सका है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को मान्य हो। काश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग अभी पाकिस्तानियों के कब्जे में है, जिसे वे 'आजाद-काश्मीर' की सजा देते हैं।

**संरक्षित राज्य (Protectorate) :**—संरक्षित होने की दशा में एक निर्बल राज्य एक प्रबल राज्य का संरक्षण उससे सन्धि करके प्राप्त करता है। परिणाम यह होता है कि मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय कारबार संरक्षक राज्य के ऊपर दिये जाते हैं। संरक्षक राज्य सन्धि के अनुबन्धों के अनुसार निर्बल राज्य के वास्तविक सम्बन्धों तथा कभी-कभी उनके आन्तरिक मामलों में भी कम या अधिक नियन्त्रण रखता है। औपनिवेशिक इस सम्बन्ध को एक प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षकत्व (international guardianship) कहते हैं।

**इजिप्ट :**—इजिप्ट ग्रेट ब्रिटेन तथा टर्की के बीच सन् १९१४ में युद्ध छिड़ने के पूर्व टर्की का सामन्त राज्य रहा। तब ग्रेट ब्रिटेन ने जो इजिप्ट के कारबारों को सन् १८८३ से नियन्त्रण करता चला आ रहा था, अपने को इजिप्ट का संरक्षक उद्घोषित किया। १९२२ में ग्रेट ब्रिटेन ने इजिप्ट को एक स्वतन्त्र प्रभुसत्तापारी राज्य घोषित किया। इजिप्ट के रक्षासम्बन्धी कुछ विषय, ब्रिटिश यातायात साधनों की सुरक्षा और इजिप्ट तथा मूडान में अल्पसंख्यकों का संरक्षण अपने विवेकानुसार निरन्तर किये जाने के लिये अस्थायी रूप से अपने हाथ में अलग रख लिया। अगस्त २६ गन् १९३६ को ग्रेट ब्रिटेन तथा इजिप्ट के बीच एक मित्रता की सन्धि हुई जिसमें अनुसार इजिप्ट की प्रभुसत्ता को स्वीकार करते हुये भी स्वयं नज़र पर उसकी रक्षा के लिये सैनिक दलों को रखने का अधिकार अपने हाथ में रखा। घटनाचक्र बड़े वेग से घूमा। अक्टूबर सन् १९५१ में इजिप्ट की पार्लियामेंट

ने ब्रिटिश सैनिक दलों को स्वेज नहर में जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, समाप्त करके सन् १९३६ की सन्धि को भङ्ग कर दिया ।

**सिक्किम :—**सिक्किम जो हिमालय पर्वत की श्रेणियों के मध्य बसा हुआ एक छोटा सा राज्य है, सन् १९०५ में भारतीय सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया । इसके पूर्व वह ब्रिटिश संरक्षण में था ।

सितम्बर ५ सन् १९५० को भारत की सरकार ने सिक्किम से एक सन्धि स्थापित कर ली जिसके द्वारा सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य रहेगा और रक्षा, बाह्य मामले तथा यातायात को छोड़कर आन्तरिक मामलों में स्वायत्तता का उपयोग करेगा ।

**भूटान :—**भूटान का भी भारतीय संघ के लिये एक बहुत बड़ा सैनिक महत्व है । यह राज्य भारत के उत्तर-पूर्वी सीमा पर है और सिक्किम, तिब्बत और नेफा (North East Frontier Agency) को तीन तरफ से स्पर्श करता है । १८६५ की संधि, जो कि भारत सरकार और भूटान के बीच हुई थी, के द्वारा भूटान को भारतीय रियासत का रूप प्रदान किया गया था, लेकिन सिक्किम की भाँति इसे भी एक विशेष स्थिति का राज्य माना गया । इस समय भूटान भारत का संरक्षित राज्य है । इस सम्बन्ध का आधार १९४९ की संधि है । इसके अनुसार भूटान के वैदेशिक नीतियों का नियंत्रण भारत-सरकार करेगी, किन्तु आन्तरिक मामलों में सिक्किम की भाँति भूटान को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है ।

**ब्रिटिश संरक्षित राज्य :—**बासुटोलैंड, बेचुआनालैंड तथा स्वाजीलैंड तीन ब्रिटिश संरक्षित राज्य दक्षिणी अफ्रीका में हैं । दक्षिणी अफ्रीका उनका हस्तान्तरण ४० वर्षों से माँग रहा है, जबकि उनको दक्षिणी अफ्रीका को अन्तर्गत करने की ब्रिटिश इच्छा दक्षिणी अफ्रीका अधिनियम में अभिलिखित की गई । किन्तु ब्रिटेन का कहना यह है कि ये संरक्षित राज्य उनकी अफ्रीकी जनता तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट की सम्मति के अतिरिक्त और किसी दशा में संघ को हस्तान्तरित नहीं किये जा सकते ।

**फ्रांसीसी संरक्षित राज्य :—**दूनोशिया तथा फ्रांसीसी मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में तथा अनाम, टोकिन और कंबोडिया दक्षिण-पूर्वी एशिया में फ्रांसीसी संरक्षित राज्य हैं । वर्साई की सन्धि द्वारा मोरक्को के तीन टुकड़े कर दिये गये जिनमें से एक फ्रांस की और दूसरा स्पेन की संरक्षकता में आये और तीसरा टैजियर-तटस्थीकृत परिधि के भीतर पड़ा । फ्रांसीसी सरकार का यह दावा है कि उसके संरक्षित राज्यों में जो कुछ उन्नति हुई है वह फ्रांस के कारण हुई है, अतः ऐसी दशा

मे अपने सरक्षणाधीन प्रदेशों के प्रशासन में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप अपमान समझते हैं। टूनीशिया तथा मोरक्को वाले बार-बार यह माँग पेश हैं कि उनका यह जन्म-सिद्ध अधिकार है कि औपनिवेशिक शासन समाप्त क जाय। एशिया तथा अफ्रीका सभ के प्रस्ताव पर टूनीशिया तथा मोरक्को १६ अक्टूबर सन् १९५२ को संयुक्तराष्ट्र सभ की साधारण सभा के कार्वा गया। फ्रांस ने इसके विरुद्ध यह आपत्ति की कि ये दोनों प्रदेश फ्रांस उभयपक्षीय सन्धियों द्वारा सम्बद्ध हैं तथा यह विषय प्रधानतः फ्रांस क्षेत्राधिकार में आता है।

जुलाई २० सन् १९५४ का नवराष्ट्रीय इंडोचीन सम्मेलन इस सहमत हो गया कि कम्बोडिया, लाओस तथा वीयतनाम की लड़ाई समा जाय।

प्रादेशित तथा न्यासित प्रदेश (Mandated and Trust Territ

प्रादेशित क्षेत्र.—प्रादेशित प्रदेशों के प्रयोग का परीक्षण सन् १९१९ तथा १९२० में लीग ऑफ नेशन्स की अध्यक्षता में किया गया। पहले शत्रु के अधिकार में थे और उनके सम्बन्ध में यह कहा जाता था कि वे आधुनिक सत्ता की प्रगतिशील स्थिति में अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। लीग ऑफ नेशन्स के प्रतिज्ञापत्र (Covenant) के अनुच्छेद २२ के अधीन ऐसे पूर्व शत्रु-प्रदेश जो जर्मनी तथा टर्की द्वारा मित्र-राष्ट्रों को समर्पण किये गये थे, लीग के अन्तिम उत्तरदायित्व के अधीन एक सरक्षक शासन के अधीनस्थ किये गये। लीग ने इन प्रदेशों को प्रशासन के लिये प्रादेश (mandate) के अधीन सम्मति में उन्नत ऐसे राष्ट्रों को सौंपा जो अपने साधन, अनुभव अथवा भौगोलिक स्थिति के कारण इस उत्तरदायित्व को उत्कृष्ट रूप से निभा सकते थे और जो इन भाग को ग्रहण करने को उद्यत थे। ऐसे राज्यों ने लीग ऑफ नेशन्स की देख-भाल तथा प्रतिभ अधिकार के अधीन इन प्रदेशों का प्रशासन किया।

प्रादेश तीन प्रकार के थे :—(अ) कतिपय वे जातियाँ जो पहले तुर्की साम्राज्य के अधीन थी और जो सतुल्यजनक रूप से उन्नति में आने लगी थीं। प्रादेशक न प्रशासन सम्बन्धी सम्मति तथा सहायता उस समय तक दी जब तक वे अपने ही पैरों पर खड़ी न हो सकीं। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा प्रादेशित ईरान और फिलिस्तीन (तथा ट्रान्सजोर्डन) और फ्रांस द्वारा प्रादेशित सीरिया तथा लेबनान इस प्रकार न उदाहरण थे।

(आ) अन्य जातियाँ, विशेषतः मध्य अफ्रीका की, जो ऐसी स्थिति में थी कि आदेशक उस प्रदेश के प्रशासन का उत्तरदायी इस प्रतिबन्ध के साथ होता था कि वह इस बात का उत्तरदायित्व ले कि वहाँ विश्वास तथा धर्म की स्वतन्त्रता इस शर्त के अधीन बनी रहेगी कि सार्वजनिक सुव्यवस्था तथा नैतिक आचरण का अनुपाचन हो तथा बुरीतियाँ जैसे दासों का व्यापार, शस्त्रों तथा शराब का यातायात इत्यादि समाप्त हो। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा प्रशासित ब्रिटिश केमेरूनस, ब्रिटिश टोगोलैंड तथा टोंगेनिका, फ्रांस द्वारा प्रशासित फ्रान्सीसी केमेरूनस तथा फ्रान्सीसी टोगोलैंड तथा बेल्जियम द्वारा प्रशासित रुआण्डा उरुण्डी इसके उदाहरण थे।

(इ) वे प्रदेश जैसे दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिणीय पैसिफिक समुद्र के कुछ द्वीप जो अपनी जनता की विरसता के कारण अथवा छोटे आकार के कारण अथवा उनके सम्यता के केन्द्रों से अत्यधिक दूरी के कारण अथवा अपनी भौगोलिक स्थिति में आदेशक के प्रदेश से मिले हुए होने के कारण आदेशक के प्रदेश के पूर्ण भागों के समान स्वदेशीय जनता के हितार्थ उपरोक्त सरक्षणार्थ प्रशासित होते थे। वे इस प्रकार हैं — दक्षिणी अफ्रीका तथा द्वारा प्रशासित दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, न्यूजीलैंड द्वारा प्रशासित समोआ, ब्रिटिश साम्राज्य अर्थात् ग्रेट ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड द्वारा प्रशासित संयुक्तराष्ट्र नौरू, भूमध्यरेखा के उत्तर में जापान तथा दक्षिण में आस्ट्रेलिया द्वारा प्रशासित पैसिफिक समुद्र के द्वीप।

इस प्रादेश पद्धति का निरीक्षण लीग एक स्थायी प्रादेश आयोग द्वारा करती थी जिसमें प्रादेशित राज्यों के सदस्यों की संख्या अधिक होती थी।

**न्यासित प्रदेश ( Trust Territories ) :**—संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर ने पुरानी समानता पद्धति के उप-सिद्धान्त के रूप में एक नयी पद्धति “न्यासित प्रदेश” की भारम्भ की। अनुच्छेद ७७ में यह व्यवस्था की गई कि यह न्यास पद्धति ( trusteeship system ) (अ) उन प्रदेशों को जो इस समय आदेशायी हैं, (आ) उन प्रदेशों को जो द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप शत्रु राज्यों से प्राप्त कर दिये जायें, तथा (इ) उन प्रदेशों को जो उनके प्रशासन के लिये उत्तरदायी राज्यों द्वारा स्वेच्छापूर्वक इस पद्धति में अधीन किये जायें, लागू होंगे।

न्यासपद्धति के उद्देश्य चार्टर के अनुच्छेद ७६ में लिखे हैं। वे हैं अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को आगे बढ़ाना, न्यासित राष्ट्रों के निवासियों को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी उन्नति तथा उनका स्वराज्य अथवा स्वतन्त्रता की ओर उत्तरोत्तर विकास; जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेद भाव को मिटाकर सबसे समान हितार्थ मानवीय अधिकारों तथा स्वतन्त्रता के मूल



सिद्धान्तों के लिये आदर का प्रोत्साहन; तथा सामाजिक, आर्थिक तथा वाणिज्य-व्यवसाय सम्बन्धी मामलों में संयुक्त राष्ट्र सभ के सब सदस्यों तथा उन राज्यों की जनता के साथ समान व्यवहार ।

संयुक्त राष्ट्र सभ के सन् १९४६ के प्रथम अधिवेशन में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस्, नीदरलैंड, बेल्जियम तथा कुछ निग्रहों के साथ फ्रान्स ने उद्धोषणाओं के द्वारा अपने आजापित प्रदेशों का न्यास पद्धति क अधीन रखने का आशय प्रकट किया । दक्षिण अफ्रीका ने यह दावा किया कि उन प्रादेशित प्रदेशों को अपने में मिलाने का अधिकार है ।

अपने आजापित प्रदेश अर्थात् दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीका द्वारा यह पक्ष ग्रहण किया जाने पर उन दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के निवासियों के प्रतिवेदन तथा प्रार्थना-पत्र संयुक्तराष्ट्र सभ को भेजना बन्द कर दिया । अतः संयुक्त राष्ट्र सभ की सामान्य सभा ने एक प्रस्तावली अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को दी ।

जुलाई ११ सन् १९५० को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने, जो कि सत्तर का उच्चतम न्यायाधिकरण है, हेतु में यह निर्णय किया कि दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका अब भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रादेश के अधीन एक प्रदेश है और दक्षिणी अफ्रीका इस सन् की अन्तर्राष्ट्रीय प्रास्थिति को भेदित करने का अधिकारी नहीं है । न्यायालय ने यह मत प्रकट किया कि दक्षिणी अफ्रीका उन अन्तर्राष्ट्रीय वर्तव्या से बाध्य है जो कि लीग आफ नेशन्स के अभिसमय के अनुच्छेद २२ में तथा दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के प्रादेश में उल्लिखित है । उनमें प्रतिवेदनों को प्रत्यपित करना तथा उस प्रदेश के निवासियों का प्रार्थना-पत्र भेजना भी सम्मिलित है और यह भी कि निरीक्षण का वर्तव्य संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा किया जावेगा जिसको वार्षिक प्रतिवेदन तथा प्रार्थना-पत्र दिये जाने चाहिये । इसने यह निर्णय किया कि न्यासपद्धति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सभ अधिकार पत्र के अध्याय १२ के अनुबन्ध दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका को इस वर्ष में लागू हो सकते थे कि वे एक साधन उपस्थित करते थे जिसके द्वारा वह प्रदेश न्यास पद्धति के अधीन लाया जा सके । न्यायालय ने ८ और ६ के अनुपात में बहुमत से यह निर्णय किया कि चार्टर के अध्याय १२ के अनुबन्ध दक्षिणी अफ्रीका सभ पर उस प्रदेश का न्यास पद्धति के अधीन करने व लिये कोई वैध कर्तव्य नहीं आरोपित करता । उपरोक्त न्यायालय ने यह भी मत प्रकट किया कि दक्षिण अफ्रीका सभ अपने कार्य करते हुए दक्षिण पश्चिमी-अफ्रीका के प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को निश्चित करने तथा भेदित करने की क्षमता नहीं रखता और यह कि उस प्रदेश की

तराष्ट्रीय स्थिति को निश्चित करने तथा भेदित करने की क्षमता दक्षिणी अफ्रीका को सयुक्त राष्ट्र सभ की सम्मति से वार्य करत हुए ही प्राप्त है ।

**स्विटजरलैंड** — स्विटजरलैंड न सन् १९४८ से तटस्थता की नीति का पालन किया है । मार्च २० सन् १८१५ का वियना की कांग्रेस में ग्रेट ब्रिटेन, स्ट्रिया, फ्रांस, पोचुगाल, प्रशा, स्पेन, स्वीडन तथा रूस ने स्विटजरलैंड को स्थायी तः तटस्थ राष्ट्र की प्राप्ति प्रदान की तथा सयुक्त रूप से उसको स्वतन्त्रता का द्वात दिलाया । स्विटजरलैंड की यह स्थिति लीग की कौन्सिल द्वारा स्वाकृत की है और उसे एक मौलिक सदस्य के समान इस सम्झौते में स्थान दिया गया कि न तो किसी सैनिक कार्यवाही में भाग लेने के लिये बाध्य किया जायगा, न तो ह विदेशी सैनिक दलों को रास्ता देगा और न अपने प्रदेश में सैनिक कार्यवाहियाँ तैयारी करने देगा । दोनों युद्धों में युद्धवर्तीभा ने उसकी तटस्थता का सम्मान किया ।

स्विटजरलैंड न सयुक्त राष्ट्र सभ में सम्मिलित होना चाा का स अस्वीकार र दिया कि कही सयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता स उसका तटस्थता भग न हो य क्योंकि चार्टर में अपराधों राज्या के विरुद्ध सैनिक समानाओं द्वारा सब सदस्यों के लिये कर्तव्य निपत किया गया है । फिर भी, वह सयुक्त राष्ट्र सभ व सब विशिष्ट र्यों में भाग लेता है ।

**तटस्थीकृत ( Neutralised ) तथा तटस्थ ( Neutral ) राज्यों में** — तटस्थीकृत राज्य तथा तटस्थ राज्य की स्थिति में जो भेद है वह दृष्टि में खना बहुत आवश्यक है । तटस्थता शब्द स यह व्यक्त होता है कि दो राष्ट्रों के बीच एक संधि है जिसके द्वारा व परस्पर इस बात पर सहमत हो गये हैं कि यदि इनमें से किसी एक पर किसी तीसरे राज्य द्वारा आक्रमण किया जाय तो दूसरा उस लहू के सम्बंध में तटस्थता का रूप धारण करेगा । अतः तटस्थता में दो आवश्यक तत्वे हैं—(१) युद्ध के कार्यों से अलग रहना तथा (२) इस बात की स्वतन्त्रता कि वेचद्वानुसार अलग रहना अथवा न रहना । तटस्थीकरण में पहली बात अर्थात् युद्ध के कार्यों से अलग रहना तो बही बनी रहती है परन्तु दूसरी बात के स्थान में या तो निपत अर्थ में आत्मसंरक्षण की छोड़कर अन्य किसी भी दशा में युद्ध न करने का कर्तव्य रहता है अथवा कुछ स्थानों तथा वस्तुओं का जिनपर अन्तराष्ट्रीय सविदा द्वारा तटस्थता की मुहर लगी रहती है, युद्ध सहज प्रयोग में लाने से अलग रहने का कर्तव्य रहता है । अतः तटस्थता एक अस्थायी मामला है । तटस्थीकरण एक स्थायी उपाय है जिसमें स्थिति का जिम्मा बड़ी शक्तियों की एक सामित सभ्यता की स्पष्ट सविदा द्वारा एवं निश्चित अनुशास्ति के साथ किया जाता है । तदनु रूप तटस्थीकृत

राष्ट्र की ओर से भी यह कर्तव्य होता है कि वह उस प्रकार से रहेगा। अतः तटस्थीकरण का तत्त्व यह है कि यह प्रेरित तटस्थता है। तटस्थीकरण में तटस्थता सम्मिलित है परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि तटस्थता में तटस्थीकरण सम्मिलित हो। सशोध में तटस्थीकरण स्थायी, सामान्य तथा अनैच्छिक होता है परन्तु तटस्थता अस्थायी, विशिष्ट तथा ऐच्छिक होती है। तटस्थीकरण तटस्थता से मूलरूप में भिन्न है। तटस्थता एक नीति है जिसका अवलम्बन अन्य शक्तियों से सम्बन्धित युद्ध की स्थिति में अस्थायी रूप से किया जाता है। वह तटस्थता घोषणा करने वाले राष्ट्र द्वारा किसी समय में भी समाप्त की जा सकती है। इसके विपरीत तटस्थीकरण एक स्थायी स्थिति है जो कि समान हितों वाली शक्तियों द्वारा प्रदान की जाती है और जो उनकी सम्मति के बिना त्याग नहीं की जा सकती।

होली सी ( The Holy See ) — चर्च तथा उसकी प्रधान संस्था होली सी ( Holy See ) ने बराबर लौकिक शक्तियों को अपनी स्वतन्त्रता स्वीकार करने के लिये बाध्य किया है। यद्यपि सन् १८७० में इटली द्वारा पोप की रिमासनों को अपने राज्य में संयुक्त करने के उपरान्त होली सी की प्रादेशिक प्रभुसत्ता समाप्त हो गई तथापि उसकी स्वतन्त्रता राज्य की विधियों द्वारा केवल मानी ही नहीं गई बल्कि स्वीकार की गई। १८७० से १९२९ के मध्यकाल में भी इटली ने होली सी पर कोई प्रभुसत्ता का दावा नहीं किया। इटली की प्रत्याभूति विधि ( Law of Guarantee ) पोप को वे व्यक्तिगत मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार प्रदान करती हैं जो कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा प्रभुसत्ताधारी राज्यों के प्रधानों को दी जाती हैं।

होली सी तथा इटली के बीच में फरवरी ११ सन् १९२९ को हुई लेटरान सन्धि ( Lateran Treaty ) ने पोप नगर ( Vatican city ) को जन्म दिया जिसमें प्रायः १०० एकर भूमि सम्मिलित है और जो कि पोप की प्रादेशिक प्रभुसत्ता का प्रतीक है। इसमें होली सी को प्रादेशिक अधिकार अर्पित किया गया है जिसे उसने १८७० में खो दिया था।

इटली प्रजातन्त्र का नया संविधान भी इस बात का स्वीकार करता है कि राज्य तथा कैथोलिक चर्च अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र तथा प्रभुसत्ताधारी हैं और यह कि उनके सम्बन्ध लेटरान गठबन्धन सन्धि ( Lateran Pacts ) द्वारा निर्धारित होते हैं।

## अध्याय ८

### राज्यों की मान्यता

#### ( Recognition of States )

राज्य की मान्यता वह क्रिया है जिसके द्वारा अन्य राज्य यह स्वीकार करते हैं कि राजनैतिक सत्ता जिस मान्यता प्रदान की जा रही है राज्यत्व के गुणों से युक्त है।

इसका लक्षण — मान्यता अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के एक वर्तमान सदस्य द्वारा अब तक उसके साथ अधिकारिक सम्बन्ध न रखनेवाले किसी राज्य अथवा राजनैतिक समुदाय के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की नियमानुसार स्वीकृति है। इससे यह उपलक्षित है कि स्वीकार करने वाले राज्य की सम्मति में नवजात समुदाय में राज्यत्व के आवश्यक गुण विद्यमान हैं और इसलिए वह अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारों तथा कर्तव्यों के अध्वधीन है।

मान्यता के सिद्धान्त — मान्यता के दो सिद्धान्त हैं — (१) निर्माणक सिद्धान्त (Constitutive Theory) तथा घोषणात्मक अथवा प्रमाणात्मक सिद्धान्त (Declaratory or Evidentiary Theory)। पूर्ववर्ती सिद्धान्त के अनुसार यह केवल मान्यता का ही कार्य है जिससे राज्यत्व का जन्म होता है और एक नयी सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकार का रूप दिया जाता है। हॉलैंड का भ्रूकाव निर्माणक सिद्धान्त की ओर है और इस अर्थ में उनका मत ओपनहेम के मत के समान है। उनका कहना है कि कोई राज्य तब तक परिपक्व नहीं कहा जा सकता जब तक वह मान्यता की मुद्रा से अंकित न हो जा कि उन अधिकारों के उपयोग के लिये परमावश्यक शब्द 'मान्यता' से व्यक्त होते हैं।

उत्तरवर्ती सिद्धान्त के अनुसार राज्यत्व अथवा नयी सरकार का प्राधिकार मान्यता के पूर्व ही से विद्यमान रहता है और मान्यता का कार्य पहले ही से स्थापित तथ्य की केवल नियमानुसार स्वीकृति है। अन्य शब्दों में इस सिद्धान्त के टीकाकार यह प्रतिपादित करते हैं कि मान्यता केवल घोषणात्मक है न कि निर्माणक प्रभाव रखती है। मान्यता केवल इस विद्यमान तथ्य को उद्घोषित करती है कि कोई विशिष्ट समुदाय अथवा सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अपेक्षित राज्य के गुणों से युक्त है। इस सिद्धान्त के टीकाकार हॉल, वैगनर, फ़िलार और पिट कोबेट हैं।

**ओपनहेम का मत :—**ओपनहेम निर्मायिक सिद्धान्त के पक्ष का समर्थन करते हुए यह मत प्रकट करते हैं कि राज्य अनन्य प्रकार से केवल मान्यता द्वारा ही एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति है तथा हो जाता है। यह यद्यपि आशिक रूप से सत्य है तथापि पूर्णतः सत्य नहीं है। इसमें सदेह नहीं कि मान्यता एक मुख्य पद्धति है जिसके द्वारा किसी राज्य के अस्तित्व पर स्वीकृति की मुद्रा अंकित की जाती है। परन्तु यदि यह मत स्वीकार लिया जाय तो फिर यह कारण बतलाना कठिन हो जायगा कि किसी राज्य को कुछ राज्य मान्यता प्रदान करते हैं और कुछ उसे मान्यता प्रदान करने से अस्वीकार करते हैं। लाल चीन की मामोसे तुङ्ग सरकार को यद्यपि भारत, ब्रिटेन, सोवियत रूस तथा एक दर्जन से अधिक अन्य राज्यो द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है तथापि इसे सयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों द्वारा मान्यता नहीं प्रदान की गई है और इसे सयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता नहीं प्राप्त हो सकी है। अमेरिका द्वारा मान्यता प्रदान न किये जाने तथा सयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता न प्राप्त होने पर भी लाल चीन का राज्य अभी, बना ही हुआ है। किसी विशिष्ट प्रदेश के भीतर एक प्रभावशाली स्थिर सरकार का होना ही इस बात को निश्चित कर देता है कि एक नया राज्य विद्यमान है तथा वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन है।

जैसा कि डा० अल्फ्रांस का इस प्रसंग में कथन है, एक प्रभावकारी स्थिरीकृत सरकार, एक निश्चित भू-क्षेत्र के भीतर नये राज्य के उत्पन्न होने और उसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन रहकर कार्य करने के लिए पूर्णतः निर्णायक है।

बुल्शेवाँन बनाम रूसियन सोशलिस्ट फेडरेटेड सोवियत रिपब्लिक के बाद में, यू० एस० कोर्ट ऑफ अपील, न्यूयार्क (१९२२, २३४ एन० वाई० ३७२) का यहाँ तक अवलोकन था कि सोवियत-सभ, भले ही उसकी सरकार सयुक्त राज्य द्वारा मान्यता-प्राप्त नहीं थी फिर भी अमेरिकी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से मुक्त थी। न्यायालय के ही शब्दों में—“The Russian Federated Soviet Republic is the existing de facto government of Russia . . . . Whether or not a Government exists, clothed with the power to enforce its authority within its own territory, obeyed by the people over whom it rules, capable of performing the duties and fulfilling the obligations of an independent power, able to enforce its claims by military force is a fact, not a theory. For its recognition does not create the State, although it may be desirable.” “रूसी फेडरेटेड सोवियत रिपब्लिक रूप की

मान्यतः सरकार है। . . . . यह प्रश्न कि क्या एक सरकार ऐसे अस्तित्व में

है, अथवा नहीं, या कि वह अपने क्षेत्र में ही अपनी शक्ति के प्रवर्तन की शक्ति से अभिभूत है, या कि उस जनता द्वारा उसकी आज्ञाभाषा का पालन किया जाता है जिस पर वह प्रशासन करता है, एक स्वतन्त्र शक्ति के कर्तव्यों को संपादित करने और उसके अभिप्रायों का पूरा करने की समता से युक्त है, अपने दावे को सैन्य शक्ति के बल पर प्रवर्तित कराने में सक्षम है, भावि, एक तथ्य का प्रश्न है, सिद्धान्त का नहीं। मले ही ये तथ्य किसी राज्य के अस्तित्व में होने के लिए आवश्यक हों, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य की संरचना इन तथ्यों की मान्यता पर अवलम्बित है।

किसी राज्य का राजनीतिक अस्तित्व अन्य राज्यों की मान्यता से इस ढंग का बंधा हुआ नहीं है कि उसकी मान्यता के बिना उसके अस्तित्व को ही अस्वीकार किया जा सके। अपितु, यहाँ तक कहा जा सकता है कि इस अस्तित्व का उस मान्यता से कोई अन्योन्याश्रय सम्बन्ध नहीं है।

जर्मन पोलिश आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल (German Polish Arbitral Tribunal) (१९२६) के प्रसङ्ग में कहा गया था कि किसी राज्य की मान्यता इसका निर्मायक तत्व नहीं, उसके अस्तित्व का घोषणात्मक तत्व है।

इसमें सन्देह नहीं कि मान्यता राज्य को अन्य राज्यों से राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ बना देती है। परन्तु यह दृष्टापूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यदि किसी राज्य को मान्यता प्रदान नहीं की गई तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति प्राप्त नहीं होती। वास्तव में राज्य जन्म से ही राज्या के कुटुम्ब का सदस्य हो जाता है और मान्यता इसके स्वतन्त्र राज्य रूप में वर्तमान रहने के लिये मार्ग प्रशस्त कर देती है तथा साक्ष्य पैदा करती है। उपरोक्त मत इस तथ्य से और भी अधिक पुष्ट हो जाना है कि मान्यता बीती हुई घटनाओं पर पूर्वग्राही (Retroactive) है, अर्थात् इसका समय उस पिछली तिथि से प्रारम्भ होता है जब से उस राज्य में, जिसे मान्यता प्रदान की गई है, राज्यत्व के आवश्यक तत्व वास्तव में पाए गये जिससे यह प्रकट होता है कि राज्य मान्यता प्रदान की जाने वाली तिथि के बहुत पहले से ही विद्यमान था।

समन्वित विचार — इस प्रसंग में ठीक ठीक विचार यह प्रतीत होता है कि 'मान्यता' (Recognition) शब्द के अन्तर्गत निर्मायक (Constitutive) और घोषणात्मक (Declaratory) दोनों प्रकार के तत्व उपस्थित हैं। जैसा कि लाउतेरपाख्ट (Lauterpacht) का कथन है, "यह किसी राजनीतिक समुदाय के अस्तित्व का सरल घोषणात्मक तत्व है और घोषणा इस तथ्य का निर्धारण करने

के बाद की जाती है कि उस राजनीतिक समुदाय में परंपरागत राज्यत्व (Statehood) विद्यमान है। ऐसी घोषणा के उपरान्त मान्यता कतिपय वैध परिणामों की निर्मायक (constitutive of certain legal consequences) हो जाया करती है।" स्टार्क (Starke) की भी उपर्युक्त निष्कर्ष से सहमति है, क्योंकि उनका कथन है कि "सत्य इन दोनों सिद्धान्तों के कही बीच में (the truth lies somewhere between the two theories) स्थिर करता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के तथ्यों के प्रसंग में दोनों में से एक या दूसरे किसी भी सिद्धान्त का प्रवर्तन किया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय अभ्यास में बहुधा साक्ष्यमूलक सिद्धान्त (evidentiary theory) का उस विस्तार तक प्रयोग होता है, जहाँ तक कि मान्यता राजनीतिक कारणों के आधार पर दी गई रहती है, और इसीलिए वह प्रकृति में निर्मायक सिद्ध होती है। विविध देश यह मान्यता प्रायः वैध सिद्धान्तों (legal principles) और पूर्ववर्ती दृष्टान्तों (precedents) के आधार पर प्रदान करते या उसे प्रदान करने से अस्वीकार करते हैं।" यही नहीं, अपितु किसी एक राज्य द्वारा मान्यता प्रदान करने से अस्वीकृति मात्र उस परिस्थिति में प्रभावकारी नहीं हो सकती, जब कि उससे पूर्व बड़ी संख्या में अन्य राज्यों ने मान्यता प्रदान कर दी है।"

स्वैलिन (Svarlien) भी इसी विचार से सहमत हैं। उनका कथन है कि, 'It might be said that' recognition is always declaratory in that it confirms the existence of a State and recognizes its legal position in the international community. But it may also, at times, be constitutive in so far as it has the effect of actually creating a State where none existed before.' "यह कहा जा सकता है कि मान्यता सदैव घोषणात्मक होती है, क्योंकि यह किसी राज्य के अस्तित्व में होने का पुष्टीकरण करती है और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी वैध स्थिति को स्वीकार करती है।"

मान्यता क्या एक वैध, राजनीतिक (a legal or a political problem) समस्या है? — साधारणतः मान्यता वैध सिद्धान्तों के आधार पर प्रदा की जाती, अथवा रोकी जाती है। फिर भी, जिन तथ्यों को मान्यता प्रदान करने या रोकते समय ध्यान में रखा जाता है, वे हैं—आर्थिक, सैन्यिक या अन्य राजनीतिक हित। ऐसे प्रसंगों में वर्तमान तथ्यों की अपेक्षा नीति अथवा राजनीतिक कालोचितता से अधिक काम लिया जाता है। यदि इस मान्यता के प्रसंग में प्रभावकारी गुटों का दबाव पड़ता है, जैसा कि इजरायल के प्रसंग में, तो मान्यता सर्वे घोषणात्मकताओं की प्रक्रिया उतनी लंबी नहीं रह जाती और मान्यता दी गई जाती है। किन्तु जैसा कि कोरबेट (Corbett) का कथन है कि, "एक बार में

कोई राजनीतिक समुदाय एक निश्चित अथ तक विकास की स्थिति या लेता है, तो उसे ऐसे अधिकार मिल जाते हैं जो कि वैध उपचार के सबंध में राज्यों में दृष्टा करते हैं। इस अर्थ में, और केवल इसी अर्थ में उसे 'मान्यता प्राप्त' (recognised) होने का अधिकार है। औपचारिक मान्यता (formal recognition) का कोई अधिकार नहीं है।" इसके साथ ही कौरबेट का कथन है कि, "This is something which States grant or refuse at discretion. It is a counter in the harsh game of international politics." "यह कुछ ऐसी चीज है जिसे राज्य अपने विवेक पर या तो स्वीकृत करते अथवा स्वीकृति देने से इन्कार करते हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कठिन खेल का एक टिकटद्वार है।" तात्पर्य यह है कि इस मान्यता के मिल जाने के बाद ही कोई नव-उत्पन्न राज्य अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो पाता है। यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में, जहाँ राजनीतिक विचारों का प्राधान्य है, मान्यता की वैध प्रकृति पर कोई इस तथ्य का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि किसी तथ्य की घोषणात्मकता स्वयं अपने प्रकृति से निर्णायक है।

बैंक आफ चाइना बनाम वेल्स फारगो बैंक और यूनियन ट्रस्ट कम्पनी [(१९५२) १०४ एफ० सु० ५६] के बाद में 'स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट' का अवलोकन था कि अभी निकट-पूर्व में मान्यता की स्वीकृतियाँ और अस्वीकृतियाँ दोनों ही राजनयिक सौदे के सम्बन्धों के दृष्टिकोण से प्रभावित होकर प्रदान की गई हैं, और यह कि इस सम्बन्ध में सघर्षरत विचारों का समुलन कार्यपालकीय निर्णयों में किया गया है।

प्रोफेसर लाउतापैच (Lauterpacht) ने अपने नये निमयिक सिद्धान्त के अन्तर्गत इस बात का संकेत किया है कि मान्यता इस प्रकार की नीति का कार्य (act of policy) नहीं है, जैसा कि परंपरा से मान्य निमयिक सिद्धान्त के अन्तर्गत माना जाता है, और यह कि प्रत्येक राज्य का अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति यह एक कर्तव्य है कि वह किसी नये राज्य, या ऐसी नई सरकार को, जिसमें कि राज्यत्व की वाछनीयतायें पूरी हो, मान्यता प्रदान करें। यह सिद्धान्त 'अन्तर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय' (International Court of Justice) के बहुमत के उस निष्कर्ष के अनुसार है, जो कि समुक्त राष्ट्र सच की सदस्यता की शर्तों के सम्बन्ध में न्यायालय ने अपनी परामर्शमूलक सम्मति देते समय व्यक्त किया था। न्यायालय का अवलोकन था कि 'बार्टर' के अनुच्छेद ४ के पैराग्राफ (१) के अन्तर्गत यह भाष्य है कि ऐसी शर्तों और भाषार जो कि इन सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं, राज्यों को इस सदस्यता के सम्बन्ध में बाधक हो सकते हैं।



स्टार्क (Starke) लाउतरपैत (Lauterpacht) के सिद्धान्त का इस आधार पर विरोध करते हैं कि दृष्टांतों और व्यवहारों की कसौटी पर विधि के सम्बन्ध में उनके विचार खरे नहीं उतरते । उनका कथन है कि इजरायल के नये राज्य (१९४८-४९) और चीन की साम्यवादी सरकार (१९४९-५७) की मान्यता के सम्बन्ध में जो विभिन्नताये हैं, उनसे कठिनाई से समझौता किया जा सकता है । यही नहीं, अपितु उन्हीं के शब्दों में, "Moreover, if there were such a legal duty to recognise, as stated by him, how would it be enforced? To each duty, these must correspond a correlative right, and how would one define this right? Is it a right of the State claiming to be recognised, or a right of the international community, and how would such claims of right be presented? The answer to these questions must be that the practice of States—particularly of the Great Powers—does not support the existence of the duty or the right mentioned ..... Recognition is treated, for the most part, as a matter of vital policy that each State is entitled to decide for itself."

"इससे भी आगे, यदि मान्यता प्रदान करने का कोई ऐसा वैध कर्तव्य हुआ होता जैसा कि लाउतरपैत ने कहा है, तो उसका प्रवर्तन किस प्रकार हो सकता था ? प्रत्येक कर्तव्य के साथ अवश्य ही सलग्न अधिकार का होना आवश्यक है, और तब कोई इस अधिकार की कैसे व्याख्या करता ? क्या यह राज्य का अधिकार है कि वह इस बात का दावा करे कि उसे मान्यता मिल चुकी है, या यह कि उसे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का यह अधिकार मिल चुका है, और फिर इस दावे को किस प्रकार सामने लाया जा सकता था ? इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही यह होना चाहिए कि राज्यों में—विशेष रूप से महान शक्तियों में—जो प्रचलन है उससे इस बात का समर्थन नहीं होता कि इस प्रकार के कर्तव्य या अधिकार का कोई अस्तित्व है ।" अधिकार भाग के लिए मान्यता एक ऐसे अनिवार्य नीति के विषय के रूप में मानी जाती है, जिसे कि प्रत्येक राज्य अपने-आप के लिए निर्धारित करने का अधिकारी है ।" किन्तु प्रत्येक राज्य ऐसी मान्यता प्रदान करते समय इस बात का पूर्ण निश्चय अवश्य कर लेता है कि नव-उत्पन्न राज्य उन सभी शर्तों को पूरा करता है, अथवा नहीं, जिससे कि उसे वैध रूप में 'राज्य' की सत्ता दी जा सके और एतद्विषयक 'मान्यता' प्रदान की जा सके । इस प्रश्न पर अवश्य ही 'मान्यता' वैध सिद्धान्तों को अपने वृत्त में खींच लिया करती है ।

इस विचार का समर्थन संयुक्त राष्ट्र सच के महासचिव के निदेशन में तैयार किए गये मार्च ८ १९५० के 'मेमोरैंडम' में भी किया गया है कि मान्यता प्रदान करना

एक वैध कार्य होने की अपेक्षा एक राजनीतिक कार्य ( a political rather than a legal act ) है । हम 'मेमोरेण्डम' को महासचिव ने साम्यवादो चीन के इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कि सुरक्षा परिषद् एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के विविध अंगों को उन सीटों पर जिन पर 'चीन की राष्ट्रवादी सरकार' आसीन है, साम्यवादी सरकार के प्रतिनिधि रखे जायें, सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किये जाने के निमित्त तैयार कराया था । प्रसंगगत मुख्य-मुख्य अवलोकन इस प्रकार हैं :—

(१) "वैध सिद्धान्त के दृष्टिकोण से, एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में सम्बन्ध का जुड़ना और एक सरकार की मान्यता दो सस्थाओं का एक द्विविधाजनक संयोग है, जिसमें अनावश्यक समानताये तो दिखाई पड़ती हैं, किन्तु अन्तरात्मा दोनों की निम्न हैं ।

(२) "किसी नये राज्य की मान्यता, या किसी अस्तित्व वाले राज्य के नई सरकार की मान्यता एकपक्षीय कृत्य है, जिसे कि मान्यता प्रदान करने वाली सरकार या तो स्वीकृति कर सकती है, या स्वीकृति रोक सकती है । यह सत्य है कि कुछ विधि-विद्वानों ने सबल माथा में यह लिखा है कि जब कभी कोई नई सरकार क्रान्तिकारी साधनों से शक्ति में आती है, जिसके स्थायित्व की सम्भावना दिखाई पड़ती है, जनता के अधिकांश वर्ग की स्वभावेन आज्ञाकारिता उसे मिल जाती है, तो अन्य राज्य एक वैध कर्तव्य के अधीन हो जाते हैं कि वे उस राज्य को मान्यता प्रदान करें । फिर भी, राज्य मान्यता प्रदान करने अथवा रोकने में कुछ वैध सिद्धान्तों का अनुसरण करना आवश्यक मान सकते हैं और राज्यों के इस सम्बन्ध के प्रचलनों से प्रकट होता है कि अब भी मान्यता प्रदान करने का कार्य अनिवार्यतः एक राजनीतिक निर्णय ( essentially a political decision ) माना जाता है, जिसे कि प्रत्येक राज्य प्रसंगगत परिस्थितियों पर अपनी व्याख्या-नुसार स्वतन्त्र इच्छा से निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं ।"

किसी राज्य की मान्यता प्रदान करना या न करना, एक राजनीतिक विषय है—इसका स्पष्टीकरण और भी इस आधार पर हो जाता है कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में कार्यपालकीय निर्णय ( executive decisions ) या अपने-अपने राज्य के वैदेशिक कार्यालय के प्रतिवेदनों को इस विषय में अन्तिम और प्रभावकारी माना जाता है ।

चूँकि किसी राज्य, या सरकार की मान्यता एक वैयक्तिक कार्य ( individual act ) है, और संयुक्तराष्ट्र संघ में सदस्यता के लिए प्रविष्टि या स्वीकृति या संगठन में प्रतिनिधित्व सामूहिक कृत्य ( collective acts ) है, अतः किसी राज्य

के लिए वैध रूप में मान्य नहीं हो सकता कि उसे संगठन में वैध रूप में पूर्व-मान्यता प्राप्त ही हो जाय। यह पद्धति 'लीग ऑफ नेशन्स' और 'संयुक्त राष्ट्र संघ' दोनों की सदस्यता के लिए प्रवर्तित रही है।

नियमानुसार मान्यता अधिकांश दशाओं में आर्थिक व युद्ध कीशल नीति अथवा अन्य राजनैतिक हितों की दृष्टि से निश्चित होती है। यह वर्तमान तथ्यों की स्वीकृति से अधिक कूटनीति तथा राजनैतिक औचित्य के आधार पर अनुशासित होती है। कौरबेट का कथन है कि जब कोई राजनैतिक समुदाय एक बार उन्नति की एक विशिष्ट स्थिति में पहुँच जाता है तो उसको वैध व्यवहार के लिये ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि राज्यों के बीच विद्यमान हैं। इस अर्थ में और केवल इसी अर्थ में इसको "मान्यता" का अधिकार प्राप्त होता है। नियमानुसार मान्यता के लिये कोई अधिकार नहीं है। इसे राज्य अपने विवेकानुसार देते हैं अथवा देना प्रस्वीकार करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कठोर दाँव का यह पाँसा है।

मान्यता के भेद :—मान्यता प्रकट (express) अथवा अप्रकट (implied) होती है। प्रकट मान्यता किसी नियमानुसार घोषणा द्वारा दी जाती है। अप्रकट मान्यता सन्धि-स्थापन द्वारा अथवा राजनैतिक प्रतिनिधियों के अधिकार-पत्र प्रदान करके दी जाती है। तथ्यतः मान्यता (De facto recognition) तथा विधितः मान्यता (De jure recognition) में भेद बतलाते हैं। तथ्यतः मान्यता का यह अर्थ है कि मान्यता प्रदान करने वाले राज्य की सम्मति में नया प्राधिकारी यद्यपि वास्तव में स्वतन्त्र है तथा अपने अधीन प्रदेश में प्रभावपूर्ण अधिकार रखता है तथापि इसने अभी इतनी पर्याप्त स्थिरता नहीं प्राप्त की है जिससे यह प्रकट हो कि यह अपनी स्वतन्त्रता एक दीर्घकालीन अवधि तक बनाये रख सकेगा। यह फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा निर्धारित माँगों को पूरा करता है। विधितः मान्यता का यह अर्थ होता है कि मान्यता प्रदत्त राज्य अथवा सरकार उन कसौटियों में ठीक उतरती है जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रभावशाली भाग लेने के लिये निर्धारित किये गये हैं। इससे राजनैतिक प्रतिनिधियों का तथा अभी जहाजों के बीच सलामी का आदान-प्रदान आवश्यक हो जाता है।

प्रतिबन्धयुक्त मान्यता (Conditional Recognition)—राज्यों की कभी-कभी वृत्तिपय प्रतिबन्धों से युक्त भी मान्यता प्रदान की जाती है। १८७८ की बर्लिन कांग्रेस ने बुल्गारिया, रूमानिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो राज्यों को इस शर्त पर मान्यता प्रदान की थी कि उन्होंने अपनी प्रजा पर किसी प्रकार की धार्मिक अवहेता (religious disability) आरोपित नहीं की थी। चूँकि एक बार मान्यता प्रदान

कर दी जाने पर साधारणतया वापस नहीं की जाती, अतः इस शर्त की पूर्ति में उन राज्यों का असफल होना मान्यता को धुन्यवृत्त नहीं करता । मान्यता प्राप्त राज्य यदि किसी अपराध का दोषी हो सकता है, तो वह अपराध अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन (Violation of International Law) ही है । मान्यता प्रदान करने वाला राज्य भी अनुशास्ति (sanction) के रूप में राजनयिक सम्बन्धों को दूर कर सकता है, इससे अधिक कोई वैध दण्ड नहीं दे सकता ।

प्रोफेसर लाउतरपैत ने राज्या के इस अभ्यास की भर्त्सना की है कि वे मान्यता प्रदान करने में कुछ प्रत्याभूति (गारंटी) या शर्तनामा (undertaking) आरोपित कर देते हैं । यह 'मान्यता' की ठीक-ठीक प्रकृति के विपरीत है, क्योंकि मान्यता राज्यत्व अथवा सरकार की क्षमता की कतिपय बाह्यनीयताओं के लक्षणों का विनिश्चय और उनकी उद्घोषणा का एक तत्त्व है । किन्तु स्टार्क इस विचार से सहमत नहीं है, और उनका कथन है कि न्यायमूर्ति लाउतरपैत प्रचलन की गुस्ता को ही दृष्टि से भ्रमल नहीं कर देते, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर मान्यता के जो महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, उन पर भी दृष्टिपात नहीं करते, उदाहरण के लिए, जहाँ तक कि संपत्ति अधिकारों (property rights) का सम्बन्ध है प्रत्येक राज्य को अपने लिये इन अधिकारों पर विचार करने का अधिकार है ।

न्यायमूर्ति लाउतरपैत इस विचार के भी हैं कि नये राज्य या नई सरकार को मान्यता देने में यह कसौटी रखना कि वह अन्तर्राष्ट्रीय आचारों को पूरा करने के लिये इच्छुक है, 'संदिग्ध न्यायिक औचित्य' (doubtful juridical soundness) से युक्त है, क्योंकि इस कसौटी से मान्यता की वास्तविक प्रकृति और प्रयोजन का कोई सम्बन्ध नहीं है । यहाँ भी स्टार्क महोदय उपर्युक्त विचार से सहमत नहीं हैं, और उनका कथन है कि उपर्युक्त अवलोकन राज्या में प्रचलित अभ्यास के विपरीत है । इस विचार में असंगति की ओर इंगित करते हुये उनका कथन है कि समुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता किसी राज्य को राजत्व, या किसी सरकार को सरकारत्व के लिए प्रमाण है, क्योंकि चार्टर के अनुच्छेद ४ में उपबन्धित है कि समुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता ऐसे 'शान्ति-प्रिय राज्यों' (peace-loving States) के लिए खुली हुई है, जो कि सभ के निर्णयानुसार चार्टर के आचारों (obligations of the Charter) को पूरा करने और उसका अनुशासन करने के लिए समर्थ और इच्छुक (able and willing) हैं ।<sup>१</sup>

१. स्टार्क 'ऐन इण्ट्रोडक्शन टु इन्टरनेशनल ला', चतुर्थ संस्करण पृ० १३.

के लिए वैध रूप में मान्य नहीं हो सकता कि उसे संगठन में वैध रूप में पूर्व-मान्यता प्राप्त ही हो जाय। यह पद्धति 'लीग आफ नेशन्स' और 'संयुक्त राष्ट्र संघ' दोनों की सदस्यता के लिए प्रवर्तित रही है।

नियमानुसार मान्यता अधिकांश दशाओं में आर्थिक व युद्ध कौशल नीति अथवा अन्य राजनैतिक हितों की दृष्टि से निश्चित होती है। यह वर्तमान तथ्यों की स्वीकृति से अधिक कूटनीति तथा राजनैतिक आचित्य के आधार पर अनुशासित होती है। कौरवेट का कथन है कि जब कोई राजनैतिक समुदाय एक बार उन्नति की एक विशिष्ट स्थिति में पहुँच जाता है तो उसको वैध व्यवहार के लिये ऐसे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि राज्यों के बीच विद्यमान हैं। इस अर्थ में और केवल इसी अर्थ में इसको "मान्यता" का अधिकार प्राप्त होता है। नियमानुसार मान्यता के लिये कोई अधिकार नहीं है। इसे राज्य अपने विवेकानुसार देते हैं अथवा देना अस्वीकार करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के कठोर दाँव का यह पाँसा है।

मान्यता के भेद :—मान्यता प्रकट (express) अथवा अप्रकट (implied) होती है। प्रकट मान्यता किसी नियमानुसार घोषणा द्वारा दी जाती है। अप्रकट मान्यता सन्धि-स्थापन द्वारा अथवा राजनैतिक प्रतिनिधियों के अधिकार-पत्र प्रदान करके दी जाती है। तथ्यतः मान्यता (De facto recognition) तथा विधितः मान्यता (De jure recognition) में भेद बतलाते हैं। तथ्यतः मान्यता का यह अर्थ है कि मान्यता प्रदान करने वाले राज्य की सम्मति में नया प्राधिकारी यद्यपि वास्तव में स्वतन्त्र है तथा अपने अधीन प्रदेश में प्रभावपूर्ण अधिकार रखता है तथापि इसने अभी इतनी पर्याप्त स्थिरता नहीं प्राप्त की है जिससे यह प्रकट हो कि यह अपनी स्वतन्त्रता एक दीर्घकालीन अवधि तक बनाये रख सकेगा। यह फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा निर्धारित माँगों को पूरा करता है। विधितः मान्यता का यह अर्थ होता है कि मान्यता प्रदत्त राज्य अथवा सरकार उन कसौटियों में ठीक उतरती है जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रभावशाली भाग लेने के लिये निर्धारित किये गये हैं। इससे राजनैतिक प्रतिनिधियों का तथा जमी जहाजों के बीच सलामी का आदान-प्रदान आवश्यक हो जाता है।

प्रतिबन्धयुक्त मान्यता (Conditional Recognition)—राज्यों की कभी-कभी वतिपय प्रतिबन्धों से युक्त भी मान्यता प्रदान की जाती है। १८७८ की बर्लिन कांग्रेस ने बुल्गारिया, रूमानिया, सर्बिया और मोंटनिग्रो राज्यों को इस शर्त पर मान्यता प्रदान की थी कि उन्होंने अपनी प्रजा पर किसी प्रकार की धार्मिक अन्तर्द्वेष (religious disability) आरोपित नहीं की थी। चूँकि एक बार मान्यता प्रदान

कर दी जाने पर साधारणतया वापस नहीं की जाती, अतः इस शर्त की पूर्ति में उन राज्यों का असफल होना मान्यता को शून्यकृत नहीं करता । मान्यता प्राप्त राज्य यदि किसी अपराध का दोषी हो सकता है, तो वह अपराध अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन (Violation of International Law) ही है । मान्यता प्रदान करने वाला राज्य भी अनुशास्ति (sanction) के रूप में राजनयिक सम्बन्धों को दूर कर सकता है, इससे अधिक कोई वैध दंड नहीं दे सकता ।

प्रोफेसर लाउत्तरपैत ने राज्यों के इस अभ्यास की भर्त्सना की है कि वे मान्यता प्रदान करने में कुछ प्रत्याभूति (गारंटी) या शर्तनामा (undertaking) आरोपित कर देते हैं । यह 'मान्यता' की ठीक-ठीक प्रकृति के विपरीत है, क्योंकि मान्यता राज्यत्व अथवा सरकार की समता की कतिपय वाछनीयताओं के लक्षणों का विनिश्चय और उनकी उद्घोषणा का एक तरफ है । किन्तु स्टार्क इस विचार से सहमत नहीं है, और उनका कथन है कि न्यायभूति लाउत्तरपैत प्रचलन की गुरुता को ही दृष्टि से भ्रमल नहीं कर देते, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर मान्यता के जो महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, उन पर भी दृष्टिपात नहीं करते, उदाहरण के लिए, जहाँ तक कि संपत्ति अधिकारों (property rights) का सम्बन्ध है प्रत्येक राज्य को अपने लिये इन अधिकारों पर विचार करने का अधिकार है ।

न्यायभूति लाउत्तरपैत इस विचार के भी हैं कि नये राज्य या नई सरकार को मान्यता देने में यह कसौटी रखना कि वह अन्तर्राष्ट्रीय आचारों को पूरा करने के लिये इच्छुक है, 'संदिग्ध न्यायिक भौचित्य' (doubtful juridical soundness) से युक्त है, क्योंकि इस कसौटी से मान्यता की वास्तविक प्रकृति और प्रयोजन का कोई सम्बन्ध नहीं है । यहाँ भी स्टार्क महोदय उपर्युक्त विचार से सहमत नहीं हैं, और उनका कथन है कि उपर्युक्त अवलोकन राज्यों में प्रचलित अभ्यास के विपरीत है । इस विचार में असंगति की ओर इंगित करते हुये उनका कथन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता किसी राज्य को राजत्व, या किसी सरकार को सरकारत्व के लिए प्रमाण है, क्योंकि चार्टर के अनुच्छेद ४ में उपबन्धित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ऐसे 'शान्ति-प्रिय राज्यों' (peace-loving States) के लिए खुली हुई है, जो कि संघ के निर्णयानुसार चार्टर के आचारों (obligations of the Charter) को पूरा करने और उसका अनुशीलन करने के लिए समर्थ और इच्छुक (able and willing) हैं ।<sup>१</sup>

१. स्टार्क: 'ऐन इण्ट्रोडक्शन टु इन्टरनेशनल ला', चतुर्थ संस्करण पृ० १३.

**सामूहिक मान्यता ( Collective Recognition )**—एक अन्तर्राष्ट्रीय सस्या के माध्यम से सामूहिक मान्यता इस मतभेद या वैषम्य को दूर करती है कि कुछ राज्य उस नये राज्य को मान्यता प्रदान कर रहे हैं, और कुछ ऐसा करने से अस्वीकार कर रहे हैं। लंदन की संधि ( Treaty of London ) ने १८३० में ग्रीस को और बेल्जियम को १८३१ में मान्यता प्रदान की। १८७८ की बर्लिन कांग्रेस ने सामूहिक रूप से बुल्गारिया, मॉण्टेनिग्रो, सर्बिया और रूमानिया को मान्यता दी, जब कि 'सुप्रीम कौंसिल आफ दौ एलाइड पावर्स' ने १९२१ में येल्योनिया और अल्बानिया को मान्यता दी। यह मान्यता फ्रान्स, इटली, जापान और ग्रेट ब्रिटेन की ओर से सामूहिक रूप में दी गई थी और फिर इसके लिये इन राष्ट्रों की पृथक्-पृथक् मान्यता की आवश्यकता न पड़ी।

यह सामूहिक मान्यता मान्यता प्राप्त राज्य के लिए राष्ट्रों के परिवार में सदस्य के रूप में सामने आने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। ऐसी सामूहिक मान्यता कतिपय लेखकों द्वारा 'simultaneous or general recognition' 'क्रमिक या साधारण मान्यता' के रूप में मानी गई है और यह कहा गया है कि आज यदि कोई सामूहिक मान्यता सम्भव है तो केवल किसी राज्य का किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त करना है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनी सदस्यता के लिये स्वीकृति।

किन्तु यह भी कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रविष्ट एक ऐसे प्राइवेट क्लब में प्रविष्टि पाने के समान है जो कि प्रविष्टि मिल जाने के बाद 'राज्य' ( Statehood ) नहीं प्रदान करता। इसके प्रमाण-स्वरूप यह कहा जाता है कि बाइलो-रूस ( Byelo-Russia ) और उक्रेन ( Ukraine ) को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रविष्टि के उपरान्त भी राज्यत्व का उससे अधिक पद नहीं मिल पाया, जितना कि असदस्य राज्य स्विटजरलैंड का रहा। केवल इजरायल और लीबिया जैसे ही प्रसंगों में कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के राजनीतिक कार्यों ने राज्यत्व के गुण प्रदान किये, किन्तु राज्य का उत्पन्न होना ही इन कार्यों से निगुणिक रूप में मान्य हो सका, मान्यता का प्रदान किया जाना नहीं।

**सामूहिक अमान्यता ( Collective Non-recognition )**—एक सां-  
 दृष्टिक प्रमान्यता, जैसे कि पहले 'लोग आफ नेगन्स' और अब संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमान्यता में विभी वर्तमान स्थिति के विरुद्ध विरोध परिलक्षित होता है। 'तीन आफ नेगन्स' की संस्तुति पर मंडुगो की सामूहिक प्रमान्यता ऐसे ही सामूहिक विरोधी प्रक्रिया का एक प्रमाण है।

जैसा कि पैलेस्टाइन के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद में संयुक्त राज्य सभ के प्रतिनिधि ने अवलोकन किया था कि सामूहिक मान्यता के मार्ग में कठिनाई यह है कि एक संप्रभु राज्य की कुछ शक्तियाँ और कुछ अधिकार होते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों द्वारा कम नहीं किये जा सकने हैं और विशेष रूप से एक तात्कालिक सरकार की तत्थ्यत स्वीकृति में कम नहीं किये गये हैं।

इससे आगे, यह भी उल्लेखनीय है कि राज्यों ने किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से सामूहिक मान्यता प्राप्त करने के सिद्धान्त को अस्वीकार कर दिया है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सभ से सामूहिक मान्यता। संयुक्त राष्ट्र सभ को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह या तो किसी नये राज्य को, अथवा किसी अस्तित्वपूर्ण राज्य की सरकार को मान्यता प्रदान कर सके। संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा सामूहिक मान्यता के प्रश्न को स्थिर करने के प्रयोजन के लिये या तो चार्टर में संशोधन वांछित होगा, अथवा कोई ऐसी सन्धि करनी होगी जिसका सम्मान सभी राष्ट्र कर सकें।

तथ्यतः और विधितः मान्यता (De facto and De jure recognition)—राजनीतिज्ञों ने मान्यता को 'तथ्यतः' और 'विधितः' मान्यता के वर्गों में भी बाँटा है। तथ्यतः मान्यता का तात्पर्य है—मान्यता प्रदान करने वाले राज्य की सम्मति में नया प्राधिकारी, यद्यपि वह वस्तुतः स्वतन्त्र है और अपने अधीनस्थ क्षेत्र में शक्ति-सम्पन्न है, फिर भी इतनी पर्याप्त दृढ़ता नहीं प्राप्त कर सका है कि उससे यह प्रकट हो कि वह लम्बी अवधि तक अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखेगा, किन्तु इतना होते हुये भी उसने इतनी क्षमता प्राप्त कर ली है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि की वादनामों को पूरा करता है और चाहे तात्कालिक रूप में, या अस्थायी रूप में, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रभावकारी रूप से भाग ले सकता है। विधितः मान्यता का तात्पर्य है—मान्यता प्राप्त राज्य या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत निर्धारित कसौटी को पूरा करती है जिससे कि वह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रभावकारी रूप से भाग ले सके। इसके अनुसार उस राज्य द्वारा राजनयिक प्रतिनिधियों के आदान प्रदान और युद्ध की अवस्था में सैनिक औपचारिकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है।

ब्रिटिश प्रचलन के अनुसार किसी नये राज्य या नई सरकार को विधित मान्यता स्वीकृत करने के लिए तीन पूर्ववर्ती शर्तों का होना आवश्यक है—(१) दृढ़ता और स्थायित्व का एक तर्कसंगत आश्वासन (a reasonable assurance of stability and permanence), (२) सरकार को जनता के सर्वसाधारण का



मर्मर्न प्राप्त है (The Government commands the general support of the population); और (३) वह अपने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों (international obligations) को पूरा करने के योग्य और इच्छुक है (it is able and willing to fulfil its international obligations)।<sup>१</sup>

राज्यों के प्रचलन के अनुसार 'तथ्यतः' मान्यता अन्तःकालीन (provisional) होती है और उसके परिणाम-स्वरूप संभव है कि पूर्ण राजनयिक अन्तःसम्बन्ध का निर्वाह न हो सके, किन्तु यह 'विधितः' मान्यता के लिए एक प्रथम सोपान है।

लाउत्तरपैत के अनुसार तथ्यतः मान्यता किसी राज्य की उस इच्छा की एक अभिव्यक्ति है कि वह प्रभुता वाले तन्त्र के सहित अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रविष्ट करना चाहता है, किन्तु इस इच्छा के साथ सामान्य राजनयिक औपचारिकताएँ नहीं सलग्न हैं।<sup>२</sup>

कुछ विद्वान् तथ्यतः मान्यता को राज्यत्व की मान्यता के लिए एक प्रतिबन्ध-युक्त निकाय मानते हैं। इनसे नये निकाय की स्थिरता के सम्बन्ध में एक संदेह आभासित होता है और समय से पूर्व प्राप्त विधितः मान्यता से वह मौलिक राज्य के प्रति कोई अपराध कथित करने से बच जाता है।

गागरा (Gagara)<sup>३</sup> के बाद में, जहाँ कि 'इस्थोनियन नेशनल कौंसिल' का प्रश्न उठाया गया था, विधि-अधिकारियों ने न्यायालय को सूचित किया था कि 'हिज़ मैजेस्टी की सरकार' ने अन्तःकालीन रूप में 'इस्थोनियन कौंसिल' को तथ्यतः स्वतन्त्र निकाय के रूप में मान्यता प्रदान की थी। 'कोर्ट ऑफ अपील' का अवलोकन था कि इस प्रकार की अन्तःकालीन मान्यता, जो तत्कालिक समय के लिए प्रदान की गई है, 'इस्थोनियन नेशनल कौंसिल' को एक वैदेशिक संप्रभु (A foreign sovereign) की स्थिति प्रदान करती है।

एक विभ्रष्टहित विधितः सरकार और एक तथ्यतः नवगठित सरकार के बीच के संघर्ष में अंग्रेजी विधि न्यायालय का अवलोकन है कि तथ्यतः सरकार के अधिकार और पद विधितः सरकार के ऊपर अधिभावी होते हैं। इस सूत्र का प्रवर्तन दो वादों में किया गया था, अर्थात् "बैंक ऑफ यूरोपिया" बनाम 'नेशनल बैंक

१. स्मिथ: ग्रेट ब्रिटेन ऐंड दी लॉ ऑफ नेशनस, वाल्यूम १, पृ० ७६.

२. लाउत्तरपैत (Lauterpacht) : रिकागिनशन इन इंटरनेशनल लॉ, पृ० ३५८.

३. (१९१९) प्रोबेट ६५.

भाव इजिप्ट<sup>१</sup> और लीगर और एस० एस० भरन्तजाज़ू मेंडी बनाम स्पेन की रिपब्लिकन सरकार<sup>२</sup> के बाद में ।

वैंक आफ यूरोपिया के बाद में मान्यता के निर्धारण का प्रश्न १९३६ में इटली द्वारा अबीसीनिया-विजय के परिणामस्वरूप उठा था । इटली की सरकार ने, अबीसीनिया की तथ्यत मान्यता के उपरान्त कुछ ऐसी विधियों का अधिनियमन किया जो कि अबीसीनिया के निष्कासित सम्राट की विधियों के सघर्ष में थी, और जो कि निष्कासन में रहते हुये भी अबीसीनिया का विधितः शासक माना जाता था । न्यायमूर्ति क्लाऊज़न (Clauson J.) का मतलोकन था कि विधितः शासक का प्राधिकार मात्र सैद्धान्तिक है और प्रवर्तन के योग्य नहीं है, जब कि इटली की सरकार अबीसीनिया के नियन्त्रण में है और तथ्यतः मान्यता प्राप्त कर चुकी है । अतः इस सरकार को ही विधियाँ अधिनियमित करने का अधिकार है, विधितः प्रशासक को नहीं ।

एस० एस० भरन्तजाज़ू मेंडी के बाद में जहाँ कि स्पेन के गृह युद्ध (१९३६-३८) में वैधानिक और प्रभुत्व वाली सरकारों के बीच सघर्ष था, स्थिति यह थी कि नये प्रभुत्व वाली सरकार ने स्पेन के अधिकांश भाग को जीत लिया था । ग्रेट ब्रिटेन स्पेन की 'रिपब्लिकन गवर्नमेंट' को अब भी स्पेन की विधितः सरकार के रूप में मान्यता दे रहा था, किन्तु साथ ही उसने स्पेन के जीते हुये क्षेत्रों के लिए नई सरकार को भी तथ्यत मान्यता प्रदान कर दी । जेनरल फ्रांको की नव-गठित तथ्यतः सरकार के विरुद्ध स्पेन की विधितः सरकार ने 'ब्रिटिश ऐडमिरैल्टी कोर्ट' के समक्ष विचारण हेतु मामला प्रस्तुत किया जिससे प्रसंगगत पोत पर उसे कब्जा वापस मिल सके । पोत का पञ्जीकरण बिलबाओ बन्दरगाह पर किया गया था, जो कि फ्रांको की सरकार द्वारा कब्जे में कर लिया गया था । जेनरल फ्रांको की तथ्यतः सरकार ने एक विदेशी राज्य में अपने विरुद्ध मुकदमे से उन्मुक्ति का दावा किया, क्योंकि वह अपने को एक पूर्णतः मप्रभु राज्य उद्घोषित कर रहा था । प्रसंगगत पोत बिलबाओ बन्दरगाह पर तथ्यतः सरकार के नियन्त्रण में था । किया गया था और उसे अर्जन सम्बन्धी डिक्ली (Requisition Decree) के अन्तर्गत उस सरकार को इंग्लैंड में हस्तान्तरित किया गया था । यह प्रक्रिया ने 'सार्जन्स सभा' में स्मरणीय निर्णय उद्घोषित करते हुये कहा था कि तथ्यतः सरकार के सभी कृत्यों का संपादन कर रही है जो कि विधि और अधिकांश की बनाने वाले हैं।

१. (१९३७) च० ५१३.

२. (१९३६) ए० सी० २५६.

विधि-न्यायालयों के पोषण और प्रवर्तन को स्थिर रखने; विधियों को धराने की लागू करने, आदि के प्रसंग में एक पूर्ण संप्रभु सरकार किया करती है : अतः सर्वे पान, चाहे युद्ध-योन हो या व्यापारिक पोत हो, उन पर स्वरव सधनः सरकार का हा है । विधितः सरकार का यह तर्क कि सधनतः प्रशासन संप्रभु राज्य गठित नहीं करता, अमान्य कर दिया गया और नवगठित राज्य को उसके दावे के अनुग उन्मुक्ति प्रदान कर दी गई ।

विदेशिक कार्यालय से सूचना ( *Information from Foreign Office* )—संबंधित देशों के विदेशिक कार्यालयों से उस देश को इस सूचना की प्राप्ति कि किसी नये राजनातिक समुदाय ने ऐसे समुदाय का स्तर प्राप्त कर लिया है, उस देश के न्यायालयों के लिए निर्णायक तत्व है । यह विचार 'गिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकारपोरेट' बनाम 'सेएट्स एयर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन' के प्रसंग में व्यक्त किया गया था । इसी प्रकार का संदर्भ अरन्जामेंटों के भी बाद में किया गया था, जिसका कि उल्लेख पहले किया जा चुका है ।

किसी विदेशी राज्य या सरकार की माग्यता के सम्बन्ध में नार्मल की उपायगता गदैव निर्णायक और निष्कर्षात्मक मानी जाती है और उस देश के न्यायालय के लिए बाध्यकारी मानी जाती है; और के उद्घोषणार्थ राज्य के कूर्यों के का है मानी जाती है, जो कि राज्य के प्रधान के विवेकाधीन है । [सूवर बनाम सादी, होरा, दूठ देवगामेंट बनाम गवर्नमेंट आफ़ द एटन और गुमगान आदर बनाम अगूरेर टुन्ड] ]

प्रश्न है, जिसका कि किसी सरकार के विधायी और कार्यपालिकीय विभागों का निर्धारण वहाँ के न्यायाधीशों के लिए बाध्यनापूर्ण है, साथ ही उस निर्धारण की उतनी ही बाध्यता वहाँ के अन्य अधिकारियों, नागरिकों और उस सरकार की प्रजाओं के लिए भी है।

न्यायालयों की मान्यता और अमान्यता के सम्बन्ध में विदेशी सरकारों के कार्याग की नीति को निस्सार या निर्णयोजन नहीं समझना चाहिए। किसी भी विशिष्ट स्थिति में कार्याग की नीति महत्वपूर्ण हो सकती है। किन्तु यह एक तथ्य है जिस पर कि न्यायालय में अन्य नथ्यों के साथ ही अवश्य विचार कर लिया जाना चाहिये। ( बैंक ऑफ चाइना बनाम वेस्त फारमो बैंक और यूनिपन ट्रस्ट कम्पनी ।<sup>१</sup> ) ।

तथ्यतः और विधितः मान्यता (Distinction between De Facto and De Jure Recognition)—तथ्यतः और विधितः मान्यताओं के बीच अन्तर स्पष्ट करते हुये स्वार्जेनबर्जर (Schwarzenberger) का निम्नलिखित अवतरण बहुत ही महत्वपूर्ण है—“De facto recognition is by nature provisional and may be made dependent on conditions with which the new entity has to comply. It differs from de jure recognition of a State. There is not yet a formal exchange of diplomatic representatives. The jurisdiction of the new international person is merely recognised (to exist within its own territory and any extra territorial effects of such jurisdiction are ignored. Thus, if a State which has received de jure recognition, should nationalise companies within its territory, its ownership in the property of such companies abroad (securities, land or ships) cannot be denied. If, however, such a State had merely obtained de facto recognition, such acts are without effect if purporting to apply to property in the country that has granted such de facto recognition .....there is an increasing tendency, both in decisions of national courts and amongst writers, to assimilate the effects of de facto recognition of a State to those of de jure recognition.... In contrast to de facto recognition, de jure recognition is considered to be retrospective, that is to say, to date back to the time when the newly recognised entity actually came into existence.”<sup>२</sup> अर्थात् “तथ्यतः

१. १०४ एफ० सुप० ५६.

२. जार्ज स्वार्जेनबर्जर : ए मैनुअल ऑफ इंटरनेशनल ला, पृ० २८-२९.

मान्यता स्वभावेन अन्तःकालीन है और ऐसी शर्तों के अधीन की जा सकती है जिसे कि नई इकाई को पूरा करना है। यह किसी राज्य की विधित मान्यता से भिन्न है। इसमें अभी तक राजनयिक प्रतिनिधियों के आदान-प्रदान की औपचारिकता शेष रहती है। इसमें नये अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति का क्षेत्राधिकार स्वयं अपने क्षेत्र में अस्तित्व में होने की बात मान्य कर ली जाती है और ऐसे क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किसी क्षेत्राधिकार की उपेक्षा कर दी जाती है। इस प्रकार यदि एक राज्य को, जिसने कि विधितः, मान्यता प्राप्त कर ली है, मंजूर है कि वह अपने क्षेत्र के भीतर की कंपनियों का, और देश के बाहर उन कंपनियों की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करे (प्रतिभूति, स्थल अथवा पोत) और उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किन्तु, यदि ऐसे राज्य को केवल तथ्यतः मान्यता मिली है, तो उसके ऐसे कृत्य उस समय प्रभावशून्य होंगे यदि उस देश में निहित संपत्ति के सदर्थ में हैं, जिसने कि ऐसी तथ्यत मान्यता दी है। ..... एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति राष्ट्रीय न्यायालयों और लेखकों, दोनों में दिखाई पड़ रही है कि किनो राज्य की तथ्यत मान्यता को विधितः मान्यता के प्रभावों से छुला-मिला दिया जाता है। ... तथ्यत मान्यता के विपरीत, विधितः मान्यता पूर्वलक्षी प्रभाव से युक्त मानी जाती है। तात्पर्य यह है कि इसका प्रभाव आज की तिथि से पीछे उस तिथि तक रहता है, जब कि नव-निर्मित इकाई वस्तुतः अस्तित्व में प्रकट हुई थी।"

जैसा कि ऊपर कहा गया है, तथ्यतः मान्य स्वभाव से अन्तःकालीन या अन्तिमकालीन होती है और इससे व्यक्त होता है कि मान्यता प्रदान करने वाला राज्य मान्यता-प्राप्त राज्य को, "as an authority in fact, with disputed control within the territorial limits of that State" उस राज्य को एक तथ्यत ऐसे प्राधिकार के रूप में मानता है जिसका नियंत्रण उस क्षेत्रीय सीमा के भीतर ही निहित है। ऐसी तथ्यतः मान्यता व्यावहारिक कारणों से प्रदान की जाती है और इसमें राजनयिक सह-संघ की प्रतिभूति नहीं होती। न तो, ऐसी तथ्यतः मान्यता के अन्तर्गत यह प्रश्न ही अन्तर्गस्त होता है कि तथ्यतः सरकार ने वैध साधनों से शक्ति प्राप्त की है, अथवा अवैध साधनों से। दूसरी ओर विधितः मान्यता अपने प्राप्ति में ही पूर्ण मान्यता है, और इसके अन्तर्गत पूर्ण और सामान्यतः सभी राजनयिक सम्बन्ध उपस्थित होने का प्रश्न अन्तर्गस्त रहता है। दोनों के वैध प्रभावों में सामान्यतः कोई अन्तर इसलिए नहीं पड़ता कि विधितः मान्यता पूर्वलक्षी प्रभाव से युक्त होती है, और उसके मिल जाने पर अपने देश से बाहर स्थित अपनी संपत्ति पर भी पूर्वलक्षी प्रभाव मसब हो जाता है। दोनों को, मुद्द-स्थिति के अनुरूप, सामान्यतः सम्बन्धों से समान उन्मुक्ति प्राप्त है।

मान्यता के लिए विचारणीय तथ्य (Considerations for Recognition)—परंपरागत विचार यह रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि किसी राज्य पर यह कर्तव्य आरोपित नहीं करती कि वह नये राज्यों को मान्यता प्रदान करे। वास्तविकता तो यह है कि मान्यता अधिवाशतः एक नीति का प्रश्न है, विधि का नहीं। राज्यों ने बहुधा नव-गठित राज्य या सरकार को मान्यता प्रदान करने में विलंब किया है, इन्कार कर दिया है, या सहसा फिर प्रदान कर दिया है। कारण बूटनीतिक या राजनयिक रहे हैं। प्रथम विश्व महायुद्ध में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स और संयुक्त राज्य और अन्य शक्तियां न पोलेंड और जेकोस्लोवाकिया को उस समय से पहले ही मान्यता दे दी थी, जबकि वस्तुतः इनका अस्तित्व स्वतंत्र राज्य या सरकार के रूप में सामने आया। रूस की सावियत सरकार ने प्रसंग में जिसकी स्थापना १९१७ में हुई, संयुक्त राज्य और अन्य शक्तियों द्वारा कुछ वर्षों तक मान्यता देने से रोक लगा दिया गया। अशत. कारण यह था कि उस सरकार की भविष्य और निरंतरता के संबंध में कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता था और अशतः कारण यह था कि वे बोलशेविक सिद्धान्तों के विरुद्ध थे।

इस प्रसंग में मार्च २१, १९२३ को सचिव ह्यूस ने कहा था कि, "In the case of Russia we have a very easy test in a matter of fundamental importance, and that is of good faith in the discharge of international obligations. I say that good faith is a matter of essential importance because words are easily spoken. Of what avail to speak of assurances, if valid obligations and rights are repudiated and property confiscated." "रूस के प्रसंग में हमारे समक्ष एक बहुत ही सरल, किन्तु मौलिक रूप से महत्वपूर्ण कमीटी है, और वह कसौटी है—अन्तर्राष्ट्रीय आचारों के निर्वहन में सद्भावना की। मैं कहता हूँ कि सद्भावना एक नितान्त महत्व का विषय है क्योंकि शब्द तो सरलता से कहे जा सकते हैं। किन्तु केवल आश्वासनों की दात बरने से ही क्या लाभ, जब कि वेध कर्तव्य और अधिकार का खंडन किया जाता रहे और संपत्ति जप्त की जाती रहे।"

साजतरपेत के अनुसार किसी को राज्य या नई सरकार की मान्यता के लिए इस कमीटी को व्यवहृत करना कि वह अन्तर्राष्ट्रीय आचारों की पूर्ति के लिए कहाँ तक इच्छुक है, एक सदिरा न्यायिक अधिवित्य से युक्त है और मान्यता के प्रयोजन से असंबध है।

मान्यता प्रायः अपरिपक्व स्थिति में ही दे दी जाती है, या देने से राक दी जाती है और कारण केवल राष्ट्रीय नीति (national policy) रहती है। तथ्यतः

और तदुपरान्त विधितः मान्यता, जो संयुक्त राज्य द्वारा पनामा को विद्रोह की अवधि के केवल तीन दिन के भीतर प्रदान की गई, राष्ट्रीय नीति के अपसरण हेतु अस्तित्व के पूर्व ही मान्यता प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है। इन्हीं भाषारों पर फ्रान्स ने १७७८ में केवल संयुक्त राज्य की मान्यता ही नहीं दी, अपितु इंग्लैंड के विरुद्ध के विद्रोहों में सहायता भी की। इजरायल के नये राज्यों की मान्यता (१९४८-४९) के संघर्ष में मतों में अनेक राजनीति कालोचितता के ही विचार का परिणाम था। इन्हीं विचारों की दृष्टि में रखते हुये, अर्थात् राजनीतिक मतभेदों को देखते हुये संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी राज्य चाऊ-एन-लाई की लाल-चीनी सरकार को मान्यता प्रदान करने से रुके। वे अब भी फारमूला में स्थिर राष्ट्रवादी सरकार को चीन की वैध सरकार मानते हैं; और अवास्तविकताओं के होते हुये भी कुमोमिन्तांग वर्ग—एक चीनी राष्ट्रीय प्रत्यायुक्त को—सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिली हुई है। फिर भी, ब्रिटेन ने चीन की जनवादी सरकार को अपने व्यापारिक हितों की दृष्टि से मान्यता प्रदान कर दी। यह मान्यता फिर भी राजनीतिक दृष्टिकोण को न बदल सकी और ग्रेट ब्रिटेन चीन की केन्द्रीय जनवादी सरकार की संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता में विरोध करता जा रहा है। विडवना यहाँ तक है कि अक्टूबर १९६२ में संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा के सत्रहवें अधिवेशन में ब्रिटेन ने रूस के इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया कि साम्यवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र में प्रविष्टि दे दी जाय, फिर भी प्रस्ताव अमान्य हो गया।

चीन की नई जनवादी सरकार को मान्यता प्रदान करते हुये स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत न जनवादी चीन को कोई कारणों से मान्यता दी है। समुचित, दृढ़ और विरस्थायी सरकार संपूर्ण महाद्वीपीय चीन पर अस्तित्व में है। उनका कथन कि देशों की मान्यता प्रदान करते समय किसी की किसी के प्रति रुचि या अनरुचि का प्रश्न विचारणीय नहीं है, अपितु केवल इतना ही विचारणीय है कि उन्होंने एक दृढ़ सरकार गठित कर लिया है और उनके निकाल दिये जाने की कोई संभावना नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा किये गये इस निवेदन पर कि 'पनामा ड्रैफ्ट डिक्लेरेशन' के अनुच्छेद २ पर जो कि राज्यों के कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण करता है, अवलोकन कर लिया जाय, इसके उत्तर में 'युनाइटेड किंगडम का अवलोकन था कि (१) जहाँ पर कोई इकाई राज्यत्व की शर्तों को पूरा करती है, अन्य सभी राज्यों का कर्तव्य है कि उसे मान्यता प्रदान करे; और (२) सभी राज्यों पर यह भी एक कर्तव्य आरोपित है कि वे किसी ऐसी इकाई को राज्य की मान्यता न दें, जो कि इन शर्तों को पूरा नहीं करती। वे इस बात से सहमत

ये कि राज्यों की मान्यता अथवा अमान्यता एक वैध कर्तव्य का प्रश्न है नीति का प्रश्न नहीं; और यह कि किसी राज्य का अस्तित्व में होना उसकी मान्यता पर निर्भर नहीं करता, अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि मान्यता का कर्तव्य उत्पन्न हो गया है। यह भी कहा गया था कि किसी इकाई की राज्य के रूप में मान्यता उस इकाई के साथ राजनयिक संबंध के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। यह तो बिशुद्ध रूप में राजनीतिक दृष्टिकोण का विषय है। दूसरी ओर किसी इकाई के साथ राजनयिक संबंधों में प्रविष्टि के अन्तर्गत अन्तर्निहित है कि वह इकाई किसी अस्तित्व के रूप में मान ली गई है। उस इकाई को विधितः या तथ्यतः राज्य की मान्यता मिली है, या युद्धसलग्न समुदाय, या यह कि उसे अधिभावी सरकार के रूप में मान्यता मिली है, आदि का प्रश्न उन विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करता है जिनके आधार पर उनकी प्रविष्टि हुई थी।

बैंक प्रावि चाइना बनाम वेल्स फारगो बैंक ऐंड यूनियन ट्रस्ट कंपनी<sup>१</sup> के बाद में अवलोकन था कि यहाँ तक कि न्यायालय भी हमारी कार्यपालिकीय वैदेशिक नीति से ही संबद्ध है, किसी मान्य सरकार के प्रत्येक कृत्य को अन्ध-प्रभाव-कारिता और अमान्य सरकार के प्रत्येक कृत्य को काल्पनिकता की संज्ञा देना भी समीचीन नहीं है।

राज्य के नये अध्यक्षों की मान्यता :—जब किसी राज्य का जो पहले ही से एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति है अध्यक्ष साधारणतया वैध प्रकार से बदलता है तो ऐसा परिवर्तन अन्य राज्यों को अधिसूचित कर दिया जाना है जो राज्य के नये अध्यक्ष को बधाई के सन्देश भेज कर स्वीकार करते हैं। कठिनाई उन समय उत्पन्न होती है जब कि राज्य में परिवर्तन क्रान्तिकारी उपायों से अर्थात् वर्तमान सरकार को उलट देने से होता है। ऐसी स्थितियों में इस प्रश्न के विचार के लिये दो कसौ-टियाँ हैं; अर्थात् क्या यह नयी सरकार वास्तव में एक ऐसी सरकार है जिसके नियन्त्रण में राज्य प्रभावशाली रूप में है और वह उस प्रदेश के एक पर्याप्त भाग पर बिना किसी प्रभावपूर्ण विरोध के प्राधिकार का प्रयोग कर रही है? इसे बाह्य आधार अथवा वस्तुनिष्ठ परीक्षण (objective test) कहा जाता है। दूसरा परी-क्षण यह है कि क्या नई सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा संयुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर द्वारा नियत किये गये कर्तव्यों को पालन करने के लिये तैयार है? इसको अधिकरण सम्बन्धी अथवा आत्मनिष्ठ परीक्षण (subjective test) कहते हैं? यदि नई सर-कार स्थिर न हुई अथवा वहाँ बारम्बार क्रान्तियाँ हो रही हों जिससे सरकार में

<sup>१</sup> यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट १६५२, १०४ एफ० सप्य० ५६.



परिवर्तन आवश्यक हो जाता हो तो मान्यता प्रदान करने वाले राज्य मान्यता प्रदान करने में विलम्ब करते हैं ।

किसी सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने की बात स्वीकार कर ली जाय या इन्कार कर दी जाय उस राज्य की स्वयं मान्यता के लिये महत्वपूर्ण नहीं है । यदि कोई वैदेशिक राज्य किसी पहले से ही चले आने वाले राज्य की नई प्रकार की सरकार के प्राख्य में होने वाले परिवर्तन को मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर देता है, तो केवल इसी कारण वह पुराना राज्य अपना अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं समाप्त कर देता ।<sup>१</sup>

किसी राज्य की सरकार कितनी ही हिंसक या उग्रवादी क्यों न हो गई हो किन्तु राज्य अस्तित्व में बना रहता है । कहा जा सकता है कि किसी राज्य के अमान्यता किसी राज्य की सरकार के अस्तित्व का खतक भी नहीं है । विलंब अमान्य सरकार के कुरूप इस मान्यता के न होने के कारण अवैध नहीं हो जाते ।<sup>२</sup>

गोल्ड (Gould) का कथन है कि "Changes in the form of government of a State no more extinguish the international personality of the State than did military occupation and existence of the statehood of Germany. Indeed, even a condition of anarchy does not remove a community from the roster of states. A parliamentary system may be replaced by a dictatorship of the proletariat, a monarchy by a military junta. But such changes do not involve the substitution of a new state for an old one." अर्थात् "किसी राज्य की सरकार के प्राख्य में होने वाले परिवर्तन, उस राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को उससे अधिक नहीं समाप्त कर सकते जितना कि मिलिट्री के कब्जा के उपरान्त भी जर्मनी के राज्यत्व का अस्तित्व बना रह गया था । वास्तव में, भराजकता की भी कोई स्थिति किसी समुदाय को राज्यत्व पद से वृद्ध कर सकती । लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिनायकत्व में घोर राजतन्त्र मिलिट्री शासन में बदल सकता है, किन्तु इन परिवर्तनों के कारण किसी पुराने राज्य के स्थान पर नया राज्य अस्तित्व में नहीं आया करता ।"

यह परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि नये परिवर्तन ने नये सरकार के रूप में ही परिवर्तन किया है, अथवा परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि

१ ले-हार्डि वैसी रल राड बम्पनी बनाम रूम राज्य (१६२७), २१ एफ० १६९

२ १८ ए० जे० आई० एल० (१६२४), पृ० १२७

राज्य मे से ही भू-क्षेत्र की कटौती, भादि करके, किसी नये राज्य या नई इकाई का प्रादुर्भाव हुआ है। १९४७ के पूर्व भारत अपने बखड रूप मे एक ही राज्य था और वे हिस्से जा अब पाकिस्तान के क्षेत्र मे हैं, भारत के ही क्षेत्र थे। किन्तु, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त देश के भू-क्षेत्र, जनता और नैतिक साधनों का विभाजन करते हुये 'पाकिस्तान' नामक एक नये राज्य का गठन किया गया। 'पाकिस्तान' उस समय से राज्य की एक इकाई है। वहाँ सरकार के प्रचारो मे बीच-बीच मे परिवर्तन होते रहे, फिर भी उस 'राज्यत्व' के पद मे इन परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

'सर्व क्रोट स्लोवीन किंगडम' के बाद मे 'जर्मन युगोस्लेव सम्मिलित भार्बो-ट्रल ट्रिब्युनल' ने निर्णय किया था कि यह सर्बिया-साम्राज्य की ही निरन्तरता का प्रश्न है, न कि वरसाइल्स की संधि के अनुच्छेद २९७ (एच) के अर्थो मे किसी नये राज्य के अस्तित्व का प्रश्न हो। इसी प्रकार से १९१७ की क्रान्ति के बाद रूसी राज्य वही राज्य माना गया जो कि वह १९१७ की क्रान्ति के पूर्व था। दूसरी ओर, ऑस्ट्रियन रिपब्लिक प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् शान्ति-सन्धियों के परिणाम-स्वरूप इतना विभ्रंशित हो गया था कि ऑस्ट्रियन रिपब्लिक न्यायालयो ने उसे सम्राट् वाले ऑस्ट्रिया से भिन्न एक नया राज्य माना। इसके ठीक विपरीत दूसरा उदाहरण उस समय का है, जबकि 'ओटोमन डेट् भार्बोट्रेशन' (Ottoman Debt Arbitration), १९२५ के एकमात्र विवाचक यूर्जेन बोरेल (Eugene Borel) का निष्कर्ष था कि टर्की का रिपब्लिक पूर्ववर्ती ओटोमन-साम्राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को धारण किये हुये हैं। इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों मे इस प्रसंग में कोई सामान्य परिभाषा देना कठिन है और जैसा कि गाउल्ड (Gould) का कथन है—*"...Ordinarily, neither territorial changes nor changes in the form of government affect the continuity of the State. Only in exceptional cases when simultaneous territorial change and change in form of government are so fundamental that the new entity, even in the national and cultural make-up of the population, hardly resembles the old, is the continuity to be regarded as broken"* "साधारणतया, न तो क्षेत्रीय परिवर्तन और न सरकार के प्रकार मे परिवर्तन ही राज्य की निरन्तरता को प्रभावित करते हैं। केवल अपवादपूर्ण स्थितियों मे, जबकि भू-क्षेत्र और सरकार के प्रकार मे साथ-साथ परिवर्तन होते हैं, और इतने आधारभूत रूप मे होते हैं कि नई इकाई, यहाँ तक कि जनता के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक क्षेत्र मे पुरानी स्थितिसे भिन्नता आ जाने की स्थिति में रहती है तभी यह निरन्तरता टूटी

हुई कही जा सकती है ।" उपर्युक्त 'पाकिस्तान' राज्य के सम्बन्ध में यही बात कही जा सकती है ।

**निर्वासित सरकार की मान्यता (Recognition of Government in Exile) :—** किसी राज्य की सरकार निर्वासित तब कही जाती है जब उस राज्य का प्रदेश शत्रु की सेना के अधिकार में हो । शत्रु द्वारा किसी प्रदेश पर अधिकार यह नहीं व्यक्त करना कि निर्वासित सरकार का उस प्रदेश पर प्रभावशाली नियन्त्रण नहीं है । ऐसी सरकार उस समय तक अधिष्ठान प्रदेश की सरकार मानी जाती है जब तक वह खोये हुये प्रदेश पर पुनः नियन्त्रण पाने में प्रयत्नशील रहती है । यदि युद्ध की समाप्ति तथा सन्धि-स्थापना होने पर निर्वासित सरकार छोड़े हुए प्रदेश पर फिर से नियन्त्रण पाने में असमर्थ रहती है तो यह अपना उस राज्य की सरकार मानी जाने का अधिकार खो देती है ।

**राज्यों की मान्यता (Recognition of States) :—** पहले के स्वतंत्र राज्य द्वारा यदि कोई नया राज्य-संघ बनाया जाता है, तो उस नये राज्य को अन्य राज्यों की मान्यता की आवश्यकता होती है । इसी प्रकार राष्ट्रों के कुटुम्ब में सम्मिलित होने में भी यह मान्यता आवश्यक होती है । यह आवश्यक नहीं है कि यदि किसी राज्य को एक राज्य मान्यता दे दे, तो अन्य राज्य भी अपनी मान्यता दे दें । इतना अवश्य है कि यदि किसी राज्य को किसी बड़े और प्रभावशाली राज्य द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है, तो उससे प्रभावित होकर अन्य राज्य भी मान्यता प्रदान करने लगते हैं ।

**स्टिमसन का अमान्यता सिद्धान्त (Stimson's Doctrine of Non recognition)—** जून १९३२ में चीन के मन्चूरिया प्रान्त पर जापान वालों का आक्रमण हो गया । उस समय संयुक्त राज्य के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Mr. Henry L. Stimson थे । उन्होंने यह कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथ्यतः (de facto) स्थिति की वैधता को नहीं स्वीकार करता और न तो यह किसी ऐसी संधि या समझौते को ही मान्यता देता है जो कि इन सरकारों या उनके अभिकर्ताओं के बीच हुआ है जो कि संयुक्त राज्य के संधि अधिकारों के बीच आवे और यह कि वे ऐसी संधि किसी स्थिति, संधि या समझौते को मान्यता नहीं देते जो कि क्वेन्ट तथा वेरिन के पैक्ट (१९२८) के सिद्धान्तों के विपरीत हो जिनमें कि चीन, जापान और संयुक्त राज्य पक्षकार थे । उनका कहना था कि कोई भी परिस्थिति यदि वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करती है तो मान्यता प्रदान करने में कारण वैध नहीं कहा जा सकता । उन्होंने आगे कहा था कि "ऐसे कार्यों पर एक अवरोध लगा दिया जायेगा जो कि

हम विश्वास करते हैं कि किसी स्वत्व या अधिकार की वैधता को दबाव से भंग करने में अथवा सधि के उपबन्धों के अतिक्रमण पर प्रभावकारी रूप से बाधा उत्पन्न करेगा ।" इस सिद्धान्त को मार्च ११, १९३२, को लीग आफ नेशन्स ने अपने प्रस्ताव द्वारा घोषित किया और प्रवर्तित किया ।

यह सिद्धान्त राष्ट्रीय नीति का एक कथन-मात्र है और यद्यपि इसके सिद्धान्त लीग आफ नेशन्स द्वारा मार्च १९३२ के प्रस्ताव पारित होने के पश्चात् निम्नलिखित शब्दों में मान लिये गये थे

"It is incumbent upon the members of the League of Nations not to recognize any situation, treaty or agreement which may be brought about by means contrary to the Covenants of the League of Nations or to the Pact of Paris"

द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् महान् शक्तियों ने समुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा इन मान्यताओं को जो कि चार्टर के उपबन्धों के विरुद्ध हैं, अस्वीकार कर दिया है ।

स्ट्राडा का सिद्धान्त (The Estrada Doctrine).—यह सिद्धान्त मान्यता के भ्रम्यास को किसी न किसी रूप में समाप्त कर देने का समर्थन करता है । सितम्बर २७, १९३०, को मैक्सिको के विदेश सम्बन्धी सचिव Senor Estrada ने एक घोषणा की जा कि उन्हीं के नाम से पुकारी जाती है । यह घोषणा निम्न-लिखित थी :— "मैक्सिको की सरकार ने अपने भविष्य को आदेश दे दिया है कि वर्तमान राजनीतिक उथल-पुथल से प्रभावित देशों में इस आशय का आदेश भेज दिया गया है कि मैक्सिको की सरकार मान्यता के रूप में कोई घोषणा नहीं कर रही है, क्योंकि राष्ट्र की यह व्याख्या है कि यह एक अपमानजनक भ्रम्यास है । इसके साथ ही साथ यह दूसरे राष्ट्रों की सम्प्रभुता पर घातक होता है । इसका अभिप्राय यह होता है कि उन राष्ट्रों के आन्तरिक मामलों में कुछ निर्णय दूसरी सरकारें करें क्योंकि दूसरी सरकारें सम्भव है—मान्यता के पक्ष का समर्थन करें भ्रम्यास न करें और यदि समर्थन करने के स्थान पर आलोचना करती हैं तो यह प्रत्यक्षत एक हस्तक्षेप का रूप है जो कि बाहरी देशों की ओर से आता है इसलिये मैक्सिको की सरकार अपने आपको जहाँ तक उचित होगा राजनयिक अभिवृत्तियों की स्थापना और प्रत्याहरण तक सीमित रखेगी और जब तक यह उचित समझेगी इस तरह के राजनयिक अभिवृत्तिमय सबष उन देशों में जारी रखेगी जो मैक्सिको से ऐसा सम्बन्ध बनाये रखते हैं । ऐसा करने में वह कोई निर्णय नहीं करेगी जो कि विदेशी राष्ट्रों के अधिकार में है कि वह अपनी सरकार या प्राधिकारियों को स्वीकार करेगी बनाये रखेगी या बदल देगी ।

Briggs (ब्रिग्स) का कथन है कि यद्यपि 'स्ट्राडा सिद्धान्त' से सरकारों की मान्यता का अभ्यास समाप्त होने का संकेत है अपेक्षा इसके कि वह मान्यता के प्रवर्तित वेध अधिकारों के लिये एक प्रस्ताव सा करता है, किन्तु इससे राजनयिक तथ्यों की समाप्ति नहीं हो जाती। पहली बात तो यह है कि यह निश्चित करना आवश्यक है कि कौन से पदाधिकारी विदेशी राजनयिक आचारों को पूरा करने या अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अर्न्तगत दावा प्रस्तुत करने में समर्थ हैं। दूसरी बात यह है कि कौन सी सरकार उन आचारों को स्वीकार करेगी और क्या ?

एस्ट्राडा के सिद्धान्त पर टिप्पणी करते हुये फेनविक् (Fenwick) का कथन है कि यदि इसे इस रूप में माना जाय कि मान्यता अभिप्राय तथ्यत राज की नई सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आचारों की पूर्ति करने की योग्यता और इच्छा से है, और इसलिए उसे मान्यता दी जाये, या यह कि इस मान्यता से राजनयिक सम्बन्ध अविच्छिन्न ढंग से बना रहेगा, और इसके माध्यम से यह प्रकटना कर कि तथ्यत सरकार राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय आचारों को आवश्यकता के रूप में पूरा करती रहेगी, संयुक्त राज्य की नीति के उस कथन से भिन्न नहीं है जहाँ कि पूरा महत्व तथ्यत प्रकार की सरकार को प्रदान किया गया था। दूसरी ओर, व्यवहार के रूप में, अमेरिकी राज्यों में उत्पन्न होने वाली शक्तियों के बीच नई सरकारों के अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आचारों को पूरा करने में अपने आशय में किसी कठिनाई की कभी भी उद्घोषणा नहीं की है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक विषय सधियों की पूर्ति में सद्भावना के विषय रहे हैं।<sup>१</sup>

यहाँ Svarlien के शब्दों में—"The Estrada Doctrine of Recognition clearly assumes that diplomats are accredited to states (than to Governments. It also recognises the clear proposition of International Law that states have a continuous existence, whereas Governments do not." अर्थात् मान्यता का स्ट्राडा सिद्धान्त स्पष्टतः यह मानता है कि राजनयिकों का सम्बन्ध राज्यों से होता है, सरकारों से नहीं। यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इस सूत्र को भी स्पष्ट रूप से मानता है कि राज्यों का एक निरन्तर अस्तित्व होता है जब कि सरकारों का नहीं।

मान्यता की पूर्ण व्याप्ति (Retroactivity of Recognition)—यह कि कोई ऐसी सरकार किसी राज्य द्वारा उस देश की विधितः सरकार (de jure Government) के रूप में मान्यता प्राप्त करती है, जो कि क्रान्ति या विद्रोह

परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है, तो ऐसी मान्यता प्रभाव में पूर्व व्याप्ति के प्रभाव से युक्त होनी है और उस राज्य के अस्तित्व में आने की तिथि से, ऐसी मान्यता उसके समस्त कृत्यों और व्यवहारों का वैधकरण कर देती है ।<sup>१</sup>

‘सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकारपोरेटेड’ बनाम सेण्ट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन<sup>२</sup> के बाद में यह अवलोकन था कि प्रथम-दृष्ट्या मान्यता (prima facie recognition) पूर्वव्यापी रूप में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यों के वैधकरण के लिए व्यवहृत नहीं होती, अपितु ऐसी तथ्यतः सरकार के कार्यों के वैधकरण के लिए होनी है जो कि अब नई विधित सरकार बन गई है ।

मान्यता की पूर्व व्याप्ति के विषय पर संयुक्त राज्य के सुप्रीम कोर्ट में ‘गारटी-ट्रस्ट कंपनी न्यूयार्क बनाम युनाइटेड स्टेट्स’<sup>३</sup> के बाद में विचार-विमर्श किया गया था और यह अवलोकन था कि “सरकार का तर्क यह है कि सावियत सरकार के कार्य की मान्यता जिसने कि अनेक प्रयोजनों के लिए यहाँ वैधकरण कर दिया है कि सरकार के पूर्वव्यापी कार्य जो कि अपने ही क्षेत्र के अन्तर्गत किये गये हैं, संयुक्त राज्य द्वारा अन्तःकालीन सरकार और उससे प्रतिनिधित्व की पूर्व मान्यता के सभी वैध परिणामों को सन्तुष्ट कर देते हैं, क्योंकि इस प्रकार की मान्यता कभी भी प्रदान नहीं की गई थी ।” किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मान्यता पूर्व-मान्य सरकार के व्यवहारों को उस सीमा तक प्रभावित नहीं करती जहाँ तक कि हमारी सरकार की उद्घोषित नीति की अनुकूलता है । हमारी सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने का मात्र प्रयोजन यह है कि हमारे राष्ट्रीय नागरिकों का परिणाममूलक ऐसा परामर्श दिया जा सके कि किन-किन सरकारों के साथ वे सुरक्षापूर्वक व्यापार-सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं और उन सरकारों के समुचित प्रतिनिधि कौन हैं । यदि वे सह-सम्बन्ध, प्रविष्टि के समय वैध थे, किन्तु उत्तरवर्ती सरकार की मान्यता के उद्घाटन प्रवेष्ट हो जाये—तो मान्यता केवल एक ऐसी निष्क्रिय औपचारिकता के रूप में रह जायेगी जो पूर्वस्थापित राजनीतिक सम्बन्धों के प्रति लाभप्रद परिणाम नहीं दे पायेगी और न तो व्यापार सम्बन्ध ही भागे बढ़ सकेंगे और उन व्यापार-सम्बन्धों को चालू रखने में हमारे राष्ट्रीय नागरिकों को कोई सुरक्षण नहीं मिल सकेगा ।” तदनुसार यह निष्कर्ष था कि सोवियत-सरकार की नवीन मान्यता पहचान की अन्तःकालीन सरकार की मान्यता के वैध परिणामों पर या उनका प्रतिनिधित्व

१. *Oetjen v. Central Leather Co* (1918) 246 U. S. 297, 302.

२. (1942) 2 All E. R. 733

३. (1938), 304 यू० एस० १२६, १४०.

की मान्यता के बीच परिणामों पर किसी प्रकार से अन्यथा रूप में प्रभावकारी न होगी ।

मान्यता के प्रकार (Methods of Recognition) :—तत्त्वपूर्ण अथवा न्यायिक मान्यता निम्नलिखित रीतियों से दी जाती है :—

१—सन्धि में प्रवेश द्वारा ।

२—संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता द्वारा ।

३—राजनैतिक प्रतिनिधियों का 'आदान-प्रदान', भेजने तथा ग्रहण करने द्वारा ।

४—एकपक्षीय अथवा सामूहिक घोषणा द्वारा ।

५—अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश द्वारा ।

६—अपने वाणिज्य दूत ( Consul ) की नियुक्ति द्वारा ।

मान्यता के परिणाम :—नई सरकार की मान्यता से जो परिणाम होते हैं उनको ओपनहेम ने निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप रूप में लिखा है :—

(१) इसके द्वारा यह अन्य राज्यों से राजनैतिक सम्बन्ध तथा सन्धि-स्थान की क्षमता प्राप्त कर लेता है ।

(२) सीमाओं के भीतर दो राज्य ( यह मानते हुए कि यह पुराना राज्य है, न कि एक नया राज्य ) के बीच पूर्व-स्थापित संधियाँ स्वतः पुनर्जीवित तथा प्रवृत्त हो जाती हैं ।

(३) इसको इसके द्वारा वह अधिकार प्राप्त हो जाता है जो इसे किसी प्रकार से अंग्रेजी विधि द्वारा पहले प्राप्त न था । वह मान्यता प्रदत्त करने वाले राज्य के न्यायालयों में दावा कर सकता है ।

(४) इसके द्वारा यह अपने लिए तथा अपनी सम्पत्ति के लिए उसकी मान्यता प्रदत्त करने वाले राज्य के न्यायाधिकारियों के अधिकार-क्षेत्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है ।

(५) इसको मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सम्पत्ति पर जो कि पहले पूर्ववर्ती सरकार की उसके अलग होने के समय की वज्रा भाँगे तथा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है ।

(६) मान्यता बीती हुई घटना पर प्रभावकारी होने के कारण तथा उस क्षण से भारम्भ होने के कारण जिस तिथि को नई मान्यता प्रदत्त सरकार ने अपना अधिकार स्थापित किया, इसका प्रभाव यह होता है कि यह मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के न्यायालयों को उस सरकार के पिछले तथा आगामी, बीच तथा

प्रशासकीय कार्यों की वैधता अथवा मान्यता पर प्रश्न उठाने से रोक देती है। अतः यह जहाँ तक उन न्यायालयों का सम्बन्ध है कुछ सम्पत्ति के हस्तान्तरणों तथा अन्य व्यापारों को वैध बना देती है जिनको वे मान्यता प्रदत्त होने के पूर्व कर सकते थे।

**अमान्य राज्यों की अर्हतायें ( Disabilities of Unrecognised States )** :—अमान्य राज्य अथवा सरकार की वैध अर्हतायें निम्नलिखित हैं :

(१) जिस राज्य ने इनको मान्यता प्रदान न की हो उसके न्यायालयों में यह दावा नहीं कर सकता। *Russian Socialist Federated Soviet Republic v. Cibrario* ( 235 New York Court of Appeals, 255 ) में यह निरूपित है कि विदेशी शक्ति को अमेरिकन न्यायालयों में दावा करने का प्राकृतिक अधिकार नहीं है। ऐसा करने का इसका अधिकार शिष्टाचार से जनित है और जब तक ऐसी सरकार को संयुक्त राष्ट्र सच द्वारा मान्यता प्रदान न की जाय कोई शिष्टाचार विद्यमान नहीं रहता।

(२) इसके प्रतिनिधि विदेशी राज्यों में वैध प्रवृत्ति से मुक्ति का दावा नहीं कर सकते।

(३) इसको अन्य राज्यों से राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने तथा उनसे सन्धि करने की क्षमता नहीं प्राप्त होती।

(४) मान्यता अग्रदत्त राज्य को देय सम्पत्ति उलटे हुए राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा वास्तव में प्रत्युद्धृत की जा सकती है।

**मान्यता और लीग ( Recognition and the League )**—यह स्वीकार किया गया था कि लीग ऑफ नेशन्स की सदस्यता के लिए किसी राज्य की प्रविष्टि से ही मान्यता अन्तर्निहित हो जाती है। वर्ष १९३५ में लक्षेमबर्ग के कामिश्नियल ट्रिब्युनल का सोवियत सच बनाम लक्षेमबर्ग और सार कम्पनी के वाद में अवलोकन था कि 'लीग आफ नेशन्स' में सोवियत रूस के प्रवेश पाने में ही लक्षेमबर्ग द्वारा सोवियत सरकार की मान्यता अन्तर्निहित है। किन्तु, इस नियम का अनुपालन समरून में सभी प्रसंगों में नहीं किया गया और स्विटजरलैंड तथा बेल्जियम ने यहाँ तक कि रूस की सरकार को 'लीग आफ नेशन्स' में प्रवेश पा जाने के उपरान्त भी मान्यता प्रदान करने से इन्कार कर दिया। फिर भी बहुमत इस पक्ष का रहा कि एक बार यदि कोई राष्ट्र किसी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वव्यापी सस्था का सदस्य मान लिया जाता है, तो उसमें राज्यत्व के पद का सामान्यतः आरोप किया जा सकता है।



**मान्यता तथा संयुक्त राष्ट्र संघ :—**संयुक्त राष्ट्र सघ के चार्टर के अनुच्छेद ४ के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सघ की सदस्यता उन शान्तिप्रिय राज्यों के लिए खुली हुई है जो चार्टर के कर्तव्यों को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार का प्रवेश सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव पर सामान्य सभा के निर्णय द्वारा होता है। प्रश्न यह उठता है कि क्या कोई मान्यता अग्रदत्त राज्य भी सदस्यता में प्रविष्ट किया जा सकता है। इसका सक्षित उत्तर यह है कि राज्य को संयुक्त राष्ट्र सघ की सदस्यता में प्रविष्ट करने से ही वास्तविक अथवा न्यायानुसार मान्यता प्रदत्त हो जाती है। ज्यों ही कोई राज्य संयुक्त राष्ट्र सघ का सदस्यता ग्रहण करता है, चाहे अन्य राज्यों द्वारा उसे मान्यता प्रदत्त की गई हो अथवा नहीं, त्यों ही वह वास्तविक अथवा द्वारा स्थापित सब कर्तव्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य सिद्धान्तों के अधीन हो जाता है। सुरक्षा परिषद् की सिफारिश पर सामान्य सभा द्वारा राज्य के संयुक्त राष्ट्र सघ की सदस्यता में प्रवेश किये जाने का परिणाम यह होता है कि उसको संयुक्त राष्ट्र सघ के सब सदस्य राज्यों द्वारा सामूहिक रूप से मान्यता मिल जाती है। इसमें सम्बन्धित राज्यों की सामूहिक इच्छा का समावेश है।

इस प्रकार की मान्यता के प्रत्याहरण के सम्बन्ध में चार्टर के अनुच्छेद ६ में यह व्यवस्था की गई है कि संयुक्तराष्ट्र संघ का जो सदस्य चार्टर के सिद्धान्तों का उल्लंघन करने का हठ करे, उसे संघ की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया जाय।

**युद्ध-संलग्नता ( Belligerency ) की दशा में मान्यता :—**जब किसी देश में राज-विद्रोह अथवा विप्लव होता है तो बाह्य शक्तियाँ उस देश के घरेलू मामलों में सामान्यतः तटस्थता का व्यवहार रखती हैं। फिर भी प्रायः ऐसा भी सम्भव है कि दूसरे राज्यों के लिए तटस्थता का व्यवहार रखना असम्भव हो जाय। इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो इस कारण से कि विप्लवकारी शक्ति मूल सरकार के प्रदेश के एक बड़े भाग पर प्रभावोत्पादक रीति से अधिकार प्राप्त कर चुके हों या उनके तथा मूल सरकार के मध्य युद्ध एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया हो जब कि बाहरी शक्तियाँ इसे केवल परस्पर का बल ही न मानें परन्तु उसमें उनके विनाश के लक्षण दिखाई पड़ते हों। बलह-स्मित राज्य तथा बाहरी शक्तियाँ या तो देश की स्थिति व कारण अथवा वाणिज्य या व्यापारिक सम्बन्धों के कारण परस्पर दाने सम्बद्ध हो सकते हैं कि एक देश का युद्धप्रद प्रता परिणाम दूसरे देश में अत्यन्त हासता हो। ऐसी दशा में राजनैतिक मनुष्य जो एक स्वतन्त्र राज्यत्व प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनका बह्युत्तः (De facto) मान्यता प्रदान कर दी जाती है किन्तु यह मान्यता युद्ध की स्थिति के लिए ही होती

है और बाद में आवश्यक होता है कि या तो उनको नियमानुसार सदस्यता में प्रविष्ट कराया जाय या फिर नियमानुसार अधीनस्थता में वापिस लाया जाय ।

युद्ध सलग्नता की मान्यता से केवल इस बात का निश्चय होता है कि राज-द्रोही अपने द्वारा अधिकृत प्रदेश पर आधिपत्य प्रयोग करने की स्थिति में हैं । इसमें मूल-राज्य को क्रुद्ध होने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता और न इस मान्यता से तटस्थता का ही उल्लंघन होता है ।

ब्रिटिश प्रवचन यह है कि विद्रोहियों द्वारा केवल इस बात की उद्घोषणा कर दिया जाना, कि उन्होंने एक अन्तर्वासीन सरकार (Provisional Government) का गठन कर लिया है युद्धसलग्न मान्यता के लिए पर्याप्त नहीं है । यह तभी संभव है जब कि नवगठित इकाई इतनी शक्ति और सरकार संयोजित कर ले कि वह विदेशी राज्यों से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाये रख सके । मान्यता प्रदान करने वाला राज्य ऐसे तटस्थ अधिकारी के लिये अधिकृत हो जाता है जो कि प्रतिद्वन्दी पक्षकारों से मान्य होते हैं । इस प्रकार की मान्यता से युद्ध-सलग्न पक्ष भूमि, जल और नभ-क्षेत्र में आक्रामक या घुसपैठ की सजा से मुक्त हो जाते हैं ।

युद्ध-सलग्नता की मान्यता युद्ध में लगे हुये लोगों को युद्ध के प्रयोजनों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति प्रदान करती है । यद्यपि राजदूतों का आदान-प्रदान अथवा सन्धि स्थापन नहीं होता तथापि वाणिज्य आपार सम्बन्धी हितों के संरक्षणार्थ वाणिज्य-दूतों का विनिमय होता है । मान्यता प्रदान करने वाला राज्य अपने क्षेत्राधिकार के भीतर विद्रोही सरकार के झंडे को भी मान्यता प्रदान करता है ।

परन्तु युद्ध-सलग्नता की मान्यता उस देश की वैध स्थापित सरकार की मान्यता से भिन्न है । युद्ध-सलग्नता की मान्यता से केवल उस मान्यता को देने वाले और उस मान्यता को प्राप्त करने वाले का परस्पर हित होता है । देश की वैध सरकार द्वारा दी गई मान्यता एक पूर्ण-कार्य है और इससे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की वैध सदस्यता प्राप्त हो जाती है ।

युद्ध सलग्नता की मान्यता का प्रश्न सरकार के उस प्रशासकीय विभाग से सम्बन्धित है जिसकी घोषणा न्यायालय पर बन्धनकारी है । ऐसी मान्यता एक नीति का प्रश्न हुआ करती है न कि विधि का । यह कई बातों पर आश्रित है जैसे क्या युद्ध में प्रवृत्ति रखने वाले समुदाय में एक संगठित सरकार है जिसमें युद्ध को स्वीकृत नियमों तथा रीति के अनुसार चालू रखने की क्षमता है ? क्या उस समय वास्तव में युद्ध वर्तमान है ? और क्या मान्यता प्रदत्त करने वाले राज्य के हित युद्ध छिड़ने से प्रभावित हो रहे हैं ?

विप्लवकरियों को युद्ध-संलग्नता की मान्यता केवल युद्ध के प्रयोजनों के लिए प्रदान की जाती है और यह उनको कोई अन्य अधिकार प्रदान नहीं करती ।

युद्ध-संलग्नता वाले राज्य जब अपनी स्थिति संधटित कर लेते हैं तो उनको स्वतन्त्र-राज्य के रूप में मान्यता दे दी जाती है । चांग कार्ड शेक की राष्ट्रीय सरकार के फारमोसा को बहिष्कृत किये जाने के उपरान्त भारत, रूस, ग्रेट ब्रिटेन तथा कुछ अन्य राज्यों द्वारा माओ से तुंग की लाल चीन को सरकार को मान्यता प्रदान किया जाना उपरोक्त का उदाहरण है ।

युद्ध संलग्नता की मान्यता के सम्बन्ध में एक दृष्टान्त दिया जा सकता है । अमेरिका के कमिश्नर नेल्सेन ( Commissioner Nielsen ) ने Oriental Navigation Co. के विवाद में General Claims Commission के सामने अपने विचार व्यक्त किये थे । यह विवाद मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच था । उनका कहना था कि तथ्याकथित रूप में युद्ध संलग्नता की दशा में सरकार की ओर से किसी राज्य की मान्यता यदि एक नये राज्य के रूप में है तो इसके अन्तर्गत बहुत से राजनीतिक विचार उठ खड़े होते हैं । ऐसी स्थिति में युद्ध-स्थित राज्यों के लिए वही मान्यता न्यायिक हो सकती है जिसे हम लोक युद्ध (Public War) कह सकते हैं । जब तक कि गृह-युद्ध को लोक-युद्ध न कह लें तब तक युद्ध-संलग्न पक्षकारों में राजनीतिक समुदाय को वास्तविक (de facto) शक्ति का होना आवश्यक है और राज्य क्षेत्र जनता हित आदि के प्रसंग में उसे एक स्वतन्त्र इकाई होना चाहिये । इतना ही नहीं बल्कि यह भी आवश्यक है कि तटस्थ राज्यों और उनके नागरिकों के हित भी ऐसी मान्यता के पूर्व प्रभावित होने चाहिये ।

युद्ध-संलग्नता की मान्यता में एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय इकाई उत्पन्न करने की क्षमता है जिसमें स्वतन्त्र-राज्यों के सभी अधिकार और कर्तव्य सन्निहित होते हैं । किन्तु इसका सम्बन्ध युद्ध तक ही होता है । मान्यता-प्रदान करने वाला राज्य तटस्थता की स्थिति में होते हुये भी युद्ध में लगे हुए पक्षकारों को युद्ध-संलग्नता की मान्यता प्रदान करता है । इससे उस नये राज्य को मान्यता देने वाले राज्य की सीमा में समुद्री जहाजों को ले जाने, समुद्र में दूसरे जहाजों का निरोक्षण करने और तलाशी लेने और अवैध सामानों के ले जाने से रोकने आदि के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं । ऐसी मान्यता युद्ध में लगे हुये समुदाय को और पैनुक राज्य को युद्ध के सम्बन्ध में समान अन्तर्राष्ट्रीय अस्तित्व प्रदान करते हैं ।

हम कह सकते हैं कि युद्ध-संलग्नता के अधिकार द्वारा मान्यता देने वाले और मान्यता प्राप्त करने वाले दोनों को सुविधायें मिलती हैं ।

राज्य प्रतिरोध ( Insurgency )—ऐसा भी सम्भव है कि एक गृह-युद्ध बाहरी शक्तियों द्वारा युद्ध-संलग्नता की दशा तक न पहुँचे। सम्भव है कि क्रान्तिकारी दल किसी संगठित प्राधिकार के अन्तर्गत कार्य न कर रहा हो या युद्ध के लिए मान्य नियमों का पालन न कर रहा हो। ऐसी स्थिति में अन्य राज्यों द्वारा उन क्रान्तिकारियों को एक विचित्र अथवा अनियत प्रकार की मान्यता (precarious form of recognition) प्रदान की जा सकती है, जैसे राज्य प्रतिरोधक की स्थिति, उन्हें कानून तोड़ने वालों के रूप में न मान कर अधिकृत क्षेत्र के वास्तविक प्राधिकारियों के रूप में मानना।

राज्य प्रतिरोध की मान्यता के लिए निम्नलिखित शर्तें हो सकती हैं :—

( १ ) यह आवश्यक है कि राज्य प्रतिरोधक एक निश्चित भू-भाग पर अधिकार कर चुके हो।

( २ ) उस राज्य की बहुमत की जनता उस राज्य प्रतिरोधक शक्ति के पक्ष में हो। यहाँ यह आवश्यक है कि जनता का यह सहयोग उनकी स्वतन्त्र इच्छा पर निर्भर हो न कि किसी दबाव पर।

( ३ ) राज्य प्रतिरोधक शक्ति में इस बात की क्षमता और इच्छा हो कि वे अन्तर्राष्ट्रीय आचारों को वहन कर सकें।

युद्ध प्रतिरोधक स्थिति की मान्यता एक नये राज्य की मान्यता नहीं कही जा सकती और न उसे सभी प्रकार के वैध अधिकार ही दिये जा सकते हैं। इसे युद्ध-संलग्नता की स्थिति भी नहीं कह सकते।

गार्नर (Garner) के अनुसार राज्य प्रतिरोध की स्थिति सम्बन्धित मान्यता के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं :—

युद्ध में संलग्न दोनों पक्षों को युद्ध संलग्नता की मान्यता दे दी जाती है और इस मान्यता से उन्हें कुछ ऐसे अतिरिक्त अधिकार मिल जाते हैं जो इसके पूर्व नहीं मिले होते किन्तु मान्यता प्रदान करने वाला राज्य, प्रतिरोध करने वाले दोनों पक्षों की ओर से कोई नया अधिकार नहीं प्राप्त करता। उसकी स्थिति दोनों पक्षों की मोर्चे से तटस्थ की स्थिति हो जाती है। यही नहीं बल्कि उसे अपने एक अधिकार को खोना भी पड़ता है। मान्यता प्रदान करने के पूर्व वह उस सरकार का जिसे कि वैध मानता, दूसरे पक्ष के विरोध में पहले सहायता कर सकता था किन्तु मान्यता प्रदान करने के बाद उसे इन दोनों पक्षों को समान रूप से देखना होगा। अब वह यदि किसी पक्ष को सहायता करता है तो वह तटस्थता की नीति का उल्लंघन करता है।

स्वाजर्जेनबर्जर (Schwarzenberger) के अनुसार राज्य-प्रतिरोध (Insurgency) की मान्यता और युद्ध-सलग्नता (Belligerency) की मान्यता में अंतर है कि युद्ध-सलग्न पक्षकारों को ही जल या नभ-क्षेत्र में युद्धसलग्न के कृत्यों को मान्यता मिल सकती है, इसके अन्यथा नहीं।

सह-युद्ध-संलग्नता (Co-belligerency):—प्रथम विश्व-युद्ध में सहाय शक्तियों ने जेकोस्लोवाक् और पोलिश नेशनल आर्मीज को स्वायत्तपूर्ण की सहाय और सह-युद्ध सलग्न (Allied and Co-belligerent) की मान्यता दी। समस्त राष्ट्रों ने द्वितीय विश्वयुद्ध में ऐसे इटालियन सैन्य को सह-युद्ध-सलग्नता के अधिकार स्वीकृत किये थे जो कि शत्रु के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रों के साथ युद्धरत थे। इस रूढ़ि में उन्हें किसी भी मान्य राज्य के समस्त सैन्य-शक्ति सम्बन्धित अधिकार प्राप्त थे।

## अध्याय ६

### राज्य उत्तराधिकार

#### (State Succession)

जब एक राज्य का प्रदेश उसके प्रभुत्व से दूसरे के प्रभुत्व में चला जाता है तो इसे राज्य का उत्तराधिकार कहा जाता है। वह राज्य जिसका प्रदेश अन्य राज्य को चला जाता है पूर्वोधिकार राज्य (Predecessor State) कहलाता है और जिस यह उत्तराधिकार में प्राप्त होता है उत्तराधिकारी राज्य (Successor State) कहलाता है। Oppenheim के शब्दों में हम इस प्रकार से कह सकते हैं—*A succession of International Persons occurs when one or more International Persons take the place of another International Person in consequence of certain changes in the latter's condition* (International Law—8th Ed. p 157) अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों की उत्तराधिकार उस समय होता है जब कि एक या एक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति का रूप ले लेते हैं और बाद के व्यक्ति में कुछ निश्चित परिवर्तन हो जाते हैं।

एक राज्य को दूसरे राज्य का उत्तराधिकार उसके कुछ निश्चित कृत्यों पर आधिपत्य प्राप्त कर लेने से मिल सकता है। एक राज्य एक से अन्य दो-दो या दो से अधिक राज्यों में बंट सकता है। या जुट होने वाले राज्य के स्व

पर दूसरे नये राज्य उत्पन्न हो सकते हैं, जैसा कि प्रथम विश्वयुद्ध में आस्ट्रो-हंगेरियन एकतन्त्र में देखा गया था। इसी प्रकार का विभाजन द्वितीय विश्वयुद्ध में जर्मन रीश के भू-भाग में भी देखा गया था। एक राज्य दूसरे राज्य में अपनी इच्छा से सन्धि के आधार पर प्रविष्ट हो सकता है, या किसी एक राज्य द्वारा उसका भू-भाग बल-पूर्वक छीना जा सकता है; या कई राज्य मिलकर किसी एक राज्य के भू-भाग का अपहरण कर सकते हैं। वागो का स्वतन्त्र राज्य १६०८ में अपनी स्वतन्त्रता खोकर बेल्जियम में मिल गया था, १६१० में कोरिया जापान का भग्न बन गया था और इसी प्रकार १६०१ में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा आरजेज के स्वतन्त्र राज्य और दक्षिणी अफ्रीका के गणराज्य पर विजय प्राप्त किया गया था। एक राज्य का भू-भाग किसी उत्पन्न होने वाले नये राज्य के सन्धि के द्वारा हासिल हो सकता है, या ऐसा भी सम्भव है कि किसी राज्य का कोई भू-भाग अलग होकर एक नये राज्य का हिस्सा हो, जैसे स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत का भू-भाग पृथक् होकर पाकिस्तान के नये राज्य के रूप में बदल गया।

उत्तराधिकार प्रारम्भिक रूप में वैयक्तिक विधि ( Private Law ) का सिद्धांत है और इससे अन्तर्गत राज्य में राजनीतिक परिवर्तन भी होते हैं। उत्तराधिकार दो प्रकार के होते हैं :-

सार्वभौमिक उत्तराधिकार ( Universal Succession )—सार्वभौमिक उत्तराधिकार उस दशा में होता है :-

(१) जब एक राज्य अन्य राज्य द्वारा समामेलन अथवा विजय के परिणाम-स्वरूप अपने में पूर्णरूप से समाविष्ट कर लिया जाता है, जैसे दक्षिणी अफ्रीका प्रजासत्तन का समामेलन ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सन् १६०१ में, कोरिया का जापान द्वारा सन् १६१० में तथा एवीसीनिया का इटली द्वारा सन् १६३६ में।

(२) जब बहुत से राज्य एक संघीय राज्य अथवा संघ में मिलने को सहमत हो जाते हैं जिस प्रकार सन् १८७१ में जर्मनी के राजा जर्मन साम्राज्य बनाने के लिए परस्पर संयुक्त हो गये, इसी प्रकार २२ फरवरी, १६५८ में संयुक्त अरब गणतन्त्र बनाने के लिए इजिप्ट और सीरिया तथा बाद में २ मार्च, १६५८ में ईमेन विलयित हो गये, या जैसे १४ फरवरी १६५८ में अरब संघ राज्य में जार्डन और ईराक का विलयन हुआ था।

(३) जब एक या अधिक राज्य बनाये जाते हैं अथवा एक या अधिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति अन्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति का स्थान पहले एक राज्य अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के विभाजन द्वारा ग्रहण करते हैं और प्रत्येक स्वतन्त्र राज्य उत्तराधिकारी राज्य होता है।

**आंशिक उत्तराधिकार (Partial Succession)**—आंशिक उत्तराधिकार निम्न दशा में होता है :—

(१) उत्तराधिकार द्वारा, जब किसी प्रदेश का एक भू-भाग पेत्रिक राज्य से अलग हो कर अन्य राज्य बन जाता है और इसके द्वारा वह अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेता है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का पेत्रिक राज्य ग्रेट ब्रिटेन से सन् १७७६ में पृथक् होना ।

(२) परित्याग अथवा विजय द्वारा, जब एक राज्य अन्य राज्य के प्रदेश के एक भाग को प्राप्त कर लेता है और उस परित्याग किये हुए भाग पर पूर्णसत्ता-धिकार ग्रहण कर लेता है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में कैलीफोर्निया का परित्याग सन् १८४७ में ।

(३) अंग विच्छेद द्वारा, जब कि एक पूर्ण प्रभु-सत्ताधारी राज्य अपनी स्वतन्त्रता आंशिक रूप से संघीय राज्य में संयुक्त किये जाने से अथवा एक अधिक शक्तिशाली शक्ति के आधिपत्य अथवा संरक्षण में आने से खो देता है, अथवा जब एक अपूर्ण सर्वोच्चसत्ताधारी राज्य अर्थात् एक अधिपति अथवा संरक्षित राज्य अथवा संघीय राज्य का कोई सदस्य पूर्ण सर्वोच्चसत्ताधारी हो जाता है । उदाहरणार्थ सन् १९३८ में म्युनिच नियमपत्र के परिणामस्वरूप चेकोस्लोवाकिया का विच्छेद ।

## राज्य उत्तराधिकार के परिणाम

**संधि-अधिकार और कर्तव्य (Treaty Rights and Obligations):—**  
अधिकार तथा कर्तव्य जो उत्तराधिकारी राज्य को प्राप्त होते हैं, उत्तराधिकार के ढंग पर निर्भर हैं । सर्वव्यापी उत्तराधिकार की दशा में जब एक राज्य स्वेच्छा से दूसरे राज्य में सम्मिलित हो जाता है अथवा जब वह अन्य राज्य द्वारा अधीनस्थ किया जाता है, तो उत्तराधिकारी राज्य वही अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति बना रहता है, परन्तु पूर्वाधिकारी राज्य जो सम्मिलित हुआ है अथवा अधीनस्थ किया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में पूर्णतः लुप्त हो जाता है । राजनैतिक सन्धियाँ तथा सम्बन्ध और उनके अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अधिकार तथा कर्तव्य व्यक्तित्व की सारभूत अविच्छिन्नता के अभाव में लुप्त तथा अवैध हो जाते हैं और उत्तराधिकारी राज्य अन्तर्धान हुए राज्य के ऐसे अधिकारों तथा कर्तव्यों को उत्तराधिकार में नहीं प्राप्त करता । वाणिज्य, नौचालन तथा प्रत्यर्पण सम्बन्धी सन्धियों के सम्बन्ध में मतेवय यह है कि वे उत्तराधिकार के अधीन नहीं हैं । इसके विपरीत राज्य-समानेयन की सन्धियाँ पूर्ण प्रभाव के साथ उसके द्वारा प्राप्त नये क्षेत्रों पर लागू होती हैं ।

दो राज्यों के सम्मिलन में प्रायः पूर्ववर्ती संधियाँ अपने मूल रूप में प्रवर्तित मानी जाती हैं। इनका प्रवर्तन उस समय तक उचित माना जाता है, जब तक कि वे सध राज्य के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच द्वन्द्व नहीं उत्पन्न करती। किन्तु यदि सम्मेलन इस प्रकार का होता है कि प्रभुसत्ता के बँटवारा का प्रश्न नहीं आता, तो प्रायः सधि-प्रधिवार और कर्तव्य लुप्त हो जाते हैं।

यदि बहुत से राज्य मिलकर एक सध स्थापित करते हैं, तो सभी संधियाँ जिसके वे पक्षकार थे, समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह का परिणाम उस समय भी होता है, जब कि एक राज्य को छिन्न-भिन्न करके अनेक राज्य उत्पन्न हो जाते हैं।

व्यक्तिगत संधियाँ जो कि अनन्य प्रकार से सविदा करने वाले पक्षकारों के व्यक्तिगत से सम्बन्धित हैं, जैसे सम्बन्ध स्थापन, पचायत भयवा तटस्थता की संधियाँ, आदि। ये संधियाँ उस कुटुम्ब के लुप्त होने पर समाप्त हो जाती हैं और इनके सम्बन्ध में कोई उत्तराधिकार नहीं होता।

व्यक्तिगत संधियाँ, जिनका कि एकात्मिक रूप से किसी सविदा में, सम्मिलित होने वाले पक्षकारों से व्यक्तिगत संबंध है, जैसे मैत्री-संधियाँ (treaties of alliances), विवाचन (arbitration) या तटस्थता (neutrality), परिवार की समाप्ति और उत्तराधिकार की धूम्यता की स्थिति में समाप्त हो जाती हैं। जहाँ तक वाणिज्य संधियों (Treaties of Commerce), नौबालन (navigation) और प्रत्यर्पण (extradition) का सम्बन्ध है, यह सर्वथा उस राज्य पर निर्भर करता है, जो कि उसे अपने में मिला रहा है, कि क्या वह उन संधियों के उपबन्धों का अनुगमन करने को तैयार है, भयवा उसका प्रत्याख्यान (repudiate) करता है। इस बात पर मतैक्य है कि ये संधियाँ उत्तराधिकार के अधीन नहीं हैं।

तेरल्लिंडन बनाम एम्स<sup>१</sup> के बाद में संयुक्त राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया था कि संयुक्त राज्य एवं प्रशा के बीच सपत्त की गई प्रत्यर्पण-सधि, जो कि जर्मन साम्राज्य के गठन के पूर्व की गई थी, इस गठन के उपरान्त भी इस आधार पर व्यवहार में प्रवर्तित रही कि सधि को जर्मनी ने अधिकारिक रूप से मान्य कर लिया।

विधि-नियामक संधियों के सम्बन्ध में राज्य-उत्तराधिकार.—परंपरागत विचार यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का एक नया सदस्य सधि आभाओं के सम्बन्ध में एक कोरी पटिया से आरम्भ करता है, छूट यदि है तो केवल उन संधियों के प्रसंग में जो स्थानीय आधार उत्पन्न करती हैं और अन्तर्राष्ट्रीय विधि की रूढ-विधियों के प्रवर्तन में भी यही छूट रहती है।

१. Terlinden v. Ames, 184 U. S. 270.



संधियों के प्रसंग में, कोरीपट्टिया (clean slate) होने के प्रसंग में विद्वानों में कुछ मतभेद है। कियातिबियन (Kiatibian) का विचार है कि वे संधियाँ जिनकी उपयोगिता समान है, प्रवर्तित रहती हैं, जैसे पोस्टल, टेलीग्राफिक, और टेलीफोन आगमसमय, घायलों की देखरेख सम्बन्धी जेनेवा कन्वेंशन, गुलाम व्यापार के विनाश सम्बन्धित ब्रुसेल्स कन्वेंशन आदि।

ह्यूबर (Huber) का कथन है कि किसी पुराने राज्य से विभाजित होकर नये राज्य के बनने में, सभी संधियाँ प्रत्यावर्तित हो जाती हैं, यहाँ तक कि बाह्य संधियों का भी प्रत्यावर्तन हो जाता है, किन्तु सैन्यीय तथा गारंटियों में ऐसा नहीं होना। ह्यूबर तो यहाँ तक कि एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य को जीन लेने के प्रसंग में भी सिद्धान्तगत संधियों के प्रत्यावर्तन को स्वीकार करते हैं।

दूसरी ओर ऐसे भी विद्वान हैं जिनकी सम्मति है कि इस प्रकार की संधियों के छुट हो जाने के बहुत से साक्ष्य उपस्थित हैं कीथ (Keith) का विचार है कि बिजेता अथवा उत्तराधिकारी राज्य को किसी भी सन्धि का उत्तराधिकार नहीं प्राप्त होता। जब कि नव-निर्मित राज्य अपने पूर्वाधिकारी राज्य की ही भाँति अन्य पक्षकारों से व्यवहार करने लगता है, तो वह परोक्ष या प्रकट रूप में उन पक्षकारों से एक प्रकार की नई सन्धि में प्रविष्ट होने लगता है। नया राज्य अपने पैतृक राज्य की संधियों पर ज्यों का त्यों चलने का अधिकारी नहीं है।

मैकनेयर (McNair) ब्रिटिश पद्धति को सक्षिप्त करते हुए लिखा है कि "It is believed to be the view of the United Kingdom Government that the general position governing the treaty position of truly new States is that newly established States which do not result from political dismemberment and cannot fairly be said to involve political continuity with any predecessor, start with a clean slate in the matter of treaty obligations" अर्थात् "ऐसा विश्वास किया जाता है कि युनाइटेड किंगडम की सरकार का यह विचार है कि वास्तविक नये राज्यों की संधि स्थिति को नियंत्रित करने वाली सामान्य परिस्थिति यह है कि नये स्थापित राज्य, जो राजनीतिक असदस्यता के परिणाम से उत्पन्न हैं, और जिनके विषय में यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि उनमें राजनीतिक निरंतरता किसी पूर्ववर्ती राज्य से सन्धि-आधारों के प्रसंग में त्रिलकुप नये सिरे से आरम्भ करते हैं।"

ग्रैंडल (Grandall) ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित पद्धति को निम्न प्रकार सक्षिप्त किया है— "A State formed by separation from another whether the personality of the original State still exists or is completely extinct"

tely lost by disintegration, succeeds to such treaty-burdens of the parent State as are permanent and attached to the territory embraced in the new State." "बोई ऐसा राज्य, जो कि किसी दूसरे राज्य से पृथक् होकर गठित हुआ है, तो भले ही पैतृक राज्य का अस्तित्व अब हो, या विभाजन के कारण सर्वथा लुप्त हो गया हो, पैतृक राज्य की ऐसी संधियों के आभारों का उत्तराधिकारी है जो कि स्थायी ढंग की रही हैं और नये राज्य के राज्य क्षेत्र से सलग्न हैं।"

अमेरीकी विद्वानों, जैसे हॉल (Hall), हॉलैंड (Holland), ओपेनहेम (Oppenheim) और ब्रियरी (Brierly) ने कोरी पटिया (clean slate) के नियम का समर्थन किया है, किन्तु वेस्टलेक (Westlake) ने विपरीत विचार प्रकट किया है। अमेरिकी विद्वान व्हीटन (Wheaton), टेलर (Taylor), हर्शी (Hershey) और फेनविक (Fenwick) ने भी उपर्युक्त कोरी पटिया के नियम का समर्थन किया है, जब कि केन्ट (Kent), फील्ड (Field), हेल्लेक (Halleck) और वूल्से (Woolsey) ने विपरीत विचार अपनाया है।

ऐसा कि ऊपर कहा जा चुका है, संधियाँ प्रायः ऐसी सायोगिकताओं के लिए उपबन्ध करती हैं। जब कि बर्मा १९३७ में भारत से पृथक् हुआ था, यह स्वीकार किया गया था कि बर्मा ऐसे सभी अन्तर्राष्ट्रीय धर्म-अभिसन्धियों (International Labour Conventions) के आभारों को अपनाने के लिए बाध्य होगा जिनमें कि वह भारत के अंग के रूप में उपस्थित रहा है।

भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, १९४७, ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारों और आभारों की नियुक्ति के उपबन्ध थे। समस्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता, नमस्त अधिकारों और आभारों सहित भारत को प्राप्त हुई, ऐसे अधिकार और आभार जिसका कि एकान्तिव रूप से भारत या पाकिस्तान की क्षेत्रीय व्यवहारिता से सम्बन्ध था, क्रमशः भारत और पाकिस्तान अधिराज्यों को मिले। इनके अतिरिक्त अन्य सभी अवशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार और कर्तव्य दोनों अधिराज्यों को प्राप्त हुये।

सदस्यता (Membership) :—यह निश्चित है कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता और उनसे उत्पन्न प्रासंगिक आभार या कर्तव्य उत्तराधिकारी राज्य में प्रत्यावर्तित नहीं होते। उदाहरण के लिए जैसे, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य पूर्ववत् बना रहा, किन्तु पाकिस्तान को ३० सितम्बर १९४७ को संयुक्त राष्ट्र संघ में एक नये राज्य के रूप में सदस्यता प्राप्त हुई।

भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन (Separation of India and Pakistan) :—ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम

सन् १९४७ के विधायन के अनुसार भारत को दो स्वतन्त्र अधिराज्यो अर्थात् भारत तथा पाकिस्तान में खण्डित कर दिया गया। दोनों राज्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार तथा कर्तव्यों के अधिकार देने के सम्बन्ध में यह स्वीकृत हुआ कि सब अन्तर्राष्ट्रीय संधी की सदस्यता ऐसी सदस्यता से सलग्न अधिकार तथा कर्तव्यों सहित केवल भारत के अधिराज्य पर अन्तरित होगी और यह कि अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अधीन अधिकार तथा कर्तव्य जो अनन्य प्रकार से प्रदेश के केवल एक विशिष्ट भाग पर ही लागू हैं, उस अधिराज्य पर अन्तरित होंगे जिसमें वह क्षेत्र पड़ता है।

भारत के दो उपखंडों में विभाजित होने के परिणामस्वरूप (भारत का एक भाग विभिन्न होकर एक नया राज्य होने पर) उत्पन्न हुए दो राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार स्थिति के सम्बन्ध में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। यह एक राज्य के रूप में सन्धियों के संपूर्ण अधिकार तथा कर्तव्यों सहित बना रहा। विच्छिन्न होने वाला प्रदेश पाकिस्तान एक नए राज्य के रूप में आया जिसको पुराने राज्य के कोई सन्धि के अधिकार तथा कर्तव्य नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र सभ के ऐसिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ने यह कहा कि उनकी समिति ने इस प्रश्न पर इसकी स्थिति आइरिश फ्री स्टेट के ग्रेट ब्रिटेन से और बेल्जियम के नीदरलैंड से पृथक् होने के अनुरूप है। इन अवस्थानों में वह भाग जो पृथक् हुआ एक नया राज्य माना गया और शेष वर्तमान राज्य के रूप में अपने पूर्ववर्ती अधिकारों तथा कर्तव्यों के सहित बना रहा।

ऐसिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की इस स्पष्ट सम्मति के विचार से खण्डित होने की दशा में भी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना रहा और पाकिस्तान एक नये राज्य के रूप में सितम्बर ३०, सन् १९४७, को संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता में प्रविष्ट हुआ।

किसी राज्य के संविधान या राज्य की सीमा के बदल जाने का प्रभाव:—यह एक सामान्य नियम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य की सदस्यता केवल इसलिए नहीं लुप्त हो जाती कि उसका संविधान या उसकी भूमि-सीमाएं बदल गई हैं। इसी प्रकार उनके अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार और कर्तव्य भी उन्हीं के त्यों बने रहते हैं। नवीन सदस्यता उस राज्य को प्राप्त करनी होती है, जिसका नया निर्माण होता है।

लोक-सम्पत्ति तथा लोक अधिकार:—जब एक राज्य अन्य राज्य का वास्तविक रूप से उत्तराधिकारी होता है तो वह कुछ हुए राज्य के सम्पत्ति स्वामित्वाधिकारों को उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त करता है। राज्य की सम्पत्ति तथा

राजस्व कोष उत्तराधिकारी राज्य को चले जाते हैं। उत्तराधिकारी-राज्य विजित राज्य के सब पावनो को लेता है जिनमें ऐसे पावनो भी सम्मिलित हैं जैसे राजकीय कोष, बाह्य लगाई हुई पूंजी और चल तथा अचल सम्पत्ति। यह बदले हुये सरकारो को देय करो से समाहरण का अधिकार भी प्राप्त कर लेता है। ऐसे स्थानीय विषयों जैसे नदियाँ, सड़क तथा रेल इत्यादि के सम्बन्ध में भी अन्तर्हित राज्य के अधिकारो को उत्तराधिकार में प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त रहता है। उत्तराधिकारी राज्य को पहले क अन्तर्हित राज्य की प्रजा से और जो लोग उसक प्रदेश में रहते हैं, उनसे राजनिष्ठता अपेक्षित करने का अधिकार होता है।

**वैयक्तिक सम्पत्ति (Private Property) :**—किसी प्रदेश के एक राज्य से दूसरे में चले जाने पर उत्तराधिकारी राज्य को उस भूमि में कोई वैयक्तिक सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं होता क्योंकि उत्तराधिकार केवल सर्वोच्चसत्ता के सार्वजनिक अधिकारो से ही सम्बन्धित है न कि वैयक्तिक स्वामित्व के अधिकारो से। नागरिको के वैयक्तिक अधिकार और उनके पारस्परिक सम्बन्ध जब तक कि वे विजेता द्वारा विशेष रूप से परिवर्तित न कर दिये जायें वही रहते हैं।

**वैयक्तिक अधिकार (Private Rights) :**—सोक विधि का यह एक सामान्य नियम है कि जब कभी किसी एक राज्य या प्रभुसत्ता का राजनैतिक क्षेत्राधिकार अथवा भूमि पर विधायन शक्ति दूसरे में हस्तान्तरित हो जाती है, तो देश की राष्ट्र-विधियाँ—अर्थात् वे कानून जो वैयक्तिक अधिकारो की रक्षा के लिए बनाये जाते हैं, उस समय तक प्रवर्तित रहते हैं, जब तक कि नई सरकार या प्रभुसत्ता द्वारा बदल नहीं दिये जाते।

पोलैंड में व्यवस्थित जर्मन नागरिकों के प्रसंग में अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of International Justice) का एक लोकन था कि "Private rights acquired under existing law do not cease on a change of sovereignty. No one denies that the German Civil Law, both substantive and adjective, has continued without interruption to operate in the territory in question. It can hardly be maintained that, although the law survives, private rights acquired under it have perished. Such a convention is based on

no principle and would be contrary to an almost universal opinion and practice.

"A cession of territory does not operate as a cession of the property belonging to its inhabitants."

अर्थात् "वर्तमान विधि के अन्तर्गत अर्जित किया गया अधिकार एक संप्रभु के परिवर्तित होने के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। कोई भी अस्वीकार नहीं करता कि जर्मन-नागरिक-विधि, सारभूत और गुणारमक दोनों रूपों में प्रस्ताव क्षेत्र में, बिना किसी विघ्न के निरंतर व्यवहारिता में रही है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि भले ही विधि अस्तित्व में बनी रहे और उसके अन्तर्गत अर्जित व्यक्तिगत अधिकार समाप्त हो गये। इस प्रकार की व्यवधारणा किसी सिद्धान्त पर आधारित नहीं है और प्रायः सार्वदेशिक सम्मति और अभ्यास के विपरीत होगी।

"किसी क्षेत्र या अधिमिलन नागरिकों की संपत्ति के भी अधिमिलन के रूप में व्यवहार्य नहीं है।"

लोक-विधि का यह एक सामान्य नियम है कि जब कभी राजनीतिक क्षेत्र-अधिकार और किसी भी क्षेत्र के ऊपर विधायिनी शक्ति का हस्तान्तरण किसी एक राष्ट्र या संप्रभु से किसी दूसरे राष्ट्र या संप्रभु के हाथ किया जाता है तो देश की नागरिक विधि, अर्थात् ऐसी विधियाँ जो वैयक्तिक अधिकारों के संरक्षण के लिए निमित्त हैं, उस समय तक प्रभावकारी रहती हैं जब तक कि उन्हें नयी संप्रभु सरकार द्वारा रद्द न कर दिया जाय, या परिवर्तित न कर दिया जाय।

**संधिदात्मक दायित्व (Contractual Liability)** —  
अधिकांशतः प्रमाणिक लेखक इस विचार के समर्थक हैं कि उत्तराधिकारी राज्य अन्तर्धान हुये राज्य की सविदाओं से बाध्य हैं। नया राज्य सब स्थानीय कानूनों तथा सविदा सम्बन्धी कर्तव्यों के लिये उत्तरदायी हो जाता है। फिर भी उत्तराधिकारी राज्य के लिये यह न्यायसंगत है कि वह उस समय पूर्ववर्ती राज्य के बाधनों को मानना अस्वीकार कर दे यदि वे उसके विरुद्ध युद्ध के प्रयोजनों के लिये किये गये हों।

सुविधाजनक अधिकार जो राज्य द्वारा अपने अन्तर्धान होने के पूर्व दिये गये हैं, वे सामान्यतः अन्तर्धान के बाद भी जीवित रहते हैं। समावेश करने वाले राज्य के ऊपर वे बाधनकारी भी होते हैं। उत्तराधिकारी राज्य का यह कर्तव्य होता है

१. शिकागो रॉक आईलैंड ऐंड पैसिफिक रेलवे कंपनी बनाम मैकगिल्लन, १९४५

कि उसके पूर्वाधिकारो द्वारा जो अधिकार न्यायोचित रीति से किसी विदेशी को दिये गये हो उनका आदर करें ।

ऐसी सविदायें जो अन्तर्हित राज्य की वैयक्तिक होती हैं, प्रायः जीवित नहीं रहती ।

वेस्ट रैंड सेटल माइनिंग कंपनी, लिमिटेड बनाम रेक्ष<sup>१</sup> के वाद में अग्नेजी न्यायालय ने इस बात को स्थिर किया है कि यह पूर्ववर्ती विचार कि किसी विजेता राज्य का संप्रभु विजित देश के आभारो के प्रति बंधा हुआ नहीं है, सारभूत रूप में परिवर्तित हो गया है और वर्तमान प्रचलनो न अनुत्तराधिकार के सिद्धान्त की छिड़ को संशोधित कर दिया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने पोलैंड में जर्मन-नागरिकों के व्यवस्थित होने के बाद<sup>२</sup> में अवलोकन किया था कि वर्तमान विधि के अन्तर्गत अर्जित वैयक्तिक अधिकार, सहित उन अधिकारों के, जो कि राज्य में संपत्ति के स्वामी के रूप में अर्जित किये गये हैं, संप्रभुता के किसी उत्तरवर्ती उत्तराधिकारी के प्रति बंध हैं, अर्थात् संप्रभुता में परिवर्तन होने पर वे अधिकार समाप्त नहीं हो जाते । फिर भी उत्तराधिकारी राज्य अधिमिलित राज्य के ऐसे आभारों को स्वीकार करने में न्यायोचित हैं जिन्हें कि उसने इस उत्तराधिकारी राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के प्रयोजन से स्थिर किया था ।

किसी राज्य की समाप्ति के पहले जहाँ तक कि उसके द्वारा सुविधाजनक अधिकार, स्वीकृत किये गये हैं, सामान्यतया ऐसी समाप्ति के बाद भी बाध्यतापूर्ण रहते हैं । उत्तराधिकारी राज्य ऐसे अधिकारों के प्रति बाधित हैं जो कि पूर्ववर्ती राज्य द्वारा किसी विदेशी व्यक्ति को बंधन दग पर प्रदान किये गये हैं । मैग्रोम्बेटिस पैलेस्टाइन वनसेशन के बाद में अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने अवलोकन किया था कि पैलेस्टाइन, जिसने कि टर्की के एक क्षेत्र का उत्तराधिकार पाया, ग्रीक-प्रजा पर दिये गये सुविधा अधिकारों को, जो कि जेरूसलम में किये गये कार्यों के प्रति हैं, स्वीकृत करने के लिए बाधित है, फिर भी ऐसी सुविधामूलक अधिकार उत्तराधिकारी राज्य द्वारा अपनी विधायिनी क्षमता के भीतर, जहाँ तक कि उनका सबंध विदेशियों के प्रति है, मुधारे या विनियमित किये जा सकते हैं ।

सोप्रा कोस्जेग लोकल रेलवे कंपनी अवार्ड (Sopran Koszeg Local Railway Co. Award)<sup>३</sup> के प्रसंग में विवाचकों का कथन था कि सिद्धान्त

१. एल० भार० (१९०५) २ के० बी० ३६१

२. पी० सी० आई० जे० (१९२३) तिरीज बी० न० ६, पृ० ३६

३. २४ ए० जे० आई० एल० (१९३०) १६४

रूप में 'डीड आफ कन्सेशन' द्वारा किसी कंपनी को जो व्यक्तिगत अधिकार दिये गये हैं केवल इस आधार पर शून्यकृत नहीं किये जा सकते, या प्रभावित नहीं हो सकते कि उस क्षेत्र की राष्ट्रीयता परिवर्तित हो गई है जिसमें कि लोकसेवा व्यवहृत हुई थी।

फिर भी, सविदाये जो कि विलुप्त राज्य के प्रति विशुद्धतः वैयक्तिक हैं, उस विलुप्ति के बाद अस्तित्व में नहीं रहती।

**लोक ऋण ( Public Debts ) :—**लोक ऋण के उत्तराधिकार का व्यवहार के सम्बन्ध में मतभेद है। अधिक अच्छा सिद्धान्त तो यह प्रनीत होता है कि यह केवल विवेक का विषय है और इस विषय का व्यवहार में बड़ा अन्तर रहा है। यद्यपि हाल में इस मत का महत्व बढ़ रहा है कि उत्तराधिकारी अपने पूर्वाधिकारों के सार्वजनिक ऋणों को इस शर्त पर अपने ऊपर ले लेता है कि वे ऐसे प्रयोजन के सम्बन्धित न हों जो स्पष्टतः स्थानान्तरित प्रदेश के निवासियों के हितों के विरुद्ध हों अथवा यदि वे उत्तराधिकारी राज्य के विरुद्ध युद्ध तथा अन्य युद्ध-कार्यों को करने के हेतु न लिये गये हों।

सार्वजनिक ऋणों के सम्बन्ध में साधारणतः सन्धि द्वारा व्यवस्था की जाती है।

सन् १९४७ में भारत के दो स्वतन्त्र राज्यों में विभाजन के उपरान्त भारत तथा पाकिस्तान दोनों पहले अविभाजित भारत के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी राज्य हो गये। दोनों राज्यों के बीच तत्कालीन केन्द्रीय सरकार के पावनों तथा ऋणों के बँटवारे के लिये आपस में करार किया गया। रेलवे, तार की लाइनें, डाकखाने, टकसाल इत्यादि के बँटवारे का हिसाब पावने तथा ऋणों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की समिति के विभागीय उप-समिति द्वारा किया गया। अविभाजित भारत के स्टिलवुड बैलेन्सज भारत तथा पाकिस्तान के बीच अनुपात के अनुसार बँट गये। निष्क्रान्तजन-सम्पत्ति सम्बन्धी प्रश्न फिर भी निरन्तर सघर्ष का विषय रहा है।

**दुष्कृति (Torts) :—**उत्तराधिकारी राज्य किसी प्रकार से लुप्त हुये राज्य के अपराधों या किसी प्रकार की दुष्कृतियों के लिये उत्तरदायी नहीं हैं। उत्तराधिकार प्राप्त करने वाले राज्य, वे भले ही विजित हो अथवा अपनी इच्छा से किसी राज्य में मिले हों, लुप्त होने वाले राज्य के अपराधों के लिये ज़िम्मेदार नहीं हो सकते। अमेरिकन तथा ब्रिटिश ब्लेम्स आर्बीट्रेशन ट्रिब्यूनल ने नवम्बर १९२३ में यह निश्चय किया था कि दक्षिणी अफ्रीकन गणतन्त्र की विजय के उपरान्त उनकी दुष्कृतियों का अनुगमन ब्रिटिश सरकार में नहीं हुआ।

सिद्धान्त रूप से विजेता राज्य को विजित राज्य की सरकार द्वारा की गई दुष्कृतियों के लिये उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दुष्कृतियाँ उस सरकार की ओर से की गई थी, उस राज्य-क्षेत्र की ओर से नहीं ।

विदेशों में पड़ी हुई सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तराधिकार :—उत्तराधिकारी राज्य किसी राष्ट्रीय सम्पत्ति का दावा कर सकता है जो उस प्रदेश में स्थित हो जिस पर यह सर्वोच्चसत्ता प्राप्त करे ।

विधियाँ (Laws):—पूर्व प्रभु-सत्ताधारी राज्य को दीवानी विधि उस समय तक प्रवृत्त रहती है जब तक कि यह उत्तराधिकारी राज्य द्वारा परिवर्तित न कर दी जाय, परन्तु सार्वजनिक विधि प्रभुसत्ता के हस्तान्तरण के साथ ही परिवर्तित हो जाती है । प्रादेशिक अन्तरण के उपरान्त जो कोई सार्वजनिक विधि प्रवृत्त रहती है वह अपना बल निश्चित नियम के रूप में प्राप्त करती है क्योंकि यह प्राप्त करने वाले राज्य द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

राष्ट्रीयता :—राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में लुप्त अथवा विजित प्रदेश के निवासी सम्मिलित राज्य की प्रजा हो जाते हैं और पहले राज्य की नागरिकता छो देते हैं । साधारणतः नागरिकों को अपने लिये एक निश्चित भविष्य का अवसर यह चुनने के लिए दिया जाता है कि वे किस राज्य की राज्यभक्ति स्वीकार करना चाहते हैं । भारत के विभाजन के उपरान्त अधिभाजित भारत के पूर्व नागरिकों को यह स्वेच्छा दी गई थी कि वे अपने लिये यह चुन लें कि वे भारत तथा पाकिस्तान के बीच किसकी राष्ट्रीयता स्वीकार करते हैं ।

विद्रोह के दबा दिये जाने के बाद उत्तराधिकार (Succession on suppression of revolt) :—“Changes in the government or the internal policy of a State do not as a rule, affect its position in International Law. A monarchy may be transformed into a republic or a republic into a monarchy; absolute principles may be substituted for constitutional, or the reverse; but, though the government changes, the nation remains, with rights and obligations unimpaired....The principle of the continuity of States has important results. The State is bound by engagements entered into by governments that have ceased to exist.”<sup>१</sup> अर्थात् “सरकार में परिवर्तन, या किसी राज्य की आन्तरिक नीति में होने वाले परिवर्तनों का अन्तर्राष्ट्रीय विधि में नियमतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता । एक राजतन्त्र बदल कर गणतन्त्र का रूप ले



सकता है, या कोई गणतन्त्र बदल कर राजतन्त्र का रूप धारण कर सकता है। निरपेक्ष सिद्धान्तों को हटाकर संवैधानिक सिद्धान्त या इसके विपरीत भी प्रवर्तित हो सकते हैं, किन्तु इन परिवर्तनों से सरकार भले ही बदल जाय, राष्ट्र अपने अधिकारों और आभारा सहित पूर्ववत् रहता है। "राज्यों की निरन्तरता के सिद्धान्त का अपना महत्वपूर्ण परिणाम है। राज्य उन सह-सम्बन्धों के प्रति बाध्य है, जिनमें समाप्त होने वाली सरकारें सम्मिलित हुई थी।"

यदि किसी राज्य में विप्लव हो जाता है, और प्रतिक्रियावादी सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दबा दी जाती है, तो यह प्रश्न उठ सकता है कि दबा दी गई सरकार की सम्पत्तियों का स्वत्व किसका होगा। जहाँ तक कि पूर्ववर्ती राज्य की क्षेत्रीय सीमा में निहित सम्पत्ति का प्रश्न है, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गस्त होने का प्रश्न नहीं उठता। जहाँ तक कि ऐसी सम्पत्ति का प्रश्न है जो कि पहले पैत्रिक राज्य की थी, किन्तु विदेशी राज्यों में विद्रोही सरकार द्वारा छीन ली गई थी, उसे पैत्रिक राज्य परमाधिकार स्वत्व (title paramount) के द्वारा वह किसी विदेशी न्यायालय में कृत कार्यवाही के आधार पर ले सकता है। अन्य सम्पत्तियों के प्रसंग में भी विदेशों में स्थित विद्रोही सरकार की ऐसी सम्पत्ति, जो पहले पैत्रिक राज्य की थी, का उत्तराधिकार अब पैत्रिक राज्य का ही होगा।

प्रश्न यह उठता है कि विद्रोही, किन्तु दबा दी गई सरकार के अण्डों, दायित्वों और अपकृत्यों के प्रति किसे उत्तरदायी माना जाय। इस प्रसंग में वाशिंगटन की संधि, १८७१ द्वारा नियुक्त सम्मिलित आयोग (Mixed Commission appointed by the Treaty of Washington, 1871) का अवलोकन या कि समुक्त राज्य अमेरिका 'कॉन्फेडरेसी' के अण्डों के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय रूप से दायी नहीं है और न तो ऐसी शक्तियों के कृत्यों के प्रति ही दायी है।

फिर भी, ग्रेट ब्रिटेन और मैक्सिको की सन्धि १८२६ में यह निर्धारित हुआ था कि एक पैत्रिक राज्य, यदि चाहे तो क्रान्तिकारी शक्तियों द्वारा की गई शक्तियों की पूर्ति करना 'स्वीकार कर सकता है। किन्तु, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है, कि ऐसी क्षति पूर्ति के लिये उस पर वैध रूप में कोई बाध्यता नहीं है।

असदस्यता की स्थिति में उत्तराधिकार (Succession in case of dismemberment) — जब कि कोई राज्य विभिन्न टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और वे टुकड़े या तो स्वतन्त्र हो जाते हैं या किसी अन्य राज्य में मिला लिये जाते हैं, तो इस प्रसंग में भी उत्तराधिकार के वही नियम लागू होंगे जो अधिक मिलन, विलीनीकरण या मिला लिये जाने की स्थिति में वर्णित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में उत्तराधिकार (Succession in International Organisation) :—ओपेनहेम का कथन है कि, “अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में उत्तराधिकार का प्रश्न उस समय उठता है जब कि लोक-अन्तर्राष्ट्रीय-भग जो कि विशिष्टोक्त प्रयोजनों के लिए गठित था, विघटित हो जाता है और अन्य संगठन समान प्रयोजनों के लिए गठित कर दिया जाता है।” द्वितीय विश्व-युद्ध के उपरान्त ‘लीग आफ नेशन्स’ का स्थान ‘संयुक्त राष्ट्र संधि’ ने लिया, स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थान अन्तर्राष्ट्रीय न्याय-न्यायालय (International Court of Justice) ने लिया, आदि। अतः निष्कर्ष रूप में ओपेनहेम का कथन है कि, “एक नियम के रूप में अधिकारों और समताओं का हस्तान्तरण या तो प्रसंगगत संगठनों के विधायी साधनों; अथवा उनके अंगों के विशिष्ट समझौतों या निर्णयों द्वारा नियन्त्रित होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में निरंतरता बनाये रखने की माँग है कि यह मान लिया जाना चाहिए कि उत्तराधिकार का नियम उन सभी प्रसंगों में लागू होता है जिनमें कि उन दोनों संगठनों के प्रयोजनों के आशय में समरूपता है।”

दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति<sup>१</sup> से सम्बन्धित वाद में अन्तर्राष्ट्रीय-न्याय-न्यायालय ने अपनी सलाह में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा उन सभी पर्यवेक्षकीय कार्यों (Supervisory functions) का निर्वहन करने के रूप में सक्षम है जिन्हें कि ‘लीग आफ नेशन्स’ दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के परमादेशित क्षेत्र के प्रशासन के निमित्त किया करता था। इस प्रकार दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका को अब भी दिसम्बर १९२० के ‘मैगडेट’ के अन्तर्गत अधीन क्षेत्र स्वीकार किया गया।

यू० ए० आर० और यू० ए० एस० के गठन की वैध समस्या (Legal Aspects of the Formation of U. A. R. and U. A. S.) :—यहाँ यू० ए० आर० का अभिप्राय ‘दी यूनाइटेड अरब रिपब्लिक—संयुक्त अरब गणतन्त्र’ और ‘यूनाइटेड अरब स्टेट्स—संयुक्त अरब राज्य’ से है। फरवरी १, १९५८ को मिस्र के राष्ट्रपति गैमेल अब्देल-नासर और सीरिया के राष्ट्रपति सुक्रीयेल कुवैलत्सी ने परस्पर वार्ता के उपरान्त मिस्र और सीरिया को मिलाकर एक ‘संयुक्त अरब गणतन्त्र’ गठित करने की घोषणा की। इस गणतन्त्र का अन्तःकालीन सविधान मार्च ५, १९५८ को तैयार हुआ। ईमेन का सोम्राज्य संयुक्त अरब गणतन्त्र के साथ, संयुक्त अरब राज्य गठित करने के लिए संघटित हुआ। फरवरी १४, १९५८

१. Oppenheim: International Law, Vol. 1, p. 168.

२. (१९५०) आई० सी० जे० रिपोर्ट्स ७९.

को ईराक और जॉर्डन ने अरब-संघ (Arab Union) गठित की, किन्तु ईराक में सैनिक सत्तारोहण के कारण पाँच मास बाद ही यह संघ विघटित हो गया।

**संयुक्त अरब गणतन्त्र** — उपर्युक्त घोषणा से यह गणतन्त्र एक राज्य के रूप में गठित हुआ और घोषणा के अनुसार इस गणतन्त्र के लिए एक विधान प्राधिकार, एक संविधान, एक ध्वज, एक सेना और एक ऐसे लोक का उपबन्ध हुआ जो अधिकारों और कर्तव्यों में समान हो, और जो कि हृदय और भावना से एक होकर संयुक्त अरब गणतन्त्र की रक्षा और उसके एकीकरण में योगदान करें। इस गणतन्त्र के अन्तर्गत कालीन संविधान ने इस बात को पुनः पुष्ट किया कि संयुक्त अरब राज्य एक लोकतन्त्रात्मक (democratic), स्वतन्त्र (independent) और संप्रभु (sovereign) गणतन्त्र है और इसके लोक अरब राष्ट्र के लोक हैं।

यहाँ उल्लेखनीय है कि इस संयोजन के उपरान्त यह गणतन्त्र न तो वैयक्तिक संघ है और न 'कन्फेडरेशन' (confederation) ही है, क्योंकि इसके दोनों सदस्य न तो राज्य हैं और न पृथक् अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति ही हैं। यूजीन कोट्रान (Eugene Cotran) ने इसे 'एक नया और अमूर्तपूर्व विधीनीकरण का दृष्टान्त (a new and unprecedented type of merger)' कहा है, यह एक संघ की अपेक्षा एक एकता (a unity rather than a Union) का रूप है।

**संयुक्त अरब राज्य** — ईमेन के संयुक्त अरब गणतन्त्र से संघटित हो जाने के कारण संयुक्त अरब राज्य की स्थिति कुछ भिन्न रही। यह एक पृथक् राज्य नहीं हुआ और दोनों सदस्य राज्य अर्थात् संयुक्त अरब गणतन्त्र और ईमेन साम्राज्य अपनी संप्रभुता बनाये रहे और अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व भी स्थिर किये रहे। इस प्रकार यह दो पूर्णतः संप्रभु ऐसे राज्यों के एक 'कन्फेडरेशन' की स्थिति को ही प्राप्त कर सका, जो कि एक संधि के सूत्र में बंध गये और जिन्होंने अपना एक संघ अपने मृच्छक अंगों की रचना द्वारा गठित कर ली।

**वैध परीक्षण** — संयुक्त अरब गणतन्त्र को मिस्र और सीरिया से पूर्ववर्ती सदस्य राज्यों की सदस्यता का संयुक्त उत्तराधिकार राष्ट्र संघ में एक ही सदस्य मानकर दिया गया।

इसी तथ्य को यूजीन कोट्रान (Eugene Cotran) ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विशिष्ट अभिकरणों ने बिना किसी विवाद के यह स्वीकार किया कि मिस्र और सीरिया की उभय सदस्यता को संयुक्त अरब गणतन्त्र की एका सदस्यता में परिणत कर दिया जाय। संयुक्त अरब गणतन्त्र को सिने सगठन ने एक नये सदस्य के रूप में नहीं माना, इसलिए उसे नई सदस्यता का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी।

संयुक्त अरब गणतंत्र से सीरिया तथा ईमेन का विभ्रंखलन (Syria and yemen break away from U. A. R.) :—सितंबर १९६१ में सीरिया में एक सैनिक उत्क्रान्ति हुई और सीरिया उपर्युक्त गणतन्त्र से पृथक् हो गया और परिणामतः ईमेन के साथ गठित संघ भी दिसम्बर २३, १९६१ को विघटित हो गया । सीरिया की नई सरकार को अधिकांश देशों ने मान्यता प्रदान कर दी ।

फरवरी १९५८ के पूर्व सीरिया संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मौलिक सदस्य था और अब संयुक्त राष्ट्र संघ में उसकी यह पूर्ववर्ती सदस्यता भी पुनर्जीवित हो गई ।

## अध्याय १०

### हस्तक्षेप

#### ( Intervention )

हस्तक्षेप क्या है :—प्रत्येक राज्य का यह अहरणीय अधिकार है कि वह अपने मामलों का अपनी इच्छानुसार प्रबन्ध करे, जो सविधान चाहे वह स्वीकृत नरे, जब चाहे इसे विधि के शब्दों के भीतर परिवर्तित करे अथवा अन्य राज्यों से सम्बन्ध तथा सन्धि स्थापित करे । लेकिन जैसा खोरेन्स कहते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि अन्य राज्य अथवा राज्यों का समूह इसके कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करता है और इसको ऐसा कार्य करने को बाध्य करने का प्रयत्न करता है जैसा यदि इसको अपने ही ऊपर छोड़ दिया जाता तो यह नहीं करता अथवा इसको ऐसा कार्य करने से रोकता है जैसा कि यह अपने ही ऊपर छोड़ दिये जाने पर करता । इस प्रकार के हस्तक्षेप को कानून की दृष्टि से वास्तविक हस्तक्षेप कहा जाता है ।

ओपेनहेम का कहना है कि हस्तक्षेप एक अधिनायकतात्मक दखल होता है जो एक बड़े राज्य द्वारा दूसरे राज्य के मामलों में वस्तुओं की वास्तविक स्थिति बनाये रखने अथवा परिवर्तन करने के लिए किया जाता है । केवल कल्याणकारी उपदेश अथवा सामान्य राजनैतिक प्रभाव इस शब्द के अधीन नहीं आते क्योंकि हस्तक्षेप की सारभूत आवश्यक वस्तु अर्थात् बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी का इसमें अभाव रहता है ।

स्टार्क ( Starke ) का कथन है कि साधारणतया अन्तर्राष्ट्रीय कानून किसी दूसरे राज्य के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने को मना करता है । यहाँ इस हस्तक्षेप का तात्पर्य साधारण दखल देने, मध्यस्थता या राजनैतिक मुद्दा से

कही अधिक बलवान है। जहाँ तक निषेध का सम्बन्ध है, इसमें अधिनायकत्व से भरा हस्तक्षेप होता है। इसका प्रभावित होने वाले राज्य की इच्छामो के विरुद्ध प्रभाव पड़ता है और प्रायः सदैव ही ऐसा होता है। जैसा कि हाईड (Hyde) ने संकेत किया है, इसे हम "serving by design or implication to impair the political independence of that State", अर्थात् हम उस राज्य की राजनैतिक स्वतन्त्रता का अपहरण कहेंगे।

जैक्सन (Jackson) के अनुसार हस्तक्षेप "the dictatorial or imperative violation by one state of the independence of another", अर्थात् एक राज्य द्वारा अधिनायक रूप में दूसरे राज्य की स्वतन्त्रता का अतिक्रमण कहेंगे।

हस्तक्षेप के प्रकार (Kinds of Intervention) :—हस्तक्षेप के तीन भिन्न-भिन्न प्रकार हैं।

(१) आंतरिक (Internal) :—यह एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के समुदाय के अंगडते हुए सम्प्रदायों के बीच हस्तक्षेप है जो या तो वैध सरकार के अथवा बलवाहियों के संरक्षण के लिए किया जाता है।

(२) बाह्य (External) :—यह एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के सम्बन्धों—सामान्य रूप से विरोधी सम्बन्धों—में हस्तक्षेप है। अन्य शब्दों में यह अन्य राज्य के विदेशी मामलों में हस्तक्षेप है और ऐसा हस्तक्षेप ऐसे राज्य के विरोधी सम्बन्धों के विरुद्ध किया जाता है। इस प्रकार का हस्तक्षेप युद्ध-घोषणा के समान होता है।

(३) दण्डिक (Punitive) :—यह एक दण्डिक उपाय है जो कुछ के थोड़ा कम है और अन्य राज्य के हाथों से हुई हानि के प्रतिकार के रूप में है। इसका प्रयोग अधिकतर बलिष्ठ राज्यों द्वारा निर्बल राज्यों पर किया जाता है।

हस्तक्षेप के मूल कारण :—प्रोफेसर ब्रैयारले के मतानुसार हस्तक्षेप वस्तुतः वैध अवसर तीन शीर्षकों के भीतर लाये जा सकते हैं अर्थात् प्रात्म-रक्षण (self-defence), प्रतिनार (reprisal) तथा सन्धि अधिकारों का प्रयोग (exercise of a treaty right)।

कुछ हस्तक्षेप ऐसे हैं जिनका न्यायोचित होना अधिकार द्वारा ठहराया जाता है और ऐसी दशा में उनको हस्तक्षेप करने वाले राज्य द्वारा अन्य राज्य स्वतन्त्रता का भंग नहीं कहा जा सकता। उनकी विवेचना अन्य कारणों से हस्तक्षेप के लिए न्यायोचित युक्ति के अनुसार नहीं की जा सकती है।—

१—**आत्मसंरक्षण ( Self-Preservation )** —राज्य का सर्वोच्च हित विधि के भी ऊपर है । आत्म-संरक्षण का अधिकार अन्य राज्यों की स्वतन्त्रता का सम्मान करने के कर्तव्य से भी कहीं अधिक पवित्र है । एक राज्य को अन्य राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार उस दशा में होता है जब पूर्ववर्ती राज्य की सुरक्षा तथा सन्निहित हितों में गड़बड़ी पड़ती हो । अतः हस्तक्षेप करने वाले राज्य के अति-सन्निहित भय के निवारणार्थ किये गये हस्तक्षेप परिस्थितियों के प्रभाव के कारण वैध कहे जा सकते हैं । भय प्रत्यक्ष तथा अतिसन्निहित होना चाहिये न कि असंदिग्ध तथा दूरस्थ । कैरोलिन वाले वैध निदर्शक वाद (leading case) में उन नियमों की व्यवस्था की गई है जिनके अनुसार आत्मसंरक्षण का सिद्धान्त निश्चित होता है । सन् १८३७ के कैंनाडा के राजद्रोह के बीच में स्टोमर कैरोलिन विप्लवकारियों द्वारा अमेरिका से नियाग्रा के उस पार शस्त्र तथा मनुष्यों को भेजने के लिये उपयोग में लाया गया था । विप्लवकारियों का उद्देश्य ब्रिटिश प्रदेश पर नियाग्रा के अमेरिका की ओर के भाग से एकाएक आक्रमण करने का था । अमेरिका की सरकार ने उपस्थित प्रस्थान को दवाने का कोई प्रयत्न नहीं किया । कुछ ब्रिटिश सैनिक दलों ने नदी को पार कर लिया और कैरोलिन को ऐसे समय में पकड़ा जब वह अमेरिका के प्रदेश में वौंधी हुई पड़ी थी और उसको बहते हुए छाड़ दिया । अमेरिका ने अपने प्रदेश के उल्लंघन का कठोर विरोध किया और इस बात पर जोर दिया कि उसके प्रादेशिक अधिकारों के इस प्रकार के उल्लंघन के लिये ब्रिटिश सरकार का यह दिखलाना चाहिये कि “आत्म-संरक्षण के लिये एक ऐसी अतिसन्निहित तथा तीव्र आवश्यकता थी जिसमें कोई अन्य उपाय नहीं चुना जा सकता था और विचार के लिये कोई समय नहीं था”—(a necessity of self-defence, instant, overwhelming and leaving no choice of means and no moment for deliberation) और यह कि कैंनेडा के अधिकारियों ने कोई ऐसी बात नहीं की जो “अयुक्त (excessive) ।” ग्रेट ब्रिटेन इस परीक्षा के आधार पर अपने कार्य को वैध नहीं ठहरा सका । अतः उसे इस घटना पर खेद प्रकट करना पड़ा जो संयुक्त राज्य द्वारा स्वीकृत किया गया ।

घणित राष्ट्र द्वारा आत्मसंरक्षण के आधार पर हस्तक्षेप को प्रोफेसर हॉल उस दशा में न्यायोचित ठहराते हैं जब पार्श्ववर्ती राज्य इतना असक्त हो गया हो कि वह अपनी प्रजा के अपने पड़ोसी पर वास्तविक आक्रमणों को रोकने में असमर्थ है अथवा यह बाहर विप्लव भड़काता है अथवा यह ऐसे विरोधों की धमकी देता है जो इसको उलट देने से हटा दिये जा सकें ।

२—सन्धि अधिकारों का लागू करना (Enforcement of Treaty Rights) :—एक राज्य का अन्य राज्य के मामले में दखल देना उस समय वैधानिक माना जाता है जब कि किसी सन्धि के अनुबन्ध पूर्ववर्ती को उत्तरवर्ती की स्वतन्त्रता प्रभावित करने की रक्षा करने को विवश करते हैं। ऐसा हस्तक्षेप स्वतन्त्रता के किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि राज्य जो करना चाहता है उसे ऐसे हस्तक्षेप करने की स्वतन्त्रता सन्धि द्वारा स्वीकार कर ली होती है।

हंगरी के मामले में सोवियत रूस का हस्तक्षेप—हंगरी का संविधान रूस की ही भाँति है। १८ अगस्त १९४६ में हंगरी को 'जन गणतन्त्र' (People's Republic) घोषित किया। अक्टूबर १९४६ में हंगरी के कम्युनिस्ट गणराज्य में एक बड़ी सख्या में हंगरी की जनता के द्वारा पुराने प्रोत्सी सरकार (old Pro-Russian Government) के विरुद्ध विद्रोह को प्राग मंत्री। इस विद्रोह ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि वहाँ पर मार्शल विधि (Martial Law) लागू किया गया। २४ अक्टूबर १९४६ को वारसा-सन्धि के अनुसार, हंगरी सरकार ने सोवियत रूस से सैनिक-सहायता माँगी जिसकी सहायता से हंगरी की सरकारी अधिकारी वहाँ शान्ति और सुरक्षा की स्थापना करने में समर्थ हो गई। इमरे नेगी (Imre Nagy) प्रधान मंत्री ने भी समाजवादी व्यवस्था के हित में रूसी सैनिक-सहायता को आवश्यक समझते हुए समर्थन किया। कई दिनों बाद सोवियत रूस ने हंगरी सरकार की सम्मति से हंगरी से सेना हटा ली। शीघ्र ही विद्रोहियों ने पुनः विद्रोह किया और चोर आतंक फैला दिया। राष्ट्रीय नेगी को जो दल के स्टालिन समर्थकों द्वारा निकाल दिये गये थे, वापस करने का माँग की। इमरे नेगी ने निरंकुश साम्यवादी शासन का अन्त करने के समर्थन में सभी दलों की सरकार का निर्माण किया किन्तु यह सरकार भी स्थिति के संभाल नहीं सके और स्थिति भयंकर होती गयी। अन्त में नेगी सरकार ने उपद्रव को ज़नास केदार (Janos Kadar) ने क्रान्तकारी मजदूरों और किसानों की सरकार बनायी जिसने इस विषय में समय में पूर्ववत् स्थिति लाने के लिये रूस से सैनिक सहायता माँगी। यह माँग वारसा सन्धि के अनुसार ही थी। हंगरी नेना की सहायता से थोड़े समय में विद्रोही दबा दिये गये।

४ नवम्बर, १९४६ को अमेरिका ने मुरसा परिषद् में एक प्रस्ताव पेश किया कि गोविन्द हंगरी के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप न करे और यह भी कि यह हंगरी सरकार से उचित व्यवस्था करके ध्विपक्ष ही नहीं ले सके। गोविन्द गण ने इस प्रस्ताव का निषेध किया जिससे समस्त राज्य संसदों वहाँ पर साधारण सभा (General Assembly) की अगुआई में

गयी । इसमें सोवियत रूस को हंगरी से सेना हटाने के लिये कहा गया जिससे संयुक्त राष्ट्र सभ के संरक्षण में हंगरी में स्वतन्त्र निर्वाचन हो सके । इस अधिवेशन के एक प्रस्ताव द्वारा यह पुनः माँग की गई कि जो विदेशी हस्तक्षेप हंगरी में हुआ है उसकी जाँच सेक्रेटरी जनरल करें ।

यह प्रकट है कि द्वितीय विश्वयुद्ध जब से समाप्त हुआ है रूसी सेना का हंगरी, पोलैंड, और रुमानिया पर अधिकार रहा है । वारसा सन्धि (जो कि उत्तरी अटलांटिक सन्धि सभ के उत्तर में निर्माण की गई) के अनुसार रूस का यह वैध अधिकार था कि उसकी सेना हंगरी में रहे । अतः सोवियत रूस का यह कर्तव्य था कि हंगरी सरकार की सहायता की माँग पर और वहाँ की शान्ति और सुरक्षा के लिये अपनी सेना भेजती रहे जो वारसा की सन्धि की ही शर्त थी । इसके परिणाम-स्वरूप रूस के बीच में पड़ने से वहाँ की विपक्ष स्थिति सुधर गयी जो कि किसी भी दशा में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता ।

१९ नवम्बर १९५६ में रूस के विदेश मंत्री ने साधारण सभा को बतलाया कि रूस हंगरी की स्थिति पूर्ववत् होने पर सेना हटा लेगी और इस सम्बन्ध में वारसा-सन्धि के एक पक्ष के रूप में हंगरी सरकार से समझौता करना आरम्भ करेगी । रूस के प्रतिनिधि ने यह भी व्यक्त किया कि हंगरी के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप करने के सम्बन्ध का कोई भी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर की धारा २ पैरा ७ के विरोध में होगा ।

३—मानवता के कारण (Grounds of Humanity) —हस्तक्षेप का अन्य उचित कारण मानवता के आधार पर स्थापित है । सीरेस का कथन है कि बहुत से लेखकों की सम्मति में ऐसे हस्तक्षेप वैध हैं किन्तु वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत नहीं आ सकते जो राज्यों पर अपने पड़ोसियों की बर्बरता को रोकने का कोई कर्तव्य नहीं सौंपते ।

। चार्टर के अनुसार व्यवस्था (Provisions in the Charter) —संयुक्त राष्ट्र सभ का चार्टर वर्ण, लिंग, भाषा भयवा धर्म के भेद-भाव को मिटाकर सब के लिए मानवीय अधिकार तथा मौलिक सारभूत स्वतन्त्रताओं के लिये प्रादर बढ़ाने तथा प्रोत्साहन देने में अपने विश्वास का पुनः पोषण करता है ।

। दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय उत्पत्ति के लोगों के विरुद्ध जिस जातीय भेद-भाव की नीति का अवलम्बन दक्षिणी अफ्रीका सभ द्वारा किया जा रहा है वह भारत के द्वारा मूलतः सन् १९४६ में वाद उपस्थित करने पर संयुक्त राष्ट्र सभ के विचाराधीन है । जातीय भेद-भाव राज्य के नागरिकों के आधारभूत मानवीय अधि-



कार तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं पर कुठाराघात है। तो भी दक्षिणी अफ्रीका ने अपने पक्ष का समर्थन अनुच्छेद ७२ के परिच्छेद द्वारा किया है और यह प्रतिपादन रिया है कि साधारण सभा इस मद को विचार करने में सक्षम नहीं है क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो वास्तव में उसके (दक्षिणी अफ्रीका के) घरेलू क्षेत्राधिकार के भीतर है। दक्षिणी अफ्रीका का यह विवाद निराधार है क्योंकि उपरोक्त अनुबन्ध जिसके अनुसार एक सदस्य राज्य के मुख्यतः घरेलू क्षेत्राधिकार के मामलों में हस्तक्षेप निषिद्ध है, इस प्रकार से लागू नहीं किया जा सकता कि जिससे चार्टर के आधारभूत अनुबन्धों द्वारा निर्धारित वर्तव्य निरर्थक हो क्योंकि मानवीय अधिकारों को बिना भेदभाव के गारंटी (guarantee) चार्टर के मुख्य अभिप्रायों में से एक है।

४—शक्ति-सन्तुलन (Balance of Power) :—यूरोप की कूटनीति शक्ति के सन्तुलन का संरक्षण एक सदेहरहित सिद्धान्त के रूप में समझी जाती है। Fenwick का कथन है कि शक्ति-सन्तुलन की आवश्यकता के सिद्धान्त ने निर्वर्णक राज्यों के बीच में पारस्परिक आराम-संरक्षण के आधार का काम किया है। इस सिद्धान्त ने एक प्रकार से १९वीं शताब्दी के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को भी प्रभावित किया है। यूरोप की राजनीति-व्यवस्था ने यह सिद्धान्त बहुत ही प्रबल रूप से प्रभावकारी रहा है। शान्ति, सुव्यवस्था और आराम-स्वतन्त्रता के संरक्षण के लिए यह अनिवार्य रहा है कि शक्ति का केन्द्रीकरण न हो जाय। अतएव यह कि शक्ति का संतुलन न होने पर कोई बलशाली राज्य दूसरों को अपने अधीन कर लेगा। अनेक दृष्टान्त हैं, जब कि शक्ति-सन्तुलन के लिये बड़े-बड़े राष्ट्रों को युद्ध की भाग में दूसरों के हित के लिये कूदना पड़ा है। १८५४ में ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रांस प्रीमिया युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की ओर से शक्ति-सन्तुलन के अभिप्राय को अनायास पड़ा था। बालकन पेनिंसुला के अधिकांश हस्तक्षेप भी इसी अभिप्राय से हुये थे।

शक्ति के सन्तुलन के संरक्षण के आधार पर हस्तक्षेप की प्रथा की निम्न प्रायः सभी युग के विधि-वेत्ताओं द्वारा की गई है।

५—व्यक्तियों तथा सम्पत्ति का संरक्षण :—अपने राष्ट्रीय जनो के शान्ति सम्पत्ति तथा हितों का संरक्षण हस्तक्षेप के लिये उचित कारण उपस्थित कर सकता है। संरक्षण की आवश्यकता भारी अन्याय अथवा अनुचित भेदभाव के कारण उत्पन्न होने के कारण उपस्थित हो सकती है।

दक्षिणी अफ्रीका में संघीय सरकार द्वारा भारतीय उत्पत्ति के (जिनके वास्तव में भारत के राष्ट्रीय नहीं हैं) व्यक्तियों के साथ जो भेदभाव का व्यवहार किया जाना है उसकी तीव्र आलोचना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपने भिन्न

प्रस्तावों में की गई है । इन प्रस्तावों में इसके द्वारा चार्टर में स्थापित मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन कहा गया है, किन्तु संघीय सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों को अंगेज करना इस आधार पर की है कि वे उन विषयों में हस्तक्षेप करते हैं जो वास्तविक रूप से उसके धरोरू क्षेत्राधिकार के भीतर आते हैं । उनका यह भी कहना है कि सब से बंधन से यह अपेक्षित नहीं किया जा सकता कि वह इस विषय पर उन प्रस्तावों को कार्यान्वित करे चाहे उनका (प्रस्ताव का) अभिप्राय कितना ही अच्छा हो अथवा चाहे उनकी बारम्बार पुनरावृत्ति ही क्यों न हुई हो, क्योंकि वे संघ की शक्ति के बाहर हैं ।

६—गृहयुद्धों में हस्तक्षेप (Intervention in Civil Wars)—संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात् अब वैयक्तिक राज्यों को किन्हीं अन्य राज्यों के गृहयुद्धों में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं रह गया है । संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर राज्यों पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में किसी राज्य की प्रादेशिक पूर्णता अथवा राजनैतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध बल-प्रयोग की धमकी देने से अथवा बल प्रयोग से अपने भाप को रोके ।

अन्य कारण —हस्तक्षेप के अन्य कारण ये हैं —अथैव हस्तक्षेप को रोकने के लिये, अनेतिकता के विरुद्ध, अन्तर्राष्ट्रीय अशान्ति को हटाने तथा राष्ट्रीय सम्मान को प्रतिरक्षा के लिये अथवा विदेश में स्थित राष्ट्रों के जनो के हितों के संरक्षण के लिये ।

हस्तक्षेप के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विद्वानों के सिद्धान्त :—

स्टार्क (Starke) :—स्टार्क के अनुसार कुछ निम्नलिखित मुख्य परिस्थितियाँ हैं जिन कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में एक राज्य को दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने का वैध अधिकार है,—

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक हस्तक्षेप, उदाहरण के लिये चार्टर के अध्याय ७ के क्रम में सुरक्षा-परिषद् के प्राधिकार के अन्तर्गत सामूहिक कार्यवाहियों का प्रवर्तन ।

(ख) दूर-स्थित अपने नागरिकों के अधिकारों और हितों तथा वैयक्तिक सुरक्षा हेतु ।

(ग) आत्म-सुरक्षा—यदि सशस्त्र आक्रमण के प्रतिरोध के लिये हस्तक्षेप का होना आवश्यक हो गया हो ।

(घ) किसी प्रोटेक्टोरेट का अपने उपनिवेश के मामलों में ।

(ड) यदि कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि की किसी दूसरे राज्य के प्रति व्यवहार में पूर्णतया उपेक्षा कर गया हो, जैसे भवैध रूप में स्वतः उसने हस्तक्षेप किया हो, आदि ।

ओपेनहेम (Oppenheim) :—ओपेनहेम ने ऐसे सात कारणों को उचित माना है, जब कि एक राज्य दूसरे के प्रसंग में हस्तक्षेप कर सकता है । वे कारण निम्न हैं :—

(१) कोई राज्य जिसके अन्तर्गत कुछ संरक्षित राज्य हैं, इस अधिकार के समुक्त कहा जा सकता है कि वह संरक्षित राज्य के समस्त बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करे ।

(२) यदि किसी एक राज्य का बाहरी मामला किसी प्रकार से एक साथ ही दूसरे राज्य का भी बाह्य मामला बन गया हो, तो यदि एक राज्य प्रकेले ही उद्यम कर लेना चाहता हो, तो उसमें दूसरे को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है ।

(३) कोई राज्य जो किसी अन्तर्राष्ट्रीय संधि से अपने बाह्य-प्रसंगों के तिरों में आबद्ध हो, या उसकी क्षेत्रीय अथवा वैयक्तिक प्रभुता उन शर्तों से प्रतिबन्धित हो रही हो, तो दूसरे पक्ष या पक्षों को हस्तक्षेप करने का अधिकार है ।

(४) यदि शान्ति या युद्ध के समय में कोई राज्य ऐसे राष्ट्रिक कानूनों की उपेक्षा करता है, जो रूढ़ि-रूप में या विधि-नियामक-संघि रूप में सार्वभौमिक बन के स्वीकार किये जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अन्य राज्यों को अधिकार है कि हस्तक्षेप कर सकें और बोयी-राज्य को उन नियमों को मानने पर विवश कर सकें ।

(५) यदि किसी एक राज्य ने संधि के आधार पर किसी दूसरे राज्य की सरकार की गारंटी दी है, या अपने साम्राज्य का कुछ भाग उसके अधिकार में प्रदान किया है, तो उस सरकार के परिवर्तन या साम्राज्य में परिवर्तन उपस्थित होने पर वह हस्तक्षेप कर सकता है । इस हस्तक्षेप की शर्त यह है कि गारंटी की संधि दोनों राज्यों के बीच हुई हो, न कि उनके अधिनायकों द्वारा वैयक्तिक रूप से की गई हो ।

(६) बाहरी देशों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार जो कि एक राज्य में निहित है, हस्तक्षेप अपने उस अधिकार द्वारा उपस्थित कर सकता है जिसमें दूसरा पक्ष वैध रूप से बाधित है ।

(७) लीग ऑफ नेशन्स के सगमन तथा समुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर में ही स्वीकार किया गया है कि यदि कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा में प्रत्यक्ष युद्ध-प्रवृत्ति के कारण विघ्न उपस्थित करता है, तो अन्य सदस्य राज्यों द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है । समुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर द्वारा गंध को यह शक्ति

सोचा गया है कि वह असदस्य राष्ट्रों के कार्यों में भी वहाँ तक हस्तक्षेप करे, जहाँ तक कि उनसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा में बाधा पड़ती है ।

**मुनरो सिद्धान्त (The Monroe Doctrine)** — इस सिद्धान्त में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो द्वारा सन् १८२३ में घोषित अमेरिका की नीति की व्यवस्था दी गई है जिसके द्वारा अमेरिका महाद्वीप के राजनैतिक मामलों में यूरोप वालों के हस्तक्षेप का अन्त कर दिया गया । यह नीति कभी कांग्रेस द्वारा प्रमाणित नहीं की गई, न किसी सन्धि का विषय बनाई गई और ऐसी दशा में यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि का नियम नहीं है । घोषणा निम्नलिखित प्रकार की है —

(१) अमेरिका के महाद्वीप को उसकी मुक्त तथा स्वतन्त्र दशा के कारण, जिसे उसने ग्रहण किया है तथा धारण किया है, अब से किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा अविष्यमे उपनिवेशन के लिए विषय नहीं समझना चाहिए ।

(२) यूरोपीय शक्तियों के युद्धों में, उन विषयों में, जो उन्हीं से सम्बद्ध हैं हमने कभी कोई भाव नहीं लिया है और न ऐसा करना हमारी नीति के योग्य है ।

(३) संयुक्त राज्य ने यूरोप के युद्धों में न कभी हस्तक्षेप किया है और न करेगा । इसके विपरीत वे अपनी ही शान्ति तथा सुख के हितार्थ अपनी राजनैतिक पद्धति को अमेरिका के किसी भाग में विस्तृत करने तथा दक्षिणी अमेरिका के प्रजातन्त्रों की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने नहीं दे सकते । उनकी ओर से इस गोलार्थ के किसी भाग में अपनी पद्धति विस्तृत करने के प्रयत्न को हम अपनी शान्ति तथा सुरक्षा के लिए अत्यप्रद समझेगे ।

मुनरो सिद्धान्त का सभ्य अधिकतर राजनैतिक है न कि वैय । इसने अमेरिका की नीति का एक प्रधान सिद्धान्त यह घोषित करके स्थापित किया कि किसी अमेरिकन शक्ति द्वारा अमेरिका की भूमि पर प्रादेशिक शक्ति का अभ्युदय न होना चाहिए और इसमें इस बात का भी समावेश किया गया कि संयुक्त राज्य यूरोपीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन जिसने संयुक्तराष्ट्र संधि का चार्टर का मसौदा तैयार किया, उसके समस्त प्रादेशिक संधि जैसे अमेरिकीय राज्यों के संधि की स्थिति विश्व संधि के सम्बन्ध में क्या होगी, इस ऋण्डे को मिटाने का कठिन कार्य उपस्थित हुआ । यह कठिनाई अनुच्छेद ५१ में रखे हुए अनुबंधों द्वारा दूर कर दी गई है जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संधि के किसी सदस्य के विरुद्ध सैनिक-प्रक्रमण की दशा में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आत्म-रक्षा का अधिकार उस समय तक के लिए स्वीकृत कर लिया गया है जब तक सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनावे ।

रखने के लिए आवश्यक उपाय न कर ले । इस प्रकार चार्टर मुनरो सिद्धान्त को उसके द्वारा स्थापित सामूहिक सुरक्षा की सार्वभौमिक पद्धति के अनुरूप बना देता है । ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी तथा जापान ने हाल में अपने प्रभाव-युक्त क्षेत्रों में उसी नीति का अवलम्बन किया जो हमें मुनरो सिद्धान्त का स्मरण दिलाती है ।

उत्तरीय अटलांटिक सन्धि (१९४९) द्वारा हस्ताक्षर करने वाले इस बात पर सहमत हो गए कि यूरोप अथवा उत्तरी अमेरिका में उनमें से किसी एक अथवा अधिक के विरुद्ध सैनिक आक्रमण उन सब के विरुद्ध आक्रमण समझा जायगा, वृद्ध शक्तीय प्रतिरक्षा समुदाय संधि (१९५२) ने पट्टराष्ट्रीय यूरोपीय सेना को जन्म दिया है तथा अन्य ऐसी सन्धियाँ प्रादेशिक वर्गीकरण विचार पर स्थापित हैं, और सभी मुनरो सिद्धान्त की गंध पाई जाती है ।

क्यूबा के गृह-युद्ध में राष्ट्रपति कैनेडी ने अप्रैल १९६१ में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव को लिखा था कि क्यूबा में यदि किसी बाहरी सैनिक शक्ति ने किसी भी प्रकार हस्तक्षेप किया तो अमेरिकी प्रया के अनुसार वे प्रत्येक बाह्य आक्रमण का प्रतिरोध करेंगे । इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति मुनरो ने जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, वह आज भी अमेरिका में ज्यों का त्यों माना जाता है ।

**डूंगो सिद्धान्त :—**“डूंगो-सिद्धान्त” का भी निर्देश यहाँ करना आवश्यक है । मार्लेन्टाइना के विदेशीय सचिव लुई एन डूंगो ने सन् १९०२ में जब वेस्ट इंडीज तथा जर्मनी द्वारा अपने राष्ट्रीय जनो की ओर से वेनेजुएला की शांतिपूर्वक नाव बन्दी कर दी गई थी यह नियम घोषित किया था । इस घोषणा के अनुसार एक की सरकार से दूसरे देश की सरकार द्वारा अपनी प्रजा को देव कर के अधिकारों की सविदा सम्बन्धी श्रद्धाओं के प्रत्युद्धरण के लिए किसी राष्ट्र को सैनिक बल का सह नहीं लेना चाहिए । उन्होंने कहा कि अपने सार्वजनिक श्रद्धाओं को देने में किसी की असफलता हस्तक्षेप के अधिकार को उत्पन्न नहीं करती । यह अभिप्राय १९०७ की दूसरी हेग सम्मेलन में संयुक्त कर लिया गया है, किन्तु इसे यह जोर निबन्धित कर दिया गया कि सैनिक बल-प्रयोग उस दशा में लागू हो सकता है श्रद्धा पचायत करना अथवा उसका निर्णय मानना अस्वीकार करे ।

डूंगो-सिद्धान्त मुनरो-सिद्धान्त का एक प्रकार से उपसिद्धान्त है ।

**नेहरू-सिद्धान्त (Nehru Doctrine)** — भारत के प्रधानमंत्री प० जवाहरलाल नेहरू ने मुनरो-सिद्धान्त को और भी विस्तार दिया था जब उन्होंने जुलाई २६ सन् १९५५ में मसद में अवलोकन किया था कि पुर्तगाल द्वारा गोवा को अपने कब्जे में बनाये रखना, भारत की स्थापित राजनैतिक नीति का उल्लंघन है ।

व्यवस्था में निरन्तर हस्तक्षेप करते रहना है। उन्होंने आगे कहा था, 'I go a step further and say that any interference by any other power would also be interference with the political system of India' अर्थात् "मैं एक कदम और आगे यह कह सकता हूँ कि किसी अन्य शक्ति द्वारा हस्तक्षेप करने का तात्पर्य भारत की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना होगा।" उन्होंने उन परिस्थितियों को दोहराया जिनमें कि राष्ट्रपति मुनरो ने १८२३ में योरोपीय शक्तियों को यह सूचना दी थी कि संयुक्त राज्य किसी भी यूरोपीय शक्ति द्वारा अमेरिकीय महाद्वीप की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का तात्पर्य स्वयं अपने प्रति अमैत्रीपूर्ण कार्य मानेगा। इस प्रकार की अमैत्री और इस प्रकार का हस्तक्षेप भविष्य के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है।

— — —

## अध्याय ११

### आवश्यकता तथा आत्म-संरक्षण का सिद्धान्त

#### (Doctrine of Necessity and Self-Preservation)

किसी प्रदेश के अतिक्रमण का न्यायोचित होना :—पूर्वकाल से ही यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि का एक स्थिर रूप से माना गया नियम रहा है कि एक राज्य को आत्म-संरक्षण के अधिकार के प्रयोग में अन्य राज्य के अधिकारों को उत्पन्न करने का अधिकार है। ऐसे उत्पन्न केवल आवश्यकता की ही दशा में क्षम्य होते हैं। ग्रीशस (Grotius) के कथनानुसार आवश्यकता एक निश्चित अधिकार उत्पन्न कर देती है और केवल एक बहाना नहीं समझी जा सकती। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र सचिव द्वारा कैरोलीन वाले मामले (१८३७) में यह कहा गया था कि "यद्यपि यह उचित है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषयों के विशेषतः राज्यों की प्रादेशिक पूर्णता के सिद्धान्त के, जो आत्मरक्षा के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त से विकसित हुआ है, अपवाद विद्यमान है फिर भी निस्सन्देह भ्यायोचित यही है कि ये अपवाद उन्ही मामलों में सीमित करने चाहिए जिनमें उस आत्मरक्षा की आवश्यकता तात्कालिक हो, ध्वराहत उत्पन्न करने वाली हो तथा उसके समानान्तर अन्य कोई साधन न रह गया हो और विचार के लिए समय न हो। (Those exceptions should be confined to cases in which the 'necessity of that self-defence is instant, overwhelming, and leaving no choice of means, and no moment for deliberation) इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो कार्यवाही की गई हो उसमें "कोई अनौचित्य या अति न की गई हो, क्योंकि

रखने के लिए आवश्यक उपाय न कर ले। इस प्रकार चार्टर मुनरो सिद्धान्त को उसके द्वारा स्थापित सामूहिक सुरक्षा की सार्वभौमिक पद्धति के अनुरूप बना देना है। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी तथा जापान ने हाल में अपने प्रभाव-युक्त क्षेत्रों में उसी नीति का अवलम्बन किया जो हमें मुनरो सिद्धान्त का स्मरण दिलाती है।

उत्तरीय अटलांटिक सन्धि (१९४६) द्वारा हस्ताक्षर करने वाले इस बात पर सहमत हो गए कि यूरोप अथवा उत्तरी अमेरिका में उनमें से किसी एक द्वारा अधिक वे विरुद्ध सैनिक आक्रमण उन सब के विरुद्ध आक्रमण समझा जायगा, वः शक्तीय प्रतिरक्षा समुदाय संधि (१९५२) ने पट्टराष्ट्रीय यूरोपीय सेना को जन शक्ति है तथा अन्य ऐसी सन्धियाँ प्रादेशिक वर्गीकरण विचार पर स्थापित हैं, और एवं मुनरो सिद्धान्त की गंध पाई जाती है।

क्यूबा के गृह-युद्ध में राष्ट्रपति केनेडी ने अप्रैल १९६१ में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव को लिखा था कि क्यूबा में यदि किसी बाहरी सैनिक शक्ति ने किसी भी प्रकार हस्तक्षेप किया तो अमेरिकी प्रयास के अनुसार वे प्राप बाह्य आक्रमण का प्रतिरोध करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति मुनरो ने जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, वह आज भी अमेरिका में उद्यो का स्थापना जाता है।

**ट्रैगो-सिद्धान्त :—**"ट्रैगो-सिद्धान्त" का भी निर्देश यही करना आवश्यक है। मॉन्टेविडिया के विदेशीय सचिव लूई एन ट्रैगो ने सन् १९०२ में जब वेस्ट इंडीज तथा जर्मनी द्वारा अपने राष्ट्रीय जनो की ओर से वेनेजुएला की शांतिपूर्वक व्यापक बन्दी कर दी गई थी यह नियम घोषित किया था। इस घोषणा के अनुसार एन एन की सरकार से दूसरे देश की सरकार द्वारा अपनी प्रजा को देम कर के अधिकार सविदा सम्बन्धी श्रुतियों के प्रत्युद्धरण के लिए किसी राष्ट्र को सैनिक बल का प्रयोग नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने सार्वजनिक श्रुतियों को देने में किसी राष्ट्र की अक्षमता हस्तक्षेप के अधिकार को उत्पन्न नहीं करती। यह सन्धि सन् १९०७ की दूसरी हेग सम्मेलन में समुक्त कर लिया गया है, किन्तु इसे यह शर्त कि नियमित कर दिया गया कि सैनिक बल-प्रयोग उम दना में लागू हो सकता है कि श्रुति पथापन करना अथवा उमका निर्णय मानना अस्वीकार करे।

ट्रैगो-सिद्धान्त मारो-सिद्धान्त का एक प्रकार से उपसिद्धान्त है।

**नेहरू-सिद्धान्त (Nehru Doctrine) :—**भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मारो-सिद्धान्त को ओर भी विस्तार दिया था कि वह उन्हीं दुर्गम २६ सन् १९५५ में नमद में घोषित किया था कि पुर्नद्वन्द्व द्वारा गोला को अपने बन्धों में बनाये रखना, भारत की स्थानिक शांति

व्यवस्था में निरन्तर हस्तक्षेप करते रहना है। उन्होंने आगे कहा था, "I go a step further and say that any interference by any other power would also be interference with the political system of India" अर्थात् "मैं एक कदम और आगे यह कह सकता हूँ कि किसी अन्य शक्ति द्वारा हस्तक्षेप करने का तात्पर्य भारत की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना होगा।" उन्होंने उन परिस्थितियों को दोहराया जिनमें कि राष्ट्रपति मुन्शे ने १८२३ में यूरोपीय शक्तियों को यह सूचना दी थी कि संयुक्त राज्य किसी भी यूरोपीय शक्ति द्वारा अमेरिकीय महाद्वीप की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का तात्पर्य स्वयं अपने प्रति अमैत्रीपूर्ण कार्य मानेगा। इस प्रकार की अमैत्री और इस प्रकार का हस्तक्षेप भविष्य के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है।

— — —

## अध्याय ११

### आवश्यकता तथा आत्म-संरक्षण का सिद्धान्त

#### (Doctrine of Necessity and Self-Preservation)

किसी प्रदेश के अतिक्रमण का न्यायोचित होना :—पूर्वकाल से ही यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि का एक स्थिर रूप से माना गया नियम रहा है कि एक राज्य को आत्म-संरक्षण के अधिकार के प्रयोग में अन्य राज्य के अधिकारों को उल्लंघन करने का अधिकार है। ऐसे उल्लंघन केवल आवश्यकता की ही दशा में क्षम्य होते हैं। ग्रीशस (Grotius) के कथनानुसार आवश्यकता एक निश्चित अधिकार उत्पन्न कर देती है और केवल एक बहाना नहीं समझी जा सकती। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र सचिव द्वारा कैरोलीन वाले मामले (१८३७) में यह कहा गया था कि "यद्यपि यह उचित है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषयों के निशेधतः राज्यों की प्रादेशिक पूर्णता के सिद्धान्त के, जो आत्मरक्षा के महत्वपूर्ण सिद्धान्त से विकसित हुआ है, भ्रमवाद विद्यमान है फिर भी निस्सन्देह न्यायोचित यही है कि ये भ्रमवाद उन्हीं मामलों में सीमित करने चाहिए जिनमें उस आत्मरक्षा की आवश्यकता तात्कासिक हो, घबराहट उत्पन्न करने वाली हो तथा उसके समानान्तर अन्य कोई साधन न रह गया हो और विचार के लिए समय न हो। (Those exceptions should be confined to cases in which the 'necessity of that self-defence is instant, overwhelming, and leaving no choice of means, and no moment for deliberation) इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि जो कार्यवाही की गई हो उसमें "कोई अनौचित्य या भ्रति न की गई हो, क्योंकि



कार्य का औचित्य आवश्यकता एवं संरक्षण के लिए ही है, अस्तु उसे केवल आवश्यकता तक ही स्पष्टतः सीमित होना चाहिए ।”

व्हीटन (Wheaton) का विचार है कि रक्षा के साधनों के प्रयोग में “कोई भी स्वतन्त्र राज्य किसी दूसरी वैदेशिक शक्ति द्वारा प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता । किन्तु कोई दूसरा राष्ट्र, यदि वह चाहता है, तो अपने आत्म-संरक्षण के अधिकार के प्रयोग में, यदि इन तैयारियों में वह किसी प्रकार से सावधान हो जाने का प्रयत्न समझता है, या वह किसी आक्रमण की आशंका से भयभीत है तो उस सम्बन्ध में निराकरण माँग सकता है ।”

**अन्तर्निहित अधिकार (Inherent Right)** — राष्ट्र सचिव फ्रैंक बी केलोग ने सन् १९२८ में ब्रिआंड-केलॉग-गठबन्धन (Briand-Kellogg Pact) तय करने के प्रसंग में कहा था कि आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्येक प्रभुसत्ताधारी राज्य में अन्तर्निहित है और प्रत्येक सन्धि में निस्सन्देह विद्यमान है । प्रत्येक राज्य हर समय सन्धियों के अनुबन्धों का बिना ध्यान किये अपने प्रदेश को घावे प्रपञ्च आक्रमण से बचाने के लिए स्वतन्त्र है और यही अकेले इस बात को निर्णय करने के लिए सक्षम है कि परिस्थितियों में आत्मरक्षा हेतु युद्ध का सहारा लेना न्यायोचित है अथवा नहीं ।

सिनेटर रूट (Senator Root) के अनुसार “It is well understood that exercise of the right of self-protection may, and frequently does, extend in its effect beyond the limits of territorial jurisdiction of the state exercising it” उनके अनुसार इस अतिक्रमणकारी प्रभाव का सबसे बड़ा उदाहरण किसी एक शक्ति की तात्कालिक सीमा पर दूसरी शक्ति द्वारा भारी सङ्ख्या में सैन्य-संग्रह है । यद्यपि यह सैनिक कार्यवाही अपनी ही सीमा में हो सकती है, फिर भी आतंकित राज्य को अपनी रक्षा हेतु युद्ध छेड़ देने का अधिकार है ।

**प्रथम विश्वयुद्ध** — प्रथम विश्वयुद्ध के बीच सन् १९१४ में जर्मनी ने आत्मरक्षा के सिद्धान्त के बहाने बेल्जियम तथा लक्सम्बर्ग की तटस्थता भंग कर दी । जर्मनी ने लक्सम्बर्ग तथा बेल्जियम की स्थायी तटस्थता का उल्लंघन इस आधार पर किया कि उसको दो बार से रूस तथा फ्रांस द्वारा आक्रमण की धमकी दी जा रही है और आत्म-संरक्षण के आधार पर उसका यह अधिकार है कि उसको दोनों आक्रमणकारी फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए लक्सम्बर्ग तथा बेल्जियम में बतौर प्रवेश करें । जर्मनी के रीख-स्टीग (Reichstag) के समक्ष अपना पक्ष गमर्धन करते हुए कहा : “हमारी सेनाओं ने लक्सम्बर्ग पर अधिकार कर लिया है



का प्रयत्न किया गया। तत्कालीन ब्रिटिश कार्य-सचिव श्री रिचर्ड स्टोक्स ने यहाँ तक कहा कि उनकी समझ में यह नहीं आता कि जब विदेशी सेनाएँ चाहे वे किसी प्रकार की हो रूस व मंचूरिया की सीमा तक पहुँच गई हो, तो यह कैसे आशा की जा सकती है कि चीनी लोग मौन रहते।

तिब्बत पर आक्रमण —समान दृष्टान्त के अनुसार चीन ने सन् १९५० में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया जिसका भारत ने तीव्र विरोध किया। किन्तु चीन ने अपने आक्रमण का इस आधार पर समर्थन किया कि मित्र राष्ट्रों को सेनाओं द्वारा कोरिया में ३८वें अक्षांश के पार किया जाने तथा उनके मंचूरिया की सीमा में घों बढाने से चीन के लिए अपने अस्तित्व की रक्षा के उपायस्वरूप तिब्बत पर आक्रमण करना आवश्यक कर्तव्य हो गया था।

इस सिद्धान्त का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह निश्चय राज्यों के हार्थों में एक शक्तिशाली यंत्र दे देता है जिससे वे छोटे राज्यों की स्वतन्त्रता का उल्लंघन कर देते हैं तथा विश्व की शान्ति को भंग करते हैं।

चार्टर के उपबन्ध (Provisions in the Charter) —संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के अनुच्छेद ५१ द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की दशा में उस सदस्य राष्ट्र के लिए व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आत्म-रक्षा का अधिकार सुरक्षित किया गया है, परन्तु आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में जो उपाय सदस्य द्वारा लिये जायें तत्काल सुरक्षा परिषद् को प्रतिवेदित करना चाहिये। यह आत्म-रक्षा का अधिकार उस समय तक जारी रहता है जब तक सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करने के उपाय न कर ले। इस प्रकार का आत्म-रक्षा का अधिकार केवल उस दशा में विद्यमान रहता है यदि यह (राष्ट्र) स्वयं सैनिक आक्रमण का विषय हो, न कि उस दशा में जब आक्रमण की आशा की जाती हो अथवा ऐसी शत्रुता के सम्बन्ध विद्यमान हो जो सैनिक आक्रमण से न्यून हों।

यह सामूहिक आत्म-रक्षा का विचार हाल में मित्र-मित्र सन्धियों के स्थापन द्वारा प्रवृत्त किया गया है अर्थात् अन्तर-अमेरिकीय पारस्परिक सहायता सन्धि (१९४७), पश्चिम-यूरोपीय सहायता तथा सामूहिक आत्म-रक्षा सन्धि (१९४८), अमेरिकी राज्य सभ का नवोद्घाटन अधिनियम (१९४८) तथा उत्तर अटलांटिक सन्धि (१९४९)। राज्य उत्तर अटलांटिक सन्धि के अनुच्छेद ५ में यह व्यवस्था की गई है कि यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में किसी एक अथवा अधिक पक्षधारों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण उन सब के विरुद्ध आक्रमण ममत्ता जापना और उनमें में प्रत्येक उत्तर अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा को बनाये रखने तथा पुनः स्थापित करने के लिए

चार्टर के अनुच्छेद ५१ द्वारा स्वीकृत वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्म-रक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा कार्य कर के जैसा यह आवश्यक समझे (जिसमें सैनिक बल-प्रयोग भी सम्मिलित है) आक्रमित पक्षकार को सहायता करेगा। इस प्रकार के उपाय जो किये जायें तत्काल सुरक्षा परिषद् को प्रतिवेदित किये जायेंगे और उस समय समाप्त हो जायेंगे जब परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखन तथा पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक उपाय कर ले।

**निष्कर्ष** — ऐतिहासिक घटनाओं पर दृष्टिपात करने से यह पता चलता है कि साधारण अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत निस्सन्देह आत्म-संरक्षण के अधिकार का अस्तित्व विद्यमान है। यह अधिकार चार्टर के अनुच्छेद ५१ में भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। १८३७ में बेरोयोन के मामले में यह सिद्ध हो गया था कि दूसरे राज्यों को राज्य मामला में अज्ञात राज्य द्वारा अतिव्रमण क्षम्य है, किन्तु शर्त यही है कि ऐसा अतिव्रमण आत्म संरक्षण हेतु ही किया गया हो। मोपेनहेम का कहना है कि यदि कोई तत्कालिक अतिव्रमण या पहले के लिए अतिव्रमण की पुनरावृत्ति आतंकित राज्य द्वारा बिना किसी अतिक्रमण के रोकी जा सके, तो यह बाद वाला अतिक्रमण आवश्यक नहीं है और इसीलिये यह न्यायोचित नहीं है। ग्रायल्ले का कथन है कि १९३१ में मधुरिया में जापानिया द्वारा बल-प्रयोग के जो भी विचार रहे हों, उसे हम आत्म-संरक्षण के अन्तर्गत नहीं समझ सकते।

चार्टर के अनुच्छेद ५१ के अन्तर्गत आत्म-रक्षा के अधिकार को "armed attack against a member of the United Nations" तक सीमित कर दिया गया है और वह भी उस समय तक के लिए, जब तक कि सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के समुचित उपाय नहीं कर लेती।

इस प्रसंग में कठिनाई यह है कि समुक्त राष्ट्र सच के चार्टर में भी सशस्त्र आक्रमण (armed attack) की व्याख्या नहीं की गई है। इसकी व्याख्या सम्बन्धित राज्यों पर ही उस समय तक के लिए छोड़ी गई है, जब तक कि सुरक्षा परिषद् उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। अस्तु, मोपेनहेम के अनुसार इस बात का निर्णय करना कि किस कार्यवाही को वे आत्म-रक्षा के अन्तर्गत की गई कार्यवाही कहेंगे, उन राज्यों पर ही छोड़ा गया है। ऐसे कार्यों की वैधता के प्रसंग में सुरक्षा परिषद् या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को प्रतिवेदित किया जा सकता है। प्रोफेसर ग्रायल्ले के अनुसार—

"It is therefore clear that the defensive or non-defensive character of any State's action is universally regarded as a question capable of determination by an objective examination of the relevant facts" अर्थात् यह स्पष्ट है कि तथ्य ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि कोई कार्य राज्य द्वारा आत्म रक्षा हेतु अथवा आक्रामक रूप में किये गये हैं।

## अध्याय १२

## राज्य-क्षेत्र

## (State Territory)

राज्य-क्षेत्र भूतल का वह भाग है जिस पर कोई राज्य सर्वोच्च तथा प्रभु सत्ता का प्रयोग करता हो। इसमें भूमि प्रदेश, प्रादेशिक जलभाग, राष्ट्रीय जलभाग तथा प्रदेश के ऊपर के आकाश का भाग तथा भूमि के नीचे का भाग भी सम्मिलित है।

**क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की सीमाएँ :—**सामान्यतः राज्य की क्षेत्रीय प्रभु सत्ता अविभाज्य है परन्तु इस सामान्य नियम के अपवाद हैं। सहाधिपत्य की दशा में प्रदेश दो या अधिक शक्तियों द्वारा बाँट लिया जाता है और प्रभुसत्ता कई राज्यों में विभक्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में अधिपति-राज्य द्वारा किसी विदेशी राज्य को पट्टे पर दिया जा सकता है अथवा बन्धक किया जा सकता है। सन् १६४१ में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राज्य को न्यूफाँडलैंड, ब्रुडर तथा जर्मेका इत्यादि में नाविक तथा हवाई प्रभुओं के लिए प्रदेश के छोटे-छोटे टुकड़े का पट्टे पर देना इसके अन्य उदाहरण हैं। संयुक्त राज्य तथा जापान का फरवरी सन् १९४२ का सुरक्षा समझौता, जिसके द्वारा संयुक्त राज्य को जापान में कुछ प्रभुओं को स्थायी रूप से उपयोग करने को दे दिया गया है तथा संयुक्त राज्य के सर्विस कोर्ट (न्यायालय) को अपने व्यक्तियों तथा उनके अधिकारों के ऊपर अन्त्य क्षेत्राधिकार रखने की व्यवस्था की है, यह जापान की असीमित प्रभुसत्ताधिकार के विस्तार प्रयोग की जा सकती है क्योंकि उस प्रदेश में ऐसी पिछड़ी जातियाँ बसी हुई हैं जिन्होंने किसी भी सीमा में स्वराज्य प्राप्त नहीं किया, उदाहरणार्थ एक भाग शित प्रदेश अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्यास रखने की पद्धति। प्रभु सत्ता संघीय राज्य तथा सदस्य राज्यों के मध्य में भी विभक्त हो सकती है। अतः में प्रभु-सत्ता की परम्परागत धारणा में तीव्र परिवर्तन हो गया है जिसके अनुसार अप्रतिबधित आत्म निश्चय व्यक्त होता था। रूस द्वारा निर्दिष्ट पूर्वीय यूरोप तथा अमेरिका द्वारा प्रभावित पश्चिम के गुटों के बनने के कारण जिसको पूर्व और पश्चिम का घात युद्ध भी कहा जाता है, राज्य-हारी व्यक्तियों को पारस्परिक आर्थिक, सैनिक तथा राजनैतिक सहयोग पर आधारित समुदायों में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति हो गई है जिसके द्वारा उनमें से किसी गुट में पड़ने वाले राज्य का बाह्य मामलों में अधिकतर अप्रतिबधित आत्म निश्चय सहाित हो गया है।

क्षेत्र :—किसी राज्य के क्षेत्र में प्रथम तो वह भूमि आती है जो उसकी सीमाओं के भीतर स्थित है। दूसरे, इसमें आन्तरिक जलभाग जैसे झील, नहर, नदियाँ, बन्दरगाह तथा जलयानों की रक्षा के स्थान होते हैं। तीसरे, इसमें वह प्रादेशिक जलभाग होता है जिसमें किनारे के जलभाग की वह समुद्रीय पट्टी सम्मिलित है जो निचले जल-चिह्न से नाप में तीन मील चौड़ी है। चौथे, इसमें इसके क्षेत्रीय भूमि तथा जलभाग के ऊपर के आकाश का भाग सम्मिलित है।

सीमाएँ :—सीमाएँ एक राज्य के क्षेत्र की सीमाओं को दूसरे राज्य के क्षेत्र से पृथक् करती हैं, और राज्य के क्षेत्रीय अधिकार के भाग हैं। सीमाएँ प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक हो सकती हैं। प्राकृतिक सीमाओं में नदियाँ (जिस प्रकार रावी नदी जो कि पूर्वी तथा पश्चिमी पंजाब की, जो भारत तथा पाकिस्तान के वयाक्रम भाग है, सीमाओं को अलग करती है), पर्वत जिस प्रकार हिमालय (जो भारत की सीमा की रक्षा करता है), मरुभूमि, जंगल तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुएँ हैं। अप्राकृतिक सीमाएँ काल्पनिक सीमा की रेखाएँ हैं जो प्रदेशों के विभाजन के प्रयोजन से बनाई जाती हैं। उनमें दीवालें, स्तम्भ, लकड़ी के टुकड़े इत्यादि सम्मिलित हैं। मेकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच की विभाजक रेखा मानी गई है।

सीमा पर स्थित झील भी दो या अधिक राज्यों के बीच के भू-भाग को एक काल्पनिक सीमा रेखा द्वारा निश्चित करती है जो झील के मध्य से पार होती है।

समुद्रीय पट्टी की सीमा-रेखा अनिश्चित है और यह किनारे से तीन मील से अधिक समीप नहीं जा सकती है।

अप्राकृतिक सीमाएँ एक प्रकार से कल्पना से उत्पन्न सीमाएँ होती हैं जो साधारणतया एक राज्य को दूसरे राज्य से पृथक् कर देती हैं। उनके अन्तर्गत दीवार, स्तम्भ, खम्भे आदि आ सकते हैं। समुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की आधे से अधिक सीमा-रेखाएँ इसी प्रकार की कृत्रिम रेखाएँ हैं।

अनेक प्रसंगों में विवाद-ग्रस्त सीमाओं ने बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय अथवा अन्तर-राज्य विवादों (arbitrations) का प्रश्न उत्पन्न किया है। १९०३ का अलास्का-वाजएडरी आर्बीट्रेशन इस बात का सबसे प्रबल उदाहरण है। यह आर्बीट्रेशन समुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच कनाडा की ओर से किया गया था। प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् से अब तक अनेक सीमा-रेखाकन आयुक्तों की नियुक्ति की जा चुकी है। विवादों का निर्णय किसी देश के वास्तविक आधिपत्य और उसकी भौगोलिक स्थिति को देखकर किया जाता है।

## अध्याय १२

## राज्य-क्षेत्र

## (State Territory)

राज्य-क्षेत्र भूतल का वह भाग है जिस पर कोई राज्य सर्वोच्च तथा प्रभु सत्ता का प्रयोग करता हो। इसमें भूमि प्रदेश, प्रादेशिक जलभाग, राष्ट्रीय जलभाग तथा प्रदेश के ऊपर के आकाश का भाग तथा भूमि के नीचे का भाग भी सम्मिलित है।

**क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की सीमाएँ :—**सामान्यतः राज्य की क्षेत्रीय प्रभु सत्ता प्रविभाज्य है परन्तु इस सामान्य नियम के अपवाद हैं। सहाधिपत्य की दशा में प्रदेश दो या अधिक शक्तियों द्वारा बाँट लिया जाता है और प्रभुसत्ता कई राज्यों में विभक्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ स्थितियों में अधिपति-राज्य द्वारा किसी विदेशी राज्य को पट्टे पर दिया जा सकता है अथवा बन्धक किया जा सकता है। सन् १८४१ में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राज्य को न्यूफाँडलैंड, बमुडा तथा जर्नेरा इत्यादि में नाविक तथा हवाई झुंडों के लिए प्रदेश के छोटे-छोटे टुकड़ों का पट्टे पर देना इसके अन्य उदाहरण हैं। संयुक्त राज्य तथा जापान का फरवरी सन् १९११ का सुरक्षा-समझौता, जिसके द्वारा संयुक्त राज्य को जापान में कुछ झुंडों को स्वामी रूप से उपयोग करने को दे दिया गया है तथा संयुक्त राज्य के सर्विस कोर्ट (न्यायालय) को अपने व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों के ऊपर अनन्य क्षेत्राधिकार रखने की व्यवस्था की है, यह जापान की असीमित प्रभुसत्ताधिकार के विस्तार प्रयोग की जा सकती है क्योंकि उस प्रदेश में ऐसी पिछड़ी जातियाँ बसी हुई हैं जिन्होंने किसी भी सीमा में स्वराज्य प्राप्त नहीं किया, उदाहरणार्थ एक भाग शित प्रदेश अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्यास रखने की पद्धति। प्रभु सत्ता सधीय राज्य तथा सदस्य राज्यों व मध्य में भी विभक्त हो सकती है। अन्त में प्रभु-सत्ता की परम्परागत धारणा में तीव्र परिवर्तन हो गया है जिसके अनुसार अतिरिक्तित्व प्राप्त निरवय व्यक्त होना था। रूस द्वारा निर्दिष्ट पूर्वीय यूरोप तथा अमेरिका द्वारा प्रभावित पश्चिम के गुटों के बनने के कारण जिसको पूर्व और पश्चिम का द्वन्द्व भी कहा जाता है, राज्य-रूढ़ी व्यक्तियों को पारस्परिक धार्मिक, सैनिक तथा राजनैतिक सहयोग पर आधारित समुदायों में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति हो गई है जिसके द्वारा उनमें से किसी गुट में पड़ने वाले राज्य का बाह्य मामलों में अतिरिक्तित्व प्राप्त निरवय सशक्त हो गया है।

क्षेत्र :—किसी राज्य के क्षेत्र में प्रथम तो वह भूमि आती है जो उसकी सीमाओं के भीतर स्थित है। दूसरे, इसमें आन्तरिक जलभाग जैसे झील, नहर, नदियाँ, बन्दरगाह तथा जलयानों की रक्षा के स्थान होते हैं। तीसरे, इसमें वह प्रादेशिक जलभाग होता है जिसमें किनारे के जलभाग की वह समुद्रीय पेटी सम्मिलित है जो निचले जल-चिह्न से नाप में तीन मील चौड़ी है। चौथे, इसमें इसके क्षेत्रीय भूमि तथा जलभाग के ऊपर के आकाश का भाग सम्मिलित है।

सीमाएँ :—सीमाएँ एक राज्य के क्षेत्र की सीमाओं को दूसरे राज्य के क्षेत्र से पृथक् करती हैं, और राज्य के क्षेत्रीय अधिकार के भाग हैं। सीमाएँ प्राकृतिक भयवा अप्राकृतिक हो सकती हैं। प्राकृतिक सीमाओं में नदियाँ (जिस प्रकार रावी नदी जो कि पूर्वी तथा पश्चिमी पंजाब की, जो भारत तथा पाकिस्तान के यथाक्रम भाग है, सीमाओं को अलग करती है), पर्वत जिस प्रकार हिमालय (जो भारत की सीमा की रक्षा करता है), मरुभूमि, जंगल तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुएँ हैं। अप्राकृतिक सीमाएँ काल्पनिक सीमा की रेखाएँ हैं जो प्रदेशों के विभाजन के प्रयोजन से बनाई जाती हैं। उनमें दीवारें, स्तम्भ, लकड़ी के टुकड़े इत्यादि सम्मिलित हैं। मेकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच की विभाजक रेखा मानी गई है।

सीमा पर स्थित झील भी दो या अधिक राज्यों के बीच के भू-भाग को एक काल्पनिक सीमा रेखा द्वारा निश्चित करती है जो झील के मध्य से पार होती है।

समुद्रीय पेटी की सीमा-रेखा अनिश्चित है और यह किनारे से तीन मील से अधिक समीप नहीं जा सकती है।

अप्राकृतिक सीमाएँ एक प्रकार से कल्पना से उत्पन्न सीमाएँ होती हैं जो साधारणतया एक राज्य को दूसरे राज्य से पृथक् कर देती हैं। उनके अन्तर्गत दीवार, स्तम्भ, खंभे आदि आ सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की भाषे से अधिक सीमा-रेखाएँ इसी प्रकार की शुद्धि रेटाएँ हैं।

अनेक प्रसंगों में विवाद-ग्रस्त सीमाओं ने बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय भयवा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों (arbitrations) का प्रश्न उत्पन्न किया है। १९०३ का अलास्का-बाउण्डरी आर्बिट्रेशन इस बात का सबसे प्रबल उदाहरण है। यह आर्बिट्रेशन संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच कनाडा की ओर से किया गया था। प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात् से अब तक अनेक सीमा-रेखांकन आगुक्तों की नियुक्ति की जा चुकी है। विवादों का निर्णय किसी देश के वास्तविक आधिपत्य और भौगोलिक स्थिति को देखकर किया जाता है।



## अध्याय

## राज्य

## (State Te

राज्य-सेन भूतल का वह भाग है ।  
सत्ता का प्रयोग करता हो । इसमें भूमि प्रदेश  
तथा प्रदेश के ऊपर के आकाश का भाग तथा

क्षेत्रीय प्रभुसत्ता की सीमाएँ :—

अविभाज्य है परन्तु इस सामान्य नियम के  
प्रदेश दो या अधिक शक्तियों द्वारा बाँट लिए  
में विभक्त हो जाती है । इसके अतिरिक्त कुछ  
किसी विदेशी राज्य को पट्टे पर दिया जा सकता  
है । सन् १८४१ में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राज्य  
इत्यादि में नाविक तथा हवाई शक्तियों के लिए प्रदेश  
देना इसके अन्य उदाहरण हैं । संयुक्त राज्य तथा  
का सुरक्षा-समझौता, जिसके द्वारा संयुक्त राज्य को  
रूप से उपयोग करने को दे दिया गया है तथा ,र.  
(न्यायालय) को अपने व्यक्तियों तथा उनके प्राधिका  
रखने की व्यवस्था की है, यह जापान की असीमित  
जाता है । कभी-कभी एक प्रदेश के ऊपर प्रभु-सत्ता अन्य  
प्रयोग की जा सकती है क्योंकि उस प्रदेश में ऐसी विद्य  
जिन्होंने किसी भी सीमा में स्वराज्य प्राप्त नहीं किया,  
सित प्रदेश भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रीय स्थापित रखने की पद्धति । प्र  
तथा सदस्य राज्यों के मध्य में भी विभक्त हो सकती है । य  
परम्परागत धारणा में तीव्र परिवर्तन हो गया है जिसके अनुसार  
निश्चय व्यक्त होना था । रूस द्वारा निर्दिष्ट पूर्वीय यूरोप  
प्रभावित पश्चिम के गुटों के बनने के कारण जिसको पूर्व  
गुट भी कहा जाता है, राज्य-रूढ़ी व्यक्तियों को पारस्परिक  
राजनैतिक सहयोग पर आधारित समुदायों में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति  
जिन्होंने द्वारा उनमें से किसी गुट में पड़ने वाले राज्य का बाह्य मामलों में  
अप्रतिबन्धित आत्म-निश्चय संश्लेष हो गया है ।

के व्यापारी तथा युद्ध-भोजों के लिए खोल दी गई। नहर में स्थायी रूप से नौईं दुर्ग बनाने की अनुमति नहीं दी गई।

नहर इजिप्ट के प्रदेश में स्थित है। किन्तु इसकी रक्षा ब्रिटेन की दुर्गरक्षाक सेना द्वारा होती रही। नहर ब्रिटिश कामनवेल्थ की जीवन पक्ति समझी जाती है और ग्रेट ब्रिटेन ने इसकी रक्षा अपने हाथों में ले रखी थी।

ब्रिटेन तथा इजिप्ट, दीर्घकालीन समझौता वार्ता के उपरान्त ब्रिटिश सेनाओं को स्वेज नहर के क्षेत्र से हटाने पर सहमत हो गये। स्वीकार-पत्र पर २७ जुलाई सन् १९५४ को काहिरा में हस्ताक्षर किए गए। इसमें यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश सेनाओं को नहर के क्षेत्र से २० मास के अन्दर खाली कर दिया जाय और यदि अरब राज्यों अथवा टर्की द्वारा आक्रमण हो तो इसमें पुनः कार्य-संचालन आरम्भ कर दिया जाय तथा इस अड़्डे की देव-मान ब्रिटेन के एक नागरिक ठेका देने वाले फर्म द्वारा किया जाय। नये स्वीकार-पत्र की अवधि सात वर्ष की थी।

स्वेज नहर का जुलाई १९५६, को बर्नस नगरी द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फलस्वरूप युद्ध की प्रवृत्ति तैयारियाँ होने लगी। सुरक्षा परिषद् तथा माघारण सभा के हस्तक्षेप से दान्तिमय वातावरण बाधित नया जा सका। स्वेज नहर का विस्तृत विवरण 'सुरक्षा परिषद् के कार्यों का निहायलाइन' नामक अध्याय में दिया गया है।

कोल नहर :—यह बाल्टिक तथा उत्तर मागर का जाहनी है। यह पूर्णतः जर्मन प्रदेश के भीतर से होकर बहती है। प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व यद्यपि जर्मनी ने इसे अन्य राज्यों के जलपथों के लिए खोल रखा था, फिर भी उसे यह अधिकार था कि अपनी इच्छानुसार बन्द कर दे। बर्तर्द्ध की सन्धि (१९१९) में यह व्यवस्था की गई कि कोल नहर तथा उनमें पहुँचने के मार्गों की देवभाव बिना किसी कारणों से की जायगी तथा यह उन सभी राज्यों के व्यापारिक तथा युद्ध-भोजों के लिए पूर्ण गमनता की शर्तों पर खुला रखा जायेगा या जर्मनी के माघ मीरी का सम्मुख रहेगा।

नवम्बर १४ सन् १९३६ का जर्मनी न बर्तर्द्ध की सन्धि में कोल नहर नववर्षी व्यवस्था की देवभाव करने तथा उसे बन्द कर दिया। इसका उपरान्त जनवरी १९, सन् १९३७ को जर्मनी के मोरेना अधिकाधिक न एक अधिनियम निश्चयित कि बर्तर्द्ध विदेशी जलपथों के यह अवेला की गई कि वे नहर में प्रवेश करने के पूर्व आज्ञा प्राप्त करें।

पनामा नहर—पनामा नहर की अन्तर्राष्ट्रीय विधि 'हू वॉशिंग्टन सन्धि' (Hay-Pauncefote Treaty) के अनुबन्धों द्वारा निर्दिष्ट की गई है जो अमेरिकन

**नदियाँ :—**नदियाँ तटस्थ राज्य के क्षेत्र की भाग है। जहाँ कोई नदी किसी राज्य के क्षेत्र अथवा सीमाओं के भीतर पूर्णरूप से पड़ती है, पूर्णतः उसी राज्य की हो जाती है, जैसे टेम्स नदी। ऐसी नदियों को राष्ट्रीय नदियाँ कहा जाता है। किसी विदेशी राज्य के सार्वजनिक तथा वैयक्तिक जहाज राष्ट्रीय नदियों में सन्धि अधिकारों के बिना नहीं चल सकते। वे नदियाँ जो कई राज्यों के मध्य से पार होती हैं राष्ट्रीय नदियाँ नहीं हैं और प्रत्येक राज्य नदी के उस भाग का अधिकारी होता है जो उसके प्रदेश के मध्य से पार होती है। ऐसी नदियों में नदी के तट पर स्थित राज्य नदी के ऐसे भागों पर जो उसके प्रदेश में पड़ती हैं, जल में यातायात को नियमित कर सकते हैं और नदी से असम्बद्ध राज्यों के जलयानों को बहिष्कृत कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी नदियाँ हैं जो सन्धियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बना दी गई हैं। पेरिस की सन्धि (१८५६) ने अन्तर्राष्ट्रीय डेन्यूब आयोग नियुक्त किया जिसमें डेन्यूब नदी पर जलयोतों का यातायात नियमित किया गया। सन् १९४७ के पेरिस के सन्धि सम्मेलन ने यह निर्धारित किया कि डेन्यूब सब राज्यों के लिये बिना किसी अवरोध के खोल देनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ने वाली नदियाँ भी इस प्रकार उभय राष्ट्रीय नदियाँ हैं।

**नहरें :—**नहरें कृत्रिम रूप से बनाई जाती हैं और ऐसी दशा में वे उस देश की भाग हैं जिसके क्षेत्र में वे स्थित हैं। नहरों को कभी-कभी तटस्थ अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बना दिया जा सकता है जब सामुद्रिक शक्तियाँ उन जल-भागों के भीतर सामुद्रिक शत्रुता न करने के लिए सहमत हो जाते हैं। स्वेज नहर, दार्दनेलस, बोसफोरस, कीन नहर तथा पनामा नहरें ऐसी झीलों के उदाहरण हैं जिनको समय पर अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है।

**स्वेज नहर :—**यह मध्य सागर तथा लाल सागर को मिलती है। यह पहले एक कानोसी कम्पनी के अधिकार में थी। इस पर नियन्त्रण का प्रबन्ध ब्रिटिश सरकार के हाथ में था। इस नहर के चार्टर की अवधि नवम्बर १९६६ को समाप्त होती। उस समय यह मित्र देशों की पूर्णतः सम्पत्ति होनी चाहिए। मार्च सन् १९४६ तक कम्पनी के ३२ सचालकों में से केवल दो इजिप्टवासी थे। उसी मास की सातवी तिथि को हस्तांतरित एक स्वीकार-पत्र द्वारा पाँच और इजिप्ट देशवासी सचालक नियुक्त किये गये।

सन् १८८८ की बुखारेस्ट सन्धि के अतिरिक्त में जो ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पाँच, जर्मनी, हॉलैंड, इटली, स्पेन, रूस तथा टर्की के मध्य में हुई थी, उसे पटल कर दिया गया। इस सन्धि द्वारा नहर शान्ति तथा युद्ध के समय सब राज्यों

के व्यापारी तथा युद्ध-पोतों के लिए खोल दी गई। नहर में स्थायी रूप से कोई दुर्ग बनाने की अनुमति नहीं दी गई।

नहर इजिप्ट के प्रदेश में स्थित है। किन्तु इसकी रक्षा ब्रिटेन की दुर्गरक्षक सेना द्वारा होती रही। नहर ब्रिटिश कागनवेल्थ की जीवन-पंक्ति समझी जाती है और ग्रेट ब्रिटेन ने इसकी रक्षा अपने हाथों में ले रखी थी।

ब्रिटेन तथा इजिप्ट, दीर्घकालीन समझौता वार्ता के उपरान्त ब्रिटिश सेनाओं को स्वेज नहर के क्षेत्र से हटाने पर सहमत हो गये। स्वीकार-पत्र पर २७ जुलाई सन् १९५४ को काहिरा में हस्ताक्षर किये गए। इसमें यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश सेनाओं को नहर के क्षेत्र से २० मास के भन्दर खाली कर दिया जाय और यदि अरब राज्यों अथवा टर्की द्वारा आक्रमण हो तो इसमें पुनः कार्य-संचालन आरम्भ कर दिया जाय तथा इस अड्डे की देख-भाल ब्रिटेन के एक नागरिक ठेका देने वाले फर्म द्वारा किया जाय। नये स्वीकार-पत्र की अवधि सात वर्ष की थी।

स्वेज नहर का जुलाई १९५६, को कर्नल नसीर द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फलस्वरूप युद्ध की प्रवृत्ति तैयारियाँ होन लगी। सुरक्षा परिषद् तथा माघारण सभा के हस्तक्षेप से शांतिमय वातावरण वापस लाया जा सका। स्वेज नहर का विस्तृत विवरण 'सुरक्षा परिषद् के कार्यों का सिंहावलोकन' नामक अध्याय में दिया गया है।

**कील नहर** :—यह बाल्टिक तथा उत्तर सागर का जाड़नी है। यह पूर्णतः जर्मन प्रदेश के भीतर से होकर बहती है। प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व यद्यपि जर्मनी ने इसे अन्य राज्यों के जलपोतों के लिए खोल रखा था, फिर भी उसे यह अधिकार था कि अपनी इच्छानुसार बन्द कर दे। वर्साई की सन्धि (१९१९) में यह व्यवस्था की गई कि कील नहर तथा उसमें पहुँचने के मार्गों की देखभाल बिना किसी कर लगाये की जायगी तथा यह उन सभी राज्यों के व्यापारिक तथा युद्ध-पोतों के लिए पूर्ण गमनाना की शर्तों पर खुला रखा जायेगी जो जर्मनी के साथ मैत्री का सम्बन्ध रखेंगे।

नवम्बर १४ सन् १९३६ को जर्मनी ने वर्साई की सन्धि में कील नहर संबंधी व्यवस्था को बेवफा करने पक्ष में भंग कर दिया। इसके उपरान्त जनवरी १६, सन् १९३७ को जर्मनी के नौसेना अधिकारियों ने एक अधिनियम निकाला जिनके अनुसार विदेशी जलपोतों से यह अपेक्षा की गई कि वे नहर में प्रवेश करने के पूर्व आज्ञा प्राप्त करें।

**पनामा नहर**—पनामा नहर की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 'हे पॉन्स-फोटे सन्धि' (Hay-Pauncefote Treaty) के अनुबन्धों द्वारा निर्दिष्ट की गई है जो संयुक्त

राज्य तथा ग्रेट ब्रिटेन के मध्य सन् १९०२ में हुई थी । । इसके अनुसार यह नहर सब राज्यों के व्यापारिक तथा युद्ध-पोतों के लिए खोल दी गई है ।

वस्तुतः इस नहर का क्षेत्र पनामा के गणतंत्र का भाग है । १९०३ में समुद्र राज्य अमेरिका और पनामा गणतंत्र के बीच एक सन्धि हुई थी । इस सन्धि के अनुसार पनामा की स्वतन्त्रता की गारंटी अमेरिका ने दी थी जिसमें पाँच मील की दूरी तक निर्माण-अधिकार को सन्चित कर लिया गया था । १९३६ में इस सन्धि में सुधार किया गया और पनामा के गणतंत्र को नहरी क्षेत्र में और भी व्यापक क्षेत्र-अधिकार प्राप्त हो गये । अमेरिका के उपरोक्त प्रभुता को छोड़कर अन्य सभी प्रसंगों में यह नहर अपनी तटस्थता को स्थिति को बनाये हुए है ।

जलडमरूमध्य—सब जलडमरूमध्य क्षेत्रीय होते हैं जो ६ मील से अधिक चौड़े नहीं होते । कुछ जलडमरूमध्य विशेष स्थानीय विनियमों ( regulations ) के अन्तर्गत हैं, जैसे दार्देनिलोज तथा बासफोरस के जलडमरूमध्य ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा कर्फू चैनल केस, आई० सी० जे० प्रतिवेदन १९४९, पृ० ४ (Corfu Channel Case I. C. J. Reports 1949, p. 4) में यह कहा गया है कि यह सामान्यतः स्वीकृत है और अन्तर्राष्ट्रीय रुढ़ि के अनुसार है कि राज्यों को शान्ति के समय अपने युद्ध-पोतों को उन जलडमरूमध्य के बीच से जो दो समुद्रों के भागों के मध्य में अन्तर्राष्ट्रीय नौबालन के लिए उपयोग में लाये जाते हैं, तटवर्ती राज्य की बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये भेजने का अधिकार है, किन्तु अनुबन्ध यह है कि यात्रा निर्दोष हो ।

सामुद्रिक पेटी—सामुद्रिक पेटी समुद्र का वह भाग है जो तट के राज्य के प्रभुत्व में हो । इस बात पर सर्वसम्मति यही है कि समुद्र का खुला भाग राष्ट्रीय सम्पत्ति नहीं हो सकता । समुद्र का केवल ऐसा भाग जो तटवर्ती जल-भाग है, तट के राज्य की सम्पत्ति है । पुनः ये जलभाग राष्ट्रीय नहीं हैं वरन् क्षेत्रीय हैं क्योंकि उस घेरे में अथवा पेटी में सम्मिलित हैं जिनमें विदेशी राज्यों को अपने व्यापारिक जलपोतों को निर्दोष रूप से चलाने का अधिकार है । उनको क्षेत्रीय जल अथवा 'पार्श्ववर्ती पेटी' भी कहा जाता है जिन पर तट के राज्य को समुद्र क्षेत्रीय-प्रभुता प्राप्त है । सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई के सम्बन्ध में ब्रिक्करशूक (Bynckerkshoek) का मत यह है कि समुद्र का उतना भाग जितनी दूर तक कि तट का एक गोला पहुँच सके, तटवर्ती राज्य की सम्पत्ति होनी चाहिए । यह मत भारत में बहुत से लेखकों द्वारा ग्रहण किया गया । १८वीं शताब्दी के अन्त में तोर का नेमन लगभग ३ मील तक पहुँच सकता था, किन्तु इस नियम के अनुसार यह सीमा निरन्तर नहीं रह सकती क्योंकि ज्यों-ज्यों प्राधुनिक आग्नेय बस्तियों के गोलों की मात्रा

दूरी बढ़ती जायगी त्यों-त्यों यह भी बढ़ती जायगी। ग्रोसस (Grotius) ने यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि प्रभुत्व उस दूरी तक सीमित कर दिया जाय जहाँ तक कि सरक्षण तट से पहुँच सके। वटेल (Vattel) का यह कथन था कि सामान्यतः राज्य का प्रभुत्व पार्श्ववर्ती समुद्र पर वहाँ तक रहता है जहाँ तक यह उसकी सुरक्षा के लिये आवश्यक हो तथा वह अपनी शक्ति से स्थापित कर सके।

ग्रेट ब्रिटेन ने भी क्षेत्रीय जल भाग क्षेत्राधिकार अधिनियम (१८७८) (Territorial Waters Jurisdiction Act, 1878) की धारा ७ को अधिनियमित करके पेटी की चौड़ाई को तीन समुद्रीय मील निर्धारित किया अर्थात् जल-जिन्हू के नीचे से तीन समुद्रीय मील, और अंग्रेजी न्यायालयों का क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय जल भागों पर किये गये अपराधों के ऊपर भी बढ़ा दिया। यह अधिनियम फ्रैंकोनिया घाते मामले (R. v. Keyn, 1876, 2 Ex D 63) में दिये गये निर्णय के निराकरण के लिए पारित किया गया जिसमें यह निर्णय किया गया था कि विधि के नियमों की अनुपस्थिति में ब्रिटेन के दह-न्यायालयों को एक विदेशी द्वारा विदेशी जलपोत पर उसके क्षेत्रीय जल-भाग में किये गये अपराधों के ऊपर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। सन् १८८८ के स्वेज नहर अभिसमय (Suez Canal Convention, 1888) द्वारा भी तीन मील का फैलाव स्वीकृत किया गया।

यद्यपि पेटी के फैलाव के सम्बन्ध में कुछ मतभेद हैं तो भी यह रुढ़ि के नियम के रूप में स्वीकृत किया गया है कि न्यूनतम चौड़ाई तीन मील है और तट के राज्य तटस्थ जल-भाग की उस चौड़ाई पर प्रभुत्व रख सकते हैं जो किनारे से तीन मील के भीतर पड़े। ग्रेट ब्रिटेन तथा समुक्त राज्य अमेरिका का भी यही विचार है। नार्वे तथा डेनमार्क चार मील की सीमा मानते हैं, टर्की तथा यूरानवे पाँच मील तथा फ्रांस और स्पेन छ मील की सीमा पर सहमत हैं।

सामुद्रिक पेटी, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सब राज्यों के व्यापारिक पातों के लिए निष्कपट रूप से नाव-संचालन के लिए खुली है, यद्यपि तट के राज्य का यह अधिकार है कि वह सामुद्रिक शिष्टाचारों के सम्बन्ध में ऐसे विदेशी व्यापारिक जलपोतों द्वारा किये जाने के लिए विधियाँ तथा विनियम बनाये। इस प्रकार की निष्कपटता से नाव-संचालन का अधिकार छुने हुए ममूद्रों की स्वतन्त्रता का ही परिणाम है। तट के राज्य विदेशी जलपोतों के ऐसे आवागमन के लिए कोई पय-कर नहीं ले सकते और न तो यह शान्ति के समय में वैदेशिक युद्ध-पातों के आवागमन को अपने सामुद्रिक पेटी में रोक सकते हैं। किन्तु तट के राज्य को यह अधिकार है कि वह मर्यादाओं को तथा तटवर्ती व्यापार को अपनी प्रजा के लिए सुरक्षित रखे तथा पुलिस अधिकारों का प्रयोग करे तथा नियन्त्रण रखे अथवा

सामुद्रिक पेटो के भीतर सामुद्रिक शिष्टाचार लागू करे। सलेप में जैसा सर राबर्ट फिलिमोर (R. Phillimore) द्वारा R. v. Keyn में व्यक्त किया गया है, इस प्रकार का तीन मील की दूरी पर प्राधिपत्य सीमित दाय का होता है। यह समोच वर्ती तट के संरक्षण के प्रयोजन तक सीमित है जिसके लिए यह दिया गया था और सब जाने-जाने वाले जहाजों पर सामान्य प्रभु-सत्ता के रूप में फैला हुआ नहीं है।

**तटीय व्यापार :—** तटीय व्यापार के सम्बन्ध में नियम यह है कि तट के राज्य को यह अधिकार है कि यह इसे केवल अपने लिए सुरक्षित रखे। प्राप्ति में तटीय व्यापार से उसी किनारे पर स्थित दो बन्दरगाहों के बीच का व्यापार सम्भाला जाता था किन्तु अब इसका अर्थ उस देश के किसी दो बन्दरगाहों के बीच के व्यापार में विस्तृत हो गया है, चाहे वे उसी तट पर स्थित हों या उसी देश के भिन्न-भिन्न तटों पर।

**खाड़ियाँ तथा आखात (Bays and Gulf) .—** आखात तथा खाड़ियाँ जिनका समुद्र से प्रवेश-द्वार छ मील से अधिक चौड़ा नहीं है (पार्श्ववर्ती पेटो की चौड़ाई का दुगुना) आन्तरिक अथवा क्षेत्रीय हैं। यदि यह द्वार-द्वार छ मील से अधिक हो तो दोनों ओर के तीन-तीन मील क्षेत्रीय शक्ति की सम्पत्ति होती है, और का जलमार्ग और खुले हुए समुद्र का भाग है जो किसी राज्य की सम्पत्ति नहीं है वरन् सबके समान उपयोग के लिए है। फिर भी यह नियम दृढ़ नहीं है क्योंकि कुछ ऐतिहासिक आखात भी हैं जो यद्यपि अधिक चौड़े हैं किन्तु क्षेत्रीय जल-मार्ग माने जाते हैं। कुछ अन्य लोग हैं जो १० मील से भी आखात को क्षेत्रीय जल मानते हैं। यह मत सन् १८८२ की उत्तरीय समुद्र अभिसमय द्वारा ग्रहण किया गया था और सन् १९१० में स्थायी पचायती न्यायालय द्वारा निर्णय किये गये। उत्तरी अटलांटिक तटीय महसूलायों वाले मामलों में भी स्वीकृत किया गया। इस नियम के अतिरिक्त क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का दावा चौड़ाई की अपेक्षा न करते हुए भी किया जा सकता है, जिसका आधार दीर्घकालीन उपयोग अथवा ऐतिहासिक प्राप्ति जो अनन्तर अन्य राज्यों द्वारा स्वीकृत की गई हो।

**बन्दरगाह (Ports) .—** अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इन्स्टीट्यूट ने स्टोक्होल्म १९२८ में घोषित किया था कि बन्दरगाह वास्तविक स्वतन्त्र वाले राज्य के माने जायेंगे, किन्तु उन पर विदेशी पोतों के आवागमन को भी व्यवस्था रहेगी।

बन्दरगाहों पर उस राज्य का अधिकार होते हुये भी वैदेशिक जहाजों के उनके प्रयोग से सर्वथा वंचित नहीं किया जा सकता। नियम का यह है कि बन्दरगाहों की शान्ति के समय सदैव अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के लिए खुला रहेगा।

चाहिये, किन्तु सैनिक बन्दरगाहों को विदेशी जहाजों के रुकने या व्यापारिक जहाजों के जाने से रोक देना भी रक्षा की दृष्टि से अनुचित नहीं कहा जा सकता ।

## तीव्र पीछा का सिद्धान्त

(The Doctrine of Hot Pursuit)

“किसी पोत का समुद्र में पीछा किया जा सकता है अथवा उसे पकड़ा जा सकता है यदि वह पोत अथवा उसमें बैठा हुआ व्यक्ति किसी विदेशी राज्य के कानूनों का उस समय अतिक्रमण करता है जबकि वह उसकी क्षेत्रीय जलसीमा में पहुँच गया है । इसे तीव्र पीछा का सिद्धान्त अथवा ‘The Doctrine of Hot Pursuit’ कहते हैं । यह सिद्धान्त किसी सलग्न राज्य के युद्धपोत को यह अधिकार देता है कि वे समुद्र में ऐसे पोत का तुरन्त ही पीछा करें, उन्हें गिरफ्तार करें और विचारण के लिये बन्दरगाह तक वापस ले आवें । इसके अन्तर्गत वे सभी व्यापारिक पोत माने हैं जिन्होंने किसी राज्य की क्षेत्रीय जलसीमा का उल्लंघन किया है ।”

राष्ट्रों की विधि के सहिताकरण सम्बन्धित हेग कांफेस (१९३०) के अंतिम अधिनियम, जो कि क्षेत्रीय सागर की वैध स्थिति (Legal Status of the Territorial Sea) के सबब में था, द्वारा एक मसौदा तैयार किया गया । उसके अनुसार “विदेशी पोतों का पीछा करना या बिना तटवर्ती राज्य के नियमों और कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उस समय आरम्भ होता है जबकि विदेशी पोत राज्य के भीतरी जल-क्षेत्र में या क्षेत्रीय समुद्र के भीतर है । यदि पीछा का विरोध न किया गया तो क्षेत्रीय सीमा के बाहर भी उस पोत का पीछा किया जा सकता है । पीछा करने का अधिकार उसी समय समाप्त हो जाता है जबकि वह पोत जिसका कि पीछा किया गया है, अपने राज्य के क्षेत्रीय समुद्र या तीसरे राज्य के क्षेत्रीय समुद्र में प्रवेश कर जाता है ।”

तीव्र पीछा का अधिकार Story J. द्वारा ‘*Marianna Flora*’ [(1826) 11 Wheaton 1, 42] में माना गया है । यद्यपि ऐसा कहा गया था कि “ऐसे मामला में पक्षवार अपने छतरे पर पात का गिरफ्तार करने हैं । यदि वह गिरफ्तार करने के काम को सिद्ध कर देते हैं तो वह न्यायोचित माना जायगा । अगर वह असफल रहते हैं तो वह दातियों की पूर्ति के उत्तरदायी होंगे ।”

इस सिद्धान्त को दो नार्वे (१९०६) [“*The North*” (1906) 37 Can. S. C. Rep. 385], के मामले में मान्यता मिली जब कि कैनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किये थे :—राष्ट्रा की विधि के अनुसार जबकि कोई पोत किसी विदेशी क्षेत्र में उपस्थित होता है तो वह कानूनों की तोड़ना है, भले ही वह मत्स्यपालन (fisheries) की सुरक्षा के लिये अथवा उसके पर के लिये



या किनारों तक पहुँचने के लिये आया हो और उसका खुले समुद्र में क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर तुरन्त पीछा किया जा सकता है और गिरपतार किया जा सकता है ।”

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इन्स्टीट्यूट (The Institute of International Law) ने ‘तीव्र पीछा’ के सिद्धान्त को स्वीकार किया था और यह व्यवस्था की थी कि ऐसी गिरपतारियों की सम्बन्धित झंडे वाले राज्य के नाम अविलम्ब विज्ञापित निकाल दी जाय ।

‘आई ऐम एलोन’ (I'm alone) [ (1933 : 1935) 3 Reports of Arbitral Awards, 1609 ] के मामले में आयुक्तों का यह कथन था कि संयुक्त राज्य अभिसमय के अनुरूप आवश्यक और उचित और प्रभावशाली शक्ति का प्रयोग पोत को ढूँढने, पकड़ने और बन्दरगाह तक ले आने के सम्बन्ध में कर सकता है और यदि अकस्मात् पोत डूब जाय और इसका कारण तीव्र पीछा में प्रयोग की गई शक्ति हो, तो पीछा करने वाला पोत बिल्कुल निर्दोष माना जायेगा किन्तु आयुक्तों (Commissioners) का विचार था कि किसी सदेहजनक पोत को डुबो देना अभिसमय के अनुसार न्यायोचित नहीं है । आयुक्तों का अन्तिम प्रतिवेदन यह था कि पोत को डुबो देना अन्तर्राष्ट्रीय विधि से न्यायोचित नहीं है और तीव्र पीछा का सिद्धान्त ऐसे मामले में नहीं लागू किया जा सकता ।

जेनेवा कान्फ्रेंस, १९५८ :—सामुद्रिक क्षेत्र के सम्बन्ध में १९५८ में जेनेवा कान्फ्रेंस के समक्ष अन्तर्राष्ट्रीय विधि कमीशन की निम्नलिखित संस्तुतियाँ थीं :—

- (१) कमीशन इस बात पर सहमत है कि सामुद्रिक क्षेत्राधिकार के प्रसंग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों में एकरूपता नहीं है ।
- (२) कमीशन इस बात पर सहमत है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि क्षेत्रीय समुद्र की सीमा को १२ मील से परे नहीं स्वीकृत करता ।
- (३) कमीशन समुद्र की चौड़ाई के सम्बन्ध में कोई निर्णय न करते हुये भी इस निष्कर्ष तक पहुँचता है कि बहुत से राज्यों ने अपनी सीमा ३ मील से अधिक निर्धारित कर रखी है और कुछ तो इस सीमा को मानते ही नहीं ।
- (४) कमीशन का विचार है कि क्षेत्रीय समुद्र का निर्धारण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा होना चाहिये ।

परामर्श के पश्चात् पारस्परिक ३ मील की परिधि का प्रस्ताव दो विधायक बहुमत से कान्फ्रेंस में पारित न हो सका ।

नभ पर सर्वोच्च-सत्ता (Sovereignty over the Air) :—यह सार्वभौमिक रूप से मान्य है कि ऊपर आकाश का क्षेत्र तथा समुद्र का खुला हुआ भाग पूर्ण स्वतन्त्र हुमा करता है ।

जहाँ तक आकाश का सम्बन्ध है, उसके क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आधिपत्य के सम्बन्ध में व्यापक-विस्तार दो में परस्पर मतभेद है । भिन्न-भिन्न सिद्धान्त इस प्रसंग में प्रतिपादित किये गये हैं । पहला सिद्धान्त यह है कि आकाश का भाग पूर्णरूप से स्वतन्त्र है और बिना किसी रोक-टोक के सब के लिये खुला है । दूसरे सिद्धान्त के अनुसार आकाश का निचला हिस्सा युद्ध आदि की दृष्टि से उस राज्य के अधीन है जिस पर नीचे प्रभुत्व है और ऊँचे का आकाशीय भाग इस प्रभुत्व से मुक्त है । तीसरा सिद्धान्त यह है कि आकाश का सुदूरवर्ती धूम्र-प्रदेश उस राज्य के अन्तर्गत आता है जिसके राज्य के ऊपर वह स्थित है । तीसरे सिद्धान्त के अनुसार आकाश का ऊपर का भाग पूर्णतः अनिश्चित दूरी तक नीचे के राज्य के प्रभुत्व में आता है । चौथा और अन्तिम सिद्धान्त इस सम्बन्ध में यह है कि जहाँ तक शान्ति-यातायात का सम्बन्ध है, आकाश का भाग सब के लिये खुला है, किन्तु युद्ध-काल में अथवा सैनिक जहाजों की उड़ानों के लिये यह स्वच्छन्दता नहीं प्रदान की जा सकती ।

पेरिस कान्फ्रेंस :—प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत था कि खुले हुये समुद्र तथा अनधिकृत प्रदेश में ऊपर के आकाश का भाग सबके लिए बिना बाधा के खुला रहना चाहिये । सन् १९१९ में पेरिस में हुए मुख्य राज्यों के सम्मेलन द्वारा एक प्रलेख स्वीकृत किया गया जो आकाशीय यात्रा संचालन विनियम के सम्बन्ध में अभिसमय (Convention for the Regulation of Aerial Navigation) के नाम से प्रसिद्ध है । यह अभिसमय केवल शान्ति के समय लागू रहता है । संयुक्त राज्य अमेरिका इस अभिसमय में पक्षकार नहीं रहा । इस अभिसमय द्वारा संविदा करने वाले राज्यों ने यह स्वीकृत किया कि प्रत्येक राज्य की अपने प्रदेश तथा प्रादेशिक जलभाग के ऊपर स्थित आकाश-भाग पर सम्पूर्ण तथा अनन्य सर्वोच्च सत्ता है किन्तु प्रत्येक पक्षकार ने यह वचन दिया कि शान्ति के समय में यह अन्य पक्षकारों के व्यक्तिगत वायुयानों को निष्कपट आवागमन की स्वतन्त्रता उस समय तक देगा जब तक वे अभिसमय के नियमों का पालन करेंगे । प्रत्येक संविदा करने वाले राज्य ने सैनिक अथवा सार्वजनिक सुरक्षा के कारणों के लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के ऊपर वैयक्तिक उड़ान का विरोध करने का अधिकार अपने लिए सुरक्षित रखा ।

**हवाना कान्फ्रेंस :**—फरवरी १९२८ में कई अमेरिकीय राज्यों ने मिल कर संयुक्त राज्य सम्मिलित था, एक अभिसमय स्थापित किया जो हवाना अभिसमय के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्यापारिक विमान चालन के लिये है और उसी आधार पर है जिस पर पेरिस का अभिसमय।

**पारिस कान्फ्रेंस :**—पारिस अभिसमय जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के सम्बन्ध में नियम निर्धारित किये गये अक्टूबर १२, सन् १९१९ में हस्ताक्षरित किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय वायु-परिवहन के शर्तों को नियमित करने वाले नियमों में सामंजस्य आ जाय।

**शिकागो कान्फ्रेंस अथवा वायु-परिवहन की पाँच स्वतन्त्रताएँ**—सन् १९४४ में शिकागो में एक अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सम्मेलन (International Civil Aviation Conference) व्यापारिक वायु-परिवहन के अधिकारों के विषय विश्वव्यापी व्यवस्था स्थापित करने तथा इस विषय सम्बन्धी विशेष बातों को ध्यान-बालन सम्बन्धी विषयों को निश्चित करने के निमित्त हुआ।

शिकागो के कान्फ्रेंस के अनुच्छेद १ द्वारा प्रत्येक राज्य की अपने क्षेत्र के ऊपर स्थित आकाश-भाग पर सम्पूर्ण तथा अन्य सर्वोच्चतत्ता स्वीकृत की गई। फिर भी सविदा करने वाले राज्यों के क्षेत्र के आधार पर बिना उतरे हुए उड़ने तथा उनके क्षेत्र में यातायात सम्बन्धी विषयों के लिये उतरने की स्वतन्त्रता इस अभिसमय द्वारा दे दी गई। सितम्बर १९४८ की पुलिस कार्यवाही के पूर्व सिडनी हार की भारतीय सरकार की आज्ञा प्राप्त किये बिना भारतीय क्षेत्र के ऊपर से होकर हैदराबाद के उड़ान की भारतीय सरकार द्वारा इस आधार पर कटु आलोचना की गई कि उसकी यह यात्रा निष्कपट नहीं थी क्योंकि वह सऊ तथा गोला-बारूक हैदराबाद को ले जाने में लगा हुआ था। भारत के परिवाद पर ब्रिटिश हवाई मंत्रिमंडल ने सिडनी काउन्सिल के उड़ान का लाइसेंस निलम्बित कर दिया था।

शिकागो कान्फ्रेंस में आकाश-उड़ान के लिये ५ प्रकार की स्वतन्त्रताएँ निर्धारित की गईं। इन्हें 'नम की पाँच स्वतन्त्रताएँ' 'Five Freedoms of the Air' कहा जाता है :—

- १—विदेशी क्षेत्र में बिना उतरे हुये उड़ान।
- २—अनायातायात उद्देश्यों से उतरना।
- ३—राज्य के वायु यातायात के उद्गम के सम्बन्ध में किसी विदेशी वायुयान सम्बन्धी प्रसंगों में उतरना।
- ४—यात्रियों को या टाक को जो उस राज्य क्षेत्र के लिये बनी है, वहाँ पहुँचाना जहाँ का वह वायुयान नागरिक है।

१—दो विदेशी देशों में यातायात-संचालन ।

इस स्वीकार-पत्र पर जो कि पारवहन की पाँच स्वतन्त्रताएँ प्रदान करना था वेबल १९ राज्यों ने हस्ताक्षर किये, और अधिकांश राज्यों ने, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन भी था, हस्ताक्षर नहीं किये । इससे पश्चात् एक दूसरा स्वीकार-पत्र अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेना पारवहन सविदा (International Air Services Transit Agreement) तैयार किया गया जो कि वेबल प्रथम दो स्वतन्त्रताएँ प्रदान करता था, अर्थात् विदेशी क्षेत्र में बिना उतरे हुये उड़ान तथा अनायातायात उद्देश्य से उतरना । इस स्वीकार-पत्र पर १९४५ में ३३ राज्या द्वारा हस्ताक्षर किये गये और १९५१ में ४१ राज्यों में यह लागू था, परन्तु साविद्यत रूप इसमें पक्षकार नहीं था ।

अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सघ (International Civil Aviation Organization) —शिकागो सम्मेलन में की गई स्वीकृतियों के परिणाम-स्वरूप एक अन्तर्राष्ट्रीय उड्डयन सघ सन् १९१९ क अन्तर्राष्ट्रीय वायुपान चालन-प्रापण के स्थान में स्थापित किया गया है । यह नया सघ समुक्त राष्ट्र सघ के विशिष्ट माधना में से एक है और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अपीलाधिकार के अन्तर्गत अभिसमय की बातों के लागू होने के सम्बन्ध में सदस्या के मध्य झगडा का निर्णय करता है । सन् १९५६ तक ७३ देश इस सघ में सम्मिलित हुए थे ।

बेतार की खबरें —किसी राज्य की सीमा के ऊपर आकाशीय क्षेत्र का प्रभुत्व हाता है । इसी प्रभुत्व के कारण वे दूसरे राज्या को अपनी नभ-सीमा में विपैली गैसा या सक्रिय किरणों को भेजने से रोकते हैं । १९०६ में बर्लिन में अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर एक वायरलेस टेलीग्राफ कान्वेशन किया गया था । उस कान्वेशन में केन्द्रों से चलते हुए जहाजों पर खबरे भेजने के सम्बन्ध में निश्चय किये गये थे । इसके पश्चात् १९१२ और १९१४ में क्रमश लन्दन रेडियो टेलीग्राफ कान्वेशन और लन्दन कान्वेशन किये गये थे । १९२७ में बार्सिलोन कान्वेशन किया गया जिसने एक सविदा अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो टेलीग्राफ अभिसमय (International Radio Telegraph Convention) नाम पर तैयार किया । इस कान्वेशन के अनुच्छेद २ में लिखा गया कि सविदा से सम्बन्धित सरकारें बेतार की खबरों को अन्तर्राष्ट्रीय सेवा और लोकहित के लिये उपयोग में लायेंगी । १९३२ में अन्तर्राष्ट्रीय टेली कम्युनिकेशन कान्वेशन मैड्रिड में किया गया । उपर अन्तर्गत सविदा के पत्रकारों के बीच बेतार की खबरों को नभ में भेजने के सम्बन्ध में निश्चित और स्पष्ट नियम बना दिये गये । १९४८ में युरोपियन ब्राडकॉस्टिंग कान्वेशन के आधार पर ब्राडकॉस्टिंग के केन्द्रों के निश्चित आधार और आभार स्थित कर दिये गये ।

किसी राज्य की ऊपरी आकाशीय सीमा की मान्यता और 'यू-२' का दृष्टान्त :—१ मई १९६० को अमेरिकन लाकहीड यू-२ टर्क और पाकिस्तान से होता हुआ सोवियत भूमि की नभ सीमा में अतिक्रमण कर गया। उसका उद्देश्य सैनिक और आयोगिक रहस्यों का पता लगाना था। यह अमेरिकी जहाज सोवियत रूस की सीमा में २००० किलोमीटर तक भीतर घुस आया। किन्तु सोवियत राकेट द्वारा स्वरदलोवस्क (Sverdlovsk) क्षेत्र में गिराया गया। नैतिक, राजनैतिक और वैध दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की ओर से किया गया यह कार्य सर्वथा उचित नहीं कहा जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय कानून इस सिद्धान्त पर दृढ़ है कि किसी देश की प्रभु-सत्ता उसकी सीमाओं के ऊपर आकाश में अनन्त दूरी तक फैली हुई है। यदि यहाँ तक की बाहरी वायुयानों को शान्तिपूर्ण उद्देश्यों से उड़ान की अनुमति प्राप्त है जैसा कि सेटलाइट (satellite) की विदेशी क्षेत्रों में उड़ान, फिर भी जहाँ तक जमी जहाजों का सम्बन्ध है और विशेष तौर से अमेरिकी यू-२ का सोवियत भूमि में इतनी दूर तक घुस आना न्यायोचित नहीं है।

अमेरिकी उड़ाकू ने रूस की भूमि के ऊपर नभ की सीमा में आकर अन्तर्राष्ट्रीय विधि की अवज्ञा की। उसका पहला अपराध तो यह था कि वह अवैध ढंग से सोवियत राज्य की सीमा में आया था और दूसरा यह कि सैनिक रहस्यों का पता लगाकर वह अमेरिकी सरकार को सूचना देना चाहता था जो कि किसी राज्य का विशेष रूप से सुरक्षित रहस्य था। यह अपराध अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से वास्तव में एक अपराध और अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में सभी सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता को समान दृष्टि से देखने का आश्वासन दिया गया है। अमेरिकी जेट विमान सोवियत भूमि अफगानिस्तान होते हुए पहुँचा। यहाँ भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से एक अपराध हुआ, क्योंकि उस विमान ने अफगानिस्तान की नभ-सीमा को बिना अफगान सरकार की सूचना के पार किया। संयुक्त राज्य अमेरिका स्वयं नभ-सीमा की प्रभुसत्ता पर बल देता है। अस्तु सोवियत भूमि में अमेरिकी विमान का आना एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध था।

२५ जनवरी, १९६१, को अमेरिका के नये राष्ट्रपति जॉन एफ० केनेडी ने यह स्वीकार कर लिया कि भविष्य में यू-२ के ढग की सीमा अतिक्रमण जैसी घटना सोवियत नभ क्षेत्र में नहीं घटेगी।

मुविधा-भार या अधिसेविता (Servitudes) :—प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्रीय मुविधा-भार के प्रश्न की विवेचना करना ठीक है। अन्तर्राष्ट्रीय मुविधा-भार एक विशिष्ट धन्य है जो मन्थि द्वारा किसी विशेष राज्य की क्षेत्रीय प्रभु-सत्ता पर

लगाया जाता है जिसके द्वारा उस राज्य का क्षेत्र किसी शर्तों अथवा ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन कर दिया जाता है जिससे अन्य राज्यों के हितों का साधन हो। इस प्रकार स्वीकृति द्वारा किसी राज्य को यह बाध्य किया जा सकता है कि वह समीपवर्ती राज्य की सेना को जाने-जाने दे अथवा उसको समीपवर्ती राज्य के हित में अपने सीमान्त क्षेत्रों पर किलाबन्दी करने से रोका जाय।

**स्वीकारात्मक तथा निषेधात्मक सुविधा-भार (Positive and Negative Servitudes)** — सुविधा-भार स्वीकारात्मक अथवा निषेधात्मक रूप से हो सकता है। प्रथम का अर्थ यह है कि किसी राज्य को अन्य राज्य के क्षेत्र में किसी विशिष्ट कार्य करने का अधिकार है, जैसे किसी विशेष क्षेत्र पर रेल-निर्माण करने तथा उसको चलाने का, चुंगी घर स्थापित करने का, तथा अन्य राज्य के क्षेत्रीय जल-भागों पर मछली पकड़ने का अधिकार, इत्यादि है। निषेधात्मक से यह अर्थ प्रकट होता है कि सुविधा भार से बाध्य राज्य उस क्षेत्र पर कुछ कार्य करने से अपने को रोकें अथवा किसी प्रकार से अपने क्षेत्रीय अधिकारों का प्रयोग करने से निषिद्ध किया जाय। इस प्रकार इसके द्वारा एक राज्य को यह अनुज्ञा दी जा सकती है कि वह राज्य यह माँग करे कि एक समीपवर्ती राज्य अपने सीमान्तों पर किलाबन्दी न करे अथवा कुछ विशिष्ट सीमा के बाहर अपनी भूमि तथा नौ-सेना को न बढ़ावे।

**सैनिक और आर्थिक अधिसेविता (सुविधा-भार) (Military and Economic Servitudes)** :—मोपेनहेम ने दो प्रकार के सुविधा-भारों का और भी वर्णन किया है। उसे सैनिक और आर्थिक सुविधा-भार कहा जाता है। सैनिक सुविधा-भार सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये होता है जैसे विदेशी क्षेत्र में अपनी टुकड़ियाँ रखने का अधिकार या विदेशी क्षेत्र से सशस्त्र टुकड़ियाँ भेजना या यह माँग करना कि विदेशी प्रमुख क्षेत्र में किलाबन्दी नहीं की जा सकती, या इसी प्रकार के अन्य अधिकार। आर्थिक सुविधा-भार व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये होता है, तथा इसका उद्देश्य यातायात, या सामान्य व्यवहार के हेतु भी होता है, जैसे विदेशी क्षेत्रीय जल में मछली पकड़ने का अधिकार, किसी नदी में नौ-चालन में चुंगी के लिये मुक्त क्षेत्र, रेलवे संचालन या विदेशी क्षेत्र से टेलीग्राफ, आदि की सुविधाएँ आदि इसके अन्तर्गत आती हैं।

**राज्य अधिसेविता (सुविधा-भार) की वैधता** :—यदि एक राज्य दूसरे राज्य के अधीन हो जाता है या उसमें विलीन हो जाता है तो उसके सुविधा-भार दूसरे में प्रत्यावर्तित हो जाते हैं। राज्य के उत्तराधिकार पर क्षेत्रीय होने के कारण सुविधा-भार समाप्त नहीं हो जाते। सबधित राज्यों की इच्छा या अनुबन्ध के आधार पर सुविधा-भार समाप्त हो सकते हैं, किन्तु साधारण स्थिति में उसका एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रत्यावर्तन हो जाता है।

अधिसेविता (सुविधा-भार) का अन्त :—सुविधाभार जो कि लोक-लक्षी अधिकार (rights in rem) हैं अनुबद्ध करने वाले राज्य अपने में संपुक्त अथवा सम्मिलित कर लेते हैं यदि सम्बन्धित राज्य उसमें विलीन होता है। सुविधा भार का अन्त अपने सम्बन्धित राज्यों के मध्य की गयी स्वीकृति द्वारा अथवा उस लाभ के अधिकारी राज्य की ओर से प्रकट अथवा अप्रकट त्याग द्वारा किया जा सकता है। उसका अन्त परिस्थितियों में अत्यन्त आवश्यक परिवर्तनों (rebus sic stantibus) के कारण भी हो सकता है।

### अध्याय १३

## राज्य-क्षेत्र का अर्जन तथा अपहरण

### (Acquiring and Losing State Territory)

प्रदेश प्राप्त करने के पाँच सामान्य प्रकार हैं :—

(१) कब्जा या दखल (Occupation) :—ओपेनहेम का कथन है कि दखल किसी राज्य का विनियोजन (appropriation) का वह कार्य है जिसके द्वारा वह स्वेच्छापूर्वक ऐसे प्रदेश के ऊपर प्रभुसत्ता प्राप्त कर लेता है जो उस समय अन्य राज्य की प्रभुसत्ता के अन्तर्गत न हो। अतः यह किसी ऐसे राज्य के ऊपर प्रभुसत्ता स्थापना करने में सम्बन्धित है जो या तो किसी के दखल में न रहा हो अथवा हाल ही में उसका पता लगा हो। अन्य शब्दों में राज्य को दखल के प्रयोजन के लिए यह किसी की भी सम्पत्ति न होना चाहिए। दखल के लिए क्षेत्र को अवरण ही अनधिकृत (res nullius) होनी चाहिए अर्थात् किसी के भी अधिकार में उसे न होना चाहिए जिससे किसी राज्य का उस पर दखल हो सके। यह या तो ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई भी बसा न हो अथवा उसमें ऐसी जातियाँ बसी होनी चाहिए जो किसी ऐसे सभ के अधीन हो जो राज्य न समझा जाय।

वेटेल (Vattel) के अनुसार "All men have an equal right to things which have not yet come into the possession of any one, and these things belong to the person who first takes possession. When, therefore, a nation finds a country uninhabited and without an owner, it may lawfully take possession of it, and after it has given sufficient signs of its intention in this respect, it may not be deprived of it by another nation" अर्थात् ऐसी वस्तु, जिस पर पहले से किसी का दखल न हो किसी की भी समान रूप से हो सकती है। ऐसी वस्तु उसी की हो जाती है जो

पहले दखल कर लेता है। इसलिए जब कोई राष्ट्र किसी देश को निवासियों से रहित और किसी के स्वत्व से परे पाता है तो वह वैध ढंग से उस पर आधिपत्य कर लेता है। उस राष्ट्र की जब कुछ समय तक दृढ़ इच्छा उस क्षेत्र का अपने अन्तर्गत दखल रखने की बनी रहती है, तो फिर कोई अन्य राष्ट्र उसे दखल के अधिकार में वचित नहीं कर सकता।

दखल के लिए राज्य की अनधिकृत सम्पत्ति पर कब्जा करने का विचार प्रथम प्रबल इच्छा होनी चाहिये तथा उस पर उसे बस जाना चाहिये, अर्थात् दखल किये हुये क्षेत्र पर किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण स्थापित होना चाहिये। ओपेनहेम कहते हैं कि अधिकार प्राप्त करना तथा प्रशासन दो आवश्यक तथ्य हैं जिनसे दखल प्रभावपूर्ण होता है। अधिकार करने से उनका आशय यह है कि दखल करने वाला राज्य-क्षेत्र को अपने निकाय (corpus) में उस पर प्रभु-सत्ता स्थापना करने के स्वल्प (animus) से ले ले। यह संकल्प क्षेत्र पर बसने तथा उसके साथ ही साथ कोई ऐसा नियमानुसार कार्य करने से होता है जिससे ये दोनों ही बातें प्रकट हो कि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है और कब्जा करने वाला उसको अपनी प्रभु-सत्ता के अधीन रखने की इच्छा रखता है। यह सामान्यतः नियमानुसार विनियोजन की घोषणा द्वारा अथवा झंडा को गाढ़ने द्वारा किया जाता है जो प्रभुसत्ता का प्रतीक है। प्रशासन से ओपेनहेम का यह आशय है कि कब्जा करने वाले को उस क्षेत्र पर किसी प्रकार का प्रशासन स्थापित करना चाहिये जिससे कि यह प्रकट हो कि क्षेत्र वास्तव में नये कब्जा करने वाले द्वारा शासित होता है।

जर्मनी की वैध स्थिति (Legal Status of Germany).—जर्मनी की पराजय और मित्र-राष्ट्रों को बिना किसी शर्त के समर्पण कर देने से उसकी वैध स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं उपस्थित हुआ, क्योंकि उसकी इस पराजय का परिणाम यह नहीं हुआ कि जर्मनी न्यायिक रूप से (de jure) विजेता राष्ट्रों के अधीन हो गया। पहले तो मित्र-राष्ट्रों की सेना ने जर्मनी का सम्पूर्ण क्षेत्र जीत लिया और जर्मनी की सरकार को उलट दिया गया। किन्तु युद्ध की समाप्ति पर तीन महान् शक्तियों (The Big Three) की बैठक बर्लिन के पोट्सडम नामक स्थान में हुई। सम्मेलन जुलाई १७, से अगस्त २, १९४५ तक हुआ। इसमें एक समझौते पर सौम्य पहुँचे जिसके अनुसार विदेश-मंत्रियों की एक परिषद बनाई गई जिसके ऊपर शान्ति समझौता की आरम्भिक तैयारी करने का कार्य दिया गया। इस परिषद् में युनाइटेड किंगडम, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ, चीन, फ्रान्स और संयुक्त राज्य के विदेश मंत्री रहे गये। समझौते के अनुसार जर्मनी के प्रशासक मशीनरी का जहाँ तक सम्बन्ध था, जर्मनी में सर्वोच्च प्राधिकार का प्रयोग उनकी क्रमशः सरकारों



के निर्देश पर होना था जिसमें से संयुक्त राज्य अमेरिका के कमाण्डर-इन-चीफ, युनाइटेड किंगडम, सोवियत सोशलिस्ट गणतन्त्र संघ, और फ्रेंच गणतन्त्र अपने-अपने दखल की सीमा में निर्देशक थे। संयुक्त रूप से भी ऐसे प्रसंगों में जिनका कि पूरी जर्मनी से सम्बन्ध था, कन्ट्रोल-कौंसिल के सदस्य होने के नाते उनका प्रभुत्व था।

कुछ विद्वानों, जैसे जेनिंग्स, फ्रीडमैन और केल्सन (Jennings, Friedman and Kelsen) का कहना है कि जर्मनी पर प्राधिकार के इस प्रकार पृथक् रूप से ग्रहण करने के कारण तथा नाज़ी सत्ता के पूर्णतः समाप्त कर देने और प्रतिद्वन्द्विता का पूर्ण रूप से तोप कर देने के कारण जर्मनी का अन्तर्राष्ट्रीय वैध व्यक्तित्व पूर्णतया समाप्त हो गया और तथ्यतः उसके क्षेत्रों पर उन शक्तियों का प्रभुत्व हो गया जिन्होंने उसे जीता था।

किन्तु यह निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मित्र-राष्ट्रों ने यह स्पष्टतया घोषित कर दिया था कि वे किसी प्रकार से जर्मनी को अपने अधीन नहीं करना चाहते। ठीक इसके विपरीत उन्होंने घोषित किया था कि वे जर्मनी के राजनीतिक जीवन को फिर से प्रजातन्त्र के आधार पर निमित्त करना चाहते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में भी जर्मनी द्वारा शान्ति-स्थापन करना चाहते हैं। मनु, मित्र-राष्ट्रों ने जर्मनी पर जो प्रभुत्व स्थापित किया उसका तारकालिक परिणाम केवल इतना हुआ कि उस समय की सरकार उलट दी गई, किन्तु कहीं इस बात की घोषणा नहीं की गई कि जर्मनी इन शक्तियों द्वारा अधीन कर लिया गया।

स्टार्क (Starke) का भी कहना है कि मित्र-राष्ट्रों द्वारा नियन्त्रण की प्रणाली स्पष्टतः एक अस्थायी व्यवस्थाभूलक नियन्त्रण (of a provisional character) था, इसके अन्तर्गत किसी प्रकार के अधीनस्थ करने का प्रश्न नहीं था, पूर्ण रूप से वह ढाँचे में सैनिकों था और उसका आधार जर्मन राज्य पर ही था और प्राविधिक युद्ध की स्थिति की निरन्तरता का परिणाम था।

सन् १९४६ में ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने [R. v. Bottrill, Ex Parte Kuechenmester (1946, 1 All E. R. 635) के मामले में] घोषित किया था कि जर्मनी पूर्व ढंग से अब भी एक राज्य है और उससे युद्ध का सभी अन्त नहीं हुआ है। चार विजेता शक्तियों ने जर्मनी को दखल रूप से चार क्षेत्रों (Four Zones) में बाँट दिया है और उनके कमाण्डर-इन-चीफ के हाथ में उन क्षेत्रों का नियन्त्रण और प्रशासन दे दिया गया है और एक नियन्त्रण परिषद् बना दी गई है जिसमें चारों शक्तियों के कमाण्डर-इन-चीफ हैं और जो उन प्रसंगों का प्रशासन और नियन्त्रण करते हैं जिनका सम्बन्ध जर्मनी से सम्बन्ध है।

१९४८ में बर्लिन में सोवियत 'वाक्-भाउट' के कारण 'मित्र-राष्ट्रो के कन्ट्रोल कमीशन' ने काम करना बन्द कर दिया और पश्चिमी शक्तियों ने एक एकीकृत 'West German State' (पश्चिमी जर्मन राज्य) की स्थापना का कार्य आरम्भ किया। इस प्रकार जर्मनी की 'फेडरल रिपब्लिक' की औपचारिक घोषणा २३ मई १९४९ को कर दी गई और बॉन (Bonn) को पश्चिमी जर्मनी राज्य की राजधानी घोषित किया गया।

पूर्वी क्षेत्र में साम्यवादियों के नेतृत्व में 'जर्मन पीपुल्स कौंसिल' अर्थात् जर्मन जन-परिषद् ने ७ अक्टूबर १९४९ को अपने घोषणा "दो पीपुल्स एसेम्बली आफ दी जर्मन डीमाक्रैटिक रिपब्लिक" अर्थात् जनतन्त्रारम्भक जर्मन गणतन्त्र की जनता की सभा घोषित किया और जर्मन ऐवय के पुनः संस्थापन की अभीस की और पूर्ण जर्मन प्रभुसत्ता को बल दिया गया तथा दखल करने वाली सेनाओं से वापस खी जाने का आग्रह किया गया।

मस्तु स्पष्ट है कि मित्र-राष्ट्रो द्वारा जर्मनी के क्षेत्रों को दखल में करना कभी भी वैध अधीनता के रूप में परिणत नहीं हुआ। यह एक प्रकार का नया प्रयोग था जिसमें युद्ध-स्थित दखल और अधीनत्व, दोनों धर्म्यो की समान प्रबलता थी। समूचे युद्धों के इतिहास में यह एक अद्भुत और अपन ढंग का अकेला प्रयोग था।

फारमूसा (टैवान) की वैध स्थिति [Legal Status of Formosa (Taiwan)] :—फारमूसा और पेस्केडोर्स, जो कि पहले चीनी क्षेत्र के अंग थे, १८ अप्रैल, १८९५ की शिमोनोस्की संधि द्वारा जापान को मिल गये। कैरो कांफ्रेंस में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, युनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री चर्चिल और चीन के राष्ट्रपति च्यांग काई शेक ने दिसंबर १, १९४३ को उद्घोषित किया कि वह समस्त क्षेत्र, जिसे कि चीन से जापान ने ले लिया था, जैसे कि मन्चूरिया, फारमूसा और पेस्केडोर्स, चीन के गणतन्त्र का वापस कर दिया जायेगा। बर्लिन (पोट्सडम) के कांफ्रेंस में संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति, चीनी गणतन्त्र की राष्ट्रीय सरकार के राष्ट्रपति और ग्रेट-ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने २६ जुलाई १९४५ को पुनः इस बात का निश्चय किया कि कैरो उद्घोषणा की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा और जापान के साथ सन्धि स्थापित करने के लिए अन्य शर्तों में यह एक निश्चित शर्त है।

सितम्बर २, १९४५ को जापान ने बिना किसी शर्त के सहायक शक्तियों के सामने समर्पण कर दिया और संयुक्त राज्य, चीन और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानों द्वारा प्रस्तावित उद्युक्त शर्तों को जुलाई २६, १९४५ को पोट्सडम में स्वीकार कर लिया और बाद में 'सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स' के यूनियन द्वारा भी इस शर्त पर

स्वीकृति दे दी गई। च्यांग काई शेक ने इस द्वीप का प्रशासन प्रक्टूबर १९४२ में अपने हाथों में लिया। ८ सितम्बर १९५१, की सैन फ्रान्सिस्को की शान्ति-सन्धि में जापान ने कारिया, फारमूसा और पेस्केडोर्स के सभी अधिकारों और स्वत्वों को छोड़ दिया।

उपयुक्त तथ्यों के आधार पर फारमूसा (तैवान) की वैध दिवसि और उसके महत्व का निर्धारण करना है।

कैरो और पोर्ट्सडम उद्घोषणामों के समय फारमूसा पर दावा करने वाली एक पार्टी थी, और वह थी चीनी गणतन्त्र की राज्यवादी सरकार। विवाद न उस समय अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का रूप धारण कर लिया जब कि चीन को राष्ट्राधीन सरकार ताइपे (तैवान की राजधानी) की ओर दिसम्बर १९४९ में बढ़ते सैन्य और पैकिंग सरकार फारमूसा को अपने द्वारा शासित क्षेत्र में निगमित न कर सकी।

वर्ष १९४३ की कैरो-उद्घोषणा में निस्संदेह एक सामान्य प्रयोजन का वक्तव्य था। फिर भी, वह जुलाई १९४५ की पोर्ट्सडम उद्घोषणा में परिपुष्ट किया गया और अन्तिम रूप में जापान से शान्ति-स्थापना की शर्तों में से एक शर्त के रूप में माना गया। ब्रिटिश की यह धारणा कि कैरो-उद्घोषणा केवल सामान्य प्रयोजन का एक वक्तव्य है और पक्षकारों पर बाध्यतापूर्ण नहीं है, प्रवर्तनीय धारणा नहीं प्रतीत होती।

यह अवलोकन किया गया है कि फारमूसा में मित्र शक्तियों के सुग्रीव कमांडर के निदेश पर एक अन्तरिम प्रशासनिक नियंत्रण की प्रवृत्ति में इस द्वीप पर चीन के पूर्ववर्ती प्रभुत्व को स्थिर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आसन के संप्रभुता को चीन के हाथों में हस्तान्तरित करने की बाध्यता भी नहीं है। ब्रिटिश वैदितिक सचिव, सर एन्थोनी ईडेन ने फरवरी १९५५ में कहा था कि इन प्रश्नों में संप्रभुता के परिवर्तन होने का प्रश्न नहीं उठता। पुनश्च, अप्रैल १९५२ की शान्ति-संधि के अन्तर्गत जापान ने औपचारिक ढंग पर सभी अधिकारों, स्वत्वों और दावों को फारमूसा और पेस्केडोर्स के द्विपों में छोड़ दिया, किन्तु इसमें फिर भी कैरो संप्रभुता को हस्तान्तरित करने का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता। यह निर्वर्ण चीन के जनवादी गणतन्त्र या चीनी राष्ट्राधीन प्राधिकारियों दोनों के प्रश्नों में समाप्त हो से लागू होगा। इसलिए फारमूसा और पेस्केडोर्स ब्रिटिश-सरकार की बाध्यता के अनुसार ऐश क्षेत्र हैं जिन पर विधितः संप्रभुता (de jure sovereignty) अस्तित्व में और अनिवार्य है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि कब्जा (Occupation), भोगाधिकार (Prescription), क्षेत्र-वृद्धि (Accretion), परित्याग (Cession) और विजय (Conquest) को क्षेत्र अर्जित करने (Acquiring territory) के पाँच साधन मानती है। चीन द्वारा जापान से युद्ध की उद्घोषणा के समय, जो कि दिसम्बर ८, १९४१ को की गई थी, चीन ने औपचारिक ढंग से शिमोनोस्की की संधि को तोड़ा था। इस संधि के द्वारा फारमूसा का क्षेत्र जापान को मिला था। संधि का इस प्रकार तोड़ा जाना एक एक-पक्षीय कार्य था और अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुसार यह वांछित नहीं था। जहाँ तक कि विजय और अधिग्रहण के माध्यम पर पेरिंग द्वारा इस क्षेत्र पर दावा किये जाने का प्रश्न है, स्थिति यह है कि जापान ने सहायक शक्तियों को आत्मापित कर दिया था, किन्तु उसने एकमात्र चीन को आत्मार्पण नहीं किया था। इसलिए केवल एक शक्ति के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने फारमूसा द्वीप को विजित कर लिया और यह कि चीन को इस माध्यम पर फारमूसा वापस मिलना चाहिये।

राष्ट्रवादी चीन का तर्क है कि जब जापान ने आत्मार्पण कर दिया, तो चीन की गणतन्त्र सरकार के अन्तर्गत: पुनः तैवान और पेंगू आ गया और इसलिए इन क्षेत्रों को चीन को वापस किया जाना चाहिये।

अप्रैल २८, १९५२ को चीनी गणतन्त्र और जापान के बीच हस्ताक्षरित शान्ति-संधि में विशिष्टतः कहा गया था कि सभी संधियाँ, अभिसमम और करार, जो कि दिसम्बर ८, १९४१ के पूर्व किये गये थे, चीन और जापान के युद्ध के कारण अब शून्यकृत एवं प्रभावहीन हो चुके हैं। संधि के इस महत्वपूर्ण खंड का परिणाम यह है कि १९४१ में चीन द्वारा एकपक्षीय रूप से शिमोनोस्की की संधि का तोड़ा जाना जापान की सहमति प्राप्त कर गया और इसीलिए चीन का आरम्भिक कार्य दोनों पक्षकारों की ओर से अप्रैल २८, १९५२ की शान्ति-संधि की ओर उत्तरवर्ती घोषणा के माध्यम पर वैधकृत हो गया।

यह सत्य है कि जापान ने एकमात्र चीन के हाथों आत्मार्पण नहीं किया, अपितु सहायक शक्तियों की पूर्ण इकाई को उसने समर्पण किया था, किन्तु उसी समय चीन-गणतन्त्र और जापान के बीच विशिष्ट रूप से १९५२ में हस्ताक्षरित शान्ति-संधि हुई और उसने १८९५ की शिमोनोस्की की उस संधि को प्रभावशून्य घोषित कर दिया जिसके माध्यम पर फारमूसा जापान को मिला था। इसके आगे भी, उत्प्रेक्षणीय है कि परावर्तन (पोस्टसीमिनियम) के सिद्धान्त (doctrine of Postliminium) ने अन्तर्गत उपबधित है कि यदि कोई ऐसा राज्य जो कि अस्थायी

रूप में किसी अन्य राज्य के अधीनस्थ है, विजय की पूर्णता होने के पहले ही अपनी स्वतंत्रता फिर से प्राप्त कर लेता है, भले ही यह पुनर्प्राप्ति युद्ध के बीच में हो, या उसकी समाप्ति पर, तो अधीनता या अग्रघर्षक कब्जे के पूर्व की वैध स्थिति पुनः स्थापित हो जाती है। यह सिद्धांत पूर्ण तौर पर फारमूसा की असफलता के सम्बन्ध में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि १८६५ की शिमोनोस्की की संधि को, कियो भी प्रकार अस्थायी या अपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

फारमूसा निश्चय रूप से तथ्यतः राष्ट्रवादी चीन का भग है। मार्शल व्याग-काई-शेक उस क्षेत्र पर सप्रभुता का प्रयोग करते रहे हैं, और भले ही फारमूसा की स्थिति उस तिथि के उपरान्त जब से कि चीन ने शिमोनोस्की की संधि को भंग किया, बिल्कुल ही बदली हुई न मानी जाय, फिर भी इसने निश्चित रूप से उस समय से एक वैध रूप धारण कर लिया जब से कि वहाँ राष्ट्रवादी सरकार ने प्रशासन करना आरम्भ किया, क्योंकि १९४५ में इसी सरकार को फारमूसा को एक सैनिक-कब्जे के रूप में सौंपा गया था और जिसकी स्थिति को गणतन्त्र चीन और जापान के बीच हुई शान्ति-संधि ने जो कि अप्रैल २८, १९५२ को हस्ताक्षरित हुई, वैधकृत कर दिया।

डॉ० स्वाजेनबर्जर इस विचार के हैं कि सैन फ्रैन्सिस्को सन्धि ■ सह-हस्ता-क्षरकर्ता, जापान की अपेक्षा अन्य सभी विधि द्वारा व्याग-काई शेक के साथ फारमूसा और पेस्कैडोर्स के मामले में एक प्रकार के सहराज्य (Condominium) का प्रयोग कर रहे हैं, और उनके अभिकर्ता के रूप में तथ्यतः कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार मार्शल व्याग फारमूसा में एक प्रत्यायोजित प्राधिकार (delegated authority) का प्रयोग कर रहे हैं। ये राज्य संयुक्त राष्ट्र के 'बाहर फारमूसा और पेस्कैडोर्स के भविष्य के बारे में सामूहिक रूप में निश्चय करने के लिए स्वतंत्र हैं, या संयुक्त राष्ट्र संधि के परामर्श पर निश्चय कर सकते हैं। यह विचार ब्रिटिश विचार के अनुरूप है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका तथ्यतः कब्जाकार, अर्थात् फारमूसा पर व्याग काई शेक की सरकार को संयुक्त अधिकारों की मान्यता देने के लिए अधिक आक्रुष्ट मालूम पड़ता है। ब्रिटिश और अमेरिकी विचार में भेद यह है कि ब्रिटिश चीन के जनवादी गणतन्त्र को मान्यता प्रदान करता है, जब कि अमेरिका चीन की राष्ट्रवादी सरकार को मान्यता प्रदान करता है, क्योंकि वही सरकार उस द्वीप पर प्रशासनिक नियन्त्रण व्यवहृत करती है।

संयुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर के अनुच्छेद १०३ में उपबोधित है कि वर्तमान चार्टर के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संधि के सदस्यों के आभास और कितनी अन्य अन्तराष्ट्रीय करार के आभासों के बीच के संबंधों में चार्टर के आभास ही प्रवर्तित होते।

यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि १९४३ में ग्रेट ब्रिटेन और समुक्त राज्य की कैंरो उद्घोषणा के आधार समुक्त राष्ट्र सच क वर्तमान चार्टर से उत्पन्न आमारों के पीछे धुंधले पड़ गये ।

अब स्थिति यह है कि राष्ट्रवादी चीन के फारमूसा विषयक अधिकार और नियन्त्रण निरिवत और निर्धारित हो चुके हैं, और तैवान की तथ्यतः संप्रभुता चीन की राष्ट्रवादी सरकार की विधितः संप्रभुता बन चुकी है ।

वास्तविकता यह है कि फारमूसा की वैध स्थिति ने महत्व का स्थान तब लिया, जब कि चीन के जनवादी गणतन्त्र की स्थापना हुई । किन्तु, यह सयोग एक स्थापित तथ्य को विचलित नहीं कर सकता, और कहा जा सकता है कि यदि अब इन दोनों के बीच कोई सघर्ष उत्पन्न होता है तो उस सघर्ष को चीन के जनवादी गणतन्त्र ( Peoples Republic of China ) और चीन की राष्ट्रवादी सरकार ( Nationalist Government of China ) के बीच का भान्तरिक मामला कहा जायेगा । विद्वानों का निष्कर्ष है कि इस स्थिति में इस प्रसंग में समुक्त राष्ट्र सच अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्याय-न्यायालय ( International Court of Justice ) का हस्तक्षेप मामले को सुलझाने के बदले और भी उसझाने का कारण बन सकता है ।

चन्द्र और ग्रहों पर मानव-विजय ( Man's Conquest of Moon and Mars ).—ओपेनहेम के अनुसार दखल किसी राज्य द्वारा विनियोग का एक कार्य है और उसके द्वारा वह राज्य स्वेच्छया धारण किये गये राज्य-क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता स्थापित करता है और उसके लिए वह अनुमान करता है कि विनियोग के समय वह क्षेत्र किसी दूसरे राज्य के स्वत्व में नहीं था । इसलिए यह एक ऐसे क्षेत्र पर संप्रभुता स्थापित करने से सम्बन्धित है, जो कि या तो पहले से किसी के अधिकार में नहीं था या हाल में उसकी नयी खोज की गई है । यह ऐसा क्षेत्र प्राप्त करने का एक साधन है जो पहले से किसी राज्य के अधीन न हो । दखल को स्थिर करने के लिए सम्बन्धित राज्य में सकल्प ( intention ) या इच्छा ( will ) का विद्यमान होना आवश्यक है जिससे उस राज्य-क्षेत्र पर वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके और वह किसी न किसी प्रश्न का नियन्त्रण उस भूमि पर स्थापित कर सके ।

ओपेनहेम ने दखल ( possession ) और प्रशासन ( administration ) को दो आवश्यक तथ्य माना है जो कि प्रभावकारी दखल का कारण बनते हैं । इसमें दो बातों का होना आवश्यक है—एक तो कोई राज्य-क्षेत्र किसी राज्य के अधिकार में आवे और उसके उपरान्त उस राज्य की इच्छा उस क्षेत्र को अपने अधिकार में रखने की हो । प्रशासन का अभिप्राय यह है कि धारणकर्ता उस क्षेत्र पर किसी न

किसी प्रकार का प्रशासन चालू करे जिससे यह प्रकट हो कि नये राज्य-क्षेत्र पर उस राज्य की संप्रभुता है।

उपरोक्त बातों को देखते हुये कहा जा सकता है कि चन्द्रमा या चन्द्रलोक पर यदि किसी राज्य का राकेट उतर जाता है तो किसी राज्य का क्षेत्रीय दावा वहाँ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि चन्द्रलोक में कोई राज्य यदि अपना झंडा भी गाड़ देते हैं तो केवल झंडा गाड़ देने से वह राज्य उस लोक पर अपनी संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता। वास्तव में संप्रभुता को नाम-मात्र की होने के स्थान पर वास्तविक होना चाहिए और न तो यह ऐरे-नैरे किसी द्वारा दावा करने का विषय ही है। दावेदार को अवश्य ही ऐसे रूप में व्यवहार करना चाहिए जो कि अन्तर्राष्ट्रीय संप्रभु व्यक्ति के लिए वैध हो जिससे वह अपनी संप्रभुता का प्रयोग कहीं कर सके। यदि मनुष्य चन्द्रलोक तथा ग्रहों को जीत भी लेता है, तो इससे कोई नया विलक्षण स्वत्व नहीं प्राप्त हो जाता। केवल किसी भूमि को खोज कर लेना या चन्द्रमा को जीत लेना ही इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है, कि वहाँ उसका दखल हो गया। इस खोज या विजय से उसे एक अपूर्ण ढंग का स्वत्व प्राप्त हो सकता है जो कि प्रभावकारी नियंत्रण और प्रशासन की पूर्णता से रहित होगा। उसके स्वत्व को दखल के एक कार्य की व्यवस्था मानेंगे। यह स्वत्व दखल के वास्तविक स्वत्व (real title of occupation) के रूप में कदापि परिवर्तित नहीं हो सकता। पूर्ण दखल के स्वत्व के लिए इसमें उचित रूप से पर्याप्त समय की अपेक्षा होगी और इसपर निकट भविष्य में चन्द्रलोक के विजय के उपरान्त भी दखल सम्बन्धी कोई अन्तर्राष्ट्रीय विधि की समस्या उत्पन्न होती हुई नहीं प्रतीत होती।

२—भोगाधिकार (Prescription) :—अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार भोगाधिकार का यह अर्थ है कि क्षेत्र कुछ अवधि तक लगातार प्रतिवृत्त दावा (adverse possession) के प्रयोग से प्राप्त कर लिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार यह अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित अवधि नियत नहीं है। परन्तु यह आवश्यक है कि कब्जा बिना विरोध के शान्तिपूर्वक होना चाहिए और दीर्घकालीन अवधि तक निरन्तर रहना चाहिए। भोगाधिकार के लिए विनयी दावा व्यतीत होनी चाहिए इस पर बहुत मतभेद है।

यद्यपि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत है कि बच्चे की अवधि के समय में कोई सामान्य नियम नहीं है किन्तु वाशिंगटन की सन्धि (१८७१) का यहाँ निर्णय दिया जा सकता है जिसके द्वारा भोगाधिकार के लिए ५० वर्ष की प्रतिवृत्त दावा की अवधि निर्धारित की गई थी, तथा ग्रेट ब्रिटेन और वेनेजुएला के मध्य की सन्धि

सन्धि (१८६७) को भी निर्देशित किया जा सकता है जिसके द्वारा भी इस अधिकार के लिए ५० वर्ष का प्रतिफल कब्जा पर्याप्त माना गया था ।

ग्रोशस (Grotius) का विचार है कि, 'a possession beyond memory, not interrupted, nor disturbed by appealing to an arbitrator, absolutely transfers dominion.' अर्थात् कोई भी दखल जब स्मरणातीत समय से चल रहा हो, उसमें न तो किसी प्रकार की रुकावट डाली गई हो और न तो किसी पक्षकार ने किसी विवाचक के समक्ष उस दखल की न्यायिकता को चुनौती दी हो, तो क्षेत्र पूर्णरूप से दखलकर्ता का हो जाता है । लेकिन वटेल (Vattel) विवाद कब्जा पर बल देते हैं । उनका कहना है कि वास्तविक स्वामी जब अपने स्वत्व से एक लंबी अवधि तक उदासीन हो जावे या उसके सम्बन्ध में सम्झे समय तक मौन रहे, तो उसका स्वत्व वास्तविक दखलकर्ता के साथ चला जाता है ।

स्वार्जेंनबर्जर (Schwarzenberger) के अनुसार इस सम्बन्ध में चार सूत्र दिये गये हैं :—

(१) जो राज्य स्वत्व का दावा भोगाधिकार के आधार पर करता हो, उस क्षेत्र पर वास्तविक प्रभुत्व प्राप्त कर चुका हो ।

(२) प्रभुत्व उचित समय तक लगातार बना रहे ।

(३) प्रभुत्व शान्तिपूर्वक हो और विशेष रूप से अन्य राष्ट्रों से शान्ति का सम्पर्क बना रहे ।

(४) प्रभुत्व सार्वजनिक होना चाहिए ।

यदि ये चारों शर्तें पूरी होती हैं तो भोगाधिकार वास्तव में एक स्वत्व है जिसका प्रभाव उतना ही प्रबल होता है, जितना कि राज्य-क्षेत्र प्राप्त करने के साधनों का हुमा करता है ।

३—क्षेत्र-वृद्धि ( Accretion ) :—यह नदियों के कार्य द्वारा अधिकार प्राप्त करने की विधि है जिससे नयी भूमि की उत्पत्ति से भूमि-वृद्धि हो जाती है । पानी का कार्य किसी राज्य की प्रभुसत्ता के अधीन तरकाल वर्तमान क्षेत्र में नई भूमि जोड़ देता है ।

४—परित्याग ( Cession ) :—यह एक राज्य द्वारा द्विर्गो व्यवहार के रूप में दूसरे राज्य को क्षेत्र का हस्तान्तरण है । क्षेत्र के हस्तान्तरण से क्षेत्र के किसी निश्चित भाग पर प्रभुसत्ता का हस्तान्तरण व्यवहृत होता है । परित्याग सन्धि द्वारा होता है जिसमें हस्तान्तरण की शर्तें निश्चित होती हैं । ऐसी सन्धि ऐच्छिक हो सकती है अर्थात् शान्तिपूर्वक समझौते का परिणाम (विक्रय, दान अथवा विनिमय) अथवा बाध्य विधे जाने पर की जा सकती है, अर्थात् युद्ध के परिणामस्वरूप तथा इसकी



व्यवस्था शान्ति-सन्धि द्वारा की जाती है, भयवा पालन न किये जाने की प्रवस्था में भयकर परिणामों की धमकी के अधीन हो सकती है। परित्याग, क्षतिपूर्ति भयवा बिना क्षतिपूर्ति की शर्त पर लिया जा सकता है।

**जनमत संग्रह (Plebiscite)** — इस प्रकार की शान्तिपूर्ण संधि परित्याग की दशा में उस राज्य के निवासियों के जनमत द्वारा भी हो सकती है। मोपेनहेय का कथन है कि इस बात में संदेह है कि सदैव राष्ट्रों की विधि क्षेत्र परित्याग को जनमत संग्रह से पुष्ट कराने की बात मानेंगी।

**काश्मीर समस्या** — १९४७ के स्वतंत्रता अधिनियम से भारत स्वतंत्र होने पर जम्मू काश्मीर अपनी वैध स्थिति चुनने के लिए स्वतंत्र हो गया। सितम्बर १९४७ से काश्मीर सीमा के उत्तरी पश्चिमी सीमा से कबीले या जनजाति (tribal people) काश्मीर क्षेत्र में घावा बोलते हुए छूटमार मचाने लगे। इसके लिए उन्हें पाकिस्तान सरकार से प्रोत्साहन और सहायता मिलती रही। काश्मीर क महाराजा ने भारत से जन जाति के आक्रमणों से काश्मीर की सुरक्षा के लिए सैनिक सहायता मांगी। काश्मीर राज्य के भारत राज्य में अधिमिलन (accession) के बिना भारत सरकार का काश्मीर क आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप करना उसके क्षेत्राधिकार के बाहर था। अतः २७ अक्टूबर १९४७ को भारत सरकार ने काश्मीर महाराजा के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए काश्मीर राज्य का भारत में अधिमिलन ग्रहण किया जिससे काश्मीर भारत राज्य का अखंड भाग हो गया किन्तु भारत सरकार ने राजनैतिक के साथ ही वैध कारणों से यह चाहा कि भारत में काश्मीर का अधिमिलन जनमत द्वारा हो। सितम्बर १९४७ में भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद् में यह प्रश्न रखवा कि जन जातियों को काश्मीर में आक्रमण करने में पाकिस्तान द्वारा सहायता दिये जाने से पाकिस्तान सरकार को रोका जाय। सुरक्षा परिषद् ने काश्मीर समस्या को बहुत प्रकार के प्रस्तावों द्वारा सुलझाने का प्रयास किया किन्तु पाकिस्तान ने जबर्दस्ती उलझन उत्पन्न करके काश्मीर समस्या को विवादपूर्ण बना दिया।

भारत सरकार की प्रभुता जम्मू-काश्मीर के तीन विषय सुरक्षा, बातायात और विदेशी मामलों में सर्वोच्च है। भारतीय संविधान के अनुसार भी काश्मीर भारत राज्य क्षेत्र का भाग है। भारत सरकार का यह तर्क भी सही है कि जनजाति की सहायता देकर पाकिस्तान ने विदेशी होकर आक्रमणकारी का कार्य किया जो कि अनुचित था। फरवरी १९६४ में काश्मीर विधान सभा ने अन्तिम रूप से भारत में प्रवेश करने का निर्णय किया। भारत सरकार ने काश्मीर का भारत में अधिमिलन जनमत द्वारा चाहा था किन्तु पाकिस्तान द्वारा इसकी दत्तने दिनों तक उपेक्षा होने के

कारण यह अग्र्याय भी समाप्त हो जाता है। काश्मीर समस्या का महत्वपूर्ण वैध रूप यह है कि दोनों राज्यों (भारत सरकार और काश्मीर राज्य) के परस्पर समझौते के कारण काश्मीर का अधिमिलन भारत राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि का रूप ले लेता है। इसके समर्थन में अन्तर्राष्ट्रीय विधि भी स्पष्ट है कि विशेष स्थिति में ही समझौता करने वाले पक्ष इसे तोड़ सकते हैं। भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, १९४७, द्वारा देशी राज्य के नरेश इसके लिए बाध्य नहीं थे कि वे अधिमिलन हेतु निर्णय जनमत संग्रह द्वारा ही करें। उन्हें पूर्ण अधिकार था कि वे स्वेच्छा से अपने राज्य को भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित करते अथवा स्वयं स्वतन्त्र हो जाते। फिर पाकिस्तान ने स्वयं जूनागढ़ का अपने राज्य में अधिमिलन जनमत की उपेक्षा करते हुए किया था। इस प्रकार काश्मीर का भारत राज्य में अधिमिलन पूर्ण रूप से वैध है।

**काश्मीर-समस्या का अन्तर्राष्ट्रीय वैध रूप :—**जम्मू और काश्मीर भारतवर्ष के उत्तरी सीमा पर स्थित हैं। समुक्त सोवियत संघ, तिब्बत और तिब्बत उत्तर तथा उत्तर-पूर्व की ओर हैं और पश्चिमी तथा दक्षिण पश्चिम की ओर पाकिस्तान है। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पूर्व भारत की अन्य रियासतों की तरह काश्मीर भी ब्रिटिश सम्राट के सीधे शासन में था। १९४७ की स्वतन्त्रता अधिनियम के पारित होने के पश्चात् जिसके आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सत्ता का हस्तान्तरण भारतीय हाथों में किया था, उस समय से ब्रिटिश सम्राट का प्रभुत्व भारतीय रियासतों से समाप्त हो गया था। भारतीय रियासतें इस बात के लिये स्वतन्त्र थी कि वे भारतीय डोमिनियन अथवा पाकिस्तान डोमिनियन में सम्मिलित हो। काश्मीर का शासक इस बात के लिये स्वतन्त्र था कि वह अपने भावी संवैधानिक स्थिति का चुनाव कर सके।

पाकिस्तान और भारतवर्ष के विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान और काश्मीर राज्यों में आर्थिक, प्रशासकीय, यातायात, सप्लाई आदि के लिये संबंध निरंतर चलते रहने के समझौते हुए। उस समय काश्मीर की सरकार ने यह शिकायत की कि पाकिस्तान के अधिकारी आवश्यक सामग्रियों, जैसे खाद्य पदार्थ, नमक, चीनी और पेट्रोल की सप्लाई से इनकार कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार के आचरण ने यह भासित कर दिया कि काश्मीर पर इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि वह पाकिस्तान में मिल जाय।

बहुत ही हड़ आर्थिक दबाव जो कि पाकिस्तान की ओर से आरंभ हुआ था आगे चलकर पूर्ण अवरोध की स्थिति तक पहुँच गया। सितम्बर १९४७ में कबालियों ने उत्तर-पश्चिम सीमाप्रांत पर कुछ उद्भव करने आरंभ कर दिये। उन्होंने पश्चिमी पंजाब के मुसलमानों के साथ काश्मीर की सीमा के गाँवों को छूटना-खसोटना

और कत्ल करना प्रारम्भ कर दिया । काश्मीर की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के विरुद्ध इस बात का कड़ा विरोध किया कि आक्रामक उनकी राज्यसीमा से होकर काश्मीर तक आने से रोके जाय, किन्तु इससे कोई लाभ न हुआ । आक्रामक बहुत ही संगठित रूप में आ रहे थे और उन्होंने थोड़े ही समय में काश्मीर राज्य क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने अधिकार में कर लिया । उनका यह अधिकार पूँछ क्षेत्र तक था । उन्होंने श्रीनगर को अपने अधिकार में कर लेने की धमकी दी । कबालियों के इस सामूहिक आक्रमण ने जिसे पाकिस्तान द्वारा भी सहायता दी जा रही थी, काश्मीर की सरकार को बहुत ही कठिन परिस्थितियों में डाल दिया । उन लोगों ने ऐसा अनुभव किया कि बिना किसी बाहरी सहायता के वे कबालियों से अपने राज्य की स्वतन्त्रता नहीं बचा सकते । तदनुसार काश्मीर के महाराजा ने भारत सरकार को सैनिक सहायता देने की सन्तुति की । भारतवर्ष को इस बात का क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त था कि वह बिना काश्मीर राज्य के भारतीय सघ में अधिमिलन हुये, उसके भीतरी मामलों में हस्तक्षेप कर सके । इस कठिनाई को हल करने के लिये २६ अक्टूबर १९४७ को काश्मीर के महाराज ने अपने राज्य को भारत में मिला लिये जाने का अनुरोध किया । भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि किसी रियासत का राज्य में मिला लाने के पूर्व वहाँ का जनता से इस प्रारम्भ का जनमत प्राप्त किया जाय । वहाँ के शासकों की इच्छा ही राज्य की इच्छा के रूप में मानी जाती थी । अस्तु भारतवर्ष को काश्मीर के महाराजा के अनुरोध पर काश्मीर को अन्तिम रूप से भारतवर्ष में मिला लेने में कोई आपत्ति न थी । २७ अक्टूबर १९४७ को भारतवर्ष ने काश्मीर का अधिमिलन स्वीकार कर लिया और उसके पश्चात् काश्मीर भारत का अन्तर्गत अंग बन गया ।

कुछ राजनीतिक अथवा सविधानिक कारणों से भारतवर्ष इस बात का समर्थक था कि राज्य में साधारण स्थिति उत्पन्न हो जाने के पश्चात् काश्मीर की जनता से भी अधिमिलन के सम्बन्ध में राय ले ली जाय । भारत के प्रधान मंत्री का कहना था कि भारतवर्ष सकट की घड़ी में जल्दी से कोई निश्चय नहीं कर सकता और काश्मीर की जनता की अपनी इच्छा प्रकट कर देने का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये । यहाँ पर उल्लेख कर देना अप्रासंगिक न होगा कि भारत के प्रधान मंत्री की यह घोषणा काश्मीर के अधिमिलन के पश्चात् हुई थी । जनमत संग्रह का कोई प्रतिबंध काश्मीर के अधिमिलन पर न था ।

३० दिसम्बर १९४७ को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद ३५ के अनुसार इस विवाद को सुरक्षा परिषद के समक्ष उपस्थित किया और सुरक्षा परिषद से इस बात का आग्रह किया कि पाकिस्तान सरकार कबालियों को

सैनिक अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता जम्मू काश्मीर पर आक्रमण करने के लिये न दे और आक्रमणकारियों को अपने राज्यक्षेत्र की सीमा से होकर आने की अनुमति न दे । पाकिस्तान ने भारत के इस आरोप का खंडन किया और कोई सतोषजनक उत्तर देने की अपेक्षा उल्टे भारत सरकार पर ही आक्रमण करने का आरोप लगाया ।

अप्रैल १९४८ में सुरक्षा परिषद ने एक आयोग इस हेतु नियुक्त किया कि वह कबालियों और पाकिस्तानी राष्ट्रीय जनो, जो कि काश्मीर राज्य में घुस आये थे, को हटाकर राज्य में शांति स्थापित करे । इस आयोग ने दोनों सरकारों से कई बार विचार-विमर्श किया, और अगस्त १३, १९४८, को एक प्रस्ताव फायरबन्दी तथा विराम-संधि का पारित किया, जो कि जनवरी १, १९४९, को दोनों सरकारों की ओर से प्रवर्तित किया गया । युद्ध-विराम के परिणामस्वरूप आयोग ने एक दूसरा प्रस्ताव जनवरी ५, १९४९, को किया जिसमें भारत पाकिस्तान की सरकार की स्वीकृतियों का विवरण दिया गया और उन भिन्न भिन्न सिद्धांतों का भी विवरण दिया गया जो कि सहायक रूप में थे । इस प्रस्ताव में जनतांत्रिक ढंग पर एक निष्पक्ष जनमत गणना की बात कही गयी । जनवरी ५ १९४९ के प्रस्ताव के क्रम में संयुक्त राज्य के नेवी के ऐड-मिरल चेस्टर निमिट्ज (Chester Nimitz) को संयुक्त राष्ट्र सच के महासचिव ने भारत, पाकिस्तान और काश्मीर की सहमति पर जनमत गणना का प्रशासक नियुक्त किया । मतभेद आरम्भ हो गये क्योंकि पाकिस्तान ने यह माँग की कि तथाकथित आजाद काश्मीर की पाकिस्तानी सेना में वहाँ की सेना को सम्मिलित कर लिया जाय । यह प्रस्ताव अगस्त १३, १९४८ के मान्य प्रस्ताव का बिलकुल उल्लंघन करता था ।

संयुक्त राष्ट्र सच आयोग ने इस विवाद के पूरे प्रसंग को दिसम्बर १९४९ में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष फिर स इस सन्तुति के साथ भेजा कि इस बीच में इस प्रसंग में एक विवाचक नियुक्त किया जाय । भूतैनीकीकरण का प्रश्न इस विवाद के सुलझाव में बाधक बनकर खड़ा रहा और सुरक्षा परिषद ने सर ओवेन डिक्सन (Sir Owen Dixon) एक विधिज्ञ और आस्ट्रेलिया के हाईकोर्ट के जज को मध्यस्थ नियुक्त कर दिया । उन्हें सफलता न मिल सकी क्योंकि दोनों सरकारों में आपस में भूतैनीकीकरण की ठेगारी की प्रक्रिया के प्रसंग में मतभेद था और निष्पक्ष जनमत गणना का प्रशासन कठिन था । कबालियों के निरन्तर काश्मीर में प्रवेश करते रहने और वहाँ पाकिस्तानी सेना के बने रहने के कारण सर ओवेन डिक्सन (Sir Owen Dixon) ने कहा था कि काश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तान सेना का बार बार घाते रहना अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुकूल नहीं है और यह कि पाकिस्तान काश्मीर में आक्रमण

१७० ]

उन्होंने अन्तिम रूप से यह सन्तुति की कि दोनों पक्षों पर अपने आप बातचीत से झीलों द्वारा समस्या को सुलझाने का काम छोड़ दिया जाय ।

३० अप्रैल, १९५१ को सुरक्षा परिषद् ने नार्थ कैरोलिना के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉ० फ्रैंक ग्राहम ( Dr. Frank Graham ) को काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधि नियुक्त किया । उन्हें यह निर्देश था कि वे अधिक से अधिक प्रयत्न कर बात का करे कि भारत व पाकिस्तान इस योजना को स्वीकार कर लें कि जम्मू और काश्मीर राज्य का असेनिकीकरण कर लिया जाय और यूनीसप (U. N. C. I P) के प्रस्तावों के सिद्धान्तों के अनुरूप यह कार्य हो । डॉ० ग्राहम भी अपने कार्य में असफल रहे यद्यपि उन्होंने सुरक्षा परिषद् को ३ रिपोर्टें दिये और सारी समस्या का केवल असेनिकीकरण के समझौते से सम्बन्धित आरम्भिक तैयारी तक संकुचित कर दिया, जैसे युद्धविगम रेखा के दोनों ओर असेनिकीकरण के पश्चात् किस ढंग की और कितने मात्रा में सेना रखी जाय । २५ अगस्त १९६२ को डॉ० ग्राहम द्वारा जेनेवा में एक मन्त्रिमण्डलीय स्तर का सम्मेलन बुलाया गया किन्तु भारत और पाकिस्तान ने सरकारें जम्मू और काश्मीर में अपने अस्तित्व के सम्बन्ध में एकमत नहीं हो सकीं ।

पाकिस्तान की सरकार काश्मीर में भारत की समानता का स्तर चाहती है । काश्मीर चूँकि भारत का एक अङ्ग बन चुका है, भारत सरकार उस राज्य की सुरक्षा के लिये उत्तरदायी है । दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार काश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बलपूर्वक अपने अधिकार में किये हुये है । अतः काश्मीर में भारतीय सेना का उपस्थित होना एक अधिकार और कर्तव्य की बात है जबकि पाकिस्तानी सेना के आक्रमण किया है ।

डॉ० ग्राहम ने १० अक्तूबर १९५२ को सुरक्षा परिषद् के मध्य अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और भारत तथा पाकिस्तान के बीच काश्मीर के असेनिकीकरण के सम्बन्ध में समझौता कराने में, जिससे जनमत द्वारा यह तय हो जाय कि काश्मीर भारत के साथ रहना चाहता है अथवा पाकिस्तान के साथ, अपनी प्रसन्नता व्यक्त की ।

नवम्बर ६, १९५५, को एंग्लो अमेरिकी संयुक्त प्रस्ताव ब्रिटेन के सर ग्लैडविन जेब (Sir Gladwyn Jebb) द्वारा सुरक्षा परिषद् में रखा गया जिसे अनुसार यह प्रस्ताव किया गया कि दोनों सरकारें संयुक्त राष्ट्र सच के मुस्ताना में तत्काल समझौता बातचीत करें और असेनिकीकरण के अत तक युद्ध विराम रेखा व दोनों ओर कितनी सेना रखी जाय यह निर्धारित करें । यह भी संकेत था कि पाकिस्तानी सैन्य-शक्ति ३ हजार से ६ हजार तक और भारतीय सैन्य-शक्ति २२ हजार से १८ हजार तक अपने-अपने क्षेत्र में रहें ।

पाकिस्तान की सरकार की प्रार्थना पर सुरक्षा परिषद् ने इस प्रश्न पर जनवरी १९५७ में फिर विचार किया। २५ जनवरी को ५ शक्तियों का एक प्रस्ताव जिसमें संयुक्त राज्य, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कोलम्बिया और क्यूबा थे, प्रस्तावित किया कि काश्मीर में यथापूर्व स्थिति रखी जाय। उनका यह प्रस्ताव पाकिस्तान सरकार को इस शिकायत पर आधारित था कि भारत सरकार जनवरी २६, १९५७ को जम्मू और काश्मीर राज्य का एकीकरण करने जा रही है। भारतीय प्रतिनिधि ने स्पष्टतः बतला दिया कि यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के विरुद्ध है क्योंकि यह प्रस्ताव एक सुलझे हुये मामले को और भी उलझा देता है और यह कि बाभारो की पूर्ति का कोई दोषारोपण यदि किया जा सकता है तो पाकिस्तान पर, भारत पर नहीं।

**जारिन-रिपोर्ट (Jarring Report) :**—सुरक्षा परिषद् ने काश्मीर की समस्या पर फरवरी १९५७ में पुनः विचार किया। ब्रिटेन ने औपचारिक ढंग से चार शक्तियों का एक प्रस्ताव रखा जो कि ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, क्यूबा और संयुक्त राज्य की ओर से था। इसके अनुसार स्वीडन के श्री गुन्नार वी० जारिन (Mr. Gunnar V. Jarring) से जो कि उस महीने के लिये सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष थे, भारत व पाकिस्तान सरकार से काश्मीर के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने को कहा गया और काश्मीर में सैनिकीकरण की पूर्ति तक के लिये संयुक्त राष्ट्र की सेना रखने की बात कही गई। भारतीय प्रतिनिधि श्री बी० के० कृष्ण मेनन ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया कि भारत सरकार अपने क्षेत्र में किसी भी विदेशी सेना को किसी भी रूप में उतरने न देगी। कोलम्बिया ने चार शक्तियों के प्रस्ताव पर कुछ संशोधन प्रस्तुत किया। सोवियत सभ ने १८ फरवरी १९५७ को सुरक्षा परिषद् में यह घोषणा कर दी कि काश्मीर में जनमत-गणना का कोई प्रश्न नहीं रह गया है और यह कि रूस की सरकार यह समझती है कि काश्मीर का प्रश्न स्वयं उस राज्य की जनता द्वारा सुलझाया जा चुका है और काश्मीर का क्षेत्र भारत का एक अविभाज्य अंग है।

चार शक्तियों ने मौलिक रूप से जिन्होंने काश्मीर में श्री जारिन को भेजने का प्रस्ताव किया था और यह प्रस्ताव था कि वे भारत व पाकिस्तान के बीच काश्मीर के सैनिकीकरण के प्रश्न पर विचार-विमर्श करें और इस प्रश्न को देखें कि तात्कालिक रूप में काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र सभ की सेना रखी जाने की कहीं तक सम्भावना है उस प्रस्ताव पर रूस ने निषेधाधिकार का प्रयोग किया। धस्तु वह सफल न हो सका।

दूसरा प्रस्ताव उन्हीं चार शक्तियों द्वारा पहले के ही प्रस्ताव के आधार पर सुरक्षा परिषद् द्वारा फरवरी २१, १९५७, को स्वीकार कर लिया गया किन्तु उसमें संयुक्त राष्ट्र सभ की सेना को काश्मीर में रखने की चर्चा नहीं थी। श्री जारिन ने अप्रैल १५, १९५७, तक अपना प्रतिवेदन सुरक्षा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने से कहा गया। भारत व पाकिस्तान की सरकारों को श्री जारिन के कार्यों में सहयोग देने का निवेदन किया गया ऐसा ही निवेदन इन दोनों देशों के संयुक्त राष्ट्र सभ स्थित प्रतिनिधियों से किया गया।

श्री जारिन ने अपने प्रतिवेदन में यह लिखा कि वे एक बात स्पष्ट काश्मीर में देख चुके हैं जो कि अवश्य विचारणीय है। परिस्थितियाँ राजनैतिक, प्राथिक और सैनिक दृष्टि से बहुत तीव्रता से बदल रही हैं। भस्तु इस प्रश्न को अवश्य ही नवीन दृष्टिकोण से देखना होगा। उन्होंने यह भी लिखा कि, यद्यपि वे परिषद् के समक्ष समस्या का कोई ठोस सुलझाव प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, फिर भी उन्होंने परिस्थितियों का जो कुछ निरीक्षण किया है उससे प्रकट होगा कि वर्तमान अवरोध के उत्पन्न होने के उपरांत भी दोनों सुलझाव ढूँढने के उरसुक हैं।

जारिन के रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में जनमत गणना से नई कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी। जारिन रिपोर्ट के प्रतिवेदन पर सुरक्षा-परिषद् ने सितम्बर १९५७ में विचार किया। २ दिसम्बर १९५७ की सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित किया जिससे उन्होंने काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि से निवेदन किया कि आगे की उचित कार्यवाहियों की सिफारिश करें जिससे १३ अगस्त १९४८ और ५ जनवरी १९४९ के संयुक्त राष्ट्र आयोग के सुझावों के अनुसार समस्या का शांतिपूर्ण ढङ्ग से सुलझा हो सके।

डॉ० ग्राहम रिपोर्ट (Dr. Graham's Report)—२ दिसम्बर, १९५७, के सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव के क्रम में डॉ० फ्रैंक ग्राहम (Dr. Frank Graham) ने उपमहाद्वीप का निरीक्षण किया। उनका उद्देश्य काश्मीर के प्रश्न का शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाव प्राप्त करना और सुरक्षा परिषद् के पहले के प्रस्तावों को तत्पर करना था। उन्होंने दोनों सरकारों से ५ प्रस्ताव किये थे। वे सदन में निम्नलिखित हैं :—

१—दोनों सरकारों की ओर से एक नई घोषणा हो जिसमें अपनी-प्रती जनता से ऐसे वातावरण को बनाये रखने की अपील की जाय जिससे आगे की समझौता-वार्त्ता अनुकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ सके।

२—दोनों सरकारें युद्ध-विराम-रेखा की अनिवार्यता की पुनः प्रतिज्ञा कर ।

३—काश्मीर से पाकिस्तानी सेना हटाने के सम्बन्ध में अगस्त १३, १९४८, के प्रस्ताव की सभावनाओं पर विचार ।

४—संयुक्त राष्ट्र सभ का प्रतिनिधि दोनों सरकारों से उन साधनों और समय की अवधि पर विचार करेगा जिस पर अगस्त १३, १९४८, के प्रस्ताव के आधार पर जनमत संग्रह सम्भव हो सके ।

५—दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन डॉ० ग्राहम की सरक्षता में हो ।

इन प्रस्तावों को प्रधान मंत्री नेहरू ने पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया । यह डॉ० ग्राहम द्वारा काश्मीर के प्रश्न पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराने का दूसरा प्रयत्न था ।

यदि कोई जम्मू और काश्मीर के विकास के स्तर का जो कि १९४८ से भ्रम तक हुआ है विचार करे तो यह अनुभव करेगा कि काश्मीर भारतीय गणतन्त्र का एक अविभाज्य भाग बन चुका और यह कि उस राज्य की जनता और भारत की जनता के संबंध इतने घनिष्ट हो चुके हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता ।

२२ जून, १९६२, को आयरलैंड ने सुरक्षा परिषद् के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसने सुरक्षा परिषद् के पूर्व के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाते हुये भारत व पाकिस्तान दोनों की सरकारों से समझौता-वार्ता करने का निवेदन किया और यह कहा कि चार्टर के अनुच्छेद ३३ के अनुसार समस्या का यथाशीघ्र सुलभाव कर लिया जाय । इस प्रस्ताव का पश्चिमी गुट ने समर्थन किया । इसी दिन सोवियत सभ ने इस प्रस्ताव पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर एक अवरोध उपस्थित किया । यह एक नियति का व्यंग ही है कि पश्चिमी गुट ने आयरलैंड के ऐसे प्रस्ताव का समर्थन किया था, जिस सम्बन्ध में ८ साल पहले ही निपटारा किया जा चुका था ।

१९६३ के आरम्भ में पाकिस्तान और भारत सरकारों ने परस्पर समझौता द्वारा काश्मीर की समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया । इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न स्थानों में मंत्रि-मंडलीय स्तर के भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की ५ बैठकें हुईं । किन्तु इन ५ बैठकों के उपरान्त भी भारत व पाकिस्तान के बीच काश्मीर के सम्बन्ध में कोई उपयोगी परिणाम न निकल सका । भारतवर्ष पाकिस्तान से सदैव मित्रता का सम्बन्ध बनाये रखना चाहता है फिर भी काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान की हठधर्मी और बढ़ती हुई माँग के कारण समस्या का कोई ठोस सुलभाव अभी तक सामने नहीं आ सका है ।



भारतीय प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष श्री एम० सी० बागला ने पाकिस्तानी प्रतिनिधि के सर्क को इस कथन द्वारा प्रस्वीकृत कर दिया कि यद्यपि पाकिस्तान कश्मीरी जनता के अधिकारों की बात करता है, किन्तु तथ्यतः उसके नेताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे कश्मीर को अन्य आधारों पर हड़पना चाहते हैं। उन्होंने उन प्रतिक्रमणों की तालिका प्रस्तुत की, जब कि पाकिस्तान ने यूनीसिप (UNCIP) को हड़पना किया है—यथा, कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और घुमसिपाहियों

श्री चांगला न चांगे और श्री कहा था कि पाकिस्तान काश्मीर पर दावा जाति, इतिहास या परम्परा के आधार पर सामान्य हित के प्रयोजन से नहीं अपितु बल धर्म के आधार पर करता है, और यह कि भारतीय समाज और गविधान की मूलभूत धारणा बहु-जातीय समाज पर आधारित है, जहाँ कि विश्व धर्म व अनुयायी एक साथ आनन्द व जीवन-यापन कर सकते हैं और विश्व समस्त समाना में से एक माने जायेंगे। भारत ने अपने धार्मिक निर्धारण के प्रति का प्रयास किया है और गविधायिका समाज व माध्यम से, जिसमें कि अनु

काश्मीर राज्य के प्रतिनिधियों ने भारत की जनता के साथ सहकार किया था और अपने आपको सविधान उपबधित करते हुये उस सविधान के हाथों आत्मार्पित किया था, वह सविधान १४ वर्षों से प्रवर्तन में रहा है। भारत में, जिसमें कि काश्मीर भी सम्मिलित है, तीन सामान्य निर्वाचन हो चुके हैं और जम्मू और काश्मीर में रहने वाली भारतीय जनता ने उस आत्म-निर्धारण में पूर्णतः हिस्सा लिया है।

भारतीय प्रतिनिधि ने तथ्यों से स्पष्ट कर दिया कि काश्मीर में पाकिस्तान और चीन दोनों आक्रामक की स्थिति में हैं—एक ने ३२,००० वर्ग मील का क्षेत्र अवैध रूप से अपने कब्जे में कर रखा है ता दूसरे ने १७,००० वर्ग मील क्षेत्र। दोनों ने उक्त क्षेत्र का अर्जन बल-प्रयोग द्वारा किया है और सबसे आश्चर्य की बात यह कि विश्व ने जब अपनी आँखों से देख लिया था कि चीन ने भारत की उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी सीमा पर बर्बरतापूर्ण आक्रमण किया है, सब पाकिस्तान के प्रतिनिधि धूम धूमकर विश्व को यह भुलावा देने में लगे थे कि चीन ने भारत पर नहीं, अपितु भारत ने ही चीन पर आक्रमण किया है। भारत ने धागे यह स्पष्ट कर दिया कि यदि पाकिस्तान अपने अतिक्रमण को नहीं रोकता और पाकिस्तानी सेना जम्मू काश्मीर राज्य के उस हिस्से को रिक्त नहीं कर देती, जिसे कि उसने विधि-विपरीत ढंग से हथिया लिया है, सब तक जम्मू और काश्मीर राज्य का कोई न्यायोचित सुलझाव हो नहीं सकता।

मई १८, १९६४ को सुरक्षा परिषद की बैठक बिना किसी सुझाव, प्रस्ताव या मतैक्य के अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, किन्तु इस स्थगन के साथ ही कार्यवाहियों का सक्षिप्तीकरण प्रस्तुत करते हुये परिषद के अध्यक्ष ने यह कहा कि परिषद के सदस्य ऐसा अनुभव करते हैं कि दोनों पक्षकार यथा सम्भव शीघ्र परस्पर एक दूसरे से सम्बंध स्थापित करें ताकि मध्यस्थता द्वारा उनका मतभेदों को सुलझाया जा सके।

१९६२ में चीनी आक्रमण के समय पाकिस्तान ने और १९६५ में पाकिस्तानी आक्रमण के समय चीन ने भारत के विरुद्ध एक दूसरे को खुलकर समर्थन, सहायता और बढ़ावा दिया था। पाकिस्तान १९६५ की युद्ध-समाप्ति और ताशक द-समझौते के उपरान्त भी काश्मीर के प्रश्न को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच के सम्बन्धों का निष्पत्तिक कहता है और उसकी धमकियाँ निरन्तर जारी हैं कि जब तक उसे जम्मू और काश्मीर की समस्या का उसके सतोप के युक्त सुलझाव नहीं हो जाता, वह अन्य किसी विवाद पर समझौता करने और युद्ध विराम रेखा पर युद्ध के आतंक को कम करने को प्रस्तुत नहीं है। इसी जम्मू और काश्मीर राज्य ने अपने को भारत संघ में पूर्णतः तथ्यत और विधित दोनों रूपों में बिलयित कर लिया

है और वहाँ की जनता ने भारतीय संविधान के सभी उपबन्धों को साधारण अंगीकृत करते हुये यहाँ तक कि अखिल भारतीय कांग्रेस दल को भी अपना विषा है और वहाँ के 'सदरे रियासत' एवं 'प्रधान मंत्री' ने भी क्रमशः राज्यपाल और मुख्य मंत्री पदों को ग्रहण कर लिया है।

यहाँ स्मरणीय है कि १९४७ में पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर राज्य पर जो आक्रमण किया था उसे संयुक्त राष्ट्र सच के मध्यस्थ सर मोवेन बिक्रम ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल घोषित किया था। उन्होंने राज्य में भारतीय सैन्यों का रहना वैध स्थिर किया था। अतः प्रश्न स्पष्ट है—आक्रामक को अपने आक्रमण का परिणाम भुगतना ही चाहिए, अतः यहाँ वास्तविक प्रश्न जो अन्तर्गत है वह काश्मीर राज्य की स्थिति का नहीं, अपितु पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण का है।

भारतीय दृष्टि निश्चय भी इस प्रसंग में स्पष्ट है कि जम्मू और काश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और उस पर किसी प्रकार की मध्यस्थता वार्ता का प्रस्ताव करना भारत की आन्तरिक स्थिति में हस्तक्षेप करना है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है, और यह कि पाकिस्तान तथाकथित आग काश्मीर पर बलपूर्वक कब्जा किये हुये है, यह अवैध है, और यह कि पाकिस्तान द्वारा वर्ष १९६५ में पाकिस्तान चीन की समझौता के परिणामस्वरूप चीन को नेफा और लद्दाख क्षेत्र में दिया गया २७,००० वर्ग मील का क्षेत्र भारत की क्षेत्रीय सीमा पर एक ऐसा अतिक्रमण है जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत किसी प्रकार वैध नहीं माना जा सकता।

जम्मू और काश्मीर राज्य भारत का अविभाज्य अंग—प्रश्न यह है कि सुरक्षा-परिपद में समय समय पर हुई कार्यवाहियों के उपरान्त भी जम्मू और काश्मीर राज्य की भारत-संघ में वैध स्थिति क्या है।

जम्मू और काश्मीर राज्य पर भारतीय संघ की संप्रभुता के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुसार जम्मू और काश्मीर राज्य भारत के क्षेत्र का अंग है। पाकिस्तान ने जातीय आक्रामकों को सहायता करके भारत के इस राज्य पर आक्रमण किया था। कोई भी विदेशी शक्ति भारत से काश्मीर राज्य की माँग करने के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि जम्मू और काश्मीर राज्य का ही प्रिय प्रशासन एवं जन साधारण की पूर्ण सहमति पर हुआ है। जम्मू और काश्मीर राज्य इस आधार से अधीन है कि वह किसी विदेशी राष्ट्र से किसी सम्बन्ध

प्रवेश न करे, क्योंकि संविधान के १९५० के जम्मू और काश्मीर आदेश के अन्तर्गत पूर्ण विलय सम्भव हो चुका है ।

फरवरी, १९५४ में काश्मीर संविधानिका सभा ने अन्तिम रूप से भारत में सम्मिलित होने का निर्णय किया । काश्मीर के प्रधान मंत्री ने उस समय घोषणा की कि जनमत संग्रह का आह्वान स्वयं भारत द्वारा मात्र से छ वर्ष पूर्व पाकिस्तान को दिया गया था, किन्तु पाकिस्तान इस आह्वान के प्रति उदासीन रहा । राज्य की जनता ने लंबे छ वर्षों तक प्रतीक्षा की और ऐसा अनुभव किया की अब वे इससे अधिक द्विविधा और अनिश्चितता की स्थिति को राज्य और जनता की प्रगति में बाधक नहीं होने देंगे । इसलिये उन्होंने अपना विलय भारत सभ में अन्तिम रूप से करके इस अध्याय को सदा सदा के लिए निर्णित और समाप्त कर दिया ।

प्रायः यह तक दिया जाता है कि अगस्त १५, १९४७ के बाद जम्मू और काश्मीर राज्य एक स्वतंत्र राज्य बन गया और इसके उपरान्त इस राज्य का भारत में विलय, दो संग्रमु राज्यों की अन्तर्राष्ट्रीय संधि का परिणाम है । इस प्रसंग में स्मरणीय है कि भारत से पाकिस्तान के हाथों शक्ति हस्तान्तरण के अवसर पर लॉर्ड साउण्ड बैटन ने भारतीय रियासतों को व्यवहारतः स्वतंत्र कर दिया था और कहा था कि, 'My scheme leaves you with all the practical independence that you can possibly use and makes you free of those subjects which you cannot possibly manage on your own.' 'मेरी योजना आपको ऐसी समस्त व्यावहारिक स्वतन्त्रताओं के साथ छोड़ती है, जिसे कि आप सम्भाव्य प्रयोग में ला सकते हैं, और उन विषयों से पूर्णतया मुक्त करती है जिसे कि आप सम्भाव्य रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते ।' उस समय केवल जूनागढ़, हैदराबाद और काश्मीर तीन राज्यों को छोड़कर शेष सभी या तो पाकिस्तान या भारतवर्ष में सम्मिलित हो गये । भारत और पाकिस्तान के बीच सवप्रथम मतभेद नवाब जूनागढ़ द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा और पाकिस्तान द्वारा उसकी स्वीकृति मिल जाने के प्रश्न पर घोरम्भ हुई । उस समय पाकिस्तान की सरकार ने न तो भौगोलिक अनिवार्यताओं पर ही बल दिया और न जनमत संग्रह पर ही । किन्तु वही पाकिस्तानी सरकार काश्मीर के प्रश्न पर, जब कि काश्मीर वैध ढंग पर भारत में सम्मिलित हुआ, तब भौगोलिक अनिवार्यता और जनमत संग्रह पर बल देने लगी । पाकिस्तान का दृष्टिकोण इन राज्यों पर समान न रहा क्योंकि जूनागढ़ के प्रसंग में उसने वहाँ की जनता की इच्छा और भौगोलिक तारतमिकता को पूर्णतया उपेक्षित कर केवल वहाँ के नवाब की घोषणा को पाकिस्तान में सम्मिलन के

लिए पर्याप्त मान लिया था, किन्तु काश्मीर के प्रश्न पर अन्यथा रूप में सांप्रदायिक आधार का आश्रय लिया ।

जम्मू और काश्मीर राज्य भारत सघ में अपनी स्वेच्छा से सम्मिलित हुआ, मले ही एक ऐसे समय यह कार्य हुआ जब कि पाकिस्तानी आक्रमण के कारण वह राज्य की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ गई थी, फिर भी, किसी राज्य पर कोई बाह्य सिकट आ जाने के कारण उसके द्वारा अपनी संप्रभुता में किया गया पूर्णतः वैध कार्य अवैध नहीं कहा जा सकता । भारत सघ की सरकार ने काश्मीर की इस भासन्न स्थिति से कोई लाभ नहीं उठाया, और न तो काश्मीर राज्य पर कोई दबाव ही डाला । इन परिस्थितियों में राज्य का सम्मिलन विधि और तथ्य दोनों रूपों में उस दिन पूरा हो गया जिस दिन अधिमिलन के साधन का कार्यान्वयन किया गया ।

जॉनसन के शब्दों में कहा जा सकता है कि, "The legality of the accession is beyond doubt. On this particular issue Jinnah has been honest with his own petard, as it was he who chose over Junagadh to take his stand on the overriding validity of the ruler's personal decision"। अर्थात् राज्य के अधिमिलन की वैधता किसी भी शका से मुक्त है । इस विशेष प्रश्न में श्री जिन्ना अपनी ही परिभाषा के प्रतिकूल हो गये हैं, क्योंकि यह श्री जिन्ना ही सुझाव था कि जूनागढ़ के प्रसंग में प्रयासक के वैयक्तिक निर्णय को अधिभाषा वैधता से युक्त माना जाय ।

यह अधिमिलन प्राये चलकर और भी दृढ़ हो गया जब कि जम्मू और काश्मीर राज्य ने भारत की संविधानिका सभा में अपना प्रतिनिधि भेज कर संघ सत्तात्मक गणतंत्र के संविधान को निर्मित करने में सक्रिय भाग लिया और उसके भारत के संविधान को अंगीकृत किया । उस समय से ही यह राज्य भारतीय संघ का सदस्य है । अतः जम्मू और काश्मीर राज्य का भारत-सघ में अधिमिलन बिना किसी शर्त के या और किसी वैध जनमत संग्रह के अधीन नहीं था । भारत के प्रधान मंत्री ने काश्मीरी जनता को आत्म-निर्णय का पूरा अवसर दिया था और दिन सामान्य निर्वाचनों में काश्मीर जनता ने इस अधिमिलन के पश्चात् भी भारत में अपनी सदस्यता को परिपुष्ट कर दिया है ।

वर्ष १९६५ में पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर क्षेत्र के साथ ही भारत अन्य उत्तर-पश्चिम और पश्चिमी भूभाग पर बल प्रयोग किया । इसने भी पूर्व दृष्टि की समस्या में पाकिस्तानी घुसपैठिया न जम्मू और काश्मीर में तोड़-फोड़ की कार्यवाही के द्वारा वहाँ के जनजीवन और प्रजासत्तन व्यवस्था को ठप कर देना चाहा था । वहाँ

जनता ने इन छद्मवेशी घुसपैठियों को मार भगाने तथा पाकिस्तान के खुले आक्रमण का सामना करने में जिस हृद्द निश्चय और सबत्प को व्यक्त किया उससे भारत से उसकी अधिभाज्यता और भी पुष्ट और प्रमाणीकृत हो गई। पाकिस्तान अब भी मन्तराष्ट्रीय परिवार के बीच अपनी पुरानी राग बलाप रहा है, किन्तु भारत ने सुरक्षा परिषद् की बैठका में स्पष्टतः सत्कार के समक्ष घोषित कर दिया है कि काश्मीर की यदि कोई समस्या सुलझने को शेष रह गई है, तो यही कि पाकिस्तान अपने द्वारा इस राज्य के हड़पे हुये २७,००० वर्ग मील क्षेत्र को, जिसे उसने 'आजाद काश्मीर' का नाम दे रखा है, भारत को लौटा दे। इसके अतिरिक्त काश्मीर के सबंध में किसी अन्य प्रश्न को उठाना भारत की आन्तरिक अवस्था और सप्रभुता पर हस्तक्षेप करना है, भारत और भारतीय जनता किसी भी मूल्य पर अपने आन्तरिक मामलों में तथा अपनी सप्रभुता पर कोई भी बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता।

५—विजय तथा पराभव (Conquest and Subjugation)—विजय शत्रु के क्षेत्र को युद्ध के समय में सैनिक शक्ति द्वारा प्राप्त करने को कहते हैं। विजय द्वारा वैध अधिकार तब उत्पन्न होता है जब क्षेत्र सैनिक विजेता द्वारा पूर्णतः दखल और नियंत्रित कर लिया जाता है, तथा विजयी राज्य विजित क्षेत्र को घोषणा द्वारा अपने में समुक्त कर लेता है।

विजय की घोषणा के उपरान्त शत्रु-राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसके स्थान पर विजेता का राज्य क्षेत्र वह मान लिया जाता है। युद्ध की समाप्ति कर दी जाती है। युद्ध की इस प्रकार समाप्ति को ओपेनहेम ने पराभव (subjugation) की संज्ञा दी है। उनके अनुसार तो विजय के द्वारा किसी राज्य-क्षेत्र को नहीं प्राप्त किया जाता, बल्कि पराभव के द्वारा ही राज्य क्षेत्र की प्राप्ति होती है। विजित शत्रु-राज्य का क्षेत्र विजेता शत्रु-सप्रभु के अधीन रहता है। किसी राज्य को अपनी सप्रभुता में ले लेना ही विजय की पराजय या पराभव में बदल देता है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विजय का वैध-स्वरूप तभी उत्पन्न होता है, जब कि सैनिक विजेता द्वारा उस राज्य पर पूरा आधिपत्य कर लिया जाता है और समुचित घोषणा द्वारा उस राज्य का विजेता राज्य में अधिमिलन हो जाता है।

## गोआ की स्वतन्त्रता (मुक्ति)

(Liberation of Goa)

घटनाचक्र का विवेचन :—गोवा अब स्वतंत्र है। अब वहाँ फिर से भारत का अपना शासन स्थापित हो चुका है। गोवा अब एक पुर्तगाली उपनिवेश नहीं, भारत के अधिभाज्य भग के रूप में एक पूर्ण प्रभुता-संपन्न राज्य की इकाई है।

भारत छोड़कर अंगरेज चले गये थे। लेकिन पुर्तगालियों की हठधर्मिता परिराम या कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत की ओर से सद्भावनापूर्ण बार-बार गोधा को मुक्त करने की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई। सहन-शक्ति की एक सीमा होती है और जब यह पूर्णतया निश्चित हो गया कि पुर्तगाल के प्रशासकों ने शान्तिपूर्ण उपायों से सद्बुद्धि नहीं जग सकेगी तो विवश होकर भारत को सैन्य पार्यवाही की शरण लेनी पड़ी।

गोआ, डामन और ड्यू को स्वतन्त्र कराने के लिए भारत की ओर से सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी उससे भारत के भाग स्वतन्त्र तो हो गये, किन्तु विषय को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में एक विशेष चहल-पहल का विषय बना लिया गया। कुछ राष्ट्रों ने तो भारत की इस कार्यवाही का मुक्त कंठ से समर्थन दिया किन्तु कुछ राष्ट्रों ने इस विषय पर मतैक्य नहीं रखा। इस कार्यवाही को एको-एक देशों ने पूर्णतः समर्थन किया किन्तु ब्रिटेन और अमेरिकी गुट ने इसकी मान्यता भी की। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि यह कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के बन्धों के सर्वथा प्रतिकूल है।

गोआ, डामन और ड्यू का कुल क्षेत्र १५३८ वर्ग मील है। वहाँ की जनसंख्या लगभग ६ लाख के है। यह भू-भाग दिसम्बर १९६१ के पूर्व तक पुर्तगाल की अधीनता में लगभग साठे चार सौ वर्ष से था। पुर्तगाल ही पहला यूरोपीय था जिसने भारतीय क्षेत्र की कुछ भूमि पर अधिकार किया था। तीन यूरोपीय महान् शक्तियों में से पुर्तगाल ही सबसे अन्तिम था जिसे भारतीय स्वतन्त्रता के रास्त भी भारत छोड़कर हटना पड़ा था। कोई भी उपाय जब बाकी न रहा विवश होकर भारत ने सैनिक कार्यवाही की ओर कदम बढ़ाया जिसके परिणामस्वरूप पुर्तगालियों को इन बस्तियों को छोड़कर दिसम्बर १९६१ में भागना पड़ा। भारत अब अधीननिवेशिकता के बन्धनों से पूर्णतः मुक्त है।

राज्य-क्षेत्र का दखल (Possession of the Territory) — अन्तर्राष्ट्रीय विधि इस सिद्धान्त को प्रवर्तित करती है कि यदि कोई राज्य-क्षेत्र दूसरे अधीनता से निकल कर अपने मौलिक राज्य की सीमा में आ जाय और दूसरे जनता विदेशी शासक के हाथों से निकल कर अपने राज्य के क्षेत्र में सम्मिलित जाय या मौलिक राज्य उस विदेशी सत्ता से अपना क्षेत्र अलपूरवक वापस कर ले विदेशी शासन स्वतः उसे मुक्त कर दे, तो वह क्षेत्र विदेशी सत्ता के नियन्त्रण से मुक्त हो जाता है। गोआ, डामन और ड्यू की बस्तियों को भारत ने पूर्णतः वापस प्राप्त कर पुनः अपने राज्य-सीमा में सम्मिलित कर लिया, और उन बस्तियों पर पूर्ण वैध हक स्थापित हो गया। राज्य-क्षेत्र के इस प्रकार के

यन की वैधता को 'ईस्टर्न ग्रीनलैंड विवाद' [१९३३ ए/बी० ५६] में अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी न्यायालय ने स्वीकार किया था ।

समुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के अनुच्छेद २ के अन्तर्गत विश्व-शान्ति और सुरक्षा के निमित्त राज्यो पर यह आभार रखा गया है कि क्षेत्रीय हक या राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग न किया जाय । किन्तु इस प्रकार राज्य-क्षेत्र की पुनर्प्राप्ति ऐसी परिस्थिति में बंध होती है जब कि किसी विशिष्ट परिवाद की न्यायिकता का प्रमाण पहले से ही सिद्ध हो चुका हो ।

भारत की नीति शान्ति की नीति सदैव सही रही है । यह किसी सैनिक-संधि से न तो बंधा है और न गुटबन्दी को प्रत्यक्ष ही देता है । शान्ति-प्रियता के साथ ही तटस्थता की नीति भी उसकी सकाट्य रही है । पुर्तगाल नार्य भटलाटिक ट्रोटी आर्गनाइजेशन की नींव डालने वालों में मुख्य रहा है । उस संधि की धारा ५ में यह विशिष्ट रूप से व्यवस्था है कि यूरोप या अमेरिका के समस्त सदस्य-राष्ट्रों में स किसी भी सदस्य पर सैनिक आक्रमण किया जाता है तो वह घूरे साठन पर आक्रमण माना जायेगा और यह कि उत्तर भटलाटिक क्षेत्र की शान्ति को सुरक्षित रखने के लिए वे सैनिक सहायता भी आक्रमण करने वाले के विरुद्ध करेंगे । गोमा में पुर्तगालिया की शक्ति अत्यन्त ही सघन रूप से केन्द्रीभूत हो गई थी । उत्तर भटलाटिक ट्रोटी आर्गनाइजेशन का सदस्य होने के नाते यह सभावना भी बढ़ रही थी कि गोमा को ये शक्तियाँ नुक्लियर बड़ा (nuclear base) के रूप में परिवर्तित कर दें ।

आत्म-रक्षा का सिद्धांत — भारत ने १४ वर्षों तक लगातार इस बात की प्रतीक्षा की कि पुर्तगाली बुद्धिमत्ता-पूर्वक भारतीय क्षेत्र को शान्ति पूर्ण ढंग से स्वतन्त्र कर दगे । सैनिक संधि से बंधे होने के कारण पुर्तगालियों ने गोमा में सैनिक-शक्ति को निरन्तर बढ़ाना ही जारी रखा । अन्य कोई उपाय जब न रह-गया, तब भारत को विवश होकर अपनी स्वाधीनता की रक्षा और छोये हुये राज्य-क्षेत्र की प्राप्ति हेतु सैनिक शक्ति को प्रयोग में लाना पडा । यह सैनिक कार्यवाही किसी दूसरे देश पर राज्य विस्तार की आकांक्षा से आक्रमण नहीं था । भारत ने इस कार्यवाही में किसी भी प्रकार समुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रतिबन्धों को नहीं तोडा । गोमा की भूमि, वहाँ की इमारतें, वहाँ की जनता कुछ भी पुर्तगाल वालों का नहीं था । भारत ने केवल अपने छोये हुये राज्य क्षेत्र को मुक्त करने के उद्देश्य से यह सैनिक कार्यवाही की थी । पुर्तगाली प्रशासन गोमा में विदेशी सत्ता के विद्यमान होने की प्रतीक रह गई थी । समुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सदस्य राष्ट्रों का यह दायित्व है कि उन क्षेत्रों में जहाँ आत्म-शासन प्रवर्तित नहीं है, अधिक से अधिक आत्म-शासन



करने की ओर ध्यान दें । साधारण सभा ने कई बार अपने प्रस्तावों द्वारा उपनिवेशवाद को समाप्त करने की ओर सक्रिय कार्यवाही की अपील की है, किंतु वे प्रस्ताव अनसुने कर दिये गये । ऐसी स्थिति में कोई भी राज्य अपनी संप्रभुता, स्वतंत्रता और राज्य-क्षेत्र की रक्षा हेतु सैनिक बल का ही प्रयोग करता । भारत ने भी इसके अलावा और कुछ नहीं किया । अस्तु, उसकी न्यायिकता पर किसी भी प्रकार की द्विविधा नहीं उत्पन्न हो सकती ।

**चार्टर और सैनिक संधियाँ (U. N' Charter and Military Alliances)** — आज उपनिवेशवाद को समाप्त करने की ओर बल दिया जा रहा है और हर देश को अपनी स्वतंत्रता बनाये रखने के अधिकार को बढ़ावा दिया जा रहा है । संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में सैनिक-गुटबन्धियों या सैनिक सन्धियों का समर्थन नहीं किया गया है । पुर्तगाल 'नाटो' का एक सक्रिय सदस्य है । अस्तु, चार्टर का विरोध स्वभाव से पुर्तगालियों ने ही किया था ।

**सैनिक कार्यवाही की वैधता (Legal Aspect of Military Operation)** — गोम्हा की स्वतंत्रता के लिए भारत की ओर से जो सैनिक कार्यवाही की गई उसे हम अन्तर्राष्ट्रीय विधि में आक्रमण नहीं कह सकते । पुर्तगाली स्व आक्रमण की स्थिति में ये और भारत की ओर से सैनिक कार्यवाही अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा तथा अपने राज्य की पुनर्प्राप्ति हेतु ही किया गया था ।

भारत आक्रमणकारी नहीं था । उसने राज्य-विस्तार के लिए किसी दूसरे राज्य-क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था । उसने अपने राज्य-क्षेत्र की स्वतंत्रता के लिए पुर्तगालियों से निवेदन किया । १४ वर्ष तक शक्तिपूर्ण ढंग से प्रतीक्षा करते के उपरान्त भी जब समस्या का कोई हल पुर्तगाली उपनिवेशवादियों की ओर से नहीं हुआ तो प्रतिक्रिया का होना आवश्यक था ।

अन्त में दिसम्बर १५, १९६२, को संयुक्त राष्ट्र सच की साधारण सभा ने पुर्तगाल-उपनिवेशों के विरुद्ध निश्चित रूप से प्रस्ताव भी पारित हुये थे ।

इन सब तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए भारत को गोम्हा की स्वतंत्रता हेतु किये गये कार्य कदापि अग्रघर्षक कार्य नहीं कहे जा सकते । विश्व में जन तर्ज प्रणाली एवं सभी देशों की सर्वव्यापी स्वतंत्रता के सिद्धान्त में जिसे क्विबु की विश्वास है, वह भारत-पुर्तगाल सम्बन्धी यथार्थता को देखते हुये भारत की कार्यवाही का समर्थन करने से कभी पीछे नहीं रहा है ।

**मूल तथा उप-रीतियाँ (Original and Derivative Methods)** — उपर्युक्त बचन की समीक्षा करने से यह प्रकट होगा कि क्षेत्र प्राप्त करने की दो

सामान्य रीतियों में से परित्याग क्षेत्र प्राप्त करने की उपरीति है किन्तु दखल, भोगाधिकार, वृद्धि तथा विजय या पराभव क्षेत्र प्राप्त करने की मूल रीतियाँ हैं। विजय क्षेत्र प्राप्त करने की दो रीतियाँ अर्थात् मूल तथा उप के बीच में हैं। इसके अनन्तर परित्याग का होना आवश्यक है।

क्षेत्र प्राप्त करने की रीति के रूप में दखल विजय से कुछ भिन्न है। विजय की दशा में क्षेत्र अन्य राज्य की सम्पत्ति होती है किन्तु दखल की दशा में प्रभुसत्ता ऐसे क्षेत्र पर स्थापित की जाती है जैसा उस समय अन्य राज्य की प्रभुसत्ता के अधीन नहीं है अथवा जो कि किसी की सम्पत्ति नहीं है। इसे हम अनधिकृत (res nullius) क्षेत्र कहते हैं।

दखल परित्याग से इस बात में भिन्न है कि परित्याग द्वारा प्राप्त करने वाले राज्य का सम्बन्धित क्षेत्र के ऊपर प्रभुसत्ता पहले अधिकारी राज्य से सन्धि द्वारा प्राप्त होती है किन्तु दखल की दशा में सर्वोच्च सत्ता ऐसे क्षेत्र के ऊपर स्थापित होती है जो किसी की भी सम्पत्ति नहीं है। इस प्रकार परित्याग प्राप्त करने की उपरीति है किन्तु दखल क्षेत्र प्राप्त करने की मूल रीति है।

अन्त में परित्याग तथा विजय के बीच का भेद भी ध्यान में रखने योग्य है। जब कोई सैनिक दल किसी राज्य के क्षेत्र पर विजय द्वारा दखल करता है जिसे युद्ध की समाप्ति पर शान्ति की सन्धि द्वारा पुष्ट किया जाता है तो क्षेत्र के ऊपर वैध अधिकार परित्याग द्वारा उत्पन्न होता है न कि विजय द्वारा। ओपेनहेम इसे पराभव (subjugation) का रूप देते हैं।

६—न्याय-निर्णय और पंचाट (Adjudication and Award) :— प्रादेशिक प्रभुसत्ता प्राप्त करने के अतिरिक्त राज्यों के सम्मेलन द्वारा न्यायिक अथवा पंचायती निष्ठान की रीति हैं। इन्हे पारिभाषिक शब्दावली में न्याय-निर्णय (adjudication) और पंचाट (award) कहते हैं। वर्साई के शान्ति-सम्मेलन में यूरोप का प्रादेशिक पुनर्वितरण इस विषय का एक उदाहरण है।

७—पट्टे (Leases) :—क्षेत्र प्राप्त करने की एक और भी रीति है जो पट्टे द्वारा की जाती है। सन् १८६८ में चीन द्वारा कियोचाऊ का जर्मनी को, स्वागछुवान का फ्रांस को तथा पोर्टस्मार्थर का २५ वर्ष के लिए रूस को पट्टे पर देना तथा सन् १९०३ में पनामा प्रजातन्त्र द्वारा पनामा नहर का समुक्त राज्य को सर्वदा के लिए पट्टे पर देना इस रीति से क्षेत्र प्राप्त करने के उदाहरण हैं।

राष्ट्रीय क्षेत्र की हानि :—क्षेत्र प्राप्त करने की ५ सामान्य रीतियाँ उनको खो देने की रीतियों के अनुपस्थित हैं। अतः क्षेत्रीय प्रभुसत्ता त्याग (जो प्राप्त करने की

दखल की रीति के समान है), भोगाधिकार, प्राकृतिक कार्य ( जो प्राप्त करने की रीति अर्थात् वृद्धि के अनुरूप है ), परित्याग तथा विजय या पराभव द्वारा खोयी जा सकती है। राष्ट्रीय क्षेत्र को खो देने की इन ५ रीतियों में एक छोटी रीति बोयी जा सकती है, वह है विप्लव।

सन् १५७६ में नीदरलैंड का स्पेन से अलग हो जाना, १७७६ में संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट ब्रिटेन से, सन् १८२२ में ब्रेजील का पुर्तगाल से तथा सन् १८३० में बेल्जियम का नीदरलैंड से विच्छेद विप्लव द्वारा ही क्षेत्र के अलग हो जाने के उदाहरण हैं।

## अध्याय १४ क्षेत्राधिकार ( Jurisdiction )

प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्र के भीतर स्थित सब व्यक्तियों तथा वस्तुओं पर अधिकार है। ऐसे व्यक्ति ऐसी प्रजा के अन्तर्गत आते हैं जिनका जन्म वही भूमा हो अथवा जिनको उसी देश का बना लिया गया हो। वे अन्य-देशीय भी हो सकते हैं जो अपना स्थायी निवास वहाँ बना लिये हो। वस्तुओं के सम्बन्ध में तो राज्य के नियन्त्रण में जितनी सम्पत्ति है वह सब सम्मिलित है। इसका अधिकार क्षेत्र इसके क्षेत्रीय जलभागों तथा बन्दरगाहों पर स्थित अपने जहाजों तथा उन पर किये गये सब कार्यों पर भी है। इसका अधिकार क्षेत्र अपने बन्दरगाहों तथा क्षेत्रीय जलभागों पर भी है। इन व्यक्तियों तथा वस्तुओं के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व के भीतर यह ( अधिकार ) अनन्य तथा परम है।

जहाँ तक एक देश के क्षेत्रीय जल का सम्बन्ध है शान्तिपूर्ण उद्देश्य से विदेशी राज्य के जहाजों को चलने का अधिकार है। १६३० के हेग कोडिफिकेशन कांफेस में इस सम्बन्ध में विस्तृत नियम, उप-नियम भी बनाये गये थे। इन नियमों का उल्लेख पूर्व के प्रसंगों में किया जा चुका है।

खुले हुए समुद्र पर क्षेत्राधिकार :—क्षेत्रीय जलभागों के प्रतिरिक्त खुला समुद्र किसी राज्य के प्रभुत्व के अन्तर्गत नहीं है। इसकी स्वतन्त्रता अब पूर्णतः निश्चित है : The Behring Sea Arbitration, १८६३। अन्तर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का यह एक असन्दिग्ध निर्देश है कि बड़े समुद्रों में सब राज्यों के जहाजों की

चलाने का अधिकार है। उसका कारण यह है कि खुले हुए समुद्र पर निरन्तर अधिकार नहीं रखा जा सकता तथा यह स्थायी रूप से विनियोजित नहीं हो सकता। इसका कारण यह भी है कि इसका उपयोग अन्तः है, अतः यह सम्पूर्ण मनुष्य जाति के लिए समान है। नौचालन की स्वतन्त्रता एक ऐसा तथ्य है जो समस्त सम्य राज्यों द्वारा स्वीकृत है।

कोई राज्य फिर भी निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में बड़े-बड़े समुद्रों पर भी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है :—

(१) अपने जलपोतो, वस्तुओं तथा व्यक्तियों पर जो उन पर स्थित हो।

(२) समुद्री डाकूती (piratical acts) के कार्यों के सम्बन्ध में।

(३) विदेशी जलपोतो के सम्बन्ध में जो अनधिकृत रूप से इसका भ्रमण चलाये हो।

(४) युद्ध में लगे हुए राज्य द्वारा तटस्थ राज्य के व्यापारी जहाजों को इन बातों के निरीक्षण तथा तलाशी लेन के सम्बन्ध में कि क्या वे नाकाबन्दी तोड़ने के प्रयत्न में अथवा निषिद्ध वस्तुओं के ले जाने में अथवा शत्रु की ऐसी सेवाएँ करने में जो तटस्थता के नियम के विरुद्ध हो, लगे तो नहीं है।

(५) शान्ति के समय में खुले हुए समुद्रों पर 'तीव्र पीछा' करने (hot pursuit) के सम्बन्ध में जब कि विदेशी जलपोत क्षेत्रीय जलभागों के भीतर किसी स्थानीय नियम को भंग करने के उपरान्त खुले हुए समुद्र में भाग जाते हैं इस अनुबन्ध के साथ कि उसका तत्काल पीछा किया जाय।

सामुद्रिक मार्ग-स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में वैय धारणाएँ (Legal conceptions on the freedom of the High Seas) :—सामुद्रिक मार्ग-स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में दो भिन्न वैय धारणाएँ हैं। पहला सिद्धान्त ता यह है कि समुद्र किसी की वैय सम्पत्ति नहीं है। इसे अनधिकृत (res nullius) क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि समुद्री मार्गों पर किसी की संप्रभुता विद्यमान नहीं है। दूसरा सिद्धान्त यह है कि समुद्र प्रत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति है। इसे हम सार्वजनिक सम्पत्ति या सर्वाधिकृत (res communis) कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि समुद्र अन्तर्राष्ट्रीय नौचालन या व्यापार के महत्वपूर्ण सोत है, इसलिए सबके अधिकार में समान रूप से है। उपरोक्त दोनों सिद्धान्त आलोचना से मुक्त नहीं हैं। Fauchille का कथन है कि यदि यह मान लिया जाय कि समुद्र सर्वथा अनधिकृत (res nullius) है, सब भी रोमन विधि के अनुसार मानना पड़ेगा कि वह वस्तु जो किसी की नहीं है, किसी की बनायी जा सकती है। दूसरी ओर यदि समुद्र को

सार्वजनिक (res communis) मान लिया जाय तो सभी राज्य समानरूप से इस अधिपति हो जाते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इन्स्टीट्यूट ने निम्नलिखित तथ्य स्वीकार किये थे —  
(१) समुद्री भाग की स्वतन्त्रता, (२) मछली पकड़ने की स्वतन्त्रता, (३) समुद्री जहाज की स्वतन्त्रता तथा (४) समुद्र पर हवाई उड़ान की स्वतन्त्रता ।

**सार्वजनिक जहाज :—**सार्वजनिक जहाज विदेशीय बन्दरगाहों में स्थान क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त हैं, फिर भी वे बन्दरगाह के विनियमों के अन्तर्गत हैं । वहाँ जो किसी राज्य का राष्ट्रीय झंडा लगाये रहता है क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए उस राज्य का तैरता हुआ एक क्षेत्र समझा जाता है चाहे जहाज मुख्य समुद्र में हो अथवा विदेशीय क्षेत्रीय जलभागों के भीतर हो ।

**समुद्री डकैती (Piracy) :—**प्रत्येक राज्य को अपने जलपोतों द्वारा पकड़े गये समस्त डाकुओं पर क्षेत्राधिकार रहता है । समुद्री डकैती, समुद्रों पर डालना अथवा समुद्र पर सशस्त्र बलात्कार करना है जो युद्ध का एक व्यापकृत नहीं है । ऐसे कार्य प्रभु सत्ताधारी राज्य द्वारा अधिकृत नहीं किये जाते । अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार यह एक अपराध है । यह समस्त राज्यों के सम्पूर्ण समुद्राधिकार अपराध है और किसी विशिष्ट राज्य के विरुद्ध सक्षित नहीं है ।

**खुले हुए समुद्र में मत्स्य क्षेत्र ( Fisheries in the Open Sea )**  
खुले हुए समुद्र की स्वतन्त्रता के कारण यह स्पष्ट है कि उस पर स्थित मत्स्य-सब राज्यों के जलपोतों के लिए खुले हैं । मछलियाँ तथा समुद्रीय जन्तु उन्त तक किसी की 'सम्पत्ति' नहीं है जब तक वे पकड़ी न जाय । अतः प्रत्येक राज्य यह अधिकार है कि खुले समुद्र पर अपने जलपोतों द्वारा मछली पकड़ने के प्रयोग के लिए विधि बनाये ।

समुद्री पेट्री के सम्बन्ध में फिर भी तटीय राज्य को मत्स्य-क्षेत्र को प्रजा के लिए सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है ।

**समुद्र की सतह :—**बहुत से मामलों में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा इस तथ्य पहुँचा गया है कि समुद्र की सतह का स्वामी क्राउन होता है । न्यायाधीश ने Lord Fitzhardinge v. Purcell (1908) 2 Ch. 139, 166 के मा अपना विचार प्रकट किया था कि "Clearly the bed of the sea, at any for some distance below low water mark, and the beds of tidal navigable rivers, are prima facie vested in the Crown, and there is no good reason why the ownership thereof by the Crown should also, subject to the rights of the public, be a beneficial use."

अर्थात् "स्पष्टतः समुद्र का तल किसी भी दर पर पानी के अधः तल में कुछ दूर तक और ऊर्मिल नीचालन योग्य नदियों तक प्रथमदृष्ट्या रूप में 'क्राऊन' में निहित है और इस बात का कोई पर्याप्त कारण नहीं मिलता कि 'क्राऊन' का उस पर स्वामित्व भी क्यों न, लोक-अधिकारों के अधीन रहते हुये, एक लाभकारी स्वामित्व माना जाय ?"

सर सेसिल हर्स्ट (Sir Cecil Hurst) ने दो प्रमुख विवादों के निष्कर्ष-स्वरूप प्राधिकारिक रूप से लिखा है कि कुछ भी हो जहाँ तक ग्रेट ब्रिटेन का सम्बन्ध है, तीन मील के भीतर समुद्र की सतह का स्वामित्व इस बात के लिए और भी मार्ग खोल देता है कि समुद्र के सतह के स्वामित्व और उसकी प्रभुसत्ता की विस्तृत माँग की जाय। जहाँ पर तीन मील की सीमा के बाहर दखल मजबूती से स्थापित किया गया है वहाँ उसमें वैधता आ गई है और उस वैधता को अन्य राज्यों ने स्वीकार भी किया है।

पुराना सिद्धान्त यह है कि चूँकि समुद्र या समुद्री मार्ग किसी राज्य विशेष की सम्पत्ति नहीं है, इसलिए समुद्र की ऊपरी और भीतरी सतह किसी राज्य की प्रभुसत्ता के अन्तर्गत नहीं आ सकता। यह सिद्धान्त अब नहीं माना जाता। अब यह स्वीकार किया जाता है कि समुद्र की भीतरी सतह में भी तटवर्ती राज्यों का आधिपत्य हो सकता है और उन पर वे विविध प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि अभी तक ऐसे कोई नियम नहीं बने हैं जिन्हें हम राज्यों को नियन्त्रित करने वाले कानून कह सकें फिर भी समुद्र की भीतरी सतह में भिन्न-भिन्न प्रयोगों को आजकल व्यापक माना जाता है।

ओपेनहेम के अनुसार पाँच नियम बनाये गये हैं जो कि समुद्र की भीतरी सतह पर आधिपत्य के प्रश्न का निराकरण करते हैं। ये नियम सूत्र रूप में हैं :—

१—छुले हुए समुद्र की भीतरी सतह किसी भी राज्य के अधिकार की सीमा में नहीं आती किन्तु तटवर्ती राज्यों द्वारा दखल के आधार पर उस पर स्वामित्व प्राप्त किया जा सक स।

२—यह दखल तथ्य रूप में स्थापित होता है।

३—भीतरी सतह के दखल की सीमा दूसरे राज्य के क्षेत्रीय जल-पेटी की सीमा की रेखा तक निर्धारित की जा सकती है क्योंकि छुले समुद्र की भीतरी सतह को प्राकृतिक रूप से अपने अधिकार के अन्तर्गत करने का स्वत्व किसी एक राज्य को नहीं प्राप्त है।

४—समुद्र की भीतरी सतह में दखल का उद्देश्य यदि छुले समुद्र की स्वतन्त्रता में बाधा डालना है तो यह किसी भी प्रकार मान्य नहीं हो सकता।

५—इसी प्रकार से यदि पहले से ही खुले हुए समुद्र की भीतरी सतह पर दखल स्थापित किया गया है तो खुले समुद्र की स्वतन्त्रता को खतरे में डालने वाला ऐसा स्वत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

**खुले समुद्र पर अणु-परीक्षण :**—संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा की लीगल कमेटी में दिसम्बर १९५६ में भारतवर्ष ने इस बात का सबल समर्थन किया था कि समुद्रों पर थर्मो-न्यूक्लियर (thermo-nuclear) प्रयोग स्पष्ट रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विधि का अतिक्रमण करेगे । भारतीय प्रतिनिधि श्री जी० एस० पाठक ने कहा था—“If the claim to conduct thermo nuclear tests in the open seas were to be recognised, the whole law of the sea will have to be rewritten and we will have to start anew from the 18th century”

अर्थात् यदि खुले समुद्र में थर्मो-न्यूक्लियर परीक्षणों के दावे को मान्यता प्रदान की जाय, तो समुद्र की समस्त विधि को फिर से, नये सिरे से लिखे जाने को आवश्यकता होगी और हमें अठारहवीं शताब्दी के बाद से एक नये रूप में प्रारम्भ करना होगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग की साधारण बैठक में भाग लेते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा था कि “भारतवर्ष इन आणविक प्रयोगों से असम्बद्ध नहीं रह सकता और यह कहना अनुचित न होगा कि रेडियो-ऐक्टिव धूल कलकत्ता की गलियों तक पहुँचती है । आयोग द्वारा बनाये गये सिद्धान्तों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था कि समुद्र हर राष्ट्र के लिए मुक्तरूप से खुले हुए हैं और कोई भी राष्ट्र समुद्र के किसी एक हिस्से पर अपनी सम्प्रभुता के अन्तर्गत नहीं कर सकता । अपने यह निष्कर्ष निकाला कि खुले हुए समुद्र पर किसी की सम्प्रभुता का प्रयोग कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है, भले ही दखल की अवधि और दूरी कितनी ही क्यों न हो ।

“जब कोई राष्ट्र थर्मो-न्यूक्लियर प्रयोगों में व्यस्त होता है तो वह समुद्र के एक हिस्से को जहाँ यह निषिद्ध क्षेत्र (prohibited area) घोषित करता है अर्थात् वास्तविक रूप में वह उस भाग को अपने एकाधिकार में सुरक्षित कर सता है और उसे अपने राज्य क्षेत्र के रूप में प्रयोग में लाता है ।” इस प्रकार समुद्र के एक भाग पर वह अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करता है किन्तु समुद्र पर एकाधिकार इतिहास और कानून की गतिशीलता को देखते हुए अभी मान्य नहीं किया जा सकता” उही शब्दों में “The argument that the seven seas have large areas and are obviously not valid” अर्थात् यह तर्क कि सात समुद्रों के अन्तर्गत व्यापक क्षेत्र हैं और एक राज्य अपने प्रयोगों को कुछ समुद्रों के किसी छोटे टुकड़े तक सीमित रख सकता है,—एक वीथ और मान्य तर्क नहीं है ।

इस प्रश्न का निराकरण करते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा था कि इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता है और वह यह है कि ऐसे प्राणविक और रेडियो-ऐक्टिव प्रयोग समुद्री क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का अतिक्रमण करेंगे। संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवीय अधिकारों और सदस्य-राज्यों के हितों का संरक्षक है और ऐसे प्रयोग मानवता के प्रतिकूल हैं तथा चार्टर के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं।

तीन मील के सामुद्रिक क्षेत्राधिकार का प्रश्न—तटवर्ती राज्यों का क्षेत्रीय सामुद्रिक अधिकार साधारणतया तीन मील की दूरी तक माना जाता है किन्तु भारतीय प्रतिनिधि ने उसे भी समीचीन नहीं माना है। उनका कहना था कि जिन कारणों से क्षेत्राधिकार की सीमा निर्धारित की गई थी वे अब समय की गति के अनुकूल नहीं हैं, इसलिए अब हम उस नियम को नहीं मान सकते। भारत ने यह सीमा साथ ही और खनिज पदार्थों की दृष्टि से ३ मील बताई, किन्तु अधिक महत्व की दृष्टि से वह घटाई बढ़ाई भी जा सकती है।

दीवानी तथा आपराधिक क्षेत्राधिकार (Civil and Criminal Jurisdiction) :—समुद्री क्षेत्र में अपराध करने वाले विदेशी वैयक्तिक पोटों पर भी राज्य अपने क्षेत्राधिकार का दावा करते हैं। यह दावा आपराधिक कार्यों (criminal acts) तथा राष्ट्रिक या नगरिक अपराधों (municipal offences) दोनों के सम्बन्ध में किया जाता है। व्यवहारिक क्षेत्राधिकार बन्दरगाह के विनियमों तथा संक्रामक रोग सम्बन्धी-नियमों के पालन तक विस्तृत है। यदि कोई व्यक्तिगत पोत मौसम भ्रमवा देवी उत्पात के कारण भाग कर आ जाय तो बन्दरगाह की स्थानीय विधि उस पर लागू नहीं की जाती, किन्तु जहाज को तटवर्ती राज्य की किसी विधि का उल्लंघन न करना चाहिए।

एस० एस० लोटस (S. S. Lotus) वाले मामले में टर्की ने एक फ्रांसीसी वाष्पचालित पोत द्वारा छुले हुए समुद्र पर किये कार्य पर जिसका कि प्रभाव टर्की के जहाज पर पड़ा, क्षेत्राधिकार का दावा किया था। इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। अगस्त २ सन् १९२६ को फ्रांसीसी डाक ले जाने वाले स्टीमर 'लोटस' (Lotus) तथा टर्की का कोयलावाही जहाज 'बोज-कोर्ट' (Boz Kourt) परस्पर टकरा गये। परिणामस्वरूप टर्की का जहाज नष्ट हो गया। टर्की के उन ८ राष्ट्रीय जनों की मृत्यु हो गई जो जहाज पर थे। जब 'लोटस' फुस्तुनतुनिया पहुँचा तो टर्की की सरकार ने टर्की के जहाज के कप्तान 'हसन बे' तथा फ्रांसीसी जहाज 'लोटस' की रक्षा में नियुक्त पदाधिकारी लेफ्टीनेन्ट 'डेमों' (Demons) के विरुद्ध संयुक्त आपराधिक कार्यवाहियों का आरोप लगाया। इस आरोप में मानव-हत्या का भी अपराध सम्मिलित था। उन दोनों को कारावास के दण्ड का आदेश हुआ।



फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांसीसी पदाधिकारी की मुक्ति के लिए कूटनीतिक भावेदन किये। उन्होंने यह दावा किया कि उनके जहाजों पर मुख्य समुद्रों पर किये गये कार्यों पर उनका ही अनन्य क्षेत्राधिकार है। किन्तु टर्की के दंड विधान में विदेशियों के लिए भी जो टर्की अथवा टर्की की प्रजा के विरुद्ध कार्य करें उसके क्षेत्राधिकार की व्यवस्था की गई थी। क्षेत्राधिकार का झगड़ा एक स्वीकार-पत्र द्वारा हेग में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय को निर्देशित किया गया। न्यायालय ने अध्यक्ष (President) के निर्णायक मत से यह निर्णय किया कि टर्की ने फ्रांसीसी पदाधिकारी के विरुद्ध दंड कार्यवाहियाँ प्रचलित करने में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों के विरोध में कोई कार्य नहीं किया क्योंकि 'लोटम' जहाज पर किये गये कार्य ने अपना प्रभाव 'बोज-कोर्ट' जहाज पर उत्पन्न किया जो टर्की का झण्डा लगाये था, अतः ऐसी जगह में जो टर्की के क्षेत्र में सम्मिलित था और इसके प्रतिरित्त विदेशियों द्वारा वहाँ किये गये अपराधों के सम्बन्ध में भी टर्की के दंड विधि के लागू किये जाने का विरोध नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने यह भी सम्मति प्रकट की कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का कोई नियम ऐसा नहीं था जिसके द्वारा उस राज्य को जिसका वह जहाज था और जिस पर कि अपराध का प्रभाव हुआ, उस अपराध को अपने क्षेत्र में किया गया मानने से और अपराधी पर अभियोग लगाने से निषिद्ध किया जाय। यह निर्णय किया गया कि अपराध जिसके लिए लैफ्टिनेन्ट डैमो पर अभियोग लगाया गया एक असावधानी अथवा अविवेक का कार्य था जिसकी उत्पत्ति 'लोटम' जहाज पर हुई किन्तु उसका प्रभाव 'बोज-कोर्ट' जहाज पर प्रकट हुआ, अतः प्रत्येक राज्य इस घटना के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।

**विदेशी राज्य में विदेशियों की स्थिति :—**किसी राज्य का विदेशियों पर उतना ही क्षेत्राधिकार होता है जितना कि अपने नागरिकों पर। इस नियम को इसलिए स्वीकार किया गया है कि कोई भी विदेशी उस राज्य की विधियों की प्रवृत्ति नहीं कर सकता जहाँ वह रह रहा हो, भले ही उसके भावास की प्रवृत्ति अस्थायी क्यों न हो। किन्तु कोई भी राज्य उन कार्यों के लिए विदेशियों को दंडित नहीं कर सकता जो उन्होंने अपने राज्य में किया हों।

**अपरदेशीयता (Exterritoriality) :—**एक राज्य को विदेशियों के ऊपर अपने नागरिकों के समान ही क्षेत्राधिकार है, इस सामान्य नियम का अपवाद राज्यों की अपरदेशीयता में पाया जाता है। यह एक वैध कल्पना है जिसके द्वारा कुछ व्यक्ति तथा वस्तुएँ क्षेत्राधिकार तथा नियन्त्रण के प्रयोजन से उस राज्य के जिसमें कि वे वास्तव में हैं, क्षेत्र के बाहर तथा किसी अन्य राज्य के क्षेत्र के भीतर सम्मिली जाती

हैं। अपरदेशीयता का अधिकार इस सिद्धान्त पर आधारित है कि यह बात किसी राज्य के लिए निर्दोष होगी यदि उसकी वैधिक स्थिति एक समान राज्य के न्यायालयों द्वारा निश्चित की जाय। क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से ऐसी भुक्तियाँ निम्नलिखित स्थिति में दी जाती हैं —

१—सप्रभु व्यक्ति (राजा) जब कि वे यात्रा कर रहे हों अथवा विदेश में रहते हों —यह विशेषाधिकार सम्राटों के लिए जिन समय वे विदेश में भ्रमण-वास कर रहे हों तब भी विस्तृत किया जाता है। सन् १८६३ में निर्णित मिघेल बनाम जोहोर के सुल्तान [Mighell v Sultan of Johore L R (1894) Q II Div 149] वाले मामले में बादी मिघेल ने प्रतिवादी जाहार के सुल्तान के विरुद्ध जा प्रलंबट करके कल्पित नाम से भ्रमणवास कर रहे थे, विवाह प्रतिज्ञा-भग का वाद उपस्थित किया। वाद प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट मलाया स्थित स्वतन्त्र राज्य ओहोर के सुल्तान प्रकट किया जिस पर न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के अभाव के कारण कार्यवाहियों को खारिज कर दिया।

२—विदेशी राज्य —कोई विदेशी राज्य किसी अन्य राज्य में होने वाली कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। क्रिस्तीना (Cristina) वाले मामले में [(1938) A C 485] लार्ड राइट द्वारा यह व्यक्त किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार एक सर्वोच्चसत्ताधारी राज्य अन्य सर्वोच्चसत्ताधारी राज्य के अधिकार क्षेत्र से उन्मुक्त माना जाता है।

लार्ड एटकिन ने क्रिस्तीना (Cristina) में यह कहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के दो सिद्धान्त, जो हमारी दीवानी विधि में समुक्त हो गए हैं, और जो दृढ़ प्रकार से स्थापित तथा निर्विवाद प्रतीत होते हैं, वे यह हैं—प्रथम तो यह है कि किसी देश के न्यायालय एक विदेशी सम्राट को पक्षकार नहीं बनावेंगे अर्थात् वे अपने आदेश पत्र द्वारा उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध वैध कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं बनावेंगे, चाहे कार्यवाहियों में आदेश पत्र उसके व्यक्तित्व के विरुद्ध निकाले जाने हो अथवा उसके द्वारा उससे विशिष्ट सम्पत्ति अथवा सतिपुण्य प्रकट की जानी हो। दूसरे यह कि वे अपने आदेश पत्र द्वारा उस सम्पत्ति को जो उसकी है अथवा जो उसके अधिकार अथवा नियन्त्रण में हो, अभिग्रहण अथवा विरुद्ध नहीं करेंगे चाहे सम्राट कार्यवाहियों में पक्षकार हो अथवा नहीं।

३—राजदूत तथा अन्य राजनैतिक अभिकर्तागण —आपराधिक क्षेत्राधिकार में राजदूत पूर्णरूप से छूटे हुए हैं किन्तु नागरिक क्षेत्राधिकार में यह उन्मुक्ति सशर्त है, कारण राजनयिक अभिकर्तागण नागरिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति

का परित्याग कर सकते हैं। यह उन्मुक्ति राजनयिक अभिकर्ताओं के कुटुम्ब तथा उनके परिजनो के लिए भी लागू है।

४—सार्वजनिक जलपोत जब वे विदेशी बन्दरगाहों अथवा क्षेत्रीय जलभागों में हों —पार्लमेन्ट वेल्ज [Parlement Belge L. R. 5 P. D. 197 (1880)] में इज्जल्लेड के अपीलीय न्यायालय ने यह निर्णय किया कि बेल्जियम राज्य का जलपोत जो सार्वजनिक सम्पत्ति थी एक टक्कर से उत्पन्न हुई क्षति-पूर्ति के सार्वजनिक अधिकार के दावे से उन्मुक्त था।

५—किसी राज्य के सैनिकदल जब वे एक विदेशीय क्षेत्र से निकल रहे हों :—एक राज्य जो अपने क्षेत्र में किसी मित्र राज्य के सैन्य दल को जाने की अनुमति देता है, तो स्वतः इस बात को मान लेता है कि वह उस सैन्य-दल पर अपना कोई हस्तक्षेप न रखेगा। उस पर न तो वह सामूहिक रूप से और न उनके वैयक्तिक सदस्यों पर किसी प्रकार के क्षेत्राधिकार प्रयोग कर सकता है।

नैटो अर्थात् उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization) ने विदेशी देशों से सैन्य-दल को इकट्ठा करने के सम्बन्ध में अधिकार दिये हैं, किन्तु ये अधिकार पैक्ट के सदस्यों तक ही सीमित कर दिये गये हैं। भेजन वाले राज्य का क्षेत्राधिकार जहाँ तक कि नियंत्रण, सुरक्षा एवं व्यवस्था का प्रश्न है, प्रमुख माना जाता है।

६—यूरोपीय अथवा अमेरिकीय वंशज विदेशी जन कुछ पृथ्वीय राज्यों में :—वे देशीय न्यायालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार अथवा अधिकार से उन्मुक्त हैं तथा सामान्यतः कोन्सुली-न्यायालयों (Consular Courts) के क्षेत्राधिकार में रहते जाते हैं।

७—अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें :—अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें जैसे कि समुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी भिन्न शाखाओं को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति प्रदान कर दी गई है।

राज्यों की न्यायिक शक्ति :—व्हीटन (Wheaton) का कथन है कि प्रत्येक स्वतंत्र राज्य की न्यायिक शक्ति जिन सभ्यों से उपबन्धित है, निम्नलिखित है :—

१—राज्य के राष्ट्रिक विधि के विरुद्ध अपराधों पर दण्ड देने की शक्ति। वे अपराध उसके राज्य-क्षेत्र में भले ही किसी भी व्यक्ति अथवा राज्य द्वारा किये गये हों।

२—उसके वैयक्तिक और सार्वजनिक मोतों पर किये गये अपराधों के विरुद्ध दण्ड देने की शक्ति—भले ही वे अपराध किसी विदेशी शक्ति द्वारा किये गये हों।

३—अपने नागरिकों को चाहे वे जहाँ हों—ऐसे अपराधों पर दंड देने की शक्ति ।

४—राष्ट्रों की विधि में समुद्री डकैती के सम्बन्ध में जलदस्युओं को दंडित करने की शक्ति—अब वे किसी भी राज्य के क्यों न हों ।

## अध्याय १५

### सार्वजनिक तथा वैयक्तिक पोत पर क्षेत्राधिकार

#### ( Jurisdiction over Public and Private Vessels )

सार्वजनिक पोत क्या है ?—“एक सार्वजनिक पोत वह है जो एक सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य की सरकार द्वारा अधिष्ठित हो, अथवा यह भी प्रतीत होता है कि एक अर्थ सर्वोच्चसत्ताधारी राज्य की सरकार द्वारा अधिकृत हो, जब तक वह बाहरी रूप से एक मित्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में स्वीकृत हो तथा उसके द्वारा उसकी कमीशन दिया गया हो”—(Pitt Cobbett) । सार्वजनिक जहाजों को अगुनी में केवल मुद्रपात ही नहीं करना निषिद्ध जलयान, गुदाम के तथा यातायात के यान भी सम्मिलित हैं ।

जलपोत का सार्वजनिक लक्षण उसके झंडे तथा उस कमीशन से निश्चित होता है जो उसके स्वामी राज्य द्वारा जारी किया जाय ।

सार्वजनिक जलयानों की खुले हुए समुद्र पर तथा विदेशीय क्षेत्रों में जलभागों पर धींध स्थिति —ओपेनहेम के मतानुसार राज्यों की विधि का यह हृदय नियम है कि किसी राज्य के मुद्र-पोत तथा अन्य सार्वजनिक जलयान जब वे खुले समुद्र में हों अथवा विदेशीय क्षेत्रों में जल भागों में हों, प्रत्येक विषय में अपने गृह-राज्य के तैरते हुए भागों के समान समझे जाते हैं ।

चीफ जस्टिस मार्शल ने उपरोक्त सिद्धान्त पर ‘स्कूनेर एक्चेंज’ (Schooner Exchange 1812, 7 Cranch 116) वाले मामले में विचार किया और यह मत प्रकट किया कि एक सार्वजनिक सशस्त्र जहाज अपने राज्य की सैनिक शक्ति का भाग है तथा सर्वोच्चसत्ताधारी के तात्कालिक तथा सीधे आदेश के अधीन कार्य करता है और उसके द्वारा राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए कार्य में लगाया जाता है ।

यह विषय पुनः चुंग ची च्यांग बनाम किंग [Chung Chi Cheung v The King (1939) A C 160] में विचार के लिए उपस्थित हुआ । लॉर्ड एटकिन ने यह मत प्रकट किया कि विदेशीय जलभागों में स्थित सार्वजनिक जहाज

अपने राज्य के क्षेत्र नहीं समझे जाते। घरेलू न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्त के अनुसार जहाज तथा उसके मल्लाहों को कुछ उन्मुक्तियाँ प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ तो उचित रूप से निश्चित हैं। अन्य के विषय में कुछ झगडा मो है। इस दृष्टि से उन्मुक्तियाँ अपरदेशीयता के बाहरी लक्षणों पर निर्भर नहीं हैं बरन् घरेलू विधि के आशय पर। वे प्रतिबन्ध सहित हैं और किसी भी दशा में उस राज्य द्वारा जिसकी सार्वजनिक जहाज एक सम्पत्ति है, त्याग किये जा सकते हैं।

अन्त में लार्ड एटकिन ने ओपेहेम के शब्दों में प्रकटित अपरदेशीयता का सिद्धांत जिसके अनुसार जहाज "जिस राज्य का वह झंडा लगाये रहे उसका वैता हुआ भाग" माना गया था, अस्वीकार किया, और यह निर्धारित किया कि वास्तविक रूप में बात यह थी कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि को रूढ़ियों के अनुसार प्रादेशिक सर्वोच्चसत्ताधारी विदेशी सर्वोच्चसत्ताओं तथा उनके राजदूतों, सार्वजनिक जहाजों तथा ऐसे जहाजों द्वारा ले जाये जाने वाले नाविक दलों को कुछ उन्मुक्तियाँ प्रदान करती हैं जिनमें से कुछ तो पूर्णतः निश्चित हैं तथा कुछ अनिश्चित हैं।

टक्कर के मामले (Cases of Collision) — टक्कर के मामले में क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में एस० एस 'साटस' वाला मामला इस विषय में प्रभाव माना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने यह निर्णय किया कि टर्की न फ्रांसीसी वाष्प-चालित जहाज 'लोटस' तथा टर्की के जहाज 'बोज कोट' बीच में हुई टक्कर तथा उसके परिणामस्वरूप, बोज कोर्ट' में हुई हानि के सम्बन्ध में जिसमें टर्की के आठ राष्ट्रीय जनों की मृत्यु भी सम्मिलित थी, टर्की की विधि के अनुसार 'लोटस' जहाज की रक्षा का अधिकारी लेफ्टिनेन्ट डैमो के विरुद्ध अधिक कार्यवाहियाँ प्रवर्तित करने में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई बात नहीं की।

सार्वजनिक सशस्त्र पोत (Public Armed Vessels). — युद्ध के समय में युद्ध-प्रवृत्त राज्य के पोतों को तटस्थ वैयक्तिक पोता की छानबीन करने का अधिकार है। उन्हें यह भी अधिकार है कि उन्हें यदि किसी प्रकार का यह संदेह हो जाय कि यह पोत सुरक्षा को आघात पहुँचाने की कार्यवाहियों में सलग्न है, उन्हें बन्दी बनाकर अपने यहाँ रोक लें। शान्ति के समय में भी सार्वजनिक सशस्त्र पोतों को अधिकार है कि दूसरे राज्यों के पोतों को निम्नलिखित परिस्थितियों में बन्दी कर लें—

(१) समुद्री डकैती के मामलों में, (२) सार्वजनिक पोत जिस राज्य का यदि उसकी सुरक्षा के विरुद्ध की कार्यवाहियों में वह पोत सलग्न हो, या उस

ऐसा सदेह करने के समुचित कारण दिखायी पड़ते हो, (३) तीव्र पीछा करने के अधिकार में, (४) यदि उन पोतों द्वारा परस्पर राज्यों में की गई किसी सन्धि का उल्लंघन किया जा रहा हो ।

**सन्मुक्तियाँ (Immunities)**—सार्वजनिक जहाज न तो स्थानीय विधि के अधीन है और न वह स्थानीय करों यथा बन्दरगाह भ्रमण प्रकाश कर को देने के लिए भ्रमण बहिर्मुख पदाधिकारियों द्वारा निरोक्षण के लिये बाध्य किया जा सकता है । उसे नष्ट भ्रमण हानि के लिये पकड़ा नहीं जा सकता । उसके पदाधिकारी तथा चालकाण जब तक वे जहाज में रहे वही उन्मुक्तियाँ उपभोग करते हैं । इसके उपरान्त उससे यह भी भाशा की जाती है कि वह उस राज्य की विधियों का जिसके जलभागों में वह रहे यथोचित आदर करे ।

**वैयक्तिक पोत क्या है ?**—वैयक्तिक पोत वे जलयान हैं जिसका वैयक्तिक स्वामित्व किसी व्यक्ति को प्राप्त हो किन्तु अपने राष्ट्रीय स्वरूप से उत्पन्न अधिकार के कारण तथा किसी राज्य के समुद्रों में के न्यायानुसार प्रयोग के कारण उस राज्य की सम्पत्ति समझे जाते हैं । ऐसे जलयान यद्यपि वे राष्ट्रीय क्षेत्र से बाहर भी हैं तथापि अपने राज्य से संरक्षण पाने के अधिकारी हैं और उसके अधिकार तथा क्षेत्राधिकार के अधीन हैं ।

**बड़े समुद्रों पर वैयक्तिक पोतों की वैध स्थिति**—वैयक्तिक पोत जब बड़े समुद्र में होते हैं, उस राज्य की सर्वोच्चसत्ता के अधीन होते हैं, जिसकी वे सम्पत्ति तथा जिसका वह झंडा लगाये हो । उस राज्य को जिसका वह झंडा लगाये हो वह अधिकार होता है कि वह अपनी प्रजा भ्रमण विदेशिया से सम्बन्धित जहाज पर ले जाने वाले समय विषयों में प्रशासकीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे ।

अपने वैयक्तिक पोतों के सम्बन्ध में झंडे वाले राज्य का क्षेत्राधिकार फिर निम्नलिखित भ्रमणों के अधीन है जो कि रूढ़ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार न्य है—

१—प्रत्येक युद्ध में सलग्न युद्धपोत को यह अधिकार है कि वह किसी व्यापारी जहाज के पास जावे और उसकी तलाशी ले और अन्त में यदि वह पकड़ा जाय तो यदि वह किसी भ्रमण कार्य में लगा हो भ्रमण प्रमाण पत्र के न के कारण उसका स्वरूप निश्चित न हो सकता हो तो उसे बन्दी कर ले ।

२—युद्ध के समय में तटस्थ व्यापारी जहाज जो प्रतिशोध भ्रमण नाका-मार्ग के नियमों को उल्लंघन करने का प्रयास करे पकड़ा जा सकता है ।

३—सब राज्यों के युद्धपोतों को यह अधिकार है कि वे बड़े समुद्र पर व्यापारी जहाजों से यह पता लगाने के लिए मुठभेड़ करे कि कहीं वे समुद्र में तो नहीं हैं ।

तटवर्ती राज्य के युद्धपोत किसी विदेशीय जलयान का उसके विविधों को का उल्लंघन करने के कारण तीव्र पीछा कर सकते हैं।

५—प्रत्येक राज्य के युद्धपोतों को यह अधिकार होता है कि वे जलयान को जो उनके राज्य का झंडा लगाकर तैर रहा हो, पकड़ें तथा दंडित किये जाने के लिए अपने बन्दरगाह पर लावें।

## अध्याय १६

### समुद्री डाका

#### ( Piracy )

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार समुद्री डाका समुद्री में वैयक्तिक लक्ष्यों के किसी राज्य की सरकार के बिना प्राधिकृत किये हुए सम्पत्ति को लूट-खसोट अपराध व्यक्तियों के विरुद्ध बलात्कार के कार्य करने के लिए तैरना है। बड़े समुद्रों पर यहाँ किया जा सकता है व्यापार की सुरक्षा के विरुद्ध अपराध समझा जाता है। समुद्री केवल अन्तर्राष्ट्रीय विधि से सम्बन्धित है। उसके प्राथमिक तत्त्व निम्नलिखित हैं—

( १ ) यह एक कार्य है जो किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जब वह समुद्रों पर तैर रहा हो।

( २ ) ऐसा कार्य किसी राज्य के प्राधिकार अथवा सहमत (commission) के बिना होता है।

( ३ ) समुद्री डाके के अपराध के लिए वास्तविक लूट आवश्यक प्राण है, लूट करने का निष्कपट प्रयत्न भी समुद्री डाका के समान है।

( ४ ) इस प्रकार की लूट एक वैयक्तिक पोत द्वारा अन्य पोतों के विरुद्ध अथवा विद्रोही चालको द्वारा अपने ही जलयान के विरुद्ध की जाती है।

( ५ ) समुद्री डाके का तत्त्व यह है कि इसमें सार्वजनिक लक्ष्यों के बड़े वैयक्तिक उद्देश्य निहित होते हैं।

समुद्री डाका के लिए आवश्यक तत्त्व—अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री डाका उस समय होता है, जब कि समुद्र में अपने वैयक्तिक हितों की दृष्टि से पोत चलाये जाते हैं, और उसके पोत-संचालन में किसी भी राज्य की ओर से प्राधिकार नहीं मिला रहता। ऐसे जहाजों का प्रायः उद्देश्य अन्य लोगों की हानि

को छूटना तथा हिंसात्मक कार्यवाहियाँ होती हैं। यह समुद्री मार्ग पर एक प्रकार का अपराध है जो कि समुद्री व्यापार के विरुद्ध है।

ह्वीटन (Wheaton) ने इसे इन शब्दों में लिखा है :—Piracy is the offence of "depredating on the seas, without being authorised by any foreign state, or with commissions from different sovereigns at war with each other" अर्थात् 'समुद्री डाका' समुद्रों पर बिना किसी विदेशी राज्य के प्राधिकार के ही अतिक्रमण करना, या युद्धरत विभिन्न सप्रभुओं की सहमति के बिना अपराध कारित होता है।

मूर (Moore) ने 'डाइजेस्ट प्राव इटरनेशनल लॉ' में समुद्री डाकैत की निम्नलिखित परिभाषा की है :—"One who, without legal authority from any state attacks a ship with intention to appropriate what belongs to it. The pirate is a sea brigand. He has no right to any flag and is justiciable by all" अर्थात् "वह व्यक्ति, जो कि बिना किसी राज्य के वैध प्राधिकार के ही इस भावसे किसी पोत पर आक्रमण करता है कि उसमें जो कुछ है उसे हड़प सके। समुद्री डाकू एक जल-दस्यु हुमा करता है। उसे कोई ध्वज रखने का अधिकार नहीं है और वह सभी के न्याय-प्रशासन का विषय है।"

किसी सरकार द्वारा प्राधिकृत समुद्री डाकैती के कार्य—कोई व्यक्ति हो नहीं, बल्कि एक स्वतन्त्र राज्य भी समुद्री डाकैती के कार्यों के लिए दोषी हो सकता है। प्रोफेसर हाइड (Hyde) का कथन है कि "national authorisation of the commission of piratical acts would not free pirates from internationally illegal aspects" अर्थात् समुद्री डाके कार्यों को कारित करने, राष्ट्रीय प्राधिकरण समुद्री डाकुओं को अन्तर्राष्ट्रीय अवैध पक्षों से मुक्त नहीं कर देता। वाशिंगटन कांफ्रेंस में १९२२ में यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि कोई भी व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करता है, मने ही वह अपने परिष्ठ प्राधिकारियों के आदेश पर कर रहा हो, उसके विरुद्ध किसी भी राज्य के न्यायालय में 'समुद्री डाकैती' का मुकदमा चलाया जा सकता है।

वैयक्तिक समुद्री डाकैती सम्बन्धी जहाजों को गिरफ्तार करना—सभी युद्ध-पोतों को यह अधिकार है कि समुद्री डाकैती, या उसका पोछा करने के प्रयत्न में लगे हुए सभी जहाजों का निरीक्षण कर सकते हैं। वे उन्हें बन्दी कर सकते हैं और उनके विरुद्ध अपने देश के न्यायालय में मुकदमा चला सकते हैं। समुद्री डाकैत को किसी प्रकार का भंडा सगाने का अधिकार नहीं रहता।



समुद्री डकैती के प्रसंग में सम्पत्ति का स्वामित्व—समुद्री डकैती में लूटी गई सम्पत्ति पर से उसके वास्तविक स्वामी का हक समाप्त नहीं हो जाता। यदि वह फिर से पकड़ ली जाती है, तो उसी व्यक्ति या राज्य की मानी जाती है।

समुद्री डकैती और राष्ट्र-विधि—अन्तर्राष्ट्रीय विधि में वर्णित 'समुद्री डकैती' और राज्यों के राष्ट्र-विधि के अन्तर्गत वर्णित 'समुद्री डकैती' में किसी प्रकार का भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए। किसी राज्य में 'समुद्री डकैती' के प्रसंग में जो विधियाँ बनाई गई हैं, वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि की अपेक्षा महत्व में न्यून हो सकती हैं या उनमें गुरुता (gravity) की कमी हो सकती है। राज्य में निर्मित समुद्री डकैती विधि को सीमित होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी राज्य केवल अपने नागरिकों को दण्ड देने की विधि निर्मित कर सकता है, विदेशी नागरिकों को दण्ड करने के नियम बनाने में कोई राज्य सक्षम नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि में समुद्री डकैती के क्षेत्राधिकार व्यापक हैं, क्योंकि इस विधि के अन्तर्गत किसी भी देश के वासियों को कोई भी राज्य समुद्री डकैती के अपराध में दण्डित कर सकता है क्योंकि समुद्री डकैती पूरी सभ्य मानवता के विरुद्ध किया गया अपराध है।

## अध्याय १७

### राष्ट्रीयता

#### (Nationality)

राष्ट्रीयता क्या है ? —राष्ट्रीयता वह लक्षण अथवा गुण है जो किसी विशिष्ट जाति अथवा राष्ट्र की सदस्यता से उत्पन्न होता है और जो किसी व्यक्ति की राजनैतिक स्थिति अथवा निष्ठा निश्चित करता है। यह एक व्यक्ति राज्य के बीच परस्पर बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। ओपेनहेम के मतानुसार व्यक्ति का "किसी राष्ट्र की प्रजा और इसलिये उसके नागरिक" होना वास्तव में यह एक प्रकार का निरन्तर चलने वाला वैध सम्बन्ध है जो कि प्रभुत्व और राज्य और नागरिक के बीच स्थापित होता है। इस वैध सम्बन्ध के अभाव में कोई एक दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्य मिले होते हैं। एक मनुष्य की राष्ट्रीयता उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक ज्यों की त्यों बनी रहने—यह आवश्यक है। वह परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन-काल में ही अपनी राष्ट्रीयता बदल सकता है। वह किसी दूसरे राज्य या नागरिक भी बन सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीयता में परिवर्तन होते रहते हैं।

इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के मत नीचे दिये जा रहे हैं :—

केल्सन (Kelsen) :—नागरिकता या राष्ट्रीयता एक व्यक्ति की स्थिति है, जो कि वैध रूप में किसी राज्य का सदस्य है, और उसे धार्मिकारिक रूप से उस समुदाय का सदस्य कहा जा सकता है ।

हाइड (H. de) —राष्ट्रीयता एक व्यक्ति और राज्य के उस सम्बन्ध का श्रोतन करता है जो इस प्रकार है कि राज्य बहुत से भाधारो पर समझ लेता है कि व्यक्ति की निष्ठा उसके प्रति है ।

स्टार्क (Starke) —“Nationality may be defined as the status of membership of the collectivity of individuals whose acts, decisions and policy are vouchsafed through the legal concept of the State representing those individuals.” अर्थात् “राष्ट्रीयता की परिभाषा ऐसे व्यक्तियों की सामूहिकता की सदस्यता की स्थिति से दी जा सकती है जिसके कृत्य, निर्णय और नीति ऐसे राज्य की वैध व्यवधारणा के माध्यम से सरक्षित हैं जो कि उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है ।”

राष्ट्रीयता का निर्धारण :—राष्ट्रीयता के निर्धारण का प्रश्न राष्ट्र विधि के क्षेत्र के भीतर आता है, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत नहीं । अन्तर्राष्ट्रीय संपर्क तथा यातायात बढ़ने के कारण नागरिक राष्ट्रीयता के विधियों में प्रायः विरोध उत्पन्न हो जाता है । सन् १९३० के हेग के संहिताकरण सम्मेलन ने राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में बहुत से लेखों को स्वीकार किया, उदाहरणार्थ राष्ट्रीयता के विधियों के विरोध में अभिसमय, राष्ट्रीयता के अभाव पर सलेख (protocol), इत्यादि ।

राष्ट्रीयता का अधिकार कोई प्राकृतिक (natural) अधिकार नहीं है । राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार है, क्योंकि वह व्यक्ति और अन्तर्राष्ट्रीय विधि के बीच की एक कड़ी है । यह कड़ी उतनी महत्वपूर्ण है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । ऊपर जिन अभिसमयों एवं सम्मेलनों की चर्चा की गई है, उनमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक राज्य स्वयं निश्चय करे कि उनकी विधि के अनुसार कौन लोग उसके नागरिक हैं और किन्हे उस देश की राष्ट्रीयता प्राप्त हो सकती है । यद्यपि वे राज्य अपने राज्य-क्षेत्र में विधियों के निर्मित करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में बनायी गयी विधियों को, जहाँ तक उनका अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों तथा कूटियों से सम्बन्ध है, अन्य राज्यों द्वारा भी मान्यता प्राप्त हानी चाहिये । उन्हें राष्ट्रीयता के सामान्य रूप से मान्य सिद्धान्तों के अनुरूप भी होना चाहिये ।

संयुक्त राज्य की 'सुप्रीम कोर्ट' ने U. S. v Wong Kum Ark (169 U. S. 649) के विवाद में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय किया था—“It is the inherent right of every independent nation to determine for itself and according to its own constitution and laws what classes of persons shall be entitled to its citizenship” अर्थात् “प्रत्येक स्वाधीन राष्ट्र का यह अन्तर्निहित अधिकार है कि वह अपने आपके लिए निर्धारित कर सके कि स्वयं उसके संविधान के अनुसार तथा उसकी विधि के अनुसार किस प्रकार के व्यक्ति उसकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो सकते हैं।”

इसी प्रकार स्टोइक बनाम पब्लिक ट्रस्टी [Stoeck v Public Trustee (1921) 2 Ch 69] के विवाद में कहा गया है—“The question to what State a person belongs must ultimately be decided by the municipal law of the State to which he claims to belong to or to which it is alleged that he belongs” अर्थात् “इस प्रश्न का, कि कोई व्यक्ति किस राज्य का है अवश्य ही उस राज्य की नागरिक विधि द्वारा अंतिम रूप में निर्णीत होता चाहिए जिसका कि नागरिक होने का वह व्यक्ति दावा करता है या जिसके लिए यह माना जाता है कि वह व्यक्ति उस राज्य का नागरिक है।”

**राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि** —अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न महत्व की प्रासंगिक बातें हैं—(१) बाह्य कूटनीतिक दृष्टि के लिए अधिकार, (२) किसी अन्य राज्य में उसके राष्ट्रीयजन द्वारा किये जाने वाले किन्हीं अनुचित कार्यों को रोकने की अथवा उनके जाने के उपरांत उनके लिए दण्ड देने की असफलता के लिए राज्य का उत्तरदायित्व, (३) राज्य को अपने नागरिकों को वापस प्राप्त करने का कर्तव्य, (४) जिस राज्य की वह राज्य भक्ति करे उस राज्य की सैनिक सेवा करने का राष्ट्रीय जन का कर्तव्य, (५) अपने राष्ट्रीय जनो को उनका समर्पण माँगने वाले अन्य राज्य को प्रत्यर्पण करने से अस्वीकार करने का किसी राज्य का सामान्य अधिकार, (६) सम्बन्धित व्यक्ति की राष्ट्रीयता के अनुसार युद्ध के समय में शत्रुत्व की स्थिति का निश्चित करना, तथा (७) राष्ट्रीयता के आधार पर राज्यों द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग।

सर जान फिशर-विलियम्स (Sir John Fischer Williams) ने ठीक ही लिखा है कि “वर्तमान विश्व, ऐसे व्यक्तियों का विश्व है जो किसी राज्य में अथवा किसी राज्य के अधीनस्थ संगठित हुए हैं, कोन-सा नागरिक किस राज्य का है, इस बात का निर्धारण उसना ही महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है, जितना कि इस प्रश्न का निर्धारण कि, अथवा राज्य-क्षेत्र किस राज्य का है। अन्तर्राष्ट्रीय अधिकारों की

कर्तव्य पूर्णरूप से व्यक्तियों की राष्ट्रीयता पर निर्भर करती है। यह कहना कि राष्ट्रीयता के प्रश्नों के लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय विधि नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के बहुत से प्रश्नों को अराजकता के हाथों सौंप देना होगा। किन्तु यह भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार राष्ट्रीयता, सामान्य नियम के रूप से, राष्ट्र-विधियों द्वारा ही निर्धारित की जाती है।”

**राष्ट्रीयता तथा स्थायी निवास**—राष्ट्रीयता तथा स्थायी निवास में सूक्ष्म अन्तर है। राष्ट्रीयता किसी विशिष्ट राष्ट्र अथवा राज्य की सदस्यता से उत्पन्न होने वाला लक्षण अथवा गुण है तथा किसी व्यक्ति की राज्य-भक्ति को निश्चित करती है। स्थायी निवास राष्ट्रीयता का गुण है और किसी व्यक्ति के निवास स्थान को सुरक्षित करता है—यह व्यक्ति तथा स्थान का सम्बन्ध है जहाँ कि उसका स्थायी निवास है। इस प्रकार राष्ट्रीयता स्थायी निवास से प्राप्त की जा सकती है। किसी व्यक्ति को स्थायी निवास प्राप्त करने का अधिकारी बना देने वाली समय की अवधि दशों में भिन्न-भिन्न है। किसी व्यक्ति की राजनैतिक स्थिति को, जिसके कारण से वह किसी विशिष्ट देश की प्रजा होकर प्राकृतिक राज्य-भक्ति की गाँठ से बँध जाता है उसका राष्ट्रीय लक्षण कहा जाता है। उसकी व्यावहारिक स्थिति का जिसके कारण वह किसी देश के नागरिक का लक्षण प्राप्त कर लेता है और जिस नागरिकता के अधिकार प्राप्त होते हैं, तथा जो कुछ कसब्या के अधीन होता है, ‘स्थायी निवास’ शब्दों से निर्देशित किया जाता है। ‘राज-भक्ति’ एक ऐसा शब्द है, जिसका साम्य उस राष्ट्रीय रूप से होता है, जिसके फलस्वरूप कोई व्यक्ति अपने राज्य के प्रति प्रास्था रखता है।

**राष्ट्रीयता प्राप्त करने के ढंग** :—ग्रोपेनहेम के मतानुसार राष्ट्रीयता प्राप्त करने के पाँच ढंग हैं। वे निम्नलिखित हैं।

राष्ट्रीयता प्राप्त करने की सबसे प्रथम और सबसे महत्व की रीति जन्म (birth) है। यह भूमि सम्बन्धी नियम (jus soli) अर्थात् जन्म का क्षेत्र अथवा स्थान के अनुसार अथवा रक्त सम्बन्धी नियम (jus sanguinis) अर्थात् जन्म के समय माता पिता की राष्ट्रीयता के अनुसार अर्थात् वंशानुक्रम के अनुसार अथवा दोनों के अनुसार हो सकती है।

विश्व के अधिकांश लोगो को जन्म से ही राष्ट्रीयता प्राप्त होती है। जर्मनों में पैतृकता की राष्ट्रीयता का द्योतक माना जाता है—मले ही बच्चा अपने देश में पैदा हुआ हो, अथवा विदेश में, पिता की राष्ट्रीयता के आधार पर उसकी राष्ट्रीयता भी निर्धारित कर दी जाती है। अर्जेन्टाइना में राज्य-क्षेत्र को महत्व

दिया जाता है अर्थात् नवजात शिशु वहीं का राष्ट्रीय माना जाता है, जिस राज्य क्षेत्र में उसका जन्म हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका में मिली-जुली पद्धति अपनायी जाती है।

राष्ट्रीयता प्राप्त करने का दूसरा ढंग देशीयकरण (naturalisation) है। यह उस समय होता है जब कोई व्यक्ति किसी राज्य का जन्म के लिए वह पहले विदेशीय था, प्रजा हो जाना है। यह व्यक्ति तथा राज्य जन्म वह रहता है कि मूल में राज्य-भक्ति का एक कृत्रिम बन्धन है। देशीयकरण की छ रीतियाँ हैं अर्थात् (१) विवाह अर्थात् पत्नी द्वारा पति को राष्ट्रीयता को ग्रहण करना (२) औरमकरण (legitimation) जिसके द्वारा जारज (illegitimate) बाबू बनने पिता की राष्ट्रीयता को प्राप्त करना है (३) विकल्प (option), (४) स्वामी निवास की प्राप्ति (५) सरकारी पद पर नियुक्ति तथा (६) राज्य अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देने पर स्वीकृति।

केलसन (Kelsen) व अनुगम देशीयकरण किसी राज्य का एक प्रशासकीय कार्य होता है जो कि किसी विदेशी का नागरिकता प्रदान करता है, किन्तु एक ऐसा अन्तराष्ट्रीय विधि या नियम भी है कि विदेशियों का किन-किन शर्तों पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है। देशीयकरण तभी संभव है, जबकि विदेशी इस भाष्य का आवेदन करता है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विदेशी व्यक्ति देशीयकरण का दावा नहीं कर सकता।

राष्ट्रीयता प्राप्त करने का तीसरा ढंग पुन प्राप्ति अथवा पुनर्ग्रहण (redintegration or resumption) है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विर काल तक बाहर रने अथवा वहाँ पर देशीयकरण होने के कारण अपनी मौलिक राष्ट्रीयता खो दी हो वे उसे कुछ शर्तों की पूर्ति करने पर पुन प्राप्त अथवा ग्रहण कर सकते हैं।

राष्ट्रीयता प्राप्त करने का चौथा तथा पाँचवा ढंग अधीनस्थ किया जाना तथा राज्य क्षेत्र का अधिमिलन (subjugation and cession of territory) है। अधीनस्थ करने में विजित प्रदेश का विजय तथा संयोजन व्यक्त होता है। संयोजन द्वारा प्रदेश विजयी के सम्पूर्ण प्रभुत्व में आ जाता है तथा अधीनस्थ अथवा अधिमिलित किये गये क्षेत्र के निवासी राज्य की राष्ट्रीयता प्राप्त कर लेते हैं।

ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम — इस प्रसंग में ब्रिटिश राष्ट्रीयता ऐक्ट और १९१४-१९२२ विदेशी की स्थिति के अधिनियम, (Status of Aliens Act. 1914 1922) का उल्लेख किया जा सकता है। वहाँ निम्नलिखित को प्राकृतिक एवं नये जन्म सिद्ध प्रजा माना जाता है।

(१) कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटिश राज्य के राज्य-क्षेत्र या उपनिवेशों में पैदा हुआ हो । (२) ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश उपनिवेशों की सीमा से बाहर पैदा हुआ हो, किन्तु या तो उसका पिता उस समय ब्रिटिश उपनिवेश की प्रजा जन्म-सिद्ध रूप से अथवा क्राउन की ओर से दिये गये किसी पद का अधिकारी रहा हो या उनका जन्म एक वर्ष के भीतर (किसी-किसी प्रसंग में २ वर्ष भी) ही ब्रिटिश कॉमन्वेल्थ में लिखा गया हो ।

**अमेरिका का राष्ट्रीयता अधिनियम .—**इमीग्रेशन ऐंड नेशनैलिटी ऐक्ट, १९५२, के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीयता प्राप्त है —

१—कोई व्यक्ति जो संयुक्त राज्य के भीतर पैदा हुआ हो और उसके क्षेत्राधिकार के भीतर माता हो ।

२—कोई व्यक्ति जो भारतीय, एस्किमो, येलूशिमान या अन्य मूल जातियों का हो किन्तु संयुक्त राज्य की सीमा में पैदा हुआ हो ।

३—कोई व्यक्ति जो संयुक्त राज्य के बाहर या उसकी बाहरी सीमा के पार पैदा हुआ हो, किन्तु उसके माता-पिता दोनों संयुक्त राज्य के नागरिक हो और उनमें से एक का निवास संयुक्त राज्य में पैदाइश के पूर्व से रहा हो ।

४—कोई व्यक्ति जो संयुक्त राज्य से बाहर या उसकी बाहरी सीमा के पार पैदा हुआ हो, किन्तु माँ-बाप में से कोई एक संयुक्त राज्य के नागरिक हो और जन्म के पूर्व लगातार एक वर्ष से अधिक से वहीं रहे रहे हो तथा उन दोनों में कोई संयुक्त राज्य का नागरिक होते हुये भी नागरिक नहीं है ।

५—कोई व्यक्ति जो अमेरिका की बाहरी सीमा के भीतर पैदा हुआ हो किन्तु ऐसे माता-पिता से जिसमें से एक संयुक्त राज्य का नागरिक हो और वहाँ शारीरिक रूप से विद्यमान रहा हो या उसकी बाहरी सीमा के भीतर जन्म के लगातार एक वर्ष पूर्व से रहा हो ।

६—ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता का कुछ पता न चल रहा हो यदि संयुक्त राज्य में ५ वर्ष की आयु के भीतर पाया जाय जब तक कि २१ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले और उस बीच में यह तथ्य प्रमाणित न हो जाय कि वह संयुक्त राज्य में नहीं पैदा हुआ है ।

७—कोई व्यक्ति जो संयुक्त राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर या उसकी बाहरी सीमा के पार पैदा हुआ हो, किन्तु उसके माता पिता में से कोई एक विदेशी हो, और दूसरा संयुक्त राज्य का नागरिक हो, जो कि ऐसे व्यक्ति के जन्म के पूर्व वहाँ या उसकी बाहरी सीमा के भीतर शारीरिक रूप से विद्यमान रहा हो और कम से

कम लगातार १० वर्ष या कुल मिला कर १० वर्ष से वहाँ रहा हो जिसमें से कम से कम ५ वर्ष १४ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद का हो ।

**दुहरी राष्ट्रीयता (Double Nationality) :**—क्या राष्ट्रीयता जन्म के समय माता-पिता की राष्ट्रीयता से प्राप्त होती है अथवा क्षेत्र से या जन्म-स्थान से, इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न राज्यों में कोई समान नियम नहीं है । इसका परिणाम यह है कि राज्यों की रीति में बड़ा भारी अन्तर है । ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा बहुत से लैटिन अमेरिकीय राज्य *jus soli* अर्थात् भूमि पर केवल जन्म लेने से ही राष्ट्रीयता प्रदान करने के सिद्धान्त का अवलम्बन करते हैं । किसी विदेशीय के शिशु को भी जिसका जन्म इंग्लैंड अथवा अमेरिका में हुआ हो यथा-स्थिति ब्रिटिश अथवा अमेरिकीय राष्ट्रीयता प्राप्त हो जाती है । फ्रांस, जर्मनी तथा अन्य यूरोपीय देश प्रधानतः *jus sanguinis* अर्थात् रक्त-सम्बन्ध सिद्धान्त का अवलम्बन करते हैं जिसके अनुसार शिशुओं की राष्ट्रीयता उनके माता-पिता की राष्ट्रीयता का अनुसरण करती है जिससे उनकी प्रजा से उत्पन्न शिशु स्वतः उनकी प्रजा हो जाती हैं चाहे वे स्वदेश में उत्पन्न हुईं हो अथवा विदेश में । इस नियम में जारज शिशु सम्मिलित नहीं हैं जो अपनी माँ की राष्ट्रीयता को प्राप्त करते हैं । इस प्रकार उस दशा में जब कोई बालक किसी राज्य की भूमि में ऐसे माता-पिता से उत्पन्न हो जो अन्य राष्ट्र के नागरिक हो, क्षेत्राधिकार का भगडा उत्पन्न हो सकता है । उदाहरणार्थ एक बालक जो संयुक्त राज्य में फ्रांसीसी माता-पिता से उत्पन्न हो, *jure soli* (भूमि सम्बन्धी नियम) के अनुसार अमेरिकीय है किन्तु उसी समय वह *jure sanguinis* (रक्त सम्बन्धी नियम) के अनुसार फ्रांसीसी नागरिक है । इस दशा में उसकी प्रभावपूर्ण नागरिकता उस क्षेत्राधिकार पर भाषित रहेगी जहाँ का वह होता । संयुक्त राज्य में वह अमेरिकीय है, फ्रांस में फ्रांसीसी और किसी अन्य देश में दोनों । इसी प्रकार से यदि कोई बालक ग्रेट ब्रिटेन में जर्मन माता पिता से उत्पन्न होता है तो उसे एक ही समय में दुहरी राष्ट्रीयता प्राप्त होगी अर्थात् ब्रिटिश तथा जर्मन, किन्तु इस दुहरी राष्ट्रीयता का अन्त हो सकता है यदि वह व्यक्ति वयस्क होने पर अपनी राज्यभक्ति घोषित कर दे ।

दुहरी राष्ट्रीयता शादी से भी उत्पन्न हो जाती है । जब एक अमेरिकी महिला किसी अंग्रेज पुरुष से शादी कर लेती है, तो ब्रिटिश वानून के अनुसार वह अमेरिकी महिला ब्रिटिश-राष्ट्रीयता प्राप्त कर लेती है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस नयी राष्ट्रीयता से उसकी मौलिक राष्ट्रीयता का लोप हो गया । वह साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय बनी रहेगी । उसकी मौलिक राष्ट्रीयता का

लोप तभी होगा जब वह शीपवारिव रूप से किसी न्यायमय के समक्ष अपनी नागरिकता के बदले जाने का प्रत्यावेदन कर लें ।

सन् १९३० के हेग के संहिताकरण कान्फ्रेंस ने यह व्यवस्था की थी कि कोई व्यक्ति जिसकी दो या अधिक राष्ट्रीयता हो, प्रत्येक राज्य द्वारा राष्ट्रिक माना जायेगा और वह व्यक्ति उस राज्य की अनुज्ञा से उस राज्य की राष्ट्रिकता परित्याग करके दूसरे राज्य का राष्ट्रिक बना रहता है । एक तीसरा राज्य भी दुहरी राष्ट्रीयता रखने वाले व्यक्ति की बेचल प्रभावोत्पादक राष्ट्रीयता स्वीकार करेगा । प्रभावोत्पादक राष्ट्रीयता का अर्थ या तो उस राज्य की राष्ट्रीयता होती है जिसमें वह स्वभावतः तथा मुख्यतः रहता हो अथवा उस राज्य की राष्ट्रीयता जिससे उसका अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्बन्ध हो । ( *The Caneyiro case, William Mackenzie Claim and Kramer v. Attorney General* ).

**भारत में राष्ट्रीयता :—**राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में भारत के संविधान में विशेष व्यवस्था पाई जाती है । सम्पूर्ण भारत के लिये एक ही नागरिकता है और संविधान में राष्ट्रीयता निश्चित करने के लिये कोई विस्तृत व्यवस्था नहीं है, किन्तु यह विषय निर्धारित करने के लिये संसद पर छोड़ दिया गया है । अनुच्छेद ५ में यह कहा गया है कि संविधान के आरम्भ में अर्थात् जनवरी २६ सन् १९५० को प्रत्येक व्यक्ति जिसका स्थायी निवास भारतीय राज्यक्षेत्र में है तथा जो

(अ) भारतीय राज्य-क्षेत्र में पैदा हुआ हो, अथवा

(भा) जिसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय क्षेत्र में पैदा हुये हो, अथवा

(इ) जो ऐसे आरम्भ के तत्काल पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारतीय क्षेत्र में सामान्यतः रहा हो, भारत का नागरिक होगा ।

अनुच्छेद ६ उन व्यक्तियों की नागरिकता से सम्बन्धित है जिन्होंने पाकिस्तानी क्षेत्र से भारतीय क्षेत्र में प्रव्रजन किया हो । अनुच्छेद ६ में यह व्यवस्था की गई है कि कोई व्यक्ति जो अथवा जिसके पिता अथवा पितामहों में से कोई एक ने भारत में जन्म लिया हो तथा जिसने भारत से बाहर किसी देश में जन्म लिया हो, भारत का नागरिक समझा जायगा यदि वह जिस देश में वह रह रहा हो वहाँ के भारतीय राजनयिक (diplomatic) अथवा वाणिज्यिक (consular) प्रतिनिधि द्वारा उनको आवेदन प्रपत्र देने पर भारत का नागरिक पंजीकृत कर दिया गया हो । अनुच्छेद ६ में यह उल्लिखित है कि कोई भी व्यक्ति जिसने विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, भारतीय नागरिक नहीं रह सकता ।



१९५५ के नागरिकता अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के ढङ्गों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान लागू होने के उपरान्त नागरिकता प्राप्त करने के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं :—जन्म (birth), वंशक्रम (descent), पंजीकरण (registration), देशीयकरण (naturalisation) और राज्य-क्षेत्र का विनियोग (incorporation of territory)। धारा ३ के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो कि २६ जनवरी १९५० को या उसके बाद भारतवर्ष में पैदा हुआ है, वह यहाँ का जन्म से नागरिक होगा। धारा ४ के अन्तर्गत वह व्यक्ति जो २६ जनवरी १९५० को या उसके बाद भारत की सीमा के बाहर पैदा हुआ है, यदि उसका पिता जन्म के समय भारतीय नागरिक होगा, तो वह भी वंशक्रम से भारत का नागरिक कहा जायेगा। धारा ५ के अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त करने के आशय का आवेदन प्राप्त करके प्राधिकृत अधिकारी उसे भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण कर सकता है, जो कि संविधान की प्रतिष्ठा के अनुसार वास्तविक रूप में नागरिक न हो या नागरिकता सम्बन्धित किसी अधिनियम के अन्तर्गत न आता हो। धारा ६ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार समुचित रूप से आवेदन करने पर प्रार्थी को देशीयकरण का प्रमाण-पत्र दे सकती है यदि वह तीसरी अनुसूची (Third Schedule) की व्यवस्थाओं के अनुसार हो। अन्तिम रूप से धारा ७ में यह व्यवस्था है कि यदि कोई राज्य-क्षेत्र भारत का भंग बन जाता है, तो केन्द्रीय सरकार यदि चाहे तो आफिसियल गजेट के नोटिफिकेशन के आधार पर आवेदन निर्गत कर सकती है कि कौन से व्यक्ति उस क्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारण भारत के नागरिक माने जायेंगे।

**राष्ट्रीयता का लोप होना (Loss of Nationality) :**—प्रोपेनहेम के मतानुसार राष्ट्रीयता का पाँच प्रकार से लोप हो सकता है जो निम्नलिखित हैं :—

१—विमुक्ति (Release) :—कुछ राज्य जैसे जर्मनी अपने नागरिकों को राष्ट्रीयता से मुक्त करने की प्रार्थना करने का अधिकार देते हैं।

२—घंचित करना (Deprivation) :—कुछ राज्यों ने कुछ नागरिक विधियाँ बनाई हैं जिनका उनके नागरिकों द्वारा भंग किये जाने के परिणामस्वरूप उनकी राष्ट्रीयता छीन ली जाती है।

३—समाप्ति (Expiration) :—कुछ राज्यों में ऐसा विधान है कि दीर्घकाल तक बाहर रहने के कारण नागरिकता समाप्त हो जाती है।

४—त्याग (Renunciation) :—शिशुओं की दुहरी राष्ट्रीयता की स्थिति में कुछ राज्यों (प्रेट ब्रिटेन) की नागरिक विधि उनको अधिकार देती है कि वग्न

होने पर वे घोषित करें कि क्या वे उनमें से किसी एक राज्य का नागरिक होना समाप्त करना चाहते हैं ।

५—प्रतिस्थापन (Substitution) :—कुछ राज्यों की विधि के अनुसार उनकी प्रजाओं की नागरिकता उनके बाहर नागरिकता अर्जन करने के कारण समाप्त हो जाती है ।

भारत के संविधान में निम्नलिखित दो दशाओं में नागरिकता के अन्त होने की व्यवस्था की गई है—

(१) कोई व्यक्ति जो पहली मार्च सन् १९४७ के उपरान्त भारत के राज्य-क्षेत्र से पाकिस्तान के राज्य-क्षेत्र को प्रजनन कर गया हो, भारत का नागरिक नहीं समझा जायेगा (अनुच्छेद ७) ।

(२) ऐसा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण कर ली हो (अनुच्छेद ८) ।

१९५५ के भारतीय नागरिकता अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकता की समाप्ति और उसके छीन लिये जाने की भी व्यवस्था है । उसके लिए विशेष परिस्थितियाँ उत्तरदायी होंगी । अधिनियम की धारा ८ के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि कोई भारतीय नागरिक जो कि वयस्क हो चुका हो, और जो किसी दूसरे देश का भी नागरिक या राष्ट्रीय है, यदि भारतीय नागरिकता छोड़ने की समुचित रीति से घोषणा करता है, तो उसका पजीयन समुचित प्राधिकारी करेंगे और उस पजीयन के पश्चात् ऐसे व्यक्ति भारत की नागरिकता से वंचित मान लिये जायेंगे । धारा ९ के अन्तर्गत भारत का कोई नागरिक जो कि देशीयकरण, पजीयन या विलय के आधार पर दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, या २६ जनवरी १९५० से अधिनियम लागू होने की तिथि के बीच स्वेच्छया दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो इस प्राप्ति पर परिस्थिति के अनुकूल वह भारत का नागरिक नहीं रह जायेगा । धारा १० के अन्तर्गत कोई भारतीय नागरिक देशीयकरण या संविधान की किसी व्यवस्था के आधार पर यदि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा इन धाराओं के अन्तर्गत नागरिकता के अधिकार से वंचित किया गया है, तो भारत का नागरिक नहीं माना जायेगा ।

राष्ट्रहीनता (Statelessness)—राष्ट्रहीनता की समस्या न हाल में राष्ट्रीयता सम्बन्धी विधियों में परस्पर विरोध होने के कारण कुछ प्रमुखता प्राप्त कर ली है । कुछ ऐसे भी मामले हुए हैं जिनमें कुछ राज्यों के राष्ट्रीय जनों के अपने देश में वापस न हो सकने पर उन्होंने अपनी राष्ट्रियता खो दी है । अगणित

ने क्रान्ति के बाद अपनी राष्ट्रीयता खो दी क्योंकि वे रूस के लिए सीटने को इच्छुक नहीं थे ।

न्यायाधीश रसल ने स्टोयेक बनाम पब्लिक ट्रस्टी [ *Stoeck v. The Public Trustee* (1921) 2 Ch 67 ] वाले मामले में यह कहा था कि राष्ट्रहीनता एक दशा है जिसे अंग्रेजी विधि स्वीकार करती है । उन्होंने ओपेनहेम के निम्न लिखित कथन को अनुमोदन करते हुए उद्धृत किया—

“कोई व्यक्ति जानते हुए भयवा बनजाने, इच्छापूर्वक भयवा अपने किसी दोष के बिना राष्ट्रहीन बनाया जा सकता है ।”

ओपेनहेम राष्ट्रहीनता की बहुत सी स्थितियाँ बतलाते हैं । उनका कहना है कि जन्म से भी व्यक्ति राष्ट्रिकताहीन हो सकता है । इस प्रकार एक जारख सिगु जो जर्मनी में एक अंग्रेजी माँ से पैदा हुआ हो वास्तव में राष्ट्रीयतारहित है क्योंकि न तो वह जर्मन विधि के अनुसार जर्मन राष्ट्रीयता प्राप्त करता है और न ब्रिटिश विधि के अनुसार ब्रिटिश राष्ट्रीयता । और भी यह कि सब बच्चे जो जर्मनी में ऐसे माता-पिता से पैदा हो जो राष्ट्रीयतारहित हो जर्मन विधि के अनुसार स्वयं राष्ट्रहीन हैं । जन्म के बाद भी राष्ट्रहीनता हो सकती है अर्थात् राष्ट्रीयता के छीन लिये जाने पर । सब व्यक्ति जिन्होंने अपनी मौलिक राष्ट्रीयता बिना दूसरी राष्ट्रीयता प्राप्त किये खो दी है, वास्तव में राष्ट्रीयतारहित हैं । इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्रीयता विरोध विधि सम्बन्धी सन् १९३० हेग अभिसमय में राष्ट्रहीनता की दशा को समाप्त करना चाहते थे किन्तु उसमें दी गई व्यवस्थायें अधिक सहायक सिद्ध नहीं हुईं क्योंकि राज्यों ने उनको स्वीकार नहीं किया ।

वह राज्य जिसके अन्तर्गत ऐसे राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति निवास करते हैं, यदि उनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो उनसे देशीकरण के लिए भावेदन-पत्र देने के लिए अपेक्षा कर सकता है भयवा उन्हें देशत्याग करने के लिए निदिष्ट कर सकता है । जो राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति किसी देश के नहीं हैं और कोई राष्ट्रीयता नहीं रखते हैं उनसे वे लान छीन लिये जाते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार किसी राज के नागरिक को प्राप्त होते हैं ।

mission) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । यह विवाद ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के बीच उठा था । उसमें यह कहा गया कि संयुक्त राज्य की कांग्रेस ने मार्च २, १६०७, को देश-निकाले के अधिकार को सामान्य रूप से स्वीकार किया है । देश-निकाले का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है ।

## अध्याय १८

### क्षेत्राधिकार से सम्बद्ध प्रत्यर्पण

#### (Extradition connected with Jurisdiction)

इसकी आवश्यकता :—जहाँ कोई व्यक्ति एक देश में अपराध करके दूसरे में भाग जाय तो दूसरे देश का उसके सम्बन्ध में क्या कर्तव्य है ? क्या शरण देने वाले को उसे अपने ही न्यायालयों में अपनी ही विधि के अनुसार विचार करना चाहिए अथवा उसे उस देश को समर्पण करना चाहिए जिसकी विधि की उसने भग किया हो ? अन्तर्राष्ट्रीय विधि इस सामान्य प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं देती । राज्यों की सार्वभौमिक रीति यही रही है कि भागे हुए अपराधियों को केवल उसी दशा में समर्पित किया जाय जब भागने वाले देश के साथ कोई विशेष सन्धि हो और अब बहुत कम विधि-वेत्ता इसे सामान्य अथवा सम्पूर्ण कर्तव्य बतलाते हैं । यह सन्धि के अनुसार तथा नियमानुसार भाग के अनुवर्तन में समर्पण प्रत्यर्पण के नाम से प्रसिद्ध है ।

परिभाषा :—प्रत्यर्पण एक राज्य द्वारा अन्य राज्य को उस व्यक्ति का समर्पण है जो उस राज्य के क्षेत्र के भीतर पाया जाय तथा जो अन्य राज्य के प्रदेश के भीतर किसी अपराध करने का दोषी ठहराया गया हो अथवा जो अन्य राज्य के प्रदेश के बाहर अपराध करे तथा उसकी प्रजा हो और ऐसी दशा में उसकी विधि के अनुसार उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्तरदायी हो ।

प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों की सम्मतियाँ :—

लॉरेंस (Lawrence):—लॉरेंस ने प्रत्यर्पण की परिभाषा निम्न की है:—

Extradition is the surrender by one state to another of an individual who is found within the territory of the former, and is accused of having committed a crime within the territory of the latter, or who, having committed a crime outside the territory of the latter, is one of its subjects and, as such, by its law amenable to its jurisdiction.

**ओपेनहेम (Oppenheim) :**—ओपेनहेम के अनुसार "Extradition is the delivery of an accused or a convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of, a crime, by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be."

**स्टार्क (Starke) :**—स्टार्क प्रत्यर्पण की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि प्रत्यर्पण को हम वह समर्पण कहेंगे जो कि एक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में है, जो कि पर एक राज्य द्वारा अपराध करने का आरोप है, भले ही यह अपराध सरण लेने वाले राज्य-क्षेत्र में किया गया हो, अथवा उसके अपने राज्य-क्षेत्र में या कहीं अन्यत्र। (Extradition is "the surrender of a person accused or convicted of a crime by the state in the territory of which he has taken refuge to the state in whose territory the crime has been committed or which has convicted him of the crime.")

**कठिनाइयाँ :**—प्रत्यर्पण के सम्बन्ध में दो व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण इस विषय पर एक समान नियम के विकास में बाधा पड़ती है। वे हैं विभिन्न देशों द्वारा ग्रहण की गई अपराध की परिभाषाओं में विभेद तथा प्रत्यर्पण सम्बन्धी प्रक्रिया का ऐसे व्यक्ति के पकड़ाने के सम्बन्ध में उपयोग करने की संभावना जो कि उसके देश के द्वारा वास्तव में न कि किसी सामान्य अपराध के लिए बल्कि राजनैतिक अपराध के लिए चाहा जाता हो। आधुनिक राज्य प्रायः बिना हेर-फेर के राजनैतिक लक्षण के अपराधी को प्रत्यर्पण विधि के प्रभाव से अलग करते हैं।

यह अब सामान्यतः स्वीकार किया जाता है कि प्रत्यर्पण एक शिष्टाचार का विषय है न कि अधिकार का। प्रत्येक राज्य सन्धि की शर्तों का सहारा लेता है और उनके अभावों में उसको अधिकार होता है कि भागे हुए व्यक्तियों का प्रत्यर्पण इन्कार कर दे और उनकी क्षेत्रीय सर्वोच्चता की दृष्टि से भाष्य देना भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम, सन् १९०३ में सच सरकार के लिए यह प्रक्रिया अनुबन्धित की गई है कि वह भागे हुए अपराधियों को मजिस्ट्रेट द्वारा को गई जाँच के आधार पर अपना समाधान करके कि अधिवासन (Requisition) के समर्थन में प्रयत्न द्वाड़े में मामला प्रतीत होता है, भागे हुए अपराधियों को प्रत्यर्पण कर सकती है। यदि अपराध राजनैतिक रूप का हो तो वह भागे हुए अपराधी को पकड़ने से इन्कार कर सकती है।

**आवश्यक शर्तें**—प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक शर्तें जो सामान्यतः प्रत्यर्पण सन्धियों में मरी जाती हैं, निम्नलिखित हैं :—

(१) राजनैतिक अपराध — यदि अपराध राजनैतिक रूप का हो जिसके कि सम्बन्ध में अपराधी का प्रत्यर्पण माँगा जा रहा है तो उस भागे हुए व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जायगा । 'राजनैतिक अपराध' शब्दों को पारिभाषित करना सरल नहीं है । यह एक सूक्ष्म विषय है । इसके अर्थ के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य भिन्न-भिन्न प्रमाण ग्रहण करते हैं । कुछ अपराध का आशय ग्रहण करते हैं और अन्य विशिष्ट अपराधों को । फिर भी यह न्यायिक निर्णयों के अनुसार मान लिया गया है कि राजनैतिक अपराध होने के लिए दो या अधिक पक्षकार होने चाहिए जिनमें से प्रत्येक अपनी रुचि की सरकार दूसरे पर लादना चाहे अथवा वह उसे राज्य में जहाँ अपराध किया जाय राजनैतिक नियंत्रण के लिए यत्न कर रहा हो तथा अपराध उस उद्देश्य की पूर्ति में किया गया हो । इससे स्वभावतः भराजकता प्रचार करने वाले तथा भातक उत्पन्न करके राज्य करने वाले अलग कर दिये गये हैं । राजविप्लव का मुख्य उद्देश्य सामान्यतः विधि को अस्वीकार करना होता है । यह केवल स्थापित विधि के ही नहीं वरन् प्रत्येक प्रकार की वैध विवशता के विरुद्ध होता है । यह विधि को पूर्णतः हटा देना चाहता है और इसी प्रकार सरकारी व्यवस्था को ही अलग कर देना चाहता है । अतः भराजको का दल सब सरकारों का शत्रु है और इसके प्रयत्न मुख्यतः नागरिकों के सामान्य समुदाय के विरुद्ध लक्षित होते हैं ।

कैस्टिमोनी वाले मामले में [(1891) 1 Q. B. 149] कैस्टिमोनी ने जो एक स्विटजरलैंड का प्रजाजन था, वहाँ एक राजनैतिक उपद्रव में भाग लिया था जिसमें उसने एक नगरपालिका के सदस्य की हत्या कर दी । प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्य-वाहियों में जो स्विटजरलैंड की सरकार की ओर से प्रचलित की गई मजिस्ट्रेट ने कैस्टिमोनी का कारावास दिया और यह सम्मति प्रगट की कि उसका अपराध जो स्विटजरलैंड में किया गया था राजनैतिक रूप का नहीं था । उसने बन्दी-प्रत्यक्षीकरण लेख (Writ of habeas corpus) के लिए आवेदन-पत्र दिया जो लंडन न्यायालय द्वारा जारी किया गया । यह निर्णय किया गया कि उन कारणों में जिसमें कैस्टिमोनी ने गोली चलाई यह अनुमान करना युक्तिसंगत है कि उसने गाली इस विचार से चलाई कि इसका द्वारा उसका उद्देश्य भाग बड़ेगा और यह एक कार्य था जो उस उद्देश्य की उन्नति के लिए था, तथा इस भावना से किया गया था कि उसी उद्देश्य की युद्ध होगी जिसके लिये विप्लव हुआ था, अर्थात् उसको बढ़ाने के लिए और उस सरकार को अलग करने के लिए जिसकी वि वह साक्ष्य था कि जब तक वह उसकी जगह न ले ले, लोगो को उस स्थान पर प्रवेश करने से रोक रही थी । वीन्स बेंच डिवाइजन ने कैस्टिमोनी को यह निर्णय करके छोड़ दिया कि उसका अपराध

राष्ट्र राजनैतिक है और उसने उसका म्विटजरलैंड को प्रत्यर्पण करने का आदेश देने से इन्कार कर दिया ।

न्यूयॉर्क वाले मामले में [(1891) 2. Q. B. 415] अभियुक्त ने पेरिस के एक काफी-गृह में विस्फोट किया था । वह भराजकतावादी था । वह अपराध जिसका उसके ऊपर आरोप लगाया गया था राजनैतिक रूप का अपराध नहीं माना जा सकता था । ब्रिटिश न्यायालय द्वारा यह माना गया कि राजनैतिक रूप का अपराध होने के लिए राज्य में दो या अधिक पक्षकारों की होने चाहिये जिन्होंने प्रत्येक अपनी रुचि की सरकार दूसरे पर लादना चाहे और यह कि यदि अपराध एक पक्ष अथवा दूसरे द्वारा उस लक्ष्य की पूर्ति में किया जाय तो यह राजनैतिक अपराध है अन्यथा नहीं । इस मामले तथा वेस्टिमीनी वाले मामले के अनुपात में बड़ा फरक है । यह निर्णय स्पष्टतः पहले वाले निर्णयों के विपरीत है ।

**अटेंटाट क्लॉज (Attentat Clause) :—**यह नियम कि राजनैतिक अपराधों का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता, अपवाद के अधीन है जो अटेंटाट क्लॉज में दिया गया है और वह यह है कि विदेशी सरकार के अधिष्ठाता अथवा उनके कुटुम्ब के सदस्य की हत्या राजनैतिक अपराध नहीं है ।

(२) सेना संबंधी अपराध :—उदाहरणार्थ भाग जाना तथा धार्मिक अपराध भी सामान्यतः प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाहियों के अधीन नहीं है । नियम यह है कि तुच्छ मामलों के विषय में प्रत्यर्पण की आज्ञा नहीं दी जाती ।

(३) स्पेशैलिटी का नियम :—माना हुआ व्यक्ति जो मारा जाय, उसके प्रत्यर्पण सम्बन्धी प्रार्थना में लिखित विशिष्ट अपराध के अतिरिक्त अन्य किसी अपराध के लिये जो उसके समर्पण के पूर्व किया गया हो, उस समय तक विचारणीय न किया जायगा जब तक उसे मुक्त न कर दिया जाय तथा देश छोड़ने का अवकाश न मिले । यह स्पेशैलिटी का नियम कहलाता है ।

**United States v. Rauscher (1886)** वाले मामले में रौशर एक नाविक था और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को हत्या के आरोप पर प्रत्यर्पित किया गया । फिर भी वह संयुक्त राज्य अमेरिका में उस व्यक्ति को, जिसकी हत्या के लिये वह पहले अभियुक्त था, निर्दय तथा असामान्य दंड देने के छोटे आदेशों पर परीक्षित तथा सिद्ध-दोष किया गया । अपील पर संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने दोष-सिद्धि का खंडन किया और बन्दी को इस आधार पर मुक्त करने का आदेश दिया कि जब तक सन्धि द्वारा अन्यथा उपबन्धित न हो बन्दी केवल अपने अपराध के लिये आरोपित किया जा सकता था जिसके लिये उसका प्रत्यर्पण किया

गया हो जब तक उसे समर्पित करने वाले देश को लौटने के लिये उचित समय न दिया गया हो ।

(४) अपराध दोनों राज्यों में अपराध की परिभाषा में हो :—अपराध दोनों राज्यों में अपराध की परिभाषा में होना चाहिये । यह दुहरी अपराधिता के सिद्धान्त पर आधारित है (Eisler's case) । किसी भी व्यक्ति को उस समय तक प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जब तक उसका कार्य प्रत्यर्पण मंजूर होने वाले तथा प्रत्यर्पण माँगने वाले दोनों राज्यों के दृष्ट-विधि के अनुसार अपराध न हो ।

(५) परीक्षण के पश्चात् प्रत्यर्पण :—कोई भगवान् अपराधी जो ऐसे अपराध से दोषित हो जो उस अपराध से जिसके लिये उसका प्रत्यर्पण माँगा जा रहा है, भिन्न हो तो उसका प्रत्यर्पण उस समय तक नहीं किया जायगा जब तक वह प्रत्यर्पण माँगे जाने वाले देश में परीक्षित न किया गया हो तथा अपने दण्ड को भोग न चुका हो ।

(६) युक्तियुक्त साक्ष्य —अभियुक्त के अपराध का ऊपर से देखने में युक्तियुक्त साक्ष्य होना चाहिये । प्रार्थित राज्य अपना समाधान कर लेगा कि प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाहियों का औचित्य सिद्ध है कि नहीं, किन्तु मामले को उसके यथार्थ तथ्यों के आधार पर परीक्षण करना ऐसे राज्य के न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र के भीतर नहीं है ।

## प्रमुख मामले तथा सिद्धान्त

१. सावरकर का मामला (Savarkar's Case) —सावरकर जो एक भारतीय तथा ब्रिटिश प्रजाजन थे, पी. ऐडमो कम्पनी के जहाज मोरिया द्वारा भीषण राजद्रोह तथा हत्या की अभिप्रेरणा के आरोपों पर परीक्षण के लिये भारत का लामे जा रहे थे । अक्टूबर २५, सन् १९१०, को जब जहाज मार्तलीज के बंदर-गाह में था वह किनारे को भाग गये । फिर भी वह प्राप्तीसी पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये जिसने अपने कर्तव्य के भ्रमात्मक पालन में प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाही किये बिना ही उसका बतान में सिपुर्द कर दिया । सावरकर एक राजनैतिक अपराधी थे इसलिए फ्रांस ने यह माँग की कि ग्रेट ब्रिटेन को उसे दे देना चाहिये तथा उसका प्रत्यर्पण अन्तर्राष्ट्रीय विधि व नियमानुबूल नियमित रीति से माँगना चाहिये । ग्रेट ब्रिटेन ने यह माँग खारिज नहीं की । पक्षकारा को सम्मति से यह विषय हेग-स्थित पञ्चायत के स्थायी न्यायमन्त्र को निर्दिष्ट किया गया । पञ्चायत ने यद्यपि यह स्वीकार किया कि सावरकर को ब्रिटिश अधिकारियों को देने में अनिमितता की गई थी तथापि ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में यह राय प्रकट करते हुए निर्णय



दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में कोई ऐसा नियम नहीं था जिसके अनुसार ऐसी परिस्थितियों में उस शक्ति के ऊपर जिसकी रक्षा में बन्दी हो, उसको वापस करने का कोई कर्तव्य निर्धारित किया गया हो, इसलिए क्योंकि विदेशी अभिकर्ता द्वारा कोई गलती की गई जिसने उसे समर्पित किया ।

२. गौडफ्रे का मामला :—*Rex. v. Godfrey* [(1923) 1 K B 24] वाले मामले में शब्द 'फरार' (fugitive) व्याख्या के लिये उपस्थित हुए और लॉर्ड हिबर्ट सी० जे० ने यह कथन किया कि यद्यपि "सर्वप्रथम यह प्रतीत है कि जब कोई मनुष्य 'फरार' शब्द से सम्बोधित किया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि वह एक देश से दूसरे देश को भाग गया है । यह प्रतीत होता है कि चाहे वह मनुष्य शारीरिक रूप से उस देश में उपस्थित रहा हो अथवा नहीं, यदि उसने अपराध वहा किया हो तो 'फरार अपराधी' का आशय इसी तरह पूर्ण करता है ।

३. मुबारक अली का मामला :—*Re Government of India and Mubarak Ali Ahmad* [1 All E. R. 1060] में *Queen's Bench* ने अनुमोदन के साथ *Re. Castioni* [(1891) 1 Q B 149] का निर्देश दिया जिसमें न्यायालय ने प्रत्यर्पण इसलिये अस्वीकार किया था कि सम्बन्धित फरार व्यक्ति का अपराध (टिसीनिग्रो के कैंटन में राज-विद्रोहकारक आन्दोलन में भाग लेते हुए सरकारी सदस्य को गोली से मार देना) राजनैतिक समझा गया, लेकिन वर्तमान मामला ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित था जो बूट-रचना अथवा जाल से घातित था । यद्यपि मामले में कुछ राजनैतिक झूठ थे जिनकी जांच न्यायालय नहीं कर सकता था फिर भी यह मानने के लिये कोई कारण नहीं था कि उसका त्यागन में न्याययुक्त परीक्षण न होगा । यह कहना कि ऐसा नहीं होगा 'इन न्यायानुसार' लिए एक असम्भव स्थिति को अंगीकार करना तथा 'भारतीय न्यायालयों के निःसम्मान-जनक' होगा है ।

४. ईस्लर का मामला (*Esler's case*) —ईस्लर प्रत्यर्पण बन्दी (१९४६) में ग्रहर्ट ईस्लर एक परदेशी कम्युनिस्ट जा कि अमेरिका में कुछ हिंसा होने वाले अपराधों के लिए सिद्ध-दोष किया गया था, न्यूयार्क से पोर्लैंड को भेजा गया । वह ब्रिटिश पुलिस अफसरों द्वारा पकड़ा गया तथा बो स्ट्रीट मार्टिन के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित किया गया । ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने ईस्लर को अभिरक्षा से इन आधार पर मुक्त कर दिया कि अपराध जिसमें लिए ईस्लर अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था, अर्थात् मिथ्या मादक, इगबैड में मिथ्या मादक के

धिक क्षीर्णक में नहीं पड़ता था । यह मामला दुहरी अपराध्यता अर्थात् अपराध दोनों राज्यों का अपराध होना चाहिए इस सिद्धान्त को पुष्ट करता है ।

५. ह्या डे ला टोरे का मामला [Haya de la Torre's Case (I. C. J. Reports 1951, p 71)] — इस मामले में विक्टर रोल ह्या डे ला टोरे जो पेरूबिया का एक राष्ट्रीयजन तथा राजनैतिक नेता था, तथा जो एक सैनिक विप्लव भड़काने का अपराध के लिए आरोपित किया गया था, उसको सीमा-स्थित कोलम्बिया के राजदूतावास द्वारा आश्रय दिया गया । अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह मत प्रकट किया कि यद्यपि हवाना के अभिसमय द्वारा यह स्पष्ट निर्धारित किया गया था कि सामान्य अपराधों स्थानीय अधिकारियों को समर्पित कर दिये जाय तथापि राजनैतिक अपराधियों के सम्बन्ध में इस प्रकार का कोई कर्तव्य विद्यमान नहीं था । इसने अपने विचार को पुन व्यक्त किया कि आश्रय अनियमित प्रकार से दिया था और यद्यपि उस आधार पर पेरू उसके अवसान को मागने का अधिकारी था, तथापि कोलम्बिया शरणार्थी को प्रत्यर्पण करने के लिए बाध्य नहीं था ।

## अध्याय १६

### अन्तर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति का स्थान

#### (Place of the Individual in International Law)

पारम्परिक मत :—रूढ़िमत से प्रायः यही माना गया है कि केवल राज्य ही न कि व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि केवल उन राज्यों के सम्बन्धों को नियमित करती है जो अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार तथा कर्तव्यों के अधिकारी होते हैं । सर फ्रेडरिक स्मिथ का कथन है कि 'राज्य और केवल राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रवेश, अथवा हस्ताक्षर करने की अधिकारिता का उपभोग करते हैं और वे ही केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व का वेश धारण किये हुए हैं । "States and states alone enjoy a locus stand in the law of nations and that they are the only wearers of international personality"—Sir Fredric Smith आपेनहेम इस मत के अनुरूप यह प्रतिपादन करते हैं कि चूंकि राष्ट्रों की विधि मुख्यतः राज्यों की विधि हुषा करती है, राष्ट्रों की विधि रिपय भी साधारणतया राज्य ही हुषा करते हैं और व्यक्ति अन्तिम रूप से अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आधार होते हैं । कुछ विशेष दायित्व भी कुछ व्यक्तियों पर सौंपे जाते हैं जैसे शासकों पर, राज्य के अधिकारता पर, राजदूतों पर, और यहाँ तक कि

साधारण नागरिकों पर भी। ये दायित्व अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप होते हैं। इस सम्बन्ध में ओपेनहेम का कथन है कि विदेशी राज्य, जो कि विदेशी व्यक्तियों को ऐसे अधिकार प्रदान करते हैं, वे अपने राष्ट्र-विधि के अन्तर्गत ही ऐसा करते हैं। इसीलिए इन अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार नहीं कहा जा सकता। वे ऐसे ही अधिकार हैं जो राज्य द्वारा व्यक्ति को उन कर्तव्यों के पालन के निमित्त सौंपे गये हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत राज्यों को करना चाहिए।

यह सच है कि इन अधिकारों की पृष्ठभूमि में अन्तर्राष्ट्रीय विधि ही दुष्प्रकारती है, किन्तु इन अधिकारों की उत्पत्ति राष्ट्र-विधियों (municipal laws) से ही होती है। इसी प्रकार वे सभी कर्तव्य, जो कि राष्ट्रों की विधि के अनुसार वैयक्तिक व्यक्ति पर आरोपित होने चाहिए, उन्हें रुढ़िगत विचारों के अनुसार हम अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों की सज़ा नहीं दे सकते। उन्हें हम ऐसे ही कर्तव्य कहेंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत राज्यों पर सौंपे गये अधिकारों और कर्तव्यों के पालन के लिए उसी के अनुरूप राष्ट्रों द्वारा व्यक्तियों को सौंपे गये हैं।

ओपेनहेम के उपरोक्त विचारों को इस तथ्य द्वारा और भी बल मिल जाता है कि यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि (Statute) भी केवल राज्यों की ही अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कार्यवाही करने का दायित्व स्थिर करता है। मनुच्छेद ३४ में स्पष्टतः लिखा गया है कि "Only States may be parties in cases before the Court" अर्थात् न्यायालय के समक्ष उपस्थित किये गये विवादों में केवल राज्य ही पक्षकार होंगे।

चरम मत :—इसके विपरीत दूसरा संप्रदाय यह प्रतिपादन करता है कि राज्य केवल मस्तिष्क की कल्पना (fiction of a brain) है किन्तु विश्लेषण करने पर अन्त में केवल व्यक्ति ही है जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय ठहरता है। वह कथन वेस्टलेक ने कथन से पर्याप्त मात्रा में पुष्ट हो जाता है जो यह है कि 'राज्य के कर्तव्य तथा अधिकार उन मनुष्यों के अधिकार तथा कर्तव्य हैं जिनसे मिलकर वे बने हैं।' "The duties and rights of the States are the duties and rights of the men who compose them."—Westlake). इस मत की व्याख्या करने वाले इस अधिकार से कहते हैं कि राज्य केवल एक सत्ता है जो कि व्यक्तियों के अधिकारों के बचाव तथा सुरक्षा के लिए बनी है जिनसे मिलकर वे स्वयं बनी हुई हैं। इसका व्यक्तित्व भी उन्हीं व्यक्तियों के व्यक्तित्व का योग है। यह मत अन्तर्राष्ट्रीय विधि की उस नई विचारधारा के प्रकाश में अधिक उद्भूत प्रतीत होता है जो व्यक्तियों पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है।

हान्स केल्सन (Hans Kelsen) के अनुसार, "सभी विधियों की तरह, अन्तर्राष्ट्रीय विधि भी मानवीय आचरण का नियम है। ( Like all law, International Law, too, is a regulation of human conduct ) । वे केवल मनुष्य ही होते हैं जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि लागू होती है और वे मनुष्य ही होते हैं जिनके विरुद्ध अनुज्ञाएँ जारी की जाती हैं। अगर अन्तर्राष्ट्रीय विधि कर्तव्यों, दायित्वों और अधिकारों को आरोपित करती है, तो ये कर्तव्य, ये दायित्व और ये अधिकार केवल मानवीय आचरण की ही अपेक्षा करते हैं। ऐसा कर्तव्य, जो कि किसी व्यक्ति का कर्तव्य न हो, उसे हम किसी भी प्रकार वैध कर्तव्य नहीं कह सकते। ऐसा दायित्व जिसमें किसी प्रकार की ऐसी अनुज्ञा न हो जिसे मनुष्यों द्वारा पूरा करना हो, या जो मनुष्यों के ऊपर लागू न होती हो, उसे हम वैध दायित्व (legal responsibility) भी नहीं कह सकते।

पी० एम० ब्राउन (P M. Brown) ने तो यहाँ तक लिखा है कि "The most serious error committed by the defenders of International Law has been found in their parrot-like reaffirmation that it applies only between sovereign States." अर्थात् वह इस बात को एक बहुत बड़ी ग़लत मानता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि केवल प्रभुता-संपन्न राज्यों का विषय माना जाय।

लौटरेपैट (अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा मानवीय अधिकार, १९५० संस्करण, पृष्ठ ६६ तथा ७०) (International Law and Human Rights (1950 Ed pp 69-70) इस मत का खंडन करते हैं कि केवल राज्य ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं। उनका कथन है कि "अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में राज्य की ओर से अखंड अनन्यता का दावा उस समय सही था जब व्यक्ति के हितों की वास्तविकता तथा अन्योन्याश्रयत्व का राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर निकलना आजकल की तुलना में कम स्पष्ट था। महाबाद का तथ्य है जो इस बात को समझता है कि क्यों व्यक्ति के अधिकारों की परिधि का निरंतर विकास जो वैध विकास का एक निरंतरावामी लक्षण है राज्य की सीमाओं पर रुक नहीं सकता।

संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि में अन्य परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यक्ति ने एक स्थिति तथा प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। अब यह विषय अन्तर्राष्ट्रीय दया के स्थान में अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार का विषय है क्योंकि चार्टर तथा अन्य स्थानों में समाविष्ट अन्तर्राष्ट्रीय विधि जहाँ तक व्यक्ति के मूलमूल अधिकारों को राज्य की विधि के अनाश्रित स्वीकार करती है वहाँ तक यह व्यक्ति को राज्यों की विधि का विषय बना देती है।

राज्य तथा व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय-वस्तु (States and individuals subjects of International Law) :—एक तीसरी विचारणा है जिसके अनुयायी अधिक सख्या में होते जा रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय हैं किन्तु व्यक्ति भी वही स्थान ग्रहण कर सके हैं जो राज्यों का अन्तर्राष्ट्रीय विधि के समक्ष है। फेनविक (Fenwick) का मत है कि, 'इन तथ्यों के बीच यह कहना गलत होगा कि व्यक्ति किसी प्रश्न तक अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विषय नहीं है। खासतौर से सारमूत विधि (substantive law) के सम्बन्ध में तो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। जहाँ तक प्रक्रियात्मक विधि (procedural law) का सम्बन्ध है, जब कि व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रवर्धन के लिए अपने राज्य की ओर देखता है, तो प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात् ऐसे भी हृदयान्वित हैं जब कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मशीनरी बनायी गई है।'

श्वरजेनबर्जर (Schwarzenberger) के अनुसार 'यह कहना एक विरोधाभास होगा कि व्यक्ति, जो कि राष्ट्रीय समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समाज, दोनों का आधार है, उसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि का केवल एक लक्ष्य मान लिया जाए' (It may be considered paradoxical that the individual, the basis both of national communities and of international society, should be merely an object of International Law.)

रूस वालों का मत :—उपर्युक्त मत सयुक्त समाजवादी सोवियत प्रजातंत्र द्वारा नहीं ग्रहण किया जाता। उनके दार्शनिक विचार बिल्कुल ही भिन्न हैं। उनके अनुसार राज्य की कर्मण्यताओं को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है। प्रायः व्यक्ति का निषेध ही कर देते हैं। सयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के विधि-वेत्ता की क्षमता में रूप के एम० बी० एम० कोरेत्सकी ने प्रदर्शित रूप से यह घोषित किया था कि उनका देश इस मन से अपने को विमुक्त रखता है कि व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय है।

मन्वि-अनुबन्ध (Treaty Stipulations) :—व्यक्तियों के अधिकारों के मरक्षण के लिए राज्यों के बीच में प्रायः मन्वियाँ की जाती रही हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने डेनज़िग के न्यायालय के प्रद्वितीय क्षेत्र [Jurisdiction of the Court of Danzig] (1921) P. C. I. J. Series B. No. 15 में यह अधिकृत रूप से निर्धारित किया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का आशय मविदाकर्ता पञ्चवारों के आशय के अनुसार यह ही सत्यता है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा कुछ निश्चित नियम प्रणयित किये जायें जिनके द्वारा वैयक्तिक अधिकारों का उत्तम उद्गम हो जो राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त किये जायें।

**नूरेंबर्ग परीक्षण (Nuremberg Trial)**—नूरेंबर्ग के अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत किया हुआ निवेदन विचार के लिए आया। निवेदन यह था कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि सर्वोच्च सत्ताधारी राज्यों से सम्बन्धित है, और उसमें व्यक्तिगत रूप से दंड की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और यह कि जहाँ विवादपूर्ण कार्य राज्य का कार्य हो वहाँ वे जिन्होंने उसे कार्य रूप में परिणत किया हो, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं हैं वरन् वे, राज्य की सर्वोच्च-सत्ता से संरक्षित हैं। न्यायाधिकरण ने इन दोनों निवेदनों को अस्वीकार किया और घोषित किया कि यह बात कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि व्यक्तियों तथा राज्यों पर कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व सौंपती है बिरकाल से स्वीकृत है।

वेब्स पॉर्टे क्विरिन [ *Ex Parte Quirin*, (1942), 317 U. S. 1 ] के विवाद में संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश स्टोन ने कहा है कि :—

“अपने इतिहास के भारम काल से ही इस न्यायालय ने युद्ध की विधि को राज्यों की विधि के उस भाग को सम्मिलित करते हुए लागू किया है जिसमें युद्ध के संचालन, शत्रु-राज्यों तथा शत्रु-व्यक्तियों की स्थिति, अधिकार तथा कर्तव्यों के लिए नियम निर्धारित किये गये हैं।

“व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन के लिए दंडित किये जा सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध अपराध व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं न कि भाववाचक सत्ताओं द्वारा, और केवल व्यक्तियों को जो ऐसे अपराध करते हैं दंडित करने से ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उपबन्ध प्रवृत्त किये जा सकते हैं।

“इसके विपरीत चार्टर का निष्कर्ष ही यह है कि व्यक्तियों के अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य होते हैं जो अलग-अलग राज्यों द्वारा लगाये गये होते हैं और राष्ट्रीय कर्तव्य से बढ़ कर होते हैं। युद्ध की विधियों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति राज्य के अधिकार के अनुसरण में कार्य करने से मुक्ति नहीं पा सकता, शर्त यह है कि राज्य कार्य को प्राधिकृत करने में अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा दी गई क्षमता के बाहर जाता है।”

प्रोफेसर ग्रीन का विचार है कि नूरेंबर्ग न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में जो कि मेजर नाजी युद्ध अपराधियों के सम्बन्ध में था, जो विचार प्रकट किया था वह वर्तमान प्रगतिशील भावनाओं की अपेक्षा रुढ़िगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि की धारणाओं से अधिक निकट था। न्यायाधिकरण ने घोषणा की थी कि “to constitute crimes against humanity, the acts relied on before the outbreak of war must have been in execution of, or in connection with, any

crime within the jurisdiction of the Tribunal." जब कि निर्णय में इस विषय का पूरा विवरण दिया गया कि जर्मनी की सरकार ने अपने राष्ट्रीय जनों में से एक बहुत बड़ी सख्या के साथ जो भी उचित अथवा अनुचित व्यवहार किए थे, अभियुक्तों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे जर्मनों के विरुद्ध बुरे व्यवहार का अपराधी ठहराया जा सके। इसके लिए आवश्यक था कि यह सिद्ध किया जाता कि वैसे व्यवहार युद्ध-अपराधों के अभिन्न अंग हैं। यहाँ तक कि (१) 'डॉक्टर के परीक्षण' (The Doctor's Trial, Annual Digest, 1947, p 296) और (२) फ़िल्ड मार्शल मिलच के परीक्षण (The Trial of Field Marshal Milch) में भी यह हदविगत अन्तर्राष्ट्रीय विधि की बात नहीं जिससे जर्मनी के नागरिकों के प्रति अपराध करने के अपराधियों के विरुद्ध परीक्षण करने का अधिकार सैनिक-न्यायाधिकरण को दिया गया। जर्मनी के शर्तहीन समर्पण कर देने के कारण और कंट्रोल कौंसिल ला न० १० के कार्य-रूप में आ जाने के कारण, सभी उद्देश्यों से यह न्यायाधिकरण एक जर्मन-म्युनिसिपल न्यायाधिकरण ही रह गया था, जिसने विजेता राष्ट्रों द्वारा निर्धारित जर्मनी की राष्ट्रविधियों का ही प्रवर्तन किया था।

जनवध अभिसमय (Genocide Convention) — जनवध का अभि-समय जो कि अपराधों को रोकने एवं दब निर्धारित करने के प्रसंग में था ९ दिसम्बर, १९४८ को संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इससे व्यक्तियों पर सीधा अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व आकर टिक जाता है, क्योंकि इससे इन व्यक्तियों को दब देने की व्यवस्था की गई है जो जनवध के कार्यों के अपराधी ठहराये जायेंगे—भले ही वे व्यक्ति सवैधानिक रूप से उत्तरदायी शासक हों, पब्लिक आफिसर हों, अथवा वैयक्तिक व्यक्ति हों। (मनुच्छेद ४)। यह निर्धारित किया गया है कि जनवध को देशनिकाले के प्रसंग में एक राजनीतिक अपराध के रूप में व्यवहृत नहीं किया जायेगा। अभिसमय के अन्तर्गत, राज्यों ने स्वीकार किया कि जनवध तथा जनवध के कृत्यों के लिए पड़्यन्त राष्ट्र न्यायालयों द्वारा दब निर्धारित करने के लिए विचाराधीन होंगे, अथवा इन पर बिना अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय भी कर सकेंगे। किन्तु यहाँ यह उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि उन मनुष्यों का जिन पर आक्रमण किया गया है, अपनी ओर से पड़्यन्तकारियों या आक्रमणकारियों पर मुकदमा चलाने या दावा करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

अटलांटिक चार्टर—१९४१ के अटलांटिक चार्टर में मानवीय स्वतन्त्रता के चार आधारभूत सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया था भय से स्वतन्त्रता (freedom from fear), कमियों से स्वतन्त्रता (freedom from want), भाषण की स्वतन्त्रता

(freedom of speech) और पूजा की स्वतन्त्रता (freedom of worship) । इन सिद्धान्तों ने पूर्व मान्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि की उस मान्यता को तोड़ दिया कि केवल प्रभुता-संपन्न राज्य ही इसके विषय हो सकते हैं । इन सिद्धान्तों ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि में एक नवीन व्यक्ति 'a new person' को लाकर खड़ा कर दिया—जिसे हम मनुष्य कहते हैं । अब यह अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य हो गया कि 'the State is an instrument to serve the people and not an end for man to serve' अर्थात् राज्य साधन है, साध्य नहीं ।

**संयुक्त राष्ट्र (United Nations).**—संयुक्त राष्ट्र का चार्टर की प्रस्तावना में महत्व लीग ऑफ नेशन्स का "उच्चकोटि के सविदाकर्ता पक्षकारों" से "संयुक्त राष्ट्र सब की जनता" में परिवर्तित कर दिया गया है । इसके द्वारा मूलभूत मानवीय अधिकारों में, मानवीय व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व में तथा पुरुष और स्त्रियों के समानाधिकारों में पुनः दृढ़ निश्चय के साथ विश्वास किया गया है ।

चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म का भेद-भाव का मिटाकर सब के हितार्थ मानवीय अधिकारों तथा मूलभूत स्वतन्त्रताओं की उन्नति तथा भद्रता-वर्धनी के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति है ।

**मानवीय अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा ( Universal Declaration of Human Rights )** —मानवीय अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा द्वारा दिसम्बर १०, सन् १९४८ को स्वीकृत की गयी । इसमें नागरिक, राजनैतिक तथा धार्मिक स्वतन्त्रताओं का सारांश दिया गया है, जिनके लिये मनुष्यों ने इतने काल तक प्रयास किया है । इसमें नये धार्मिक तथा सामाजिक अधिकार, जो आज केवल धीरे-धीरे स्वीकृत किये जा रहे हैं, भी सम्मिलित किये गये हैं ।

घोषणा की प्रस्तावना "मानवीय व्यक्ति के गौरव तथा महत्व" पर विशेष बल देती है । प्रथम दो अनुच्छेद इस बात पर जोर देते हैं कि अधिकार तथा स्वतन्त्रता प्रत्येक पर तथा सब स्थानों पर लागू हैं । प्रत्येक बिना किसी प्रकार के भेद के जैसे जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक अथवा अन्य विचार, जातीय अथवा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म अथवा स्थिति-भेद घोषणा में उल्लिखित सम्पूर्ण अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं का अधिकारी है ।

अनुच्छेद ३ से १५ तक जीवन, स्वतन्त्रता, व्यक्ति की सुरक्षा, विधि के समक्ष सब स्थानों में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति तथा विधि के समान संरक्षण के अधिकारों



को वर्णित करते हैं। किसी को भी अविहित गिरफ्तारी, परिरोध अथवा निर्वासन के अधीन न किया जाय। घोषणा द्वारा दासता, यातना देना, निर्दय अमानुषिक अथवा अपकृष्टकारी दंड, गृह, कुटुम्ब अथवा पत्र-व्यवहार में अविहित हस्तक्षेप, विधि-विरुद्ध किये गये हैं। राष्ट्रीयता का अधिकार स्वीकृत किया गया है और बाधा तथा उद्बल से अन्य देशों में आश्रय ढूँढ़ने के अधिकार का विश्वास दिलाया गया है।

अनुच्छेद १६ द्वारा पूर्णव्यस्क पुरुषों तथा स्त्रियों को जाति, राष्ट्रीयता अथवा धर्म के प्रतिबन्ध के बिना विवाह करने तथा कुटुम्ब स्थापित करने के अधिकार का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद १७ द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार की गारंटी दिलाई गई है। यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी की संपत्ति अविहित रूप से उससे छीनी नहीं जायेगी। अनुच्छेद १८ तथा १९ में व्यक्ति के विचार, बुद्धि और धर्म तथा मत और भाव अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद २० और २१ में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक को शान्तिपूर्ण एकत्रित होने तथा समागम करने की, अपने देश की सरकार में भाग लेने की तथा अपने देश की सार्वजनिक सेवा में प्रवेश करने की स्वतन्त्रता का समान अधिकार है।

२२ से २६ तक के अनुच्छेद आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की घोषणा करते हैं। इनमें कार्य करने का अधिकार, व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता, समान वेतन, समान कार्य का, विश्राम तथा अवकाश का, बेकारी, अस्वस्थता, अयोग्यता, वैधर्म्य, वृद्धावस्था अथवा अन्य प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में जो कि किसी के नियंत्रण के बाहर हो, जीविका के अभाव के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार सम्मिलित है। घोषणा द्वारा यह भी स्वीकृत किया गया है कि प्रत्येक को एक जीवन स्तर रखने का अधिकार है जो उसके तथा उसके कुटुम्ब के स्वास्थ्य तथा हित के लिये पर्याप्त हो, जिसमें भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सम्बन्धी ध्यान तथा आवश्यक सामाजिक सेवाएँ सम्मिलित हैं। अनुच्छेद २६ शिक्षा सम्बन्धी अधिकार की गारंटी लेता है जो कम से कम प्रारम्भिक तथा मूलभूत अवस्थाओं में निःशुल्क तथा मानवीय व्यक्तित्व के पूर्ण विकास तथा मानवीय अधिकारों तथा मूलभूत स्वतन्त्रताओं के सम्मान की प्रारंभ लक्षित होनी चाहिये।

**घोषणा का महत्व :—**घोषणा एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर स्थापित करती है। इतिहास में प्रथम बार पृथ्वी में अधिकांश सरकारों के प्रतिनिधि इन बात पर सहमत हो गये हैं कि कोई अधिकार किसी विशेष जाति अथवा समुदाय की ही सम्पत्ति नहीं है वरन् वे प्रत्येक मानव की मानवता की सम्पत्ति हैं। समुदाय

राष्ट्र सघ न यह घोषणा की है कि लोगों को यह अधिकार इसलिये नहीं मिले हैं कि वे स्वीडन देशवासी हैं अथवा अरब हैं या ईसाई अथवा बुद्ध हैं, या इस्किमो, होटेन्टाट अथवा दक्षिणी समुद्र के द्वीपवासी हैं वरन् इसलिए कि वे मनुष्य हैं। सर्व-व्यापी घोषणा का वास्तविक अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री अपने-अपने गुणों के आधार पर योग्य सम्मान जाना चाहिये और प्रत्येक को पूर्ण तथा सुखी जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलना चाहिये।

**करण का वैध पक्ष (Legal aspect of the Instrument) :—**  
यद्यपि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य घोषणा के महत्व पर अधिकारों की घोषणा के रूप में विशेष महत्व देने में एकमत थे, फिर भी वे अपने मन में सामान्यतः स्पष्ट थे कि इसके द्वारा इसको प्रवृत्त करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस घोषणा द्वारा सदस्यों पर मानवीय अधिकारों तथा मूलभूत स्वतन्त्रताओं को जो यह सामने रखता या सम्मान करने का वैध कर्तव्य भी नहीं सौंपा गया है। घोषणा का कोई वैध करण नहीं था और न कोई वैध बाध्यकारी प्रभाव हा था। प्रोफेसर लौटरपैट (Professor Lauterpacht) का कथन है कि घोषणा उन बातों को प्रकट करती है जो समय आने पर संयुक्त राष्ट्र सघ के सदस्य-राष्ट्रा द्वारा सामान्यतः स्वीकृत तथा कार्यरूप में परिणित विधि के सिद्धान्त होना चाहिये। उनकी सम्मति में यह घोषणा सामान्य सभा के अभिस्ताव के रूप में नहीं सम्माना जा सकती क्योंकि घोषणा का प्रमुख भाग केवल “घोषणा करता है,” लेकिन संयुक्तराष्ट्र सघ के सदस्यों से यह अभिस्ताव नहीं करता कि वे इसके सिद्धान्तों का पालन करें।

**घोषणा का अप्रत्यक्ष वैध प्राधिकार :—**चार्टर की घोषणा में “सभी राष्ट्रों के सभी मनुष्यों के लिये एक सामान्य सफलता का स्तर निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग, इस घोषणा को अपने अस्तित्व में रखते हुये, इन अधिकारों और स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान की भावना रखने के लिए शिक्षित किये जा सकेंगे और राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों रूपों से उसका पालन करेंगे।”

प्रोफेसर लौटरपैट का कहना है कि यद्यपि यह घोषणा भले ही एक वैध लेख्य न हो और इसके अन्तर्गत भले ही वैध आभार न उत्पन्न होते हों, फिर भी इसका वहाँ तक अवश्य ही वैध महत्व है जहाँ तक कि वह प्राधिकारिक रूप में “अन्तर्राष्ट्रीय स्वतन्त्रताओं और मानवीय अधिकारों” की व्याख्या करते हैं। यह व्याख्या अवश्य ही एक आभार उत्पन्न कर देती है, जो कि भले ही पूर्ण अथवा अपूर्ण हो, फिर भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों पर बन्धनकारी है। उन्हीं के शब्दों में—“To say, therefore, that a document is not legally binding and that it embodies,

nevertheless, an authoritative interpretation of a legally binding instrument is to make a statement the first part of which contradicts the second." अर्थात् "यह कहना कि इस आधार पर एक प्रलेख बाध्यकारी नहीं है कि उसमें वैध बाध्यकारीकरण का निर्वचन निहित नहीं है, एक ही तथ्य के दो वचनों में द्विविधा उत्पन्न करना होगा।"

**घोषणा का नैतिक प्रभाव (Moral Force of the Declaration)**—घोषणा, जिसमें सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों ने वास्तविक रूप से एकमत होकर मत दिया, एक नैतिक प्रभाव तथा प्राधिकार है। यह सत्कार के इतिहास में एक अपूर्व वस्तु है और इसमें अन्तर्राष्ट्रीय विधि की पद्धति का आत्म है। अब एक साधारण मनुष्य की आवाज जो कुछ अधिकारों की मांग करता है जंगल में एक निःसहाय व्यक्ति के चिल्लाने के समान न होगी बल्कि यह एक आवाज होगी जिसका समर्थन सत्कार के सब लोग करेंगे और जिसका प्रतिनिधित्व इन सभी में है।

सामान्य सभा के समस्त मिटेन के प्रतिनिधि ने यह कथन किया था कि "अवश्य ही यह ऐतिहासिक अवसर है क्योंकि यद्यपि ये प्रलेख ही एक बड़ी वस्तु है तथापि इससे पूर्व कभी इतने राज्य व्यक्ति के आधारभूत तथा मूलभूत अधिकारों तथा स्वतन्त्रता सम्बन्धी अपने विचारों में संयुक्त रूप से एकमत नहीं हुए थे।"

प्रोफेसर लौटरेवेट ने प्रसंगानुकूल बहुत ही उचित कहा है कि "इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय घोषणाओं का अधिकार तथा प्रभाव राज्यों की सर्वोच्चता के त्याग की माना के सीधे अनुपात में होना चाहिये जो इससे सम्बद्ध है।" उनके अनुसार "इस प्रकार की घोषणाओं का अधिकार उसके लिए ऐसे प्राधिकार का दावा करने वाले अभिसमय से नहीं उत्पन्न किया जा सकता। घोषणा में व्यक्तियों के अधिकार स्पष्टतः प्रकट किये गये हैं। किन्तु इसने राज्यों के कर्तव्यों को निश्चित करना सदेह में रख दिया है और व्यक्ति के कोई अधिकार उस समय तक निश्चित नहीं किये जा सकते जब तक कि "उसके प्रतिरूप" राज्य के कर्तव्य स्पष्टतया परिभाषित न कर दिये जायें। कोई अधिकार उस समय तक अधिकार नहीं होते जब तक उनके प्रवृत्त करने के उपाय न दिये गये हों।

**परिणाम :—**इस घोषणा को हमें पूर्णरूप से लक्ष्य-सिद्ध नहीं कहना चाहिए। यह तो वांछित उद्देश्य की प्राप्ति का पहला कथन है। सभी मानव अधिकारों की ऐसी पूर्ण घोषणा (Complete declaration of human rights) का कार्य पूरा नहीं हुआ है जो सभी सदस्य राज्यों पर पूरी तरह बन्धनकारी रहे। फिर भी यह पहला कदम इस घोषणा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

इससे इतना तो अवश्य ही हो जाता है कि जनता के अधिकारों के सम्बन्ध में कोई वितर्क पैदा होने पर इस घोषणा से एक व्यावहारिक और महत्वपूर्ण आधार मिल जाता है। मानवीय अधिकारों के प्रवर्तन में इसी कारण इस घोषणा का अपना विशिष्ट महत्व है। संयुक्त राष्ट्र सभ इसे और व्यापक बनाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील है।

मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिए यूरोपीय अभिसमय (European Convention for the Protection of Human Rights)—सन् १९४८ के मानवीय अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा को बंध प्रवसता देने के लिये यूरोप की सभा के सदस्यराष्ट्रों ने ४ नवम्बर सन् १९५० को ऐसे मानवीय अधिकारों तथा मूलभूत स्वतन्त्रताओं का संरक्षण के लिए यूरोपीय अभिसमय पर हस्ताक्षर किये। यह पंद्रह राज्यों की सरकारों द्वारा वैध रूप से बचनबद्ध होकर मानवीय अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा में स्थापित आदर्शों पर पहुँचने की दिशा में पहला पग था। अभिसमय में दो नये वैकल्पिक वाक्य-खंड जोड़ दिये गये हैं—अपने अधिकारों के लिए प्रत्येक व्यक्ति की किसी भन्तर्राष्ट्रीय संस्था में पहुँच तथा एक भन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्था का संस्थापन जो राज्य-सरकारों के ऊपर तथा उससे बढ़कर निर्णय कर सके। यह वाक्य-खंड यद्यपि वैकल्पिक है तथापि व्यक्ति के लिये उसके मानवीय अस्मित्व की रक्षा के लिए जीवन का एक नया दृश्य सामने उपस्थित कर देता है। यह सुरक्षा उस सभी प्रकार की क्रूरताओं एवं निरंकुश शासन व विषय मिलेगी।

मानवीय अधिकारों पर यूरोपीय अभिसमय एक अपूर्ण चरण है किन्तु यह प्रगति की ओर एक बहुत बड़ा पग है। यह संयुक्त राष्ट्र सभ के मानवीय अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा से कहीं आगे बढ़ गया है। यह घोषणा अन्तिम इच्छाओं को प्रकट करने से और अधिक कुछ नहीं थी, जब यूरोपीय अभिसमय में विशिष्ट वैध अभिसमय है जो पन्द्रह सरकारों द्वारा स्वीकृत है। सबसे अधिक महत्व की नई बातें दो हैं जिनकी आशा की जाती थी कि यूरोपीय अभिसमय में रहेगी, अर्थात् अधिकार से वंचित किये गये व्यक्तियों का संरक्षण करने में समर्थ भन्तर्राष्ट्रीय अंग में सीधी पहुँच तथा भन्तर्राष्ट्रीय आधार पर एक न्यायिक संस्था का संस्थापन जो राज्य-सरकारों के ऊपर न्याय करने में सक्षम हो। दुर्भाग्यवश इस अवसर पर इन दो उपबन्धों पर एकमत से स्वीकृति प्राप्त करना सम्भव न हो सका। अतः इनमें से प्रत्येक इस अर्थ में वैकल्पिक रह जाता है कि यह अभिसमय हस्ताक्षर करने का आवश्यक परिणाम नहीं है, वरन् सम्बन्धित राज्यों की प्रकट अनुपूरक घोषणा पर आधारित है।

**अन्तर्राष्ट्रीय विधि के समक्ष राष्ट्रीयता :—**जब कभी कोई व्यक्ति किसी विदेश में घायल हो जाता है या उसे क्षति पहुँचायी जाती है, तो उसे अपनारे उपचार के लिए उस राज्य की विधियों या न्यायाधिकरण की शरण लेनी पड़ती है। यदि, किसी प्रकार, उसे अपने प्रति किये गये दुष्कृत्यों का पूरा उपचार नहीं मिल पाता, तो वह उस राज्य के माध्यम से इस उपचार के लिए प्रयत्न करता है जिसका कि वह नागरिक है और जिसके प्रति राज-भक्ति की भावना उत्पन्न होती है। राज-राज्य ऐसे उपचार की पूर्ति विरोध-प्रदर्शन (Representation), प्रार्थना (Remonstrance) या अन्य कार्यों द्वारा करता है : De Huber v. The Queen of Portugal (17 Q. B. p. 151.) इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राज्य का राष्ट्रीयजन हो। हाईड (Hyde) का कथन कि "Nationality is the relationship between a state and an individual which is such that the former may with reason regard the latter as owing allegiance to itself."

मानवीय अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा (The Universal Declaration of Human Rights) में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्रीयता का अधिकार है और उसकी राष्ट्रीयता निर्दोष ढंग पर निर्धारित की जा सकती है और न तो राष्ट्रीयता बदलने के अधिकार के अभाव में उसे बाधित किया जा सकता है (अनुच्छेद १५)। किसी विशेष राज्य की राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिये एक व्यक्ति को कुछ आवश्यक बातें पूरी करनी पड़ती हैं जैसे किसी विशेष समुदाय से उसका परिचय, जन्मस्थान, रक्त और निवास का माध्यम नै।

राष्ट्रीयता-विधि की कुछ उपमनों के सम्बन्ध में अप्रैल १९३० में हेग में सम्मेलन हुआ जिसमें निर्धारित किया गया था। उनमें स्पष्टतः लिखा गया था कि राज-राज्य का निर्णय करना कि कौन-कौनसे राज्य-जन हैं, राज्य पर ही निर्भर करता है। यह कानून अन्य राज्यों द्वारा भी मान्य होगा, क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक विधि का अंग है, और सामान्य रूप से राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में मान्य विधि के अनुरूप है। (अनुच्छेद १)।

**निदेशियों के अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण :—**राज-राज्य के अन्तर्गत निवास करने वाले व्यक्ति को एक स्वाभाविक अधिकार प्राप्त है कि वह विदेशियों की भाँति राज्य-जन में प्रवेश करने में बाध न लगे, यानी कि वह अपने देश की राज-सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दे। यह सर्व-सामान्य विधि का अंग है, क्योंकि यह राज्य की सार्वभौमिकता का अंग है।

दूसरे के सम्पर्क और एक दूसरे पर निर्भर स्वतन्त्रता के कारण प्रत्येक राज्य अपने राज्य-क्षेत्र में विदेशियों के प्रवेश के सम्बन्ध में अपना पृथक् कानून बनाता है। यदि राज्य ऐसा समझना है कि विदेशी उसके राष्ट्रीय-जनो से किसी भी प्रकार की होड़ लेने भा रहे हैं, तो वह उनके प्रवेश को पूर्णतया रोक सकता है। इसी प्रकार कोई भी राज्य उन विदेशियों को विवासित (deportation) कर सकता है जिनकी उन्न-स्थिति उसके विचार से अवाञ्छित है क्योंकि यह पूर्णतया उसकी प्रभुमत्ता से अवधित प्रश्न है।

जब कभी कोई विदेशी, किसी दूसरे राज्य-क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह उस राज्य की विधियों का दायित्व अपने ऊपर ठीक उसी प्रकार ले लेता है जैसे उस राज्य के स्वयं नागरिक लिया करते हैं। अगर वह उस राज्य में स्थायी रूप से रहने लगता है तो वह उस देश द्वारा लगाये गये टैक्सों या अन्य आभारों से अपने को मुक्त नहीं कर सकता। विदेशी राज्य का यह कर्तव्य है कि वह एक विदेशी की जान-माल की उचित ढंग से रक्षा करे और उसे उचित न्याय दे। उसे उस राज्य द्वारा सैनिक सेवा करने के लिये उस समय तक विवश नहीं किया जा सकता, जब तक कि इस आशय की अनुमति उसके देश से न ले ली जाय। दूसरी ओर मातृक देश अपने सभी नागरिकों को किसी भी समय दुनिया के किसी भी कोने से वापस बुला सकता है और अपनी सेवा में उनका उपयोग कर सकता है। एक विदेशी अपने मातृक देश द्वारा सुरक्षित रहने के अधिकार से पूर्णतया वंचित नहीं हो जाता। यह बात दूसरी है कि ऐसे हस्तक्षेप हर समय उचित और उपयोगी न हों।

कोई भी व्यक्ति अपने देश की पासपोर्ट के आधार पर छोड़ता है। पासपोर्ट एक लिखित प्रमाण है जो उस देश के संप्रभु की ओर से व्यक्ति के नाम दिया जाता है। उसका अभिप्राय विदेशी राष्ट्रों की सरकारों के अन्तर्गत उपस्थित होने से होता है। इसका उपयोग व्यक्ति की सुरक्षा के लिये किसी विदेशी नागरिक की हैसियत से किया जाता है। यह एक प्रकार की रसीद है जो कि परिचय के लिये उपयोगी रहती है। इस लेख्य प्रमाण के उपस्थित करने पर किसी व्यक्ति को विदेशी राज्य में उसी सुरक्षा का अधिकार मिल सकता है, जो वहाँ के नागरिकों को साधारणतया प्राप्त है।

प्रोफेसर एल० सी० ग्रोन का कथन है, "The minimum standard of International Law in respect of the treatment of aliens does not operate to give the alien any rights which he can exercise himself. Any infringement of this minimum standard will remain uncorrected

unless the state of which the injured alien is a national decides to take the matter up with the offending state." इसी प्रसंग में उनका कथन है कि यदि विदेशी राष्ट्र-हीन है, तो किसी ऐसी सधि के न होने के कारण कि राष्ट्र-हीन व्यक्तियों की सुरक्षा का दायित्व किस पर है, कोई राज्य इस विषय का आभार अपने ऊपर लेने के लिये विवश नहीं है।

खुले समुद्र की स्वतन्त्रता व्यक्ति की है, अथवा राज्य की :—इसमें सन्देह नहीं है कि समुद्र यातायात के लिए सभी के लिये समान रूप से खुले हुये हैं। किन्तु यहाँ 'भास्या' जल-पोत (Motor Vessel Asya) का दृष्टान्त दिया जा सकता है। मार्च २७, १९४६, को ब्रिटिश ध्वंसक द्वारा मेडोटेरेनियन सागर में जाफा के लगभग १०० मील उत्तर-पश्चिम में 'भास्या' नामक पोत देखा गया। उस पर कोई झंडा न था, बाद में उस पर टर्की का झंडा लगा दिया गया और उसके बाद फिर जीयनवाद झंडा बदलकर लगा दिया गया। वह पोत हैफा नामक स्थान में लाया गया। वहाँ इस रहस्य का उद्घाटन हुआ कि उसमें बैठे हुये ७११ यात्रियों में से किसी के पास भी पासपोर्ट नहीं था और न तो वैलेस्टाइन में प्रवेश करने के लिये उनके पास कोई यात्रा सम्बन्धित लिखित प्रमाण-पत्र था। १९४१ ई. इन्मीग्रेशन आर्डिनैन्स के सुरक्षा-संशोधन के अनुसार वैलेस्टाइन के न्यायालय में अपराधन की कार्यवाही आरम्भ की गई। 'भास्या' के मालिक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि समुद्री मार्ग सभी के लिये खुले हुये हैं, अस्तु उसके जहाज को पकड़ना एक गलत काम था। किन्तु न्यायालय इस तर्क से सहमत न हो सका। न्यायालय का निष्कर्ष था कि समुद्री स्वतन्त्रता, अन्तर्राष्ट्रीय अन्य सभी स्वतन्त्रताओं की ही भाँति व्यक्ति को प्राप्त होने की अपेक्षा राज्य को ही प्राप्त है और इसी कारण पर उस पोत की अपराधन या निन्दा (condemnation) की गई। इस निर्णय को वहाँ की प्रिवी कौंसिल की जुडोशियल कमिटी ने भी स्वीकार किया और नव विचार प्रकट किया कि किसी भी राष्ट्र की ध्वजा और प्राधिकार के अभाव में 'भास्या' समुद्र-संचालन का अधिकारी न था और इसलिए उसे गिरफ्तार कर लेने से वैलेस्टाइन की ओर से किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि का अतिक्रमण होने का प्रयत्न नहीं उठता।

व्यक्ति और अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ :—अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों में संलग्न करने वाले पक्षों में राज्य ही हुमा करते हैं और उस रूप में व्यक्ति का कोई भू-भाग नहीं है। किन्तु इस प्रसंग में भी अन्तिम हिताधिकारी व्यक्ति ही हुमा करता है। अतः ही उसके अधिकारों का प्रवर्तन राज्य-रूपी माध्यम में निहित होता है।

कारो का प्रवर्तन राज्य में निहित होने से उसके अधिकारों में कोई अन्त्योक्ति राज्य में भी उसके हित और अधिकार सुरक्षित हैं—यह रूप से अन्तर्राष्ट्रीयकरण द्वारा नियमित की जाती है।

## अध्याय २०

### राजनयिक अभिकर्ता

#### (Diplomatic Agents)

राजनयिक अभिकर्ता राजदूत होते हैं जो विदेश में उस राज्य के प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं जिसके द्वारा वे भेजे गये हैं। लॉरेन्स का कथन है कि विदेशों राज-सभाओं में स्थायी रूप से रहने के लिए राजदूतों को भेजने की रीति का आरम्भ उपयोगिता से कहीं अधिक राजनैतिक कारणों पर निर्भर है।

स्थायी दूतावासों की स्थापना प्राधुनिक सभ्यता की उत्पत्ति है। फिर भी यह प्रतीत होता है कि दूतावास पहला ही विषय था जिसकी ओर अन्तर्राष्ट्रीय विधि का ध्यान आकृष्ट हुआ। मध्ययुग में राज्यों के मध्य सम्पर्क बहुत कम रहता था। ऐसे सम्पर्क बाहर भेजे हुये राजदूतों द्वारा सम्पन्न किये जाते थे जिन्हें किसी विशिष्ट कार्य करने का भार सौंपा जाता था। उस कार्य के समाप्त होने पर वे तत्काल ही वापस आ जाते थे। स्थायी राजदूतों की भेजने की पद्धति चौदहवीं शताब्दी में इटली के बड़े-बड़े प्रजातन्त्रों में, विशेषकर वनिस में, आरम्भ हुई। फ्रांस का लुई ग्यारहवाँ (१४६१-१४८३) यूरोप में प्रथम सम्राट् था जिसने अन्य राज्यों की राजधानियों में रहने के लिये स्थायी प्रतिनिधि भेजे थे। अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क की सुविधा तथा याता-यात-साधनों की वृद्धि के कारण यह पद्धति सामान्यतः ग्रहण की जाने लगी और सत्रहवीं शताब्दी के मध्य तक राजदूतों का स्थायी निवास सामान्य हो गया। यहाँ तक कि आज प्राधुनिक स्थिति में वे गृह-सरकार तथा उस राज्य के बीच में जिसका कि उनको अभिचार पत्र प्राप्त है, बन्धुत्व के सम्बन्ध को स्थापित करने तथा उसको पुष्ट करने में एक बहुत ही प्रमुख कड़ी बन गये हैं।

स्थायी दूत-कर्म के लिए बहुत ही विशेष सन्धियों की गयी हैं जैसे १५२० में इङ्ग्लैंड के राजा और जर्मनी के प्रशासक ने बीच हुई थी। सर सेसिल हर्स्ट (Sir Cecil Hurst) का कथन है, "१६४८ की वेस्टफेलिया की संधि ने सम्प्रभुता को उत्साहित किया और यूरोपीय शक्तियों के एकाधिकार और उनमें परस्पर



राजनैतिक और व्यापारिक सम्बन्धों को बढ़ाने में आधार का काम किया, जिस पर कि राजनैतिक सम्बन्धों का पूरा ढाँचा खड़ा हुआ।" अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों को सुविधा और यातायात की बढ़ती हुई सुविधाओं के कारण यह व्यवहार और प्रयुक्त होने लगा। सत्रहवीं शताब्दी के मध्य में स्थायी निवासी दौलतपद की दर सामान्य रूप से ग्रहण कर ली गयी। आज तो स्थिति यह है कि दूतावास एक देश की सरकार और दूसरे राज्य के बीच मित्रता का सम्बन्ध बनाये रखने और उसे दृढ़ करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

१६१२ में Russian Indemnity के स्थायी विवाचक न्यायालय ने विवर प्रकट किया था, "Diplomatic channels are the normal and regular means of communication between states in their relations governed by International Law." अर्थात् राजनयिक स्रोत अन्तर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा नियन्त्रित राज्यों के बीच आवागमन या सम्बन्ध के साधारण साधन हैं।

१६६१ में राजनयिक सम्बन्धों पर वियना में एक अभिसमय (Convention) किया गया था जिसने अपने प्रतिज्ञा-पत्र में यह प्रकट किया था कि अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय राजनयिक सम्पर्कों, प्रतिष्ठाओं तथा उन्मुक्तियों के निर्माण में कि राज्यों में परस्पर मित्रता के सम्बन्धों को बढ़ा सके। भले ही वे राजनीतिक और सामाजिक रीतियों की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हों। ऐसी सुविधाओं और उन्मुक्तियों का उद्देश्य राजनयिक अभिवर्तियों को अपने राज्य के प्रतिष्ठित रूप में अधिक सफलता के साथ कार्य करने के निमित्त साधन देना है।

(Aix la-Chapelle) की कांग्रेस न उसमें एक चौथी श्रेणी जोड़ दी। वरिष्ठता के क्रम से वे श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं —

१ राजदूत-पोपदूत तथा नसियो (Ambassador, Papal Legates and Nuncios) — वे अधिकार-पत्र देने वाले सम्राट् के अथवा राज्य के अध्यक्ष के व्यक्ति तथा प्रतिष्ठा के प्रतिनिधि हैं। विदेशी राजधानी में पहुँचने पर जब वे अपना अधिकार प्रदत्त करने वाला शुद्धांकित परिचय पत्र उपस्थित करते हैं तो वे उस राज्य के अध्यक्ष का जिसके नाम अधिकारपत्र दिया गया है, सार्वजनिक रूप से दशन पाने के अधिकारी हो जाते हैं। उनको यह भी विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे राज्य के अध्यक्ष से माझात् सम्पर्क स्थापित करें। उनको “एक्सलेन्सी” करके सम्बोधित किये जाने का अधिकार है। केवल वे ही राज्य जिनको राजकीय सम्मान प्राप्त हो, राजदूत भेज सकते हैं।

धर्म क अधिकारता द्वारा जो राजनयिक दूत भेजे जाते हैं उन्हें पोपदूत (Papal Legates) या नसियो (Nuncios) कहते हैं।

२ पूरु सक्षम मंत्री तथा असाधारण दूत (Ministers Plenipotentiary and Envoys Extraordinary) — ये अपने सम्राटों अथवा राज्यों के अध्यक्ष के व्यक्तिगत प्रतिनिधि नहीं होते, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं है कि वे उनका अधिकार-पत्र प्राप्त किये होते हैं। विदेशी राजधानी में पहुँचने पर जब वे अपना परिचय-पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उनका राज्य के अध्यक्ष के साथ वैयक्तिक सायात्कार होता है। उनका राज्य क अध्यक्ष के साथ व्यक्तिगत रूप से ही, अधिकार के रूप से नहीं साक्षात्कार होता है, और वे “एक्सलेन्सी” के सम्बोधन से केवल शिष्टता के नाते सम्बोधित किये जाते हैं।

३ निवासी मंत्री (Ministers Resident) — ये सम्राटों के पास अधिकार-पत्र द्वारा राजदूत बना कर भेजे जाते हैं, और पूरु सक्षम मंत्री तथा असाधारण दूतों की श्रेणी से नीचे होते हैं। वे नम्रता की दृष्टि से भी “एक्सलेन्सी” उपाधि का उपनाम नहीं कर सकत। यह श्रेणी १८१८ में जोड़ी गई है।

४ कार्यदूत या निस्पृष्ट दूत (Charges d' Affaires) — इनको अधिकार-पत्र किसी राज्य के अध्यक्ष द्वारा किसी दूसरे राज्य क अध्यक्ष का नहीं दिया जाता वरन् एक वैदेशिक विभाग क मंत्री द्वारा दूसरे विभाग के मंत्री को दिया जाता है। विदेशी राजधानी में पहुँचने पर वे अपना अधिकार-पत्र वैदेशिक विभाग क मंत्री क समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

हालांकि (Hols Sec) अर्थात् धर्म अधिकारता द्वारा भेजे गये राजदूत, पापदूत या पोप के गेटिज अथवा नमिधायक कहे जात है। वापनवेल्ल क चन्स्या के बीच एक दूसरे के पास भेजे गये राजदूत हार्ड कमिशनर कहे जात हैं।

राजनयिक कार्यकर्ताओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के मध्य का अन्तर केवल शिष्टाचार मात्र है क्योंकि वे सब एक ही प्रकार की राजनयिक मुक्तियों का उन्मूलन करते हैं।

राजनयिक अभिकर्ताओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों में भेद प्रायः उपचारात्मक होता है क्योंकि सभी अभिकर्ताओं को, चाहे किसी भी श्रेणी के क्यों न हो समान उन्मुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। यहाँ तक कि राजदूत का यह विशेषाधिकार है कि वह उस राज्य के प्रसाशक या सम्प्रभु अधिष्ठाता से मिलकर किसी विषय का निवारण कर ले, व्यवहारतः किसी विशेष महत्त्व का नहीं हुआ करता क्योंकि प्रवि-काश विषयों की देख-रेख वैदेशिक मामलों के मन्त्रों ही किया करते हैं।

सम्यक्ता के विकास के साथ-साथ विचारों का आदान-प्रदान, वैज्ञानिक अनु-सन्धान और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि के लिए राज्य के सम्प्रभु पदाधिकारियों का अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में बिना राजनयिक दूतों के माध्यम से सम्पर्क सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी राष्ट्र जो राजनयिक अभिकर्ताओं से लाभ नहीं उठा वह राष्ट्रों के कुटुम्ब में अपने-आप बहुत पीछे रह जाता है।

उपरोक्त के प्रतिरिक्त Commonwealth के हाई कमिश्नर, सयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, राज्यों के प्रतिनिधि और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का भी राजनयिक उन्मुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। यहाँ उन राजनीतिक व्यक्तियों में जो कि अस्थायी रूप में कुछ विशेष कार्यों के उद्देश्य से जैसे काँरोनेशन, विवाह, मृत्यु प्रत्या-का-फेन्स में, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें जो स्थायी रूप में राजदूत हैं एक औपचारिक भेद ही माना जा सकता है।

**नियुक्ति ( Appointment ) :—**अन्तर्राष्ट्रीय विधि में राजनयिक अभि-कर्ताओं के लिए कोई विशेष योग्यता स्थिर नहीं की गयी है बल्कि ही राज्यों में राष्ट्र-विधि के अन्तर्गत किसी विशेष योग्यता का निर्धारण किया गया हो। किसी व्यक्ति की राजदूत, दूत-मन्त्री अथवा कार्यवाहक दूत की नियुक्ति अधिकारिक पत्रों द्वारा जिस राज्य को भेजे जाते हैं, घोषित की जाती है। पहले अधिकारिक पत्र के Letter of Credence या lettres de Creance कहने हैं। इन पत्र में राजनयिक अभिकर्ता का नाम लिखा रहता है और उसके भेजे जान का अभिप्राय भी अंकित रहता है। दूत अपने साथ उस परिचय-पत्र का, एक प्रति शुन पत्र के रूप में और दूसरी प्रति मुहरबन्द ले जाता है। राजदूतों और मन्त्रियों के मन्त्र में यह परिचय-पत्र राज्य के सम्प्रभु प्रमुख द्वारा उस राज्य के प्रमुख को दिया जाता है जहाँ यह भेजा जा रहा है। विन्तु कार्यदूत ( Charge d'affaires ) के सम्बन्ध में यह पत्र राज्य के विदेश मन्त्री द्वारा दूसरे राज्य के विदेश मन्त्री के

नाम लिखा जाता है। राजनयिक अभिकर्ता जो कुछ विशेष कार्यों के उद्देश्य से दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं उनके पास एक अधिकार पत्र रहता है जिसे Full Powers (Pleins Pouvoirs) कहते हैं। यह अधिकार-पत्र राज्य के प्रमुख द्वारा अपने हस्ताक्षर से पत्र के रूप में दिया जाता है।

पहुँचने की विज्ञप्ति ( Notification of Arrival )—राजनयिक दूत जब अपने गन्तव्य राज्य की राजधानी में पहुँच जाता है तो वह अपने पहुँचने की विज्ञप्ति उस देश के विदेश मन्त्री के पास भेजता है और उससे प्रार्थना करता है कि उसे राज्य के प्रमुख से मिलने का समय दिया जाय जिससे वह अपना परिचय-पत्र उसे दे सके। राजनयिक अभिकर्ता अपने साक्षात्कार के समय उस राज्य के प्रमुख के समक्ष अपना सम्भाषण करता है और दास्ती का विश्वास दिलाता है। बदले में उस राज्य का प्रमुख भी उसकी नियुक्ति का स्वागत करता है और अपने देश की ओर स दोस्ती का विश्वास दिलाता है।

किन्तु दशाश्रों में राज्य इन दूत-सन्धन्धों को अस्वीकार कर सकते हैं :—

कोई राज्य किसी विशिष्ट व्यक्ति को दूत-रूप में ग्रहण करने से निम्नलिखित दशाश्रों में अस्वीकार कर सकता है .—

(१) यदि वह उस देश के सम्राट् को जहाँ वह भेजा जाय, अपने व्यक्तिगत चरित्र के कारण वैयक्तिक रूप से आपत्ति का कारण हो। उदाहरणार्थ, फ्रांस द्वारा इयूक आफ बर्किंगम को इज्जलैंड के चार्ल्स प्रथम के दूत के रूप में स्वीकार न करना क्योंकि अपनी एक पूर्वकान्क्षित यात्रा में उसने अपने को सम्राज्ञों का प्रेमी प्रकट किया था, अथवा अस्ट्रिया हंगरी द्वारा सन् १८८५ में मिस्टर कीली को संयुक्त-राज्य अमेरिका के मन्त्रों के रूप में स्वीकार न करना, क्योंकि मिस्टर कीली को छी यहूदी थी।

(२) यदि उसने अपने को अपने सार्वजनिक कथना से अथवा दूसरे रूपों में जिस क्षेत्र के लिये उसको अधिकार पत्र दिया गया हो, उस देश के लोगों अथवा सत्ताश्रों का घोर विरोध प्रकट किया हो। उदाहरणार्थ इटली द्वारा मिस्टर कीली को संयुक्त राज्य के राजदूत के रूप में सन् १८८५ में अस्वीकार करना, क्योंकि सन् १८७१ में उसने इटली द्वारा पोप की रियासतों के सत्ताजन का विरोध किया था।

(३) यदि वह उस राज्य का प्रजाजन हो जिसको वह भेजा जा रहा हो और वह राज्य जिसके नाम अधिकार-पत्र हो, उसको वे उन्मुक्तिर्पा न देना चाहे जो इस पद से सलग्न है। लेकिन यदि वह एक बार स्वीकृत हो जाय तो उसे पूर्ण राजनैतिक विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। यही बात सर हैल्डे मैकार्टनी के प्रसंग में

व्यवहार की गई जो यद्यपि एक ब्रिटिश प्रजाजन थे, फिर भी जिन्होंने सन् १८६० में सदन में चीन के राजदूत के सेक्रेटरी का कार्य किया था ।

१८६१ के वियना वनवेन्शन ने जो कि राजनयिक सम्बन्धों के लिए किया गया था निर्धारित किया है कि राजनयिक कर्मचारीगण सिद्धान्ततः उस राज्य के राष्ट्रीय होने चाहिए जहाँ से वे भेजे गये हैं । उस राज्य के राष्ट्रीयों में से भी हो सकते हैं जहाँ वे भेजे जा रहे हैं किन्तु ऐसी नियुक्ति के पूर्व उस राज्य की अनुमति प्राप्त कर लेना आवश्यक है । जिस राज्य में राजनयिक अभिर्त्ता भेजे जा रहे हैं उसे भी ऐसे राष्ट्रीय जनों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जो कि किसी तीसरे राज्य के राष्ट्रीय हैं तथा राजनयिक दूत भेजने वाले राज्य के भी राष्ट्रीय नहीं है, समस्त अधिकार हैं ।

**राजनयिक अभिर्त्ताओं की पदसंज्ञा ( Designation of Diplomatic Agents )** — राजनयिक दूतों को भेजने वाले राज्या को यह पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह किस देश को किस श्रेणी का राजदूत भेज । प्रायः यह दोनो राज्यों के करार पर निर्भर करता है । साधारणतया व्यवहार यह है कि समान कोटि के मंत्री ही आपस में एक दूसरे से भदले बदले जाते हैं ।

कामनवेल्थ देशों में जिन राजनयिक अभिर्त्ताओं को दिया गया जाता है उन्हें उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर कहते हैं । इन्हें अब राजदूत या ( Ambassador ) भी कहने लगे हैं तथा इनके सम्बोधन के लिए "Your Excellency" भी कहा जाता है ।

राजनयिक दूत भेजने वाले राज्य का प्रभुता-तत्त्व प्रमुख राजदूत को अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का पूर्ण अधिकार प्रदान कर सकता है ।

**राजनयिक अभिर्त्ता के कार्य ( Functions of Diplomatic Agent )** — राजनयिक अभिर्त्ताओं को विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं । वह अपने राज्य के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस रूप में वह विदेशी राज्य में गृह सरकार के प्रमुख हैं । उन्हें अपने सरकार की नीति की व्याख्या उस राज्य से करनी पड़ती है जिसके नाम उनको अधिकार पत्र दिया गया है तथा साथ ही और उस राज्य के मध्य सद्भावना स्थापित करना पड़ता है । यदि उनके देश किसी प्रकार से निरादर किया जाय अथवा उनका देशवासियों को हिंसा की दी जाय तो उनका कर्त्तव्य होता है कि उस विषय को तुरन्त अधिकार पत्र द्वारा राज्य के वैदेशिक मंत्री के सामने प्रस्तुत करें । सदैव वे अपने देश की नीति को यथासमय प्रत्येक रीति से बढ़ाना होता है । डॉक्टर रीस का कथन है कि

तक अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सम्बन्ध है एक राजदूत अपने देशीय राज्य में मक्षम प्राधिकारियों के लिये पारस्परिक सम्पर्क का साधन होता है ।

एक राजदूत का मुख्य कार्य इस प्रकार है—“To create in the country to which one is accredited, the greatest possible degree of understanding of one's own nation its hopes and fear, its achievements, and the objectives towards which it aspires” उसका कार्य यह भी है कि वह बड़ी ही सतर्कतापूर्वक इस बात का निरीक्षण करे कि उस राज्य में जो घटनाएँ घट रही हैं उनका अपने राज्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है । इस प्रकार की सूचना वह अपनी सरकार को भी भेजता है ।

एक राजनयिक दूत को उस राज्य में स्थित अपने देशवासियों की जान-माल की सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है ।

उसके कार्यालय में उसके अपने राज्य के प्रजाभना के जन्म, मृत्यु तथा विवाह पजीवृत किये जाते हैं । उसे अपने राज्य को अधिकार-पत्र प्रदत्त राज्य की राज-नैतिक तथा सामाजिक दशाओं के सम्बन्ध में आवश्यक पत्रादि भेजन पड़ते हैं, जिसे उसने उस राज्य के हिता में प्रभाव पड़ता हो । उसको अपने जातीयजन के प्रत्यर्पण के लिए उस देश में जब उसने कोई अपराध किया हो, अधिकार पत्र प्रदत्त राज्य के वैदेशिक कार्यालय से व्यवहार करना पड़ता है । वह पासपोर्ट जारी करता है तथा अपने देश व जातीय जन की सम्पत्ति तथा हितों का संरक्षण करता है ।

यह भाषा की जाती है कि राजनयिक अभिकर्ता उस राज्य के स्थानीय मामलों तथा अन्य आन्तरिक अथवा राजनैतिक मामलों में भाग नहीं लेगा । उसको उस राज्य में विचाराधीन किसी विधान की वाछनीयता अथवा अवाछनीयता की विवेचना नहीं करनी चाहिये अथवा अधिकार पत्र प्रदत्त राज्य को उसके आन्तरिक मामलों में अपने हस्तक्षेप द्वारा असंतुष्ट या किसी भी प्रकार से अप्रसन्न नहीं करना चाहिये ।

मोपेनहेम बहुत ही उचित रूप से दूत के कृत्यों को तीन शीर्षकों में सक्षित करत हैं—वार्ता (negotiation) अर्थात् अपने गृह-राज्य तथा विदेशी राज्य के बीच में वह मध्यस्थ का कार्य करता है (acting as a medium between his home state and the foreign state), निरीक्षण (observation) अर्थात् विदेशी राज्य में होने वाली घटनाओं पर सतर्क दृष्टि रखना तथा संरक्षण (protection) अर्थात् अपने गृह-राज्य के बाहर रहने वाले राष्ट्रीय जनो के शरीर तथा संपत्ति का संरक्षण ।

राजनयिक उन्मुक्तिया तथा उनका स्वभाव और प्रवर्तन (Diplomatic Immunities—Nature and Enforcement)। —अधिकार क्षेत्र तथा नियम क प्रयोजन के लिये कूटनीतिक राजदूत उस राज्य के क्षेत्र के बाहर समझा जाता है जिसमें वह वास्तव में है। वह उस राज्य के अध्यक्ष के समान पवित्र गिना जाता है जिनका वह प्रतिनिधि है तथा उन्मुक्तियों का उपयोग करता है जिससे वह अपने कृत्यों को कुशलता से और निर्भय के वातावरण में कर सके। उन्मुक्तियों का आधार राज्यों का सामान्य व्यवहार तथा उनकी मीन स्वीकृति है। “प्राधुनिक सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि अपरदेशीयता के सिद्धान्त को अस्वीकृत करती है, वरन् राजदूत को प्रतिनिधि के रूप में भेजने वाले राज्य के पूर्ण गौरव को स्वीकृत करने की आवश्यकता का अधिक आदर करती है। संक्षेप में राज्य अपने आपस में अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की समानता स्वीकार करते हैं तथा प्राधिकार और क्षेत्राधिकार को पूर्ण समता देते हैं।”

राजनयिक सुविधायें तथा उन्मुक्तियाँ प्रदान करने के तीन सर्व-साधारण सिद्धान्त —

( १ ) अपरदेशीयता (Exterritoriality) —अपरदेशीयता का माना यह कल्पना है कि कोई राजदूत जब कि वह किसी राज्य में रहता है उसके क्षेत्राधिकार का प्रयोग ऐसा ही होना चाहिए कि वह जैसे वहाँ उपस्थित न हो अपरदेशीयता एक ऐसी कल्पना है कि जिसकी नींव न तो कानून में है और न ही वास्तविक प्रक्रिया की कोई कार्यवाही यह सिद्ध करने में सफल न होगी कि दूतावास के पदाधिकारी और उसका भवन जो कि यदि “क” राज्य में है वह एक ऐसे राज्य-क्षेत्र में है जो राज्य के प्रश्नों की दृष्टि में विदेशी है।

( २ ) राजनयिक का प्रातिनिधिक व्यक्तित्व (Representative character of diplomat) —दूसरा सिद्धान्त राजनयिक सुविधाओं का उन्मुक्तियाँ प्रदान करने का आधार यह बतलाता है कि राजनयिक व्यक्तियों का प्रातिनिधिक होता है। किन्तु यह सिद्धान्त सर्वमान्य इसलिए नहीं है कि मन्त्रिणा को ये सुविधायें और उन्मुक्तियाँ केवल प्रातिनिधिक मामलों में ही न बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी मिली रहती हैं।

( ३ ) कार्य के हित (Interest of work) —तीसरा सिद्धान्त है कि दो राज्यों के बीच बिना किसी रुकावट के सम्बन्धों के बने रहने के लिये उन्मुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

व्यक्तिगत सुरक्षा (Personal safety) —सार्वजनिक मनो का पवित्र तथा अनुस्मरणीय माना जाता है। जो कोई उस पर आक्रमण करता है

केवल उस सम्राट् का ही अपमान नहीं करता है जिसका कि वह प्रतिनिधि है, वरन् राज्यों की समान सुरक्षा तथा उनके कल्याण को आघात पहुँचाता है । वह समस्त ससार के विरुद्ध अपराध का दोषी है ।

राजनयिक अभिकर्ता को यदि वह उसको ग्रहण करने वाले राज्य के अध्यक्ष, अध्यक्ष या स्वयं राज्य के विरुद्ध पदग्रहण करे अथवा पदग्रहण या गुप्तचर का कार्य करने के अपराध में दोषी पाया जाय अथवा आंतरिक सुव्यवस्था तथा शांति में विघ्न डाले तो निकाला जा सकता है, तथा यदि आवश्यक हुआ तो गृह-राज्य को वापस भेजने के लिये गिरफ्तार किया जा सकता है । उसी रीति पर उसे शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं होता यदि उसे अपने असंगत अथवा अनुचित आचरण के कारण किये गये प्रतिकार से कोई हानि पहुँचे ।

आपराधिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति ( Immunity from criminal jurisdiction ) — अधिकार-पत्र देकर किसी राज्य को भेजा गया राजदूत आपराधिक क्षेत्राधिकार से पूर्ण उन्मुक्ति का उपभोग करता है क्योंकि वह किसी भी भ्रम में उसके वैध प्राधिकार के अधीन नहीं समझा जाता । यदि कोई राजनयिक अभिकर्ता अपराध करे तो केवल उपाय जो अधिकार-पत्र प्रदत्त राज्य के लिये खुला है वह यह है कि इस विषय को उसके गृह सरकार को प्रतिवेदन करे तथा यह माग प्रस्तुत करे कि उसे वापस बुला लिया जाय तथा अपने देश की विधि के अनुसार दंडित किया जाय । यदि वह सन्धि-पत्र प्रदत्त राज्य को उससे देने का पदग्रहण करे तो वह उस समय गिरफ्तार किया जा सकता है जिससे उसे उचित समय पर सुरक्षित रूप से गृह को भेजा जा सके । उसे उस राज्य की विधि के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता जहाँ वह दूत बनकर आया है ।

राजनयिक अभिकर्ताओं की उन्मुक्ति प्रत्येक देश की स्थानीय विधि के अन्तर्गत होती है । इंग्लैण्ड की सामान्य विधि, सन् १९२८ की सर्वप्रमेयिणीय अभियुक्त तथा सर्वोच्च सोवियत की १४ जनवरी, सन् १९२७, की डिग्री गणनयिक अभिकर्ताओं तथा दूतमंडल के अन्य सदस्यों को विदेशी सम्राटों के प्रतिनिधि होने के नाते व्यक्तिगत उन्मुक्ति देते हैं ।

१९६१ के वियना कन्वेंशन के २६वें अनुच्छेद में, निर्धारित किया गया है कि राजनयिक दूतों को किस प्रकार आवागमन की मुक्ति देना अन्य उन्मुक्ति प्रदान की जाये । सर सिल्वेस्टर हर्स्ट का कथन है कि राजनयिक व्यक्ति को उस देश का नागरिक न माना जाना स्थानीय विधि में स्वीकार किया जाना है क्योंकि व्यक्ति का राजनयिक अभिकर्ता के रूप में किया दण्ड देना में उपस्थित उद्देश्य से होता है कि वह अपने राज्य और इस राज्य के सम्पत्तियों के



स्थापन के लिए एक कड़ी का काम करे। उसे जो सुविधायें प्रदान की जाती हैं वे केवल उन उद्देश्यों की पूर्ति की शर्तों पर प्रतिबधित हैं। अगर भेजने वाला राज सम्बन्ध-स्थापन के अलावा उन्हें अन्य कार्य सौंपता है तो उसे पहले की उन्मुक्तिों ज्यों की त्यों नहीं दी जा सकती।

**दिवानी क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति (Immunity from Civil Jurisdiction) :**—राजनयिक अभिकर्ता तथा उसके अनुचर स्थानीय क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त होते हैं। वह स्थानीय विधि तथा वैयक्तिक प्रतिबन्ध से स्वतंत्र है। उनके विरुद्ध अधिकार-प्रदत्त राज्य के न्यायालय में किसी प्रकार का कोई व्यवहार या दिवानी विवाद नहीं लाया जा सकता। वह न्यायालय में उपस्थित होने के लिये तथा पैरवी करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। किन्तु यदि वह अपने विशेषाधिकार का परित्याग कर दे तो न्यायालय उसके साथ साधारण नागरिक के समान व्यवहार करेगा।

**दूतों के कर्मचारीवर्ग की उन्मुक्ति (Immunity of Envoy's Retinue) :**—

दूत के कर्मचारीवर्ग में निम्नलिखित आते हैं :—

- (अ) दूतक्षेत्र सम्बन्धी पदाधिकारीगण तथा अन्य परिचारक।
- (आ) स्त्री, बालक तथा उसके कुटुम्ब के अन्य सदस्य जो उसके साथ रहते हों।
- (इ) उसके निजी सेवक, तथा
- (ई) हरकारे।

राजनयिक अभिकर्ता को अपने तथा अपने परिचारकों के शरीर के सम्बन्ध में पूर्ण उन्मुक्ति है। यह उन्मुक्ति अल्पतम मात्रा में प्रसारित की गई है जो उसकी स्त्री, बालक, सरकारी पदाधिकारी वर्ग, सचिवगण, दुभाषिया, नाविक तथा सैनिक सहगामी लोग, पादरी तथा नौकरो को भी प्राप्त हैं जिनका उसके आराम तथा सुविधा के लिये साथ होना आवश्यक है।

राज्य के क्षेत्राधिकार से वैयक्तिक उल्लंघनीय अधिकार दूतावास के स्वामी तथा पिछलग्गुओं को नहीं प्रसारित किया जाता।

राजनयिक अभिकर्ताओं के परिचारकों के अन्य सदस्य जैसे दूतमहल के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भी उपरिलिखित उन्मुक्तियों का उपभोग करते हैं, किन्तु ऐसे विशेषाधिकार केवल उन्हीं को दिये जाते हैं जो सरकारी हन से दूतावास से सलग्न हों।

राजनयिक अभिकर्ताओं के साथ रहने वाले तथा उन पर आश्रित उनके सम्बन्धी भी दिवानी तथा आपराधिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त हैं तथा अन्य विशेषाधिकार का उपभोग करते हैं । उनके निजी नौकरो क सम्बन्ध में अभी तक कोई नियम स्पष्टतः स्थापित नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि वे दिवानो अथवा राष्ट्रिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त हैं लकिन आपराधिक विषयो में ग्रेट ब्रिटेन का दावा है कि यदि अपराध नौकरो द्वारा राजनयिक अभिकर्ता क निवास-स्थान के बाहर किया जाय तो उन पर उस राज्य को क्षेत्राधिकार प्राप्त है ।

हरकार अथवा सदेशवाहक सरकारी तौर पर दूतावास से सम्बन्धित होने के कारण दिवानी तथा आपराधिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त हैं । उनको एक विशेष पास-पोर्ट अपने कत्तव्यों के पालन के लिए दिया जाता है तथा राज्या क बीच से निश्चय यात्रा करने का अधिकार है ।

निवास स्थान के सम्बन्ध में उन्मुक्ति (Immunity connected with residence) — राजदूत वा सरकारी निवासस्थान, असबाब, सामान, अस्तबल तथा गाड़ियाँ सहित ऐसा समझा जाता है कि माना यह सधि पत्र प्रदत्त राज्यों के बाहर स्थित है । यह पवित्र माना जाता है और स्थानीय क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त है । यह वस्तुतः सधि-पत्र देने वाले राज्य का भाग माना जाता है । अन्य शब्दों में अन्तरदेशीयता की कल्पना राजनयिक अभिकर्ता क निवासस्थान के सम्बन्ध में लागू की जाती है ।

यह उन्मुक्ति निवासस्थान के अतिरिक्त उन सभी भवना को भी धी जाती है जो राजनयिक अभिकर्ता के अधिकार में राजनयिक कार्य के लिये हो । यह उन गाड़ियों को भी लागू की जाती है जो वे अभिकर्ता अपने कृत्यों क पूरा करने में उपभोग करे । ऐसी उन्मुक्ति वा यह अर्थ होता है कि कोई पुलिस पदाधिकारी अथवा कर (टैक्स) वसूल करने वाला अपने कर्तव्यों के पालन के लिये उसके निवास-स्थान में बिना उसके सहमति क प्रवेश नहीं कर सकता ।

इस सम्बन्ध में वैटल (Vattel) का कहना है कि "the independence of the ambassador would be very imperfect and his security very precarious if the house in which he lives were not to enjoy a perfect immunity and to be inaccessible to the ordinary officer of Justice to insult it is a crime both against the State and against all other nations " अर्थात् "राजदूत की स्वतन्त्रता बहुत ही अपूर्ण होगी और उसकी सुरक्षा बहुत ही संदिग्ध होगी, यदि वह घर, जिसमें वह रहता है पूर्ण उन्मुक्ति का उपभोग नहीं करता, और वह साधारण न्याय अधिकारी के क्षेत्राधिकार के बाहर

नहीं है। उसकी अवमानना करना एक अपराध है—उस राज्य और अन्य सभी राष्ट्रों के विरुद्ध किया गया अपराध है।”

(करो) टेक्सों से छूट (Exemption from Taxes) — राजदूत उनके निवासस्थान पर लगाये गये करों को देने से उन्मुक्त हैं क्योंकि कर को प्राप्त करने वाले राज्य का उसके निवासस्थान पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। उससे भागा की जाती है कि वह नाली, प्रकाश तथा जल-सम्बन्धी करों को देगा लेकिन वह उनको देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि वह वैध कार्यवाही से उन्मुक्त है। प्रायः इस प्रकार के कर उससे नहीं लिये जाते।

माल के अभिग्रहण होने से छूट — राजदूत पर ऋणसम्बन्धी दावे नहीं किये जा सकते चाहे ये ऋण उसने दूतकर्म करने के पहले किये हो भयवा बाद में। वह गिरफ्तारी से उन्मुक्त है और उसका माल उससे अभिग्रहण भयवा कुर्ब नहीं किया जा सकता। बिकरशोक (Bynkershoek) का कथन है कि राजदूत का माल न तो ऋण देने के लिये और न सेक्यूरिटी के लिये अभिग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि वे उसके शरीर से सम्बद्ध मान जाते हैं।

यदि कोई सार्वजनिक मन्त्री व्यापार में लगा हो तो सम्भवतः उसकी व्यक्तिगत वस्तुएँ किसी दावे के उत्तरदायित्व में उसे बाध्य करने के लिये कुर्ब की जा सकती हैं।

अंग्रेजी तथा अमेरिकी न्यायालयों ने यह निर्णय किया है कि किसी राज्य नयिक अभिवृत्तियों के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही सम्भव नहीं है, तथा कोई व्यक्ति जो ऐसा करता है वह राज्य की विधि का उल्लंघन करता है तथा सार्वजनिक शांति में बाधा डालता है। फिर भी, यदि वह किसी स्थानीय न्यायालय में दावा करे तो वह न्यायालय के नियमों को पालन करने के लिये तथा यदि हार जाय तो अपील के लिये बाध्य है। [In re Suarez Suarez v. Suarez (1917) 2 Ch 131 The Amazone (1940) Probate 40, Bergman v. De Sieyes (1946) 71 F Supp 334]

उपासना का अधिकार (Right to Worship) — राजदूत को अपने होटल में अपने धर्मानुसार एक निजी मंदिर रखने का अधिकार है। उनको अपनी ही रीति पर ईश्वर की उपासना करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है, भले ही वह ख्रिस्त मर रहा हो, उसके अनुसार यह निषिद्ध हो।

यातायात की स्वतन्त्रता (Freedom of Communication) — राजनयिक अभिवृत्तियों को अपने धर्मों का उचित रूप से निमाने में समर्थ होने के लिये

यात की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। उसके सन्देश स्थानीय क्षेत्राधिकार तथा सैन्य स तीसरे देशों में भी उन्मुक्त हैं।

**उन्मुक्तियों का आरम्भ और उनकी परिसमाप्ति (Commencement and discontinuance of Immunities)** — राजनयिक अधिकारी उसी समय से उन्मुक्तियाँ प्रदान करने लगते हैं जिस समय कि वे उस राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं जहाँ वे राजनयिक उद्देश्यों से भेजे जा रहे हैं। ये उन्मुक्तियाँ उस समय तक चलती हैं जब तक कि उनका राजदूतत्व या मिशन निलम्बित नहीं कर दिया जाता। और यहाँ तक कि वह मिशन समाप्त कर दिया जाता है तो एक उचित समय तक उस समाप्ति के पश्चात् भी दूतावास उन्मुक्तियाँ और सुविधायें प्रदान की जाती हैं जिनसे वे अपना सामान आदि बाँधकर सुरक्षित ढंग से अपने राज्य वापस चले जायें।

**निष्कपट गमन का अधिकार (Right of Innocent Passage)** — अभी हाल में निष्कपट गमन क पक्ष में सम्प्रति स्थिर हो गई है। राजनयिक अभिकर्ता पूर्ण व्यक्तिगत सुरक्षा उपभोग करने के अधिकारी हैं तथा उनकी कोई हानि भयवा उनका कोई अपमान संधि पत्र प्रदत्त राज्य तथा गुप्त राज्य दोनों की हानि तथा अपमान समझा जाना है। उपरोक्त सम्प्रति *Bergman v De Sieres* [(1946) 71 F Supp 334] के मामले से पुष्ट होती है। प्रतिवादी बोलीविया का फ्रांसीसी मंत्री था। जब वह फ्रांस से बोलीविया की न्यूयॉर्क से जा रहा था तब वादी ने उस पर व्यावहारिक आदेशिका तामील की। प्रतिवादी ने अपनी उन्मुक्ति का अभिभाषण किया। यह निर्णय किया गया कि वैदेशिक मंत्री जो मार्ग में हों, चाहे वह अन्य देशों में अपने पद से आ रहा हो भयवा वहाँ का जा रहा हो एक तीसरे देश से निष्कपट गमन करने का अधिकारी है, तथा वह तीसरे देश के अधिकार क्षेत्र से उन्मुक्ति का भी अधिकारी है जो यदि वह वहाँ का निवासी होता तो उसे मिलती।

सर्व अमेरिकीय अभिसमय में जिस पर हवाना में २० फरवरी, १९२८ का हस्ताक्षर हुये, यह स्पष्टरूप से अनुवर्णित है कि राजनयिक कार्य करने वाले उस राज्य में जिसको कि वे अपने पद पर पहुँचने के लिए भयवा अपने देश में वापस आने के लिये पार कर रहे हों और जिनकी सरकारों का उन्होंने अपनी स्थिति विदित करा दी हो, उन्ही उन्मुक्तियों तथा विशेषाधिकारों का उपभोग करेंगे।

जब तीसरा राज्य उस राज्य से जिससे नाम अभिकर्ता संधि पत्र दिया गया हो, युद्ध पर हो तो स्थिति भिन्न हो जाती है। एबी दशा में यदि तीसरा राज्य

विरुद्ध राज्य के दूत को ' गरपतार ' कर ले, तो यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि को किसी प्रकार से भंग नहीं करता ।

**अस्थायी राजदूत :—**अस्थायी राजनैतिक राजदूत जिनके विशेष दूतत्व होते हैं यथा अपने राज्य का मित्र-मित्र राज्यों की कांग्रेस में प्रतिनिधित्व करना, अथवा अराजनैतिक राजदूत जिनके कृत्य शिष्टाचार के होते हैं यथा अपने राज्य का किसी दरबार में प्रतिनिधित्व करना, वे भी अपरदेशीयता, अपने शरीरों का रक्षक तथा जातीय टैक्सो तथा सार्वजनिक मांगों के सम्बन्ध में भी उन्हीं विशेष अधिकारों का उपयोग करते हैं ।

**राजनयिक मिशन की समाप्ति (Termination of Diplomatic Mission) :—**राजनयिक कार्य मित्र-मित्र कारणों से समाप्त हो सकता है । ये निम्नलिखित हैं :—

१. सन्धि-पत्र प्रदत्त करने वाले राज्य द्वारा राजदूत का वापस बुला लेना :—राजदूत सन्धि-पत्र प्रदत्त करने वाले राज्य द्वारा वापस बुलाया जा सकता है, यदि वह अस्थायी रूप से किसी गम्भीर कारण के लिए राजनैतिक सर्वपक्षीय दक्षिणी अफ्रीका संघ का भारतीय हाई कमिश्नर भई सन् १९४६ में वहाँ रहने वाले भारतीय उत्पत्ति के लोगों के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका द्वारा जातीय भेद-भाव की नीति व्यवहार किये जाने के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिये वापस बुला तिल गया था तथा हाई कमिश्नर के कार्यालय का भार एक कनिष्ठ पदाधिकारी को हटा दिया गया था । भारत तथा दक्षिण अफ्रीका के मध्य के सम्बन्धों का यह पता धागा भी संघ के भारतीय हाई कमिश्नर के कार्यालय को जुलाई सन् १९५४ से हटा कर देने से टूट गया । इस प्रकार की वापसी सम्बन्धों के टूटने का चिह्न है और दो देशों के बीच की तनावशीलता को प्रकट करता है । भारतीय सरकार ने **लेगेशन (legation)** को जुलाई १९५३ में पुर्तगाली सरकार द्वारा भारत सरकार से स्नेह के सम्बन्ध में समझौता की बातचीत चलाने से इन्कार करने के कारण विरुद्ध वापस बुला लिया ।

२. राजनयिक मिशन का प्रयोजन पूरा हो जाना :—जब दूत-वर्ग किसी विशेष प्रयोजनों के लिये होता है तो उस प्रयोजन के पूरा होने पर वह हटा हो जाता है । ये वे दूत होते हैं जो सम्मेलनों, कांग्रेसों और महोत्सवों में प्रतिनिधित्व करने के लिये भेजे जाते हैं ।

३. दो राज्यों में से किसी एक में क्रान्तिकारी परिवर्तन :—यदि किसी देश में किसी एक में क्रान्ति के कारण अस्थायी परिवर्तन होने पर अथवा उसके दो-

रामस्वरूप नयी सरकार बनने पर उदाहरणार्थ प्रजातन्त्र राज्य के राजतन्त्र में परिवर्तित होने पर अथवा इसके विपर्यय अथवा एक सम्राट् को गद्दी से उतार कर दूसरे को बैठाने पर दूत का भी अपने सरकार का प्रतिनिधित्व करना समाप्त हो जाता है और उसे एक नया परिचय-पत्र प्राप्त करना होता है ।

४. राजदूत की मृत्यु :—दूत की मृत्यु पर दूतकर्म समाप्त हो जाता है और परिचय-पत्र अपना प्रभाव खो देता है । जब एक नया दूत नियुक्त होता है तो एक नया परिचय-पत्र जारी करना होता है ।

५. दो राज्यों में से किसी एक के अध्यक्ष की मृत्यु अथवा उसके द्वारा पद-त्याग :—इस प्रकार की घटना भी दूतकर्म को समाप्त कर देती है और अपने पदों में स्थित राजदूतों को नये परिचय-पत्र बदलकर लेना पड़ता है ।

६. स्थायी मंत्री की अपने स्थान पर वापसी :—जब किसी मंत्री को मध्यवर्ती काल के लिये सधि-पत्र प्रदत्त किया गया हो तो स्थायी मंत्री के लौटने पर दूतकर्म समाप्त हो जाता है ।

७. राजनयिक अभिकर्ता के पदवी में परिवर्तन :—जब सन्धि-पत्र प्रदत्त राजनयिक अभिकर्ता की पदवी में बिना स्थानान्तरण किये वृद्धि कर दी जाय तो दूतकर्म समाप्त हो जाता है । ऐसे समय में भी एक नये परिचय-पत्र की आवश्यकता होती है ।

८. भेजने वाले तथा ग्रहण करने वाले राज्यों के बीच में युद्ध :—युद्ध के समय भी दोनों देशों में परस्पर दूतकर्म समाप्त हो जाता है तथा दूतों की अपना-अपना पासपोर्ट मिल जाता है ।

९. किसी एक राज्य का सम्मेलन अथवा संयोजन द्वारा अंत :—ऐसी वशा में दूतकर्म समाप्त हो जाता है ।

१०. भेजने वाले अथवा ग्रहण करने वाले राज्य द्वारा राजदूत का अधिकार से हटाया जाना :—किसी राजदूत का ग्रहण करने वाले राज्य द्वारा हटाया जाना अन्तिम पग है जो वह उस समय लेता है जब उसको वापस बुलाने की उसकी माँग का अनुवर्तन नहीं होता । भेजने वाले राज्य तथा ग्रहण करने वाले राज्य में मतभेद हो सकता है तथा ग्रहण करने वाले राज्य द्वारा राजदूत को पास-पोर्ट दिया जा सकता है जो उसको हटाये जाने का द्योतक है ।

११. संधि-पत्र दिये गए राज्य द्वारा वापस बुलाये जाने की माँग :—ग्रहण करने वाला राज्य किसी राजदूत को वापस बुलाये जाने की माँग प्रस्तुत कर सकता है यदि उसने अपने को उस देश की सरकार का अग्रिम बना दिया हो ।

ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जिनमें सधि-पत्र प्रदत्त राज्य ने राजदूत को राज्य के प्रति दुःखदामी आचरण अथवा आन्तरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने के कारण वापस बुलाये जाने की माँग प्रस्तुत की है।

१२. पासपोर्ट के लिये प्रार्थना :—राजनयिक अभिकर्ता द्वारा ग्रहण करने वाले राज्य के दुर्व्यवहार के कारण पासपोर्ट के लिये प्रार्थना करना दूतकर्म की समाप्ति का द्योतक है।

१३. परिचय-पत्र की अवधि की समाप्ति :—यदि परिचय-पत्र सीमित अवधि के लिये है तो राजदूत वा दूतकर्म उस अवधि के अन्त होने पर समाप्त होता है।

दूतकर्म की समाप्ति पर औपचारिकताएँ .—जब किसी दूत का रूप उसके वापस बुलाये जाने के कारण समाप्त होता है तो यदि वह राजदूत हो अथवा मन्त्री हो तो अपने राज्य के अध्यक्ष से और यदि कार्यवाहक दूत (Charged Affairs) हो तो अपने वैदेशिक मन्त्री से वापसी का पत्र पाता है। अपनी विभागा पर भी उसका उसी प्रकार का एक औपचारिक साक्षात्कार होता है जहाँ राज्य अथवा मन्त्री अपने वापस बुलाये जाने के पत्र को ग्रहण करने वाले राज्य के अध्यक्ष को तथा कार्यवाहक वैदेशिक मन्त्री को अर्पण करता है।

## अध्याय २१

### वाणिज्य-दूत

#### ( Consuls )

परिभाषा :—वाणिज्य दूत व्यापारिक अभिकर्ता होते हैं जिनको शासक राज्य अन्य राज्यों के देशों में राजनयिक अभिकर्ताओं के अतिरिक्त बनाये रहते हैं। उनका कर्तव्य अपने देश के व्यापार, नीचालन तथा अन्य सम्बन्धित विषयों पर सरक्षण है। वे उपरोक्त प्रयोजन के लिय निवासी अभिकर्ताओं के रूप में भेजे जाते हैं।

हॉल (Hall) ने वाणिज्य दूत की परिभाषा करते हुये लिखा है कि वे वे व्यक्ति होते हैं जो किसी एक राज्य द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, उनका उद्देश्य किसी राज्य में रहना होता है और उन्हें विदेशी राज्य द्वारा भी इस बात की अनुमति मिलती है कि वे वहाँ रहकर अपना राज्य के हितों को देखा करें और उन हितों

के सौजन्य से महत्वपूर्ण लाभ के कार्य करे, उनका यह कार्य प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों हो सकता है ।

**उनकी उत्पत्ति .—**उनका अस्तित्व स्थायी राजनयिक दूत-मंडल स्थापना के बहुत पूर्व से ही रहा है । उनकी उत्पत्ति की निधि पीछे मध्य युग में पहुँचती है जब इटली, स्पेन तथा फ्रांस के व्यापारी जो व्यापार के लिये मध्य सागर के किनारे बसते थे अपने एष आदिमों को उनके व्यापारिक भण्डों को पचायत द्वारा तम करने के लिये छोट सेते थे । बाद में मध्यसागर के मुसलमान देशों ने व्यापारियों की जातियों के भीतर बसने के कारण बाणिज्य दून पद्धति ग्रहण की । समय बीतने पर तथा मुसलमान युवराजों के तथा व्यापारियों के गृह-राज्यों के बीच संधि होने के परिणामस्वरूप बाणिज्य दूतों का यह कृत्य हो गया कि वे नगर में रहने वाले स्वदेशीय नागरिकों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा करें । पन्द्रहवीं शताब्दी में इटली के बाणिज्य दूतों को इंग्लैंड तथा नोदर्लैंड के बन्दरगाहों में रहने वाले इटली के व्यापारियों पर पूर्ण क्षेत्राधिकार था । सत्रहवीं शताब्दी में स्थायी राजदूत पद्धति के प्रचलित होने के कारण बाणिज्य-दूत पद्धति की महत्ता कम हो गई और इससे दीवानी तथा आपराधिक क्षेत्राधिकार के विशेषाधिकार छीन लिये गये । उन्नीसवीं शताब्दी में व्यापार तथा नौचालन की वृद्धि के कारण बाणिज्य-दूत पद्धति ने यूरोपीय राज्यों में प्रगति प्राप्त की । भिन्न-भिन्न राज्यों के बीच असह्य संधियों की गईं जिनमें उनका स्वरूप तथा कृत्य परिभाषित थे । संधियों के प्रतिबन्ध अब प्रायः समान हैं और बाणिज्य दूतों की रीति अब रूढ़ अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा अनुशासित होती है ।

**बाणिज्य दूतों की श्रेणियाँ .—**बाणिज्य दूतों की अनेक श्रेणियाँ हैं अर्थात् कौन्सल-जनरल, वाइस-कौन्सल, कौन्सुलर-एजेण्ट तथा प्रो-कौन्सल । कौन्सल-जनरल कई बाणिज्य दूतीय जिलों के अथवा एक बड़े जिले के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होते हैं तथा उनके अधीन कई बाणिज्य-दूत होते हैं । कौन्सल जो श्रेणी में उनका बाद आते हैं केवल छोटे जिलों अथवा बस्त्रों और बन्दरगाहों के लिये नियुक्त किये जाते हैं । वाइस-कौन्सल जैसा कि नाम से ही व्यक्त है कौन्सल-जनरलों तथा कौन्सलों के सहायक है । कौन्सुलर एजेंट सबसे निम्न श्रेणी के होते हैं जो कौन्सल जनरलों अथवा कौन्सलों द्वारा स्वदेशीय सरकार की स्वीकृति के अधीन नियुक्त किये जाते हैं । प्रो कौन्सल अल्पकालीन अवधि अर्थात् कौन्सल-जनरल अथवा कौन्सल की अनुपस्थिति अथवा अस्वस्थता में नियुक्त किये जाते हैं तथा कौन्सल के अपने कार्य पर लौटने के साथ उनकी नियुक्ति समाप्त हो जाती है ।



**कौन्सलों की नियुक्ति :—**बोन्सल एक विशिष्ट अधिकार-पत्र प्रया  
 मायोग द्वारा नियुक्त किये जाते हैं जिसे *Lettre de provision* कहा जाता है  
 और जा नियुक्त करने वाले राज्य के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाता है। उसे  
 ग्रहण करने वाला राज्य एक अनुमति-पत्र जारी करता है, जिसे इक्वेटर  
 (*Exequatur*) कहते हैं जिसके द्वारा वे उस राज्य में अपने कृत्य करने में समर्थ  
 होते हैं। इक्वेटर (*Exequatur*) का अनुदान उनके मायोग को पुरस्कृत  
 करता है।

**उनके कार्य :—**वाणिज्य-दूत अपने राज्य के व्यापारिक हितों की देख रेख  
 रखते हैं, अपने व्यापारियों को परामर्श देते हैं तथा उनके कामजों का निरीक्षण  
 करते हैं। उनको अपने-अपने गृह-राज्यों तथा उनको स्वीकृत करने वाले राज्यों के  
 मध्य हुई व्यापारिक संधियों का निष्पादन ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। वे जिस देश  
 का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके नागरिकों के व्यापारिक हितों की देख-भाल करते  
 हैं। वे बहुत से अन्य विविध कार्यों का संचालन करते हैं, जैसे वसीयत बिहीन मृत  
 प्रजाजनों की रियासतों का प्रबन्ध, कप्तान तथा नाविका के झगड़ों का निपटारा  
 अपने राज्य के जहाजों के स्वामियों से प्रतिवेदन प्राप्त करना, अपने अपने देश के  
 जहाजों की समुद्र में जो हानि हुई हो तथा उसके सम्बन्ध में प्रश्नों को तय करना  
 इत्यादि। उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे अपने-अपने सरकारों को उन  
 राज्य के व्यापार, उद्योग तथा कृषि के सम्बन्ध में सूचना देते रहें जिसमें वे  
 रहते हों। उनको अपने-अपने गृह-राज्यों के व्यापारियों तथा शिल्पकारों को  
 उनके व्यापारिक हितों के संरक्षण सम्बन्धी किसी भी विषय में परामर्श देना  
 पड़ता है।

वाणिज्य-दूतों को अपने अपने गृह-राज्यों के प्रजाजनों का संरक्षण करना पड़ता है  
 जो कार्य ठीक वैसा ही है जैसा कि राजनयिक अभिकर्त्ता का। उनको एक रजिस्टर  
 रखना पड़ता है जिसमें वाणिज्य द्वितीय जिलों में रहने वाले उनके अपने राज्य के  
 नागरिकों के नाम तथा पते दिये होते हैं। वे विवाह, जन्म तथा मृत्यु को पंजीकृत  
 करते हैं और इच्छा-पत्रों का भार ग्रहण करते हैं।

वाणिज्य दूतों को अपने अपने राज्यों के नौचालन की भी देख भाल करनी  
 पड़ती है। उनको अपने व्यापारी जहाजों की देख-रेख करनी पड़ती है, सकट में पड़े  
 हुये जलपोतों की सहायता करनी पड़ती है तथा जैसा ऊपर कथित है जलपोतों के  
 स्वामियों तथा उनके नाविकों के बीच के झगड़े तय करने पड़ते हैं।

वे प्रमाणित करने वाले अधिकारी के कार्यों को भी करते हैं, यथा हस्ताक्षरों  
 को सही तथा प्रमाणित करना, साक्षियों से पृच्छा करना, शपथ देना, विवाहों का

पंजीकृत करना, इच्छा-पत्रों का भार ग्रहण करना, जन्म तथा मृत्यु का पंजीकृत करना तथा दत्तक-ग्रहण की प्रमाणीकृत करना ।

**विशेषाधिकार (Privileges) :—**वाणिज्य-दूत राजनयिक अभिकर्ता नहीं हैं तथा ऐसी दशा में वे स्थानीय क्षेत्राधिकार से उन्मुक्त नहीं हैं जब तक यह बात सन्धि द्वारा स्वीकृत न कर ली जाय । वे कुछ रूढ़ विशेषाधिकारों का उपभोग करते हैं जिनके अनुसार वे स्थानीय, दिवानी तथा सम्मन्वित अपने पदोप अधिकार में किये गये कार्यों के सम्बन्ध में आपराधिक कार्यवाहियों से भी उन्मुक्त समझे जाते हैं । आपराधिक विषयों में भी उनके विरुद्ध कार्यवाही केवल गम्भीर अपराधों के लिये की जाती है । उनके पदोप पत्र तथा ग्रन्थ रक्षाग्रह प्रयानुसार अभिग्रहण किये जाने से उन्मुक्त हैं । व्यापारिक तथा वाणिज्यदूतीय सन्धियों द्वारा वे स्थानीय उप-शुल्कों तथा करों से प्रायः उन्मुक्त किये जाते हैं ।

राजदूत के समान वाणिज्य-दूत का पद राज्य के अध्यक्ष के परिवर्तन पर अथवा दोनों राज्यों में से किसी एक के सम्राट् की मृत्यु पर समाप्त नहीं होता ।

**वाणिज्य-दूत के पद का अन्त (Termination of Consular Office) :—**निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक के होने पर वाणिज्य-दूत के पद का अन्त होता है :—

(१) वाणिज्य-दूत की मृत्यु ।

(२) ग्रहण करने वाले राज्य के मान्यता-पत्र (exequatur) के वापस ले लिये जाने पर ।

(३) वाणिज्य-दूत के वापस बुला लिये जाने पर अथवा अलग कर दिये जाने पर ।

(४) भेजने वाले तथा ग्रहण करने वाले राज्यों के बीच युद्ध की घोषणा होने पर ।

दोनों राज्यों में से किसी एक के सम्राट् अथवा अध्यक्ष की मृत्यु पर वाणिज्य-दूत के पद का अन्त नहीं होता ।

भारतीय सरकार ने अपने कौन्सुलेट जनरल को गोआ से सितम्बर १९५५ से वापस बुला लिया तथा पुर्तगाल वालों के कौन्सुलेट-जनरल को बम्बई में तथा उनके भवैतनिक कौन्सुलेटों को कलकत्ता तथा मद्रास में उसी दिनांक पर अथवा उससे पहले बन्द करने को इस कारण से कहा कि भारतीय सत्याग्रहियों पर गोली चलाई गई जो कि सम्य सरकारों की प्रथा के विरुद्ध थी तथा यह नि शस्त्र तथा अहिंसक भारतीयों के विरुद्ध मर्यादाहीन तथा अमानुषिक बल-प्रयोग था ।

# अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार

अध्याय २२

सन्धियाँ

( Treaties )

संधि क्या है ?—संधि एक स्वीकारोक्ति अथवा सविदा है जो दो या अधिक राज्यों के बीच की जाती है जिसके द्वारा वे उन कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं जो उनमें से प्रत्येक के ऊपर आरोपित किये जाते हैं।

संधियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रमुख मूलधार हैं। वे पक्षकारों के मध्य के वैध सम्बन्धों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्वीकृत रूढ़ नियमों से भिन्न आकार पर निश्चित कर सकती हैं अथवा वे पूर्वस्थित अन्तर्राष्ट्रीय विधि की मूलता को पुष्टि कर सकती हैं, या उसको रूपभेदित अथवा परिभाषित कर सकती हैं।

संधि की परिभाषा कुछ विद्वानों ने निम्नलिखित ढंग से की है :—

ओपेनहेम (Oppenheim) :—“अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ सविदात्मक प्रवृत्ति के वे करार हैं जो दो राज्यों के बीच में या राज्यों के समूहों के बीच में किये जाते हैं और जो वैध अधिकार और पक्षकारों के बीच आभार उत्पन्न करते हैं।”

स्टार्क (Starke) :—संधि एक वह करार है जिसमें दो या दो से अधिक राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अपने आप में सम्बन्ध स्थापित करते या सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। (A treaty is an agreement whereby two or more States establish or seek to establish a relationship under International Law between themselves.)

हार्बर्ट ड्रेफ्ट कन्वेंशन :—इस कन्वेंशन के अनुसार ‘Treaty’ शब्द को “a formal instrument of agreement by which two or more states establish or seek to establish a relation under International Law between themselves” मानते हैं जो कि स्टार्क के कथन से बहुत ही ईश्वर में है।

सन्धियों के प्रकार :—ओपेनहेम संधियों को विधि-विधायक संधियाँ और बहुत राज्यों के बीच आचरण के सामान्य नियम निर्धारण करने के लिये की जाती हैं, तथा अन्य प्रयोजन के लिये की गई संधियों में वर्गीकृत करते हैं।

विषयानुसार वर्गीकरण में संधियाँ निम्नलिखित हैं :—संधि स्थापन करने वाली संधियाँ, प्रतिभूति देने वाली संधियाँ, व्यापारिक संधियाँ, और किसी राज्य को तटस्थ बनाने वाली संधियाँ।

वतल (Vattel) सन्धिया को समान, सममान, वास्तविक तथा व्यक्तिगत में वर्गीकृत करते हैं ।

वास्तविक सन्धियाँ सविदा करने वाले पक्षकारों के व्यक्तिगत व समानित केवल समानमय व विषय से ही सम्बन्धित होती हैं । ये राज्य पर उसके शासक के वैयक्तिक परिवर्तनों से अनपेक्षित निरन्तर बाधकारी होती हैं । व्यक्तिगत सन्धियाँ सविदाकार पक्षकारों व व्यक्तिगत से सम्बन्धित होती हैं और मझाट्ट की मृत्यु पर समाप्त हो जाती हैं ।

एक पक्ष अथवा उभय पक्ष में बाध्यकारी होने के अनुसार सन्धियों को एक-पक्षीय तथा उभयपक्षीय में बाँटा जा सकता है । बहुपक्षीय सन्धियाँ भी होती हैं जो दो से अधिक राज्यों पर पक्षकारों व रूप में बाध्यकारी होती हैं । ऐसी सन्धियाँ या तो राजनैतिक अथवा अराजनैतिक होती हैं । विधि विधायक सन्धियाँ भी होती हैं जैसे परिस का पैक्ट, सींग आफ नेशन का कान्वेंट तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर ।

उद्देश्यों व अनुसार वर्गीकृत किये जाने पर सन्धियाँ निम्नलिखित हैं— राज-नैतिक, व्यापारिक, सामाजिक सन्धियाँ तथा प्रतिभूति, सटस्पता, परित्याग तथा प्रत्यर्पण की सन्धियाँ ।

सन्धियाँ स्थायी तथा अस्थायी भी होती हैं ।

सर्वोद्वीष्ट परिपूर्ण वर्गीकरण में नायर व अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रिटिच द्यर बुक (१९३०) में पाया जाता है । यह जैसा जैक्सन द्वारा अपनी पुस्तक 'ए मैनुअल ऑफ इंटरनेशनल लॉ' व पृष्ठ ४७ में उद्धृत किया गया है निम्न-लिखित हैं :—

(१) प्रत्येकस्वस्व सन्धियाँ ।

(२) सविदास्वरूप सन्धियाँ ।

(३) विधि-विधायक सन्धियाँ जिनका निम्न प्रकार से उपविभाजन किया जा सकता है —

(४) सन्धियाँ जिनके द्वारा सवैधानिक विधि बनाई जाती है यथा स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सेखबद्ध सन्धियाँ (Statutes) (यह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय) ।

(५) शुद्ध विधि-विधायक सन्धियाँ, उदाहरणार्थ भिन्न-भिन्न धर्म सम्बन्धी अभिसमय जो अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सघ द्वारा तय की गई हैं ।

(६) निगमन (Incorporation) के चार्टर के समान प्रकृति की सन्धियाँ, उदाहरणार्थ सन्धियाँ जिनके द्वारा विश्व बैंक सघ १९७४ में स्थापित हुआ था ।

को पारिभाषित कर सकती है जिनके अनुसार सबन्धित अभिकरण (एजेन्सी) समुक्त राष्ट्र के सम्बन्ध में लाया जायगा ।

न्यास पद्धति (trusteeship system) सम्बन्धी स्वीकृतियों के सम्बन्ध में प्रासंगिक उपबन्ध अध्याय १२ में दिये गये हैं । अनुच्छेद ७७ में यह अनुबन्धित है कि न्यासपद्धति ऐसे प्रदेशों को लागू की जायगी जैसे उसके अधीन न्यासस्वीकृतियों द्वारा रखे जायें तथा यह वाद की स्वीकृतियों का विषय होगा कि कौन प्रदेश न्यास पद्धति के अन्तर्गत लाये जायें और किन शर्तों पर । इसमें कोई सन्देह नहीं कि न्यास प्रदेशों के प्रशासन में समुक्त राष्ट्र सच का दखलाल का कर्तव्य रहेगा । क्लाइव की का कथन है कि “चार्टर के अध्याय १२ पर विचार करने के उपरान्त परिणाम इतने अधिक नहीं निकलता कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि न्यास-समझौता (trusteeship agreements) का जिनके सम्बन्ध में उसका कथन है कि अपने ही प्रकार के विविध (sul generis) प्रलेख है, ‘सन्धियों’ के नाम से संबोधित किये जाने के लिये बनाया जा चुका भी हो, विधि के अनुसार ऐसे कार्य हैं जिनसे अधिकार तथा कर्तव्य उत्पन्न होते हैं ।”

अब विशेषाधिकार तथा उम्मुक्तियों के सम्बन्ध में समझौता पर विचार करना शेष रह गया है । अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने समुक्त राष्ट्र की सेवा में सही हुई हानियों के लिये क्षतिपूर्ति वाले मामले में, अनुच्छेद १०५ में यथाव्यवस्थित, हानि के अधीन सच के अधिकारों का उपयोग करने तथा कर्तव्य को पालन करने के क्षमता के विषय में निर्देशित करते हुए यह घोषित किया कि चार्टर में सच उसी उसके सदस्यों के बीच सविदा करने की व्यवस्था की गई है तथा सच एक बड़ी मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व तथा क्षमता रखता है जिससे वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य कर सके (Clive Parry Article in Br. Year Book of I. L. 1949, F 108 at p 127)

सविदाकारों में पारस्परिक सहमति — चूँकि सन्ध एक प्रकार का समझौता है, अस्तु सविदा के पक्षकारों में परस्पर विचारों की सहमति होना चाहिए । यह सहमति कुछ चिह्नों, कथित शब्दों या लिखित शब्दों के रूप में होना चाहिए । पक्षकारों की पारस्परिक सहमति का होना आवश्यक है । केवल एक पक्ष प्रस्ताव कर दे और दूसरा उसे न माने तो यह सन्धि नहीं कहो जा सकती है । यह दूसरे पर बन्धनकारी नहीं है ।

सविदायें तथा संधियाँ (Contracts and Treaties) — नागरिक विधि में सविदा स्वीकार्य है जो विधि ने अनुसार लागू की जा सकती है ।

एक राज्य के नागरिकों के बीच की जाती हैं। इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ वे स्वीकारोक्तियों हैं जो उनके बीच स्थित अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों से उत्पन्न होने वाले भिन्न-भिन्न व्यवहारों को पूर्ण करने के प्रयोजन से की जाती हैं।

वैयक्तिक सविदाओं में स्वतंत्र प्रस्ताव तथा स्वतंत्र स्वीकृति होनी चाहिये और इससे अतिरिक्त ठोस प्रतिकूल होना चाहिये। तदनुसार नागरिक विधि में सम्मति की स्वतंत्रता प्रत्येक स्वीकारोक्ति की वैधता के लिये सारभूत और सविदाओं या किसी बन्धन के अधीन प्राप्त की गई है अथवा धमकी देकर या बलपूर्वक प्राप्त की गई हो, पक्षकारों पर बन्धनकारी नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि में बन्धन कुछ परिमाण तक सन्धियों के करने में स्वीकृत किये गये हैं। युद्ध के अन्त में विजयी राज्य ऐसी स्थिति में रहता है कि वह जिन शर्तों को चाहे लिखा ले। पराजित राज्य को वे शर्तें माननी ही पड़ती हैं। पराजित राज्य की दयनीय दशा के कारण कोई भी सन्धि जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जायगी, कुछ न कुछ बल प्रयोग का धब्बा अवश्य होगा। हाल (Hall) भी इस विचार से सहमत है कि "अन्तर्राष्ट्रीय विधि में बलप्रयोग तथा धमकी अपकारों के प्रतिकार के लिये अनुज्ञात साधन हैं, तथा यह असम्भव है कि अनुज्ञात साधनों को स्वीकारोक्ति को भंग करने वाला माना जाय जब वे (स्वीकारोक्तियों) उनके (साधनों के) प्रयोग में की जाय, जिनसे प्रतिकार की व्यवस्था की गई है।" ह्यूटन के भी विचार उसी के अनुसार हैं "समाज का कल्याण इस बात की अपेक्षा करता है कि किसी राज्य द्वारा ऐसे बन्धन के अधीन, जैसा इसके सैन्य बलों के पराजय, इसकी जनता के वृष्ट तथा इसके क्षेत्रों के शत्रु द्वारा दलल किये जाने के कारण, वे बन्धनकारी माने जायें, क्योंकि यदि ऐसे न माने जायें तो युद्धों का अन्त केवल दुर्बल पक्ष के सम्पूर्ण दमन तथा नाश से ही हो सकता है। और न राज्यों के बीच अपर्याप्त प्रतिकूल अथवा सन्धि की शर्तों की असमानता जैसा अलोक व्यक्तियों के बीच की सविदा का भंग करने के लिये भारी असमानता अथवा अपकार के कारण पर्याप्त होती, सन्धि के निष्पादन को असंभव करने के लिये पर्याप्त कारण होती है।"

वर्साई की सन्धि इसका एक ज्वलंत उदाहरण है जहाँ सन्धि करने के बिना किसी बहाने जर्मनी पर शर्तों आरोपित की गई थी। जर्मन प्रजातंत्र वर्साई सन्धि की दुसह शर्तों तथा प्रतिबन्धों को स्वीकार करने के लिये बाध्य किया गया, केवल इसलिये कि मित्र तथा संयुक्त सरकारों का बल घबड़ा देने वाला था और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के बीज का बपन हुआ।

मह भी स्मरण रहे कि सम्राट् अथवा राजनयिक अधिकारों के विरुद्ध वैयक्तिक रूप में बल-प्रयोग अथवा धमकी देकर की गई सन्धि बन्धनकारी नहीं होती।

बर्नहेड का कथन है कि “सन्धिकर्ता को डराकर उसे मानने को बाध्य करने के लिए सम्मेलन के कमरे में सैनिक बल का प्रवेश कराना उससे इस प्रकार बलपूर्वक प्राप्त की गई स्वीकारोक्ति का भवैध कर देगा।” (to introduce an armed force into the Conference Chamber for terrorising a negotiator into submission would invalidate the agreement extorted from him—Lord Birkenhead.)

यदि सहमति किसी सारपूर्ण गलती पर आधारित हो अथवा घोषा या मिथ्या-वार्ता के कारण दी गई हो तो इसके अनन्तर नागरिक विधि की सविदाओं के समान सन्धियाँ बन्धनकारी नहीं होती।

संयुक्त राष्ट्र सघ के स्थापन ने विश्व के लोगो के हृदयों में बड़ी-बड़ी आशा उत्पन्न कर दी हैं तथा यह आशा करनी चाहिये कि सन्धियों के करने के विषय में राज्या के कार्य की स्वतन्त्रता को अनुचित दबाव, धमकी अथवा बल-प्रयोग द्वारा सामित करने का बहुत ही कम अवसर होगा।

**चार्टर से असंबद्ध तथा अनैतिक सन्धियाँ :—**संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद १०३ में यह दिया गया है कि विरोध की दशा में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन कर्तव्य उनके किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अधीन कर्तव्यों में अधिक प्रबल होंगे। इसका अनुसार जहाँ तक वे चार्टर के सिद्धान्तों से असंगत हैं, सन्धि के अधीन कर्तव्य वैध नहीं होंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रथा के अनुसार यह स्वीकृति है कि वे अनैतिक कर्तव्य पक्षकारों पर बन्धनकारी नहीं होते जो सन्धियों अथवा सार्वजनिक रीति के विरुद्ध सन्धियों द्वारा लागू किये गये हों।

**संवैधानिक आवश्यकतायें :—**पूर्ण प्रभुसत्ताधारी राज्यों की दशा में संधि करने की शक्ति राज्यों के अध्यक्ष तथा उनके अधिकर्ताओं के ऊपर रहती है। उस दशा में जब वे अपने-अपने राज्यों की नागरिक विधि द्वारा किये गये संवैधानिक सीमितियों का उल्लंघन करें, वे पक्षकारों पर बन्धनकारी नहीं मानी जातीं। कुछ राज्यों में जैसे ब्रिटानिया में सन्धि का करना एक प्रशासकीय कार्य है किन्तु उनके पालन करने में यदि उनसे वर्तमान घरेलू विधि में परिवर्तन होता है तो संवैधानिक कार्य अपेक्षित है।

**सन्धियों का करना :—**सन्धियों के करने के लिये कोई विशिष्ट प्राण नहीं है। राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच की मौखिक स्वीकारोक्ति, जिनको समझौता-वार्ता करने का भार सौंपा गया हो तथा जिन्हें अपने-अपने देशों को बाध्य करने के लिये सशक्त बिधा गया हो, बाध्यकारी प्रभाव रखने के लिये पर्याप्त होता है यदि

प्रतिनिधियों का यह आशय हो कि वैधिक रूप से वाध्यकारी व्यवहार किया जाय । फिर भी विवेचनीय प्रश्नों के आधार पर महत्व के कारण यह आवश्यक होता है कि नियमानुसार अपेक्षित बातों का पालन किया जाय तथा स्वीकाराक्ति का प्रलेख में परिवर्तित कर दिया जाय ।

सन्धि करने में जो भिन्न-भिन्न कार्यवाहियाँ करनी पड़ती हैं वे निम्नलिखित हैं —

१. प्रतिनिधियों का प्रत्यापन (Accrediting of Representatives) :— समझौता वार्ता चलाने वाला प्रत्येक राज्य एक प्रतिनिधि अथवा पूर्ण शक्तियुक्त दूत इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करता है । उसको वैदेशिक मामलों के मन्त्री द्वारा प्राप्त एक प्रलेख मिलता है जिसमें उसका प्राधिकार उन समझौता-वार्ता का चलाने के लिये लिखा रहता है और जिसको पूर्ण शक्ति कहते हैं । ऐसा ही प्रलेख जब वह सम्राट् द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तथा “बड़ी मुद्रा” से मुद्राङ्कित किया जाता है तो यह “विशिष्ट पूर्ण शक्ति” कहा जाता है ।

२. वार्ता (Negotiation) — अपना कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व दोनों पूर्ण शक्तियुक्त राजदूत अपनी-अपनी पूर्ण शक्तियों की अथवा उनके प्रतिनिधियों की बदला-बदली कर लेते हैं । तब वे समझौता वार्ता मागे बढ़ाते हैं और अन्तिम मसौदा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये तैयार करते हैं ।

३. हस्ताक्षर (Signature) — जब सन्धि का अन्तिम मसौदा बन जाता है तो प्रलेख हस्ताक्षरित होने के लिये तैयार हो जाता है । हस्ताक्षर यथारूप अन्तिम बैठक में किया जाता है । यदि पक्षकार उनके सत्याकन के अधीन न करना चाहें तो सन्धि सामान्यतः सविदाकार राज्यों के पूर्ण अधिकारयुक्त दूतों के हस्ताक्षर होने पर लागू होती है ।

४. सत्याकन (Ratification) — अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि का उसके पक्षकारों द्वारा स्वीकृत करने का कार्य है । अन्य शब्दों में सत्याकन यह प्रकट करता है कि वह सन्धि अनुसमर्थित कर दी गई है जो भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई है । जब तक सन्धि का देश के संविधान के अन्तर्गत उचित प्राधिकारी द्वारा सत्याकन नहीं किया जाता, तब तक इसमें वैधता तथा प्राणालिकता का अभाव रहता है । यद्यपि सन्धियाँ बाद में पुष्ट की जाती हैं, फिर भी उनके वैध प्रभावों के होने की विधि हस्ताक्षर के क्षण से ही मानी जाती है । हस्ताक्षर तथा वास्तविक सत्याकन के बीच का समय सन्धि के पक्षकार राज्यों को इसलिये दिया जाता है कि वे उस विषय पर विचार करें तथा स्वीकाराक्ति को किन्हीं वैध कारणों से पुष्ट अथवा सत्याकन करने से अस्वीकार कर दें । इससे उनको यदि आवश्यक हो तो



संसद की स्वीकृति प्राप्त करने तथा अन्य प्रकार से जनमत प्राप्त कर लेने का प्रयत्न भी प्राप्त होता है। किसी संधि का सत्याकन करने से अस्वीकार करने के कारण मनमाने अथवा अस्थिर न होने चाहिये। किसी संधि का सत्याकन निम्नलिखित कारणों से रोका जा सकता है —

(१) यदि प्रतिनिधि अथवा पूर्णशक्तियुक्त राजदूत ने उसको प्रदत्त शक्ति की सीमा से बाहर कार्य किया हो।

(२) यदि तथ्य के विषयो में उसके साथ धोखा किया गया हो।

(३) यदि संधि के अधीन कर्तव्यों का पालन करना असम्भव हो जाय।

(४) यदि एक ही विषय के सम्बन्ध में (consensus ad idem) दोनों सहमति न हो।

सत्याकन का प्रारूप के लिये जैसा ऊपर कहा गया है कोई स्पष्ट नियम नहीं है। यह प्रकट रूप से अथवा अप्रकट रूप से किया जा सकता है। प्रायः सत्याकन निग्रहों के साथ किया जाता है। ऐसे निग्रहों के लिये इससे पूर्व कि संधि बधनकारी प्रभाव रख सके, संधि के अन्य पक्षकार राज्यों की सहमति नियमानुसार अनिवार्य होती है।

**द्विपक्षीय संधियों में सत्याकन के प्रतिबन्ध :—**जैसा कि ऊपर कहा गया है सत्याकन सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने का कार्य है। दूसरे शब्दों में सत्याकन के अन्तर्गत संधि में प्रविष्ट हुए राज्यों के प्रति निधियों की ओर से संधि के पुष्टीकरण को सत्याकन (ratification) कहते हैं किन्तु यदि यह सत्याकन अथवा अनुसमर्थन कुछ शर्तों पर प्रतिबन्धित है तो संधि की प्रवृत्ति ही बदल जायगी। ओपेनहेम का कथन है कि प्रतिबंध एक प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दूसरे प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है इसलिए सिद्धान्त रूप में आवश्यक प्रतीत होता है कि दूसरा पक्ष प्रकट या सम्बद्ध रूप में इन प्रतिबंधों को स्वीकार करे।

**बहुपक्षीय अभिसमय (Multilateral Conventions) :—**बहुपक्षीय अभिसमयों में प्रथम में, जो कि विधि-विधायक दल की है और जो आवश्यक है, समान सिद्धान्त प्रस्तुत करती हैं, पक्षकारों के अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की जाती है, इसलिए यहाँ भी वही सामान्य सिद्धान्त लागू होते जो द्विपक्षीय संधियों में होते हैं।

**५. अधिमिलन तथा ससक्ति (आसंजन) (Accession and Adhesion) :—**कोई तीसरा राज्य वर्तमान संधि का पक्षकार अधिमिलन द्वारा

सकता है। यह या तो तीसरे राज्य के प्रारम्भिक पक्षकारों की सहमति से नियम-पूर्वक समिलन द्वारा होता है, अथवा जैसा ओपेनहेम का कथन है "अन्य राज्यों के बीच में हुई संधि के सम्यक् रूप से पालन के लिये प्रतिभूति होने के प्रयोजन से पक्षकार होकर" जिसके द्वारा समिलन करने वाला राज्य भी संधि का पक्षकार हो जाता है।

सत्ति या आसजन से एक तीसरे राज्य का केवल कुछ शर्तों अथवा सिद्धान्तों के लिये, जो संधि का भाग हैं, किसी वर्तमान संधि में अधिमिलन प्रकट होता है।

६. संधियों का प्रवर्तन (Coming into force of treaties) — संधि का यदि सत्याकन आवश्यक न हो तो वह हस्ताक्षरित होने के दिनांक से लागू हो जाती है। सत्याकन की दशा में संधि हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के सत्याकनों की जमा करने के उपरान्त लागू होती है। बहुपक्षीय संधियाँ नियत सख्या के सत्याकनों के जमा किये जाने के उपरान्त लागू होती हैं।

७. पंजीकरण (Registration) — इस प्रकार सत्याकित होने के उपरान्त संधि को अन्तर्राष्ट्रीय सच के मुख्यालय में पंजीकृत कराना पड़ता है। लीग के कावेनन्ट (Covenant) के अनुच्छेद १८ में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक संधि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अभियुक्ति लीग के सचिवालय में पंजीकृत करना चाहिए तथा उसके द्वारा यथासम्भव शोधातिशीघ्र प्रकाशित करना चाहिए। इस प्रकार की कोई संधि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अभियुक्ति किसी राज्य पर उस समय तक बन्धनकारी नहीं होती जब तक वह इस प्रकार पंजीकृत न किया जाय। इसका यह अर्थ हुआ कि विवाद की दशा में संधि पर यदि वह पंजीकृत न हुई तो विश्वास नहीं किया जा सकता। समुक्त राष्ट्र सच के चार्टर में अभिसंधिदाओं का भी वही प्रभाव है। चार्टर के अनुच्छेद १०२ में यह दिया गया है कि —

(१) "वर्तमान चार्टर के लागू होने के उपरान्त प्रत्येक संधि तथा प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय संधिदा जो समुक्त राष्ट्र सच के किसी सदस्य द्वारा की जाय, यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र सचिवालय में पंजीकृत की जायगी तथा उसके द्वारा प्रकाशित की जायगी।

(२) ऐसी संधि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संधिदा का, जो इस अनुच्छेद के खंड (१) के अनुबन्धों के अनुसार पंजीकृत नहीं है, कोई पक्षकार, उस संधि अथवा संधिदा को कोई सहायता समुक्त राष्ट्र सच के किसी अंग के समक्ष नहीं ले सकता है।"

अनुच्छेद १०२ का द्वितीय भाग राज्यों को किसी गुप्त संधि को विश्वसम्मति के कटघरे में समक्ष लाने से स्पष्टतया वर्जित करता है। रजिस्ट्री न कराने का

प्रभाव केवल यही तक सीमित है कि संधि के पक्षकार समुक्त राष्ट्र के किसी अंग के समक्ष उसकी सहायता की प्रार्थना नहीं कर सकते ।

८. संधि का राज्य-विधि में निगमन :—संधि की अंतिम स्थिति उसके संविदाकार राज्यों की नगरिक विधियों में वास्तविक निगमन है जहाँ ऐसा समोजन बन्धनकारी प्रभाव रखने के लिये आवश्यक हो ।

अथैव संधियाँ :—अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार संधियाँ निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के आधार पर अवैध मानी जा सकती हैं :—

(१) जहाँ संधि का उद्देश्य अवैध हो । संधियाँ जिनमें अनैतिक कर्तव्यों की शर्त हो, आरम्भ से ही प्रभावहीन होती हैं ।

(२) जहाँ संधि करने में पक्षकारों के साथ धोखा अथवा मिथ्याव्यापन किया गया हो ।

(३) जहाँ धमकी देकर, अनुचित दबाव डालकर अथवा रुज दिखाकर संधि कराई गई हो ।

(४) जहाँ संधि करने में धोखे से उत्पन्न हुई कोई गलती हो गई हो ।

(५) जहाँ संधि में ऐस कर्तव्यों की व्यवस्था की गई हो जिनका कला असम्भव हो ।

(६) जहाँ संधिकर्ता पक्षकारों की स्थिति ही उनको अयोग्य बना देती हो ।

(७) जहाँ सन्धियाँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों का उल्लंघन करती हैं अथवा चार्टर के सिद्धान्तों को गौरवहीन करती हो ।

सन्धिया की समाप्ति :—सन्धियाँ निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण समाप्त हो सकती हैं :—

(अ) उस विशिष्ट अवधि की समाप्ति पर जिसके लिये सन्धि की गई थी ।

(आ) जब सन्धि का मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो गया हो । उन सन्धियों की दशा जिनमें निरन्तर जारी रहने वाले कर्तव्य न आरोपित किये गये हो, वे (संधियाँ) उद्देश्य के पूर्ण होने के उपरान्त लागू नहीं होती ।

(इ) सन्धि के पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से । किसी सन्धि के पक्षकार उसके स्वामी हैं, अतः यदि पारस्परिक सहमति से वे संधि को समाप्त करना चाहे अथवा संधि में उसके किसी एक पक्ष का अथवा सब पक्षों को संधि-भंग का एक-पक्षीय अधिकार दिया गया हो तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि उनके मार्ग में कोई रोड़े नहीं भरकाती ।

(ई) कुछ आवश्यक शर्तों का न पूरा करना । यदि सन्धि में कुछ आवश्यक शर्तों के पालन करने में असफल रहने की दशा में प्रतिस्पर्धी राज्यों में से किसी एक

अथवा सब राज्यों को सन्धि भग करने का एक-पक्षीय अधिकार दिया गया हो, तो ऐसा घटित होने पर सन्धि समाप्त हो जाती है।

(उ) जब सन्धि के कर्तव्य सयुक्त राष्ट्र के चार्टर से असंगत हो जायें। अनुच्छेद १०३ में यह विशिष्टतया प्रतिबन्धित है कि सयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के कर्तव्यों तथा उनके अन्य सविदाभा के अन्तर्गत कर्तव्यों के विरोध की दशा में उनके कर्तव्य का चार्टर के अधीन है, प्रबल रहेंगे।

(ऊ) जब सविदाकार पक्षकारों के बीच युद्ध छिड़ जाय। फिर भी प्राधुनिक मत यह है कि युद्ध छिड़ना सन्धि का अश्वमेव ही भग नहीं कर देता। [Techt v. Hughes, (1920) 229 N. Y. 222].

(ए) जब कि सविदाकार पक्षकारों में से कोई एक अधिमिलन अथवा सम्मेलन द्वारा वितण्डित हो गया हो। सयुक्त राज्य अमेरिका तथा त्रिपोली ने बीच सन्धि का अस्तित्व समाप्त हो गया जब त्रिपोली इटली द्वारा सन् १९१२ में मिला लिया गया।

(ऐ) प्रबल शक्ति (Force Majeure) तथा कार्य करने की असंभाव्यता। रूस का क्षतिपूर्ति वाला मामला (Russian Indemnity Case, Permanent Court of Arbitration, 1912, No XI) जो रूस तथा टर्की के बीच हुआ था उसमें पचायत के स्थायी न्यायालय ने यह मत प्रकट किया कि प्रबल शक्ति (vis major) के अपवाद की अभिव्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय तथा वैयक्तिक विधि में की जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि को अपने को राजनैतिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना चाहिये। रूस ने तुर्की के इस तर्क के साथ कि "यदि राज्य का अस्तित्व ही सकटग्रस्त हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करना सम्बन्धित राज्य के प्रति धारम-घातकारी हो तो राज्य की सन्धियों की शर्तों को पूरा करने के कर्तव्य हट जाने चाहिये", यद्यपि सहमत प्रकट की तथापि उस (रूस) ने यह बहुत किया कि सन् १८८१ से १९०२ तक तुर्की में अत्यन्त अथक आर्थिक सकट रहे लेकिन फिर भी उस अवधि के भीतर तुर्की को अन्य ऋणों तथा सार्वजनिक ऋण के एक बड़े भाग को चुकाने के लिये अनुकूल दरों पर ऋण प्राप्त हो सका। न्यायालय रूस के इस तर्क से सहमत हो गया और उसने मत प्रकट किया कि रूसी दावेदारों को एक छोटी सी साठ लाख फ्रैंक की धनराशि देने को बाध्य किये जाने से तुर्की के राज्य का अस्तित्व न तो सकटग्रस्त हुआ और न उसकी आन्तरिक अथवा बाह्य स्थिति किसी प्रकार से हीन हुई। अतः तुर्की द्वारा उठाया गया प्रबल शक्ति का अपवाद नहीं माना गया।

(थो) तदवस्था का सिद्धान्त (Rebus sic stantibus) । इस सिद्धान्त का यह अर्थ है कि जब किसी राज्य का अस्तित्व अथवा विकास उसके सन्धि के अन्तर्गत के कर्तव्यों के अपरिहार्य विरोध में हो तो राज्य तथा उसके अति आवश्यक भागों के अनुसार आत्मसंरक्षण तथा विकास के लिये सन्धि के कर्तव्य शिथिल हो जा सकते हैं। प्रोफेसर हॉल इस सिद्धान्त से सहमत होते हुये कहते हैं कि "अतः सन्धि जो किसी राज्य के जीवन के लिये अत्यावश्यक हो जाती है, अथवा उसकी स्वतन्त्रता के असंगत हो जाती है तो वह निष्प्रभाव हो जाती है, इस अनुबन्धन के साथ कि इसे करने के समय दोनों सविदाकार पक्षकारों का आशय उसके हानिकारक प्रभावों से नहीं रहा है। "A treaty, therefore, becomes voidable so soon as it is dangerous to the life or incompatible with the independence of a State, provided that its injurious effects are not intended by the two contracting parties at the time of its conclusion."—Professor Hall

इस सम्बन्ध में लौरन्स का यह मत है कि "यह बात निश्चित है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि राज्य के कुटुम्ब के किसी अनिच्छित चलने वाले सदस्य को जो अनेक प्राचीन-अन्यरक्षा गृह से किसी अप्रचलित सन्धि को निकाल सके और हस्तान्तर करने वाली अन्य शक्तियों की इच्छा के विरुद्ध उसकी शर्तों को पूरा करने का हक दे अपने विशेषाधिकार द्वारा उन्नति में रोड़ा अटकाने का अधिकार नहीं देती है। "International law certainly does not give a right of veto on political progress to any reactionary member of the family of nations who can discover in its archives some obsolete treaty, on the fulfilment of whose stipulations, it insists against the wishes of all the contemporary signatory powers."—Lawrence.

इस प्रकार प्रत्येक सन्धि में यह प्रतिबन्ध व्यक्त है कि सविदाकार पक्षकारों को यह अधिकार होना चाहिये कि यदि परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण राज्य का सतत अस्तित्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में भय में हो तो वे सन्धि को समाप्त करने के लिये उचित कदम उठाने की माँग करें।

रूस द्वारा पेरिस की सन्धि १८५६ की सन्धि के उस भाग के भाग के अन्तर्गत में जो वाले समुद्र के तटस्थीकरण तथा रूस के ऊपर वाले समुद्र में सन्धि रखने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध लगाने के विषय में था, शक्तियों ने १८७० में सन्धि किया कि तदवस्था के सिद्धान्त (rebus sic stantibus) के सह की सहायता के बिना सन्धि को समाप्त करने के लिये आचार रूप में माँगी जा सकती थी किन्तु यह कथन कि रूस एक पक्षीय रूप से सन्धि भंग नहीं कर सकता था।

सन्धियों का पुनरीक्षण :—सन्धियों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में लीग आफ नेशन्स के कावनेट (१९२०) के अनुच्छेद १९ में यह व्यवस्था की गई थी :—

“समा समय-समय पर उन सन्धियों को जो लागू करने के अयोग्य हो गई हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय दशाओं को जिनका जारी रहना विश्व-शान्ति के लिये भयप्रद हो विचार करने के लिये लीग के सदस्यों को परामर्श दें ।”

इसमें सन्देह नहीं कि इस अनुच्छेद में सन्धियों में जो एक नई स्थिति के उत्पन्न होने के कारण लागू रहने के अयोग्य हो गई है परिवर्तन करने तथा उनको रद्द करने की अनुमति दी गई है किन्तु सन्धि केवल उसी दशा में पुनरीक्षित हो सकती थी जब ५० राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एकमत से निर्णय प्राप्त हो सके । अतः कावनेट के अनुच्छेद १९ द्वारा तदवस्था के सिद्धान्त (*rebus sic stantibus*) के खड को पुष्ट किया गया लेकिन साथ ही उसे एकपक्षीय रूप से लागू करने के किसी दावे को अस्वीकृत किया गया । उस अनुच्छेद में केवल उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण को सामने रखने का अवकाश देने की व्यवस्था की गई है जो सन्धि का पुनरीक्षण चाहते थे । लीरेस का कथन है कि यह सम्मति को जीवने के साधनरूप में लाभदायक है । समझौता, जाँच तथा समझाने-बुझाने से सन्धि में परिवर्तन करने की रीति अवश्य ही असफल रहेगी क्योंकि इसमें उन आवश्यक बातों का अभाव है जो एक राष्ट्रीय सभा में होती हैं जिसके द्वारा मानव-जाति को शान्ति, सुरक्षा तथा सुख के हित में पुनरीक्षण चाहने वाले बहुमत को इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है ।

गत शताब्दी से यह सम्मति जोर पकड़ती जा रही है कि परिस्थितियों में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के होत ही राज्य को तदवस्था के सिद्धान्त (*rebus sic stantibus*) के आधार पर तत्काल ही सन्धि के अन्तर्गत कर्तव्यों को भग करने का अधिकार न मिलना चाहिये, किन्तु उसे उनसे उन्मुक्त किये जाने का अधिकार केवल सन्धि के अन्य पक्षकार अथवा पक्षकारों की सम्मति से ही मिलना चाहिये । यही प्रक्रिया तुर्की द्वारा सन् १९३६ में की गई जब उसने यूरोप की राजनैतिक तथा सैनिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के कारण डार्डेनेल्लोस तथा बास्फोरस खाडियों सम्बन्धी सन् १९२३ की लीसाने की सन्धि को समाप्त करना चाहा । तुर्की प्राथमिक पर मौंट्रो में सन् १९३६ में सम्बन्धित राज्यों का एक सम्मेलन बुलाया गया जिसने एक नई सन्धि करके पहली सन्धि को समाप्त कर दिया ।

संयुक्त राष्ट्र सभा के चार्टर में कावनेट के अनुच्छेद १९ के समान सन्धियों के पुनरीक्षण सम्बन्धी कोई व्यवस्था नहीं है । चार्टर में इससे सम्बद्ध अनुच्छेद १०३ है जिसमें यह लिखा है कि :—

“संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के कर्तव्यों के वर्तमान चार्टर तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकार-पत्रों के अधीन कर्तव्यों के विरोध की दशा में उनके वर्तमान अधिकार के अधीन कर्तव्य प्रबल रहेंगे।”

इस सम्बन्ध में चार्टर के अनुच्छेद १४ की अभिसन्धिदाये भी ध्यान देने योग्य हैं, जिनमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि सामान्य सभा की सम्मति में उससे राष्ट्र का सामान्य-हित अथवा उनके बीच के मित्रता के सम्बन्धों में बाधा पड़ती हो तो सामान्य सभा किसी स्थिति के शान्तिपूर्ण समाधान के लिये उपायों का प्रतिस्ताप कर सकती है चाहे वह स्थिति किसी प्रकार उत्पन्न हुई हो। सामान्य-हित के विचार से सन्धि का पुनरीक्षण आवश्यक हो सकता है। उसी प्रकार से यदि सन्धियाँ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दे जिनसे सभा की राय में सामान्य-हित अथवा राज्यों के बीच की मित्रता के सम्बन्धों में बाधा पड़ती हो तो वह ऐसी स्थितियों के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकती है। ऐसी सिफारिशें सामान्य सभा द्वारा अनुच्छेद १० के अधीन भी की जा सकती हैं जिनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ को वर्तमान चार्टर के क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रश्न अथवा विषय के विवेचन की शक्ति दी गई है तथा कोई भी स्थिति जिससे सामान्य-हित अथवा राज्यों के बीच की मित्रता के सम्बन्धों में बाधा पड़ती हो चार्टर के क्षेत्र के भीतर आता है।

**आंग्ल-मिश्रीय (ब्रिटेन तथा इजिप्ट के मध्य की) सन् १९३६ की सन्धि .—**सन् १९३६ में इटली ने ऐबीसीनिया पर कब्जा कर लिया तथा अपने नील नदी के चारों ओर के उपनिवेशों में बड़ी भारी सेनाएँ भेजी। असाधारण स्थिति के कारण इजिप्ट ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ सहयोग करने को हाथ बँटाया तथा अगस्त २१ सन् १९३६ को ग्रेट ब्रिटेन तथा इजिप्ट के बीच सहयोग की सन्धि हो गई जिसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन को स्वेज नहर के समीप नहर की रक्षा के लिये सेनाएँ रखने दिया गया। यद्यपि स्वेज नहर इजिप्ट का अन्तर्गत भाग माना जाता था फिर भी परिस्थितियों के कारण ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी। सन् १९५० में इजिप्ट ने यह माँग प्रस्तुत की कि ब्रिटानिया की सेनाएँ स्वेज नहर से तत्काल हटा ली जावें तथा सूडान की रक्षा के सम्राट् के अधीन कर दिया जाय। इन पर वैदेशिक विभाग के सचिव मिन्स अर्नेस्ट बेविन ने उत्तर दिया कि ब्रिटानिया का कोई इरादा मध्य पूर्व को प्रत्यक्ष दगा में छोड़ कर चले जाने का नहीं है और इस पर महत्व दिया कि सन्धि रूपरेखा अथवा पुनरीक्षित करने का, पारस्परिक सहयोग से अन्य ओर कोई बन्ध नहीं है। इजिप्ट का यह दावा था कि सन् १९३६ की सन्धि अपने प्रयाप्त अधिक दिनों तक जीवित रह गई है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को सब देशों की स्थापना चाहिये तथा उसको मध्यपूर्व के सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा

करनी चाहिये तथा यह उसी दशा में किया जा सकता है जब ब्रितानिया का बला-त्कार मध्यपूर्व में समाप्त कर दिया जाय ।

इजिप्ट ने सन् १९३६ की सन्धि तथा १८६६ का सूदान का सहाराज्य-सम-झौता-पत्र ( Condominium agreement ) को सन् १९५१ में भंग कर दिया ।

ब्रिटेन और इजिप्ट में ब्रितानिया की सेनाओं को स्वेज नहर क्षेत्र से हटाने के सम्बन्ध में जुलाई २७, सन् १९५४ को समझौता हो गया जिसके द्वारा ब्रितानिया की सेनाओं को हटाने का कार्य बीस मास में पूर्ण कर दिया जाने को था । इस बात की व्यवस्था कर दी गई कि अरब राज्य अथवा तुर्की पर आक्रमण की दशा में अड़डे को पुन खालू कर दिया जायगा । नई संधिदा की अवधि सात वर्ष की थी ।

एक जनवरी १९५७ को राष्ट्रपति नसीर ने ब्रितानिया से की हुई १९५४ की संधि को रद्द कर दिया । ब्रितानिया ने पुन इजिप्ट के इस एकपक्षीय अधिकार को अस्वीकृत किया ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि संधियों के पुनरीक्षण की शक्ति एक अन्तर्राष्ट्रीय संध के हाथ में देना चाहिये क्योंकि सम्बन्धित पक्षकारों की सम्मति से पुनरीक्षण प्राप्त करने की सम्भावना बहुत कम रहती है । लीग के कान्वेण्ट के अनु-च्छेद १६ में इस दिशा में एक निश्चित प्रयत्न था तथा संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर इन विषयों को और अधिक आगे नहीं ले जाता है ।

**संधियों की व्याख्या :—**अन्तर्राष्ट्रीय संधियों की व्याख्या के नियम जिनकी भिन्न-भिन्न व्याख्याओं तथा व्याख्याधिकरणों द्वारा प्रशंसा की गई है निम्न-लिखित प्रकार में सक्षिप्त किये जा सकते हैं :—

( १ ) सब संधियों की व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिये जिससे मूल के प्रत्येक शब्द का कारण तथा अर्थ निकले ( लाइट होस वाला मामला ) ।

( २ ) यदि संधि दो भाषाओं में लिखी हो जिससे कुछ परस्पर विरोधी अर्थ निकलता हो तो वह व्याख्या ग्रहण करनी चाहिये जो पक्षकारों की इच्छा तथा दोनों पाठों के अनुरूप हो ।

( ३ ) किसी संधि के अनुबन्धों का ऐसा संकुचित अर्थ नहीं करना चाहिये जिससे किसी राज्य की सार्वभौमिक सत्ता घट जाय ।

( ४ ) जब कोई प्रलेख अस्पष्ट हो तो उसका अर्थ इस प्रकार का लेना चाहिये जिससे उसका आभार उस व्यक्ति पर कम पड़े जो सन्धि के अधीन भार वहन करने के उत्तरदायी हो ।

( ५ ) यदि दो व्याख्यायें संभव हो तो वह व्याख्या जिससे पक्षकारों पर कम से कम कर्तव्य भार पड़ता हो ग्रहण की जानी चाहिये ।



(६) अन्तर्राष्ट्रीय संधियों की केवल व्याकरण के अनुकूल परिभाषा उस स्थान पर रुक जानी चाहिये जहाँ से वह परस्पर विरोधी अथवा असंभव परिणामों पर ले जाती हो अथवा जो पक्षकारों की इच्छा के ती हुई प्रतीत होती हो। (विम्बल्डन वाला मामला)

(७) संधि को सम्पूर्णतः पढ़ा जाना चाहिये तथा इसका अर्थ केवल उसके किसी विशिष्ट वाक्यखंड पर ही निश्चित नहीं करना चाहिये यदि उस वाक्य का, सन्दर्भ से अलग किये जाने पर, एक से अधिक अर्थ निकलते हो।

(८) जब संधि में किसी अनुच्छेद का उद्देश्य साम्या (equity) का हो तो उसकी बहुत रुक्ष प्रकार से व्याख्या नहीं करनी चाहिये।

(९) अन्तर्राष्ट्रीय विधि में जब पक्षकारों के आशय के सम्बन्ध में सन्देह हो तो ऐतिहासिक व्याख्या की रीति प्रयोग करने की अनुमति है। इसके अनुसार पक्षकारों के आशय को ज्ञात करने के लिये तथा संधि के वास्तविक बातों को ज्ञात करने के लिये जिनके अनुसार उन्होंने अपने आशय को प्रकट करने का प्रयत्न किया है बातचीत के इतिहास का परीक्षण किया जाता है अथवा प्रारम्भिक कार्य का निर्देश किया जाता है।

(१०) ऐसी व्याख्या जिससे संधि के अनुबन्ध निरर्थक अथवा प्रभावहीन हो जाय, अंगीकार करने योग्य नहीं है।

(११) संधि की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिये जिससे वह प्रयोग भागे बड़े जिसके लिये यह की गई हो।

(१२) संधियों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिये जिससे कि संभव हो तथा उनका प्रयोग सद-भावना से हो सके।

(१३) राजनैतिक तथा आर्थिक बातों का विचार जिनके अनुसार संधि प्रारम्भ में की गई थी संधि की व्याख्या करने के समय किया जा सकता है।

## अध्याय २३

### मैत्री और व्यापारिक सन्धियाँ

#### (Alliances and Commercial Treaties)

मैत्रियाँ (Alliances) :—नीच पाप नेगम के वाक्योक्त के अनुसार मैत्रियाँ जो वाक्योक्त के अनुच्छेदों के विपरीत थीं, स्वीकार की गईं। समुक्त राष्ट्र महा के चार्टर में श्रेष्ठ व्यवस्थाओं तथा अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रीय और मुरता की रक्षा करें, की स्थिति को सम्बोधित नहीं किया

है। शर्त यही है कि ऐसी व्यवस्था या ऐसे अभिकरण अपने कार्यों के सम्पादन में संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सिद्धान्तों का उल्लंघन न करें। [अनुच्छेद ५२(१)]

**संघ कारण (Casus Foederis) :—**ओपेनहेम का कथन है कि संघ कारण वह घटना है जिसके घटित हो जाने पर यह एक परम आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि सम्मिलित इकाइयाँ एक दूसरे की सहायता करने के लिये कटिबद्ध हो गयी हैं। इस प्रकार किसी सुरक्षात्मक मैत्री में संघ कारण तब उपस्थित होता है जब कि मित्र राष्ट्रों में से किसी एक पर युद्ध की घोषणा कर दी जाती है अथवा युद्ध छेड़ दिया जाता है।

**गारन्टी सन्धियाँ (Guarantee Treaties) .—**प्रतिभूति या गारन्टी सन्धियाँ दो राज्यों के पारस्परिक अथवा एकपक्षीय समझौते को कहते हैं जब कि पक्षकारों में से कोई एक दूसरे पक्षकार के हित में कोई कार्य करने को बचनबद्ध होता है। यह गारन्टी सामूहिक भी हो सकती है जैसा कि लक्षमबर्ग की तटस्थता के सम्बन्ध में हुआ था।

**व्यापारिक सन्धियाँ (Commercial Treaties) :—**व्यापारिक सन्धियों का सम्बन्ध सविदाकार राज्यों के व्यापार और नीचालन से होता है। उनके अन्तर्गत वाणिज्य दूत तथा अन्य सम्बन्धित प्रसङ्ग आते हैं। पूर्ण प्रभुतासम्पन्न राज्य किसी भी व्यापारिक सन्धि में प्रविष्ट होने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं।

**परम-मित्र-राष्ट्र धारा (Most-favoured-nation Clause) :—**अधिकतम व्यापारिक सन्धियाँ “परम-मित्र-राष्ट्र धारा” पर आधारित रहती हैं। इस परम-मित्र-राष्ट्र धारा की परिभाषा करते हुये ओपेनहेम ने लिखा है कि वे सभी पक्ष जो कि सविदाकारों ने भूतकाल में स्वीकार किया है या भविष्य में स्वीकार करेंगे जो कि किसी तीसरे राज्य के हित में होगा, वह दूसरे पक्ष को स्वीकृत किया जावेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में १६२३ तक इसका एक सीमित अर्थ लिया गया। इस अर्थ के अनुसार प्रतिभूति की शर्तों को पूरा करने पर ही यह स्वीकृत किया जाता था, तात्पर्य यह कि यदि पक्ष बिना किसी शर्त के दिया गया है तो दूसरे पक्षकार को भी बिना किसी शर्त के स्वीकार करना पड़ेगा। ओपेनहेम इस शर्तयुक्त पक्ष को इस कारण से न्याय उचित नहीं मानते कि इसमें अनेक आपत्तियाँ उठायी जा सकती हैं। पहली आपत्ति तो यह है कि यह कहना ही कठिन है कि समान अथवा बराबर मूल्य का प्रतिकर किस प्रकार स्थिर किया जाय। दूसरी आपत्ति यह है कि उन देशों के लिए यह ठीक न होगा जिनके ऊपर बहुत कम कर्तव्य आरोपित किये गये हैं और वे जिनके ऊपर बहुत से कर्तव्यों का आभार सौंपा गया है। १६१६ के अमेरिकन टेरिफ कमीशन की सिफारिश तथा १६२२ के टेरिफ ऐक्ट के आधार पर

संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य देशों के समतुल्य था गया है कि वह परम मित्र-राष्ट्र व्यवहार के सिद्धान्त को बिना किसी शर्त के निगमिन करे।

वामनवेत्त सदस्यों के बीच टेरिफ की जो प्रथा प्रचलित है वह परम-मित्र राष्ट्रधारा में सम्मिलित नहीं की गयी है क्योंकि उनका पारस्परिक सम्बन्ध एक विशेष प्रकार का है जो कि ऐसे सम्बन्धों का अन्तर्राष्ट्रीय न मानकर घरेलू मानता है।

## अध्याय २४

### अन्तर्राष्ट्रीय दुष्कृतियाँ और क्षतियाँ

#### ( International Torts and Damages )

**अन्तर्राष्ट्रीय दुष्कृतियों के प्रकार :—**अन्तर्राष्ट्रीय दुष्कृति या तो एक राज्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप में दूसरे राज्य का अपकार करने से उत्पन्न होती है या दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रीय जनो के प्रति कुछ अपकार करने से होती है। दोनों मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व की उपस्थिति बनी रहती है। दो शर्तें अवश्य ही विद्यमान रहती हैं जब कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत किसी राज्य के राष्ट्रीय जनो को क्षति पहुँचती है। पहला दावे की राष्ट्रीयता (nationality of the claim) और दूसरा स्थानीय उपचारों की परिसमाप्ति (exhaustion of local remedies)।

**दावे की राष्ट्रीयता :—**राजनयिक कार्यों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रिया की शरण लेने का अधिकार अपने ही राष्ट्रीय जनो की मध्यस्थता में विद्यमान रहता है। इसका उद्देश्य अपने राष्ट्रीय जनो में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान उपस्थिति करना होता है क्योंकि राज्य और व्यक्ति के बीच में राष्ट्रीयता का प्रतिबन्ध यह है जिसके एकमात्र कारण से राज्य को राजनयिक सुरक्षा का अधिकार मिलता है (Panevezys Saldutisks Railway, 1939)।

**स्थानीय उपचारों की परिसमाप्ति :—**उपरोक्त प्रकार के दावे के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के सम्बन्ध में 'यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि दुष्कृतियों के सम्बन्ध में स्थानीय उपचारों का परिसमापन कर बिना जाय जिससे राज्य अपने राष्ट्रीय जनो को और से दूसरे राज्य के विरुद्ध दुष्कृतियों का दावा कर सके। यह केवल प्रक्रिया का नियम नहीं है और न तो यह सामान्य आचरण का ही नियम है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मौलिक विधि का नियम है जिसे हम राज्य का राज्य से दायित्व (State to State responsibility) कहते

हैं। यदि एक व्यक्ति को अपने प्रति की गई दुष्टृतियों का बदला मिल जाता है तो फिर अब राज्य का अधिकार नहीं रह जाता कि अपने राष्ट्रीय जनो की ओर से दूसरे राज्य के विरुद्ध दावा कर सके। जब तक कि उपचार की स्थानीय प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती तब तक अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व नहीं उत्पन्न हो सकता।

**सामूहिक कार्यों का दायित्व (Liability for mob action).**—यह निर्धारण करने में एक कठिनाई उत्पन्न होती है कि एक विदेशी व्यक्ति की क्षतियों के लिए कोई राज्य उत्तरदायी है अथवा नहीं, सामान्यतः से यदि यह क्षति सामूहिक हिंसात्मक कार्यवाहियों का रूप से लेती है। अगर सामूहिक हिंसा की कार्यवाही सिद्ध हो जाती है तो राज्य का कोई दायित्व नहीं रह जाता किन्तु दूसरी ओर यदि यह सिद्ध हो जाता है कि यह क्षति राज्य के प्राधिकारियों की उपेक्षा या उदासीनता के परिणामस्वरूप हुई है और एक विदेशी को सम्पत्ति अशक्त हुई है तो निश्चय ही इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य का दायित्व माना जायेगा।

हारवर्ड रिसर्च (Harvard Research) ने यह एक सिद्धान्त निर्धारित किया था कि यदि किसी विदेशी को किसी व्यक्ति या सामूहिक हिंसा द्वारा क्षति पहुँचती है तो इसके लिए सम्बन्धित राज्य पर दायित्व होगा, किन्तु शर्त यह कि वह राज्य उस हिंसात्मक कार्यवाही को रोकने में उदासीन रहा हो। कुछ व्यक्तियों या किसी समूह द्वारा एक विदेशी पर क्षति पहुँचाये जाने के आधार पर राज्य का जो दायित्व माना जाता है, सिद्धान्त रूप में उस नियम से भिन्न नहीं कहा जा सकता कि किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गये कार्यों के दायित्व का नियन्त्रण राज्य ही किया करता है किन्तु यदि उस क्षति में किसी बहुत बड़े समूह का हाथ है तो क्षतियों को रोकने की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। विदेशियों के सम्बन्ध में राज्य के दायित्व के सिद्धान्त का निरूपण रिचार्ड ओलेनी (Richard Olney) जो अमेरिका के सेक्रेटरी आफ स्टेट थे, ने निम्नलिखित शब्दों में किया है :

"The general position is that the responsibility of an established government for acts committed by rioters or insurgents depends upon the failure of the constituted authorities to exercise due diligence for protection of alien property when in a position to protect it and the imminence of danger is known." अर्थात् "साधारण स्थिति यह है कि लुटेरों द्वारा कारित किये गये कार्यों के प्रति किसी प्रस्थापित सरकार का उत्तरदायित्व सविधायिक प्राधिकारियों की उस असफलता पर निर्भर करता है कि वे विदेशी संपत्ति के संरक्षण में उस समय पूरी सतर्कता न कर सके, जब कि ऐसे खतरे का आभास हुआ कि उस संपत्ति का संरक्षण आवश्यक है।"

# अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें

## अध्याय २५

### १. लीग ऑफ नेशन्स

#### (The League of Nations)

**इसकी उत्पत्ति** —लीग की स्थापना वर्साई की सन्धि के अन्तर्गत जो विश्व तथा संयुक्त राज्या और जर्मनी के मध्य हुई छून २८ सन् १९१९ को हुई। सन्धि सम्मेलन में कई मसौदों पर विचार किया गया और प्रतिज्ञा पत्र सम्मेलन द्वारा अप्रैल २८ सन् १९१९ को मंगीत किया गया। इसके अनुसार लीग एक २६ अनुच्छेद वाला प्रतिज्ञा पत्र के अधीन सन् १९२० में स्थापित की गई। यह प्रतिज्ञा-पत्र वर्साई की सन्धि तथा अन्य सन्धि संधियाँ का प्रथम भाग था। लीग की स्थापना किया जाना प्रेसीडेन्ट विल्सन के १४ बिन्दुओं (points) में से एक था किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ने वर्साई संधि का अनुसमर्थन अस्वीकार कर दिया जिसका कारण अमेरिका को लीग का बाहर रहना पड़ा।

**सदस्य** —लीग के सदस्य शान्ति-संधियाँ पर हस्ताक्षर करने वाले विश्व राष्ट्र थे जिन्होंने बाद में अपनी संधियों का अनुसमर्थन किया—उदाहरणार्थ ब्रिटिश साम्राज्य, इटली, जापान, चीन, इत्यादि, तटस्थ राज्य जिन्होंने आरम्भ में ही लीग के प्रतिज्ञा पत्र को स्वीकृत कर लिया था अर्थात् स्विटजरलैंड, नीदरलैंड, फारस, इत्यादि तथा वे राज्य जो प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १ के अनुबन्धों के अधीन सदस्य बनने लगे थे।

**उद्देश्य** —लीग के मुख्य उद्देश्य दो थे अर्थात् (१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाय रखना, तथा (२) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की उत्पत्ति जैसा कि प्रतिज्ञापत्र की निर्मललिखित प्रस्तावना से प्रकट है।

‘उच्च सविदाकार पक्षकार अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की उत्पत्ति के विभिन्न तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा प्राप्त करने के लिये, युद्ध से विमुक्त रहने के कर्तव्यों को मान कर, राज्यों के बीच में सर्वसामान्य न्याय तथा सम्मानपूर्ण सम्बन्धों की व्यवस्था करके सरकारों के मध्य पारस्परिक व्यवहार के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विधि का समुचित ज्ञान के अनुसार आचरण ही को वास्तविक नियम मानकर तथा संगठित लोगों के पारस्परिक व्यवहार में न्याय तथा सच्चा सम्मान को स्थापन करने लीग ऑफ नेशन्स के इस प्रतिज्ञा-पत्र से सहमत होते हैं।’

**संविधान** —लीग एक सभा, एक संसद तथा एक स्थायी सचिवालय मिलकर बनी थी।

सभा ( The Assembly ) .—लीग की सभा की बैठक प्रतिवर्ष जेनेवा में होती थी । प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद ३ में यह व्यवस्था की गई थी कि लीग का प्रत्येक सदस्य सभा में तीन प्रतिनिधि भेज सकता था किन्तु सदस्यों में से प्रत्येक को केवल एक ही वोट का अधिकार था । सभा का अधिवेशन जनता के ममल होता था तथा इसके निर्णय एकमत से होने चाहिये थे यदि प्रतिज्ञा-पत्र में अन्यथा उपबन्धित न हो तो । सभा अपने अधिवेशन में किसी विषय पर विचार कर सकती थी जो लीग के क्षेत्र के भीतर आता हो अथवा जिससे विश्व-शान्ति पर प्रभाव पड़ता हो ( अनुच्छेद २ ), परन्तु ऐसे भी विषय थे जो केवल परिषद् के विचार के लिये ही भेजा जा सकता था और वे सभा द्वारा अपने अधिवेशन में नहीं लिये जा सकते थे । प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद ५ के अनुसार सभा के किसी अधिवेशन में किये गये निर्णयों के लिये सभा में उपस्थित लीग के सब सदस्यों की स्वीकृति अपेक्षित थी । इसके अपवाद प्रक्रिया के विषय थे जिनके सम्बन्ध में निर्णय सभा में उपस्थित लीग के सदस्यों के बहुमत से किये जा सकते थे ।

परिषद् ( Council ) :—यह लीग की कार्यकारिणी समिति थी । प्रारम्भ में लीग की कौंसिल पाँच मुख्य मित्र तथा सम्बन्धित शक्तियों जिनके स्थायी स्थान थे तथा चार अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों तक ही सीमित थी जो सभा द्वारा निर्वाचित होते थे, किन्तु संयुक्त राज्य की कांग्रेस ने वर्साई की संधि को सन् १९२० में अनुसमर्थन करने तथा लीग में सम्मिलित होने से अस्वीकार कर दिया । सभा के बहुमत की स्वीकृति से कौंसिल लीग के लिये और अधिव सदन्यो का नाम प्रस्तावित कर सकती थी जिनके प्रतिनिधि सदन के सदस्य होते थे । लीग के सदस्य का तदर्थ ( ad hoc ) प्रतिनिधित्व भी होता था जब उसके हित विचाराधीन होते थे किन्तु अनुबन्धन यह था कि उसका कौंसिल में नियमित प्रतिनिधित्व न हो । सन् १९२६ में कौंसिल का संगठन जर्मनी को लीग में प्रवेश करने तथा कौंसिल में एक स्थायी स्थान दिये जाने के कारण बदल दिया गया और अन्त में कौंसिल में भी ११ अस्थायी सदस्य हो गये जिनमें से तीन प्रत्येक वर्ष तीन वर्षों के लिये निर्वाचित होते थे ।

परिषद् भी लीग के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत के अथवा विश्व शान्ति पर प्रभाव डालने वाले किसी विषय पर भी विचार कर सकती थी, लेकिन इसके प्रतिरिक्त कुछ ऐसे विषय थे जो केवल इसी के प्रसंग में थे यथा सेक्रेटरी-जनरल द्वारा की गई कर्मचारी गणों की नियुक्ति वा पुष्टिकरण, निशस्त्रीकरण की योजनाओं का बनाना, प्रतिज्ञा-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण किसी सदस्य का निकालना, आदेशित प्रदेशों से व्यवहार तथा उनका निरीक्षण, इत्यादि । इसके

निर्णय सामान्यतः उन विषयों को छोड़ कर जो प्रक्रिया सम्बन्धी होते थे प्रपचा जिनमें ग्रन्थया उपबन्धित होता था एवमत से होने चाहिए थे । सामान्यतः परिषद् का अधिवेशन वर्ष में तीन बार होता था ।

**सचिवालय ( The Secretariat ) :**—सचिवालय के सर्वोच्च पद पर सेक्रेटरी जनरल होता था जो ससद की स्वीकृति पर ग्रन्थ सचिवों तथा कर्मचारियों को नियुक्त करता था । सचिवालय एक स्थायी संस्था थी जो जेनेवा में स्थापित की गई थी । सचिवालय का व्यय लीग के बजट से होता था जिसका भा लीग के सदस्य सभा द्वारा निर्णीत अनुपात में वहन करते थे । सचिवालय परिषद तथा सभा का कार्यक्रम बनाता था तथा अधिवेशनों का विवरण रखता था और प्रशासकीय कार्य का प्रारूप रखता था । सचिवालय भिन्न-भिन्न खंडों में विभाजित था और प्रत्येक खंड उसका दिये गये विशेष कार्य को करता था ।

लीग के प्रतिज्ञा-पत्र में परिषद् को सैनिक, नाविक तथा वायु सम्बन्धी प्रस्ताव पर सामान्यतः सम्मति देने के लिये तथा निःशस्त्रीकरण की योजनाओं के निष्पादन के लिये, स्थायी आदेशित प्रदेश सम्बन्धी आयोग, स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सघ के स्थापन के लिये एक स्थायी आयोग की व्यवस्था की गई थी ।

**विरह-शान्ति का पोषण ( The Maintenance of World Peace )**—लीग का मुख्य उद्देश्य भगडों के शान्तिपूर्वक समझौता द्वारा युद्ध का निराकरण था तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रतिज्ञा-पत्र में अनेक व्यवस्थाएँ की गईं । प्रतिज्ञा पत्र के अनुच्छेद ८ में यह स्वीकृत किया गया कि शान्ति-स्थापना में यह अपेक्षित है कि राज्य की सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों के पालन के लिये सामान्य कार्य-शैली के अनुरूप राज्य का शस्त्रीकरण जितना कम हो सके उतना कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिये इसके द्वारा परिषद् से यह अपेक्षित था कि वह भिन्न-भिन्न सरकारों के विचारार्थ तथा कार्य-शैली के लिये ऐसे अभाव के निमित्त योजनाएँ बनाये । अनुच्छेद १० के अधीन लीग के सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे लीग के सब सदस्यों की क्षेत्रीय अखंडता तथा वर्तमान राजनैतिक स्वतंत्रता का बाह्य आक्रमण के विरुद्ध सम्मान करेंगे तथा उसे बनाये रखेंगे । इस अनुच्छेद द्वारा वसर्दी की सधि के फलस्वरूप सुलह के उपरान्त किये गये क्षेत्रीय प्रबन्धों का बाह्य आक्रमण के विरुद्ध बनाये रखने की प्रतिभूति थी । प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद ११ से १७ में भगडों का शान्तिपूर्वक समझौता करने की योजना थी । अनुच्छेद ११ में सदस्यों को यह आज्ञा दी गई थी कि किसी भगडे को तय करने के लिये इन प्रयोग न करें वरन् उसे या तो पंचायत के अथवा न्यायिक निर्णयार्थ प्रपचा सदन

द्वारा जाँच के लिये प्रत्यपित करें। यदि लीग अथवा विवाचक भगड़े के सौंपे जाने के उपरान्त छः मास के भीतर एकमत से निर्णय पर न पहुँच सकें तो वे राज्य जिनके आपस में झगड़ा था, पंचायती फैमले अथवा न्यायिक निर्णय अथवा परिपद् की रिपोर्ट के उपरान्त तीन मास तक युद्ध नहीं कर सकते थे। अनुच्छेद १४ द्वारा समा अथवा परिपद् को यह अधिकार दिया गया था कि वे किसी भगड़े अथवा प्रदन को अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय को सम्मति के लिये निर्देशित करें। अनुच्छेद १६ में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई लीग का सदस्य पंचायत, न्यायिक निर्णय अथवा परिपद् द्वारा जाँच सम्बन्धी अपनी प्रतिज्ञा को उल्लंघन करके युद्ध करे तो यह समझा जायगा कि उसने स्वतः लीग के सब सदस्यों के विरुद्ध युद्ध का कार्य किया है और वे तदुपरान्त तत्काल ही प्रतिज्ञा भंग करने वाले राज्य से सब व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध तोड़ देंगे तथा अपने तथा उसके राष्ट्रीय जनों के बीच सब आवागमन निषिद्ध कर देंगे। अनुच्छेद १७ में लीग के किसी सदस्य तथा बाहरी जनों के बीच भगड़े को तय करने की भी व्यवस्था की गई थी। उस दशा में बाहरी राज्य के नाम एक निदेश जारी किया जाता था कि वह ऐसे भगड़े के प्रयोजन के लिये उसकी सदस्यता के कर्तव्यों को स्वीकृत करे, किन्तु यदि उसने लीग के किसी सदस्य के लिये युद्ध करके उसे स्वीकृत करने से इन्कार किया तो अनुच्छेद १६ के अनुबन्ध ऐसे कार्य करने वाले राज्य के विरुद्ध लागू कर दिये जाते थे।

**प्रत्यहरण (Withdrawal) :**—लीग के सदस्य को दो वर्ष की नोटिस देकर अलग हो जाने का अधिकार था। वह प्रतिज्ञा को उल्लंघन करने के लिये, संसद के निर्णय से जिससे अन्य सदस्यों के प्रतिनिधि सहमत हो जायें, निकाला जा सकता था। इसी प्रकार कोई सदस्य अपनी सदस्यता को, प्रतिज्ञा-पत्र के किसी संशोधन से, यदि वह संशोधन संसद तथा सदस्यों के बहुमत से अनुसमर्थित कर दिया गया हो तो सहमत होने से सदस्यता समाप्त कर सकता था।

**लीग की स्थिति (Position of League) :**—लीग मात्र वेशन्त कोई चरिष्ठ राज्य नहीं था तथा उसमें कोई सर्वव्यापी वैधानिक शक्ति नहीं थी। अपने निर्णयों को प्रवृत्त करने के लिये यह पूर्णतः अपने सदस्य राज्यों की सद्भावना पर आश्रित था। लीग के सम्पूर्ण ढाँचे की जड़ ही सदस्यों की सम्मति पर थी। लीग के प्रतिज्ञा-पत्र में दी गई व्यवस्थायें सदस्यों की स्वतन्त्रता को पूर्णतः संरक्षित करती थी क्योंकि बहुत से प्रमुख विषयों में उनमें परिपद् अथवा समा का एकमत से निर्णय अपेक्षित था। उनमें लीग के सदस्यों को कुछ विशेष अवस्थाओं के उत्पन्न होने पर लीग से अलग हो जाने की अनुमति थी।



लीग राज्यों की एक सभा थी जिसके द्वारा वे कुछ विषयों में अन्तर-सहयोग की उन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा प्राप्त करने के निवे-  
रने की स्वतन्त्रता की पारस्परिक रूप से सीमित कर देते थे। वह निर्वि-  
स न तो सच था और न प्रसन्न, क्योंकि प्रत्येक सदस्य अपने बाह्य व्यापार  
नियमित करने की पूर्ण स्वतन्त्रता रखता था और लीग अपने सदस्य राज्य  
जो कुछ उन्होंने लीग को इच्छापूर्वक तथा सहमति से आत्मसमर्पण किया था,  
अतिरिक्त और कोई नियमन का प्रयोग नहीं कर सकती थी। किन्तु इस  
लीग के निर्णय केवल सन्तुति की प्रकृति के होते थे, और अधिकांश में सदस्य  
के निर्णयों के एकमत होने की अपेक्षा करते थे। इसको राज्य भी नहीं वह  
सकता था। इसमें राज्य के लक्षणों का अभाव था क्योंकि यद्यपि यह स्थायी  
से संगठित सभा थी तथापि इसका नञ्चा एक विशिष्ट क्षेत्र पर, जिसके अन्तर्गत  
सर्वोच्च प्राधिकार हो, नहीं था। लीग का प्रतिज्ञा-पत्र इस समय तक अनेक  
राज्यों के कुटुम्ब की एक लिखित सविधान द्वारा संगठित करने का एक प्रयत्न  
था, तथा लीग संगठित राज्यों के एक कुटुम्ब के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी।

लीग की असफलता के कारण ( Causes of the Failure of the League ) :—महायुद्ध का अन्त सन् १९१९ में जर्मनी के साथ शान्ति की संधि  
स्थापित करके हुआ जो वर्साई की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है जिसके सबसे अग्रणी  
पर लीग आफ नेशन्स का प्रतिज्ञा-पत्र था। प्रतिज्ञा-पत्र बाद में चीन, रूस, पराजित  
जर्मनी तथा उसके मित्रों को छोड़कर विश्व की प्रत्येक शक्ति द्वारा स्वीकृत कि-  
गया। प्रेसीडेंट विल्सन ने वर्साई की सन्धि पर जिसमें लीग आफ नेशन्स का प्रतिज्ञा-  
पत्र सम्मिलित था, हस्ताक्षर किये थे जिसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका लीग का  
संस्थापक सदस्य बन गया। तथापि संयुक्त राज्य के सेनेट ने प्रवेश का अनुमति  
रोक देने का निश्चय किया और संयुक्त राज्य अमेरिका को लीग के बाहर आ-  
रूप में इसीलिये रखा क्योंकि कांग्रेस यूरोप के क्षेत्रीय स्थिति ( व्यवस्था ) में सह-  
होने अथवा उसकी प्रतिभूति करने के लिये उत्तम न थी।

सन् १९१४-१८ के विश्वयुद्ध के विजेताओं तथा पराजितों में बड़ा व्याप-  
क मतभेद था और पराजित जर्मनी पर दुसह शतों को आरोपित किये जाने के सत-  
किसी विश्व-संघ को सफलतापूर्वक कार्य करने का अवसर बहुत ही कम होता।  
अतः लीग आफ नेशन्स की स्थापना आये आने वाले कष्टों के निवारणार्थ केवल  
उपाय थी। लीग के आरम्भ से ही इससे सदस्य इस बात से सतर्क रहे कि  
कोई खट न भरा जाय जिससे उसकी वैयक्तिक सार्वभौमिकता में विघ्न पड़े।  
अवश्यभावी परिणाम यह हुआ कि लीग अपने इतिहास के आरम्भ में ही, एक

इसके सगठित होने के सक्कटपूर्ण वर्षों में ही सयुक्त राज्य अमेरिका के अलग हो जाने से तथा रूस और प्रथम विश्वयुद्ध के मित्र राष्ट्रों के शत्रुओं के प्रवेश न किये जाने से लँगड़ी हा गई ।

लीग वर्साई सन्धि की धारा थी और उसकी पूर्ति के साथ बधी हुई थी । प्रारम्भ में जितने शक्तिशाली राज्य लीग में सम्मिलित हुये थे, उन्हें वर्तमान संधियाँ तथा क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के लिये किसी वस्तु की आवश्यकता थी । लीग का प्रत्येक सदस्य विजेता राज्यों द्वारा पेरिस में बनाये गये मानचित्र में दिये हुये प्रत्येक दूसरे सदस्य के प्रादेशिक ऐक्य तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता की प्रत्याभूति करने की पूर्ण प्रतिज्ञा किये हुए था ।

लीग आफ नेशन्स का इन शस्त्रीकरण सम्मेलन अपने उद्देश्य में असफल रहा । जर्मनी ने वर्साई की सन्धि के सेना सम्बन्धी खंडों को अस्वीकृत करके अपने शस्त्रीकरण तथा सैनिक शक्ति को बढ़ाना प्रारम्भ किया । लीग का पवित्र प्रस्ताव जिसके द्वारा यह उद्घोषित किया गया कि जर्मनी ने वर्साई की संधि को भंग किया है, किसी प्रयोजन का न रहा ।

जब जर्मनी लीग में सन् १९२५ में सम्मिलित हुआ तो लीग के सम्बन्ध में लोगों की यह आशा बढ़ गई थी कि यह सफलतापूर्वक कार्य करेगी किन्तु सन् १९३३ में हिटलर के अधिनायक-तन्त्र शासन की स्थापना के उपरान्त जर्मनी ने लीग को पुनः त्याग दिया । सन् १९३१ में लीग मंचूरिया में चीन के विरुद्ध जापानी आक्रमण को रोकने में असफल रही । इसमें सन्देह नहीं कि लीग ने जापान द्वारा प्रतिज्ञा पत्र के कर्तव्यों का उत्पन्न किये जाने की तीव्र निंदा की लेकिन इससे जापान लीग से हट गया और लीग मौन रही । सन् १९३४ में रूस लीग में सम्मिलित हुआ तथा लीग की गति कुछ तीव्र हुई, किन्तु यह शक्ति की प्राप्ति केवल क्षणिक थी । सन् १९३५ में इटली ने ऐबीसीनिया पर आक्रमण कर दिया तथा उसी वर्ष सितम्बर में ऐबीसीनिया ने प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १० के अन्तर्गत लीग से अग्रिल की । इस अनुच्छेद के अंतर्गत सदस्यों को लीग के सब सदस्यों की क्षेत्रीय अखंडता तथा वर्तमान राजनैतिक स्वतन्त्रता का सम्मान करने तथा उनको बाह्य आक्रमण के विरुद्ध रक्षा करने की बाध्य किया गया था । जब लीग ने इटली के विरुद्ध आधिक तथा द्रव्य सम्बन्धी रोक आज्ञाये लगाना चाहा तो इसको पता लगा कि इसके हाथ बँधे हुए थे क्योंकि भिन्न-भिन्न सदस्य जो इसके अवयव थे अपने-अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे थे, और तब आक्रमणकारी की शान्ति के लिये बाध्य करने का लीग का कार्य असफल रहा । इटली लीग से अलग हो गया और ऐबीसीनिया को जीतने से नहीं राका जा सका, क्योंकि लीग ने अपनी रोक-अनुशास्तियों (sanctions) को केवल व्यापार तक

ही सीमित रखना और सैनिक रोक अनुशास्त्रियों को देने के लिये आगे न बढ़ सकी। जर्मनी ने सन् १९३६ में राइनलैंड पर पुनः कब्जा कर लिया। जर्मनी द्वारा १९३८ में ओस्ट्रिया के, तथा म्यूनिच की सन्तुष्टीकरण नीति के होने पर भी १९३९ में चेकोस्लोवाकिया के संयोजन के विरुद्ध लीग आवाज नहीं उठा सकी। जब स्पेन में फिनलैंड पर आक्रमण किया तो लीग असहाय अवस्था में खड़ी रही तथा अपने अपनी प्रभावशाली अप्रसन्नता तथा नैराश्य सोवियत सरकार को निकाल कर दिखलाई। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लीग का अन्तिम कार्य था। विश्व भर के असंख्य लोगों के लिये शान्ति प्राप्त करने में लीग को इस नैराश्यपूर्ण असफलता का यह परिणाम हुआ कि शक्ति का संतुलन स्थापन करने के लिये लीग पर विश्वास करने के स्थान पर राज्य गठबन्धनों, संधियों तथा गुटों की पुरानी रीति पर भाव बलें गये।

लीग की असफलता के अन्य कारण भी ध्यान देने योग्य हैं। लीग में हर महत्वपूर्ण निर्णयों में एकमत का होना अपेक्षित था। सभा तथा परिषद के बीच के कृत्यों की कोई स्पष्ट सीमा नियत नहीं थी। परिषद को केवल अभिस्ताव करने से (सिफारिशों) शक्तियाँ थी तथा यह अपने निर्णयों को सैनिक अनुशास्त्र लगाकर लागू नहीं कर सकती थी। लीग एक सर्वोच्च सार्वभौमिक राज्य नहीं था तथा शांत हिक्र उपायों का, जो किसी विश्वसंध के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिये आवश्यक अंग है, अवलम्बन नहीं कर सकता था। लीग राज्यों की एक सभा थी तथा विश्व के लोगों की आवश्यकताओं का अधिक ध्यान नहीं रखती थी। राज्यों को धार के सामान्यतः मामान्य हितों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का भार धरने और वे की अनिच्छा थी। निःशस्त्रीकरण पर बारम्बार असहमति होने के कारण वहाँ उन्नति प्रवृद्ध रही। बर्साई की सन्धि पर विजित राज्यों के साथ जो प्रत्यापन किया गया वह उनके मस्तिष्क में अभी ताजा था क्योंकि सन्धि के अनुबन्ध अपनी प्राप्ति में कहीं अधिक कठोर थे और लीग में सन्धि के पुनरोक्षण की व्यवस्था सदस्यों के एकमत निर्णय को छोड़कर अन्यथा कोई नहीं की थी। कोई सदस्य परिषद में सभा के सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुसमर्थित सशोधन से सहमत होने से प्रत्योहार हार पर निकाला जा सकता था अथवा अपनी सदस्यता समाप्त कर सकता था। इस परिणाम यह हुआ कि हठी सदस्य लीग के निर्णयों के अनुसार चलने को मजबूर नहीं किया जा सकता था। फिर अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्वायत्त न्यायालय के अन्तर्गत उल्लंघन करने दिया गया अथवा उनको आत्महानि के बिना विश्व की शान्ति की सुरक्षा को संकट में डालने दिया गया। किसी बड़ी शक्ति द्वारा किये गये दबाव

के साथ प्रभावोत्पादक रीति से व्यवहार करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे अधिक लोग का किसी राज्य द्वारा युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया जाने की दशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। दोनों युद्धकारियों द्वारा युद्ध के नियमों का कठोरता से पालन प्रवृत्त कराने के लिये अपराध दंडनीय बना दिया जाना चाहिये थे।

अन्त में यह कहा गया है कि लोग आफ नेशनस इसलिये असफल रही कि इसके दाँत नहीं थे। यह बात जहाँ तक इसका सम्बन्ध है, सत्य है। लोग की असफलता का मुख्य कारण यह था कि इसके सदस्य उन सिद्धान्तों को जिसके लिये यह खड़ी थी पालन नहीं करते थे। वे उन बातों को पूर्ण नहीं करते थे जिनके लिये वे बचनबद्ध थे।

## अध्याय २६

### २. संयुक्त राष्ट्र सघ

(United Nations Organization)

**इसकी उत्पत्ति (Its Genesis)**—सन् १९३८ तक लोग आफ नेशनस एक निष्क्रिय संस्था के रूप में रह गई थी। जापान, इटली तथा जर्मनी के हठ के कारण तो बाधाय इसके समक्ष उपस्थित हुईं वे भ्रष्ट प्रमाणित हुईं। इनका कारण यह था कि बड़ी बड़ी शक्तियाँ उन विषयों में ढीला-ढाला दृष्टिकोण रखती थी, जो उनको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते थे। ये बड़ी-उड़ी शक्तियों का संतुलन स्थापना करने के निमित्त गठबन्धनों, सन्धियों तथा गुटों की नीति को अपना रही थी। सन् १९३९ में द्वितीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हुआ। ज्यों-ज्यों युद्ध का रोमांचकारी भय तथा क्रूर विनाश भीषण होता गया त्यों त्यों शान्ति स्थापना करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की उन्नति के लिये राज्यों के एक सामान्य सघ की स्थापना करने के विचार का महत्त्व बढ़ता गया। इस विषय में अवश्य कुछ संदेह था कि क्या लोग आफ नेशनस को पुनर्जीवित किया जाय किन्तु इस सर्वसामान्य सम्मति के कारण कि एक नया विश्वसघ होना चाहिये जो विश्व के असंख्य प्राणियों में अटल शान्ति की प्राप्ति का संचार कर सके तथा उनमें विश्वास उत्पन्न कर सके, यह विचार त्याग दिया गया। संक्षेप में वह क्रम निम्नलिखित है जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र सघ बना।

१. लन्दन की घोषणा (London Declaration) :—लन्दन की घोषणा जून १२ सन् १९४१ को सेंट जेम्स पैलेस में ब्रिटानिया, कनेडा, मोस्टोविया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका तथा बहुत सी निर्वासित सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित की गई। प्रलेख ने पृथक शान्ति के विरुद्ध घोषणा की और कहा कि उनका विचार परस्पर तथा अन्य स्वतंत्र लोगों के साथ शान्ति के समय तथा युद्ध में संयुक्त रूप से कार्य करने का है।

२. अटलांटिक चार्टर (Atlantic Charter) :—अगस्त सन् १९४१ में प्रेसीडेंट रूजवेल्ट तथा मिस्टर चर्चिल एक सम्मेलन में अटलांटिक महासागर में प्रिन्सिपल बेल्स नामक जहाज में मिले। उन्होंने १४ अगस्त सन् १९४१ को एक चार्टर पर हस्ताक्षर किया जो अटलांटिक चार्टर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा नए प्रयोग की तथा क्षेत्रों को हड़प जाने की निंदा की गई तथा आक्रमण से सुरक्षा का प्रश्न सामने रखा गया और लोगों को अपनी स्वेच्छा से शासन व्यवस्था चुनने की स्वतंत्रता दी गयी।

३. संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा (United Nations Declaration) :—इसके उपरान्त संयुक्त राष्ट्र संधि की घोषणा आयी है जिस पर २६ राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा जनवरी १ सन् १९४२ को वाशिंगटन में हस्ताक्षर किया गया। इस घोषणा में अटलांटिक चार्टर के सिद्धान्तों का समर्थन किया गया और प्रत्येक राज ने शपथ ली कि वह अपने सम्पूर्ण साधनों को शत्रु के विरुद्ध प्रयोग करेगा। प्रत्येक सदस्य-राज्य की सरकार ने प्रत्येक सरकार के साथ सहयोग करने का लिये और वैयक्तिक रूप से शत्रु से शान्ति करने या सौदा लेने से अपने को रोक रक्खा कर लिया।

४. मास्को तथा तेहरान-सम्मेलन (Moscow and Teheran Conferences) :—१ नवम्बर, सन् १९४१ की मास्को की घोषणा में ब्रिटानिया, यू.एस. राज्य अमेरिका, रूस तथा चीन के परराष्ट्र-मंत्रियों ने यह स्वीकृत किया कि एक राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि वर्तमान तत्काल एक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाय जो सब शान्तिविहीनता की सार्वभौमिक एकता के सिद्धान्तों पर आधारित हो और ऐसे सब राज्यों के बीच में छोटी हों अथवा बड़ी, सदस्यता के लिये खुली हुई हों।

दो मास उपरान्त रूजवेल्ट, स्टैलिन तथा चर्चिल ने तेहरान में यह घोषणा की कि उनको इस बात का विश्वास है कि उनका ऐवय अमर शान्ति साधने का है।

५. डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन (Dumbarton Oaks Conference) :—अटलांटिक चार्टर तथा मास्को और तेहरान की घोषणाओं के सिद्धान्तों को

में परिणत करने के लिये सितम्बर १९४४ में वाशिंगटन में ब्रितानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा चीन के प्रतिनिधियों के बीच एक भवन में जिसे डबारटन भवन कहा जाता है वार्तालाप हुआ । सम्मेलन अक्टूबर ७ सन् १९४४ को समाप्त हुआ जब विश्वसंध की रूपरेखा के लिये प्रस्ताव प्रकाशित किए गए । यह संयुक्त राष्ट्र संध को प्रथम सरकारी रूपरेखा ( blue print ) थी ।

डबारटन भवन के प्रस्तावों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संध में विश्वशांति स्थापित करने के लिये प्रमुख संस्था सुरक्षा परिषद् ( Security Council ) की स्थापना का अभिप्राय था जिसमें पाँच बड़ी शक्तियाँ ( Big Five ) अर्थात् चीन, फ्रांस, संयुक्त समाजवादी रूसीय प्रजातन्त्र, ब्रितानिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थायीरूप से प्रतिनिधित्व था । किन्तु परिषद् में मत देने की प्रक्रिया प्रस्तावों में वर्णित नहीं थी । इसकी विवेचना रूजवेल्ट, चर्चिल तथा स्टेलिन के मध्य में याल्टा ( क्रीमिया ) में हुए सम्मेलन में की गई । ११ फरवरी सन् १९४५ को सम्मेलन ने यह घोषणा की कि यह विषय निश्चित हो गया है । यह भी निश्चय हो गया कि संयुक्त राष्ट्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में अप्रैल २५ सन् १९४५ को एक सम्मेलन में ऐस संध का डबारटन भाव में परस्पर हुई वार्तालापों में प्रस्तावित क्रमानुसार एक चार्टर तैयार करने को बुलाया जाय ।

६ सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ( The San Francisco Conference ) —  
अन्त में ५० राज्यों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को में २५ अप्रैल तथा २६ जून सन् १९४५ के बीच मिले । डबारटन भवन के प्रस्ताव, याल्टा की सविदा तथा उन पर विभिन्न राज्यों द्वारा सुझाये गए सशोधनों पर विचार करते हुए सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र संध का चार्टर तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि ( Statute ) निर्मित किया । चार्टर को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तथा सभी प्रतिनिधियों ने उस पर २६ जून सन् १९४५ को हस्ताक्षर किया । संयुक्त राष्ट्र संध का चार्टर २४ अक्टूबर सन् १९४५ को लागू हुआ जब पाँच मूल सदस्यों ने अर्थात् चीन, फ्रांस, रूस, ब्रितानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा आधिकार में अन्य हस्ताक्षर करने वालों ने अपने-अपने अनुमोदन के अंश स्वीकृत किए । उस समय से २४ अक्टूबर निरन्तर "संयुक्त राष्ट्र-दिवस" स्मरणोद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

इसके उद्देश्य :—संयुक्त राष्ट्र संध के उद्देश्य उसका चार्टर में व्यक्त किये गये हैं । अन्य विवरणों को दृष्टि से हटा देने पर चार्टर की प्रस्तावना निम्नलिखित है .—

"हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, अपने भावों सन्तानों को युद्ध के उत्पात से बचाने के लिए जिससे कि दो बार हमारे जीवनकाल में हो मानवता का भवणाय कष्ट

१. लन्दन की घोषणा ( London Declaration ) —लन्दन की घोषणा जून १२ सन् १९४१ को सेंट जेम्स पैलेस में ब्रितानिया, केनेडा, ओस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका तथा बहुत सी निर्वासित सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित की गई। प्रलेख ने पृथक् शान्ति के विरुद्ध घोषणा की घोर कक्षा कि उनका विचार परस्पर तथा अन्य स्वतन्त्र लोगों के साथ शान्ति के समय तथा युद्ध में संयुक्त रूप से बांध करने का है।

२. अटलांटिक चार्टर (Atlantic Charter) —अगस्त सन् १९४१ में प्रेसीडेंट रूजवेल्ट तथा मिस्टर चर्चिल एक सम्मेलन में अटलांटिक महासागर में प्रिंस आफ वेल्स नामक जहाज में मिले। उन्होंने १४ अगस्त सन् १९४१ को एक चार्टर पर हस्ताक्षर किया जो अटलांटिक चार्टर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा बल प्रयोग की तथा क्षेत्रों की हड़प जाने की निंदा की गई तथा आक्रमण से सुरक्षा का प्रश्न सामने रखा गया और लोगों का अपनी स्वेच्छा से शासन व्यवस्था चुनने की स्वतन्त्रता दी गयी।

३. संयुक्त राष्ट्र सभ की घोषणा (United Nations Declaration) — इसके उपरान्त संयुक्त राष्ट्र सभ की घोषणा आयी है जिस पर २६ राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा जनवरी १ सन् १९४२ को वाशिंगटन में हस्ताक्षर किया गया। इस घोषणा में अटलांटिक चार्टर के सिद्धान्तों का समर्थन किया गया और प्रत्येक राज्य ने शपथ ली कि वह अपने सम्पूर्ण साधनों को शत्रु के विरुद्ध प्रयोग करेगा। प्रत्येक सदस्य-राज्य की सरकार ने प्रत्येक सरकार के साथ सहयोग करने का व्रत लिया और वैयक्तिक रूप से शत्रु से शान्ति करने या लोहा लेने से अपने को प्रतिबन्धित कर लिया।

४. मास्को तथा तेहरान-सम्मेलन (Moscow and Teheran Conferences) — १ नवम्बर, सन् १९४१ की मास्को की घोषणा में ब्रितानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा चीन के परराष्ट्र-मंत्रियों ने यह स्वीकृत किया कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि यथासम्भव तत्काल एक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जाय जो सब शान्तिप्रिय राज्यों की सार्वभौमिक एकता के सिद्धान्तों पर आधारित हो और ऐसे सब राज्यों की बाहें वे छोटी हो भयवा बड़ी, सदस्यता के लिये खुली हुई हो।

दो मास उपरान्त रूजवेल्ट, स्टेलिन तथा चर्चिल ने तेहरान में यह घोषणा की कि उनको इस बात का विश्वास है कि उनका ऐक्य अमर शान्ति लायेगा।

५. डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन (Dumbarton Oaks Conference) — अटलांटिक चार्टर तथा मास्को और तेहरान की घोषणाओं के सिद्धान्तों को कार्यरूप

में परिणत करने के लिये सितम्बर १९४४ में वाशिंगटन में ब्रितानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा चीन के प्रतिनिधियों के बीच एक भवन में जिसे डंबारटन ओवस कहा जाता है वार्तालाप हुआ। सम्मेलन अक्तूबर ७ सन् १९४४ को समाप्त हुआ जब विश्वसंघ की रूपरेखा के लिये प्रस्ताव प्रकाशित किए गए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रथम सरकारी रूपरेखा (blue print) थी।

डंबारटन ओवस के प्रस्तावों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वशान्ति स्थापित करने के लिये प्रमुख संस्था सुरक्षा परिषद् (Security Council) की स्थापना का अभिप्राय था जिसमें पाँच बड़ी शक्तियाँ (Big Five) अर्थात् चीन, फ्रांस, संयुक्त समाजवादी रूसीय प्रजातन्त्र, ब्रितानिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थायीरूप से प्रतिनिधित्व था। किन्तु परिषद् में मत देने की प्रक्रिया प्रस्तावों में वर्णित नहीं थी। इसकी विवेचना रुशवेल्ट, चर्चिल तथा स्टेलिन के मध्य में याल्टा (क्रीमिया) में हुए सम्मेलन में की गई। ११ फरवरी सन् १९४५ को सम्मेलन ने यह घोषणा की कि यह विषय निश्चित हो गया है। यह भी निश्चय हो गया कि संयुक्त राष्ट्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में अप्रैल २५ सन् १९४५ को एक सम्मेलन में ऐसे संघ का डंबारटन ओवस में परस्पर हुई वार्तालापों में प्रस्तावित क्रमानुसार एक चार्टर तैयार करने को बुलाया जाय।

६. सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन (The San Francisco Conference).— अन्त में ५० राज्यों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को में २५ अप्रैल तथा २६ जून सन् १९४५ के बीच मिले। डंबारटन ओवस के प्रस्ताव, याल्टा की सविदा तथा उन पर विभिन्न राज्यों द्वारा सुझाये गए सशोधनों पर विचार करते हुए सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सविधि (Statute) निर्मित किया। चार्टर को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया तथा सभी प्रतिनिधियों ने उस पर २६ जून सन् १९४५ को हस्ताक्षर किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर २४ अक्तूबर सन् १९४५ को लागू हुआ जब पाँच मूल सदस्यों ने अर्थात् चीन, फ्रांस, रूस, ब्रितानिया, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा घाघकाष में अन्य हस्ताक्षर करने वाला ने अपने-अपने अनुसमर्थन के प्रलेख प्रस्तुत किए। उस समय से २४ अक्तूबर निरन्तर "संयुक्त राष्ट्र-दिवस" स्मरणीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

इसके उद्देश्य :—संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य उस चार्टर में व्यक्त किये गये हैं। अन्य विवरणों को दृष्टि से हटा देने पर चार्टर की प्रस्तावना निम्नलिखित है :—

"हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, अपने भावों सन्तानों को युद्ध के उत्पात से बचाने के लिए जिससे कि दो बार हमारे जीवनकाल में ही मानवता का भवनायक कष्ट



मिला है; मनुष्य के मौलिक अधिकारों और उसके व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व में तथा पुरुषों और स्त्रियों के तथा छोटे और बड़े राष्ट्रों के समान अधिकारों में अपना विश्वास। पुनः एक बार दृढ़ कराने के लिये तथा स्थितियाँ उत्पन्न करने के लिये जिनमें न्याय और संधियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्याय से अन्य मूलभूत आधारों से उत्पन्न होने वाले वर्तव्यों का प्रति सम्मान स्थापित हो सके, तथा स्वतन्त्रता के और अधिक विस्तृत क्षेत्र में सामाजिक उन्नति बढ़ाने और जीवन स्तर और अधिक उन्नत करने के लिये, तथा इन लक्ष्यों का निमित्त सहिष्णुता का अभ्यास करने तथा शान्तिपूर्वक प्रच्छेद पद्धतियों के समान रहने के लिये, तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने के लिये अपनी शक्ति को संयुक्त करने के लिये, तथा इस बात को निश्चित करने के लिए कि सैनिक बल प्रयोग सामान्य हित के अतिरिक्त अन्य किसी अवसर पर नहीं किया जायेगा, तथा अन्तर्राष्ट्रीय यंत्र का सब जातियों की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति में प्रयोग करने के लिये यह दृढ़ निश्चय करते हैं कि इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये अपने प्रयासों को संयुक्त कर दें।

“इसी के अनुसार हमारी अपनी सरकारें... संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान चार्टर से सहमत हो गई हैं तथा इसके द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय सच स्थापित करती हैं जो संयुक्त राष्ट्र सच कहा जायगा।”

इस प्रस्तावना के मूल शब्द इस प्रकार हैं—“We the peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of International Law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom, and for these ends to practise tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and to unite our strength to maintain international peace and security, and to ensure... that armed force shall not be used, save in the common interest, and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples, have resolved to combine our efforts to accomplish these aims—

Accordingly, our respective governments... have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations”

चार्टर के अनुच्छेद १ में उद्देश्यों को और भी अधिक विस्तार में व्यक्त किया गया है। उममें यह कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन निम्नलिखित हैं :—अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच जन समुदाय के लिये समान अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धान्त पर आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना, आर्थिक, सामाजिक अथवा मानव जाति के लिये प्रेम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राष्ट्रों के कार्यों को समन्वय करने के निमित्त एक केन्द्र का कार्य करना।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्त :—चार्टर के अनुच्छेद २ में वे सिद्धान्त दिये गये हैं जो सघ तथा उनके सदस्यों द्वारा उपर्युक्त प्रयोजनों की सिद्ध करने में अनुसरण किये जाने चाहिये। वे निम्नलिखित हैं —

१. सघ अपने सब सदस्यों की सर्वव्यापी समानता के सिद्धान्त पर आधारित है। यह खूब कुछ प्रतिबन्धों के अन्तर्गत है। सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों के अधिकार संयुक्त राष्ट्र सघ के अन्य सदस्यों की अपेक्षा विशद हैं। परिषद् तथा सभा दोनों के प्रमुख निर्णयों की वैधता के लिए परिषद् के स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। चार्टर के मशोधन के लिये, संयुक्त राष्ट्र सघ में अन्य सदस्यों को प्रवेश करने के लिये, झगड़ों को तय करने के सम्बन्ध में निर्णयों तथा सन्तुतियों के लिये तथा उनको लागू करने के लिये उनकी सहमति आवश्यक है। इसके उपरान्त किसी विषय को प्रवृत्त करने के उपाय उनकी सहमति के बिना उनके विरुद्ध लागू नहीं किए जा सकते। इन विशद अधिकारों के अन्तर्गत स्थायी सदस्यों की समानता सार्वभौम राष्ट्रों के रूप में किसी प्रकार कम नहीं होती है।

२. सब सदस्य उन सब के लिये सदस्यता से उत्पन्न होने वाले अधिकारों तथा लाभों को निश्चित रूप से प्राप्त करने के लिये वर्तमान चार्टर के अनुसार अपने ऊपर लिये गये कर्तव्यों का सत्यता से पालन करेंगे।

३. सब सदस्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को इस प्रकार तय करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय को भय की भासना न हो।

४. सब सदस्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में किसी राज्य की क्षेत्रीय अखण्डता अथवा राजनीतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध बल प्रयोग की धमकी देने से अथवा बल प्रयोग करने से अलग रहेंगे।

५. सब सदस्य संयुक्त राष्ट्र सघ को किसी कार्य में जा इस चार्टर के अनुसार हो, सब प्रकार की सहायता देंगे तथा ऐसे किसी राज्य को जिसके विरुद्ध

संयुक्त राष्ट्र संधि प्रवर्तन (enforcement) कार्य कर रहा हो, सहायता देने से अपने का रोकेंगे ।

६. संयुक्त राष्ट्र संधि इस बात को सुनिश्चित करेगा कि संयुक्त राष्ट्र संधि के ऐसे राज्य जो सदस्य नहीं हैं, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिये चाटर के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेंगे ।

७ चाटर में दिया हुआ कोई भी विषय संयुक्त राष्ट्र संधि का उन विषयों में हस्तक्षेप करने को प्राधिकृत न करेगा जो वस्तुतः किसी राज्य के आन्तरिक क्षेत्राधिकार के भीतर हो अथवा सदस्यों से यह अपेक्षा करेगा कि ऐसे विषयों को वर्तमान चाटर के अन्तर्गत तय किये जाने के लिये प्रत्यपित करें, किन्तु इस सिद्धान्त से अध्याय ७ के अन्तर्गत प्रवर्तन (enforcement) के उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।

मुख्य प्रतिबन्ध के साथ सलग्न परिशिष्ट में सुरक्षा परिषद् का यह अनुमति प्रदान की गई है कि उस भगड़े को प्रसजान में ले जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को धमकी दी जाती हो तथा जो उसे सुलभाने के लिये प्रवृत्त उपायों को अपेक्षित करता हो चाहे वह उस राज्य के आन्तरिक क्षेत्राधिकार के भीतर ही क्यों न आता हो ।

यह प्रश्न कि क्या यह मामला पूर्णतया राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार के भीतर है, प्रायः बहुत उलझन उत्पन्न कर दिया करता है । इसलिये विवादप्रस्त मामलों को संयुक्त राष्ट्र संधि के किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित होना चाहिये । भारत दक्षिणी अफ्रीका विवाद में, जो कि रङ्गभेद और जाति-भेद से सम्बन्धित है, दक्षिणी अफ्रीका का कहना है कि भारत की ओर से यह शिकायत कि मूल भारतीय निवासियों के प्रति यहाँ के लोगों के व्यवहार ठीक नहीं हैं संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में नहीं उठाया जा सकता क्योंकि यह प्रश्न चाटर के अनुच्छेद २ पैरा ७ के अन्तर्गत दक्षिणी अफ्रीका के घरेलू क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है ।

दक्षिण-अफ्रीका की सच्ची सरकार ने जातिभेद की जो नीति अपनायी है वह भौतिक मानवीय अधिकारों का पूर्णतया अतिक्रमण करना है और उन्होंने अपनी इस नीति से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिये एक खतरा उत्पन्न कर दिया है । संयुक्त राष्ट्र सच्ची द्वारा दक्षिण अफ्रीका की इस नीति के विरोध में अनेक बार प्रस्ताव पारित किये गये हैं, किन्तु दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इन प्रस्तावों पर कोई ध्यान नहीं दिया है और इसका आधार यह बताया जाता है कि यह उनका घरेलू मामला है ।

इसी प्रकार हङ्गरी के प्रसङ्ग में भी क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुये । साम्यवादियों के बढ़ते हुये गणतन्त्र की प्रतिक्रिया अक्टूबर १९५६ में यह हुई कि बहुत संख्या में वहाँ के देशवासी परिवर्तन की माँग करने लगे । हङ्गरी के कार्य-वाहक प्रधानमन्त्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को यह सूचना दी कि इस परिस्थिति का सामना करना बिल्कुल हङ्गरी के घरेलू क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है और साधारण सभा यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पारित करती है तो उसका तात्पर्य यह होगा कि वह हङ्गरी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और चार्टर के अनुच्छेद २ पैरा ७ के प्रतिकूल है ।

**सदस्यता :—**सब राज्य सदस्य हैं जिन्होंने चार्टर को हस्ताक्षरित तथा अनुसमर्थित किया है । सदस्यता सब अन्य शांति-प्रिय राज्यों के लिये भी खुली है जो वर्तमान चार्टर में दिये गये कर्तव्यों को स्वीकार करें तथा सभ के निर्णय में उन कर्तव्यों के पालन करने के योग्य तथा इच्छुक भी हो । किसी राज्य का संयुक्त राष्ट्र सभ की सदस्यता में प्रवेश सुरक्षा परिषद की सन्तुति पर सामान्य सभा के निर्णय होने पर किया जाता है ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ में प्रवेश चार्टर द्वारा नियन्त्रित है । संयुक्त-राष्ट्र के सदस्य अनुच्छेद ३ के अनुसार मौलिक रूप से स्थायी सदस्य हैं और अनुच्छेद ४ के अन्तर्गत नये अपनाये गये सदस्य आते हैं । चार्टर के अनुच्छेद ३ के अन्तर्गत मौलिक सदस्य जो कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ को निमित्त किये थे वही राष्ट्र हैं जिन्होंने सन् १९४५ में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया था, या जिन्होंने जनवरी १, १९४२, की संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की घोषणा पर हस्ताक्षर किया था । अनुच्छेद ४ के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के नये सदस्य भी अपनाये जाते हैं किन्तु इसके लिये साधारण सभा की दो-तिहाई बहुमत और सुरक्षा परिषद की सन्तुति होनी चाहिये । सुरक्षा परिषद में परिषद के ६ सदस्यों का बहुमत और स्थायी सदस्यों की सहमति का होना आवश्यक है ।

अनुच्छेद ४ ने यह व्यवस्था की गई है कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की सदस्यता सभी शांतिप्रिय राज्यों के लिये खुली हुई है किन्तु उन्हें चार्टर के आभारों को स्वीकार करना होगा और उन आभारों को पूरा करने की इच्छा प्रकट करनी होगी । चार्टर में सदस्यता के लिये दूसरा कोई प्रतिबन्ध नहीं, बल्कि "शांतिप्रिय" (peace-loving) होना आवश्यक है । सदस्यता के सम्बन्ध में स्वीकार करने का सारा अधिकार साधारण सभा को और मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद का है यदि वे सम्भावनापूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि सदस्यता के लिये अभ्यर्थी राज्य शांतिप्रिय

है और चार्टर के अनुबन्धों या आभारों को मानने की इच्छा या सामर्थ्य रखता है तो वह नया सदस्य बनाया जा सकता है ।

नयी सदस्यता के लिये निम्नलिखित ५ मुख्य बातें हैं —

१—वह एक राज्य हो ।

२—शांतिप्रिय हो ।

३—चार्टर के आभारों को स्वीकार करता हो ।

४—संघ के निर्णयों के अनुसार उन आभारों को पूरा करने में समर्थ हो ।

५—संघ के निर्णयानुसार उन आभारों का पूरा करने की इच्छा रखता हो ।

बिस्सी नये राज्य को सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिये साधारणतया उस समय तक निर्णय नहीं कर सकती जब तक कि उसकी सदस्यता के लिये सुरक्षा परिषद् की सन्तुष्टि न हो जिसमें स्थायी सदस्यों की सहमति अवश्य सम्मिलित होनी चाहिये ।

चीन के पीपुल्स रिपब्लिक अर्थात् साम्यवादी चीन की सदस्यता का प्रश्न बहुत समय से संयुक्त राष्ट्र के सामने है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि चीन एक बहुत बड़ा देश है और बहुत शक्तिशाली भी है । उस संघ से चीन के पृथक् रहने का अभिप्राय विश्व के ६० करोड़ लोगों का विश्व-संस्था से पृथक् रहना है । प्रसुत चीन की सदस्यता के सम्बन्ध में उठने वाले प्रश्नों पर यहाँ विचार कर लेना उचित होगा ।

### चीन का प्रतिनिधित्व (The Representation of China)

जूलियस स्टोन (Julius Stone) का कहना है कि चीन की सदस्यता के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् में जो विवाद उत्पन्न हुआ है वह इसलिये है कि चीन की दो सरकारें हैं जो कि अपने-अपने को राज्य कहती हैं और प्रतिनिधित्व की माँग करती हैं ।

सर्वप्रथम चीन के प्रतिनिधित्व का प्रश्न चीन गणतन्त्र द्वारा १८ नवम्बर १९४९ को सुरक्षा परिषद् के समक्ष लाया गया । १९५० में सोवियत रूस ने अपने को अनुपस्थित करना शुरू किया जिससे से १३ जनवरी १९५० को बैठक में प्रस्ताव को इस कारण से अस्वीकृत कर दिया गया कि राष्ट्रवादी चीनियों का प्रतिनिधित्व उचित नहीं था ।

इस प्रसङ्ग में संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष कई बार प्रस्ताव आ चुके हैं किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका का रूस राष्ट्रवादी चीन और रूस का रूस साम्यवादी चीन की ओर है । इस गुटबन्दी के कारण तथा चीन द्वारा समय-समय पर अपनाये गये

अग्रघर्षक मार्गों के कारण यह विषय अभी तक नहीं सुलझ सका है। भारत, ग्रेट-ब्रिटेन और सोवियत सरकार का कहना है कि राष्ट्रवादी सरकार द्वारा चीन का प्रतिनिधित्व पूरा प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता क्योंकि राष्ट्रवादी सरकार का चीन के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार नहीं है। अस्तु चार्टर के अनुच्छेद २३ के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद में चीन का आंशिक प्रतिनिधित्व अन्तराष्ट्रीय विधि के अनुकूल नहीं है।

इस प्रश्न का उत्तर देते हुये महासचिव ने यह स्पष्टीकरण किया था कि चीन के प्रसंग में अनुच्छेद ४ के अनुसार विचार होना चाहिये जिसमें यह एक आवश्यक प्रतिबन्ध है कि सदस्यता के लिये अभ्यर्थी राज्य इस योग्य हो और ऐसी इच्छा रखता हो कि सदस्यता से सम्बन्धित आभारों का पालन कर सके। उनका कहना था कि दो प्रतिद्वंद्वी सरकारों के बीच वास्तव में जो सरकार इस आभार को ग्रहण कर सक और सदस्यता के आभार अपनी जनता पर भी आरोपित कर सके उसी का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

परिस्थितियाँ जो कुछ भी हो साम्यवादी चीन के अन्तर्गत जितना बड़ा अभिप्रेत है और जितनी जनता उस राज्य में है तथा अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में चीन की जो स्थिति है उसे देखते हुये यह उचित नहीं प्रतीत होता कि चीन अन्तराष्ट्रीय प्रतिबन्धों से बाहर रखा जाय।

चीन का भारत-आक्रमण (Chinese Aggression against India) — भारत आरम्भ से ही साम्यवादी चीन की सदस्यता का प्रबल समर्थक रहा है। उसने स्वतः कई प्रस्ताव इस सम्बन्ध में राष्ट्र सभ के समक्ष रखे हैं, किन्तु १९६२ में चीन ने भारतीय सीमा पर प्रबल आक्रमण कर दिया और निरंकुश रूप में अन्तराष्ट्रीय विधि के विरुद्ध कार्य किया। इस आक्रमण को देखते हुये संयुक्त राष्ट्र सभ में साम्यवादी चीन की सदस्यता के प्रश्न का पुनरीक्षण आवश्यक प्रतीत होता है। चीनियों ने १९५९ में मैकमहन रेखा को पार किया था और यह सीमा-अतिक्रमण ५ वर्ष पहले सहास में किया गया था। उसी समय से वे भारतीय राज्य-क्षेत्र का १२ हजार स्क्वायर मील अपने अधिकार में अवैध रूप से कर लिये थे। २० अप्रैल १९६२ को उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा आक्रमण किया जो कि (नेपा) नार्थ ईस्ट फ्रान्टियर एजेन्सी तथा सहास दोनों क्षेत्रों में समान रूप से किया गया था। आक्रमणों की सहर सीमाती रहो तथा भारी मार्टार तथा मशीनगनों से लैस चीनी सना ने उपरोक्त दोनों क्षेत्रों में बहुत बड़ी भारतीय भूमि का अपहरण कर लिया। इस प्रकार भारतीय सीमा से बढ़कर चीनियों ने अपनी आक्रमण नीति का और भी बढ़ावा दे दिया।

चार्टर के अनुच्छेद ४ के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था दी गई है कि सयुक्त राष्ट्र सङ्घ की सदस्यता सभी शांतिप्रिय राज्यों के लिये तथा उनके लिये जो चार्टर के आभारों को सङ्घ के निर्णयानुसार स्वीकार कर सकें और उन आभारों को पूरा करने के इच्छुक हो सबके लिये खुली हुई है। उपरोक्त उपबन्ध को देखते हुये कहा जा सकता है कि साम्यवादी चीन इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता। उसने अपनी आक्रामक नीति के द्वारा यह आशंका उत्पन्न कर दी है कि वह चार्टर के आभारों को पूरा करने की इच्छा से रहित है। एक ओर तो साम्यवादी चीन भारतीय सीमा के समीप बहुत बड़ी सैनिक शक्ति इकट्ठा कर रहा है और किसी भी समय आक्रमण की आवृत्ति होने की सम्भावना बनी हुई है। हिमालय पर किये गये इस आक्रमण से विश्व-शांति को एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। चीन की यह नीति कोई नई नहीं है। १९५० में कोरिया के युद्ध में भी उसकी आक्रामक कार्यवाहियों को देखा जा चुका है।

**चीनियों का भारतीय सीमा पर छाया आधार-रहित—अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार चीनियों का लद्दाख पर इसलिये दावा करना कि वह क्षेत्र उनके (प्रवेष्ट) दखल में रहा है, इनकी सम्प्रभुता को नहीं सिद्ध करता कि वहाँ उनकी सम्प्रभुता है। Aksai Chin भी चूँकि उनके आक्रमण के कारण उनके आधिपत्य में आ चुका था वे इसलिये सम्प्रभुता का दावा नहीं कर सकते कि वह क्षेत्र वस्तुतः उनका है, क्योंकि वह क्षेत्र भारत का है और भारत ने अपन हक का विलोप नहीं किया है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि का यह मान्य सिद्धान्त है कि कोई राज्य जिसने संधि द्वारा किसी क्षेत्र पर दूसरे राज्य का दावा स्वीकार कर लिया है फिर उस क्षेत्र के सम्बन्ध में स्वतः दावा करना बन्द कर देता है। डा० कृष्ण राव भारत सरकार के वैदेशिक मन्त्रालय के सीनियर ऐडवाइजर का कहना है कि यह सत्य है कि भारत ने आक्रमणकारियों को बाहर नहीं निकाला है बल्कि चीनियों ने भारतीय क्षेत्र पर अपनी आक्रामक कार्यवाहियों को निरन्तर जारी रखा है।**

जहाँ तक नेफा क्षेत्र का सम्बन्ध है चीन ने मैकमहन रेखा को मानने से इन्कार कर दिया है और उस रेखा को बल प्रयोग द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तित करने का आशय प्रकट किया है। यह रेखा वही रेखा है जो भारत को तिब्बत से भलग करती है और इतिहास परम्परा और सन्धियों के द्वारा बहुत पहले से विभाजक रेखा के रूप में रही है। चीन ने स्वतः कई रूपों में समय-समय पर इस रेखा को माना है यद्यपि वे फिर इस रेखा को प्रवेष्ट कहने लगे हैं। चीन की वर्तमान सरकार की स्थापना के पूर्व से ही इस रेखा की मान्यता रही है और तिब्बत ने सभी भी इसका विरोध नहीं किया था।

जहाँ तक साम्यवादो चीन के संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की सदस्यता का प्रश्न है सोवियत रूस ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के १७वें अधिवेशन में एक प्रस्ताव का प्राख्य रखा जिसके अनुसार कम्युनिस्ताग चीनी प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सभी अङ्गों से बहिष्कृत करने का प्रस्ताव किया और बदले में साम्यवादो चीन को रखने की संस्तुति की। अक्टूबर १९६२ में इस प्रस्ताव पर साधारण सभा द्वारा विचार किया गया और भारतीय प्रतिनिधि ने यह दोषारोपण करते हुये कि चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर खुला आक्रमण किया है, कहा कि चीन की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति को रोकने और चीन को अन्तर्राष्ट्रीय आभारो को स्वीकार करने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसे विश्व-संघ के उपबन्धों में बाँधा जाय। आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था और कहा था कि भारतीय सीमा पर चीन की आक्रामक कार्यवाहियों से जहाँ हमारी चिन्ताएँ बढ़ती हैं वहाँ हमारा सन्देह भी बढ़ता है कि क्या साम्यवादो चीन चार्टर के आभारो को मानने का इच्छुक है या उसमें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को मानने का सकल्प अथवा नहीं है ?

भारत और ब्रिटेन ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया किन्तु अभी तक यह निर्णय नहीं हो सका है कि वास्तव में चीन इस बात के लिये तैयार है कि वह चार्टर के अनुसार आभारो को ग्रहण कर सकेगा किन्तु उसकी कार्यवाहियाँ ऐसी उत्तेजक हैं कि उसे पूर्णतः निरकुश रहने देना भी उचित नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान (The Constitution of the U. N.) :—संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित मुख्य अंग हैं :—(१) साधारण सभा, (२) सुरक्षा परिषद, (३) सचिवालय, (४) न्याय परिषद, (५) आर्थिक तथा सामाजिक परिषद तथा (६) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय।

### १. साधारण सभा

#### (The General Assembly)

इसमें संयुक्त राष्ट्र के सब सदस्य सम्मिलित हैं जिनका प्रतिनिधित्व पाँच-पाँच सदस्यों से होता है। साधारण सभा की प्रक्रिया की नियमावली का नियम २१ निम्नलिखित है—

“किसी सदस्य का प्रतिनिधि मंडल पाँच प्रतिनिधियों, पाँच वैकल्पिक प्रतिनिधियों तथा उतने ही मंत्रणा देने वालों, विशिष्ट विषयक मंत्रणा देने वालों, विशेषज्ञों तथा उसी प्रकार की स्थिति के इतने व्यक्तियों से जितने कि प्रतिनिधि-मंडल द्वारा अपेक्षित किए जायें, से और अधिक न होगा।”



साधारण सभा एक अध्यक्ष ( President ) तथा सात उपाध्यक्ष ( Vice-Presidents ) निर्वाचित करती है जो उस सत्र के अन्त तक पद ग्रहण करते हैं जिसमें वे चुन जाते हैं । साधारण सभा का अधिवेशन नियम वार्षिक सत्रों में तथा ऐसे विशेष सत्रों में होता है जैसे अवसर के अनुसार आवश्यक हो । विशेष सत्र महासचिव ( Secretary General ) द्वारा सुरक्षा परिषद् अथवा संयुक्त राष्ट्र सभ के अधिकांश सदस्यों को प्रार्थना पर बुलाया जा सकता है ।

यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा ने भारत की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को अपने आठवें सत्र के लिये सभारति निर्वाचित किया था और श्रीमती पंडित विश्व की पहली महिला हैं जिसे यह सम्मान प्राप्त हुआ ।

कार्य तथा शक्तियाँ—साधारण सभा के कार्य चार्टर के अनुच्छेद १० से १७ तक में दिये गये हैं । सभा चार्टर के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले किसी प्रश्न पर विवेचना आरम्भ करवा सकती है तथा किसी ऐम प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों से अथवा सुरक्षा परिषद् से अथवा दोनों से सिफारिश कर सकती है । यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापना सम्बन्धी किसी प्रश्न पर विवेचना कर सकती है जो इसके समक्ष संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य अथवा सुरक्षा परिषद् अथवा किसी असदस्य राज्य द्वारा रखा जाय तथा इस प्रकार के किसी प्रश्न के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य तथा राज्यों का अथवा सुरक्षा परिषद् को अथवा दोनों को सिफारिश कर सकती है । मोपेनेहेम का कथन है कि यद्यपि यह सभा वैधानिक शक्तियों से विनिहित नहीं है तथा इसकी सिफारिशें वैधानिक रूप से बन्धनकारी नहीं हैं तथापि वे सिफारिशें संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों पर विश्व क जन-साधारण की सम्मति का प्रभाव डालने के लिये प्रमुख साधन बन जाती हैं ।

साधारण सभा सुरक्षा परिषद् का ध्यान उन स्थितियों की ओर आकर्षित करा सकती है जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा का संकट में पड़ना सम्भव हो । यह किसी स्थिति का जिससे राष्ट्रों के कल्याण तथा उनके मध्य मैत्री के सम्बन्धों में बाधा पड़ना सम्भव हो, शान्तिपूर्ण निपटारे के लिये सिफारिश कर सकती है ।

अनुच्छेद १३ में यह विशिष्ट रूप से अनुबन्धित है कि साधारण सभा निम्नलिखित विषयों के लिये अध्ययन आरम्भ करावेगी तथा सिफारिश करेगी :—

(अ) राजनीतिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि और इनके सहिताकरण के उत्तरोत्तर विकास को प्रोत्साहित करना ।

(घा) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा सम्बन्धी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को वृद्धि करना तथा जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेदभाव को मिटा कर सब के लिये मानवीय अधिकारों तथा मूलभूत स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में सहायता देना ।

अनुच्छेद १२ सभा के कृत्यों को सीमित कर देता है क्योंकि इसमें यह अनुबन्धित है कि जब सुरक्षा परिषद् किसी ऋण स्थिति के सम्बन्ध में वर्तमान चार्टर के अनुसार सौंपे गये कृत्यों में से किसी कृत्य को कर रही हो तो साधारण सभा उस ऋण स्थिति के सम्बन्ध में कोई सिफारिश न करेगी जब तक कि सुरक्षा परिषद् ऐसी प्रार्थना न करे ।

अन्य कृत्य जो साधारण सभा का दिये गये हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रत्यास पद्धति के सम्बन्ध में हैं जिनमें ऐसे क्षेत्रों के लिये प्रत्यक्ष स्वायत्तता भी सम्मिलित हैं जिनका नाम सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों में नहीं लिखा गया है । यह सब के बजट को तथा विशिष्ट एजेंसियाँ के साथ दिये गये किसी आर्थिक तथा बजट सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करती है तथा उनको स्वीकार करती है, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन में भाग लेती है, सुरक्षा परिषद् के छ प्रस्थायी सदस्यों, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के सदस्यों तथा न्याय परिषद् के कुछ सदस्यों का निर्वाचन करती है । यह सुरक्षा परिषद् को सिफारिश पर महासचिव को निर्वाचित करती है तथा सचिवालय के कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति के लिए नियम बनाती है । यह सुरक्षा परिषद् को सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र सन के किसी सदस्य को चार्टर के सिद्धान्तों का उल्लंघन करने के लिये निकाल सकता है ।

मतदान प्रक्रिया (Voting Procedure) — साधारण सभा के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है । प्रमुख प्रश्नों पर उदाहरणार्थ अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापना के सम्बन्ध में सिफारिश, सुरक्षा परिषद् के प्रस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन, न्याय परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र सभ में नये सदस्यों का प्रवेश, सदस्यता के अधिप्राप्त तथा विशेषाधिकारों का निर्यात, सदस्यों का निष्काशन, प्रत्यास पद्धति के लागू होने के सम्बन्धी प्रश्न तथा बजट विषयक प्रश्न साधारण सभा के निर्णयों के लिये उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत अपेक्षित है । अन्य प्रश्नों के निर्णय के लिये, जिनमें दो-तिहाई बहुमत से निम्न क्रिय जाने वाले प्रश्नों के अतिरिक्त बगैरों का निर्णय भी सम्मिलित है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का केवल बहुमत अपेक्षित है ।

**सङ्गठन (Organisation) :—**साधारण-सभा के कार्य प्रायः समितियों में हुमा करते हैं जिन्हे चार श्रेणियों में बाँटा गया है ।

(१) मुख्य समितियाँ (Main Committees)

(२) प्रक्रियात्मक समितियाँ (Procedural Committees)

(३) स्टैंडिंग समितियाँ (Standing Committees)

(४) तदर्थ समितियाँ (Ad hoc Committees)

१—मुख्य समितियों में ६ समितियाँ सम्मिलित हैं : १—राजनीतिक और सुरक्षा सम्बन्धी, २—आर्थिक-व्यवस्था सम्बन्धी, ३—सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक, ४—न्यासिता सम्बन्धी, ५—प्रशासकीय और बजट सम्बन्धी, तथा ६—वैध ।

२—प्रक्रियात्मक समितियों में साधारण सभा के सङ्गठन और व्यवहार सम्बन्धी विषय रहते हैं । ये दो हैं : १—साधारण समिति और २—प्रत्यय-पत्र-समिति (क्रीडेन्शियल्स-समिति) ।

३—स्टैंडिंग कमेटी में लगातार चलने वाली समस्याओं पर विचार किया जाता है । उनमें से कुछ प्रशासन और बजट के प्रश्नों पर सलाहकार समिति के रूप में होती है और कुछ खन्दा समिति, बोर्ड आफ आडिटर, इन्वेस्टमेन्ट कमेटी और संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी पेंशन कमेटी ।

४—तदर्थ समितियों में साधारण सभा या उसकी कोई भी समिति विशेष प्रयोजनों के कारण ऐसी समितियाँ निमित्त कर सकती है ।

एक अन्तरिम समिति और होती है जिसे “लिटिल एसेम्बली” या लघु सभा कहते हैं जिसकी स्थापना १९४७ में हुई थी ।

**संयुक्त राष्ट्रों से प्रत्याहरण (Withdrawal from the United Nations)**—संयुक्त राष्ट्र-चार्टर में किसी सदस्य के प्रत्याहरण, या संघ से अपनी सदस्यता वापस लेने का उपबन्ध नहीं है । डम्बार्टन ओक्स के से उन संकल्पों में, जिनमें कि एक साधारण अन्तर्राष्ट्रीय संघटन (General International Organization) का प्रस्ताव था, और जिसका कि प्राख्य संयुक्त राज्य, सोवियत सभ, ग्रेट ब्रिटेन और चीन द्वारा तैयार किया गया था, सदस्यता के प्रत्याहरण के उपबन्धों को पूर्णतया लुप्त कर दिया गया था । यह व्यवस्था संभवतः इस कारण से की गई थी कि लीग-नवनेएट का अनुभव सामने था और नवनेएट जिस कमजोरी का शिकार हुमा, थब उस कमजोरी से वे इस नये अन्तर्राष्ट्रीय संघ को बचाना चाहते थे । नवनेएट में उपबन्धित था कि यदि किसी सदस्य-राज्य के सभी अन्तर्राष्ट्रीय पूरे हो, तो वह दो वर्ष की अधिमूचना के आधार पर लीग से अपनी सदस्यता

प्रत्याहारित कर सकता था (कवनेट का अनुच्छेद १, पैरा ३)। कवनेट को इस व्यवस्था से लोग शायद नश्वर में यह स्थिरता और स्थायित्व न था सारा, जिसको अपेक्षा की गई थी। इस उपरान्त भी कवनेट के अनुच्छेद २६ में यह भी उप-बधित था कि यदि कोई सदस्य कवनेट के किना सशायन से असंतुष्ट या असहमत है तो उस असहमति का उल्लेख करते हुये अपनी सदस्यता वापस ले सकेगा।

सान-फ्रांसिस्को सम्मेलन में मई २१, १९४४, को एक उपसमिति गठित की गई जिसमें चार महान् शक्तियों का प्रतिनिधित्व हुआ। इस उपसमिति ने संघ से सदस्यता वापस लेने के प्रश्न पर विचार किया और यह सम्मति प्रकट की कि समिति को एक व्याख्यामूलक घोषणा (interpretative declaration) देना उचित होगा जिसमें कि निम्नलिखित कथन सम्मिलित हो। नीचे दिया कथन जून २५, १९४५ को सम्मेलन द्वारा अनुमोदित कर दिया गया—

"The Committee deems that the highest duty of the nations which will become members is to continue their co-operation within the Organization for the preservation of international peace and security. If, however, a member because of exceptional circumstances feels constrained to withdraw, and leave the burden of maintaining international peace and security on the other members, it is not the purpose of the Organization to compel that member to continue its co-operation in the Organization; nor would it be the purpose of the Organization to compel a member to remain in the Organization if its rights and obligations as such were changed by Charter amendment in which it has not concurred and which it finds itself unable to accept, or if an amendment duly accepted by the necessary majority in the Assembly fails to secure the ratification necessary to bring such amendment into effect." अर्थात् "समिति का विचार यह है कि ऐसे राष्ट्रों का, जो कि सदस्य बनें, उच्चतम कर्तव्य यह है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने के लिये संघ में अपने सहयोग को निरन्तर बनाये रखें। फिर भी यदि कोई सदस्य किन्हीं विशेष अववादजनित परिस्थितियों में सदस्यता वापस लेने के लिये अपने को विवश हो पाता है, और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा का भार अन्य सदस्यों पर ही छोड़ना चाहता है, तो संघ का उद्देश्य यह नहीं होगा कि एक सदस्य को उस समय भी संघ में बने रहने के लिये विवश किया जाय, जबकि चार्टर के सशायन द्वारा उस सदस्य के ऐसे अधिकार और भाग्य को ही परिवर्तित कर दिया गया हो, जिसके लिये कि अपने पहले से सम्मति नहीं दी

थी; और यह कि जिस संगोपन को यह धरा स्वीकार करने को तत्पर नहीं है, या यह कि महा द्वारा बहुमत से मान्य किसी संगोपन को प्रभावकारी होने के लिये जिस रुग्णभेदन की आवश्यकता थी, यह न दिया जा सका।”

सोवियत संघ ने यह दावा किया कि किसी राज्य की सम्प्रभुता में किसी समस्या से अपने को वृष्ट कर लेने की शक्ति स्वयमिच्छा शक्ति है, किन्तु इन विचार को उस आयोग द्वारा पुष्ट नहीं किया जा सका जिनमें कि मान्-फ्रांसिस्को सम्मेलन के नवें प्लेनरी-अधिवेशन में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये थे।

यही विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या किसी सदस्य-राष्ट्र को चार्टर में किसी विनिष्ट एतद्विषयक उपबंध के न रहते हुये संघ से प्रत्याहरण कर लेने का अधिकार है, अथवा नहीं। डा० पस्वोल्स्की ( Dr. Pasvol'sky ) ने जो कि मान्-फ्रांसिस्को सम्मेलन में 'इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन ऑफ़ सेक्यूरिटी अपेयर्स' के राज्य-मंत्री के विशेष सहायक थे, सम्मति प्रकट की थी कि मूल दंबार्टन ओक्स संस्थाओं ( Original Dumbarton Oaks Proposals ) के अन्तर्गत, जहाँ कि न तो प्रत्याहरण का कोई उपबन्ध है, और न प्रत्याहरण के विषय का उपबन्ध है, तो एक विधि-प्रसंग के रूप में यह तत्पर्य हुआ कि प्रत्याहरण के अधिकार का अस्तित्व है, कारण यह है कि वरार एक ऐसे प्रकार का नहीं है जो कि किसी भी अर्थ में सदस्य-राज्यों को एक नई सरकार के हाथों में या उसके अन्तर्गत अपनी स्वतंत्रता सौंप देने का उपबन्ध करता हो। यह भी कहा जा सकता है कि प्रसंग का एक पक्ष यह भी है कि सम्प्रभु राज्यों के किसी संघ में सभी सदस्यों में प्रत्याहरण की क्षमता विद्यमान होती है। अतः चार्टर में प्रत्याहरण करने की शक्ति स्वयमेव अन्तर्निहित मानी जानी चाहिए।

दूसरा पक्ष यह है कि चूँकि लीग-कवनेंट ने प्रत्याहरण के अधिकार को एक ऐसे अन्तर्निहित-अधिकार की मान्यता दी थी, जो कि सभी सदस्य-राज्यों में विद्यमान है, और यह कि वह इसका प्रयोग किसी कारण के आधार पर एक बिना कारण के भी कर सकता है; अतः चार्टर के प्रसंग में भी प्रत्याहरण स्वीकृत किये जाने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये, किन्तु इस बात पर भी ध्यान रहे कि इस स्वीकृति के लिये प्रसंगगत मामले में पर्याप्त आधार होने चाहिये। इस पर्याप्त कार्य-कारण आधार के सिद्धान्त का शास्त्रीय भाषा में 'क्लायुला रिवस-सिक् स्टैंटिबस' ( clausula rebus sic stantibus ) कहा गया है। यह सिद्धान्त परिस्थितियों के अनिवार्य परिवर्तन के आधार पर प्रत्याहरण को अनुमति देता है और वे परिस्थितियाँ उस राज्य के अस्तित्व को खतरे में डालने वाली हो सकती हैं, जिनमें कि वह अपने-आप को संघ से आभारों से मुक्त कर दिये जाने की माँग कर रहा

है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसा प्रत्याहरण एकपक्षीय (unilateral) नहीं हो सकता। जो राज्य सदस्यता में मुक्त होना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम सदस्यता से मुक्त किये जान के लिये संधि से आवेदन करे। केलसन (Kelsen) का कथन है कि कार्य-कारण आधार न तो कोई प्रत्याहरण का अधिकार उनकी संप्रभुता की एक अभिव्यक्ति के रूप में प्रदान करता है और न तो अपवाद जनितपरिस्थितियों (exceptional circumstances) में ही यह अधिकार प्रदान किया गया है।<sup>१</sup>

यह प्रश्न उस समय और भी विचारणीय हो गया जब कि इण्डोनेसिया ने इस आधार पर कि १९६३ में जेकोस्लावाकिया द्वारा जनवरी १, १९६५ को रित्त किये गये स्थान पर एक वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा परिषद में मलायेशिया का चुनाव हो गया, और चूंकि इंडोनेसिया मलायेशिया से प्रतिस्पर्धी रूप में रहा है, इंडोनेसिया ने संयुक्त राष्ट्र संधि से अपने प्रत्याहरण की अधिसूचना कर दी। इस प्रसंग में भी यही तर्क सामने रखे गये कि संयुक्त-राष्ट्र के चार्टर में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं प्रतीत होता कि कोई भी देश, जिसने कि उस पर हस्ताक्षर किये हैं, निकाय से प्रत्याहरण नहीं कर सकता। और राष्ट्रा की लोग के कवेंनेंट की ठीक विनयीत चार्टर के उपबन्धों में यह व्यवस्था है कि कोई सदस्य राष्ट्र अपनी सदस्यता स्वेच्छया वापस नहीं ले सकता। इसमें सदेह नहीं है कि कोई देश सभा का बहिष्कार कर सकता है, या किसी सन्तुतिमूलक संकल्प (recommendatory resolution) का पालन करने, या उसका सम्मान करने से इनकार कर सकता है किन्तु एक हस्ताक्षरकर्ता के लिये चार्टर पर हस्ताक्षर करने के उत्तरान उससे आभारों से अपने को मुक्त कर लेने का मार्ग नहीं खुला हुआ है। चार्टर के अनुच्छेद ६ के द्वारा सदस्य-राष्ट्र की इच्छा के विरुद्ध भी उनको सदस्यता समाप्त की जा सकती है, क्योंकि इस अनुच्छेद में उपबन्धित है कि संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य, जिसने कि वर्तमान चार्टर में निहित सिद्धान्तों का निरंतर उल्लंघन किया है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा निष्काशित किया जा सकता है।

इस प्रसंग में यहाँ उल्लेखनीय है कि W. H. O. या (World Health Organisation) विश्व-स्वास्थ्य-संघ के संविधान में ऐसा कोई खंड नहीं है जो कि किसी राष्ट्र को इस घोषणा के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर सदस्यता वापस करने का अधिकार दे सके कि संधि के संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन या संशोधन हो गया, जो कि उसके सर्वथा अहित में हैं, या यह कि कोई ऐसा संशोधन हुआ है, जिस पर कि उसने पहले हस्ताक्षर के समय कदापि सहमति

१. Hans Kelsen: The Law of the United Nations, p. 128.

नहीं दी थी। जब कि। सयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व-स्वास्थ्य-सभ में प्रविष्ट होना चाहा, तो कांग्रेस के दोनों सदनों ने स्पष्टतः प्रस्थापित किया कि सयुक्त राज्य उस सभ से पृथक् हो जाने के अपने अधिकार को प्रारक्षित किये हुये है और यह कि यह प्रत्याहरण १ वर्ष की अधिसूचना के आधार पर हो मकेगा। जुलाई २, १९४८, को विश्व-स्वास्थ्य-सभा ( World Health Assembly ) ने, फिर भी, सयुक्त राज्य द्वारा सविधान के उस रूप में ग्रहण किये जाने की वैधता को मान्यता प्रदान की।

१२ फरवरी, १९४९ को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकस ने विश्व-स्वास्थ्य-सभ की क्रियाविधि से असंतुष्ट होकर घोषित किया कि अब वह इस सभ का सदस्य नहीं है। उन्नतियन सोवियत समाजवादी गणतन्त्र और बार्डेलोस्की सोवियत समाजवादी गणतन्त्र ने भी तदनन्तर अपने प्रत्याहरण को अधिसूचित कर दिया। डायरेक्टर जनरल ने, फिर भी, सयुक्त समाजवादी सोवियत सभ का सूचित किया कि चूँकि विश्व स्वास्थ्य-सभ के सविधान में प्रत्याहरण का कोई उपबन्ध नहीं है, अतः वे उसकी अधिसूचना को सभ से प्रत्याहरण के रूप में स्वीकृत नहीं कर सकते। इस तर्क को सभा ने २५ जून, १९४९, का अनुमोदित किया। जुलाई १९५५, में सोवियत सभ ने पुनः उद्धोषित किया कि वह विश्व स्वास्थ्य सभ में सम्मिलित हो रहा है। एकमात्र कठिनाई केवल उस अधिविध के बकामे के चर्चे की थी, जिसमें कि प्रत्याहरण करने वाले राज्यों ने अपने को सभ से पृथक् मान लिया था। इस कठिनाई का समाहार ५ प्रतिशत प्रतीकात्मक चन्दे की पूर्ति द्वारा कर लिया गया और प्रत्याहार स्थिर न हो पाया।

फियनबर्ग ( Feinberg ) का कथन है कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से प्रत्याहरण करने का अधिकार अस्तित्व में नहीं है। यह न तो सप्रभुता या समता के सिद्धान्त में निहित है और न तो किसी सभात्मक राज्य या राज्यों के कंफेडरेशन के सिद्धान्त में ही पाया जाता है। यह अधिकार केवल तभी अस्तित्व में है, जब कि उसे मान्यता दी गई हो, और यह मान्यता सविधान में स्पष्टतः दी गई हो, यह आवश्यक नहीं है। यदि ऐसी मान्यता सविधान में दी गई हो, तब तो यह विचारों की भिन्नताओं से बचने का सर्वोत्तम उपाय हो सकता था। दूसरे शब्दों में, प्रत्याहरण का अधिकार अन्तर्निहित रूप में भी दिया जा सकता है, अर्थात् प्रत्येक प्रसंग में यह अवश्य ही सिद्ध हो जाना चाहिए कि यद्यपि लिखत (instrument) में प्रत्याहरण उपबन्धित नहीं है, फिर भी पक्षकारों का आशय यह है कि इसे स्वीकार कर लिया जाय। किसी अन्तर्राष्ट्रीय सभ से, जब कि उसके सविधान में प्रत्याहरण का उपबन्ध नहीं है, फिर भी यह अधिकार मिन सके, ऐसा दृष्टांत सयुक्त राष्ट्र सभ

मे है । सैन फ्रान्सिस्को में सच की विशेष अनुज्ञात्मक घोषणा में पक्षकारों के अभिप्राय को अभिव्यक्ति मिली । यद्यपि कुछ लेखकों ने आदेशात्मक घोषणा की वैधता को स्वीकार नहीं किया है (विशेष रूप में केल्सन ने 'दो लाख भाँव दी युनाइटेड नेशन्स' पृ० १२२) किन्तु जैसा कि फिशनबर्ग ने लिखा है इस तर्क का समर्थन अधिकांश विद्वानों ने नहीं किया है । केल्सन ने निष्कर्ष रूप में कहा है कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय सच से एकपक्षीय प्रत्याहरण के अधिकार का समर्थन नहीं किया जा सकता और इसलिये प्रत्याहरण केवल तभी स्वीकृत किया जा सकता है जब कि इसका स्पष्टतः उपबन्ध हो या यह कि अन्तर्निहित सात्वय के रूप में इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है ।<sup>१</sup>

अब भी प्रसंग कठिनाइयों से मुक्त नहीं है । विश्व-स्वास्थ्य-सच ने मूल सवैधानिक समस्या का सुलभाय प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि रूस ने जब प्रत्याहरण के प्रस्ताव के उपरान्त ५ प्रतिशत बकाया प्रतीकात्मक शुल्क भुगत करके सदस्यता बनाये रखा, तब सच बहुत अधिक वैध तर्क-वितर्क में पड़ने नहीं गया । इस विवाद का सुलभाय इस प्रकार हो सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को यह प्रसंग प्राधिकारिक सम्मति के लिये सदाभित कर दिया जाय । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि चूँकि चार्टर में प्रत्याहरण का उपबन्ध नहीं है, और सच अपनी प्रवृत्ति और प्रयोजनों के लिये इस उद्देश्य से अनुप्राणित है कि जहाँ तक संभव है, अपनी परिधि में विश्व के समस्त देशों को आवृत्त कर ले, अस्तु सार्वभौम आशय सच की सार्व-देशिकता से है और यह कि एक सदस्य को प्रत्याहार का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये और न ता उसे अपने आभारा से उस समय तक भागने की ही अनुमति दी जानी चाहिये जब तक कि परिस्थितियों से एकपक्षीय प्रत्याहरण के लिए पर्याप्त आधार और कारण न उपस्थित हो गये हों, यहाँ तक कि उपनमिति की आदेशा-त्मक घोषणा के आधार पर, जिसे कि प्रथम आयोजन में अनुमोदित किया था, और बाद में जिसका अनुसमर्थन सैन फ्रान्सिस्को की साधारण सभा ने किया था, स्पष्टतः प्रस्थापित हो गया कि सदस्य बनने वाले राज्यों का यह सर्वोत्तम कर्तव्य होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने के लिये वे सच में अपना सदस्यता निरन्तर जारी रखें, और यह कि सच का उद्देश्य यह नहीं था कि ऐसी स्थिति में भी किसी सदस्य को सदस्यता जारी रखने के लिए विवश किया जाय जब कि अपवादजनित परिस्थितियाँ इस योग्य उपस्थित हो गई हों कि प्रत्याहरण तर्कसंगत

१. The British Year Book of International Law, 1963 Unilateral Withdrawal from an International Organization by N. Flenberg, 189, 215, 218



उपाय प्रतीत होने लगे। इसलिए यह स्पष्ट है कि सभ से प्रत्याहरण की अनुमति देने के लिए, और उसे न्यायोचित बहे जाने के लिए पर्याप्त न्यायोचित कारणों का होना आवश्यक है। ऐसे अपवादजनित कारण 'रिबस सिक् स्टैन्डिस' या पर्याप्त कार्य-कारण आधार के अन्तर्गत परिवर्तित परिस्थितियाँ होंगी क्योंकि यदि प्रत्याहरण सम्बन्धित पक्षकार की इच्छा पर स्वीकृत कर दिया जाता है, तो इसका स्पष्टतः बुरा प्रभाव विश्व-संगठन की दृढ़ता पर पड़ेगा।

शास्त्र (Schachter) का कथन है कि, "The omission of the usual clause permitting denunciation or withdrawal was evidently due, not to an oversight, but to a general policy which favoured universality and deprecated unilateral action." अर्थात् सामान्यतः विमुक्ति या प्रत्याहरण की अनुमति उपबन्धित करने वाले खंड का लोप किसी अपवादधानी के कारण नहीं हुआ है, अपितु एक सामान्य नीति के आधार पर इस लोप को रखा गया है, जिससे सार्वदेशिकता का समर्थन हो सके और एकपक्षीय कार्यवाही रोकी जा सके। जनवरी १७, १९७१ के सन्धन प्रोटोकॉल द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय विधि में इस सिद्धान्त को और भी बल मिला, क्योंकि इस प्रोटोकॉल में महान् शक्तियों ने घोषणा की कि यह राष्ट्रों की विधि का एक अनिवार्य सिद्धान्त है कि कोई भी शक्ति के संधि के आधारों से अपने-आप को विमुक्त नहीं कर सकता, जब तक कि अन्य सविदाकार शक्तियों द्वारा सौहार्दता-पूर्वक मान्य न हो जाय। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना उचित होगा कि इजानेशिया संयुक्त राष्ट्र सभ में पुनः वापस आ गया और उसने सितम्बर, १९६६ में हुई संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के २१वें अधिवेशन में भाग ले लिया।

“शान्ति के लिये संगठित होने” का सरूप (Uniting for Peace Resolution)—चार्टर की संरचना इस अन्तर्निहित विचार के साथ की गई थी कि इससे महान् शक्तियों की एकता होगी। वस्तुतः जब चार्टर प्रभावकारी हुआ, उस समय यह एकता अस्तित्व में थी। किन्तु, बाद में यह देखा गया कि यह एकता स्थायी या अविच्छिन्न नहीं रह गई। संयुक्त राष्ट्र के पुलिस बल का, जिसका कि उपबन्ध चार्टर द्वारा किया गया था, सुरक्षा परिषद के नियन्त्रण में रहे जाने का आशय था, जिसमें कि महान् शक्तियाँ अपने निषेध-अधिकार (right of veto) को लेकर बैठी हुई हैं। इसलिये, यदि महान् शक्तियाँ किसी अप्रत्यक्ष के विरुद्ध नहीं खड़ी होना चाहती, तो सम्भावना यह थी कि पुलिस की शक्ति द्वारा संयुक्त राष्ट्र ऐसी स्थिति में शान्ति प्रवर्तित न कर सके। इस कठिनाई को दूर करने के लिए

संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे 'शान्ति के लिये एकता' (Uniting for Peace) का नाम दिया गया। नवम्बर ३, १९५०, को साधारण सभा ने प्रस्ताव को अंगीकृत कर लिया, जिसमें निम्नलिखित संकलन था —

If the Security Council because of lack of unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case where there appears to be a threat to peace, breach of the peace, or act of aggression, the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to members for collective measures, including in the case of a breach of the peace or act of aggression the use of armed force when necessary to maintain or restore international peace and security. If not in session at the time, the General Assembly may meet in emergency special session within twenty-four hours of the request therefor. Such emergency special session shall be called if requested by the Security Council on the vote of any seven members or by a majority of the members of the United Nations."

'यदि सुरक्षा परिषद, स्थायी सदस्यों में एकमत हा सकने के अभाव में, किसी ऐसे प्रसंग में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के अपने प्राथमिक कर्तव्य व अनुपालन में विफल हो जाती है, जहाँ कि शान्ति के लिए खतरा प्रतीत होता हो, या शान्ति भंग होने की स्थिति हो, या अग्रघर्षण का कार्य किया गया हो, तो साधारण सभा प्रसंग पर तत्काल विचार करेगी जिससे कि वह सदस्यों के पास सामूहिक उपाय अपनाने की सत्तुति कर सके, जिससे कि प्रसंग में निहित शान्ति क भंग होन, या ऐसे अग्रघर्षण के कार्य में, जहाँ कि सैन्य बल का प्रयोग आवश्यक हो गया हो, जिससे कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को या तो बनाये रखा जा सके, या फिर से स्थिर किया जाय। यदि उस समय साधारण सभा सत्र में न हो, तो सभा आपातकाल में, इस आशय के निवेदन पर २४ घंटे के भीतर बैठक के लिए बुलाई जा सकती है। इस प्रकार का आपातकालीन विशेष सत्र सुरक्षा परिषद द्वारा उसके किसी भी सात सदस्यों के बहुमत के आधार पर किये गये निवेदन पर, या संयुक्त राष्ट्रों के सदस्यों के बहुमत के निवेदन पर आयोजित किया जा सकेगा।'

सभा ने एक 'सामूहिक उपाय समिति' (Collective Measures Committee) की भी संरचना की जिसके उत्तरदायित्व में यह काम दिया गया कि वह प्रत्यक्ष या रोचक या लिये संघ की प्रथम योजना तैयार करे। इसी मंत्रालय के द्वारा एक 'शान्ति-निरीक्षण-आयोग' (Peace Observation Commission) का भी गठन किया गया।

'शान्ति के लिये संगठित होने' (Uniting for Peace) के संकल्प का संयुक्त समाजवादी सोवियत गणतन्त्र द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि इससे सुरक्षा परिषद कमजोर हो जायेगी, क्योंकि परिषद के शान्ति और सुरक्षा संबंधित पूर्ण दायित्व को उससे छीना जायेगा और चार्टर में निषेध (veto) के आधार पर जिस समरूपता की प्रवृत्ति थी गई है, वह मिथ्या मत माना हो जायेगा।

'शान्ति के लिये संगठित होने' के संकल्प के अन्तर्गत महासभा को जाति प्रदान की गई है, उसके अनुसरण में महासभा का एक विशेष प्रापात्वालीन अधिवेशन नवम्बर, १९५६ में प्रथम महासभा में बुलाया गया। इन अधिवेशन के लिये विचारणीय प्रश्न अक्टूबर, १९५६ में मिल पर हिजरायल-एंग्लो-फ्रेंच-प्राक्रमण पर उस स्थिति में विचार करना था जबकि सुरक्षा परिषद में संयुक्त राज्य अमेरिका के इस प्रस्ताव पर ब्रिटेन और फ्रान्स ने निषेध का प्रयोग कर दिया था कि मिल में सभी राष्ट्रों से बल प्रयोग या आतंक को रोकने का आग्रह किया जाय।

'शान्ति के लिये संगठित होने' के संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र संघ के दो महत्वपूर्ण अंगों अर्थात् महासभा और सुरक्षा परिषद के बीच विश्व शान्ति को बनाये रखने के प्रसंग में परस्पर के आधारभूत संबंधों को ही बदल डाला। इसने महासभा को वह सार्वभौमिक प्रदान कर दी कि वह ऐसी स्थिति में स्वयं आगे कदम उठा सके, जब कि परस्पर महान् शक्तियों की मत-भिन्नता के कारण सुरक्षा परिषद प्रभावकारी कदम उठा सकने में असफल हो रही हो; और यह कि सभा ऐसी संस्तुतियों भी कर सके जिनमें सैन्य-बलों के प्रयोग के भी उपबन्ध हो। इस संकल्प के विभिन्न उपबन्धों का उद्देश्य है सामूहिक उपायों को शान्ति और सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावकारी कर बनाने और उनमें त्वरितता से आना। प्रभाव रूप में प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय किया गया है कि जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो, जिसका कि उल्लेख ऊपर किया गया है, तो महासभा, जिसके समूह में महत्वपूर्ण प्रस्तावों के लिये बांझित है कि उपस्थित और मतदान करने वाले राज्यों में से दो तिहाई का बहुमत हो, इस बहुमत के आधार पर अपने हाथ में प्रसंगगत मामले को ले सकती है और सदस्य राज्यों के नाम कोई भी संस्तुति कर सकती है।

१९६० में कांगो विवाद में जिसमें सुरक्षा परिषद् ने ८ और २ के अनुपात के बहुमत से संकल्प पारित किया था कि महासभा का विशेष सत्र बुलाया जाय, उसकी वैधता को पोलैंड और संयुक्त समाजवादी सोवियत गणतन्त्र ने चुनौती दी थी। सोवियत रूस की चुनौती का आधार यह था कि शान्ति के लिये संगठित होने का संकल्प चार्टर के उन उपबन्धों के प्रतिबल अंगीकृत हुआ है जिनमें कि वांछित है कि आपातकालीन सत्रों की बैठक बुलाएँ के लिये सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों का एकमत होना आवश्यक है। सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव की वैधता को दी गई इस चुनौती में इस आधार पर शान्ति के लिये संगठित होने का संकल्प की सैधान्तिकता का प्रश्न नहीं उठा क्योंकि महासभा की सक्षमता चार्टर के अनुच्छेद ११ क पैरा २ और अनुच्छेद १२ के सम्बन्ध में सीमित है। इसका कारण यह है कि इससे पूर्व दो अवसरों पर सोवियत रूस ने इस आधार पर सभा के विशेष आपातकालीन अधिवेशन को बुलाने के प्रश्न पर स्वीकृत मतदान का प्रयास किया था क्योंकि सुरक्षा परिषद् का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने से सम्बन्धित जो प्राथमिक दायित्व है, उसके निर्वाहन में परिषद् के स्थायी सदस्यों की एकमतता के अभाव से बाधा पड़ी थी। वे अवसर इस प्रकार थे—(१) अक्टूबर, १९५६ में हज़रामल, फ्रांस और युनाइटेड किंगडम ने जब अगस्त, १९५५ में मिस्र पर आक्रमण किया था, उस समय सशस्त्र हस्तक्षेप के सम्बन्ध में, और (२) लेबनान और जार्डन में शान्ति के भंग होने की आशंका के सम्बन्ध में प्रस्तावित संकल्प के प्रसंग में। १९५६ में सुरक्षा परिषद् में यह आपत्ति, जब कि दो स्थायी सदस्यों, अर्थात् फ्रांस और युनाइटेड किंगडम ने के स्वेज हस्तक्षेप के सम्बन्ध में नकारात्मक मतदान किया था फिर भी इस आपत्ति को बढ़ावा न मिल सका।

चार्टर के अनुच्छेद २० के अन्तर्गत विशेष अधिवेशन महासचिव द्वारा सुरक्षा परिषद् के निवेदन पर बुलाये जाने का उपबन्ध है। उसके अन्तर्गत ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि कोई विशेष अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के ऐसे किसी भी सात सदस्यों के निवेदन पर बुलाया जा सके जिनका कि सुरक्षा परिषद् में प्रतिनिधित्व है। चूँकि सोवियत रूस ने महासभा के उत्तरवर्ती आपातकालीन विशेष अधिवेशन की वैधता को चुनौती नहीं दी थी अतः मामले को सुलझा हुआ मान लेना चाहिये और महासभा के इस अधिकार को भी स्वीकार कर लेना चाहिये कि विशेष सत्र के बुलाने की प्रक्रिया वह स्वयं निर्धारित करे।

पोलैंड ने दूसरी आपत्ति इस आधार पर उत्पन्न की थी कि सुरक्षा परिषद् को जहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के बनाये रखने के प्राथमिक दायित्व का प्रश्न है, यह दायित्व अव्यक्त नहीं हुआ है क्योंकि परिषद् ने कांगो के

प्रसंग में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से तीन सकल्पों को अंगीकृत किया है। इसलिये विशेष अधिवेशन बुनाये जाने के लिये जो शर्त बांझित थी वह पूरी नहीं हुई। इस आपत्ति के उत्तर में केवल इतना कहा जा सकता है कि इस तथ्य में कि सुरक्षा परिषद् ने तीन सकल्पों को अंगीकृत किया है, यह अर्न्तनिहित नहीं है कि सदस्य आगे फिर इस आधार पर सभा का विशेष अधिवेशन बुलान का मापह न कर सके। कि सोवियत रूस द्वारा ऐसे सक्त्प पर निषेध, जिसमें कि काँगो सरकार को संयुक्त राष्ट्र निधि से वित्तीय सहायता प्रदान करने का उपबन्ध था, परिषद् को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाये रखने के दायित्व के प्रयोग पर बाधक सिद्ध हुआ है। सात मतों की बांझनीयता की शर्त वास्तव में पूरी हो चुकी है।

शान्ति के लिये सगठित होने के सकल्प के अंगीकृत किये जाने के उपरान्त भी "सुरक्षा परिषद् शान्ति बनाय रखने में सम्बन्ध में वैध रूप में प्रस्थापित प्राथमिकता को अब भी बनाये हुये है और इसके पूर्व सबनान, जार्जन और काँगों की विकट परिस्थितियों में परिषद् न स्थिति का सम्भालने के लिये अपने अधिकार का प्रयोग किया है, किन्तु जब तक कि शीत युद्ध का तनाव बना रहता है, यह सम्भव है कि महासभा अधिक प्रभावकारी कार्य सम्पन्न कर सकें।" (जे० एल० ब्रायली, दो लाँ आफ नेशनस, सालहवाई सस्करण, पृष्ठ ११८)।

कार्यों का सिंहावलोकन — साधारण सभा ने केवल एक क्षेत्र (forum) ही नहीं प्रस्तुत किया है बरन् उसने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में निश्चित निर्णय करने की क्षमता भी व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र सभ के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी विषयों पर वह बहुसं कर सकती है और यह कहना ठीक ही है कि 'कई भी ऐसी बातें जो कि सूर्य की किरणों की सीमा में मानवीय हित की है अथवा मानव अधिकारों से सम्बन्धित है या मनुष्य के भोजन, उसके शरण और उसने वस्त्रादि से सम्बन्धित है' वह साधारण सभा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है।

स्टार्क (Starke) के अनुसार "It is remarkable that in practice the General Assembly has been able to take a leading role in questions of international peace and security." — तात्पर्य यह कि साधारण सभा ने अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रश्नों के निपटारा के लिये प्रशंसनीय कार्य किया है। पैलास्टाइन, प्रीस, स्पेन, कोरिया, बाश्मीर, बांग्ला आदि, सभी विवादों में उसने विचार-विमर्श किया है तथा समस्याओं के मुकामों का जरूरतक प्रमाण किया है।

साधारण सभा ने ३ जनवरी, १९५० को (Uniting for Peace) अर्थात् शांति के लिये संयुक्त होने का प्रस्ताव पारित किया था । इस प्रस्ताव से साधारण सभा की शक्तियाँ बहुत ही बढ़ गई हैं । इस प्रस्ताव ने पाँच महान् शक्तियों द्वारा प्रयोग किये गये निषेधाधिकार की प्रखरता को आंशिक रूप से कम कर दिया है ।

## २ सुरक्षा परिषद् (Security Council)

सुरक्षा परिषद् में पारम्भिक रूप में संयुक्त राष्ट्र के ग्यारह सदस्य होते थे । चीन का गणतन्त्र, फ्रांस, रूस का समाजवादी गणतन्त्र सभ, ग्रेट-ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका पाँच स्थायी सदस्य हैं और छ अस्थायी सदस्य साधारण सभा द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिये निर्वाचित होते थे ।

महासभा द्वारा दिसम्बर १७, १९६३, को स्वीकृत किये गये संशोधन जो प्रभावकारी रूप में अगस्त ३१, १९६५, को अस्तित्व में आया, सुरक्षा परिषद् पंद्रह सदस्यों द्वारा गठित होगी जिनमें महासभा दस अन्य संयुक्त राष्ट्र सदस्यों को सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्यों के रूप में निर्वाचित करेगी । अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन में विशेष रूप से उन राष्ट्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य में संयुक्त राष्ट्र सभ को विशेष सहयोग दिया है । इसके साथ ही इस निर्वाचन में समान भौगोलिक वितरण के भी सिद्धान्त को व्यवहृत किया जाएगा ।

चार्टर में यह भी अनुबन्धित है कि संयुक्त राष्ट्र सभ का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद् का सदस्य न हो मतदान का अधिकार न रखते हुये भी किसी प्रश्न की विवेचना में जो सुरक्षा परिषद् के समक्ष रखा गया हो, यदि उस सदस्य के हितों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता हो तो भाग ले सकता है । इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र सभ का कोई सदस्य जो सुरक्षा परिषद् का सदस्य न हो अथवा कोई राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र सभ का सदस्य न हो यदि वह सुरक्षा परिषद् के विचाराधीन किसी झगड़े में पक्षकार हो तो उसे मतदान के अधिकार के बिना उस झगड़े संबंधी विवेचना में भाग लेने के लिये आमन्त्रित किया जायगा ।

सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष पारी-पारी से सुरक्षा परिषद् के सदस्यों द्वारा उनके नाम से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रमानुसार ग्रहण किये जाते हैं । प्रत्येक अध्यक्ष कैलेंडर के एक मास के लिये पद ग्रहण करता है ।

सुरक्षा परिषद् की शक्तियाँ और कार्य — संयुक्त राष्ट्र सभ के सम्पूर्ण वैधानिक रूप से प्रमुख कार्यों का संचालन सुरक्षा परिषद् को दिया गया है जो उन्हें

या तो अकेले अथवा साधारण सभा से परामर्श करके करती है। अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापना करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों द्वारा सुरक्षा परिषद् को सौंपा गया है। सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र सभ का एक अंग है। इसका अधिक अथवा कम मात्रा में कार्य-कारिणी के रूप में कार्य करने पड़ते हैं। अतः यह चार्टर अनुच्छेद २५ के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों की ओर से कार्य करती है तथा सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे सुरक्षा परिषद् के निर्णयों को स्वीकार करेंगे तथा उनका पालन करेंगे।

**भगडों या शान्तिपूर्ण तथा अनुरोधपूर्वक समझौता** — सुरक्षा परिषद् प्रमुख दो कार्य करती है। यह चार्टर के अध्याय ६ के अन्तर्गत भगडों के बारे में जाँच करती है तथा अध्याय ७ के अन्तर्गत शान्ति भंग के सम्बन्ध में कार्यवाही करता है। अध्याय ६ के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् जब कभी आवश्यक समझती है भगडे के पक्षकारों को बुलाती है जब कि भगडे के आरो रहने से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना संकटापन्न हो तथा उनसे उनका वार्ता-समझौता, जाँच, मध्यस्थता, सत्त्वना, पचायत, न्यायिक नियम, प्रादेशिक अभिकर्तृत्व अथवा प्रबंधक का अत्यन्तम्बन्ध अथवा उनकी इच्छा के अन्य शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा करने का कहती है। ऊपर निर्देशित प्रकार के भगडों के पक्षकार बतायी गयी रीतियों से यदि इस तय करने में असफल रह तो सुरक्षा परिषद् यह निर्णय करती है या तो ठीक ठीक प्रक्रियाओं की अथवा तय करने की रीतियों की सिफारिश की जाय अथवा तय करने के वास्तविक निबन्धना की सिफारिश की जाय। सुरक्षा परिषद् स्वतः अथवा संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य द्वारा निर्देशित किये जाने पर अथवा किसी सदस्य द्वारा जो भगडे में पक्षकार हो अथवा साधारण सभा द्वारा निर्देशित किये जाने पर किसी ऐसे भगडे अथवा स्थिति की जाँच कर सकती है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुष्टि उत्पन्न हो। भिन्न-भिन्न कार्यवाहियाँ जो सुरक्षा परिषद् द्वारा भगडों के शान्तिपूर्वक समझौते की दिशा में की गई वे निम्नलिखित हैं :—

सन् १९४७ में नीदरलैंड तथा इटालीयाना स युद्ध बन्द करने को कहना, सुरक्षा परिषद् के २५ अंगस्त सन् १९४७ के प्रस्ताव पर इंडोनेशिया के मामले में सुसेवा मध्यस्थता, आयाग, वैनस्टाइन के मामले में मध्यस्थ की तथा बाद में समायोजन समायोजन की नियुक्ति तथा भारत और पाकिस्तान के भगडे में मैत्रीपूर्ण समझौते पर पहुँचने का प्रयास आदि है।

अध्याय ७ के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् यह निश्चय करती है कि शान्ति के विरुद्ध कोई घमकी अथवा शान्ति भंग अथवा आक्रमणकारी कार्य तो विद्यमान नहीं है तथा सिफारिश करती है अथवा निश्चित करती है कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा

सुरक्षा स्थापित रहने के लिये अथवा उनका पुनः स्थापनार्थ किन उपायों का अवलम्बन किया जाय। सुरक्षा परिषद् द्वारा जो उपाय अवलम्बित किए जाय वे प्रवर्तक कार्य व भीतर आते हैं तथा बाह्य प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के उपाय वे हैं जिनमें सैनिक बल प्रयोग सम्मिलित नहीं है जैसे कि अनुच्छेद ४१ में अनुबन्धित है। इस अनुच्छेद व अनुबन्धों व अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् समुक्त राष्ट्र सच क सदस्यों से यह माँग कर सकती है कि ऐसे उपायों को लागू करें जैसे आर्थिक सम्बन्धों, यातायात व माध्याम तथा दूरनीतिक सम्बन्धों का विच्छेद। दूसरे प्रकार के उपाय अनुच्छेद ४२ व अन्तर्गत लागू किए जाते हैं जब उपरोक्त अनुच्छेद ४१ में अनुबन्धित उपाय अपर्याप्त सिद्ध होते हैं तथा उनमें स्थल, जल अथवा वायु सेनाओं द्वारा ऐसा कार्य सूचित है जिसमें नाकाबन्दी भी सम्मिलित है जैसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापना के अथवा पुनः स्थापना के लिए आवश्यक हो। इन कर्तव्यों का पालन करने व लिये समुक्त राष्ट्र सच व सब सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा की है कि सुरक्षा परिषद् द्वारा माँगे जाने पर तथा विशेष स्वीकार-पत्र अथवा स्वीकार-पत्रों के अनुसार वे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापना के निमित्त आवश्यक सैनिक दल, सहायता तथा सुविधायें जिनमें यातायात अधिकार भी सम्मिलित हैं उसको प्रदान करेंगे। चार्टर के अनुच्छेद ४५ में यह व्यवस्था की गई है कि पाँच स्थायी सदस्यों की सेनाओं के प्रधानों की एक सैनिक दल-समिति बनगी जो सुरक्षा परिषद् को प्रवर्तक कार्य में सैनिक दृष्टिकोण के सम्बन्ध में सम्मति तथा सहायता प्रदान करेगी। समुक्त राष्ट्र सच की प्रति आवश्यक समय पर सैनिक उपायों के अवलम्बन करने योग्य बनाने के लिये सदस्यों ने यह भी प्रतिज्ञा की है कि वे राष्ट्रीय वायु सैनिक दलों की टुकड़ियों व समुक्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रवर्तक कार्य के लिए तत्वाल ही प्राप्त करावेंगे।

सुरक्षा परिषद् ने सर्वप्रथम निराकरणकारी अथवा प्रवर्तक कार्यवाही का कार्रवाई की सजाई में प्रयोग किया जब इसने अपने जून २७ तथा जुलाई ७ सन् १९५० के प्रस्तावों द्वारा उत्तरी कोरिया में आक्रमण की निन्दा की तथा सदस्यों से यह प्रार्थना की कि वे सैनिक दल तथा अन्य सहायता दें तथा उनको समुक्त राष्ट्र के अधीन एक सम्मिलित कमान ( unified command ) को उपलब्ध करें। जुलाई ७ के प्रस्ताव द्वारा समुक्त राष्ट्र से प्रार्थना की गई कि वे इन सेनाओं के समावेश को नियुक्त करें तथा सम्मिलित कमान को यह प्राधिकृत किया गया कि वह स्वेच्छानुसार समुक्त राष्ट्र सच के भेड़े का उपयोग करे। कोरिया प्रजातन्त्र की सेनाओं को अमेरिका के सहायक तथा बम फेंकनेवाले वायुयानों द्वारा सहायता प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त समुक्त राष्ट्र सच ने सदस्य तथा असदस्य राष्ट्रों द्वारा कम्युनिस्ट चीन तथा उत्तरी कोरिया को सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पदार्थों के निर्यात



३०२ ]

मे रोक लगा दी। इसके पूर्व सुरक्षा परिषद ने पैलेस्टाइन, इजिप्टिया तथा कासीर के मामले में अपने को मुख्यतः पत्रकारों के बीच में समझौता होने पर मोलाबारी बंद कराने के कार्य तक ही सीमित रखा।

तो भी यह अभी तक अनिश्चित ही है कि यदि एक राष्ट्र झगड़े को शान्तिपूर्ण उपायों से निर्यात करने में असफल रहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लागू की गई प्रवर्तक कार्यवाही कहाँ तक प्रभावपूर्ण होगी। चार्टर के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद को छोड़कर अन्य किसी रीति से प्रवर्तक कार्यवाही सम्भव नहीं है। सुरक्षा परिषद में बड़े पाँच को निषेधाधिकार (Veto Right) है जिनके परिणामस्वरूप किसी बड़ी शक्ति के विरुद्ध प्रवर्तक कार्यवाही पूर्णतः बहिष्कृत है।

सुरक्षा परिषद के तीन प्रस्ताव जिसके आधार पर उत्तरी कोरिया के विरुद्ध कार्यवाही करना था सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य की अनुपस्थिति में भी पारित हुये। अनुच्छेद २७ (३) के अनुसार सुरक्षा परिषद के नियम प्रक्रियात्मक प्रसंगों के अलावा अन्य सभी प्रसंगों में ७ (तथा संशोधन के पश्चात् ६) सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट द्वारा होता है जिसमें स्थायी सदस्यों का निर्णायक वोट भी रहता है।

कोरिया में की गई कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा झगड़े के बाध्यकर समाधान के क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

Dr Murray का कथन है कि "सुरक्षा के उपबन्ध संघ को बहुत ही तेज दौड़ और बहुत ही प्रबल शक्ति प्रदान कर देते हैं और नया चार्टर पुराने कावेनेण्ट की अपेक्षा सुरक्षा परिषद को कहीं ऊँचे स्तर पर ला देता है। पहली बार पठन पर ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन आगे सन्देहों के कारण भी उत्पन्न हो जाते हैं। अधिक शक्ति से सम्पन्न राज्य प्रायः विश्व-शान्ति को खतरे में डाल दिया करते हैं। उनकी निरन्तर बढ़ती हुई शक्ति यह सन्देह उत्पन्न कराती है कि शान्ति के लिये स्थापित किया हुआ यह संघ उन्हें अपने प्राधिकार में न ला सकेगा। वे बहुत सी साधारण प्रतिज्ञायें करते हैं कि अच्छा व्यवहार करेंगे किन्तु मनमाने व्यवहार के लिये स्वतन्त्र रहते हैं किन्तु हमें इस बात के लिये अपने आपको बचाई देना चाहिये कि नए संघ के दाँत हैं।"

सुरक्षा परिषद के अग्र वृत्त स्थानीय झगड़ों को शान्तिपूर्वक निर्यात के हैं। यह न्यासित प्रदेश का नियन्त्रण और निरोधण का अधिकार रखती है। यह साधारण सभा के समस्त सदस्यों के प्रवेश, निषेधन तथा निष्कासन की सिफारिश करती है।

सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया (Young Procedure) — सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक मतदान का अधिकार है। प्रक्रिया सम्बन्धी

विषयो में सुरक्षा परिपद का निर्णय सात (तथा सलायन के पश्चात् ६) सदस्यों के, अगोकारसूचक मतदान से होता है। अन्य सभी विषयों में सुरक्षा परिपद के निर्णय सात (तथा सलायन के पश्चात् ६) सदस्यों के अगोकार-सूचक मतदान द्वारा होता है जिसमें स्थायी सदस्यों वा सहमतिसूचक मतदान भा सम्मिलित है। इन स्थितियों में स्थायी सदस्यों के अगोकारसूचक मतदान उस विशिष्ट निर्णय के पक्ष में आवश्यक हैं अन्यथा वह निर्णय भयरुद्ध हो जाता है अथवा विशेषाधिकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है और पड़ा रह जाता है।

**निषेधाधिकार (Veto Right) :—**स्थायी सदस्यों के निषेध सम्बन्धी निषेधाधिकार का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, अतः इस विषय पर कुछ विवेचना की आवश्यकता है। प्रारम्भ में सैन फ्रान्सिस्को सम्मेलन में यह योजना बनाई गई थी कि पाँच बड़ी शक्तियों पर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने का विशेष उत्तरदायित्व है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जी द्वितीय विश्वयुद्ध के अन्तिम दिनों में विश्वसंध के विचार को विचारपूर्ण विषय बनाने के लिये उत्तरदायी थे, उनका यह विचार था कि युद्धोत्तर काल में बड़ी शक्तियों के लिये सत्कार की गाँधी साथ-साथ खीचनी आवश्यक है तथा इस उद्देश्य पर वे तभी पहुँच सकते थे यदि वे परस्पर सहाय्य करें तथा एक दूसरे से न लड़ें। वे इस बात को पहले से ही समझते थे कि अमेरिका तथा रूस ऐसी बड़ी-बड़ी शक्तियों के लिये यह कदापि सम्भव नहीं था कि वे एक ऐसी सभा में सम्मिलित हों जहाँ कुछ छोटे-छोटे राष्ट्र एकत्रित हों तथा केवल बहुमत के बल से उन्हें अपनी इच्छानुसार नचायें। वे समझते थे कि ये राष्ट्र भिन्न प्रकार से संगठित हैं तथा उनके आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में भिन्नता है। बड़े राष्ट्रों के लिये अपने को इस प्रकार सकटापन्न करना बड़ा ही कठिन था, अतः विश्व को उस स्थिति में निषेध का विशेषाधिकार आवश्यक हो गया, अन्यथा वे समुक्त राष्ट्र किसी दशा में नहीं हो सकते थे। अतः उन्होंने इसको एक निश्चित विशिष्टता के रूप में वास्तविकता प्रकट करने वाली स्थिति मानकर ग्रहण किया। अतः निषेधाधिकार का अभिप्राय यह था कि समुक्त-राष्ट्र बड़ी शक्तियों में से किसी को न तो बाध्य कर सकता था और न ऐसा करना चाहिये था क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा करने का मतदान के बल पर प्रयास किया तो वह शक्ति अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर सकती थी। इसका अर्थ अन्य शब्दों में यह हुआ कि किसी बड़ी शक्ति को बलपूर्वक बाध्य करने का परिणाम निश्चय ही एक विश्वयुद्ध होगा और अभिप्राय यह था कि उस विश्वयुद्ध का बचाया जाय तथा संघर्ष और विरोध को सम्मेलन के मेज पर ही रखा जाय और उसे युद्धक्षेत्र में न ले जाया जाय।

चार्टर के अन्तर्गत कोई प्रवर्तक कार्य (enforcement action) सुरक्षा परिषद् को छोड़कर किसी अन्य द्वारा सम्भव नहीं है। सुरक्षा परिषद् में बड़ी शक्तियों को निषेध का विशेषाधिकार है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी शक्तियों के विरुद्ध प्रवर्तक कार्य पूर्णतया बहिष्कृत हैं। केन्सन का कथन है कि सुरक्षा परिषद् के पाँच स्थायी सदस्यों का निषेध का विशेषाधिकार जिसके द्वारा विशेषाधिकार संयुक्त राष्ट्र सभ की विधि के ऊपर हो जाते हैं, यह स्थापित करना है कि उनका वैश्विक प्रभुत्व संयुक्त राष्ट्र सभ के सब सदस्यों के ऊपर है तथा इनको (संयुक्त राष्ट्र सभ) एक निरंकुश अथवा कुलीनतन्त्र राज्य की मुद्रा से अंकित करता है। उनका यह भी कथन है कि चार्टर में यह उद्घोषित किया गया है कि इसका प्रथम सिद्धान्त इनके सब सदस्यों की सर्वव्यापी समानता है, अतः संयुक्त राष्ट्र सभ के राजनैतिक भावार्थ तथा इसके वैधानिक संगठन में स्पष्ट विरोध है। इस चार्टर से वह बड़ा लाभ पूर्णतः कुण्ठित हो सकता है जो चार्टर ने सुरक्षा परिषद् को प्रायः सरकार को समान शक्तियाँ प्रदत्त करके कावनेएट की शर्तों से अधिक प्राप्त करने का प्रयास किया।

निषेध का विशेषाधिकार इस आशा से आरम्भ किया गया था कि बड़ी शक्तियाँ सभ के शान्तिपूर्ण तथा निर्विघ्न संचालन का निश्चित करने के लिये वही सद्वृद्धि स्थापना करने में सफल होंगे जो उन्होंने युद्ध के मध्य में प्रदर्शित की थी। यह निरर्थक समझा गया कि विभिन्न देशों के विस्तार, जनसंख्या, शक्ति की अपेक्षा किये बिना एक छोटे देश यथा आइसलैंड को वही मतदान तथा बोलने का अधिकार द दिया जाय जैसा रूस, ब्रिटेन अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका को। स्थायी सदस्यों के मध्य वैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने की उत्कट इच्छा असत्य सिद्ध हुई है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच के शीतयुद्ध ने संयुक्त राष्ट्र सभ को अपने लक्ष्य पर अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की प्राप्ति पर पहुँचने के बीच में रोड़ा अटक दिया है।

संयुक्त राष्ट्र सभ के निर्माण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में निषेध के विशेषाधिकार द्वारा बड़ी शक्तियाँ अपनी विदेशीय अथवा आन्तरिक नीति को संयुक्त राष्ट्र सभ के बहुमत निर्णयों से सुरक्षित करने में समर्थ हुई थीं। यह 'अनेच्छक दामता के विरुद्ध प्रतिरक्षा के रूप में, बड़े राष्ट्रों के भाग्य को विदेशी बमानों के अधीनस्थ किये जाने व सम्बन्ध में समुचित भय के पूर्ण उत्तर के रूप में तथा अन्तर्राष्ट्रीय बमान की शाश्वत स्वतन्त्रता की गारन्टी के रूप में समझी जाती थी। इसमें सन्देह नहीं कि रूस अपने निषेधाधिकार को किसी भी मात्रा में कम किये जाने व बहुत ही विरुद्ध है। यहाँ तक कि सुरक्षा परिषद् का मुखरूप से संचालित

करने के लिये पुनर्निर्धारण के लिये प्रयासों को भी वह सदेह की दृष्टि से देखता है। उसने इस सदेह को ममता भरी भावना से देखा है मरल है क्योंकि रूस वालों के साथ उनके निषेधाधिकार की नीति के संबंध में दूसरे पक्ष वाले निष्पक्ष नहीं रहे हैं। यदि रूस वालों ने अपने निषेधाधिकार का दुरुपयोग किया है तो दूसरे पक्ष वाले ने भी उनको इस दुरुपयोग के लिये अपराध कहने में चूक नहीं की है। निश्चय ही कुछ स्थितियों में निषेधाधिकार का प्रयोग स्पष्ट रूप से रूस के अनुयायियों की रक्षा के लिये किया गया था तथा अन्य दशाभा में रूस का अभिप्राय संयुक्त राष्ट्र सभ में अपनी आपेक्षिक शक्ति स्थिति बनाय रखने का था, न कि उसके कार्यों में रोड़ा भटकाने का। निषेधाधिकार का उपयोग नये सदस्यों के प्रवेश के विरुद्ध भी किया गया जिससे साधारण सभा में बहुमत वालों की संख्या में वृद्धि न हो जाय तथा दोष निषेधाधिकार साधारण सभा की क्षमता की वृद्धि का रोकने में उपयोग किये गये।

निषेधाधिकार के प्रभाव को कम करने के लिये साधारण सभा ने सोवियत रूस के मत के विरुद्ध नवम्बर ३, १९५० को यह प्रस्ताव किया कि सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्यों के मतों में अभाव में अपने प्रमुख दायित्व को प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाती। जहाँ कहीं भी शान्ति के लिए धमकी दी जाती है या शान्ति भंग की जाती है या आक्रमण किया जाता है, उन सभी मामलों में ऐसा ही मतविभेद देखने को मिलता है। इसलिये इस विषय पर साधारण सभा तत्काल ही विचार करेगी जिससे सदस्यों के सामूहिक कार्यवाही के सम्बन्ध में सिफारिश की जा सके जिससे शांति भंग की व्यवस्था में और आक्रमण के समय यदि आवश्यक हो तो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिये सैनिक कार्यवाही की जा सके। यह भी प्रस्ताव पारित हुआ कि यदि साधारण सभा उस समय अपने सत्र में नहीं है तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने के २४ घंटे के भीतर उसकी आपातकालिक बैठक बुलाई जा सके। ऐसी बैठक सुरक्षा परिषद् के किसी भी सात सदस्यों से बोट पर या संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की बहुमत पर बुलाई जा सकती है।

M. Alvarez ने अपनी सहमति सूचक निष्कर्ष "साधारण सभा की क्षमता पर कि वह नये राज्यों को संयुक्त राष्ट्र सभ में सम्मिलित करने में कहाँ तक सक्षम है", के वाद में अवलोकन किया है कि—"To decide that the right of veto may be freely exercised in every case in which the Security Council may take action would mean deciding that the will of a single Great Power could frustrate the

will of the other members of the Council and of the General Assembly, even in matters other than the maintenance of peace and security, and that would reduce the U. N. O. to impotence.” अर्थात् यह निश्चय करना कि हर मामले में निषेधाधिकार का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग किया जाय जिसमें कि सुरक्षा परिषद् को कार्यवाही करना आवश्यक होता है, अभिप्राय यह होगा कि केवल एक महान् शक्ति परिषद् के अन्य सदस्यों की इच्छाओं को दबा सकती है और यहाँ तक कि साधारण सभा की इच्छाओं को उन मामलों में भी जो कि शांति और सुरक्षा की अपेक्षा अन्य हैं। इससे संयुक्त राष्ट्र सभ पूर्ण रूप से अक्षम हो जायेगा।

**दुहरा निषेधाधिकार (Double Veto).**— सुरक्षा परिषद् की मतदान-प्रक्रिया में देखा जा चुका है कि इस परिषद् में प्रत्येक सदस्य का एक मत देने का अधिकार प्राप्त है। प्रक्रिया सम्बन्धी (procedural) विषयों में सुरक्षा परिषद् का निर्णय कोई सात (और अनुच्छेद २७ के सशोधन के पश्चात्, नौ) सदस्यों के अग्रीकार सूचक मत (affirmative vote) से होता है। अन्य सब विषयों में सुरक्षा परिषद् का निर्णय सात (और अनुच्छेद २७ के सशोधन के पश्चात्, नौ) सदस्यों के अग्रीकारसूचक मतदान से होना है जिसमें स्थायी सदस्यों की सहमतिमूचक मतदान भी सम्मिलित है। यदि स्थायी सदस्य किसी ऐसे विषय पर जो प्रक्रिया सम्बन्धी न होकर मौलिक विषय हो, निषेधात्मक (negative) मत देता है तो उसे विरोधाधिकार द्वारा निषेध अधिकार (veto) कहा जाता है।

सुरक्षा परिषद् के मतदान प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता तब प्रकट होती है जब उनके विषयों का अन्तर प्रक्रिया (procedure) और मौलिक विषयों (matters of substance) में होता है। संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर में भी इन दो विषयों के सबंध में व्याख्या नहीं दी गई है। जिन विषयों से सुरक्षा परिषद् का कार्य सगठित रूप से निरन्तर चलता रहता है, वे विषय प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों के अन्तर्गत आते हैं, जैसे सुरक्षा परिषद् के अधिवेशन का समय तथा स्थान निर्दिष्ट करना, सदस्यों को आमन्त्रित करना, उसके प्रक्रिया के लिये नियम बनाना, आदि। सन् १९४५ में २३ विषयों का एक लेखपत्र बनाया गया लेकिन जहाँ तक विरोधाधिकार के द्वारा निषेध के अधिकार का प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों पर लागू होने का सम्बन्ध है, इस लेखपत्र ने उसे सीमित नहीं किया। लेकिन दुहरे निषेधाधिकार द्वारा निषेध के अधिकार (Double Veto) नामक एक अन्य नियम द्वारा यह सीमित हो गया है; यद्यपि विरोधाधिकार द्वारा निषेध के अधिकार के समान ही इसका विवरण भी चार्टर में नहीं है। जहाँ भी एक स्थायी सदस्य को एक वास्तविक निर्णय पर

विशेषाधिकार द्वारा निषेध करना होना है चाहे वह प्रश्न प्रक्रिया सम्बन्धी हो अथवा मूल विषय हो, वही दुहरा विशेषाधिकार द्वारा निषेध का अधिकार (Double Veto) होता है। जब प्रारम्भिक प्रश्न यह होता है कि कोई प्रक्रिया सम्बन्धी विषय है या नहीं तब उसे विशेषाधिकार द्वारा निषेध किया जा सकता है। एक निषेधात्मक मतदान द्वारा किसी प्रश्न को पहिले तो प्रक्रिया सम्बन्धी विषय बनाने से रोका जाता है। उसके उपरान्त प्रस्ताव की मौलिकता (substance) के विरोध में दुबारा मत दिया जाता है। इसी नियम से निषेध का अधिकार दुहरे निषेधाधिकार द्वारा निषेध के अधिकार में बदल जाता है।

सुरक्षा परिषद् में मत प्रदान करने की प्रणाली में एक विभेद प्रक्रियात्मक तथा अन्य सभ्य सम्बन्धी मामलों में उपस्थित होता है। चार्टर में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है। यह तो १९४५ में महात्त शक्तियों द्वारा एक समझौता के आधार पर विभेद मान लिया गया था। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस वक्तव्य (Statement) पर कोई औपचारिक कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप यद्यपि व्यवहारतः यह वर्गीकरण मान्य है फिर भी वैध प्राधिकार समुक्त राष्ट्र सभ के प्रति कोई नहीं है।

Andrew Martin John और Edwards के शब्दों में "जहाँ तक मौमावर्ती मामलों का सम्बन्ध है यह प्रारम्भिक प्रश्न कि क्या विषय प्रक्रियात्मक है स्वतः एक निषेधाधिकार का विषय है। वास्तव में इसी नियम ने निषेधाधिकार को दुहरे निषेधाधिकार के रूप में बदल दिया है। पहले तो एक नकारात्मक वोट दिया जाता है जिससे कि किसी विषय को सुरक्षा परिषद् प्रक्रियात्मक न मान ले, और उसके बाद दूसरी बार मतदान किया जाता है कि प्रस्ताव का तत्त्व ही निष्कल हो जाय।" (First a negative vote is cast to prevent the Council from treating a question as procedural, and a vote is then cast for the second time to defeat the substance of the motion.)

निषेधाधिकार के प्रयोग के सम्बन्ध में १९४८ में साधारण सभा द्वारा गम्भीरता से विचार किया गया था। सभा ने सुरक्षा परिषद् को यह सिफारिश की थी कि कम से कम ४५ प्रकार के प्रक्रियात्मक ढङ्ग के निर्णय मान लिये जायें जिससे कि बड़ी शक्तियाँ दुहरे निषेधाधिकार का प्रयोग न कर सकें। यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद् द्वारा नहीं माना गया जिसका परिणाम यह हुआ कि "निषेधाधिकार का केवल उन प्रसंगों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में वैध रूप से प्रयोग किया जा सकता है जिनमें जून १९४५ के Interpretative Statement के अन्तर्गत प्रक्रियात्मकता आरोपित कर दी गई है।

**आत्मरक्षा (Self Defence) .**—चार्टर के अनुच्छेद ५१ में संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की स्थिति में वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्म-रक्षा का स्वाभाविक अधिकार स्वीकृत किया गया है। यह अधिकार उस समय तक रहता है जब तक कि सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करने के लिए उपाय न कर ले। इस प्रकार के आत्मरक्षा में किये गये उपाय तत्काल सुरक्षा परिषद् को प्रतिवेदित कर दिये जाने चाहिये तथा वे वर्तमान चार्टर के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् के अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना अथवा पुनः स्थापना के लिए किसी समय में ऐसे कार्यों के करने के प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व को जैसे कि यह आवश्यक समझे किसी प्रकार से प्रभावित न करेंगे। किन्तु यह आत्मरक्षा का अधिकार बल सशस्त्र आक्रमण की स्थिति में उत्पन्न होता है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं होना चाहिये। जैसे किमी पड़ोसी राज्य द्वारा अशान्तिपूर्ण सैनिक एकत्रीकरण के कारण उस राज्य के लिये यह उचित नहीं होगा जिसकी शान्ति पर आघात किये जाने की धमकी दी जाय कि आत्मरक्षा की क्रिया द्वारा बल प्रयोग करे। इससे उसको केवल यह अधिकार होगा कि ऐसे एकत्रीकरण को जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा पर प्रभाव पड़ना अथवा उसको धमकी दिया जाना सम्भव हो सुरक्षा परिषद् से प्रतिवेदित करे।

अतः चार्टर सैनिक आक्रमण के विरुद्ध आत्म रक्षा के अधिकार को छोड़कर अन्य दशाओं में सदस्यों द्वारा बल प्रयोग का निषेध करता है।

अनुच्छेद ५१ की व्यवस्था के अनुसार "The right of individual or collective self-defence shall have precedence in fact over the functions assigned to the organs of the United Nations" अर्थात् वैयक्तिक या सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार की प्राथमिकता उन सभी तथ्यों में होगी जो कि कार्यरूप में संयुक्त राष्ट्र सभ के अंगों को सौंपे गये हैं।

आत्म सुरक्षा की व्यवस्था का जहाँ तक सम्बन्ध है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर लीग ऑफ नेशन्स के कावनेन्ट से तथ्य रूप में भिन्न है। कावनेन्ट आत्म-सुरक्षा के अधिकार को सभी मामलों में जिसमें कि लीग अंगों का निपटारा नहीं कर सकती थी, सदस्यों को प्रदान करती थी, किन्तु चार्टर में ऐसी बात नहीं है।

**संघ की वैध स्थिति (Legal Status of the Organization)**—वेल्टन का कथन है कि संयुक्त राष्ट्र सभ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में तथा सदस्य राष्ट्रों के जातीय विधि के क्षेत्र में न्यायिक व्याप्ति रखता है और इस रूप में वेध वर्तमान तथा अधिकारों के अधीन होने, वेध व्यापारों को करने तथा न्यायालयों में दावा करने और इनके विरुद्ध दावा किये जाने के योग्य है। संयुक्त राष्ट्र सभ को

उन अन्तर्राष्ट्रीय सविदाओं के करने का अधिकार है जिनके करने के लिए इसे चार्टर के विशेष अनुबन्धों द्वारा प्राधिकृत किया गया है। सुरक्षा परिषद् का प्रायः एक सरकारी संस्था का स्वरूप है। चार्टर के अनुच्छेद २६ के अधीन इसे भुद्धसामग्री नियमित करने के लिए पद्धति-स्थापना करने के निमित्त संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये योजनाये बनाने के लिये प्राधिकृत किया गया है। इसके उपरान्त अनुच्छेद १०४ द्वारा यह प्रतिबन्धित करके कि सभ अपने प्रत्येक सदस्य के प्रदेश में ऐसी वेध क्षमता का उपभोग करेगा जैसा इसको अपने कृत्यों के संपादन तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक है, सभ को राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में न्यायिक व्यक्तित्व प्रदत्त किया गया है। अनुच्छेद ४३ में सुरक्षा परिषद् तथा संयुक्त राष्ट्र सभ के बीच अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा-स्थापना के निमित्त सुरक्षा परिषद् के समक्ष सैनिक बल, सहायता तथा सुविधायें प्राप्त करने के लिये अनुबन्धित किया गया है। अनुच्छेद ८१ में संयुक्त राष्ट्र सभ को प्रत्यास सविदा क अधीन प्रदेशों के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी तथा विधायी शक्तियाँ उपभोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है।

सभ अपने प्रत्येक सदस्य के क्षेत्र में ऐसे विशेषाधिकार तथा उन्मुखितयाँ रखता है जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक हैं।

संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों के प्रतिनिधि तथा सभ के पदाधिकारी भी ऐसे विशेषाधिकारों तथा उन्मुखितयों का उपभोग करते हैं जो सभ के सम्बन्ध में उनको अपने कृत्यों को स्वतन्त्रतापूर्वक करने के लिये आवश्यक हैं।

इस प्रकार सभ के वे कार्य हैं तथा वह उन अधिकारों का उपभोग करता है जिनको केवल इस आधार पर समझाया जा सकता है कि वह अधिक सोमा में अन्तर्राष्ट्रीय अविनित्व रखता है तथा उसको अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य करने की क्षमता है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के कथनानुसार यह एक सर्वोच्च प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय सभ है और यदि यह अन्तर्राष्ट्रीय अविनित्व से रहित होता तो यह अपने संस्थापकों का अभिप्राय पूरा न कर पाता। इनके सदस्यों ने इसको कुछ कृत्य उनसे संलग्न कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व सहित देकर इसे उम क्षमता से संलग्न कर दिया है जो कि उन कृत्यों को प्रभावपूर्ण रीति से करने के लिये योग्य बनाने के लिये अपेक्षित है।

फैनेकिक का कथन है कि स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र सभ एक 'वरिष्ठ राज्य' (super-State) नहीं है क्योंकि चार्टर के अनुच्छेद २ में यह घोषित किया गया है कि सभ अपने सब सदस्यों की सर्वव्यापी समानता से सिद्धान्त पर प्रभावित है परन्तु यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सभ को अपने व्यक्तिगत सदस्यों से भिन्न एक निरिबत वेध व्यक्तित्व का एक अपना ही निगम निकाय रखता है। लोग के समान यह भी



अपने नाम में सम्पत्ति का स्वामित्व ग्रहण करने, नियम नि्काय के समान संविदा करने तथा अधिकार प्राप्त करने और कर्तव्यों को अपने ऊपर लेने में समर्थ होगा। यह सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं के अधिशासन करने तथा व्यक्तिगत राज्यों के लिये न्यासी के रूप में कार्य करने योग्य होगा। यह क्षेत्र पर अपने मनोनीत अभि-कर्ताओं द्वारा शासन कर सकेगा तथा अधीनस्थ अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए संरक्षक तथा पालनकर्ता के रूप में कार्य करेगा। इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये राज्यमंडल (confederation) शब्द प्रयोग किया जा सकता है, फेनबिक का कथन है कि यह एक शास्त्र-विषयक प्रश्न है और इसका विवेचन भविष्य के लिये छोड़ा जा सकता है। मोपेनहेम का मत यह है कि संयुक्त राष्ट्र, सभ की अपेक्षा राज्यमंडल के अधिक निकट पहुँचना है। “यह विशेषतः इन कारणों से है कि सभ से अलग हो जाने का अधिकार है, संयुक्त राष्ट्र सभ में व्यावहारिक रूप से कोई वेध शक्तियाँ निहित नहीं हैं तथा संयुक्त राष्ट्र सभ और सदस्य राज्यों के राष्ट्रीय जनो के बीच किसी प्रत्यक्ष सम्बन्ध का अभाव है।”

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने “संयुक्त राष्ट्र की सेवा में सहन की गई हानियों के लिये क्षतिपूर्ति” वाले मामले में यह कथन किया है कि “सभ एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह एक राज्य है। यह निश्चित रूप से राज्य नहीं है, अथवा यह कि इसका वेध व्यक्तिस्व तथा अधिकार और कर्तव्य वही है जो एक राज्य के होते हैं। यह अर्थ इसे बरिष्ठ राज्य कहने में तो और भी अधिक कम निकलेगा। इससे यह भी व्यक्त नहीं होता कि इसके सब अधिकार तथा कर्तव्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने चाहिये जैसा यह एक राज्य के सम्बन्ध में भी नहीं प्रकट होता। इसका यह अर्थ है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत है और अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार तथा कर्तव्यों की धारण करने योग्य है तथा इसे अपने अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय वाद प्रस्तुत करके स्थापित करने की अमता प्राप्त है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा तथा सुरक्षा परिषद् का संबंध (Relation of the United Nations Assembly with the Security Council)—सुरक्षा परिषद् प्रायः एक शासकीय सस्था का स्वरूप धारण करती है। मोपेनहेम के कथनानुसार यह मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना से संबंधित है। दूसरी ओर साधारण सभा अधिकांश में एक विचार विमर्श का अंग है जो संयुक्त राष्ट्र सभ के क्षेत्र के भीतर पढ़ने वाले संपूर्ण विषयों से संबंधित है। किसी भगदोर अथवा स्थिति जिससे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के स्थापित रहने के लिये सकट उत्पन्न होना सम्भव हो, उसके सम्बन्ध में केवल सुरक्षा परिषद् को विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसमें सन्देह नहीं कि साधारण सभा अनुच्छेद १५ के अधीन

सुरक्षा परिषद् से उसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापना के लिये निश्चित अथवा किये गये उपायों के वार्षिक प्रतिवेदनो को प्राप्त करती है तथा उन पर विचार करती है । परन्तु ओपेनहेम का कथन है कि चार्टर से यह विचार प्रकट नहीं होता कि ऐसे प्रतिवेदनो को प्राप्त करने में तथा उन पर विवेचना करने में साधारण सभा सुरक्षा परिषद् की कार्यवाहियों पर इस प्रकार से मत प्रकट करेगी कि जिससे यह प्रकट हो सके कि यह झगड़ों के निर्णय करने के सम्बन्ध में समवर्ती क्षेत्राधिकार प्राप्त कर रही है अथवा यह कि परिषद् सभा के अधिभावी प्राधिकार ( overriding authority ) के अधीनस्थ है ।

बहुत से विषयों के सम्बन्ध में साधारण सभा सुरक्षा परिषद् के साथ कार्य करती है । उदाहरणार्थ सदस्यों का प्रवेश तथा निष्कासन, महासचिव (Secretary-General) की नियुक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों का निर्वाचन ।

सुरक्षा परिषद् प्रायः एक निरन्तर कार्य करने वाली संस्था है और साधारण सभा जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक है नियमित वार्षिक सत्रों में अथवा विशेष सत्रों में बैठती है जो महासचिव द्वारा सुरक्षा परिषद् के अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सदस्यों के बहुमत से बुलायी जाती है । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल जो सभा के सत्र में भाग लेने आता है, अपने किये जाने वाले कार्यों के प्रकृति के कारण अधिकतर राजनैतिक व्यक्तियों का बना होता है और सुरक्षा परिषद् में कूटनीतिज्ञ तथा पदाधिकारी होते हैं । सभा का वादानुवाद सदन का स्वरूप ग्रहण कर लेता है किन्तु सुरक्षा परिषद् के अधिवेशन कूटनीतिज्ञों की अधिवेशनों के समान प्रतीत होती है ।

सभा जिसमें १२१ राष्ट्र हैं अधिक प्रतिनिधित्व का रूप धारण करती है तथा जन-साधारण की सम्मति के प्रभाव की ओर ११ (अनुच्छेद २३ के संशोधन के पश्चात्, १५) सदस्यों की सुरक्षा परिषद् से कहीं अधिक ध्यान आकर्षित करती है ।

१९५० का "Uniting for Peace" अर्थात् शांति के लिये संगठित होने के प्रस्ताव ने चार्टर में दिये गये सुरक्षा परिषद् और साधारण सभा के सम्बन्धी में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है और साधारण सभा में बहुत अधिक शक्तियों का आरोप कर दिया है क्योंकि स्थायी सदस्यों के मतैक्य के अभाव में सुरक्षा परिषद् अपने प्रमुख उत्तरदायित्व अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करने में असफल हो जाती है; खासतौर पर उन मामलों में जहाँ कि शांतिभङ्ग की घमकी दी गई हो, शांति भङ्ग की गई हो या आक्रमण की कार्यवाही की गई हो ।

राष्ट्र संघ में विधि (Law in the United Nations)—सयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर अन्तर्राष्ट्रीय विधि के बहुत ही उदार सिद्धान्त को मानता है और न्याय तथा सहिष्णुता, स्त्री और पुरुष के समान अधिकार, मानवीय अधिकारों के लिये सम्मान और बिना किसी जाति, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के मनुष्य की स्वतन्त्रताओं का सम्मान, सन्धियों से उत्पन्न होने वाले आभारों के प्रति सम्मान तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्य स्रोतों तथा सभी राष्ट्रों के समान अधिकार भले ही छोटे हो अथवा बड़े, सभी के प्रति समान न्याय और सहिष्णुता के सिद्धान्तों का अपनाता है ।

कुछ प्रसङ्ग ऐसे भी हैं जिन्हें लेकर कभी-कभी विवाद भी उठ खड़े हुये हैं जैसे चार्टर के अन्तर्गत ५ महान् शक्तियाँ को दो गईं निरक्षुभ शक्तियाँ । इनसे ५ महान् शक्तियों की प्रभुता स्थापित होती है और अन्य छोटे-छोटे राष्ट्र पृष्ठभूमि में चले जाते हैं । इसमें संदेह नहीं है कि चार्टर अनुच्छेद २ ( १ ), के अनुसार संघ की स्थापना सभी प्रभुता-सम्पन्न सदस्य-राज्यों की समानता के सिद्धान्त पर हुई है किन्तु अनेक ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जिनके परिणामस्वरूप महान् शक्तियाँ ही एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार कर सकती हैं ।

सयुक्त राष्ट्र संघ तथा लीग (U. N. and the League):—लीग ऑफ नेशन्स का प्रतिष्ठा-पत्र वर्साई की सन्धि का अंश था तथा इसकी पूर्ति से सम्बद्ध था । सब शक्तिशाली राज्य प्रारम्भ में लीग में इस प्रयोजन से सम्मिलित हुये थे कि उनको वर्तमान सन्धियों तथा वर्तमान क्षेत्रीय व्यवस्थाओं की पुष्टि के लिए कुछ आवश्यक था । सयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म विजित राष्ट्र पर लादो गई शान्ति की सन्धि से सम्बन्धित नहीं है, बरन् उसका सम्बन्ध सयुक्त हुये राष्ट्रों के लोगों के अपने अपने वाली सन्तानों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के निश्चय से है ।

अपनी उत्पत्ति के अतिरिक्त लीग तथा सयुक्त राष्ट्र संघ दोनों के उद्देश्य मूलरूप में प्रायः एक ही हैं अर्थात् राष्ट्रों के परस्पर के झगड़ों को मैत्रीपूर्ण रीति से बिना बलप्रयोग किये, निर्णय करने को प्रोत्साहित करके अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना ।

सयुक्त राष्ट्र संघ के छ मुख्य अङ्ग हैं अर्थात् साधारण सभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्, न्याय परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय । लीग में केवल तीन मुख्य अङ्ग थे अर्थात् सभा, परिषद् और सचिवालय । अतः लीग मुख्यतः अपने को राजनैतिक क्रियाएँ तक ही सीमित रखती थी और सयुक्त राष्ट्र संघ में अधिक महत्व अर्थात् आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानव-प्रेम सम्बन्धी विषयों पर भी बल दिया गया है जो मानव समाज के सुख से

घनिष्ठता से सम्बन्धित हैं। वर्तमान संघ मानवीय व्यक्तित्व के विकास तथा व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों के संरक्षण पर अधिक महत्व प्रदान करता है।

चार्टर के अधीन प्रमुख प्रश्नों पर साधारण सभा के निर्णयों के लिये उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत अपेक्षित है और अन्य विषयों के निर्णयों के लिये उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का केवल बहुमत अपेक्षित है। सुरक्षा परिषद् में प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों में केवल सात (अनुच्छेद २७ के संशोधन के पश्चात्, नौ) सदस्यों का स्वीकारात्मक मतदान अपेक्षित है। अन्य सब विषयों के लिये सात (अनुच्छेद २७ के संशोधन के पश्चात्, नौ) सदस्यों के स्वीकारात्मक मतदान अपेक्षित है जिसमें स्थायी सदस्यों के सहमतिपत्र मतदान भी सम्मिलित हैं। लीग में सब महत्वपूर्ण निर्णयों के लिये मतैक्य अपेक्षित था क्योंकि राष्ट्र अपने सार्वभौमत्व का कोई भी अंश त्यागने को उद्यत न थे। अतः संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की मतदान प्रक्रिया लीग की मतदान प्रक्रिया से स्पष्टतः सुधरी हुई है।

इसमें सन्देह नहीं कि बड़ी शक्तियों का निषेध का विशेषाधिकार सङ्घ की प्रगतियों के लिये बाधक प्रमाणित हो सकता है। यहाँ बात मतैक्य निर्णय के अन्वय का कारण लीग के सम्बन्ध में भी थी। बड़ी शक्तियों का निषेधाधिकार उनके विरुद्ध प्रवर्तक कार्य किये जाने में बाधा डालता है। निम्न इसके साथ ही यह भी स्मरण रखने योग्य है कि लीग की परिषद् के निर्णय केवल परामर्श अथवा सफा-रिश का स्वरूप रखते थे क्योंकि लीग के सदस्य जिनका प्रतिनिधित्व परिषद् में नहीं होता था, परिषद् के निर्णय को पालन करने के लिये बाध्य नहीं थे।

सुरक्षा परिषद् तथा साधारण सभा के कार्यों के बीच एक स्पष्ट सीमा बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सदस्यों ने सुरक्षा परिषद् पर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करने का प्रारम्भिक उत्तरदायित्व सौंपा है। लीग की सभा तथा परिषद् के कार्यों के बीच ऐसी कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी तथा ऐसी स्थिति में लीग निर्बल थी और उसमें किसी विश्व संघ के उन लक्षणों का अभाव था जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा सफलतापूर्वक स्थापित की जा सकती थी। सुरक्षा परिषद् यद्यपि इसने कार्य लीग की परिषद् के कार्यों से अधिक सीमित हैं, तथापि यह अपने निर्णयों का प्रवर्तन कराने के लिये अधिक शक्तिशाली साधन प्रयोग कर सकती है।

प्रवर्तक उपायों के सम्बन्ध में लीग तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत बड़ा अन्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को धमकी दिये जाने की दशा में भी प्रवर्तक उपायों का प्रयोग कर सकता है। इसके विपरीत लीग की शक्ति सीमित थी कि यह उपायों का प्रयोग केवल उसी दशा में कर सकती थी

राज्य अपनी प्रतिज्ञाओं को भङ्ग करके युद्ध में प्रवृत्त होते थे। सुरक्षा परिषद् को यहाँ तक प्राधिकृत किया गया है कि यह आवश्यकता पड़ने पर सैन्य बल का उपयोग कर सकती है अथवा वायु या जलसेना से भी युद्ध का संचालन कर सकती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापन के लिये संयुक्त राष्ट्र सघ के सदस्यों से यह माँग कर सकती है कि वे माँगे जाने पर सुरक्षा परिषद् को सैनिक बल, सहायता तथा सुविधा प्रदान करें जिनमें यातायात अधिकार भी सम्मिलित है। इस कार्य के लिए सुरक्षा परिषद् को सैनिक पदाधिकारी समिति द्वारा सहायता दी जाती है। लीग के उपयोग के लिए कोई सैनिक बल नहीं था तथा इसके निर्णय भी केवल सफारिश के रूप के होते थे। इसके परिणामस्वरूप कोई धृष्ट सदस्य लीग के निर्णयों को पालन करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता था।

संयुक्त राष्ट्र सघ के चार्टर तथा लीग आफ नेशन्स के कावनेंट के मध्य एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कराने योग्य अन्तर है। कावनेंट से यह उपलक्षित होता है कि इसमें प्रवर्तक उपायों के लागू किये जाने की प्रक्रिया के केन्द्रीभूत होने का पूर्णतः अभाव है। लीग के इस प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १६ में यह बात इसके सदस्यों पर छोड़ दी गई थी कि वे निर्णय करें कि क्या किसी अन्य सदस्य ने प्रतिज्ञा पत्र के अधीन कर्तव्या का उल्लंघन किया है तथा क्या प्रवर्तक उपायों को लागू किये जाँय जिनमें सैनिक बल प्रयोग सम्मिलित नहीं था। इसके अनुसार समझ को केवल सफारिश करने के लिये प्राधिकृत किया गया था। इसके विपरीत चार्टर ने इन दोनों बातों के निर्णय को अर्थात् इस प्रश्न का निर्णय कि क्या शान्ति भंग की घमकी अथवा शान्ति भङ्ग अथवा आक्रमणकारी कार्य विद्यमान है या नहीं तथा प्रवर्तक उपायों के लागू किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय केन्द्रीभूत कर दिया है तथा सदस्यों पर उस निर्णय के पालन का कर्तव्य सौंप दिया है।

भारमरक्षा के बारे में लीग आफ नेशन्स ने कोई बात वैयक्तिक अथवा सामूहिक भारमरक्षा के अधिकार के सम्बन्ध में नहीं की है। जो कुछ प्रतिज्ञा-पत्र में अनुबन्धित किया गया है वह अनुच्छेद ११, खंड ७ में दिया गया है जो निम्न-लिखित है —

“यदि परिषद् ऐसे प्रतिवेदन पर पहुँचने में असमर्थ हो जो भगड़े के पक्षकारों के एक अथवा अधिक प्रतिनिधियों से भिन्न उसके सदस्यों द्वारा एकमत से स्वीकृत हो ता लीग के सदस्य अपने लिये यह अधिकार सुरक्षित रखते हैं कि वे ऐसी कार्यवाही करेंगे जैसा वे अधिकार तथा न्याय के लिये आवश्यक समझेंगे।”

चार्टर के अनुच्छेद ११ में इस विषय को स्पष्ट किया गया है। इसमें लीग के अधिकार का क्षेत्र तथा विस्तार स्पष्टतः परिभाषित है तथा इसमें

संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य के विरुद्ध आक्रमण की दशा में वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्मरक्षा का अधिकार उस समय तक स्वीकृत है जब तक सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिये आवश्यक उपायों का प्रयोग न कर सके। किन्तु इस बात पर महत्व देना आवश्यक है कि वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्मरक्षा का अधिकार केवल उसी दशा में उत्पन्न होता है जब सैनिक आक्रमण हुआ हो, न कि सीमा पर सैन्य एकत्रीकरण की दशा में, और यह उस समय तक जारी रहता है जब तक सुरक्षा परिषद् ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिये आवश्यक उपाय न कर लिया हो। इस प्रकार की आत्मरक्षा के उपाय सुरक्षा परिषद् में तत्काल ही प्रतिवेदित किये जाने चाहिये।

दोनों सभों से अलग हो जाने के सम्बन्ध में प्रतिज्ञा-पत्र में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि लीग के किसी सदस्य ने किसी संशोधन के विरुद्ध मतदान किया तथा उसको अनुसमर्थन करने से अस्वीकृत किया तो वह स्वेच्छापूर्वक हट सकता था। किन्तु संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य यदि वे चार्टर के किसी संशोधन को अनुसमर्थन करना अस्वीकार कर दें तो उनका सदस्य बना रहना समाप्त नहीं हो जाता वरन् वे ऐसे संशोधन से बाध्य हो जाते हैं।

न्याय परिषद् के सम्बन्ध में भी कुछ कह देना आवश्यक है। लीग के प्रतिज्ञा-पत्र के अन्तर्गत आदेश पद्धति प्रचलित थी जो प्रथम महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी तथा टर्की से विजित प्रदेशों के संयोजन का स्थान ग्रहण करने के लिये प्रयुक्त की गई थी। पद्धति का विशिष्ट अंग स्थायी आयाग था जो परिषद् द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों से निर्मित था और जिसमें सरकारों के प्रतिनिधि नहीं होते थे। चार्टर के अन्तर्गत न्याय परिषद् है जो न्यास पत्रों को प्रशासन करने वाले सदस्यों से बनी है जिसमें सुरक्षा परिषद् के सभी स्थायी सदस्य हैं तथा साधारण सभा के निर्वाचित सदस्य हैं। इस प्रकार केवल संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्य ही न्याय परिषद् के सदस्य हो सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय न्याय-पद्धति लीग के आदेशों के आयोग के ऊपर एक स्पष्ट सुधार है।

किसी भी दृष्टि से विचार करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सभ लीग आफ नेशन्स की तुलना में एक स्पष्टतः सुधार की हुई तथा संशोधित सभा है और अधिक व्यापक अधिकारों से विभूषित है।

लीग और संयुक्त राष्ट्र सभ की सुरक्षा परिषद् में अन्तर (The Council of the League and the Security Council) — यद्यपि लीग की परिषद् की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्र सभ की सुरक्षा परिषद् को अधिक प्रतिबद्धित कार्य करने पड़ते हैं, फिर भी सुरक्षा परिषद् में अपने निर्णयों के प्रवर्तन के लिये अधिक

शक्तियाँ विद्यमान हैं। सुरक्षा परिषद् और साधारण सभा दोनों व कार्यों में स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है जब कि लीग में ऐसा वाई विभाजन न था।

लीग की कौंसिल एक शक्तिहीन संस्था थी और उसके पास अपने निर्णय के प्रवर्तन के लिये वाइ सना नहो थी। सुरक्षा परिषद् के पास अपनी भूमि, हवाई और नौ-सना की शक्तियाँ उसके पास सदस्य राज्यों की ओर स दी गई होगी, और प्रापा-तिक परिस्थितियाँ में प्रत्येक सदस्य-राज्य सक्रिय सहायता करने के लिये बाध्य है।

संयुक्त राष्ट्र सच के कार्यों में प्रतिबंध (*Limitations on the functions of the United Nations*) — निम्नलिखित व्यवस्थाओं के द्वारा चार्टर में संयुक्त राष्ट्र सच के कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिये गये हैं —

१—संयुक्त राष्ट्र सच किसी भी ऐसे विषय पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता जो कोई किसी राज्य के घरेलू क्षेत्राधिकार के भीतर आता है, परन्तु यह सिद्धान्त प्रवर्तन के उपायों पर लागू नहीं होता जो अध्याय में ७ उपबन्धित है। (अनुच्छेद २, पैराग्राफ ७)

२—वर्तमान चार्टर के अनुसार वैयक्तिक या सामूहिक आत्मसुरक्षा का अधिकार उस समय तक बना रहता है जब तक कि सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं कर लेती। (अनुच्छेद ५१)

३—वर्तमान चार्टर में दूसरे विश्वयुद्ध के ऐसे देशों व शत्रुओं, जो कि चार्टर पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, के विरुद्ध कार्यवाही करने से नहीं रोकता। (अनुच्छेद १०७)

### ३ सचिवालय (The Secretariat)

सचिवालय सामान्यतः लीग के सचिवालय का प्रतिरूप है। चार्टर में सचिवालय को अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि इसे सौंपे गये कार्य के सम्पूर्ण सम्पादन पर सच का निर्विघ्न रूप से कार्य करना बहुत अर्थों में आश्रित है। सचिवालय में एक महासचिव तथा ऐसे कार्यकर्तागण सम्मिलित हैं जिसे सच अपेक्षित करे। महासचिव (*Secretary General*) सच का प्रमुख अधिशासी पदाधिकारी है और साधारण सभा द्वारा सुरक्षा परिषद् की संसृति पर नियुक्त किया जाता है। महासचिव उस रूप में साधारण सभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् तथा न्याय परिषद् के सभी अधिवेशनों में कार्य करता है। वह सच के कार्यों के विषय में साधारण सभा को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्ताव करता है। इसके अतिरिक्त उसे यह भी प्राधिकृत दिया गया है कि वह सुरक्षा परिषद् का ध्यान किसी भी ऐसे विषय की ओर आकर्षित करे जिससे उसकी सम्मति में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना में बाधा पड़ती हो। चार्टर के

अनुच्छेद १०० में यह व्यवस्था दी गई है कि सचिवालय, का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप की प्रतिभूति के लिये महासचिव तथा कर्मचारीगण अपने-अपने कर्तव्यों के पालन में सध से बाह्य किसी सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी से अनुदेश न तो माँगे और न प्राप्त करेंगे। अनुच्छेद ६७ में यह व्यवस्था की गई है कि महासचिव साधारण सभा द्वारा सुरक्षा परिषद् की सत्सुति पर नियुक्त किया जायेगा जो सात (और अनुच्छेद २७ के सशोधन के पश्चात्, नौ) सदस्यों के स्वीकारसूचक मतदान द्वारा होगा जिसमें परिषद् के स्थायी सदस्यों के सहमतिसूचक मतदान भी सम्मिलित हैं।

कर्मचारीगण महासचिव द्वारा साधारण सभा द्वारा स्थापित नियमावली के अन्तर्गत नियुक्त किये जाते हैं किन्तु सबसे विशेष ध्यान जो कर्मचारीगण को नियुक्ति में रक्खा जाता है वह उत्कृष्ट कुशलता, योग्यता तथा सत्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है।

महासचिव तथा सत्र सहायक महासचिव पूर्ण राजनैतिक उन्मुखितियों का उपभोग करने हैं। समुक्त राष्ट्र सघ के पदाधिकारी अपने पदीय क्षमता में कथित अथवा लिखित शब्दों तथा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में वैध प्रक्रिया से उन्मुखित हैं। वे उनको राष्ट्र सघ द्वारा दिये गये वेतनों तथा उपलब्धियों पर कर देने से मुक्त है।

#### ४. न्यास-परिषद् (Trusteeship Council)

न्यास परिषद् के अधीन न्यास क्षेत्रों की विवेचना अन्य स्थान में एक दूसरे अध्याय में पूर्ण रूप से की गई है और यहाँ पर इसी क्रम में प्रसंग में कुछ बतलाने की आवश्यकता है।

समुक्त राष्ट्र सघ ने अपने प्राधिकार के अधीन एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यास-पद्धति ऐसे प्रदेशों के अधिशासन तथा निरीक्षण के लिए स्थापित की है जो इसके अधीन उत्तरवर्ती वैयक्तिक स्वीकार-पत्रों द्वारा रखे जायें। न्यास-पद्धति निम्नलिखित प्रदेशों पर लागू है जो उसके अधीन न्यास स्वीकृतियों द्वारा रखी जा सकती हैं।

(१) प्रदेश जो इस समय आदेश के अधीन रखे गये हैं।

(२) प्रदेश जो द्वितीय विश्वयुद्ध के परिणामस्वरूप क्षत्र-राष्ट्रों से पृथक् किये जायें, तथा

(३) प्रदेश जो उन राष्ट्रों द्वारा जो उनके अधिशासन के लिये उत्तरदायी हैं स्वच्छा से उस पद्धति के अधीन रखे गये हों।

न्यास-पद्धति (Trusteeship System) के आधारभूत लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को अग्रसर करना, न्यास क्षेत्रों के निवासियों की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी उन्नति को बढ़ाना, उनका स्वराज्य अथवा



उनकी स्वतन्त्रता की ओर क्रमशः विकाम करना तथा मानवीय अधिकारों के लिये ओर जाति, लिंग, भाषा अथवा धर्म के भेद-भाव को मिटाकर सबके निमित्त मौलिक स्वतन्त्रताओं के लिये सम्मान का प्रोत्साहन करना तथा सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक विषयों में समुक्त राष्ट्र सघ के सब सदस्यों और उनके राष्ट्रीय जनता के लिये समानता का व्यवहार निश्चित करना है।

न्यास क्षेत्रों का निरीक्षण तथा अधिशासन न्यास परिपद (ट्रस्टीशिप कौंसिल) के हाथ में है। इस परिपद में न्यास क्षेत्रों को अधिशासन करने वाले सदस्य, सुरक्षा परिपद के स्थायी सदस्य तथा समुक्त राष्ट्र सघ के सदस्य होते हैं जो माधारण सभा द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की सख्या न्यास क्षेत्रों को अधिशासन करने वाले परिपद के सदस्यों की सख्या के समान न्यास क्षेत्रों को अधिशासन न करने वाले सुरक्षा परिपद के स्थायी सदस्यों की सख्या को घटाकर होगी।

शक्तियाँ तथा कार्य (Powers and Functions) :—सामान्य सभा के प्राधिकार के अधीन न्यास परिपद की शक्तियाँ तथा कृत्य अधिशासन करने वाले प्राधिकारियों द्वारा आवेदित प्रतिवेदनो पर विचार करना अधिशासन करने वाले प्राधिकारियों की सम्मति के साथ प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत करना तथा उनका परीक्षण करना, न्यास स्वीकार-पत्रों की शर्तों के अनुसार अलग-अलग न्यास क्षेत्रों के निश्चित अवधि के निरीक्षण के लिये व्यवस्था करना तथा उनको और अन्य कार्यों को करना है। इसका यह भी कार्य है कि प्रत्येक न्यास क्षेत्र के देशवासियों की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा सबधी उन्नति पर एक प्रश्नावली तैयार करे, तथा ऐसी प्रश्नावली अधिशासन करने वाले प्राधिकारी द्वारा साधारण सभा को दिये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन का आधार ग्रहण करेगी।

सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र :—न्यास स्वीकारपत्र में न्यास क्षेत्रों के भागों को सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के नाम से प्रतिष्ठित किया जा सकता है। सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सबध में समुक्त राष्ट्र सघ के सब कृत्य सुरक्षा परिपद द्वारा किये जाते हैं, जिनमें न्यास स्वीकारपत्रों के शर्तों की स्वीकृति तथा उनका परिवर्तन तथा सशोधन भी सम्मिलित हैं। सुरक्षा परिपद सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सबध में सुरक्षा सम्बन्धी विचारों को बिना हानि पहुँचाये न्यास परिपद की सहायता का लाभ समुक्त राष्ट्र सघ के न्यास-नदति के अधीन राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा सबधी विषयों के सबध में उठा सकती है।

दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का प्रश्न .—केवल एक प्रसंग को छोड़कर अन्य सभी राज्य क्षेत्र जो कि लोग आफ नेशन के समावेश के अन्तर्गत थे या ता स्वतन्त्र राज्य बन चुके हैं या अन्तर्राष्ट्रीय न्याय पद्धति व अन्तर्गत भा चुके हैं । अपवाद केवल पूर्व जर्मन उपनिवेश अर्थात् दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका का है ।

१९४६ में दक्षिण अफ्रीका व प्रतिनिधि ने साधारण सभा के अन्तर्गत कहा था कि दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका बहुत ही घना आबाद है और अपनी व्यवस्था अपने आप न कर सकने के कारण राज्य क्षेत्र के बहुमत के निवासी दक्षिण-अफ्रीका सच राज्य में सम्मिलित होना चाहते हैं ।

१९४७-४८ में साधारण सभा ने यह सिफारिश की कि दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका न्याय पद्धति के अन्तर्गत भा जाय ।

१९४९ में सुरभा परिषद् ने साधारण सभा का विज्ञप्ति दी कि सच सरकार दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के प्रशासन के संबंध में अब कोई प्रतिबन्धन देने का तैयार नहीं है । १९४९ में ही Reverend Michael Scott ने यह कहा कि जब तक दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के हेरेरो और बर्ग-डमारा जातियों (Herero and Berg-Damara tribes) से न पूछ लिया जाय दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता ।

१९५० में न्यायालय की सम्मति (Court's opinion in 1950)—महासभा ने १९४९ में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के प्रश्न पर परामर्शात्मक सम्मति की माँग की । जुलाई ११, १९५०, को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपनी परामर्शात्मक सम्मति प्रस्तुत की, जिसमें न्यायालय ने सर्वसम्मति से यह प्रस्थापित किया कि दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका दिसम्बर १७, १९२० के दक्षिण अफ्रीका के संघ (Union of South Africa) की मान्यता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय परमादेश के अधीनस्थ एक क्षेत्र है । न्यायालय का इसके आगे निष्कर्ष था कि उन्मुखित संघ राष्ट्रों की लीग के कन्वेंट और मैन्डेट के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय आचारों से युक्त बना हुआ है, जिसमें क्षेत्र से पेट्रीशन अप्रसरित करने का आचार भा सम्मिलित है, और यह कि चार्टर के अध्याय १२ के उपबन्ध उस पर इस अर्थ में लागू हैं कि उन्होंने एक ऐसा साधन प्रस्तुत किया है जिससे कि यह क्षेत्र न्यायित क्षेत्र व्यवस्था के अन्तर्गत लाया जा सकता है । फिर भी न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि चार्टर ने अफ्रीकी संघ सरकार के ऊपर इस बात के लिए कोई वैध आचार आरोपित नहीं की है कि वह क्षेत्र को न्यायित व्यवस्था के अन्तर्गत सौंप दे । इतना होते हुए भी न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि कथित संघ सरकार एकान्तिक रूप से कार्य करते हुए, क्षेत्र के अन्तर्राष्ट्रीय अस्तित्व को रूपभेदित करने में सक्षम नहीं है । संघ-

३२० ]

सरकार में ऐसी क्षमता अभी आ सकती है जब कि वह संयुक्त राष्ट्र की सहमति में कार्य करे।

अपने १९५० के सत्र में, महासभा ने पुनः सकल्प पारित किया कि क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को रूपभूदित करने का सामान्य ढंग न्यासित-करार (trusteeship agreement) ही हो सकेगा, जो कि चार्टर के अध्याय १२ के उपबन्धों के अनुकूल है। सभा ने एक समिति का भी गठन किया जो कि सघ-सरकार के क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में न्यायालय की परामर्शात्मक सम्मति के प्रक्रियात्मक प्रसंगों में मार्ग दर्शन करे। समिति को एक अन्तरिम व्यवस्था के रूप में प्राधिकृत किया गया था कि वह किसी ऐसे प्रतिवेदन का परीक्षण करे जो कि सघ-सरकार द्वारा क्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाय, तथा पेट्रीशनो और ऐसे किन्हीं भी प्रश्नों का परीक्षण करे जो कि महासचिव को समर्पित किये जाय।

महासभा के आठवें सत्र, १९५३ में दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि ने अपनी सरकार के विचारों को फिर से दुहराया कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की १९५० की सम्मति केवल विशुद्ध रूप में परामर्शात्मक (purely advisory) थी और उसका वही प्रभाव नहीं है जो कि विधि-न्यायालय के निर्णय का हुआ करता है। उनका कथन था कि अफ्रीकी सघ-सरकार पूर्ववर्ती भिन्न शक्तियों से समझौता बार्ता करने को प्रस्तुत है, किन्तु वह संयुक्त राष्ट्र सघ के साथ ऐसा समझौता करने को प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि उनका कथन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में डेटे बरार का पक्षकार नहीं था। बाद-विवाद के प्रसंग में प्रतिनिधियों के बहुमत ने इस बात का दावा किया कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सम्मति से असह-मति न्यायोचित नहीं है, और कई प्रतिनिधियों का यह विचार था कि अफ्रीकी सघ न वस्तुतः क्षेत्र को एक पाँचवें प्रान्त के रूप में निगमित कर लिया है।

चौथी समिति के बाद-विवाद के उपरान्त महासभा ने फिर से दक्षिण अफ्रीका सघ में गम्भीर भयोल की, कि वह क्षेत्र की स्थिति के सम्बन्ध में फिर से विचार करने और उसे संयुक्त राष्ट्रों की न्यासित व्यवस्था के अधीनस्थ कर दे। सभा ने एक नई सान सदस्यीय समिति दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के प्रसंग में गठित की, जिसके दायित्व में डेटे व्यवस्था की प्रक्रियाओं का परीक्षण करने का काम दिया गया और यह भी निर्धारित किया गया कि इस परीक्षण के उपरान्त सभा को क्षेत्र की परिस्थितियों के सम्बन्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करे तथा प्रतिवेदनों और पेट्रीशनो के परीक्षण की प्रक्रिया भी तैयार करे। अन्तिम रूप में, समिति को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया कि यह संघ सरकार से इस प्रसंग में बार्ता जारी रखे कि

१९५० की वह सम्मति जिसे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दी थी, पूर्णतः व्यवहृत कर ली जाय। एक दूसरे सक्ल ने सभा के पूर्ववर्ती संवलों पर यहाँ तक बल दिया कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को ही चार्टर के अध्याय १२ के अनुसार न्यसित व्यवस्था के अधीन कर दिया जाय।

दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के प्रश्न पर गठित नई समिति ने महासभा के नवे सत्र में अपने प्रयत्नों का पुनर्विलाकन इस प्रकार किया—(१) दक्षिण अफ्रीका सच से वार्ता जारी रखना जिससे कि क्षेत्र की स्थिति के प्रश्न का सुलभाय अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सम्मति के अनुसार किया जा सके, (२) सच सरकार द्वारा परमादेशित क्षेत्र के सम्बन्ध में धार्मिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कराना, प्रतिवेदनो के परीक्षण में समिति को सहयोग दिलाना; और (३) दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में मूल निवासियों के पेट्रीशनो को सच सरकार द्वारा अग्रसरित कराना तथा उनके परीक्षणो में समिति को सहयोग दिलाना। समिति ने प्रतिवेदन किया कि उसके यह सभी प्रयत्न विफल हो गये। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने समिति को यह सूचना दी थी कि उसे इस बात में सन्देह है कि समिति को सन्दर्भित किये गये क्षेत्र के अन्तर्गत की जाने वाली नई वार्ताओं से कोई ठोस परिणाम निबल सकेगा और उसने प्रतिवेदन तथा पेट्रीशन प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि ने इस विचार पर बल दिया कि चूँकि राष्ट्रों की लीग का मेम्बेट सुप्त हो चुका है, अतः दक्षिण अफ्रीका के ऊपर इस बात का कोई बंध आभार नहीं है कि वह इन क्षेत्र के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रों से सम्झौता-वार्ता करे।

महासभा ने अपने दसवे सत्र में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर गठित अपनी समिति के एक दूसरे प्रतिवेदन पर विचार किया, जिसमें यह कहा गया था कि देशी निवासियों के कल्याण के सम्बन्ध में उस क्षेत्र में कोई भी प्रगति नहीं हुई है; और यह कि जातिगत विभेद ( Racial Discrimination ) प्रखर रूप में प्रचलित है; और यह कि प्रशासन के मुख्य प्रयत्न इस दिशा में हैं कि यूरोपीय निवासियों के पक्ष का ही एकान्तिक रूप से समर्थन किया जाय। सभा ने अपनी समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किया और इस स्वीकृति में केवल दक्षिण अफ्रीका ही अकेला प्रतिनिधि था जिसने असहमति सूचक मतदान किया। सभा ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की उस परामर्शात्मक सम्मति का भी अनुमोदन किया जो कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में मतदान की प्रक्रिया उपबन्धित करती थी और इस बात को पुष्ट किया कि दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के सम्बन्ध में गठित की गई समिति को पेट्रीशन-कर्ताओं के प्रति मौखिक सुनवाई स्वीकृत करने का स्वत्व है।

३२२ ]

अन्तिम रूप में, दक्षिण-अफ्रीकी सरकार ने दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रों की मदमावना समिति (United Nations Good Offices Committee on South-West Africa) को इस बात के लिये प्रार्थन किया कि वह जून १२, १९५८ से आरम्भ होने वाली वार्ता में प्रिटोरिया जाय। त्रि-मदस्थीय समिति ने इस आग्रह को स्वीकार किया। ब्रिटेन, आर्जेन्टीना और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनयिक प्रतिनिधियों ने समिति गठित की, यही समिति महासभा द्वारा इसके पूर्व भी गठित की गई थी।

दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका की स्थिति, जो कि १९२० के लीग ऑफ नेशन्स मैन्डेट के द्वारा संघ-प्रशासन के अधीन थी, १९४६ में लीग के विघटन के बाद से ही संघ (Union) और संयुक्त राष्ट्रों के बीच विचार-वैपश्य के लिये एक विषय बनी हुई है।

सभा या वह सकल्प जिसमें कि एक समझौता का आधार तैयार करने का उपबन्ध था, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका से क्षेत्र की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में अब भी एक समझौता वार्ता का विषय बना रहा और सभा ने समिति को आदेश दिया कि वह सभा के अगले सत्र में अपने प्रयत्नों की प्रगति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

संयुक्त राष्ट्र की दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका-समिति (U. N.'s South-West Africa Committee) के सभापति श्री विक्टोरिया कारपियो (Victoria Carpio) ने इस बात का तर्क प्रस्तुत किया कि परमादेशित क्षेत्र से दक्षिण अफ्रीका के प्रभुत्व को हटाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ बल का प्रयोग करे। दशान्दियों से, दक्षिण अफ्रीका के गौरांग प्रशासकों ने दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका को अवैध रूप से अपने कब्जे में कर रखा है और कई वर्षों से संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात का गम्भीर प्रयत्न करता चला आ रहा है कि वे विश्व सब के निर्णय से अपने को बाधित कर लें। निरन्तर विफलताओं के उपरान्त मई १९६२, में समिति ने दक्षिण अफ्रीका से जाकर वस्तुस्थिति के अवलोकन करने की अनुमति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इस वस्तुस्थिति के परिज्ञान से भी दक्षिणी अफ्रीका पर कोई प्रभाव न पड़ा। अब समिति को अपने दूसरे कदम के सम्बन्ध में विचार करना था। श्री कारपियो ने यह सुझाव दिया कि दक्षिण-पश्चिम-अफ्रीका के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का संवत्स वार्षिक उसी स्थिति में कार्यवाही हो सकेगा जब कि दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र संघ की सैन्य शक्ति उपस्थित रहे। किसी प्रश्न के सुलभाव के प्रति किये गये शान्तिपूर्ण प्रयत्न शास्वत् नहीं हो सकते और अवश्य ही किसी प्रश्न के सुलभाव के लिये समय की कोई अवधि निर्धारित

होनी चाहिये जिससे कि उस अवधि के भीतर मुलभाव न किया गया तो न्याय को व्यवस्था स्थापित करने के लिये अन्यथा उपाय भी काम में लाये जा सके । भारत द्वारा गोघा की विमुक्ति के सम्बन्ध में की गई सैनिक कार्यवाही इस बात के लिये प्रबलतम दृष्टान्त है ।

दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने १२ जून १९५८, को संयुक्त राष्ट्र सच को सद्भावना समिति से यह प्रार्थना किया कि वह प्रिटोरिया में बातचीत के लिये जाय । ब्रिटेन, ग्राजील और अमेरिका के राज्य प्रतिनिधियों की समिति साधारण सभा द्वारा बनाई गई ।

यूथोपिया और लाइबेरिया का मामला :—नवम्बर ४, १९६० को यूथोपिया और लाइबेरिया ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का अन्य बातों के साथ यह भी घोषित करने के लिए कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने समादेश की शर्तों को दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के सम्बन्ध में हेर-फेर कर लिया और इसलिये उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि वहाँ प्रचलित जातीय पृथक्वासन (apartheid) को मिटाने की कार्यवाही करे । दक्षिण अफ्रीका ने तर्क किया कि यूथोपिया और लाइबेरिया को यह अधिकार नहीं है कि वह दक्षिण पश्चिम सच का मामला राष्ट्र सच के सामने ले आवे । वास्तविकता यह है कि लीग की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्र-सच ने दक्षिण अफ्रीका के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था कि दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका को उससे साथ मिला दिया जाय । इसीलिये दक्षिण अफ्रीका ने न्यायिता का ममकीता मानने से इन्कार कर दिया । २१ दिसम्बर १९६२, को न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीका की इस आपत्ति को अस्वीकार कर दिया कि सम्बन्धित विषय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है । कानून की दृष्टि से इसने यह भी निर्णय किया कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में ऊपर दक्षिण अफ्रीका का समादेश एक अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्ध है जो कि सन्धि या अभिमत के रूप में है ।

१८ जुलाई, १९६६ को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने एक वोट से छ वर्ष पुराने विवाद को और दक्षिण अफ्रीका के पड़ोसी दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के नियंत्रण को समाप्त करने का सकल्प विधित कर दिया । न्यायालय ने अष्टवश, ऑस्ट्रेलिया के सर पर्सि स्पेण्डर (Sir Percy Spender) (न्यायालय के अन्य १४ सदस्यों में ७-७ का मतदान रहा) ने निर्णायक वोट द्वारा यह व्यवस्था दी कि यूथोपिया और लाइबेरिया ने ऐस वैध अधिकार का प्रस्थापित नहीं किया है जिससे कि वे लीग भाव नग्नता में उस भेद के तोड़े जाने के सम्बन्ध में वाद उपस्थित कर सकें, जिसके अन्तर्गत रहकर दक्षिण अफ्रीका ने गौराग प्रशासक क्षेत्र का प्रशासन करें । इस निर्णय के द्वारा, जो कि इस प्राविधिकता पर निर्भर करता है कि न तो यूथोपिया,

और न लाइबेरिया को ही इस बात का वैध अधिकार था कि वे न्यायालय में दक्षिण अफ्रीका के प्रशासन के विरुद्ध दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका पर लीग-ऑफ नेशन्स सैनिकों के अन्तर्गत शिवायत कर सकें, परिणाम यह हुआ कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या अब भी दक्षिण अफ्रीकियों के औपनिवेशिक और जातीय भेदभाव की शिकार बनी रहेगी।

## ५ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्

(The Economic and Social Council)

अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा केवल संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा लगाये गये कर्तव्यों के सत्यनिष्ठापूर्वक पालन पर ही नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य सम्बन्धित विषयों के सफलतापूर्वक संचालन पर भी आश्रित है। इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र सभ ने सामान्य सभा के प्राधिकार में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् स्थापित की है। इस परिषद् में संयुक्त राष्ट्र सभ के १८ सदस्य होते थे किन्तु अब २७ सदस्य होते हैं। इनके चुनाव की प्रक्रिया और अवधि का उल्लेख आगे किया जा रहा है।

कार्य तथा शक्तियाँ.—अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग के क्षेत्र में आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् संयुक्त राष्ट्र सभ का प्रमुख अंग है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के कार्य निम्नलिखित हैं.—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य तथा अन्य सम्बन्धित विषयों का अध्ययन करना अथवा प्रारम्भ करना तथा किसी विषय के सम्बन्ध में साधारण सभा से, संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों से तथा सम्बन्धित विशिष्ट अभिवृत्तियों से सिकांरिश करना, (२) सब के लिए मानवीय अधिकारों तथा साधारणतः स्वतन्त्रताओं के प्रति आदर की भावना बढ़ाने तथा उन पर आचरण करने के लिये सिकांरिश करना, (३) इसकी क्षमता के भीतर आगे वाले विषयों के सम्बन्ध में साधारण सभा को आवेदन करने के लिये प्रतिज्ञापत्रों की रूप-रखा तैयार करना, और (४) इसकी क्षमता के भीतर आगे वाले विषयों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना।

आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् की विशिष्ट अभिवृत्तियों के कार्यों के एकीकरण का कार्य, उनके सम्बन्ध में परामर्श देकर तथा सिकांरिश करने तथा साधारण सभा को और संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों को प्रतिवेदन करने के लिये सीता गया है। परिषद् विशिष्ट अभिवृत्तियों से नियमित प्रतिवेदनों को प्राप्त करे

के लिये उपयुक्त उपाय कर सकती है और इन प्रतिवेदनो पर अपने विचारो को साधारण सभा का सूचित कर सकती है । इसे सुरक्षा परिषद् को, उसके प्रार्थना पर सहायता भी करनी पड़ती है । इसे प्राथिक तथा सामाजिक क्षेत्र में मानवीय अधिकारो की उन्नति के लिये आयोगो को नियुक्त करनी पड़ती है । प्रादेशिक प्राथिक आयोग भी होते हैं जो विशिष्ट क्षेत्रो में विशिष्ट समस्याओ को हल करते हैं ।

**प्रादेशिक तथा सुरक्षा-प्रबन्ध (Regional and Security Arrangements)**—लीग आफ नेशन्स का प्रतिज्ञा पत्र अन्तर्राष्ट्रीय अभियुक्तियों की वैधता को प्रभावित नहीं करता था, उदाहरणार्थ शान्ति स्थापना के लिये पचासवीं संधियाँ अथवा प्रादेशिक सम्झौते, जैसे मुनरो-सिद्धान्त । संयुक्त राष्ट्र सभ का चार्टर भी प्रादेशिक प्रबन्धको के सम्बन्ध में इसी प्रकार की व्यवस्था करता है । अनुच्छेद ५२ (१) में यह अनुबन्धित है कि :—

“वर्तमान चार्टर में कोई विषय प्रादेशिक प्रबन्धो तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापन सम्बन्धो ऐसे विषयो से व्यवहार करने वाले अभिकर्तृत्वो को नहीं रोकती है जो प्रादेशिक कार्यक्षेत्रो के लिये उपयुक्त हैं, किन्तु अनुबन्ध यह है कि ऐसे प्रबन्ध अथवा अभिकर्तृत्व तथा उनके कार्य संयुक्त राष्ट्र सभ के उद्देश्य तथा सिद्धान्तो के अनुरूप हों ।”

प्रादेशिक प्रबन्ध-संधियों का स्वरूप प्रादेशिक है । “प्रादेशिक अभिकर्तृत्व” शब्द से ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकर्तृत्व व्यक्त होते हैं जो प्रादेशिक प्रबन्ध द्वारा स्थापित किये गये हों ।

संयुक्त राष्ट्र सभ का चार्टर, प्रादेशिक प्रबन्धो अथवा अभिकर्तृत्वो पर, स्थानीय झगडों का, उनके सुरक्षा परिषद् में निर्देशित होने के पूर्व शान्तिपूर्वक सम्झौता कराने का कार्य सौंपता है । प्रादेशिक प्रबन्ध अथवा अभिकर्तृत्व प्रवर्तक कार्य में भी संयुक्त राष्ट्र सभ व अंग के रूप में भी कार्य कर सकते हैं क्योंकि सुरक्षा परिषद् को ऐसे प्रादेशिक प्रबन्धो अथवा अभिकर्तृत्वो को अपने प्राधिकार के अधीन उपभोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया है । सुरक्षा परिषद् को सर्वदा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापनार्थ जो जो कार्य किये जाय अथवा जो प्रादेशिक प्रबन्धो अथवा अभिकर्तृत्वो के अन्तर्गत विचाराधीन हों उनसे अवगत रखा जाता है ।

**अफ्रीका में राजनीतिक जागृति**—पिछले समयों में अफ्रीका में बहुत ही राजनीतिक परिवर्तन हुये हैं । १९४६ में ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम ने अफ्रीका के सम्बन्ध में अपने समादेश को संयुक्त राष्ट्र सभ की न्यासिता पद्धति के अन्तर्गत कर दिया । परिणाम यह हुआ कि पहले के समादेशित राज्य तांगान्या, कैमरून,



तोगोलैंड और रुवान्डा-उरुंडी न्यास क्षेत्र माने गये जो कि उन्ही समादेशक शक्ति के अन्तर्गत थे। दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका इसमें सम्मिलित न किया जा सका।

लीबिया के संयुक्त राज्य ने १९५१ में अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी। १९५२ में इरीट्रीया यूयोपिया से मिल गया। १९५६ में सुडान स्वतन्त्र गणतन्त्र हो गया। १९५६ में मोरोक्को ने फ्रांस से समझौता करके सम्प्रभुता प्राप्त कर ली और भागे चलकर १९५८ में स्पेन से भी स्वतन्त्र हो गया। १९५६ में टुनीशिया भी स्वतन्त्र हुआ। १९५७ में पश्चिम अफ्रीका में गोल्डकोस्ट घाना नाम से स्वतन्त्र हो गया और नीग्रो राज्य की स्थापना हुई। १९६० में घाना ने अपने आपको घामनबेस्य के अन्तर्गत गणतन्त्र घोषित किया। १९६० और १९६१ में क्रमशः नाइजीरिया और सियरालियोन स्वतन्त्र हो गये। इस प्रकार बड़ी ही तीव्र गति से वहाँ राजनीतिक परिवर्तन उपस्थित हुये हैं। १९६० में काँगो भी स्वतन्त्र हो गया और कासाबुबु (M. Kasavubu) वहाँ के राष्ट्रपति तथा लुमुम्बा (M. Patrice Lumumba) प्रधान मंत्री हुये। इन दोनों पदाधिकारियों का चुनाव जनतांत्रिक प्रणाली पर बेलजियन प्रशासकों की देखरेख में हुआ था। कटंगा प्रान्त में थाये (M. Tshombe) ने संयुक्त काँगो के विरुद्ध एक क्रांति खड़ी कर दी। कटंगा घानुमो से भरा-पुरा एक प्रान्त है जिसको बेलजियम काँगोलियों के हाथ नहीं देना चाहते थे। रूस, चीन और जेकोस्लो-वाकिया की सरकारों ने लुमुम्बा की सरकार की सहायता की जब कि पश्चिमी शक्तियों ने बेलजियम को काँगो वापस आने में सहायता दी। पैट्रिस लुमुम्बा गिरफ्तार कर लिये गये और १३ फरवरी, १९६१ को यह घोषणा की गई कि लुमुम्बा और उनके दो साथी मार डाले गये हैं। यह घोषणा थाये (Tshombe) की सरकार द्वारा की गई थी।

२२ फरवरी १९६१ को सुरक्षा परिषद् ने इन कृत्यों की भर्त्सना का प्रस्ताव पारित किया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को, यदि आवश्यकता पड़े तो सैन्य-शक्ति द्वारा भी परिस्थिति को काबू में लाने का प्रस्ताव किया। यहाँ संयुक्त राष्ट्र की ओर से भेजी गई सेना में भारत की ओर से ५००० सैनिक भी भेजे गये थे।

२५ नवम्बर, १९६५ को कांगोली सेना के कमाण्डर जेनरल जोसेफ मोबेतु ने प्रेसिडेंट कासाबुबु को रक्तहीन सैन्य-क्रान्ति में अपदस्थ कर दिया और अपने-आप के निदेशन में सैनिक-सरकार का गठन किया। बर्नस लिमोनार्ड मुलाम्बा को श्री बिंबा में स्पान पर प्रधान मंत्री घोषित किया गया। श्री बिंबा दस दिन पूर्व ही प्रेसिडेंट कासाबुबु द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नाम-निर्देशित किये गये थे। इस अवसर पर १३ सूत्रीय उद्घोषणा में कहा गया कि उच्चस्तरीय सैन्य पदाधिकारियों की बैठक ने इस कारण से कासाबुबु सरकार को धादम्य कर देने का निश्चय लिया

कि वह राजनीतिक क्षेत्र में पूर्णतः अस्पर्धन हो गई है और 'मिस्टर किवा की सरकार की प्रभुता' को दृष्टि में रखते हुये भी यह कदम आवश्यक हो गया था। जेनरल मोघुतु, जो कि अब राष्ट्रपति मोघुतु हो गये थे, ने घोषणा की, कि विद्रोही नेताओं से कोई संपर्क नहीं रखा जायेगा और यह कि संपर्क उस समय तक जारी रहेगा, जब तक कि विद्रोह सैन्य साधनों से पूर्णतया दबा नहीं दिया जाता। सैन्य अवरोहण के पश्चात् प्रेसिडेण्ट कासाबुबु और पूर्ववर्ती बटागा नेता मोयसे थांम्बे व बीच घोर संपर्क हुआ। थांम्बे अक्टूबर १३, १९६५ को प्रेसिडेण्ट द्वारा वागोली प्रधान मंत्री पद से हटा दिए गये थे। नई सरकार ने कागोली पार्लियामेंट में विश्वास का मत प्राप्त कर लिया और वह मोयसे थांम्बे द्वारा अभिनन्दित हुई। अल्जीरिया, सोवियत रूस और साम्यवादी चीन ने नई सरकार के गठन की भर्त्सना की, किन्तु पश्चिमी देशों ने सामान्य रूप से इस सरकार का स्वागत किया।

रुआण्डा-उरुण्डी, जो कि एक न्यास-क्षेत्र था और जिसपर बेल्जियम का प्रशासन था, जनवरी १९६१ में गणतन्त्र हुआ गया और यद्यपि बेल्जियम ने रुआण्डा-उरुण्डी के गणतन्त्र को मान्यता प्रदान करने के निश्चय की घोषणा की, फिर भी, ऐम्बो एसियन राष्ट्र कांग्रेस के प्रसङ्ग में उसके द्वारा किये गये कार्यों को देखते हुये उसके आशय पर विश्वसित नहीं थे। बेल्जियन प्रशासित रुआण्डा-उरुण्डी का क्षेत्र जुलाई १, १९६२ का स्वतन्त्र हुआ और उसी समय से उसका दो भाग हो गये—रुआण्डा गणतन्त्र और बुरुण्डी साम्राज्य। फिर भी, बेल्जियन सेनाओं को दो कन्द्रीय अफ्रीकी राज्यों से वापस बुलाये जान का प्रश्न कठिनाइयों से मुक्त नहीं रहा।

पूर्वी अफ्रीका में, इटली ने अपने न्यास-क्षेत्र सोमालीलैंड को स्वतन्त्रता के लिये तैयार कर लिया और ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सोमालीलैंड को जून १९६० में स्वतन्त्रता प्रदान करने का निश्चय किया जिससे कि वह न्यास-क्षेत्र से संगठित हो सके। अप्रैल १९६० में दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि परस्पर मिले और दोनों क्षेत्रों को मिलाकर संगठित सोमालिया-गणतन्त्र के लिए सहमत हो गये।

वह राजनीतिक जागरण, जिसने कि अफ्रीका के मानचित्र में इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये, अब भी अफ्रीकी औपनिवेशिक क्षेत्रों में तीव्र गति से बढ़ रहा है और इससे और भी परिवर्तन समाचित है। अफ्रीका में जीवन की हँकार गू जने लगी है। वर्ष १९५० के आरम्भ में केवल चार अफ्रीकी राज्य—मिस्र, यूगोपिया, लाइबेरिया और दक्षिण अफ्रीका सच ही स्वतन्त्र थे, जब कि शेष महाद्वीप किसी न-किसी रूप में पश्चिमी युरोपीय शक्तियों के औपनिवेशिक परतन्त्रता में था। अगस्त १९६०, में २० राज्य स्वतन्त्र हो गये थे और १९६०-६१ तक ८ और राज्य स्वतन्त्र होने के लिए तत्पर हो चुके थे। इन परिवर्तनों के कारण बेल्जियम को

अपने एकमात्र अफ्रीकी उपनिवेश कांगो से हटना पड़ा, ब्रिटेन अपने ११,२७,३१६ वर्ग-मील के क्षेत्र से वापस हटा और फ्रान्स के पास अब केवल ८,५५,००० वर्ग-मील का औपनिवेशिक क्षेत्र शेष रहा, जब कि पहले यह क्षेत्र ४०,५५,६०० वर्ग-मील तक फैला हुआ था ।

कुल ६८ वर्षों के निरन्तर ब्रिटिश-संरक्षण के उपरान्त ६ अक्टूबर, १९६२ को उगाण्डा अफ्रीका का ३३वाँ राष्ट्र स्वतन्त्र हुआ । उस तारीख को ब्रिटेन ने उगाण्डा के ऊपर से अपना संरक्षण और आधिपत्य हटाया और अफ्रीका के इन नये राष्ट्रों की स्वतन्त्रता स्वीकार की ।

अफ्रीकी देशों में अल्जीरिया भी एक ऐसा देश था, जहाँ पिछले कई वर्षों तक स्वतन्त्रता का सपना चलता रहा । फ्रान्सीसी निवासी, जो कि अल्जीरिया में जाकर बस गये थे, अब भी अल्जीरिया पर अपना प्रभुत्व बनाये रखना चाहते थे । साम्यवादी देशों तथा अफ्रीका के अधिकांश देशों ने स्वतन्त्र अल्जीरिया की निष्कासित सरकार को, जो कि फरहत-अब्बास ( Ferhat Abbas ) की अध्यक्षता में गठित थी, मान्यता प्रदान की । फिर भी, अल्जीरिया में ७ वर्षों का पुराना युद्ध १८ मार्च, १९६२ को समाप्त हुआ और परिणाम यह था कि फ्रान्सीसी और अल्जीरिया के वार्ता प्रतिनिधियों के बीच एक युद्ध-विराम समझौता हो गया । प्रेसिडेण्ट डी-गोले को पूर्ण शक्ति प्रदान की गई कि वे अल्जीरिया के माध्यम सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर कर सकें । अक्टूबर ८, १९६२, को अल्जीरिया औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता में प्रविष्ट होने की अनुमति प्राप्त कर सका । ब्रिटेन पूर्वी और मध्य अफ्रीका स्थित अपने क्षेत्रों के लिये एक संविधान की क़ार्रेखा तैयार करने का प्रयत्न कर रहा है जिससे कि अफ्रीकी जनता को महत्वाकांक्षामयी और वहाँ जाकर बसने वाले यूरोपीय लोगों की माँगों के बीच संतुलन स्थापित करते हुये दोनों को संतुष्ट किया जा सके । केवल पुर्तगाल ही ऐसा औपनिवेशिक प्रभुत्व का देश है, जो कि निरन्तर युग की पुकार को सुनने से इनकार करता जा रहा है और अपनी उपनिवेशवादी दमन-नीति में किंचित् भी परिवर्तन करने को प्रस्तुत नहीं है । दक्षिण-अफ्रीका संघ की सरकार भी अपनी जातिगत विभेद की नीति को ज्यों का त्यों अपनाती जा रही है और वह भी अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को किसी प्रकार की राजनीतिक या सवैधानिक विमुक्ति देने को तत्पर नहीं है । अंगोला भी जो कि पश्चिमी अफ्रीका में एक पुर्तगाली उपनिवेश है, स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है और इस देश को, जिसे कि कोई भी नहीं जानता था, पुर्तगालियों द्वारा आंगोला जनता पर किये गये अत्याचारों ने अब प्रकाश में ला दिया है । अफ्रीका से यूरोपीय दमनकारी उपनिवेशवाद युग की पुकार के आगे

दुम दबाकर पीछे की ओर भाग रहा है और वह दिन भी अब दूर नहीं है, जब पुर्त-गाली साम्राज्य का वहाँ से समापन हो जायेगा ।

नये स्वतन्त्र होने वाले देशों के कारण व्यापक स्तर पर अफ्रीकी एकता के विचारों को प्रफुटित होने की प्रेरणा मिली है । पूर्वी अफ्रीका में एक पूर्वी-अफ्रीकी संघ (East African Federation) का स्वप्न साकार रूप से चुका है, क्योंकि १९६४ में तागान्यका, जाजीबार, उगाण्डा और केन्या ने मिलकर इस संघ को स्थापित संसार से निवासकर मध्याह्न जगत में एक संघ का रूप प्रदान किया था जो 'तागान्यका और जाजीबार के संयुक्त गणतन्त्र' के नाम से विहित हुआ । न्यासालैंड, जिसे अब मालावी के नाम से जाना जाता है, जून १९६४ में स्वतन्त्र हुआ । पश्चिम की ओर घाना के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री डा० क्वामे नुक्रमाघाना, गायना और माली का एक यूनियन गठित किया । महात्मा के पाँचवें सत्र में ये नव-उत्पन्न राज्य संयुक्त-राष्ट्र संघ के सदस्य के रूप में स्वीकृत हुये । अब इन राज्यों का संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना विशिष्ट महत्त्व और स्थान है । अफ्रीका में होने वाले व्यापक राजनीतिक परिवर्तनों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ का नया बल प्रदान कर दिया है और पूर्वी-पश्चिमी दलों के मध्याह्न में ये देश सबल सुगमभाव का रूप बनते जा रहे हैं ।

ज़ाम्बिया गणतंत्र (Republic of Zambia)—१४, अक्टूबर, १९६४ को उत्तरी रोडेशिया, जिसे अब जाम्बिया के नाम से जाना जाता है, एक स्वतन्त्र संप्रभु राज्य बन गया । इसका नया नामकरण जांबेई नदी के नाम पर किया गया । उत्तरी रोडेशिया जाम्बिया के राज्य का स्वतन्त्र होना ब्रिटिश औपनिवेशिक-विस्तार के टूटने का एक महत्वपूर्ण सोपान है । घाना, नाइजीरिया, सियरा लिओन, तागान्यका, उगाण्डा, जाजीबार (जो कि अब तागान्यका के साथ संगठित है), बर्मा और मालावी के उपरान्त यह नवाँ अधीनस्थ राज्य था जो कि स्वतन्त्र हो गया ।

डा० केनेथ कांडा (Dr. Kenneth Kaunda), जो कि उत्तरी रोडेशिया की स्वतन्त्रता-संग्राम के नेता थे, जाम्बिया के स्वतन्त्र गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति हुये ।

अन्य सभी स्वतन्त्र अफ्रीकी राष्ट्रों की भाँति जाम्बिया एक तटस्थ राष्ट्र है । राष्ट्रपति केनेथ कांडा ने स्वतन्त्र संप्रभुता बनाये रखने के अपने दृढ़ संकल्प की घोषणा की तथा विश्व के उन दो दलों के बन्धन में अपने को बाँध लेने से असहमति व्यक्त की, जिसमें आज का विश्व उथल-पुथल के मायाजाल में पड़ा हुआ है । उनका कथन था कि उनका राष्ट्र एक स्वतन्त्र और तटस्थ राष्ट्र

रहेगा तथा इस बचाव या उस बचाव में सम्मिलित होने के स्थान पर दोनों के बीच एक समुलन बनाये रखने का प्रयत्न करेगा। फिर भी जांबिया का यह भाष्य नहीं है कि परिस्थितियों में वह किसी एक पक्ष का समर्थन करे, भले ही वह शक्ति-राजनीति (power politics) का क्षेत्र हो, या सहायता प्राप्त करने का प्रसंग हो, और यह राष्ट्र किसी भी अन्य राष्ट्र या राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली किसी भी शर्त-रहित सहायताओं को सहर्ष स्वीकार करेगा।

### चार्टर के अनुच्छेदों में संशोधन

संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के कतिपय अनुच्छेदों में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं। इनमें अनुच्छेद २३, अनुच्छेद २७ और अनुच्छेद ६१ का संशोधित रूप अब इस प्रकार है—

#### अनुच्छेद २३

(१) सुरक्षा-परिषद् में संयुक्त राष्ट्रों के पन्द्रह सदस्य<sup>१</sup> होंगे। चीन गणतन्त्र, फ्रांस, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन सभ, ग्रेट ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम और उत्तरी आयरलैंड, और संयुक्त राज्य अमेरिका सुरक्षा-परिषद् के 'स्थायी सदस्य' होंगे। साधारण सभा संयुक्त राष्ट्र के अन्य दस सदस्यों को सुरक्षा-परिषद् के 'स्थायी सदस्यों' के रूप में निर्वाचित करेगी और ऐसा करने में यह सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्रों में अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने के प्रयत्नों को प्रथम रूप में दृष्टि में रखेगी और इसी प्रकार संघ के अन्य प्रयोजनों के हित में और साम्यात्मिक भौगोलिक विभाजन के हित में किये गये कार्यों को ध्यान में रखेगी।

(२) सुरक्षा-परिषद् के 'स्थायी सदस्य' दो वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होंगे। सुरक्षा-परिषद् के सदस्यों की संख्या ११ से बढ़कर १५ हो जाने के बाद होने वाले 'स्थायी सदस्यों' के प्रथम निर्वाचन में चार प्रतिरिक्त सदस्यों में से दो का निर्वाचन एवं वर्ष की अवधि के लिये होगा। निवृत्त होने वाला कोई सदस्य उसके सुरन्त बाद ही पुनर्निर्वाचन के योग्य नहीं होगा।

(३) सुरक्षा-परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।

#### अनुच्छेद २७

(१) सुरक्षा-परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक 'वोट' होगा।

(२) प्रक्रियात्मक मामला (Procedural matters) में सुरक्षा-परिषद् के निर्णय ९ सदस्यों की स्वीकृतिपरम्व प्रसिद्धि पर मान्य होंगे।

१. पहले सुरक्षा-परिषद् के ऐसे सदस्यों की संख्या ११ थी।

(३) सुरक्षा परिषद् के अथवा सभी विषयों पर निर्णय ६ सदस्यों व स्वीकृति सूचक मत से किये जायेंगे जिनमें कि स्थायी सदस्यों की सहमति के मत सम्मिलित होंगे, परंतु अध्याय ६ के और अनुच्छेद ५२ के पैराग्राफ ३ के निर्णयों के अन्तर्गत किसी विवाद का पक्षकार वोट देने में सम्मिलित न होगा ।<sup>१</sup>

### अनुच्छेद ६१

(१) आर्थिक और सामाजिक परिषद् (Economic and Social Council) का गठन संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा द्वारा निर्वाचित २७ सदस्यों से मिल कर किया जायेगा ।

(२) पैराग्राफ ३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये आर्थिक और सामाजिक परिषद् के ६ सदस्य प्रत्येक वर्ष तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होंगे । एक निवृत्त सदस्य अपनी निवृत्ति के ठीक बाद वाले निर्वाचन के लिये पात्रन होगा ।

(३) आर्थिक और सामाजिक परिषद् की सदस्य-संख्या १८ से बढ़कर २७ हो जाने के बाद के प्रथम निर्वाचन में उस वर्ष ६ निवृत्त सदस्यों के स्थान पर ६ अतिरिक्त सदस्यों का निर्वाचन किया जायेगा । इन ६ अतिरिक्त सदस्यों में, दस प्रकार निर्वाचित सदस्यों में से ३ की अवधि १ वर्ष बीतने पर समाप्त हो जायेगी और ३ सदस्यों की अवधि दो वर्ष बाद समाप्त होगी । इस प्रकार का समापन महासभा द्वारा की गई व्यवस्था के अनुरूप होगा ।

(४) आर्थिक और सामाजिक परिषद् के प्रत्येक सदस्य का एक प्रतिनिधि होगा ।

चार्टर का पुनरीक्षण (Revision of the Charter) — चार्टर के अनुच्छेद १०८ में यह अनुमति दी गई है कि साधारण सभा के सदस्यों के दो-तिहाई मतों से जो संयुक्त राष्ट्र सभा के सदस्यों के दो तिहाई मतों से जिसमें सुरक्षा परिषद् के सब स्थायी सदस्य भी सम्मिलित हैं, अनुसमर्थित कर दिया जाय, तो चार्टर का संशोधन हो सकता है । अनुच्छेद १०९ में यह अनुबन्धित है कि चार्टर का पुनरीक्षण के लिये संयुक्त राष्ट्र सभा के सदस्यों का एक साधारण सम्मेलन किसी भी समय में साधारण सभा व सदस्यों के दो तिहाई स्वीकृति-सूचक मतों से तथा सुरक्षा परिषद् के सात सदस्यों के मत से हो सकता है और यदि ऐसा सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव साधारण सभा के दसवें वार्षिक अधिवेशन के पूर्व न हुआ हो तो ऐसा सम्मेलन

१ अनुच्छेद २७ का संशोधित रूप जो कि १७ दिसम्बर, १९६३ को साधारण सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और ३१ अगस्त, १९६५ को प्रवर्तन में आया । इसके पूर्व खंड (२) और (३) में सदस्यों के मतों की संख्या ७ थी ।

बुलाने का प्रस्ताव उस अधिवेशन के कार्यक्रम में रखा जायगा तथा यदि ऐसा साधारण सभा के सदस्यों के बहुमत के तथा सुरक्षा परिषद् के सात सदस्यों के मत से निश्चित किया जाय तो सम्मेलन होगा।

उपरोक्त कथन से यह प्रष्ट होगा कि चार्टर के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में भी स्थायी सदस्यों का बहुत बड़ा हाथ है और पाँच बड़ी शक्तियों में से कोई भी जिसे निषेधाधिकार प्राप्त है, चार्टर के किसी भी उचित संशोधन को रोक सकती है। चार्टर का जन्म सन् १९४५ में सैन फ्रान्सिस्को के सम्मेलन में हुआ तथा उस तिथि पर जो कुछ स्वीकारोक्ति हो सकती थी, उसका कुल निबोड यह प्रकट करता है। परन्तु यह यदि असंभव नहीं तो कठिन घबराहट ही प्रतीत होता है कि किसी सभा में इन बड़ी शक्तियों के सम्बन्ध बहुत धीरे-धीरे सामंजस्य पूर्ण नहीं हो पाये हैं। मतः वर्षों के मध्य चार्टर की कार्यशैली में प्राप्त हुये अनुभव के परिणामस्वरूप जो संशोधन इसमें आवश्यक समझे जाते हैं, उनसे सम्बन्ध में मतभेद हो जाय। यदि संयुक्त राष्ट्र संधि को जीवित तथा स्वस्थ अवस्था में संचालित रखना है तथा इस बात को रोकना है कि यह लीग ऑफ नेशन्स की गति को न प्राप्त कर ले, तो इसका पिछले वर्षों के बालू रहने के अनुभव बहुत ही सहायक मित्र होंगे जिससे वे शीघ्र दूर हो जाय जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संधि को अक्षत-लगड़ा बना दिया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्र सचिव मिस्टर जॉन फील्डर डलेट ने चार्टर को 'पूर्वाणु चार्टर' (pre-atomic Charter) कहा है और यह कि इस भ्रम में यह प्रवर्तन होने के पूर्व ही अप्रचलित था।

निषेधाधिकार तथा बड़े पाँच (Veto and the 'Big Five') :—प्रथम विषय जो विचारणीय है वह यह कि सुरक्षा परिषद् के कार्यक्रम में शक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र संधि में अपने भाग्य को छोटे राष्ट्रों के वोटों के किसी प्रकार अधीनस्थ किये बिना ही सम्मिलित हो सके। निषेधाधिकार का उद्देश्य, जैसा अनुच्छेद २७ के खंड ३ में दिया गया है, बड़ी शक्तियों में एकता की प्रतिभूति करना है। चार्टर के इस अनुबन्ध के बिना न तो संयुक्त राष्ट्र संधि होता और न चार्टर होता। इसमें सन्देह नहीं कि इस विशेष निषेधाधिकार का उपयोग उचित सीमितियों के भीतर रखना चाहिये। इस अधिकार का दुरुपयोग न होना चाहिए। निषेधाधिकार आज मेल के प्रतीक होने के स्थान में संपर्क का प्रतीक हो गया है। रूस तथा पश्चिमी शक्तियों ने अपनी विवेक-शून्य कार्य-प्रणाली से इसका समय-समय पर दुरुपयोग किया है और जेना एम० ऐलबेरेज ने किसी राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र-संधि में प्रवेश करने के लिए सामान्य सभा की क्षमता वाले मामले में (I. C. J. Reports, 1950 pp. 3-4) अपने मतभेद प्रकट करने वाली सम्मति में कहा था, "यह निर्णय

करने का कि प्रत्येक विषय में जिनमें सुरक्षा परिषद् उपार्यों का अयनम्यन कर। तबे विदेश निपेधाधिकार का उपयोग स्वतन्त्रतापूर्वक किया जाय, यह धर्म होगा कि दान्ति तथा सुरक्षा स्थापना के अनिवार्य अन्य विषयों में भी एक बड़ी शक्ति की इच्छा उस परिषद् के अन्य सदस्यों की तथा सामान्य मता की इच्छा की निरर्थक बना दे, तथा उससे समुक्त राष्ट्र सच निश्चय हो जाय ।”

विदेश निपेधाधिकार के प्रतिबन्ध की तेज धार व्यावहारिक प्रयोग में बहुत-कुछ कुठिन कर दी गई है । इनका यह धर्म माना गया है कि जब तक पाँच बड़ी शक्तियों में से कोई भी स्पष्ट रूप से निपेधाधिकार मनवान न करे उस समय तक किसी बड़ी शक्ति द्वारा अलग रहना कोई विशेष निपेधाधिकार का उपयोग नहीं है । इसी प्रकार किसी स्थायी सदस्य की अनुपस्थिति विशेष निपेधाधिकार का उपयोग नहीं मानी जाती । यह सिद्धान्त सबसे प्रथम सन् १९४६ में निर्धारित किया गया जब रूप ने ईरान तथा इंग्लैण्ड के भगडे के बाद विवाद के बीच अपनी अतहमति उठकर चले जाने से प्रदर्शित की और इसके उपरान्त स्त सुरक्षा परिषद् से इस मापार पर अलग हो गया कि उसमें वास्तविक चीन का प्रतिनिधित्व नहीं है ।

विदेश निपेधाधिकार की धार की और अधिक कुठित करने के लिए सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों की चाहिये कि वे कोई ऐसी आचार विधि बना लें जिससे निपेधाधिकार का उपयोग कम से कम हो सके । सबसे अधिक जो वस्तु आवश्यक है वह यह कि मतैक्य पर पहुँचने की इच्छा बिना निपेधाधिकार की उठा देने से समुक्त राष्ट्र सच में जो कुछ भी समुक्तता है वह भी छिन्न-भिन्न हो जायगी । एक दूसरा सुझाव यह है कि मतैक्य नियम अनुच्छेद २७ (३) के स्थान में बहुमत निर्णय के नियम को रख दिया जाय ।

आन्तरिक विषय (Domestic Matters) :—दूसरा विषय जो विचारणीय है वह चार्टर के अनुच्छेद २ के खंड ७ में किसी राज्य के आन्तरिक क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले विषयों के सम्बन्ध में है । यह वाक्य कि किसी एक राज्य के आन्तरिक क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले विषय, सन्देह से मुक्त नहीं हैं, और समुक्त राष्ट्र सच में ऐसे विषयों पर विचार के समय जैसे दक्षिणी अफ्रीका द्वारा व्यवहार की गई भारत-विरोधी नीति, बोरिया का भगडा तथा ब्रिटेन और ईरान का तेल के भगडा आदि पर विचार विमर्श हुआ है । अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय ने Tunis-Morocco Nationality Decrees (P. C. I. J. Series B. No. 4) वाले मामले में इस विषय पर विचार किया और कहा कि “केवल आन्तरिक क्षेत्राधिकार के भीतर” का आशय ऐसे विषयों में प्रतीत होता है जो यद्यपि वे एक से अधिक राज्यों के हितों से अनिष्ट रूप से सम्बन्धित हो



सिद्धान्त में अन्तर्राष्ट्रीय विधि से नियमित नहीं होते। ऐसे विषयों के सम्बन्ध में केवल प्रत्येक राज्य ही निर्णायक हैं। इस खंड के उत्तरवर्ती भाग में निम्न सन्धोघन वाञ्छनीय है जिससे यह पढ़ने में ऐसा हो जाय कि "परन्तु इस सिद्धान्त से अध्याय ७ के अन्तर्गत निराकरण तथा प्रवर्तक कार्यों के लागू किये जाने में तथा उन विषयों में कोई बाधा नहीं पड़ेगी जो अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों के अन्तर्गत हैं और जिनमें मानवीय अधिकारों तथा आधारभूत स्वतन्त्रताओं का पालन तथा उनके लिए सम्मान भी सम्मिलित है।"

चार्टर के अनुच्छेद २ (७) में इस प्रतिबन्ध होने से चार्टर के अनुच्छेद ६ को प्रायः निरर्थक कर दिया है कि कोई सदस्य यदि वह चार्टर के सिद्धान्तों का उल्लंघन करे तो सघ से निष्कासित किया जा सकता है। यदि इस खंड का पुनरीक्षण न किया गया तो संयुक्त राष्ट्र सघ का जलजान जिस पर कि इस अनुच्छेद में आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है, सर्वव्यापकता की चट्टान से टकराकर हूब सकता है।

सदस्यता (Membership).—अनुच्छेद ४ में यह दिया गया है कि कतिपय नियमों के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र सघ की सदस्यता ऐसे सब शांति-प्रिय राज्यों के लिए खुली हुई है जो चार्टर के कर्तव्यों को स्वीकार करें। प्रथम शक्तिशाली होने वाली राजनीति ने सदस्यता को सार्वजनिक बनाये जाने से रोका है। प्रत्येक गुट इस बात पर महत्व देता है कि 'उसी विचार के' देशों का प्रवेश किया जाय तथा विरोधी दल के देशों का प्रवेश का विरोध करता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये अनुच्छेद ४ में यह अनुबन्धित कर दिया जाय कि संयुक्त राष्ट्र सघ की सदस्यता किसी भी ऐसे राज्य के लिये खुली है जो ऐसी सदस्यता के कर्तव्यों को बिना अधिक नियामिका का पालन करने को उद्यत हो। एक कठिनाई उन राज्यों के सम्बन्ध में उत्पन्न होती है, जैसे स्विटजरलैण्ड, जो अध्याय ७ के अन्तर्गत प्रवर्तक उपाय सम्बन्धी कर्तव्यों को अपनी स्थायी तटस्थता को भंग किए बिना स्वीकार करने को उद्यत न हो। अतः चार्टर के अनुच्छेद ४ में और सन्धोघन की आवश्यकता है जिससे ऐस राज्यों को अध्याय ७ के सैनिक अपेक्षण सम्बन्धी कर्तव्यों का पालन किए बिना सघ में सम्मिलित हो सके।

अनिवार्य क्षेत्राधिकार (Compulsory Jurisdiction):—दूसरा सुझाव जो दिया गया है वह न्यायालय को अनिवार्य क्षेत्राधिकार उपयोग करने के लिए सक्षम किए जाने के सम्बन्ध में है। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को युद्ध के बीच में संयुक्त अभिग्रहणों के सम्बन्ध में निर्णय करने वाले नागरिक न्यायालयों के निर्णयों से अपीलें सुनने का क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जाय। इसके अतिरिक्त न्यायान्वय का

व्यवस्थान इस प्रकार सन्तुष्ट कर दिया जाय जिससे न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध अपराधो से आरापित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सके ।

**असदस्य राज्यों का भाग लेना :—**चार्टर के अनुच्छेद ३२ के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि असदस्य राज्य भी सुरक्षा परिषद के उन बहुसा में सम्मिलित हो सकते हैं जिसमें कि वे पक्षकार हैं किन्तु उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं है । चार्टर में यह भी उपरन्वित होना आवश्यक है कि साधारण सभा किसी असदस्य राज्य को सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रित करे जब कि यह किसी ऐसे विषय पर विचार कर रही हो जिसमें कि असदस्य राज्य पक्षकार हो ।

**न्यास-पद्धति (Trusteeship System) :—**अनुच्छेद ७६ (ब) जिसमें न्यास-पद्धति के लिए अनुबन्धित किया गया है स्पष्ट नहीं है । इसमें प्रत्येक प्रदेश को जो आत्म-शासन न कर रहा हो स्वतन्त्रता दिए जाने के लिए एक निश्चित समयावधि की व्यवस्था होनी चाहिए । समयावधि समुक्त राष्ट्र सभ के आयोग द्वारा प्रशासक शक्ति की सहमति के साथ प्रत्येक प्रदेश के विकास का दृष्टि में रखत हुए नियत होनी चाहिए ।

अनुच्छेद ७७ (अ) भी पुनरीक्षित होना चाहिए जिससे पूर्व आदेशित प्रदेश अनिवार्य रूप से न्यास-पद्धति के अधीन रख दिए जाय । यह संशोधन दक्षिणी अफ्रीका द्वारा अपने पूर्व आदेशित प्रदेश दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका को न्यास-पद्धति के अधीन रखने की स्वीकार करने के कारण आवश्यक हो गया है ।

अनुच्छेद ७७ (स) में यह व्यवस्था की गई है कि न्यास-पद्धति उन क्षेत्रों में लागू होगी जो उनकी प्रशासन के लिए उत्तरदायी राज्यों द्वारा स्वेच्छापूर्वक उस पद्धति के अधीन रखे जाय । इस वाक्य खंड के भीतर राज्यों के उपनिवेश भी इस अनुबन्ध के साथ सम्मिलित होना चाहिये कि वे न्यास में स्थानीय लोगों के समुक्त राष्ट्र सभ को प्रार्थना पत्र देने पर सम्मिलित किए जाएं ।

**सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र (Strategic Areas) —**यह समय है जब सामान्य तथा सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण न्यास क्षेत्रों का भेद इस अनुबन्ध के साथ हटा दिया जाय कि अधीनस्थ प्रदेश एवं नियत अवधि में स्वतन्त्रता प्राप्त कर लें । जिसमें वे सब साधारण सभा के निरीक्षण में प्रशासित हो सके, इसके लिए चार्टर के अनुच्छेद ८३ तथा ८५ (१) का संशोधन आवश्यक होगा ।

**प्रादेशिक सुरक्षा (Regional Security) .—**चार्टर के अनुच्छेद ५२ (१) में यह अनुमति दी गयी है कि प्रादेशिक व्यवहार के यथानुरूप अन्तर्राष्ट्रीय

३३६]

शान्ति तथा सुरक्षा स्थापनार्थ सम्बन्धी विषयों को निपटाने के लिए प्रादेशिक प्रबन्ध व्यवस्था अभिकर्तृत्व बनाए जायें, किन्तु अनुबन्ध यह है कि ऐसे प्रबन्ध संयुक्त राष्ट्र संधि के उद्देश्य तथा सिद्धान्तों के अनुरूप हों। ८ सितम्बर १९४४ को दक्षिणी पूर्वी एशिया प्रतिरक्षा संधि (SEATO) की स्थापना उपरांत अनुबन्धों के अनुरूप नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके धर्मपिता सब आशियाई शक्तियाँ हैं अर्थात् वे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड आठ राष्ट्रों में से हैं। यह उपनिवेशीय शक्तियों का एक शक्तिशाली झुंड है जो उन लोगों को सरक्षण देने के उत्सुक हैं जो किसी का सरक्षण नहीं चाहते। इन बातों की व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसी संधियों की जाँच उनका वास्तविक स्वरूप निश्चित करने के लिए की जानी चाहिए।

**अस्पष्टता (Vagueness)** — चार्टर के भिन्न-भिन्न अनुबन्धों में कुछ अस्पष्टता विद्यमान है। सुरक्षा परिषद् तथा साधारण सभा की शक्तियाँ निपुणता से वर्णित नहीं हैं तथा जैसा भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिसम्बर सन् १९४३ में नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय वैध सम्मेलन में व्यक्त किया कि पूरे चार्टर को सरसरी दृष्टि से पढ़ने से भी प्रत्येक मनुष्य के मन में एक अस्पष्ट छाप रह जाती है कि यहाँ एक सत्ता वर्तमान है जो कुछ मतों के एक प्रकार से उपयोग किए जाने पर अन्य की अपेक्षा जातीय हितों को हानि पहुँचा सकती है, यदि वे केवल विशिष्ट जातीय वर्गों के दृष्टिकोण से देखे जायें। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि सदस्य राज्य संयुक्त राष्ट्र संधि को जो-जो शक्तियाँ देने को उत्सुक हों उनको स्पष्टतः घोषित कर दिया जाय।

**प्रक्रिया सम्बन्धी विषय (Procedural Matters)** :— इसके उपरान्त अनुच्छेद २७ में यह निर्दिष्ट है कि 'प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों' तथा 'अन्य संधि विषयों' के सम्बन्धों में सुरक्षा परिषद् का निर्णय प्राप्त करने के लिए मत प्राप्त किए जायें। यह आवश्यक है कि ऐसे प्रक्रिया सम्बन्धी विषय अनुच्छेद २७ में एक व्याख्या का वाक्यसङ्ग भरकर स्पष्टतः परिभाषित कर दिए जायें।

**चीन का प्रतिनिधित्व** — इसके अतिरिक्त चीन के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संधि में अस्पष्टता विद्यमान है। इस समय सुरक्षा परिषद् में चीन का प्रतिनिधि पुरानी सरकार का प्रतिनिधि है जिसका चीन में नाममात्र का भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार अवास्तविकता को रोकने के लिये वही न कही व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। चीन की बढ़ती हुई उग्र आक्रमणवादी नीति को दमते हुये यह और भी आवश्यक हो गया है कि वह राष्ट्रों में कुटुम्ब में नियमित किया जाय।

• भारित मतदान (Weighted Voting) :—इसके अतिरिक्त साधारण सभा के प्रतिनिधि-रूपक स्वरूप को उन्नत करने के लिये कुछ भारनिष्ठ मतदान की पद्धति प्रवर्तित करनी चाहिये जिससे आईसलैंड के १,४१,००० निवासियों को वहाँ वही मतदान का अधिकार न प्राप्त हो जाय जैसा चान के ५२½ करोड़ निवासियों को ।

सुरक्षा-परिपद् में स्थायी स्थानों की वृद्धि :—ग्रन्त में शीतयुद्ध से उत्पन्न हुई तनातनी को कम करने के लिये एशियाई देशों को संयुक्त राष्ट्र सभ में सामान्यतः तथा सुरक्षा परिपद् में विशेषतः अधिक प्रभावपूर्ण मतदान मिलना चाहिये । यह सुरक्षा परिपद् में स्थायी स्थानों की वृद्धि करके छ. कर देने तथा एक स्थान भारत को दे देने से किया जा सकता है जो कि पहले ब्रिटेन का एक उपनिवेश था परन्तु अब एशिया की एक प्रमुख लोकतन्त्रात्मक शक्ति है । इन समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की मर्यादा १२१ है किन्तु एफो-एशिया के देशों का सुरक्षा परिपद् में अब भी प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत बहुत ही कम है ।

संयुक्त राष्ट्र सभ के प्रथम चरण के कार्यों की समीक्षा—भाज का युग प्राणुविक युग है । मानव-मात्र का जीवन आज बहुत अनिश्चित-सा हो गया है । बढ़ती हुई शक्ति की होड़ ने यह आवश्यक-भा कर दिया है कि कोई एक ऐसी संस्था हो जिसका समूचे विश्व पर प्रभुत्व हो, और जो मानव-मात्र की रक्षा में तत्पर हो । इसमें कोई संदेह नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र सभ ने अपने कार्यों से अपने भाषका एक ऐसी ही प्रभावकारी विश्व-संस्था के रूप में सिद्ध किया है ।

बर्लिन, तेहरान, ग्रीक, जेरुसलम, काश्मीर और कोरिया के मामलों में संघ ने जो सुझाव रखे उनका अपना विशेष महत्व है । एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी उत्पत्ति के प्रथम दस वर्षों में ही ५ युद्धों को रोकने का महत्वपूर्ण कार्य किया—वे युद्ध ग्रीस की सीमा, काश्मीर की सामा तथा पैलेस्टाइन, इन्डोनेशिया और मल्ल के प्रसंगों में सम्भावित युद्ध थे । कोरिया में राष्ट्र-मज्ज न ही शांति स्थापित की । इसने सीरिया, लेबनान, बर्मा और ईरान से विदेशों में नए हटाया और बर्लिन अवरोध को तोड़ने में सहायता की ।

युद्धों को रोकने और शांति स्थापित करने के साथ ही दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य संयुक्त राष्ट्र ने किया है वह है प्राणुविक शक्ति को युद्ध और विनाश से मोड़कर शांति और निर्माण की ओर लगाना । १९५५ में ७२ राष्ट्रों की एक “पीस वाकन्से” अणु-शक्ति के सम्बन्ध में जेनेवा में हुई थी । उस सम्मेलन में यह घोषणा बंधी थी कि “यच० वाम्ब” की प्रबल शक्ति भगते २० वर्षों में मनुष्य की बिजली और शक्ति सम्बन्धित माँगों को पूरा करने में लग जायेगी ।

भारम्भ में राष्ट्र सङ्घ ५० राष्ट्रों की सदस्यता से भारम्भ हुआ था किन्तु अक्टूबर १९६६ तक १२१ सदस्य हो चुके थे।

कोरिया का प्रश्न समुक्त राष्ट्र संघ के लिये एक बहुत ही कठिन परीक्षा का प्रश्न था। नवम्बर १९५२ में भारतीय प्रतिनिधि द्वारा कोरिया के सम्बन्ध में एक दान्ति-योजना प्रस्तुत की गई और कोरिया में युद्ध की विभीषिका ने दान्ति का रुख लिया। इन्डोनेशिया में समुक्त राष्ट्र प्रायोग ने युद्ध को समाप्त किया जिसमें कि इन्डोनेशिया ने नीदरलैंड से स्वतन्त्रता की माँग की थी। इन्डोनेशिया स्वतन्त्र होने के पश्चात् २८ सितम्बर, १९५० को समुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य हो गया। काश्मीर-विवाद के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र प्रायोग ने भारत व पाकिस्तान के बीच एक झुले युद्ध को विराम की स्थिति तक पहुँचाया; यद्यपि यह प्रश्न आगे और भी उलझता गया।

समुक्त राष्ट्र संघ ने अपना ध्यान निःशस्त्रीकरण (disarmament) की ओर केन्द्रित किया।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के अन्य संगठन जैसे 'अन्तर्राष्ट्रीय लेबर भारगेनाइजेशन', 'अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय', 'अन्तर्राष्ट्रीय मानेदरी फंड', 'विश्व हेल्थ भारगेनाइजेशन' और 'संयुक्त-राष्ट्र-शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन' अपने-अपने उद्देश्यों की पूर्ति में बहुत अधिक सफल रहे हैं।

१९५६ के अन्त में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई मानो मिस्र में एक विरघ-युद्ध हो जायेगा। यह भावना 'इजरायली एंग्लो फ्रेंच' आक्रमण के कारण उत्पन्न हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ इस स्थिति में दृढ़ रूप से खड़ा हुआ, और राष्ट्रों की नैतिक आवाज इतनी सबल सिद्ध हुई कि युद्धरत राज्य संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के आदेशों की अवज्ञा न कर सके। सोवियत रूस को भी हज़ारी के आन्तरिक मामलों के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में सङ्घ की आवाज को मानना पड़ा।

१९५८ में लेबनान में मध्य-पूर्वी संकट के समय तथा जार्डन के मामले में राष्ट्र सङ्घ ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि का अतिक्रमण करने वाले आक्रामक राज्यों को रोका। १९६१ में "कगो" के संकट में सफलतापूर्वक परिस्थिति का सामना किया।

संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्त्व—जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव या कथन था कि यह कहना गलत है कि 'लोग भाग नेशन्स' इस कारण अपने उद्देश्यों में असफल रही कि वह अपने अस्तित्व के प्रभाव से द्वितीय विश्व-युद्ध न रोक सकी। असफलता लोग में नहीं, वरन् उन राष्ट्रों में निहित है जो अपनी

प्रतिज्ञा के पालन में असमर्थ रहे और लोग में इतनी शक्ति न उत्पन्न कर सके कि वह एक आवश्यक सस्था बन सके ।

संयुक्त राष्ट्र सच का चार्टर पहले से ही यह अनुमान करता है कि महान् शक्तियों में ऐवय स्थापित है किन्तु जैसा कि Hans J Morgenthau ने लिखा है कि इसमें वे अवयव नहीं हैं जिनके द्वारा इसे दृढ़ता से स्थापित किया जा सके । उन्हों के शब्दों में—“The United Nations was originally envisaged as the second storey of an edifice, built upon the foundations of the continuing unity of the Great Powers to be maintained by the traditional methods of diplomacy With that unity having crumbled, the United Nations, as intended by the Charter, has no foundation upon which to rest. The only foundation that is left is the unity of the Western alliance under the leadership of the United States, and what is—politically speaking called—the United Nations today is but a wing of the original structure resting on that foundation.”

तत्पर्य यह कि संयुक्त राष्ट्र सच और कुछ नहीं बल्कि महान् शक्तियों पर आधारित एक परम्परागत राजनयिक महल है । महान् शक्तियों की एकता टूटने के पश्चात् अब केवल पारस्परिक मित्र-राष्ट्रों की एकता है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में है, और जिसे कि राजनीतिक परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र सच कहने हैं । यह और कुछ नहीं बल्कि उसी नींव पर आधारित मौलिक संरचना है ।

अपनी अनक कमियों के उद्धार में भी संयुक्त राष्ट्र सच एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावकारी सस्था के रूप में कार्य कर रहा है और विपक्ष सम्मन्ध अन्तर्राष्ट्रीय शांति-समझौता और सुवर्भाव से है । राष्ट्रपति 'माइकल रोबर्ट' ने इसे मनुष्य की सबसे अच्छी सङ्गठित भाषा कहा था, जो कि युद्ध का सम्झौता वास्तव बदलने में सहायक है । यह सस्था इस बात का अवसर प्रदान करती है कि शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था हो तथा जनता का सार्वभौमिक विकास हो । धार्मिक और सामाजिक जीवन की प्रगति में भी सस्था ने अपने विविध सङ्गठनों के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया है ।

पञ्चशील—इस प्रकरण की सभापति के पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पञ्चशील के सिद्धान्तों का परिज्ञान कर लिया जाय । इस सिद्धान्त का प्रवर्तन भारत और चीन के द्वारा हुआ था और यह भाषा की गई थी कि यदि इसे सही ढंग से अपनाया गया तो विश्व-शांति का ढाँचा ही बदल जायेगा । चीन के प्रधान

मन्त्रो चाऊ एन लाई जून १९५४ में भारत आये थे। जून २८ को भारत और चीन के प्रधान मन्त्रियों का संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ, जिसके अनुसार निम्न के सम्बन्ध में भारत और चीन के ५ समझौते के सिद्धान्त पुष्ट किये गये। वे निम्न-लिखित हैं :—

१—प्रत्येक के राज्य-क्षेत्र और सम्प्रभुता का पारस्परिक सम्मान (Mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty)।

२—आक्रमण का न करना (Non-aggression);

३—परस्पर किसी के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना (non-interference in each other's internal affairs);

४—समानता और पारस्परिक लाभ (Equality and mutual benefit); और

५—शांतिपूर्ण सहअस्तित्व (peaceful co-existence)।

दोनों प्रधान मंत्रियों ने यह स्वीकार किया था कि एशिया और विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार की सामाजिक और राजनैतिक प्रथाएँ विद्यमान हैं। अगर किसी प्रकार उपरोक्त सिद्धान्त स्वीकार कर लिये गये और उनका अनुशीलन किया गया तथा एक-दूसरे के भीतरी मामलों में प्रत्येक देश हस्तक्षेप न करे तो ये भिन्नताये शांति स्थापित करने के मार्ग में बाधक न बनेगी। किसी राज्य के भू-भाग और उसकी सम्प्रभुता का जब सम्मान किया जायेगा और राष्ट्र आक्रमण न करने की नीति अपनायेगी तो शांति-पूर्ण सहअस्तित्व और देशों में आपस के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनेंगे। इनसे आज के विश्व की बढ़ती हुई तनातनी कम होगी और शांति का वातावरण उत्पन्न होगा। पंचशील का सिद्धान्त “जीवित रहो और जीने दो” (Live and let live) पर आधारित है।

यह सिद्धान्त एक दूसरे से बहुत ही सम्बद्ध है किन्तु इनमें शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का एक विशेष स्थान है।

मयुवन राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद १, पैरा २ में यह उद्देश्य लिखा हुआ है कि “राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाये जाय, समान अधिकारों के सिद्धान्त का आधार हो तथा जनता का आत्म-निर्णय तथा सार्वभौमिक शांति को बढ़ाने व उचित उपाय किये जाय।” इस प्रकार हम देखते हैं कि यह पाँचो सिद्धांत मयुवन राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देश्यों को अधिक व्यावहारिक रूप में भागे बढ़ाते हैं। इस सिद्धान्त की मुख्यतः भारत, सोवियत रूस, गणतन्त्र चीन, इन्डोनेशिया,

बर्मा, सीरिया, नेपाल, कम्बोडिया, लाओस, सोदी-घरब, पोर्लेड और योगोस्लाविया द्वारा माना गया ।

पञ्चशील के सिद्धान्त से विश्व-शान्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ था और ऐसी भाषा की जाती थी कि इस सिद्धान्त के आधार पर सह-अस्तित्व शान्ति, निरस्त्रीकरण तथा विपैले विस्फोटक बम के प्रयोग को रोकने में सहायता मिलेगी ।

किन्तु, पञ्चशील का सिद्धान्त व्यापक रूप से प्रभावकारी हो, इसके पूर्व ही इस सिद्धान्त के प्रवर्तकों में से एक ने इन सिद्धान्तों का पूर्णतया उलट्टन कर दिया । भारत, तिब्बत व चीन की सीमाओं का हमेशा सम्मान करता रहा और दोस्तों का हाथ आगे बढ़ाता रहा; किन्तु चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर निरकुश ढङ्ग से आक्रमण कर १९६२ में मानो इस सिद्धान्त की रोड को ही हिला दिया । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय जगत् की बहुत ही विलक्षण घटना थी, कि जिन सिद्धान्तों का प्रति-पादन भारत और चीन द्वारा सर्वप्रथम लिया गया और जिन्हें विश्व में बहुत सम्मानपूर्वक देखा गया, उन्हीं सिद्धान्तों का अतिक्रमण चीन ने ही भारत के विरुद्ध कर दिया ।

आज पंचशील का सिद्धान्त फिर भी उपयोगी है और यदि विश्व के राष्ट्र एक दूसरे की राज्य-सत्ता का सम्मान करना सीख लें तो निश्चय ही यह सिद्धान्त सह-अस्तित्व और शांति के लिए व्यापक रूप से अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर देगा ।

## अध्याय २७

### सुरक्षा परिषद् के कार्य का सिंहावलोकन

#### (Survey of Security Council at Work)

सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है । इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के ग्यारह (संशोधन के पश्चात् अब १५) सदस्य होते हैं । चीन का गणतन्त्र, फ्रान्स, सांघियत समाजवादी गणतन्त्रों का संघ, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके पाँच स्थायी सदस्य हैं और छ. (तथा संशोधन के पश्चात् अब १०) अस्थायी सदस्य साधारण सभा द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिये निर्वाचित होते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रायः सभी प्रमुख वैधानिक कृत्यों के करने का उत्तर-दायित्व सुरक्षा परिषद् पर है । यह इन्हें या तो अकेले अथवा साधारण सभा के



परामर्श से कर सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करने का प्राग्भिक उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुरक्षा परिपद को दिया गया है। प्रायः इसे अधिशासी प्रकार का कार्य सम्पन्न करना पड़ता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कार्य करती है और चार्टर के अनुच्छेद २३ के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों ने सुरक्षा परिपद के निर्णयों को स्वीकार करने तथा पालन करने की प्रतिज्ञा की है।

सुरक्षा परिपद दो प्रकार के कार्यों को करती है। यह झगड़ों की जाँच करती है तथा शान्ति-भंग के सम्बन्ध में कार्यवाही करती है। यह इन बात का निश्चय करती है कि शान्ति के विच्छेद कोई घमकी भयवा अग्रघर्षण का कार्य तो नहीं है तथा इस सम्बन्ध में संस्तुति करनी है अथवा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने अथवा उसे पुनः संस्थापित करने के लिये जो उपाय अवलम्बन किये जाय, उनका निर्णय करती है।

यहाँ पर हम कतिपय सर्वाधिक महत्व के झगड़ों तथा स्थितियों पर विचार करेंगे जो इस समय तक सुरक्षा परिपद के सामने लाये गये हैं।

**इंडोनेशिया :—** द्वितीय विश्वयुद्ध में जापानियों ने डच लोगों को पूर्वी इण्डोनेशिया से बाहर भगा दिया था। इंडोनेशिया जो कि पहले नीदरलैंड के नियन्त्रण में था, राष्ट्रवादियों ने वहाँ पर जापानी सैन्यों के आत्म-समर्पण के उपरान्त ही एक गणतन्त्र स्थापित कर लिया। उन्होंने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। नीदरलैंड्स तथा भारत ने स्थिति को सुरक्षा परिपद के समक्ष रखा, जिसने अपनी सेवायें इस झगड़े को निपटाने के लिये प्रदान की। इसने मध्यस्थता समिति (Good Offices Committee) की नियुक्ति की। इस समिति ने अगस्त १९४७ में युद्ध-विराम की स्थिति उत्पन्न कर दी। नीदरलैंड और गणतन्त्र ने एक शान्ति-समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके उपरान्त नीदरलैंड की ओर से शान्ति भंग कर दी गई। सुरक्षा परिपद ने युद्ध बन्द करने का निर्देश किया, किन्तु नीदरलैंड की सरकार ने इस पर कोई ध्यान न दिया। मध्यस्थता समिति के प्रतिवेदन पर जनवरी २८, १९४८ को सुरक्षा परिपद ने नीदरलैंड सरकार की सैनिक कार्यवाही को रोक देने का आदेश दिया और यह भी आदेश दिया कि सभी राजनैतिक बन्धियों को छोड़ दिया जाय। परिपद ने यह भी संस्तुति की कि एक स्वतन्त्र, संप्रभु और संघीय, संयुक्त राज्य इंडोनेशिया की स्थापना की जाय तथा १ जुलाई १९५० तक दोनों सरकारें सत्ता नये संघ-राज्य को हस्तान्तरित कर दें। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निरन्तर प्रोत्साहित किये जाने पर नीदरलैंड की सरकार ने गणतन्त्र को एक स्वतन्त्र सर्वभौमिक राज्य

माना । साधारण सभा के सन् १९५० में हुये दूसरे सत्र में इडोनेशिया का प्रवेश संयुक्त राष्ट्र सघ में साठवें सदस्य के रूप में हुआ ।

ग्रीस —द्वितीय विश्व-युद्ध ने ग्रीस को बहुत ही बुरी दशा में छोड़ा था । इसकी सेना तितर बितर हो गई थी । उधर साम्यवादी गुरिल्लो के छापे पड़ते जा रहे थे । उन छापों की पृष्ठभूमि में अल्बानिया, युगोस्लेविया और बुल्गारिया के साम्यवादी राज्य सहायक थे । ब्रिटिश सेना ने ग्रीस को आत्म-रक्षा में सहायता की । २१ जनवरी १९४६ को सोवियत साम्यवादी रूस ने सुरक्षा परिषद् में शिकायत की कि ब्रिटिश की निरन्तर सेना ग्रीस में रहने के कारण यहाँ के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप होता है और इससे शान्ति और सुरक्षा के खतरे में पड़ जाने की आशंका है । ग्रीस ने ऐसे किसी हस्तक्षेप के होने से इन्कार किया, अस्तु इस और सुरक्षा परिषद् ने कोई विशेष ध्यान न दिया । इसके पश्चात् ग्रीस की ओर से सुरक्षा परिषद् में शिकायत पहुँची कि साम्यवादी राज्य गुरिल्लो को सहायता पहुँचा रहे हैं । परिस्थिति की जाँच के लिये सुरक्षा परिषद् की ओर से विशेष आयोग नियुक्त किया गया । इस आयोग ने मई २७, १९४७ को एक बहुमत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि तीन उत्तरी राज्यों अर्थात् युगोस्लेविया और कुछ मात्रा में अल्बानिया और बल्गेरिया ने ग्रीस के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध को बढ़ावा दिया है ।

परिणामतः ग्रीस को आधिक रूप से सहायता पहुँचाने का कार्य संयुक्त राज्य द्वारा आरम्भ किया गया और उसका विवेचन सुरक्षा परिषद् में भी कर दिया गया ।

ग्रीस के प्रश्न पर साधारण सभा ने सितम्बर १९४७ को विचार करना शुरू किया । सभा ने सन्तुष्टि की कि ग्रीस और उसके तीनों पड़ोसी भगड़ो का निपटारा करे और इसके लिए समुचित ढंग से राजनायिक संपर्क आपस में स्थापित करे । सभा ने युगोस्लाविया, अल्बानिया और बल्गेरिया को निर्देश किया कि वे गुरिल्ला-युद्ध को किसी भी प्रकार सहायता न पहुँचावें ।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाल्कन पर संयुक्त राष्ट्र सघ ने एक विशेष समिति निर्मित की, किंतु यह समिति साधारण सभा की सन्तुष्टियों का कार्यान्वित कराने में असफल रही ।

धीरे-धीरे परिस्थिति में सुधार हुआ । युगोस्लाविया ने ग्रीस में गुरिल्ला-युद्ध को सहायता देना बन्द कर दिया । ग्रीक सेना भी इतनी सशक्त हो चुकी थी कि शान्ति को फिर से स्थापित कर सके । २५ हजार ग्रीक बच्चों के निर्वासन का प्रश्न अब भी एक समस्या बनकर खड़ा था । सभा की सन्तुष्टि पर युगोस्लाविया ने इस बात पर सहयोग दिया कि जो बच्चे अपने घर वापस जाना चाहते हों, उनके

जाने की व्यवस्था कर दी जाय। इस सम्बन्ध में अन्य पूर्वी यूरोपीय राज्यों ने अनु-  
सार नीति बर्तों और इस कार्य में व सहायक नहीं हुये।

बर्लिन की नाकाबंदी (The Berlin Blockade) :—सन् १९४८ में फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने यू० एस० एस० आर० की सरकार द्वारा एकपक्षीय तौर पर जर्मनी के दखल किये गये पश्चिमी क्षेत्रों तथा बर्लिन के बीच लगाये गये उद्बहन तथा यातायात सम्बन्धी अवरोधों के कारण जो गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसकी और सुरक्षा परिपद का ध्यान आकर्षित किया और बतलाया कि यह कार्य चार्टर के अनुच्छेद २ के अन्तर्गत लगाय गये कर्तव्यों के विरुद्ध था तथा यह शान्ति के लिये एक घमकी थी। यह प्रश्न परिपद के कार्यक्रम में रखवा गया। संयुक्त राष्ट्र सभ में दखल करने वाली चार दक्षिणों के प्रतिनिधियों ने परस्पर मई १९४९ को बर्लिन की समस्या पर वार्तालाप किया तथा वे इस बात पर सहमत हो गई कि यू० एस० एस० आर० द्वारा बर्लिन तथा पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों के बीच लगाये गये यातायात, उद्बहन तथा व्यापार सम्बन्धी सब अवरोध हटा दिए जाय।

फिलस्तीन (Palestine) —यूनाइटेड किंगडम के प्रस्ताव पर अप्रैल २ सन् १९४७ को फिलस्तीन का प्रश्न सभा के कार्यक्रम में रखा गया। अप्रैल तथा मई में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और उसने फिलस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र सभ की विशेष समिति को स्थापित किया। समिति ने यह सन्तुष्टि किया कि फिलस्तीन को भरव राष्ट्र, यहूदी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय सरकार के अधीन एक विशेष क्षेत्र में जिसमें जेरुसलम सम्मिलित हो, विभाजित कर दिया जाय। यह योजना सभा द्वारा स्वीकृत की गई जिसका परिणाम यह हुआ कि यह व्यवस्था की गई कि ब्रिटेन का फिलस्तीन के ऊपर आज्ञापत्र के अन्तर्गत अनुशासन समाप्त हो जाय तथा ब्रिटेन की सेना अगस्त १ सन् १९४८ तक हटा ली जाय। सभा ने योजना को कार्यरूप में परिणत करने के लिये संयुक्त राष्ट्र सभ का फिलस्तीन आयोग बैठाया। आयोग ने यह प्रतिवेदन किया कि फिलस्तीन की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और यह सम्मति प्रकट की कि ब्रिटेन के चले जाने के उपरान्त सम्पूर्ण फिलस्तीन में शासन अव्यवस्थित हो जायेगा तथा भुखमरी और भ्रम हो जायेंगे। सभा ने एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया जिसने न्यास परिपद (Trusteeship Council) से प्रार्थना की कि वह जेरुसलम में मुख्यवस्था स्थापित करने के निमित्त एक योजना तैयार करे। परिपद भरव तथा यहूदियों के प्रतिनिधियों से यह सम्-  
झौता प्राप्त करने में सफल हुई कि युद्ध बन्द (cease-fire) हो तथा तत्पश्चात् विराम-संधि हो। एक विराम संधि आयोग बनाया गया किन्तु स्थिति में सुधार नहीं

हुआ । ब्रिटेन ने आज्ञापत्र के अधीन अपना अनुशासन १५ मई को त्याग दिया । १७ सितम्बर को मध्यस्थ बॉट बर्नाडोट (Count Bernadotte) तथा फ्रान्सीसी प्रेसको का मुखिया Colonel Andre Serot जेरूमलम क इसरायली क्षेत्र में गानी से मार डाले गये । निरन्तर लड़ाई के उपरान्त मध्यस्थता के प्रयत्न सफल सद्ध हुए तथा इजिप्ट और इसरायली सरकारों ने फरवरी २४ सन् १९४९ का रोडम में एक सामान्य युद्ध निवृत्ति सन्धि के स्वोत्तिात्र पर हस्ताक्षर किये ।

सीरिया-लेबानॉन :—फरवरी ४ सन् १९४६ को लेबानॉन तथा सीरिया ने सुरक्षा परिषद् का ध्यान बढ़ी पर ब्रिटिश तथा फ्रान्सीसी फौजों को निरन्तर उपस्थिति की ओर आकर्षित किया । सुरक्षा परिषद् में एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसमें यह विश्वास प्रकट किया गया कि विदेशी सेनाओं को यथासम्भव वीज्जाति-शीघ्र हटा लिया जायेगा किन्तु यह रूस के निषेधाधिकार के कारण रुक गया । फिर भी ब्रिटेन और फ्रांसीसी सेनाओं का वहाँ से हटाने का कार्य प्रायः दो मास में पूर्ण हो गया ।

आंग्ल ईरानी तेल का झगडा (Anglo-Iranian Oil Dispute) :—ईरान के तेल-उद्योग को मई सन् १९५१ में राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी आंग्ल-ईरानी झगडे में ब्रिटेन द्वारा अस्थायी कार्यवाही के लिये प्रार्थनापत्र दिये जाने पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ईरानी-तेल झगडे में ब्रिटिश सरकार को "रोक दो" (Ireze) प्रार्थना को स्वीकार कर लिया । ईरान ने विश्व न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार कर दिया । यह झगडा सुरक्षा परिषद् को निर्दोशन किया गया जिसने १९ अक्टूबर सन् १९५१ को इस पर विचार-विमर्श उस समय तक के लिये स्थगित कर दिया जब तक कि न्यायालय यह निर्णय न दे कि क्या यह विषय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है । न्यायालय ने अन्तिम रूप में जुलाई २२ सन् १९५२ को यह निर्णय दिया कि यह आंग्ल-फारस के तेल के झगडे को निपटाने के लिये योग्य नहीं है तथा ब्रिटेन के इस दावे को अस्वीकृत किया कि न्यायालय फारस के विरुद्ध उनके (ब्रिटेन के) अधिकार के तेल-उद्योग को राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में ब्रिटेन के परिवाद को निपटाने के योग्य है ।

कार्फू चैनल झगडा ( The Corfu Channel Dispute ) :—अक्टूबर सन् १९४६ में ब्रिटिश जंगी जहाजों को अलबेनिया के क्षेत्रीय जलभागों में सुरगों ने टकराने के कारण भारी क्षति पहुँची । ग्रेट ब्रिटेन ने इस विषय को सुरक्षा परिषद् के समक्ष इस कथन के साथ उठाया कि चैनल में सुरगों की उपस्थिति के लिये अलबेनिया उत्तरदायी है । यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष आया जिनने यह निर्णय दिया कि विस्फोट के लिये अलबेनिया उत्तरदायी है तथा यह कि उन अवसर पर जब विस्फोट हुआ ब्रिटेन अलबेनिया के जलभागों में अनधिकृत प्रकार से

नहीं जा रहा था, किन्तु हमने यह निर्णय दिया कि ग्रिटेन ने असवेनिया के जन-भागों का उत्सर्जन दूसरे ही मामले में किया था तथा इन परिस्थितियों में जो कुछ क्षतिपूर्ति दी जा सकती थी वह न्यायालय के निर्णय द्वारा जो घोषणा की गई थी वही थी।

**कोरिया (Korea)**—कोरिया की घटना का भारमदिसम्बर १९४३ में उस समय हुआ जब चीन, ग्रिटेन तथा समुच्चत राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियान बाहिरा में यह निर्णय किया कि समय आने पर कोरिया एक स्वतन्त्र राज्य हो जायगा। यह निर्णय उन तीनों शक्तिशाली देशों द्वारा पोर्टस्मथ में जुलाई सन् १९४५ को पुष्टीकृत किया गया। जून सन् १९४० में उत्तरा कोरिया ने बिना किसी प्रकार का उत्तेजना के दक्षिणी कोरिया गणतन्त्र पर आक्रमण कर दिया। सुरक्षा परिषद् का एक तारका-लिक बैठक बुलाई गई किन्तु जनवरी १३ सन् १९४० को रुम का प्रतिनिधि इस बात को विरोध में सभा छोड़कर बाहर चला गया था कि परिषद् ने कम्युनिस्ट चीन को स्थान देना अस्वीकार किया। जून २५ को सुरक्षा परिषद् की पुन बैठक हुई तथा एक प्रस्ताव दिया गया जिसमें सब सदस्यों से प्रार्थना की गई थी कि वे समुक्त राष्ट्र सभ को प्रस्ताव के निष्पादन में सहायता दें तथा उत्तरी कोरिया को प्राधि-कार्य को सहायता देना बन्द कर दें। सदस्य-देशों द्वारा भेजी गई सेनायें समुक्त राष्ट्र सभ के समक्ष प्रस्तुत राज्य अमेरिका के झंडे के नीचे समुक्त कर दी गई। सुरक्षा परिषद् ने सर्वप्रथम कोरिया के मामले में अवधर्षण को रोकने के निमित्त सैनिक कार्यवाही करके बल प्रयोग की स्वीकृति दी। एक दीर्घकालीन युद्ध के डर-रात जिसमें कम्युनिस्ट चीन के साथ समुक्त राष्ट्र सभ की सेनाओं का खुले रूप से संघर्ष हुआ तथा सुरक्षा परिषद् के भिन्न भिन्न कार्य सोवियत नियेबाधिकार के कारण रुके, अप्रैल सन् १९५२ के अन्त तक दोनों पक्ष युद्धविराम (cease-fire) की सब शर्तों पर सहमत हो गये, केवल इस प्रश्न को छोड़ कर कि युद्धबन्दी अपने अपने स्वदेशों को लौट जाने के लिये बाध्य किये जायें। अन्त में इस विषय पर भी बढ़िया की उन्मुक्ति को निरीक्षण करने के लिये 'स्वदेश पुनरागमन आयोग' (repatriation commission) का भारतीय प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया। समुक्त राष्ट्र सभ की बुद्धिमत्ता तथा शान्ति की शक्तियाँ जो निरन्तर कार्य करती रहो सराहनीय हैं कि कोरिया दूसरा मच्चूरिया नहीं हुआ और अतः वहाँ शान्ति स्थापित हो गई।

**कोरिया-युद्ध में वैध प्रश्न**—द्वितीय विश्व युद्ध के अन्त में सोवियत और अमेरिकी सेना ने कोरिया के क्षेत्र को जापानियों के हाथ से छीन लिया और एक विभाजक रेखा खींच दी गई। कोरिया पक्षकारों से परामर्श के संदर्भ में रुम और अमेरिका में मतभेद उत्पन्न हो गया। अमेरिका ने कोरिया के पूरे प्रश्न को सितम्बर १९४७ में समुक्त राष्ट्र की साधारण सभा के समक्ष रखा। सभा ने उस देश में

प्रतिनिधियों के चुनाव के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण करने के लिये एक अस्थायी आयोग नियुक्त किया । उत्तरी कोरिया ने इसी बीच दक्षिणी कोरिया गणतन्त्र पर आक्रमण कर दिया । सुरक्षा परिषद् ने २५ जून १९५० को एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार शत्रुतापूर्ण कार्यों को तत्काल समाप्त करना था, और सेनाओं को पीछे हटाना था । उत्तरी कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र के उक्त प्रस्ताव की उपेक्षा की और धीरे-धीरे यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय शांति के भङ्ग करने का प्रश्न बन गया । इसके पश्चात् सुरक्षा परिषद् ने २७ जून १९५० को एक दूसरा प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार उपबन्धित किया गया कि चूँकि उत्तरी कोरिया ने लड़ाई बन्द नहीं की है, अतः सदस्यों से सिफारिश की गई कि वे सैन्य आक्रमण को रोकने के लिये तथा शान्ति स्थापना के लिये हर सम्भव सहायता करे । अमेरिका की सैन्य-शक्ति कोरिया सरकार की सहायता के लिये आगे बढ़ आयी । ७ जुलाई १९५०, को सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव द्वारा सदस्य राष्ट्रों से सैनिक सहायता की अपील की जिससे संयुक्त राष्ट्र सच के कमान के अन्तर्गत वहाँ शान्ति स्थापित की जा सके ।

इस सम्बन्ध में दो प्रकार के प्रश्न ऐसे थे जिनका सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधि से था :—

१—क्या उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिणी कोरिया पर सशक्त आक्रमण वास्तविक अप्रघर्षण का कार्य और शान्ति के भङ्ग करने का कार्य कहा जायगा ?

२—क्या सुरक्षा परिषद् द्वारा कोरिया में की गई कार्यवाही वैध थी और क्या युद्धरत न होने वाले सदस्य-राष्ट्रों पर इसका कोई आभार था ?

जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है सुरक्षा परिषद् ने चार्टर के अनुच्छेद ३६ के अनुसार यह निश्चय किया था कि उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया के विरुद्ध सशक्त आक्रमण किया है जिसमें शान्ति भङ्ग होने का भी प्रश्न सन्निहित है । यहाँ यह प्रश्न नहीं उठता कि युद्धरत दोनों पक्षकार चार्टर के अन्तर्गत राष्ट्र-सच के सदस्य थे या नहीं अथवा उन्हें राज्य भी कहा जा सकता है या नहीं, क्योंकि सुरक्षा परिषद् को उन प्रसङ्गों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार है जो सदस्य-राज्य नहीं हैं किन्तु जहाँ की घटनाओं का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय शांति पर पड़ सकता है । तदनुसार उत्तरी कोरिया को संयुक्त राष्ट्र सच द्वारा आक्रामक घोषित किया गया और शांति-भङ्ग के लिये उत्तरदायी ठहराया गया ।

जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है सुरक्षा परिषद् को चार्टर के अनुच्छेद ३६, ४०, ४१ तथा ४२ में सैन्य-शक्ति सग्रह करने का प्राधिकार दिया गया है ।

इस सम्बन्ध में प्रो० जूलियस स्टोन का विचार बहुत ही उपयुक्त मान्य पड़ता है कि जून २७ और जुलाई ७ को सुरक्षा परिषद् द्वारा प्रस्ताव रूप में जो सिफारिशें

की गई, वे सदस्य-राष्ट्रो की वैयक्तिक इच्छाओं की एक सामूहिक अभिव्यक्ति मात्र थी जिसमें किसी प्रकार का भार सदस्य-राष्ट्रा पर प्रवर्तित नहीं होता था।

**अलजीरिया का प्रश्न**—जनवरी ५, १९५५, को सीदी अरब ने सुरक्षा परिपद का ध्यान अलजीरिया की गम्भीर स्थिति की ओर आकृष्ट किया।

अलजीरिया द्वारा स्वतन्त्रता की माँग का समर्थन विश्व के सभी न्यायप्रिय लोगों ने किया। यहाँ का प्रश्न निम्नलिखित कारणों से बहुत ही उलझन में पड़ गया था :—

१—अलजीरिया में आकर बस जाने वालों का प्रश्न जो कि अब वहाँ स्थायी निवास चाहते थे।

२—वहाँ के आदिमवासी जो लगातार स्वतन्त्रता की माँग कर रहे थे।

३—फ्रांस की अर्थ-व्यवस्था अलजीरिया को छाड़ने के लिये तत्पर न थी।

अलजीरिया का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र के समक्ष लाया गया। फ्रांस ने यह घोषणा की कि वह अलजीरिया के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी भी प्राधिकार को स्वीकार न करेगा। उसने यह दावा किया कि अलजीरिया फ्रांस का एक भाग है। ब्रिटेन और अमेरिका ने १९५७ की फरवरी में फ्रांस का पक्ष-समर्थन किया।

संयुक्त राष्ट्र की राजनयिक समिति में फरवरी १९५७ में एशिया-प्रशिया-प्रायद्वीपों की १८ शक्तियों ने प्रस्ताव पारित किया जिसमें फ्रांस को अलजीरिया की जनता के हित-निर्णय पर उचित प्रक्रिया करने की माँग की गई।

संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा के १२वें अधिवेशन में फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सभ को यह चेतावनी दी कि संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा अलजीरिया में यदि कोई हस्तक्षेप किया गया तो इसका अभिप्राय रक्तपात का अवधि को बढ़ाना होगा। फ्रांस के प्रतिनिधि ने स्पष्टतः कहा था कि फ्रांस को सरकार जिस राज्य क्षेत्र में अपनी अनुपस्थिति से अराजकता, दुष् और गृहयुद्ध की स्थिति का अनुभव करनी है उसे वह किसी के दबाव के कारण नहीं छोड़ सकती। उसने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सभ को ऐसे मामले में हस्तक्षेप न करना चाहिए जिसमें हस्तक्षेप करने का उसे न तो अधिकार हो और न सामर्थ्य। १० दिसम्बर १९५७ को अलजीरिया के संघ में १५ शक्तियों का समझौता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा ने स्वीकृत किया। किन्तु १३वें अधिवेशन में १७ शक्तियों का एक प्रस्ताव रखा गया और १९५८ में इसे अंगीकार करने का समुचित वोट न मिल सका।

अप्रैल ८, १९६२ को फ्रांस के मतदाताओं ने राष्ट्रपति डी गाले के फ्रांस-अलजीरिया शांति-समझौता का स्वीकार कर लिया। ३ जुलाई, १९६२ का अलजीरिया स्वतन्त्र हुआ।

इस प्रकार अलजीरिया १३२ वर्षों के बाद स्वतन्त्र हुआ जिसका स्वागत संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, संयुक्त अरब गणतन्त्र, युनेस्को, भारत, आदि देशों द्वारा किया गया और अलजीरिया को प्रभुता-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य मान लिया गया ।

**काश्मीर :—**काश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद् के समक्ष आरम्भ से ही एक उलझन के रूप में रहा है । अक्टूबर १९४७ में कबानियो द्वारा पाकिस्तान से सहायता तथा प्रेरणा पाने पर काश्मीर के क्षेत्र पर सामूहिक रूप से आक्रमण किया जा रहा था । काश्मीर के महाराजा ने भारतीय सरकार से सैनिक सहायता के लिये निवेदन किया । भारत सरकार को काश्मीर रियासत के आन्तरिक मामलों में, जब तक कि वह भारत में अपने को अधिमिलित न कर ले हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न था । इस कठिनाई को दूर करने के लिये काश्मीर के महाराजा ने रियासत को भारत में अधिमिलित कर लिया तथा भारत के प्रधानमंत्री ने इस अधिमिलन (accession) का स्वीकृत किया । उन्होंने यह भी कहा कि सामान्य परिस्थिति के वापस आने उपरान्त काश्मीर के लोगों की जनमत गणना होगी । भारत ने जनवरी १ सन् १९४८ को सुरक्षा परिषद् के सामने यह शिकायत की कि आक्रमण-कारियों को पाकिस्तान क्षेत्र के भीतर से जाने दिया जाता है तथा उसे सक्रियता (operation) के अड्डों के रूप में प्रयोग करने दिया जाता है । सुरक्षा परिषद् ने सड़न वाले राज्यों के मध्य ऋं डे की जाँच करने तथा मध्यस्थता करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया । इसने गोलाबारी तो बन्द करवा दी किन्तु सुरक्षा परिषद् आयोग के सरक्षण में जनमत (plebiscite) के लिये मार्ग स्पष्ट करने को समर्थ न हुई । जम्मू तथा काश्मीर की वैध स्थिति इस प्रकार है कि यह भारतीय क्षेत्र का भाग है जिसमें अपने तीन दायित्व अर्थात् प्रतिरक्षा, यातायात और विदेशी विपणन भारत को सौंप दिये हैं । पाकिस्तान सरकार ने कबाची आक्रमणकारियों को प्रायश्चर्य रूप से सहायता देकर भारतीय सभ के विरुद्ध अप्रत्यक्षता का कार्य किया । काश्मीर के भारत में सम्मिलन व प्रश्न का पूर्ण तथा अन्तिम रूप से निर्णय काश्मीर की जनता द्वारा उस समय किया गया जब काश्मीर की विधान सभा ने काश्मीर के भारत में सम्मिलन का सत्यापित करने का निर्णय किया ।

पाकिस्तान की प्रार्थना पर सुरक्षा परिषद् ने काश्मीर के प्रश्न पर जनवरी सन् १९५७ में पुन विचार विमर्श किया । २५ जनवरी सन् १९५७ को संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कोलंबिया तथा क्यूबा इन पाँच शक्तियों द्वारा पुन प्रस्तुत (पुन) एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसमें काश्मीर में यथा-पूर्व स्थिति बनाए रखने के लिये कहा गया था । पाकिस्तान ने यह विवाद प्रस्तुत



किया कि भारतीय सरकार ऐसा पग रख रही है जिसमें जम्मू तथा काश्मीर की रियासत भारतीय सभ में जनवरी २६, सन् १९५७ को सम्मिलित कर लिया जाय । भारतीय प्रतिनिधि ने इस प्रस्ताव को चार्टर के विरुद्ध बतलाया क्योंकि इसके द्वारा एक निश्चित तथ्य को अनिश्चित होने का रूप दिया जा रहा था और यह कि यदि किन्हीं कर्तव्यों की अपेक्षा का आरोप लगाया जाय तो वह भारत पर न लगाकर स्वयं पाकिस्तान पर लगाया जाना चाहिए था ।

सुरक्षा परिषद् ने काश्मीर के प्रश्न पर फरवरी, सन् १९५७ में पुनः विवेचना प्रारम्भ की । ब्रिटेन ने अपने, आस्ट्रेलिया, न्यूवा तथा समुक्त राज्य अमेरिका, इन चार शक्तियों की ओर से एक प्रस्ताव नियमित रूप से उपस्थित किया जिसमें स्वीडन के जॉरिंग (Gunnar V. Jarring) को, जो उस मास में सुरक्षा परिषद् के सभापति थे, पाकिस्तान तथा भारत की सरकारों के साथ काश्मीर के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने को कहा गया था । यह कल्पना की गई थी कि निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी जटिल कठिनाई को दूर करने के लिये काश्मीर में समुक्त राष्ट्र सभ की सेना भेजायी जाएगी । तत्कालीन भारतीय प्रतिनिधि श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने यह प्रश्न उठाया था कि क्या चार्टर के अधीन समुक्त राष्ट्र सभ को भारतीय प्रदेश में सैनिकों के रखने का अधिकार है ? उन्होंने स्पष्ट रूप से यह व्यक्त कर दिया था कि भारत सरकार किसी भी दशा में विदेशीय सेनाओं को अपने भूमि पर आने की अनुमति न देगी । कोलंबिया के प्रतिनिधि ने इस उक्ति में नये विचारों का समावेश किया कि वर्तमान प्रस्ताव में दो बातों को मुच्छ नहीं समझना चाहिये अर्थात् यह कि यू० एन० सी० आई० पी० ने जम्मू तथा काश्मीर के राज्य की सार्वभौमिकता तथा काश्मीर में पाकिस्तानी सेनाओं की उपस्थिति की अवस्था को स्वीकार कर लिया है । इसके अनुसार कोलंबिया ने मूल चार शक्तियों के प्रस्ताव में संशोधन का सुझाव दिया । सोवियत सभ ने फरवरी १८ सन् १९५७ को सुरक्षा परिषद् में यह धोपणा की कि काश्मीर में जनमत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता तथा यह कि किसी सरकार के विचार में काश्मीर का प्रश्न वास्तव में रियासत के लोगों द्वारा निर्णय कर दिया गया था जिनके विचार में उनका क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है ।

मूल चार शक्तियों वाला काश्मीर सम्बन्धी प्रस्ताव जिसमें यह उपबन्ध किया गया था कि स्वीडन के मिस्टर गुनार जॉरिंग काश्मीर के निःशस्त्रीकरण प्रश्न की विवेचना के लिये भारत तथा पाकिस्तान भेजे जाय तथा यह सुझाव रखा गया था कि काश्मीर में समुक्त राष्ट्र की एक अस्थायी सेना रखने के पाकिस्तान के प्रस्ताव का परीक्षण किया जाय, सोवियत सभ द्वारा निषेधाधिकार लगा कर रद्द कर दिया गया ।

एक दूसरा प्रस्ताव जिसकी रूपरेखा उन्ही चार शक्तियों द्वारा पहले वाले प्रस्ताव के उन्ही आधारों पर बनायी गयी थी, किन्तु जिसमें संयुक्त राष्ट्र की सेना का निर्देश छोड़ दिया गया था, सुरक्षा परिषद् द्वारा फरवरी २१ सन् १९५७ का स्वीकृत किया गया। इसमें सुरक्षा परिषद् के सभापति जो स्वीडन के प्रतिनिधि थे से यह प्रार्थना की गई कि वे भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों के साथ सुरक्षा परिषद् से तथा भारत तथा पाकिस्तान के लिये संयुक्त राष्ट्र सच के भाषाओं के पूर्व प्रस्तावों की अपेक्षा करते हुए उन सुझावों को परीक्षा करें जिनसे उनकी सम्मति में भाग्य के निपटारे में सहायता मिलना सम्भव हो। उनसे निवेदन किया गया कि वे इस प्रयोजन के लिये उप-महाद्वीप में जायें तथा सुरक्षा परिषद् को प्रतिवेदन करें जिसमें १५ अप्रैल सन् १९५७ से अधिक विलम्ब न हो। इसमें भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों को इन कार्यों के करने में उसके साथ सहयोग करने को आमन्त्रित किया गया तथा सेक्रेटरी-जनरल और संयुक्त राष्ट्र सच को भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से प्रार्थना की गई कि वे उनकी प्रार्थना के अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करें।

उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार स्वीडन के मिस्टर गुनार जारिंग, सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष, फरवरी १९५७ में पाकिस्तान तथा भारत की सरकारों में काश्मीर-समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिये इस उप-महाद्वीप में आये। इन्होंने इस विषय पर ३० अप्रैल को सुरक्षा परिषद् में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उन्होंने व्यक्त किया कि वे कोई ठोस सुझाव देने में असमर्थ हैं जिससे काश्मीर समस्या सुलभ सके, यद्यपि दोनों सरकार इस समस्या के लिये इच्छुक हैं। इस रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हुआ कि जनमत द्वारा काश्मीर सम्मिलन का निर्णय अनेक नयी कठिनाइयों को उत्पन्न कर देगा क्योंकि भारत सरकार के विचार के अनुसार पाकिस्तान के सैनिक-गठबन्धनों ने काश्मीर की स्थिति बदल दी है और काश्मीर की जनता के विचार भी काश्मीर की द्रुत प्रगति के कारण जनमत से विचलित हो गए हैं।

सितम्बर १९५७ में सुरक्षा परिषद् ने जारिंग रिपोर्ट पर विचार किया। इसके उपरान्त २ दिसम्बर १९५७ में सुरक्षा परिषद् ने अपने प्रतिनिधि डाक्टर फ्रेन्क ग्राहम को भेजा जिन्हें सुरक्षा परिषद् के पूर्व प्रस्तावों के अनुसार काश्मीर के प्रश्न का शान्तिपूर्वक निपटारा करने के सुझाव देने को कहा गया। डाक्टर ग्राहम ने दोनों सरकारों के समक्ष १५ फरवरी १९५८ को कुछ प्रस्ताव किये जो सारांश में निम्नलिखित हैं :—

(१) दोनों सरकारें जनता में समझौते का अनिवार्य वातावरण बनाने लवें।

(२) दोनों सरकारों युद्ध-विराम की स्थिति मुहृद रखें ।

(३) पाकिस्तान की सेना हटाकर 'पाकिस्तान जम्मू काश्मीर की सीमा पर' पाकिस्तान की भार संयुक्त राष्ट्र संधि की सेना रखी जाय ।

(४) संयुक्त राष्ट्र सन्धि के प्रतिनिधि दोनों सरकारों के साथ सुरक्षा परिषद् के पूर्व प्रस्तावों पर मुख्यतः जनमत द्वारा निर्णय वाले अंश पर विचार करें ।

(५) दीर्घ ही डाक्टर ग्राहम के नेतृत्व में दोनों सरकारों के प्रधान मंत्रियों की कांग्रेस हो ।

डाक्टर ग्राहम की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की सी उत्पन्न पाँचों प्रस्ताव स्वीकार थे, किन्तु भारत सरकार की एक भी प्रस्ताव स्वीकार न हुये । सुरक्षा परिषद् द्वारा काश्मीर समस्या की मुनस्काने का यह दूसरा प्रयास घमकन रहा । जम्मूतः काश्मीर की वैधिक स्थिति भारत में सम्मिलन की इतनी मुहृद और व्याधोचिन है कि सुरक्षा परिषद् के सभी अन्यथा प्रयास निष्फल सिद्ध होते रहे हैं । काश्मीर का प्रश्न अब समाप्त इसलिये माना जाना चाहिये कि काश्मीर की जनता भारत व साथ अपनी धर्मनीयता का वैषयः और सत्पतः अन्तिम निर्णय कर चुकी है ।

स्येज नहर (The Suez Canal) :—एक बहुत बड़ा प्रश्न जो सुरक्षा परिषद् का ध्यान आकर्षित किये हुये था, वह बर्नस नसीर द्वारा स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा किये जाने का प्रश्न था । मौलिक विवाद का विषय यह था कि क्या नहर के ऊपर कोई अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण हो सकता है । इजिप्ट (मिस्र) ने नहर का प्रबन्ध करने वाली फ्रांसीसी कम्पनी के अंशधारियों को, जिसमें नियन्त्रण-हित ब्रिटिश सरकार के हाथ में था, पूर्ण क्षतिपूर्ति देने की प्रतिज्ञा की थी । यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस ने राष्ट्रीयकरण की बहुत गम्भीर आलोचना की तथा काहिरा में कड़े विरोधपत्र भेजे और दावे के साथ यह कहा कि नहर का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप सन् १८८८ की कन्वन्शन् की सन्धि तथा प्रतिज्ञा द्वारा स्थापित हो गया था और यह कि इजिप्ट द्वारा की गई कार्यवाही से नहर की स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा की घमकी दी जा रही है जैसा कि वह सन् १८८८ की प्रतिज्ञा से प्रतिभूत है । इजिप्ट ने विरोध-पत्रों को अस्वीकार कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि अगस्त सन् १९५६ में अन्दन में एक २४-राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया । ब्रिटेन, फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी किये गये नियन्त्रण पर २२ राज्यों के प्रतिनिधि आये । इस सम्मेलन में स्वेज नहर के भगंडे को निर्णय करने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका के मिस्टर डलेस ने एक योजना फिर से स्थापित की तथा यह कहा कि जैसा सन् १८८८ की प्रतिज्ञा की प्रस्तावना में कहा गया है, सद्बुद्धि

स्वेज नहर को सब समय में सब शक्तिशाली के स्वतन्त्र उपयोग के लिये एक निश्चित पद्धति स्थापित होनी चाहिये। इसमें इजिप्ट की सार्वभौमिकता के लिये सम्मान व्यक्त किया गया किन्तु यह व्यवस्था की गई कि एक स्वेज नहर मंडल (बोर्ड) स्थापित किया जाय जिसको अपने कार्य करने के लिये इजिप्ट सब प्रकार के उपयुक्त अधिकार तथा सुविधाएँ प्रदान करेगा। मंडल समुक्त राष्ट्र सघ को समय-समय पर इसका विवरण देता रहेगा।

भारत ने एक अन्य योजना का सुझाव रखा जिसमें भौगोलिक प्रतिनिधित्व तथा हितों के आधार पर उपयोग करने वाले हिस्सों की एक परामर्शदात्री संस्था बनाई जाती जिसे परामर्श, विचार तथा मेल के कार्य दिये जाते। भारतीय योजना ने इजिप्ट के सार्वभौमिक अधिकारों को तथा स्वेज नहर को उसका अन्तरंग होना तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का एक जलमार्ग होना स्वीकृत किया तथा सन् १८८८ की कुस्तुन्युनिया की प्रतिज्ञा के अनुसार सब राज्यों के लिये स्वतन्त्र तथा प्रवाह्य नौका-परिवहन की व्यवस्था की।

सत्रह राष्ट्रों ने नहर का प्रबन्ध करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय मण्डल स्थापित करने की डलेस (Dulles) योजना का समर्थन किया तथा लन्दन सम्मेलन की कार्यवाहियों के अभिलेख इजिप्ट को भेज दिये गये। प्रेसिडेन्ट नमीर ने स्वेज नहर का अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण की डलेस-योजना को इजिप्ट के लोगों के लिये आराम-परायणकारिणी तथा उत्तेजक कहकर उसकी निन्दा की। इसके उद्घाटन सितम्बर १२ सन् १९५६ को ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने यह घोषणा की कि ब्रिटेन, फ्रांस तथा समुक्त राज्य अमेरिका एक "उपयोग कर्ताओं का सम्मेलन" स्थापित कर रहे हैं जो स्वेज नहर के भीतर यातायात का उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा। इजिप्ट द्वारा गत जुलाई में अन्तर्राष्ट्रीय स्वेज नहर कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के हेतु जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसके कारण ब्रिटेन तथा फ्रांस ने स्वेज नहर का मामला सुरक्षा परिषद् को निवेदित किया।

अक्टूबर १३ सन् १९५६ को सुरक्षा परिषद् ने एकमत से इस प्रस्ताव के एक भाग को स्वीकृत कर लिया। प्रस्ताव पर दो भागों में मतदान लिया गया, और स्वीकृत भाग में छ-सिद्धान्तों पर महत्व दिया गया जो मविष्य में स्वेज नहर के झगड़े के सम्बन्ध में आधार बनेंगे—(१) नहर के भीतर से स्वतन्त्र तथा खुला याता-यात बिना भेदभाव के होगा, (२) इजिप्ट की सार्वभौमिकता का सम्मान किया जायगा, (३) नहर का संचालन किसी भी देश की राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए, (४) खुली तथा व्यय निर्धारण करने की रीति इजिप्ट तथा उपयोगकर्ताओं के बीच सहमति से निर्णय की जायगी, (५) प्राप्त धन का एक पर्याप्त भाग विकास

मे लगाया जायगा, और (६) भगदो की दंगा म स्वेज नहर कम्पनी तथा इजिप्ट की सरकार के मध्य जो मामले सुलभे हुये नही होंगे पचायत द्वारा तय किये जायेंगे जिसमे निर्देश के समुचित शर्त (terms) होंगे तथा देय पाई गई धन राशि के चुकाने की समुचित व्यवस्था होगी ।

आंग्ल फ्रांसीसी प्रस्ताव का द्वितीय भाग जिसमे स्वेज नहर के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के लिये १८ राष्ट्रों की योजना का अनुमोदन किया गया था, सोवियत रूस द्वारा निषेधाधिकार द्वारा रद्द कर दिया गया जिसका प्रयोग उसने सुरक्षा परिपद् मे ७८वीं बार किया था । रूसी निषेधाधिकार का प्रभाव यह हुआ कि स्वेज सम्बन्धी समझौते का केवल प्रत्यक्ष परिणाम जो निकला यह था कि छ सिद्धांतों का अनुमोदन शेष रह गया ।

नवम्बर २६ सन् १९५६ को इजरायली सैन्य दलों ने स्वेज नहर के क्षेत्र में इजिप्ट के स्थानों पर आक्रमण किया । दो दिन उपरांत यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस ने भी वही किया । सुरक्षा परिपद् के समक्ष समुक्त राष्ट्र सङ्घ द्वारा प्रस्ताव, जिसमे सब राष्ट्रों से कहा गया था कि इजिप्ट में बल-प्रयोग करने भयवा बल प्रयोग की धमकी देने से रुके रहे, ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा नवम्बर ३१ सन् १९५६ को निषेधाधिकार प्रयोग करके रद्द कर दिया गया ।

नवम्बर २ सन् १९५६ को समुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा ने एक विशेष आधिवेशन में अत्यधिक बहुमत से अमेरिका के उस प्रस्ताव पर मतदान किया जिसमे स्वेज नहर क्षेत्र में ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजरायली की सैनिक क्रियाशीलता पर बड़ी चिन्ता प्रकट की गई थी तथा तत्काल गोलाबारी बन्द किये जाने पर महत्व दिया गया था । नवम्बर ४ को सभा ने कैनाडा के उस प्रस्ताव को स्वीकृति दिया जिसमे महासचिव ( Mr Dag Hammarskjöld ) से यह कहा गया था कि इजिप्ट में सलाई की समाप्ति को सुरक्षित रखने तथा निरीक्षण करने के लिये एक सकटवालीन समुक्त राष्ट्र सभ दल रखने की योजना प्रस्तुत करें ।

नवम्बर ५ सन् १९५६ को रूस ने ब्रिटेन तथा फ्रांस को यह चेतावनी दी कि वह समुक्त राष्ट्र सङ्घ के अन्य सदस्यों के साथ मध्यपूर्व में अग्रघर्षण को कुचलने तथा पुन शान्ति स्थापित करने का दृढ़ निश्चय रखता है ।

नवम्बर ७ सन् १९५६ को समुक्त राष्ट्र सङ्घ की साधारण सभा द्वारा एक एगिया तथा अफ्रीका का प्रस्ताव पारित किया गया जिसमे ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजरायली सनाओं को इजिप्ट के प्रदेश से तत्काल हटा देने को कहा गया था । सभा ने इस पर भी मतदान किया कि स्वेज-क्षेत्र में समुक्त राष्ट्र सङ्घ का एक पालिस दल कार्य करे ।

इन प्रस्तावों व परिणामस्वरूप लडाई के क्षेत्र में गोलाबारी बन्द कराई गई ।

इजिप्ट ने समुक्त राष्ट्र सङ्घ से सैन्यदल को इजिप्ट में स्थापित करना सब प्रतिभूतियों (गारण्टियों) के लिये क उपरान्त कि उसके ऐसा करने से इजिप्ट की सार्वभौमिकता को किसी प्रकार से धक्का न पहुँचेगा, सप्रतिबन्ध स्वीकृत किया गया ।

नवम्बर २४ सन् १९५६ को साधारण सभा ने ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजरायली सैन्यदल को इजिप्ट से तुरन्त हटा दिये जाने की माँग की तथा सेक्रेटरी-जनरल को प्राधिकृत किया कि विश्वसङ्घ के सरक्षण में नहर को साफ करने की योजनायें प्रस्तावित करें ।

२२ अप्रैल सन् १९५७ को स्वेज कैनाल की परिवहन के लिये खोल दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने इजिप्ट को स्वेज कैनाल का देश चुकाना आपत्तिसहित स्वीकार किया ।

२५ अप्रैल १९५७ को इजिप्ट सरकार ने १८८८ के फ्रान्सो-ब्रिटिश समझौता और समुक्त राष्ट्र सङ्घ के चार्टर के अनुबन्धों को मानना स्वीकार किया । इसके अतिरिक्त नहर प्रशासन के विरुद्ध कोई भी परिवाद उस विवाचन-समिति में प्रतिप्रेषण करना स्वीकार किया जिसके निर्णय के लिये पक्षकार बद्ध थे । उसने समुक्त राष्ट्र सङ्घ में नहर के प्रयोग के सम्बन्ध में एक घोषणा प्रस्तुत की और यह भी प्रस्तुत किया कि यदि पक्षकारों के मध्य १८८८ के फ्रान्सो-ब्रिटिश समझौते के उपबन्धों की व्याख्या या प्रयोग के सम्बन्ध में कोई वैध विवाद उठेगा तो वह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मान्य होगा ।

हंगरी —हंगरी में सोवियत नमूने का संविधान है । अगस्त १८ सन् १९४६ को हंगरी की ससद ने हंगरी को "जनतन्त्र" उद्घोषित किया । अक्टूबर सन् १९५६ में हंगरी के कम्युनिस्ट जनतन्त्र में हंगरी की जनता के एक बहुत बड़े भाग ने अपनी पुरानी रूस की समर्थक सरकार के विरुद्ध क्रान्ति किया । अक्टूबर २३ को बुडापेस्ट में बहुत बड़ी अशांति देखी गई जो क्रान्ति में परिणत हो गई । हंगरी में सेना विधि (मार्शल ला) स्थापित किया गया, तथा अक्टूबर २४ सन् १९५६ को हंगरी की सरकार ने यू० एस० एस० आर० की सरकार से यह प्रार्थना की कि वह बुडापेस्ट में शान्ति तथा सुव्यवस्था के लिए प्राधिकारियों को सहायता देने के लिए वारसा सन्धि के अधीन हंगरी में रखी हुई सैनिक टुकड़ियों को उपयोग करने की अनुमति दें । कई दिनों के उपरान्त यू० एस० एस० आर० की सरकार

ने हंगरी की सरकार की अनुमति से अपने सैन्यदलों को हटा लिया। उनके हटाये जाने के उपरान्त शीघ्र ही क्रान्तिकारियों ने पुनः जोर पकड़ लिया तथा कारखानों और अस्पतालों को तोड़-फोड़ दिया और पियेटर तथा संग्रहालयों में आग लगा दी।

जिस समय रूसी सेनाएँ बुडापेस्ट में अभियान (march) कर रही थी Mr. Imre Nagy, भूतपूर्व हंगरी के प्रधान मंत्री, ने कलह-विदीर्ण हंगरी की स्थिति को सुरक्षा परिषद् के पास निर्देशित किया। सोवियत प्रतिनिधि ने स्थिति को हंगरी की वैध सरकार के विरुद्ध कैसिस्ट प्रकार के अपराधी तरीकों की क्रान्ति बता कर खारिज कर दिया।

नवम्बर ४ सन् १९५६ को संयुक्त राज्य अमेरिका ने सुरक्षा परिषद् के समक्ष एक प्रस्ताव रखवा जिसमें सोवियत यूनियन से कहा गया था कि वह तुरन्त अपने को किसी प्रकार के भी हस्तक्षेप से रोके। इसमें परिषद् से यह कहा गया था कि वह सच्ची भाषा प्रकट करे कि यू० एस० एस० द्वारा हंगरी की सरकार के साथ यथोचित प्रबन्ध करके सब रूसी सेनाओं को हंगरी से तुरन्त हटा लेया। सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध निवेद्याधिकार का प्रयोग किया जिसपर संयुक्त राज्य अमेरिका ने साधारण सभा के संकटकालीन अधिवेशन किए जाने की प्रार्थना की।

नवम्बर ६ सन् १९५६ को संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने रूस से अपनी सेनाओं को हंगरी से हटा लेने को कहा जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण में वहाँ स्वतन्त्र रूप से चुनाव हो सके। एक प्रस्ताव में सेक्रेटरी-जनरल से की गई इस प्रार्थना को दुहराया गया कि विदेशी हस्तक्षेप के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो गई हो, उसका अनुसंधान अपने प्रतिनिधियों द्वारा जारी रखें, तथा यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र उसका प्रतिवेदन करें।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी-जनरल ने नवम्बर ३० को यह प्रतिवेदन किया कि वह साधारण सभा के प्रस्ताव का पालन हंगरी के लोगों द्वारा कराने में अपने प्रयत्नों में अग्रसर रहे हैं।

दिसम्बर १२ सन् १९५६ को संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने हंगरी की स्वच्छंदता तथा स्वतन्त्रता का अपहरण तथा उसके लोगों को अपने मूलभूत अधिकारों का प्रयास करने से रोकने के फनस्वरूप सोवियत यूनियन द्वारा चार्टर का उल्लंघन किए जाने के कारण उसकी निन्दा की। इसने सोवियत यूनियन से अपनी सेनाओं की तत्काल कलह-विदीर्ण हंगरी से संयुक्त राष्ट्र संघ के निरीक्षण में हटाने को कहा।

सोवियत रूस के, उस भाग की उपेक्षा करने पर, कि उसकी सेना हंगरी से हटा ली जाय, साधारण सभा ने १० जनवरी १९५७ को अपने प्रस्ताव द्वारा एक

विशेष समिति की नियुक्ति की। इस विशेष समिति में फ्रांस, डेनमार्क, टुनीसिया तथा उरुग्वे के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इस समिति का विशेष लक्ष्य सही तथ्यों तथा प्रमाणों के माध्यम से हंगरी की स्थिति का निरीक्षण करना था। २० जून को इस समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रूस के सशस्त्र हस्तक्षेप से हंगरी की राष्ट्रीय क्रान्ति के दमन का इस समिति ने रूस को उत्तरदायी बतलाया। समिति को यह भी ज्ञात हुआ कि हंगरी की क्रान्ति विद्यार्थियों, श्रमिकों, सैनिकों, विद्वानों तथा साम्यवादियों द्वारा संचालित हुई थी। समिति की रिपोर्ट ने बतलाया कि यह असत्य था कि क्रान्ति प्रतिक्रियावादी भयवा शाही वर्ग के द्वारा हुई। रिपोर्ट ने आगे व्यक्त किया कि सोवियत रूस के हस्तक्षेप से स्वतन्त्रता-संग्राम के सैनिकों का प्रयास शिथिल रहा।

समिति को यह ज्ञात हुआ कि २३ अक्टूबर को प्रथम तो इस क्रान्ति का प्रदर्शन शान्तिपूर्ण ढंग से होता रहा किन्तु जब राज्य की सुरक्षा पुलिस ने प्रदर्शन-कारियों पर गोली चलायी और रूस की सेना का पदार्पण हुआ तो क्रान्ति ने भीषण रूप ले लिया।

हंगरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सच की निरीक्षण समिति की रिपोर्ट को मिथ्यापूर्ण तथ्यों का संग्रह कहा और उन्हें समिति के कार्यों को अपने घरेलू मामलों में एक हस्तक्षेप समझा। यद्यपि समिति की इस सस्तुति पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जा सकी किन्तु इसने एक अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा उत्पन्न करने में सहायता की। इस प्रश्न ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि साधारण सभा निरीक्षण करने की सस्तुति करने का और निर्णयों को घोषित करने का अधिकार तो रखती है किन्तु उसे निर्णयों को पालन करवाने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं है। चार्टर के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् को ही केवल अधिकार है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना के लिए बल का प्रयोग करे।

१० सितम्बर १९५७ को साधारण सभा में इस समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष में ३१ राष्ट्रों द्वारा, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन भी थे, एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस प्रस्ताव ने रूस के इस कार्य की निन्दा की कि उसने हंगरी की स्वतन्त्रता से, विशेष रूप से राजनैतिक स्वतन्त्रता से, हंगरी को वंचित किया। साधारण सभा के प्रेसीडेंट प्रिंस वैन वेदायकन के प्रति हंगरी की स्थिति का निरीक्षण के लिए विशेष मिशन ले जाने का प्रस्ताव भी रखा गया। हंगरी के स्थायी प्रतिनिधि ने समिति पर अभियोग लगाया कि हंगरी के घरेलू मामले में हस्तक्षेप करके साधारण सभा ने चार्टर का अतिक्रमण किया है। उसने साधारण सभा से उस मिथ्यापूर्ण रिपोर्ट को अस्वीकृत करने के लिये कहा। इसके अतिरिक्त हंगरी के प्रतिनिधि ने हंगरी के



प्रश्न को साधारण सभा के एजेन्डा से हटाने की भी माँग की। स्पष्ट प्रतिनिधि ने भी साधारण सभा के हंगरी व प्रश्न व प्रस्ताव का विरोध किया।

१३ सितम्बर की बर्मा के प्रतिनिधि ने साधारण सभा में हंगरी और मलेशीरिया व हत्याबाँड पर खेद प्रकट करते हुए यह भाव्य प्रकट किया कि दोनों अपने भाग्य का स्वयं निर्णय कर स। प्रतिनिधि ने यह भी राय दी कि इस के काय की निंदा न करके, खेद प्रकट किया जाय किन्तु यह मत मनमुना ही रहा गया।

१७ जून १९५८ को हमारे नेगी के और उनके तीन सहयोगी के प्राणदण्ड की घोषणा गोपनीय मुकदमे के उपरान्त युद्धावेस्ट की एक सूचना के द्वारा हुई। साधारण सभा की विनायक समिति १९५६ के विद्रोह के बन्दी नेताओं के सम्बन्ध में और उनके प्राणदण्ड पर विचार करने के लिये बुलायी गई। हमने २१ जून को हमारे नेगी व प्राणदण्ड पर खेद प्रकट करते हुये इस प्रश्न में रुचि रखने वाली सरकारों से निवेदन किया कि इनके बन्दी हान, इनके मुकदमे और प्राणदण्ड की स्थितियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें।

१२ दिसम्बर १९५८ को संयुक्त राष्ट्र सच की साधारण सभा ने सोवियत इस की निंदा की क्योंकि उसने हंगरी के प्रश्न पर साधारण सभा की घनेक सिफारिशों की उपेक्षा की थी। इस सभा ने पुनः हमारे नेगी की दुःखद हत्या पर खेद प्रकट किया। हंगरी के प्रतिनिधि डाक्टर वीटर ने इसके उत्तर में कहा कि हमारे नेगी ने कई वर्षों तक ऐसे गुप्त पद्धति किए थे जिसका उद्देश्य हंगरी में स्थायित्व और सरकार को नष्ट करना था। ऐसे के प्रतिनिधि श्री बैलेरियन जारिन ने भी पुनः इस पर महत्व दिया कि यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सच का नहीं है। अमेरिका तथा ब्रिटेन हंगरीयन जनता या उसके रचनात्मक कार्यों की शिता न करके मिथ्या सहानुभूति प्रकट करते हैं।

इसी सभा ने बहुमत से प्रिन्स वैन वेदकायन के स्थान पर स्पीजीनैण्ड के सर लेजली मुनरो को हंगरी की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया।

**टुनीसिया (Tunisia)** — जून १९५८ में टुनीसिया ने सुरक्षा परिषद् में फ्रांस पर यह आरोप लगाया कि फ्रेंच सेना उसकी भूमि पर उसकी इच्छा के विरुद्ध उपस्थित है। इस सेना से वहाँ की सरकार और जनता में बड़ी उत्तेजना बढ़ रही है। १७ जून को फ्रांस की सरकार इस पर सहमत हो गई कि वह अपने समस्त सशस्त्र सैनिकों को बिजरेटा के जल और वायु के आश्रयान को छोड़कर ४ मास के अंदर हटा लेगी। दोनों सरकारें इस बात पर भी सहमत हुईं कि सेना के हट जाने पर वे लोग सैनिक आस्थान की उपयुक्त स्थिति के सम्बन्ध में समझौता करना आरम्भ करेंगे।

दक्षिण अफ्रीका के जातीय रक्तपात — २१ मार्च १९६० को दक्षिणी अफ्रीका में जातीय भेदभाव ने एक बहुत बड़ा रक्तपात उपस्थित कर दिया, जब कि अफ्रीकियों ने सरकार द्वारा पारित कानूनों के विरोध में बहुत ही हिंसक दम प्रारम्भ कर दिये। बहुत बड़ा जन-समुदाय पुलिस स्टेशन के सामने आइडेन्टिटी पास (परिचय-पत्र) न रखने तथा अपने आपको गिरफ्तार कराने के लिये खड़ा हो गया। पुलिस ने हजारों प्रदर्शनकारियों पर शार्पेस्ले और लाँगा में खुले-आम गोली चलायी जिससे बहुत से अफ्रीकियों की मृत्यु हुई। २३ मार्च को श्री नेहरू ने लोकसभा में कहा कि वे केपटाउन के समीप बहुत बड़ी जनसंख्या को कत्ल करने की भर्त्सना करते हैं। उनका कहना था कि इस घटना ने दुनियाँ की चेतना-शक्ति और खास तौर से एशिया और अफ्रीका की जनता को बहुत अधिक धक्का पहुँचाया है।

संयुक्त-राज्य अमेरिका न भी इस हिंसा-कांड की भर्त्सना की। इङ्ग्लैण्ड में भी यही प्रतिक्रिया हुई। उस ने इसे बीसवीं शताब्दी की गुलामी-प्रथा के पुनर्जागरण की सजा दी।

२६ सदस्यों की एफ्रो-एशिया दल ने संयुक्त-राष्ट्र के समक्ष सुरक्षा परिषद् की आपातकालीन बैठक में यह माँग की कि दक्षिणी अफ्रीका की सरकार को जातीय हिंसा से रोका जाय। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद् को बताया कि अफ्रीका की जनता की, संघ सरकार द्वारा जाति का पक्षपात करते हुए हिंसक रूप से हत्या करना तथा उसे दबाना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

अप्रैल १, १९६० को सुरक्षा परिषद् न शून्य के विरुद्ध ६ मतों ने एक प्रस्ताव पारित किया जिनमें ब्रिटेन और फ्रांस अनुपस्थित रहे। प्रस्ताव एफ्रो एशिया सदस्य राज्यों की ओर से था। इसमें कहा गया था कि इस घटना से अन्तर्राष्ट्रीय सत्तातन्त्र बढ़ सकती है। महासचिव श्री डेग हैमर्सजोल्ड से निवेदन किया गया कि वे अफ्रीका की संघ सरकार को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धान्तों के अनुसार समानता के व्यवहार के सिद्धान्तों को अपनाने का प्रयत्न करें।

कांगो का संकट (Congo Crisis) — कांगो के संकट के प्रसंग में पहले भी लिखा जा चुका है। यहाँ इस सम्बन्ध में हम सुरक्षा परिषद् के कतिपय प्रस्तावों और उनमें निहित वेध प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सुरक्षा परिषद् ने जुलाई १४, जुलाई २२ और अगस्त ६, १९६० को क्रमशः तीन प्रस्ताव पारित किये। १४ जुलाई के प्रस्ताव में परिषद् ने बेलजियम की सरकार को कांगो के क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेने की माँग की और महासचिव को प्राधिकृत किया कि वे कांगो की गण-तन्त्र सरकार से आवश्यक कार्यवाही हेतु परामर्श करें जिससे वहाँ की सरकार की आवश्यकतानुसार सैनिक सहायता उस समय तक दी जा सके जब तक कि

परिषद् की सेना कंगोली सरकार की प्राविधिक सहायता से पूर्णतः शान्ति स्थापित न कर दे। जुलाई २२ के प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद् ने बेलजियम की सरकार को परिषद् के १४ जुलाई वाले प्रस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित करने को कहा। अगस्त ८ के प्रस्ताव में परिषद् ने बेलजियम की सरकार को कटागा प्रान्त से अपनी सेना को तुरन्त वापस लेने की माँग की।

१४ जुलाई १९६० के प्रस्ताव के आधार पर जो सैनिक कार्यवाही की गई वह वास्तव में पुलिस या आपराधिक विधि का कार्य था जो कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था जिससे कि वे बेनजियम सेनाएँ शीघ्रता से वापस की जा सकें। उसे हम सैनिक अनुशासन की प्रवर्तन की कार्यवाही नहीं कह सकते।

१४ जुलाई १९६० के आधार पर कांगो में समुक्त राष्ट्र सच की जो सेना सन्नहीत की गई वह समुक्त राष्ट्र सकटकालीन कार्रिया सैन्य-शक्ति से भिन्न थी। इस मामले में कांगो में जो सेना इकट्ठी हुई उसका प्रवर्तन महासचिव ने सुरक्षा परिषद् के प्राधिकार पर किया था। यह सेना सहायक श्रम के रूप में सुरक्षा परिषद् की ओर से महासचिव को अभिकरण मान कर उनके कमान के अन्तर्गत कार्य कर रही थी।

कांगो के गणतन्त्र ने एक आधारभूत समझौते पर समुक्त राष्ट्र सच में महा-सचिव के साथ हस्ताक्षर किया जिसमें यह कहा गया कि यहाँ की सरकार ने अपने सप्रभु-अधिकारों के प्रयोग में समुक्त राष्ट्र सच से सैनिक सहायता की माँग की थी, इससे देश के भीतरी भाग में सना स्वतन्त्रता से आ-जा सकेगी और उस समस्त उन्मुक्तियाँ प्रदान की जायगी। निश्चय ही समुक्त राष्ट्र सच की सेना वहाँ शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिये भेजी गई थी। महासचिव इस बात में सह-मत न हो सके कि समुक्त राष्ट्र सच की सेना कटागा में एक विदिष्ट ढङ्ग से कार्य करने के लिये दबाने का प्रयत्न करेगी। वहाँ की निरन्तर बढ़ते वाली हिंसक घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि वे घटनाएँ केवल धरेलू नहीं हैं बल्कि उनका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय शांति पर भी पड़ेगा।

२१ फरवरी, १९६१ को सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव द्वारा समुक्त राष्ट्र सेना को प्राविष्टित किया कि कांगो में गृहयुद्ध रोकने के सम्बन्ध में शक्ति का प्रयोग किया जाय। कांगो के राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी की निन्दा की गई। सियोवार्ड विले, एसिजाबर्थ विले और बासाइ में अधिकारियों को ऐसी कार्यवाहियों से दूरे रहने की बात कही गई।

## १९६५ का भारत-पाक सशस्त्र-संघर्ष

( Indo-Pak. Armed Conflict of 1965 )

काश्मीर में घुसपैठियों का प्रवेश—अगस्त, १९६५ में पाकिस्तान ने काश्मीर के प्रश्न को सैनिक बल के प्रयोग के आधार पर अपने पक्ष में निर्णीत करा लेने के उतावलेपन में काश्मीर में सहस्रो घुसपैठियों को भेज दिया। इन घुसपैठियों का उद्देश्य काश्मीर में तोड़-फोड़ करना और अव्यवस्था उत्पन्न करना था। भारतीय प्रतिरक्षा के सजग प्रहरियों ने इन छद्मवेशी पाकिस्तानी घुसपैठियों को समय पर पहचान लिया और वे इन घुसपैठियों का काश्मीरी जनता के पूर्ण सहयोग से सफाया करने में लगे हुये थे, कि पाकिस्तान के खुले सैन्य आक्रमण के आतंक भी विराम रेखा के इस ओर फैल गये। परिस्थिति और भी गंभीर रूप ले, इससे पूर्व भारतीय सुरक्षा फौज ने आत्मरक्षा के अधिकार के अन्तर्गत काजिल में तीन पर्यवेक्षण चौकियों पर कब्जा कर लिया। काश्मीर-स्थित संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सैनिक पर्यवेक्षक लेफ्टिनेंट जेनरल निम्नो ने महासचिव का इस प्रतिवेदन के साथ लिखा कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों की जाँच ने इस तथ्य को प्रतिस्थापित किया है कि भारतीय युद्ध-विराम-रेखा की सीमा के भीतर आक्रमण किये गये हैं। इस प्रतिवेदन में पाकिस्तानी घुसपैठियों का तोड़-फाड़ की कार्यवाही का भी पुष्टीकरण किया गया और विशेष रूप से घुसपैठियों द्वारा भारत-सीमा के भीतर की कतिपय ध्वंसा-रमक कार्यवाहियों का भी उल्लेख किया गया।

पाकिस्तान ने जब यह अनुभव किया कि उसके द्वारा किया गया यह कुचक्र विफल हो गया है, तो निराश होकर उसके अधिकारियों ने सीधी कार्यवाही करने का ही अन्तिम मार्ग अपनाया। सितम्बर १, १९६५ को वायुयानों और भारी अस्त्र-शस्त्रों सहित पाकिस्तानी सेना ने युद्ध-विराम-रेखा और जम्मू और काश्मीर राज्य तथा पश्चिमी पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा दोनों का पार जम्ब क्षेत्र के समीपवर्ती भाग पर भारी संख्या में आक्रमण कर दिया। बदले में सितम्बर ६ को भारतीय फौज सीमा के उस पार लाहौर क्षेत्र में आगे बढ़ी। भारतीय सेना ने ऐसा इसलिये किया कि पाकिस्तान खड़ाई का दूसरा मोर्चा न खोल दे। यह भी उद्देश्य था कि इस कदम द्वारा भारतीय सीमाओं की भी रक्षा की जा सके। उन्ही समय पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र के भीतर पैदूरानों को अनेक स्थानों पर एक साथ ही गिराया। उसी दिन राष्ट्रपति अयूब ने पाकिस्तान को राष्ट्रव्यापी रेडियो-संदेश में बताया कि 'हम युद्धरत हैं' (We are at war)। एक क्षण ऐसा आ गया था, मानो अब औपचारिक ढङ्ग से राष्ट्रपति अयूब भारत के विरुद्ध खुले युद्ध की घोषणा कर देंगे। किन्तु, दोनों पक्षों से यह औपचारिक घोषणा नहीं की गई। घटनाओं की विभीषिका युद्ध का कठिनतर वातावरण उत्पन्न करती जा रही थी। भारतीय


स्थल और नभ-शक्ति अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए चोरता के साथ युद्ध-कील दिखाती हुई आगे की बढ़ती जा रही थी। इसी बीच ग्रेट-ब्रिटेन के प्रधान मंत्री विंस्टन ने भारत और पाकिस्तान को अर्जेंट अपील भेजी कि तुरन्त युद्ध-विराम कर दिया जाय, और उन्होंने राष्ट्रमंडल के सभी राष्ट्रों से यह आग्रह किया कि इस प्रसंग में संयुक्त राष्ट्र संधि की गतिविधियों और उसके प्रस्तावों को सफल बनाने में सहयोग दिया जाय।

सितंबर ४, १९६५ का सुरक्षा-परिपदीय प्रस्ताव—सितंबर ४, १९६५ को संयुक्त राष्ट्र संधि की सुरक्षा-परिपद ने काश्मीर में तुरन्त युद्ध-विराम का एक प्रस्ताव सच-सम्मति से पारित किया और भारत-पाकिस्तान से आग्रह किया कि दोनों देश क्षेत्र में युद्ध-विराम-रेखा का सम्मान करें, और सभी प्रकार की सैन्य-शक्ति को विराम-रेखा से अपनी-अपनी ओर वापस कर लें। भारत की ओर से आरंभ से ही इस बात की भाँग की जा रही थी कि सर्वप्रथम पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्र में आक्रामक घोषित करते हुये उससे कहा जाय कि जम्मू और काश्मीर-क्षेत्र से वह अपनी सेनाएँ और अपने छद्मवेदी घुमपैठिये सैनिकों एवं असेनिकों को वापस बुलाये। सितंबर ६ को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने विश्व के समस्त राष्ट्रों से इस बात की अपील की कि वे निष्पक्ष होकर इस बात का निर्णय और घोषणा करें कि प्रथम आक्रामक कौन है, और भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध छेड़ने की सर्व-प्रथम कुचेष्टा किसने की है? पाकिस्तान ने फिर भी इस बात को दुहराया कि शान्ति तभी संभव होगी, जब कि जम्मू और काश्मीर में जनमत-संग्रह की बात स्वीकार कर ली जाय। पाकिस्तान ने इस बात पर भी बल दिया कि युद्ध-विराम की घोषणा के पूर्व हम जनमत-संग्रह की गारंटी मिल जानी चाहिए।

पाकिस्तान ने अन्य राष्ट्रों को भी झूठी सूचनाओं से भ्रान्ति में रखने का प्रयत्न किया। फलतः साम्यवादी चीन, इंडोनेशिया और उत्तरी वियतनाम ने पाकिस्तान का पक्ष समर्थित किया और टर्की तथा ईरान ने अपने सैनिक समझौते के आधार पर पाकिस्तान की सैन्य सहायता पहुँचाना आरम्भ किया। सभी राष्ट्रों के बीच मलायेशिया, सिंगापुर और साइप्रस ने भारतीय स्थिति का निष्पक्ष, किन्तु सबल समर्थन किया। अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र संधि के प्रस्तावों का समर्थन इस उद्देश्य से किया कि भारतीय उपमहाद्वीप में तुरन्त शान्ति स्थापित की जा सके। अतः उन्होंने इस समर्थन के अतिरिक्त, आक्रामक कौन है, इस विषय पर मौन रहना ही परिस्थितियों को देखते हुये, शान्ति-स्थापना के प्रयोजन में हितकर माना।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध-विधि की पूर्णतः उपेक्षा—इसी बीच युद्ध अपने पूरे रोप पर आ चुका था। साहस हार जाने वाला योद्धा युद्ध के नियमों को भूल-

कर इधर उधर हाथ-पैर मारने और अपनी शक्ति का दुस्प्रयोग करने लगता है । पाकिस्तान ने भी ठीक यही काम करना आरम्भ किया । उसने अन्तर्राष्ट्रीय अभि-समयों और सम्य देशों के बीच युद्ध-कौशल की प्रस्थापित नीतियों की पूर्णतः उपेक्षा करके निहत्थी नागरिक जनता एवं शान्तिपूर्ण नगरों पर दुर्घर्ष रूप में बर्बाद-हत्या करना आरम्भ कर दिया । विध्वंस का ताड़न नर्तन होने लगा, किन्तु भारतीय सेनाओं ने कभी भी सम्य देशों के बीच प्रस्थापित युद्ध-कौशल को नहीं छोड़ा और उन्होंने पाकिस्तानी फौजी महत्व के स्थानों, शस्त्रागारों और फौजी भण्डारों को छोड़कर अन्यत्र नागरिक जनता पर वही भी बम नहीं गिराये । पाकिस्तान ने खुल रूप में भारतीय गाँवों और नगरों की निहत्थी जनता स्कूलों, कालेजों, मन्दिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों को यहाँ तक कि विशाल नेपाम बमों (Napalm Bomb) से ध्वस्त करना आरम्भ कर दिया था और यहाँ तक कि बिना किसी निशाने के पाकिस्तानी युद्धको द्वारा फेंके गये भयंकर बम उड़ो के रंगों बालू या रक्त स्थानों में गिरकर भारतीय फौजों के हाथ लगे ।

सितंबर ६ का सुरक्षा-परिषदीय प्रस्ताव—६ सितंबर, १९६५ को, जब कि महासचिव ने यह रिपोर्ट दी कि दोनों में से किसी सरकार द्वारा युद्ध-विराम-प्रस्ताव को स्वीकार करने की औपचारिक स्वीकृति नहीं दी है, तब सुरक्षा-परिषद् ने  प्रस्थायी सदस्यों बोलीविया, आइवरीकोस्ट, जोर्डन, मलायेशिया, नीदरलैंड्स और ऊरुग्वे ने सम्मिलित रूप से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें दोनों पक्षकारों को तुरन्त युद्ध-विराम करने के लिए कहा गया और महासचिव से निवेदन किया गया कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए वे जो भी उचित समझे हर समय प्रयत्न करें, साथ में सितंबर ४ के भी प्रस्तावों को कार्यान्वित करावे । यह प्रस्ताव परिषद् द्वारा निर्विरोध रूप में सर्वसम्मति से पारित हुआ । इस प्रस्ताव द्वारा प्रत्यानिधित अधिकार के परिणामस्वरूप महासचिव ने दोनों देशों के नेताओं से व्यक्तिगत रूप में मिलने का निश्चय किया ।

पाकिस्तान की रुढ़ि-प्राप्तता के कारण महासचिव का शान्ति-संदेश विकल हो गया ।

सितंबर १७ को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने सुरक्षा परिषद् से कहा कि भारत और पाकिस्तान को युद्ध समाप्त करने का आदेश करे । इसी समय चीन ने भारत को एक चुनौती दी कि इस टिप्पणी को प्राप्त करने की तिथि के तीन दिन के भीतर वह चीनी-सिन्धु सीमा पर अपने द्वारा तैयार किये गये आक्रामक निर्माणों को ध्वस्त कर दे ।

भारत के तत्कालीन शिक्षामंत्री श्री मुहम्मद करीम चागला ने १८ सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में भारत की वास्तविक स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुये कहा कि

इतने साक्ष्यो एवं प्रमाणों के होते हुये भी यदि सुरक्षा-परिषद् विवाद का निर्णय करने से इन्कार करती है और दोनों पक्षकारों को समान स्थिति पर व्यवहृत करती है, तो अब सुरक्षा परिषद् की आवश्यकता ही क्या रह गई है ?

सितंबर २० का सुरक्षा-परिषदीय प्रस्ताव—सितंबर २० को सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह मांग की गई कि दोनों सरकारें युद्ध विराम की घोषणा करें, जो कि सितम्बर २२, के १२-३० बजे अपराह्न से लागू हो।

सितंबर २२ को भारत-सरकार को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का एक संदेश मिला जिसमें भारत को सलाह दी गई थी कि सुरक्षा परिषद् के सदसित प्रस्ताव के अनुपालन-स्वरूप वह एकपक्षीय युद्ध-विराम घोषित कर दे, किन्तु यह भी उपबन्ध रहे कि यदि उसपर आक्रमण किया गया तो फिर भारतीय फौजें गोली का जवाब गोली से देंगी। भारतीय सरकार इस प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकृत करने को विवश हो गई कि युद्ध जब चल रहा है तो एक पक्ष के लिए यह संभव नहीं है कि वह कबल अपनी सेना को गोली चलाने से रोककर दूसरे पक्ष को अग्नाघुन्ध गोली चलाने का खुला अवसर दे दे।

युद्ध-विराम ( Cease Fire )—सितंबर २२ को पाकिस्तान दूसरे दिन ३.३० बजे पूर्वाह्न में युद्ध-विराम की घोषणा के लिए सहमत हो गया। फिर भी, पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को यह धमकी दी कि यदि काश्मीर का प्रश्न एक मुक्तिसंगत अवधि के भीतर नहीं सुलझाया जाता, तो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सच को छोड़ देगा।

सितम्बर १६ को चीन ने भारत के नाम दी गई अपनी चुनौती की अवधि को तीन दिन तक के लिये विस्तारित कर दी। सितम्बर २२ को चीन ने यह घोषित किया कि कतिपय 'सैनिक निर्माणों' को जिन्हें कि 'सीमा के चीनी क्षेत्र की ओर' भारत ने बना रखा था, उसने अब स्वयं नष्ट कर दिया है।

पाकिस्तान द्वारा नागरिक लक्ष्यों पर धम धर्या—उपर्युक्त तीन सप्ताह की अवधि के भारत पाक युद्ध के बीच पाकिस्तानी धम-धर्या ने भारतीय नागरिक लक्ष्यों पर धम-धर्या करने का लक्ष्य किया। भारतीय नागरिक जीवन को नष्ट-भ्रष्ट करना, विरोध रूप से उस समय जब कि भारतीय नम-शक्ति ने बम्बी भी पाकिस्तानी नागरिक जीवन को नष्ट करने का लक्ष्य नहीं धननाया और अपनी कार्यवाही का लक्ष्य पाकिस्तानी सैन्य-शक्ति तक ही सीमित रखा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और सम्य राष्ट्रों में प्रस्थापित युद्ध-विधि के धतिर्लपन का कार्य था। पाकिस्तानी धम धर्या ने अम्बाला और जायपुर में दा बड़े-बड़े धस्तानों को

घराशायी कर दिया । उन्होंने अम्बाला में १५० वर्ष पुराना सम्मानित सेण्ट पॉल्स कैथिड्रल ( गिरजाघर ) को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला और क्षम्ब क्षेत्र में एक विशाल मस्जिद को तहस-नहस कर डाला, जबकि इस्लाम धर्म के अनुयायी नमाज के लिए मस्जिद में एकत्र हुये थे । पाकिस्तान की अन्धाधुन्ध बम-वर्षा के कारण सैरुडों लोग या तो अकाल और अप्रत्याशित मृत्यु के शिकार हुये, या बेघरबार हो गये । पाकिस्तानी बमवर्षकों ने दो संयुक्त राष्ट्र के यानों को भी नष्ट कर डाला । पाकिस्तान में इतना भी अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य शेष नहीं रह गया था कि वह संयुक्त राष्ट्र-संघ के भी ध्वज को उचित सम्मान दे सके ।

युद्ध-विराम पर विश्व के प्रायः समस्त देशों ने सन्तोष व्यक्त किया ।

सितम्बर २८ का सुरक्षा-परिषदीय प्रस्ताव—सितम्बर २८, १९६५ को सुरक्षा-परिषद् ने सर्वसम्मति से पुनः अपने प्रस्तावों दिनांक ४, ६, और २० का पुष्टीकरण किया और भारत और पाकिस्तान को आह्वान किया कि वे सुरक्षा-परिषद् के युद्ध-विराम-सम्बन्धित प्रस्तावों पर अपनी पूर्व स्वीकारोक्तियों का अग्रसरण करें । इस प्रस्ताव में दिनांक सितम्बर २० के प्रस्ताव के क्रम में सेनाओं के प्रत्याह्वान पर बल दिया गया । भारतीय प्रतिनिधि ने सुरक्षा-परिषद् को बतलाया कि पाकिस्तान का आशय अब भी अगस्त ५, १९६५ की भाँति युद्ध की अग्नि भड़काने का है, जिससे कि उसके द्वारा तयामयित काश्मीर के प्रश्न का हल उसके हित में हो सके । उन्होंने परिषद् को यह भी सूचना दी कि भारत-पाकिस्तान की समूची सीमा पर पाकिस्तान उत्तेजनापूर्ण कार्यवाहियाँ कर रहा है और भारतीय सैनिकों पर गोलियाँ चला रहा है, और यह कि जम्मू और काश्मीर में सैन्य घुस-पैठियों ने अपनी कार्यवाहियों को समाप्त नहीं किया है, और यह कि पाकिस्तान इस सम्बन्ध में कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है । यही नहीं, पाकिस्तानी रेडियो उन्हें अपनी तोड़-फोड़ की कार्यवाहियाँ जारी रखने को उत्प्रेरणा देता जा रहा है । उनका कथन था कि ऐसी परिस्थिति में, परिषद् के लिये इस प्रश्न पर विचार करना कि सेनायें वापस बुलाई जाँय, व्यर्थ का समय गँवाना होगा ।

नवम्बर ५ का सुरक्षा-परिषदीय प्रस्ताव—नवम्बर ५, १९६५ को, फिर भी, सुरक्षा-परिषद् ने दूसरा प्रस्ताव पारित किया । इस प्रस्ताव का लक्ष्य यह था कि भारत-पाक-संघर्ष की स्थिति को सुलझाने की दिशा में परिषद् के पूर्वोक्त प्रस्तावों का अनुपालन किया जाय । इस बात पर भी बल दिया गया कि भारत और पाकिस्तान अपने-अपने प्रतिनिधियों के नाम घोषित करें जो कि ऊ-पाँ के प्रतिनिधि से मिलकर अगस्त ५ की स्थिति की वापसी की योजना तैयार करें ।



सोवियत सङ्घ एवं जोरडन ने मतदान नहीं किया। भारत ने परिषद् की बैठक का बहिष्कार इस आधार पर कर दिया कि यदि बैठक में जम्मू और काश्मीर के राजनैतिक प्रश्न पर विचार किया ही जाता है, तो वह इस बैठक की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

## भारत-पाक-संघर्ष का वैध पक्ष

(Legal Aspects of the Indo-Pak. Conflict)

**अघोषित युद्ध ( Undeclared War )**—भारत-पाक-राज्य संघर्ष में कुछ असाधारण विशेषताएँ रही हैं। ये विशेषताएँ साधारणतया युद्ध की विधियों और अभिसमयों से अनुशास्त नहीं हैं। युद्ध का संचालन आधुनिक शस्त्रास्त्रों से किया गया और पाकिस्तान की ओर से बहुत ही आधुनिकतम शस्त्र जैसे पैटन टैंक, सैबर जेटो, क्षेप्यास्त्र और १,००० पाउंड तक के बमों का खुलकर प्रयोग किया गया। ये सभी शस्त्र पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा दिये गये थे। इतने भयंकर और विनाशकारी शस्त्रों के प्रयोग और राष्ट्रपति अयूब के इस रेडियो प्रसारण के उपरान्त भी, कि 'हम युद्धरत हैं—We are at war' युद्ध अघोषित और अनौपचारिक ही रहा। क्षम्य क्षेत्र में तथा भारत की सम्ची सीमा पर चारों ओर से पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किये जान, तथा भारतीय सेना द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में जमकर सामना करने और युद्ध की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाने के बाद भी दोनों देशों के राजनयिक सन्धान ज्यों के त्यों बने रहे और उनके वापस बुलाने का प्रश्न किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक रूप में नहीं उठाया गया। फिर भी, रावलपिंडी में भारतीय दूतावास के लोगों के साथ जो दुर्घटनाएँ किये गये और उन्हें जित्त बन्धनों में रक्ष दिया गया, वे अत्यन्त ही कठोर तो थे ही, साथ ही अत्यन्त अमानवीय और अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के सम्बन्धों के विरुद्ध थे। युद्ध घोषित नहीं हुआ, फिर भी, पाकिस्तान-स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की अवैध तलाशी पाकिस्तानी पुलिस द्वारा की गई और उनकी सम्पत्तियों को बलात् छीन लिया गया। उनके परिवार को तब किया गया और अनेक अन्य अपमानजनक कृत्य किय गये।

## प्राइज कोर्ट की कार्यवाहियाँ

( Prize Court Proceedings )

युद्ध की औपचारिक घोषणा न की जाने के उपरान्त भी, पाकिस्तान ने भारतीय 'वार्षों' पर, जिसे कि उनमें अवैध रूप से पकड़ रखा था, प्राइज कोर्ट-कार्यवाही आरम्भ की, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय व्यापारिक पोत, जिसमें कि

जूट और चाय भरी हुई थी, ज्वत कर लेने का अवध आदेश किया गया। जूट और चाय का 'कार्गो' किसी भी प्रकार से विनिषिद्ध नहीं कहा जा सकता था। यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के लिये एक बहुत बड़ी प्रतिकूलता का कार्य था जिसके लिये पाकिस्तानी अधिनारी उत्तरदायी थे, क्योंकि दोनों देश औपचारिक रूप से युद्ध-सलग्न नहीं थे। यहाँ तक कि कतिपय विदेशी पोता को भी, जा कि व्यापारिक और नागरिक लक्ष्यों के लिये भारत आ रहे थे, पाकिस्तान ने मनमाने ढंग पर रोक लिया। यह सब कार्य किसी भी सम्य राष्ट्र के लिये उचित नहीं कहे जा सकते और न तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत प्रस्थापित अभिसमयों के अनुकूल ही कहे जा सकते।

नैपाम बमों का प्रयोग—जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, पाकिस्तान ने भारत के अधिकांश नागरिक लक्ष्य, अस्पतालों, मस्जिदों, गिरजा-घरों, आदि पर उपर्युक्त सघष में नैपाम-बमों जैसे आग्नेय शस्त्रों का खुलकर प्रयोग किया। यहाँ स्मरणीय है कि नभ युद्ध-कौशल के अन्तर्गत ऐसे बमों का प्रयोग निषिद्ध है। आश्चर्य का विषय है कि इसके उपरान्त भी अमेरिका ने पाकिस्तान में यह पूछने की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया कि उसके द्वारा दिये गये शस्त्रास्त्रों का इस प्रकार अन्तर्गल प्रयोग क्यों किया गया ?

संयुक्त राष्ट्र सघ, कालोचितता का एक माध्यम—उपयुक्त भारतीय सकट के समय संयुक्त राष्ट्र सघ एक प्रमुखपूर्ण स्वतन्त्र निकाय के रूप में अग्रने को न सिद्ध कर सका, अपितु महान् शक्तियों के नियन्त्रण को कालोचितता प्रदान कर देने वाला एक साधन मात्र ही बनकर रह गया। यहाँ तक कि सुरक्षा परिषद् में स्पष्ट परिस्थितियों को भारतीय प्रतिनिधि द्वारा सामने रखने, बार बार आग्रह करने और महासचिव द्वारा स्वयं परिस्थितियों का अवलोकन कर लेने के उपरान्त भी सघ अपने भाप में इतना साहस नहीं सँजो सका कि वह दोनों में से, जिस किसी को आक्रामक समझता, आक्रामक होने की घोषणा कर देता या नाम-निर्दिष्ट कर देता। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि सितम्बर २० का सुरक्षा परिषद् का प्रस्ताव, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के लिये युद्ध विराम का आदेश उपबन्धित था, स्वयं सुरक्षा-परिषद् का प्रस्ताव १९४९ का अतिरिक्त का स्वरूप था। वर्ष १९४९ के प्रस्ताव में यह निर्देशित था कि पाकिस्तान काश्मीर से अपनी सेना वापस बुला ले। इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि पाकिस्तान वहाँ पहले से ही आक्रामक की स्थिति में रहा है। पाकिस्तान ने १९४९ के प्रस्ताव का अनुपालन नहीं किया और काश्मीर में पन्द्रह वर्षों तक आक्रामक की स्थिति में बना रहा। सितम्बर २०, १९६५ का प्रस्ताव में दानो दशो

के बीच केवल युद्ध-विराम का निर्देश था। यदि इसका यह तात्पर्य हुआ कि पाकिस्तान अगस्त ५, १९६५ की स्थिति में रहकर भी, काश्मीर क्षेत्र में अपनी सेना रखे रहे, तो यह प्रस्ताव स्वयं वर्ष १९४६ के प्रस्ताव के विरुद्ध है।

आत्म-प्रतिरक्षा में भारतीय कार्यवाही—विगत वर्ष में भारत की ओर से की गई कार्यवाही पूर्णतः आत्म-प्रतिरक्षात्मक रही है। यह पाकिस्तान ही था जिसने कि छद्म-वेशी सेनिकों को काश्मीर में भेजा। यह पाकिस्तान ही था जिसने कि भारत-भूमि पर सशस्त्र सेनिकों द्वारा भारी संख्या में आक्रमण किया। यह पाकिस्तान ही था जिसने कि युद्ध की घोषणा किये बिना ही भारत के नगरों को ध्वस्त करने के लिये पहले अपने बम-वर्षकों को भेजा। भारत की ओर से की गई कार्यवाही प्रतिरक्षा और सीमा पर पाकिस्तान की आक्रामक कार्यवाहियों को रोक देने के उद्देश्य से प्रत्युत्तर रूप में की गई। यहाँ तक कि भारतीय सेना ने कहीं भी पाकिस्तानी जन-जीवन को न तो नष्ट किया और न तो कहीं भी भारतीय सेना या भारतीय बम-वर्षकों ने किसी भी पाकिस्तानी नगर पर बम-वर्षा की। इसीगिल नहर के चारों ओर भारतीय जवान लाहौर को घेरे खड़े रहे; भारतीय वायुयान और बम-वर्षक पाकिस्तानी सीमा के उस छोर पर पेशावर तक सैनिक भद्रों को नष्ट कर सकने में समर्थ हो सके; किन्तु कहीं भी पाकिस्तानी क्षेत्र में किसी नगर पर बम गिराये जाने का हठान्त सामने नहीं आया।

पाकिस्तान ने पाँच हजार सशस्त्र व्यक्तियों को, जो कि पाकिस्तानी सेना के व्यक्ति थे, नागरिकों के छद्म-वेश में भारत के काश्मीर-क्षेत्र में घुसाया। वे तोड़-फोड़ की कार्यवाही तथा काश्मीर के उच्च अधिकारियों को बरत करने के प्रयास में भेजे गये थे। पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से इन घुसपैठियों का अपनी ओर से भेजा जाना अस्वीकार किया और उसने यह घोषित किया कि काश्मीर की जनता भारतीय प्रशासकों के विरुद्ध विद्रोह कर बैठी है। उनकी इस भ्रान्तिपूर्ण उद्घोषणा का सहज सयुक्त राष्ट्र के मुख्य पर्यवेक्षक जेनरल निम्नो के प्रतिवेदन में किया गया, जिन्होंने स्पष्टतः कहा कि ये व्यक्ति युद्ध-विराम-रेखा पार कर आक्रमण के प्रयोजन से घुस आये थे। इस प्रकार पाकिस्तान १९४६ के युद्ध-विराम समझौते को भंग कर अन्तर्राष्ट्रीय अमर्याद का भागी था।

उपर पाकिस्तानी रेडियो और समाचार-पत्र भारत के विरुद्ध द्वेष उत्पन्न करने के जघन्य प्रचारों में सजे हुये थे, इधर पाकिस्तानी फौजें भारतीय सीमा पर आक्रमण हेतु बढ़ आयीं। पाकिस्तानी कार्यवाहियों से दिवंगत होकर अगस्त १६, १९६५ को भारतीय सेना ने विराम-रेखा के पार बजिल क्षेत्र में प्रतिरक्षा के उद्देश्य से तीन पाकिस्तानी योनियों को बन्ने में कर लिया। इन कार्यवाही का

का कारण यह था कि पाकिस्तानी निरन्तर जीवन प्रदायिनी श्रीनगर लेह-रेखा को काट देने के प्रयत्न में लगे हुये थे। यहाँ स्मरणीय है कि इही चौकियों को पहले भी १७ मई, को भारतीय जवानों ने अपने कब्जे में कर लिया था, किन्तु समुक्त-राष्ट्र के इस आश्वासन पर जून में रिक्त कर दिया था कि उसके पर्यवेक्षक पाकिस्तान की ओर भारतीय प्रतिरक्षा-रेखा पर होने वाले किसी भी आक्रमण को रोकेंगे। जबकि पाकिस्तान ने अपने आक्रमणों की शृंखला विराम-रेखा के पार गुलमार्ग, धम्ब, ऊरो, तिथवाल और नोसेरा क्षेत्रों तक विस्तारित कर दिया, तब विवश होकर भारतीय सेना को भी अगस्त २५, १९६५, को दो स्थानों पर विराम-रेखा को पार करना पड़ा और तिथवाल क्षेत्र में नई स्थिति प्रस्थापित करनी पड़ी। अगस्त २८ को भारतीय जवान विराम-रेखा के पार ऊरी क्षेत्र में घुसे, जिससे कि वे पाकिस्तानी सशस्त्र एवं भयंकर जमाव को रोक सकें और काश्मीर-घाटी में प्रवेश करने वाले पाक घुसपैठियों का रोक सक। दो दिन पश्चात् भारतीय सेना ने हाजीपीर दर्रे पर कब्जा कर लिया। यह दर्रा पाकिस्तानियों के काश्मीर-प्रवेश का मुख्य द्वार था। इसके साथ ही भारतीय जवानों ने १२३०० फीट ऊँची पहाड़ी बिदूर और कतिपय अन्य पाकिस्तानी चौकियों पर भी कब्जा कर लिया।

उपयुक्त पृष्ठभूमि के आधार पर ही भारतीय सैन्य शक्तियों ने अपनी सीमिन कायवाहियाँ अपनी सीमाओं की प्रतिरक्षा की दृष्टि से की। ये कार्यवाहियाँ समुक्त-राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद ५१ के उपबन्धों के अन्तर्गत पूर्णतः न्याय संगत थी। पाकिस्तान ने जब एक साथ काश्मीर, पंजाब और राजस्थान क्षेत्रों में बबरतापूर्ण आक्रमण कर दिया तब इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों के लिये दूसरा कोई माग शेष न रह गया कि वे लाहौर और स्यालकोट क्षेत्रों की ओर भागे बढ़। इधर चीन की प्रसामयिक चेतावनी ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों शत्रु भारत का दो मोर्चों पर एक साथ ही उलझा लेने के कुचक्र में हैं। अतः भारत के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह एक शत्रु की सैन्य शक्तियों पर प्रहार कर उसे निर्बल कर दे जिससे कि वह उससे बाद उससे भी प्रबल शत्रु की ओर पूरी शक्ति से अपने भाव को लगा सके।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, कुछ महान शक्तियाँ, जैसे समुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटन ने पाकिस्तान के इन दुष्टतापूर्ण कार्यों को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया और विश्व के परिवार में किसी न किसी प्रकार पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया। चीन, इण्डोनेशिया, टर्की और ईरान ने स्पष्टतः पाकिस्तान का समर्थन किया, और भारत के विरुद्ध हर प्रकार की सैनिक सहायता प्रदान करने

का आश्वासन दिया। परिस्थितियों को इस विभाषिका में पाकिस्तान को भारत-क्षेत्र के उपर और भी भयकर आक्रमण करने में रोक देने के अभिप्राय से यदि भारतीय सेना युद्ध विराम-रेखा के पार घुसी, तो उसने कोई भी विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया। प्रतिरक्षा की सक्रिय कार्यवाही के अन्तर्गत केवल इतना ही नहीं अपेक्षित है कि आक्रामक को अपनी सोमा से बाहर मार भगाया जाये, अपितु यह भी सन्निहित है कि वह बढ़कर अपने शत्रु को उसके घोंसले में ही नष्ट कर दे, जहाँ से कि शक्ति लेकर वह घाते की ओर बढ़ता आ रहा है।

मलायेशिया द्वारा भारत के पक्ष का समर्थन—भारत के कठिन सकट के समय, जबकि चीन, इण्डोनेशिया, टर्की और जॉर्डन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया, और ग्रेट ब्रिटेन एक संयुक्त राज्य अमेरिका ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान को समर्थन और बढ़ावा दिया, वहाँ मलायेशिया ने न्याय का पक्ष लेकर भारतीय हित का खुले शब्दों में समर्थन किया और सुरक्षा परिपद् के समक्ष भारत की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर दिया। भारत ने अपने विरुद्ध बोलने वालों और पाकिस्तान को खूली प्रशंसा गुप्त सहायता करने वाले किसी भी राष्ट्र के प्रति बैर-भाव नहीं स्थापित किया और उसके राजनयिक सम्बन्ध सभी देशों से ज्यों के त्यों बने रहे, और यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय सभी नियमों की अवहेलना कर जब इण्डोनेशिया में भारतीय दूतावास पर अनाचार के घटाटोप गिराये गये, तब भी, भारत शान्त होकर उन अनाचारों को सहता रहा, किन्तु पाकिस्तान ने इतनी भी अन्तर्राष्ट्रीय उदारता होप न रह गई थी कि वह किसी भी राष्ट्र द्वारा सुरक्षा-परिपद् में अपना विरोध और भारत का समर्थन सहन कर सके। परिणामतः पाकिस्तान ने मलायेशिया के साथ अपना दीर्घ-सम्बन्ध तोड़ लिया। एक कामनवेल्थ राष्ट्र के प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार पाकिस्तान ने किया, फिर भी, ग्रेट ब्रिटेन, जो कि कामनवेल्थ का जनक-स्थान है, पाकिस्तान को तोरियाँ गा गाकर डुलराता रहा और पाकिस्तान एक लड्डेते शिशु की भाँति जहाँ कहीं भी हाथ पैर मारता रहा, युद्ध की स्थिति उत्पन्न करता रहा।

पाकिस्तानी धम-धपकों द्वारा भारतीय जीवन पर घण्टाघात—हम उत्सेख कर चुके हैं कि भारतीय सेनाप्रा ने अपनी उपर्युक्त कार्यवाही में अपना सदैव केवल सैनिक महत्त्व के स्थानों का बनाया, उन्होंने कभी भी नागरिक जीवन को नष्ट नहीं किया। किन्तु, पाकिस्तान ने इसके ठीक विपरीत सभी मानवीय मान्यताओं के विपरीत शान्त नगरों, पूजा व स्थानों और अस्पतालों को अपना सदैव बनाया। ये कार्य सवया चरितार्थपूर्ण थे और सम्य राष्ट्रों व बीच मान्य युद्ध-विधियों के सर्वथा विपरीत थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान द्वारा इन अनीतिचारिक युद्ध में की गई वृत्तिपर्य कार्यवाहियाँ पिछले दो महान् विश्व-युद्धों में भी नहीं मुनी

गई थी। ऐसे नगरो पर, जिनका कोई भी सैनिक महत्व नहीं था, पाकिस्तान ने नृशंस रूप में नेपाम बमों, और यहाँ तक कि १०,०० पौंड तक वजन के विनाशकारी बमों का प्रयोग किया। पाकिस्तानी नम-शक्ति ने अम्बाला में सेण्ट पॉल्स केथोड्रल पर दो बार बम-वर्षा की—पहले आक्रमण ने गिरजाघर को नष्ट कर दिया और दूसरे ने उसे विलकुल ही चूर-चूर कर डाला। पाकिस्तान का सम्भवतः सबसे प्रबल अमानवीय कृत्य अस्पतालों और रेड-क्रास केंद्रों पर बम गिराना था। पूर्व में एक अस्पताल ध्वस्त कर दिया गया और अम्बाला सैनिक अस्पताल के घाट बाई घराशायी कर दिये गये। जोधपुर के जेन-अस्पताल को भी नष्ट कर दिया गया और फिरोजपुर में चार एंबुलेस गाड़ियाँ विधोर्ण कर दी गईं। पाकिस्तानी जहाजों ने भारतीय नागरिक जहाजों पर भी आक्रमण किये और ऐसे ही एक आक्रमण में गुजरात के मुख्यमन्त्री अपने परिवार-सहित मारे गये। ये सभी कृत्य पाकिस्तान की ओर से सम्बन्धपूर्ण राष्ट्रों द्वारा किये जाने वाले कार्यों और मान्यताओं की सर्वथा उपेक्षा के दृश्य थे। खेद का विषय है कि सुरक्षा-परिषद् ने पाकिस्तान द्वारा किये गये अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार-सहिता के उल्लंघन के कृत्यों को कभी भी अपने विचार-विमर्श का विषय नहीं बनाया और सितम्बर मास में पारित उनके विभिन्न प्रस्ताव पाकिस्तान और भारत को समान स्तर पर सबाक मानते रहे। सम्पूर्ण विश्व इस तथ्य को जानना है कि भारत ने कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, फिर उसे पाकिस्तान जैसे आक्रामक देश के समकक्ष मानना आज भी विचारशील राष्ट्रों के लिये एक आश्चर्य का विषय बना हुआ है।

परिणाम :—इन तथ्यों के होते हुये भी यह स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संधि ही एक वर्तमान ऐसा सक्षम और व्यापक यंत्र है जो विश्व में शान्ति स्थापित कर सकता है। इन थोड़े वर्षों के भीतर जो बर्लिन, तेहरान तथा प्रोस सम्बन्धी मामलों तथा जेरुसलम, काश्मीर की स्थिति, कोरिया, इजिप्ट और मन्त में हंगरी और कामो या कटागा के मामले के बारे में और जो विनाशकारी कार्य-वाहियाँ हुई हैं उनके धक्के को हमने सम्हाल लिया है। हमने प्रोस, काश्मीर, पैलेस्टाइन, इडोनेशिया और मिस्र की सोमनामा में पाँच युद्धों को रोक रखा है। हमने कोरिया में पुनः शान्ति स्थापित की है। हमने सीरिया, लेबनान, यमन तथा ईरान से विदेशी सेनाओं को हटाया है तथा बर्लिन की नाकाबन्दी के ओ भवरोध उत्पन्न हुआ था, उसे तोड़ा है। हमने जार्डन और सेबानान से विदेशी सेनाओं को हटा दिया है। विश्व की भाग्यें संयुक्त राष्ट्र संधि में उन आदर्शों की पूर्ति के लिये केन्द्रित हैं जिनके लिये संयुक्त राष्ट्र संधि स्थापित किया गया है, और शान्ति तथा

सुरक्षा की प्राप्ति और अपने निष्पक्ष और सार्वदेशिक दृष्टियों से मानव-मान के सर्वांगीण विकास का एक दीर्घ-स्तम्भ प्रमाणित हो सकता है। इसी और विश्व आशाभरी यात्रा से देख रहा है।

## अध्याय २८

### सामूहिक सुरक्षा ( Collective Security )

**लीग प्रतिज्ञा-पत्र ( League Covenant ) :—**प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १० के अन्तर्गत लीग के सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे लीग के सब सदस्यों की क्षेत्रीय एकता तथा वर्तमान राजनीतिक स्वतन्त्रता का सम्मान करेंगे तथा बाह्य भ्रष्ट-धर्म के विरुद्ध सरक्षण करेंगे। अनुच्छेद ११ के अन्तर्गत कोई युद्ध अथवा युद्ध की धमकी चाहे उसका प्रभाव लीग के किसी सदस्य पर तत्काल पड़ता हो अथवा नहीं सम्पूर्ण लीग के लिये एक चिन्ता का विषय थी तथा लीग से यह अपेक्षा की गयी कि वह राज्यों की शान्ति सुरक्षित रखने के लिये कोई कार्यवाही करे जो विवेक युक्त तथा प्रभावपूर्ण समझी जाय। कोई ऐसा सबूत उपस्थित होने पर सेक्रेटरी-जनरल से यह अपेक्षा की गई थी कि लीग के किसी सदस्य की प्रार्थना पर तत्काल परिपद की बैठक बुलायी जाय।

अनुच्छेद १२ के अन्तर्गत लीग के सदस्य इस बात पर सहमत थे कि यदि उनके मध्य कोई झगड़ा उठता हो, जिससे सम्बन्ध-विच्छेद की संभावना हो तो वे उस विषय को या तो पचायत अथवा न्यायिक निर्णय या परिपद द्वारा जांच के लिये प्रत्यर्पित करेंगे तथा वे इस बात पर भी सहमत थे कि वे किसी भी दशा में उस समय तक युद्धरत न होंगे जब तक पक्षों के निर्णय, न्यायिक निर्णय अथवा परिपद के प्रतिवेदन के उपरान्त तान मास न व्यतीत हो जाय। पक्षों का निर्णय अथवा न्यायिक निर्णय आवश्यक समय के भीतर दे देना चाहिये या तथा परिपद का प्रतिवेदन झगड़े के प्रत्यर्पण के उपरान्त छः महीने के अन्दर हो जाना चाहिये या।

अनुच्छेद १३ के अन्तर्गत लीग के सदस्य इस पर भी सहमत हुए कि जब कभी उनके मध्य कोई ऐसा झगड़ा उठता हो जिसे वे स्वीकार करें कि पचायत अथवा न्यायिक निर्णय के लिये प्रत्यर्पण करना उचित है, तथा आ कूटनीति के द्वारा सतोपजनक रीति से तय नहीं हो सकता हो तो वे सम्पूर्ण विवादपूर्ण विषय को पचायत अथवा न्यायिक निर्णय के लिये प्रत्यर्पित करेंगे।

अनुच्छेद १५ में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि लीग के सदस्यों के बीच सम्भवतः संघर्ष-विच्छेद में परिणत होने वाला कोई झगड़ा उत्पन्न हो जो अनुच्छेद १३ के अन्तर्गत पचायत अथवा न्यायिक निर्णय के लिये प्रवर्तित न किया गया हो तो लीग के सदस्य इस विषय पर सहमत थे कि वे उस विषय को परिषद् को निवेदित करेंगे ।

अनुच्छेद १६ में यह व्यवस्था की गई थी कि यदि लीग का कोई सदस्य लीग की प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १२, १३ अथवा १५ के अन्तर्गत प्रतिज्ञाओं की उल्लंघना करके युद्ध में प्रवृत्त हो तो उसके द्वारा स्वतः लीग के सब अन्य सदस्यों के विरुद्ध युद्ध करने वाला समझा जायगा । सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा की कि उससे तत्काल सब व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्धों का विच्छेद कर दिया जायगा, उनके राष्ट्रीयजनो तथा प्रतिज्ञा-भंग करने वाले राज्य के राष्ट्रीयजनों के बीच सब सम्पर्क तोड़ दिये जायेंगे तथा प्रतिज्ञा-भंग करने वाले राज्य के राष्ट्रीयजनों तथा किसी अन्य राज्य के राष्ट्रीयजनों के बीच सब सम्पर्क रोक दिये जायेंगे चाहे वे लीग के सदस्य हों अथवा नहीं ।

प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १७ के अन्तर्गत लीग के सदस्य तथा असदस्य अथवा असदस्यों के बीच के झगड़े में असदस्य राज्य अथवा समूह ऐसे झगड़े के प्रयोजनों के लिये लीग की सदस्यता के कर्तव्यों को स्वीकृत करेंगे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर ( Charter of the United Nations ) :—चार्टर के अध्याय ६ में झगड़ों की जाँच तथा शान्तिपूर्ण समाप्ति के विषय में विवरण दिया गया है । यह किसी ऐसे झगड़े के पक्षकारों पर जिसके जारी रहने से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिये संकट उत्पन्न होता हो यह कर्तव्य सौंपता है कि उसकी निवृत्ति प्रथमतः बातचीत, जाँच, मध्यस्थता, सार्वना, पचायत, न्यायिक निर्णय, क्षेत्रीय अभिकरणों के पास पहुँच कर अथवा उनसे प्रबंध करके अथवा किसी अपनी इच्छानुसार अन्य शान्तिपूर्ण उपायों से करे ।

चार्टर के अनुच्छेद ७ में शान्ति के लिये धमकी अथवा शान्ति-भंग होना का निर्णय करके सामूहिक सुरक्षा के लिये व्यवस्था की गई है तथा यह निर्णय किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करने के लिये कौन-सी सन्तुति अथवा उपाय का अवलम्बन किया जायेगा (अनुच्छेद ३६) । स्थिति का गंभीर आधिकारिक विवरण देने से रोकने के लिये सुरक्षा परिषद् सन्तुति करने अथवा उपायों का निर्णय करने के पहले सम्बन्धित पक्षकारों से यह माँग करे कि वे कुछ बाल के लिये ऐसे उपायों का अवलम्बन करे जैसा कि वह (सुरक्षा परिषद्) आवश्यक अथवा वांछित समझे (अनुच्छेद ४०) । यह इन बातों का निर्णय करे कि भ्रान्ति निर्णयों



को प्रभावित करने के लिये कौन से उपाय प्रयुक्त हो जिसमें सैनिक बलप्रयोग सम्मिलित नहीं है, तथा संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों से ऐसे उपायों का प्रयोग करने को कह सकती है। इनमें आर्थिक सम्बन्धों तथा रेल, समुद्र, वायु, डारु, तार तथा रेडियो और अन्य यातायात साधनों का पूर्ण अथवा आंशिक अवरोध तथा कूटनीति सम्बन्धों का विच्छेद भी सम्मिलित है (अनुच्छेद ४१)। यदि इसके विचार में अनुच्छेद ४१ में व्यक्त किये गये उपाय अपर्याप्त हो अथवा अपर्याप्त सिद्ध हो तो यह वायु, जल अथवा स्थल सेनाओं से ऐसे कार्य करवा सकती है जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थायी रखने अथवा पुनः स्थापित करने के निमित्त आवश्यक हो। ऐसे कार्यों में प्रदर्शन, नाकाबन्दी तथा अन्य संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों के वायु, जल अथवा स्थल सेनाओं द्वारा अन्य कार्य सम्मिलित हैं (अनुच्छेद ४२)।

संयुक्त राष्ट्र सभ के सब सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने में सहयोग देने के लिए यह प्रतिज्ञा की है कि वे सुरक्षा परिषद् के पास उसके द्वारा मगि जाने पर तथा विशिष्ट सविदा अथवा सविदाओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से आवश्यक सैन्य बल, सहायता तथा सुविधाये प्राप्त करायेंगे जिनमें जाने-जाने के अधिभार भी सम्मिलित हैं (अनुच्छेद ४३)।

जब सुरक्षा परिषद् बल प्रयोग करना निश्चित कर ले तो किसी सदस्य के जिसका प्रतिनिधित्व उसमें (परिषद् में) न हो, उससे सैन्य बल देने के लिये कहने के पूर्व उस सदस्य से यदि वह ऐसी इच्छा प्रकट करे तो उस सदस्य के सैन्य बल की टुकड़ियों को प्रयोग करने से सम्बन्धित सुरक्षा परिषद् के निर्णयों में भाग लेने को आमन्त्रित करे। संयुक्त राष्ट्र सभ को आवश्यक सैनिक उपायों के अवलम्बन करने योग्य बनाने के लिये सदस्यगण अन्तर्राष्ट्रीय हवाईदल की टुकड़ियों को संयुक्त राष्ट्रीय प्रवृत्तिकारी कार्यों के लिये प्राप्त करायेंगे। इन टुकड़ियों की शक्ति तथा तैयारी की सीमा तथा उनकी संयुक्त कार्यवाही की योजनाएँ मिलिटरी स्टाफ कमेटी की सहायता से सुरक्षा परिषद् द्वारा निश्चित की जायेगी। सैन्य बल प्रयोग की योजनाएँ मिलिटरी स्टाफ कमेटी की सहायता से सुरक्षा परिषद् द्वारा बनाई जायेंगी।

अन्त में अनुच्छेद ५१ में यह व्यवस्था की गई है कि यदि संयुक्त राष्ट्र सभ किसी सदस्य के विरुद्ध सैनिक आक्रमण हो तो चार्टर में दिया गया वैयक्तिक अन्तर्भूत अधिकार अथवा सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार में उस समय तक बन्दी होगी जब तक सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को स्थायी बनाये

रखने के लिये आवश्यक उपाय न कर ले । इस आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में सदस्यों द्वारा किये गये उपाय तुरन्त सुरक्षा परिषद् को प्रतिवेदिन किये जायेंगे, तथा वे किसी भी प्रकार से चार्टर के अधीन सुरक्षा परिषद् के अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा बनाये रखने अथवा पुनः स्थापित करने के निमित्त ऐसी कार्यवाही करने जैसे कि यह आवश्यक समझे, अधिकार तथा उत्तरदायित्व को प्रभावित न करेंगे ।

**सामूहिक सुरक्षा की असफलता (The Failure of Collective Security) :**—प्रतिज्ञा पत्र में जैसी शान्ति का लक्ष्य मानने था, उसको सुरक्षित रखने में लीग आफ नेशन्स असफल रही । सन् १९३१ में यह मछूरिया में चीन के विरुद्ध जापानियों के अग्रघर्षण को रोकने में असफल रही । सन् १९३५ में अबीसीनिया में इटली का आक्रमण हुआ तथा अबीसीनिया ने प्रतिज्ञा-पत्र के अनुच्छेद १० के अन्तर्गत लीग में अपील की । इस पर लीग ने इटली के विरुद्ध आर्थिक अनुज्ञाओं का प्रयोग किया, किन्तु उनके भिन्न-भिन्न अग्रभूत सदस्यों ने अपने कर्तव्यों का प्रतिपालन नहीं किया तथा अग्रघर्षक पर बलपूर्वक शान्ति रखवाने की लीग की कार्यवाही असफल रही । इटली लीग से अलग हो गया तथा उसने अबीसीनिया पर विजय प्राप्त की । राइनलैण्ड पर जर्मनी द्वारा सन् १९३६ में दखल किया गया । जर्मनी द्वारा आस्ट्रिया सन् १९३८ में तथा चेकोस्लोवाकिया सन् १९३९ में सयोजित कर लिया गया, किन्तु लीग अग्रघर्षक के विरुद्ध कोई प्रभावपूर्ण कार्यवाही नहीं कर सकी । जब रूस ने सन् १९३९ में फिनलैण्ड पर आक्रमण किया तो लीग असहाय अलग खड़ी रही । यह अपनी अप्रसन्नता केवल रूसी सरकार को निकाल कर ही प्रकट कर सकी । शान्ति की स्थापना करने में लीग की असफलता का भयकर दुःखद परिणाम द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ ।

युद्ध की रीतियों में वैज्ञानिक उन्नति के कारण द्वितीय विश्वयुद्ध के साथ नवीन समस्याएँ उत्पन्न हुईं । लोगों को परस्पर मिल-जुल कर शान्तिपूर्वक रहने के लिये एक प्रभावशाली साधन की व्यवस्था करने के लिये विश्व की आशाएँ तथा इच्छाएँ संयुक्त राष्ट्र सभ के चारों ओर केन्द्रीभूत हुईं तथा इसी आशा ने शान्तिप्रिय लोगों को शीतयुद्ध (cold war) तथा रूसी सत्तार और पश्चिमीय देशों के आदर्शवादों में सधर्प होते हुये भी जीवित रक्खा है । कभी-कभी अन्य देशों के लोगों के प्रति साद्भावना रखने की आवश्यकता विस्मृत हो जाती है और इसी कारण विश्व के देशों के दृष्टिकोण में विभिन्नता आ जाती है । इसी का परिणाम यह हुआ है कि क्षेत्रीय गठबन्धनों के द्वारा शान्ति की स्थापना करने के लिये व्यापक तथाग्रह-विश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है । संयुक्त राष्ट्र सभ की उपयोगिता का ठीक-

ठीक अनुमान लगाने के लिये हमको इसके किसी विशिष्ट समस्या का हल प्राप्त करने के लिये सफलता अथवा असफलता पर दृष्टिपात नहीं करना है वरन् यह देखना है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा बन्धुत्व स्थापित करने के लिये एक साधन है अथवा नहीं। निस्सन्देह इस बात के होते हुये कि इसका संगठन इसके सब सदस्यों की सार्वभौमिक समानता पर आश्रित है इसने विश्व-बन्धुत्व का भावना को कुछ अंश तक अवश्य उत्पन्न कर दी है।

सुरक्षा परिषद् को सन् १९५० में कोरिया में अग्रघर्षण तथा शान्ति-भंग के विरुद्ध प्रभावशाली सामूहिक उपाय किये जाने की अनुज्ञा देनी पड़ी तथा इसको अक्टूबर सन् १९५६ के अन्त में इजिप्ट के प्रदेश में इजरायली अग्रघर्षण को जिसमें बाद को आगल-फ्रांसीसी आक्रमण हुआ रोकने के लिये प्रभावपूर्ण पग उठाना पड़ा व भिन्न-भिन्न उपाय इससे पूर्व बहुत विस्तारपूर्वक वर्णित किये जा चुके हैं। यह पर इतना कहना पर्याप्त होगा कि संयुक्त राष्ट्र सच इन उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में शान्ति पुनः स्थापित करने तथा अग्रघर्षण को रोकने में बहुत ही सफल रहा है। कानो और कटागा के उथल-पुथल में भी इसकी सहायता देखी जा चुकी है।

शक्ति-संतुलन (Balance of Power) :—यह कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का झुकाव 'शक्ति-संतुलन' को 'सामूहिक सुरक्षा' (Collective Security) के रूप में परिणत कर देने की ओर है। इस प्रश्न पर विचार करते हुये हमें यह विचार करना ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र सच 'सामूहिक सुरक्षा' के प्रयोजन की पूर्ति में कहाँ तक सफल रहा है।

भूतकाल में, खासतौर से १८वीं और १९वीं शताब्दी में यूरोप की मुख्य शक्तियाँ अपने को यूरोपीय महाद्वीप के लिये भाग्य-विधायक प्राधिकार से युक्त मानती थीं। उन्होंने कम शक्तिशाली देशों पर एक प्रकार से अपना स्वत्व स्थापित कर रखा था और उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के निर्धारण के प्रश्नों के अन्तम विवाचक बन बैठे थे। उन्होंने बहुत से कान्सर्ट (concert), लीग (leagues), मैत्री सम्मन्ध (alliances) और इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं का निर्माण कर लिया था, किन्तु वास्तविकता यह थी कि इस उदार आचरण के पीछे यह भावना अवश्य विद्यमान थी कि कहीं कोई प्रबल शक्ति अकेली हो छोटे-छोटे राज्यों की शक्तियों पर उनके पारस्परिक झगड़ों में अपने स्वार्थों के हित में हावी न हो जाय। पारस्परिक अविश्वास और दूसरे राष्ट्रों की शक्तियों का अनुमान करके घातकित रहन की बात इन मामलों में शक्तियों वाले राष्ट्रों में विद्यमान था, और एकमात्र शक्ति-संतुलन के साधन के द्वारा या तथेव स्थिति बनी रहने (status quo) के सिद्धान्त के द्वारा वे ऐसा विश्वास कर लिया करते थे कि कोई राष्ट्र किसी दूसरे पर हावी होकर एकमात्र प्रभुत्वपूर्ण राष्ट्र नहीं बन सकेगा।

शक्ति सतुलन का प्रत्यक्षतः सिद्धान्त तो समान न्याय और प्रभुत्व की तथैव स्थिति बनी रहने का पोषक है। वस्तुतः छोटे राज्य लगातार बड़े राज्यों का अपने ऊपर आभार मानते रहे हैं कि उन्होंने उन्हें अन्य राज्यों से आक्रमण किये जाने की स्थिति में बचाने का आश्वासन दे रखा है और ऐसी स्थितियों में सहायता करने का भी प्रलाभन दे रखा है। किन्तु, बड़ी शक्तियों की इस सदाशयता का वास्तविक उद्देश्य बहुधा यह रहा है कि बड़ा सत्त्वा में राज्य उनके आश्रित बने रहे ताकि विश्व में प्रतिद्वन्द्वी रूप में कोई दूसरा राष्ट्र न खड़ा हो सके। यहाँ तक की बड़ी शक्तियाँ ने इन बातों को भा अपने अधीनस्थ रखा कि कौन-सा छोटा राज्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में व्यक्ति रूप में सामने आ सकता है, और यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को भंग करने या हस्तक्षेप व विशेषाधिकार, आदि की वे पूर्णतया अपने अधिकार में रखते थे और ऐसा वे इस परदे में किया करते थे कि घुसरीय महाद्वीप में शान्ति और सुरक्षा को बनाय रखने के उत्तरदायित्व का उन्हें ही निर्वाह करना है किन्तु वास्तविकता यह था कि यह सब आश्वासन और तर्क थोपे थे और इस आशय से गढ़े हुए थे कि युद्ध या आक्रमण की स्थिति में जा अस्त-व्यस्तना फैलेगी उससे कहीं कोई एक राज्य अकेले ही लाभ न उठा ले।

जहाँ तक राष्ट्रों की विधियों का सम्बन्ध है कल्पन न लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में सिद्धान्त रूप से "सामूहिक सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सभ का मुख्य उद्देश्य है और चार्टर के प्रतिबंधों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि इस उद्देश्य के पीछे बड़े पाँच राज्यों की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो अपनी राजनैतिक सम्प्रभुता के प्रयोग करने की अनुमति अन्य सदस्य-राज्यों पर दे सके और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र सभ के असदस्य राज्यों के लिए भी यही बात है। अनुच्छेद १ में व्यवस्था दी गई है कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखेगा और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह प्रभावकारी सामूहिक कार्यवाहियाँ के लिये दी जाने वाली धमकियों को राकेगा तथा आक्रमण की कार्यवाहियों को दबायेगा तथा शान्तिभंग होने की स्थिति को दूर करेगा और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रभावकारी और सामूहिक कार्यवाहियाँ करेगा जिससे कि शान्ति पर होने वाले आघातों को रोक जा सके और अक्रामक कार्यों का दबाया जा सके या शान्ति का भंग करने वाली अन्य स्थितियों पर अवरोध किया जा सके। चार्टर संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों का सामूहिक कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में बल-प्रयोग करने से स्पष्टः वर्जित करता है और अनुच्छेद २, पैराग्राफ ४ के अनुसार संयुक्त राष्ट्र व प्रजाजन की असंगत में किसी भी प्रकार के प्रयाजन से बचन-बद्धता दा है। अनुच्छेद २४ उपबन्धित करता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा तात्कालिक, समुचित और प्रभावकारी

कदम उठाये जाने का मुनिश्चय करने व उद्देश्य से इसके सदस्य सुरक्षा परिषद् को यह प्राथमिक उत्तरदायित्व सौंपत हैं कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखे। अनुच्छेद २१ यह भी उपबन्धित करता है कि सभी सदस्य-राष्ट्र इस चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद् द्वारा शान्ति और सुरक्षा की दिशा में किये गये निर्णयों का पालन करने को महमत है। यही नहीं, अनुच्छेद २, का पैराग्राफ ५, इस बात का भी उपबन्धित करता है कि वर्तमान चार्टर के अनुसार सयुक्त राष्ट्र द्वारा किये गये किसी भी वाय में, सभी सदस्य उनको सहायता करेंगे और ऐसे किसी भी राज्य को सहायता नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध सयुक्त राष्ट्र सच कार्यवाही कर रहा है, या करना आवश्यक मान रहा है।

चार्टर के मर्यादित उपबन्धों के सम्बन्ध में, जैसे अध्याय ६ जिसका सम्बन्ध झगड़ों की जाँच में है, और अध्याय ७ जिसका सम्बन्ध सामूहिक सुरक्षा के पापण से है, को पहले क प्रकरणों में चर्चा की जा चुकी है। इसके भागे अनुच्छेद ५१ यहाँ उल्लेखनीय है, क्योंकि यह अनुच्छेद उपबन्धित करता है कि इस चार्टर का कोई भी तत्व किसी सदस्य-राष्ट्र को यदि उस पर आक्रमण किया जाता है तो उस समय तक व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म प्रतिरक्षा के आत्मनिहित अधिकार से वंचित नहीं करेगा, जब तक कि सुरक्षा परिषद् ने ऐसे आवश्यक उपाय अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने की दिशा में न लिया हो। आत्म प्रतिरक्षा के अधिकार की रक्षा की दिशा में उठाये गये सदस्य-राष्ट्रों के कदम तुरन्त ही सुरक्षा परिषद् के समक्ष प्रतिवेदित होंगे और इन कदमों का किसी भी प्रकार चार्टर के अन्तर्गत सुरक्षा परिषद् को प्रदत्त प्राधिकार और उत्तरदायित्व पर भ्रम या प्रभाव न पड़ेगा और परिषद् इस बात के लिये किसी भी समय प्राधिकृत है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के पोषण के लिये वह जो भी कार्यवाही उचित समझे, कर सके।

तथ्यों के प्रबलोजन से पता चलता है कि चार्टर में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे ५ महान् शक्तियाँ छोटे राज्यों पर जो कि राष्ट्र सच के सदस्य हैं अपनी प्रभुता का प्रयोग कर सकें। शक्ति सतुलन के सिद्धान्त को पुनर्जीवित करने का प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि जो भी कार्यवाही की जाने को है राष्ट्र-सङ्घ उन ५ महान् शक्तियों के स्थान पर स्वतः किया करता है। यही नहीं बल्कि ऐसी परिस्थितियाँ जब कि सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता या पड़ती है, वैध धारणाओं पर निर्भर हैं जो कि जब कभी शान्ति भंग या आक्रमण के समय छोटी और बड़ी शक्तियों का कोई भेदभाव नहीं रहती। ऐसे सामूहिक कार्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को बनाये रखने तथा फिर से स्थापित करने के लिये बड़ी शक्तियों में से सभी के लिये भयवा सभी में से एक के हित के लिये नहीं किये जाते।

संयुक्त राष्ट्र सच सामूहिक सुरक्षा की स्थापना में कोरिया, स्वेजनहर, कांगा प्रादि के प्रसंगों में अपने प्रयत्नों में सफल रहा है। स्वेज के मामले में अक्टूबर १९५६ के अन्त में, जब कि इजरायली द्वारा मित्र-क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था, और फिर उस आक्रमण का अनुगमन ऐंग्लो फ्रेंच आक्रमणों ने किया था संयुक्त राष्ट्र सच ने आक्रमणों को रोक करारा और पुन शान्ति स्थापित की। सोवियत-संघ भी हंगरी के आन्तरिक मामला में हस्तक्षेप करने से रुकने को इस विश्व-संगठन द्वारा प्रेरित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लेबेनान और ग्रेट-ब्रिटेन द्वारा जुलाई १९५८ में जार्डन के मामलों में हस्तक्षेप के प्रसंग में भी इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र सच प्रभावकारी रहा। कांगो के संकट में अन्त-युद्ध के कारण छिन्न-भिन्न हुये राज्य की पुन शान्ति व्यवस्थित करने में भी बहुत अधिक सफल रहा है।

क्षेत्रीय समझौते (Regional Pacts) — इस स्थान पर यह उपयुक्त होगा कि उन विभिन्न क्षेत्रीय समझौता का निर्देश किया जाय जिन्हें उनके पक्षकारों द्वारा विश्वशान्ति के आधार पर व्यापकित ठहराया गया है। संयुक्त राष्ट्र सच का चार्टर ऐसे क्षेत्रीय समझौता अथवा अभिकरणों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता जो प्रादेशिक कार्यवाही के लिये उचित अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना से सम्बन्धित विषयों के निपटाने के लिये हों, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे प्रबन्ध अथवा अभिकरण संयुक्त राष्ट्र सच के प्रयोजनों तथा सिद्धान्तों के अनुरूप हों (अनुच्छेद ५२)। इसमें सदेह नहीं कि चार्टर के अनुबन्ध सरल है क्योंकि वे संयुक्त राष्ट्र सच के प्रयोजनों तथा सिद्धान्तों से सगत प्रादेशिक गठबन्धों को दृष्टि में रखते हैं, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बचाने तथा सुरक्षा करने के निमित्त मूलसंस्था की तुलना में सीमित सच स्वीकृतियों पर अधिक महत्व दिया गया है। ये सचीकरण "शक्ति-सन्तुलन" के पुनरुत्थान सिद्ध हुये हैं, तथा इनके द्वारा विश्वव्यापी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धान्त को अपित विश्वसंघ को निम्नतर स्तर में उतारा गया है।

'नाटो' या उत्तरी अटलांटिक संधि सङ्गठन (The North Atlantic Treaty Organization) :—यह अप्रैल ४, सन् १९४९ को चारह राज्यों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में बीस वर्ष की प्रतिज्ञात अवधि के लिये इस भाष्य से हस्ताक्षरित किया गया कि प्रजातन्त्र, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, तथा विधि के नियम पर आधारित उनकी जनता की स्वतन्त्रता, सामान्य पैतृकता तथा सम्यता सुरक्षित रह सके। ८०० ए० टी० ओ० के बारह मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, ग्राइसलैण्ड, इटली, लक्जेमबर्ग, नीदरलैंड्स, नार्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड

किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका थे। ग्रीस तथा इटली फरवरी मन् १९५२ में सम्मिलित हुये। पश्चिमी जर्मनी का प्रवेश 'नाटो' परिषद् द्वारा मई ५ मन् १९५५ को प्राधिकृत किया गया।

संगठन इस शब्द के वास्तविक अर्थ में क्षेत्रीय प्रबन्ध नहीं है क्योंकि इसमें ऐसे देश सम्मिलित हैं जिनमें भौगोलिक प्रादेशिकता नहीं है, जैसे इटली, ग्रीस और टर्की। यह एक गठबन्धन है जिसका उद्देश्य साम्यवादो रूस का पश्चिम की ओर फैलना बन्द करना है तथा इस दृष्टि से यह एक आत्मरक्षा की पद्धति है अथवा मेल है। इसके अतिरिक्त यह एक सामूहिक सुरक्षा की पद्धति केवल उन्हीं भिन्न भिन्न राज्यों के आन्तरिक सम्बन्धों के विषय में है जिन्होंने परस्पर सैन्य कर रक्खा है। किन्तु जहाँ तक यह अन्य राज्यों अथवा राष्ट्रों की पद्धतियों के विरुद्ध लड़ाना है, इसे सैनिक मेल के परिचित वर्ग में समझना चाहिये। यह बात उत्तरी अटलांटिक संधिपत्र के अनुच्छेद ५ में स्पष्ट कर दी गई है—“पक्षकार इस बात पर सहमत होते हैं कि यूरोप अथवा उत्तरी अमेरिका में उनमें से एक अथवा अधिक के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण उन सबके विरुद्ध आक्रमण समझा जायेगा। अतः वे इस बात पर सहमत होते हैं कि यदि इस प्रकार का सशस्त्र आक्रमण हो तो उनमें से प्रत्येक संयुक्त राष्ट्र सभ के चाटर के अनुच्छेद ५१ द्वारा स्वीकृत वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में, उस पक्षकार अथवा पक्षकारों को जिन पर इस प्रकार आक्रमण किया जाय, उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में सुरक्षा पुन स्थापना करने तथा बनाये रखने के निमित्त ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह आवश्यक समझे, जिसमें सशस्त्र बल-प्रयोग सम्मिलित है, वैयक्तिक रूप से तथा अन्य पक्षकारों के साथ मिल कर सहायता करेगा।

११ दिसम्बर १९५६ को १५ राज्यों के अटलांटिक पैक्ट कोसिन के अधिवेशन में मिस्टर डलेस अमेरिका के राष्ट्र सचिव ने चेतावनी दी कि विश्व बहुत ही सकट-पूर्ण स्थिति में रहा है और सङ्घ अपनी सैनिक शक्ति बनाये रखे। निस्संदेह इसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही हो। तभी वे लोग इससे निश्चित रह सकते हैं कि लाल सेना कर्टेक जो बुड पेस्ट में गये, वे पश्चिमी यूरोप में नहीं जायेंगे।

सन् १९४७ का रियो पैक्ट (The Rio Pact, 1947) -- इस “Inter-American Defence Treaty of Reciprocal Assistance”, अर्थात् आन्तरिक अमेरिका सुरक्षा एवं पारस्परिक सहायता सन्धि भी कहा जाता है। यह एक सामूहिक सुरक्षा नियम पत्र है जो चाटर के अनुच्छेद ५१ के अन्तर्गत एक अनिश्चित काल के लिये किया गया है तथा जो पारस्परिक सहायता की अन्तर-अमेरिकी संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर सितम्बर २ मन्

१९४७ को रियो डे जेनीरा में हस्ताक्षर किये गये । यह संधि सभी अमेरिकीय राज्यों के लिये खुली हुई है । इस संधि में एक परामर्श का अंग उत्पन्न किया है जिसमें हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के जिन्होंने संधि का सत्यापित किया है, दो-तिहाई मतों से निर्णय लिये जाते हैं । अनुच्छेद ३ में यह व्यवस्था की गई है कि किसी अमेरिकीय राज्य के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण अमेरिका के सब राज्यों के विरुद्ध आक्रमण समझा जायगा तथा उनमें से प्रत्येक ने यह प्रतिज्ञा की है कि वह वैयक्तिक अथवा सामूहिक प्रातरक्षा के अधिकार के प्रयोग में उसका विरोध करने में सहायता करेगा ।

डनकर्क संधि (Dunkirk Treaty) — उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में अन्त-संधि डनकर्क संधि है जो फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम के मध्य ४ मार्च सन् १९४७ को ५० वर्ष के लिये की गई । इसमें यह व्यवस्था की गई है कि (प्र) जर्मनी द्वारा सशस्त्र आक्रमण किये जाने पर, (प्रा) जर्मनी द्वारा अग्रघर्षण सरल करने के लिए कार्यवाही किये जाने पर या अग्रघर्षण की नीति धारण किये जाने पर, (इ) समुक्त राष्ट्र संधि की सुरक्षा परिषद् द्वारा जर्मनी के विरुद्ध प्रवर्तक कार्यवाही किये जाने पर जर्मनी के साथ युद्ध छिड़ने की दशा में हस्ताक्षर करने वाले अपनी शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सैनिक तथा अन्य सहायता तथा सहायता प्रदान करेंगे । इनमें आर्थिक सहयोग के लिये निरन्तर परामर्श करने की व्यवस्था की गई है ।

सन् १९४८ की ब्रसेल्स की संधि (The Brussels Treaty, 1948) — आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहकारिता तथा सामूहिक आत्मरक्षा की संधि मार्च १७ सन् १९४८ को ब्रसेल्स में ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, लक्जमबर्ग तथा नीदरलैंड्स द्वारा पश्चिमी यूरोप में सामूहिक सुरक्षा प्राप्त करने के हेतु हस्ताक्षरित की गई । संधि में प्रतिज्ञा की अवधि ५० वर्ष है । संधि के अनुच्छेद ४ में यह व्यवस्था की गई है कि “यदि उच्च सविदाकार पक्षकारों में से कोई यूरोप में सशस्त्र आक्रमण का लक्ष्य हो तो अन्य उच्च सविदाकार पक्षकार समुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर के अनुच्छेद ५१ के उपबन्धों के अनुसार उस पक्षकार का जिस पर आक्रमण किया जाय, यथाशक्ति सब प्रकार की सैनिक तथा अन्य सहायता देगा ।” पश्चिमी शक्तिवादी ने एक यूरोपीय परिषद् बनाई है जिसमें परामर्श के लिये वैदेशिक मंत्रियों की एक समिति है ।

यूरोपीय सुरक्षा समुदाय (European Defence Community) — एक संधि जिसे यूरोपीय शिक्षा समुदाय कहते हैं, ६ देशों से निर्मित थी जिसमें फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, बेल्जियम तथा लक्जमबर्ग थे । संधि पर २७ मई १९५२ को हस्ताक्षर किये गये । इसके अनुसार छहों देशों की एक सम्मिलित सुरक्षा सेना बनने की थी और यह सगठन नाटो में पूर्ण एकाकी सगठन के रूप में



सम्मिलित होने को था। फ्रांस को पालियामेन्ट ने इस संधि को मानने से इन्कार कर दिया जिससे १९५४ में संधि विश्रल्लित हो गई।

**ऐन्जु पेक्ट (Anzus Pact) :—**यद्यपि आरम्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका किसी पैसिफिक सुरक्षा पैक्ट के विरुद्ध था जो कि नार्थ एटलांटिक ट्रीटी के समकक्ष हो, १९५० में एशिया में जो घटनाएँ घटी उससे अमेरिका ने भी अपना विचार बदला। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रुमन ने १८ अप्रैल १९५१ को एक बयान दिया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया और न्यूजिलैंड के बीच के सुरक्षा पैक्ट के सम्बन्ध में था और कहा कि "आस्ट्रेलिया और न्यूजिलैंड की सरकारों ने आपस में और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव किया है जो संयुक्त राष्ट्र की चार्टर धारा ५१ और ५२ के अनुकूल है। इससे स्पष्ट होगा कि किसी संश्लेषण के समय में जो कि इनमें से किसी पर भी पैसिफिक क्षेत्र पर किया गया तो ये तीनों शक्तियाँ खतरे का मिल कर सामना करेंगी और प्रभावकारी और पारस्परिक सहायता को जारी रखते हुये सुरक्षा को दृढ़ रखेंगी।" जून १९५१ को यह स्वीकार कर लिया गया और मैन फ्रांसिस्को में १ सितम्बर १९५१ को इस पर हस्ताक्षर किये गये।

**दक्षिण-पूर्वी एशिया सामूहिक प्रतिरक्षा संधि अथवा मनिला पैक्ट (South-East Asia Collective Defence Treaty or Manila Pact):—** सन् १९५४ में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र सचिव मिस्टर डलेस ने दक्षिण-पूर्वी एशिया में कम्युनिस्टों का बढ़ना रोकने के लिये एक शान्तिपूर्ण प्रादेशिक गठबन्धन का प्रस्ताव किया। उनी साल सितम्बर के महीने में मनिला में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें आस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजिलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा तीन एशियाई प्रदेश अर्थात् फिलिपाइन, थाईलैंड तथा पाकिस्तान सम्मिलित थे। सम्मेलन ने ८ सितम्बर सन् १९५४ को दक्षिणपूर्वी एशिया सामूहिक प्रतिरक्षा संधि स्वीकृत की तथा पक्षधारों ने यह प्रतिज्ञा की कि यदि किसी सदस्य पर आक्रमण किया जाय तो वे प्रतिरक्षा के लिये संयुक्त हो जायेंगे अथवा कोई अन्य क्षेत्र जो सदस्यों के एकमत से सहमत होने पर अपने सामान्य प्रतिरक्षा पक्ष में सम्मिलित कर लें। संधि के अन्तर्गत सामोन, मलेशिया तथा ब्रिटेन के तीन राष्ट्रों का भाग जो कम्युनिस्ट नहीं था, अर्थात् दक्षिणी ब्रिटेन तथा इन्डोनेशिया के तीन राष्ट्रों की रक्षा का यह गठबन्धन एवं प्रतिरक्षा के लिये मेन है जिसमें नाटो (NATO) के राष्ट्र कोई संयुक्त सैनिक बल नहीं है। संधि की प्रतिज्ञा की अथवा प्रतिरक्षा के नाम के लिये है लेकिन एच. व. की नोटिस देने पर कोई भी पक्षकार परिणाम में घनग हो सकता है।

**अमेरिका-जापान पैक्ट (U. S.-Japanese Defence Pact) :—** संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान के बीच ८ सितम्बर सन् १९५१ को अनिश्चित काल के लिये एक संधि की गई जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि जापान पर बाहर से आक्रमण हो अथवा बाह्य शक्ति अथवा शक्तियों के अभिप्रेरण अथवा हस्तक्षेप द्वारा किये गये भीषण रूप के क्रान्ति तथा उपद्रव हो तो जापान का सहायता प्रदान की जाय। इस संधि के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका उपर्युक्त समानताओं में तथा सामान्यतः सुदूर पूर्व में शान्ति तथा सुरक्षा स्थापनार्थ भूमि, वायु तथा समुद्रीय बल को जापान में तथा उसके चारों ओर लगाने का अधिकार रखता है। जापान संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वीकृति बिना पहले प्राप्त किये किसी तीसरी शक्ति को बढ़ा-बढ़ाने अथवा सेना रखने अथवा यातायात का अधिकार नहीं दे सकता।

**बाल्कन पैक्ट (Balkan Pact) :—** ६ सितम्बर सन् १९५४ को २० वर्ष की प्रतिज्ञा की अवधि के लिए ग्रीस, टर्की तथा यूगोस्लाविया के मध्य संधि हुई तथा उसमें एक अथवा अधिक हस्ताक्षर करने वालों के विरुद्ध सैनिक अप्रवर्धन की दशा में सैनिक तथा अन्य सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

**फ्रांस तथा लीबिया के मध्य मैत्री संधि (Treaty of Friendship between France and Libya) :—** उत्तरी अफ्रीका के प्रदेश में १० अगस्त १९५५ को मित्रता की संधि की गई तथा उसमें उस क्षेत्र में युद्ध अथवा युद्ध की धमकी की दशा में सब प्रकार की सैनिक तथा अन्य सहायता की व्यवस्था की गई। संधि में फ्रांस को कुछ सुविधायें देने की व्यवस्था उपलब्ध है। संधि की अवधि २० वर्ष की है किन्तु यह १० वर्ष के उपरान्त पुनः समीक्षा की जाने को है।

**इजिप्ट-सीरिया प्रतिरक्षा पैक्ट (Egypt-Syria Defence Pact) :—** यह गठबन्धन २० अक्टूबर सन् १९५५ को पाँच वर्ष के लिये किया गया। इसमें सशस्त्र आक्रमण की दशा में समस्त प्रकार की सैनिक तथा अन्य सहायता की व्यवस्था की गई है। एक सर्वोच्च परिषद् संगठन की गयी है जिसमें दोनों सरकारों के वैदेशिक तथा प्रतिरक्षा मन्त्री होंगे और उसके साथ एक युद्ध-परिषद् होगी जिसमें दो चीफ्स आफ स्टाफ होंगे जो सर्वोच्च परिषद् के लिये एक परामर्शदात्री सस्था होगी। इसमें सब उपलब्ध सैन्य बलों के लिये एक संयुक्त कमान (Joint Command) की व्यवस्था है।

**सामूहिक सुरक्षा की सोवियत पद्धति (The Soviet System of Collective Security) :—** कम्युनिस्ट देश भी द्विपक्षीय संधियों की धेड़ों में आबद्ध हैं जो पश्चिमी बहुमुखी संधिदात्रों में मिश्र हैं। इस प्रकार सोवियत संधि प्रायः

मभी बम्पूनिस्ट देशों से पारस्परिक सहायता की संधियों में सबद्ध है, उदाहरणार्थ यूगोस्लेविया, पोलैंड, रूमानिया, जेकोस्लावाकिया, हंगरी, बल्गेरिया तथा पोलैंड और ये देश स्वयं पारस्परिक सहायता के पैक्टों से सम्पन्न हैं। इन द्विपक्षीय संबि-  
दाओं से सोचियत संध तथा उनके अनुयायियों के मध्य मास्को के लिये केवल एक  
साइन ही स्थापित नहीं हो जाती वरन् ये साइनें मक्की के जाले के समान इसी  
प्रकार की अन्य संधियों से पार करती हैं जिससे "जनता के प्रभातन" परस्पर  
सम्बद्ध हो जाते हैं। (Barbier : Introduction to the Law of Nations,  
p. 318).

मित्रता सम्बन्ध तथा पारस्परिक सहायता की संधि (Treaty of  
Friendship, Alliance and Mutual Assistance) — यह संधि यू० एस०  
एस० आर० तथा सेंट्रल पीपुल्स गवर्नमेन्ट आफ चाइना के मध्य १४ फरवरी सन्  
१९५० को ३० वर्ष की अवधि के लिये की गई। इसमें जापान अथवा जापान के  
मित्र किसी अन्य राष्ट्र द्वारा मलख आक्रमण की दशा में पूर्ण सैनिक तथा अन्य  
सहायता की व्यवस्था की गई है।

वारसा सन्धि अथवा पूर्वोच्च यूरोपीय सन्धि संघ (Warsaw Treaty  
or East European Treaty Organization) — मई १४, १९५५ को वारसा  
में एक पूर्वोच्च यूरोपीय संधि संध का जन्म नियमित रूप से हुआ जब आठ यूरोपीय  
राज्यों के बीच जिनको पीपुल्स रिपब्लिक आफ चाइना का समर्थन प्राप्त था, मित्रता-  
सहयोग तथा पारस्परिक सहायता के निमित्त बीस वर्ष की अवधि के लिये संधि  
समाहित की गई। इसके सदस्य अल्बेनिया, बल्गेरिया, जेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी,  
हंगरी, पोलैंड, रूमानिया तथा यू० एस० एस० आर० है। संधि में उस पर हस्ता-  
क्षर करने वाले राज्यों के सैन्यबलों के संयुक्त कमान की व्यवस्था की गई है। आठ  
दलों के सैन्यबलों के संयुक्त कमान का मुख्यालय (headquarter) मास्को में होगा  
तथा उसके सर्वोच्च पदाधिकारी सोवियत संध के मार्शल आई० एस० कोनोव, होंगे।  
हस्ताक्षर करने वाले देशों के प्रतिरक्षा मंत्री अथवा अन्य सेनानायक डिप्टी कमांडर  
इन चीफ नियुक्त किये गए तथा उनको अपने-अपने देश द्वारा संयुक्त कमान में दिये  
गये सैन्यबलों का समादेशक नियुक्त किया गया।

अमेरिका-फिलिपाइन्स पारस्परिक प्रतिरक्षा संधि (U. S. Phil-  
ippines Mutual Defence Treaty) — संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फिलि-  
पाइन्स के बीच ३० अगस्त सन् १९५१ को संधि समाहित हुई तथा इसमें व्यवस्था  
की गई है कि पैसिफिक क्षेत्र में अथवा किसी भी पक्षकार पर सशस्त्र आक्रमण की  
स्थिति में पारस्परिक सहायता प्रदान की जाय। संधि अनिश्चित अवधि के  
लिये है।

**अरब लीग (Arab League) .**—यह अरब राज्यों का एक मंडल है जो २२ मार्च सन् १९४५ को अनिश्चित काल की अवधि के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य अरब देशों की परस्पर एकता को बनाये रखना है। लीग के सदस्य इजिप्ट, ईराक जोर्डन, सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, येमेन तथा लीबिया हैं। यह एक क्षेत्रीय पद्धति है जो आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग तथा सामूहिक आत्म-रक्षा के लिये संगठन की गई है। यह संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के अन्तर्गत सविदाकार पक्षकारों पर पड़ने वाले किसी भी अधिकार तथा कर्तव्यों को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती।

**बगदाद पैक्ट (Baghdad Pact) .**—यह गठबन्धन मध्यपूर्व प्रदेश में सुरक्षा स्थानार्थ हुआ। यह २४ फरवरी सन् १९५० को सम्पादित हुआ और इसके सदस्य ईराक, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान तथा ईराक थे जिनमें यूनाइटेड किंगडम सबसे अधिक शक्तिशाली था। संधि की अवधि पाँच वर्ष है किन्तु संधि पुनः नवीन की जा सकती है। इसमें सविदाकार पक्षकारों में से एक या अधिक के विरुद्ध सशस्त्र भयपूर्ण प्रयत्न उसकी धमकी की स्थिति में पारस्परिक सैनिक सहायता को व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य इस प्रदेश से सोवियत सभ के प्रभाव को छुड़ाना था किन्तु इस गठबन्धन द्वारा सोवियत सभ का ध्यान मध्यपूर्व में और अधिक आकर्षित हुआ है तथा यह एक बड़ा कारण बना जिससे पश्चिमी एशिया के देश परस्पर ही एक दूसरे से भिड़ गये हैं। मित्र ने इस गठबन्धन का विरोध इस आधार पर किया है कि अरब समार की प्रतिरक्षा अरब देशों की सामूहिक सुरक्षा गठबन्धन से निकलनी चाहिये जिसमें बड़ी शक्तियों को भाग न लेना चाहिये तथा यह कि अरबों को ऐसा कोई मेल स्वीकार न करना चाहिये जो सामूहिक सुरक्षा गठबन्धन के क्षेत्र से बाहर जाता हो। मित्र न यह दावे के साथ व्यक्त किया कि बगदाद पैक्ट ने ईराक को यथार्थ में ब्रिटेन का उपनिवेश तथा ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र का भाग बना दिया है।

१९५८ की जुलाई के मध्य में ईराक गणतन्त्र घोषित हुआ और जनरल नूरी एल सईद के शासनान्तर से मुक्त हुआ। ईराक की नयी सरकार ने २४ मार्च १९५९, को बगदाद पैक्ट से अलग होने की घोषणा भी कर दी।

बगदाद पैक्ट का नाम अब बदलकर केंद्रीय संधि संगठन अर्थात् "Central Treaty Organization" कर दिया गया है। यह परिवर्तन ईराक के पैक्ट से अलग हो जाने के कारण हुआ है। इस परिवर्तन को सदस्य देशों ने अगस्त १९५९ में स्वीकार कर लिया।

संयुक्त राज्य अमेरिका और टर्की तथा ईरान और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता समझौता —नेटो, सीटा, एन्जु और बहुपक्षीय सैनिक

संधियों के अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रकार से द्विपक्षीय समझौते (Bilateral Pacts) का भी नेतृत्व करता है जिसमें समझौते के अन्तर्गत आने वाले राज्य की आवश्यकता के समय में अमेरिका को ओर से सहायता की शर्त रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रकार के द्विपक्षीय समझौता में मुख्यतः राष्ट्रवादी चीन, कोरिया, जापान, फिलिपाइन्स और पाकिस्तान के साथ सम्मिलित हुआ है।

तथ्यों के अध्ययन और प्रलेखों के अवलोकन से पता लगता है कि सबसे निकटवर्ती समझौते के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को केवल आर्थिक और सैनिक सहायता ही नहीं करते रहेगे, बल्कि उसको प्रार्थना पर पाकिस्तान की सरकार को संयुक्त राज्य की सेना की भी सहायता मिलेगी किन्तु यह सहायता पाकिस्तान पर बाहरी आक्रमण के समय होगी।

### आर्थिक और राजनैतिक सहकारिता

बेनेलक्स (Benelux) :—आर्थिक और राजनैतिक सहकारिता के द्वारा भी शक्ति स्थापित करने के प्रयत्न बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जेंबर्ग के बीच समझौते द्वारा हुए है जिसे बेनेलक्स कहते हैं।

यूरोपीय आर्थिक सहकारिता संघ (Organization of European Economic Co-operation) :—इस संज्ञक को आईसी (O. E. E. C.) का नाम से पुकारते हैं। यह १९४८ में यूरोपीय राज्यों के कार्यों को मार्शल प्लान के साथ एकबद्धता में बाँधने के लिये किया गया था। इसका मुख्य कार्य EPU अर्थात् European Payments Union के रूप में दिखाई पड़ता है।

अमेरिकी राज्यों का संघ (The Organization of American States) :—इसे OAS भी कहते हैं। नगोटा की बैठक में १९४८ में पान-अमेरिकी संघ तथा अमेरिकी गणतन्त्र के बीच व्यापार की उन्नति के लिये किया गया था। OAS सदस्यों को आर्थिक, वैश्व और सांस्कृतिक क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

शूमन प्लान या यूरोपीय कोयला व लोहा समुदाय (The Schuman Plan or the European Coal and Steel Community) :—६ मई १९५० का फ्रांस की ओर से प्रस्ताव किया गया कि यूरोप में कोयले और लोहे से संबन्धित समुदाय पर राजनीतिक नियन्त्रण रखा जाय। १८ अप्रैल १९५१ को पेरिस में फ्रांस, जर्मनी के संघीय गणतन्त्र, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जेंबर्ग के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

कोलम्बो योजना (The Colombo Plan) —यह एक क्षेत्रीय सम्मेलन है जो एशिया के देशों के बीच म ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्यों को सम्मिलित करते हुये तकनीकी सहायता हेतु किया गया है ।

परिणाम (Conclusion) —मिश्र में इसरायल और आंग्ल-फ्रांसीसी तथा हंगरी में रूसी सेनाप्रा के आक्रमण के कारण जो हाल में दुःखद घटनाये हुई हैं उनसे सैनिक भैत्री तथा गठबन्धनों को निरर्थकता स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई है । जन-सम्पत्ति न इतना उपलब्ध धारण कर लिया कि प्रत्येक सम्प्रघर्षक को उपयुक्त देशों से पीछे हटना पड़ा । पण्डित नेहरू ने २० दिसम्बर सन् १९५६ को न्यूयार्क में समुक्त राष्ट्र सच की सभा में भाषण देते हुए कहा कि विश्व की सम्पत्ति, जो मुख्यतः समुक्त राष्ट्र सच की सभा तथा अन्य स्थानों में प्रकट हुई है, एक प्रमुख तथ्य है जो भविष्य में सम्भवतः किसी राष्ट्र द्वारा सदाचार के पथ से इस प्रकार के व्यतिक्रम को रोकेंगे तथा प्रत्येक देश को चाहे वह सन्न हो भयवा निबल, विश्व-सम्पत्ति को क्रुद्ध करने वाले किसी कार्य को करने क पूरा वा धार विचार करना पड़ेगा । अपने भाषण को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि यह भारत का लक्ष्य है जैसा प्रत्येक विवेकयुक्त व्यक्ति का होना चाहिए कि विश्व में शान्ति रहे । इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि 'शीतयुद्ध' नहीं होना चाहिये । यदि हम 'शीतयुद्ध' नहीं चाहते तो उसका अवश्यम्भावी परिणाम यह है कि हमको अपने शान्ति के विचार का पुराने सैनिक संस्थापनों, गठबन्धनों तथा मेलों पर आश्रित न रखना चाहिये ।

'शीतयुद्ध' का परिणाम यह हुआ है कि राज्यों के बड़े-बड़े सैनिक गुट बन गये हैं जिनमें से प्रत्येक अपने को प्रतिरक्षा का गुट कह कर दूसरे से भयभीत रहता है । इस प्रकार के किसी भी प्रतिरक्षा गुट को प्रवृत्त यह हातो है कि उनके परिणामस्वरूप अन्य देशों के मस्तिष्क में आक्रमणकारी गुट का प्रभाव उत्पन्न होता है तथा दोनों गुट एक दुश्चक्र (vicious circle) में पड़ जाते हैं ।

छोटे राज्य बड़ी शक्तियों से भयभीत रहते हैं जब कि बड़ी शक्तियाँ सुरक्षा सम्बन्धी विषयों को समुक्त राष्ट्र सच की परिधि के बाहर विशेष सम्मेलनों में विवेचना करती हैं । यह आलोचना मान्य है कि बड़ी शक्तियाँ सैनिक भैत्री करके समुक्त राष्ट्र सच को फतराकर निकल जा रही हैं । प्रादेशिक गठबन्धनों का सामान्यतः यह लक्ष्य होना चाहिये कि वे उन समस्याओं को विवेचना कर जो एक विशेष प्रदेश में समान हो तथा उसमें उन शक्तियों को सम्मिलित न करना चाहिये जो भौगोलिक प्रादेशिकता के लिए विदेशी हो । जीवन का स्तर उच्च करने के लिये भयवा मानवीय कल्याण के लिये जो गठबन्धन हैं जैसे Benelux तथा

अथवा कोलम्बो योजना ठीक दिशा में है तथा प्रोत्साहन के

मन्त्री पंडित नेहरू ने इस विचार पर विशेष महत्व दिया कि तत्त विश्व की आवश्यकता पचशील में विश्वास रखने में है। सिद्धान्त जो इसमें समावेशित हैं वे ये हैं :—प्रत्येक के प्रादेशिक एवम् तथा सार्वभौमिकता के लिये पारस्परिक समादर, अग्रघर्षण न करना, प्रत्येक के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता, पारस्परिक लाभ तथा शान्तिपूर्वक साथ-साथ रहना। नाटो ( NATO ), सामूहिक सुरक्षा की रूढ़ी पद्धति, संयुक्त राज्य अमेरिका का पाकिस्तान के साथ सहायता का गठबन्धन अथवा बगदाद पैक्ट के रूप में गठबन्धन शान्ति के दूत नहीं हैं बरन् यह विचार किया जाता है कि उनसे युद्ध का बीज-वपन ही अधिक होता है।

## अध्याय २६ निःशस्त्रीकरण ( Disarmament )

आज निःशस्त्रीकरण की समस्या ने अत्यधिक प्रमुखता प्राप्त कर ली है। इसके कारण हैं युद्ध के नवीन शस्त्रों के आविष्कार। आग्नेय और विप्लव शस्त्र विनाशकारी हैं। यहाँ तक कि तापवृष्टि (thermo-nuclear) विस्फोट से मानव जाति ही का समूलोच्छेद हो सकता है। निःशस्त्रीकरण की समस्या ने आज विश्व के प्रमुख राजनीतिज्ञों का ध्यान विशेषरूप से आकर्षित किया है। प्रश्न है कि अपनी भावी मानव-सन्तान को युद्ध के भयंकर उत्पात से किस प्रकार बचाया जाय।

सैन्यदलों का अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण तथा उनको कम करने का विचार सर्व-प्रथम सन् १८६६ में रूस के जार द्वारा धामनित एक शान्ति-सम्मेलन में उठाया गया। शान्ति-सम्मेलन की सुरक्षिता में नियुक्त की गई विशेषज्ञों की एक समिति ने यह प्रतिवेदन किया कि वह सेना तथा नौसेना के कम करने के विषय में सहमति प्राप्त करने के अपने प्रयासों में असफल रहो है। दूसरा शान्ति-सम्मेलन जो सन् १९०७ में बुलाया गया वह शस्त्रों के कम करने के सम्बन्ध में एकरस नहीं हो सका।

लीग ऑफ नेशन्स :—प्रथम विश्वयुद्ध ने निःशस्त्रीकरण प्राप्त करने की परमावश्यकता को सामने रखा। लीग के प्रतिज्ञापत्र के अनुच्छेद ८ में यह स्वीकृत

किया गया है कि शान्ति की स्थापना में यह अपेक्षित है कि राष्ट्रीय अस्त्र-शस्त्रों को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से जितना कम हो सके उतना कम किया जाय । लीग-परिपद् से यह अपेक्षा की गई कि वह विभिन्न सरकारी के विचार के लिये तथा कार्यरूप में परिणत करने के लिये इस प्रकार कमी किये जाने की योजनाएँ बनावे । लीग के सदस्यों ने यह प्रतिज्ञा की कि वे अपने अस्त्र-शस्त्रों के परिमाण अपने सैनिक, नौसैनिक तथा हवाई कार्यक्रमों तथा अपने ऐसे उद्योगों की दशा के सम्बन्ध में जो युद्ध सहज प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं, सूचनाओं का परस्पर पूर्ण और स्पष्ट आदान-प्रदान करेंगे । निश्चय किया गया था कि अपेक्षित स्पीडितियों की पूर्ति के लिये परिपद् को मंजूर देने के लिये एक प्रायोगिक निर्मित किया जाय ।

सन् १९२१ में नियुक्त किये गये एक आयोग ने यह मिळान्त निर्धारित किया कि कोई योजना उस समय तक कार्य नहीं कर सकती जब तक कि प्रत्येक राष्ट्र उसमें सहयोग न दे । ऐसा निश्चय किया गया कि सभी राष्ट्रों को प्रत्येक ऐसे देश की सहायता करनी चाहिये जिस पर किसी अन्य देश ने आक्रमण कर दिया है । ये सिद्धान्त लीग सभा द्वारा सन् १९२२ में स्वीकृत किये गये तथा एक पारस्परिक सहायता की प्रस्तावित संधि का मसौदा सन् १९२३ में सैनिक रहस्यों को पूर्णरूप से प्रकट करने, सदस्यों की सर्वव्यापकता, सामूहिक सुरक्षा इत्यादि के आधार पर तैयार किया गया । किन्तु यूरोप के राष्ट्रों के लिये संधि के मसौदे में दी गयी ऐसी प्रबल आकांक्षापूर्ण योजना पर सहमत होना कठिन था, अस्तु लीग आफ नेशन्स के समाप्त होते ही यह योजना लुप्त हो गई ।

**जेनेवा सम्मेलन :—**सन् १९३२ में ६१ राष्ट्रों का सम्मेलन जेनेवा में हुआ जिसमें कुछ दलों के निषेध जैसे वायुयानों से गिराये जाने वाले बमों अथवा गुब्बारों, दलों को सीमित करने की आवश्यकता, दल के कारबार के अन्तर्राष्ट्रीय निरोधण तथा दल सम्बन्धी बजटों के प्रकाशन के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त हुई, किन्तु भिन्न-भिन्न राष्ट्र अपनी-अपनी स्वीकृतियों को कार्यरूप में पूर्ण करने में असफल रहे ।

जब लीग की पता चला कि जर्मनी पुनः शस्त्रोकरण के लिये उन्मत्तना से प्रयास कर रहा है तो उसने निःशस्त्रीकरण-वृद्धि के अपने प्रयत्न त्याग दिये ।

**संयुक्त राष्ट्र संधि :—**द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी वार्तालाप समुक्त राष्ट्र संधि के भीतर तथा बाहर समुचित उत्साह के साथ चलता रहा । संयुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर के अनुच्छेद २६ में सुरक्षा परिपद् को यह प्राधिकृत किया गया है कि वह दलों को नियमित करने के लिये एक पद्धति स्थापित



करने के निमित्त योजनाये बनावे जो समुक्त राष्ट्र सघ के सदस्यों को निवेदित की जाये। चार्टर के हस्ताक्षरित किये जाने के शीघ्र ही उपरान्त तथा द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति के ठीक पहले अणुबम के आविष्कार ने निःशस्त्रीकरण के प्रश्न को और भी अधिक महत्व दे दिया।

**आणविक शक्ति आयोग — (Atomic Energy Commission):—**  
समुक्त राष्ट्र सघ की सामान्य सभा न जनवरी २४ सन् १९४६ को आणविक शक्ति को शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के निमित्त नियन्त्रण तथा राष्ट्रों द्वारा उत्पन्न तथा कपट से बचाने के निमित्त निरीक्षण रूप से प्रभावपूर्ण सुरक्षा के हेतु सुझाव देने के लिये एक आणविक शक्ति आयोग स्थापित किये जान के लिये एक प्रस्ताव स्वीकृत किया। दिसम्बर १३ को अपने प्रथम प्रतिवेदन में आयोग ने यह व्यवस्था किया कि आणविक शक्ति के नियन्त्रण की प्रभावपूर्ण पद्धति अन्तर्राष्ट्रीय होनी चाहिये तथा एक प्रवर्तक बहुपक्षीय संधि अथवा प्रतिज्ञा-पत्र द्वारा स्थापित होनी चाहिये जो अपनी पारी में समुक्त राष्ट्र सघ के भीतर स्थित एक अन्तर्राष्ट्रीय अग अथवा अभिकरण द्वारा अधिशासित तथा संचालित हो।

सितम्बर ११ सन् १९४७ को आयोग ने सुरक्षा परिषद् को अपना दूसरा प्रतिवेदन निर्वाचित किया तथा आणविक शक्ति के नियन्त्रण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण के कृत्य तथा शक्तियों पर बिजिट्ट सुझावों की रूपरेखा दी जिनमें निम्न-लिखित आधारभूत सिद्धान्त प्रकट किये गये हैं :—

(१) आणविक शक्ति के उत्पादन तथा प्रयोग सम्बन्धी निर्णय राष्ट्रों के हाथों में नहीं छोड़ने चाहिये।

(२) आणविक शक्ति के उत्पादन तथा प्रयोग सम्बन्धी नीतियाँ जो वास्तव में विश्व की सुरक्षा को प्रभावित करती हो उन सिद्धान्तों के अनुशासित होनी चाहिये जो सन्धि अथवा प्रतिज्ञा पत्र में स्थापित हो जिनको अभिकरण को पूर्ण करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

(३) राष्ट्र सन्धि या अभिसमय में प्रतिज्ञा करे कि वे अभिकरण को अपने राज्य-क्षेत्र के किसी भी हिस्से का निरीक्षण करने का अधिकार देते हैं, भले ही यह निरीक्षण उचित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं और सीमाओं से प्रतिबन्धित हो।  
सन् १९४८ में साधारण सभा ने आयोग के प्रतिवेदनो पर विचार किया तथा ४ नवम्बर सन् १९४८ को यू० एम० एस० प्रार० का यह प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया कि आणविक शस्त्रों का निषेध तथा आणविक शक्ति पर प्रभावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापना के लिये एक प्रतिज्ञा-पत्र का मसौदा तैयार किया जाय। सभा ने आयोग के सामान्य नियमों को स्वीकृत किया। मुख्य कठिनाई यह

है कि सयुक्त राज्य अमेरिका अपने अधिकार में इस समय तक बनाये गये जितने धम हैं उनको छोड़ने तथा अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की प्रतिभूति दिये बिना उनका बराबर उत्पादन जारी रखने का कार्य रोकने के लिये उद्यत नहीं है। दूसरी ओर रूस अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की योजना में स्वीकृत करने के लिये प्रस्तुत नहीं है जो उसके अनुसार मार्क्सवादीयता के सिद्धान्त के लिये अपमानजनक है।

साधारण सभा १८ नवम्बर २३ सन् १९४६ को सरकारों से कहा कि वे आणविक शस्त्रों का प्रभावपूर्ण निषेध करने तथा उन्हें हटाने का प्रयास करें। इसने आयोग के स्थायी सदस्यों में निवेदन किया कि वे अपने परामर्श जारी रखें तथा आयोग और सभा को अपनी प्रगति से अवगत कराते रहें।

साधारण सभा के सन् १९५० के पाँचवें अधिवेशन में बारह व्यक्तियों की एक समिति इस विषय पर विचार तथा प्रतिवेदन करने के निमित्त गठित की कि आणविक शक्ति आयोग तथा लौकिक शस्त्र आयोग का कार्य किस प्रकार एकीकृत किया जाय। बारह की समिति ने सितंबर २८ सन् १९५१ को यह सन्तुष्टि की कि आणविक शक्ति आयोग तथा लौकिक शस्त्र आयोग को सँपे गये कार्य को आगे बढ़ाने के लिये सभा एक नया आयोग स्थापित करे और यह कि नये आयोग की स्थापना होने पर ये दोनों आयोग छुट हो जाय।

शस्त्रों का नियमन तथा न्यूनिकरण :—दिसम्बर १४ सन् १९४६ को साधारण सभा ने सन्तुष्टि दी कि सुरक्षा परिषद् शस्त्रों तथा सेनाओं को तत्काल सामान्य नियमन और न्यूनिकरण के लिये आवश्यक व्यावहारिक उपायों पर विचार करे। सभा ने यह भी सन्तुष्टि दी कि सुरक्षा परिषद् चार्टर के अनुच्छेद ४३ में यथा व्यवस्थित सैन्यबल को अपने अधीन रखने के उपायों को शीघ्रता से लागू करे। उपर्युक्त उद्देश्य-प्राप्ति के लिये सुरक्षा परिषद् ने १३ फरवरी सन् १९४७ को एक आयोग लौकिक शस्त्रों के सम्बन्ध में बनाया। अगस्त १२ सन् १९४८ को आयोग ने दो प्रस्तावों को स्वीकृत किया। प्रथम में सुझाव था कि सामूहिक विनाश के शस्त्रों की परिभाषा में स्वयं विस्फोटक शस्त्र, शस्त्र जिनमें रेडियो क्रियाशील पदार्थ हो, प्राणघातक रासायनिक तथा कीटाणु शस्त्र सम्मिलित होने चाहिये। दूसरे प्रस्ताव में शस्त्रों तथा सैन्यबलों के नियमन तथा न्यूनिकरण को अधिशासित करने वाले निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्त समावेशित थे —

(१) शस्त्रों तथा सैन्यबलों के नियमन तथा न्यूनिकरण सम्बन्धी किसी भी पद्धति में समस्त राष्ट्र अन्तर्गत होने चाहिये।

(२) ऐसी पद्धति को प्रभावपूर्ण बनाने के निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास तथा सुरक्षा होनी चाहिये, किन्तु शस्त्रों का नियमन तथा न्यूनकरण और विश्वास की विद्यमानता परस्पर सम्बद्ध हैं।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास तथा सुरक्षा के लिये आवश्यक शर्तों में चार्टर के अनुच्छेद ४३ के अन्तर्गत स्वीकृतियों की एक पर्याप्त पद्धति, आणविक शक्ति का प्रभावपूर्ण नियन्त्रण तथा जर्मनी और जापान के साथ व्यवस्था सम्मिलित हैं।

(४) चार्टर के अनुच्छेद २६ के अनुरूप होने के लिये ऐसी पद्धति के अन्तर्गत तथा सैन्यबल को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना हेतु जितना सङ्गत हो तथा परिस्थान करने योग्य न हो, उसने ही पर सीमित कर देना चाहिये तथा उनको सदस्यों के कर्तव्यों को पूर्ण करने और चार्टर के अन्तर्गत उनके अधिकारों के संरक्षण के लिये जितना आवश्यक हो, उससे अधिक न होना चाहिये।

(५) इनका पालन निश्चित करने के लिये ऐसी पद्धति में पर्याप्त बचाव देना चाहिये जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की एक स्वीकृत पद्धति भी सम्मिलित है।

(६) उल्लंघन की दशा में प्रभावपूर्ण प्रवृत्ति के लिये व्यवस्था होनी चाहिये।

दिसम्बर ५ सन् १९४६ को सभा ने सदस्य-राष्ट्रों द्वारा अपने लौकिक शस्त्रों तथा सैन्य बलों के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना निवेदित तथा स्थापित करने का आयोग के प्रस्तावों को स्वीकृत किया।

सन् १९५० में साधारण सभा की पाँचवें अधिवेशन के मध्य कोरिया का युद्ध जारी था तथा "प्रतिरक्षा उपाय" के रूप में शस्त्रों के ढेर पर ढेर लग रहे थे। सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें अग्रघर्षक के विरुद्ध तत्परता से कार्यवाही करने को कहा गया था तथा जैसा पहले कह दिया गया है बारह व्यक्तियों की एक समिति इस बात को विचार करने तथा दूसरे अधिवेशन में प्रतिवेदन करने के लिये स्थापित की गई कि आणविक शक्ति आयोग तथा लौकिक शस्त्र आयोग के कार्य को एकीकृत करने के लिये क्या रीति तथा साधन उपयोग में लाये जाय तथा क्या वे इस बात पर सम्मति देगे कि उनके कृत्य परस्पर मिला दिये जाय तथा एक नये और एकीकृत नि शस्त्रीकरण आयोग के अन्तर्गत कर दिये जाय।

बारह व्यक्तियों की समिति नवम्बर २८ सन् १९५१ का छठवाँ सभा से सन्तुष्टि की कि दोनों आयोगों के कार्य का भाग बढ़ाने के लिये एक नया नि शस्त्रीकरण आयोग स्थापित किया जाय तथा यह कि नये आयोग के स्थापित

होने पर दोनों प्रायोग विसर्जित कर दिये जायें। सभा ने जनवरी सन् १९५२ में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का यह सिद्धान्त स्वीकृत किया जिसमें नये प्रायोग व पथ-प्रदर्शन के लिये कुछ सिद्धान्तों के सुझाव दिये गये थे। रूस का यह सशोधन अस्वीकृत कर दिया गया कि सत्र प्राणविक सस्थापनों का सरकाल निरीक्षण किया जाय तथा सामान्यतः एक-तिहाई दस्र घटा दिमें जाय।

नये नि.राष्ट्रीकरण प्रायोग का अधिवेशन फरवरी ४ सन् १९५२ में हुआ तथा निम्नलिखित विषयों के अध्ययन के लिये एक प्रांसीसी योजना स्वीकृत की गई जैसे सब दस्र तथा सैन्यबलों का प्रकटीकरण तथा सस्थापन जिसमें प्राणविक तथा अन्य सामूहिक पिनाशकारी दस्रों का हटा देना सम्मिलित है तथा इस हटा दिये जाने को निश्चित करने के लिये नियन्त्रण, सामान्य दस्रों की परिमितता तथा ममभीता के गोपनीय उत्सर्जन को रोकने के लिये नियन्त्रण भी हैं। कार्य की योजना पर सहमति होने पर भी प्रायोग इस बात पर एकमत नहीं हो सका कि कार्यों का क्रम (order of steps) क्या रहे।

सामान्य सभा के सुझाव पर मई तथा जून सन् १९५४ में लन्दन में प्रमुख रूप से सम्बन्धित पाँच राष्ट्रों अर्थात् कनाडा, फ्रांस, यू० ए० ए० आर०, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के जो स्थायी सदस्य भी हैं के प्रतिनिधियों की एक बैठक एकमत से समस्या का हल जात करने के लिये हुई। इसका परिणाम उत्साहजनक नहीं हुआ। नवम्बर ४ सन् १९५४ को सभा ने एकमत से पाँचों शक्तियों के पुनः वार्तालाप के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। सन् १९५५ में वार्तालाप पुनः आरम्भ की गई। सोवियत सङ्घ ने न्यूक्लियर (अणु) दस्रों (nuclear weapons) के निषेध तथा अधिक से अधिक सेनाये तथा लौकिक दस्रों के रक्खे जाने के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से कार्य करने के विषय में एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा कम्युनिस्ट चीन दस, लाख से पन्द्रह लाख तक, लेकिन ब्रिटेन तथा फ्रांस केवल ६,५०,००० तथा अन्य सब देश डेढ़ लाख से दो लाख तक सशस्त्र दलों को रख सकते थे। शिखर सम्मेलन (Summit Conference) आ जुलाई सन् १९५५ में सरकारी के अध्यक्षों के मध्य हुआ उसमें प्रेसीडेंट आइजनहोवर ने हवाई निरीक्षण द्वारा अपनी "छुले आकाश" वाली योजना को सामने रक्खी। यू० ए० ए० आर० इस योजना से सहमत नहीं हुआ और इसके बदले उसने अपनी पूर्व यात्रना को दुहराया।

गत सम्मेलन में उठाई गई समस्याओं की विवेचना के लिये पाँचों सरकारों के वैदेशिक मन्त्रियों की बैठक जेनेवा में अक्टूबर २७ सन् १९५५ को हुई, किन्तु वे भी किसी प्रकार से सहमत नहीं हो सके।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की नि शस्त्रीकरण उप समिति की बैठक सन् १९६४ तथा मई ४ सन् १९६६ क मध्य हुई । ब्रिटेन तथा फ्रांस की सरकारों ने कार्य बाहियों का भारम्भ जून सन् १९६४ की मूल आग्न-फ्रासीसी योजना का पुनः सशोधित पाठान्तर उपस्थित किया जिसमें सोवियत सरकार के गत प्रस्तावों को सन्तुष्ट करने के लिये व्यवस्था थी । सोवियत प्रतिनिधि ने पुनः सशोधित आग्न फ्रासीसी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और उसके बदले व्यावहारिक सैन्यबल तथा व्यावहारिक शस्त्रों को विस्तृत रूप से कमी की व्यवस्था करने वाली एक योजना निवेदित की किन्तु उसमें यूक्लिडर शस्त्रों को पूर्णतः गणना से बाहर रखा । यद्यपि इसमें कुछ विषय आग्न फ्रासीसी योजना के समान थे किन्तु नियंत्रण संगठन के कृत्या तथा क्षतियों के सम्बन्ध में रूसी सरकार तथा ग्रेट ब्रिटेन की सरकार के मध्य महत्वपूर्ण मतभेद था । रूसी सरकार ने मित्रों के हवाई निरीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करना अस्वीकार किया जा कि यदि निरीक्षण विमान क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण होता तो आवश्यक समझा जाता ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के नि शस्त्रीकरण आयोग के १२ राष्ट्रों की बैठक में, जो न्यूयार्क में १२ जुलाई, सन् १९६६ को हुई तत्कालीन भारतीय मंत्री श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने जो और यूक्लिडर परीक्षणों पर निषेध सबंधी भारतीय दृष्टिकोण को महत्व देने के लिये इसके समक्ष उपस्थित थे, कहा कि भारत ब्रिटेन के विस्फोटों को सीमित करने के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं कर सकता क्योंकि सीमित चाहे किसना ही किया जाय फिर भी विनाश की शक्ति बची ही रहेगी ।

श्री मेनन ने भारत की ओर से सप्ताह के नि शस्त्रीकरण के लिये निम्न लिखित पग उठाये जाने का सुझाव दिया ।

(अ) बमों के उत्पादन के लिये विकीर्ण होने वाला विस्फोटक पदार्थ और अधिक प्राप्त न होने दिया जाय । यदि परीक्षण रोक दिये जाय तथा कोई नया बम न बनाया जाय तो यूक्लिडर शस्त्रों के लिये कोई और उपयोग न रह जायगा क्योंकि वे पुराने हो जायेंगे और पुराने नमूने को कोई नहीं चाहता ।

(आ) संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत सङ्घ के सन्देशरहित न्यूक्लियर नि शस्त्रीकरण की ओर साकेतिक पग के रूप में कुछ सीमित सख्या के शस्त्रों को तोड़ने व निये हो जाना चाहिये तथा विकीर्ण हानि वाले विस्फोटक पदार्थों को नाशितपूर्ण प्रयोजन के लिये लगा देना चाहिये ।

(इ) सैनिक बजटा न वह चाह छोड़ा ही क्यों न हो, कुछ बची होनी चाहिये ।

रूस की शिखर नि शस्त्रीकरण सम्मेलन के लिये पुकार :- नवम्बर १७ सन् १९५६ को रूस न प्रेसीडेंट ब्राइजनहोवर की "छुते आवाज" वाली निरीक्षण योजना को सीमित रूप से स्वीकृत करत हुय तथा उत्तरीय अटलांटिक सन्धि बनन वाली शक्तिया तथा कम्युनिस्ट बारसा गठबन्धन बनने वाली शक्तियों के मध्य अग्रघपण न होने के गठबन्धन का मुझाव देते हुये चारो बड़ी शक्तिया तथा भारत की एक "शिखर नि शस्त्रीकरण सम्मेलन" की पुकार की। साविगत सरकार ने यह प्रस्ताव किया कि यूरोप के पूर्वी पश्चिमी किनारे के दानो ओर जो प्रदेश हैं ओर जहाँ पर नाटो (NATO) तथा बारसा गठबन्धन वालो के मुख्य सैन्य दल रहते हैं, उनकी हवाई फोटोषाफी की जाय।

प्रेसीडेंट ब्राइजनहोवर ने श्री निकोलाई बुल्गानिन के नवम्बर १७ सन् १९५६ क पत्र के उत्तर मे अपने जनवरी २ सन् १९५७ के दिनांकित पत्र में कहा कि यह ऐसी बड़ी शक्तियों के सम्मेलन का समय नहीं है तथा यह कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ क ढाँचे के भीतर विचार विमर्श से यह प्रतीत होता है कि बहुत सम्भव है कि नि शस्त्रीकरण क अत्यन्त जटिल विषय मे एक पग आगे बढ़ा जाय। मार्शल बुल्गानिन क यूरोप मे हवाई निरीक्षण मध्य क्षेत्र स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव के विषय में प्रेसीडेंट ने ध्यान किया कि यद्यपि शस्त्रों की समस्या के सम्बन्ध मे रूस की हवाई निरीक्षण को सद्देशरहित तथ्य के रूप मे विचार करने की इच्छा आशाजनक थी, फिर भी रूसी सरकार की घोषणा इस विषय पर यह इच्छा व्यक्त नहीं करती कि यह प्रेसीडेंट ब्राइजनहोवर के जेनेवा प्रस्ताव अर्थात् अचानक आक्रमण को उनके सैनिक शक्ति क वेदों के निरीक्षण द्वारा रोकने के आचारभूत तत्त्व पर सहमत होना चाहती है।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के नि शस्त्रीकरण क आयोग की पाँच राष्ट्रीय उपसमिति जो कि साधारण सभा क १९५३ के प्रस्ताव के अनुसार गठित हुई थी, ने १९५७ क मार्च से सन्धन में अपनी बैठक आरम्भ की। रूस द्वारा तीन प्रस्ताव सामने लाये गये। वे निम्नलिखित हैं—(१) सभी प्रकार के आणुविक परीक्षण दो या तीन वर्ष के लिये स्थगित कर दिये जाय। (२) एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग नियुक्त किया जाय जो कि इस बात का निरीक्षण करे कि परीक्षणों का स्थगन किया गया है या नहीं। (३) संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मे हर वैज्ञानिक यन्त्रों से युक्त एक नियन्त्रण केन्द्र खोला जाय जो कि अमेरिका, रूस, इङ्ग्लैंड, ओर पैसिफिक क्षेत्र मे एक स्थगन समझौता करा सके।

६ नवम्बर १९५७ को संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक समिति न संयुक्त पारित्य प्रस्तावों को स्वीकार किया। भारत की ओर से रखे गये मुझाव भी माने



(ग) वे शक्तिशाली जिनके पास न्यूक्लियर शस्त्र हैं, इस क्षेत्र के विरुद्ध इन न्यूक्लियर शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे ।

(घ) दूसरे राज्य इस क्षेत्र के भीतर जिनकी सना है वे भी इसी प्रकार का आभार ग्रहण करेंगे ।

३—भाग दा के आभारों का पुष्ट करने के लिये संबंधित राज्य एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे इन क्षेत्र में न्यूक्लियर शस्त्रों का विस्तृत और प्रभावकारी रूप से नियंत्रण हो सक ।

नाटो के सुप्रीम कमांडर नारस्टड ने मध्य यूरोप में न्यूक्लियर मुक्त क्षेत्र उत्पन्न करने का विरोध किया । उनका कहना था कि इससे नाटो की शक्ति और पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी ।

पुनरीक्षित रपाकी प्लान (Revised Rapacki Plan)—पोलैंड के विदेश मंत्री न नवम्बर १९५८ में पूर्व प्रस्तावित प्लान में बहुत से परिवर्तन कर दिये । उन्होंने इस योजना पर एक सम्मेलन बुलाने का विचार किया जहाँ कि सम्बंधित पक्षकारों में ममभीता होना । उनके विचार से जो पक्षकार सीधे संबंधित थे, वे निम्नलिखित हैं —

१—प्रस्तावित न्यूक्लियर मुक्त क्षेत्र के चार राज्य अर्थात् पोलैंड, जेको-स्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी ।

२—चार महाशक्तियों अर्थात् ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ।

३—वे भी सभी देश जिनके पास जर्मन क्षेत्र में सेना थी अर्थात् बेल्जियम, कनाडा डेनमार्क ।

नि शस्त्रीकरण आयोग —जेनेवा के न्यूक्लियर परीक्षण निलम्बित करने के सम्मेलनों तथा संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के १९५८ और १९५९ के अधिवेशनों में इस और काफी प्रयत्न किये गये हैं । नि शस्त्रीकरण आयोग में नवम्बर १९५७ में २५ सदस्य बढ़ाकर कर दिय गये । इस ने सदस्यता स्वीकार कर ली किन्तु आयोग में काम करने से अपने को पृथक् रक्ता । भारत युगोस्लेव द्वारा प्रेरित संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की राजनीतिक समिति ने ३ नवम्बर १९५८ को एक प्रस्ताव स्वीकृत किया कि संयुक्त राज्य नि शस्त्रीकरण आयोग का पुनर्गठन किया जाय जिससे कि उसमें संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सभी सदस्य सम्मिलित किये जा सकें । भारत-युगोस्लेव प्रस्ताव के अनुसार नि शस्त्रीकरण आयोग १९५९ में ऐड हाक अर्थात् तदर्थ आधार पर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सभी सदस्यों द्वारा बनाया जाय और यदि आवश्यक हो तो साधारण सभा की विशिष्ट बैठक में यह आयोग रचनात्मक प्रस्ताव



१९५७ के अन्त तक निःशस्त्रीकरण सम्बन्धित मध्यस्थता-वार्ता के आचार पर इस तथ्य तक पहुँचा जा चुका था कि एक सिद्धान्त ऐसा मान लिया जाय जिससे न्यूक्लियर परीक्षणों का स्थगन अन्तर्राष्ट्रीय देख-रेख का विषय रहे और यह कि हवाई तथा स्थलीय आकास्मिक निरीक्षण को किसी तात्कालिक आक्रमण की रक्षा का एक साधन माना जाय। किन्तु अभी तक इस बात का कोई समझौता नहीं हो सका है कि विपैले शस्त्रों के उत्पादन की मात्रा को कैसे रोका जाय या वर्तमान सैनिक शक्ति को किस प्रकार घटाया जाय; सैनिक शक्ति पर किये जाने वाले व्यय पर परस्पर एक-दूसरे के साथ सूचना का आदान-प्रदान, तथा इन पर अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण और नियन्त्रण कैसे आरम्भ किया जाय।

सोवियत सरकार ने तर्क प्रस्तुत किया था कि न्यूक्लियर शस्त्रों के प्रयोग पर पूर्णतया रोक लगा दी जाय या पूर्णतया रेडियो-सक्रिय शस्त्रों को समाप्त कर दिया जाय, विदेशी मिलिट्री छावनियों को भी समाप्त किया जाय और जर्मनी, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी आर्गनाइजेशन और वारसा पैक्ट स्थित चार महान् राष्ट्रों की सेना कम कर दी जाय। किन्तु अभी तक इस प्रश्न का कोई ठोस और सर्वमान्य सुझाव सामने नहीं आ सका है।

**रपाकी योजना (Rapacki Plan) :—**१४ जनवरी १९५८ को, पोलैंड के वैदेशिक मामलों के मन्त्री श्री अदम रपाकी ने एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था कि मध्य यूरोप में सक्रिय किरण-मुक्त एक क्षेत्र बनाया जाय। उनका यह प्रस्ताव उनके २ अक्टूबर, १९५७ के प्रस्तावों के तारतम्य में था। प्रस्ताव निम्न-लिखित थे :—

१—मध्य यूरोप में डी-न्यूक्लियराइज्ड क्षेत्र के अन्तर्गत स्थायी रूप से पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य और जर्मन सहोदय गणराज्य भी सम्मिलित कर लिये जाय। इस क्षेत्र में न्यूक्लियर शस्त्र न तो बनाये जाय और न सग्रहीत किये जाय।

२—निम्नलिखित क्षेत्रों में डी न्यूक्लियराइज्ड क्षेत्रों के आभार होंगे :—

(क) इस क्षेत्र के राज्य यह आभार ग्रहण करेंगे कि वे न्यूक्लियर शस्त्र न तो बनायेंगे और न सुरक्षित रखेंगे और न बाहर से मंगावेंगे। इसमें मिसाइल (missile) भी सम्मिलित है।

(ख) चार शक्तियाँ—फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत रूस—यह आभार ग्रहण करेंगी कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार का न्यूक्लियर शस्त्र नहीं सुरक्षित रखा जायगा और न तो किसी तरह से इन शक्तियों का स्थानान्तरण ही होगा।

(ग) वे शक्तिशाली जिनके पास न्यूक्लियर शस्त्र हैं, इस क्षेत्र के विरुद्ध इन न्यूक्लियर शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे ।

(घ) दूसरे राज्य इस क्षेत्र के भीतर जिनकी सेना है वे भी इसी प्रकार का आभार प्रकट करेंगे ।

३—भाग दा के आभारों का पुष्ट करने के लिये संबंधित राज्य एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे इन क्षेत्र में न्यूक्लियर शस्त्रों का विस्तृत और प्रभावकारी रूप से नियन्त्रण हो सके ।

नाटो के सुप्रीम कमांडर नारस्टड ने मध्य यूरोप में न्यूक्लियर मुक्त क्षेत्र उत्पन्न करने का विरोध किया । उनका कहना था कि इससे नैटो की शक्ति और पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा क्षेत्रों में पड़ जायेगी ।

पुनरीक्षित रपार्की प्लान (Revised Rapacki Plan)—पोलैंड के विदेश मंत्री नवम्बर १९५८ में पूर्व प्रस्तावित प्लान में बहुत से परिवर्तन कर दिये । उन्होंने इस योजना पर एक सम्मेलन बुलाने का विचार किया जहाँ कि सम्बंधित पक्षकारों में समझौता होता । उनके विचार से जो पक्षकार सीधे संबंधित थे, वे निम्नलिखित हैं —

१—प्रस्तावित न्यूक्लियर मुक्त क्षेत्र के चार राज्य अर्थात् पोलैंड, चेको-स्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी ।

२—चार महात्वा शक्तियाँ अर्थात् ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ।

३—वे अन्य सभी देश जिनके पास जर्मन क्षेत्र में सेना थी अर्थात् बेल्जियम, कनाडा डेनमार्क ।

नि शस्त्रीकरण आयोग —जेनेवा के न्यूक्लियर परीक्षण निलम्बित करने के सम्मेलनों तथा संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के १९५८ और १९५९ के अधिवेशनों में इस और काफी प्रयत्न किये गये हैं । नि शस्त्रीकरण आयोग में नवम्बर १९५७ में २५ सदस्य बढ़ाकर कर दिये गये । रूस ने सदस्यता स्वीकार कर ली किन्तु आयोग में काम करने से अपने को पृथक् रखता । भारत युगोस्लेव द्वारा प्रेरित संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की राजनीतिक समिति ने ३ नवम्बर १९५८ को एक प्रस्ताव स्वीकृत किया कि संयुक्त राज्य नि शस्त्रीकरण आयोग का पुनर्गठन किया जाय जिससे कि उसमें संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सभी सदस्य सम्मिलित किये जा सकें । भारत-युगोस्लेव प्रस्ताव के अनुसार नि शस्त्रीकरण आयोग १९५९ में ऐड हाक अर्थात् तदर्थ आधार पर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सभी सदस्यों द्वारा बनाया जाय और यदि आवश्यक हो तो साधारण सभा की विशिष्ट बैठक में यह आयोग रचनात्मक प्रस्ताव

३६८ ]

और सिफारिशो निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत करे और यह कि यह भाषण अपने ढंग की प्रक्रिया वा अनुसरण करे और सुरक्षा परिपद् तथा साधारण सभा को प्रतिवेदन भेजे ।

शान्ति के लिये श्रमण :—दिसम्बर ८, सन् १९५३ को प्रेसीडेंट ब्राइजन-होवर ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की साधारण सभा में भाषण करते हुये आणुविक तथा हाईड्रोजन बमों से सम्पूर्ण विश्वस वा निर्देश किया तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनातनी को कम करने के लिये एक नवीन "शान्ति के लिये श्रमण" योजना वा समर्पण किया । प्रेसीडेंट ने यह सुझाव दिया कि शक्तियाँ जिनके पास न्यूक्लियर सम्बन्धी पदार्थ हो उनमें से कुछ अंश को वितरण के लिये एक कोष में दान कर दें जो आणुविक शक्ति के शान्तिपूर्ण विकास क लिए उपयोग में लाई जाय । उन्होंने सुझाव दिया कि एक अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति अभिकरण बनाया जाय जो संयुक्त राष्ट्र संघ के संरक्षण में रहे । इसी सरकार ब्राइजनहोवर योजना में सुझाये गये मुख्य सिद्धान्तों पर सहमत हो गई किन्तु उसने चाहा कि सब देश प्रथम आणुविक शस्त्रों के निषेध के लिये सहमत हो जाय तथा अभिकरण निषेधाधिकार के अधीन सुरक्षा परिपद् द्वारा नियन्त्रित किया जाय । दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बात पर आप्रह्व किया कि अभिकरण अन्य विशिष्ट अभिकरणों के समान संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के अधीन होना चाहिये और उसे साधारण सभा को प्रतिवेदन करना चाहिये तथा सुरक्षा परिपद् द्वारा नियन्त्रित न होना चाहिये ।

नवम्बर १५, सन् १९५४ को संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरेनियम २३५ के १०० किलोग्राम तथा एक दिन उपरान्त यूनाइटेड किंगडम ने २० किलोग्राम शान्ति के लिए 'श्रमण योजना' की श्राव देने को कहा ।

दिसम्बर ४, सन् १९५४ को सभा ने एकमत से प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय आणुविक शक्ति अभिकरण को हट करने वाले प्रस्ताव को स्वीकृत किया । अक्टूबर २३, सन् १९५६ को ८२ राष्ट्रों के एक सम्मेलन ने एकमत से एक २३ अनुच्छेद वाले व्यवस्थान के मूलवाक्य को स्वीकृत किया, जिसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय "शान्ति के लिये श्रमण" अभिकरण को प्रवृत्त करने की योजना थी । सम्मेलन ने यह निर्णय किया कि अन्तर्राष्ट्रीय आणुविक शक्ति अभिकरण का मुख्यालय वियेना में रहेगा । नियमपत्र के अन्तर्गत अभिकरण विकीर्ण होने वाले विस्फोटक पदार्थों को सदस्य-राष्ट्रों की रासायनिक क्रिया के लिए देगा । गवर्नरों के बोर्ड (मनु-शासन करने वालों की परिपद्) को यह प्राधिकार होगा कि वह निरीक्षकों को प्राप्त करने वाले देशों में यह बात निश्चित करने के लिये भेजे कि ये पदार्थ प्रथम उनके से गोण उत्पादित वस्तुएँ केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाय ।

व्यवस्थान में समान के ढेर लगाये जाने को रोकने के लिये रक्षा के उपाय रखे गये हैं तथा यह व्यवस्था की गई है कि अभिकरण द्वारा रासायनिक क्रिया के लिये दिये गये पदार्थ चालाकी से सैनिक प्रयोजनों के लिये न भेज दिये जाय ।

**नभक्षेत्र के शान्तिपूर्ण उपयोग (Peaceful Uses of Outer Space)**—नवम्बर १९५८ में साधारण सभा ने २० राष्ट्रीय एक पुनरीक्षित प्रस्ताव पारित किया जो कि नभ-क्षेत्र के शान्तिपूर्ण उपयोग के सम्बन्ध में था । इस प्रस्ताव में इस आवश्यकता पर बल दिया गया कि नभ के नवीन क्षेत्र में राष्ट्रीय होड न बढे । इस प्रस्ताव में नभ क्षेत्र के उपयोग सम्बन्धित एक तदर्थ समिति बनाने का प्रस्ताव किया गया । यह निश्चय किया गया कि यह समिति साधारण सभा के १४वें अधिवेशन में अन्य बातों के साथ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के साधना, उसके कार्य, उसके विशिष्ट अभिकरण और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ जिनका सम्बन्ध नभ-क्षेत्र के शान्तिपूर्ण उपयोग से था, आदि बातों पर विस्तृत प्रतिवेदन करेगी ।

**एटम शक्ति का शान्तिपूर्ण उपयोग**—संयुक्त राष्ट्र के एटम शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग सम्बन्धी द्वितीय सम्मेलन की बैठक जेनेवा में सितम्बर १९५८ में हुई । ब्रिटेन, अमेरिका तथा रूस ने यह घोषणा की कि उन्होंने निम्नलिखित अवर्गीकरण किया है । अर्थात् थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया के नियन्त्रित कार्यक्रम सम्बन्धी शोध से सुरक्षा प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं । सम्मेलन में सुरक्षा सहिता तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया ।

**१९६०-६१ की संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा (U. N. General Assembly, 1960-61)** :—दिसम्बर १९६० में साधारण सभा द्वारा एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसमें सभी सरकारों से न्यूक्लियर शस्त्रों के रोक पर स्थायी समझौता करने पर जोर दिया गया । साधारण सभा की राजनीतिक समिति ने पूर्णमत के साथ ३० मार्च १९६० में एक अमेरिकी-रूसी प्रस्ताव स्वीकार किया जिससे कि आगामी सितम्बर तक निःशस्त्रीकरण संबंधित बहस स्थगित कर दिया गया । सोवियत संघ ने पाँच तटस्थ देशों को १० राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र उपसमिति में सम्मिलित कर लेने का प्रस्ताव किया किन्तु अमेरिका ने इसे केवल भारत और मैक्सिको तक सीमित रखा और यह भी कि उसने इन दोनों देशों को वोट के अधिकार से वंचित माना ।

**संयुक्त मेमोरेन्डम** :—आठ तटस्थ राष्ट्रों अर्थात् ब्राजील, बर्मा, एथोपिया, भारत, मैक्सिको, नाइजीरिया, स्वीडन और संयुक्त अरब एमिरेट्स ने एक समझौता-प्रस्ताव रखा जिसके आधार पर न्यूक्लियर-परीक्षण रोकने और अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक आयोग निर्मित करने का सुझाव था । यह प्रस्ताव १४ अप्रैल

और सिफारिशें नि शस्त्रीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत करें और यह कि यह प्रायोगिक रूप से दण्ड की प्रक्रिया का अनुमरण करें और सुरक्षा परिपक्व तथा साधारण समाज को प्रतिवेदन भेजें ।

शान्ति के लिये शस्त्र — दिसम्बर ८, सन् १९५३ का प्रेसीडेंट आइजनहोवर ने संयुक्त राष्ट्र सभा की साधारण सभा में भाषण करते हुये आणुविक तथा हाईड्रोजन बमों से सम्पूर्ण विश्वस्य का निर्देश किया तथा अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने के लिये एक नवीन "शान्ति के लिये शस्त्र" योजना का समर्थन किया । प्रेसीडेंट ने यह सुझाव दिया कि दक्षिणी जिनव पास न्यूबिलियर सम्बन्धी पदार्थ हो उनमें से कुछ शस्त्रों का वितरण के लिये एक बोध में दान करें जो आणुविक शक्ति के शान्तिपूर्ण विकास के लिए उपयोग में लाई जाय । उन्होंने सुझाव दिया कि एक अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति अभिकरण बनाया जाय जो संयुक्त राष्ट्र सभा के सरक्षण में रहे । रूसी सरकार आइजनहोवर योजना में सुझाये गये मुख्य सिद्धान्तों पर सहमत हो गई किन्तु उसने चाहा कि सब दश प्रथम आणुविक शस्त्रों के निषेध के लिये सहमत हो जाय तथा अभिकरण निषेधाधिकार के अधीन सुरक्षा परिपक्व द्वारा नियन्त्रित किया जाय । दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस बात पर आप्रह्व किया कि अभिकरण अन्य विविध अभिकरणों के समान संयुक्त राष्ट्र सभा के अधीन होना चाहिये और उस साधारण सभा को प्रतिवेदन करना चाहिये तथा सुरक्षा परिपक्व द्वारा नियन्त्रित न होना चाहिये ।

नवम्बर १५, सन् १९५४ को संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरेनियम २३५ के १०० किलोग्राम तथा एक दिन उपरांत यूनाइटेड किंगडम ने २० किलोग्राम शक्ति के लिए 'शस्त्र योजना' का आरंभ करने की कहा ।

दिसम्बर ४, सन् १९५४ को सभा ने एकमत से प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय आणुविक शक्ति अभिकरण का गठन करने वाले प्रस्ताव को स्वीकृत किया ।

फरवरी २३, सन् १९५६ को ८२ राष्ट्रों के एक सम्मेलन ने एकमत से एक २३ अनुच्छेद वाले व्यवस्थान को स्वीकृत किया, जिसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय "शान्ति के लिये शस्त्र" अभिकरण को प्रवृत्त करने की योजना थी । सम्मेलन ने यह निर्णय किया कि अन्तर्राष्ट्रीय आणुविक शक्ति अभिकरण का मुख्यालय वियेना में रहेगा । नियमपत्र के अन्तर्गत अभिकरण विकीर्ण होने वाले विस्फोटक पदार्थों को सदस्य राष्ट्रों को रासायनिक क्रिया के लिए देना । गवर्नरों के बोर्ड (प्रशासन करने वालों की परिपक्व) को यह प्राधिकार होगा कि वह निरीक्षकों व करने वाले देशों में यह बात निश्चित करने के लिये भेजें कि ये पदार्थ से गोण उत्पादित वस्तुएँ केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिये उपयोग में ।

एक बार जब इस राक का आरम्भ हो चुका है, तो अवश्य ही आशा की जाती है कि इससे एक अंश तक ऐसी सद्भावना उत्पन्न होगी जो कि आगे चलकर पूर्ण परीक्षण-रोक को प्रभावकारी कर सके। इस संधि के प्रमुख उपबन्ध इस प्रकार हैं —

संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के संयुक्त साम्राज्य और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संधि का सरकार, जिन्हें कि यहाँ आरम्भिक पक्षकारों के रूप में सर्वाभित किया गया है, अपने प्रमुख लक्ष्य की घोषणा करती हैं कि कठिन अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अन्तर्गत सामान्य और पूर्ण निःशस्त्रीकरण के लिए जहाँ तक सम्भव हो सक, अति शीघ्र एक समझौता हो। यह समझौता संयुक्त राज्यों के उद्देश्या के तारतम्य में हो, जो कि शस्त्रीकरण को होड़ का रोक सक और सभी प्रकार के शस्त्रों, न्यूक्लियर-शस्त्रों सहित, के उत्पादन और परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगा सके, इसके साथ ही सभी समयों के लिए अर्थात् सदा-सदा के लिये न्यूक्लियर-शस्त्रों के परीक्षणारम्भक-विस्फोटों को बन्द कर देने के उपाय ढूँढे जाय। ये सरकारें इस बात के लिए भी वृत्त-सदृश्य हैं कि वे इस सम्बन्ध में समझौता-वार्ता जारी रखेंगी और मानवीय वायुमण्डल को रेडियोऐक्टिव तत्वों से भर देने के विरुद्ध अपने प्रयत्न जारी रखेंगी। इतनी बातों पर सहमत होते हुये निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार किया जा रहा है—

**अनुच्छेद १—(१)** इस संधि का प्रत्येक पक्षकार इस बात का व्रत लेता है कि वह किसी प्रकार के न्यूक्लियर शस्त्रों के परीक्षात्मक विस्फोटों को निषेधित करेगा, रोकेंगा और स्वयं इस प्रकार का कोई परीक्षण नहीं करेगा या अपने क्षेत्राधिकार या नियंत्रण में किसी भी स्थान पर होने वाले किसी भी अन्य न्यूक्लियर विस्फोटों को नहीं होने देगा,

(क) वातावरण में, अपनी सीमा के बाहर, बाहरी नम या घघाजल में या अन्तरीय जल या शुले समुद्र में, या

(ख) किसी भी अन्य वातावरण में, यदि ऐसे विस्फोट 'रेडियो-ऐक्टिव डेब्रीज' उत्पन्न करत हों, उस राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं में, जिसके क्षेत्राधिकार या नियंत्रण में ऐसे विस्फोट किये जा रहे हैं।

ये उपबन्ध सभी प्रकार के न्यूक्लियर विस्फोटक प्रयोगों को स्थायी रूप से वर्जित करने वाली संधियों का समर्थन करते हैं, जिसमें कि अथ तब के ऐसे विस्फोट भी सम्मिलित होंगे जिन्हें कि संधि की प्रस्तावना में पक्षकारों ने वर्जित करना निदिष्ट माना है।

(२) इस संधि का प्रत्येक पक्षकार इस बात के लिए बल-वृद्ध है कि वह किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर परीक्षात्मक विस्फोटों का करान, प्राप्ताहित करने,

४०० ]

१९६२ को नि शस्त्रीकरण समिति की १८वी बैठक में जेनेवा में किया गया। इसमें १५ सदस्यो का प्रस्ताव था जिसमें रूस, मेक्सिको और अमेरिका स्थायी सदस्य थे। आयोग का साधारण दायित्व यह था कि वह न्यूक्लियर-परीक्षण सम्बंधित सभी प्रकार के मौखिक इकट्ठा करे तथा जहाँ कहीं भी न्यूक्लियर-परीक्षण को प्रभावित करे। इन परीक्षणों पर रोक निम्नलिखित क्षेत्राधिकार में होगा।

(ग) वातावरण के भीतर और ऊपर या क्षेत्रीय अथवा खुले समुद्र में।

(ख) किसी ऐसे वातावरण में जहाँ से सक्रिय किरण दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में पहुँच सके।

संयुक्त राष्ट्र मण्डल के साधारण सभा का १७वाँ अधिवेशन :—२१ सितम्बर, १९६२ को सोवियत प्रतिनिधि ने साधारण सभा के समक्ष घोषित किया कि सोवियत सरकार ने पहले से ही १८ राष्ट्रीय नि शस्त्रीकरण समिति का प्रस्ताव ग्ल दिया है। उन्होंने सभा के अध्यक्ष के पास एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि ऐसे सभी राज्य जिनके पास न्यूक्लियर शस्त्र हैं, वह सर्वप्रथम उनके प्रयोग से अपने को रोकें और दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा करें कि वे उन शस्त्रों का प्रयोग न करेंगे।

न्यायिक परीक्षण प्रतिव्यवस्था (१९६३)—अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस तथा अन्य देशों ने १९६३ में न्यायिक परीक्षण के आधिकारिक प्रतिबन्ध की संधि पर हस्ताक्षर किये जो १० अक्टूबर १९६३ को कार्यान्वित हुई। इस संधि से सम्भावना है कि शीघ्र ही अविष्य में परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जा सके जो नि शस्त्रीकरण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा शांति की प्रगति में सहायक हो। इसके अनुसार प्रत्येक पक्षकार न्यायिक शस्त्रों के विस्फोट को अपने क्षेत्र में किसी भी स्थान में न तो करेगा और न किसी को करने देगा —(क) नभ क्षेत्र में, उसकी सीमा के बाहर जिसमें बाहरी नभ भी सम्मिलित है, या पानी के भीतर जिसमें क्षेत्रीय जल या उमुक्त समुद्र भी सम्मिलित है। या (ख) अन्य किसी भी वातावरण में यदि ऐसा विस्फोट होना है जिसके कारण राज्य की क्षत्रीय सीमाओं के बाहर रेडियो-सक्रिय मलबा (डिब्रो) के उपस्थित होने की सम्भावना है।

इस प्रकार यह न्यायिक परीक्षण संधि पूर्ण नि शस्त्रीकरण की ओर लक्षित होकर अन्तर्राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डल की सुदृढ़ और मैत्रीपूर्ण बनाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति स्वर्गीय केनेडी के अनुसार यह संधि पूर्व-गठित्व के शीत युद्ध के गहन अंधकार में प्रकाश की किरण है। यह संधि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सूक्ष्म-युद्ध के इतिहास में एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि परीक्षण पर रोक एक मोचित प्रवृत्ति तक है, किन्तु

एक बार जब इस राक का आरम्भ हो चुका है, तो अवश्य ही आशा की जाती है कि इससे एक अग्र तक ऐसी सद्भावना उत्पन्न होगी जो कि आगे चलकर पूर्ण परीक्षण-रोक को प्रभावकारी कर सके । इस संधि के प्रमुख उपबन्ध इस प्रकार हैं:—

संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के संयुक्त साम्राज्य और सोवियत सोसलिस्ट रिपब्लिक संधि का सरकार, जिन्हें कि यहाँ आरम्भिक पक्षकारों के रूप में सदर्भित किया गया है, अपने प्रमुख लक्ष्य की घोषणा करती हैं कि कठिन अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अन्तर्गत सामान्य और पूर्ण निःशस्त्रीकरण के लिए जहाँ तक सम्भव हो सक, अति शीघ्र एक समझौता हो । यह समझौता संयुक्त राज्यों के उद्देश्यों के तारतम्य में हो, जो कि शस्त्रीकरण को होड़ का रोक सके और सभी प्रकार के शस्त्रों, न्युक्लियर-शस्त्रों सहित, के उत्पादन और परीक्षण पर प्रतिबन्ध लगा सके, इसका साथ ही सभी समयों के लिए अर्थात् सदा-सदा के लिये न्युक्लियर-शस्त्रों के परीक्षात्मक-विस्फोटों को बन्द कर देने के उपाय ढूँढे जाय । ये सरकारें इस बात के लिए भी कृत-सकल्प हैं कि वे इस सम्बन्ध में समझौता-वार्ता जारी रखेंगी और मानवीय वायुमण्डल को रेडियोऐक्टिव तत्वों से भर देने के विरुद्ध अपने प्रयत्न जारी रखेंगी । इतनी बातों पर सहमत होते हुये निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया जा रहा है—

**अनुच्छेद १—(१)** इस संधि का प्रत्येक पक्षकार इस बात का व्रत लेता है कि वह किसी प्रकार के न्युक्लियर शस्त्रों के परीक्षात्मक विस्फोटों को निषेधित करेगा, रोकेंगा और स्वयं इस प्रकार का कोई परीक्षण नहीं करेगा या अपने क्षेत्राधिकार या नियन्त्रण में किसी भी स्थान पर होने वाले किसी भी अन्य न्युक्लियर विस्फोटों को नहीं होने देगा ,

(क) वातावरण में, अपनी सीमा के बाहर, बाहरी नभ या अघाजल में या अश्वेत्रीय जल या खुले समुद्र में, या

(ख) किसी भी अन्य वातावरण में, यदि ऐसे विस्फोट 'रेडियो-ऐक्टिव डेब्रीज' उत्पन्न करते हों, उस राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं में, जिसके क्षेत्राधिकार या नियन्त्रण में ऐसे विस्फोट किये जा रहे हों ।

ये उपबन्ध सभी प्रकार के न्युक्लियर विस्फोटक प्रयोगों को स्थायी रूप से वर्जित करने वाली संधियों का समर्थन करते हैं, जिसमें कि अद्य तल के ऐसे विस्फोट भी सम्मिलित होंगे जिन्हें कि संधि की प्रस्तावना में पक्षकारों ने वर्जित करना निदिष्ट माना है ।

(२) इस संधि का प्रत्येक पक्षकार इस बात के लिए बल-वद्ध है कि वह किसी भी प्रकार के न्युक्लियर परीक्षात्मक-विस्फोटों का कराना, प्रोत्साहित करना,



या उसमें किसी भी रूप में भाग लेने से अपने को दूर रखेगा, या किसी भी अन्य विस्फाटा से दूर रहेगा, जिनका बि उपग्रह्य पैराग्राफ १ में किया जा चुका है ।

**अनुच्छेद २—(१)** कोई भी पक्षकार इस संधि में संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है । किसी भी प्रस्तावित संशोधन की मूल भाषा समुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटन और सावियत गणतन्त्र की सरकारों के पास भेजी जायेगी, जो कि सभी पक्षकारों का इस प्रचारित कर दगी । हमें उपरान्त यदि ऐसा करना आवश्यक माना गया, तो एक तिहाई या हमें अधिक पक्षकारों की सहमति पर ये सरकारें एक सम्मेलन बुलायेंगी और व उस सम्मेलन में सभी पक्षकारों को प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने के लिए आमन्त्रित करेंगी ।

(२) इस संधि में कोई भी संशोधन इस संधि के सभी पक्षकारों के बहुमत द्वारा अवधार ही स्वीकृत होना चाहिये, जिसमें कि सभी आरम्भिक पक्षकारों के भी वाट सम्मिलित होना चाहिये । संशोधन सभी पक्षकारों के लिए सुधार के संबंध साधन के रूप में उसी प्रकार प्रभावकारी होगा, जिस प्रकार कि आरम्भिक पक्षकारों के लिये ।

**अनुच्छेद ३—(१)** यह संधि सभी राज्यों के लिए हस्ताक्षर करने के लिए खुली रहेगी । यदि कोई राज्य इस संधि के प्रवर्तन के समय इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (३) के अनुसार इसमें प्रविष्ट नहीं होता, तो वह कभी भी तदनुसार हस्ताक्षर करके संधि में प्रविष्ट हो सकता ।

(२) संधि का संशोधन हस्ताक्षरकर्ता सभी राज्यों के संशोधन के सम्पादन होगा ।

(३) यह संधि सभी आरम्भिक पक्षकारों के संशोधन साधनों द्वारा संचित होने के उपरान्त प्रभावकारी होगी ।

यह संधि आरम्भिक सरकारों द्वारा समुक्त राष्ट्रों के चार्टर के अनुच्छेद १०२ के क्रम में प्रमाणित होगी ।

**अनुच्छेद ४—** यह संधि असीमिन् अवधि की होगी । प्रत्येक पक्षकार अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रयोग में इस संधि से अपने को अलग करने का अधिकारी होगा किन्तु यह सभी होगा जब कि वह निश्चय करता है कि इस संधि के विपक्ष-वस्तु में सम्बन्धित असाधारण घटनाएँ घटी हैं और उससे उसके देश के संप्रभु हिता पर ग्राह्य आई हैं । वह पक्षकार संधि के प्रत्येक सभी पक्षकारों को अपने प्रत्याह्वान मन्त्रों के सूचना ३ मास पूर्व देगा ।

यह संधि १० अक्टूबर, १९६३ को प्रभाव रूप में लागू हुई । इस संधि पर सर्वप्रथम तीन मन्त्र शाक्तियों द्वारा अवस्त ५, १९६३ को मास्को में हस्ताक्षर किये गये और अक्टूबर, १९६३ तक लगभग १०० देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर

चुके थे । चीन, फ्रांस और अल्बानिया ने आशिक न्युट्रि प्रयोग रोक की सधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है ।

मास्को टेस्ट बैन ट्रीटा और न्युट्रिपर शस्त्रा की सामग्रिया के उत्पादन में कमी की सोवियत सङ्घ द्वारा घोषणा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा १९६४ में एतद्विषयक घोषणा नि शस्त्रीकरण के भाग में प्रथम मोचान थी ।

५ अगस्त १९६४, को सोवियत सङ्घ, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य ने इस बात की प्रतिज्ञा की कि वे अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिये मयावम्भव समझौता बातों का सहारा लेंगे । मास्को-टेस्ट बैन-ट्रीटा के प्रथम बार्थिकोत्सव पर तीनो सरकारों ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि शस्त्रों की होड़ और प्रभावकारि नि श्त्रीकरण के प्रश्नों को सुलझाने के लिये गहनतम समस्याओं को सुलझाना है । हस्ताक्षरकर्ताओं ने पुन इस बात को पुष्ट किया कि यह सधि शान्ति को बढ़ावा देने और शस्त्रों की घुड़दौड़ को निर्यान्वित करने के मार्ग में एक मागदर्शक तारा के रूप में है । यह भी खेद से साय व्यक्त किया गया कि जहाँ भी से अधिक राज्य इस सधि में हस्ताक्षर कर चुके हैं, कुछ शक्तियाँ जैसे चीन, फ्रांस और अल्बानिया इस पर अभी हस्ताक्षर नहीं कर सके हैं । यह भी प्रस्तावित किया गया कि आशिक-परीक्षण रोक सधि का विस्तार अघोषभूमि में किये जाने वाले परीक्षणों तक भी होना चाहिये ।

अक्टूबर १६, १९६४ को अपने पश्चिमी अक्षर में चीन द्वारा किया गया एटम-बम विस्फोट शान्ति के पोषण को दिशा में एक अभावह खतरा है । भले ही चीन अभी ऐसे परीक्षणों की अल्पतम उपलब्धि कर सका हो कि नु उनके लगातार के प्रयोग संपूर्ण एशिया और अफ्रीका को आतंकित किये हुये हैं । राष्ट्रपति जॉनसन ने भले ही एशिया के देशों को इस आतंक के विरुद्ध आश्वासन दिया है कि नु चीन की निरकुशता का आतंक किसी भी समय राष्ट्र पर बना रहना, उस समय तक स्वाभाविक है जब तक कि प्रभावकारि रूप में चीन को ऐसे प्रयोगों से रोक नहीं दिया जाता ।

निष्कर्ष —अणु शक्ति के शान्तिपूर्ण प्रयोग से सम्बन्धित प्रस्ताव इस प्राप्ति को व्यक्त करता है कि विश्व को वह युद्ध से दूर हटायेगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि के शब्दों में —“It is a new prism through which we can look at the problem of the world” अर्थात् यह एक नया स्रोत है जिसके आधार पर हम विश्व की समस्याओं को एक नये ढंग से देख सकते हैं । यह एक ऐसा कदम है जहाँ से हमें चलना आरम्भ करना है । पूर्ण विश्वास में पता चलता है कि युद्ध की सम्भावनाओं और शस्त्रों के अभाव सग्रह को रोक जा सकता

है, केवल यदि राज्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाय और दूसरे से भय कम हो जाय । प्रत्येक देश में जनता पूर्ण बहुमत के साथ शांति चाहती है । यही एक ऐसी किरण है जिससे राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति शत्रुता और सन्देह के कम होने की आशा की जा सकती है ।

अभी तक निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में कोई सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं अपनाया जा सका है । एक ओर निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में वार्तायें चलती रहती हैं और दूसरी ओर दो महान् कक्षा जाने वाली शक्तियाँ न्यूक्लियर-परीक्षण भी करती रहती हैं । वास्तव में निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर ही मान्यता एवं विश्व-शांति तथा सुरक्षा का भविष्य निर्भर करता है । महान् शक्तियों ने जो शस्त्र तैयार कर रखे हैं और आज भी जो निरन्तर तैयार हाते जा रहे हैं, उन्हें पूर्णतया त्याग देना और फिर यह विश्वास कर लेना कि दूसरा प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र भी इन शस्त्रों को त्याग देगा और तथा नहीं बना लेगा, एक कठिन समस्या है । इसके लिये क्रमशः प्रयत्न होते रहे तो आशिक सफलता मिल सकती है, पूर्ण सफलता तो अभी एक दूरस्थ कल्पना ही प्रतीत होती है ।

## अध्याय ३०

### विशिष्ट अभिकरण

#### (The Specialized Agencies)

विशिष्ट अभिकरण वे सघ हैं जो अन्तर-सरकारी स्वीकार-पत्रों द्वारा स्थापित किये गये हैं तथा जिनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा-सम्बन्धी, स्वास्थ्य तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में बहुत विस्तृत उत्तरदायित्व है । स्वीकारोक्तियों की वार्ता जिनके द्वारा उनका सम्बन्ध समुक्त राष्ट्र सघ से स्थापित हो जाता है पहले अभिकरणों के साथ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित एक स्थायी समिति द्वारा की जाती है जिसे 'अन्तर-सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वित की समिति' कहा जाता है । इसके उपरान्त वे स्वीकृत के लिये आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के पास भेजी जाती हैं तथा परिषद् द्वारा सामान्य सभा को । प्रवर्तन होने के पूर्व प्रत्येक स्वीकार पत्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के सम्बन्धित विशिष्ट अभिकरण के समुचित भ्रम द्वारा स्वीकृत भी किया जाना चाहिये ।

समुक्त राष्ट्र सघ के भिन्न विशिष्ट अभिकरण निम्नलिखित हैं —

१. अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सघ (International Labour Organization : I. L. O.)—यह समुक्त राष्ट्र से सम्बन्धित सघ में पुराने अभिकरणों में

से एक है और प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त जो अन्तर सरकारी सस्थापे स्थापित की गईं उनमें से अकेला बचा हुआ है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सङ्घ के संविधान में जो सन् १९१६ में बनाया गया वह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि सार्वजनिक तथा स्थायी शान्ति केवल उसी दशा में स्थापित की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो । इसका त्रिकोणाकार संयुक्त राष्ट्र सङ्घ में अनोखा है, तथा इसके विशिष्ट श्रमिकरण श्रमिकों के प्रतिनिधि, प्रबन्ध तथा सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सङ्घ के निर्णयों को देने तथा उसकी नीति को आकार देने में योग देते हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन न फिलिडेल्फिया में सन् १९४४ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सङ्घ को शान्ति में निष्ठा को पुनः दृढतापूर्वक व्यक्त किया । फिलिडेल्फिया की घोषणा में पुनः जो सिद्धान्त दृढतापूर्वक कहे गए, वे निम्नलिखित हैं —

- (अ) श्रम पदार्थ (वस्तु) नहीं है,
- (आ) किसी एक स्थान की भी दरिद्रता सभी स्थानों की समृद्धि के लिये भयजनक है ।
- (इ) अभिव्यक्ति तथा सङ्घ की स्वतन्त्रता स्थायी उन्नति के लिये परमावश्यक है ।
- (ई) दरिद्रता के विरुद्ध युद्ध प्रत्येक राष्ट्र के भीतर दृढ उत्साह के साथ किये जाने की आवश्यकता है ।

२. संयुक्त राष्ट्र सघ का खाद्य तथा कृषि सचिवनी सघ (Food and Agriculture Organization of the United Nations F. A. O.)— यह प्रथम अन्तर-सरकारी अभिकरण है जो सन् १९४५ में द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् स्थापित हुआ । यह एक सम्मेलन द्वारा कार्य करता है जिसमें ७७ सदस्य-राष्ट्रों (जनवरी १९५६) में से प्रत्येक का एक वोट है । इस सम्मेलन का प्रत्येक दो वर्षों में अभिवेशन होता है किन्तु जब बहुमत यह इच्छा व्यक्त करता है तो इसका अभिवेशन बीच के वर्ष में हो सकता है । सत्रा के मध्य में एक ० ए० ओ० परिषद् प्रशासकीय सस्था का कार्य करती है जो १८ सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से निर्मित होती है ।

इसके मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों को अपना जीवनस्तर उन्नत करने में, सब देशों के लोगों के आहार का सुधारने में, कृषि, वन तथा मत्स्यालयों की क्षमता को बढ़ाने में, ग्रामवासियों की दशा को सुधारने में तथा इन सब साधनों द्वारा सब लोगों का उत्पादन कार्य में अवकाश को और अधिक विस्तृत करने में सहायता देने का है ।

३. संयुक्त राष्ट्र सघ का शिक्षा मन्त्रणी, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सघ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Or-

ganization : UNFSCO.)—राजनैतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में यह प्रजातन्त्र का मुख कहा जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्रों में सह-कारिता को बढ़ाकर शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना करने में भाग लेने का है जिससे न्याय, विधि शासन, मानवीय अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताओं के लिये सावभौमिक सम्मान और अधिक व्यापक हो, जो समुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर द्वारा जात, लिंग, भाषा धर्म के भेदभाव को हटा कर ससार के लोगों के लिये मान्य की गई है।

इसका संस्थान निम्नलिखित से निमित्त है —

(१, साधारण सम्मेलन (८७ सदस्य राज्यों के एक-एक प्रतिनिधि सहित), (२) २० सदस्यों का एक इक्जीक्यूटिव बोर्ड, (३) सचिवालय (जिसमें कि डायरेक्टर जनरल और अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी जो कि ६ प्रमुख विभागों—शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक कार्य क्रम, सामूहिक विनियम और प्राविधिक सहायता, के होते हैं।)

४ अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सघ (International Civil Aviation Organization . I C A.O.)—इसके उद्देश्य और लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय वायु-उड्डयन कला के सिद्धांत तथा यंत्र कला का विकास करना है तथा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात की योजनाओं को बनाने तथा उनके विकास में वृद्धि करने का है जिससे ससार भर में अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का सुरक्षित तथा नियमित रूप से विकास हो सक।

५. पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction and Development.)—पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के कृत्य सदस्यों के प्रदेशों के पुनर्निर्माण तथा विकास में उत्पादक प्रयोजनों के लिये पूंजी को लगाने की सुविधा प्रदान कर सहायता करना, वैयक्तिक विदेशी पूंजी के लगाने जाने की वैयक्तिक पूंजी लगाने वालों द्वारा दिये गये ऋणों तथा अन्य लगाई गई पूंजी की प्रतिभूति देकर तथा भाग लेखर प्रोत्साहित करना तथा वैयक्तिक पूंजी लगाई जाने की क्षमता उत्पादक प्रयोजनों के लिये अपनी पूंजी में सघन की व्यवस्था करके धन एकत्र करके तथा अन्य साधनों से करना है।

६ अन्तर्राष्ट्रीय धन कोष (International Monetary Fund . I. M. F.)—यह राष्ट्रों का एक मण्डल है जिसने स्वीकार-पत्र के कोष सम्बन्धी अनुच्छेदों की स्वीकृत करने यह प्रतिज्ञा की है कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग तथा विश्व-व्यापार की और अधिक बढ़ावेंगे। इसने उद्देश्य मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

के विस्तार और सतुलित विकास को सुगम करना, तथा इसके द्वारा व्यवसाय और वास्तविक आय की उन्नति में तथा उसमें एक उच्च स्तर स्थापित करने में सहयोग देना, विनिमय में स्थिरता को बढ़ाना तथा समुचित रक्षणों के अधीन सदस्यों को कोष के साधन प्राप्त कराकर उनमें विश्वास उत्पन्न करना है ।

७. विश्व स्वास्थ्य संघ ( World Health Organization : W. H. O. )—यह सब से बड़े विशिष्ट अभिकरणों में से एक है तथा १९५६ में इसके ८८ राष्ट्र सदस्य हैं । इसका उद्देश्य सब लोगों द्वारा स्वास्थ्य का उच्च स्तर प्राप्त करना है ।

८. अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ ( International Refugee Organization : I. R. O. )—अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ शरणार्थियों अथवा देशों से निकल गये व्यक्तियों को अपने मूलदेश को अथवा अपने पुराने घर का लौटाने में सहायता करता है तथा सामूहिक पुनर्वास सम्बन्धी यात्रायात्रा को पूर्ण करता है जिसके द्वारा प्रत्येक देश अन्तर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ के साथ एक स्वीकार-पत्र लिखता है जिसमें शरणार्थी देशान्तरवासी सम्बन्धी ग्रहणीयता की माप, पुनर्वासोत्तर दशायें, वैधिक स्थिति तथा वास्तविक छांटने की प्रक्रियाएँ दी रहती हैं ।

९. सार्वदेशिक डाक संघ ( Universal Postal Union : U. P. U. )—सार्वदेशिक डाक संघ प्रथमतः जुलाई १ सन् १८७५ में स्थापित हुआ जब बर्न की डाक कांग्रेस द्वारा अक्टूबर ६, सन् १८७४ को सार्वदेशिक डाक प्रतिज्ञा प्रकीर्ण की गई । यह अन्तर्राष्ट्रीय डाक यातायात की अनिश्चितता, गड़बड़ों तथा प्रत्यधिक व्यय को, अपने सदस्य देशों को डाक के परस्पर विनियम के लिये एक डाक प्रदेश में बाँध कर दूर करने के लिये स्थापित किया गया है । डाक प्रतिज्ञा विभिन्न डाक कांग्रेसों द्वारा विस्तृत तथा उन्नत की गई है ।

१०. अन्तर्राष्ट्रीय तार सन्देश यन्त्र संघ ( International Telecommunication Union : I. T. U. )—अन्तर्राष्ट्रीय तार सन्देश सन्घ के तीन मुख्य उद्देश्य हैं अर्थात् तार सन्देशयन्त्र के सुधार तथा युक्कियुक्त उपयोग के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का स्थापित करना तथा उसका विस्तार करना, उनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिये यांत्रिक कला विज्ञान सम्बन्धी सुविधाओं का विकास तथा उसका सबसे अधिक दक्षता से धारण, तथा यथासम्भव उनको सामान्यतः जनता को प्राप्त कराना और इन समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राष्ट्रों के कार्यों को एक-रूप करना ।

११. विश्व-अन्तरिक्ष विद्या सम्बन्धी संघ ( World Meteorological Organization : W. M. O. )—यह विश्व के अन्तरिक्ष विद्या सम्बन्धी कार्यों

को एकरूप करने, मानकीकरण करने तथा उनमें सुधार करने के लिये तथा मानवीय कार्यों के सहायतार्थ देशों के बीच में अन्तरिक्ष विद्या सम्बन्धी सूचना का दक्षतापूर्ण विनिमय प्रोत्साहित करने के लिये स्थापित किया गया है।

यह सबसे नया अन्तर-सरकारी अभिकरण है जो समुन्नत राष्ट्र संघ के अधीन हुआ है। यह अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष विद्या सम्बन्धी सन्त्र का उत्तराधिकारी है जो अतु सूचना सम्बन्धी सेवाओं को अपने सदस्यों के बीच सन् १८७८ से एकरूप कर रहा था।

## अध्याय ३१

### अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की विधि

#### १. विवाचन का स्थायी न्यायालय

#### (The Permanent Court of Arbitration)

उत्पत्ति — विवाचन के स्थायी न्यायालय की उत्पत्ति दो प्रतिज्ञाओं के कारण हुई जो अन्तर्राष्ट्रीय भण्डों के शान्तिपूर्ण समझौते के बारे में सन् १८६६ तथा १९०७ में हुई। पहली प्रतिज्ञा सन् १८६६ के हेग सम्मेलन में विवाचन के एक स्थायी न्यायालय के संगठन का विचार प्रस्तुत किया गया जिसमें हेग में एक अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो (कार्यालय) भी बनाने का निश्चय था, जो इसके सचिवालय तथा स्थायी प्रशासकीय परिषद् के रूप में कार्य करे।

इसका ढाँचा — विवाचन के स्थायी न्यायालय के ढाँचे में तीन तत्वाएँ सम्मिलित हैं अर्थात् (१) न्यायालय के सदस्यों का पैनल, (२) एक प्रशासकीय परिषद् तथा (३) एक अन्तर्राष्ट्रीय ब्यूरो (कार्यालय)।

पैनल के सदस्य — प्रत्येक राष्ट्र को जो सन् १८६६ तथा १९०७ की प्रतिज्ञाओं में से किसी एक में भी पक्षकार रहा हो यह अधिकार है कि वह चार सदस्यों का नाम भेजे "जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्नों के सम्बन्ध में योग्यता की प्रसिद्धि हो तथा जिनकी नैतिक प्रतिष्ठा सर्वोच्च हो और विवाचन के कार्यभार को ग्रहण करने का उद्यत हो।" उनकी नियुक्ति छ वर्ष की अवधि के लिये होती है जिसे पुनः बढ़ाया जा सकता है। राज्यों द्वारा इस प्रकार जिनका नाम भेजा गया है उन व्यक्तियों की सूची में से, जो प्रतिज्ञा के पक्षकार सब राज्यों के सम्मत् रूप से विभाजित की जाती है, किसी भण्डों के पक्षकारों को यह स्वतन्त्रता है कि किसी

न्यायाधिकरण के सदस्यों को निर्वाचित करें। उस स्थिति में जब पक्षों को छांटने में मतभेद हो जाय तो प्रत्येक पक्षकार को दो दो नियुक्त करने पड़ते हैं और इस प्रकार छांटे गये चारों पक्ष एक सरपक्ष नियुक्त कर लेते हैं और यह सब उभो तालिका में से छांटे जाते हैं। दूसरी प्रतिज्ञा अर्थात् सन् १९०७ के हेग सम्मेलन ने इस योजना में कुछ सुधार किये तथा गौण महत्व के मामलों के विषय में झगडा के सम्बन्ध में एक सक्षिप्त प्रक्रिया की व्यवस्था की। प्रत्येक पक्षकार को जिसका मतभेद हो जाय दो पक्ष नियुक्त करने पड़ते थे जैसा पहले कहा जा चुका है, परन्तु केवल एक ही व्यक्ति इसका जातीय हो सकता था अथवा उन व्यक्तियों में से चुना जा सकता था जो इसके द्वारा स्थायी विवाचन न्यायालय के सदस्य निर्वाचित हुए हो।

**प्रशासकीय परिपद्** —परिपद् में नीदरलैण्ड के वैदेशिक विभाग का मंत्री समापति के रूप में रहता है तथा प्रतिज्ञा के पक्षकार राज्यों द्वारा हेग क लिये अधि-कार प्रदत्त राजनैतिक प्रतिनिधि रहते हैं।

**द्यूरो ( कार्यालय )** :—न्यायालय का कार्यालय हेग में शांति-महल (Peace Palace) में स्थापित है और इसमें विवाचन का स्थायी न्यायालय वा महासचिव तथा थोड़े से कर्मचारी वर्ग हैं। कार्यालय प्रशासन करता है तथा प्रलेखा-गार का भार वहन करता है। यह न्यायाधिकरणों के संगठन सम्बन्धी पत्र व्यवहार भी करता है।

**अर्थ-व्यवस्था** —न्यायाधिकरण के व्यय सविदाकार राज्यों, द्वारा नियत अनुपात में वहन किये जाते हैं। प्रतिज्ञा-पत्र में यह भी दिया गया है कि पक्षकार का प्रत्येक पक्षकार अपना-अपना व्यय वहन करेगा तथा न्यायाधिकरण क अन्य पक्षकारों द्वारा समान भाग में वहन किये जायेंगे।

**न्यायालय का प्रकार** —वस्तुतः विवाचन का स्थायी न्यायालय कोई न्यायालय नहीं है वरन् पक्षों की केवल एक तालिका है जिसमें से न्यायाधिकरण संगठित किया जा सके। ऐसी स्थिति में शब्द के वास्तविक अर्थ में इसमें कोई स्थिरता नहीं है। मैनसी ओ हडसन का वचन है कि 'विवाचन का स्थायी न्याया-लय' का नाम वास्तव में एक मिथ्या नाम है तथा ऐसी आशाएँ उत्पन्न करके जो पूरी नहीं की जा सकती थी सार्वजनिक विचारधारा को कुछ धोखा देने क लिये उत्तरदायी हो सकता है। विवाचन का स्थायी न्यायालय वास्तव में कोई न्यायालय नहीं है, यह मयार्थ में एक न्यायाधिकरण है, यद्यपि यह प्रायः 'हेग का न्यायाधि-करण' इस नाम से निर्दिष्ट किया जाता है। इसके स्थान में यह 'तदर्थ (ad hoc)



न्यायाधिकरणों को सगठित करने में सुविधा प्रदान करने की एक युक्ति है। यह स्थायी केवल इस अर्थ में है कि एक तालिका स्थायी रूप से प्राप्य है।

**विवाचक निर्णय** — सन् १९०० तथा १९३२ के बीच में हेग के विवाचन के स्थायी न्यायालय द्वारा बीस निर्णय दिये गये जिनमें समुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन के बीच का उत्तरी अटलांटिक मत्स्यालयों का झगडा (१९१०), सावरकर का मामला (१९११), नौर्वे तथा समुक्त राज्य अमेरिका के बीच में नौर्वे के जहाजों के प्रथम महायुद्ध में अधिवाचन सम्बन्धी मामला (१९२२) सम्मिलित हैं।

### न्यायाधिकरण के समक्ष के कुछ मामले

१. उत्तरीय अटलांटिक मत्स्यालयों का मामला (१९१६) :— जनवरी २७, सन् १९०६, को एक विशेष स्वीकार पत्र लिखा गया जिसके द्वारा अमेरिका तथा ब्रिटेन की सरकारें इस बात पर सहमत हो गयी कि कुछ प्रश्नों को हेग के विवाचन के स्थायी न्यायालय के सदस्यों में से चुने गये विवाचन न्यायाधिकरण के निर्णय पर छोड़ दिया जाय। समुक्त राज्य अमेरिका यह दावा करता था कि उसको न्यूफाउण्डलैंड के कुछ भागों से मछली लेने का अधिकार है तथा यह भी दावा किया कि मत्स्यालयों के सम्बन्ध में विनियम, केनाडा, ग्रेट ब्रिटेन तथा समुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समुक्त रूप से बनाया जाना चाहिये न कि ग्रेट ब्रिटेन तथा केनाडा द्वारा अकेले। न्यायाधिकरण ने अपने पंचाट में यह प्रकट किया कि समुक्त राज्य अमेरिका को दी गई मत्स्यालयों की स्वतन्त्रता से उनके पक्ष में कोई अन्तर्राष्ट्रीय दावत उत्पन्न नहीं होता। इसने यह भी मत प्रकट किया कि ग्रेट ब्रिटेन का समुक्त राज्य अमेरिका की सम्मति के बिना विनियम बनाने के अधिकार का उपयोग इस बात पर सीमित था कि ऐसे विनियम भाव मुक्त होने चाहिये तथा उनको सन् १९१८ की संधि का उल्लंघन न करना चाहिये।

२. सावरकर का मामला (१९११) :— सावरकर एक भारतीय नेता, जो ब्रिटेन के डाक जहाज मोरिया में बन्दी के रूप में इंग्लैण्ड से भारत को ले जाये जा रहा थे, का जब जहाज मार्सलीज पहुँचा तो वे भाग गये। यह फ्रांस की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये तथा जहाज के कप्तान को, बिना प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाही किये, हस्तगत कर दिया गया। फ्रांस की यह माँग कि मागे हुये बन्दी को वापस कर दिया जाय ब्रिटेन की सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दी गयी। प्रश्न जो विवाचन के स्थायी न्यायालय के पाँच सदस्यों से बने हुये न्यायाधिकरण के सामने विचार के लिये उपस्थित हुआ यह था कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों के अनुसार भागा हुआ बन्दी फ्रांस की सरकार को वापस कर दिया जाय ? न्यायाधि-

करण ने इस प्रश्न का उत्तर इस कथन के साथ नकारात्मक दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में कोई नियम ऐसा नहीं है जिसके द्वारा ऐसी दशाओं में किसी शक्ति पर जिसके अभिग्रहण में कोई बन्दी हो उसको वापस कर देने का कर्तव्य आरोपित किया गया हो इसलिये कि विदेशी अभिवर्त्ता द्वारा गलती की गई थी जिसने कि उस शक्ति को हस्तगत किया ।

३ रूस का क्षतिपूर्ति वाला मामला (१९१२) — यह भगडा जनवरी २७ तथा फरवरी ८ सन् १८७९ की कुस्तुन्तुनियाँ की सन्धि के परिणामस्वरूप क्षति-पूर्ति की घनराशि पर सूद दिये जाने के सम्बन्ध में था जो (घनराशि) टर्की द्वारा रूसी प्रजाजनो तथा सस्थाओं को उस क्षति के लिये देय थी जो उन्होंने युद्ध के बीच में सहन किया । यह भगडा विवाचन के स्थायी न्यायालय के सदस्यों से संगठित एक न्यायाधिकरण को निर्देशित हुआ । न्यायाधिकरण ने यह घोषित किया कि रूस का दावा ग्राह्य था किन्तु उन्होंने यह मत प्रकट किया कि तुर्की की सरकार सूद-क्षति देने को बाध्य नहीं है ।

विवाचन वा स्थायी न्यायालय अब भी विद्यमान है यद्यपि सन् १९३२ से इसके अनुसन्धों के अधीन संगठित न्यायाधिकरण को कोई मामला निर्देशित नहीं हुआ है ।

इसके प्रतिरिक्त समय समय पर पायस फड केस (१९०२), जापानी गृहकर का मामला (१९०५), बैसाब्लाका का मामला (१९०६), वेनेजरा का मामला (१९१२), आदि विशेष उल्लेखनीय हैं ।

## अध्याय ३२

### २. अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय

#### [The Permanent Court of International Justice]

न्यायालय की उत्पत्ति :—अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय सन् १९२१ में लीग ऑफ नेशन्स की प्रतिज्ञा के, जिस पर वार्सलीज में जून २८ सन् १९१९ को हस्ताक्षर किये गये, अनुच्छेद १४ के अनुसार स्थापित किया गया । उस अनुच्छेद में यह व्यवस्थापित है :—

“परिषद् लीग के सदस्यों द्वारा ग्रहण किये जाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के स्थापनार्थ योजनाएँ बनायेगी तथा उनको समर्पित करेगी” ।

“The Council shall formulate and submit to the members

न्यायाधिकरणों को संगठित करने में सुविधा प्रदान करने की एक युक्ति है। यह स्थायी केवल इस अर्थ में है कि एक तालिका स्थायी रूप से प्राप्य है।

**विवाचक निर्णय** — सन् १९०० तथा १९३२ के बीच में हेग के विवाचन के स्थायी न्यायालय द्वारा बीस निर्णय दिये गये जिनमें सयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन के बीच का उत्तरी अटलांटिक मत्स्यालयों का झगड़ा (१९१०), सावरकर का मामला (१९११), नीर्वे तथा सयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में नीर्वे के जहाजों के प्रथम महायुद्ध में अधिवाचन सम्बन्धी मामला (१९२२) सम्मिलित हैं।

### न्यायाधिकरण के समक्ष के कुछ मामले

१. उत्तरीय अटलांटिक मत्स्यालयों का मामला (१९१६) :— नवम्बर २७, सन् १९०६, को एक विशेष स्वीकार पत्र लिखा गया जिसके द्वारा अमेरिका तथा ब्रिटेन की सरकारें इस बात पर सहमत हो गयी कि कुछ प्रश्नों को हेग के विवाचन के स्थायी न्यायालय के सदस्यों में से चुने गये विवाचन न्यायाधिकरण के निर्णय पर छोड़ दिया जाय। सयुक्त राज्य अमेरिका यह दावा करता था कि उनको न्यूफाउण्डलैंड के कुछ भागों से मछली लेने का अधिकार है तथा यह भी दावा किया कि मत्स्यालयों के सम्बन्ध में विनियम, कैनाडा, ग्रेट ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सयुक्त रूप से बनाया जाना चाहिये न कि ग्रेट ब्रिटेन तथा कैनाडा द्वारा अकेले। न्यायाधिकरण ने अपने पचाट में यह प्रकट किया कि सयुक्त राज्य अमेरिका को दी गई मत्स्यालयों की स्वतन्त्रता से उनके पक्ष में कोई अन्तर्राष्ट्रीय दासत्व उत्पन्न नहीं होता। इसने यह भी मत प्रकट किया कि ग्रेट ब्रिटेन का सयुक्त राज्य अमेरिका की सम्मति के बिना विनियम बनाने के अधिकार का उपयोग इस बात पर सीमित था कि ऐसे विनियम भाव युक्त होने चाहिये तथा उनको सन् १८१८ की संधि का उल्लंघन न करना चाहिये।

२. सावरकर का मामला (१९११) :— सावरकर एक भारतीय नेता, जो ब्रिटेन के डाक जहाज मोरिया में बन्दी के रूप में इंग्लैण्ड से भारत को ले जाये जा रहा था, का जब जहाज मार्सलीज पहुँचा तो वे भाग गये। वह फ्रांस की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये तथा जहाज के कप्तान को, बिना प्रत्यक्ष सम्बन्धी कार्यवाही किये, हस्तगत कर दिया गया। फ्रांस की यह माँग कि भागे हुये बन्दी वापस कर दिया जाय ब्रिटेन की सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दी गयी। विवाचन के स्थायी न्यायालय के पाँच सदस्यों से बने हुये न्यायाधिकरण विचार के लिये उपस्थित हुआ वह यह था कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि अनुसार भागा हुआ बन्दी फ्रांस की सरकार को वापस कर दिया

‘वार्थरूप मे परिणत करना बड़ा ही कठिन, समय नष्ट करने वाला तथा अधिक अप्रव्ययी था’ तथा “न्यायशास्त्र के समूह को एकत्रित करने का कोई आधार नहीं था । यद्यपि १६०७ की प्रतिज्ञा द्वारा एक ऐसे न्यायालय का संगठन अपेक्षित था जो स्वतन्त्र हो, सुविधा से प्राप्त हो और ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बना हो जो विश्व की विभिन्न न्यायिक पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करते हो तथा विवाचन न्याय शास्त्र मे अविच्छिन्नता सुनिश्चित करने के लिये योग्य हो, तथापि जो न्यायाधिकरण हेतु मे बना वह एक स्थायी न्यायालय नहीं था । इसके न्यायाधीश भी स्थायी पदाधिकारियों के वर्ग के नहीं थे । वास्तव मे न्यायाधिकरण को न्यायालय केवल सीज यत्ता से कहा जा सकता था । यह कवल एक उपाय ‘तदर्थ’ (ad hoc) न्यायाधिकरणों को संगठन करने का था । इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय एक स्थायी न्यायालय था जिसमे न्यायाधीशों तथा पदाधिकारियों की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए थी । यहाँ राज्यों को अपने न्यायाधीशों को एक सूची मे छानने का विकल्प नहीं था जैसी दशा कि विवाचन के स्थायी न्यायालय मे थी ।

**न्यायालय की पहुँच (Access to Court)** — सविधि के अनुच्छेद ३४ मे यह व्यवस्था की गई थी कि केवल राज्य अथवा लीग आफ नेशन्स के सदस्य न्यायालय के समक्ष मामलों मे पक्षकार हो सकते थे । अनुच्छेद ३५ ने न्यायालय को लीग आफ नेशन्स के सदस्यों तथा उन राज्यों के लिये खोल दिया जो प्रतिज्ञापत्र की अनुसूची मे उल्लिखित थे, किन्तु लीग आफ नेशन्स के उन सदस्यों के लिये नहीं जो दिसम्बर ६, सन् १९२० के हस्ताक्षर के मसौदे मे पक्षकार हुए थे ।

**न्यायालय का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of the Court)** — सविधि के अनुच्छेद ३६ के अन्तर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे वे सब मामले आते थे जिनमें किसी झगड़े का पक्षकार उसे निर्देशित करे चाहे उस समय उसका प्रवर्तन किसी संधि अथवा प्रतिज्ञापत्र के विशेष प्रतिबंध के अधीन अथवा एक घोषणा द्वारा जिसमे न्यायालय का क्षेत्राधिकार “अनिवार्य स्वतः सिद्ध तथा बिना किसी विशेष स्वीकार पत्र के” स्वीकार किया गया हो । अनुच्छेद ३७ मे यह व्यवस्था की गयी थी कि जब उस समय उसका प्रवर्तन किसी संधि अथवा प्रतिज्ञापत्र मे यह अनुबोधित हो कि किसी विषय को लीग आफ नेशन्स द्वारा संगठित किये गये न्यायाधिकरण में निर्देशित किया जाय तो उस दशा मे न्यायालय ही सम्यक् न्यायाधिकरण था । यह भी व्यवस्था की गई थी कि सदस्यगण वैकल्पिक खंड को एक भिन्न मसौदे पर हस्ताक्षर करके स्वीकृत कर ले जिस पर हस्ताक्षर से यह प्राण्य प्रकट होता था कि निम्नलिखित विषयों पर न्यायालय में निर्णय किया जाय अर्थात् —

of the League for adoption plans for the establishment of a Permanent Court of International Justice" ) । इसके अनुसार परिषद् ने फरवरी १३, सन् १९२० को कुछ सुविख्यात न्यायविशारदों को न्यायालय के स्थापनार्थ योजनाएँ बनाने तथा परिषद् को प्रतिवेदित करने के लिए एक समिति बनाने के लिये निमन्त्रित किया । इस पर उन्होंने एक योजना बनायी जो मुख्यतः परिषद् तथा सभा द्वारा ग्रहण की गयी ।

**न्यायालय के सदस्यगण** — न्यायालय सन् १५ स्वतंत्र विचार के न्यायाधीशों का एक समूह था जिसमें उनकी राष्ट्रीयता का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था और ये लोग उन व्यक्तियों में से होते थे जो उच्च नैतिक चरित्र के थे तथा अपने-अपने देश में सर्वोच्च न्यायिक पद में नियुक्ति की योग्यता रखते थे । वे नौ वर्षों के लिये निर्वाचित होते थे तथा पुनः निर्वाचित हो सकते थे । विवाचन के न्यायालय में जातीय वर्गों द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्तियों की सूची में से न्यायाधीशों का निर्वाचन सभा तथा परिषद् को सौंपा गया था । किसी निर्वाचन के लिए मतों का पूर्ण बहुमत होना आवश्यक था । निर्वाचन केवल उसी दश में निश्चिन माना जाता था जब प्रार्थी उसे स्वीकृत कर ले । उपबन्ध के अनुच्छेद ३१ में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक प्रतिस्पर्धी पक्षकार के जातीय न्यायाधीशों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले में बैठन का अधिकार है ।

न्यायालय नौ न्यायाधीशों की गणपूर्ति (कोरम) से बनता था ।

अनुच्छेद २१ में यह व्यवस्था की गई कि न्यायालय अपना समापति तथा उप-समापति तीन वर्ष के लिये निर्वाचित कर लेगा और एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा ।

न्यायालय का स्थान हग में स्थापित किया गया ।

न्यायालय ने फरवरी १५, सन् १९२२ को १५ सदस्यों से प्रारंभ ११ न्यायाधीशों तथा ४ उप-न्यायाधीशों से उस समय कार्य करना प्रारम्भ किया जब उन्होंने शपथ ग्रहण की ।

**राजनैतिक विशेषाधिकार** :—संविधि के अनुच्छेद १८ में यह व्यवस्था की गई थी कि "न्यायालय के सदस्यगण जब ये न्यायालय के कार्य में लगे हों राजनैतिक विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ का उपयोग करेंगे ।"

**विवाचन न्यायालय पर सुधार** : (Improvement on the Arbitration Court) — अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय विवाचन के स्थायी न्यायालय पर एक स्पष्ट सुधार था । यह एक उचित चपन था कि विवाचन न्यायालय को जिसका विचार सन् १८६६ की प्रतिज्ञा में सामने रखा गया था,

“वार्धरूप मे परिणत करना बड़ा ही कठिन, समय नष्ट करने वाला तथा अधिक अप्रयोज्य था” तथा “न्यायशास्त्र के समूह को एकत्रित करने का कोई आधार नहीं था” । यद्यपि १९०७ की प्रतिज्ञा द्वारा एक ऐसे न्यायालय का संगठन अपेक्षित था जो स्वतन्त्र हो, सुविधा से प्राप्य हो और ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बना हो जो विश्व की विभिन्न न्यायिक पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करते हो तथा विवाचन न्यायशास्त्र में अविच्छिन्नता सुनिश्चित करने के लिये योग्य हो, तथापि जो न्यायाधिकरण जेग में बना वह एक स्थायी न्यायालय नहीं था । इसके न्यायाधीश भी स्थायी पदाधिकारियों के वर्ग के नहीं थे । वास्तव में न्यायाधिकरण को न्यायालय केवल सौजन्यता से कहा जा सकता था । यह केवल एक उपाय ‘तदर्थ’ (ad hoc) न्यायाधिकरणों को संगठन करने का था । इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय एक स्थायी न्यायालय था जिसमें न्यायाधीशों तथा पदाधिकारियों की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए थी । यहाँ राज्यों को अपने न्यायाधीशों को एक सूची में छानने का विकल्प नहीं था जैसी दशा कि विवाचन के स्थायी न्यायालय में थी ।

न्यायालय की पहुँच (Access to Court) :—संविधि के अनुच्छेद ३४ में यह व्यवस्था की गई थी कि केवल राज्य अथवा लीग आफ नेशन्स के सदस्य न्यायालय के समक्ष मामलों में पक्षकार हो सकते थे । अनुच्छेद ३५ ने न्यायालय को लीग आफ नेशन्स के सदस्यों तथा उन राज्यों के लिये खोल दिया जो प्रतिज्ञापत्र की अनुसूची में उल्लिखित थे, किन्तु लीग आफ नेशन्स के उन सदस्यों के लिये नहीं जो दिसम्बर ६, सन् १९२० के हस्ताक्षर के मसौदे में पक्षकार हुए थे ।

न्यायालय का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of the Court):—संविधि के अनुच्छेद ३६ के अन्तर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वे सब मामले आते थे जिनको किसी ऋगठे का पक्षकार उसे निदेशित करे चाहे उस समय उसका प्रवर्तन किसी संधि अथवा प्रतिज्ञा-पत्र के विशेष प्रतिबन्ध के अधीन अथवा एक घोषणा द्वारा जिसमें न्यायालय का क्षेत्राधिकार “अनिवार्य स्वतःसिद्ध तथा बिना किसी विशेष स्वीकार-पत्र के” स्वीकार किया गया हो । अनुच्छेद ३७ में यह व्यवस्था की गयी थी कि जब उस समय उसका प्रवर्तन किसी संधि अथवा प्रतिज्ञा-पत्र में यह अनुबन्धित हो कि किसी विषय को लीग आफ नेशन्स द्वारा संगठित किये गये न्यायाधिकरण में निदेशित किया जाय तो उस दशा में न्यायालय ही सम्पूर्ण न्यायाधिकरण था । यह भी व्यवस्था की गई थी कि सदस्यगण वैकल्पिक खड को एक भिन्न मसौदे पर हस्ताक्षर करके स्वीकृत कर ले जिस पर हस्ताक्षर से यह भाष्य प्रकट होता था कि निम्नलिखित विषयों पर न्यायालय में निर्णय किया जाय अर्थात् :—

(१) किसी सन्ध की व्याख्या (The Interpretation of a Treaty) ,

(२) अन्तर्राष्ट्रीय विधि क कोई प्रश्न (Any Question of International Law),

(३) किन्हीं तथ्यों (facts) का अस्तित्व जिनके प्रमाणित होने पर अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन हो जाये (The existence of any fact, which, if proved, would involve a breach of international obligation) ,

(४) अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य के उल्लंघन के लिये जो क्षतिपूर्ति की जाय उसका स्वरूप तथा विस्तार (The nature or extent of the reparation to be made for breach of an international obligation) ।

बीस से अधिक राष्ट्रों ने इस मसौदे का स्वीकार किया । ब्रिटिश सरकार ने न्यायालय का क्षेत्राधिकार सन् १९२७ में कुछ निग्रह के साथ स्वीकार किया ।

न्यायालय अपनी परामर्शदात्री सम्पत्ति स्वतः नहीं दे सकता था । न्यायालय केवल उसी दशा में कार्य कर सकता था जब कोई प्रार्थना उसके अधिकार क्षेत्र में होती थी और यह स्वयं उसी स्थिति में सम्भव था जब परिपक्व प्रयत्न लोग आफ नेशन्स की सभा ऐसा करे ।

न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली विधियाँ — सविधि के अनुच्छेद ३८ में चार वर्ग के विधि के स्रोत दिये गये थे जिनको लागू करने के लिये न्यायालय को निर्देशित किया गया था । वे निम्नवत् थे —

(१) अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Conventions),

(२) अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ियाँ (International Custom),

(३) सम्य राज्यों द्वारा विधि के स्वीकृत सामान्य सिद्धान्त (General Principles of Law accepted by civilized States), और

(४) न्यायिक निर्णय तथा भिन्न भिन्न राष्ट्रों के उच्च विद्वानों के उपदेश (Judicial decisions and teachings of the most highly qualified publicists of the various nations) ।

### स्थायी न्यायालय के प्रमुख निर्णय

१ एस० एम० विम्बेल्डन [ (1923) P C I J Ser A No 1 ] — २१ मार्च, सन् १९२१ का विम्बेल्डन नामक एक विनानिया के जहाज को जर्मन प्राधिकारियों द्वारा बीन नहर में प्रवेश वर्जित कर दिया गया । न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वाससीज की सन्धि व अनुच्छेद ३८० के अन्तर्गत जर्मनी के विम्बेल्डन को वास नहर में निकल जाने की अनुमति देनी चाहिये थी

क्योंकि सन्धि में यह दिया गया है कि कोल नहर उन सभी राष्ट्रां के व्यापारी तथा जमीन जहाजों के लिये स्वतन्त्र रूप से खुली रखी जायगी जिनकी कि जर्मनी ने साथ सन्धि है।

२. पोलैंड में जर्मन निवासी (German Settlers in Poland) :—  
लोग आफ नेशनस की कोन्सिल ने न्यायालय के समान परामर्श के लिये जर्मन निवासियों की समस्या जो कि पोलैंड में बसे हुए थे, रखी। न्यायालय का निष्कर्ष था कि "यहाँ तक कि वे लोग जो कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में एक सामान्य सिद्धान्त के रूप में राज्य के उत्तराधिकार का दावा करते हैं, यह नहीं कहते कि वैयक्तिक अधिकार जिनमें कि राज्य से प्राप्त अधिकार भी सम्मिलित हैं, जहाँ तक कि सम्प्रभुता में उत्तराधिकार के विरुद्ध हैं, अवैध है।"

३. पोलैंड प्रवर साइलेसिया का मामला (Polish Upper Silesia Case) — पोलैंड प्रवर साइलेसिया के मामले में जर्मन हिता का ध्यान में रखते हुये न्यायालय ने सामान्य रूप से स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय विधि को अपनाया, जो कि भले ही अन्ततः जिनेवा अभिसमय का एक अंग बना।

४ एस० एस० लोटस [(1927) P. C I J Ser. A No 10] —  
अगस्त २, सन् १९२६ को फ्रांसीसी डाक जहाज लाटस तथा टर्की के कायला डाने वाले जहाज बोज कोर्ट के बीच में टक्कर हा गई जिसके परिणामस्वरूप टर्की के आठ जातीय जनो को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। न्यायालय ने यह कथन किया कि "अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्वतन्त्र राज्यों के बीच के सम्बन्धों को अनुशासित करती है। अतः राज्यों पर बाध्यकारी विधियाँ उन्हीं की स्वतन्त्र इच्छा से उत्पन्न होनी हैं जो प्रतिज्ञाओं द्वारा अथवा रुढ़ियों द्वारा प्रकट की जाती हैं जिन्हें विधि के सिद्धान्तों का द्योतक माना जाता है तथा जो सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये माय साथ रहने वाला स्वतन्त्र जातियों के बीच के सम्बन्धों को नियमित करने के लिये स्थापित की गई हैं। अतः राज्यों की स्वतन्त्रता पर बन्धना का अनुमान नहीं किया जा सकता।" न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि तुर्की १ तुर्की विधि के अनुसार लेफ्टिनेंट डेमो पर जो टक्कर के समय लोटस जहाज पर पहरे का पदाधिकारी था, दार्डिक् कार्यवाहियाँ भलाकर अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य नहीं किया था। अपराध जिसके लिये लेफ्टिनेंट डेमो के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया था एक असाधधानी तथा अविवेक का कार्य था जो लाटस जहाज पर उत्पन्न हुआ और उसका परिणाम बोजकोर्ट पर प्रकट हुआ। यह दोनों तथ्य ऐसे हैं कि वे वैधिक रूप से पूणतः प्रविभक्त हैं यहाँ तक कि उनके पृथक् करने से अपराध का अस्तित्व ही लुप्त हो जायगा और ऐसी स्थिति में दोनों राष्ट्रो में से प्रत्येक इस घटना के सम्बन्ध में पूर्णरूप से क्षेत्त्राधिकार का उपयोग कर सकता है।



४१६ ]

५. कोरजो की फैक्ट्री से सम्बन्धित मामला (The Case concerning the Factory of Chorzow) :—न्यायालय का मत था “यह एक विधि का सिद्धान्त है कि किसी करार के भंग करने में प्रतिकार का भार सम्मिलित है। यदि किसी अभिसमय को पूरा न किया गया तो उसकी दति-पूर्ति उसके द्वारा होगी।”

अन्य मामले अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय द्वारा निर्णीत कुछ अभियोगों में प्रमुख निम्नलिखित हैं :—डैन्जिग और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सङ्घ, पूर्वोप-प्री-लैंड का मामला, ग्रेको टर्किश समझौते की व्याख्या, मेमेल की सविधि (Statute of Memel) की व्याख्या, लीसान की सन्धि की व्याख्या, डैन्जिग के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, मलबानिया के मत्पसख्यको और ट्यूनिश और मोरक्को की राष्ट्रीयता सम्बन्धित डिग्रियाँ, डैन्जिग में पोलैंड के नागरिकों का व्यवहार, डैन्जिग में पोलैंड की डाक व्यवस्था और रीयर बोर्डर के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, आदि।

### अध्याय ३३

### ३. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय

#### ( The International Court of Justice )

इसकी उत्पत्ति :—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र सङ्घ का अंग है क्योंकि इसकी सविधि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के चार्टर का एक अभिन्न अंग है। इसका परिणाम यह है कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के सब सदस्य सविधि के स्वतः पक्षकार हैं। केवल इसी अर्थ में यह अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय से भिन्न है क्योंकि यह वैधिक रूप से लीग ऑफ नेशन्स का अंग नहीं था और उसकी सविधि प्रतिज्ञा-पत्र से भिन्न एक गृहक अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकार पत्र था। इसका व्यवस्थान प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के व्यवस्थान की असरश-प्रतिलिपि है।

द्वितीय महायुद्ध ने अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के कार्य में, विशेषतः जर्मनी द्वारा होलैण्ड के कारण, अन्तर्भङ्ग किया, किन्तु दो महायुद्धों के बीच में इसके कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास करने तथा भगड़ों का शान्ति-पूर्वक समझौता प्राप्त करने की क्षमता के कारण एक नई भाषा का संचार किया। इसके निर्णय इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं कि इसने अन्तर्राष्ट्रीय विधि के जटिल

प्रश्नों की गुत्थियों को सुलझा कर अन्तर्राष्ट्रीय तनावों को कम करने का निष्कपट प्रयास किया। अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्थायी न्यायालय अन्न में लीग आफ नेशन्स की अन्तिम सभा द्वारा अप्रैल सन् १९४६ में विधित्त कर दिया गया। इसके पूर्व संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के चार्टर ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के मुख्य अंग के रूप में स्थापित किए जाने की व्यवस्था पहले से ही कर ली थी। वर्तमान न्यायालय की बैठक हेग में सर्वप्रथम अप्रैल ३, सन् १९४६ को हुई।

चार्टर के अनुच्छेद ९२ में यह विशेष रूढ़ि से उपबन्धित है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र सङ्घ का मुख्य न्यायिक अंग होगा और सलग्न सबिधि के अनुसार कार्य करेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के व्यवस्थान पर आधारित है।

**न्यायालय का संगठन:**—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के समान पन्द्रह न्यायाधीश एक समापति तथा एक उप-समापति के अधीन होते हैं जो न्यायालय के सदस्यों द्वारा उन्हीं में से निर्वाचित किये जाते हैं। न्यायालय के न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र सङ्घ की सुरक्षा परिषद् तथा साधारण सभा द्वारा उन उम्मीदवारों में से निर्वाचित होते हैं जो पहले विवाचन के स्थायी न्यायालय के जातीय वर्गों द्वारा मनोनीत किये गये हैं। न्यायाधीश उनकी जातीयता की अपेक्षा किये बिना उन व्यक्तियों में से छाटे जाते हैं जो बहुत उच्च नैतिक चरित्र के हों तथा जो ऐसी योग्यता रखते हों जो उनके अपने देश में सबसे उच्च न्यायिक पद की नियुक्ति के लिये अपेक्षित हों अथवा जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि में मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाले न्याय-विशारद हों, किन्तु इस बात के स्पष्ट अनुबन्ध हैं कि कोई दो न्यायाधीश उसी राष्ट्र के जातीयजन नहीं हो सकते। वे न तो कोई राजनैतिक अथवा प्रशासकीय कृत्य कर सकते हैं और न व्यावसायिक रूप के किसी कार्य में लग सकते हैं। न्यायालय के न्यायाधीश नौ वर्ष के लिये निर्वाचित किये जाते हैं और उनका पुनः निर्वाचन हो सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की सबिधि के अनुच्छेद ३१ में झगड़े के प्रत्येक पक्ष-कार के जातीय न्यायाधीशों को यह अनुज्ञा दी गई है कि वे न्यायालय के समक्ष मामले में अपने बैठने के अधिकार को बनाये रखें। यदि न्यायालय न्यायसभा में केवल एक ही पक्षकार का न्यायाधीश है तो दूसरे पक्षकार को यह अधिकार है कि वह अपने ही मनोनीत व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित करे। यदि न्यायालय न्याय-सभा में पक्षकारों के जातीय कोई न्यायाधीश सम्मिलित नहीं हैं तो प्रत्येक पक्षकार अपनी इच्छा अनुसार किसी न्यायाधीश को मनोनीत कर सकता है।

न्यायालय के बैठने का स्थान हेग में स्थापित किया गया है किन्तु जब कभी इसे वांछनीय हो तो न्यायालय अन्य स्थान में भी बैठ सकता है ।

न्यायालय की क्षमता (Competence of the Court) :—संविधि के अनुच्छेद ३४ के अन्तर्गत यह व्यवस्था दी गई है कि न्यायालय के समस्त राज्य ही पक्षकार के रूप में प्रकट होंगे । इस नियम की दृढ़ता आगे के दो अनुच्छेदों द्वारा कुछ कम हो गई है । पहले तो नियमों के अनुसार सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से न्यायालय निवेदन करेगा जिसमें मामलों की सूचना दी जायेगी और ऐसी सूचनाएँ वह ऐसे संगठनों द्वारा उन्हीं की इच्छा के आधार पर प्राप्त करेगा । संविधि में सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा नहीं दी गई है । ओपेनहेम इसकी परिभाषा करते हुए इसे "A body created by a treaty between states and composed, at least in part, of representatives of states", कहते हैं, अर्थात् यह एक ऐसा संगठन है जो कि इसे निर्मित करने वाले राज्यों के बीच की सन्धि के आधार पर कम से कम अंश रूप में ही राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित है । दूसरी बात यह है कि जब कभी सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ को निर्मित करने वाले तथ्यों या किसी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय को स्वीकृत करने का प्रश्न न्यायालय के समक्ष आता है तो रजिस्ट्रार इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय सार्वजनिक सङ्घ की विज्ञप्ति करेगा और इसकी समस्त लिखित कार्यवाहियों की सूचना देगा ।

न्यायालय का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of the Court) :—न्यायालय उन राज्यों के ऊपर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है जो संविधि के पक्षकार हैं तथा उन राज्यों पर जो न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास एक घोषणा जमा कर दे जिसमें वार्टर के अनुसार न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्वीकृति व्यक्त हो तथा यह प्रतिज्ञा की गई हो कि वे न्यायालय के निर्णयों का सद्भावनापूर्वक पालन करेंगे और वार्टर के अनुच्छेद ६४ के अनुसार कर्तव्यों को स्वीकृत किया गया हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के वार्टर का अनुच्छेद ६४ निम्नलिखित है—

"संयुक्त राष्ट्र सघ का प्रत्येक सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि किसी मामले में जिसमें वह पक्षकार हो वह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करेगा ।" Each member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party."

न्यायालय का क्षेत्राधिकार तीन भागों में विभाजित है, अर्थात् [१] ऐच्छिक, [२] अनिवार्य तथा, [३] मंत्रणा ।

१ ऐच्छिक क्षेत्राधिकार (Voluntary Jurisdiction) — न्यायालय की सविधि के अनुच्छेद ३६ में यह उपबन्धित है कि इसके क्षेत्राधिकार के अन्दर वे सब मामले आते हैं जो पक्षकार न्यायालय को स्वीकारोक्ति द्वारा निर्दिष्ट करे। भगडे को निर्दिष्ट करने की स्वीकारोक्ति दोनों पक्षकारों द्वारा की जा सकती है अथवा केवल एक पक्षकार मामले को निर्दिष्ट करे और दूसरा पक्षकार निर्दिष्ट के लिये अपनी सहमति प्रकट करे।

२ अनिवार्य क्षेत्राधिकार (Obligatory Jurisdiction) — अनुच्छेद ३६ के खंड २ में यह उपबन्धित है कि वे राष्ट्र जो वर्तमान सविधि का पक्षकार हैं किसी समय भी यह घोषणा कर सकते हैं कि वे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अनिवार्य स्वरूप सिद्ध तथा उसी कर्तव्य को स्वीकार करने वाले किन्हीं अथवा राज्यों के सम्बन्ध में किसी विशेष स्वीकारोक्ति बिना निम्नलिखित से सम्बन्धित सब वैधिक भगडों में स्वीकार करते हैं।

(अ) किसी सन्धि की व्याख्या (The interpretation of a treaty),

(आ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि का कोई प्रश्न (Any Question of International Law),

(इ) किसी तथ्य का अस्तित्व जिसके सिद्ध होने पर किसी अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाय। (Existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation), और

(ई) किसी अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्य के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप तथा परिमाण। (Nature and extent of the reparation for the breach of an international obligation),

राज्यों द्वारा की गई उपरोक्त घोषणा स्वीकारोक्ति द्वारा अनिवार्य क्षेत्राधिकार को व्यवस्था करती है क्योंकि न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल उसी दशा में कर सकता है जब भगडे के दोनों पक्षकारों ने घोषणा की हो जैसा अनुच्छेद ३६ के खंड २ में उपबन्धित है।

सविधि में यह उपबन्धित है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय की सविधि के पुराने वैकल्पिक वाक्यखंड के अन्तर्गत की गई घोषणाओं से यह समझा जायेगा कि वर्तमान न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को स्वीकृति कर ली गई है। वर्तमान न्यायालय के बनने के समय १७ राज्यों की घोषणाएँ उस समय प्रवृत्त थी जो इसको अन्तर्लिखित कर दी गयी। अधिकांश घोषणाएँ अदला-बदली की शर्त के अधीन हैं अथवा उनमें कुछ निग्रह है।

न्यायालय का अनिवार्य अथवा आवश्यक क्षेत्राधिकार भी उस दशा में है जब सम्बन्धित पक्षकार किसी ऐसी प्रतिज्ञा से बद्ध हो जिसके अधीन उन्होंने उस मामले को किसी न्यायाधिकरण को निदिष्ट करने के लिये स्वीकृत दी हो जो सींग आफ नेशनस द्वारा बनाया जाने वाला था अथवा अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय को निदिष्ट करने के लिये स्वीकृत दी हो और व्यवस्थान के अनुच्छेद १७ के अनुसार ऐसे विषय स्वतः अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को निदिष्ट किये जाते हैं। न्याय सम्बन्धी स्वीकारोक्तियाँ भी हैं जिनमें किसी स्वीकार-पत्र की व्याख्या अथवा उसके लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासकीय अधिकारी तथा समुक्त राष्ट्र सङ्घ के किसी अन्य सदस्य के बीच झगडा उठने में उस विषय को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में निदिष्ट किये जाने की व्यवस्था की गई है। इसके उपरान्त कुछ विशिष्ट अभिकरण भी हैं जिन्होंने झगडे को न्यायालय में निदिष्ट करने की व्यवस्था की है किन्तु यहाँ फिर यह कहा जा सकता है कि ऐसे मामले न्यायालय के समक्ष केवल उसी दशा में रह जाते हैं जब प्रशासकीय अधिकारी तथा समुक्त राष्ट्र सङ्घ अथवा विशिष्ट अभिकरणों के बीच कोई स्वीकृति हो।

चार्टर में विशेष रूप से उपबोधित विषयों के संबंध में उसके अनुच्छेद ३६ के खंड ३ में यह उपबोधित है कि वैधिक झगडे सामान्यतः पक्षकारों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को न्यायालय की सविधि के अनुबन्धों के अनुसार निदिष्ट किये जाने चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सामान्य सिद्धान्त जहाँ तक न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित है इस प्रकार सक्षिप्त किया जा सकता है। राज्यों को बिना उनकी सहमति के अपने झगडों को न्यायालय के समक्ष बादानुवाद करने को बाध्य नहीं किया जा सकता है और न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन मामलों तक सीमित है जो स्वेच्छा से इसके समक्ष रहे जाय, केवल उस दशा को छोड़कर जब झगडे के पक्षकारों में से एक ने अपने वा स्पष्टतया इस बात के लिये पहले से बद्ध कर दिया है कि वह किसी विशिष्ट झगडे अथवा झगडों के वर्ग के सम्बन्ध में न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्वीकार करेगा।

३. मंत्रणा क्षेत्राधिकार ( Advisory Jurisdiction ) :— न्यायालय सुरक्षा परिषद् अथवा सामान्य सभा द्वारा इसको निदिष्ट किये गये वैध विषयों में परामर्शदाता का कार्य कर सकता है। समुक्त राष्ट्र सङ्घ के अन्य अथवा विभिन्न अभिकरण या सामान्य सभा द्वारा सजत किये जाने पर वैध प्रश्नों पर परामर्शदाता सम्मति माँग सकते हैं। इन विषय पर सींग चार्टर वा अनुच्छेद ६६ प्रवर्तित है जो कि निम्नलिखित है :—

१. साधारण सभा अथवा सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी वैध प्रश्न पर परामर्शदात्री सम्मति देने के लिये प्रार्थना कर सकती है ।

२. संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंग तथा विशिष्ट अभिकरण भी सामान्य सभा द्वारा इस सम्बन्ध में कभी भी प्राधिकृत किये जाने पर अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न होने वाले वैध प्रश्नों पर न्यायालय की परामर्शदात्री सम्मति के लिये प्रार्थना कर सकते हैं ।

स्वीकार-पत्रों से अधिकांश में जिनके द्वारा कुछ विशिष्ट अभिकरण संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति घनिष्ठ संपर्क में कार्य करने के समक्ष होते हैं ऐसी व्यवस्थायें हैं जिनसे उन्हें प्राधिकृत किया गया है कि वे अपने-अपने कार्य-क्षेत्रों के भीतर उत्पन्न होने वाले वैध प्रश्नों पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शदात्री सम्मति के लिये प्रार्थना कर सकते हैं ।

ऐसी परामर्शदात्री सम्मति पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं है किन्तु राज्य न्यायालय द्वारा इस प्रकार दी जाने वाली सम्मति के सम्बन्ध में अपने को पहले से ही सधि अथवा स्वीकार पत्र द्वारा बाध्य कर सकते हैं । यह उस संधि में किया गया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों पर सामान्य प्रतिज्ञा के नाम से प्रसिद्ध है जिसकी धारा ३० में यह उपबन्धित है कि एक ओर से संयुक्त राष्ट्र संघ तथा दूसरी ओर से किसी सदस्य के बीच में वर्तमान प्रतिज्ञा की व्याख्या तथा उसके लागू किये जाने के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले सब मतभेद अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को किसी वैध प्रश्न के सम्बन्ध में परामर्शदात्री सम्मति के लिये निदिष्ट किये जायेंगे और न्यायालय द्वारा दी हुई सम्मति पक्षकारों द्वारा निर्णायक स्वीकार की जायगी ।

परामर्श क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रक्रिया (Procedure with regard to exercise of advisory jurisdiction) :—ऐसा प्रश्न जिनके सम्बन्ध में न्यायालय से परामर्श माँगा जाता है लिखित निवेदन के आधार पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है । उसमें प्रश्न का ठीक-ठीक वक्तव्य होता है जिसमें कि परामर्श की आवश्यकता होती है । उसके साथ सभी लेख्यप्रमाण जो कि उस प्रश्न पर प्रकाश डाल सके, संलग्न होते हैं । रजिस्ट्रार उन सभी राज्यों से जिनके कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की संभावना रहती है उस निवेदन की परामर्श हेतु सूचना देता है । वह विशिष्ट और सीधे पत्र-व्यवहार द्वारा किसी राज्य को सूचना दे सकता है जिसे कि न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है या यह सूचना न्यायालय के विचार के अनुसार किसी अन्तर्राष्ट्रीय संघ को भी दी जा सकती है । राज्य और संघ जब लिखित या मौखिक वक्तव्य दे लेते हैं तो संघ के अन्य राज्यों

द्वारा उसकी व्याख्या होती है और रजिस्ट्रार समय के क्रम से ऐसे किसी भी लिखित वक्तव्य की सूचना राज्यों और सघों की समानान्तर वक्तव्य के रूप में दे सकता है। न्यायालय को अपनी सलाह खुले न्यायालय में देनी होती है। इसकी सूचना पहले से ही सयुक्त राष्ट्र सघ के महासचिव और सदस्य प्रतिनिधियों को दे दी जाती है। ये प्रतिनिधि दूसरे राज्यों और अन्तर्राष्ट्रीय सघों से तात्कालिक रूप में सम्बद्ध होते हैं। अपने परामर्शदात्री वक्तव्य के पालन में न्यायालय वर्तमान सविधि की भी सहायता लेता है।

**न्यायाधीशों की उन्मुक्तियाँ (Immunities of the Judges)** — न्यायाधीशों के सदस्य जब न्यायालय के कार्य में लगे हो राजनैतिक विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों का उपभोग करते हैं। न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के प्रतिवक्ता, प्रतिवक्ता तथा अधिवक्ता भी अपने-अपने वक्तव्यों के स्वतन्त्रतापूर्वक पालन के आवश्यक विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का उपभोग करते हैं। न्यायालय के सदस्यों तथा रजिस्ट्रार का वेतन, भत्ता तथा प्रतिकार सब करो से उन्मुक्त हैं।

**न्यायालय द्वारा लागू की जाने वाली विधि** — सविधि के अनुच्छेद ३८ में यह व्यवस्था की गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका कार्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार ऐसे झगड़ों का निर्णय करना है जैसा कि इसके समक्ष रखे जायें लागू करेगा :—

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों (International Conventions) को चाहे वे सामान्य हो अथवा विशेष जिनसे वे नियम स्थापित हो जो प्रतिस्पर्धी राज्यों द्वारा स्पष्टतया स्वीकृत किये गये हो।

(आ) अन्तर्राष्ट्रीय रूढ़ियों (International Custom) को इस बात के साक्ष्य में कि कोई सामान्य प्रथा विधि के रूप में स्वीकृत है।

(इ) सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धान्त।

(ई) न्यायिक निर्णय तथा भिन्न-भिन्न राज्यों के अत्यन्त उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले लेखकों के उपदेश, विधि के नियमों को निश्चित करने के लिये सहायक उपायों के रूप में।

सविधि के अनुच्छेद ५६ के अनुसार न्यायालय का निर्णय पक्षकारों तथा उस विशिष्ट मामले को छोड़ कर और कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता।

**न्यायालय की प्रक्रिया (Procedure of the Court)** — न्यायालय के समक्ष मामले या तो विशेष स्वीकारोक्ति की अधिसूचना द्वारा अथवा रजिस्ट्रार के नाम दिये गये एक लिखित प्रार्थना-पत्र द्वारा लाये जाते हैं। किसी झगड़े के निर्णय के लिये जब तक व्यवस्थान में अन्यथा उपबोधित न हो पूरा न्यायालय बैठता है।

नौ न्यायाधीशों की गणपूर्ति ( फोरम ) से न्यायालय बनता है । सब प्रश्न, निर्णय को सम्मिलित करते हुए, बहुसंख्या से निर्णित होते हैं । मतों के समान होने की दशा में समापति अथवा उस न्यायाधीश को जो उसका स्थान में कार्य करता है निर्णायक मत देने का अधिकार है । निर्णय अन्तिम होता है और उसकी अपील नहीं होती । निर्णय का पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा केवल उसी दशा में किया जाता है जब कोई तथ्य इस प्रकार का उपलब्ध हो जो निर्णायक तथ्य के रूप में हो तथा जो निर्णय देने के समय न्यायालय को तथा पुनरीक्षण चाहने वाले पक्षकार को अज्ञात रहा हो, किन्तु उपबन्ध यह है कि ऐसी अज्ञानता असावधानी के कारण न हुई हो । निर्णय क लिये कारण दिए जाते हैं । जैसा ऊपर कहा जा चुका है न्यायालय के निर्णय उत्तरवर्ती मामलों में वैध रूप से बाध्यकारी नहीं हैं और प्रत्येक निर्णय अपने ही तथ्यों पर रहता है । न्यायालय यदि ऐसा करना चाहे तो अपने पूर्ववर्ती निर्णयों की आत्महानि के बिना उनकी उपेक्षा कर सकता है । न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी है किन्तु न्यायालय अन्य भाषा का भी प्रयोग अधिकृत कर सकता है ।

**अन्तरिम अथवा अन्तःकालीन उपाय ( Interim or Provisional Measures ) :**—न्यायालय की सविधि के अनुच्छेद ४१ में उन अन्तःकालीन उपायों की व्यवस्था की गई है जिन्हें न्यायालय झगड़े के निर्णय के अलबित रहने तक निर्दिष्ट करे । इसमें लिखा है —

१. न्यायालय को यह अधिकार होगा कि यदि वह निश्चय करे कि परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित है तो कोई अन्तःकालीन उपाय बतावे जो प्रत्येक पक्षकार के यथाक्रम अधिकारों के संरक्षण के लिए करना चाहिये ।

२ अन्तिम निर्णय के अलबित रहने तक प्रस्तावित उपायों का नोटिस तत्काल पक्षकारों को तथा सुरक्षा परिपद को दे दी जायेगी ।

**आग्ल-ईरानी तेल कम्पनी का मामला ( I C J Report 1952, p 93 )** —फारस के तेल उद्योग राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी आग्ल-ईरानी झगड़े में ब्रिटेन ने आग्ल-ईरानी कम्पनी के साथ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र दिया कि फारस में उसके अधिकारों की रक्षा के लिये मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय होने तक अन्तःकालीन उपाय अवलम्बन किये जायें । इसी बीच में फारस ने अपनी जून २६ सन् १९५१ को जारी की गई डिग्री के आधार पर आग्ल-ईरानी तेल उपकरणों के अभिग्रहण का आदेश दिया । अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने जुलाई ५, सन् १९५१ के निर्णय द्वारा ब्रिटिश सरकार की इस



प्रार्थना का समर्थन किया कि फारस के तेल के भण्डे में स्थिति यथापूर्व रहने दो जाय । न्यायालय ने अपने बहुमत की सम्मति से यह निर्णय किया कि दानो सरकारें ऐसे उपायो का अवलम्बन करने से अपने को अलग रखें जिनसे तेल का बहाव उस आधार पर रुक जाय जैसा कि यह १ मई से पहले था जब फारस ने राष्ट्रीयकरण विधि को पारित किया । न्यायालय ने यह संस्तुति की कि यह निश्चित करने के लिये कि तेल-उद्योग बराबर बिना बाधा के जारी रहेगा एक निरीक्षक बोर्ड बने जिसमें प्रत्येक सरकार के दो-दो सदस्य रहे तथा एक पाचवाँ भी हो जो एक तीसरे राष्ट्र का जातीय जन हो और ब्रिटेन तथा फारस की स्वीकृति से चुना गया हो ।

फारस सरकार ने आंग्ल-ईरानी तेल प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को इस आधार पर अस्वीकार किया कि न्यायालय को इस विषय में कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, क्योंकि आदेश का अर्थ वास्तव में एक सार्वभौमिक राज्य के विरुद्ध एवं आदेश था जिसके द्वारा उसे आदेश दिया गया था कि अपने आन्तरिक मामलों की न्यायालय ने निर्देशानुसार व्यवस्था करे ।

इस बीच में ब्रिटेन ने इस विषय को सुरक्षा परिषद् को निर्देशित कर दिया और वह इस बात पर सहमत हो गई कि फारस के विरुद्ध ब्रिटेन की शिकायत पर वादानुवाद करे । प्रवृत्त १६, सन् १९५१ को सुरक्षा परिषद् ने आंग्ल-फारस तेल भण्डे पर वादानुवाद उस समय तक स्थगित कर दिया जब तक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय यह निर्णय न करे कि वास्तव में वह आंग्ल-फारस तेल भण्डे को निबटाने के लिये सक्षम है अथवा नहीं । जुलाई २२, सन् १९५२ को न्यायालय ने पाँच के विरुद्ध नौ वोटों से यह निर्णय किया कि वह ब्रिटेन के इस आरोप का विचार नहीं कर सकता कि फारस ने आंग्ल-ईरानी तेल कम्पनी की ५० लाख पीट स्टॉकिंग की फारसी सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उलघन किया । इसके अनुसार न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह आंग्ल-फारस तेल-भण्डे को निबटाने में सक्षम नहीं है और फारस के विरुद्ध ब्रिटेन की इस शिकायत का अस्वीकृत कर दिया कि उसने ब्रिटिश स्वत्वाधिकार वाले तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया ।

न्यायिक निर्णय का निष्पादन (Execution of Judicial Decisions) :—अब हम अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों के निष्पादन के प्रश्न पर आते हैं । न्यायालय की सर्वाधिक न्यायिक निर्णयों को प्रवर्तन करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं करती । जो कुछ व्यवस्था सयुक्त राष्ट्र सच के चार्टर के अनुच्छेद ८४ में पाई गई है, वह यह है :—

“यदि किसी मामले का पक्षकार न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अधीन इसके द्वारा प्रतिपाद्य किसी कर्तव्य को पूरा करने में असफल रहे तो अन्य पक्षकार सुरक्षा परिषद् के पास जा सकता है, जो कि यदि वह आवश्यक समझे तो उन उपायों का अभिस्ताव कर सकती है अथवा निर्णय कर सकती है जो निर्णय प्रभावित करने के लिए करना चाहिये।” “If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment.”

उपरोक्त व्यवस्थायें सुरक्षा परिषद् के लिये यह आवश्यक नहीं करती कि न्यायालय के निर्णयों को हठी पक्षकार के विरुद्ध प्रवर्तन करे। वे केवल सुरक्षा परिषद् के पास एक अपील की प्रक्रिया को प्रकट करती हैं, जो निर्णय को प्रभावित करने के लिए जिन उपायों का अवलम्बन करना चाहिये उनका अभिस्ताव करे या निर्णय करे। सुरक्षा परिषद् के अभिस्तावों के लिये ७ (तथा, अब, अनुच्छेद २७ के सशोधन के पश्चात्, १०) सदस्यों का बहुमत अपेक्षित है जिसमें स्थायी सदस्यों के वोट भी सम्मिलित हैं। यदि सुरक्षा परिषद् न्यायालय के निर्णय का प्रभावित करने के लिये प्रवर्तक उपायों का अवलम्बन करना चाहे तो ऐसा अधिन के अनुच्छेद ४१ अथवा ४२ के अन्तर्गत कर सकती है। अनुच्छेद ४१ में सुरक्षा परिषद् को यह प्राधिकृत किया गया है कि वह सैनिक बल प्रयोग का छोड़ कर ऐसे उपायों का अवलम्बन करे जिनमें आर्थिक सम्बन्ध, रेल समुद्र, डाक, टेलिग्राफ, रेडियो तथा अन्य यातायात साधनों का तथा राजनैतिक सम्बन्धों का विच्छेद सम्मिलित है। अनुच्छेद ४२ उस दशा में लागू होता है जब सुरक्षा परिषद् यह विचार करती है कि अनुच्छेद ४१ में अनुबन्धित उपाय अपर्याप्त हैं और उस दशा में यह वायु, जल तथा स्थल सेनाओं द्वारा ऐसा कार्य कर सकती है जैसा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिये आवश्यक हो। इस कार्य में ऐसे भी कार्य सम्मिलित हो सकते हैं जैसे प्रदर्शन, नाकाबन्दी इत्यादि। फिर भी केल्सन का ध्यान है कि “इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि चार्टर में न्यायालय के निर्णय के अनुपालन न होने की दशा में अपील की प्रक्रिया दी हुई है यह विचार करना कठिन है कि ऐसे अनुपालन को शान्ति के विरुद्ध घमकी अथवा शान्ति को भंग करना कहा जाय।” (Hans Kelsen : The Law of United Nations, p 541)। अपनतेहम का कहना है कि “चार्टर के अनुच्छेद ६४ को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि इसका सशोधन इस प्रकार हो जिससे कि सुरक्षा परिषद् का कार्य आदेशात्मक हो

जाय, न कि केवल अनुज्ञापक तथा इस विषय में सुरक्षा परिषद् का कार्य इसके स्थायी सदस्यों के मतव्य होने की आवश्यकता के बन्धन से मुक्त हो जाय ।"

(Oppenheim : International Law, Vol. II, p. 77).

### न्यायालय के समक्ष मामले

१. कौफू चैनल वाला मामला (I. C. J. Reports 1949, p. 4) :—  
अक्टूबर २२, सन् १९४६ को कुछ ब्रिटेन के जंगी जहाजों को अल्बेनिया के प्रादेशिक जल भागों में सुरंगों के साथ टकराने के कारण क्षति पहुँची । नवम्बर १२ तथा १३ को ब्रिटिश नौसेना द्वारा अल्बेनिया के प्राधिकारियों की बिना सहमति प्राप्ति किये खाड़ी की सफाई किये जाने पर एक हाल ही में लगाई गई लंगड डाली हुई सुरंगों की लाइन उसी स्थान पर पाई गई जहाँ अक्टूबर में घडाके हुये थे । ग्रेट ब्रिटेन का यह भ्रांति था कि खाड़ी में सुरंगों की उपस्थिति के लिये अल्बेनिया उत्तरदायी था ।

फगडे के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को निर्दिष्ट किये जाने पर उसे यह ज्ञात हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत अक्टूबर सन् १९४६ को अल्बेनिया के जल भागों में होने वाले घडाको के लिये तथा उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली क्षति तथा मानव जीवन की हानि के लिए अल्बेनिया की जनता का गणतन्त्र उत्तरदायी था तथा यह ब्रिटेन ने ब्रिटिश नौसेना द्वारा अक्टूबर २२ सन् १९४६ को उसके द्वारा अल्बेनिया के जलभागों में किये गये कार्य के कारण अल्बेनिया की जनता के गणतन्त्र की सार्वभौमिकता का उल्लंघन नहीं किया और यह कि अल्बेनिया के जल-भागों में ब्रिटिश नौसेना के कार्यों द्वारा जो नवम्बर १२ तथा १३ सन् १९४६ के कार्यक्रम में किये गये ब्रिटेन ने अल्बेनिया की जनता के गणतन्त्र की सार्वभौमिकता का उल्लंघन किया तथा न्यायालय की इस घोषणा से ही स्वतः उचित समुचित हो गई । इसके परिणामस्वरूप अल्बेनिया २,४३,६४७ पौण्ड ब्रिटेन को देने के लिये उत्तरदायी ठहराया गया ।

२. ह्या डे ला टोरे का मामला (I. C. J. Reports, 1951, p. 71) :—  
विक्टर रोल ह्या डे ला टोरे पेरुविया का एक नागरिक तथा राजनैतिक नेता को, जो एक सैनिक बग़ावत भडकाने के लिये दोषारोपित था सोमा के कोलम्बिया के राजद्रोतावास में धाग्र्य दिया गया । इस विषय को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को निर्दिष्ट किये जाने पर न्यायालय ने यह बयन किया कि यद्यपि हवाना की प्रतिज्ञा में यह स्पष्टनः निर्धारित है कि सामान्य अपराधियों को स्थानीय अधिकारियों को समर्पित कर दिया जाय तथापि राजनैतिक अपराधियों के सम्बन्ध में ऐसा कोई बर्तव्य विद्यमान नहीं है । फिर भी, इसने अपने पूर्व मत को पुनः दुहराकर कहा कि धाग्र्य अनिवार्य

रूप से दिया गया है और यह कि यद्यपि इस आधार पर वेह इसकी सम्मति की माँग करने का अधिकारी है तथापि कोलम्बिया शरणार्थी को समर्पण करने के लिये बाध्य नहीं है ।

३. एंग्लो-ईरानियन तेल की कम्पनी का मामला—इस विवाद के विषय में पूर्व के प्रसंग में विस्तृत रूप से लिखा जा चुका है ।

४. भारत के कतिपय क्षेत्रों पर पुर्तगालियों के आधिपत्य के अधिकार का मामला—भारत के कतिपय क्षेत्रों में पुर्तगालियों के आधिपत्य के बने रहने के मामले में, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष दिसम्बर २२, १९५५ को लाया गया था, भारत ने न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चार वैध, तथा दो वैध और तथ्य विषयक आधारों पर यह कहकर चुनौती दी कि पुर्तगाल ने इस मुकदमे को जिस पद्धति से न्यायालय के समक्ष रखा है, उसमें न्यायालय-प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है ।

न्यायालय ने नवम्बर २६, १९५७ को अपने निर्णय में कहा कि वह भारत के इस तर्क को मानने में अपने को असमर्थ पा रहा है कि २२ दिसम्बर, १९५५ को पुर्तगाल ने अपना आवेदन पत्र देने में संविधि की असंगति में कार्य किया है । न्यायालय ने ऐसा निश्चय लिया कि समुक्त राष्ट्र सङ्घ के महामन्त्री के साथ न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्वीकृति की घोषणा के उपरान्त अनुच्छेद ३६ के अन्तर्गत दोनों पक्ष समान आभारों के विषय बन जाते हैं । दोनों पक्षकारी के बीच संविदा-रमण सम्बन्ध और उत्पन्न होने वाले न्यायालय के क्षेत्राधिकार की तथ्यतः स्थापना हो जाती है, और यह स्थापना एतदविषयक घोषणा करने के बिना किसी विशेष समझौते पर ही होती है ।

प्रथम सामान्य आपत्ति, जिसमें कि आवेदन प्रस्तुत किये जाने की पद्धति पर आरोप था, न्यायालय ने कहा कि भारत का कथन है कि पुर्तगाली घोषणा भवैध इस कारण है कि इसकी शर्त के अनुसार पुर्तगाल उस घोषणा के किसी भी वर्ग के संघर्ष से किसी भी समय वंचित किया जा सकता है और इसके लिए मान्य महामन्त्री को सूचना देना ही आवश्यक होगा, किन्तु शर्त में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, यदि उनका साधारण अर्थ ग्रहण किया जाय तो सीधा-सा अर्थ यह है कि उस शर्त के अन्तर्गत विजति की व्यवहृति केवल ऐसे विवादों पर होगी जो कि इस विजति के बाद न्यायालय के समक्ष लाये जाएँगे । इस सम्बन्ध में किसी पूर्वगामी प्रभाव की कल्पना नहीं करनी चाहिये । अतः न्यायालय का निष्कर्ष था कि पुर्तगाली घोषणा की शर्त संविधि की असंगति में नहीं थी ।

४२८ ]

भारत की ओर से उठायी गई चौथी आपत्ति, जो कि पुन प्रक्रिया से संबंधित थी, के सम्बन्ध में न्यायालय ने कहा था कि भावेदन को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी ऐसी नहीं है जिसे कि सविधि की अवसिति में कहा जा सके क्योंकि सविधि में स्वीकृति की घोषणा और भावेदन प्रस्तुत करने की अवधि में किसी मध्यान्तर का उपबन्ध नहीं है ।

तीसरी आपत्ति में भावेदन प्रस्तुत करने के पूर्व किसी राजनीतिक समझौते या मध्यस्थता-वार्ता के अभाव की बात उठाई गई थी । इस सम्बन्ध में न्यायालय का अवलोकन था कि दोनों पक्षकारों के बीच जो पत्र व्यवहार हुये हैं, उन्हें समझौता वार्ता के सम्बन्ध में गतिरोध उत्पन्न हो जाने का अभ्यास मिलता है । अतः यह प्रकल्पना करते हुये कि सविधि के अनुच्छेद ३६ के पैरा २ जिसमें कि वैय भगदो का उल्लेख है, समझौता-वार्ता के द्वारा भगदो की स्थिति की परिभाषा अपेक्षित थी, और यह कि उस परिभाषा में सतैं पूरी हो गई थी ।

पाँचवी आपत्ति के सम्बन्ध में न्यायालय का कथन था कि भारत स्वयं अपनी स्वीकृति की घोषणा में एक धारक्षण पर आश्रित है जिसके अन्तर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार से ऐसे भगदो बाहर कर दिये गये हैं, जिनमें कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रश्न भारत सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एकात्मिक रूप से आते हैं, और यह कि भारत ने इस तथ्य की स्वीकार किया है कि न्यायालय के समक्ष आये हुये तात्त्विक और वैध विचार इस निष्कर्ष को नहीं स्वीकृत करते कि प्रस्तुत प्रश्न की विषयवस्तु भारत के घरेलू-क्षेत्राधिकार की सीमा से एकात्मिक रूप में बाहर थी । न्यायालय ने कहा कि जिन तर्कों पर भारत आश्रय ले रहा है, पुर्तगाल उसे मानने की तैयार नहीं है, अतः बिना 'मेरिट' के पूर्व निर्णय किये इस प्रश्न का परीक्षण नहीं किया जा सकता । तदनुसार न्यायालय ने पाँचवी आपत्ति के प्रश्न को 'मेरिट' के प्रश्न के लिये संयुक्त कर दिया ।

अन्तिम रूप में, भारत द्वारा उठायी गई छठी आरम्भिक आपत्ति पर, जो कि समय की अवधि के आधार पर उठायी गई थी, न्यायालय ने कहा कि यह निश्चय करने के लिये कि ठीक-ठीक किस तिथि को यह भगदो आरम्भ हुआ, इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या यह भगदो १९३० में आरम्भ हुये मार्गाधिकार के भगदो की निरन्तरता में है अथवा नहीं । दोनों ओर से एक-दूसरे के तर्कों को खण्डन करने वाले तथ्य प्रस्तुत किये गये और न्यायालय प्रस्तुत प्रश्न का निर्णय न कर सका । अतः इस प्रश्न को भी उसने 'मेरिट' के प्रश्न के लिये संयुक्त कर दिया गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पुर्तगाल विवाद के प्रसंग में भारत की ओर से प्रत्यायुक्त तदर्थ न्यायाधीश श्री एम० सी० चागला ने, जो कि बम्बई के मुख्याधीश थे, एक असहमतिसूचक निर्णय दिया और कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं, जिनपर किसी भी प्रकार दो मत नहीं हो सकते। पहली बात यह है कि पुर्तगाल जिस भू क्षेत्र से आवागमन या परिवहन का अधिकार माँग रहा है, वह एकान्तिक रूप से भारतीय भू-क्षेत्र है और उस पर उसकी संप्रभुता अखंड है। इसके साथ ही यह भी एक विवादरहित बात है कि प्रथम दृष्ट्या कोई राज्य जब क्षेत्रीय संप्रभुता का उपभोग कर रहा है, तो उसे यह अधिकार है कि किसी अन्य राज्य को उस क्षेत्र से आवागमन या परिवहन की अनुमति दे, अथवा ऐसा करने से निषेधित कर दे, या ऐसे आवागमन या परिवहन की अनुमति अपने द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों की सीमा में प्रदान करे।

श्री चागला ने आगे कहा था कि पुर्तगाली डामन, दावरा और नगर हवेली के बीच से आवागमन एवं परिवहन की अनुमति चाहते हैं जिससे कि वे डामन और इन स्थानों से संचार-सम्पर्क बनाये रखें। जब कोई राज्य इस न्यायालय के समक्ष इस दावे को लेकर आता है कि दूसरे राज्य के प्रति उसका अधिकार है, तो वह अधिकार अवश्य ही ऐसा होना चाहिये जिसका कि प्रवर्तन किया जा सके। इस प्रसंग में पुर्तगालिया के दावे की सबसे माश्चर्यजनक विशेषता यह है कि यदि वह अपने तर्कों में सफल भी हो गये, तो भी जो निर्णय इस न्यायालय द्वारा उन्हें मिलेगा, भारत उसे कदापि भी प्रभावकारी रूप नहीं लेने देगा। इस सम्बन्ध में श्री चागला ने तर्क प्रस्तुत किया था कि "If the Court were to declare that Portugal had a right of transit over Indian territory, from Daman to the enclaves, it would be impossible for India to know what the nature, extent or content of that right would be. Would Portugal be entitled under this right to transport a whole army from Daman to the enclaves in order to suppress the revolt which taken place there? Would she be able to transport tanks and artillery and all the paraphernalia of modern arms and armaments? Would she be able to fly aeroplanes over Indian territory in order to bomb the enclaves in order to reduce them to subjection?"—अर्थात् "यदि न्यायालय यह घोषित भी करे कि पुर्तगाल को डामन के भारतीय क्षेत्र में यातायात करने का अधिकार है, तब भी भारत के लिए यह जान पाना एक असम्भावितता होगी कि उस अधिकार की वास्तविक प्रकृति, विस्तार और विषय तत्व क्या होगा? क्या इस अधिकार के अन्तर्गत पुर्तगालियों को यह अधिकार होगा कि वे डामन से होकर अपनी पूरी सेना,



१७७६ की संधि तथा १७८३ और १७८५ के संधि में मराठों का आशय पुर्तगालियों को केवल जागोर सौंप देने का था, या सरजाम दे देने का था, और उन गाँवों की पूरी संप्रभुता ही उन्हें सौंप देने का आशय न था, क्योंकि मात्र राजस्व संप्रह करने के अधिकार का तात्पर्य संप्रभुता सौंप देने का अधिकार नहीं हुआ करता ।

इसके बाद जब मराठों से आधिपत्य अंग्रेजों ने लिया, तब भी न तो अंग्रेजों ने स्वयं उस क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा किया और न कभी भी पुर्तगालियों की संप्रभुता को ही मान्यता प्रदान की ।

पुर्तगाल अपने अधीनस्थ उन क्षेत्रों पर अपनी संप्रभुता के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी नियन्त्रण के बिना आवागमन का अधिकार चाहता था । दोनों पक्षकारों के बीच यह एक सामान्य आधार था कि व्यक्तिगत व्यक्तियाँ और नागरिक अधिकारों के बीच दैनिक नियन्त्रण की अपेक्षा कोई अन्य प्रतिबन्ध नहीं है । इसका प्रतिफल सिद्ध करने का कोई दूसरा प्रमाण नहीं था । इसलिये न्यायालय का निष्कर्ष था कि वैयक्तिक व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों और माल के सम्बन्ध में सामान्यतः डामन से होकर आवागमन की स्वतन्त्रता ब्रिटिश और उत्तर-ब्रिटिश काल में दी गई है और सरकार के बदलते रहने पर भी यह परंपरा उभरी बनी रही है और यहाँ तक भारत के स्वतन्त्र हो जाने के उपरांत भी इस परंपरा का पालन किया गया है । अतः न्यायालय का निर्णय था कि व्यक्तिगत व्यक्तियाँ, नागरिक अधिकारों और माल के इस यातायात का अन्तराष्ट्रीय दृष्टि से एक मान्यता मिल चुकी है और अब भी उस मान्यता का प्रवर्तन किया जा सकता है ।

जहाँ तक सैन्य-शक्तियों के आवागमन का प्रश्न है, न्यायालय का अवलोकन था कि ब्रिटिश और उत्तर-ब्रिटिशकाल में भी पुर्तगाल वालों को डामन से होकर सशस्त्र सेनाएँ ले आने और ले जाने का अधिकार नहीं था और १८७८ के बाद से, इस प्रकार का यातायात केवल ब्रिटिश के प्राधिकार और तदनन्तर भारत के प्राधिकार पर ही सम्भव था । बाद की विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुये न्यायालय की अभिप्राय थी कि इस प्रकार के प्राधिकार प्राप्त करने की शर्त का अर्थ है स्वाभाविक रूप में उस अधिकार को न प्राप्त किया जाना । मन्दाय यह प्रमाणित करता है कि क्षेत्रीय संप्रभु को यह शक्ति थी कि वह अपने विवेक के अनुसार यह अनुमति दे, अथवा देने में इन्कार कर दे । अतः यह अनुमति स्वेच्छया दी जा सकती है, आभार और बाध्यता के रूप में नहीं । न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि भारत द्वारा आवागमन में अतिरिक्त उत्पन्न कर देना परिस्थितियों



४३० ]

किसी विद्रोह को दबाने के लिए भेज सकें ? क्या वे वहाँ से टैंक, मार्टिलरी तथा ग्रायुनक बाँधों की पूरी साज सज्जा भेज सकेंगे ? क्या वे क्षेत्र को सम्पूर्णतः प्रवीन बना लेने के लिए वहाँ तक भारत क्षेत्र से होकर हवाई जहाज भेज सकेंगे, जिससे कि वहाँ से बम वर्षा कर सकें ? ... ..

**‘मेरिट’ पर निर्णय** — (Decision on merits) १२ अप्रैल, १९६० को मेरिट के आधार पर निर्णय करते हुये अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उपर्युक्त वाद के प्रसंग में कहा था कि पुर्तगालियों को भारतीय नियमों के प्रवीन रहते हुये अपने वैयक्तिक व्यक्तियों को ले जाने का अधिकार है, किन्तु सशस्त्र सैनिकों को ले जाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने निष्कर्ष पाया कि भारत ने पुर्तगाल वालों के वैयक्तिक व्यक्तियों के प्रति आभारों के प्रतिशूल आचरण नहीं किया है। साथ ही न्यायालय ने भारत की ओर से उठाई गई दो आभारों को न मानते हुये कहा कि न्यायालय को प्रस्तुत विवाद में विचारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

दिसम्बर २२, १९५५ के अपने आवेदन में पुर्तगाल ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से कहा था कि वह पुर्तगाली डामन से होकर अपने प्रवीनक्षेत्र क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तक नागरिक और सशस्त्र सैनिकों को ले आने और ले जाने के अधिकार को मान्यता प्रदान करे, जहाँ से वह अब प्रभावकारी नियन्त्रण छोड़ चुका है। पुर्तगाल का यह भी कहना था कि न्यायालय यह भी व्यवस्था करे कि भारत पुर्तगालियों के आवागमन को अनुमति देकर वहाँ की तथ्यपूर्ण स्थिति का समापन करे।

भारत ने पुर्तगाली आवेदन का इस आधार पर विरोध किया था कि पुर्तगालियों द्वारा माँग किये गये आवागमन के अधिकार को उस समय तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि वह क्षेत्रीय संप्रभु की स्वकीय इच्छा या अनुमति या सहमति पर न दी जाय। भारत का यह भी तर्क था कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्य यह नहीं प्रकट करते कि क्षेत्रीय संप्रभु की ऐसी कोई प्रकट सहमति या अनुमति नहीं है जो भारत के क्षेत्राधिकार को परिमोमित कर सके।

न्यायालय ने यह निष्कर्ष पाया कि १७७६ की संधि का अनुच्छेद १७ वैध है किन्तु पुर्तगाल वालों का संप्रभुता नहीं प्रदान करता। पुर्तगाल का दावा था कि उस दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र संधि के अनुच्छेद १७ के क्रम में मिले थे और यह कि मराठा ने उन्हें संप्रभुता भी सौंप दी थी। इधर भारत का कहना था कि यह दावा मराठा द्वारा नवस जागीरा की हस्तियत से अपनी संप्रभुता में से वनत १२,००० रु० व मूल्य पर दिया गया था। न्यायालय ने अवलोकन किया कि

१७७६ वीं संधि तथा १७८३ और १७८५ के सवाद में मराठों का आशय पुर्तगालियों को केवल जागीर सौंप देने का था, या सरजाम दे देने का था; और उन गाँवा की पूरी संप्रभुता ही उन्हें सौंप देने का आशय न था, क्योंकि मात्र राजस्व संग्रह करने के अधिकार का तात्पर्य संप्रभुता सौंप देने का अधिकार नहीं हुआ करता ।

इसके बाद जब मराठों से आधिपत्य अंग्रेजों ने लिया, तब भी न तो अंग्रेजों ने स्वयं उस क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा किया और न कभी भी पुर्तगालियों की संप्रभुता को ही मान्यता प्रदान की ।

पुर्तगाल अपने अधोनित्य उन क्षेत्रों पर अपनी संप्रभुता के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी नियन्त्रण के बिना आवागमन का अधिकार चाहता था । दोनों पक्षकारों के बीच यह एक सामान्य आधार था कि व्यक्तिगत व्यक्तियों और नागरिक अधिकारों के बीच दैनिक नियन्त्रण की अपेक्षा कोई अन्य प्रतिबन्ध नहीं है । इसके प्रतिफल सिद्ध करने का कोई दूसरा प्रमाण नहीं था । इसलिये न्यायालय का निर्णय था कि वैयक्तिक व्यक्तियों के नागरिक अधिकारियों और माल के सम्बन्ध में सामान्यतः डामन से होकर आवागमन की स्वतन्त्रता ब्रिटिश और उत्तर-ब्रिटिश काल में दी गई है और सरकार के बदलते रहने पर भी यह परंपरा उन्नीसवीं शताब्दी की तक बनी रही है और यहाँ तक भारत के स्वतन्त्र हो जाने के उपरांत भी इस परम्परा का पालन किया गया है । अतः न्यायालय का निर्णय था कि व्यक्तिगत व्यक्तियों, नागरिक अधिकारियों और माल के इस यातायात को मन्तराष्ट्रीय दृष्टि से एक मान्यता मिल चुकी है और अब भी उस मान्यता का प्रवर्तन किया जा सकता है ।

जहाँ तक सैन्य-शक्तियों के आवागमन का प्रश्न है, न्यायालय का अवलोकन था कि ब्रिटिश और उत्तर-ब्रिटिशकाल में भी पुर्तगाल वालों को डामन से होकर सशस्त्र सेनाएँ ले जाने और ले जाने का अधिकार नहीं था और १८७८ के बाद से इस प्रकार का यातायात केवल ब्रिटिश के प्राधिकार और तदनन्तर भारत के प्राधिकार पर ही सम्भव था । बाद की विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुये न्यायालय की अभिमत थी कि इस प्रकार के प्राधिकार प्राप्त करने की शर्त का अर्थ है स्वामाविक रूप में उस अधिकार को न प्राप्त किया जाना । अग्न्यात यह प्रमाणित करता है कि क्षेत्रीय संप्रभु को यह शक्ति थी कि वह अपने विवेक के अनुसार यह अनुमति दे, अथवा देने में इन्कार कर दे । अतः यह अनुमति स्वेच्छया दी जा सकती है, आभार और बाध्यता के रूप में नहीं । न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि भारत द्वारा आवागमन में गतिरोध उत्पन्न कर देना परिस्थितियों

४३० ]

किसी विद्रोह को दबाने के लिए भेज सकें ? क्या वे वहाँ से टैंक, मार्टिलरी तथा प्राधुनिक शस्त्रों की पूरी साज-सज्जा भेज सकेंगे ? क्या वे क्षेत्र को सम्पूर्णतः घवीन बना लेने के लिए वहाँ तक भारत-क्षेत्र से होकर हवाई जहाज भेज सकेंगे, जिससे कि वहाँ से बम वर्षा कर सके ?.....”

‘मेरिट’ पर निर्णय :—(Decision on merits) १२ अप्रैल, १९६० को मेरिट के आधार पर निर्णय करते हुये अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने उपर्युक्त वाद के प्रसंग में कहा था कि पुर्तगालियों को भारतीय नियमों के अन्तर्गत रहते हुये अपने वैयक्तिक व्यक्तियों को ले जाने का अधिकार है, किन्तु सशस्त्र सैनिकों को ले जाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने निष्कर्ष पाया कि भारत ने पुर्तगाल वालों के वैयक्तिक व्यक्तियों के प्रति आभारों के प्रतिकूल आचरण नहीं किया है। साथ ही न्यायालय ने भारत की ओर से उठाई गई दो आरम्भिक आपत्तियों को न मानते हुये कहा कि न्यायालय को प्रस्तुत विवाद में विचारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

दिसम्बर २२, १९५५ के अपने आवेदन में पुर्तगाल ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से कहा था कि वह पुर्तगाली डामन से होकर अपने अन्तर्देशीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तक नागरिक और सशस्त्र सैनिकों को ले जाने और ले जाने के अधिकार को मान्यता प्रदान करे, जहाँ से वह अब प्रभावकारी नियन्त्रण खो चुका है। पुर्तगाल का यह भी कहना था कि न्यायालय यह भी व्यवस्था करे कि भारत पुर्तगालियों के आवागमन को अनुमति देकर वहाँ की तथ्यपूर्ण स्थिति का समापन करे।

भारत ने पुर्तगाली आवेदन का इस आधार पर विरोध किया था कि पुर्तगालियों द्वारा माँग किये गये आवागमन के अधिकार को उस समय तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि वह क्षेत्रीय संप्रभु की स्वकीय हृच्छा या अनुमति या सहमति पर न दी जाय। भारत का यह भी तर्क था कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्य यह नहीं प्रकट करते कि क्षेत्रीय संप्रभु की ऐसी कोई प्रकट सहमति या अनुमति नहीं है जो भारत के क्षेत्राधिकार को परिमोमित कर सके।

न्यायालय ने यह निष्कर्ष पाया कि १७७६ की संधि का अनुच्छेद १७ वैध है किन्तु पुर्तगाल वालों को संप्रभुता नहीं प्रदान करता। पुर्तगाल का दावा था कि उसे दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र संधि के अनुच्छेद १७ के क्रम में मिले थे और यह कि मराठों ने उन्हे संप्रभुता भी सौंप दी थी। इधर भारत का कहना था कि यह क्षेत्र मराठों द्वारा केवल जागीरों की हैसियत से अपनी संप्रभुता में से केवल १२,००० रु० के मूल्य पर दिया गया था। न्यायालय ने अवलोकन किया कि

१७७६ की संधि तथा १७८३ और १७८५ के सवाद में मराठों का आशय पुर्तगालियों को केवल जागीर सौ देने का था, या सरजाम दे देने का था, और उन गाँवों की पूरी संप्रभुता ही उन्हें सौंप देने का आशय न था, क्योंकि मात्र राजस्व संग्रह करने के अधिकार का तात्पर्य संप्रभुता सौंप देने का अधिकार नहीं हुआ करता ।

इससे बाद जब मराठों ने आधिपत्य अंग्रेजों ने लिया, तब भी न तो अंग्रेजों ने स्वयं उस क्षेत्र पर संप्रभुता का दावा किया और न किसी भी पुर्तगालियों की संप्रभुता को ही मान्यता प्रदान की ।

पुर्तगाल अपने अधीनस्थ उन क्षेत्रों पर अपनी संप्रभुता के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी नियन्त्रण के बिना आवागमन का अधिकार चाहता था । दोनों पक्षकारों के बीच यह एक सामान्य आधार था कि व्यक्तिगत व्यक्तियों और नागरिक अधिकारों के बीच दैनिक नियन्त्रण की अपेक्षा कोई अन्य प्रतिबन्ध नहीं है । इसका प्रतिशूल सिद्ध करने का कोई दूसरा प्रमाण नहीं था । इसलिये न्यायालय का निष्कर्ष था कि वैयक्तिक व्यक्तियों के नागरिक अधिकारियों और माल के सम्बन्ध में सामान्यतः डामन से हाकर आवागमन की स्वतन्त्रता ब्रिटिश और उत्तर ब्रिटिश काल में दी गई है और सरकार के बदलते रहने पर भी यह परंपरा जारी रही है और यहाँ तक भारत के स्वतन्त्र हो जाने के उपरांत भी इस परम्परा का पालन किया गया है । अतः न्यायालय का निर्णय था कि व्यक्तिगत व्यक्तियों, नागरिक अधिकारियों और माल के इस यातायात को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से एक मान्यता मिल चुकी है और अब भी उस मान्यता का प्रवर्तन किया जा सकता है ।

जहाँ तक सैन्य-शक्तियों के आवागमन का प्रश्न है, न्यायालय का अवलोकन था कि ब्रिटिश और उत्तर ब्रिटिशकाल में भी पुर्तगाल वालों को डामन से होकर सशस्त्र सेनाएँ ले आने और ले जाने का अधिकार नहीं था और १८७८ के बाद से इस प्रकार का यातायात केवल ब्रिटिश के प्राधिकार और तदनन्तर भारत के प्राधिकार पर ही सम्भव था । बाद की विशिष्ट परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुये न्यायालय की अभिप्राय थी कि इस प्रकार के प्राधिकार प्राप्त करने की शक्त का अर्थ है स्वाभाविक रूप से उस अधिकार को न प्राप्त किया जाना । अभ्यास यह प्रमाणित करता है कि क्षेत्रीय संप्रभु को यह शक्ति थी कि वह अपने विवेक के अनुसार यह अनुमति दे, अथवा देने में इन्कार कर दे । अतः यह अनुमति स्वेच्छया दी जा सकती है, आभार और बाध्यता के रूप में नहीं । न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि भारत द्वारा आवागमन में गतिरोध उत्पन्न कर देना परिस्थितियों

की विशिष्टताओं को देखते हुये किसी प्रकार से पुर्तगाल के आवागमन के अधिकार के प्रतिकूल नहीं था, क्योंकि इस प्रकार का भारत को घोर से नियन्त्रण, प्रस्तुत परिस्थितियों में विधि-प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता ।

परिणाम-स्वरूप न्यायालय ने ४ के विरुद्ध ११ वोटों से यह निर्णय पाया कि पुर्तगाल को १९५४ में भारत-क्षेत्र और दादरा और नगर हवेली के क्षेत्र में तथा अन्य ऐसे क्षेत्रों में आवागमन का अधिकार था जो कि विदेशी सरक्षण में थे, जिससे कि पुर्तगाली उन सरक्षित क्षेत्रों में सम्प्रभुता का प्रयोग कर सकें और भारतीय नियन्त्रण और नियमों के अधीन रहते हुये व्यक्तिगत व्यक्तियों, नागरिक अधिकारियों और सामानों को भेज सके या मंगा सके, तथा ७ के विरुद्ध ८ वोटों से यह भी निर्णय पाया कि पुर्तगालियों को १९५४ में इन क्षेत्रों में सशस्त्र सेनाओं, सशस्त्र पुलिस, और शस्त्र आदि ले आने और ले जाने का अधिकार नहीं था और ९ के विरुद्ध ६ वोटों से यह निर्णय पाया कि भारत ने पुर्तगालियों के व्यक्तिगत व्यक्तियों, नागरिक अधिकारियों और साधारण सामानों को ले आने या ले जाने के अधिकार के सवध में आचारों के प्रतिकूल कार्य नहीं किया है ।

सोवियत न्यायाधीश एफ० आई० कोजेविनकोव ने अपना निर्णय स्वतन्त्र हो रखा कि प्रस्तुत तथ्यों में न्यायालय को विवाद के मेरिट पर विचारण करने और निर्णय करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं प्राप्त है । उनका कथन था कि, "Portugal did not possess and does not possess any sovereign right over Dadra and Nagar Aveli and since it never had and has not now any right of passage over Indian territory to these regions and between each of them," अर्थात् पुर्तगाल को दादरा और नगर हवेली पर न पहले कभी सम्प्रभु अधिकार था, और न अब है, और चूँकि उसे भारतीय क्षेत्र से इन क्षेत्रों तक आवागमन का कोई अधिकार पहले से नहीं रहा है, अस्तु अब भी वह अधिकार नहीं है ।

कतिपय अन्य न्यायाधीशों ने तो स्पष्टतः यह कहा कि पुर्तगाल के सीमित आवागमन का अधिकार, जो कि वैयक्तिक व्यक्तियों, नागरिक अधिकारियों और साधारण सामानों के सम्बन्ध में है, वह भी १९५४ में घटित दादरा और नगर-हवेली की घटनाओं के कारण अब समाप्त हो चुका है ।

मर्जेन्टाइना के न्यायाधीश कुइनताना ने तो यहाँ तक कहा था कि "To support the Portuguese claim in this case, which implies survival of

the colonial system, without categorical and conclusive proof is to fly in the face of the United Nations Charter.” इस प्रसंग में पुर्तगालियों के पक्ष का समर्थन करने का तात्पर्य औपनिवेशिक प्रणाली को पुनर्जीवित करना और बिना किसी स्पष्ट और निर्णायक प्रमाण के, संयुक्त राष्ट्र संधि के स्वयं-चार्टर के ऊपर कीचड़ फेरना है।”

## मन्त्रणा परामर्श

१. संयुक्त राष्ट्र संधि की सदस्यता के लिये किसी राज्य का प्रवेश (I. C. J. Reports, 1948, p. 57) .—१९४६ तथा १९४७ के बीच में बहुत से राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संधि की सदस्यता में प्रवेश करने से अस्वीकार किया गया विशेषतः इस कारण से कि सोवियत रूस ने सुरक्षा परिषद् में विशेष निषेधाधिकार का उपयोग किया। पूर्वोक्त यूरोप के पूर्व शत्रु राज्यों के सम्बन्ध में सोवियत रूस ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि वह अपने विशेष निषेधाधिकार का उपयोग नहीं करेगा यदि परिषद् के अन्य सदस्य उन राज्यों के प्रार्थना-पत्रों को स्वीकृत कर लें जिन्हें सोवियत सरकार का समर्थन प्राप्त हो। नवम्बर सन् १९४७ को सामान्य सभा ने सुरक्षा परिषद् का यह प्रश्न निर्दिष्ट किया कि क्या संयुक्त राष्ट्र संधि का कोई सदस्य जिसे किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र संधि की सदस्यता में प्रवेश करने के लिये मत देने को कहा जाय प्रवेश के लिये अपनी सहमति इस शर्त पर आश्रित कर सकता है या नहीं कि अन्य राज्य भी संयुक्त राष्ट्र संधि की सदस्यता में प्रवेश किये जाय। न्यायालय ने दो मतों के विरुद्ध नौ मतों से इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया।

२. किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र संधि में प्रवेश करने के लिए साधारण सभा की क्षमता (I. C. J. Reports, 1950, pp. 4-34) .—नवम्बर २२, सन् १९४९ को साधारण सभा ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से यह कहा गया कि वह अपनी परामर्शदात्री सम्मति इस प्रश्न पर दे कि क्या साधारण सभा अपने ही निर्णय से किसी राज्य को संयुक्त राष्ट्र संधि की सदस्यता में उस दशा में प्रवेश कर सकती है जब सुरक्षा परिषद् ऐसी सन्तुष्टि न करे। न्यायालय ने दो मतों के विरुद्ध बारह मतों से इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दे दिया।

३. संयुक्त राष्ट्र संधि की सेवा में प्राप्त हानि के लिये क्षतिपूर्ति (I. C. J. Reports, 1949, p. 174) .—कौंट फोक बर्नाडट की, जो ऐलेस्टाइन में संयुक्त राष्ट्र संधि का मध्यस्थ था, जब कि वह शान्तिदल के अध्यक्ष का कार्य कर रहा था १७ सितम्बर, १९४८ को हत्या कर दी गई। इस पर संयुक्त राष्ट्र संधि की साधारण सभा ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को परामर्शदात्री सम्मति के लिये यह प्रश्न भेजा कि क्या

४३४ ]

उस दशा में जब संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के किसी अभिकर्ता को अपने कर्तव्य-पालन के बीच में, ऐसी परिस्थितियों में जब कि उसका उत्तरदायित्व किसी राज्य पर हो कोई हानि पहुँचे तो संयुक्त राष्ट्र सङ्घ को एक सङ्घ के रूप में यह क्षमता है कि नहीं कि वह वेध रूप से अथवा वास्तविक रूप से उत्तरदायी सरकार के विरुद्ध एक अन्तर्राष्ट्रीय दावा उस हानि की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में कर सके जो (अ) संयुक्त राष्ट्र सङ्घ का तथा (आ) पीड़ित व्यक्ति को अथवा उस व्यक्ति को जो उसके द्वारा अधि-कारो हो, पहुँचो है।

न्यायालय न प्रश्न के दोनों भागों का स्वोकारात्मक उत्तर दिया। इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय की मन्त्रणा की चर्चा पूर्व प्रसंगों में यथास्थान की जा चुकी है।

इन मामलों के अतिरिक्त जो प्रमुख मामले इस न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु प्राये, उनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। एंग्लो नार्वे मत्स्यालय का मामला, संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के मोरक्को सम्बन्धित अधिकार, ऐम्बेटेलियो का मामला (Ambatielos Case), नाटेबहम का मामला (Nottebohm case) — (Leichtenstein v. Guatemala), मिनक्पूरस ऐक्रेमास का मामला (Minquiers and Ecrebos Case), घन-सम्बन्धित स्वर्ण-अभियोग (Monetary Gold Case), फ्रांस में दिये गये नार्वे के ऋण का मामला (Case of the Norwegian Loans issued in France), १९०२ के अभिसमय को लागू करने से सम्बन्धित मामला जो कि शिशुओं की सुरक्षा के नियन्त्रण के सम्बन्ध में था (Case concerning the application of the Convention of 1902 governing the guardianship of infants), हवाई घटना का मामला (Aerial Incident case - Israel v. Bulgaria) आदि। विषय विस्तार की दृष्टि से इन विवादों के पूर्ण विवरण यहाँ देना उपयुक्त न होगा। फिर भी, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इन सभी विवादों में अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय किये हैं।

## भाग ३ युद्ध की विधियाँ

(The Laws of War)

अध्याय ३४

झगड़ों का निपटारा

(Settlement of Disputes)

राष्ट्रों के बीच में राजनैतिक स्या वैध मतभेदों को मिटाने की भिन्न भिन्न रीतियाँ हैं । ऐसे मतभेद या तो क्षान्तिपूर्ण रीति या से प्रथम सम्बन्धकारी रीतियों से मिटाये जा सकते हैं, जो युद्ध से कुछ ही कम हो ।

**शांतिपूर्ण रीतियाँ (Amicable Means) :—**झगड़ों को तय करने के लिये विभिन्न क्षान्तिपूर्ण रीतियाँ निम्न प्रकार से परिगणित का जा सकती हैं —

(१) वार्ता (Negotiation), (२) सद्भावना और मध्यस्थता (Good Offices and Mediation), (३) समाधान (Conciliation), (४) अन्तर्राष्ट्रीय जाँच आयोग (International Commission of Enquiry), (५) विवाचन (Arbitration), (६) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा न्यायिक निपटारा (Judicial Settlement through International Court of Justice) तथा (७) संयुक्त राष्ट्र सच के माध्यम से (Machinery of the U. N. O.) ।

**वार्ता (Negotiation) :—**यह शब्द झगड़े के निर्णय पर पहुँचने के प्रयोजन के लिये राज्यों के बीच में समागम या अन्तर्राष्ट्रीय सनातनी को कम करने का द्योतक है । ऐसी वार्ता या तो राज्यों के अध्यक्षों द्वारा की जाती है अथवा उनके प्रमाणपत्र-प्राप्त अधिकारियों द्वारा प्रायः झगड़े को स्पष्ट करने के लिये पत्र-व्यवहार किया जाता है । भारत तथा पाकिस्तान द्वारा जो भिन्न-भिन्न प्रयत्न अपने कुछ मुख्य-मुख्य झगड़ों को तय करने के लिये किये गए वे वार्ता के उदाहरण हैं । सबसे हाल का उदाहरण अलसखको के विषय में भारत तथा पाकिस्तान का स्वीकार-पत्र है ।

न्यायाधीश मूर ने (Moore J.) ने *Mavrommatis Palestine Concession* के विवाद के प्रसंग में लिखा था कि, "in the international sphere and in the sense of International Law, negotiation is the legal and





**विवाचन (Arbitration) :—**अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को शान्तिपूर्वक विधियों से तय करन के लिये विवाचन सब से प्रमुख रीति है। जैसा लौरेंस का कथन है:—इसका महत्व इसके न्यायिक अथवा न्यायिक-कल्प स्वरूप में रहता है। यह झगड़े का एक व्यक्ति को अथवा व्यक्तियों के छोटे समूह को निर्दिष्ट करना प्रकट करता है जिससे पक्षकार अपने-अपने पक्षों को व्यक्त करते हैं और जिसके निर्णय को वे प्रतिष्ठावश मानन के लिये बाध्य हैं और वस्तुतः सर्वदा माना है। इसके विपरीत उदाहरण केवल उसी दशा में मिलता है जब पक्ष अपनी शक्ति के बाहर गया हो। जब कोई झगड़ा किसी पक्ष को सौंप दिया जाता है तो मामला एक न्यायालय के समक्ष परीक्षण का रूप धारण करता है (Lawrence : The Principles of International Law, p. 566)। राज्यों का यह कर्तव्य नहीं है कि वे अपने झगड़े को विवाचन के हाथ उस समय तक सौंपे जब तक उन्होंने अपने को पहले से एक संधि द्वारा बाध्य न कर लिया हो। परन्तु जहाँ उन्होंने मामले को एक बार विवाचन को निर्दिष्ट किया उसके निर्णय की अपेक्षा का अर्थ होता है प्रतिज्ञा भग, जब तक वह धोखा, कपट तथा उसी प्रकार की अन्य बातों से दूषित न हो, अथवा पक्ष जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपनी शक्तियों के बाहर न गया हो।

१९५१ में संयुक्त राष्ट्र सभ के प्रतिनिधि डा० फ्रैंक ग्राहम की नियुक्ति काश्मीर के झगड़े का निपटारा विवाचन द्वारा करने के लिये हुई। भारतवर्ष ने इस झगड़े को विवाचन में भेजने से इकार किया क्योंकि वह महान् शक्तियों का खेल बनना नहीं चाहता था और इसके अतिरिक्त इससे काश्मीर के आत्म-निर्णय के अधिकार पर मूलतः भारत की स्थिति पर आघात होता, किन्तु सुरक्षा परिषद् में ब्रिटिश प्रतिनिधि ने यह स्पष्ट किया कि विवाचन असैनिकीकरण संबंधित उन विषयों पर विचार करेगा जिस पर भारत तथा पाकिस्तान सहमत हैं। अन्त में भारत उसका परामर्श और सुझाव लेने के लिये राजी हो गया।

सन् १९६६ के प्रथम हेग सम्मेलन ने विवाचन का स्थायी न्यायालय एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यूरो सहित हेग में स्थापित किया जो उनके सचिवालय का कार्य करे तथा एक स्थायी प्रशासकीय परिषद् स्थापित किया। प्रत्येक हस्ताक्षर करने वाली शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्नों में विशिष्ट योग्यता रखने वाले तथा सर्वोच्च नैतिक चरित्र रखने वाले व्यक्तियों को विवाचन के स्थायी न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य करने के लिये चुनती थी। समस्त न्यायाधीशों की सूची में से पक्षकारों को यह स्वतन्त्रता थी कि किमी न्यायाधिकरण के लिये सदस्यों को चुनें। सन् १९७७ के हेग सम्मेलन ने इस योजना में कुछ सुधार किये तथा गौण महत्व के झगड़ों को मामलों के विषय में सक्षम प्रक्रिया की व्यवस्था की। वस्तुतः विवाचन का स्थायी

orderly administrative process by which Governments, in the exercise of their unquestionable powers conduct their relations with one another and discuss, adjust and settle their differences" तात्पर्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के भावार्थ में वार्ता वैध और नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अपने दृढ़-प्रवर्तित अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में बातचीत, विचार विमर्श तथा परस्पर के मतभेदों का निपटारा करती हैं। प्रायः मतभेदों के निवारण के लिए सरकारों में भाषस में पत्र व्यवहार किये जाते हैं। यहाँ तक कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय में भी और उसके पश्चात् भी, तेहरान, याल्टा, पोर्ट्समउथ, आदि के प्रसंगों में बहुत से मतभेदों को इन देशों की सरकारों ने वार्ता द्वारा ही सुलझाया है।

यह आवश्यक नहीं है कि वार्ता का परिणाम अवश्य ही पक्षकारों के बीच के हर मतभेद को दूर कर दे। इससे यह भी सम्भव है कि दोनों सरकारों के बीच एक समझौता हो जाय या एक पक्ष दूसरे पक्ष के दावों को स्वीकार कर ले या दावों को बम कर दिया जाय अथवा आपत्तियाँ उठाई जाय। वार्ता से विश्व के जनमत के समक्ष यह भी प्रकट हो जाता है कि एक राज्य जब कि वार्ता के लिए प्रस्तुत था, दूसरे ने हठ नहीं छोड़ा और इसलिए पहले को विवश होकर युद्धरत होना पड़ा।

**सद्भावना (Good Offices)** — जब पक्षकार परस्पर वार्ता करना अस्वीकार कर देते हैं तो एक तीसरा राज्य भागें बढ सकता है तथा अपनी सेवायें समझौते के लिये दे सकता है। "सेवायें" शब्द से ऋणवत् हुए पक्षकारों को एक साथ बैठाना तथा उनको मन्नणा देना अथवा बिना वार्ता में भाग लिये हुए तय करने का सुझाव देना प्रकट होता है। ऐसे सुझाव तथा मन्नणाओं की उपेक्षा ऋणवत् के किसी पक्षकार द्वारा बिना किसी मनोव्यथा अथवा विधि के भग के की जा सकती है।

यहाँ 'good offices' शब्द के प्रयोग से तात्पर्य विवादप्रस्त दोनों पक्षकारों को एक साथ बैठकर सलाहा के आदान-प्रदान या बिना वार्ता में प्रविष्ट हुये ही निपटारे के ढंग के सुझाव देने से है। ऋणवत् के एक पक्ष द्वारा ऐसी सलाह या ऐसे सुझाव को अस्वीकृत भी किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कानून के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं उठता। भारत-पाक तनावन की प्रसंग में आस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने सद्भावना कार्यालय का उपयोग १९५१ में किया था जिससे उनके वर्तमान भगहो का निपटारा हो सके। किन्तु भारत के प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने कहा था कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच आस्ट्रेलिया के इस सद्भावना प्रयत्न कोई से लाभ सम्भव नहीं है।

**मध्यस्थता (Mediation) .**—मध्यस्थ भगडते हुए पक्षकारों के बीच में किसी तीसरे पक्षकार के अभिकरण द्वारा वार्ताओं को चलाता है। मध्यस्थ को या तो उसके अपने ही अभियंत्रण पर अथवा भगडते हुए पक्षकारों की प्रार्थना पर यह कार्यभार सौंपा जाता है कि वह भगडे को देखे तथा शान्तिपूर्ण समझौते का कोई ढंग निकाले। उसके सुझाव कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखते तथा पक्षकार उनको स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने अथवा हारमेटित करने के लिये स्वतन्त्र रहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सघ ने अरब तथा यहूदियों के भगडे में कोट फोक बर्माडाट को सन् १९४८ में पैलेस्टाइन में मध्यस्थ नियुक्त किया तथा उनको यह कार्यभार सौंपा कि जा घटनायें घटे उनका प्रतिवेदन करें तथा पैलेस्टाइन की भावी स्थिति को शान्तिपूर्ण ढंग से तय करने में सहायता करे। इसी प्रकार अप्रैल १२, सन् १९५० को सुरक्षा परिषद् ने सर मोवेन डिकसन आस्ट्रेलिया के एक न्यायाधीश को काश्मीर सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान के भगडे में मध्यस्थ नियुक्त किया और उनको यह कार्यभार सौंपा कि भगडे के क्षेत्र में नि शस्त्रीकरण कार्यक्रम बनाने तथा उसके निरोधन करने में सहायता करे, तथा कोई ऐसा सुझाव दे जिससे भगडे के निपटारे में सहायता हो।

अन्तर्राष्ट्रीय भगडों के शान्तिपूर्वक समझौते के लिये की गईं हों प्रतिज्ञा ने इस आवश्यकता पर अधिक महत्व दिया था कि शक्तियां द्वारा बारम्बार सद्भावनाएँ दी जाँच तथा मध्यस्थता की जाय तथा यह निर्धारित किया था कि कोई राज्य जो कि भगडे में पक्षकार नहीं है उसको उसमें मध्यस्था करने का, तथा अपनी सद्भावनाएँ देने का अधिकार है जो परामर्शदायक रूप में हो तथा बिना किसी बाध्यकारी प्रभाव के हों और शत्रुता के कार्य-रूप में न हो।

चार्टर के अनुच्छेद ३४ तथा ३५ में भी यह अनुबन्धित है कि जब कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जिससे अन्तर्राष्ट्रीय भगडा पैदा हो, संयुक्त राष्ट्र सघ सामूहिक मध्यस्थता करे।

सद्भावना-प्रयत्न तथा मध्यस्थता का अन्तर मूल्य है जो केवल परिमाण का है। प्रथम अवस्था में तीसरा राज्य भगडे को जाँच कर सकता है अथवा सुझाव दे सकता है, किन्तु वह वार्ता में भाग नहीं लेता। तीसरा राज्य प्रतिस्पर्धी पक्षकारों को केवल एक साथ लाता है। दूसरी दशा में मध्यस्थता करने वाला राज्य भगडे के शान्तिपूर्ण समझौते के लिये किये गये विचार-विमर्श में व्यावहारिक भाग लेता है। अन्य शब्दों में यही तीसरा राज्य पक्षकारों के बीच में वार्ता चलाता है। "वस्तुतः राज्य का उस दशा में 'सद्भावना प्रयत्न प्रदान करना कहा जाता है जब यह पक्ष-

orderly administrative process by which Governments, in the exercise of their unquestionable powers, conduct their relations with one another and discuss, adjust and settle their differences." तात्पर्य यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि के भावार्थ में वार्ता वैध और नियमित प्रशासकीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अपने दृढ़-प्रवर्तित अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में बातचीत, विचार विमर्श, तथा परस्पर के मतभेदों का निपटारा करती हैं। प्रायः मतभेदों के निवारण के लिए सरकारों में आपस में पत्र व्यवहार किये जाते हैं। यहाँ तक कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय में और उसके पश्चात् भी, तेहरान, माल्टा, पोर्ट्सडम, आदि के प्रसंगों में बहुत से मतभेदों को इन देशों की सरकारों ने वार्ता द्वारा ही सुलझाया है।

यह आवश्यक नहीं है कि वार्ता का परिणाम अवश्य ही पक्षकारों के बीच के हर मतभेद को दूर कर दे। इससे यह भी सम्भव है कि दोनों सरकारों के बीच एक समझौता हो जाय या एक पक्ष दूसरे पक्ष के दावों को स्वीकार कर ले या दावों को कम कर दिया जाय अथवा आपत्तियाँ उठाई जाय। वार्ता से विश्व के जनमत के समक्ष यह भी प्रकट हो जाता है कि एक राज्य जब कि वार्ता के लिए प्रस्तुत था, दूसरे ने हठ नहीं छोड़ा और इसलिए पहले को विवश होकर मुड़रत होना पड़ा।

**सद्भावना (Good Offices) :**—जब पक्षकार परस्पर वार्ता करना अस्वीकार कर देते हैं तो एक तीसरा राज्य आगे बढ़ सकता है तथा अपनी सेवायें समझौते के लिये दे सकता है। "सेवायें" शब्द से भ्रमित हुए पक्षकारों को एक साथ बैठाना तथा उनको मंत्रणा देना अथवा बिना वार्ता में भाग लिये हुए तय करने का सुझाव देना प्रकट होता है। ऐसे सुझाव तथा मंत्रणाओं की उपेक्षा भ्रमों के किसी पक्षकार द्वारा बिना किसी मनोव्यथा अथवा विधि के भग के की जा सकती है।

यहाँ 'good offices' शब्द के प्रयोग से तात्पर्य विवादग्रस्त दोनों पक्षकारों को एक साथ बैठकर सलाहों के आदान-प्रदान या बिना वार्ता में प्रविष्ट हुये ही निपटारे के टग के सुझाव देने से है। भ्रमों के एक पक्ष द्वारा ऐसी सलाह या ऐसे सुझाव को अस्वीकृत भी किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कानून के उत्पन्न का कोई प्रश्न नहीं उठता। भारत-पाक तनावों के प्रसंग में आस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने सद्भावना कार्यान्वय का उपयोग १९५१ में किया था जिससे उनके वर्तमान भगड़ों का निपटारा हो सके। किन्तु भारत के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने कहा था कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच आस्ट्रेलिया के इस सद्भावना प्रयत्न कोई से लाभ सम्भव नहीं है।

**मध्यस्थता (Mediation) :—**मध्यस्थ भगडते हुए पक्षकारों के बीच में किसी तीसरे पक्षकार के अभिकरण द्वारा वार्ताओं को चलाता है। मध्यस्थ को या तो उसके अपने ही अभियंत्रण पर भयवा भगडते हुए पक्षकारों को प्रार्थना पर यह कार्यभार सौंपा जाता है कि वह भगडे को देखे तथा शान्तिपूर्ण समझौते का कोई ढंग निकाले। उसने सुझाव कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखते तथा पक्षकार उनको स्वीकृत करने, अस्वीकृत करने भयवा रुग्णभेदित करने के लिये स्वतन्त्र रहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सभ ने भरव तथा यहूदियों के भगडे में कौंट फोक बर्नाडाट को सन् १९४८ में पैनेस्टाइन में मध्यस्थ नियुक्त किया तथा उनको यह कार्यभार सौंपा कि जा घटनाये घटे उनका प्रतिवेदन करें तथा पैनेस्टाइन की भावी स्थिति का शांतिपूर्ण ढंग से तय करने में सहायता करें। इसी प्रकार अप्रैल १२, सन् १९५० को सुरक्षा परिषद् ने सर मोवेन डिवसन आस्ट्रेलिया के एक न्यायाधीश को काश्मीर सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान के भगडे में मध्यस्थ नियुक्त किया और उनको यह कार्य-भार सौंपा कि भगडे के क्षेत्र में निःशस्त्रीकरण कार्यक्रम बनाने तथा उसके निरो-क्षण करने में सहायता करे, तथा कोई ऐसा सुझाव दे जिससे भगडे के निपटारे में सहायता हो।

अन्तर्राष्ट्रीय भगडों के शांतिपूर्वक समझौते के लिये की गई हेग प्रतिज्ञा ने इस आवश्यकता पर अधिक महत्व दिया था कि शक्तियां द्वारा बारम्बार सद्भाव-नाएँ दी जायं तथा मध्यस्थता की जाय तथा यह निर्धारित किया था कि कोई राज्य जो कि भगडे में पक्षकार नहीं है उसको उसमें मध्यस्था करने का, तथा अपनी सद्भावनाएँ देने का अधिकार है जो परामर्शदायक रूप में हो तथा बिना किसी बाध्यकारी प्रभाव के हो और शत्रुता के कार्य-रूप में न हो।

चार्टर के अनुच्छेद ३४ तथा ३५ में भी यह अनुबन्धित है कि जब कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जिससे अन्तर्राष्ट्रीय भगडा पैदा हो, संयुक्त राष्ट्र सभ सामू-हिक मध्यस्थता करे।

सद्भावना-प्रयत्न तथा मध्यस्थता का अन्तर मूल्य है जो केवल परिमाण का है। प्रथम अवस्था में तीसरा राज्य भगडे की जाँच कर सकता है भयवा सुझाव दे सकता है, किन्तु वह वार्ता में भाग नहीं लेता। तीसरा राज्य प्रतिस्पर्धी पक्षकारों को केवल एक साथ लाता है। दूसरी दशा में मध्यस्थता करने वाला राज्य भगडे के शांतिपूर्ण समझौते के लिये किये गये विचार-विमर्श में व्यावहारिक भाग लेता है। अन्य शब्दों में यही तीसरा राज्य पक्षकारों के बीच में वार्ता चलाता है। "वस्तुतः राज्य का उस दशा में 'सद्भावना प्रयत्न प्रदान करना कहा जाता है जब यह पक्ष-

वारों को परस्पर वार्ता करने के लिये प्रोत्साहित करता है और इसका 'मध्यस्थ बनना उस दशा में कहा जाता है जब यह वार्ता में भाग लेता है परन्तु स्पष्टतः एक प्रकार की रीति दूसरे में विलय हो जाती है ।"

**समाधान (Conciliation)** — इस शब्द द्वारा व विभिन्न रीतियाँ व्यवहृत होती हैं जो एक तीसरे पक्षकार द्वारा दो या अधिक राज्यों के बीच में झगड़े को शांतिपूर्वक तय करने के लिये ग्रहण की जाती हैं । इसमें तथ्या के अनुसंधान के उपरांत तय करने के लिए प्रस्तावों का बनाना सम्मिलित है । ऐसे प्रस्ताव झगड़े के पक्षकारों पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखते । हेग की १८६६ तथा १९०७ की प्रतिज्ञाओं में समाधान के आयोगों द्वारा झगड़ों का शांतिपूर्ण समझौता अनुबन्धित है ।

समाधान तथा मध्यस्थता में यह अन्तर है कि प्रथम तो तथ्यों को ज्ञात करने तथा निपटारे की शर्तों को सुझाने के लिए झगड़े को एक व्यक्तियों की संस्था को निदिष्ट किया जाना प्रकट करता है और दूसरे पक्षकारों के बीच में एक-तीसरे पक्षकार के अतिक्रमण द्वारा वार्ता चलाया जाता व्यक्त होता है । समाधान विषय से भी इस बात में भिन्न है कि पहली दशा में किसी झगड़े के पक्षकार वार्ता के परिणाम की अपेक्षा करने के लिए स्वतन्त्र हैं लेकिन दूसरी दशा में पक्ष का एक वैध नियुक्त पक्ष के नियुक्त के रूप में होता है जो पक्षकारों पर बंधनकारी होता है ।

**अन्तर्राष्ट्रीय जॉच आयोग (International Commissions of Inquiry)** — यद्यपि ये आयोग कंसिलियेशन आयोगों से जिनका कि ऊपर बखन किया जा चुका है भिन्न हैं जब आयोग झगड़ों के सम्बन्ध में जॉच पड़ताल करने और जब तक कि प्रतिवेदन न कर लें तब तक के लिए शत्रुतापूर्ण कार्यों को निरन्तर करने में सहायक होते हैं । १८६६ के हेग सम्मेलन के पहले अभिसमय में सुझाव दिया गया था कि अन्तर्राष्ट्रीय जॉच आयोग की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के लिए जिसमें कि न तो सम्मान का प्रश्न और न आवश्यक हित का ही प्रश्न सम्मिलित है और तथ्य के विषयों के सम्बन्ध में जिससे कि तथ्या का निराकरण हो सके सदा अज्ञान की अवस्था को दूर करने, जिससे कि शत्रुता दूर हो सके, आयोग सहायक होता है । सम्मेलन में यह व्यवस्था दी गई कि ऐसे आयोग, सम्बन्धित पक्षकारों के विशिष्ट समझौते के आधार पर निर्मित हो सकते हैं और आयोग के अभिसमय के अनुच्छेद ३२ के आधार पर नियुक्त होंगे । यह अनुच्छेद विवा-  
५ (Arbitral Tribunals) की नियुक्ति के सम्बन्ध में है ।

**विवाचन (Arbitration) :—**अन्तर्राष्ट्रीय झगडों को शान्तिपूर्वक विधियों से बचाने के लिये विवाचन सब से प्रचुर रीति है। जैसा मीरत या कथन—इसका महत्व हमने न्यायिक धर्म या न्यायिक-व्यवस्था के रूप में देखा है। यह ठीक का एक व्यक्ति को धर्म या व्यक्तिगत या छोटे समूह को निर्दिष्ट करना प्रबलता है जिससे पक्षकार अपने-अपने पक्षों को ध्यान करते हैं और जिसके निर्णय से प्रतिष्ठावश माना कि सत्य शास्त्र है और यस्तुत गम्यमाना है। इसके परीत उदाहरण बयल उसी दशा में मिलता है जब एक अपनी शक्ति के दाहरता है। जब कोई झगडा किसी पक्ष को सौंप दिया जाता है तो मामला एक न्यायालय व समस्त परीक्षण का एक धारण करता है (Lawrence : The Principles of International Law, p. 566)। राज्या का यह वर्तमान नहीं कि वे अपने झगडे को विवाचन के हाथ उस समय तक भीजे जब तक उन्होंने अपने पहले से एक सपि द्वारा शास्त्र न कर लिया हो। परन्तु जहाँ उन्होंने मामले को धार विवाचन को निर्दिष्ट किया उन्ने निर्णय की उपेक्षा का धर्म होता है किता भग, जब तक वह घोषा, कष्ट तथा उसी प्रकार की अन्य बातों में दूषित न है, धर्म या पक्ष जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपनी शक्तियों व बाहर न गया हो।

१९५१ में संयुक्त राष्ट्र सचिव प्रतिनिधि डा० फैंक ग्राहम की नियुक्ति शमीर व झगडे का निपटारा विवाचन द्वारा करने के लिये हुई। भारतवर्ष ने उ झगडे को विवाचन में भेजने में इकार किया यद्यपि यह महान् शक्ति का लक्षण नहीं चाहता था और इसके प्रतिरिक्त इससे बाश्मीर के धारम-निर्णय के धिकार पर मूलतः भारत की स्थिति पर भाषात होता, किन्तु सुरक्षा परिषद् में दित प्रतिनिधि ने यह स्पष्ट किया कि विवाचन धर्मेनिकीकरण संबंधित उन पक्षों पर विचार करेगा जिस पर भारत तथा पाकिस्तान सहमत हैं। अन्त में तत्त उसका परामर्श और सुझाव लेने के लिये राजी हो गया।

सन् १८६६ के प्रथम हेग सम्मेलन ने विवाचन का स्थायी न्यायालय एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यूरो सहित हेग में स्थापित किया जो उसके सचिवालय का कार्य करेगा एक स्थायी प्रशासकीय परिषद् स्थापित किया। प्रत्येक हस्ताक्षर करने वाली शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रश्नों में विशिष्ट योग्यता रखने वाले तथा सर्वोच्च नैतिक चरित्र रखने वाले व्यक्तियों को विवाचन के स्थायी न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिये चुनती थी। समस्त न्यायाधीशों की सूची में से पक्षकारों को यह स्वतन्त्रता थी कि किसी न्यायाधिकरण के लिये सदस्यों का चुने। सन् १९०७ के हेग सम्मेलन ने इस योजना में कुछ सुधार किये तथा मूल महत्व के झगडों को मामलों के विषय में सक्षम प्रक्रिया की व्यवस्था की। वस्तुतः विवाचन का स्थायी



न्यायालय कोई न्यायालय नहीं था वरन् यह केवल एक पक्षी की सूची थी जिसमें से न्यायालय बनाए जा सकते थे । ऐसी दशा में यह वास्तविक अर्थ में कोई न्यायालय नहीं था इसलिये इसमें स्थिरता नहीं थी ।

सन् १६०२ तथा १६३२ के बीच में विवाचन के स्थायी न्यायालय द्वारा चीस निर्णय दिये गये जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन के बीच का उत्तरीय अटलांटिक महासागर मत्स्यालयों वाला मामला (१६१०), सावरकर का मामला (१६११) तथा प्रथम महायुद्ध में नीर्वे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच का नीर्वे के जहाजों को अधिवाचन का मामला (१६२२) सम्मिलित हैं ।

सन् १६१६ की वार्सलीज की संधि से उत्पन्न हुए क्षेत्रीय झगड़ों का निर्णय करने के लिए यूरोप में बहुत से मिश्रित न्यायाधिकरण नियुक्त किये गये । ऐसे झगड़े या तो एक अकेले व्यक्ति द्वारा पक्षों के रूप में अथवा प्रतिस्पर्धी राज्यों द्वारा मनोनीत किये गये सदस्यों से बने आयोग द्वारा अथवा बाहरी लोगों द्वारा तथा प्रतिस्पर्धी राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय किये गये ।

राज्यों के बीच में झगड़ों को शान्तिपूर्वक निपटाने के साधनों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा संयुक्त राष्ट्र सच की विवेचना पहले की जा चुकी है ।

**अध्यनकारी रीतियाँ (Compulsive means) :—**अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने की प्रतिरोधी रीतियों का अथवा अन्य राज्य से बलपूर्वक बदला लेने की रीतियाँ का जो युद्ध की सीमा को न पहुँचती हो अब अध्ययन किया जाय । वे निम्नलिखित हैं —

**शिकायतें (Complaints) :—**अनिवार्य साधनों का वर्णन करने के पहले यह आवश्यक होगा कि यहाँ दूसरे सरल साधनों का, जिससे कि ऐसे झगड़ों को निपटारे हो सके जो कि सेना के कमांडरों के बीच की शत्रुता से उत्पन्न होते हैं, अध्ययन कर लिया जाय । वे प्रायः एक दूसरे के विरुद्ध अवैध युद्ध विधि अपनाने की शिकायत करते हैं । ऐसे कार्य या तो युद्ध विराम के झड़े के अथवा सम्बन्धित होता है या जेनेवा अभिसमय के अतिक्रमण के सम्बन्ध में होता है या इसी प्रकार के अन्य । ऐसी शिकायतें शत्रु के पास फ्लैग ऑफ़ ट्रूस अर्थात् शांति के झड़े के सरक्षण में भेजी जाती है और शत्रु का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह ऐसी शिकायतों की छानबीन करे तथा यदि शिकायतें न्यायोचित हैं तो अपराधियों को दण्डित करे ।

**प्रतिकार (Retorsion) :—**यह एक बदले का उपाय अथवा जवाबी कार्य-वाही है जो किसी राज्य द्वारा अन्य राज्य के शत्रुतापूर्ण अथवा अश्लिष्ट व्यवहार के

लिये प्रयोग किया जाता है। अपराधी राज्य के विरुद्ध जो उपाय निर्देशित किये जाते हैं युद्ध का कारण तो नहीं होते तथा वस्तुतः उनको अवलम्बन करने वाले राज्य के वैध अधिकारी के भीतर आते हैं। ऐसे उपाय मित्र-मित्र रूप धारण कर सकते हैं। वे अपराधी राज्य द्वारा पीड़ित राज्य के प्रजाजनो के ऊपर लगाये गये निरोधो के बदले में अपराधी राज्य के प्रजाजनो के ऊपर उसी प्रकार के निरोधो को लगाने के रूप में, राजदूत को वापस बुलाने के रूप में, राजकर तथा पण्य शुल्क सम्बन्धी रियायतों को वापस लेने के रूप में हो सकता है। बदले के सम्बन्ध का हाल का उदाहरण उन उपायो से प्राप्त होता है जो भारत द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध उसके भारत विरोधी रुख तथा जातीय भेदभाव की नीति के लिये अवलम्बन किये गये। जब भारत द्वारा भारतीय उत्पत्ति के नागरिकों की दशा सुधारने के लिये बारम्बार के प्रतिवेदन विफल हो गये तो वह दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिकार के उपायो का अवलम्बन करने के लिये बाध्य हो गया जिनके द्वारा भारत में दक्षिण अफ्रीका निवासियों पर अयोग्यताये लादी गईं। फिर भी, दक्षिण अफ्रीका में भारत-विरोधी विधान नहीं रहा और भारत को अपने हार्ड कमिशनर को दक्षिण अफ्रीका से वापस बुलाना पड़ा तथा व्यापारिक सम्बन्धों को ताँड देना पड़ा।

**प्रत्यपकार ( प्रतिशोध ) ( Reprisal )** :—यह शब्द बहुत व्यापक है और हमने बलपूर्वक बाध्य करने के वे सब उपाय सम्मिलित हैं जो किसी राज्य द्वारा बदला लेने के प्रयोजन से ग्रहण किये जाते हैं। यह बदले से इस बात में भिन्न है कि इसमें वे कार्य भी सम्मिलित हैं जो ऐसे नियम विरुद्ध हैं, किन्तु जो विशिष्ट परिस्थितियों में न्याययुक्त हो जाते हैं, जब बदले की दशा में बदले के उपाय के सम्बन्ध में कोई वैध आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि वे कवल शत्रुता के कार्य हैं जो पीड़ित राज्य की क्षमता के भीतर हैं।

लोरेंस ने प्रत्यपकार ( प्रतिशोध ) की परिभाषा इस प्रकार की है कि यह अपराधी पर दबाव डालने की रीतियाँ हैं जो अथक रूप की हैं यद्यपि वे वास्तविक युद्ध की सीमा तक नहीं पहुँचती। वे प्रत्यपकार का प्रक्रिया को दृढ़, निपेयात्मक, विशेष तथा सामान्य में विभाजित करते हैं। दृढ़ बदले का अर्थ असम्यो की विधि के सिवा और कुछ नहीं है जो 'सर वे बदले सर' है अथवा जैसा कि इसे परिभाषा-नुसार प्रत्यपकार नियम 'lex talionis' कहा जाता है। निपेयात्मक बदला शत्रुता-पूर्वक किन्तु शान्तिपूर्वक रीति से कार्य करने वाले राज्य के विरुद्ध उसी प्रकार से आवरण करना है जैसा उसने किया है। उनका बलप्रयोग अथवा युद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनमें किसी राष्ट्रीय ऋण को चुकान अथवा संधि के आभारों को

पालन करने से अस्वीकार करना सम्मिलित हो सकता है। वे किसी प्रकार से उग्र कार्य नहीं है वरन् केवल बदले हैं। विशेष प्रत्यपकार जिनका कि मध्ययुग में अधिकतर उपयोग किया जाता था, वे हैं जो वैयक्तिक जनो को अन्य राष्ट्र के प्रजा-जनो द्वारा पहुँचाई गई हानि की क्षतिपूर्ति के लिये किये जाते हैं। जिनको हानि होती थी उनको सम्राट द्वारा मुद्रांकित पत्र दिये जाते थे, और उनको प्राधिकृत किया जाता था कि वे अपराधी राष्ट्रकता के जहाजों तथा उसमें लादे हुए माल का अभिग्रहण करके अपनी क्षतिपूर्ति कर लें। सामान्य बदला उस दशा में होता है जब कोई राज्य जो अपने को पांडित समझता है और बिना युद्ध करने के विचार के युद्ध सदा कार्यवाहियाँ करता है अर्थात् अपराधी राज्य पर उसकी सम्पत्ति का अभिग्रहण अथवा उसे नष्ट करके, उसके क्षेत्र को ग्रहण करके अथवा उसके स्थानों या जहाजों को अभिग्रहण करके दबाव डालता है।

बदला लेने के उपाय केवल अपराधी राज्य के विरुद्ध कार्य करने तक ही सीमित नहीं हैं परन्तु वे राज्य के नागरिकों के विरुद्ध भी लागू किये जा सकते हैं। सन् १९३५ में जब मार्सलीज में यूगोस्लेविया के सम्राट भलेकजेविच को हत्या के परिणामस्वरूप हंगरी के लाग, जिन पर हत्या करने का सन्देह किया गया था प्रत्यपकारस्वरूप यूगोस्लेविया से निकाल दिये गये।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यपकार उस दशा में अनुज्ञात है जब न्याय न प्राप्त हो अथवा कोई अन्तर्राष्ट्रीय अपराध किया गया हो। हानि पहुँचाये गये राज्य के लिए वे आराम-सहायता के कार्य हैं। नौलिला वाले मामले में विवाचन के विशेष अधिकरण द्वारा यह कहा गया कि वैध बदले की रीति का अवलम्बन करने के लिये दो बातें आवश्यक हैं अर्थात् हानि पहुँचाये गये राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति के लिये एक असफल माँग जिससे कि बल-प्रयोग आवश्यक हो गया तथा अपराधी राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति के लिये अस्वीकार किया जाना। पुनः उपाय जो अवलम्बन किये जाय अत्यधिक अथवा प्राप्त हुए प्रकोप के अनुपात से बहुत अधिक नहीं होने चाहिये।

प्रत्यपकार के उपरोक्त उप-विभाजनो के अतिरिक्त दो उप-विभाजन जिनकी विवेचना करना शेष रह गया है वे हैं—शत्रुतापूर्ण अधिरोध (Hostile Embargo) तथा शान्तिपूर्ण नावाबन्दी (Pacific Blockade)।

शत्रुतापूर्ण अधिरोध (Hostile Embargo)—इसका अर्थ अपराधी राज्य के व्यापारी जहाजों अथवा संपत्ति का क्षतिपूर्ति चाहने वाले राज्य के बन्दर-गाहों में अभिग्रहण अथवा रोकना है। यह शान्तिपूर्ण अथवा नागरिक जहाजों के

रोक से भिन्न है जो एक राज्य द्वारा अपने ही जहाजों पर अपने ही बन्दरगाह पर लगाया जाता है। अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग तथा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम भाग में शत्रुतापूर्ण अधिरोध का अवलम्बन प्रायः शत्रुता की आशा में किया जाता था, किन्तु यह रीति बाद में व्यापारिक हितों की वृद्धि के कारण त्याग दी गई जिसका परिणाम यह हुआ कि जोड़ा राज्य शत्रु के व्यापारी जहाजों को जो उनके बन्दरगाहों में पाये जायें रियायती दिनों के भीतर चले जाने को अनुमति प्रदान कर दे।

**शांतिपूर्व संरोध ( नाकाबन्दी ) ( Pacific Blockade )**—यह किसी अपराधी अथवा हठी राज्य के व्यापार को अस्थायी रूप से कुछ काल के लिये रोकना है। यह अपने समुद्री किनारे में अथवा उसके किसी विशेष भाग में प्रवेश रोकने से होता है किन्तु यह बिना किसी उग्र विरोधी कार्यों का अवलम्बन करते हुए होना चाहिये, केवल उतना छोड़कर जितना कि इस रुकावट को प्रवर्तन करने के लिये आवश्यक हो।

यह साधारणतः प्रयोग में इस प्रकार लाया जाता है अर्थात् या तो ( १ ) बलपूर्वक बदले के रूप में अथवा प्रतिकार के उपाय के रूप में जो युद्ध से कुछ ही कम हो, अथवा ( २ ) अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस उपाय के रूप में। इस उपाय का निर्वल राज्यों के विरुद्ध उन राज्यों द्वारा अवलम्बन किया जाता है जिनके पास बहुत बड़ी नाविक शक्ति हो अथवा जो बहुत बलशाली शक्तियाँ हैं; अन्यथा यदि दोनों प्रतिस्पर्धी राज्य सामान्यतः बलशाली हो तो युद्ध अवश्यभावी हो जाय। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्व नाकाबन्दी पूर्णतः एक युद्ध का उपाय था। शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी को अर्थात् इसे अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को शान्ति के समय में निपटाने के लिये एक बलपूर्वक बाध्यकारी उपाय के रूप में लागू किया जाना उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे चौथाई काल से स्वीकृत हुआ।

सन् १८८७ में हीडलबर्ग स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विधि की सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी उस दशा में वैध है जब कि यह प्रभावपूर्ण हो, सम्पूर्ण रूप से अधिसूचित हो, पर्याप्तबल से स्थापित हो तथा विदेशी झुंडों के जहाजों से हस्तक्षेप न करता हो। इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि जब तक नाकाबन्दी संचालित रहे रोकने के अतिरिक्त और कोई कठोरता का व्यवहार न करे तथा उसकी समाप्ति पर वे बिना क्षतिपूर्ति के छोड़ दिये जायें।

समुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर अपराधी राज्यों के विरुद्ध समुक्त राष्ट्र संघ अथवा उसकी ओर से शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी की प्रवृत्ति प्राधिकृत करता है।

**हस्तक्षेप (Intervention)** :—यह राज्यों के बीच झगड़ों को निपटाने के लिये एक दूसरा बन्धनकारी उपाय है जो युद्ध की सीमा तक नहीं पहुँचता। पूर्व प्रसंग में इस विषय पर विस्तार से लिखा जा चुका है।

**चार्टर द्वारा बन्धनकारी रीतियों की अनुशास्ति (Sanction of Compulsive Means by the Charter)** :—अब संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के सम्बन्ध में बन्धनकारी रीतियों की स्थिति के विषय में अध्ययन किया जाय। चार्टर का अनुच्छेद २ (३) सदस्यों को यह प्राधिकृत करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को शान्तिपूर्ण रीतियों से इस प्रकार निपटावे कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय के लिये कोई भय उत्पन्न न हो। इस अनुबन्ध का प्रभाव यह है कि प्रतिरोध तथा प्रत्यपकार उदाहरणार्थ शत्रुतापूर्ण जहाजों का अधिरोध तथा शान्तिपूर्ण नाकाबन्दी केवल तभी तक अनुमति प्राप्त हैं जब तक वे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के लिये भयोत्पादक न हों। अनुच्छेद २ (४) द्वारा सदस्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में किसी राज्य की क्षेत्रीय एकता अथवा राजनीतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध बल प्रयोग की धमकी न दें अथवा बलप्रयोग न करें अथवा किसी ऐसी अन्य रीति से व्यवहार न करें जो संयुक्त राष्ट्र सभ के उद्देश्यों से असंगत हो। कोई प्रत्यपकार अथवा हस्तक्षेप जिसका परिणाम किसी राज्य के समीप क्षेत्रीय ऐश्वर्य अथवा राजनीतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध बल-प्रयोग करने की धमकी अथवा बल प्रयोग हो स्वतः संयुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर के स्पष्ट अनुबन्धों के विरुद्ध अवैध होगा, तथापि प्रवर्तक अनुबन्ध जिनका उल्लेख चार्टर के अध्याय ७ में किया गया है सुरक्षा परिषद् को यह प्राधिकृत करता है कि चूक करने वाले सदस्य-राज्यों के विरुद्ध तथा चार्टर के अनुच्छेद २ (६) के अनुसार असदस्य राज्यों के विरुद्ध सामूहिक उपायों को लागू करे जो आर्थिक सम्बन्धों, रेल, सड़क, वायु, डाक, तार, रेडियो तथा अन्य यातायात साधनों में बाधा डालने तथा राजनैतिक सम्बन्धों के विच्छेद में जिसमें शान्ति भंग को रोकने के प्रयाजन से नाकाबन्दी भी सम्मिलित है, से सम्बद्ध है।

### अध्याय ३५

#### युद्ध तथा इसका प्रभाव (War and its Effects)

**परिभाषा** :—लीरेंस के अनुसार युद्ध को हम प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यह राज्यों के बीच में अथवा राज्यों तथा जातियों के बीच में जिनको

प्रतिस्पर्धा के सम्बन्ध में राज्य के अधिकार हो, सार्वजनिक बल से की गई एक प्रतिस्पर्धा (contest) है जिसमें पक्षकारों का यह आशय रहता है कि शान्तिपूर्ण संबंध समाप्त कर दिये जायें तथा उनके स्थान में शत्रुता को उसके समस्त वैध परिणामों सहित बदल दिया जाय । "War is a contest carried on by public force between States, or between States, and communities having with regard to the contest the rights of States, the parties to it having the intention of ending peaceful relations, and substituting for them those of hostility with all the legal incidents thereof." (Lawrence The Principles of International Law, p. 309) । उपरोक्त परिभाषा के अनुसार युद्ध वे दो प्रमुख लक्षण प्रतिस्पर्धा तथा आशय हैं जिनका अस्तित्व युद्ध होने के लिये साध ही साध रहना चाहिये । दूसरे के बिना पहले का परिणाम युद्ध न होकर प्रत्यपकार में परिणत होता है ।

ग्रीफेनर वेस्टलेक की परिभाषा में युद्ध सरकारों की वह दशा अथवा स्थिति है जब वे बलपूर्वक परस्पर लड़ते हो । ग्रीशस (Grotius) ने भी युद्ध को एक स्थिति (condition) माना है । सीरेस इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है । वह शत्रुता में लगे रहने की दशा को युद्धकारिता अथवा युद्ध सलग्नता (belligerency) कहते हैं तथा लड़ाई के मध्य में जो एक के बाद दूसरे शत्रुतापूर्ण कार्य होते हैं उनको 'युद्ध' (war) । उनके अनुसार युद्ध एक प्रतिस्पर्धा है न कि एक स्थिति और इसके अनन्तर यह उन प्रतिस्पर्धाओं तक ही सीमित है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों द्वारा दिये गये राज्य के अधिकार के अन्तर्गत किये जाते हैं ।

रूसी के विचार में युद्ध दो राज्यों के बीच में बल प्रयोग द्वारा झगडा (a contention by force between two states) है । यह विचार इस अर्थ में अप्रचलित है क्योंकि आधुनिक युद्ध निर्दयता से नैतिक विचारों की अपेक्षा किए बिना लड़े जाते हैं जो युद्धों को अधिक अमानुषिक बनाने का यत्न करते हैं । आजकल का युद्ध का विचार सर्वाङ्गीण युद्ध है जहाँ प्रत्येक वस्तु युद्ध में विजय प्राप्त करने के सर्वोच्च कार्य के अधीन रखी जाती है । लड़ने वाले तथा न लड़ने वाले तथा सैनिक और असैनिक लक्ष्यों का पुराना अन्तर अब मान्य नहीं है । नागरिकों के जीवन को अब पवित्र नहीं समझा जाता ।

ग्रीफेनहेम युद्ध को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि यह दो या अधिक राज्यों के मध्य में अपने सैनिक बल द्वारा एक दूसरे को पराजित करने तथा शान्ति को दोनों पक्षों को आरोपित करने के लिए जैसा विजयी राज्य चाहे, लड़ाई है—  
a contention between two or more States through their armed forces for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases

अतः युद्ध की परिभाषा इस प्रकार हो सकती है—यह दो या अधिक राज्यों के मध्य में सैनिक बल द्वारा की गई प्रतिस्पर्धा है जिसमें प्रत्येक लड़ने वाले का चरम लक्ष्य दूसरे को जीतना तथा अपनी ही शान्ति की शर्तों को आरोपित करना है ।

हॉल (Hall) के अनुसार "When differences between States reach a point at which both parties resort to force or one of them does acts of violence which the other chooses to look upon as a breach of the peace, the relation of war is set up in which the combatants may use regulated violence against each other, until one of the two has been brought to accept such terms as his enemy is willing to grant" अर्थात् दो राज्यों में मतभेद जब बढ़कर इस स्थिति तक पहुँच जाता है कि दोनों पक्ष बल-प्रयोग पर उतर आते हैं या उनमें से एक हिंसा के कार्य करने लगता है और जिसे प्रतिद्वन्द्वी राज्य शान्ति-भंग की एक कार्यवाही मानता है, तो उनके बीच युद्ध का संबंध स्थापित हो जाता है जिनमें दोनों एक दूसरे पर हिंसात्मक कार्यवाहियाँ कर सकते हैं, यह क्रम उस समय तक जारी रहता है, जब तक कि एक पक्ष अपने शत्रु की इच्छाओं को मानने के लिए विवश न कर दिया जाय ।

युद्ध के प्रकार (Kinds of War)—अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्राचीन लेखकों ने युद्ध को लोक (Public) और व्यक्तिगत (Private), सम्मिश्रित युद्ध (mixed war), पूर्ण या अपूर्ण युद्ध (perfect or imperfect war), न्यायोचित या न्याय-प्रतिकूल युद्ध (just or unjust war) और औपचारिक या अनौपचारिक युद्ध (formal or informal war) में विभाजित किया है ।

स्वतन्त्र सम्प्रभु राज्यों के बीच के बल-प्रयोग को लोक-युद्ध कहते हैं । हाईड (Hyde) के अनुसार यह राज्यों के बीच सशस्त्र शत्रुता की एक शर्त (a condition of armed hostility between states) है । सम्प्रता के विकास के साथ ही वैयक्तिक युद्ध समाप्त हो गये, और वैयक्तिक व्यक्ति जो कि शान्ति भंग करने का प्रयत्न करते हैं, वे शान्ति ने तोड़ने वालों के रूप में माने जाते हैं । आज के युग में सभी युद्ध एव प्रकार से लोक युद्ध हुआ करते हैं और युद्ध-सलमनता और यहाँ तक कि विद्रोह की स्थिति में भी राज्य की ससम्प्रता के कारण लोक-युद्ध में तत्त्व विमान होते हैं ।

ग्रोशस (Grotius) ने एक ही समाज के विभिन्न सदस्यों द्वारा किए जाने वाले गृह-युद्ध को सम्मिश्रित युद्ध की संज्ञा दी थी । उनके अनुसार एक पक्ष प्रस्थापित सरकार के पक्ष में सोच रहता है और दूसरी ओर उसके प्राधिकार का

विरोध करने वाले वैयक्तिक लोभ होते हैं, जिन्हें द्रोही कहा जाता है। आज की परिस्थितियों में यह वर्गीकरण सत्य नहीं स्थिर होता, नभोवि जैसा कि ऊपर कहा गया है, युद्ध सलग्नता की भाव्यता के साथ ही साथ युद्ध का समूचा रूपा ही बदल गया है। ओपेनहेम के अनुसार एक युद्ध युद्ध उस समय अस्तित्व में होता है, जबकि एक ही राज्य में दो एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी पक्षकार राज्य में प्रभुत्व में आने के लिए शस्त्रों की शरण लेते हैं या जबकि एक राज्य की अनुराधा का एक बहुत बड़ा वर्ग वैध सरकार के विरुद्ध खड़ा होकर सामने आ जाता है।

एक पूर्ण युद्ध वह है, जहाँ कि सम्पूर्ण राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से युद्ध-रत हो, जबकि एक अपूर्ण युद्ध कतिपय स्थानों, व्यक्तियों और वस्तुओं तक ही सीमित हो।

जहाँ-कहीं युद्ध के लिए न्यायोचित कारण उपस्थित रहते हैं, उस न्यायोचित युद्ध कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी राष्ट्र की राजनैतिक स्वतन्त्रता और क्षेत्रीय एकता के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध न्यायोचित युद्ध कहा जायेगा। दूसरी ओर, एक न्याय प्रतिकूल युद्ध वह है जो कि न्याय-विरुद्ध आधारों पर लड़ा जाता है। अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा की पूर्ति के लिए पड़ोसी राज्य की क्षेत्रीय सीमा में घुसकर उस प्राप्त करने के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध न्याय-प्रतिकूल युद्ध कहा जायेगा।

एक औपचारिक युद्ध वह है जो कि वांछित सभी औपचारिकताओं के साथ घोषित कर दिया जाता है और उसका संचालन लोक-प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। एक अनौपचारिक युद्ध किसी दूसरे राज्य पर सहसा आक्रमण कर देने से उत्पन्न हो जाता है।

अन्तिम रूप से, ओपेनहेम (Oppenheim) के अनुसार, गुरिल्ला युद्ध-कोशल उस युद्ध में अपनाये गये कोशल को कहते हैं जो कि शत्रु द्वारा विजित क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो सशस्त्र और संगठित सेना के अंग नहीं हैं।

पूर्ण युद्ध (Total War) :—वर्तमान युग के युद्ध ने पूर्ण युद्ध का रूप धारण कर लिया है जिसमें वे नैतिक विचार जा उन अभिसमयों पर आधारित हैं जो युद्ध के अधिक मानुषिक बनाना चाहते हैं अथवा युद्ध के नियम नियत करते हैं कोई युद्ध अथवा वैधता रखने वाले नहीं माने जाते। प्रत्येक वस्तु युद्ध-शासित करने वाली साम्राज्यों के अन्तर्गत रखी जाती है। नियम, विनियम, आचरण, सन्धियाँ तथा युद्ध के घूल में मिला दिये जाते हैं तथा इस प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत प्रभावों से उन्मुक्त होकर, अतिसूचक अपने शत्रु को परास्त करने के



लक्ष्य से और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रीनियो तथा उपायों की अपेक्षा न करते हुये युद्ध किया जाता है (R. W. Cooper : The Nuremberg Trial, p. 299) । इस प्रकार गत युद्ध में अणुबम का प्रयोग स्पष्टतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अति प्राचीन सम्य युद्ध के नियमों का उल्लंघन था तथा मानवता के विरुद्ध एक अपराध था ।

क्या यह आवश्यक है कि युद्ध के पूर्व युद्ध की घोषणा की जाय ? (Prior Declaration of War) :—किसी समय राज्यों के बीच में शत्रुता को वैध करने के लिये यह आवश्यक समझा जाता था कि एक राज्य अपनी ओर से शत्रु-राज्य को नियमपूर्वक अधिसूचना द्वारा यह घोषित करे कि हमकी ओर उसकी लड़ाई है । इस रीति का रोमन तथा यूरोप के राज्यों द्वारा सत्रहवीं शताब्दी के मध्य तक समान रूप से अनुकरण किया गया । लड़ने के लिये ललकारने के पत्र अथवा अप्रदूत अन्य पक्षधार के पास भेजे जाते थे जिनके द्वारा सन्देश पहुँचने तथा युद्ध आरम्भ होने के बीच में तीन दिन का समय दिया जाता था । इस लोकाचार का सबसे आधुनिक उदाहरण सन् १६३५ में वसेस्म में युद्ध की घोषणा है जिसमें सहाय्य अप्रदूतों द्वारा जो अत्यधिक शिष्टता से भेजे गये थे, शत्रु को आवश्यक सूचना दी गयी । अप्रदूतों को भेजने की इस रीति को त्याग देने के उपरान्त अन्य पक्ष को युद्ध आरम्भ करने की सूचना देने के लिए एक नियमानुसार राजनैतिक वक्तव्य देने की प्रथा प्रचलित हुई, किन्तु अठारहवीं शताब्दी तक ऐसे राजनैतिक वक्तव्य भी प्रायः त्याग दिये गये और हम देखते हैं कि बहुत सी दशाओं में ऐसे वक्तव्य केवल युद्ध आरम्भ करने के उपरान्त ही किये गये । सन् १७०० तथा १८७० के बीच में यह ज्ञात किया गया है कि दस मामलों में युद्ध की घोषणा की गयी परन्तु १०७ मामलों में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई । युद्ध आरम्भ करने के पूर्व उसकी घोषणा करने की प्रथा उन्नीसवीं शताब्दी के बाद के वर्षों में पुनः सामान्य रीति से व्यवहार की जाने लगी और उस समय यह प्रायः स्वीकृत कर लिया गया था कि कुछ प्रकार की घोषणा अथवा अन्तिम चेतावनी आवश्यक है ।

राज्यों की रीति के पुनरावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विषय में कोई सामान्य नियम नहीं निकाला जा सकता कि शत्रुता के कार्य आरम्भ करने के पूर्व कोई पूर्वकालिक अथवा नियमपूर्वक युद्ध की घोषणा आवश्यक है या नहीं, किन्तु यह प्रकट है, जैसा कि लौरेंस न सकेत किया है, कि इसमें सन्देह नहीं कि राजनैतिक आचरण के अनुसार यह आवश्यक है कि बिना सावधानी के युद्ध की शत्रुता के कार्य आरम्भ न किये जायें । किसी राज्य को परम शान्ति की व्यवस्था



कर देना चाहिये और यह उनके सम्बन्ध में तब तक प्रभाव न रखेगा जब तक कि अधिसूचना प्राप्त न हो जाय, जो तार द्वारा भी दी जा सकती है।

इस प्रसिद्ध अभिसमय का शोचनीय रूप से भग उस समय हुआ जब सन् १९३१ में जापान ने मंचूरिया का अभिग्रहण सन् १९३५ में किया और शांघाई पर आक्रमण किया तथा जब इटली ने अबीसीनिया पर नाममात्र की भी चेतावनी दिये बिना आक्रमण कर दिया। जापान ने इस इतिहास की पुनरावृत्ति जुलाई सन् १९३७ में की जब उसने बिना पहल कोई चेतावनी दिये हुये चीन के विरुद्ध पुनः युद्ध आरम्भ कर दिया। उसके उपरान्त द्वितीय महायुद्ध हुआ जिसका भी आरम्भ सितम्बर १९३९ में जर्मनी द्वारा पोलैण्ड पर बिना किसी सूचना के आक्रमण करने तथा आकाश से बमबर्षा करने के कारण हुआ। इस द्वारा फिनलैण्ड पर जो आक्रमण किया गया वह भी बिना किसी सूचना के किया गया था। जून १९४१ में जर्मनी ने रूसी संधि पर भी बिना किसी सूचना के आक्रमण कर दिया। इन सब के शिखर पर दिसम्बर १९४१ का पर्ल हारबर का मामला आता है जब जापान ने पर्ल हारबर में स्थित समुक्त राज्य अमेरिका के जहाजी बेड़े पर अचानक ही आक्रमण कर दिया। जापान ने इस कार्य का समर्थन अन्तर्राष्ट्रीय विधि के युद्ध-संचालन सम्बन्धी किसी भी सिद्धान्त पर नहीं किया जा सकता। १९६२-६३ में भारत की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर जो चीन की ओर से प्रबल आक्रमण हुआ था, उसकी भी चान की ओर से कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी और युद्ध में रत होने के पश्चात् भी दोनों देशों ने युद्ध की घोषणा नहीं की थी।

**युद्ध का तत्कालिक प्रभाव (Immediate Effects of War)** — युद्ध का तत्कालिक तथा सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि प्रत्येक पक्ष के युद्धकर्ताओं के सार्वजनिक सैन्य दलों को यह अधिकार प्रदत्त कर दिया जाता है कि युद्ध-संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार युद्ध आरम्भ कर दें।

**राजनयिक तथा वाणिज्य-सम्बन्धी नियम (Diplomatic and Consular Relations)** — इसका यह भी प्रभाव होता है कि राजनयिक सम्बन्ध समाप्त हो जाता है तथा राजदूतों को घरना-प्रपना पारगोर्ट निकलना होता है। असम होन वाले दूत को यह अधिकार होता है कि वह अपने देश के वापस की यात्रा भर में राजनयिक उन्मुक्तियों का उपयोग कर तथा प्रलेखाना छोड़ देना स्या हो ता वह मुद्रावित करके रत दिया जाता है।

वाणिज्यदूतों का भी कार्य नहीं करन दिया जाना और उरदादि अन्य राज्य के वाणिज्य दूत को सौंप दिय जाते हैं।

**वाणिज्य सम्पर्क (Commercial Intercourse)** —युद्ध छिड़ने पर कुछ प्रतिबंधों के साथ दोनों लड़ने वाले राज्यों के बीच के प्रायः वैध सम्बंध या तो कुछ समय के लिये स्थगित कर दिये जाते हैं अथवा समाप्त कर दिये जाते हैं । इनका परिणाम यह होता है कि शत्रु प्रजातंत्रों के बीच के सभी व्यापारिक सम्पर्क प्रवैध हो जाते हैं । दोनों महायुद्धों के बीच ग्रेट ब्रिटेन ने सन् १९१४ तथा सन् १९३६ के शत्रु से व्यापार सम्बन्धों अधिनियम पारित किए जिसके अनुसार युद्ध के बीच ऐसे सब लेन देना का निषेध किया गया जिनमें शत्रुदेश में रहने वाले अथवा व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का सुधार हो ।

**संधियाँ (Contracts)** —युद्ध करने वाले प्रजातंत्रों के बीच युद्ध के समय में कोई नयी संधिदाएँ नही की जा सकती तथा यदि वे ऐसे नियोजनों के होते हुये भी की जायें तो न्यायालय उनको मूलतः अवैध तथा प्रभावहीन घोषित करते हैं यह शर्त कि वे किसी विशेष लाइसेन्स के अधीन न किए गए हों । युद्ध से पूर्व की गई संधियाँ या तो विघटित कर दी जाती हैं अथवा कुछ काल के लिए स्थगित कर दी जाती हैं । यदि संधिदाएँ प्रशासकीय संधिदाएँ हों अथवा यदि समय संधिदा के लिए सारभूत तथ्य रहा हो तो वे स्वतः विघटित हो जाती हैं ।

युद्ध का प्रथम परिणाम यह होता है कि युद्ध में लगे हुये देश प्रजातंत्र तथा एक तटस्थ के बीच में हुई कोई संधिदा का पूर्ति उस समय तक नहीं हो सकती जब तक युद्ध का क्रम उस समय तक रहता है यदि युद्ध में लगे हुए प्रजातंत्र ने यह संधिदा की हो कि वह शत्रु शत्रु के देश में प्रवेश करेगा ।

**साझेदारी वाले फर्म (Partnership Firms)** —युद्ध छिड़ने पर यदि साझेदारी शत्रु का सम्पत्ति प्राप्त कर ले तो साझेदारी वाले फर्म समाप्त हो जाते हैं किंतु विदेशी साझेदार को युद्ध के समाप्त होने पर अपना धन वापस प्राप्त करने का अधिकार है ।

**ऋणों का भुगतान (Payment of Debts)** —युद्ध में सलग्न राज्य द्वारा अन्य राज्य के प्रजातंत्रों को युद्ध छिड़ने के पहले की गई हुई संधिदामा के लिये देय ऋण केवल कुछ काल के लिए स्थगित हो जाते हैं तथा स्थगित होने वाली शर्तित ऋणदाता के पूर्व अधिकारों को पुनर्जीवित कर देती है । ऐसी दशा में युद्ध चलने के काल तक ऋण की संधि ऋणदाता के विरुद्ध लागू नहीं होती, किन्तु यदि ऋण शत्रु द्वारा युद्धकाल में लिया जाय तो इसके लिये युद्ध समाप्त होने पर दावा की जा सकता है ।

**शत्रु के देश में प्राप्त सम्पत्ति (Property found in the Enemy Country)** —अन्तर्राष्ट्रीय रीति पर आधारित आधुनिक नियम से यह प्रकट होता

है कि शत्रु की सम्पत्ति जो युद्ध में सलग्न राज्य के क्षेत्र के भीतर युद्ध के आरम्भ में पाई जाय उसका युद्ध में लूटी हुई सम्पत्ति के रूप में अभिग्रहण तथा अपहरण नहीं हो सकता। फिर भी, नियम प्रायः सधि की शर्तों से अनुशासित होता है। अतः कोई ऐसा अचल अथवा घटल नियम नहीं बनाया जा सकता जिससे समस्त मामले सब समय में अनुशासित हों। शत्रु की आर्थिक सहायता रोकने के लिए सम्पत्ति प्रायः अलग या नष्ट कर दी जाती है। द्वितीय महायुद्ध के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहाँ तक किया कि उसने जर्मनी द्वारा कुचले गए तटस्थ देशों का पावना भी निश्चालन (froze) कर दिया जब वह प्रावैधिक तटस्थता की दशा में था। इस नीति का परिणामस्वरूप अमेरिका ने जर्मनी तथा इटली के पावनों को सन् १९४१ में पारित एक प्रशासकीय आदेश द्वारा निश्चालन कर दिया तथा रूमानिया, लेटविया तथा इथोपिया के पावनों को भी जिनपर जर्मनी द्वारा आक्रमण किया गया था, निश्चालित कर दिया था।

यह स्थापित कर दिया गया है कि जबल युद्ध की घोषणा स्वतः यह प्राधिकृत नहीं करती कि राज्य के क्षेत्र के भीतर प्राप्त शत्रु की सम्पत्ति को दण्ड के रूप में युद्ध में उस समय तक अभिग्रहीत सम्पत्ति के रूप में लूट लिया जाय, जब तक कि इसके प्राधिकृत करने वाला विधायी अधिनियम बाद में पारित न हो।

प्रथम तथा द्वितीय दोनों महायुद्धों के बीच में शत्रु सम्पत्ति के संरक्षण के लिए ब्रिटिश सरकार ने शत्रु की सम्पत्ति के संरक्षक नियुक्त किये। प्रथम महायुद्ध के उपरान्त शान्ति-संधियों द्वारा भूमि पर वैयक्तिक सम्पत्ति को पुनः समायोजन करने की व्यवस्था की गई। सन् १९४७ की शान्ति संधि द्वारा विजेता राज्य इस बात के लिये समर्थ हुये कि वे मित्र-राष्ट्र तथा उनके आताय जनों के दावों की पूर्ति के लिये शत्रु की सम्पत्ति को अपने पास रखें।

तटस्थ राज्यों में युद्ध-स्थित सम्पत्ति (Belligerent Property in Neutral States).—साधारण नियम के अनुसार युद्ध-स्थित ऐसी सम्पत्ति जो कि तटस्थ राज्यों में पाई जाती है अभिग्रहण से मुक्त है किन्तु ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ ऐसी सम्पत्तियाँ तटस्थ राज्य-क्षेत्र के लिए अपव्यक्त हो सकती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसे अवसर आये जब कि मित्र राष्ट्रों के तटस्थ देशों के नाम इस प्रकार विषय को चेतावनी भेजनी पड़ी कि वे अपने राष्ट्रों के जर्मनी और उसके मित्र राष्ट्रों की सम्पत्ति का संप्रक्षेत्र न बनायें। सन् १९४१ अमेरिका ने तटस्थ देशों को इस प्रकार की सूचना १९४१ के युद्ध प्रावधानों के अन्तर्गत ही जर्मनी के विरुद्ध दे दी थी।

**युद्ध का संधियों पर परिणाम (Effect of War on Treaties) :—**

जैसा कि Judge Cardozo ने *Techt v. Hughes* [ (1920) 229 N. Y. 222 ] में लिखा है : “अन्तर्राष्ट्रीय विधि में युद्ध का संधियों पर प्रभाव एक सबसे बड़े उलझन का प्रश्न बनकर बचा रहता है। (The effect of war on treaties remains as yet one of the most unsettled subjects in International Law.)” इस बात पर एक सामान्य स्वीकारोक्ति है कि संधियाँ तो युद्ध होने पर ही समाप्त हो जाती हैं और कुछ हम प्रकार की हैं जो युद्ध से बिल्कुल ही अप्रभावित रहती हैं। इसके उपरान्त भी कुछ ऐसी संधियाँ हैं जो युद्ध चलने के काल में स्थगित रहती हैं किन्तु युद्ध समाप्त होने पर पुनर्जीवित हो जाती हैं।

विधि की अव्यवस्थित दशा में किसी सशक्त सिद्धान्त अथवा सिद्धान्त को एकरूपता का बताना कठिन है। इस सम्बन्ध में दो प्रकार से परीक्षा प्रयुक्त की जा सकती है। पहली विषय-वस्तु सम्बन्धी (subjective) परीक्षा इस भाष्य की है— क्या संधि पर हस्ताक्षर करने वालों का यह भाष्य था कि युद्ध के आरम्भ में यह बाध्यकारी रहे ? दूसरी परीक्षा उद्देश्य-सम्बन्धी (objective) इस भाष्य की है— क्या संधि का निष्पादन युद्ध के संचालन के साथ असंगत है ?

संधियाँ जिनमें युद्धसंलग्न तथा अन्य शक्तियाँ पक्षकार हैं (Treaties to which the belligerents and other powers are parties) :— बड़ी संधि विधायक संधियाँ उदाहरणार्थ पेरिस की घोषणा (१८५६) जो राज्यों के समाज के लिये विधान बनाती हैं अपने सदस्यों में स दो अथवा अधिक के बीच में युद्ध से अप्रभावित रहती हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य, स्वच्छता, भौषधि सम्बन्धी विधियाँ जो अन्तर्राष्ट्रीय समाज को समस्त सुविधाएँ प्रदान करने की व्यवस्था करती हैं युद्ध-रत तथा तटस्थों के बीच में बराबर चालू रहती हैं। केवल ऐसी व्यवस्थाएँ जो युद्ध-संचालन से असंगत हो स्थगित कर दी जाती हैं और युद्ध की समाप्ति होने पर पुनर्जीवित होती हैं।

सामान्यतः ऐसी संधियाँ, जैसी विभिन्न राज्यों के बीच मित्रता तथा सम्बन्ध की, जिनमें कि युद्ध-रत राज्य भी सम्मिलित हैं, विग्रह के आरम्भ में ही विनष्ट कर दी जाती हैं, केवल उन घटों को छोड़ कर जो स्पष्टतः सम्बन्ध-विच्छेद के सम्बन्ध में की गई हो। व्यापारिक संधियाँ केवल जो युद्ध में वस्तुतः संलग्न हो उनके ही सम्बन्ध में लोप कर दी जाती हैं किन्तु जहाँ तक तीसरे पक्षकार का सम्बन्ध है वे चालू रहती हैं।

ऐसी संधियाँ जिनमें युद्ध की सभाव्यता पर विचार किया गया हो, अथवा जो स्पष्टतः युद्ध की व्यवस्था के लिये की गई हों तथा युद्ध-संचालन से संबंधित हो,

युद्ध के आरम्भ होते ही चालू हो जाती हैं। युद्धकाल में अस्वस्थ तथा घायलों की चिकित्सा के सम्बन्ध में सन् १८६४, १९०६ तथा १९४९ के जेनेवा अभिसमयों तथा सन् १८६९ और १९०७ के हेग अभिसमयों जो युद्ध के नियम तथा युद्धमानों को पारस्परिक सम्बन्धों और उनके तटस्थों के प्रतिभावों को निर्धारित करती हैं, सम्पूर्ण युद्धकाल में बधनकारी रहती हैं।

संधियाँ जिनमें केवल युद्ध-संलग्न राज्य ही पक्षकार हैं (Treaties to which the belligerents only are parties) :—संधियाँ जो अन्तिम रूप से विषयों को निर्धारित करती हैं तथा उनके सम्बन्ध में एक स्थायी स्थिति उत्पन्न करती हैं, वह सीमा सम्बन्धित अभिसमय तथा संधियाँ हैं जो एक निश्चित क्षेत्र के तटस्थीकरण के सम्बन्ध में व्यवस्था करती हैं, तथा प्रदान (cession), स्वतन्त्रता अथवा राजवश व्यवस्था सम्बन्धी स्वीकृतियाँ हैं, जो युद्ध से प्रभावित नहीं होती तथा प्रवृत्त रहती हैं।

राजनैतिक संधियाँ, उदाहरणार्थ मित्रता की संधियाँ तथा अभिसमय जो सामान्यतः मैत्री तथा परस्पर के स्नेह में बढ करते हैं, अथवा विवाचन सम्बन्धी संधियाँ युद्ध आरम्भ होने पर रद्द हो जाती हैं।

फाइड्स एटियम हास्टाई सर्वेएन्डा (Fides etiam hosti servanda) :—यह एक सिद्धान्त है, जो कि युद्ध-संलग्न राज्यों के शत्रुता-रहित सबंधों को निर्देशित करते हैं। यद्यपि युद्ध के आरम्भ होने का तात्पर्य प्रतिद्वन्द्वी राज्यों के बीच के ऐसे समस्त सम्बन्धों को समाप्त कर देना है, फिर भी, परिस्थितियों की आवश्यकताएँ, मानवोचित विचारधाराएँ, तथा अन्य माँगें, ऐसी आवश्यकता को उत्पन्न कर सकती हैं कि युद्ध में संलग्न रहने के उपरान्त भी प्रतिद्वन्द्वी राज्यों के बीच कुछ ऐसे सम्बन्ध बने रहें जो शत्रुतापूर्ण न हों। ऐसे शत्रुता-रहित सम्बन्धों के उदाहरण युद्ध-बन्धियों को छोड़ने, वैयक्तिक प्रयोग की सभी सामग्रियों को लौटाने, पत्नी, जवाहरात, आदि के प्रत्यर्पण, आदि हैं। ऐसे शत्रुता-रहित सबंधों की रक्षा तथा उनका निर्वाह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत सुरक्षित हैं।

## अध्याय ३६

### शत्रु-स्वभाव

#### (Enemy Character)

व्यक्तियों का शत्रु-स्वभाव (Enemy Character of Individuals) :—सामान्य नियम यह है कि युद्ध-स्थित राज्य की जनता युद्ध शुरू होने पर शत्रु-स्वभाव

की बन जाती है। तटस्थ राज्यों के लिये यह बात लागू नहीं होती। सबसे पहली बात जो कि किसी व्यक्ति के शत्रुत्वभाव को सिद्ध करती है, वह है उसकी देश-भक्ति। इस सामान्य नियम क कुछ अपवाद भी हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि भूतकाल में एक और ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धतियों में तथा दूसरी ओर महा-द्वितीय देशों में बहुत भिन्नता थी।

लारेंस ने उन व्यक्तियों के वर्ग को जिन्हें शत्रुता का लक्षण रखने वाला समझा जाय, एक आरोहण (ascending) तथा अवरोहण (descending) श्रेणी में उन मात्रा के अनुसार जिममें कि शत्रुता के लक्षण की उन पर छाप डाली जाय, सक्षिप्त किया है जो निम्नलिखित है—

१ प्रथम महत्व के क्रम में वे व्यक्ति आते हैं जो शत्रु के सैनिक दलों में भर्ती हैं। वे पूर्ण रूप से शत्रु हैं।

२ इसके उपरान्त वे नाविक जो शत्रु-राज्य के व्यापारिक जलयानों को चलाते हैं अथवा शत्रु के व्यापारिक जलयानों के मल्लाहों के जत्थे आते हैं। उनकी स्थिति सैनिक दलों तथा नागरिक जनता के बीच की है। सन् १९०७ के हेग अभि-समय द्वारा वे बन्दी के रूप में रखे जाने के उत्तरदायित्व में इस शर्त पर उन्मुक्त कर दिये गये कि वे इस बात की एक लेखबद्ध प्रतिज्ञा कर दें कि युद्ध के बीच में उनके संचालन सम्बन्धी कोई सेवा न करेंगे।

३. इसके उपरान्त वे व्यक्ति आते हैं जो किसी सेना का अनुगमन बिना प्रत्यक्ष रूप से उससे सम्बन्ध रखते हुए करते हैं। हेग विधान के अनुच्छेद १३ में जो स्थल युद्ध की विधियों तथा रुझियों के सम्बन्ध में हैं, समाचारपत्र के सवाददाता, सूचना देने वालों, सेना का रसद पहुँचाने वालों को उपरान्त वर्ग में बतलाया गया है। ऐसे व्यक्ति रोकें जान पर युद्धबन्दी के रूप में व्यवहार किये जाने के अधिकारी हैं किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उनके पास उस सेना के प्राधिकारियों का प्रमाण-पत्र हो जिसके कि साथ वे हो।

४ वे व्यक्ति जो शत्रु के देश में निवास करने लगे हो चाहे वे जातीयता से तटस्थ ही क्यों न हो, शत्रु के लक्षण प्राप्त कर लेते हैं, शर्त यह कि वे शत्रु के देश में युद्ध की घोषणा के उपरान्त भी व्यापार के प्रयोजना के लिये रहना जारी रखें।

५. वे व्यक्ति जो ऐसे स्थानों में रहने लगे जो शत्रु द्वारा केवल सैनिक दखल रखने वाले के रूप में प्राधिकृत किए गए हो उस समय तक शत्रु समझे जाते हैं जब तक कि दखल रहता है। विग्रह-स्वरूप दखल की समाप्ति पर निवासियों के साथ नागरिकों के, न कि शत्रु-क्षेत्र के निवासियों के, रूप में व्यवहार किया जाता है।



६. जो तटस्थ देश निवासी व्यक्ति जिनकी शत्रु के देश में व्यापारिक कोठियाँ हैं, उनको यह समझा जाता है कि उन्होंने शत्रु का लक्षण प्राप्त कर लिया है। ऐसे व्यक्ति व्यापारियों के रूप में स्थायी निवास प्राप्त कर लेते हैं और तत्संबंधित अपने माल को अभिग्रहीत किये जाने की आपत्ति में डालते हैं।

यहाँ यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति जो शत्रु-राष्ट्रीय हैं, यदि वे तटस्थ राज्य के निवासी हो तथा वहाँ व्यापार करते हो तो अवश्य ही वे शत्रु-स्वभाव से पूर्ण हो, आवश्यक नहीं है।

सामान्य नियम यह है कि युद्ध में सलग्न राज्यों के प्रजाजन युद्ध छिड़ने पर शत्रु का लक्षण प्राप्त कर लेते हैं किन्तु युद्ध में भाग न लेने वाले राज्यों के राष्ट्रीय-जन तटस्थ समझे जाते हैं। उपरोक्त नियम उस दशा में लागू नहीं होगा जब तटस्थ राज्यों के प्रजाजन युद्ध में सलग्न किसी की ऐसी सेवाएँ करें जो एक तटस्थ राज्य को न करनी चाहिये अथवा यदि वे शत्रु देश के स्थायी निवासी होकर करो के दान तथा अन्य रीतियों से शत्रु की शक्ति बढ़ाने में अपना हाथ बटाते हो।

अमेरिका के सन् १९१७ के शत्रु के साथ व्यापार सम्बन्धी अधिनियम में 'शत्रु' की परिभाषा इस प्रकार है—“(अ) कोई व्यक्ति, मालेदारी अथवा किसी राज्य के व्यक्तियों की अन्य संस्था जो किसी ऐसे राज्य के क्षेत्र के भीतर निवास करती हो जिससे कि संयुक्त राज्य से युद्ध हो रहा हो, (आ) किसी राज्य की सरकार जिससे संयुक्त राज्य से युद्ध हो रहा हो, (इ) ऐसे अन्य व्यक्तिगण अथवा संस्थाएँ अथवा व्यक्तिगणों के वर्ग जो किसी ऐसे राज्य के नागरिक अथवा प्रजाजन हो जिससे संयुक्त राज्य से युद्ध हो रहा हो।

सन् १९३९ के अंग्रेजी शत्रु के साथ व्यापार वाले अधिनियम में व्यक्तियों के सम्बन्ध में 'शत्रु' की परिभाषा इस प्रकार है—“कोई व्यक्ति जो शत्रु के क्षेत्र में रहे हो (Any individual residing in enemy territory)।”

स्थायी निवास (Domicil) —स्थायी निवास के प्रश्न पर लार्ड स्टोवल द्वारा The Harmony [(1800) 2 C. Rob. 322] में विचार किया गया। यह कथन किया गया कि स्थायी निवास के निर्णय करने में समय सब से बड़ा अंश है। यह बार-बार कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी देश में केवल किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये आवे तो उससे उसका स्थायी निवास स्थिर न होना चाहिये। किन्तु यदि प्रयोजन इस प्रकार का हो जिससे उस व्यक्ति को एक दीर्घ-कालीन अवधि तक रुकना पड़े अथवा वास्तव में रुकना पड़ा हो तो उस विशिष्ट प्रयोजन पर एक सामान्य निवास अकुरित हो सकता है। इतनी लम्बी अवधि तक

निवाम के पश्चात् प्रारम्भिक मूल प्रयोजन की प्रार्थना सार्थक नहीं हो सकती थी, और इससे यह अनुमान होना चाहिये कि प्रारम्भिक आशय में अन्य प्रयोजन प्रवेश कर गए हैं, और इस प्रकार उन्होंने पक्षकार पर उस देश के लक्षणों की छाप डाल दी है जिसमें कि वह रह रहा है ।

**शत्रु-पोत (Enemy Vessels)** — किसी जहाज का यह लक्षण कि क्या वह शत्रु का जहाज है या तटस्थ देश का प्रथम दृष्टि में ही उस झड़े से निश्चित होता है जिसको फहराने को वह प्राधिकृत है । सन् १९०६ की लन्दन की घोषणा ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि के इस प्रचलित नियम को पुष्ट किया । शत्रु द्वारा शासन पत्र दिया हुआ जहाज अथवा शत्रु द्वारा चालित उसके कप्तान तथा मल्लाहों के दल सहित शत्रु की सम्पत्ति समझी जायेगी चाहे वह किसी तटस्थ मालिक की ही क्या न हो और वही दशा एक तटस्थ जहाज की भी होगी या स्वभावतः शत्रु के झड़े के नीचे तैरता हो अथवा शत्रु से आज्ञा-पत्र (पास) अथवा लाइसेन्स प्राप्त किया हो । यह सामान्य नियम कि किसी जहाज के शत्रु अथवा तटस्थ लक्षण निश्चित करने की परीक्षा उस झड़े से होती है जिसे लगाने का उसे अधिकार है, आजकल कुछ अपवादों से अनुशासित होता है जो निम्नलिखित हैं —

१. ऐसे जहाज जिनके स्वामी शत्रु हो और जो एक तटस्थ झड़े के नीचे तैर रहे हों, शत्रु का लक्षण प्राप्त कर लेते हैं, यदि वे सैनिक व्यक्तियों तथा सदेशों को अन्य निरपराध क्रियाओं के साथ ही ले जा रहे हों ।

२. तटस्थ व्यापारी जहाज यदि वे (अ) विग्रह में प्रत्यक्ष भाग ले (या) किसी शत्रु के अभिकर्ता के आदेशों अथवा नियन्त्रण के अधीन हों (इ) शत्रु के कार्य में अनन्य रूप से लगे हों अथवा (ई) शत्रु द्वारा अपने ही प्रयोजनों के लिये अनन्य रूप से अपनाये गये हों, तो शत्रु का लक्षण प्राप्त कर लेते हैं ।

३. जहाज जिनके स्वामी शत्रु हो और जो तटस्थ झड़ा लगाये हों अथवा तटस्थ व्यापारी जहाज यदि वे उनको देखने, तलाशी लेने अथवा उनका पकड़ने के वैध अधिकार का विरोध करें, तो शत्रु का लक्षण प्राप्त कर लेते हैं ।

**जहाजों का हस्तान्तरण (Transfer of Ships)** — १९०७ के प्रसिद्ध सन्धि के अनुसार यदि युद्ध में सलग्न शक्तियों में से किसी एक का जहाज युद्ध के प्रारम्भ में शत्रु के बन्दरगाह में रहा तो उसे स्वच्छन्द रूप से या तो तत्काल ही अथवा रिभागत की पर्याप्त अवधि के उपरान्त जाने दिया जाता था तथा उसे एक आज्ञा-पत्र (पास) देकर सीधे अपने लक्ष्य बन्दरगाह को अथवा ऐसे अन्य बन्दरगाह को जिसका कि उसमें नाम दिया गया हो, जाने दिया जाता था । यही नियम उन

जहाजों के सम्बन्ध में भी लागू होता था जो युद्ध छिड़ने के पूर्व अपने अन्तिम बन्दर-गाह से यात्रा आरम्भ कर चुके हो तथा युद्ध छिड़ने का ज्ञान न होने पर शत्रु के बन्दरगाह में प्रविष्ट हो गए हो । (अनुच्छेद १)

यदि किसी व्यापारिक जहाज को देवदूत (force majeure) के कारण अथवा अनुच्छेद १ में विचार का गई अवधि के भीतर नहीं जाने दिया गया तो इसको निरुद्ध किया जा सकता था, किन्तु इसे जबरन नहीं किया जा सकता था । अनुच्छेद ३ में उन शत्रु के जहाजों के प्रश्न पर विचार किया गया था जिन्होंने युद्ध के आरम्भ के पूर्व बन्दरगाह को छोड़ दिया था जो मद्रम विद्रोह के अस्तित्व का ज्ञान न होने के कारण पाये गये । इनको भी जबरन नहीं किया जा सकता था किन्तु उनको निरुद्ध किया जा सकता था तथा युद्ध के उपरान्त बिना क्षतिपूर्ति के वापस किया जा सकता था अथवा माँगा जा सकता था अथवा क्षतिपूर्ति देने पर उनको नष्ट भी किया जा सकता था । शत्रु के माल के साथ जो जहाज पर था वही व्यवहार किया जाता था जो कि जहाज के साथ ।

**नौभार (Cargoes)** — ऐसा नौभार जा कि किसी शत्रुपोत द्वारा ले जाया जा रहा हो, उसके राष्ट्रीय चरित्र का निर्धारण करने में और भी कठिनाई होती है । फ्रांस, जर्मनी, इटली और अन्य यूरोपीय देश किसी सम्पत्ति के स्वामी की राष्ट्रीयता को ही अधिक महत्व देते थे । ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और हालैंड इमे देश की निवास स्थिति पर शत्रु स्वभाव को आधारित करते थे और उनका कहना था कि ऐसे लोग जो शत्रुराज्य में रहते हैं और वहाँ व्यापार करते हैं उनमें शत्रु स्वभाव आ जाता है और उन्हें वही बनाया जाता है ।

**तटस्थों का माल युद्ध में सलग्न व्यापारिक जहाजों पर तथा इसी का विपरीत (Neutral Goods on Belligerent Merchant ships and Vice Versa)** — ग्रेट ब्रिटेन ने उस नियम का अनुमरण किया जो कौन्सिलेटो डेल मेयर (Consolato del Mare) में दिया गया था जो कि मध्ययुग की बड़ी समुद्रीय संहिता थी, जिसके अनुसार माल का स्वामित्व अभिग्रहण किये जाने के उत्तर दायित्व को कसौटी थी । इसके अनुसार तटस्थ देशों का माल जब वह शत्रु के जहाज में ले जाया जा रहा हो जर्मनी से उन्मुक्त था किन्तु शत्रु का माल जब वह तटस्थ देश के जहाजों में ले जाया जा रहा हो जबरन कर लिया जाता था । संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी परम्परागत ब्रिटेन के नियम का अनुसरण किया किन्तु उस दशा को छोड़ कर जब इसके विरुद्ध संधि के अंतर्गत कर्तव्य होते थे । यह विषय पेरिस की घोषणा (१८५६) द्वारा निश्चय किया गया जिसमें यह व्यवस्था की गई कि तटस्थ राष्ट्र के भ्रष्ट से शत्रु के माल का संरक्षण होता था केवल उस

माल को छोड़ कर जो युद्ध में विनिषिद्ध हो तथा तटस्थ देशों का माल युद्ध में विनिषिद्ध माल को छोड़कर शत्रु के झंडे के नीचे अभिग्रहण नहीं किये। पेरिस की घोषणा प्रथमतः सात शक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित की गई। इसके उपरान्त अन्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत की गई, परन्तु युद्ध में सलग्न शक्तियों ने इसका पालन सब उत्तरवर्ती सामुद्रिक लड़ाइयों में किया है चाहे उन्होंने हस्ताक्षर किया हो अथवा नहीं।

यहाँ पर पिट् कोवेट की राय उनके 'Leading Cases on International Law' नामक पुस्तक, खंड २ से उद्धृत करना प्रसंग के अनुकूल होगा, क्योंकि वे इस नियम सम्बन्धी सम्पूर्ण झगड़े को कि "तटस्थ देशों का झंडा शत्रु के माल का संरक्षण करता है" संक्षेप में ही समाप्त कर देते हैं। उनका कहना है कि —

"विनिषिद्ध" शब्द का विस्तार युद्ध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रयाग में आने वाली सब वस्तुओं में करके, अनवरत यात्रा के सिद्धांत का विस्तार करके तथा जान का इष्ट प्रदेश वैरी का होना यह अनुमान लगाकर, यह नियम कि तटस्थ झंडे से शत्रु के माल का, केवल युद्ध की विनिषिद्ध वस्तुओं का अतिरिक्त, संरक्षण हो जाता है प्रायः पूर्णतः निष्प्रभाव हो जाता है।"

'By the extension of the term 'contraband' to cover all commodities of use, direct or indirect, in war, by the extension of the doctrine of continuous voyage and by the presumption of hostile destination the rule that the neutral flag covers enemy goods except contraband of war, has been almost wholly nullified'

**शत्रु सम्पत्ति (Enemy Property) :**— विरोध के लक्षणों से युक्त शत्रु की सब सम्पत्ति यथा शस्त्रों से सुसज्जित जहाज, तोपें, बन्दूक, गोलाबारूद विधिपूर्वक ग्रहण की जा सकती है, केवल कला की वृत्तियों अथवा युद्ध से असम्बन्धित अन्य सम्पत्ति को छोड़कर। युद्ध में सलग्न राज्य के क्षेत्र में पढ़ने वाली शत्रु का सार्वजनिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में अभिग्रहण किये जाने से कोई उन्मुक्ति नहीं है यथा शत्रु राष्ट्र की पूंजी (Fund), चलत भण्डारपूँजी (rolling stock), इत्यादि।

भूमि पर शत्रु के प्रयोजनों की सम्पत्ति सामान्यतः अभिग्रहीत किये जाने से उन्मुक्त है। वे उसी दशा में अभिग्रहण किये जाने योग्य होती हैं यदि वे हम प्रचार की हो कि युद्ध में लाभदायक सिद्ध हो। किन्तु वास्तविक सघर्ष की आवश्यकताओं ने कुछ दशाओं में यह आवश्यक कर दिया कि कोठियों का विनाश

कर दिया जाय अथवा उनको किलेबन्दी के रूप में रखा जाय । युद्ध में भाग लेने वाली जनता की चल-सम्पत्ति उस समय तक अभिग्रहीत नहीं की जा सकती जब तक वे ऐसी वस्तु न हो जैसे शस्त्र, युद्ध-सामग्र्य अथवा सवाद भेजने का यन्त्र तथा उनके अभिग्रहण किये जाने की दशा में भी उनको मुलह होने पर वापस करना होता है । साधारणतः शत्रु की सम्पत्ति को दण्डनीय नहीं ठहराया जाता, जब तक कि ऐसा प्राधिकृत करने वाला कोई अधिनियम न हो । दोनो विश्वयुद्धों के बीच ग्रेट ब्रिटेन ने शत्रु की सम्पत्ति के सरक्षक नियुक्त किये इस आशय से कि युद्ध के अन्त में उसके सम्बन्ध में अविवक्षित व्यवस्था निर्णय किये जाने तक उसे सुरक्षित रखा जाय ।

तटस्थ राज्य में युद्धस्थित की सम्पत्ति शत्रु राज्य द्वारा अभिग्रहण किये जाने से अनुत्त है क्योंकि वह पूर्ववर्ती द्वारा सुरक्षित रहती है ।

**निगम (Corporations) :-** निगमों का शत्रु-लक्षण उनके स्थायी निवास से निश्चित होता है । पिट कोबेट के अनुसार किसी निगम का स्थायी निवास वह स्थान है जहाँ कम्पनी का मस्तिष्क जो उसके कार्यों को चालन करता हो, स्थित हो । निगम का मस्तिष्क उस स्थान में स्थित कहा जाता है जहाँ उसके संचालकगण मिलते रहते हैं तथा अपनी नीति निर्धारित करते हैं । यह निरर्थक है कि क्या वह व्यक्ति जो निगम का नियन्त्रण करते हैं संचालकों के नाम से प्रसिद्ध हैं या नहीं । इसमें पक्ष-प्रदर्शक उन व्यक्तियों का निवास-स्थान है जो कम्पनी के भाग्य का नियन्त्रण करते हैं अथवा उसके कार्य की रीति का संचालन करते हैं । [Pitt Cobbett . Leading Cases on International Law, Vol. 11, p 40 (Ed. V)]. Daimler Co. Ltd. v. Continental Tyre and Rubber Co. (Great Britain) Ltd. [(1916) 2 A. C. 307] बाचे मामले में लार्ड पार्कर ने यह निर्णय किया कि एक समवाय जो यूनाइटेड किंगडम में समुक्त (incorporated) तथा पञ्जीकृत (registered) हो किन्तु शत्रु के देश में कार्य कर रही हो शत्रु मानी जानी चाहिये तथा वैयक्तिक अंशभागियों का लक्षण स्वतः समवाय के लक्षण को प्रभावित नहीं कर सकती । तथ्य सक्षिप्त में यह है कि काटिनेन्टल टायर तथा रबर कम्पनी लिमिटेड सन् १९०५ में निर्मित हुई तथा उसका पञ्जीकृत कार्यालय लन्दन में रहा । इसके संचालकगण जर्मन प्रजावरग थे तथा एक दोसर के अतिरिक्त पूर्ण अंश एक जर्मन समवाय के अथवा जर्मन राष्ट्रीय जनों के अधिवार में थे । काटिनेन्टल टायर तथा रबर कम्पनी लिमिटेड डेपर कम्पनी लिमिटेड पर एक दावा शाये वसूल करने का किया । डेपर कम्पनी ने यह अभि-

बचन दिया कि काटिनेन्टल टायर तथा रबर कम्पनी एक विदेशी शत्रु है और उनको शत्रु से व्यापार सम्बन्धी अधिनियम सन् १९१४ के लागू होने के कारण रूपा देन से रोक दिया गया है। हाउस आफ् लार्ड्स ने यह निर्णय किया कि दावा मान्य नहीं हो सकता।

लार्ड पार्कर ने निर्णय देते हुये विधि के निम्नलिखित सिद्धांतों का निर्धारित किया —

१. किसी निगम द्वारा शत्रु का लक्षण उस समय ग्रहण किया जा सकता है जबकि इसके अभिकर्तागण अथवा वे व्यक्ति जो इसके व्यापार को वास्तव में नियन्त्रण करते हों, शत्रु के क्षेत्र में रहते हों अथवा चाहे वे कहीं भी रह रहे हों शत्रु की सहायता कर रहे हों अथवा शत्रुओं से अनुदेश प्राप्त करते हों अथवा उनके नियन्त्रण में कार्य करते हों।

२. कोई कम्पनी जो यूनाइटेड किंगडम में संयुक्त की गई हो उस स्थिति में न तो मित्र और न शत्रु हो सकती है किन्तु ऐसी कम्पनी केवल अपने अभिकर्ताओं द्वारा कार्य कर सकती है और ये युद्ध के समय में शत्रु का लक्षण ग्रहण कर लेती हैं यदि वे शत्रु के देश में रहते हों अथवा शत्रु अशभागियों के अनुदेशों पर कार्य कर रहे हों।

३. अशभागियों का वैयक्तिक रूप से असंग्रहण स्वतः कम्पनी में लक्षण को प्रभावित नहीं कर सकता। यह इस प्रश्न पर आधारित है कि अथवा कम्पनी के अभिकर्तागण या वे व्यक्ति जो वस्तुतः उसके व्यापार का नियन्त्रण करते हैं शत्रुओं का वास्तव में अनुकरण कर रहे हैं अथवा उनसे अनुदेश प्राप्त कर रहे हैं या उनका नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं।

४. कम्पनी जो वि यूनाइटेड किंगडम में पञ्जीकृत हुई हो किन्तु जो एक तटस्थ देश में अवस्थित रूप से प्राधिकृत तथा यहाँ अथवा तटस्थ देश के निवासी अभिकर्ताओं द्वारा एक तटस्थ देश में कार्य कर रहा हो, प्रथम दृष्टि में मित्र समझी जानी चाहिये, परन्तु अपने अभिकर्ताओं अथवा व्यक्तियों द्वारा जो इसके कारोबार को वास्तविक रूप से नियन्त्रण करते हैं, शत्रु का लक्षण ग्रहण कर सकती है।

५. एक कम्पनी जो यूनाइटेड किंगडम में पञ्जीकृत हुई हो परन्तु शत्रु के देश में कारोबार कर रही हो, शत्रु समझी जानी चाहिये।

सामान्य नियम से निगमन ( Incorporation ) तथा वह स्थान जहाँ व्यापार किया जाता हो इसके दो कमीटो हैं जिनसे किनो निगम को शत्रु लक्षण को निश्चित किया जाता है। प्रथम तथा द्वितीय महायुद्ध के बीच इंग्लैंड ने सन् १९१४

तथा सन् १९३६ के सन्धु में व्यापार सम्बन्धी अधिनियम बनाये जाने के द्वारा यूनाइटेड किंगडम निवासी निगमों को निजी व्यापार में जो सन्धु देना था, अथवा ऐसे क्षेत्र का जो सन्धु के अधिनियम में था, रहना था या अथवा यही व्यापार कर रहा था, व्यापार करना भी मना कर दिया गया तथा यह पारल्लो का कि निगम जो सन्धु देना में व्यापार कर रहे हैं सन्धु के सन्धु में मुक्त हो जाते हैं बाहे उनका निगम यही भी क्या न हुआ था ।

दसम तथा विजय का प्रभाव (Effects of Occupation and Conquest) —दसम मन्दह नही कि जब एक मित्र के क्षेत्र पर सन्धु द्वारा सम्पादित रूप में दसम किया जाता है, तो पक्षी सरकार को मार्बमोमिक्ता स्पष्ट कर दी जाती है परन्तु उररोस्त क्षेत्र तथा उनका निवासी सन्धु का सन्धु प्राप्त नहीं करता । उभी प्रकार यदि सन्धु के क्षेत्र पर अस्थावी रूप में एक मित्र सन्धु द्वारा दसम किया जाता है तो उररोस्त क्षेत्र तथा उनका निवासी सन्धु सन्धु में उररोस्त नहीं होत । अतः दसम में स्थानीय नागरिकों का आशय का कोई पूर्ण परिवर्तन नहीं होता । राजभक्ति का हस्तान्तरण केवल सम्पादित है तथा युद्ध की अवधि अथवा दसम तक रहता है । सैनिक सम्पादित दसम पूर्ण विजय तथा सन्धु में पूर्ण रूप से मित्र है क्योंकि पूर्ण विजय तथा सन्धु एक स्थायी घटना होती है तथा मार्बमोमिक्ता को पूर्णतः स्थापित कर देती है । परिणाम यही होता है कि जब कोई क्षेत्र पूर्णतः विजित तथा किया जाता है तो यह विजयी के सन्धु अथवा मित्र-राष्ट्र हान के अनुसार सन्धु अथवा मित्र का सन्धु प्राप्त कर लेता है ।

## अध्याय ३७

### युद्ध की नई समस्याएँ

#### (New Problems of Warfare)

युद्ध का उद्देश्य —युद्ध का उद्देश्य चाहे वह भूमि, समुद्र कहीं भी हो एक ही होता है—शत्रु को बलाभिभूत करना । आपेनहेम के अनुसार "जहाँ स्वयं युद्ध का उद्देश्य शत्रु की सेना को हरा देना और शत्रु के राज्य-क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेना होता है वहाँ समुद्री युद्ध का उद्देश्य होता है शत्रु की नौसेना को पराजित करना, शत्रु व्यापारी पोत का कब्जा करना, शत्रु बन्दरगाहों का विनाश

करना और शत्रु के समुद्री किनारे पर सैनिक नियन्त्रण स्थापित करना, शत्रु का उसक बन्दरगाह से सबव-विच्छेद करना, विनिषिद्ध (contraband) वस्तु को रोकना, और शत्रु को अतटस्थ सेवा से वंचित करना, स्थल पर सभी प्रकार की सैनिक कार्यवाहियाँ की सहायता जैसे शत्रु के समुद्री किनारे पर सत्ता का उतारा जाना और अन्तिम रूप से अपने घरेलू समुद्री किनारे की रक्षा करना और घरेलू समुद्री व्यापार की रक्षा करना ।”

सक्षेप में समुद्री युद्ध का उद्देश्य अपने जहाज के लिये संचालन की स्वतन्त्रता प्राप्त करना और शत्रु का समुद्र के उपयोग से वंचित करना होता है ।

युद्ध की नई पद्धतियाँ (New Methods of Warfare) —युद्ध की पुरानी विधियों में आज विनिषिद्ध (contraband) और नाकाबन्दी (blockade) की नवीन धारणाओं का विस्तार का कारण तथा भट्ट यात्रा के सिद्धांत में विस्तार, किसी तटस्थ राज्य के पोत के माल के सम्बन्ध में यह आभास कि प्रेषक अपने निर्दोष गन्तव्य स्थान का सबूत दे, विनिषिद्ध तालिका की आशातीत वृद्धि, युद्धस्थिति जहाजों के जाँच सबधित अधिकार आदि कारणों से अनेक नवीन परिवर्तन हो गये हैं । इन सभी तथ्यों के ऊपर अणु बम और क्षेप्यास्त्रों का प्रयोग ने पूर्णतया आज के युद्ध को क्रांतिकारी ढंग से परिवर्तित कर दिया है और सामूहिक रक्तपात और निरीह जनता की सामूहिक हत्या को बचाते हुये शान्ति को स्थापित करना आज बिल्कुल नई और विकट समस्या है ।

लीग (The League) —राष्ट्रों की लीग ने युद्ध न करने के आभार को स्वीकार करके अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयत्न किया था । किन्तु यह युद्धों का न रोक सकी, फिर भी शान्तिपूर्ण समझौते के लिये अनुज्ञा दे सकी । उसकी अनुज्ञा के प्रवर्तन के पूर्व कोमिस के निर्णय की एकरूपता का होना आवश्यक था । इसके पास अपने निर्णयों के प्रवर्तन के लिए कोई सेना नहीं । इसका परिणाम यह हुआ कि १९३६ में इटली-ग्रबोसीनिया युद्ध में लीग ने आशिक अनुज्ञा जारी की, किन्तु यह अनुज्ञा पूर्णतः विफल रही ।

१९२८ का पेरिस पैक्ट (The Paris Pact, 1928) —केलाग ब्रियान्ड पैक्ट (Kellogg-Briand Pact) जिस साधारणतया अगस्त २७, १९२८, का पेरिस पैक्ट कहा जाता है, राष्ट्रों के बीच युद्ध का बन्द कर देने की दिशा में एक दूसरा आधार स्तम्भ था । हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ा का निपटारा करने के लिये युद्ध का सहारा लेने की पद्धति की निन्दा की और प्रतिज्ञाबद्ध हुये कि ऐसे झगड़ा को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाएँगे । यह समझौता एक मृतपत्र (dead letter) ही बन कर रह गया क्योंकि इसमें अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ा को सुलझाने के लिये



कोई विशिष्ट पद्धति न थी, केवल शान्तिपूर्ण मध्यस्थता, सद्भावना कार्य, विवाचन समझौता या झगड़ों को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में निवेदित करने की ही प्रथा का सहारा था ।

**संयुक्त राष्ट्र संघ (The United Nations)** —राष्ट्रों की लोग की विफलता के कारण एक नये सच की स्थापना हुई जिसे संयुक्त राष्ट्र सच कहते हैं । हस्ताक्षर करने वाले राज्यों ने इस बात का आभार अपने ऊपर लिया कि वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को शान्तिपूर्ण साधनों से और इस ढंग से सुलझाएँ कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, सुरक्षा और न्याय खतरे में न पड़े और यह कि वे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में धमकी देने या किसी राज्य के स्वतन्त्र राज्य क्षेत्र में शक्ति के प्रयोग करने या किसी भी तरह से संयुक्त राष्ट्र सच के उद्देश्यों से विमुख होने से अपने आप को रोकेंगे ।

संयुक्त राष्ट्र सच के गठन में यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा और न्याय के प्रति भक्ति की उच्च स्तर से धोखाएँ की गईं फिर भी कोरिया में युद्ध हुआ, इजिप्ट और हंगरी की घटनाएँ घटी और आक्रामक देशों ने अपने इस आभार को हवा में उड़ा दिया कि वे अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शान्तिपूर्ण ढङ्ग से करेंगे । संयुक्त राष्ट्र सच को भिन्न-भिन्न स्थलों पर सामूहिक सेना भेजकर हस्तक्षेप करना पड़ा है ।

लीग और संयुक्त राष्ट्र की शान्ति और सुरक्षा की स्थापना में असफल होने का कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय नौसेना, स्थल सेना और हवाई सेना के अभाव में यह संगठन आक्रामक राज्य को रोकने में समर्थ नहीं हो पाते । इसी कारण संयुक्त राष्ट्र सच के बाहर राज्यों ने अपने आपको भिन्न-भिन्न सुरक्षा संधियों में बाँध रखा है, जैसे रायडी जेनीरो की १९४७ की संधि, ब्रसेल्स की संधि १९४८, नार्थ, एटलान्टिक ट्रीटी १९४९, अरब लीग, बगदाद पैक्ट ( सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ), आदि । सोवियत ब्लाक ने दूसरी ओर बहुत से द्विपक्षीय समझौतों और बहुपक्षीय संधियों में भाग लिया है जैसे ईस्ट यूरोपियन ट्रीटी । ये सैनिक संधियाँ जिन्हें कि तथाकथित रूप से क्षेत्रीय पैक्ट भी कहते हैं मानवता की इस भाशा को विदीर्ण कर चुकी हैं कि इनसे अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था हो सकेगी । इन मर्यादात्मक पैक्टों में एक प्रवृत्ति यह है कि वे दूसरे देशों के प्रतिष्ठा में आक्रामक पैक्टों का रूप लेते हैं । ऐसे पैक्ट जैसे नाटो (NATO), सीटो (SEATO) और ऐन्ज़ू (ANZUS) यूरोपीय सुरक्षा की धारणाओं के प्रतिफल हैं जो विश्व की शान्ति का और भी खतरे में डालते चले जा रहे हैं । पाकिस्तान सीटो, बगदाद पैक्ट ( सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ) और संयुक्त राज्य-पाकिस्तान सैनिक सहायता पैक्ट, न प्रविष्ट होकर अन्तर्एशिया देशों में तनावों का कारण बन चुका है । भाज

की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि ऐसे क्षेत्रीय सैनिक पैक्टो पर रोक लगा दी जाय और समुचित अन्तर्राष्ट्रीय सेना का गठन किया जाय जिसमें समुक्त राष्ट्र की देख रेख में स्थल सेना, नौसेना और हवाई सेना रहे जो कि शान्ति भंग होने की किसी कार्यवाही को रोक सके और आक्रमण के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा के साधन उपस्थित कर सके ।

## अध्याय ३८ स्थल-युद्ध की विधियाँ

### ( Laws of Land Warfare )

वर्तमान युग में युद्ध की उन विधियों में तोत्र परिवर्तन हो गये हैं जिनकी उत्पत्ति रूढ़ियों से है । सन् १९०७ के हेग अभिसमय की प्रस्तावना में यह घोषित किया गया था कि "जनता तथा युद्धमान, राष्ट्रों की विधि के सिद्धान्तों के संरक्षण तथा नियमों के अधीन रहते हैं, क्योंकि वे ( सिद्धान्त और नियम ) सम्य राष्ट्रों के मध्य स्थापित रूढ़ियों, मानवता की विधियों, और जनता के विवेक की आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप निकलने हैं । प्राधुनिक युद्ध प्रतिद्वन्द्वी पक्षकारों के मध्य का एक साधारण युद्ध नहीं है । यह एक संपूर्ण युद्ध है जहाँ संपूर्ण राष्ट्र एक युद्ध के शिविर में परिवर्तित हो जाता है । बहुधा व्याक्त जिन्होंने आयु की एक विशेष अवधि को पार कर लिया है, अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती कर दिये जाते हैं । कारखानों, कार्यालयों, रेलवे संचालन तथा इग्न और घायलों की सेवा करने में स्त्रियाँ पुरुषों का स्थान ग्रहण करती हैं । युद्धरत तथा अयुद्धरत तथा सैनिक और असैनिक उद्देश्यों सम्बन्धी पुराना अन्तर भव प्रभावकारी नहीं रह गया है । युद्ध का उद्देश्य अर्थात् शत्रु को परास्त करना पवित्र समझा जाता है और जब तक वह उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता युद्धस्थित अपने लक्ष्य की पहुँचने के निमित्त प्रत्येक आवश्यक साधन प्रयोग में लाता है । युद्ध-सम्बन्धी सभी मानवता के नियम युद्ध में विजय प्राप्त करने के सर्वोच्च कार्य के समक्ष दब जाते हैं । जर्मनों ने दोनों महायुद्धों के मध्य सैनिक आवश्यकता के दबाव के अधीन नागरिक जनता का बारम्बार क्रूरता से सहार किया था । गत महायुद्ध में अमेरिका द्वारा अणुबम का प्रयोग भी सम्य युद्ध को अनुशासित करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का एक बड़ा गम्भीर उल्लंघन था जो बहुत से उन वैज्ञानिकों के विरोध के उल्लंघन में किया गया जिन्होंने उसके अनुसंधान में सहायता की थी ।

१८६४ का जेनेवा अभिसमय ( Geneva Convention of 1864 )—  
 आधुनिक मनोवृत्ति के हाते हुए भी सम्य युद्ध के नियम अतीत काल से विद्यमान रहे हैं । सन् १८६४ में स्विटजरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, स्पेन फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, पोर्चुगाल, प्रशा तथा जर्मन राष्ट्रों में से अधिकांश ने युद्ध में घायलों की दशा सुधारने के लिये परस्पर एक स्वीकारोक्ति प्रकट की जो जेनेवा अभिसमय का नाम से प्रसिद्ध है । अभिसमय में रोगियों की गाड़ियों, सैनिक अस्पतालों तथा अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी वर्ग का तटस्थ लक्षण स्वीकार किया ।

सेंट पीटर्सबर्ग का घोषणा ( St Petersburg Declaration ) —  
 जेनेवा अभिसमय के पीछे सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा हुई जो सन् १८६४ में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के बीच युद्ध की आपत्तियों को जहाँ तक संभव हो सके कम करने की दृष्टि से की गई । घोषणा में युद्धरत शत्रु के सैनिक बलों को निश्चय करने अथवा उनका मनुष्यता को सबसे अधिक सख्या में असमर्थ बनाने के अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन हथियारों के ऐसे प्रयोग को निषिद्ध कर दिया जिससे असमर्थ व्यक्तियों के कष्ट निरर्थक ही बढ़ जाय अथवा उनकी मृत्यु अवश्यम्भावी हो जाय । इसने ४०० ग्राम से नीचे के भार के प्रक्षेपणों ( जैसे तोप की गोलियों ) का प्रयोग निषेध किया जा घडाके के साथ फटने वाले हथियारों अथवा फटने वाले या जलने वाले पदार्थों से युक्त हो ।

युद्ध की रीतियाँ — भूमि युद्ध की रीतियाँ सन् १९०७ के हेग अभिसमय ४ में दी गई हैं जो भूमि पर युद्ध की विधियों तथा रूढ़ियों के सम्बन्ध में हैं, तथा सन् १९४९ के जेनेवा अभिसमय में भी हैं ।

सन् १९०७ का हेग अभिसमय (Hague Convention of 1907) —  
 हेग विनियम के अनुच्छेद २३ में जो अभिसमय से सलग्न है, युद्ध के ऐसे उपकरणों का निषेध किया गया है जो विनाशकारी हथियारों अथवा दुःखदायी हों । इसके द्वारा विशिष्ट रूप से विष अथवा विषाक्त द्रव्यों का तथा ऐसे हथियारों, प्रक्षेपणों अथवा वस्तु का उपयोग निषिद्ध किया गया जिससे अकारण दुःख या विनाश का होना संभव हो । विनियमों द्वारा प्रक्षेपणों, फटने वाले पदार्थों को गुब्बारों तथा इसी प्रकार का अन्य नवी रीतियों द्वारा फेंका जाना निषिद्ध किया गया । फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस तथा जापान ने इस वाक्यसूत्र को स्वीकृत नहीं किया ।

उन प्रक्षेपणों का प्रयोग रोक दिया गया जिनका उद्देश्य केवल दुःख देने वाला तथा विप्रेरी गैसों को फैलाना था । संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल ने इस पर हस्ताक्षर करने से परस्वीकार कर दिया । सन् १९१४-१८ के महायुद्ध में भी इन नियमों का उग्र रूप में उल्लंघन हुआ । वासिंगटन की संधि (१९०२) के अनुच्छेद

५ द्वारा समुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रांस, इटली तथा जापान ने युद्ध में दम घुटन वाली, विपैली अथवा अन्य गैरी तथा इसी प्रकार के अन्य तरल पदार्थों, वस्तुओं तथा युक्तियों का प्रयोग किया जाना निषिद्ध स्वीकार किया ।

फैलने वाली (डमडम) गोलियों का प्रयोग भी निषिद्ध कर दिया गया ।

अनुच्छेद २३ द्वारा युद्ध विधाम के भंडे, राष्ट्रीय भंडे अथवा शत्रु के सैनिक तमगों तथा बर्दी और जेनेवा अभिसमय के विशेष बिन्दुओं के अनुचित उपयोग का निषेध किया गया ।

व्यूह-रचना के नियम या 'युद्ध-कौशल' के अनर्गत आते थे, इस अनुबन्ध के साथ सीमित कर दिये गये कि उनसे सद्भाव का उत्पन्न न हो । अतः शत्रु के राष्ट्र अथवा सेना के व्यक्तियों को धोखा देकर मारना अथवा घायल करना निषिद्ध कर दिया गया ।

ऐसे शत्रु को मारना अथवा घायल करना भी निषिद्ध कर दिया गया जिसने हथियार छोड़ दिया हो, अथवा जिसके पास आत्मसमर्पण का कोई उपाय न रह जाने के कारण इन्डा से आत्मसमर्पण कर दिया हो ।

युद्ध में भाग न लेने वालों को व्यक्तिगत हानि से उन्मुक्त कर दिया गया, केवल उस दशा को छोड़कर जब कि हानि प्रसंगवश युद्ध के समुचित कार्यों के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न हुई हो अथवा उन अपराधों के लिये दंड स्वरूप दी गई हो जो कि आक्रमणकारियों के विरुद्ध किये गये हों । अनुच्छेद २५ द्वारा अरक्षित नगरों, ग्रामों तथा निवास स्थानों पर किसी प्रकार से भी आक्रमण करना अथवा बम-वर्षा करना निषिद्ध कर दिया गया । सन् १९१४-१८ के महायुद्ध में लड़ाई न लड़ने वालों पर भी हवाई जहाजों से बम बरसाये गये तथा उनका व्यक्तिगत हानि से उन्मुक्ति क मत्र वादा-नुवाद हवा में उड़ गये जब की एक युद्धरत को कथित ज्यादातियों के बदले में हमारे ने ज्यादातियाँ की । वास्तव में बहुत से मामलों में सैनिक आवश्यकताओं के कारण एक युद्धरत लड़ाई में भाग न लेने वाला की हानि से रक्षा न कर सका । सन् १९१४ में जब जर्मनी ने बेल्जियम पर आक्रमण किया तो बाद में यह आवश्यक समझा गया कि उन निवासियों को जिस प्रकार समझ हो दबाया जाये जो कि जर्मन सेना का विरोध कर रहे थे । अतः लड़ाई में भाग न लेने वालों को सरक्षण न दिया जा सका । द्वितीय महायुद्ध में वे सभी नियम मिट्टी में मिल गये जिनसे लड़ाई न लड़ने वालों को उन्मुक्ति दी गई थी जब कि तटस्थ नगरों जैसे वारसा, लन्दन और ब्रिटेन पर जर्मन हवाई जहाजों द्वारा बम बरसाये गये । इसके बदले में ब्रिटेन तथा अमेरिका के हवाई जहाजों के बंदों ने जर्मन नगरों जैसे बर्लिन, म्यूनिख, हैम्बर्ग, तथा अन्य व्यावसायिक महत्व के स्थानों पर बम बरसाये ।

हेग विनियमों के अनुच्छेद २३ द्वारा युद्धरत वा अन्य पक्ष के प्रजाजनों को उन्हीं के देश के विरुद्ध युद्ध-कार्यों में भाग लेने के लिये बाध्य करने को निषिद्ध किया गया चाहे वे युद्ध छिड़ने के पूर्व उसी की सेवा में क्यों न रहे हों ।

हेग विनियमों ने शत्रु की सम्पत्ति का विनाश तथा अभिग्रहण उस समय तक के लिये स्वीकार किया जब तक कि ऐसा विनाश अथवा अभिग्रहण युद्ध की आवश्यकता से अत्यन्त आवश्यक न हो । विनियम के अनुच्छेद २८ के अन्तर्गत आक्रमण द्वारा अधिकार में लिये गये नगर अथवा स्थान को सूटना निषिद्ध किया गया । अत्यन्त आवश्यकता की दशा में शत्रु की सम्पत्ति के विनाश अथवा अभिग्रहण सम्बन्धी नियम ने असन्दिग्ध युद्धरत को बड़ी ढील दे दी । प्रथम महायुद्ध के बीच युद्ध को शासित करने वाले नियमों को समय समय पर सग किया गया जब पुस्तकालय तथा गिरजा गृह या तो जला दिये गये अथवा विनष्ट कर दिये गये । लेकिन जैसा फेनविक का कहना है “यह द्वितीय महायुद्ध के लिये कहा गया कि वह ऐसे विनाशकारी दृश्य देखे जिससे हेग अभिसमय केवल एक विडम्बना-मान रह जाय ।” शत्रु की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति अभिग्रहीत की गयी चाहे वह व्यक्तिगत हो अथवा सार्वजनिक । जर्मन सेनाओं के आगे बढ़ने के मार्ग में रूस के विस्तृत क्षेत्रों को तथा उनके पीछे हटने के मार्ग में उससे भी अधिक विस्तृत क्षेत्रों को नष्ट कर दिया गया । एक के बाद दूसरे देश पर आक्रमण करते समय ऐतिहासिक स्मारकों को भी नहीं छोड़ा गया ।

**स्थल युद्ध की विधियों का विकास (Developments of the Laws of Land Warfare)** — स्थल-युद्ध की विधि का विकास का ज्ञान निम्नलिखित संधियों से किया जा सकता है —

१. अगस्त २२ सन् १८६४ का जेनेवा अभिसमय जो युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के घायल सिपाहियों की दवा सुधारने के सम्बन्ध में था ।

२. दिसम्बर ११ सन् १८६८ की सेंट पीटर्सबर्ग की घोषणा जिसके द्वारा ऐसे प्रक्षेपणों का निषेध किया गया था जो ४०० ग्रांम से नीचे न हों तथा फटने वाले पदार्थों से युक्त हों ।

३. सन् १८६६ तथा १९०७ के हेग अभिसमय जो फेंकने वाली गोलियों (डमडम), प्रक्षेपणों, गुब्बारों से फेंके जाने वाली प्रक्षेपणों तथा फटने वाले पदार्थों, दम फोटने वाली अथवा हानिकारक गैसों का फेंकने वाले प्रक्षेपणों तथा युद्ध छेड़ने और तटस्थ शक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा भूमियुद्धों में लगे हुये व्यक्तियों के सम्बन्ध में हैं ।

४. सन् १८६४ का प्रोटोकॉल (Protocol) जो युद्ध में दम फोटने वाली, विषाक्त तथा अन्य गैसों के सम्बन्ध में है ।

५. सन् १९२९ का जेनेवा अभिसमय जो अस्वस्थ तथा घायल और युद्ध-बन्दियों के सम्बन्ध में है ।

६. जेनेवा में सन् १९४९ में किये गये चार अभिसमय ।

सन् १९४९ का जेनेवा अभिसमय—सन् १९४९ में जेनेवा में ४ अभिसमय किये गये जो कि निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में थे —

(१) युद्धबन्दियों से व्यवहार (२) युद्ध में सलग्न सैनिक दलों के घायलों तथा बीमारों की दशा में सुधार, (३) घायल तथा बीमारों की तथा समुद्र में जहाज डूबने पर बचे हुये सैनिक दलों के सदस्यों की दशा का सुधार, तथा (४) युद्ध के समय में नागरिक जनता का संरक्षण ।

**युद्धबन्दी (Prisoners of War)** — युद्धबन्दियों की देख-रेख होनी चाहिये तथा उनसे मानवता-पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये । बन्दी को पकड़ने वाले वैयक्तिक सिपाहियों को, न कि पदाधिकारियों को उपयोगी कार्य में लगाया जा सकता है जो युद्ध-संचालन के कार्य से किसी प्रकार सम्बन्धित न हो । कार्य भी अत्यधिक न होना चाहिये । प्रत्येक दशा में उनको उनके कार्य के लिये पारिश्रमिक देना चाहिये । सन् १९४९ के हेग अभिसमय में अन्तर्गत अनायुक्त पदाधिकारीगणा से केवल निरीक्षण वा कार्य अपेक्षित है किन्तु वे अन्य कार्य का भी माँग कर सकते हैं । सन् १९०७ के विनियमों के अनुसार बन्दियों को पूजा-सम्बन्धी पूर्ण स्वतन्त्रता का अधिकार है । यदि देश की विधियाँ इस प्रक्रिया की अनुमति देती हों तो उनको उनकी हठ प्रतिज्ञा पर छोड़ा जा सकता है बन्दियों को जो भागने के प्रयत्न में पकड़े जाँव अग्निम उपाय के रूप में गोली मारा जा सकता है । यदि उनको पकड़ लिया जाय तो उन्हें दण्डित किया जा सकता है । सन् १८६४ तथा १९०७ के हेग सम्मेलनों ने प्रत्येक युद्धरत का वह कार्यभार सौंपा कि वह अपने प्रदेश में एक सूचनाशुद्ध स्थापित करे तथा युद्ध समाप्त होने पर अन्य युद्धरत की सरकार के पास आवश्यक सूचना भेजें ।

सन् १९२९ के जेनेवा अभिसमय ने भी युद्ध-बन्दियों से व्यवहार के सम्बन्ध में व्यवस्था की । सत्यापन करने वाले राज्यों के बीच में इस अभिसमय ने सन् १८६४ तथा १९०६ के अभिसमयों का स्थान ग्रहण कर लिया ।

सन् १९४९ में किए गए जेनेवा अभिसमयों में से एक युद्धबन्दियों के सम्बन्ध में था, जो किसी सैनिक सघर्ष में, चाहे वह स्वीकृत हो अथवा न हो, जो कि युद्धरत पक्षकारों के बीच उत्पन्न हुआ हो, लागू है । अभिसमय द्वारा युद्धबन्दियों के जीवन तथा शरीर से बलात्कार, वधक व्यक्ति रखना तथा मान-हानि का कार्य और निरुपेक्ष व्यवहार निषिद्ध किया गया है । बन्दियों को उनको मूचना देने के

लिए धाव्य करने के लिए कोई शारीरिक अथवा मानसिक यन्त्रणा नहीं दी जा सकती। अभिग्रहण किए जाने के उपरान्त उनको सतरे वाले क्षेत्र से हटाना आवश्यक है। बन्धन की स्थिति बन्दी के अपने देश को वापस कर दिए जाने पर, तटस्थ देश में स्थान दिए जाने पर, मुक्त किए जाने पर, भाग जाने पर, अथवा उसकी मृत्यु पर समाप्त हो सकती है।

सर राबर्ट फिलिमोर ने निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों की गणना उनमें की है जिनको युद्धबन्दी के रूप में व्यवहार किये जाने का कोई अधिकार नहीं है।

१. लुटेरों के झुंड जो बिना सन्नाट अथवा सेनानायक से अधिकार प्राप्त किए बिना कार्य कर रहे हों।

२. अभियक्ता (deserters) जो शत्रु की सेना में पकड़े गए हों।

३. भेदिये जाहे वे सामान्य सेना के ही वर्गों में हों। युद्ध की विधियों में यह व्यवस्था की गई है कि भेदिये जब उसकी सेना की पक्ष के भीतर अथवा उसकी योजनाओं तथा गतिविधियों की सूचना शत्रु को देते हुये पाये जाय तो उनको प्राणदण्ड दिया जा सकता है।

अस्वस्थ तथा घायल (Sick and Wounded) — अस्वस्थ तथा घायलों के सम्बन्ध में नियम सन् १८६४ के जेनेवा अभिसमय द्वारा निर्धारित किये गये जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। वे बाद में सन् १९०६ में जेनेवा में रूप-भेदित किए गए। सन् १९०७ के हेग सम्मेलन ने अस्वस्थ तथा घायलों के प्रति युद्धरत के वर्तव्यों को स्वीकार किया। विनियमों के अनुसार अस्वस्थ तथा घायल सड़ाई लड़ने वालों की देख-रेख युद्धरत द्वारा पक्ष अथवा जातीयता का भेदभाव रखे बिना किया जाना चाहिए। विजयी सेनानायकों का यह कर्तव्य था कि रणक्षेत्र में घायल सिपाहियों की लूट अथवा अन्य दुर्व्यवहार से रक्षा करे तथा मृत व्यक्तियों के शरीरों से प्राप्त हुई सब व्यक्तिगत सम्पत्ति को एकत्र करे तथा उन वस्तुओं को शत्रु के देश के प्राधिकारियों के पास उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के पास भेजे जाने के लिये रखवा कर दे। विनियमों में यह भी व्यवस्था की गई कि अस्वस्थ तथा घायलों का अभिग्रहण करने वाली सरकार का यह कर्तव्य है कि उनको भोजन तथा वस्त्र दें तथा इस सम्बन्ध में उनसे अपनी सेना के स्तर के अनुसार व्यवहार करे। प्रथम महायुद्ध के उपरान्त सन् १९०६ के अभिसमय में सन् १९२९ का दूसरा अभिसमय जोड़ दिया गया जिसके द्वारा रणक्षेत्र की सनाओं के अस्वस्थ तथा घायलों के साथ व्यवहार के वर्तमान नियम सशोधित किये गये थे।

सन् १८६४ का जेनेवा अभिसमय अन्त में १९४९ में जेनेवा में हुए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा संशोधित किया गया । सन् १९४९ के रणक्षेत्र के सैनिक दलों के घायल तथा अस्वस्थ की दशा सुधारने के अभिसमय में यह व्यवस्था की गई है कि सेनाओं से अधिकारी रूप से बन्धित अस्वस्थ तथा घायल व्यक्तियों का सम्मान, संरक्षण तथा देख-रेख, जातीयता, लिंग, कुल, धर्म अथवा राजनैतिक सम्पत्ति के भेद-भाव को भुला कर करना चाहिए । अनुच्छेद ३६ द्वारा चिकित्सा सम्बन्धी यातायात के रूप में उपयोग किए जाने वाले विमानों को संरक्षण प्रदान किया गया है जब तक वे चिकित्सक वर्ग को तथा चिकित्सा-सम्बन्धी वस्तुओं को ले जाने में तथा घायल और अस्वस्थ के हटाने में लगे हों । यह भी व्यवस्था की गयी है कि पक्षकारों की स्वीकृति से इसकी समाधान है कि घायल तथा अस्वस्थ के संरक्षण के लिए अस्पतालों के क्षेत्र स्थापित किये जाय । अनुच्छेद १५ तथा १६ मृत सिपाहियों से व्यवहार के सम्बन्ध में हैं । उनमें इस बात की अनिवार्य व्यवस्था की गई है कि युद्धरत द्वारा घायल तथा मृत व्यक्तियों के नाम तथा उनके परिचय के सम्बन्ध में परस्पर शीघ्र पत्र-व्यवहार कर लिया जाय तथा रण-क्षेत्र में अथवा मृत व्यक्तियों पर प्राप्ति हुई वस्तुओं को एकत्र कर वापस कर दिया जाय ।

**युद्ध-छल (Ruses of War)** — युद्ध-छल ऐसे युद्ध-भेदिये होते हैं जो कि शत्रु सेना को उसकी कार्यवाही में गलत मार्ग दिखाते हैं । हेग अधिनियम के अनुच्छेद २४ में शत्रु को धोखा देने के लिये शत्रु-छल की निषिद्धि निषिद्ध नहीं कर दी गई है ।

**युद्ध-भेदिये और धोखेबाज (Stratagem and Deceit)** — लरि-स के अनुसार युद्ध भेदिये ऐसे युद्ध-छल हैं जो कि शत्रु के ऊपर प्रयोग किये जाते हैं जिनका उद्देश्य शत्रु को धोखा देना होता है और उन्हें अरक्षित करना होता है । इनका प्रयोग इसलिये होता है कि युद्ध जितना ही शस्त्रों से लड़ा जाता है उतना ही बुद्धि से भी । हेग अधिनियम के अनुच्छेद २४ में शत्रुओं के विषय में आवश्यक सूचना की जानकारी के लिये युद्ध-भेदिया का निषिद्ध किया जाना नियमित माना गया है । ये युद्ध-भेदिये जहाँ तक प्रकट या परोक्ष रूप से युद्ध स्थित राज्यों के कानूनों का उल्लंघन नहीं करते वहाँ तक उनकी निषिद्धि सर्वथा वैध और नियमित है क्योंकि प्रत्येक सेनानायक अपनी सुरक्षा के लिये अपनी बुद्धि और कोशल के अनुसार सतर्क रहना चाहता है ।



## अध्याय ३६

## युद्ध-स्थित के दखल

( *Belligerent Occupation* )

दखल का अर्थ — क्षेत्र को अधिकार में लेने तथा उस पर दखल करने वाले अथवा प्राप्त करने वाले राज्य के नाम से प्रशासन स्थापित करने से दखल पूर्ण हो जाता है। अतः दखल आक्रमण से भिन्न है जो विजय का केवल एक स्थितिमात्र है तथा उसमें सरकार की स्थापना निहित नहीं है। दखल से सार्व-भौमिकता का पूर्ण हस्तान्तरण व्यक्त नहीं होता किन्तु वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत सैनिक प्राधिकार का द्योतक है। सन् १९०७ के चतुर्थ हेग सम्मेलन से सलग्न हेग विनियम का अनुच्छेद ४२ यह घोषित करता है कि एक क्षेत्र दखल में उस समय कहा जाता है जबकि वह वास्तव में विरोधी सेना के प्राधिकार में आ गया हो तथा ऐसा दखल केवल तभी प्रभावपूर्ण होता है जब इसे ऐसे दल का आश्रय प्राप्त हो जो दखल करने वाले के प्राधिकार का स्थायी रखने के लिए पर्याप्त हो। दखल शत्रु के देश पर आक्रमण तथा उसको अधिकार में लेने के उद्देश्य से कब्जा या शक्तिवश में लेना है, चाहे वह अस्थायी रूप से ही बयो न हो।

इसके परिणाम :—जब कोई क्षेत्र शत्रु के हाथ में आ जाता है तो उसके निवासियों की राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ह्यूटन का कथन है कि उनकी (निवासियों की) पूर्व सरकार को सार्वभौमिकता स्थगित हो जाती है और उनकी उससे राजभक्ति उस समय के लिये लुप्त हो जाती है। दखल के बीच वे ऐसी विधियों के अधीन हो जाते हैं जिस प्रकार का विजयी उन पर लगाना चाहे। निवासियों को अपने देश के विरुद्ध भ्रष्ट ग्रहण करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। उसी समय उनके व्यक्तिगत अधिकार तथा उनके एक दूसरे से सम्बन्ध वही रहते हैं जब तक कि वे विजयी द्वारा विशेष रूप से परिवर्तित न कर दिये जायें। मुहठ सैनिक दखल पूर्व सरकार से प्राप्त सार्वभौमिकता के सम्पूर्ण अधिकारों को विजयी को हस्तान्तरित कर देता है। अतः वह पहले की सार्वजनिक सम्पत्ति को जिस प्रकार चाहे उस प्रकार उपयोग कर सकता है, तथा उसके देय करा और उपकारों को स्वयं विनियोग कर सकता है। लेकिन यह स्थिति तभी तक रहती है जिस समय तक दखल रहता है। यदि जिला मून सार्वभौम से पुनः ले लिया जाता है तो फिर उसी पूर्व स्थिति में आ जाता है जिसमें वह लोप होने के पूर्व था। सैनिक दखल के प्रभाव चल तथा भ्रूल सम्पत्ति के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न हैं। यह विजयी को चल सम्पत्ति पर पूर्ण स्वतन्त्राधिकार प्राप्त करने का तथा उसको जिते

चाहे उसे हस्तान्तरित करने का अधिकार देता है, किन्तु इसके द्वारा अचल सम्पत्ति पर उसे केवल सीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। वह दखल के बीच वास्तविक सम्पत्ति का इच्छानुसार उपयोग कर सकता है किन्तु यदि वह उसका विक्रय करे तो खरीदने वाला मूल स्वामी द्वारा निष्कासन किये जाने के खतरे पर उसे लेता है। ऐसी सम्पत्ति पर आक्रमणकारी के अधिकार केवल शान्ति स्थापित होने के उपरान्त ही स्थायी होते हैं। हेग विनियमों के अनुच्छेद ४३ में यह घोषणा की गई है कि दखल करने वाला यथासम्भव सार्वजनिक सुव्यवस्था तथा सुरक्षा पुनः स्थापित करने के लिये समस्त प्रकार के ऐसे प्रयास करेगा जो उसकी शक्ति में हैं, तथा सर्वथा देश में प्रवृत्त विधियाँ का सम्मान करेगा जब तक वह रोका न जायगा। अतः दखल करने वाली शक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वर्तमान स्थानीय विधियों को जहाँ तक वे दखल करने वाले की सुरक्षा के अनुरूप हो, बनाये रखे।

हेग विनियमों द्वारा दखल करने वाले को दखल किये गये क्षेत्र की जनता को विरोधी शक्ति के पक्ष में राजभक्ति की शपथ लेने को बाध्य करने से निषिद्ध किया गया है, किन्तु उसे यह अनुमति दी गई है कि उनसे तटस्थता की शपथ तथा ऐसी शपथ ले कि वह उसी प्रकार से उसकी आज्ञा पालन कर तथा राजभक्ति दिखलाये जैसा वैध सार्वभौम सत्ता को अधिकार था भले ही वह अस्थायी रूप से हो हा। दखल करने वाला दखल किये गये क्षेत्र के निवासियों को बाध्य नहीं कर सकता कि वे उसे अपने सैनिक दलों के सम्बन्ध में सूचना दे।

उपासना के लिए समर्पित संस्थायें (Institutions dedicated to worship) — हेग विनियमों के अनुच्छेद ५६ में यह स्पष्ट रूप से निषिद्ध किया गया है कि सार्वजनिक उपासना, दया, शिक्षा, विज्ञान तथा कला के लिये समर्पित संस्थाओं का अभिग्रहण तथा विनाश न किया जाय। इसी प्रकार ऐतिहासिक स्मारक तथा कला अथवा विज्ञान की वृत्तियाँ भी सुरक्षित करने योग्य हैं। यह भी व्यवस्था की गई है कि धर्म, दया, शिक्षा, कला तथा विज्ञान के लिये समर्पित संस्थाओं की उपजीविका के निमित्त भूतल खाली हुई भूमि से प्राप्त आय उनके लाभकारी प्रयोजनों को हटाकर दखल करने वाली सेना के द्रव्य साधना को बढ़ाने के काम में न लायी जाय।

अचल सम्पत्ति (Immovable Property) — सामान्य नियम के अनुसार अचल सम्पत्ति आक्रमणकारी द्वारा उपयोग किये जाने के अयोग्य मानी गयी है। वे क्षेत्र के साथ बँधी हुई हैं। उनसे उत्पन्न होने वाला लाभ जवन किये जाने से उन्मुक्त है, तथा उनके स्वामी उनके सब प्रकार के विधिपूर्वक उपयोग में

सरक्षित किये जाने चाहिये । (अनुच्छेद ४६) । किन्तु व्यक्तिगत गृहा में सेना क दल रखे जा सकते हैं यद्यपि निवासियों को सिपाहियों के लिए अधिक स्थान प्राप्त करने के हेतु निकाला नहीं जा सकता । तथापि वास्तविक झगड़े की आवश्यकता भाने पर यह न्यायोचित हो सकता है, कि भवनो को विनष्ट कर दिया जाय भयवा उनका दुर्ग के रूप में उपयोग किया जाय । यदि लड़ाई न लड़ने वाले आक्रमणकारी दलों पर अपने रहने के स्थानों में गोली चलावें भयवा उनका उपयोग अन्य प्रभाविकृत विरोध क कार्यों के करने के प्रयोजना के लिये कर, तो युद्ध की विधियाँ युद्धस्थित को जिसकी हानि हुई हो, यह अधिकार देता है कि सम्बन्धित सम्पत्ति को नष्ट करके तथा अपराधियों के विरुद्ध कठोरता का व्यवहार करके दंड दे ।

लड़ाई न लड़ने वालों की चल-सम्पत्ति (Movable Property of Non-Combatants) — दखल किये गये जिलों की लड़ाई न लड़ने वाली जनता की चल-संपत्ति के सम्बन्ध में अनुच्छेद ५३ इसके अभिग्रहण किये जाने से उन्मुक्ति देता है, यदि यह अस्त्र, युद्ध-सामग्री, आदि न हा । ऐसी दशाभा में भी युद्ध समाप्त होने पर उन्हें वापस कर देना चाहिये तथा उनके लिये क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिये ।

सार्वजनिक चल सम्पत्ति (Public Movable Property) — हेग-विनियमों के अनुच्छेद ५३ के वाक्यखंड १ में यह अनुमति दी गई है कि दखल करने वाला राज्य उस राज्य की चल सम्पत्ति का उपयोग करे । व्यक्तिगत सम्पत्ति जो सैनिक प्रयोजनों के लिये उपयोग करने के योग्य है, अनुच्छेद ५३ वाक्यखंड २ के अन्तर्गत अभिग्रहीत की जा सकती है किन्तु जब शान्ति घोषित हो तो इसे वापस कर देना चाहिये और क्षतिपूर्ति निश्चित कर देनी चाहिये ।

व्यक्तिगत सम्पत्ति (Private Property) — व्यक्तिगत सम्पत्ति का सम्मान होना चाहिये । उसे जब्त नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद ४६) । अनुच्छेद ५२ के अन्तर्गत नगरपालिकाओं भयवा निवासियों से द्रव्य तथा सेवाओं की माँग दखल करने वाली सेना की आवश्यकता के अतिरिक्त और किसी स्थिति में नहीं की जा सकती । वे देश के द्रव्य साधनों के अनुरूप होंगे तथा इस प्रकार के होंगे जिसस निवासी इस बात के लिए बाध्य न हो कि उन्हें अपने देश के ही विरुद्ध सैनिक दखल में भाग लेना पड़े ।

व्यक्तिगत सम्पत्ति की लूट पूर्ण रूप से निषिद्ध है किन्तु आक्रमणकारी दखल किये गये क्षेत्र में पाई गई तटस्थ की सम्पत्ति को उचित क्षतिपूर्ति देने पर उपयोग कर सकता है ।

**युद्ध-कार्य (Operations of War):**—हेग विनियमा के अनुच्छेद ५२ में दखल करने वाले को यह निषेध है कि वह विरोधी पक्ष के जातियों को अपने ही देश के विरुद्ध संचालित कार्यों में भाग लेने के लिये बाध्य करे और यह प्रतिबन्ध उस दशा में भी सामान्यतः लागू है जब वे उसकी सेवा में युद्ध आरम्भ होने से पूर्व से रहे हों। लड़ाई न लड़ने वाले निवासियों को कोई सैनिक प्रकार की सेवा करने को बाध्य किया जा सकता है। लड़ाई न लड़ने वालों का मृत्युदण्ड के अन्तर्गत यह निषिद्ध किया गया है कि वे दखल करने वाले के विरुद्ध कोई विरोध का कार्य न करें जैसे शत्रु को सूचना देना, आदि।

**सामूहिक दण्ड (Collective Penalty)**—अनुच्छेद ५० में यह निर्धारित किया गया है कि निवासियों पर वैयक्तिक कार्यों के लिये, जिनके लिये वे सामूहिक प्रकार से उत्तरदायी नहीं समझे जा सकते, घन का अपराध अन्य प्रकार का सामूहिक दण्ड नहीं दिया जा सकता। जर्मनी द्वारा इस नियम का भंग सन् १९१४-१८ के महायुद्ध तथा १९३९-४५ के विश्वयुद्ध में किया गया, जब उसके द्वारा अनेक मामलों में दखल किये गये क्षेत्र के निवासियों को सामूहिक रूप से दण्डित किया गया।

**न्यायालय (Courts):**—न्याय-वितरण के सम्बन्ध में यह है कि सैनिक दखल के बीच व्यवहार न्यायालय पूर्व विधियों के अनुसार कार्य करते रहते हैं लेकिन दण्ड न्याय विधि तथा प्रक्रिया में परिवर्तन हो सकते हैं। अनुच्छेद ४३ में यह व्यवस्था की गई है कि दखल करने वाले को यदि उसके मार्ग में बाधा न हो, तो देश में प्रवृत्त विधियों का सम्मान करना चाहिये, लेकिन वह सामान्य न्यायालयों के स्थान में सैनिक न्यायालय स्थापित कर सकता है। न्यायालय दखल करने वाली शक्ति के नाम पर निर्णय न देकर न्यायपूर्वक स्थापित सरकार के नाम पर निर्णय देते हैं, लेकिन दखल करने वाला उनको न्यायपूर्वक स्थापित सरकार के नाम में निर्णय देने से रोक सकता है। उस दशा में जैसा कि ब्रिटेनशली का सुझाव है, न्यायालय एक तटस्थ नियम का अवलम्बन कर सकते हैं तथा निर्णयों को “विधि के नाम में” (“In the name of the law”) दे सकते हैं।

**अधिग्रहण, अंशदान तथा अर्थ दण्ड (Requisitions, Contributions and Fine)**—अधिग्रहण दैनिक उपभोग की वे वस्तुएँ हैं जो दखल करने वाली सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सभरण की जाय तथा दखल किये गये प्रदेश के निवासियों से माँगी जाय। हेग विनियम अधिग्रहण के लिये वहाँ तक अनुमति देते हैं जहाँ तक कि वे दखल करने वाली सेना की आवश्यकताओं के लिये

अपेक्षित हो तथा देश के साधनों के अनुरूप हो। वे दखल किये गये क्षेत्र में केवल समादेशक के ही अधिकार से माँगे जा सकते हैं।

अशदान वह धनराशि है जो सामान्य करो के अतिरिक्त एकत्र की जाय। वह समादेश देने वाले जनरल के उत्तरदायित्व पर उसके लिखित आदेश के अन्तर्गत एकत्र किया जा सकता है, तथा सेना की आवश्यकताओं के लिये तथा दखल किये गये क्षेत्र के प्रशासन के व्यय की पूर्ति के लिये लगाया जा सकता है। अशदान केवल उसी दशा में अनुज्ञेय है जब करो से प्रायः कम हो तथा प्रशासन के व्यय की पूर्ति के लिये अपर्याप्त हो, किन्तु सेना की आवश्यकताओं के लिये उनको लगाने की आवश्यकता न्यायविरुद्ध माँग की एक नयी स्थिति उत्पन्न कर देती है। चन्दा देने वालों को रसीद दी जानी चाहिये, यद्यपि वापसी के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

अर्धदण्ड किसी जिले पर लगाई गई वह शास्ति है जो उसके निवासियों द्वारा प्राक्रमणकारियों के विरुद्ध किये गये किसी कार्य के लिए लगाई जाय। हेग विनियमों के अनुच्छेद ५० में जैसा ऊपर व्यक्त किया गया है यह घोषित किया गया है कि कोई सामान्य शास्ति द्रव्य अथवा अन्य प्रकार की, जनता पर उन कार्यों के लिये नहीं लगायी जा सकती, जो व्यक्तियों द्वारा किये गये हो तथा जिनके लिये उनको सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं समझा जा सकता।

सन् १९४९ का जेनेवा अभिसमय (Geneva Convention, 1949)—जर्मनी द्वारा युद्धस्थित दखल करने वाले के रूप में दखल किये गये क्षेत्र की नागरिक जनता पर द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्य किये गये निर्मम क्रूरता के कार्यों के कारण यह आवश्यक हो गया कि हेग विनियमों का पुनरोक्षण किया जाय तथा सन् १९४९ के जेनेवा अभिसमय को अंगीकृत किया जाय। ४७ से ७८ तक अनुच्छेद जो युद्ध के समय में नागरिक व्यक्तियों के संरक्षण के सम्बन्ध में हैं केवल दखल किये गये क्षेत्र के विषय में हैं तथा वर्तमान अनुबन्धों के उद्घोषणात्मक हैं यद्यपि कुछ विषयों में वे हेग विनियमों के सम्बन्धों के बाहर चल गये हैं।

अनुच्छेद ४९ के अन्तर्गत वैयक्तिक अथवा सामूहिक अन्तरण तथा संरक्षित व्यक्तियों का दखल किये गये क्षेत्र से दखल करने वाली शक्ति क क्षेत्र अथवा किसी अन्य क्षेत्र को निवालेना निषिद्ध किया गया है।

अभिसमय में यह निषिद्ध किया गया है कि दखल करने वाली शक्ति दखल किये गये क्षेत्र के निवासियों का यह बाध्य करे कि उसक सैनिक अथवा सहायक दत्ता में कार्य करें। किसी प्रकार के ऐसे दबाव अथवा प्रचार की अनुमति नहीं है जिसका उद्देश्य ऐच्छिक भर्ती कराना हो।

दखल करने वाली शक्ति दखल किये गये क्षेत्रों में सार्वजनिक पदाधिकारियों अथवा न्यायाधीशों की स्थिति बदल नहीं सकती (अनुच्छेद ५४) ।

राज्य के व्यक्तियों अथवा अन्य सार्वजनिक अधिकारियों की वास्तविक अथवा व्यक्तिगत सम्पत्ति का विनाश केवल उस दशा को छोड़कर जबकि ऐसा विनाश सैनिक कार्यों के लिये नितान्त आवश्यक हो गया हो, पूर्णतया निषिद्ध है । (अनुच्छेद ५३) ।

दखल किये गये क्षेत्र की दह-विधियाँ इस अपवाद के साथ प्रवर्तित रहेंगी कि उनको दखल करने वाली शक्ति द्वारा उन्हें निरसित तथा स्थगित उन दशाओं में किया जा सकता है जब वे उसकी सुरक्षा के लिये एक घमकी बन जाती हैं । दखल करने वाली शक्ति द्वारा बनाई गई दह-व्यवस्था उसके प्रकाशित किये जाने तथा निवासियों को उन्हीं की भाषा में परिचित कराने के पूर्व प्रवर्तित नहीं होगी । (अनुच्छेद ६४-६५) ।

दखल करने वाली शक्ति द्वारा मृत्युदण्ड नागरिक निवासी को केवल उन्हीं दशाओं में दिया जा सकता है जब वह व्यक्ति जासूसी कार्यों के करने दखल करने वाली शक्ति के सैनिक प्रतिष्ठापनों को तोड़-फोड़ करने के गम्भीर कार्यों अथवा इच्छापूर्वक ऐसे अपराधों का करने का दोषी हो जिनसे एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाय, किन्तु अनुबन्ध यह है कि दखल के आरम्भ होने के पूर्व ऐसे अपराध दखल करने वाले प्रदेश की विधि के अन्तर्गत मृत्युदण्ड द्वारा दण्डनीय हों ।

संरक्षित व्यक्ति दखल करने वाली शक्ति द्वारा दखल के पूर्व किये गये कार्यों अथवा प्रकट की गई सम्मतियों के लिये पकड़े, अभियोजित अथवा सिद्ध-दोष इस अपवाद के साथ नहीं होंगे कि युद्ध की विधियों तथा रूढ़ियों का उल्लंघन न हुआ हो । (अनुच्छेद ७०) । अनुच्छेद ५५ में दखल करने वाली शक्ति पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह जनता के लिये भोजन तथा औषधि का सामान पहुँचाने का निश्चित प्रबन्ध करे ।

## अध्याय ४०

### समुद्री युद्ध की विधियाँ

#### ( Laws of Maritime Warfare )

उद्देश्य :—समुद्री युद्ध का उद्देश्य शत्रु को उन यातायात के साधनों से वंचित करना है जो समुद्र अनधिकृत सम्पत्ति के रूप में प्रत्येक राष्ट्र को देने हैं और शत्रु के

समुद्री बेड़े को पराजित करना तथा उसके व्यापारिक बेड़े का भूलोच्छेदन करना है। भूमियुद्ध के असदृश समुद्रीय युद्ध में यह अनुमति प्राप्त है कि शत्रु के जहाजों में प्राप्त व्यक्तिगत सम्पत्ति, अतटस्थ सेवाओं में लगा हुआ तटस्थों का माल तथा उनके जहाज तथा शत्रु का सम्पूर्ण माल जो समुद्र पर हो यदि तटस्थ भेड़े से संरक्षित न हो तो ग्रहण कर लिया जाय।

रुडियो के अतिरिक्त समुद्री युद्ध विधियाँ मुख्यतः सन् १८५६ की पेरिस की घोषणा में तथा सन् १९०७ के पष्ठ हेग अभिसमय में समावेशित हैं जिसका निर्देश पूर्व पृष्ठों में किया गया है।

पेरिस की घोषणा (Declaration of Paris) :— पेरिस की घोषणा ने निम्नलिखित चार सिद्धान्तों को सूचित किया :—

(१) निजी जहाजों द्वारा शत्रु के जहाजों को लूटे जाने के प्राधिकरण (Privateering) का उन्मूलन कर दिया जाता है।

(२) तटस्थ भेड़े से शत्रु के माल की रक्षा होती है युद्ध में विनिपिद्ध वस्तुओं को छोड़कर।

(३) तटस्थों का माल युद्ध में विनिपिद्ध वस्तुओं को छोड़कर शत्रु के भएड़े के नीचे ग्रहण करने योग्य नहीं है।

(४) नाकेबन्दी वास्तविक तथा बाध्यकारी होने के निमित्त प्रभावपूर्ण होनी चाहिये।

शत्रु के सार्वजनिक तथा वैयक्तिक-पोत पर आक्रमण (Attack on Public and Private Vessels of the Enemy):—सामान्य नियम के रूप में शत्रु के सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जहाजों पर उसी के बन्दरगाहों तथा जल में, आक्रमणकारी शक्ति के बन्दरगाहों तथा जल में तथा छुने हुए समुद्रों में आक्रमण किया जा सकता है लेकिन तटस्थ तथा तटस्थीकृत बन्दरगाहों तथा जल में नहीं। किन्तु सामान्य नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं :—

अपवाद :—

१. अस्पताली जहाज (Hospital Ships).—सन् १८६६ तथा १९०७ के हेग अभिसमय द्वारा उनको पकड़े जाने से इस आचार पर उन्मुक्त दी गई कि वे उदारता तथा परोपकार के कार्य करते हैं। ऐसे अस्पताली जहाज सफेद रंग के होने चाहिए तथा उनमें जेनेवा का झंडा लगा रहना चाहिए। यह बात स्वीकृत की गई कि अस्पताली जहाज लड़ाई लड़ने वालों की गतिविधि में बाधा न डालें।

२. वे जहाज जो धार्मिक, वैज्ञानिक अथवा सार्वजनिक उपकार के कार्यों में लगे हों, वे भी सन् १९०७ की ग्यारहवीं हेग अभिसमय के अनुच्छेद ४ के अन्तर्गत पकड़े जाने से उन्मुक्त हैं।

३. कार्टेल जहाज ( Cartel Ships ) .—यह वे जहाज हैं जो बन्दियों के विनिमय कार्य में लगे रहते हैं तथा युद्धस्थित शक्ति द्वारा अभिग्रहीत करने से उन्मुक्त हैं ।

४. मछली मारने वाले जहाज तथा बाजारी नावे (Fishing Smacks and Market Boats) —ये छोटे-छोटे जहाज किनारे पर मछली पकड़ने अथवा स्थानीय व्यापार में लगे रहने के कारण युद्धस्थित शक्तियों द्वारा अभिग्रहीत करने से उन्मुक्त हैं, लेकिन यदि वे युद्ध के कार्यों में भाग ले ता उन पर यह उन्मुक्ति लागू नहीं होती ।

५. शत्रु के जहाज लाइसेन्सो द्वारा सरक्षित हो, अभिग्रहीत करने से तब तक उन्मुक्त रहते हैं जब तक वे लाइसेन्स में दी हुई शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुसार नाव चलाते अथवा व्यापार करते हैं ।

६. सन् १९०७ के छठे हेग अभिसमय ने तीन प्रकार के व्यापारी जहाजों का एक श्रेणी तथा सीमित प्रकार की उन्मुक्ति प्रदान की —

(अ) जो युद्ध के आरम्भ में शत्रु के बन्दरगाह में पाय जाय ।

(आ) जो ऐसे बन्दरगाह में लड़ाई छिड़ने से अनभिज्ञ होकर प्रवेश करे तथा जिन्होंने अपने प्रस्थान के अनन्तर बन्दरगाह को तब छोड़ा हा जब शान्ति रही हो ।

(इ) जिनसे खुले समुद्र पर उसी अनभिज्ञता का दशा में मुठभेड़ हा तथा जो अन्तिम बन्दरगाह से जिसमें कि वे पहले पहुँचे हो युद्ध आरम्भ होने के पूर्व बच दिये हो ।

अभिसमय द्वारा युद्धस्थित को यह अनुमति दी गई थी कि वह किसी व्यापारी जहाज को क्षतिपूर्ति दिये बिना रोक रखें, किन्तु इस उत्तरदायित्व के साथ कि युद्ध के उपरान्त इसे वापस कर दें । युद्धस्थित क्षतिपूर्ति देकर जहाज को अधि-याचित भी कर सकता था । उन जहाजों के सम्बन्ध में जिन्होंने युद्ध आरम्भ होने के पूर्व बन्दरगाह छोड़ दिया था, तथा जिनसे उसी अज्ञानता की दशा में खुले समुद्र में मुठभेड़ हुई हो, उनको इस विफल के साथ विनष्ट करने दिया जाता था कि उसके बदले में क्षतिपूर्ति दी जाय तथा जहाज के कागजों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाय ।

प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्धों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस अभिसमय का सश्रमान सम्मान किया गया तथा युद्ध संहिता के उपरान्त उनसे बन्दरगाहों में तथा खुले समुद्र में पाय गये जहाजों को स्थानबद्ध तथा पकड़ लिया गया और उसको बिना क्षतिपूर्ति दिये चलाया गया ।



शत्रु की सेना में संलग्न तटस्थ व्यापारी जहाज (Neutral Merchant Ships in Enemy Service) :—सन् १९०६ की सन्धन की घोषणा में जो स्थापित नहीं की गई यह व्यवस्था की गई है कि “तटस्थ जहाज उस समय दोषी ठहराया जायगा तथा सामान्य रीति में उससे निम्नलिखित दशाओं में वही व्यवहार किया जायगा जैसा उससे शत्रु का व्यापारी जहाज होने पर किया जाता, यदि वह —

(१) युद्ध में प्रत्यक्ष भाग लेता ।

(२) किसी अभिक्ता के आदेशों के अधीन अथवा नियन्त्रण में हो जो जहाज पर शत्रु की सरकार द्वारा रखा गया हो ।

(३) शत्रु के सरकार की अन्य सेवा में हो ।

(४) उस समय अनन्यरूपेण या तो शत्रु की सेनाओं को ले जाने में लगा हो अथवा शत्रु के हित में सूचना देने के कार्य में व्यस्त हो (अनुच्छेद ४६) ।”

तटस्थ व्यापारी जहाज शत्रु के पथरक्षक जहाजों के साथ (Neutral Merchant Ships in Enemy Convoy) :—जर्मनी तथा ग्रीस के, मिश्रित विवाचक व्यापारिकरण ने *Kyriakides v Germany* (1928) [8 M. A. T. (1929) p. 350] में कथन किया है कि केवल वही तथ्य कि व्यापारी जहाज ने अपने को शत्रु की नौसेना के संरक्षण में रख लिया है तथा इसने यात्रा एक या कई युद्धपोतों के साथ की इस बात के लिये पर्याप्त है कि उसे शत्रु के युद्धपोतों में मान लिया जाय और उससे शत्रुत्व व्यवहार किये जाय ।

तटीय नगरों पर बम बरसाना (Bombardment of Coast Towns) :—युद्ध के समय में नौसेना द्वारा बम बरसाये जाने के सम्बन्ध में इस विषय में एक अभिसमय सन् १९०७ के द्वितीय हेग सम्मेलन द्वारा अंगीकृत किया गया । अनुच्छेद १ में यह नियम बनाया गया कि बन्दरगाहों, नगरों, ग्रामों, निवासस्थानों अथवा अन्य भवनों पर नौसेना द्वारा बम बरसाया जाना किसी भी परिस्थिति तथा दशा में निषिद्ध है तथा किसी भी स्थान पर बम केवल इन कारण नहीं बरसाया जा सकता कि स्वसंचालित सम्पर्क स्थापित करने वाली सुरंगे बन्दरगाह से हट कर बिछाई हुई हैं । अनुच्छेद २ में यह अनुबन्धित है कि अरक्षित स्थानों के विषय में भी सैनिक अथवा नौसेना के संस्थापन, शस्त्र अथवा युद्ध सामग्री के भागार, कारखाने अथवा अन्य जिनका युद्धकार्य में उपयोग किया जा सके, तथा बन्दरगाह में खड़े युद्धपोतों पर भी बम बरसाये जा सकते हैं यदि स्थानों अधिकारीवर्ग सूचना दिये जाने पर भी उनको विनष्ट करने में असमर्थ रहे । युद्धस्थित को यथासम्भव सार्वजनिक उपस्थान, कला, विज्ञान, अथवा उपकारके हेतु समर्पित सदनों को भी छोड़

देना था जिनको कि निर्धारित दृष्टिगत चिन्हों से लक्षित किया गया था। अभिसमय संरक्षित बन्दरगाह अथवा नगर को परिभाषित करने में असमर्थ रहा जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों विश्वयुद्धों में प्रतिज्ञा का पालन केवल उसके उल्लंघन में ही हुआ।

**सुरंगों ( Mines ) :—**सन् १९०७ के हेग सम्मेलन के अभिसमय ८ द्वारा बिना लगर डाली हुई सम्पर्क स्थापित करने वाली सुरंगों का बिछाना निषिद्ध किया गया जब तक उनकी बनावट ऐसी न हो कि वे उनका नियन्त्रण समाप्त होने के एक घंटे भीतर हानिकारक न रह जाय। इसके द्वारा लगर डाली हुई सम्पर्क वाली ऐसी सुरंगों का बिछाना भी निषिद्ध किया गया जो अपने निर्धारित स्थान से छूटने पर निर्दोष न हो जाय तथा ऐसे टारपीडो का उपयोग भी निषिद्ध किया गया जो अपने लक्ष्य को छूकने पर निर्दोष न हो जाय। इसके द्वारा यह भी निषिद्ध किया गया कि शत्रु के तटों तथा बन्दरगाहों से दूर सम्पर्क स्थापित करने वाली सुरंगों व्यापारिक नौवासन में बाधा डालने के लिये न बिछाई जाय।

**पनडुब्बियाँ ( Submarines ) :—**प्रथम महायुद्ध के छिड़ने पर जर्मन पनडुब्बियों ने व्यापारिक जहाज, युद्धपोत तथा तटस्थ जहाजों का विनाश किया क्योंकि पनडुब्बियाँ अपनी प्रकृति से ही नाविक युद्ध की परम्परागत विधियों का अनुसरण नहीं कर सकती थी। पनडुब्बियाँ टारपीडो द्वारा प्रभावशाली कार्यवाहियाँ करती हैं। यद्यपि उनके लिये यह सर्वथा उचित है कि शत्रु के युद्धपोतों को बिना कोई सूचना दिये डुबा दें, तथा शत्रु के व्यापारिक जहाजों पर जाकर उनकी तलाशी ले तथा उनको पकड़ें लेकिन उनका प्रमुख दोष प्रोफेसर होल के कथनानुसार यह है कि वे जिन जहाजों को डुबाती हैं उन पर स्थित व्यक्तियों की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं तथा किसी-किसी समय उस जहाज को पहिचानने में भी असमर्थ रहती हैं जिस पर वे आक्रमण करती हैं।

सशस्त्र व्यापारिक जहाजों के सम्बन्ध में जर्मनी द्वारा यह तर्क दिया गया कि वे बिना किसी चेतावनी के डुबाये जा सकते हैं क्योंकि कोई चेतावनी अथवा पूर्व-सूचना पनडुब्बियों को स्वयं गम्भीर आपत्ति में डाल देगी। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटेन की नौसना ने अपने पदाधिकारियाँ अथवा व्यापारिक जहाजों को पनडुब्बियों पर देखते ही आक्रमण करने का आदेश दिया था अतः कोई चेतावनी देने का अवसर ही नहीं आता। यह विषय यहाँ तक बढ़ा कि ७ मई १९१५ को 'लुसिटानिया', ब्रिटेन का घटलाटिक में चलने वाला एक जहाज, जर्मन टारपीडो द्वारा डुबो दिया गया। उस पर प्रायः २००० यात्री यात्रा कर रहे थे जिनमें से अधिकांश अमेरिका वाले थे। यह तत्काल हुआ गया तथा लगभग

१,२०० व्यक्ति प्राणों से हाथ धोये। अमेरिका ने, जो उस समय तक तटस्थ था, जर्मनी से कठोर शब्दों में इसका विरोध प्रकट किया। जर्मन सरकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि 'लूसिटानिया' एक सामान्य निःशस्त्र व्यापारी जहाज नहीं था वरन् वह एक सहायक सैनिक जहाज था, जिसका नाम ब्रिटिश नौसेना विभाग द्वारा प्रकाशित नौसेना की सूची में सम्मिलित था तथा यह अपनी पिछली यात्राओं में मित्रराष्ट्रों की सहायता के लिये केनाडा की सेना, शस्त्र और गाला-बारूद ले गया था। मित्रराष्ट्रों द्वारा दिये गये इस तर्क के सम्बन्ध में कि सन् १९०६ की लन्दन-घोषणा में यह अनुबन्धित किया गया है कि किसी जहाज को बिनष्ट करने के पूर्व जहाज पर के व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये, जर्मनी ने यह उत्तर दिया कि सामुद्रिक युद्ध के पूर्वकालीन नियम पनडुब्बियों के प्रकट हो जाने से भ्रम उत्पन्न हो गये हैं तथा ऐसी दशा में जबकि परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई हैं, उनसे लड़ाई न लड़ने वाले लोगों तथा यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व नहीं लिया जा सकता।

सन् १९२१ तथा १९२२ के शस्त्रों को परिसीमित करने के वांशिंगटन सम्मेलन में पनडुब्बियों के सम्बन्ध में नियम निर्धारित करने के प्रयास किये गये। सम्मेलन ने यह निर्णय किया कि समुद्री लड़ाई के वर्तमान नियम पनडुब्बियों पर भी लागू हैं तथा वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के संस्थापित भाग माने गये। सन् १९१४-१८ के मध्य जर्मन पनडुब्बियों द्वारा दिखलाये गये पराक्रम के विरुद्ध इसमें एक सामान्य प्रतिक्रिया प्रकट की गई। यह भी निर्णय किया गया कि यदि कोई पनडुब्बी इन नियमों के अनुरूप कार्य न कर सके, तो इसको व्यापारिक जहाज पर आक्रमण नहीं करना चाहिये। वह संधि जिसमें ये घोषणायें थीं, राज्यों द्वारा स्थापित नहीं की जा सकी क्योंकि पनडुब्बियों के लिये युद्ध की विधियों के अनुरूप कार्य करना असम्भव था। नौसेना के शस्त्रों को परिसीमित तथा घटाने के सम्बन्ध में किये गये सन् १९३० के लन्दन के सम्मेलन में इसके पूर्व के वांशिंगटन सम्मेलन में निर्धारित किये गये नियमों की पुनरुक्ति की गई। ये ही नियम सन् १९३६ के लन्दन पनडुब्बी नियमों में प्रसरण समावेशित किये गये। सन् १९३६ तक ३६ राज्य इस मूललिपि के पक्ष कार हो गये थे। इन सब के होते हुये द्वितीय महायुद्ध में पनडुब्बियों के सम्बन्ध में प्रायः कोई बन्धनकारी नियम नहीं देखे गये। नाजियों के संपूर्ण युद्ध की विचार धारा ने युद्ध सम्बन्धी सब नियमों को एक प्रहसन बना दिया। सभी वस्तुयुद्ध की सबसे अधिक आवश्यकता के अधीनस्थ हो गई। खुले समुद्र में नाविकों की अपेक्षा न करते हुए व्यापारिक जहाजों को डुबाना, चाहे वे शस्त्र युक्त हो अथवा निःशस्त्र, एक 'दनचर्या' हो गई।

**डाक द्वारा पत्र-व्यवहार (Postal Correspondence)** — सन् १९०७ के ग्यारहवें हेग अभिसमय द्वारा शत्रु का डाक द्वारा पत्र व्यवहार अनुल्लंघनीय माना गया, यद्यपि यह उन्मुक्ति-पत्र ले जाने वाले जहाजों के लिए लागू नहीं थी। नाके-बन्दी बन्दरगाह से यद्यपि वहाँ के लिये निर्देशित पत्र व्यवहार पकड़े जाने से उन्मुक्त नहीं की गयी। यदि जहाज रोके गये तो यह नियम बनाया गया कि पकड़ने वालों द्वारा पत्रादि यथासंभव शीघ्र भेज देना चाहिये। हेग अभिसमय के अन्तर्गत डाक द्वारा भेजे गये पार्सलों को उन्मुक्ति नहीं प्रदान की गई थी।

**शत्रु के जहाजों को पकड़ने वाले जहाज (Privateers).** — ये वे जहाज हैं जो व्यक्तिगत स्वामियों के हैं, जिनको युद्धकाल में राज्य की ओर से एक कमिशन दिया जाता है कि जो 'विशिष्ट पत्र' के नाम से पुकारा जाता है। इससे उनको यह प्राधिकार दिया जाता है कि शत्रु के विरुद्ध युद्ध कर, उनके जहाजों और संपत्ति को पकड़े तथा उसके व्यापार को विनष्ट कर। सन् १८५६ की पैरिस घोषणा के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि "यह प्रथा समाप्त हो रहेगी।"

**समुद्री युद्ध में छल (Ruses in Sea Warfare)** — जिस प्रकार स्थल-युद्ध में छल एक निश्चित सीमा तक मान्य है, उसी प्रकार समुद्री युद्ध में भी एक निश्चित सीमा तक छल ग्राह्य माना जाता है। युद्ध-स्थित व्यक्ति द्वारा यदि गलत झूठे का प्रयोग शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, तो उस समय निषेधित माना जाता है, जब कि वह किसी शत्रु-पोत का पीछा कर रहा हो या भागने के प्रयत्न में हो। शत्रु-पोत को कार्य-रत करने के उद्देश्य से यदि तटस्थ भयवा शत्रु के झूठे का प्रयोग किया जाता है, तो वह भी अवैध नहीं माना जाता, किन्तु यदि उसे आक्रमण करना है, तो आक्रमण के पूर्व अवश्य अपना राष्ट्रिय झंडा लगा लेना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन क्रूजर 'येम्डेन' (Emden) ने जापानी झंडा लगाकर अपने का छद्म बना लिया था। वह मलाया राज्य में पेनांग बन्दरगाह पार कर गया था। उसने रूसी क्रूजर 'झेमशुग' (Zhemshug) को सामने पाकर जापानी झंडा का नीचे झुका दिया और जर्मन झंडा का लहरा दिया, तथा गोली चलाना शुरू करके टारपोटो से उस क्रूजर को गिरा दिया।

सन् १९४९ का जेनेवा अभिसमय (Geneva Convention, 1949) — सन् १९४९ के जेनेवा अभिसमय में समुद्री सेना के घावला, अस्त्रधारी तथा हथियार जहाजों के सैनिकों की दशा सुधारने की व्यवस्था विस्तृत रूप से की गई है। अनुच्छेद १२ में यह व्यवस्था की गई है कि सैनिक दला के सदस्य तथा अन्य व्यक्ति जो उनमें सम्मिलित कर लिये गये हों तथा जो समुद्र में हों और जिनका जहाज हूँ

गया हो उनका सम्मान करना चाहिये तथा उनकी प्रत्येक परिस्थिति में रक्षा होनी चाहिये ।

युद्धस्थित के सब युद्धपोतों को यह अधिकार होगा कि वे घायल, अस्वस्थ अथवा जहाज में डूबे हुए व्यक्तियों का जो सैनिक अस्पताली जहाजों पर हो तथा सहायता समिति के अथवा व्यक्तिगतजनो के अस्पताली जहाजों का प्रत्यर्पण मंगे, लेकिन अनुबन्ध यह है कि घायल तथा अस्वस्थ ऐसी दशा में हो कि वे हटाये जा सकें तथा युद्धपोतों में आवश्यक चिकित्सा के लिये पर्याप्त सुविधायें प्रदान की जा सकें । (अनुच्छेद १४)

यदि घायल अस्वस्थ अथवा डूबे हुए जहाज के व्यक्ति एक सदस्य युद्धपोत पर अथवा तटस्थ सैनिक हवाई जहाज पर ले लिये जाय और यदि अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा ऐसा अपेक्षित हो कि वे युद्ध के कार्यों में और अधिक भाग न ले सकें तो इस बात की निश्चित व्यवस्था कर दी जायगी । (अनुच्छेद १५)

अस्पताली जहाज (Hospital Ships) — सैनिक अस्पताली जहाज प्रत्येक दशा में आक्रमण किये जाने तथा पकड़े जाने से उन्मुक्त हैं, किन्तु अनुबन्ध यह है कि उनके नाम तथा विवरण भगड़े के पक्षकारों को उनके उपयोग में लाये जाने के दस दिन पूर्व अधिसूचित कर दिये गये हों । (अनुच्छेद २२) राष्ट्रीय रेडक्रास समितियों अथवा अन्य सहायता समितियों को सैनिक अस्पताली जहाजों के समान संरक्षण मिलेगा तथा वे पकड़े जाने से उन्मुक्त रहेंगे, अनुबन्ध यह है कि उनको अपने राज्य से एक सरकारी कमीशन प्राप्त हो । (अनुच्छेद २४) । अस्पताली जहाज किसी भी दशा में किसी सैनिक प्रयोजन के लिये उपयोग में नहीं लाये जाएंगे और न ऐसे जहाज लड़ाई लड़ने वालों की गति-विधि में बाधा डालेंगे । (अनुच्छेद ३०) । अस्पताली जहाजों के अधिकार में अपने बायरलेस के लिये कोई युत कोड अथवा सूचना भेजने का अथ साधन नहीं होना चाहिये तथा न उसका उपयोग होना चाहिये । [अनुच्छेद ३४ (२)] । अभिसमय भगड़े के पक्षकारों को यह अधिकार देता है कि उपर्युक्त कर्तव्यों के पालन को निश्चित करने के लिये अस्पताली जहाजों पर नियन्त्रण रखे तथा उनकी तलाशी ले । यह संरक्षण जिसके कि अस्पताली जहाज अधिकारी हैं उस समय समाप्त हो जायेंगे जब वे अपने उदारता के कर्तव्यों से परे ऐसे कर्तव्य करें जो शत्रु के लिए हानिकर हों (अनुच्छेद ३४) ।

वर्मचारी वर्ग (Personnel) — अस्पताली जहाजों के धार्मिक, चिकित्सा तथा अस्पताल सम्बन्धी वर्मचारी वर्ग का तथा उसके नाविकों का सम्मान होना चाहिये तथा उन्हें संरक्षण मिलना चाहिये । उनको उस समय नहीं पकड़ना चाहिये जब वे अस्पताली जहाज की सेवा में हों, चाहे अस्वस्थ तथा घायल जहाज पर हो

अथवा नहीं। यदि वे दानु के हाथों में पड़ जाय तो उनका सम्मान तथा संरक्षण होना चाहिये तथा उनको अपने वर्तव्यों को सब तक बरते रहने देना चाहिए जब तक कि मायसो तथा अस्वस्थों के लिये आवश्यक हो।

## अध्याय ४१ नीजितमाल न्यायालय (Prize Courts)

नीजितमाल का अर्थ :—यन्त्रु की सम्पत्ति जो शत्रु समुद्र में पकड़ी जाय समुद्री लूट या नीजितमाल (prize) कहलाती है। यह 'लूट' (booty) से भिन्न है जो दानु की उस सम्पत्ति के लिये प्रयोग की जाती है जो भूमि पर प्राप्त की गई हो। नीजितमाल के लिये स्वस्थ वैवल सभी प्राप्त होता है जब यह एक सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी ठहराई गई हो तथा जब तक यह निर्णय न हो जाय सम्पत्ति का अधि-कारी एक वैध ऋण सम्पत्ति की दशा में रहता है।

यदि बलात् अभिग्रहण किये जाने योग्य दानु की सम्पत्ति समुद्र में पकड़ी जाय तो मूल स्वामी के अधिकार विनिष्ट हो जाते हैं किन्तु कभी-कभी यह संदेहपूर्ण रह जाता है कि क्या कोई सम्पत्ति वास्तव में किसी दानु के स्वत्व की है, या नहीं अथवा अभिग्रहण ऐसे स्थान पर किया गया जहाँ युद्ध सदृश कार्य किये जाय, तथा यह सर्वदा आवश्यक है कि व्यक्तिगत अभिग्रहण करने वालों को उत्पन्न होने वाले स्ववाधिकारों की ठीक-ठीक सीमा निर्दिष्ट की जाय। अतः किसी न्यायालय का हस्तक्षेप उस दशा में भी अत्यंत ही वांछनीय है जब युद्धस्थित की सम्पत्ति ही केवल सम्बन्धित विषय हो। वांछनीयता उस दशा में आवश्यक हो जाती है जब तटस्थों के अधिकार तथा दावे सम्बद्ध हों। अतः सभी सम्बन्धित युद्धस्थित नीजित सम्बन्धी न्याया-लयों को तटस्थों के प्रजाजनो के संरक्षण तथा अभिग्रहण करने वालों के दावा के उचित समीकरण के लिये स्थापित करते हैं।

परिभाषा.—लारेन्स ने 'नीजितमाल न्यायालय' (prize courts) की परिभाषा इस प्रकार की है कि ये युद्धस्थित राज्यों द्वारा अपने प्रदेश में, अपने सैनिक दल के अग्रिम क्षेत्र में अथवा उसमें जो युद्ध में मित्र राष्ट्र की सम्पत्ति हो, अपने युद्धपोतों द्वारा अभिग्रहीत सम्पत्ति की वैधता निर्णय करने के लिये स्थापित नागरिक न्यायाधिकरण हैं। अन्तिम दशा में मित्रराष्ट्र की अनुमति पहले प्राप्त कर लेनी चाहिये। (Lawrence : The Principles of International Law, p. 460).

नोजितमाल न्यायालयो के कृत्य सक्षेप मे निम्नलिखित हैं :—

(१) समुद्रीय अभिग्रहण के मामलो मे जाँच ।

(२) जहाँ अभिग्रहीत सम्पत्ति वैध नोजितमाल सिद्ध हो दण्ड की डिगरी पारित करना ।

(३) जहाँ यह सिद्ध न हो तो असली मालिक को वस्तु न्यायोचित क्षतिपूर्ति सहित दे देना ।

(४) भ्रानुपगिक रूप से सब के हितो को छूट तथा अव्यवस्था से सरक्षण प्रदान करना । (Pitt Cobbett's Leading Cases, Vol. II, Ed. V. p. 258 ).

**क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) :—**नोजितमाल न्यायालय का क्षेत्राधिकार इसके युद्धपोतो द्वारा युद्ध के बीच खुले समुद्र पर किये गये अभिग्रहणो पर, इसके नौसेना द्वारा भूमि पर किये गये अभिग्रहणो पर तथा बन्दी को मुक्त करने के लिये धन और क्षतिपूर्ति के अन्य सम्बन्धित मामलो पर विस्तृत है । इसमे पुनर्ग्रहण भी सम्मिलित है ।

नोजितमाल न्यायालयो को अपना क्षेत्राधिकार उनको स्थापित करने वाले युद्धस्थित राज्य से प्राप्त होता है तथा उसको उसकी नागरिक विधि से प्रदान किया जाता है ।

**निर्णय का प्रभाव (Effect of Decision) :—**नोजितमाल न्यायालय का निर्णय निश्चयात्मक माना जाता है तथा इसके द्वारा समुद्रो छूट या नोजितमाल सम्बन्धी सम्पूर्ण स्वत्वाधिकारो का निर्णय हो जाता है ।

जर्मनी तथा पुर्तगाल के बीच वाले पचायती मामले मे [ (१९३०) (Zeitschrift III (1933) p 5) ] न्यायालय ने यह विचार प्रकट किया कि अन्तिम नोजितमाल न्यायालय के निर्णय, चाहे उनका आधार कितना ही अनुचित हो क्यों न हो, अन्तर्राष्ट्रीय स्वत्वाधिकार प्रदान करते है, जो सामान्यतः स्वीकृत किये जाते है तथा जिनके विरुद्ध कोई न्यायिक सहारा समभव नहीं है ।

**प्रक्रिया (Procedure) :—**Katrantsios v. Bulgaria [7 M A. T. (19 8) p 39] मे बल्गेरिया तथा ग्रीस के समिश्रित पचायती न्यायाधिकरण ने इस दृढ स्थापित नियम को पुनः स्थिर किया कि प्रत्येक राज्य अपना नोजितमाल न्यायालय संगठित करने तथा इसकी प्रक्रिया नियमित करने क लिये स्वतन्त्र है । नोजितमाल न्यायालयो के कुछ अन्तर्राष्ट्रीय रूढ हैं जो उनके कृत्यो के प्रकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि को युक्तिसंगन रीति मे लगाने के कर्तव्य के परिणामस्वरूप हैं । अतः यह आवश्यक है कि एत ऐसो न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिये

जिसके बीच में दोनों पक्षकारों को सुनवाई का मौका मिले तथा निर्णय न केवल राष्ट्रीय व्यवस्थानों तथा हितों पर ही आधारित होने चाहिये वरन् अन्तर्राष्ट्रीय विधि पर भी ।

नौजितमाल न्यायालयों के कर्तव्य (Duties of Prize Courts) :—  
ये कर्तव्य लार्ड स्टोवेल द्वारा बहुत ही ललित भाषा में स्वीडन के रक्षित जहाजों के बेटे मेरिमा [(1799) I. C. Rob Adm. Rep., p 340] वाले मामले में निम्न-लिखित शब्दों में वर्णित किए गए हैं :—

“अपना निर्णय देने में मैं विश्वास करता हूँ कि एक क्षण के लिये भी मैंने अपनी स्मृति से यह बात दूर नहीं की है कि जिस पद पर मैं आसीन हूँ उसका कर्तव्य क्या है अर्थात् प्रासंगिक तथा परिवर्तित सम्मतियों को न देना जिससे केवल विशिष्ट राज्य-हित के वर्तमान प्रयोजन ही सफल हो वरन् निष्पक्ष होकर वह न्याय देना जो राष्ट्रों की विधि बिना भेदभाव के स्वतन्त्र राज्यों में फैलती है जिनमें कुछ तटस्थ होते हैं तथा कुछ युद्धस्थित । इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्रों की शांत विधि तथा रीति के अनुसार न्यायिक प्राधिकारों का आसन इस स्थान पर है जो युद्धस्थित का देश है लेकिन विधि का स्वयं कोई स्थान नहीं है । यहाँ पर बैठने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि इस प्रश्न का निर्णय यहाँ पर बैठ कर ठीक-ठीक उसी प्रकार से करे जिस प्रकार कि वह इसका निर्णय स्टार्कहोम में बैठे करता;—ग्रेट ब्रिटेन की ओर से किसी प्रकार के कृत्रिम व्यवहार पर उसकी ओर से किसी दावे को मान न लेना जो वह उन्हीं परिस्थितियों में स्वीडन की ओर से न दिलाता तथा स्वीडन को कोई ऐसे कर्तव्य न सौंपता जो वह उसी स्वरूप में ग्रेट ब्रिटेन के भी होना न मानीकृत करे ।”

लार्ड स्टोवेल ने इस विषय को ‘रेकवरी’ (Recovery) वाले मामले [ (6 C. Rob. 341 (1807) ] में और भी स्पष्ट किया है कि “यह स्मरण रखना जाय कि यह राष्ट्रों की विधि का न्यायालय है जो यहाँ ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट् द्वारा प्रदत्त प्राधिकार से बैठा है । यह हमारे सहित अन्य राष्ट्रों का भी है तथा विदेशियों को इससे जो माँगने का अधिकार है वह यह कि राष्ट्रों की विधि को हमारे राष्ट्रीय विधिशास्त्र से लिये गये सिद्धान्तों के प्रवेश किये बिना लागू करे ।”

नौजितमाल न्यायालय की स्थापना (Location of Prize Courts) —  
नौजितमाल न्यायालय एक युद्धस्थित राज्य द्वारा एक तटस्थ प्रदेश में तटस्थता की विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का गंभीरता से भग्न किये बिना नहीं स्थापित किया जा सकता । लारेस के शब्दों में यदि युद्ध का एक पक्षकार यह प्रयत्न करे कि तटस्थ क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र के भीतर ऐसे न्यायालय स्थापित किये जाय तो वह



एक मित्र तथा शान्तिप्रिय राज्य के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रकार की सार्वभौमिकता को प्रयोग में लाने के यत्न द्वारा तटस्थ की स्वतन्त्रता पर बड़ा भारी अत्याचार करता है। ऐसे न्यायालय युद्धस्थित राज्य द्वारा अपने क्षेत्र में, अपने सैनिक दल के अधीन क्षेत्र में तथा एक मित्र राष्ट्र के प्रदेश में उसकी अनुमति द्वारा स्थापित किये जाते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विधियाँ तथा उनके द्वारा प्रदत्त की जाने वाली विधियों में उनकी स्थिति—नौजितमाल न्यायालयों का एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप है। वह इस अर्थ में कि वे ऐसे सभी व्यक्तियों के लिये खुले हैं जिनके हित उससे प्रभावित हो रहे हो चाहे उनकी राष्ट्रियता कुछ भी हो। इस विषय में न्यायिक विचारधारा में मतभेद है कि क्या नौजितमाल न्यायालय राष्ट्रीय विधि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्थापित करते हैं? लॉरेस को यह सम्मति है कि नौजितमाल न्यायालय राष्ट्रीय न्यायाधिकरण हैं जिनका अस्तित्व अन्तर्राष्ट्रीय विधि की स्थापना के प्रयोजन से है। उनका कथन है कि आधुनिक युग में उससे उत्कृष्ट विचार यह है कि नौजितमाल न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं है तथा इसके निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय विधि नहीं हैं चाहे वे उसी पर आधारित क्यों न हो। वे केवल अपने ही राष्ट्र द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं और केवल उसी राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी हैं। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय विधि उनके निर्णयों का स्रोत है, फिर भी निर्णय स्वयं राष्ट्रीय विधि के अंग हैं और ऐसी दशा में अन्तर्राष्ट्रीय विधि नहीं है, वरन्, यदि वे कोई नया नियम निर्धारित नहीं करते तो, वे केवल प्रमाण मात्र हैं। यदि वे कोई नया नियम निर्धारित करें और अन्य राज्य उन्हें अंगीकृत कर ले तो वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नये नियम के स्रोत हो सकते हैं। लेकिन जब तक इस प्रकार अंगीकरण न हो जाय यह नियम राष्ट्र-विधि ही रह जाता है। लॉरेस का कथन है कि सब देश इस बात को स्वीकार करने के लिये सहमत हो जायेंगे कि उनके नौजितमाल न्यायालय उन मामलों में से जो उनके समक्ष निर्णय के लिये आवें, राष्ट्रों की विधि के नियमों को लागू करने के लिये बाध्य हैं और अधिकांश मामलों में इस विषय में व्यवहार सिद्धान्त के अनुकूल हैं। जब तक मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति यही रहती है, जैसी कि इस समय है, अत्यन्त सत्यनिष्ठ तथा योग्य न्यायाधीश भी ऐसा निर्णय देने के लिये बाध्य हो सकते हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के स्वीकृत सिद्धान्तों तथा नियमों के विरुद्ध हो, जब कि कोई ऐसा विधान उन पर लाद दिया जाय जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध हो। यह भी सम्भव है कि उनके लिये अपने को जातीय पक्षपातों अथवा ध्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रभावों से अलग करना पूर्णरूप से असम्भव हो। उनका भागे कथन है कि यह मान लिया गया है कि नौजितमाल न्यायालय अन्त-

राष्ट्रीय विधि स्थापित करते हैं, तथा वे ऐसा ही करते हैं जब तक कि उनके अपने राज्यों के सम्यक् रूप में नियुक्त प्राधिकारीगण उनको इसके स्थानों में उससे असंगत नियमों का प्रवर्तन करने के लिये न कहें। सामान्यतः ऐसे हस्तक्षेप बहुत ही कम होते हैं और इस प्रकार यह देखा गया है कि नोजितमाल न्यायालयों के निर्णयों का सम्मान उनके न्यायाधीशों की विद्वत्ता, योग्यता, तथा निष्पक्षता की विख्याति के अनुरूप होता है।

ओपेनहेम का यह निश्चित विचार है कि नोजितमाल न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं वरन् राष्ट्र विधि द्वारा सस्थापित एक राष्ट्रीय न्यायालय है। प्रत्येक राज्य के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा बाधित है कि अपने नोजितमाल न्यायालयों के लिये केवल ऐसी ही सविधि तथा विनियम बनावे जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि से संगत हों। उनका कथन है कि यह बात कि ब्रिटेन के नोजितमाल न्यायालय पार्लियामेंट के अधिनियम को लागू करने के लिये बाध्य हैं, स्पष्ट रूप से यह प्रकट करता है कि जो विधि वे लागू करते हैं वे राष्ट्र विधि हैं, यद्यपि साराश में यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि है जो राष्ट्र विधि द्वारा व्यवहार में लाई गई हैं तथा जिसका निराकरण पार्लियामेंट के किसी ऐसे अधिनियम अथवा किसी आर्डर इन-कौन्सिल द्वारा नहीं हुआ है जिससे उसके द्वारा प्रदत्त अधिकार में कमी होती।

पकड़े गये तटस्थ जहाजों का नोजितमाल न्यायालयों द्वारा परीक्षण करना राष्ट्रीय विषय है तथा जहाजों के तटस्थ स्वदेशी राज्यों का प्रतिनिधित्व परीक्षण में नहीं होता है। इस प्रकार यद्यपि नोजितमाल न्यायालयों की विधिशास्त्र सम्बन्धी स्थिति उनके कृत्यों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय है फिर भी वे सस्थापन और संगठन में राष्ट्रीय प्रकृति के हैं।

पिट कीबेट का कथन है कि यह नोजितमाल न्यायालय ऐसा विषय नहीं है कि यह वह जाँच करे कि क्या उस विधि को जिसको यह लागू करता है राष्ट्रीय विधि द्वारा अनुसरण किया गया है, अथवा नहीं। नोजितमाल न्यायालयों के निर्णय शत्रु तथा तटस्थ राज्यों पर समान तौर से बाध्यकारी हैं तथा नोजितमाल न्यायालय विदेशी प्रजाजनों पर अपना क्षेत्राधिकार नागरिक प्राधिकारियों से नहीं, जो इसे प्रदान करने में असमर्थ हैं वरन् राज्यों की सम्मति से प्राप्त करते हैं। उनके अनुसार नोजितमाल न्यायालय निश्चित रूप से राष्ट्रीय न्यायाधिकरण हैं, लेकिन वे राष्ट्रीय विधि का प्रवर्तन करने के प्रयोजन से नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय विधि-स्थापना के प्रयोजन से बनाये जाते हैं।

फॉक्स (Fox) ( Edwards' Adm. Rep., p. 312 ) के बाद में, जिसका निर्णय १९११ में किया गया था, लॉर्ड स्टोवेल (Lord Stowell) का कथन था कि

“वाद-विवाद के प्रसंग में एक प्रश्न उठाया गया है कि न्यायालय का परिषद् के ऐसे आदेशों के प्रति क्या कर्तव्य होगा जो कि राष्ट्रों की विधि के प्रतिकूल हों ? एक ओर यह तर्क किया गया है कि न्यायालय प्रत्येक परिस्थिति में परिषद् के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, और दूसरी ओर यह कि न्यायालय विशिष्ट विवाद की परिस्थितियों के अनुसार, यहाँ तक कि परिषद् के आदेशों की उपेक्षा करते हुये भी राष्ट्रों की विधि के नियम को व्यवहृति प्रदान करने के लिए बाध्य होगा ।” “यह न्यायालय अन्य देशों की जनता पर विभिन्न ऐसे सम्बन्धों के बीच, जिसमें कि यह देश या सरकार रखी जाय, राष्ट्रों की विधि के प्रशासन के लिए बाध्य है । यही प्रशासन दूसरे देशों द्वारा भी अपनी जनता के सम्बन्ध में माँगा जा सकता है और यदि न प्राप्त कर सक तो वे देश शिकायत कर सकते हैं । यह इसकी एक अलिखित विधि है, इसका साक्ष्य इसके निर्णयों के क्रम में मिला है और इसका सग्रह सम्म्य राज्यों की प्रथाओं से किया गया है । साथ ही साथ यह अक्षरशः सत्य है कि इस देश के गठन द्वारा परिषद् में ‘किंग’ इस न्यायालय के ऊपर विधायी अधिकारों से युक्त हैं और उसे शक्ति है कि आदेश और निर्देश कर सके, जिनके पालन के लिये यह न्यायालय बाध्य है । यही न्यायालय की लिखित विधि का रूप गठित करते हैं । ये दो सूत्र, कि न्यायालय राष्ट्रों की विधि के प्रशासन के लिए बाध्य है, और यह कि वह परिषद् में ‘किंग’ के आदेशों के प्रवर्तन के लिये बाध्य है, एक दूसरे से सर्वथा असंगति में नहीं हैं, क्योंकि ये आदेश और निर्देश प्रस्तुत परिस्थितियों में इसकी अलिखित विधि के सिद्धान्तों के लिए स्वयमेव प्रामाणित हैं ।”

इस सम्बन्ध में प्रमुख मामला ‘जमोरा’ (Zamora) [(1916), 2 A.C. 77] पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है —

प्रथम महायुद्ध के बीच सन् १९१५ में ‘जमोरा’ नाम का एक स्वीडन का बाध्यचालित जहाज जो न्यूयार्क से स्टॉकहोम को अनाज तथा ताँबा लाद कर ले जा रहा था, एक ब्रिटिश युद्धपोत द्वारा रोककर पकड़ा गया तथा नौजितमाल न्यायालय के मार्शल की अभिरक्षा में मुपुर्द किया गया । इसमें सन्देह नहीं कि ताँबा विनिपिद वस्तु था लेकिन जहाज प्रकट रूप में एक तटस्थ बन्दरगाह को जा रहा था । अतः प्रश्न जो विचार के लिये उपस्थित हुआ वह यह था कि क्या लदा हुआ माल वास्तव में शत्रु के लिये अभिप्रेत था तथा उसके निर्णय पर मामले का अन्तिम परिणाम आश्रित था, अर्थात् क्या जहाज अथवा उसमें लदा हुआ माल विधि-प्रनु-कूल नौजितमाल है या नहीं ?

इस प्रश्न पर कोई निर्णय न होने के कारण प्रोक्चुरेटर-जनरल की प्रार्थना पर प्रेसीडेंट ने सन् १९१४ के ब्रिटेन के नौजितमाल न्यायालय के नियमों के अन्तर्गत

एक आदेश दिया जिसके द्वारा युद्ध विभाग को यह अनुमति दी गई कि तांबे को अधियाचित करे किन्तु इस प्रतिज्ञा के अन्तर्गत कि आँके हुए मूल्य का न्यायालय में दे दे। यह आदेश स्वीडन की नम्पनी तथा माल पाने वालों द्वारा अपील किये जाने पर उलट दिया गया। बोर्ड का निर्णय घोषित करते हुये लार्ड पार्कर ने यह मन प्रकट किया कि नोजितमाल न्यायालय का प्रारम्भिक कर्तव्य तथा कृत्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि स्थापित करना है। नोजितमाल न्यायालय पार्लियामेंट के अधिनियम से बाध्य है लेकिन यह बिग-इन-कौंसिल के किसी ऐसे आदेश से बाध्य नहीं है जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल हो अथवा जिसका आशय उसके किसी नियम को परिवर्तित करने का हो; यद्यपि अनुमानतः नोजितमाल न्यायालय पार्लियामेंट के अधिनियम को अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रतिक्रमण करके अनुसरण करने को बाध्य है। अतः नोजितमाल न्यायालय पार्लियामेंट के अधिनियमों से बाध्य है, किन्तु यदि वे राष्ट्रीय विधि से असंगत हो, तो नोजितमाल न्यायालय फिर अन्तर्राष्ट्रीय विधि नहीं प्रवर्तित करेंगे। उन क्षेत्र का जो ऐसे अनुबन्धों के अन्तर्गत आते हो, नोजितमाल न्यायालय रूप के उचित दूरवो से वचित कर दिया जायगा। यह भी मान लिया गया कि यह न्यायालय ऐसे कार्यकारी आदेशों की अपेक्षा न करेगा जिससे सम्राट के अधिकार तटस्थ अथवा शत्रु के पक्ष में क्षीण होते हो, तथा उसको उन्हे प्रवृत्त करना चाहिये था।

विचारण के आलम्बित रहने तक नोजितमाल न्यायालय की अभिरक्षा में स्थित सम्पत्ति के विक्रय तथा प्राप्त करने के सम्बन्ध में उसकी शक्ति के विषय में यह कहा गया कि नोजितमाल न्यायालय का प्रधान कर्तव्य सम्पत्ति को उन व्यक्तियों के हस्तगत करने के लिये सुरक्षित रखना है जो उस पर अपना स्वत्व स्थापित कर सके। न्यायालय की अन्तर्भूत शक्ति के अधीन सम्पत्ति पक्षकारों के हितों में उस दशा में देची जा सकती है, यदि वह नाशवान् प्रकृति को हो। यह भी मान लिया गया कि युद्ध-स्थिर शक्ति को अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा जहाजों तथा माल को जो नोजितमाल न्यायालय की अभिरक्षा में इस प्रश्न के निर्णय के आलम्बित रहने तक था कि क्या उनको दोषी ठहराया जाय अथवा उन्मोचित कर दिया जाय, अधियाचित करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा अधिकार परिसीमित है। प्रथम यह कि जहाज अथवा माल राज्य की सुरक्षा, युद्ध को चलाने अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित तथा अन्य विषयों से सम्बन्धित अन्य मामलों के लिये अत्यन्त आवश्यक रूप से अपेक्षित होना चाहिये। द्वितीय परीक्षण के लिये एक वास्तविक प्रश्न होना चाहिये। तृतीय नोजितमाल न्यायालय को प्रार्थना-पत्र देकर अधिकार प्रवर्तित करना चाहिये जो इस बात को न्यायिक रूप से निश्चित करे कि क्या, उस मामले

की उन विशिष्ट परिस्थितियों में, अधिकार प्रयोग किया जा सकता है। इस विचाराधीन मामले में यह सिद्ध न होने पर कि तांबा राज्य की प्रतिरक्षा अथवा युद्ध को चलाने के लिये अत्यन्त आवश्यक था, न्यायालय ने यह निर्णय किया कि अधिपक्षन के आदेश न्यायोचित नहीं हैं।

**नौजितमाल का विनाश (Destruction of Prizes) :—**यह सभी लोगो द्वारा स्वीकार किया जाता है कि, जबकि पकड़े गये जहाज और माल शत्रु की सम्पत्ति हैं, और उनको कुछ कारणों से किनारे तक से भाना खतरे से खाली नहीं हैं तो वे वही बिना किसी शिकायत का अवसर दिये नष्ट किये जा सकते हैं। यह सिद्धान्त कि आवश्यकता विनाश को भी न्यायोचित कह देती हैं, बहुत से विवादों में ब्रिटिश तथा फ्रान्सीसी नौजितमाल व्यापारियों द्वारा प्रवर्तित किया गया है। यही नियम तटस्थ राज्यों की सम्पत्ति के विषय में लागू नहीं होता। तटस्थ राज्य अपनी पकड़ी हुई सम्पत्ति का दावा कर सकते हैं और सतिपूर्ति के लिए वह राज्य जिम्मेदार होगा जिसने पकड़ा है।

**जर्मन नौजितमाल न्यायालय (German Prize Courts) :—**इस सम्बन्ध में दोनों महायुद्धों में जर्मन नौजितमाल न्यायालयों द्वारा अनुसरण किये गये विधि के नियम की ओर ध्यान आकषिप्त करना उपयुक्त होगा। बर्लिन के सर्वोच्च नौजितमाल न्यायालय ने यह नियम निर्धारित किया कि अन्तर्राष्ट्रीय न्याय के सिद्धान्त उनके नौजितमाल न्यायालयों में केवल उन्ही दशा में स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं जब उनके राष्ट्रीय विधान उन्हें अपने में समावेशित कर लें, तथा यह कि नौजितमाल न्यायालय का कुरूप राष्ट्रीय विधि को लागू करना है, न कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि को संक्षेप में जर्मन नौजितमाल न्यायालयों ने सर्वदा यह माना है कि राष्ट्रीय विधि को इस बात की अपेक्षा किये हुये बिना लगाया गया है कि क्या वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के वर्तमान सिद्धान्तों के अनुरूप हैं अथवा नहीं? इसके उपरान्त जर्मन नौजितमाल न्यायालयों के निर्णयों में राष्ट्रीय विधि पर आधारित निर्णयों के रूप में होने पर विवादपूर्ण विषय अथवा उस पर उठाये गये विषयों पर कोई विस्तृत विवेचना नहीं पाई जाती, लेकिन वे अपने परिणाम पर 'परिणाम से कारण' (a priori) वाली रीति से पहुँचते हैं। वे अधिराज विवेकहीन तथा मर्मभेदरहित निर्णय हैं।

**अन्तर्राष्ट्रीय नौजितमाल न्यायालय की आवश्यकता (Need for International Prize Court) :—**सारेन का कथन है कि यह तथ्य गम्भीर दोष प्रकट करता है कि नौजितमाल न्यायालय राष्ट्रीय न्यायालय हैं। उनके द्वारा मुदस्सिन राज्य व्यवहारतः अपने ही मामले में न्यायाधीन हो जाते हैं। यह

आवश्यक नहीं रहता कि उन योग्य व्यक्तियों पर जो उनमें न्यायाधीश के पद पर आसीन होते हैं, जानबूझ कर पक्षपात का दोषारोपण किया जाय, लेकिन अज्ञात रूप में पक्षपात का होना कठिनाई से ही रोक सकता है। यह सत्य है कि युद्ध के दबाव में नौजित-माल न्यायालय वह असंगत पक्षपात का रूप धारण करने की स्थिति में न हो, जो एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय से आशा की जाती है। दन दोषों का उपचार करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन तथा जर्मनी दोनों ने सन् १९०७ के हेग सम्मेलन के समक्ष एक अन्तर्राष्ट्रीय नौजितमाल न्यायालय स्थापित करने की योजना रखी। यद्यपि यह प्रस्ताव उस अभिसमय के १२वें भाग का अंग बना और वहाँ पर एकाग्रत आधिकांश शक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया तथापि यह उन राज्यों द्वारा स्थापित नहीं किया गया, मुख्यतः इस आधार पर कि समुद्री विधि पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं थी जो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सुचारु रूप से संचालन के लिये मूलरूप में आवश्यक है। प्रस्ताव की उत्पत्ति तथा उसके सविधान की बिना विवेचना किये हुये यह निःशक रूप से कहा जा सकता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विकास का मार्ग जो सम्भव है, वह यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को युद्ध के बीच समुद्रीय अभिग्रहणों के सम्बन्ध में निर्णय देने वाले नागरिक न्यायालयों के निर्णयों से अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाय।



## अध्याय ४२

### हवाई युद्ध की विधियाँ

#### ( Laws of Air Warfare )

द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्य हीरोशीमा तथा नागासाकी में सन् १९४५ में अणुबम के प्रयोग ने अन्तर्राष्ट्रीय विधि की हवाई युद्ध सम्बन्धी धारणा में ही पूर्ण परिवर्तन कर दिया। इसके द्वारा किये गये निर्मम विनाश तथा अपूर्व विध्वंस ने सम्य युद्ध के सम्पूर्ण नियमों को मिट्टी में मिला दिया। हाइड्राजन बम के आविष्कार के उपरान्त, जो कि अणुबम से दसगुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है, हवाई युद्ध ने और भी अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है तथा इससे सम्बन्धित लौकिक नियम प्रायः अतीत की स्मृति-मान रह गये हैं। इस तीव्र परिवर्तन के होते

हुए भी यह आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न सम्मेलनों में निर्धारित सिद्धान्तों का अध्ययन किया जाय ।

**ब्रसेल्स सम्मेलन (The Brussels Conference) :**—रूस के प्रशासक की प्रेरणा से सन् १८७४ में ब्रसेल्स में बुलाए गये सम्मेलन में युद्ध की विधि तथा रुढ़ियाँ निर्धारित की गईं । यद्यपि ये नियम भिन्न-भिन्न राज्यों पर बन्धनकारी नहीं थे तथापि वे अत्यधिक महत्व के थे, क्योंकि उनमें से अनेक को अधिकांश सम्मेलन राज्यों द्वारा इस क्षेत्र में स्थित अपने पदाधिकारियों के अनुदेश के लिये निकाले हुए सार-संग्रह में स्थान मिला । नियमों में यह निर्धारित किया गया कि नगर तथा ग्रहो अथवा ग्रामों के समुदायों पर जो खुले अथवा शान्तिपूर्ण थे, आक्रमण अथवा बमवर्षण नहीं किया जा सकता । यदि कोई नगर, किला अथवा ग्राम प्रतिरक्षित हो तो आक्रमणकारी दलों का नायक प्राधिकारियों को सावधान करने के लिए जो कुछ उसकी शक्ति में हो, करेगा । यह भी निर्धारित किया गया कि धर्म, कला, विज्ञान तथा उदारता के कार्यों के लिए समर्पित आवासों, अस्पतालों तथा ऐसे स्थानों को जहाँ अस्वस्थ तथा घायल एकत्र हों, बचाने के लिए यथासम्भव सब आवश्यक उपाय काम में लाए जायेंगे इस प्रतिबन्ध के साथ कि वे उस काल में सैनिक प्रयोजनों के लिये उपयोग न किए जायें ।

**हेग सम्मेलन (Hague Conference) :**—सन् १८६६ के प्रथम हेग सम्मेलन ने हवाई युद्ध के सम्बन्ध में निश्चित नियमों की व्यवस्था करने का प्रयास किया । अनुच्छेद २५ में शान्तिपूर्ण नगरों, ग्रामों, आवासों अथवा भवनों पर आक्रमण अथवा बमवर्षण निषिद्ध किया गया । सन् १९०७ की प्रतिज्ञा से सलग्न हेग विनियमों द्वारा प्रक्षेपण अथवा विस्फोटक पदार्थों को गुब्बारों से अथवा इसी प्रकार की अन्य रीतियों से फेंकना निषिद्ध किया गया । प्रक्षेपणों का प्रयोग, जिसका उद्देश्य केवल दम घोटने वाली अथवा हानिकारक गैसों का फैलाना था तथा ऐसी गोलियों का प्रयोग भी जो मनुष्य के शरीर में फैलती अथवा चिपटी जाती थी, निषिद्ध किया गया । अभिसमय में यह भी निर्धारित किया गया कि तटस्थ राज्य यह देखने के लिए बाध्य हैं कि युद्धस्थित के मध्य तटस्थ क्षेत्र के ऊपर कोई हवाई लड़ाई न हो ।

हेग विनियमों ने प्रक्षेपण अथवा विस्फोटक पदार्थों को वायुयान से फेंकने वाले निषेधों को दुहराया तथा हेग विनियम के अनुच्छेद २५ में और भी जोड़ा जिसके द्वारा शान्तिपूर्ण नगरों, ग्रामों, आवासों, अथवा भवनों पर आक्रमण अथवा बमवर्षण 'किसी भी प्रकार से' निषिद्ध किया गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि की सस्था ने मैड्रिड में सन् १९११ में यह सिद्धांत स्वीकृत किया कि "हवाई युद्ध की अनुमति है, लेकिन अनुबन्ध यह है कि इससे शान्तिप्रिय

जनता अथवा उसकी सम्पत्ति को स्थलीय अथवा समुद्री युद्ध से और अधिक भय उत्पन्न न हो ।”

**प्रथम महायुद्ध (First World War)** — प्रथम महायुद्ध में युद्धस्थित में से प्रत्येक ने यह दावा किया कि उन्होंने अपने उडाको को यह निर्देश दे दिया है कि वे अपना आक्रमण केवल सैनिक लक्ष्यों तक ही सीमित रखें, लेकिन उडाको के लिये इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करना असम्भव था क्योंकि अधिक ऊँचाई से तथा तीव्र गति में ठीक-ठीक निशाना मारना कठिन होता था । इसका परिणाम यह हुआ कि लड़ने तथा न लड़ने वालों का भेद प्रायः लुप्त हो गया तथा युद्ध के अन्त में सैनिक लक्ष्यों के क्षेत्र के बाहर खुले हुये नगरों पर बम बरसाना प्रायः एक सामान्य घटना हो गई ।

**वॉशिंगटन सम्मेलन (Washington Conference)** — प्रथम महायुद्ध के परिणामस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि युद्ध में हवाई जहाजों के उपयोग सबंधी विनियम परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये सम्पूर्णतः अपर्याप्त थे । अतः शत्रु को सीमित करने के लिये सन् १९२२ में वॉशिंगटन में हुये सम्मेलन में जिसमें समुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान तथा हार्लैंड सम्मिलित थे, एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि विधि वेत्तामा का एक आयोग नियुक्त किया जाय जो हवाई युद्ध की समस्या पर विचार करे, और वॉशिंगटन सम्मेलन द्वारा नियुक्त वायुयान समिति ने सन् १९२३ में प्रस्तावित वायुयुद्ध सबंधी नियमों की संहिता की भिन्न-भिन्न व्यवस्थाओं का वर्णन किया । यद्यपि संहिता सत्यापित नहीं की गई तथापि इसकी भिन्न-भिन्न व्यवस्थाएँ स्थल तथा हवाई युद्ध में वायुयान के उपयोग के लिये पथ-प्रदर्शक का कार्य करेगी ।

वायु-युद्ध नियम (सन् १९२३) को निम्न रूप में सक्षित किया जा सकता है :—

१. शास्त्ररक्षा के लिये भी व्यक्तिगत वायुयानों का शस्त्रीकरण पूर्ण रूप से निषिद्ध है ।

२. नागरिक जनता को भयभीत करने के लिये बमवर्षण, सैनिक लक्ष्यों से रहित व्यक्तिगत सम्पत्ति का विनाश या उसको अथवा सड़ाई न लड़ने वालों को आघात करना निषिद्ध किया गया ।

३. वस्तु अथवा धनरूप में चन्दे को भाँग वी पूर्ति को बाध्य करने के प्रयोजन से हवाई बमवर्षण निषिद्ध है ।

४. हवाई बमवर्षण केवल उसी दशा में वैध है जब कि यह ऐसे सैनिक लक्ष्यों पर किया जाय, जिनका विनाश युद्धस्थित के नियम एवं स्पष्ट सैनिक लाभ हो, उदा—



हरणार्थ सैनिक संस्थापन, गोला बारूद के कारखाने, यातायात के मार्ग जो सैनिक प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाय आदि ।

५. हवाई बमवर्षण उस दशा में भी वैध नहीं है जब यह ऐसे सैनिक लक्ष्यों पर किया जाय जिसको कि नागरिक जनता पर विवेकरहित बम बरसाये बिना नहीं त्याग किया जा सकता ।

६. स्थल सेना के कार्यकारी क्षेत्र के अत्यन्त निकट पड़ोस के नगर, पुर तथा भवनों पर बमवर्षण निषिद्ध है ।

७. उस क्षेत्र के जिसमें स्थल-सेना कार्य कर रही हो, अत्यन्त सन्निहित क्षेत्र पर बम बरसाने की केवल उसी दशा में अनुमति है, जब इस बात का युक्ति-संगत अनुमान हो कि सैनिक एकत्रीकरण पर्याप्त रूप से इतना प्रमुख है, कि ऐसा बमवर्षण न्यायोचित ठहराया जा सके ।

८. ऐसे भवन जो सार्वजनिक पूजा, कला, धर्म, विज्ञान तथा उदारता के लिये समर्पित हैं तथा ऐतिहासिक स्मारक तथा शरणार्थियों के लिये अस्पताल उन्मुक्त हैं ।

९. युद्ध तथा तटस्थता की विधियाँ जो भूमि संबंधी सेनाओं के लिए लागू हैं, वही हवाई युद्ध के लिये भी लागू हैं ।

१०. एक युद्धस्थित राज्य अपने पदाधिकारियों अथवा सैनिक दलों द्वारा उपर्युक्त नियमों के सम्बन्धों के उल्लंघन के कारण व्यक्तियों अथवा सम्पत्ति को की गई हानियों के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य हैं ।

सन् १९२५ के जेनेवा के सलेख (protocol) ने युद्ध में गैस अथवा कीटाणुनाशक का प्रयोग निषिद्ध किया ।

निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के सामान्य आयोग ने जुलाई सन् १९३२ में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि नागरिक जनता के विरुद्ध हवाई आक्रमण पूर्ण रूप से निषिद्ध रहेगा ।

**अयोधियों की स्थिति (Position of Non-combatants) :—**  
निःशस्त्रीकरण सम्मेलन के सामान्य आयोग ने जुलाई १९३२ में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया कि नागरिक जनता पर हवाई आक्रमण पूर्णतया निषिद्ध रहेगे । द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व अयोधियों की यह उन्मुक्ति कि उन पर हवाई आक्रमण कदापि नहीं किया जायगा, युद्धविधि के एक प्रवर्तित सिद्धान्त के रूप में मानी जाती थी । ओपेनहेम ने तीन बातों का उल्लेख किया है जिनके कारण युद्ध-विधि के इस प्रवर्तित सिद्धान्त को अबर्द्धत धक्का लगा—(क) आधुनिक युद्ध-विधि का विस्तार तथा परिवर्तित युद्ध-ढंग जिनमें अयोधियों और अयोधियों का कोई भेद ही नहीं रह गया,

(ख) यह निर्णय करने की कठिनाई कि सैनिक उद्देश्य वस्तुतः किस कृत्य को कहना चाहिए जिससे कि उसके विरुद्ध सीधी कार्यवाही की जा सके; और (ग) हवाई बम-वर्षा के सम्बन्ध में प्राविधिक कठिनाई (technical difficulty) जो कि शत्रुतापूर्ण कार्य के प्रभाव वाले अभीष्ट स्थान को चुनने या आक्रमण के निश्चित स्थान को निर्धारित करने के प्रसंग में है ।

लीग की सभा ने सितम्बर १९३८ के १६वें अधिवेशन में निम्नलिखित सिद्धान्त स्वीकार किया था :—नागरिक जनता पर जानबूझकर बमबर्षा करना अवैध है । हवाई बमबर्षा का उद्देश्य अवश्य ही सैनिक होना चाहिए और वह भी अभिज्ञान के योग्य हो । वहाँ भी, सैनिक उद्देश्य से बमबर्षण इस ढंग से होना चाहिए कि आसपास की नागरिक जनता को कोई क्षति न पहुँचे ।

द्वितीय विश्व-युद्ध ( Second World War ) :—द्वितीय विश्वयुद्ध में हवाई युद्ध के नियमों का घोर तिरस्कार किया गया । सन् १९३९ में पोलैण्ड के चारता तथा अन्य नगरों पर विवेकशून्य बमबर्षण द्वारा युद्ध के नियमों का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया । इसके उपरान्त मई १४ सन् १९४० को तटस्थ नगर रोटरडम पर विनाशकारी बमबर्षण हुआ । जर्मन हवाई जहाजों द्वारा होलैंड के तटों में स्थित अड्डों से राकेट बमों के प्रयोग द्वारा ब्रिटेन के लंदन तथा अन्य नगरों पर जो बमबर्ष-नीय दुःखद तथा विनाशकारी बमबर्षण किये गये उससे भी यही बात प्रकट हुई कि युद्धस्थित राष्ट्र युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए कितने निम्न स्तर तक उतर सकता है । ब्रिटेन तथा अमेरिका के हवाई बेडों ने भी अपनी पारी में जर्मन नगरों पर उसी प्रकार विवेक-शून्य तथा क्रूर बमबर्षण किया । सारी लड़ाई युद्ध के नियमों का विचार स्मरण करके लड़ी गई, तथा लड़ाई न लड़ने वाले निर्दयता से मारे गये और सार्वजनिक पूजा, कला तथा धर्म के लिये समर्पित भवनो तथा ऐतिहासिक स्मारकों पर भी बम बरसाये गए । इन सब से अधिक भयावह अमेरिका द्वारा अगस्त ६, तथा ९, सन् १९४५ को होरोशीमा तथा नागासाकी पर अणुबम का प्रयोग था, जो लड़ाई न लड़ने वालों को बिना उचित चेतावनियों दिये हुये तथा उन वैज्ञानिकों के, जिन्होंने इस योजना में कार्य किया था अनुरोध का उल्लंघन करके किया गया था । केवल होरोशीमा पर ही एक अणुबम गिराये जाने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप प्रायः ६०,००० जापानी स्त्री, पुरुष तथा बच्चे मारे गये, लगभग १,००,००० जनता घायल हुई, तथा प्रायः एक सारे बन्दरगाह का, जिसकी जनसंख्या २,५०,००० थी, धमके से प्रचंडाग्नि से विध्वंस हो गया । थोड़े ही दिनों के उपरान्त अणुबमों के गिराने के परिणामस्वरूप होने वाले विनाश के कारण जापान ने हार मान ली तथा द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया ।

**अणुबम के प्रयोग की नैतिकता पर विचार ( Ethics of Atom Bomb )** — अणुबम का प्रयोग कहाँ तक नीतियुक्त है इस पर बहुत ही गरमागरम विचार-विमर्श हुआ। यह एक अत्यन्त नृशंस कार्य था। किसी भी दशा में जापानियों को अमेरिका द्वारा इसके प्रयोग के किये जाने के विचार की तथा इससे होन वाली भीषण काँड की चेतावनी पहले से दी जानी चाहिये थी।

अणुबम का प्रयोग अतीत काल से सम्म युद्ध को अनुशासित करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का उल्लंघन था। इसका प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा मानवता के विरुद्ध एक अपराध है। श्री जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि अणुबम उससे सलग्न तथा उसमें अन्तर्हित भयकरता के अतिरिक्त भूतिमान पाप का एक प्रतीक हो गया है, तथा यदि परिस्थितियों के दबाव के कारण ससार इसका प्रयोग करने के लिये बाध्य हुआ तो इसका यह अर्थ होगा कि ससार ने अपने-आप को पूर्णरूप से पाप के हाथों समर्पण कर दिया है।

किसी राष्ट्र का युद्ध में अपने शस्त्रों को प्रयोग करने का अधिकार इस उत्तरदायित्व के अन्तर्गत सीमित है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि में सम्मिलित युद्ध के नियमों का पालन करे। यह स्मरण रखने योग्य है कि जर्मनों पर प्रथम महायुद्ध में जब उन्होंने पनडुब्बियों का प्रयोग किया अन्तर्राष्ट्रीय विधि को उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया क्योंकि उन नवीन आविष्कृत बाहनों का प्रयोग युद्ध की विधियों से असंगत था। जर्मनों ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि नये शस्त्रों के आविष्कार की यह माँग है कि युद्ध की पुरानी विधियों का पुनरीक्षण किया जाय। राजनीतिज्ञ तथा विधि-वेत्ताओं दोनों द्वारा यह तर्क न्याय विरुद्ध माना गया। युक्ति तथा तर्क में कितनी ही खीचा-तानी की जाय फिर भी अमेरिका वाले अब उस विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते जिसे कि जर्मनों को सही रूप से अस्वीकृत किया गया। अणुबम, हाइड्रोजन बम तथा बी-बमों को बिना अग्रिमदित विनाश तथा अव्यवस्थित हूनन किये हुये उपयोग में नहीं लाया जा सकता जो युद्ध के सब नियमों के विरुद्ध है। अतः हीरोशीमा तथा नागासाकी का प्रमाण पूर्व दृष्टान्त के रूप में नहीं दिया जा सकता तथा वे एक पूर्णरूप से अवैध शस्त्र को वैध रूप नहीं दे सकते।

अणुबम या एन बम का प्रयोग समुक्त राष्ट्र सभ के चार्टर की प्रकृति के प्रतिकूल है। यह नम युद्ध कोशल के नियम, १९२३, के भी विपरीत है। इस नियम के अन्तर्गत स्पष्टतः उपबन्धित है कि नम बमवर्षा केवल तभी वैध हो सकती है, जब कि किसी सैनिक प्रयोजन से की गई हो और जिसके विनाश से युद्ध सलग्न राष्ट्र की निश्चित सैनिक अनुलाभ मिले, जैसे सैनिक व्यवस्था, शस्त्र-निर्माण फैक्टरियों, सैनिक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त संचार के मार्ग, आदि। निःशस्त्रीकरण के सामान्य

सम्मेलन द्वारा भी जुलाई १९३२, में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया था कि नागरिक जनता पर नभ-आक्रमण निषिद्ध कर दिये जाय । जहाँ तक अणुबमों का प्रश्न है, यदि उन्हें सैनिक प्रयोजनों से ही गिराया गया, तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनका फेनाव या प्रभाव केवल उन्हीं उद्देश्यों तक सीमित और नियन्त्रित रहेगा ।

मृत्यु की वर्षा करने वाले ये विनाशक अस्त्र, यू० एन० चार्टर के प्रतिकूल होने के साथ ही स्वयं हमारी अन्तः चेतना के प्रतिकूल हैं, क्योंकि इन अस्त्रों के प्रयोग से सदैव के लिये राष्ट्रों में एक भातक सा छा जाता है और उस एक राष्ट्र के साथ और भी ऐसे राष्ट्र प्रतिद्वन्द्विता में खड़े होत हैं जो राष्ट्र का अतुल्य धन उस मृतकारी अस्त्रों के निर्माण में भोक देते हैं । यह उस समय होता है, जब कि उसी राष्ट्र के बच्चे पोष्टिक आहार के बिना मरते हैं, और जनता आवास, स्वास्थ्य और काम की कमी के कारण त्राहि-त्राहि करती रहती है ।

**अणुशक्ति आयोग** —संयुक्त राष्ट्र सभ की साधारण सभा ने जनवरी २४, सन् १९४६ को एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसके द्वारा एक अणुशक्ति सम्बन्धी आयोग स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य शान्ति के प्रयोजनों के लिये अणुशक्ति का नियन्त्रण तथा राज्यों की ओर से उत्पन्न तथा छल-कपट से बचाने के लिये निरीक्षण रूपी प्रभावपूर्ण सरक्षण-स्थापना के लिये सुझाव देना था । सन् १९४८ में साधारण सभा ने आयोग के प्रतिवेदनो पर विचार किया तथा हून के इस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया कि अणुशक्तियों के नियम के लिये तथा अणुशक्ति पर प्रभावपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित करने के लिये अभिसमयों का मसौदा बनाया जाय । सभा ने आयोग के सामान्य निष्कर्षों को स्वीकृत किया । मुख्य कठिनाई यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो बम धन चुके हैं उन पर अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की प्रतिभूति न देकर वह उनका बराबर उत्पादन करते रहना छोड़न को तैयार नहीं है । दूसरी ओर हून अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की योजना स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत नहीं है क्योंकि इससे उसके सार्वभौमिकता के सिद्धान्त में बट्ठा लगता है ।

**शत्रु के नागरिक जहाज पर आक्रमण (Attack on Enemy Civil Aircraft)** —हवाई युद्ध में इस बात का भय बना रहता है कि शत्रु के नागरिक हवाई जहाजों से आक्रमण न हो जाय । इस भय को दृष्टि में रखते हुये हेग अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि युद्ध-स्थिति असैनिक जहाज यदि शत्रु के क्षेत्राधिकार की सीमा में उड़ रहे हों तो उन्हें मार गिराया जा सकता है ।

## अध्याय ४३

## युद्ध-अपराध

## (War Crimes)

युद्ध-अपराध किस प्रकार से स्थापित होता है :—युद्ध-अपराध की परिभाषा करने में एक कठिन समस्या उपस्थित होती है क्योंकि युद्ध के नियमों का प्रत्येक उल्लंघन युद्ध-अपराध में परिणित नहीं हो जाता। ब्रिटेन के सैनिक ग्रथ में यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रकार के कार्य जैसे मायम न देना, युद्ध के बन्दिओं के प्रति दुर्व्यवहार, लूट तथा निष्प्रयोजन विनाश युद्ध-अपराध हैं। सन् १८६६ के हेग सम्मेलन ने भी ऐसे ही अपराधों को युद्धापराध माने जाने का सुझाव दिया था। प्रोफेसर लीटरपैट ने भी सन् १९४४ को ब्रिटिश इयर बुक में सकेत किया है कि यह शब्द ऐसे कार्यों के लिये सीमित होना चाहिये जो अपनी निर्दयता, अमानुषता अथवा युक्ति-संगत सैनिक आवश्यकता से असम्बद्ध सम्पत्ति के सम्बन्ध में मर्यादाहीन उपेक्षा के कारण मनुष्यों द्वारा एक स्वर से निन्दित किये जाय।

प्रोफेसर हिजिन्स (Prof. Higgins) के अनुसार युद्ध अपराधों के अन्तर्गत सैन्य बलों के सदस्यों द्वारा युद्ध-कौशल के मान्य नियमों का अतिक्रमण (violation of the recognised rules of warfare by members of the armed forces), ऐसे व्यक्तियों अवैध जो कि सैन्य बलों के सदस्य नहीं हैं, द्वारा शत्रुों को सम्बन्ध में कारित किये गये अवैध शत्रुतापूर्ण हो (illegitimate hostilities in arms committed by individuals who are not members of the armed forces), जासूसी (espionage) और युद्ध-प्रतिद्रोह (war treason) और लूट-मार (marandng) सम्मिलित हैं।

हान्स वेल्सन का कथन है कि

"violations of the rules of warfare are called war crimes General International Law obligates the States to punish their own war criminals, and authorizes any belligerent State to punish the prisoners of war in its power for having violated the rules of warfare prior to capture. Hence general International Law imposes upon individuals, as private persons, the obligation to refrain from committing war crimes, and establishes individual

criminal responsibility for the commission of such crimes by private persons."

अर्थात् युद्ध-नियमों के अतिक्रमण को युद्धापराध कहते हैं। साधारण अन्तर्राष्ट्रीय कानून राज्यों पर यह भार आरोपित करता है कि वे अपने अपराधियों को स्वतः दण्डित करें और किसी भी युद्ध-स्थित राज्य को प्राधिकार देता है कि वे युद्ध के बन्दिता को अपनी शक्ति के भीतर बन्दी होने के पूर्व युद्ध की विधियों का उल्लंघन करने के प्रसंग में दण्डित करें। अस्तु सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि व्यक्तियों पर यह भार सौंपती है कि वैयक्तिक व्यक्ति रूप में वे युद्ध-अपराध के कृत्यों से अपने को बचावें और व्यक्तियों द्वारा ऐसे युद्धापराध किये जाने पर वैयक्तिक अपराध का दायित्व प्रवर्तित करता है।

ओपेनहेम (Oppenheim) के अनुसार युद्धापराध ऐसे शत्रुतापूर्ण कार्य हैं, या सैनिकों के अन्य कार्य हैं, या अन्य व्यक्तियों के ऐसे कार्य हैं जिनपर कि शत्रु द्वारा अपराधियों को पकड़े जाने पर दण्ड दिया जा सकता है। उन कार्यों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रतिकूल ऐसे कृत्य आते हैं, जो कि स्वयं अपराधी द्वारा अपने ही राज्य में किये जाने पर अपराध होते जैसे व्यक्तिगत प्रलोभन या लाभ की पूर्ति के लिए बल करना, साथ ही ऐसे अपराधिक कृत्य भी आते हैं जो कि उन युद्ध विधियों के प्रतिकूल हैं जो कि शत्रु-राज्य के आदेश पर या उसकी ओर से कारित किये गये हैं। उपर्युक्त विद्वान् ने युद्धापराधों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है—

(१) युद्ध-कौशल से सम्बन्धित मान्य नियमों का उल्लंघन, जो कि सशस्त्र शक्तियों द्वारा कारित किया जाय,

(२) शस्त्रों द्वारा संपन्न किये गये सभी शत्रुतापूर्ण कार्य, जो कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा कारित किये जाय जो कि शत्रु की सशस्त्र सेना के सदस्य नहीं हैं,

(३) छुफियागिरी और युद्ध के रहस्यों का उद्घाटन, और

(४) लूटमार के कृत्य (marauding acts)।

अन्य बातों के साथ-ही उपर्युक्त विद्वान् ने निम्नलिखित कृत्यों को युद्ध-कौशल के नियमों का उल्लंघन कहा है— विपेली गैस का प्रयोग, धातल अथवा समर्पण किये हुये सैनिकों का वध, युद्ध के मैदानों में भूतकों के प्रति दुर्व्यवहार, या अपमानजनक-व्यवहार, क्वार्टर के लिये आघातकारी आग्रह, वधन के रूप में समर्पित व्यक्तियों का वध, युद्धबंदियों के प्रति दुर्व्यवहार, हानिरहित व्यक्तिगत शत्रु व्यक्तियों पर आक्रमण या वध, सप्रहालयों, अस्पतालों, उपासना के स्थानों और स्कूलों पर, अथवा-अरक्षित खुले नगरों या ऐतिहासिक स्मारकों पर बमबर्षा, अस्पताली पोतों पर आक्रमण, शान्ति के ध्वज के साथ चलने वालों पर आक्रमण, आदि।

**नूरम्बर्ग परीक्षण—**इसकी उत्पत्ति :—सन् १९४३ में मास्को सम्मेलन में तीनो बड़ी शक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के नाम बोलते हुए यह घोषणा की कि नाजी दल के वे जर्मन पदाधिकारी तथा मनुष्य और सदस्य जो अत्याचारों, मनुष्यों के हत्याकांड तथा उनको प्राणदण्ड देने के लिये उत्तरदायी हों उन देशों को जिनमें उनके घृणित कार्य किये गये परीक्षण तथा दण्डित करने के लिये वापस भेजे जायेंगे। सन् १९४५ के याल्टा सम्मेलन में, जिसमें इङ्ग्लैंड, अमेरिका तथा रूस पक्षकार थे, युद्धापराधियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के दृढ़ निश्चय को और भी सुदृढ़ किया गया। इसके उपरान्त युद्धापराधियों की सूची तैयार करने के लिये लॉर्ड राइट की अध्यक्षता में संयुक्तराष्ट्र युद्धापराध आयोग स्थापित किया गया तथा उसको यह अधिकार प्रदान किया गया कि उन अपराधियों को विश्व के अधिकांश देशों में बन्दी कर ले। चारों राष्ट्रों के अभियोजकों द्वारा एक चार्टर तैयार किया गया। अगस्त ८ सन् १९४५ को संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन तथा रूस के प्रतिनिधियों के मध्य लन्दन में एक स्वीकारपत्र हस्ताक्षरित किया गया जिसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यूरोपीय अक्ष के बड़े-बड़े अपराधियों का परीक्षण किया जाय जिनके अपराध करने का कोई विशिष्ट भौगोलिक स्थान नियत न था। इस स्वीकारपत्र के साथ यह अधिपत्र सलग्न था जिसके द्वारा युद्धापराधियों के परीक्षण के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक-न्यायाधिकरण स्थापित किया गया। इसके परिणामस्वरूप नाजी नेताओं का नूरम्बर्ग में परीक्षण हुआ।

**नूरम्बर्ग परीक्षण का औचित्य** —नूरम्बर्ग परीक्षण के औचित्य को इस आधार पर स्थापित करने का प्रयत्न किया गया कि सितम्बर २४, सन् १९२७ को लीग ऑफ नेशन्स ने, जिसमें जर्मनी सम्मिलित था यह घोषणा की थी कि युद्ध जिसमें अग्रघर्षण (यकाएक आक्रमण) किया जाय एक अपराध है। इसके उपरान्त केलोग त्रिभान्वल पैक्ट अथवा पेरिस पैक्ट द्वारा जो सन् १९२८ में संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन वैदेशिक सचिव फ्रेक बी कैलॉग तथा फ्रांस के वैदेशिक सचिव त्रिभान्वल द्वारा परस्पर सहयोग करके हस्ताक्षरित किया गया था, युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय अंगों को तय करने के लिये उपाय की दृष्टि से निन्दा की गई थी, तथा यह प्रतिज्ञा की गई थी कि ऐसे अंगड़े शान्तिपूर्ण रीतियों से तय किये जायेंगे। हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र प्रायः ससार के सभी राष्ट्र थे जिनमें जर्मनी, जापान तथा इटली भी सम्मिलित हैं। उन्होंने अपने को बाध्य कर लिया था कि वे युद्ध के उगम का आश्रय लेना अपनी राष्ट्रीय नीति नहीं रखेंगे।

अभूतपूर्व अत्याचारों के कारण भी सब मित्र-देशों में संयुक्त दृढ़ निश्चय उत्पन्न हुआ कि बदला लिया जाय और जर्मनी के दखल द्वारा मित्र देशों की सेनाओं की

**अनुरोध की श्रेणियाँ (Categories of Crimes) :—** बांटेर के अनुच्छेद ६ में अन्तर्राष्ट्रिकरत को निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अपराधों के समूह में दरी-कृत करने का प्राधिकार देना बना :—

**(१) शान्ति के विरुद्ध अपराध (Crimes against Peace) :—** इन अपराधों में अग्रमर्क युद्ध के निमित्त योजना बनाना, उसके विरोध लेदारी करना, प्रेरणा देना अथवा ऐसी सहायि सड़ना, अन्तर्राष्ट्रीय संधियों, स्वीकारपत्रों अथवा आश्वासनों को उल्लंघन करके युद्ध सड़ना, अथवा अनुकूल शिपयों में से किसी एक को नो करने के लिए पड़गन करना सम्मिलित है ।

**(२) युद्ध-अपराध (War Crimes) :—** इसके अन्तर्गत युद्ध की विधियों अथवा कड़ियों का उल्लंघन आता है जिनमें हत्या, दसत बिदे हुए शेर में नागरिक जनता से दुर्भ्यहार, युद्धबन्धियों की हत्या अथवा उनसे दुर्भ्यहार, बन्धक के रूप में समर्पित बन्धियों की हत्या, सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत सम्पत्ति को लूट, शायरी का मर्यादाहीन विनाश सम्मिलित है जिसका मोक्षिय सैनिक आवश्यकता से गहीं ठहराया जा सकता ।

**(३) मानवता के विरुद्ध अपराध (Crimes against Humanity) :—** इस श्रेणी के अन्दर पड़ने वाले अपराधों में हत्या, समूल विनाश, दासतय तथा ग्राम धमामनुषिक कार्य जो युद्ध के पूर्व अथवा मध्य किये गये हों, राजनीतिक, जातीय अथवा धार्मिक आधार पर उत्पीड़न सम्मिलित हैं जो ग्यायाधिकरण के दोषाधिकार के भीतर पड़ने वाले किसी अपराध के निष्पादन में किये गये हों यादे वह किये जाने वाले देश की परेसू विधि के उल्लंघन में हों अथवा नही ।

अभियोग के दार्यों में प्रतिवादिनों ने अगनी समान योजना से अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को स्वीकार-पत्रों अथवा आश्वासनों का उल्लंघन करके अग्रमर्क युद्ध



योजना की ओर युद्ध किया। प्रतिवादियों के मध्य परस्पर उनके पड़्यन्त्र के उद्देश्यों तथा प्रयोजनों को पूरा करने के लिये नाज़ीदल ने एक सहयोगकारी साधन का कार्य किया। इसके उद्देश्य थे, (अ) वारसलीज की सधि तथा उसके सैनिक पुनः शस्त्रीकरण के निरोधो का निराकरण तथा उसको मिटा देना, (आ) प्रथम महायुद्ध में जर्मनी द्वारा खोये हुए प्रदेशों की प्राप्ति, (इ) यूरोपीय प्रदेश में जर्मन जाति द्वारा अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये पड़ोसी तथा अन्य देशों को हानि करके और अधिक प्रदेश प्राप्त करना (Lebensraum)।

**प्रतिरक्षा (Defence) :—**प्रतिवादियों की ओर से यह कहा गया कि सभी विधियों का, चाहे वे अन्तर्राष्ट्रीय हों अथवा घरेलू हों, मूलभूत सिद्धान्त यह है, कि बिना पूर्वस्थित विधि के किसी अपराध के लिये दण्ड नहीं दिया जा सकता—(Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege)। यह प्रार्थना की गई कि घटनोत्तर (ex post facto) दंड सब सम्यक् राष्ट्रों की विधि के लिए घृणित है, यह कि किसी भी सार्वभौमिक सत्ता ने अप्रघर्षक युद्ध को उस समय एक अपराध नहीं माना है जिस समय कि कथित अपराध के कार्य किये गये थे, यह कि किसी भी व्यवस्था ने अप्रघर्षण की परिभाषा नहीं की है, यह कि इसके करने के लिये कोई दंड नियत नहीं किया गया है तथा यह कि अपराधियों को दंडित करने के लिए कोई न्यायालय नहीं बनाया गया है।

**न्यायाधिकरण के निष्कर्ष (Observations of the Tribunal) :—**प्रतिरक्षा द्वारा उठाये गये विवाद का खंडन करते हुये न्यायाधिकरण ने यह निरूपण किया कि पूर्वस्थित विधि वाले सिद्धान्त (maxima nullum crimen sine lege) से सार्वभौमिकता सीमित नहीं होती लेकिन यह सामान्य रूप में न्याय का एक सिद्धान्त है। इस बात को दृढ़तापूर्वक कहना कि उनको दण्ड देना अन्याय है जिन्होंने सन्धियों तथा आश्वासन दिलाने के पश्चात् भी उनका उल्लंघन करके पड़ोसी राष्ट्रों पर बिना चेतावनी दिए हुए आक्रमण किया था, यह स्पष्ट रूप से असत्य है क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आक्रमणकारी को यह जानना चाहिये कि उसका कार्य उचित नहीं है, अतः उसको दंड देना तो नहीं बरन् यदि उसके दोष बिना दंडित किये हुए छोड़ दिया जाय तो यह अन्याय होगा। जर्मनी की सरकार में जिन पदों पर वे आसीन थे, उन पदों से प्रतिवादियों को अथवा कम से कम उनमें से कुछ को जर्मनी द्वारा हस्ताक्षरित उन सन्धियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, जिनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने के लिये युद्ध का आश्रय लेना न्याय-विरुद्ध ठहराया गया था। जब उन्होंने पूर्ण तर्क-वितर्क के उपरान्त अपने आक्रमण तथा अप्रघर्षण के लक्ष्यों को कार्यान्वित किया, तो उन्हें यह अवश्य ज्ञात रहा होगा कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सम्पूर्ण नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। प्रश्न की

केवल इस दृष्टिकोण से देखने के उपरान्त यह प्रकट होगा कि मामले के तथ्यों में सिद्धान्त लागू नहीं है ।

सन् १९३६ में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की स्थिति पर जहाँ तक अग्रघर्षक युद्ध का सम्बन्ध है, विचार करने पर इस दृष्टिकोण ने और भी अधिक दृढ़ता पकड़ ली । युद्ध छिड़ने के समय सन् १९३६ में युद्ध-त्याग सम्बन्धी अगस्त २७ सन् १९२८ की सामान्य सन्धि जो सामान्यतः पेरिस पैक्ट अथवा केलोग-ब्रिग्गाड पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है, ६३ राष्ट्रों पर बन्धनकारी था जिनमें जर्मनी, इटली तथा जापान भी सम्मिलित थे ।

इस पैक्ट का वैध प्रभाव यह हुआ कि वे राज्य जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किये थे, तथा जो इस पर स्थिर रहे उनका भविष्य में अपनी नीति के साधन के रूप में युद्ध का आश्रय लेने का कार्य अप्रतिबन्धित रूप से निन्दित किया गया, तथा उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसको त्याग दिया । पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त, जिस किसी राज्य ने अपनी राष्ट्रीय नीति के रूप में युद्ध का आश्रय लिया उसने पैक्ट का उल्लंघन किया । न्यायाधिकरण को यह ज्ञात हुआ कि युद्ध के राष्ट्रीय नीति के रूप में पवित्र भावना से त्याग में यह साध्य अवश्य ही सम्मिलित था, कि इस प्रकार का युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधि में अवैध है, तथा वे लोग जिन्होंने ऐसे युद्ध की योजना की तथा ऐसा युद्ध लड़ा जिसके इस प्रकार अवश्यम्भावी तथा भयंकर परिणाम हुये, इस प्रकार करने में एक अपराध कर रहे थे ।

प्रतिवादियों ने यह निवेदन किया कि उन्होंने जो कुछ भी किया हिटलर के आदेशानुसार किया, अतः उन आदेशों के पालन करने के परिणामस्वरूप वे अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराये जा सकते । चार्टर के अनुच्छेद ८ में यह विशेष रूप से प्रतिबन्धित था कि “यह तथ्य कि प्रतिवादी ने अपनी सरकार अथवा एक सर्वोच्च के आदेशानुसार कार्य किया, उसको उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करेगा, लेकिन इसका विचार उसके दंड के अन्वीकरण में किया जायगा ।”

यह कि किसी सैनिक को युद्ध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय विधि को उल्लंघन करके बंध अथवा उत्पीड़न का आदेश दिया गया, ऐसे क्रूर कार्य के लिये कमी प्रतिरक्षा के रूप में नहीं स्वीकृत किया जा सकता, यद्यपि जैसा कि यहाँ चार्टर में अनुबन्धित है यह आदेश दण्ड के म्यूनीकरण के लिये निवेदित किया जा सकता है । परीक्षा की रीति जो दण्डविधि में भिन्न-भिन्न परिमाण में पाई जाती है, वह आदेश की विद्यमानता नहीं, बरन् यह है कि नैतिक चुनाव अथवा विकल्प वास्तव में सम्भव था ।

न्यायाधिकरण की सम्मति में साक्ष्य से यह स्थापित हो गया कि कुछ प्रतिवादियों द्वारा युद्ध की तैयारी तथा युद्ध करने के लिए सामान्य योजना बनाई गई। न्यायाधिकरण द्वारा यह तर्क अविवेकपूर्ण माना गया कि उस स्थान में जहाँ पूर्ण तानाशाही हो सामान्य योजना नहीं रह सकती। कोई योजना जिसके निष्पादन में बहुत से व्यक्तियों ने भाग लिया हो, फिर भी एक योजना ही है, चाहे वह उनमें से किसी एक ही द्वारा सुझाई गयी हो, तथा वे जिन्होंने योजना का निष्पादन किया यह दिखाकर उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते कि उन्होंने उस व्यक्ति के निर्देश पर कार्य किया जिसने उन्हें सुझाया। हिटलर स्वयं ही एक अप्रघर्षक युद्ध नहीं कर सकता था। उस राजनीतिज्ञों, सेनानायकों, कूटनीतिज्ञों तथा व्यापारियों का सहयोग प्राप्त करना पड़ा था। जब उन्होंने उसके लक्ष्यों का ज्ञान रहते हुये उसे अपना सहयोग प्रदान किया तो उन्होंने अपने को उसका द्वारा प्रारम्भ की हुई योजना में पक्षकार बना लिया। जब उन्हें इस बात का ज्ञान था कि वे क्या कर रहे हैं अतः इस आधार पर कि हिटलर ने उनका उपयोग किया वे निर्दोष नहीं ठहराये जा सकते।

परीक्षण की आलोचना (Criticism of the Trial).—सन् १९२८ के पेरिस के पैक्ट अथवा केलोग-त्रिप्राड पैक्ट पर बहुत ही विश्वास किया गया। यह तो भी प्रकट है कि पराजित नेताओं तथा जनरलों के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए इस प्रकार का शंकाहीन विश्वास इस पर नहीं रखा जा सकता था। प्रथमतः पेरिस के पैक्ट में सन् १८६६ हेग अभिसमय में उनमें दिये गये अनुबन्धों को प्रवृत्त करने के लिये कोई आज्ञाएँ नहीं दी गई हैं। यह कथन ठीक है कि "पैक्ट की शब्दावली एक दृढ़-व्यवसाय की शब्दावली नहीं है। यह भाषा अध्यात्म-विषयक गई है न कि विधि-विषयक"। द्वितीय यह कि यद्यपि केलोग-त्रिप्राड पैक्ट ने अप्रघर्षक युद्धों को अवैध घोषित किया तथापि इस प्रकार की अवैधता किसी प्रकार की खीचातानी के उपरान्त एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय अपराध में परिवर्तित नहीं की जा सकती थी जिसमें भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाय। अन्त में पेरिस के पैक्ट का इसके आरम्भ होने के साथ ही उल्लंघन होना आरम्भ हो गया था जबकि एक दिन सुप्रभात में मित्र-राष्ट्रों ने यह निर्णय किया कि पराजित नेताओं तथा जनरलों का अभियोजन इस पर आधारित किया जाय। सन् १९३१ में जापान ने चीन पर मंचूरिया में आक्रमण किया लेकिन पेरिस पैक्ट की पुष्टि में जापानी नेताओं पर अभियोजन चलाने के लिए एक अंगुली भी नहीं उठाई गई। इस कार्य की निन्दा किये जाने पर परिणाम यह हुआ कि जापान लीग ऑफ नेशन्स से हट गया और यही पर बात समाप्त हो गई। सन् १९३५ में इटली ने

अवीसीनिया पर आक्रमण किया और यद्यपि उस वर्ष सितम्बर में लीग की प्रतिज्ञा के अनुच्छेद १० के अन्तर्गत अवीसीनिया ने अपनी भी की तथापि पेरिस पैक्ट के उल्लंघन पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई। जर्मनी द्वारा सन् १९३६ में आस्ट्रिया तथा चेकोस्लोवेकिया के संयोजन का भी लीग द्वारा विरोध नहीं किया गया, यद्यपि उस समय वही विश्वस्य वर्तमान था, परन्तु पेरिस पैक्ट उस समय भी विस्मृत किया गया। यह जैसे कूड़े की कोठरी से तमो ढूँढ़ कर निकाला गया जब विजयी शक्तियों के लिये यह सुविधाजनक समझा गया कि वे नाजी नेताओं के परीक्षण के लिए प्रयत्नरत हो जायें। शिक (Schick) अपनी पुस्तक 'नूरम्बर्ग परीक्षण' में मित्र राष्ट्रों के इस दृढ़ कथन की शुद्धता पर गम्भीर संदेह रखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण का चार्टर ऐतिहासिक वैध पूर्व दृष्टान्त पर आधारित है। यह भी सकेत किया गया है कि विजेताओं का न्यायालय एक समुचित न्यायाधिकरण नहीं था तथा उसमें तटस्थ और जर्मन न्यायाधीशों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये था। कितनी ही खोचातानी की जाय इसको अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं कहा जा सकता। प्रोफेसर स्मिथ का तर्क है कि परीक्षण ने निष्पक्षता के आधारभूत सिद्धांतों का ही उल्लंघन किया—निष्पक्षता जिसका प्रतीक न्याय की वह मूर्ति है जो धन्धी है तथा जिसके हाथ में एक तराजू है जिसके दोनों पलड़े बराबर हैं। "The trial has violated the fundamental principle of impartiality—the ideal symbolised by the traditional figure of Justice blindfolded and holding a balanced scale" (H A Smith—The Crisis in the Law of Nations, p. 47)। नौजितमाल न्यायालयों तथा सैनिक न्यायाधीशों की शक्ति जिनमें न्यायाधीश सर्वदा अभिग्रहण करने वाले राज्य के व्यक्ति और दूरदर्शन परीक्षण से कोई समानता नहीं रखता। नौजितमाल न्यायालय कोई शांतिपूर्ण विवाद से युक्त नहीं है, फिर भी ऐसे एकपक्षीय परीक्षणों में अन्तिम निर्णय बिना पक्षपात किये हुए हो जाता है उसके भय को दूर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नौजितमाल न्यायालय स्थापना करने की बातचीत जारी है।

का उल्लंघन होता है। "The Charter applied with retrospective effect, which was a rule contrary to Municipal Law of civilized nations, and was, therefore, in violation of International Law"

प्रोफेसर स्मिथ ने आगे यह विचार प्रकट किया है कि सन् १९४२ तक ब्रिटेन की सैनिक विधि की पुस्तिका में एक अनुच्छेद (अध्याय १४ अनुच्छेद ४४३) ऐसा था कि संप्रभु के आदेश युद्धापराधों के आरोपों के लिये एक उपयुक्त प्रतिरक्षा का कार्य करते थे। अप्रैल सन् १९४२ में युद्ध वायसलिय ने एक सशोधन द्वारा संप्रभु आदेशों की प्रतिरक्षा समाप्त कर दी। प्रोफेसर स्मिथ का कथन है कि यह घटनोत्तर (ex post facto) विधान के चरमसीमा पर पहुँचे हुये होने का एक सबल उदाहरण है।

परीक्षण के विरुद्ध मुख्य धारणा यह थी कि किसी सरकार के सदस्यों तथा सेवकों पर अपने देश को अग्रघर्षण युद्ध में ले जाने का अभिप्राय चलाने का अर्थ एक पूर्वकालिक प्रभावकारी दण्डविधान बनाना है। इससे दण्डविधि के उस व्यापककारी सिद्धांत का उल्लंघन होता है जिसके अनुसार किसी कार्य के लिये दण्ड नहीं दिया जा सकता था, जो कि उस समय प्रवर्तित विधि द्वारा परिभाषित न किया गया हो तथा जिसके लिये दण्ड नियत न किया गया हो। यह स्पष्ट है कि नूरम्वर्ग परीक्षण एकपक्षीय था। युद्धापराधियों को सम्पूर्ण रूप से दण्ड देने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया जिनमें मित्र राष्ट्रों के भी अपराधी सम्मिलित हैं। मृत जर्मनों द्वारा किये गये अत्याचारों का प्रश्न केवल एक परिमाण मात्र का है। रूस ने सन् १९३६ में फिनलैण्ड पर आक्रमण करने में पेरिस पैक्ट का घोर उल्लंघन किया था कि तु इसमें सन्देह नहीं कि उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का निश्चय कभी नहीं किया गया।

वोरबेट अपने परिणामों को इस कथन के साथ समाप्त करते हैं कि न्यायाधिकरण की "कायवाहियाँ, चाहे उनकी वर्णनशीली कितनी ही सुंदर रही हो, चाहे उनका पथ प्रदर्शन इस निष्कपट प्रयास द्वारा हुआ हो कि निर्दोष छूट जाय तथा जिनके विरुद्ध अपराध सिद्ध हो जाय उन पर दण्ड समान रूप से पड़े, उचित रूप से तथा कथित न्याय के पद पर नहीं पहुँचता। न्यायाधिकरण का निर्माण, इसके निर्देश की शक्तें तथा परिस्थितियाँ जिनमें कि यह बैठे, इन सब से निष्पत्ती की बाह्य विषमक प्रतियुक्तियाँ अलग हो जाती हैं, जिनसे कि कठोर न्याय उपलब्ध है। इसके द्वारा आवाहन किये गये सिद्धांतों के बीच वैध स्वरूप के सम्बन्ध में गम्भीर सन्देह निरन्तर जारी है।" उनके शब्द इस प्रकार हैं — "that the proceedings, admirable as they were in tone and guided as they were by a genuine

effort to spare the innocent and to equate punishment with the proved offence, did not amount to adjudication properly so-called. The structure of the tribunal, its terms of reference, and the circumstances in which it sat, excluded the objective guarantees of impartiality that characterize strict adjudication. There continues to be grave doubt as to the legal character of the principles which it invoked." P. E. Corbett: *Law and Society in the Relations of States*, p. 235).

**टोकियो परीक्षण (The Tokyo Trial) :**—जापान के बड़े युद्ध अपराधियों का परीक्षण भी उन्ही सामान्य सिद्धान्तों पर हुआ जिन पर कि जर्मनी के युद्ध अपराधियों का हुआ था। यह कथन किया गया कि २० जुलाई सन् १९४५ को पोद्स डम घोषणा, २ सितम्बर सन् १९४५ के प्रत्यर्पण के सलेख तथा सुद्ध पूर्व के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के चार्टर के जो सर्वोच्च सेनानायक जनरल मैक आर्थर द्वारा १९ जनवरी सन् १९४६ को स्वीकृत किया गया, इसी का अभियोजन परिणाम है। परीक्षण जून ४, सन् १९४६ को सुद्धपूर्व के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सर विलियम वेब की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ। न्यायाधिकरण ग्यारह न्यायाधीशों का बना, जिनमें उन राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे जिनका जापान से युद्ध हो रहा था तथा जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, आस्ट्रेलिया, केनाडा, फ्रांस तथा भारत सम्मिलित थे। अभियोजन चलाने वाले ११ राष्ट्रों द्वारा २८ अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग प्रस्तुत किया गया जिनमें से दो तो परीक्षणों के आलम्बित रहने की दशा में ही मर गये, तथा एक कार्यवाहियों से उन्मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसकी मानसिक दशा ने उसे अक्षम स्थिर कर दिया था।

अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत पचपन सूत्र के आरोप लगाये गये थे—

१. शान्ति के विरुद्ध अपराध (Crimes against Peace):—इस वर्ग में पूर्वी एशिया के राज्य प्राप्त करने के पद्धत्यन्त्र भी सम्मिलित हैं, साथ ही पैसिफिक और हिन्द महासागर, मन्चूरिया और चीन के राज्य हड़पने का पद्धत्यन्त्र भी था, क्योंकि १६ विशिष्ट देशों के विरुद्ध अवैध युद्ध छेड़कर जर्मनी और इटली से मिलकर विश्व का राज्य हड़पने की भी बात थी, क्योंकि इसके विरुद्ध जो भी देश खड़ा होता, उसी से युद्ध होता।

२. हत्या (Murder) :—इसके अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता की हत्या करने का पद्धत्यन्त्र भी था। इसके साथ ही जापान की सैन्य-शक्ति को यहाँ तक कि शान्ति के समय में अमेरिका, ब्रिटिश कामनवेल्थ, नीदरलैण्ड्स, और थाईलैण्ड (स्याम) की जनता के बध का पद्धत्यन्त्र भी था जो कि हेग अभिसमय (चुतौथ) तथा

अनेक सधियों का अतिक्रमण था । यह आक्रमण जापान की सैन्यशक्ति द्वारा दिसम्बर ७ और ८, १९४१, को पल-हार्वर, हाँगकाँग तथा शंघाई पर किया गया था ।

३ अन्य अभिसमयात्मक युद्धापराध और मानवता के विरुद्ध अपराध (Other Conventional War Crimes and Crimes against Humanity) — इनके अन्तर्गत ऐसे अपराध थे जो कि ऐसे व्यक्तियों पर थे जिन्होंने जापानी सैन्य शक्ति एवं युद्ध मिनिसटरी अफसरों को पड़्यन्त्र करके प्राधिकृत किया था कि वे सधिया तथा अन्य कानूनों का उल्लंघन सहस्रों युद्ध बन्दिओं पर नाना प्रकार के अत्याचार द्वारा करें, इसमें समुक्त राज्य, ब्रिटिश कामनवेल्थ, फ्रांस, नीदरलैण्ड्स चीन, रूस आदि की नागरिक जनता भी सम्मिलित थी ।

अभियुक्तों ने अवसर मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र यह प्रकट किया कि तथान्वित न्यायाधिकरण के हाथों उनको इस कारण न्याय न पाने का भय है कि न्यायाधिकरण के सदस्य उन राज्यों के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने जापान को हराया है और जो इस मामले में अभियोगी हैं, अतः वे उनके हाथों न्याययुक्त तथा निष्पक्ष परीक्षण की आशा नहीं कर सकते । न्यायाधिकरण ने इस तर्क का खंडन इस आधार पर कर दिया कि इसमें संदेह नहीं कि न्यायाधीश भिन्न-भिन्न विजेता राष्ट्रों में से थे, किन्तु वे वहाँ अपनी व्यक्तिगत क्षमता में उपस्थित हैं ।

न्यायाधिकरण ने मृत्युदण्ड का आदेश केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जो अन्य अपराधों के अतिरिक्त सामान्य युद्ध अपराधों को करने का आदेश देने अथवा अनुमति देने अथवा युद्ध बन्दिओं तथा नागरिक नजरबन्दिओं के सम्बन्ध में युद्ध की रूढ़ियों तथा विधियों को रोकने के विषय में पर्याप्त प्रबन्ध करने में असफल रहने के दोषी पाये गये । अभियुक्तों में से अधिकांशों को केवल शान्ति के विरुद्ध अपराधों के लिये ही भिन्न-भिन्न अवधि का कारावास दिया गया ।

न्यायाधिकरण का निर्णय ४ नवम्बर, सन् १९४८ को दिया गया ।

मतभेद प्रकट करने वाला निर्णय (Dissenting Judgment) — भारत के, डाक्टर राधा विनोद पाल का निर्णय जिसमें मतभेद प्रकट किया गया है, अप्रचर्चित युद्ध सम्बन्धी उद्देगजनक प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश डालता है ।

विभिन्न प्रमाणों के पुनरीक्षण के उपरान्त वे इस परिणाम पर पहुँचे कि युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में यथापूर्व विधि के क्षेत्र के बाहर है, केवल इसका संचालन विधि के क्षेत्र के भीतर लाया जा सका है । पेरिस का वैध विधि की अणी के भीतर तनिक नहीं आता, अतः यह युद्धस्थित राज्य की वैध स्थिति में अथवा युद्ध सलग्नता के न्यायिक क्रम में कोई नया परिवर्तन करने में असफल रहा है । कोई ऐसी रूढ़ि

विधि विकसित नहीं हुई जिससे युद्ध एक अपराध हो जाय। अन्तराष्ट्रीय समाज स्वतः ऐसी नींव पर नहीं खड़ा है जिससे अन्तराष्ट्रीय जीवन में अपराध के विचार का प्रवृत्त करना समुचित हो सके। उनका कथन है कि यह जांच करना आवश्यक नहीं है कि क्या इस सम्बन्ध में द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त अन्तराष्ट्रीय विधि में कोई विकास हुआ है कि नहीं, क्योंकि चाहे विधि में उस समय विकास भी हो गया हो जिससे अब इस प्रकार का युद्ध एक अपराध हो गया हो, फिर भी उससे वर्तमान अभियुक्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ("International community itself is not based on a footing which would justify its introduction of the conception of criminality in international life It is not necessary to examine whether there had been any development of International Law in this respect since the second World War, for even if the law has since developed so as now to make such a war a crime this will not affect the present accused")

डाक्टर पाल का कथन है कि अन्तराष्ट्रीय समाज की वर्तमान स्थिति में शब्द आक्रामक (aggressor) वास्तव में "रंगपरिवर्तनशील" (chameleonic) है तथा इसका अर्थ 'हारने वाले पक्षकार के नेनागण' से ही हो सकता है।

सम्पूर्ण साक्ष्य के, जो कि न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित किया गया, सामूहिक प्रभाव से वे इस परिणाम पर पहुँचे कि जो कुछ टोचो तथा उनके समुदाय ने किया वह उन्होंने शुद्ध देशभक्ति से प्रेरित होकर किया। उनकी तुलना हिटलर समुदाय से नहीं की जा सकती, जैसा अभियोजन का सुझाव है, क्योंकि जापान की जनता उस प्रकार दासत्व से नहीं जकड़ी थी जिस प्रकार हिटलर की जर्मनों की, तथा जनता के सदस्यों को अपने धर्म, विश्वास तथा व्यवहार के सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता थी। इसके अनुसार जनवरी १, सन् १९२८ से सितम्बर २, सन् १९४५ तक अथवा किसी अन्य समय में एक व्याप्त तथा निरंतर जारी रहने वाले लक्षण का अथवा किसी भी लक्षण तथा स्वरूप का न कोई पड्यन्त्र तो कभी बना अथवा वर्तमान या कार्यशील रहा और न प्रतिवादियों में से, न कोई भी किसी समय, किसी ऐसे पड्यन्त्र का सदस्य रहा।

विद्वान् न्यायाधीश ने यह और भी मन्तव्य प्रकट किया कि अन्तराष्ट्रीय विधि में पड्यन्त्र स्वतः अभी कोई अपराध नहीं है।

अतः विद्वान् न्यायाधीश ने यह मन्तव्य दिया कि प्रत्येक तथा सब अभियुक्त अभियोग में दिये गये प्रत्येक तथा सब आरोपों के लिए निर्दोष माने जाने चाहिए तथा उनको इन सब आरोपों से विमोचित कर देना चाहिए। ("As a judicial tribunal, we cannot behave in any manner which may



Justify the feeling that the setting up of the Tribunal was only for the attainment of an objective which was essentially political though cloaked by a judicial appearance.....The name of justice should not be allowed to be evoked only for the prolongation of the pursuit of vindictive retaliation. The world is really in need of generous magnanimity and understanding charity..... When time shall have softened passion and prejudice, when reason shall have stripped the mask from misrepresentation, then justice, holding evenly his scales, will require much of past censure and praise to change places.")

“एक न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में, हम किसी ऐसे ढंग से आवरण नहीं कर सकते जो इस भावना को न्यायोचित सिद्ध कर सके कि न्यायाधिकरण का गठन केवल ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था जो कि अनिवार्य रूप से राजनीतिक थे, भले ही उसे एक न्यायिक आवरण में ढँक दिया गया था। न्याय का नाम केवल इस प्रयोजन से लिये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये कि दंडात्मक बदले के अनुगमन को सख्त किया जाय। आज के विश्व में वास्तव में उदार आशय और सूझ-बूझ की आवश्यकता है। समय जब सवेगों और प्रकृति को शांत कर सकेगा, जब विवेक भ्रामक प्रस्तुतिकरण का स्थान ग्रहण कर सकेगा, तभी न्याय के लिए वांछित होगा कि वह अपने तराजू को समान रखते हुये अतीत की निन्दा कर सके और स्थान-परिवर्तन की सराहना कर सके।

**जनवध (Genocide) :**—जनवध के अपराध ने कुछ महत्त्व का रूप धारण कर लिया है तथा वह नाज़ी युद्ध अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियोगों में सम्मिलित था।

जनवध अन्तर्राष्ट्रीय विधि के लिए एक नयी धारणा है तथा इसका अर्थ “राष्ट्रीय, जातीय अथवा धार्मिक समूहों का विनाश” है। यह कहा गया है कि नाज़ियों के समय में जनवध का अपराध इतनी अधिक मात्रा में तथा इतने सीमातीत रूप में फैल गया था कि इस समय युद्ध को उस योजना के केवल एक भग के रूप में देखा जाता है। नाज़ियों द्वारा यहूदी जाति के उन्मूलन का प्रयत्न स्पष्ट रूप से जनवध का अपराध था।

जनवध पर संयुक्त राष्ट्र संधि के चार्टर ने उन बातों को जिनका लक्ष्य राष्ट्रीय, जातीय अथवा कुल समूहों को विनष्ट करने का है, इस रूप में दण्डनीय बनाया है, चाहे वे राष्ट्र के शासकों, सार्वजनिक पदाधिकारियों अथवा असार्वजनिक

व्यक्तियों द्वारा बिये गये हैं । प्रतिज्ञा जनवरी १९५६ तक ५६ राष्ट्रों द्वारा सत्यापित की गई है ।

**अन्तर्राष्ट्रीय दण्डिक न्यायालय ( International Criminal Court ) :—**अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं को उल्लंघन करने के लिए आरोपित व्यक्तियों को अभियोजित करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय दण्ड न्यायालय की स्थापना जो इस प्रकार का सर्वप्रथम न्यायालय होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा द्वारा दिसम्बर सन् १९५० में स्वीकृत किया गया । प्रस्तावित न्यायालय के लिये एक सविधि बनाने के उद्देश्य से इसके पाँचवें अधिवेशन में सत्रह राष्ट्रों को एक समिति बनाई गई ।

यह सन्देहजनक है कि न्यायालय राष्ट्रों के मुख्य कर्तव्यों को ग्रहण करने के स्वीकार-पत्र के आधार पर बिना पूर्ण ऐक्य तथा सहयोग के प्रभावशाली रीति से कार्य कर सकता है । केवल एक विश्व सरकार ऐसे न्यायालय के लिये क्षेत्राधिकार प्राप्त कर सकती है तथा उसकी प्रतिभूति दे सकती है । फिर भी, ऐसे न्यायालय के लिए एक सविधि का मसौदा सन् १९५३ की अन्तर्राष्ट्रीय दण्ड क्षेत्राधिकार समिति द्वारा तैयार किया गया जिसकी बैठक अगस्त २०, सन् १९५३ को समाप्त हुई । पुनरीक्षित सविधि के मसौदे ने अन्तर्गत न्यायालय को उन व्यक्तियों के परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार होगा जिन पर ऐसे अपराधों का आरोप लगा हो जो सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा स्वीकृत हो । नयी सविधि के मसौदे में अपराधों का स्वरूप प्रदर्शित नहीं किया गया है तथा इनकी परिभाषा भविष्य के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं के लिये छोड़ दी गई है जो राष्ट्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से १९४८ के जनवरी के अभिसमय की तरह सत्यापित की जाएंगी ।

**बन्धक-व्यक्तियों का घब एक युद्धापराध (The Killing of Hostages as a War Crime) —**मोपेनहेम का कथन है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने एक भयावह कार्य आरम्भ किया, और वह कार्य यह था कि वह बन्धक व्यक्तियों को अपनी सेना द्वारा दखल किये गये क्षेत्र में ले जाना, और उन्हें उस समय गोली मार देना, जबकि उसे यह आभास हो कि नागरिकों ने जर्मन टुकड़ियों पर गोली चलायी है ।<sup>१</sup> ऐसी कार्यवाही द्वितीय विश्व युद्ध में और भी बड़े पैमाने पर की गई । द्वितीय विश्व-युद्ध में बन्धक व्यक्तियों को मार डालने की यह जर्मन नीति, उसके द्वारा विजित क्षेत्रों में वहाँ के आन्दोलन को दबाने के अभिप्राय से अपनायी जाती थी ।

1: Oppenheim's International Law, Vol II, p 591

लॉर्ड राइट (Lord Wright) के अनुसार "Hostage means an innocent member of the population of the occupied country who is seized and held in custody and dealt with and generally shot in order to terrorize and repress the resistance movement. These so-called hostages who are slaughtered in this way are simply innocent non-combatants. The term 'reprisal-prisoner' also does not differ essentially in its meaning from hostage."<sup>१</sup> बन्धक का तात्पर्य उस अधीन किये गये क्षेत्र की जनता के ऐसे निर्दोष व्यक्तियों से है, जो कि गिरफ्तार कर लिये जाते हैं और अधिरक्षा में रक्खे जाते हैं और क्रांतिकारी आन्दोलन को दबाने के लिये, भारतक उत्पन्न करने की दृष्टि से मार डाले जाते हैं। ये तथाकथित बन्धक व्यक्ति, जो कि इस रूप में काट डाले जाते हैं वे सीधे-सादे सैनिक व्यक्ति हुआ करते हैं। 'रेप्राइजस प्रिजनर' शब्द के अन्तर्गत जो अभिप्राय होता है, सामान्यतः 'बन्धक व्यक्ति' के अन्तर्गत भी वही है।

नूरम्बर्ग परीक्षण में भी बन्धक व्यक्तियों का बधन अपराध माना गया था; और अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक-न्यायाधिकरण का निर्णय था कि बन्धक-व्यक्तियों को रोकने और दंडित करने की जर्मन कार्यवाही उचित नहीं थी।

ग्रोशस (Grotius) का भी कथन है कि बन्धक-व्यक्तियों का उस समय तक बध नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि वे स्वयं कोई ऐसा अपराध करने के भागी न हों।

जेम्स विल्फ्रेड गार्नर (James Wilfred Garner) ने 'इन्टरनेशनल लॉ ऐंड दी वर्ल्ड वार' में अवलोकन किया है कि यद्यपि हेग-अभिसमय में बन्धक व्यक्तियों का विशिष्टतः नाम नहीं लिखा हुआ है, फिर भी, व्यवहारतः प्राधुनिक सभी विद्वान् इस बात से सहमत हैं कि बन्धक-व्यक्तियों को युद्ध-बन्धियों के समान व्यवहार मिलना चाहिए। इसलिए वे मृत्यु के भागी नहीं हो सकते, या ऐसी कठोरताओं से अधिक के लिए भी भागी नहीं हैं जिन्हे सामान्यतः सैनिक-बन्धियों को सहन करनी पड़ती है। उन्होंने आगे लिखा है कि जर्मनों द्वारा बन्धकों को ले जाने और मार डालने की संपूर्ण नीति मानवता और न्याय की सामान्य सम्य अवधारणा के सर्वथा प्रतिकूल है, क्योंकि इस नीति से ऐसे व्यक्तियों को दंड मिलता है, जो कि सर्वथा निर्दोष हैं और यह कि जिन पर किसी प्रकार के अपकार का दायित्व नहीं सौंपा जा सकता।

१. Lord Wright's Article in the British Year Book of International Law, 1948, p. 296.

लॉर्ड राइट का निष्कर्ष है कि सिद्धान्त और प्राधिकार दोनों रूपों में बंधकों को भार डालना युद्ध-विधि के प्रतिकूल है और यह कि किसी भी परिस्थिति में यह अनुमत नहीं है। इसे 'हत्या' (Murder) की सजा दी जायेगी।

जेनेवा कन्वेंशन, १९४९ के अनुच्छेद ३४ में, जिसमें कि युद्ध के समय नागरिक जनता के संरक्षण का उपबन्ध है, बन्धक-व्यक्तियों को ले जाने के लिए स्पष्टतः निषेध किया गया है।

युद्ध-अपराधियों, विद्रोहियों और राज्यद्रोहियों के लिए शरण-स्थान (Asylum for War Criminals, Quislings and Traitors)—द्वितीय विश्व-युद्ध के उपरान्त से अनेक बहुपक्षीय संधियों में यह उपबन्ध है कि युद्ध-अपराधियों के निष्कासन (extradition) की कार्यवाही की जाय। युद्ध-विधियों के विरुद्ध किये गये अपराध स्वभावेन राजनीतिक अपराध नहीं हुमा करते और इसलिए उनके द्वारा आत्म-समर्पण किये जाने पर आवश्यक नहीं है कि राजनीतिक अपराधियों की भाँति उन्हें भी परम्परागत आवास में रखा जाय। यह नियम विद्रोहियों (Quislings) और राज्यद्रोहियों (traitors) के प्रति व्यवहृत नहीं होता। उनके अपराध राजनीतिक ढंग के होते हैं, भले ही युद्ध के समय उसे सबसे बड़े अपराध की संज्ञा दी जा सके। यहाँ तक कि दिनांक ३० अक्टूबर १९४३ की मास्को उद्घोषणा और संयुक्त राष्ट्रों की साधारण सभा के प्रस्ताव दिनांक १३, फरवरी १९४६ में भी उपबन्धित है कि समर्पण केवल युद्ध-अपराधियों का किया जाय, विद्रोहियों (Quislings) और राज्यद्रोहियों (traitors) का नहीं।

युद्धापराध परीक्षण और युद्धविधियाँ (The War Crimes Trials and the Laws of War) :—द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय अपराध-विधि में क्षेत्र का बहुत ही व्यापक विस्तार हो गया है। बहुत से सैनिक-न्यायाधिकरणों, जो कि युद्ध के बाद बनाये गये, ने केवल उन सिपाहियों को ही दोषी नहीं ठहराया जिन्होंने वस्तुतः शारीरिक रूप से युद्ध कार्य में भाग लिया या नाशक अग्नि बरसाया, बल्कि उच्च वर्ग के अफसरों और चीफ आफ स्टाफ तथा नागरिकों को भी इस अपराध से मुक्त नहीं माना।

जहाँ तक इस तर्क का सम्बन्ध है, दूरम्बर्ग परीक्षण तथा अन्य परीक्षण के प्रसंग में कहा जा चुका है कि वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर किसी अपराध के कृत्य करने पर, उस व्यक्ति को आभार और दायित्व से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि कृत्य करने वाला इस तथ्य को माली-भाँति जानता था, कि वह जो कुछ भी करने जा रहा है, वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से एक अपराध है। ऐसे प्रसंगों में वास्तविक तथा किसी आदेश की उपस्थिति को नहीं, बल्कि इस तथ्य को आधार माना

जाता है कि क्या कृत्य करने वाले के समस्त नैतिकता का धरनाया जाना सम्भव था। आदेश की उपस्थिति अपराधी के दण्ड निर्धारण में मात्रा कम करने में भले ही सहायक हो, किन्तु उसे निर्दोष सिद्ध करने में कदापि सहायक नहीं हो सकती।

## अध्याय ४४

### परावर्तन तथा पुनर्ग्रहण या पुनः बन्दीकरण का सिद्धान्त

#### ( The Doctrine of Postliminium and Recapture )

**पृष्ठ भूमि :—**परावर्तन ( Postliminium ) के सिद्धान्त की उत्पत्ति रोमन विधि के नियमों की तुलना से हुई है, जिसके अनुसार जैसा लीरेंट ने बताया है कि व्यक्तियों तथा वस्तुओं को शत्रु के अधिकार से मुक्त करने पर अपनी मूल स्थिति वापस मिल जाती थी। रोमन विधि का परावर्तन नियम जैसा ऊपर कथित है, व्यक्तियों तथा वस्तुओं दोनों से सम्बन्धित था। व्यक्ति के सम्बन्ध में नियम यह था कि उसकी बन्दीपुह से मुक्ति तथा रोमन साम्राज्य में वापस आने पर एक रूमी नागरिक को यह अधिकार था कि अपनी मूल वैध स्थिति में पुनः संस्थापित कर दिया जाय। अभिप्रेत भयवा उनको जो अपने देश में अवैध रूप से वापस पाये हो यह अधिकार नहीं दिया जाता था। आधुनिक काल में गुलामी प्रथा के लोप हो जाने से परावर्तन के सिद्धान्त का उपयोग केवल क्षेत्र तथा चल सम्पत्ति के लिये ही सीमित रह गया है। वस्तुओं के सम्बन्ध में रोमन विधि का अभिप्राय यह था कि वे वस्तुएँ जो शत्रु द्वारा ले ली जाती थी, उस अवधि में जिसमें वे शत्रु के अधिकार में रहती थी, प्रत्याहृत मानी जाती थी, किन्तु पुनः प्राप्त होने पर वे रोम-देशवासी पूर्व-स्वामी को लौटा दी जाती थी।

**अभिप्राय तथा प्रयोग :—**अन्तर्राष्ट्रीय विधि में परावर्तन ( Jus postliminium ) युद्ध का ही प्रसंग माना गया है, तथा इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई राज्य जो अन्य राज्य की अस्थायी अधीनता में हो अपनी स्वतन्त्रता विजय के पूर्ण होने के पूर्व ही प्राप्त कर सके, चाहे युद्ध चलने के बीच हो मे भयवा उसकी समाप्ति पर, तो अधीनता भयवा शत्रुतापूर्ण दखल के पूर्व वस्तुओं की जो वैध स्थिति थी, वह पुनः संस्थापित हो जाती है।

प्रोफेसर हॉल ने परावर्तन इन शब्दों में वर्णन किया है—“जब कोई क्षेत्र जो शत्रु के अधिकार में रहा हो, तथा जनता जिस पर उसका नियन्त्रण रहा हो

युद्ध की प्रगति के बीच अपने राज्य के अधिकार में पुनः वापस आ जाय, भयवा जब कोई राज्य जो पूर्णतः अधीनस्थ कर लिया गया हो विजय के स्पष्ट रूप व्यवस्थित होने के पूर्व ही, अपने को भारोन्मुक्त कर ले, भयवा अन्त में जब कोई राज्य भयवा राज्य का भाग विदेशीय प्रभुत्व से किसी मित्र द्वारा विजय के समेकन के पूर्व ही मुक्त कर दिया जाय तो शत्रुतापूर्ण दखल के पूर्व विद्यमान वस्तुओं की वैध स्थिति पुनः स्थापित हो जाती है।" ("When a territory which has been occupied and a population which has been controlled by an enemy, comes again into the power of its own State, during the progress of a war, or when a State, the whole of which has been subjugated, throws off the yoke which has been placed upon it before a settled conquest has been clearly effected, or finally when a State or a portion of a State is freed from foreign domination by the action of an ally, before a conquest of it has been consolidated, the legal state of things, existing prior to the hostile occupation is re-established.")

तटस्थ देशों में इसके प्रवर्तन की संभावनाएँ (Its Enforceability in Neutral Countries) :—यह अधिकार तटस्थ राज्यों में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि तटस्थ प्रत्येक युद्धस्थित की माँगों को न्याययुक्त समझने के लिये बाध्य है, तथा यदि उसके अधिकारों का उल्लंघन न हुआ हो, तो दोनों पक्षकारों की प्राप्ति को समुचित समझते हैं।

चल-सम्पत्ति पर प्रभाव (Effect on Movable Property) :—समस्त चल सम्पत्ति अभिग्रहण करने वाले के अधिकार में चली जाती है चाहे नीजितमाल युद्ध के बीच सशुद्ध में पकड़ा गया हो भयवा अन्यथा। यदि शत्रु उसे एक तटस्थ का समर्पित कर देता है तो पूर्ववर्ती स्वामी का उसको वापस माँगने का अधिकार चला जाता है। ऐसी व्यक्तिगत चल-सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो युद्ध सामग्री के रूप में अभिग्रहीत की जाय उसके स्वामी ऐसे अभिग्रहण के लिये क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं। यदि सम्पत्ति अभिज्ञात की जा सकती हो तथा उसका पता लगाया जा सकता हो तो वह अपने स्वामी को वापस चली जायगी। युद्ध सामग्री के रूप में अभिग्रहीत सार्वजनिक चल सम्पत्ति, यदि शत्रु के हट जाने के उपरान्त वह पाया जाय कि वह अग्रयुक्त है, तो पूर्ववर्ती राज्य को वापस चली जाती है।

अचल सम्पत्ति पर प्रभाव (Effect on Immovable Property) :—शत्रु द्वारा युद्ध में अभिग्रहीत अचल सम्पत्ति पर अधिकार उस समय तक,

नहीं होता है जब तक कि वह प्रदेश जिसमें वह सम्पत्ति स्थित है विजयी द्वारा अधिष्टृत प्रदेश में सम्युक्त न कर लिया जाय अथवा उसे विजित तथा अधीनस्थ न कर लिया जाय । सार्वजनिक अचल सम्पत्ति शत्रु के हट जाने के उपरान्त उस सरकार के पास चली जाती है जो न्यायानुसार उसकी अधिकारिणी हो । व्यक्तिगत संपत्ति युद्धस्थित अधिकारी द्वारा उपभोग नहीं की जा सकती । वह केवल उनका उपयोग कर सकता है । शत्रु के हट जाने पर वैयक्तिक स्वामी उनको वापस पाने का अधिकार रखता है ।

**ऋण शोधन ( चुकाना ) ( Payment of Debt )** — यदि ऋण विजय के उपरान्त अपनी सरकार स्थापित करने वाले विजयी को दिया गया हो तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जाता है कि वह चुका दिया गया है, तथा नष्ट हो गया है ।

**इसका प्रभाव ( Its Influence )** :—परावर्तन के सिद्धान्त ने वर्तमान समय में अपना अधिकांश महत्व इस कारण खो दिया है कि शान्ति की संधियों में जो बहुत ही प्रवीणता से तैयार की जाती हैं, पूर्व शत्रुओं के बीच का प्रत्येक सूक्ष्म विवरण दिया रहता है । जहाँ शान्ति की संधि मौन हो, और उसमें अधिकारों अथवा सम्पत्ति के सम्बन्ध में जिनमें युद्ध के उलट फेर के मध्य वस्तुतः परिवर्तन हुआ हो, कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यवस्था न दी गई हो, तो सम्पत्ति तथा कर्तव्यों तथा वैयक्तिक स्थिति के विषय में यह सिद्धान्त बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है तथा जैसा फिलिमोर का कहना है ये सम्पत्ति के अधिकार वास्तव में शत्रु के बल के दबाव से उन्मुक्त होकर उन्हीं खोतों में बहने लगते हैं जिनमें वे उस बल के दबाव से हटाये जाने के पूर्व बहते थे । फिलिमोर आगे कहते हैं कि मूलतः जिस पर यह सिद्धान्त आधारित है, यह है कि ऐसे अधिकार जो समुचित रूप से प्राप्त किये गये हो बिना उस राज्य की सम्पत्ति के जिसका कि मूल स्वामी निवासी है, स्थायी रूप से न तो किसी व्यक्ति द्वारा न किसी शत्रु राज्य के कार्य द्वारा, छीने नहीं जा सकते । अतः यह एक स्थिर नियम रहा है कि अचल सम्पत्ति की दशा में विजयी का वास्तविक वंशा भी अन्तरण का ऐसा अधिकार उन समय तक नहीं देता जिसका मुख्य मूल स्वामी का अधिकार छीन लेना हो जब तक कि ऐसा परिणाम किसी संधि की शर्तों का भग्न न बनाया गया हो अथवा राष्ट्र के किसी सावजनिक कार्य द्वारा स्थापित न किया गया हो । उन्हीं के शब्दों में -

'The principles upon which the doctrine rests is that rights duly acquired cannot be permanently taken away, either by the act of an individual or by the act of an enemy State, without the consent of the State, to which the original owner belongs. It has therefore, been the

established rule that, in the case of immovable property even actual possession by the conqueror does not confer a right of alienation which, after the conqueror has departed, will ensure to oust the original owner, unless such a result has formed part of the stipulations of a treaty or been ratified by some public act of the State "

—Phillimore.

**सिद्धान्त की परिसीमा (Limitations of the Doctrine) :—**परावर्तन सिद्धान्त की परिसीमाये निम्नलिखित हैं :—

१ यह सिद्धान्त उस दशा में लागू नहीं है जब कि किसी क्षेत्र का विजयी द्वारा कब्जा करने तथा प्रशासन स्थापन करने द्वारा स्वायत्तीकरण हो गया हो, अथवा जब कोई क्षेत्र संधि द्वारा शत्रु को समर्पित कर दिया गया हो । विजय अर्थात् कब्जा तथा प्रशासन की दशा में विजित राज्य की सार्वभौमिक सत्ता समाप्त हो जाती है । इस प्रकार हेस्से-केसल (Hesse Cassel case) वाले मामले में इस सिद्धान्त का प्रयोग इस आधार पर नहीं किया गया कि विजयों ने संधियों द्वारा पूर्ण स्वत्व प्राप्त कर लिया था तथा निर्वाहक संपत्ति पर अपना स्वत्व स्थापित नहीं कर सकता था । इस सिद्धान्त का प्रयोग केवल भ्रष्टाचारी दखल अथवा अधीनता की दशा में किया जाता है जब विजय का समेकन न हुआ हो ।

२ सटस्थ देशों में इस सिद्धान्त का प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है ।

३ अधिकार करने वाले द्वारा किये गये न्यायोचित कार्य इस सिद्धान्त के विषय नहीं हो सकते । ओपेनहेम का कथन है कि परावर्तन का सिद्धान्त पूर्ववर्ती सैनिक अधिकारी के अधिवृत्त क्षेत्र, व्यक्तियों और उस पर स्थित सम्पत्ति से संबंधित ऐसे कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं रखता जिनको वह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार करने के लिये समर्थ था, उदाहरणार्थ अपराधियों को दंड देना ऐसी चल सम्पत्ति का विक्रय जिसको अधिकार करने वाला स्वायत्तीकरण के लिये समर्थ था । वास्तव में उस राज्य को जिनके अधिकार में ऐसे क्षेत्र वापस आ गया हो इन न्यायोचित कार्यों को स्वीकृत करना चाहिये ।

४ अधिकार करने वाले द्वारा चन्दा लगाना, अधिवासन तथा करों का संग्रह पूर्वस्थिति पर पुनः स्थापन के सिद्धान्त के प्रयोग से उन्मुक्त है ।

५. क्षेत्र पर अधिकार करने वाले शत्रु द्वारा अभिग्रहीत राज्य की अथवा व्यक्तिगत भूचल सम्पत्ति मूल स्वामी ने पास वापस नहीं जानी यदि शत्रु का स्वत्व विजय अथवा संधि द्वारा पूर्ण कर दिया गया हो ।

६ सन् १८६४ के नाविक नौजितमान अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई जहाज अथवा उसमें लदा हुआ सामान उस युद्ध के बीच किसी समय में



पुनर्ग्रहण किया जाय जिसमें कि अभिग्रहण हुआ था तो उसको पुनर्ग्रहण संपत्ति के मूल्य के कुछ अंश दिये जाने पर वास्तविक मालिक को दे देना चाहिये। यह 'दिया जाना' परिभाषानुसार उबार या पुरस्कार (salvage) (जहाज अथवा उस पर की सामग्री को बचाने का पुरस्कार) कहा जाता है तथा एक प्रकार की क्षतिपूर्ति के रूप में उन बचाने वालों को दिया जाता है जिनकी सहायता से कोई जहाज अथवा उस पर की सामग्री समुद्र में भय अथवा नाश से बचाई गई हो। पुरस्कार अथवा उबार का यह दिया जाना भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न है तथा इस विषय में कोई एकरूपता नहीं है।

**हेसे-कैसल का मामला (Hesse-Cassel Case)** — परावर्तन के सिद्धान्त पर प्रमुख विवाद हेसे-कैसल के इलेक्टर के सम्बन्ध में है। विवाद के तथ्य, निस्संदेह कुछ उलझे हुये हैं, किन्तु संक्षेप में वे इस प्रकार हैं :—

फ्रांस और प्रशा के बीच १८०६ के युद्ध के परिणाम हेसे-कैसल के इलेक्टर तक पहुँचे, जो कि एक तटस्थ राज्य-क्षेत्र था। फ्रांस की सेना ने उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और वहाँ के इलेक्टर को मार भगाया। उनका तर्क यह था कि इलेक्टर की तटस्थता फ्रांस की सेना की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।

हेसे-कैसल फ्रांस के सैनिक शासन के अन्तर्गत १८०७ में प्राप्त तक रहा और उस समय नैपोलियन ने इसके बहुत बड़े भाग को नवनिर्मित राज्य वेस्ट-फैलिया में निगमित कर लिया। यह टिलसिट की शान्ति (Peace of Tilsit) के परिणाम-स्वरूप हुआ था, जिसके द्वारा रूस और प्रशा ने जेराम बोनापार्ट को वेस्टफैलिया का सम्राट स्वीकार कर लिया था। नैपोलियन और जेरोम में २२ अप्रैल १८०८ को बर्लिन में इस बात पर समझौता हुआ था कि हेसे-कैसल के ध्वंस को व्यवस्थित किया जाय।

जेरोम ने घोषित किया कि वह नैपोलियन के क्षेत्र में उन सभी व्यक्तियों को अपनी ओर से शरणमुक्त करता है जो फ्रांस के प्रसामक नैपोलियन का ऋण का मुग्ध-तान कर दें। इसी प्रकार की उदारतापूर्ण घोषणाएँ नैपोलियन की ओर वेस्टफैलिया के प्रजाजन के प्रति की गई थी।

१८१३ में नैपोलियन पैप्सिक (Potsdam) के युद्ध में शक्ति-शीला हो गया और हेसे के इलेक्टर का पुत्र अपने पैतृक राज्य क्षेत्र की ओर लौटा और दिसम्बर १८१३ में मित्र शक्तियों द्वारा उसने पिता के स्थल को स्वीकार लिया गया, जिसका सत्यापन पुनः १८१४ में पेरिस की शान्ति (Peace of Paris) में हुआ।

काउण्ट वॉन हाइन (Count von Hahn) एक बहुत बड़ी भूमि मालिक का स्वामी था। उसने हेसे-कैसल के राजकुमार से शरण रूप में घन लिया था।

उमने इस ऋण का केवल एक भाग नैरोलियन को अदा किया, और शेष के लिए उसे नैरोलियन की धार से उन्मुक्ति मिल गई ।

उस वाउचर की मृत्यु के पश्चात्, हेसे-वैसल के राजकुमार ने फिर शक्ति प्राप्त करने के पश्चात् अपने धन की अदायगी की माँग की । उमने नैरोलियन द्वारा प्रदत्त उन्मुक्ति को अवैध ठहराया और यह सिद्ध किया कि उम धन का नैरोलियन द्वारा अभिग्रहण एवं डाकू के अभिग्रहण के रूप में था, एक विजेता के रूपा में नहीं ।

अपील के अन्तिम न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि राजकुमार का वापस आना अपनी पूर्व-सरकार के तारतम्य में क्रमिक नहीं माना जा सकता और इसलिए निष्कर्ष यह था कि सभी ऋण, भले ही समूचा धन अदा किया गया अथवा नहीं, जिसके लिए नैरोलियन ने उन्मुक्ति प्रदान कर दी, वैध माना जायगा और तथ्यतः उसे भुगतान किया हुआ समझा जायगा ।

परिणाम यह हुआ कि इस विवाद में परावर्तन का सिद्धान्त लागू नहीं हो सका । इसका आधार यह था कि इलेक्टर का विजयता उस पर पूर्ण स्वत्व प्राप्त कर चुका था ।

— — —

## अध्याय ४५

### युद्ध का समापन

#### (The Termination of War)

युद्ध समापन की रीतियाँ (Modes of Termination of War) — हेफ्टर (Heffter) का कथन है (as quoted by Phillimore in his International Law, Vol. III, p 770) कि युद्ध को समाप्त करने तथा शान्ति पुनः स्थापित करने की तीन रीतियाँ हैं ।

१ दोनों पक्षकारों की ओर से शत्रुतापूर्ण कार्यों को वास्तविक रूप से बन्द किया जाना तथा शान्ति के सम्बन्धों का वास्तविक रूप से नवीनीकरण ।

२ एक युद्धस्थित का बिना किसी शर्त के दूसरे की अधीनता स्वीकार करना अथवा जैसा पिट कोबेट का कथन है कि विजय तथा एक युद्धस्थित राज्य का दूसरे द्वारा अपने में पूर्ण रूप से समावेश किया जाना ।

३ युद्धस्थित के बीच नियमानुसार शान्ति की संधि का किया जाना ।

युद्ध-समाप्ति की प्रथम रीति की ओर ध्यान आकर्षित करने पर शान्ति पुनः स्थापित करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि नियमानुसार युद्ध समाप्ति की एक

घोषणा की जाय। राज्यों द्वारा साधारणतया बर्तों जाने वाली रीति यह है कि ऐसी घोषणा की जाती है किन्तु इस प्रकार के भी उदाहरण हैं जहाँ युद्धकार्य मौन ह्वा से बन्द हो गये तथा वास्तविक रूप में शान्ति हो गई। स्वीडन तथा पोलैंड का युद्ध सन् १७१६ में परस्पर शत्रुतापूर्ण कार्यों के बन्द कर देने से समाप्त हो गया, लेकिन शान्ति न्यायानुसार दस वर्ष बीतने के उपरान्त घोषित की गई। फ्रांस तथा स्पेन के युद्ध (१७२०) और रूस तथा प्रशा के युद्ध (१८०१) की समाप्ति इन रीति के दूसरे अधिक उदाहरण हैं। यह रीति असंतोषप्रद है, क्योंकि इससे तब तक के युद्धस्थित तथा तटस्थों के सम्बन्धों में संदिग्धता तथा अनिश्चितता बनी रह जाती है।

तीसरी रीति अर्थात् युद्ध समाप्ति के लिये शान्ति-संधियों का किया जाना सबसे अधिक सामान्य रूप है। वार्साई की संधियों से युद्ध समाप्ति की इन रीति के उदाहरण प्राप्त होते हैं। यह सब से अधिक संतोषपूर्ण रीति है क्योंकि यह प्रादेशिक संमंजसों तथा युद्ध सम्बन्धी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करके भविष्य के सभी वाद-विवाद को समाप्त कर देती है।

**शान्ति-संधि का प्रभाव (Effect of Treaty of Peace) :—**संधि का तत्कालिक प्रभाव शत्रुतापूर्ण कार्यों का बन्द करना तथा पूर्वस्थिति पर पुनः संस्थापन करना है। इससे सामान्य व्यापारिक सम्बन्ध प्रारम्भ हो जाते हैं। युद्धबन्दी मुक्त कर दिये जाते हैं। सन् १६४६ के युद्धबन्दियों से व्यवहार सम्बन्धी जेनेवा अभिसमय के अनुच्छेद ११ में यह विशेष रूप से अनुबन्धित है कि क्रियाशील शत्रुतापूर्ण कार्यों के बन्द होने के उपरान्त युद्धबन्दी बिना विलम्ब के मुक्त तथा अपने देश को वापस कर दिये जायेंगे। इन अनुच्छेद का अक्षरशः प्रतिपालन कोरिया युद्ध में विराम-संधि के लिये मुख्य बाधक रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्यस्थों ने अनिच्छुक बन्दियों को बलपूर्वक कम्युनिस्टों को वापस करने में इस आधार प्राप्त पर की कि यदि बन्दियों को उन्मोचन के उपरान्त उत्पीडन दिया गया तो अभिसमय का प्रयोजन ही असफल हो जावेगा, किन्तु कम्युनिस्टों ने अनुच्छेद की शर्तों के अनुसार जो स्पष्ट हैं उत्तरी कोरिया निवासी तथा चीनी युद्धबन्दियों को समग्र रूप से कम्युनिष्ट प्रदेश को वापस किये जाने की माँग की। अनुच्छेद ११ में वापस करने की प्रक्रिया विस्तृत रूप से दी गई है। मूल्यवान् वस्तुएँ जो युद्ध बन्दियों से छीन ली गईं हो उनको वापस कर देनी चाहिये। उनको अपने साथ अपने निजी असबाब को ले जाने की अनुमति है।

शत्रुता के कार्यों को बन्द होने के परिणामस्वरूप कूटनीतिक सम्पर्क पुनः प्रारम्भ हो जाता है। संधियों में जैसा कहा गया है क्षेत्रों के संयोजन के सम्बन्ध में स्पष्ट शर्तें रहती हैं, लेकिन किसी प्रकार की व्यवस्था न होने की दशा में व्यक्तिगत

सम्पत्ति वापस कर दी जाती है । किन्हीं नये जहाजों का अभिग्रहण तथा क्षेत्रों का दखल समुचित नहीं होता । शान्ति-संधि पर हस्ताक्षर होने के उपरान्त पुनः अधि-याचन नहीं किये जा सकते, तथा चंदा नहीं लगाया जा सकता ।

शान्ति की संधि यदि संधि में कोई विशिष्ट अनुबन्ध इसके विरुद्ध न हुआ हो तो युद्ध से पूर्व लिये गये श्रुतों अथवा की गई संधियों पर आधारित दावों को पुनर्जीवित कर देती है ।

यथाधृत (Uti Possidetis) — लॉरेंस का कथन है कि “युद्धस्थित शक्तियों के मध्य स्वतः यह माना गया है कि शान्ति-स्थापना तत्काल विद्यमान अधिकार की स्थिति को उस समय तक वैधकर देती है जब तक इसके विरुद्ध विशिष्ट उपबन्ध संधि में न दिये गये हों । यह ‘यथाधृत का सिद्धान्त’ (Uti Possidetis) कहलाता है । ऐसे नगर, जिले तथा सूबे जो शत्रु द्वारा युद्धस्थित दखल में हों विजय रूपी स्वत्व द्वारा उनके हो जाते हैं जब तक यह स्पष्ट रूप से न कहा गया हो कि उनका परिहारा कर दिया जाय । समुद्र में शत्रु से किये गये अभिग्रहण जो तब तक नौजितमाल न्यायालय द्वारा दोषयुक्त न ठहराये गये हों अभिग्रहण करने वाले की वैध सम्पत्ति हो जाती है, तथा भूमि पर ऐसी वस्तुओं का अभिग्रहण जिनका कि युद्धस्थित द्वारा विनियोग किया जाना युद्ध के नियमों के अनुसार स्वीकृत है, युक्तरूप से उसी की स्वत्व हो जाती है । (Lawrence : The Principles of International Law, p. 562) । यदि संधि में कोई विरुद्ध अनुबन्ध न हो तो विजित क्षेत्र अधिकारी के कब्जे में रह जाता है और उसे यह अधिकार रहता है कि उसे सयोजित कर ले । युद्धस्थित द्वारा अभिग्रहीत राज्य की सब चल-सम्पत्ति से लाभ उसी अधिकार में रह जाते हैं ।

युद्ध-विराम सन्धि तथा युद्ध-विश्रान्ति सन्धि (Armistice and Truce) :—

शान्ति संधियों के पहले सामान्यतः युद्ध विराम संधियाँ होती हैं जो युद्धमानों के मध्य शत्रुतापूर्ण कार्यों के अस्थायी निलम्बन के लिए स्वीकारोक्तियाँ हैं । लॉरेंस के अनुसार किसी सीमित क्षेत्र के भीतर अल्प काल के लिये तथा एक निश्चित प्रयोजन पूरा करने के उद्देश्य से क्रियाशीलता बन्द कर देना यथा मुद्दों को गाड़ने के लिए सामान्यतः सशस्त्र प्रयोग स्थगन कहलाता है, लेकिन इसको युद्ध विराम संधि कहना भी उसी के समान शुद्ध है तथा यही प्रयोग इसका आग्रहमात्रा में है । इसी प्रकार की स्वीकारोक्ति जो एक लम्बी अवधि तक विस्तृत हो तथा युद्ध के सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू हो प्रामाण्य युद्ध-विश्रान्ति संधि या ट्रूस के नाम से प्रचलित है ।

सन् १९०७ के चतुर्थ हेग सम्मेलन से सलग्न भूमियुद्ध सम्बन्धी विधियाँ तथा रुढ़ियों के विनियमों का अनुच्छेद ३७ सामान्य तथा स्थानीय विराम संधियों का भेद बतलाता है । सामान्य विराम संधियाँ युद्धस्थित राज्यों की सम्पूर्ण सैनिक क्रिया-

शीलता को प्रत्येक स्थान में स्थगित कर देती है, किन्तु स्थानीय विराम संधियाँ उनकी सैनिक क्रियाशीलता को केवल युद्धस्थित सेनाओं के कुछ भागों के बीच तथा एक नियत परिधि के भीतर ही स्थापित करती हैं।

युद्ध-विराम संधि से युद्ध की वैध स्थिति अप्रभावित रहती है। हेग विनियमों में यह व्यवस्था दी गई है कि पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा युद्ध विराम संधि का गम्भीर उल्लंघन पीड़ित पक्षकार को उसे भग करने का तथा आवश्यकता की दशा में शत्रुतापूर्ण कार्यों को तत्काल पुन आरम्भ करने का अधिकार देता है। यदि युद्ध विराम संधि की अवधि निश्चित न की गई हो, तो युद्धमानों में से कोई भी किसी क्षण क्रियाशीलता पुन आरम्भ कर सकता है, लेकिन उपबन्ध यह है कि वह अपने शत्रु को स्पष्ट तथा पर्याप्त सूचना दे।

सामान्य युद्ध-विराम संधि प्रधान सेनानायकों अथवा राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है, तथा इसमें राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा सत्यापन अपेक्षित है। आंशिक अथवा स्थानीय युद्ध-विराम संधि किसी सेनानायक द्वारा की जा सकता है क्योंकि इसमें केवल वे ही सेना बल तथा स्थान सम्मिलित रहते हैं, जो उसके तात्कालिक समादेश के अधीन हैं। इस प्रसंग में सत्यापन आवश्यक नहीं है।

प्रथम विश्व युद्ध — प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों तथा जर्मनी के मध्य समझौता होने पर नवम्बर ११, सन् १९१८ को समाप्त हुआ। इस समझौते का नाम 'युद्ध विराम संधि' (Armistice) रखा गया। इस समझौते का नाम युद्ध-विराम संधि रखना शब्द का अशुद्ध प्रयोग था क्योंकि यह एक प्रकार का आत्मसमर्पण था, तथा 'युद्ध समाप्ति' शीर्षक के अन्तर्गत पड़ता था।

द्वितीय विश्व युद्ध — द्वितीय विश्व युद्ध पराजित सेनाओं द्वारा अपने आपको बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने से समाप्त हुआ। इसके उपरान्त संधियाँ जिनसे युद्ध को समाप्ति हुई वे पराजित शक्तियों के साथ नहीं की गईं वरन् उनपर बलपूर्वक लादी गईं। जर्मनी के अनुयायी राज्यों के साथ वेरसि म फरवरी १०, सन् १९४७ को संधियाँ हस्तक्षरित की गईं। जर्मनी तथा आस्ट्रिया के साथ की गई संधियाँ एक और इङ्ग्लैण्ड और अमेरिका तथा दूसरी ओर रूस के मध्य मनु-मुटाव के प्रभावशाली कारण बनी हैं। जापान की शान्ति संधि जिसके प्रवर्तक अमेरिका तथा ब्रिटेन थे सैनफ्रांसिस्को में हुये सम्मेलन में सितम्बर ८, सन् १९५१ को हस्ताक्षरित की गई। रूस ने इस बात पर जापानी शान्ति-संधि की तीव्र आलोचना की कि इससे जापान का युद्धबन्दी के लिए पूर्णरूप से प्रोत्साहित करने की नीति प्रकट होती थी और इसे नए युद्ध का मसौदा नाम दिया गया। भारत ने जापान के साथ ९ जून, १९५२ को एक अलग शान्ति-संधि पर हस्ताक्षर किए जिसे २७ अगस्त, १९५२ को अनुसमर्थित किया गया।

## भाग ४

### तटस्थता की विधि

अध्याय ४६

तटस्थता

(Neutrality)

**परिभाषा** — लोरेस तटस्थता की परिभाषा इस प्रकार करते हैं कि यह वह स्थिति उन राज्यों की है जो युद्ध के समय मुठभेड़ में कोई भाग नहीं लेते किन्तु युद्धस्थित के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध जारी रखते हैं। तटस्थता एक अर्थ में पूर्व-कालिक स्थिति को जारी रखने का नाम है। युद्ध में प्रविष्ट होने से युद्धस्थित पारस्परिक सम्बन्धों को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन वे शक्तियाँ जो तटस्थ रहना पसन्द करती हैं बाधियाँ में किसी से भी अपने सम्बन्धों में कोई परिवर्तन नहीं होने देती तथा दोनों पक्षकारों के समान रूप में मित्र बनी रहती हैं। तटस्थता एक स्थिति है जो केवल उसी दशा में निश्चिन्ता रहती है जब युद्ध हो रहा है।

ओपेनहैम की तटस्थता की परिभाषा के अनुसार निष्पक्षता वह प्रवृत्ति है जो एक तीसरे राज्य द्वारा बाधियों की ओर ग्रहण की जाय और बाधियों द्वारा स्वीकृत की गयी हो तथा जिस (दृग्) से निष्पक्ष राज्यों तथा बाधियों के बीच अधिकार तथा कर्तव्य उत्पन्न होवे। (Neutrality is the attitude of impartiality adopted by third States towards belligerents and recognised by belligerents, such attitude creating rights and duties between the impartial States and the belligerents — Oppenheim)

अतः तटस्थता शब्द से यह व्यक्त होता है कि यह राज्य की वह वैध स्थिति है, जिससे वह दो या अधिक बाधियों के मध्य युद्ध से अपने को अलग रखता है तथा निष्पक्षता का दृग् धारण करता है। इस निष्पक्षता की अवस्था से निष्क्रिय निष्पक्षता अथवा अकर्मण्यता उपलक्षित नहीं होती यद्यपि इससे एक तटस्थ राज्य को उसके अधिकारों के उत्पन्न किये जाने की अवस्था में अपनी सीमाओं के संरक्षण करना तथा अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्राप्त होता है। तटस्थता से यह भी सम्बद्ध नहीं है कि बाधियों में से किसी से भी सम्बन्ध तोड़ दिये जायें। दूसरी ओर यह विधि तटस्थ राज्य को बाधियों व विरुद्ध कुछ अधिकारों को प्रदान करती है तथा उसको रूढ़ विधि अथवा अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय से निर्धारित कुछ कर्तव्यों के पालन करने के लिये बाध्य करती है।

अतः विकरणीक उन राज्यों को तटस्थ कहते हैं जो युद्धमान राज्यों में से किसी के साथ भी भाग न लें तथा जो उनमें से किसी से भी मैत्री की संधि से सम्बद्ध न हों ।  
 ("Those States are neutrals who take part with neither of the belligerent powers, and who are not bound to either by any alliance ")  
 यदि वे इस प्रकार से सम्बद्ध हो तो वे फिर तटस्थ नहीं बरन् मित्र हैं ।

**तटस्थता के भेद (Kinds of Neutrality) .—**अन्तर्राष्ट्रीय विधि में निम्न निम्न प्रकार की तटस्थता मान्य है । तटस्थता पूर्ण अथवा अपूर्ण (Perfect or Imperfect) हो सकती है । प्रत्येक सार्वभौम राज्य को यह अधिकार है कि उन युद्धों के सम्बन्ध में जिनमें अन्य राज्य सलग्न हो, पूर्ण तटस्थता रखें । पूर्ण तटस्थता को निरपेक्ष अथवा नैसर्गिक (Absolute or Natural) तटस्थता भी कहा जाता है । अपूर्ण तटस्थता उस दशा में पायी जाती है जब कोई राज्य भले ही तटस्थ हो, फिर भी युद्ध से पूर्व की गई हुई किसी संधि के परिणामस्वरूप बाधियों में से किसी एक को प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कुछ सहायता देने को बाध्य हो । इसको संप्रतिबंध तटस्थता (Qualified Neutrality) भी कहा जाता है । इसके उपरान्त चिर-कालिक अथवा स्थायी (Perpetual or Permanent) तटस्थता होती है, जिसका उदाहरण स्विटजरलैण्ड है । तटस्थता के अन्य विभाजन इस प्रकार हैं—सामान्य तथा आंशिक तटस्थता (General and Partial Neutrality), स्वेच्छापूर्वक तथा अनिश्चितकालिक तटस्थता (Voluntary and Conventional), सशस्त्र तटस्थता ( जिसका अर्थ है सेना के स्थायी सज्जाकरण की दशा ) (Armed Neutrality) तथा हितैषी तटस्थता ( Benevolent Neutrality ) जिससे यह प्रकट होता है कि राज्य यद्यपि तटस्थता का बहाना कर रहा है, तथापि उसका ढग पक्षपात युक्त है ।

सन् १९०७ के हेग अनिश्चितकालिक के अनुच्छेद २ में यह व्यवस्था दी गई है कि युद्ध की स्थिति की विद्यमानता तटस्थों को बिना विलम्ब के अधिसूचित कर दी जानी चाहिये तथा इसका प्रवर्तन उनके सम्बन्ध में उस समय तक न होगा जब तक कि अधिसूचना प्राप्त न हो जाय ।

किसी युद्धस्थित द्वारा तटस्थता का केवल उल्लंघन तटस्थता को समाप्त नहीं करता बरन् यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन का एक कार्य है । तटस्थता का अन्त युद्ध की समाप्ति पर अथवा युद्धस्थित तथा तटस्थ राज्य के मध्य युद्ध छिड़ जाने से होता है ।

**तटस्थता तथा तटस्थीकरण (Neutrality and Neutralization) —**  
 यह विषय पूर्व प्रसंग में वर्णित किया जा चुका है ।

**तटस्थता सम्बन्धी आधुनिक धारणा :—**अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में तटस्थता की आधुनिक धारणा अज्ञात थी। उन दिनों युद्ध उचित अथवा अनुचित माने जाते थे। ग्रीस का कथन है कि तटस्थों का कर्तव्य है कि वे ऐसा कोई कार्य न कर जिससे अन्यायपूर्ण कारण के लिये कार्य करने वालों को बल प्राप्त हो अथवा जिससे उसकी प्रगति में बाधा पड़े जो कि एक अन्यायोचित युद्ध लड़ रहा हो। किन्तु यदि कारण सदेहपूर्ण हो तो उन्हें दोनों पक्षकारों की ओर, उनको अपने देश के भीतर से जाने देने से, उनकी सेनाओं के लिये भोजन-सामग्री देने में तथा घिरे हुए को सहायता न पहुँचाने से अपनी निष्पक्षता प्रकट करनी चाहिये।

व्यापार के विकास तथा मातामृत साधनों के उन्नत हो जाने से तटस्थता के विचार का महत्व और भी बढ़ा है तथा तटस्थ वाणिज्य और व्यापार के बिना अडचन के चालू रहने के लिये युद्ध को रोकना आवश्यक हो गया है।

उन्नीसवीं शताब्दी में विशिष्ट बातें जो तटस्थता विषयक हुईं, ये हैं — स्विटजरलैंड तथा बेलजियम का स्थायी तटस्थीकरण हुआ तथा पेरिस की घोषणा (१८५६) हुई जिसमें इस बात पर महत्व दिया गया कि शत्रु के जहाजों पर के माल का स्वायत्तीकरण न होना चाहिये।

**हेग का द्वितीय सम्मेलन १९०७ (The Second Hague Conference 1907) :**—हेग के द्वितीय शान्ति सम्मेलन में जो कि १९०७ में हुआ तटस्थता सम्बन्धित दो अभिसमय थे। अभिसमय पाँच में तटस्थ शक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों का आरोपण किया गया था, तथा भूमि के उन निवासियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निरूपण था जो कि युद्ध के बीच पड़ गये हैं। अभिसमय १३ में नव युद्ध के समय तटस्थ राज्यों के अधिकार एवं कर्तव्य दिये गये थे।

अभिसमय पाँच अनुच्छेद एक में तटस्थ शक्तियों के राज्य क्षेत्र की अकाट्यता के सम्बन्ध में निरूपण किया गया है। इसी प्रकार उसके अनुच्छेदों १४ और १६ में तथा अनुच्छेद एक के तैरहवें अभिसमय में तटस्थ राज्यों के व्यापक अधिकारों की विवेचना की गई है।

कॉन्वेंशन १३ के अनुच्छेद १ में प्रवर्तित है कि युद्ध सलग्न राष्ट्र तटस्थ शक्तियों के सप्रभु अधिकार का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं और उन्हें तटस्थ क्षेत्र और तटस्थ जल सीमा में प्रवेश करने से अपने-आप को रोकना चाहिए, और ऐसे किसी भी कृत्य से अपने को रोकना चाहिए, जिसे कि यदि जान-बूझ कर किया जाय तो तटस्थता के उल्लंघन की सजा दी जा सकती है। अनुच्छेद २ में उपवर्तित है कि शत्रुतापूर्ण किया गया कोई काम, जिसमें कि बंदीकरण और तलाशी का अधिकार



भी सम्मिलित है, जो कि युद्ध-संलग्न सैनिक पोतो द्वारा किसी तटस्थ शक्ति के क्षेत्रीय जल में किया जाता है, तो उसे तटस्थता के उल्लंघन की सजा दी जायेगी और कड़ाई के साथ ऐसे कृत्य निषेधित हैं । अनुच्छेद ३ में उपबधित है कि जबकि कोई पोत किसी तटस्थ शक्ति के क्षेत्रीय जल में पकड़ लिया जाता है और यदि लाभ की वस्तु अब भी उसके क्षेत्र में है तो उस तटस्थ शक्ति को अवश्य ही अपने हर-सम्भव साधनों का प्रयोग करके 'प्राइज', 'माफिसरो' और 'क्रू' सभी को मुक्त कर देने का प्रयत्न करना चाहिए । अनुच्छेद ७ के अन्तर्गत एक तटस्थ शक्ति इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि दोनों में से किसी युद्ध-संलग्न शक्ति द्वारा शस्त्रों या सामान्यतः किसी भी ऐसी वस्तु के यातायात को अवश्य ही राके जिनका कि उपयोग युद्ध में किया जाना है । अनुच्छेद ८ के अन्तर्गत एक तटस्थ राष्ट्र को यथासंभव अपने साधनों का अवश्य ही इस आशय से प्रयोग करना चाहिये कि वह अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे सैनिक पोत की 'फिटिंग' और सैनिक साधनों आदि के लादने के काम को रोके, जिसके लिए उसके पास यह विश्वास करने का आधार है कि उसका उपयोग किसी मैत्रीपूर्ण राष्ट्र के विरुद्ध शत्रुता की कार्यवाही में प्रयोग किया जायेगा । अनुच्छेद १२ के अन्तर्गत, जब तक कि स्थानीय विधि में कोई प्रतिकूल विशिष्ट उपबन्ध न किया गया हो, युद्ध संलग्न सैनिक पोतो या युद्ध के अन्य अभिकरणों को एक तटस्थ राष्ट्र के बंदरगाहों, राजमार्गों या क्षेत्रीय जल में २४ घंटे से अधिक ठहरने की अनुमति नहीं है । कॉन्वेंशन में उल्लिखित विशिष्ट उपबन्ध यहाँ अपवाद माने जायेंगे । युद्ध संलग्न सैनिक पोतो को तटस्थ बंदरगाहों में केवल अपनी ही मरम्मत की अनुमति दी जा सकती है, जितने में कि वे समुद्र में चलने-योग्य हो सकें । कौन-सी मरम्मत आवश्यक हो गई है, इसका निर्णय तटस्थ शक्ति को ही करना है । (अनु० १७) । अनुच्छेद २१ के अन्तर्गत युद्ध में प्राप्त लाभ की मामग्रियों से युक्त पोत तटस्थ शक्ति की सीमा में केवल समुद्र के प्रकोप, मौसम की प्रतिकूलता या ईंधन की कमी आदि के आधार पर ही प्रवेश कर सकते हैं और यद्यपि वे परिस्थितियाँ अनुकूल हो, उन्हें वह सीमा छोड़ देनी होगी । कॉन्वेंशन की व्यवहृति केवल सविदात्मक पक्षकारों के बीच होगी और सभी जबकि सभी युद्ध-संलग्न शक्तियाँ कॉन्वेंशन की सदस्यता से युक्त हो ।

लन्दन की घोषणा ( The London Declaration ) :—तटस्थता की विधि के सहिताकरण के प्रयत्न लन्दन नौसेना कांग्रेस में १९०८-९ में किया गया था । लन्दन की यह घोषणा सत्याकृत न हो सकी । इसमें नाकाबन्दी से सम्बन्धित नियमों का तटस्थों के अधिकार के सम्बन्ध में प्रवर्तन का उल्लेख था । इसमें युद्ध के विनिषिद्ध (Contraband of War) को दो भागों, निरपेक्ष विनिषिद्ध (absolute Contraband) और सप्रतिबन्ध विनिषिद्ध (conditional contraband), में विभाजित कर दिया गया था ।

अनुच्छेद ४८ में तटस्थ पोत जो कि बन्दी कर लिया गया है के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गई है कि उसे नष्ट नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि समुचित बन्दरगाह तक ले जाकर उसके बन्दीकरण के प्रश्न की वैधानिक निर्धारण किया जाना चाहिये । यदि नौजितमाल को बन्दरगाह तक ले जाने में बन्दी करने वाले को अपनी सुरक्षा खतरे में दिखाई पड़े तो नौजितमाल को नष्ट भी किया जा सकता है । यदि तटस्थ पोत का बन्दीकरण भवैष पाया गया तो बन्दी करने वाला समुचित पक्षकार को मुआवजा देगा भले ही पोत के विनाश का कारण न्यायोचित रहा हो । इसी प्रकार से अनुच्छेद ५६ व ५७ में भी तटस्थ पोत के भंडे, नाकाबन्दी, आदि के सम्बन्ध में विस्तृत उपबंध किये गये हैं ।

अनुच्छेद ५६ के अन्तर्गत किसी युद्ध-संलग्न शक्ति द्वारा अपने किसी भी पोत का किसी तटस्थ ध्वज में हस्तान्तरण उस समय प्रभावशून्य होगा, यदि वह हस्तान्तरण किसी समुद्री यात्रा या किसी संरोधित ( Blockaded ) बन्दरगाह में किया जाता है, या उस पोत को फिर से खरीद लेने या प्राप्त कर लेने का अधिकार हस्तान्तरकर्ता द्वारा प्रारक्षित कर दिया गया है, या नागरिक विधि की बांझनीयता, जो कि जिस ध्वज के साथ वह पोत जा रहा था, उसके अधिकार को नियंत्रण करने के संबंध में है, पूरी नहीं हुई है ।

घोषणा के अनुच्छेद ५७ में कहा गया है कि किसी पोत की तटस्थता या शत्रुता का निर्धारण उस ध्वज से होगा, जिसके साथ वह जाने के लिए प्राधिकृत है, जब कि किसी शत्रु-पोत में पाये गये माल का निर्धारण उस पोत के स्वामी की तटस्थता या शत्रुता की प्रकृति से किया जायेगा ।

१९वीं शताब्दी में तटस्थता संयुक्त राज्य की तटस्थ प्रकृति से, जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्रभावित थी । साथ ही इस पर स्विटजरलैंड और बेल्जियम के स्थायी तटस्थीकरण, और १८५६ की पेरिस-घोषणा का भी तटस्थता पर विशेष महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है ।

प्रथम विश्वयुद्ध :—प्रथम विश्वयुद्ध में यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह घोषित किया था कि उसके सम्बन्ध युद्ध में संलग्न शक्तियों के साथ मैत्री तथा सौहार्द के हैं तथापि युद्ध के विनाशकारी शस्त्रों विशेषतः पनडुब्बियों और नाकेबन्दियों तथा प्रतिपिद्ध वस्तुओं के अभिग्रहण सम्बन्धी योधियों के बढ़े हुए अधिकारों के कारण समुद्र की स्वतन्त्रता बनाये रखना और तटस्थ व्यापार का संरक्षण असंभव प्रतीत हुआ । जर्मनी की इस घोषणा के उपरान्त कि सब जहाज राष्ट्रीयता की अपेक्षा बिना जो एक निर्धारित क्षेत्र के भीतर पाये जायेंगे उसके द्वारा डुबा दिये जायेंगे, अमेरिका ने ६ अप्रैल सन् १९१६ को युद्ध घोषित कर दिया ।

भी सम्मिलित है, जा बि युद्ध-सलग्न सैनिक पोता द्वारा किसी तटस्थ शक्ति के क्षेत्रीय जल में बिया जाता है, तो उसे तटस्थता में उलपन की सजा दी जायेगी और कहाई व साथ ऐस दृश्य निषेधित हैं । (अनुच्छेद ३ में उल्लिखित है कि जबकि कोई पोत किसी तटस्थ शक्ति व क्षेत्रीय जल में पकड़ लिया जाता है और यदि लाभ की वस्तु प्रब भी उसका क्षत्र में है तो उस तटस्थ शक्ति को अवश्य ही प्रान हर-समय साधना का प्रयाग करव 'प्राइज', 'पार्किंग' और 'ट्रू' सभी को मुक्त कर देने का प्रयत्न करना चाहिए । अनुच्छेद ७ व अन्तर्गत एक तटस्थ शक्ति इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि शानो में से किसी युद्ध-सलग्न शक्ति द्वारा शस्त्रा या सामान्यतः किसी भी एमी वस्तु व यातायात को अवश्य ही रोक जिनका बि उपयोग युद्ध में किया जाता है । अनुच्छेद ८ के अन्तर्गत एक तटस्थ राष्ट्र का मयासमय अग्न साधना का अवश्य ही इस आशय से प्रयोग करता चाहिये कि वह अपने दोषाधिकार में ऐसे सैनिक पोत की 'फिटिंग' और सैनिक साधना आदि के साधने के काम को रोक, जिनके लिए उसके पास यह विश्वास करने का आधार है कि उनका उपाग किसी मैत्रीपूर्ण राष्ट्र के विरुद्ध शत्रुता की गायवाही में प्रयोग किया जायेगा । अनुच्छेद १० के अन्तर्गत, जब तक कि स्थानीय विधि में कोई प्रतिफल विशिष्ट उपबन्ध न किया गया हो, युद्ध सलग्न सैनिक पोता या युद्ध के अन्य अभिगणना की एक तटस्थ राष्ट्र के बदरगाहा, राजभागी या क्षेत्रीय जल में २४ घंटे से अधिक ठहरने की अनुमति नहीं है । काँ वेंशन में उल्लिखित विशिष्ट उपबन्ध यहाँ अपवाद माने जायेंगे । युद्ध सलग्न सैनिक पोता को तटस्थ बदरगाहो में केवल उननी ही मरम्मत की अनुमति दी जा सकती है, जितने में कि वे समुद्र में चलने योग्य हो सकें । कौन-सी मरम्मत आवश्यक हा गई है, इसका निर्णय तटस्थ शक्ति को ही करना है । (अनु० १७) । अनुच्छेद २१ के अन्तर्गत युद्ध में प्राप्त लाभ की मामग्रिया से मुक्त पोत तटस्थ शक्ति की सीमा में केवल समुद्र के प्रकोप, मोसम की प्रतिकूलता या ईंधन की कमी आदि के आधार पर ही प्रवेश कर सकते हैं और उकोही ये परिस्थितियाँ अनुकूल हो, उन्हें वह सीमा छोड़ देनी होगी । काँ वेंशन की व्यवहृति केवल सविदात्मक पक्षकारो के बीच होगी और सभी जबकि सभी युद्ध सलग्न शक्तियाँ काँ वेंशन की सदस्यता से मुक्त हो ।

लन्दन की घोषणा ( The London Declaration ) —तटस्थता की विधि के सहितावरण के प्रयत्न लन्दन नीसेना काफेस में १९०८ ई में किया गया था । लन्दन की यह घोषणा सत्याकित न हो सकी । इसमें नाकाब दो से सम्बन्धित नियमो का तटस्थो के अधिकार के सम्बन्ध में प्रवर्तन का उल्लेख था । इसमें युद्ध के विनिषिद्ध (Contraband of War) की दो भागो, निषेध विनिषिद्ध (absolute Contraband) और सप्रतिबन्ध विनिषिद्ध (conditional contraband), में विभाजित कर दिया गया था ।

को प्रवर्तित न करने के उपायों की व्यवस्था नहीं की गई। यह प्रश्न उठा कि क्या किसी हस्ताक्षर करने वाले द्वारा पैक्ट के अनुबन्धों का उल्लंघन किये जाने पर अन्य राज्य उससे विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने को बाध्य हैं ? इस सन्धि के बहुमुखी होने के कारण यह अनुमान किया जा सकता था कि प्रत्येक मविदाकार पक्षकार सन्धि के अधीन अपने कर्तव्यों को पूरा करने को बाध्य है। इस प्रकार किसी हस्ताक्षर करने वाले राज्य द्वारा सन्धि के उल्लंघन किये जाने की दशा में उसे प्रतिकार करना पड़ता था। ऐसे उपायों के हानि पर उनका विरोध परम्परागत निष्पक्षता की व्यवस्था से उत्पन्न होता था। केवल तटस्थता पर पैक्ट के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहते हैं, "इस प्रकार तटस्थ राज्य अर्थात् उस राज्य का जो कि अन्य राज्यों के बीच के युद्ध में सम्मिलित नहीं हैं, यह कर्तव्य कि योधियों के सम्बन्ध में कठोर निष्पक्षता का दृष्टिकोण ग्रहण करे, उस दशा में जब युद्ध राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में लड़ा जाय, पैक्ट के पक्षकारों के बीच के सम्बन्ध के विषय में वैध नहीं है।"

"Thus the obligation of a neutral State, that is, a State not involved in the war between other States, to adopt an attitude of strict impartiality toward the belligerents is not valid in the relationship among the parties to the pact in case of war waged as an instrument of national policy"—Kelsen

स्पेन का गृह युद्ध (Spanish Civil War) —स्पेन के गृह-युद्ध (१९३६-३९) में यद्यपि जर्मनी तथा इटली तटस्थता बनाये रहे फिर भी उन्होंने जनरल फ्रैंको के कार्य का समर्थन छुले रूप में किया तथा उसे युद्ध सामग्री प्रदान की। फ्रांस तथा रूस ने भी हस्तक्षेप न करने की भाव में जनतन्त्रवादियों की अधिकाधिक परिमाण में युद्ध-सामग्री प्रदान की।

पनामा की घोषणा (Declaration of Panama) .—पनामा में एक सम्मेलन सितम्बर २३ और अक्टूबर ३, १९३६ को किया गया जिसमें २१ अमेरिकी गणराज्यों ने जिसमें कि समुक्त राज्य भी था एक साधारण घोषणा की जिसने इस आवश्यकता को स्वीकार किया कि एकता की एक सामान्य प्रवृत्ति अपनायी जाय, जो कि Buenos Aires Treaty १९३६ और Declaration of Lima of 1938 में निहित है। उन सबका अनुशीलन उस समय किया जाय जबकि अमेरिकी सुरक्षा को योरोपीय सघर्षों के कारण खतरा होने की सम्भावना हो। घोषणा में यह कहा गया कि व्यवहार के कुछ ऐसे नियम बनाये जाय जो कि अमेरिकी गणराज्य प्रस्तावित करें और जो तटस्थ राज्य की स्थिति के लिये आवश्यक हो तथा तटस्थ के कर्तव्यों को पूरा करें।

लीग आफ नेशन्स के अधीन तटस्थता:—लीग आफ नेशन्स के अभिसमय ने दो प्रकार के युद्ध सामने रखे अर्थात् प्रथम वे युद्ध जिनसे अभिसमय के वर्तव्यो की अपेक्षा नहीं होती थी अर्थात् जिनका अवलम्बन भगडो के शान्तिपूर्ण समझौते के उपायो को करने के उपरान्त किया जाता था तथा द्वितीय वे युद्ध जिनसे अभिसमय के कर्तव्यो की अपेक्षा होती थी। प्रथम दशा में अभिसमय ने लीग के अन्य सदस्यों के ऊपर कोई कर्तव्य नहीं आरोपित किया तथा उनको 'तटस्थता' शब्द के परम्परागत अर्थ में बनाये रखने को स्वतंत्र छोड़ दिया।

दूसरी दशा में जहाँ कि युद्ध का अवलम्बन भगडो को तय करने के सम्पूर्ण शान्तिपूर्ण साधनों को बिना अन्त किये हुए ही किया जाय, अभिसमय का बड़ा ही प्रभाव पड़ा। अनुच्छेद १६ में यह व्यवस्था की गई है कि "यदि लीग का कोई सदस्य अनुच्छेद १२, १३ अथवा १५ के अन्तर्गत अपनी प्रतिज्ञायो की अपेक्षा करके युद्ध का आश्रय ग्रहण करे तो उसके द्वारा लीग के सब सदस्यों के विरुद्ध वास्तव में एक युद्ध का कार्य किया हुआ समझा जायगा और वे इसके द्वारा प्रतिज्ञा करते हैं कि वे तत्काल उसमें सब व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध तोड़ देंगे, अपने राष्ट्रीय-जनो तथा प्रतिज्ञा भग करने वाले राज्य के राष्ट्रीयजनो के मध्य सब सम्पर्क भग कर देंगे तथा प्रतिज्ञा भग करने वाले राज्य के राष्ट्रीयजनो तथा किसी भी अन्य राज्य के राष्ट्रीयजनो के मध्य चाहे वह लीग का सदस्य हो अथवा नहीं सब आर्थिक, व्यापारिक अथवा वैयक्तिक सम्पर्क रोक देंगे।" सदस्यों से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वे सदस्य के अभिस्ताव के अनुसार लीग की प्रतिज्ञायो के संरक्षण के लिए उपयोग में लाये जाने वाले सशस्त्र बलों के लिए अपना अंशभाग अलग-अलग प्रदान करेंगे। इसके अनन्तर सदस्यों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे प्रतिज्ञा भग करने वाले राज्य द्वारा उन सदस्यों में से किसी के विरुद्ध प्रयोग में लाये गये किन्हीं विशिष्ट उपायो के प्रतिकार करने में परस्पर एक दूसरे की सहायता करेंगे तथा लीग के किसी सदस्य के सैनिक हलों को अपने क्षेत्र में से आने-जाने देंगे जो लीग की प्रतिज्ञायो के संरक्षण के लिये कार्य कर रहे थे। प्रतिज्ञा में ऐसे उपायो के समावेश किये जाने का परिणाम स्पष्ट रूप से "पूर्ण निष्पक्षता की अवस्था का परिणाम तथा तटस्थता का उत्पन्न करना था।",

तटस्थता तथा केलोग-ब्रिआड पैक्ट (Neutrality and the Kellogg-Briand Pact) :—सन् १९२८ के केलोग-ब्रिआड पैक्ट के अन्तर्गत जो एक बहुमुखी सन्धि थी हस्ताक्षर करने वाले राज्यों ने जो सत्ता के प्रायः सभी राष्ट्रों के युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय भगडो को निपटाने के साधन रूप में निन्दा की, तथा यह प्रतिज्ञा की कि ऐसे भगडों को शान्तिपूर्ण उपायो से निपटावेंगे। पैक्ट में इन कर्तव्यों

को प्रवर्तित न करने के उपायो की व्यवस्था नहीं की गई। यह प्रश्न उठा कि क्या किसी हस्ताक्षर करने वाले द्वारा पैक्ट के अनुबन्धों का उल्लंघन किये जाने पर अन्य राज्य उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने को बाध्य हैं ? इस सन्धि के बहुमुखी होने के कारण यह अनुमान किया जा सकता था कि प्रत्येक सविदाकार पक्षकार सन्धि के अधीन अपने कर्तव्यों को पूरा करने को बाध्य है। इस प्रकार किसी हस्ताक्षर करने वाले राज्य द्वारा सन्धि के उल्लंघन किये जाने को दशा में उसे प्रतिकार करना पड़ता था। ऐसे उपायो के होने पर उनका विरोध परम्परागत निष्पक्षता की अवस्था से उत्पन्न होता था। केलसन तटस्थता पर पैक्ट के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहते हैं : "इस प्रकार तटस्थ राज्य अर्थात् उस राज्य का जो कि अन्य राज्यों के बीच के युद्ध में सम्मिलित नहीं है, यह कर्तव्य कि योधियों के सम्बन्ध में कठोर निष्पक्षता का दृष्टिकोण ग्रहण करे, उस दशा में जब युद्ध राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में लड़ा जाय, पैक्ट के पक्षकारों के बीच के सम्बन्ध के विषय में वैध नहीं है।"

"Thus the obligation of a neutral State, that is, a State not involved in the war between other States, to adopt an attitude of strict impartiality toward the belligerents is not valid in the relationship among the parties to the pact in case of war waged as an instrument of national policy."—Kelsen.

**स्पेन का गृह युद्ध (Spanish Civil War) :**—स्पेन के गृह-युद्ध (१९३६-३९) में यद्यपि जर्मनी तथा इटली तटस्थता बनाये रहे फिर भी उन्होंने जनरल फ्रैंको के कार्य का समर्थन खुले रूप में किया तथा उसे युद्ध सामग्री प्रदान की। फ्रांस तथा रूस ने भी हस्तक्षेप न करने की भाव में अन्तर्जवादियों को अधिक परिमाण में युद्ध-सामग्री प्रदान की।

**पनामा की घोषणा (Declaration of Panama) :**—पनामा में एक सम्मेलन सितम्बर २३ और नवम्बर ३, १९३६ को किया गया जिसमें २१ अमेरिकी गणराज्यों ने जिसमें कि समुक्त राज्य भी था एक साधारण घोषणा की जिसने शम आवश्यकता को स्वीकार किया कि एकता की एक सामान्य प्रवृत्ति अपनायी जाय, जो कि Buénos Aires Treaty १९३६ और Declaration of Lima of 1938 में निहित है। उन सबका अनुशीलन उस समय किया जाय जबकि अमेरिकी गुरशा को योरोपीय सभ्यों के कारण खतरा होने की सम्भावना हो। घोषणा में यह कहा गया कि व्यवहार के कुछ ऐसे नियम बनाये जाय जो कि अमेरिकी गणराज्य प्रस्तावित करें और जो तटस्थ राज्य की स्थिति के लिये आवश्यक हों तथा तटस्थ के कर्तव्यों को पूरा करें।

**पनामा की घोषणा का महत्व :—**पनामा की यह घोषणा मुनरो सिद्धान्त का ही एक विस्तार था क्योंकि अब इसे एक महाद्वीपी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया गया था । अभी तक यह समुक्त राज्य की ओर से एकपक्षीय नीति थी । मुनरो का सिद्धान्त राष्ट्रपति मुनरो द्वारा २ दिसम्बर १८२३ को कांग्रेस में दिया गया एक सन्देश था जिसमें अमेरिका की नीति का एक सिद्धान्त था जो कि योरोप की ओर से अमेरिकी महाद्वीप के राजनैतिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप का बहिष्कार करता था । पनामा की घोषणा ने इस सिद्धान्त को २१ अमेरिकी गणराज्यों के एक सामूहिक दायित्व के रूप में परिणित कर दिया जिससे यदि किसी बाहरी शक्ति द्वारा उनके किसी भीतरी मामले में हस्तक्षेप हो तो वे अपनी सुरक्षा कर सकें ।

घोषणा ने तटस्थ सुरक्षा के एक नये नियम का प्रतिपादन किया जैसे अमेरिकी गणराज्यों का सुरक्षा-क्षेत्र तक दावा । एक भारत-सुरक्षा के अधिकार के रूप में यह भी घोषणा की गई कि युद्धस्थित राज्यों के हितों को तटस्थ राज्य क्षेत्रों के अधिकार पर हावी नहीं होने दिया जायेगा ।

इससे तटस्थ गणराज्यों को एक नया अधिकार मिला क्योंकि हस्ताक्षर करने वाली शक्तियों के लिये यह मार्ग खुल गया कि वे आपातक परिस्थितियों में इस बात का परामर्श करें कि वे व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से घोषणा की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन-सा कदम उठावे ।

घोषणा में आने यह व्यवस्था दी गई थी कि—“अगर शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिये क्षेत्रीय जलभाग में सामूहिक शक्ति का प्रयोग करना हो तो अमेरिकी गणराज्यों को यह अधिकार है कि वे ऐसे युद्ध स्थित पक्षधारों के लिये जो उनके दावों का सम्मान न करे, अपने बन्दरगाहों को बन्द कर सकते हैं और इससे किसी प्रकार की शिकायत का आधार नहीं उपस्थित होता । घोषणा में शत्रुता के कार्य में लगे हुये मोघियों के विरुद्ध समुक्त प्रतिवेदन का अधिकार दिया गया है ।

**द्वितीय विश्वयुद्ध (Second World War) :—**सन् १९३९ तथा १९४० में जब रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण किया तो यह अतटस्थता-व्यवहार मित्र-मित्र राज्यों की ओर से पाया गया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से फिनलैंड को सहायता प्रदान की । द्वितीय विश्वयुद्ध में अमेरिका ने तटस्थता बनाये हुये जर्मनी द्वारा आक्रान्त तटस्थ देशों के परिसम्पत्ति (assets) को निश्चालन करने (freeze) के उपायों का अवलम्बन किया । उसने ग्रेट ब्रिटेन को घन तथा युद्ध-सामग्री देकर क्रियात्मक रूप में सहायता की । “नगद तथा ले जाओ” योजना जो अमेरिकी

तटस्थ अधिनियम सन् १९३६ के अधीन बनाई गई थी तथा उधार पट्टा अधिनियम सन् १९४१ के पारित करने के माध्यम से उसने ग्रेट ब्रिटेन को विशाल परिमाण में बमवर्षक तथा विध्वंसक दिये । संयुक्त राज्य अमेरिका ने आत्म-संरक्षण के आधार पर तटस्थता की परम्परागत नीति से इस विचलन का औचित्य स्थापित किया । लेकिन उसके आचरण का पूर्णतः विचार करने पर उससे सप्रतिबन्ध तटस्थता का उदाहरण मिलता है जिसमें एक युद्धस्थित के विरुद्ध भेदभाव प्रकट किया गया है जिसने युद्ध का आश्रय लेकर अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन किया था ।

**चार्टर के अन्तर्गत तटस्थता (Neutrality under the Charter):—**

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद २ (५) सब सदस्यों पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी कार्यवाही में जो यह चार्टर के अनुसार करे, प्रत्येक सहायता देंगे तथा किसी ऐसी राज्य को सहायता देने से अपने को रोक रखेंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ निवारक अथवा प्रवृत्तिकारक कार्यवाही कर रहा हो । अनुच्छेद २५ के अन्तर्गत सदस्यों ने सुरक्षा परिषद् के निर्णयों को मानना तथा उनका पालन करना स्वीकार कर लिया है । अनुच्छेद ४१, ४२ तथा ४३ ने अपने भिन्न-भिन्न उपबन्धों से तटस्थता का विचार एक वैध पद्धति के रूप में ही समाप्त कर दिया । अनुच्छेद ४१ सदस्यों को बाधित करता है कि यदि सुरक्षा-परिषद् अपेक्षित करे तो वे ऐसे उपायों को प्रयोग में लायें जैसे कि "आर्थिक संबंधों तथा रेल, समुद्र, वायु, डाक, तार, रेडियो तथा अन्य यातायात साधनों का पूर्ण अथवा आंशिक अवरोध और राजनयिक सम्बन्धों का विच्छेद ।" यदि सुरक्षा-परिषद् के विचार में उपर्युक्त उपाय अपर्याप्त हो तो वह अनुच्छेद ४२ के अन्तर्गत वायु, समुद्र अथवा भूमि सेना से ऐसी कार्यवाही कर सकती है, जैसी कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखने अथवा उसके पुनः स्थापित करने के लिये आवश्यक हो । इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की वायु, समुद्र अथवा भूमि बलों की क्रियाशीलता भी सम्मिलित है । अन्त में अनुच्छेद ४३ में यह व्यवस्था की गई है कि "संयुक्त राष्ट्र संघ के समस्त सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापित रखने में अपना भाग देने के लिये यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे सुरक्षा परिषद् के माँगने पर अथवा किसी विशेष स्वीकारोक्ति अथवा स्वीकारोक्तियों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिये सैनिक बल, सहायता तथा सुविधायें प्रदान करेंगे ।" ("All members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance and facilities, including rights of



passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security")

चार्टर के अनुच्छेद ४८ में यह और व्यवस्था की गई है कि "अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापना के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् के निर्णयों के निष्पादन के लिये जो कार्यवाही अपेक्षित है वह सुरक्षा परिषद् के समस्त सदस्यों अथवा उनमें से कुछ ही के द्वारा की जावेगी जैसा सुरक्षा परिषद् निश्चय करे।" ("The action required to carry out the decisions of the Security Council for the maintenance of international peace and security shall be taken by all the members of the United Nations or by some of them, as the Security Council may determine") इस अनुबन्ध का यह प्रभाव है कि संयुक्त राष्ट्र सभ के कुछ सदस्य तो अग्रवर्षक के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष में आ जाते हैं तथा अन्य सदस्यों की जिन्हें सुरक्षा परिषद् अपने निर्णयों को पालन करने के लिये सहायता देने के लिये नहीं बुलाती, युद्धस्थित के साथ शान्ति अथवा कम से कम अयुध्यमानता रहती है।

अन्त में अनुच्छेद ५१ में तटस्थता को भी यह अनुमति दी गई है कि संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य के विरुद्ध सशस्त्र आक्रमण की दशा में वे भी वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्मसंरक्षण में भाग ले सकते हैं। इस अनुच्छेद का लक्ष्य सशस्त्र आक्रमण से पीड़ित व्यक्ति को सहायता पहुँचाना है। अनुच्छेद में उल्लिखित है कि "इस चार्टर में दी गई कोई भी बात संयुक्त राष्ट्र सभ के किसी सदस्य के विरुद्ध किए गए आक्रमण की दशा में वैयक्तिक अथवा सामूहिक आत्मसंरक्षण के अधिकार को उस समय तक क्षीण न करेगी जब तक कि सुरक्षा परिषद् अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिये आवश्यक उपाय न कर ले।" केलसन का कथन है कि "इस उपबन्ध की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि संयुक्त राष्ट्र सभ के तटस्थ सदस्यों को चार्टर द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वे उस राज्य के विरुद्ध जो सशस्त्र आक्रमण करने का दोषी हो केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि ऐसे प्रवृत्ति-विषमक कार्य कर सकते हैं, जिनमें सशस्त्र बलों का प्रयोग न करना पड़े लेकिन वे सशस्त्र आक्रमण से उत्पन्न ऐसे राज्य के विरुद्ध जो प्रतियुद्ध (counter-war) लड़ रहा हो, प्रवृत्तिविषमक कार्य नहीं कर सकते चाहे उनमें सशस्त्र बल का प्रयोग करना पड़े अथवा नहीं। यदि यह व्याख्या ठीक मान ली जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय विधि का वह सामान्य नियम रद्द हो जाता है जिसके द्वारा तटस्थ राज्यों पर निष्पक्षता का कर्तव्य ठाला गया है।" (Principles of International Law, p 87).

सक्षेप में जैसा ओपेनहेम ने कहा है “यद्यपि चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों के तटस्थ रहने के अधिकार को निश्चित रीति में प्रभावित किया है तथापि इसने संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों के मध्य के अथवा असदस्यों के मध्य के अथवा सदस्यों तथा असदस्यों के मध्य के युद्धों में तटस्थता के उनके अधिकार को वस्तुतः समाप्त नहीं कर दिया है। सिद्धान्त में संयुक्त राष्ट्र सभ का कोई भी सदस्य किसी ऐसे युद्ध में अपनी स्वेच्छा से तटस्थ रहने का अधिकार नहीं रखता जिसमें सुरक्षा परिषद् ने किसी विशिष्ट राज्य को शान्ति भंग करने अथवा किसी अग्रघर्षक कार्य के लिये दोषी ठहराया हो, तथा जिसमें इसने संयुक्त राष्ट्र सभ के सम्बन्धित सदस्य को उस राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने अथवा युद्ध से अभिन्न सैनिक कार्य-वाही करने के लिए माहूँन किया हो।” ( *International Law, Vol 2, 7th Ed, p 647* )

जून २७, सन् १९५० को सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभ के सदस्यों से यह अभिस्ताव किया गया कि वे उस क्षेत्र में जो प्रकट में चार्टर के अनुच्छेद ५१ के उपबन्धों के अन्तर्गत था कोरिया के गणतन्त्र को ऐसी सहायता प्रदान कर जैसी सशस्त्र आक्रमण को रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा के पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक हो लेकिन इसके सदस्यों से जो प्रयुक्तर मिला उसे हम बहुत उत्साहवर्धक नहीं कह सकते जिससे यह अनुमान किया जा सके कि जब कभी सुरक्षा परिषद् चार्टर के अनुच्छेद ४१ अथवा ४२ के अन्तर्गत प्रवृत्तिविषयक उपाय करे तो उसके अनुसरण में उपयुक्त वर्णित वैध परिणाम अवश्य ही होंगे।

तटस्थता और आवश्यकता का सिद्धान्त ( *Neutrality and the Doctrine of Necessity* ) —तटस्थता का दृढ़ रूप में पालन करना सैनिक आवश्यकताओं के कारण प्रथम और द्वितीय विश्वयुद्ध में भंग होता रहा है। ‘जमोरा’ में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कुछ प्रतिबन्धों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत युद्धस्थित को अधिकार है कि वह पोत और पण्य-सामग्री को नौजितमाल न्यायालय के निर्णय के पूर्व कि इसे दण्डित किया जाय अथवा मुक्ति प्रदान की जाय, अभिग्रहण कर ले।

तटस्थों के अधिकार तथा कर्तव्य ( *Rights and Duties of Neutrals* ) —ओपेनहेम बतलाते हैं कि युद्धकाल में तटस्थ राज्यों के अधिकारों तथा कर्तव्यों दोनों का तटस्थ अथवा युद्धस्थित के दृष्टिकोण से यथाक्रम विचार करने पर उनको निष्पक्षता तथा सहर्ष स्वीकृति में सक्षिप्त किया जा सकता है। तटस्थों के अधिकार युद्धस्थित द्वारा उनके साथ व्यवहार में किए जाने वाले कर्तव्यों से परस्पर

सम्बद्ध हैं। तटस्थ राज्यों का यह अधिकार है कि प्रत्येक योधी से निष्पक्षता के ढंग से व्यवहार करने की माँग करे। इसी प्रकार तटस्थों का योधियों के प्रति यह कर्तव्य है कि वे युद्ध स्थित को तटस्थ क्षेत्रों तथा द्रव्यसाधनों का उपयोग उनके सैनिक तथा नाविक प्रयोजनों के लिए न करने देने से निष्पक्ष बने रहें। इसी प्रकार तटस्थ राज्यों का यह अधिकार है कि युद्धस्थित से यह माँग करें कि उसका (तटस्थ) शत्रु से बिना किसी हस्तक्षेप के सम्पर्क विशेषतः व्यापार का बना रहे। दूसरी ओर तटस्थ राज्यों को युद्धस्थित की ओर से बहुत सी कार्यवाहियों को शान्त रूप से सहन करना पड़ेगा जो वे शान्ति के समय में न करते। तटस्थ जहाजों को युद्धस्थित के उनको देखने तथा ढूँढ़ने के अधिकारों को विनम्र भाव से स्वीकृत करना पड़ता है चाहे यह कितना ही दुःखद तथा उद्देगपूर्ण क्यों न हो। प्रत्येक योधी को यह भी अधिकार रहता है कि तटस्थ राज्य के प्रजाजनो को नाकाबन्दी तोड़ने, विनिविद्ध वस्तुओं को ले जाने तथा अतटस्थ सेवा के लिए बंद दे।

प्रोफेसर लॉरेस ने तटस्थों के अधिकारों तथा कर्तव्यों को विस्तृत रूप से यथाक्रम गणना की है जिस पर नीचे विचार किया जा रहा है :—

तटस्थ राज्य के अधिकार अथवा युद्धस्थित राज्य का तटस्थ राज्य के प्रति कर्तव्य (Rights of a Neutral State or the Duties of a Belligerent towards a Neutral State) —लॉरेस के मतानुसार ये पाँच हैं :—

१. अपने राज्य क्षेत्र को शत्रुतापूर्ण कार्यों से मुक्त रखना—शत्रुतापूर्ण कार्य युद्धस्थित में से किसी के क्षेत्र में, छुले समुद्रों में तथा ऐसे क्षेत्रों में जो किसी के भी अधिकार में न हो किये जा सकते हैं। तटस्थ क्षेत्र की भूमि तथा तटस्थ क्षेत्र के क्षेत्रीय जलभाग असंश्लेष्य माने जाते हैं। सन् १९०७ के हेग अभिसमय में भूमियुद्ध में तटस्थता के सम्बन्ध में घोषित किया गया है कि “तटस्थ शक्तियों का प्रवेश अनुत्प्रेक्षणीय है” (अनुच्छेद २) तथा समुद्रीय युद्ध सम्बन्धी तदनु रूप अभिसमय में यह घोषित किया गया है कि “कोई शत्रुतापूर्ण कार्य जिसमें युद्धस्थित के युद्धपोत द्वारा तटस्थ क्षेत्र के क्षेत्रीय जलभागों में अभिग्रहण तथा ढूँढ़ने के अधिकार का प्रयोग भी सम्मिलित है, तटस्थता का उल्लंघन करता है तथा सर्वदा निषिद्ध है।” (अनुच्छेद २)। केवल अत्यधिक आवश्यकता ही इन हितकर सिद्धान्त के प्रस्थापी उल्लंघन का भोविष्य सिद्ध कर सकती है लेकिन ऐसी आवश्यकता बहुत ही बड़ी होनी चाहिए जो आत्मसंरक्षण की सीमा तक पहुँच जाय, तथा स्पष्टीकरण और क्षतिपूर्ति यदि कोई हो, उसके सहित व्यथित तटस्थ को तत्त्वास समर्पित करनी चाहिये।

२. अपने समुद्र के गर्भ में स्थित समुद्र तार (cables) के साथ जहाँ तक सम्भव हो उपद्रव न होने देना—जहाँ कोई केबिल किसी युद्धस्थित क्षेत्र के किसी तटस्थ के क्षेत्र से जोड़ता हो वहाँ उसे युद्धस्थित द्वारा अभिग्रहीत अथवा विनष्ट नहीं करना चाहिए, जब तक यह न पाया जाय कि वह युद्धकारी के आत्मरक्षण के लिए परम आवश्यक है, अथवा जब युद्धकारी को वास्तविक भय इस बात का हो कि वह उसके विरुद्ध हानिकारक रूप में उपयोग किया जायेगा। सन् १९०७ में मया रूप-भेदित भूमि युद्ध सम्बन्धी हेग संहिता के अनुच्छेद ५४ में यह उपबन्धित है कि समुद्र के गर्भ में स्थित केबिल जो युद्धस्थित के अधिकार में स्थित क्षेत्र को तथा तटस्थ क्षेत्र को जोड़े, अत्यधिक आवश्यकता के कारण बाधयता को छोड़कर अन्य किसी दशा में अभिग्रहीत अथवा विनष्ट नहीं करना चाहिए। यदि वे काट दिए जाय तो उनको वापस कर देना चाहिए तथा शान्ति स्थापित होने पर सतिपूर्ति का प्रबन्ध करना चाहिये।

३. शत्रुतापूर्ण कार्यों की प्रत्यक्ष तैयारी से अपने प्रदेश की उन्मुक्त रखना—सन् १९०७ के पचम तथा त्रयोदश हेग अभिसमय के भिन्न-भिन्न अनुच्छेदों में यह व्यवस्था की गई है कि युद्ध सट्टा अभियानों की तटस्थ सीमाओं के भीतर सुसज्जित नहीं होना चाहिये, और न तटस्थ भूमि अथवा उसका भाग शत्रु के विरुद्ध क्रियाशीलता के भण्डे बनाना चाहिए। तटस्थ क्षेत्र में योद्धादलों की सख्या न तो बढ़ाई जानी चाहिए, न उनकी भर्तियों की जानी चाहिए तथा न वहाँ पर युद्धस्थित के युद्धपोतों द्वारा शस्त्रों तथा युद्ध-सट्टा सामग्रियों अथवा अन्य सामग्रियों का संचय करना चाहिए जो युद्ध के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो। अतः युद्धस्थित का यह कर्तव्य है कि तटस्थ क्षेत्र की क्रियाशीलता के लिए भण्डे के रूप में अथवा युद्ध सट्टा अभियान के संगठन के लिए सुविधाजनक स्थान के रूप में प्रयोग न करें।

४. तटस्थता के लिए बनाये गए विनियमों का युद्धस्थित द्वारा पालन कराना—स्थलयुद्ध सम्बन्धी तटस्थता पर सन् १९०७ के हेग अभिसमय में यह व्यवस्था की गई है कि समर्प करने वालों के स्थलीय सैन्यदल तटस्थ सीमाओं को पार नहीं कर सकते, उस दशा को छोड़ कर जब वे युद्धस्थित के सेनाओं के प्रत्यक्ष तथा धायलों को ले जा रहे हों, अथवा जब मृतसैनिकों के समूह शत्रु द्वारा ले जाय जा रहे हो। इन दो दशाओं को छोड़ कर अन्य किसी भी दशा में जो सैन्यदल तटस्थ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं एक नियत स्थान में रहने को बाध्य (नज़रबन्द) किए जाते हैं। समुद्रीय युद्ध में जब तक कोई तटस्थ स्पष्टरूप से युद्धस्थित के युद्धपोतों का प्रवेश निषिद्ध न करे वे उसके बन्दरगाहों तथा जनभागों के आतिथ्य का उपभोग स्वतन्त्र रूप से कर

सकते हैं। युद्धस्थित के सेनानायक यह माँग कर सकते हैं कि तटस्थों द्वारा बनाये गए नियमों को दोनों पक्षों पर निष्पक्षतापूर्वक प्रवर्तन कराया जाय।

५. जिसने अपनी तटस्थता का उल्लंघन किया हो ऐसे युद्धस्थित राज्य से क्षतिपूर्ति करवाना—क्षतिपूर्ति के मूल्य निरूपण के लिये कोई नियत सिद्धान्त नहीं है। कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय विधि को अनुशासित करने वाले नियम इस विषय में स्पष्ट हैं कि धनैष रूप से पकड़ी गई सम्पत्ति अथवा तटस्थ क्षेत्राधिकार के भीतर अभिग्रहीत जहाज अथवा माल वापस किए जाने चाहिए। लेकिन नियम इससे अधिक नहीं जाते जिससे कि क्षतिपूर्ति की गणना का क्रम अथवा क्षमा याचना के शब्द निर्धारित किए जाय। तथापि क्षतिपूर्ति पर्याप्त तथा अपराध की गम्भीरता के अनुरूप होनी चाहिये।

तटस्थ राज्यों के युद्ध-स्थित राज्यों के प्रति कर्तव्य अथवा युद्धस्थित राज्यों के अधिकार (Duties of Neutral States towards Belligerent States or the Rights of Belligerents) :—युद्ध-स्थित के प्रति तटस्थों के कर्तव्यों को परहेज (अलग रहने के कर्तव्य), रोकने के कर्तव्य, सहर्ष स्वीकृति (उपमति) के कर्तव्य, वापसी के कर्तव्य तथा क्षतिपूर्ति के कर्तव्यों में सक्षित में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन सब कर्तव्यों के ऊपर एक तटस्थ से यह आशा की जाती है कि वह अत्यन्त निष्पक्ष रहे। निष्पक्षता से तटस्थ राज्य की ओर से वे सक्रिय उपाय व्यक्त होते हैं जिनसे वह युद्धस्थित राज्यों को तटस्थ क्षेत्र तथा तटस्थ साधनों को अपने सैनिक तथा नाविक प्रयोजनों के लिए उपयोग करने से रोकता है। तटस्थ राज्य को किसी प्रकार का अधिक सम्मान अथवा भेदभाव दिखाने से बचा रहना चाहिए क्योंकि यही निर्लेपभाव तटस्थता का मुख्य तत्व है।

परहेज (अलग रहने के कर्तव्य) (Duties of Abstention) :—तटस्थ शक्ति को किसी पक्ष को सैनिक सहायता न देनी चाहिए। इसे युद्धस्थिति में से किसी को भी रुपया उधार देने अथवा युद्ध के उपकरण या गोला बारूद देने अथवा वेचने से अपने आप को अलग रखना चाहिये। इससे अधिक तटस्थ राज्य को सन्तुष्टापूर्ण कार्यों से सम्बन्धित विषयों में एक पक्ष को ऐसे विशेषाधिकार देने से अपने को वर्जित करना चाहिये जैसा कि यह दूसरे को नहीं देता। लेकिन तटस्थ पर यह कर्तव्य भार नहीं लादा गया है कि वह ऐसे सामान की व्यक्तिगत विक्रय पर रोक लगावे। जैसा लीरेस ने सकेत किया है कि बहुत से अन्य विषयों के समान इस विषय में भी व्यक्तिगत वह कर सकते हैं जो कि उनकी सरकार न करे। इसी आधार पर वेकिन की सरकार ने कोरिया के युद्ध की प्रारम्भिक अवस्था में, जब यह विषय संयुक्त राष्ट्र सच के समक्ष उठाया गया, उन लाल चीत असैनिक व्यक्तियों का

उत्तरदायित्व लेने से अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने उत्तरी कोरिया वालों को सहायता देने के लिये सीमा को पार कर दिया था। सन् १९०७ के हेग अभिसमय ५ के अनुच्छेद ६ में यह व्यवस्था की गई है, कि केवल इसी बात से कि व्यक्तिगत सीमा को अलग-अलग योधियों में से किसी एक को अपनी सेवाये प्रदान करने के लिये पार करते हैं तटस्थ शक्ति का उत्तरदायित्व लपेट में नहीं आता।

तटस्थ राज्य से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह युद्धस्थित में से किसी को ओर से भी ऋण की प्रतिभूति करे। लेकिन यदि उसके प्रजाजन युद्धकारियों में से किसी एक को युद्ध व्यापारिक व्यवहार के रूप में ऋण दे तो इसमें तटस्थ की ओर से कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।

**रोकने का कर्तव्य (Duties of Prevention) :**—सक्षिप्त रूप में कहे जाने पर रोकने के कर्तव्यों में तटस्थ द्वारा अपने सन्नाधिकार के भीतर उन बातों का रोकना आता है जिनको युद्धस्थित वहाँ न करने के लिये बाध्य हैं। सन् १९०७ के हेग अभिसमय के भिन्न-भिन्न अनुच्छेदों में यह व्यवस्था की गई है, कि योधियों के हितों में तटस्थ शक्ति के प्रदेश में लड़ने वालों को पसटन नहीं बनाई जानी चाहिये, न वहाँ भर्तों के कार्यालय खोले जाने चाहिये तथा तटस्थ शक्तियों को वह उपाय करना चाहिये जिससे उनके भूमि-क्षेत्र में युद्धस्थित राज्यों में से किसी एक को भी सेनाओं के लिये मनुष्यों की भर्ती होती जा सके। तटस्थ राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र के किसी भाग का भी युद्धस्थित के नाविक भयवा सैनिक क्रियाशीलता में प्रयोग किया जाना भयवा वहाँ से उनके हितों में संगठित युद्ध सहाय अभियानों का सुमज्जित किया जाना भयवा पृथक् होना रोके..... तटस्थ अपने क्षेत्र में योधियों द्वारा नौजितमाल न्यायालय की स्थापना तथा अपनी भूमि के किसी भाग के ऊपर से भूमि सेना का आवागमन रोकने को बाध्य है।—

(Lawrence : The Principles of International Law, p. 634)

**युद्धपोतों का ठहरना तथा उनकी मरम्मत (Stay and Repairs of Warships) :**—तटस्थ राज्य को युद्धस्थित के युद्धपोतों का तथा उनके नौजितमाल का अपने बन्दरगाहों तथा जलभागों में अनुचित ठहरना रोकना चाहिये।

सन् १९०७ के द्वितीय हेग सम्मेलन ने तेरहवें अभिसमय में यह नियत किया गया कि युद्धस्थित के युद्धपोतों को अधिक से अधिक सरस्रा जो किसी तटस्थ के एक बन्दरगाह में भयवा उसके यातायात मार्गों में एक साथ किसी समय में रह सकती है, वह तीन होनी चाहिये, लेकिन इसने तटस्थ देश को यह अधिकार दिया कि इसके विरुद्ध विशेष उपबन्ध बना सकती है। सन् १९०७ के द्वितीय हेग सम्मेलन में यह भी नियत किया गया कि तटस्थ शक्ति के विधियों में इसके विरुद्ध कोई विशेष

उपबन्धों के न होने की दशा में, किसी युद्धकारी का युद्धपोत उसके किसी एक बन्दरगाह में केवल २४ घंटों के लिये ही ठहर सकता है। जहाज को क्षति भ्रष्टा प्रतिकूल मौसम के कारण और अधिक बाल के लिये ठहरने की अनुमति दी जा सकती थी। ऐसी दशा में उसे विलम्ब का कारण समाप्त होते ही विदा हो जाना चाहिये और इसमें चूक होने पर उसे नियंत्रित स्थान में किया रहने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये। 'ट्रेक' वाले मामले में यह निर्धारित किया गया, कि युद्धस्थित के जहाजों को गम्भीर आवश्यकता अथवा तीव्र वायु की दशाओं को छोड़ कर भय किसी दशा में चौबीस घंटों से अधिक ठहरना वर्जित है। उन्हें यह भी वर्जित किया गया कि अपने देश के सब से निकटवर्ती बन्दरगाह में पहुँचाने के लिये जितनी खाद्य सामग्री आवश्यक हो उससे अधिक वे अपने साथ न ले जायें। 'मन्सूर' वाले मामले में भी इस बात पर महत्व दिया गया कि तटस्थ क्षेत्रों को युद्ध में लगे हुये राज्यों के जहाजों का आश्रय न बनाना चाहिये तथा कोई युद्धस्थित जहाज २४ घंटों से अधिक नहीं ठहर सकता। 'लीना' वाले मामले में यह भी सम्मति प्रकट की गई कि तटस्थ क्षेत्र में केवल असैनिक मरम्मत की जा सकती थी तथा यदि सैनिक मरम्मत की जाय तो जहाज तटस्थ बन्दरगाह में रखना चाहिये तथा उसके नौबालकों को पैगेल पर छोड़ देना चाहिये और उनकी राज्य के क्षेत्र से भागने न दिया जाना चाहिये। अन्य शब्दों में उन मरम्मतों का कठोर निषेध था जिनसे जहाज को युद्ध करने की क्षमता तथा कार्यक्षमता बढ़ती थी।

सन् १९०७ के तेरहवें हेग सम्मेलन के अनुच्छेद २३ में यह व्यवस्था की गई है कि तटस्थ राज्य नौजितमाल न्यायालय के निर्णय के आलम्बित रहने तक नौजितमाल को अपने बन्दरगाहों में जमा रहने दे सकता है किन्तु तटस्थ बन्दरगाह युद्धस्थित नौजितमाल के लिये आश्रय अथवा स्थायी भण्डे न बनने चाहिये।

सन् १९२३ के वायु युद्ध सम्बन्धी नियमों की प्रक्रिया के मतों में यह व्यवस्था की गई है कि तटस्थ सरकार को युद्ध में लगे हुये राज्य के सैनिक हवाई जहाजों को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रवेश करने से रोकने के लिये उन साधनों का उपयोग करना चाहिये जो उसके अधिकार में हों तथा यदि वे ऐसे क्षेत्राधिकार के भीतर प्रवेश कर जायें तो उन्हें उतरने को बाध्य करें। एक तटस्थ सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि किसी के युद्ध में लगे हुए सैनिक हवाई जहाज को जो इसके क्षेत्राधिकार के भीतर हो, तथा जो किसी भी कारण से उतरा हो, नजरबन्द करने के लिये उन साधनों का उपयोग करे जो उसके अधिकार में हों।

तटस्थ राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र के किसी भाग को युद्धस्थित द्वारा सूचना स्थान के रूप में उपयोग न करने दे। द्वितीय हेग सम्मेलन ने युद्ध में

लगे हुए राज्यों को यह निषिद्ध किया कि तटस्थ क्षेत्र में कोई ऐसा बेतार का गृह प्रयत्न या यन्त्र न स्थापित करें जो उनकी भूमि तथा समुद्रीय सेना को सूचना भेजने के साधन के रूप में काम में लाया जा सके ।

**उपमति के कर्त्तव्य (Duties of Acquiescence) :**—तटस्थ राज्य को समुचित युद्ध सह्य क्रियाशीलता के बीच में पहुँचाई हुई प्रासंगिक सति को मौन रूप में ही स्वीकार करना चाहिये । इसे उपमति का कर्त्तव्य कहते हैं । युद्धस्थित के समुद्र में दूँदने तथा अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में यह अपनी उपमति के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये बाध्य हैं, चाहे वे कितनी ही दुःखद क्यों न हो ।

**पुनःस्थापन या वापसी के कर्त्तव्य (Duties of Restoration) :**—सौरेंस यह बतलाते हैं कि ऐसे कर्त्तव्य “तब उत्पन्न होते हैं जब कि युद्धस्थित राज्य विधि को भंग कर देता है तथा तटस्थ सार्वभौमिकता का अपने शत्रु को हानि पहुँचाने में तिरस्कार करता है । उदाहरणार्थ यदि वह तटस्थ जलाशयों के भीतर नौजितमाल अभिग्रहण करे तो द्विगुणित अपकार हो जाता है । वह शक्ति जिसके अधिकार का तिरस्कार किया गया, तथा वह जिसने शाना जहाज गँवाया, दोनों उसके इस दुष्कार्य के कारण हानि उठाते हैं । हानि उठाने वाले युद्धस्थित को क्षतिपूर्ति के लिये उस तटस्थ से प्रार्थना करनी चाहिये, जिसके क्षेत्राधिकार के भीतर प्रवेश कार्य किया गया तथा तटस्थ को हानि पहुँचाने वाले युद्धस्थित के विरुद्ध उसके सार्वभौमिक अधिकारों का तिरस्कार करके शान्ति भङ्ग करने के लिये दावा करने का अधिकार है ।” ( *Lawrence : The Principles of International Law, p. 652* ) । इसी प्रकार जब कोई नौजितमाल किसी तटस्थ बन्दरगाह में समुद्रयात्रा के लिये प्रयोज्यता, सौत्र हवा, ईंधन अथवा खाद्य-सामग्री का अभाव इत्यादि के अतिरिक्त अन्य किसी नियमविरुद्ध रीति में लाया जाय तो प्रतिदान या वापसी का कर्त्तव्य उत्पन्न होता है । तटस्थ शक्ति का यह कर्त्तव्य है कि जहाज को उसके पदाधिकारियों तथा चालकों सहित उन्मुक्त किये जाने के लिये प्रयत्नशील होवें । तटस्थ राज्य के ऊपर यह कर्त्तव्य भार है कि नौजितमाल को उस युद्धस्थित को वापस कर दे जिसकी हानि हुई हो ।

**क्षतिपूर्ति के कर्त्तव्य (Duties of Reparation) :**—“जब कोई युद्ध में लगे हुआ राज्य किसी तटस्थ पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा लगाये गये कर्त्तव्यों के उसके (तटस्थ के) द्वारा अपनी कुभावना अथवा शिथिलता के कारण पालन किये जाने में असमर्थ रहने के कारण हानि उठावे, तो उस हानि तथा क्षति की पूर्ति के लिये एक वैध अधिकार उत्पन्न हो जाता है ।” ( *Lawrence : The Principles*



of International Law, p. 654) । लेकिन यदि निवारण के उपाय किये जाय तथा असफल रहे तो तटस्थ राज्य पर कोई दायित्व नहीं रहता ।

**निर्णय विधि (Case Law) :—**तटस्थता का स्पष्ट विचार रखने के लिये इस विषय पर मामलों से निर्धारित निम्नलिखित निर्णय-विधि उल्लेखनीय हैं :—

*Twee Gebroeders* [(1800) 3 C. Rob. 162] में लार्ड स्टोवेन द्वारा यह निरूपण किया गया कि “शत्रुता का कार्य तटस्थ भूमि पर प्रारम्भ न होना चाहिये । इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि यह वहाँ पूर्ण नहीं हुआ—आपको वहाँ कोई ऐसा उपाय नहीं करना चाहिये जिससे तत्काल हिंसात्मक कार्य उत्पन्न हो, आपको किसी स्थान का ऐसा लाभ न उठाना चाहिये जिससे यह प्रतीत हो कि आप उस तटस्थ क्षेत्र को सुविधाजनक स्थान के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिसे दोनों युद्धस्थित राज्यों के मध्य पूर्ण समानता के साथ व्यवहार करना है जिससे उनमें से किसी एक को कोई विशेष लाभ न पहुँचे ।”

*Alabama Claims* [ (1872) 1 Moore, International Arbitration, p. 653 ] में न्यायाधिकरण द्वारा यह निर्णय किया गया कि तटस्थ सरकार अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किसी जहाज का सुसज्जित किया जाना अथवा उसके शस्त्रीकरण अथवा साधनयुक्त किया जाना उचित उद्योग के साथ रोकने के लिये बाध्य है, जिसके (जहाज के) लिये उसके पास यह विश्वास करने के लिये युक्तियुक्त आधार हो कि उसका (जहाज का) अभिप्राय उस शक्ति के विरुद्ध समुद्र में इधर उधर चक्कर लगाना अथवा युद्ध करना है जिसके साथ उसकी सन्धि हो ।

*General Armstrong* (*Pitt Cobbett's Leading Cases*, Vol. II. Ed. V. p. 351) वाले मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि यदि कोई युद्धस्थित राज्य आक्रमण किये जाने पर तटस्थ का संरक्षण ढूँढ़े बिना ही अपनी प्रतिरक्षा करना पसन्द करता है तो वह तटस्थ राज्य को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त कर देता है ।

*Appam* वाले मामले में एक जर्मन जंगी जहाज ने *Appam* नामक एक ब्रिटिश व्यापारिक जहाज को एमडन से १६०० मील दूरी पर बन्दी बना लिया तथा फरवरी १, सन् १९१६ को उसे नारफोक बन्दरगाह (संयुक्त राज्य अमेरिका) पर लाया, यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका उस समय तटस्थ था । जहाज के विरुद्ध मानहानि की कार्यवाही इस आधार पर प्रारम्भ की गई कि बन्दरगाह में उसकी उपस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका की तटस्थता के उल्लंघन स्वरूप था । सर्वोच्च

न्यायालय ने यह निर्णय किया कि एक अमेरिकन बन्दरगाह को बन्दी किये गये जहाजों को वहाँ अनिश्चित काल के लिये रखने के लिये सग्रहस्थान के रूप में उपयोग किये जाने का प्रयत्न करना संयुक्त राज्य अमेरिका की परम्परागत नीति तथा जल-युद्ध में तटस्थ शक्तियों के अधिकार तथा कर्तव्यों के सम्बन्ध में हेग प्रतिज्ञा के अनु-बन्धों के अधीन तटस्थता का भंग करना है ।

जमोरा [ (1916) 2 A. C. 77 ] वाले मामले में निर्णय के लिये नौजितमाल न्यायालय की अभिरक्षा में स्थित अपने जहाजों तथा माल के सम्बन्ध में तटस्थों के अधिकारों की विवेचना करते हुये लार्ड पार्कर ने यह कथन किया कि युद्धस्थित शक्ति को अपने जहाजों अथवा माल को जो नौजितमाल के न्यायालयों की अभिरक्षा में इस प्रश्न के निर्णय के अलम्बित रहने तक पड़े हो कि उनको दोषी ठहराया जाय अथवा उन्मुक्त किया जाय, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अधिमाचना करने का अधिकार है किन्तु ऐसा अधिकार कुछ सीमितियों के अधीन है । प्रथम यह कि विवादग्रस्त जहाज अथवा माल राज्य की प्रतिरक्षा, युद्ध के चलाने अथवा राज्य की सुरक्षा सम्बन्धी अन्य विषयों के लिए अल्पमत आवश्यक रूप से अपेक्षित होना चाहिये । द्वितीय, परीक्षण के लिये प्रश्न वास्तविक रूप का होना चाहिये जिससे तत्काल उन्मोचित किये जाने का आदेश देना अनुचित हो । तृतीय, यह कि अधिकार नौजितमाल न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर प्रवृत्त कराया जाना चाहिये, जो इस बात का न्यायिक रूप से निर्णय करेगा कि क्या मामले की उन विशिष्ट परिस्थितियों में अधिकार का उपयोग किया जा सकता है अथवा नहीं ।

## अध्याय ४७

### संकटाधिकार

#### ( Right of Angary )

संकटाधिकार (Right of Angary) से युद्ध में स्थित राज्य की युद्ध अथवा अन्य सार्वजनिक भय उत्पन्न होने पर तटस्थ राज्य की ऐसी सहायता को उपयोग करते अथवा यदि आवश्यकता भा जाय तो उसको विनष्ट करने का भी अधिकार होता है जैसा उसके क्षेत्रिक अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशेष समय में हो । यह युद्धस्थित राज्य को सार्वजनिक आवश्यकता के समय जहाजों, रेल के डिब्बों, वायुयानों तथा यातायात के अन्य साधनों का जो तटस्थ शक्तियों के

राष्ट्रीयजनों के अधिकार में हो, किन्तु जो उस समय उसके अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर आते हो, अधिपावन अथवा उपयोग करने का अधिकार देता है। यह इस सिद्धान्त पर आधारित होता है कि राज्य का सर्वोच्च हित विधि का प्रति-क्रमण कर जाता है। यह इस सामान्य सिद्धान्त पर भी आधारित है कि युद्धस्थित राज्य के क्षेत्र में स्थित तटस्थ राज्य की सम्पत्ति को वैसे ही सकटों का सामना करना पड़ता है जैसा कि युद्ध में लगे हुए राज्य के राष्ट्रीयजनों की सम्पत्ति को तथा वह युद्ध एवं अन्य राष्ट्रीय सकट के समय अधिपावन करने अथवा भ्रंशमान प्रदान करने के लिये उसी प्रकार के उत्तरदायित्व के अधीन है। इसी अधिकार को *driot d'angarie* अथवा पीतवर्षण (*jus angariae*) भी कहते हैं तथा इसी का रूपान्तर अंग्रेजी में *angary* है जिसे सकटाधिकार के नाम से पुकारते हैं।

इसकी उत्पत्ति :—सकटाधिकार (*Angary*) शब्द की व्युत्पत्ति फारसी शब्द से है जिसका अर्थ नम्राट् के दूत सेवा में लगे हुये 'दूत' से है। इस शब्द ने तदनन्तर ग्रीस तथा रोम में स्थान प्राप्त किया। ओपेनहेम का कथन है कि शब्द *angaria* की व्युत्पत्ति जिसका अर्थ मध्यकालीन लैटिन में *post-station* ग्रीक भाषा के उस शब्द से हुई है जिसका अर्थ दूत है। अतः *jus angariae* का अर्थ अक्षरशः दुलाई का अधिकार होगा। रोमन विधि में इससे गाड़ियों, घोड़ों, इत्यादि का अधिपावन प्रकट होता था तथा यह केवल भूमि-सम्बन्धी दुलाई तक ही सीमित था। मध्ययुग में सकटाधिकार (*angary*) से यह व्यक्त होता था कि युद्धस्थित राज्य के बन्दरगाह में स्थित तटस्थ जहाज पकड़ लिये जाँव तथा सैन्य दलों और रसद से जाने की बाध्य किये जाँव। आधुनिक युग में यह अधिकार, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, युद्धस्थित को युद्ध अथवा अन्य सार्वजनिक भय के समय में इस अधिकार से मुक्त करता है कि वह आक्रमण अथवा प्रतिरक्षा के लिये क्षतिपूर्ति देने पर विदेशी जहाजों, हवाई जहाजों तथा यातायात के अन्य साधनों का अधिपावन करे जो उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर हो।

ओपेनहेम (*Oppenheim*) का मत :—मूल *angary* के अधिकार के विपरीत में आधुनिक *angary* का अधिकार युद्धस्थित राज्य का वह अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर आक्रमण अथवा प्रतिरक्षा के लिये अपने क्षेत्र में अथवा शत्रु के क्षेत्र में अथवा खुले समुद्र में स्थित तटस्थ राज्य की सम्पत्ति को विनाश करे अथवा उनका उपयोग करे। उनके अनुसार यह अधिकार ऐसा अधिकार है जो युद्ध के विधि से व्युत्पन्न है, तथा इसका भ्रम उस अधिकार से नहीं करना चाहिये जो प्रत्येक राज्य अत्यन्त आवश्यकता की दशा में क्षतिपूर्ति देने के अधीन अपने क्षेत्र में

स्थित किमी विदेशी सम्पत्ति को ध्वंसग्रस्त करने का रखता है। अतः किसी का इस प्रकार की उन्नति न करनी चाहिये कि तटस्थों तथा युद्धस्थित से सम्बन्धित नवट का अधिकार है अथवा शान्ति तथा युद्ध में नवट का अधिकार है। (International Law, Vol. 2, 7th Ed. 765).

पिट कोबेट ( Pitt Cobbet ) का मत — पिट कोबेट सक्टाधिकार (angary) को सार्वभौमिक अधिकार मानते हैं।

फिलिमोर का मत — डा० फिलिमोर का कथन है कि "कभी एक अन्य उपाय है जिसमें युद्धस्थित के लक्षण का भी घट है और यद्यपि नहीं वाद कही जाय तो उसका प्रयोग शान्ति के समय में भी किया जाना है जिसे फ्रान्स की भाषा में le droit d'angarie कहते हैं। यह राज्य का एक कार्य है जिसके द्वारा विदेशीय तथा निजी घरेलू जहाज भी जो उनके क्षेत्राधिकार के भीतर पाये जाय पकड़ लिये जाते हैं, तथा सैनिकों, गोलाबारूद अथवा युद्ध के अन्य उपकरणों का दान करने के लिये बाध्य किये जाते हैं। अन्य भाषा में एक शक्ति के विरुद्ध जिसमें उनकी सवि है अपनी इच्छा के प्रतिबल प्रत्यक्ष शक्ति के कार्य करने में पक्षपात बनने के लिये बाध्य किये जाते हैं।"

सन् १८७७ के द्वितीय हेग सम्मेलन के धर्मावली ५ के अनुच्छेद १८ में सक्टाधिकार विशेष रूप से स्वीकृत किया गया है जिनके द्वारा प्रति आवश्यक दान में क्षतिपूर्ति दिये जाने के अधीन युद्ध में लगे हुए वस्तुओं की तटस्था की देनब मान्यता उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अन्य तटस्थ सम्पत्ति भी यदि सैनिक आवश्यकता ऐसा निदिष्ट करे तो उपयोग में लाई अथवा विनष्ट की जा सकती है। फिलिमोर का यह मत है कि इस अधिकार का प्रयोग केवल तथा ही करना है जब मात्रा पेशगी दिया जाय तथा उनके साथ यह भी शर्त है कि नाम अथवा जहाजों के स्वामियों की यह क्षतिपूर्ति की जाय जो उनके धन के लाने में विघ्न पड़ने तथा जिस मान को वे ले जा रहे हैं उनके सम्मान्य दिनांक के कारण उत्पन्न हो।

सन् १८७० का फ्रांस तथा जर्मनी का युद्ध (Franco-German War of 1870) :—सन् १८७० के युद्ध तथा जर्मनी के बीच संपादित जर्मनी के जनरल ने ब्रिटेन के छ जहाजों को मान नदी में डनरनेयर नगर के समीप परदा तथा उनका मान नदी में डुबा दिया जिसमें नदी का मार्ग रुक जाय तथा फ्रांस की तोपी से मुमकिन नदी के ऊपर जाकर जर्मनी की सैनिक विमानाना में विघ्न न डाल सकें। इंग्लैंड युद्ध में तटस्थ था। जिस दिवसार्क ने उनके विमानाना स्वीकार किया तथा न्यायाधिकार मानान के अनुसार मुख्य दान का प्रभाव।

उन्होंने यह तर्क किया कि विवादपूर्ण उपाय चाहे उसका स्वरूप कितना ही भ्रूलौकिक हो अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध सदृश आचरण की सीमा का उल्लंघन नहीं करता। एक उत्कट सकट सन्निकट था तथा उसको टालने का कोई भी अन्य उपाय उपलब्ध नहीं था। अतः यह मामला एक आवश्यक विषय था जिससे शान्ति के समय में भी विदेशी सम्पत्ति का उपयोग अथवा विनाश की क्षतिपूर्ति किये जाने की शर्त के अधीन ग्राह्य होता। इसके उपरान्त जर्मन चान्सेलर ने सर आर० कलिमार के प्रयत्न से उस अनुच्छेद का उद्धरण प्रस्तुत किया जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। तत्पश्चात् अंग्रेजी जहाज मालिकों को उनकी हानि के लिये क्षतिपूर्ति की धनराशि दी गई।

**परिसीमन (Limitations) :—**सकटाधिकार (Angary) सार्वभौमिक अधिकार है तथा किसी सार्वभौम राज्य द्वारा राष्ट्रीय सकट में इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उपबन्ध यह है कि अधियाचित माल तथा यातायात के साधन उनके अधियाचन करने वाले राज्य के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर पड़े हों। यह अधिकार अधियाचन करने वाले राज्य के क्षेत्रीय जलभागी तक ही सीमित है तथा इसकी क्षेत्रीय सीमाओं को उल्लंघन नहीं करता। भारी राष्ट्रीय सकट उपस्थित होने पर यह अधिकार का प्रयोग तटस्थ राज्य द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसे अधियाचन क्षतिपूर्ति की पूर्ण धनराशि देन की शर्त के अन्तर्गत ही किये जा सकते हैं। इस अधिकार का प्रयोग उस युद्धस्थित राज्य द्वारा नहीं किया जा सकता जिसके अधिकार में शत्रु का क्षेत्र हो। जहाजों अथवा हवाई जहाजों के विदेशी चालकगणों की सेवाओं के सम्बन्ध में सकटाधिकार (angary) लागू नहीं होता।

**जमोरा (The Zamora) :—**जमोरा वाले मामले में [(1916) 2 A. C. 77] लकड़ी तथा तैला अधियाचित हुए जो युद्ध को सफलतापूर्वक चालू रखने के लिए आवश्यक थे। लार्ड पार्कर द्वारा यह निरूपण हुआ कि युद्धस्थित को समुचित दशा में तटस्थ के जहाजों तथा माल को अधियाचन का अधिकार है, जो नौजित-माल न्यायालय की अभिरक्षा में निर्णयार्थ रहे हों। इसमें सन्देह नहीं कि सम्पत्ति पर वैध अधिकार अथवा प्राधिपत्य तटस्थ का ही है। अधियाचन का अधिकार एक परिपूर्ण अधिकार नहीं है, किन्तु यह एक अधिकार है जिसका केवल निश्चित परिस्थितियों में तथा निश्चित प्रयोजनों के लिये ही प्रयोग किया जा सकता है। अतः यह निर्णय किया गया कि जहाज अथवा उस पर लदे हुये तैले का अधियाचन करन का अधिकार मान्य है जो नौजितमाल न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा में पड़े

हूए हो किन्तु इस अनुबन्ध के साथ कि (घ) विवादस्थल जहाँ अथवा मान्य राज्य की प्रतिरक्षा, युद्ध के संयोजन, अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी अन्य विषयों के लिये परमेश्वर या परमेश्वर के लिये स्वीकृत है, (घा) परीक्षण के लिये एक या अधिक प्रश्न होना चाहिए, और (ङ) अविश्वसनीय व्यापारिक एवं मालवाहत का निर्माण करेगा कि वरना मानने के लिये विनिश्चित परिस्थितियों में अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है ।

— — —

## अध्याय ४८

### संरोध या नाकाबंदी

#### ( Blockade )

**परिभाषा :—**प्रोफेसर हेन के मतानुसार "नाकाबन्दी युद्धशक्तियों द्वारा समुद्र के समुद्रतट अथवा उसके किसी भाग पर मूल राज्यों के जहाजों अथवा हवाई जहाजों का प्रवेश तथा निराव राज्यों के प्रवाहों से प्रतिषेध अथवा अवरुद्ध लगाना है ।" ("Blockade is the blocking by men of war of the approach to the enemy coast, or a part of it, for the purpose of preventing ingress and egress of vessels or aircraft of all nations."—Oppenheim) हान के अनुसार नाकाबन्दी युद्धस्थित राज्य द्वारा युद्ध के समय में समुद्र के अधिकार पर स्थित किसी क्षेत्र अथवा स्थान में प्रवेश अथवा पहुँच को रोकना है । यह युद्ध का एक कार्य है जो युद्धस्थित के युद्धशक्तियों द्वारा किया जाता है जिसका उद्देश्य समुद्र के तटस्थ किसी भीमांशित बन्दरगाह में प्रवेश अथवा उसके प्रस्थान को रोकना है ।

**संरोध या नाकाबन्दी के लक्षण :—**उपर्युक्त परिभाषाएँ नाकाबन्दी के निम्नलिखित लक्षणों को प्रकट करती हैं । प्रथम तो नाकाबन्दी युद्धपोतों द्वारा होनी चाहिये चाहे यह अन्य साधनों द्वारा अधिक प्रबल भी जाय । द्वितीय, केवल समुद्र का समुद्रतट अथवा उसका भाग अथवा समुद्र के बन्दरगाह ही नाकाबन्दी के लक्ष्य होने चाहिये । तृतीय, नाकाबन्दी से प्रवेश अथवा निर्गमन दोनों रोक जा सकते हैं । चतुर्थ, नाकाबन्दी सार्वजनिक मानने के लिये सब राज्यों के जहाजों अथवा हवाई जहाजों के विरुद्ध निषेधना से लगानी चाहिये । अन्त में नाकाबन्दी एक युद्ध लक्ष्य क्रिया-शीलता है ।

नाकाबन्दी का भ्रमात्मक अर्थ घेरा डालने से नहीं लगाना चाहिए जिसका लक्ष्य घिरे हुए स्थान का अभिग्रहण करने का होता है। नाकाबन्दी समुद्र द्वारा प्रत्येक पारस्परिक ससर्ग को रोकती है।

**पेरिस की घोषणा १८५६ (Declaration of Paris, 1856).**— १८५६ की पेरिस की घोषणा के चौथे अनुच्छेद में यह निर्धारित किया गया है कि नाकाबन्दी बाध्यकारी होने के लिये प्रभावपूर्ण होनी चाहिए अर्थात् ऐसे बल से स्थापित की जानी चाहिये जो शत्रु के समुद्रतट में पहुँचने को रोकने के लिये वस्तुतः पर्याप्त हो। इस नियम ने राष्ट्रों की विधि के एक सिद्धान्त को लेखबद्ध कर दिया किन्तु इस विवादपूर्ण प्रश्न को कि “पर्याप्त बल” (Sufficient Force) क्या है विचारणीय छोड़ रखा है। लार्ड चीफ जस्टिस कीकबर्न ने *Geipel v Smith* वाले मामले में [ (1872) L R 7 Q B. 404, p. 410 ] यह कथन किया कि “विधि की दृष्टि में नाकाबन्दी नभी प्रभावपूर्ण समझी जाती है जब शत्रु के जहाजों की संख्या तथा स्थिति ऐसी हो कि नाकाबन्दी को तोड़कर भाग निकलना अपने को संकट में डालना हो चाहे कुछ जहाज भाग निकलने में समर्थ हो जायें।” (In the eye of the law a blockade is effective if the enemy's ships are in such numbers and positions as to render running the blockade a matter of danger, although some vessels may succeed in getting through) नाकाबन्दी करने वाले दल का स्वरूप तथा उसकी नाकाबन्दी किय गये समुद्रतट से दूरी प्रमुख नहीं मानी जाती। पेरिस की घोषणा ने केवल इन बातों पर महत्व दिया कि इनके पूर्व में नाकाबन्दी पूर्ण मानी जाय यह आवश्यक है कि उसके बीच से होकर निकलने में वास्तव में भारी संकट का सामना करना पड़े।

क्रीमिया के युद्ध (१८५४) में यह माना गया कि ब्रिटेन के समुद्र में इधर-उधर चक्कर लगाने वाले केवल एक युद्धपातन १२० मील की दूरी छोड़कर नाकाबन्दी संगठित किया। दूसरी ओर फारमोसा की नाकाबन्दी अपूर्ण समझी गयी जो फ्रांस द्वारा १८८४ में अधिसूचित की गई थी जब ब्रिटेन ने उसके विरुद्ध यह आपत्ति की कि मासीसी नौसेना नायक के अधिकार में जो सैनिक बल था वह पर्याप्त था। इसके परिणामस्वरूप नाकाबन्दी उस समय त्याग दी गई जब तक उसको पुष्ट करने के लिये और अधिक बल नहीं पहुँचा।

व्हीटन (Wheaton) का कथन है कि नाकाबन्दी इस प्रकार तटस्थ के अधिकारों का अतिक्रमण होने के कारण उसका प्रभाव मामले की परिस्थितियों में जितना आवश्यक है उसमें अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये।

लन्दन की घोषणा १९०६ (Declaration of London, 1909) :—  
 लन्दन की अस्थापित घोषणा ने पेरिस की घोषणा (१८५६) द्वारा स्थापित इस  
 नियम की पुष्टि की कि वन्दनकारी होने के लिये नाकाबन्दी प्रभावपूर्ण होनी  
 चाहिये । इसमें आगे यह भी कहा गया कि नाकाबन्दी घोषित तथा अधिसूचित होनी  
 चाहिये । लन्दन की घोषणा के अनुसार नाकाबन्दी की घोषणा या तो युद्ध-  
 स्थित सरकार द्वारा अथवा उसके राज्य की आर से कार्य करने वाले नौसेना दल के  
 समादेशक द्वारा नाकाबन्दी आरम्भ होने वाले दिनांक नाकाबन्दी के अवीन समुद्र  
 तट की सीमाएँ तथा अवधि जिनके भीतर तटस्थ जहाज नौल जा सकें उनका  
 विशेष रूप से निर्देश करते हुए की जानी चाहिए । यह नियम तटस्थ के इस हित  
 पर आधारित है कि उनको अपने दायित्व की सीमा सम्पक रूप से विदित होनी  
 चाहिये । लन्दन की घोषणा के अनुच्छेद ११ में यह व्यवस्था की गई है कि नाका-  
 बन्दी की अधिसूचना उसे स्थापित करने वाले राज्य द्वारा तटस्थ राज्यों को उनकी ①  
 सरकारों के नाम पत्र-व्यवहार करके की जानी चाहिये । लन्दन की घोषणा में यह  
 भी व्यवस्था की गई है कि नाकाबन्दी शत्रु के अधिकार में अथवा उसके द्वारा अधि-  
 कार किये हुये बन्दरगाहों अथवा समुद्र तट से बाहर विस्तृत न होनी चाहिए, तथा ②  
 नाकाबन्दी करने वाले सैन्यदलों को तटस्थ बन्दरगाहों अथवा समुद्रतटों में पहुँच को  
 नहीं रोकना चाहिये । ③

यदि नाकाबन्दी प्रभावपूर्ण हो तथा उसका उत्पन्न हुआ हो तो उसका  
 वास्तविक ज्ञान, जहाज को पकड़े जाने तथा अपराधी प्रमाणित किये जाने का  
 उत्तरदायी ठहरा देता है । लन्दन की घोषणा के अनुच्छेद १५ के अनुसार यदि  
 जहाज ने तटस्थ बन्दरगाह को, क्षेत्रीय शक्ति को नाकाबन्दी की सूचना देने तथा ④  
 स्थानीय अधिकारियों को उसे प्रकाशन के लिये पर्याप्त समय मिला जाने के उपरान्त,  
 छोड़ा हो तो उसे इसका ज्ञान मान लिया जाना है । अनुच्छेद १७ में यह व्यवस्था  
 की गई है कि तटस्थ जहाजों को नाकाबन्दी को प्रभावपूर्ण बनाने के लिये नियम ⑤  
 किये गए जमी जहाजों की क्रियाशीलता के क्षेत्र का छोड़कर और कहीं न पकड़ना  
 चाहिये । अनुच्छेद १८ में यह व्यवस्था की गई है कि जहाज का अथवा उसके माल ⑥  
 का चाहे उसका भाग का लक्ष्य क्षेत्र कोई भी हो, यदि उस समय वह एक-एक  
 बन्दरगाह को जा रहा हो जिसमें नाकाबन्दी नहीं है तो उसे नाकाबन्दी तोड़ने के  
 लिये नहीं पकड़ना चाहिये । अनुच्छेद २१ में नाकाबन्दी भंग करने पर दण्ड की ⑦  
 व्यवस्था की गई है । इसमें यह नियम किया गया है कि जहाज जो नाकाबन्दी भंग  
 करने का अपराधी पाया जाय, उसे दण्डित किया जायगा । उसमें सदा हुआ माल  
 भी अपराधी समझा जाता है जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि माल सादे



समय व्यापारी को नाकाबन्दी भग किये जाने का न तो ज्ञान था, और न उसको ज्ञान हो सकना सम्भव था ।

**नाकाबन्दी के प्रकार (Forms of Blockade)** — नाकाबन्दी के कई ढंग हो सकते हैं जैसे प्रभावकारी नाकाबन्दी (Effective Blockade), तथ्यत नाकाबन्दी (Blockade de facto), विज्ञप्ति द्वारा नाकाबन्दी (Blockade by Notification), कागजी नाकाबन्दी (Paper Blockade), सैनिक नाकाबन्दी (Strategic Blockade), व्यापारिक नाकाबन्दी या वैसफिक नाकाबन्दी (Commercial Blockade or Pacific Blockade) साधारण और सार्वजनिक नाकाबन्दी (Simple and Public Blockades), आदि ।

**वास्तविक तथा बन्धनकारी नाकाबन्दी के आवश्यक अंग (Essentials of a Real and Binding Blockade)** — वास्तविक तथा बन्धनकारी नाकाबन्दी के आवश्यक अंग निम्नलिखित हैं —

१. उचित सस्थापन ( Proper Establishment ) — इसलिये कि नाकाबन्दी वैध मानी जाय यह युद्धस्थित सरकार के प्राधिकार अथवा किसी विशिष्ट नाकाबन्दी को घोषित करने के लिये विशेष रूप से प्राधिकृत नीसेना के समादेशक के अधीन सस्थापित करना चाहिये ।

२. प्रभावकारिता (Effectiveness) — नाकाबन्दी सम्यक् रूप से प्रभावशालिनी होनी चाहिये । यह काल्पनिक अथवा कागजी नाकाबन्दी न होनी चाहिये वरन् शत्रु के समुद्रतटों में पहुँच को रोकने के लिये पर्याप्त सैन्यबल से स्थापित करना चाहिये । नाकाबन्दी के इस रूप पर पेरिस की घोषणा (१८५६) तथा लंदन की घोषणा (१९०६) दोनों के द्वारा महत्व दिया गया । जहाजों को उसके बीच से निकलकर जाने के किसी प्रकार के यत्न करने में वास्तविक तथा प्रबल भय होना चाहिये ।

प्रभावशाली नाकाबन्दी के लिये क्या क्या आवश्यक बातें अपेक्षित हैं इसके सम्बन्ध में कोई मतव्य नहीं है । राइट आनरेबुल डाक्टर लुसिगटन ने Franciska [ (1855) Spinks, 217 ] में नीसेना के उच्च न्यायालय में यह व्यक्त किया कि नाकाबन्दी किये गए स्थान की चौकसी ऐसे सैन्य बल से की जानी चाहिये जो निर्यात तथा आयात को पर्याप्त रूप से सक्त्पूर्ण बना दे अथवा अग्न शब्दा में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों जैसे कुहरा, प्रबल हवा, तथा कुछ आवश्यक अनुपस्थितियों को छोड़ कर भीतर प्रवेश करने अथवा बाहर निकलने के प्रयत्न करने वाले जहाजों का अभिग्रहण अत्यधिक समभव बना दे ।

लार्ड चीफ जस्टिस कौकबर्न ने *Geipal v. Smith* [(1872) L. R. 7 Q. B. 404] में यह कथन किया कि नाकाबन्दी तभी प्रभावशाली है यदि शत्रुओं के जहाजों की सख्या तथा स्थिति ऐसी हो जिससे नाकाबन्दी तोड़कर निकल भागना एक सकट का विषय हो जाम यद्यपि कुछ जहाज ऐसा करने में सफल भी हो जाय ।

सन् १७८० के प्रथम सैनिक तटस्थता में यह उद्घोषणा करके कुछ कठोर-तम विचार प्रकट किये गये कि "नाकाबन्दी केवल उस समय प्रभावशाली है, जब समुद्रतट पर पहुँच, युद्धपोतों की एक पक्ति से रोक दी गई हो जो उस स्थान पर लगर डाले हों तथा एक दूसरे के इतने समीप हो कि निकलने वाला जहाज प्रकट रूप से बिना सकट का सामना किए हुए निकल नहीं सकता हो (Cf Oppenheim: International Law, Vol. II 7th Ed. p. 779) । फिलिमोर भी इसी प्रकार का विचार इस कथन से व्यक्त करते हैं कि "एक वास्तविक नाकाबन्दी कई जहाजों की सहा करने से की जाती है जो निषिद्ध बन्दरगाह के मुख के चारों ओर घेरे का एक मडल बना दे जिसमें कि यदि मडल किसी एक भाग में असफल रहे तो नाकाबन्दी पूर्णतया असफल हो जाती है ।" (iii, S 263)।

यह प्रश्न कि क्या कोई नाकाबन्दी प्रभावशाली है अथवा नहीं, एक तथ्य का प्रश्न है [ Cf Art 3, Declaration of London 1909, and Oriental Navigation Company ( 1928 ) A. J. I. L. 23 (1929), P. 435 at ¶ 442 ) ] ।

३. निरन्तर बनाये रखना ( Continuously Maintained ) — नाकाबन्दी निरन्तर बनाई रखनी चाहिये । उस दशा में जब नाकाबन्दी करने वाला दल शत्रु के सर्वोच्च दल द्वारा भगा दिया जाय यह माना गया है कि नाकाबन्दी आरम्भ से ही निष्फल तथा दोषपूर्ण है लेकिन यदि नाकाबन्दी करने वाला दल दुर्दिन व कारण अस्थायी रूप से हटा लिया जाय तो नाकाबन्दी में कोई कमी नहीं समझी जायगी ।

४ अधिसूचना (Notification) :—सन्धन की घोषणा में यह निर्धारित किया गया कि नाकाबन्दी स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि यह घोषित की जाय । अधिसूचना या तो विज्ञप्ति या युद्धस्थित सरकार द्वारा अथवा उस राज्य की ओर से कार्य करने वाले नौसेनादल के समादेशक द्वारा होनी चाहिये तथा उसमें नाकाबन्दी आरम्भ होने का दिनांक, नाकाबन्दी के अधीन समुद्रतट की भौगोलिक सीमाएँ, तथा वह अवधि जिसके भीतर तटस्थ जहाज बाहर निकल या नकें, विशिष्ट प्रकार से वर्णित भी जानी चाहिये । नाकाबन्दी की सूचना वास्तविक तथ्यों के अनु-रूप होनी चाहिये अन्यथा नाकाबन्दी निष्प्रभाव हो जायगी ।

५ निष्पक्षता ( Impartiality ) —नाकाबन्दी करने वाले सैन्यदल को नाकाबन्दी निष्पक्षता से सब जहाजों के विरुद्ध प्रवृत्त करानी चाहिये । तटस्थता को बहिष्कृत करके किसी एक युद्ध में लगे हुये राज्य के पक्ष में शिथिलता नाकाबन्दी को निरर्थक कर देती है । नाकाबन्दी केवल तभी ग्राह्य है जब वह सर्वव्यापी हो । *Franciska* वाले मामले में [ ( 1855 ) *Spinks* 287 ] रूस के विरुद्ध क्रिमिया के युद्ध में ब्रिटेन द्वारा सीमा की नाकाबन्दी प्रिवी कौन्सिल द्वारा अवैध घोषित की गई क्योंकि तटस्थता को बहिष्कृत करके युद्धस्थित के व्यापारिक जहाजों के सम्बन्ध में शिथिलता दिखाई गई थी ।

६ नाकाबन्दी करने वाले सैन्य दल को तटस्थ बन्दरगाहों अथवा समुद्रतट तक पहुँचने में नहीं रोकना चाहिये ।

७ नाकाबन्दी उसको स्थापित करने वाले सैन्यदल की क्रियाशीलता से व्याप्त क्षेत्र के बाहर विस्तृत नहीं हो सकती ।

नाकाबन्दी का भङ्ग ( Breach of Blockade ) —सर विलियम स्काट का कहना है कि नाकाबन्दी का उल्लंघन स्थापित करने के लिये तीन बातें प्रमाणित होनी चाहिये — प्रथम वास्तविक नाकाबन्दी का अस्तित्व, द्वितीय, ज्ञान उस पक्षकार को झार से जिसके सम्बन्ध में यह माना गया है कि उसका अवरोध हुआ है, तथा तृतीय, कुछ उल्लंघन का कार्य—नाकाबन्दी भारम्भ होने के उपरान्त लड़ा हुआ माल लेकर या तो भीतर जाना या बाहर घाना । इस बात को प्रकट करने के लिये कि नाकाबन्दी का उल्लंघन हुआ है उसका अस्तित्व ही नहीं बरन् उसके अस्तित्व का ज्ञान भी पक्षकार को हो जाना चाहिये ।

इस सम्बन्ध में कि किस बात से नाकाबन्दी का भंग स्थापित होता है राज्यों की रीति में भेद रहा है । इंग्लैंड तथा अमेरिका यह मत रखते हैं कि इस बात का सभाविन रूप से स्थापित करना पर्याप्त है कि तटस्थ जहाज के कार्यभार साधकों को यह ज्ञान था कि नाकाबन्दी स्थापित की गई है । ग्रेट ब्रिटेन ने सर्वदा यह मत रखा है कि नाकाबन्दी की प्रसिद्धि ही उनके अस्तित्व की सूचना दिये जाने के बराबर है । फ्रांसवालों के मतानुसार तटस्थ जहाज नाकाबन्दी के प्रवृत्त रहने अथवा उसके समाप्त होने के अनुमानों से प्रभावित नहीं होता तथा तटस्थ जहाज का समादेशक नाकाबन्दी किये गये क्षेत्र में पहुँचने पर नाकाबन्दी करने वाले नौसेना दल द्वारा नाकाबन्दी के अस्तित्व को चेतावनी दिये जाने का अधिकारी है । फिर भी यह बात स्थिर है कि विजिति द्वारा नाकाबन्दी के सम्बन्ध में सूचना का अनुमान कर लिया जाना है यदि सूचना सम्पूर्ण रूप से जारी की गई हो, तथा उस समय से तटस्थ सरकारों को उसे प्राप्त करने के लिये पर्याप्त समय व्यतीत हो गया हो ।

**नाकाबन्दी की समाप्ति ( Cessation of Blockade ) :—**निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक के होने पर नाकाबन्दी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है ।

- (१) युद्ध की समाप्ति पर;
- (२) नाकाबन्दी स्थापित करने वाली सरकार क उसे हटा देने पर;
- (३) उसकी प्रभाविकता की समाप्ति पर;
- (४) जब नाकाबन्दी करने वाला नौसैन्य दल शत्रु दल द्वारा पराजित कर दिया जाय तथा भगा दिया जाय;

(५) जब यह अनुसरण अथवा युद्ध क लिये हटा लिया जाय,

(६) जब नाकाबन्दी के अधीन स्थान अथवा बन्दरगाह विजयी युद्धस्थित द्वारा अधिकार में ले लिया जाय ।

**नाकाबन्दी भंग करने के लिए दंड ( Penalty for Breach of Blockade ) :—**नाकाबन्दी को उल्लंघन करने का केवल विचारमात्र ही अपराधी प्रमाणित किये जाने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है । विचार के साथ ही साथ कोई कार्य भी होना चाहिये जिससे यह प्रकट हो कि बन्दरगाह में प्रवेग करने का यत्न किया गया है । सामान्य नियम यह है कि जहाज नाकाबन्दी भंग करने के लिये अपराधी प्रमाणित किया जाता है, तथा साथ ही साथ उनमें लदे हुए माल की भी वही गति होती है । माल के स्वामीगणों के सम्बन्ध में यह अनुमान कर लिया जाता है कि उनके माल लादते समय उन्हें नाकाबन्दी के अस्तित्व का ज्ञान था, तथा वे नाकाबन्दी उल्लंघन करने में गुप्त रूप से भागी सम्भवे जाते हैं ।

लन्दन की घोषणा के अनुच्छेद २१ में इस नियम को यह कह कर स्पष्ट किया गया है कि जो जहाज नाकाबन्दी भंग करने का अपराधी पाया जाय वह दण्डित किया जायगा । उस पर लदा हुआ माल भी अपराधी प्रमाणित किया जायगा जब तक यह प्रमाणित न हो जाय कि माल लादते समय व्यापारी को नाकाबन्दी भंग करने के विचार का न तो ज्ञान रहा और न ज्ञान रहना सम्भव ही था ।

पकड़े जाने के बाद नाकाबन्दी करने वाला जहाज नौजितमाल द्वारा उसके सम्बन्ध में निर्णय के लिये एक बन्दरगाह को भेजा जाता है । चालरगणों को बन्दी करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें किसी भी दशा में नौजितमाल न्यायालय के निर्णय के उपरान्त छोड़ देना चाहिये । यदि जहाज तथा उस पर लदे हुये माल के स्वामी एक ही हुये तो जहाज तथा उस पर लदा हुआ मान दानों जवन कर लिये जाते हैं । यदि वे भिन्न-भिन्न हुए तो मान केवल उनी दशा में जवन किया जाता है जब वह युद्ध में प्रतिपिद्ध हो अथवा स्वामियों को मान लादने समय नाकाबन्दी का ज्ञान रहा हो ।

**निर्णीत वाद (Case Law)**—कुछ महत्वपूर्ण वादों का यहाँ उल्लेख आवश्यक है। फ्रान्सिसका (Franciska) क वाद में, जिसका कि सन्दर्भ पहले ही दिया जा चुका है, स्मरणीय है कि फ्रान्सिसका एक डेनिश पोत था, जो कि एक ब्रिटिश क्रूजर द्वारा उस समय पकड़ा गया जब कि वह रीगा के लिये जा रहा था और जब कि रीगा नामक बन्दरगाह ब्रिटेन के द्वारा रूस के विरुद्ध किये गये क्रोमिया युद्ध के समय सरोधित कर दिया गया था। पोत के मालिकों द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि नाकाबन्दी को तोड़ने का कोई आशय नहीं था और फ्रान्सिसका को सभी रीगा के लिये आने बढने का आदेश दिया गया था जब कि नाकाबन्दी या सरोध न हो। यह कहा गया कि सरोधित स्थान के प्रति अज्ञान का तर्क इस विशिष्ट वाद में इस कारण से अवैध है कि जहाज के कप्तान को नाकाबन्दी की सूचना उमी समय से हो गई थी जब कि जहाज पिछले बन्दरगाह से आगे को बढ़ा। प्रीमी कौंसिल क न्यायाधीशों का निष्कर्ष था कि नाकाबन्दी, भले ही अन्यथा परिस्थितियों में वैध हो, किन्तु यहाँ पर अवैध माना जायगी क्योंकि कुछ ऐसी छूट युद्ध सलग्न व्यापारी पोतों को दी गई हैं। जिससे तटस्थ शक्तियाँ बचिती थी।

फ्रेडरिक मोल्के (Frederic Molke)<sup>१</sup> के वाद में एक डेनिश पोत एक ब्रिटिश पात द्वारा उस समय बन्दी बना लिया गया जब कि वह हैवर (Havre) नामक बन्दरगाह से बाहर आ रहा था। यह बन्दरगाह फ्रांस से युद्ध के समय ब्रिटेन द्वारा सरोधित कर दिया गया था। डेनिश पोत एक तटस्थ पोत था और वास्तविक उसका गन्तव्य हैवर ही था किन्तु प्रकट रूप से वह कोपेनहेगेन के लिये ब्रुक किया गया था। लार्ड स्टोवेल (Lord Stowell) ने उस पोत और बेड़े की भर्त्सना की क्योंकि पोत का नाकाबन्दी की अस्तित्व के जानकारी करा दी गई थी। यह अवलोकन किया गया कि एक ऐसा पोत जो कि किसी सरोधित बन्दरगाह से बेड़े सहित बाहर आ रहा है, प्रथम दृष्टया बन्दी बना लिये जान क योग्य है।

**वांछित साक्ष्य (Proof Required)**—बेट्सी (Betsey)<sup>२</sup> के वाद में, जिसका कि सन्दर्भ ऊपर दिया जा चुका है, सर विलियम स्कॉट (Sir William Scott) ने लिखा था कि नाकाबन्दी के प्रश्न पर तीन बातों को अवश्य ही प्रमाणित हो जाना चाहिये पहली बात यह कि एक वास्तविक नाकाबन्दी अस्तित्व में है (The existence of an actual blockade), दूसरी बात यह कि पक्षकार को उसका ज्ञान था (The knowledge of the party), और तीसरी बात यह कि उनके

1. (1793) 1 C Rob 85.

2. (1793) 1. C Rob, 93

अतिलंघन में कोई कार्य किया गया हो (Some act of violation), जैसे नाकाबन्दी के लागू होने के बाद लदे हुए कार्गो का भीतर ले जाना या बाहर ले आना ।

प्राइज केसेज इन रो० हिवाथा (Prize cases in re Hiwatha)<sup>१</sup> के बाद में संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अवलोकन किया गया था कि पोत चूँकि संरोधित बन्दरगाह में है तो यह प्रकल्पना की जा सकती है कि वहाँ पहुँचते ही उसे नाकाबन्दी की सूचना मिल गई होगी । राष्ट्रों की विधि में यह निर्णित नियम है । अतः कार्गो और पोत दोनों को एक परिणाम का भागी होना चाहिये ।

जमोरा (Zamora)<sup>२</sup> में सार्ड पार्कर (Lord Parker) का अवलोकन था कि किसी नाकाबन्दी की घोषणा करने वाला आदेश प्रथम दृष्टया रूप में संरोधित बन्दरगाहों में प्रवेश करने वाले पोतों को पकड़ लेने को न्यायोचित घोषित करेगा ।

लियोनोरा (Leonora)<sup>३</sup> के बाद में एक स्वीडिश कम्पनी द्वारा एक डच पोत पकड़ने वाला ब्रिटिश प्रजूर था । इस प्रसंग में यह अवलोकन किया गया कि वह परिपक्व आदेश जिसने कि पोत को पकड़े जाने को प्राधिकृत किया तदस्य बन्दरगाहों की नाकाबन्दी की घोषणा के लिये उपयुक्त नहीं है और यह कि उस आदेश में तदस्थो द्वारा सामानों को ले आने से जाने का पूर्ण निषेध नहीं था ।

### लम्बी दूरी की नाकाबन्दी

प्रथम विश्वयुद्ध (First World War) :—प्रथम विश्वयुद्ध (१९१४-१८) में ब्रिटेन की नौ सेना ने मुरंगों तथा पनडुब्बियों का भय सामने आने पर अपने जहाजों द्वारा जर्मनी की अत्यधिक दूरी की नाकाबन्दी प्रवृत्त की जो जर्मन बन्दरगाहों से एक हजार मील से भी अधिक दूरी छाये हुये थी । नागरिक जनता को बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ा तथा जर्मनी ने नाकाबन्दी को अवैध कहकर उसकी निन्दा की । इग्लैंड द्वारा प्रवृत्त यह अत्यधिक दूरी की नाकाबन्दी जर्मनों के उस निर्णय के प्रतिकार स्वरूप थी जिसके द्वारा उसने ब्रिटिश आइस के चारों ओर के जलभागों में स्थित ब्रिटेन तथा मित्रों के व्यापारिक जहाजों पर उनके यात्रियों भ्रमण चालकगणों की रक्षा का ध्यान दिये बिना आक्रमण करने को कहा था । Stigstad वाले मामले (1919) A. C. 279] में लार्ड समर द्वारा यह निर्णय किया गया कि एक युद्धमान को अन्य युद्धमान की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय विधि के मंग किये जाने पर प्रतिकारक उपायों के करने का अधिकार है तथा यह कि प्रतिपिद्ध वस्तुओं वा

1. (1862) 2 Black, 635.

2. (1916) 2 A. C. 77.

3. (1919) A C. 974.

यातायात, अतटस्थ सेवा तथा नाकाबंदी के नियमों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए तटस्थ व्यापार को बिना हस्तक्षेप अथवा निराध ने निरकुश रूप से जारी रहने का अधिकार नहीं है ।

द्वितीय विश्वयुद्ध (१९३६-४५) (Second World War) :—द्वितीय विश्वयुद्ध (१९३६-४५) में ब्रिटेन तथा फ्रांस द्वारा सम्पूर्ण आर्थिक युद्ध के अभिकरण पर लम्बो दूरी की नाकाबन्दी का पुन अवलम्बन किया गया किन्तु पूर्व में भी युद्ध छिड़ जाने के कारण इससे अधिक प्रभाव नहीं पड़ा । जर्मनी ने भी सुरंग बिछाना तथा पनडुब्बियों द्वारा युद्ध आरम्भ किया । ग्रेट ब्रिटेन ने प्रतिवार के उपाय स्वरूप नवम्बर २७ सन् १९३६ का एक आर्डर-इन-कौंसिल जारी किया जिसके द्वारा जर्मन बन्दरगाहों अथवा जर्मन उत्पत्ति अथवा स्वामित्व के माल का अतिप्रचणु प्राधिकृत किया गया । जुलाई ३१ सन् १९४० के आर्डर-इन-कौंसिल ने यह निर्देश दिया कि उनकी बचत के लिये नैवीसर्ट प्रमाणपत्र (प्रमाण पत्र जो तटस्थ देश के कूट-नीतिक प्रतिनिधि द्वारा दिया जाय जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाय कि तटस्थ जहाज में लदा हुआ माल पकड़े जाने योग्य नहीं है) की अनुपस्थिति में माल पकड़ लिया जा सकता है तथा यह व्यवस्था की गई कि यह अनुमान कर लिया जायगा कि माल जिनके लिये नैवीसर्ट प्रमाणपत्र न हा शत्रु के प्रदेश को जा रहे हैं । नैवीसर्ट, मेलसर्ट इत्यादि की पद्धति ने नाकाबन्दी को सरल कर दिया तथा इसका प्रभाव वास्तव में तटस्थ व्यापार को तटस्थ देश के राजनयिक तथा कौंसिल प्रतिनिधियों द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्रों तथा प्रवेशपत्रों द्वारा नियंत्रण करने का था । ये उपाय कठारता से नाकाबन्दी के सामान्यतः स्वीकृत नियमों की आवश्यकताओं के अन्तर्गत नहीं लाये जा सकते थे किन्तु नौसेना युद्ध की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो गये थे ।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो जायगा कि पुरानी पद्धति जिसके अन्तर्गत नौ-शक्तियों को सरोधित कर दिया जाता था, आधुनिक परिस्थितियों में प्रबन्धीय नहीं है, विशेष रूप में उस समय जब कि टारपीडो नौकायें और सबमैरीन्स का ऐसा युग आ गया है जिसमें कि सरोधित किनारों पर को जाने वाली कार्यवाहियाँ भीलों से दिखाई तक नहीं पड़ती । नौसेना स्कवाड्रन की नाकाबन्दी भी नम आक्रमण के चंगुल से नहीं बच सकती । ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि हिजिन्स (Higgins) और कोलम्बोस (Colombos) द्वारा कहा गया है, वास्तविक नाकाबन्दी आज एक अव्यवहारिक हो चुकी है । अब नाकाबन्दी सम्बन्धित प्रतिबन्ध ऐसे ही द्वितीय दशके के बीच पोतों के आवागमन के प्रसंग में लागू हो सकती है जैसे ग्रेट ब्रिटेन और जापान ।<sup>1</sup>

1. Higgins & Colombos The International Law of the Sea, 2nd Ed, p 559

निकट नावाबन्दी ( Close Blockades ) अब असम्भव हो जाने के कारण दूरवर्ती नाकाबन्दी की वैधता को उम समय चुनौती नहीं दी जा सकती यदि युद्ध सलग्न शक्ति का यह अधिकार मान्य कर लिया है कि वह व्यापारिक पोतों का भी सम्बन्ध विच्छेद कर दे।

अतः यहाँ हिजिन्स और कोलम्बस के शब्दों में कहा जा सकता है कि 'blockades conducted in strict accordance with the old rules are of little strategic value and that in the circumstances of modern naval warfare long range blockades are valid provided that they effectually prevent the ingress to or egress of all vessels and goods from the blockaded area by sea and provided also that they are properly announced and maintained'

अर्थात् प्राचीन नियमों के अक्षरशः पालन में किया गया सरोध आज के युग में किसी भी सैनिक महत्व का नहीं है और यह कि आधुनिक नौयुद्ध कौशल की परिस्थितियों में ऐसे दूरवर्ती सरोध वैध हैं शर्त यह कि वे प्रभावकारी रूप में सरोधित क्षेत्र से पोत और सामान आने या जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा सकें और शर्त यह भी है कि उन्हें समुचित रूप से घोषित कर दिया जाय और बनाये रखा जाय।

## अध्याय ४६

### विनिषिद्ध

#### (Contraband)

परिभाषा —आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में "युद्ध में विनिषिद्ध ऐसी वस्तुओं का नाम है जो युद्धस्थिति में से किसी एक के द्वारा शत्रु के पास ले जाये जाने को इस आधार पर निषिद्ध की जाती है कि उनसे वह लड़ाई अधिक प्रबलता के साथ लड़ने में समर्थ हो जाता है।" ("Contraband of war is the designation of such goods as are forbidden by either belligerent to be carried to the enemy on the ground that they enable him to carry on the war with greater vigour" Oppenheim International Law, Vol II, p, 799)। केलसन के अनुसार "युद्ध में विनिषिद्ध वे वस्तुएँ हैं जिनका शत्रु के पास परिवहन युध्यमानों में से किसी एक के द्वारा सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार निषिद्ध है" (Contraband of war are goods the transport of



which to the enemy is forbidden by either belligerent in conformity with general International Law. : Hans Kelsen : Principles of International Law, p. 79) । युद्ध में विनिषिद्ध ऐसी वस्तुओं का द्योतक है जिनका तटस्थ द्वारा युद्धस्थित के पास ले जाना आपत्तिजनक समझा जाता है क्योंकि वे युद्ध को जारी रखने में प्रत्यक्षरूप से उपयोगी समझी जाती हैं अथवा अन्य प्रकार से युद्धस्थितों में से एक को युद्ध संचालन में सहायता प्रदान करती हैं ।

जैकसन ( Jackson ) का कथन है कि विनिषिद्ध वह सम्पत्ति है जो शत्रु के क्षेत्र को जा रही हो और इस प्रकार की हो कि शत्रु को युद्ध में सहायता दे सके ।

इसका आधार ( Its Basis ) :—पिटकोवेट के अनुसार विनिषिद्ध की विधि का आधार युद्धस्थित का वह अधिकार है जिससे वह उस तटस्थ सम्पत्ति को अपराधी प्रमाणित कर सकता है जो उसके शत्रु के सैनिक उपयोग के लिये जा रही हो ।

पण्य का विभाजन ( Division of Commodities ) :—ग्रोशस ( Grotius ) ने पण्य को तीन वर्गों में विभाजित किया है :—(१) वे वस्तुएँ जो केवल युद्ध के लिये उपयोगी हैं, उदाहरणार्थ शस्त्र, प्रक्षेपण, बारूद इत्यादि (२) वे वस्तुएँ जो युद्ध-सदृश प्रयोजनों के लिये निरर्थक हैं, उदाहरणार्थ फैशन की तथा फेंसी वस्तुएँ, घड़ियाँ, जेबघड़ियाँ तथा साबुन इत्यादि तथा (३) वे वस्तुएँ जो युद्ध तथा शान्ति की बिना अपेक्षा किये हुए उपयोगी हैं यथा द्रव्य, खाद्य पदार्थ, जहाज, नौसेना सामग्री, इत्यादि । उनके अनुसार प्रथम तो जब वे शत्रु के क्षेत्र को जा रही हो मार्ग में अभिग्रहीत की जा सकती हैं, दूसरी अभिग्रहीत किये जाने से सर्वदा उन्मुक्त हैं तथा तीसरी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर हैं ।

वत्सल ( Vattel ) कुछ अंशों में इसी प्रकार का भेद करते हैं लेकिन वह लकड़ी तथा नाविक सामग्री को उन वस्तुओं में सम्मिलित करते हैं जो युद्ध के प्रयोजन के लिए उपयोगी हैं तथा ऐसी परिस्थिति में तटस्थों को उन्हें शत्रु के पास ले जाने का निषेध करते हैं ।

इस सम्बन्ध में कि कौन सी वस्तुएँ विनिषिद्ध वही जाँच मतभेद है । ब्रिटेन का मत विनिषिद्ध वस्तुओं की एक लम्बी सूची बनाने के पक्ष में है तथा उसके अनुसार वस्तुओं के पूर्णतः विनिषिद्ध, सप्रतिबन्ध प्रासंगिक अथवा सापेक्षिक विनिषिद्ध पदार्थों में विभाजित करता है । पूर्णतः विनिषिद्ध पदार्थों में ऐसी वस्तुएँ सम्मिलित हैं जैसे शस्त्र, उनको बनाने के यंत्र, गोला, बारूद, सैनिक प्रचार या बपड़ा इत्यादि; लेकिन सप्रतिबन्ध, प्रासंगिक अथवा सापेक्षिक विनिषिद्ध वस्तुओं में ऐसे पदार्थ माते हैं जैसे खाद्यसामग्री, बोटिंग, सोना इत्यादि जो परिस्थितियों के अनुसार विनिषिद्ध

होते हैं अथवा नहीं। फ्रांस वालों के मतानुसार जिसका अनुकरण यूरोप की अन्य शक्तियों द्वारा किया गया इसकी तुलना में बहुत कम वस्तुओं को विनिषिद्ध माना गया तथा यह माना गया कि संप्रतिबन्ध विनिषिद्ध वस्तुएँ नहीं हो सकती हैं। वही वस्तु विनिषिद्ध थी अथवा नहीं थी, तथा वह दोनों नहीं हो सकती थी अर्थात् एक प्रकार की परिस्थितियों में विनिषिद्ध तथा अन्य प्रकार की परिस्थितियों में निर्दोष।

सन् १९०६ की असत्यापित सन्धन की घोषणा ने दो परस्पर विरोधी मतों के इस दीर्घकालीन झगड़े को तय करने का प्रयत्न किया। इसने वस्तुओं को तीन वर्गों में विभाजित कर दिया अर्थात् निरपेक्ष विनिषिद्ध, संप्रतिबन्ध विनिषिद्ध तथा अनिषिद्ध।

**निरपेक्ष विनिषिद्ध (Absolute Contraband).**—निरपेक्ष विनिषिद्ध माल वे वस्तुएँ हैं जो विशेष रूप से युद्ध के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाये जाने के निमित्त हैं अर्थात् सब प्रकार के शस्त्र, उनको उत्पादन करने का यंत्र, प्रक्षेपण, बारूद, तोपों के आरोपण, कपड़ा तथा सामान जो स्पष्ट रूप से सैनिक लक्षणों से युक्त हो, विशेष रूप से सैनिक लक्षण की जीन तथा लगाम, कवच, युद्धरोत इत्यादि। ऐसी वस्तुएँ ऐसे रूप तथा लक्षणों से ही दोषयुक्त हैं। वे ऐसी वस्तुएँ हैं जो शत्रु को ऐसा सैनिक लाभ प्रदान करने वाली हैं कि युध्यमान को उनके अभिग्रहण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः घोषस का यह विचार उचित ही है कि तटस्थ जो इस प्रकार से पूर्णतः विनिषिद्ध वस्तुओं को युध्यमान को प्राप्त करवाये “शत्रु के पक्ष का” हो जाता है। ऐसा माल अपराधी प्रमाणित तथा जप्त कर लिया जा सकता है चाहे माल सीधा जा रहा हो अथवा उसे दूसरे जहाज में लादना हो या भनंतर स्थान से परिवहन करना हो।

**संप्रतिबन्ध विनिषिद्ध (Conditional Contraband).**—संप्रतिबन्ध विनिषिद्ध माल में वे वस्तुएँ आती हैं जो युद्ध तथा शान्ति दोनों प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जा सकें। वे इस प्रकार की वस्तुएँ हैं जैसे खाद्य पदार्थ, चारा तथा घनाज, कपड़े, वस्त्र, सोना, तथा चाँदी सिक्कों तथा चाँदी या सोने की ठोस ईंटों के रूप में बाहन, नावे, रेलवे सामान, जलाने की लकड़ी तथा जीन और लगाम, इत्यादि। ऐसी वस्तुएँ यदि वे युध्यमान के सैनिक दलों के लिए जा रही हों अथवा किसी जहाज पर लदी हुई पाई जाय जो ऐसे देश को जा रहा हो जो शत्रु का अधिकार अथवा दखल में हो तथा जब वे मध्यवर्ती तटस्थ बन्दरगाह में उतराने जान को न हो तो अभिग्रहीत की जा सकती हैं।

**अनिषिद्ध (Non Contraband).**—अनिषिद्ध अथवा प्रतिबन्धरहित वस्तुओं में कच्ची रूई, ऊन, रेशम, जूट, तिलहन, रबर, कच्चा खमड़ा, चीनी मिट्टी

के पात्र, घड़ियाँ, तथा जेब घड़ियाँ, फैशन तथा फैसी का माल, कार्यालय का सामान इत्यादि आते हैं। ऐसी वस्तुएँ किसी भी देश में विनिषिद्ध घोषित नहीं की जा सकती।

**पीटरहोफ़ वाला मामला (The Peterhoff Case) :**—विनिषिद्ध के विषय ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान पीटरहोफ़ वाले मामले [(1866) 5 Wallace 58] में आकर्षित किया जिसमें शुद्ध युद्ध के मध्य इंग्लैण्ड से विनिषिद्ध माल मैटामोरास को भेजा गया था जो रायो डे ग्रेनेड में मेक्सिको की ओर स्थित एक तटस्थ बन्दरगाह था। यह कहा गया कि जहाज का मालय दक्षिणी मध्य के समुद्रतट की नाकाबन्दी को उल्लंघन करने का था यद्यपि वह प्रत्यक्षतः एक तटस्थ बन्दरगाह को जा रहा था। न्यायालय ने व्यक्त किया कि “माल को विनिषिद्ध अथवा अविनिषिद्ध वस्तुओं में वर्गीकरण ने मूलग्रंथ लेखकों तथा विधि विद्वानों को बहुत उद्विग्न किया है। पूर्णतः से शुद्ध तथा संतोषपूर्ण वर्गीकरण कदाचित् असाध्य है लेकिन यह कहा जा सकता है कि अमेरिका तथा इंग्लैण्ड के निर्णयों से जो कुछ सबसे अधिक पुष्ट किया गया है उसके अनुसार व्यापारी माल को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात् (१) वे वस्तुएँ जिनका उत्पादन तथा मुख्यतः अथवा सामान्यतः उपयोग युद्ध के समय में सैनिक प्रयोजनों के लिये किया जाय, (२) वे वस्तुएँ जो परिस्थितियों के अनुसार युद्ध अथवा शान्ति के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जायें। तथा (३) वे वस्तुएँ जो केवल शान्ति के प्रयोजनों के लिये उपयोग की जायें। प्रथम वर्ग का व्यापारिक माल जो एक युद्धस्थित देश को अथवा युद्धस्थित की सेना अथवा नौसेना द्वारा अधिकृत स्थानों को ले जाया जा रहा हो सर्वदा विनिषिद्ध है, दूसरे वर्ग का व्यापारिक माल केवल उसी देश में विनिषिद्ध है जब वह वास्तव में युद्धस्थित की सेना अथवा नौसेना के उपयोग के लिये ले जाया जा रहा हो और तीसरे वर्ग का व्यापारिक माल किसी प्रकार से भी विनिषिद्ध नहीं है तथापि वह नाकाबन्दी अथवा घेरे के उल्लंघन करने के लिये अभिग्रहण अथवा अपराधी प्रमाणित किय जाने के अधीन है।”

लन्दन की असद्व्यपित घोषणा के अनुच्छेद ३० में यह निर्धारित किया गया है कि पूर्णतः विनिषिद्ध माल यदि वह शत्रु के अधीन अथवा शत्रु द्वारा अधिकृत क्षेत्र को अथवा शत्रु के सैनिक दलों को ले जाया जा रहा हो तो वह अभिग्रहीत किया जा सकता है। निरपेक्ष विनिषिद्ध वस्तुओं के लिये केवल जो बात अपेक्षित है वह यह है कि वह किसी भी प्रकार के शत्रु के क्षेत्र को ले जाया जा रहा है। जब जहाज के कागजपत्रों से यह प्रकट हो कि माल शत्रु के किसी बन्दरगाह में उतारा जाने वाला है अथवा उसकी सेनाओं या जंगी जहाजों को दिया जाने वाला है तो शत्रु के क्षेत्र का अनुमान किया जा सकता है।

अनुच्छेद ३३ में यह व्यवस्था की गई है कि संप्रतिबन्ध विनिपिद्ध माल केवल उसी दशा में अभिग्रहीत किया जा सकता है जब वह या तो शत्रुराज्य के सैनिक दलों अथवा सरकारी विभाग तक ले जाया जा रहा हो । संप्रतिबन्ध विनिपिद्ध वस्तुओं के प्रसंग में अभिग्रहण किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि वे शत्रुराज्य के सैनिक दलों अथवा उसके किसी सरकारी विभाग के लिए जाये जा रहे हों । यदि संप्रतिबन्ध विनिपिद्ध माल शत्रु द्वारा अधिकृत किसी सुरक्षित स्थान के लिए अथवा उसकी क्रियाशीलता के आस्थान तक, अथवा उसके प्राधिकारियों अथवा शत्रु देश के किसी ठेकेदार तक जो शत्रु की सरकार को विवादग्रस्त प्रकार की वस्तुओं को पहुँचाता हो, भेजा जा रहा हो तो माल का लक्ष्य शत्रु का क्षेत्र होना अनुमानित किया जा सकता है । लोरेस उचित रीति से यह व्यक्त करते हैं कि “यह बात कि माल किस उपयोग में लाया जायगा उसके दोषी होने अथवा निर्दोष होने को प्रमाणित करती है । उपयोग का प्रमाण माल का लक्ष्य स्थान है तथा कागज पत्रादि लक्ष्य स्थान के प्रमाण हैं ।”

अपराध के आवश्यक अंग (Essentials of Guilt) —लोरेस विनिपिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में अपराधी होने के अंगों को निम्नलिखित शब्दों में संक्षिप्त करते हैं :—सर्वप्रथम यह कि विनिषेध की विधि का लक्ष्य परिवहन है न कि सोदाया विक्रय । तटस्थ व्यापारीगण तटस्थ क्षेत्र के भीतर शस्त्र तथा अन्य विनिपिद्धमाल युद्धस्थित शक्तियों के अभिकर्ताओं को बेचने के लिए स्वतन्त्र हैं । केवल उस दशा में जब वे ऐसी वस्तुएँ युद्धस्थितों में से किसी एक को निर्यात करते हैं उनके शत्रु को अभिग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होता है ।

द्वितीय यह कि युद्धस्थित लक्ष्यक्षेत्र आवश्यक है ।

तृतीय यह कि अपराध उसी क्षण पूर्ण हो जाता है जब कोई विनिपिद्ध वस्तुओं से लदा हुआ जहाज तटस्थ जलमार्ग को युद्धस्थित लक्ष्य क्षेत्र के लिए छोड़ता है । जैसा कि लार्ड स्ट्रावेन ने इमिना (Imina) वाले मामले में (C. Robinson, Admiralty Reports, Vol. III, p. 164) में कहा है “वस्तुओं को शत्रु व किसी बन्दरगाह की यात्रा वास्तविक रूप से कराये जाने में ही दोषी मान लेना चाहिये ।”

सन् १९०६ की सन्धन की घोषणा के अनुसार वस्तुएँ जो केवल प्रस्वस्थ तथा घायलों के उपयोग के लिए अथवा यात्रा के मध्य वहन करने वाले जहाज और उसके चालकगणों तथा यात्रियों के उपयोग के लिए हो, अभिग्रहण किए जाने से उन्मुक्त हैं चाहे उनका लक्ष्य क्षेत्र शत्रु का स्थान ही क्यों न हो क्योंकि ऐसी वस्तुएँ विनिपिद्ध नहीं मानी जाती ।

विनिषिद्ध का वहन करने के लिए दंड (Penalty for Carrying Contraband) :—सन्धन की घोपणा के अनुच्छेद ३६ तथा ४० में यह व्यवस्था की गई है कि केवल विनिषिद्ध वस्तुएँ ही नहीं वरन् वह जहाज भी जो उनको ले जा रहा हो, यदि विनिषिद्ध माल की गणना उसके मूल्य, भार, राशि अथवा भाड़े से किये जाने पर वह कुल लदे हुए माल के आधे से अधिक हो जस्त किया जा सकता है। उस दशा में जब माल अपराधी प्रमाणित किया जाय तथा जहाज छुड़ा लिया जाय तो उसे अभिग्रहण करने वाले को राष्ट्रीय नौजितमाल न्यायालय की कार्यवाहियों तथा उनके बीच जहाज तथा उस पर लदे हुए माल की अभिरक्षा के सम्बन्ध में लगे हुए कीमत तथा खर्च देने का उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इससे विनिषिद्ध माल का स्वामी अपने ऐसे निर्दोष माल की भी हानि उठाने का उत्तरदायी हो जाता है जो कि उसी जहाज पर लदा पाया जाय, किन्तु निर्दोष माल जो अन्य स्वामियों की सम्पत्ति है ऐसे दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है। यदि जहाज में लदे हुए माल में से आधे से कम विनिषिद्ध वस्तु हो तो वह अपराधी प्रमाणित नहीं किया जा सकता तथा उसका मालिक विनिषिद्ध वस्तु को उसे हस्तगत कर सकता है।

व्यावहारिक रूप में ब्रिटेन के तथा यूरोपीय महाद्वीप के देश अभिग्रहीत विनिषिद्ध माल अथवा उनको ले जाने वाले जहाज को युद्धस्थित राज्य द्वारा स्थापित नौजितमाल न्यायालय के पास निर्णय के लिये भेजते हैं। यदि नौजितमाल न्यायालय अभिग्रहण को पुष्ट कर देता है तो माल अथवा जहाज उपयुक्त नौजितमाल समझा जाता है तथा अभिग्रहण करने वाले राज्य द्वारा जप्त कर लिया जाता है।

सर विलियम स्कॉट द्वारा न्यूट्रैलिटी (The Neutralitet : 6 C. Rob. 30) में यह व्यक्त किया गया कि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि का नियम निश्चित रूप से यह है कि जहाज विनिषिद्ध माल ले जाने के लिये अपराधी प्रमाणित किये जाने के अधीन न होगा। किन्तु इस नियम के कुछ अपवाद हैं। जब जहाज माल के स्वामी की सम्पत्ति हो अथवा जब जहाज मिथ्या-क्षेत्र को लक्ष्य दिखा कर अपवाद मिथ्या कागज-पत्र लेकर जा रहा हो तो ये परिस्थितियाँ अपराध को बढ़ा देती हैं तथा ऐसे मामले आधुनिक नियम के अपवादस्वरूप हो जाते हैं।

वैध अभिग्रहण के लिये मुआवजा (Compensation for Lawful Seizure) :—तीन दशाओं में जब कि माल वैध रूप से अभिग्रहण किया जाय मुआवजा देना पड़ता है। वे निम्नलिखित हैं :—

१. जब जहाज से सशस्त्र में घुठने हो तथा उसका मालिक युद्ध छिड़ने अथवा वस्तुओं के विनिषिद्ध घोषित किये जान से अनभिज्ञ हो।

२. जब मालिक को यह ज्ञात हो जाय कि युद्ध छिड़ गया है किन्तु उसे विनिषिद्ध वस्तुओं को उतारने का अवसर न प्राप्त हुआ हो ।

३. जब अत्यन्त आवश्यकता के दबाव में चिकित्सा-सम्बन्धी सामग्री अभि-  
ग्रहीत कर ली जाय ।

लन्दन की घोषणा ( १९०६ ) सत्यापित न किये जाने के कारण प्रवृत्त न हो सकी । प्रथम विश्वयुद्ध के मध्य ग्रेट ब्रिटन ने असंख्य वस्तुओं को लन्दन की घोषणा की पूर्णतः विनिषिद्ध वस्तुओं की सूची में जोड़ दिया । द्वितीय विश्वयुद्ध के सघात ने विनिषिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में लन्दन की घोषणा को पूर्णतः हवा में उड़ा दिया । विनिषिद्ध सम्बन्धों पुराने नियमों की निर्भीकता से उपेक्षा की गई । सितम्बर सन् १९३९ में ग्रेट ब्रिटन द्वारा विनिषिद्ध पदार्थों की एक नयी सूची घोषित की गई जिसमें प्रत्येक वस्तु जो इस कोटि में आ सकती थी, समावेशित थी ।

अलवाकी ( The Alwaki ) के वाद में, अलवाकी और तीन अन्य डच पोत नार्वे पोत के साथ थे जो कि दक्षिणी अमेरिकी बन्दरगाहों की ओर शत्रुता प्रारम्भ होने के पूर्व ही चल पड़े थे, और उनमें ऐसी सामग्रियाँ थी जो कि कुछ तो आशिक रूप से निर्पक्ष विनिषिद्ध थी और कुछ अशत सन्नत पर विनिषिद्ध थी । युद्ध प्रारम्भ होने के बाद यह पोत पकड़ लिये गये । इस प्रसंग में न्यायालय का अभिमत था कि युद्ध के लाभ की सामग्रियों के सम्बन्ध में दावेदार के ऊपर भार है कि वह अपने दावे को सिद्ध कर सके और यह क्राउन का काम नहीं है कि वे एक अस्तिवाची वाद को विशिष्ट बनाने का तर्क उपस्थित करें । अतः यह बन्दीकरण उस समय तक समुचित प्रतीत होता है जब तक कि उसका कोई दावेदार सामने आकर अपने दावे को प्रस्थापित नहीं कर देता । न्यायालय ने पोतों में निहित माल को विनिषिद्ध करार दिया ।

विनिषिद्ध और नाकाबन्दी से सम्बन्ध ( Relationship between Contraband and Blockade )—विनिषिद्ध शब्द के अर्न्तगत दो मुख्य बातें आती हैं, पहली यह है कि माल किस प्रकार का है और दूसरी यह कि माल शत्रु के गन्तव्य तक जा रहा है । अतः केवल ऐसे ही माल को पकड़ा जा सकता है जो कि विनिषिद्ध सूची में है और जिसका कि निर्यात शत्रु के क्षेत्र तक होना है । नाकाबन्दी के अर्न्तगत शत्रु के सभी आवागमन को किनारे या बन्दरगाहों तक रोक देने की क्रिया आती है जिससे कि उसका समुद्र यातायात विभ्रूललित हो जाय । विनिषिद्ध और नाकाबन्दी में मुख्य अन्तर यह है कि विनिषिद्ध के अर्न्तगत जहाँ केवल निषेधित वस्तुओं के ले आने या ले जान पर रोक लगाई जाती है वहाँ नाकाबन्दी में शत्रु के सभी प्रकार के पोतों और मालों को रोक दिया जाता है ।

विनिषिद्ध का वहन करने के लिए दंड (Penalty for Carrying Contraband) :—लन्दन की घोषणा के अनुच्छेद ३६ तथा ४० में यह व्यवस्था की गई है कि केवल विनिषिद्ध वस्तुएँ ही नहीं बल्कि वह जहाज भी जो उनको ले जा रहा हो, यदि विनिषिद्ध माल को गणना उसके मूल्य, भार, राशि अथवा भाड़े से किये जाने पर वह कुल लदे हुए माल के आधे से अधिक हो जन्त किया जा सकता है। उस दशा में जब माल अपराधी प्रमाणित किया जाय तथा जहाज छुड़ा लिया जाय तो उसे अभिग्रहण करने वाले को राष्ट्रीय नौजितमाल न्यायालय की कार्यवाहियों तथा उनके बीच जहाज तथा उस पर लदे हुए माल की अभिरक्षा के सम्बन्ध में लगे हुए कोमत तथा व्यय देने का उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इससे विनिषिद्ध माल का स्वामी अपने ऐसे निर्दोष माल की भी हानि उठाने का उत्तरदायी हो जाता है जो कि उसी जहाज पर लदा पाया जाय, किन्तु निर्दोष माल जो अन्य स्वामियों की सम्पत्ति है ऐसे दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है। यदि जहाज में लदे हुए माल में से आधे से कम विनिषिद्ध वस्तु हो तो वह अपराधी प्रमाणित नहीं किया जा सकता तथा उसका मालिक विनिषिद्ध वस्तु को उसे हस्तगत कर सकता है।

व्यावहारिक रूप में ब्रिटेन के तथा यूरोपीय महाद्वीप के देश अभिग्रहीत विनिषिद्ध माल अथवा उनको ले जाने वाले जहाज को युद्धस्थित राज्य द्वारा स्थापित नौजितमाल न्यायालय के पास निर्णय के लिये भेजते हैं। यदि नौजितमाल न्यायालय अभिग्रहण को पुष्ट कर देता है तो माल अथवा जहाज उपर्युक्त नौजितमाल समझा जाता है तथा अभिग्रहण करने वाले राज्य द्वारा जन्त कर लिया जाता है।

सर विलियम स्वाँट द्वारा न्यूट्रैलिटी (The Neutralitet . 6 C. Rob. 30) में यह व्यक्त किया गया कि आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि का नियम निश्चित रूप से यह है कि जहाज विनिषिद्ध माल ले जाने के लिये अपराधी प्रमाणित किये जाने के अधीन न होगा। किन्तु इस नियम के कुछ अपवाद हैं। जब जहाज माल के स्वामी की सम्पत्ति हो अथवा जब जहाज मिथ्या-क्षेत्र को सक्षय दिखा कर अथवा मिथ्या कागज-पत्र लेकर जा रहा हो तो ये परिस्थितियाँ अपराध को बढ़ा देती हैं तथा ऐसे मामले आधुनिक नियम के अपवादस्वरूप हो जाते हैं।

वैध अभिग्रहण के लिये मुआवजा (Compensation for Lawful Seizure) :—तीन दशकों में जब कि माल वैध रूप से अभिग्रहण किया जाय मुआवजा देना पड़ता है। वे निम्नलिखित हैं :—

१. जब जहाज से समुद्र में छुठने हो तथा उसका मालिक युद्ध दिखने अथवा वस्तुओं के विनिषिद्ध घोषित किये जाने से अनभिज्ञ हो।

२. जब मालिक को यह ज्ञान हो जाय कि युद्ध छिड़ गया है किन्तु उसे विनिपिद्ध वस्तुओं को उतारने का अवसर न प्राप्त हुआ हो ।

३. जब अत्यन्त आवश्यकता के दबाव में विकिरसा-सम्बन्धी सामग्री अभि-  
ग्रहीत कर ली जाय ।

सन्दन की घोषणा ( १९०६ ) सत्यापित न किये जाने के कारण प्रवृत्त न  
हो सकी । प्रथम विश्वयुद्ध के मध्य ग्रेट ब्रिटेन ने असह्य वस्तुओं को लन्दन की  
घोषणा की पूर्णतः विनिपिद्ध वस्तुओं की सूची में जोड़ दिया । द्वितीय विश्वयुद्ध के  
समय ने विनिपिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में सन्दन की घोषणा को पूर्णतः हवा में उड़ा  
दिया । विनिपिद्ध सम्बन्धी पुराने नियमों की निर्भीकता से उपेक्षा की गई । सितम्बर  
सन् १९३६ में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा विनिपिद्ध पदार्थों की एक नयी सूची घोषित की गई  
जिसमें प्रत्येक वस्तु जो इन कोटि में आ सकती थी, समावेशित थी ।

अलवाकी ( The Alwaki ) के बाद में, अलवाकी और तीन अन्य  
इव पोत नावें पोत के साथ थे जो कि दक्षिणी अमेरिकी बन्दरगाहों की ओर  
शत्रुता प्रारम्भ होने के पूर्व ही चल पड़े थे, और उनमें ऐसी सामग्रियाँ थी जो कि  
कुछ तो आंशिक रूप से निषेधित थी और कुछ अशत संशय पर विनिपिद्ध  
थीं । युद्ध प्रारम्भ होने के बाद यह पोत पकड़ लिये गये । इस प्रसंग में न्यायालय  
का भूमिका था कि युद्ध के लाभ की सामग्रियाँ के सम्बन्ध में दावेदार के ऊपर  
प्रामाण्य है कि वह अपने दावे को सिद्ध कर सके और यह क्राउन का काम नहीं है  
कि वे एक अस्तिवाची वाद को विशिष्ट बनाने का तर्क उपस्थित करें । अतः यह  
बन्दीकरण उस समय तक समुचित प्रतीत होता है जब तक कि उसका कोई दावेदार  
सामने आकर अपने दावे को प्रस्थापित नहीं कर देता । न्यायालय ने पोतों में निहित  
माल को विनिपिद्ध करार दिया ।

विनिपिद्ध और नाकाबन्दी से सम्बन्ध ( Relationship between  
Contraband and Blockade )—विनिपिद्ध शब्द के अन्तर्गत दो मुख्य बातें  
आती हैं, पहली यह है कि माल किस प्रकार का है और दूसरी यह कि माल शत्रु  
के गन्तव्य तक जा रहा है । अतः केवल ऐसे ही माल को पकड़ा जा सकता है जो  
कि विनिपिद्ध सूची में है और जिसका कि निर्यात शत्रु के क्षेत्र तक होना है ।  
नाकाबन्दी के अन्तर्गत शत्रु के सभी आवागमन को किनारे या बन्दरगाहों तक रोक  
देने की क्रिया आती है जिससे कि उसका समुद्री यातायात विभ्रूललित हो जाय ।  
विनिपिद्ध और नाकाबन्दी में मुख्य अन्तर यह है कि विनिपिद्ध के अन्तर्गत जहाँ  
केवल निषेधित वस्तुओं के ले आने या ले जाने पर रोक लगाई जाती है वहाँ  
नाकाबन्दी में शत्रु के सभी प्रकार के पोतों और भागों को रोक दिया जाता है ।



नाकाबन्दी के अन्तर्गत किसी पोत की मर्त्सना करने के लिये इतना ही पर्याप्त है कि वह सैरोपित क्षेत्र में धुम रहा था, या घुसने का प्रयत्न कर रहा था ।

पिछले दो विश्व युद्धों ने नाकाबन्दी और विनिपिद्ध के अन्तर को बहुत कुछ मिटा दिया है और आज की समुद्री युद्ध विधि में विनिपिद्ध और नाकाबन्दी दोनों का प्रयोग एक ही अर्थों में किया जाने लगा है ।

**निरन्तर यात्रा का सिद्धान्त (Doctrine of Continuous Voyage):—**

“निरन्तर यात्रा के सिद्धान्त में वह साहसिक कार्य निहित है जिसमें माल प्रथम तो किसी तटस्थ बन्दरगाह को और वहाँ से आगे किसी शत्रु के प्रदेश को ले जाया जाय, जो कुछ प्रयोजनों के लिये केवल एक ही परिवहन हो तथा जिसमें वे सब परिणाम होते यदि तटस्थ बन्दरगाह बीच में न पड़ता ।” ( पिट कोर्ट ) ।

तटस्थ जहाज अपनी यात्रा दो भागों में विभक्त करके विनिपिद्ध वस्तुओं का अभिग्रहण बचाने का प्रयत्न करते थे । जब वे युद्ध में विनिपिद्ध पदार्थों को शत्रु के देश में ले जाते तो वे प्रकट रूप में अपने कागज पत्रों के अनुसार किसी तटस्थ प्रदेश को रवाना होते, उस प्रकट रूप से लक्ष्य प्रदेश में अर्थात् तटस्थ बन्दरगाह में अपना माल उतारते, यदि आवश्यकता हुई तो कर देते और तब अपने वास्तविक लक्ष्य प्रदेश अर्थात् युद्धस्थित बन्दरगाह में पहुँचने का प्रयास करते । इसी प्रकार नाकाबन्दी तोड़ने के लिये वे किसी तटस्थ बन्दरगाह को जो नाकाबन्दी किये गये समुद्र तट के समीप में स्थित हो अपना प्रकट लक्ष्य प्रदेश मानेंगे तथा तटस्थ बन्दरगाह से माल को नाकाबन्दी किये गये बन्दरगाह में पुनः जहाज से ले जायेंगे । लेकिन निरन्तर यात्रा अथवा निरन्तर परिवहन का सिद्धान्त लागू किये जाने से तटस्थों का युद्ध में विनिपिद्ध अथवा नाकाबन्दी सम्बन्धी नियम को बचाने का प्रयत्न विफल हो गया । सिद्धान्त में यह निर्धारित किया गया कि उस माल को जो यदि शत्रु के बन्दरगाह को ले जाया जाता तो विनिपिद्ध होता बीच में ही विनिपिद्ध के रूप में रोका जा सकता है, चाहे वह प्रकट रूप में किसी तटस्थ बन्दरगाह को ही क्यों न ले जाया जा रहा हो यदि वास्तव में अभिप्राय यह ही कि वह उस तटस्थ बन्दरगाह से भूमि अथवा समुद्र द्वारा किसी शत्रु क्षेत्र को ले जाया जाय ।

**निरन्तर यात्रा के सिद्धान्त की नाकाबन्दी, विनिपेध तथा अतटस्थ सेवा में उपयोगिता:—**हाइड का कथन है कि “निरन्तर यात्रा का सिद्धान्त नीजितमाल व्यापारियों के हाथों में तटस्थ व्यापारियों द्वारा युद्ध-स्थित के निपेधों को बचाने के प्रयत्नों के विफल करने के उपयोग में लाये जाने का एक साधन प्रदान करता है । वे निपेध इस प्रकार के होते हैं जैसे शत्रु के उपनिवेशों से व्यापार अथवा विनिपिद्ध पदार्थों को उसके क्षेत्र में ले जाना अथवा उसके तटों की नाकाबन्दी तोड़ने का प्रयत्न करना ।”

“यात्राओं के निरन्तर बनी रहने का परीक्षण नाकाबन्दी, शत्रुओं से व्यापार, घटस्थ सेवा, विनिपिद्ध पदार्थों का ले जाना तथा वास्तव में उन सब मामलों में आवश्यक है अथवा हो सकता है जिसमें जहाज का लक्ष्य क्षेत्र अथवा माल महत्व रखता हो । घट्ट यात्रा का परीक्षण मुख्यतः तब होता है जब यह समझा जाय कि अभिग्रहण करने वाली शक्ति का कोई प्रजाजन शत्रु से व्यापार कर रहा है अथवा कोई तटस्थ विनिपिद्ध वस्तुओं को शत्रु के पास अथवा उस नियम के अधीन जिसे “सन् १७५६ का नियम” कहते भेज रहा हैं । यह उस मामले में भी महत्वग्रहण कर लेता है जब कि नाकाबन्दी तोड़ने के आशय का सदेह हो । यदि कोई माल नाकाबन्दी के भीतर से ले जाये जान क लिए निर्देशित हो तो वह यात्रा के किसी भी स्थिति में पकड़ा जा सकता है । ऐसी दशा में कोई तटस्थ क्षेत्र बीच में डाल दिया जायगा और उतारने, दूसरे जहाज में लादने तथा बिक्री इत्यादि की सब रीतियाँ वैसी ही व्यवहार की जायेंगी जैसी विनिपिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में, और दोनों के विषय में वही जांच तथा तर्क क सिद्धान्त उपयोगी हैं ।” (Cf. Wheaton . Elements of International Law, 1936 pp 558-560)

अतः इस सिद्धान्त का उपयोग निपिद्ध व्यापार, नाकाबन्दी तथा विनिपिद्ध वस्तुओं के मामलों में किया गया है । सन् १७५६ के युद्ध के नियम ने जिसकी विवेचना थोड़े ही भागों की गई है युध्यमानों को इस योग्य बनाया कि वे तटस्थों को ऐसा व्यापार करने से वञ्चित करें जो उनके लिये सान्तिकाल में बन्द रहा हो । सिद्धान्त के नाकाबन्दी के विषय में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में इसने यह अनुमति दी कि माल यात्रा के किसी भी स्थिति में पकड़ा जा सकता है यदि उसका उद्देश्य नाकाबन्दी के भीतर से ले जाए जाने का हो ।

विनिपिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में सन् १९०७ की घोषणा के अनुच्छेद ३६ में यह व्यवस्था की गई है कि पूर्णतः विनिपिद्ध माल यदि वह शत्रु के अधिकार वाले अथवा उसके द्वारा अधिकृत क्षेत्र को अथवा उसके सशस्त्र दलों को जा रहा हो तो वह अभिग्रहीत किया जा सकता है । इसने लिये इस बात का विचार आवश्यक है कि माल सीधा जा रहा था अथवा उसे दूसरे जहाज में लादना पड़ता था या कि उसे भन्तर पुनः स्थल से परिवहन करना पड़ता था ।

निरन्तर की समुद्री यात्रा के महत्वपूर्ण वाद ( Leading Cases on Continuous Voyage )—‘लॉर्ड स्टोवेल’ ने निरन्तर समुद्री यात्रा के सिद्धान्त का तात्पर्य मैरिया (Maria)<sup>१</sup> के वाद में निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट किया है—

१ . (१७६६) ५ सी० रॉब० ३६८ ।

“यह एक अन्तर्निहित सुनिश्चित सिद्धान्त है कि केवल किसी बन्दरगाह को स्पर्श कर देना ही समुद्री यात्रा की प्रकृति को बदल देने के लिए पर्याप्त नहीं है, निरन्तर समुद्री यात्रा प्रत्येक रूप में वहाँ तक तथैव मानी जायेगी जिस देश के लिए बेड़ा लक्ष्य मानकर अन्तिम बन्दरगाह तक पहुँचने के लिये चला है।”

पॉली (Polly)<sup>१</sup> के बाद में सर विलियम स्कॉट (Sir William Scott) का अवलोकन था कि “यदि कोई अमेरिकी व्यक्ति (प्रसंग के अन्तर्गत तटस्थ) इस व्यापार संचार के लिए सीधे ढंग से (directly) अनुमति नहीं प्राप्त कर पाता है, तो उसे चक्करदार (circuitous) ढंग से भी नहीं प्राप्त कर सकता।”

‘बरमूडा’ (Bermuda)<sup>२</sup> के प्रसंग में, जो कि इङ्ग्लैण्ड से नसाऊ तक की समुद्री यात्रा के बीच बन्दी किया गया था, न्यायालय का निष्कर्ष था कि “इससे कोई अन्तर नहीं उत्पन्न होता है कि बिद्रोही पोत का गन्तव्य गूढ (ulterior) था, या सीधा (direct)। न तो गन्तव्य का प्रश्न पोत के परिवर्तन से ही प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यदि जहाज का आदान-प्रदान ही आशयित है, तो वह कार्गो के यातायात की निरन्तरता को नहीं भंग कर देता। किसी तटस्थ बन्दरगाह से चलकर किसी युद्ध सलग्न गन्तव्य तक पहुँचने में किसी तटस्थ बन्दरगाह का अन्तरास्थापन (interposition) सदैव से ही विनिषिद्ध और सरोध-गमन के लिए कारण रहा है। एक परिवहन जो कि एक स्थान से आरम्भ होकर कि दूसरे स्थान तक के लिए आशयित है, उस समय तक निरन्तर माना जायेगा, जब तक कि वह आशय ही परिवर्तित नहीं हो जाता। बीच में रुकने के कितने स्थान आये, या पोत में परिवर्तन किया गया, इस बात का उस यात्रा की निरन्तरता में बाधक नहीं है।

‘स्प्रिंगबॉक’ (Springbok)<sup>३</sup> के बाद में समुक्त राज्य अमेरिका के ‘सुप्रीम कोर्ट’ ने एक ब्रिटिश पोत की प्रतारणा की थी, जो कि नसाऊ नामक बन्दरगाह तक पहुँचने के मार्ग में था। कारण यह था कि बेड़े की प्रकृति को देखते हुये इस बात में संदेह नहीं रह गया था कि उसका वास्तविक गन्तव्य एक सरोधित बन्दरगाह तक पहुँचने का था।

‘पीटर हॉफ’ (Peter Hoff)<sup>४</sup> के बाद में इस सिद्धान्त को अत्यधिक विस्तार दिया गया, जब कि विनिषिद्ध कार्गो का अन्तिम उद्देश्य भूमि परिवहन पर भी संचारित किया गया।

१. (१८००) २ सी० आर० ३६२।

२. ३ विलेस ५५१।

३. (१८५६) ५ विलेस, १।

४. (१८६६) ५ विलेस, ५६।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने निरन्तर समुद्री यात्रा के सिद्धान्त का प्रयोग, यहाँ तक कि एक ऐसे सरोधित बन्दरगाह तक के लिये किया है, जहाँ कि एक आशय यह था कि कार्गो तटस्थ बन्दरगाह पर विराम करने के बाद आगे सरोधित बन्दरगाह तक भेजा जाये ।

यद्यपि निरन्तर की यात्रा के सिद्धान्त मुख्यतः राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत कर लिए गये किन्तु उन प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में मतभेद रहा जिनके अधीन विनिषिद्ध वस्तुयें अभिग्रहीत की जा सकती थी । संयुक्त राज्य अमेरिका में तटस्थ बन्दरगाह में उतारे गए विनिषिद्ध पदार्थ यदि युद्धस्थिति के उपयोग के लिये शत्रु के बन्दरगाह में भेजे जान को हो तो वे बिना किसी प्रतिबन्ध के उसी प्रकार से अभिग्रहीत किये जा सकते थे जैसे मानो वे एक भट्ट यात्रा द्वारा सीधे शत्रु के बन्दरगाह को जा रहे हो । यह सिद्धान्त फ्रांस के नौजितमाल न्यायालयों द्वारा क्रीमिया के युद्ध के मध्य, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमेरिका के गृहयुद्ध के मध्य तथा ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के युद्ध के मध्य स्वीकृत किया गया । यूरोपीय महाद्वीप ने फिर भी इस सिद्धान्त को नहीं माना तथा इस बात पर हठ किया कि केवल पूर्णतः तथा सप्रतिबन्ध विनिषिद्ध पदार्थों की सूची ही स्वीकृत की जाय । इसके अनुसार सन् १९०६ की लन्दन की असत्यापित घोषणा ने एक समझौता निकाला जिसके अनुसार निरन्तर यात्रा का सिद्धान्त पूर्णतः विनिषिद्ध पदार्थों के सम्बन्ध में यथापूर्व बना रहने दिया गया तथा यह घोषित किया गया कि इस बात का विचार अनावश्यक है कि क्या माल का वहन सीधा है अथवा उसे दूसरे जहाज में लादना पड़ता है या अनन्तर पुनः स्थल से वहन करना पड़ता है, लेकिन इसका उपयोग सप्रतिबन्ध विनिषिद्ध पदार्थों के सम्बन्ध में नहीं किया जाता था नवल उन विरल दशाओं को छोड़ कर जब अन्तिम लक्ष्य प्रदेश ऐसा युष्ममान देश हो जिसमें कोई समुद्र-तट या तट न हो । सन् १९०६ की लन्दन की घोषणा में यह निर्धारित किया गया कि किसी जहाज अथवा उसके माल का आगे का लक्ष्य-प्रदेश चाहे कुछ भी क्यों न हो यदि वह उस समय ऐसे बन्दरगाह का जा रहा हो जिसमें नाकाबन्दी न हो तो उसे नाकाबन्दी भग करने के निमित्त पकड़ा नहीं जा सकता । लेकिन यह घोषणा असत्यापित रही तथा दो विश्वयुद्धों के मध्य उपर्युक्त नियम का प्रज्ज्वलत रूप से उल्लंघन किया गया क्योंकि भट्ट यात्रा का सिद्धान्त सप्रतिबन्ध तथा पूर्णतः विनिषिद्ध दोनों पदार्थों के सम्बन्ध में लगाया गया ।

प्रथम विश्वयुद्ध में ब्रिटिश न्यायालयों ने निरन्तर समुद्री यात्रा के सिद्धान्त को लन्दन डिवेलियेशन में प्रस्थापित नियमों से बाहर तक विस्तार दिया । किम् (Kim)<sup>१</sup> के वाद में प्रसंग यह था कि किम् नामक पोत नार्वे के अन्य तीन पोतों

१. (१९१५) प्रोवेट डिबीजन, पृ० २१५ ।

और स्वीडेन के एक पोत सहित न्यूयार्क से कोपेनहेगेन के लिए अधिक मात्रा में खाद्य-सामग्रियाँ लादकर आगे को बढ़ रहा था । किम् मे कुछ अन्य साधारण सामग्रियाँ और कुछ रबर लदा था । ये सभी पोत नवम्बर १९१४ में बन्दी बना लिये गए और कार्गो को शतयुक्त विनिषिद्ध रूप में जप्त कर लिया गया । किम् में भरे हुये रबर को निरपेक्षतः विनिषिद्ध के रूप में माना गया । सर सैमुअल इवान्स (Sir Samuel Evans) ने निर्णय देते हुये कहा था कि "निरन्तर समुद्री यात्रा, या आयात, दोनों के सिद्धान्त का जहाँ तक समुद्रो और स्थलीय परिवहन से सम्बन्ध है, वर्तमान युद्ध व आरम्भ होने के समय यह राष्ट्रों की विधि का एक अंश बन चुका है, और मान्य वैध निर्णयों के सिद्धान्त के अनुरूप है, और आधुनिक विधिशास्त्रियों की अत्यधिक बड़ी सख्या द्वारा और वर्तमान मैरीटाइम युद्ध कौशल के व्यवहारों के रूप में राष्ट्रों द्वारा मान्य है ।" जहाँ तक कि शतयुक्त विनिषिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में 'सन्दन डिब्लेयरेशन' के अनुसार आशिक छूट स्वीकृत करने का प्रश्न था, विद्वान् न्यायाधीश ने अवलोकन किया था कि "जहाँ तक समझौते का सम्बन्ध है, यहाँ अपवाद स्थिर करने के लिये सर्कसंगत कारणों का अभाव प्रतीत होता है यदि यह उचित है कि एक युद्ध सलग्न शक्ति को अनुमति दी जानी चाहिए कि वह विभिन्न समुद्री यात्राओं द्वारा ले जाए जाने वाले निरपेक्षतः विनिषिद्ध वस्तुओं को पकड़ ले, या ऐसे यातायात को रोक दे जिसका कि अन्तिम गन्तव्य शत्रु के क्षेत्र तक पहुँचना है, तो उसे भी क्यों न अनुमति दी जानी चाहिये कि वह साधारण सभी माल को पकड़ ले, मले ही वह माल निरपेक्षतः विनिषिद्ध हो, क्योंकि वह सभी माल शत्रु की सरकार या उसकी सशस्त्र सेनाओं तक पहुँचकर विनिषिद्धता का रूपा ले लेगा । यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि आज के सहज सुलभ यातायात के युग में यदि निरन्तर समुद्री यात्रा के सिद्धान्त, या निरन्तर परिवहन के सिद्धान्त का प्रवर्तन किया जाना है, तो इसके अन्तर्गत समुद्र के एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक की यात्रा ही नहीं, अपितु स्थलीय परिवहन का भी उसमें समावेशन किया जाना चाहिये, जब तक कि माल पहुँचने का गन्तव्य स्थान न मिल जाय ।

विद्वान् न्यायाधीश ने निष्कर्ष दिया था कि कार्गो का अन्तिम लक्ष्य डेनमार्क में उपभोग करने का अथवा वहाँ के स्टॉक में माल बढ़ाने का न था और कोपेनहेगेन रेलिवरी का अन्तिम स्थान भी न था, वह तो जर्मन क्षेत्र को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहा था । यह भी अवलोकन किया गया कि पोत में किसी विशिष्ट माल के होन की जानकारी का होना जप्त किए जाने या अपराध से छूट के लिए पर्याप्त आधार नहीं है ।

सन् १७५६ का युद्धका नियमः—निरन्तर यात्रा का सिद्धान्त "सन् १७५६ के युद्ध के नियम" से सम्बन्धित माना जाता है जिसके अनुसार युद्ध में सगे हुए राज्य

तटस्थों को ऐसा व्यापार करने से निषिद्ध कर सकने थे जो उनके लिए शान्ति के समय बन्द रहा हो । इङ्ग्लैण्ड के साथ सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस ने यह ज्ञात करके कि इङ्ग्लैण्ड की घड़ी नीसेना के कारण वह अपना औपनिवेशिक व्यापार नहीं कर सकता, नीदरलैण्ड को जो तटस्थ था, यह अनुमति दी कि आजापत्र द्वारा व्यापार करे । ब्रिटिश सरकार ने डेनमार्क के जहाजों को उनमें लदे हुए माल सहित अभिग्रहण किए जाने की आज्ञा इस आधार पर दी कि उन्होंने अपने को शत्रु के व्यापारिक जहाजों से समुक्त कर लिया है तथा ऐसी स्थिति में वे अभिग्रहण किये जा सकते हैं । संक्षेप में सन् १७५६ का नियम उस रीति को प्रकट करता था, जो वास्तव में सन् १७५६ से भी अधिक पुरानी थी, कि युद्धस्थित के एक बन्दरगाह तथा अन्य बन्दरगाह के बीच की मातृभूमि और उसके उपनिवेश के बीच का व्यापार, जो सामान्यतः शान्ति के समय बन्द रहा हो, अन्य मुख्यकारी द्वारा तटस्थ जहाजों के माध्यम से नहीं करने दिया जाता था । लार्ड स्टार्वेल ने इमैनुअल (Immanuel) वाले मामले [(1799) 2 C Rob. 186] में कहा कि जहाँ तटीय तथा औपनिवेशिक व्यापार तटस्थों के लिए शान्ति के समय बन्द रहा हो और युद्ध के बीच खोल दिया जाय तो तटस्थ जो ऐसे व्यापार में लगते हैं अपने को शत्रु के व्यापारिक जहाजों से समुक्त कर लेते हैं तथा शत्रुओं में से प्रत्येक के लिए उत्तरदायी होते हैं । सन् १७५६ का नियम बाद में अमेरिका तथा जापान द्वारा अंगीकृत किया गया । लन्दन की प्रस्थापित घोषणा में सन् १७५६ के नियम पर कोई मन नहीं प्रकट किया गया और इसे अनिवार्य ही छोड़ दिया गया (अनुच्छेद ५७) ।

## अध्याय ५०

### अतटस्थ सेवा

#### (Unneutral Service)

इसका अर्थ—“अतटस्थ सेवा” से “उन कार्यों का चोतन होता है जो कभी तटस्थों द्वारा किए जाय जिसमें कुछ समय के लिए युद्धस्थिति की सेवा में प्रवेश तथा उसके लिए ऐसे कार्य करना भी सम्मिलित है जो युद्ध में उसके लिए प्रत्यक्षरूप से लाभदायक हो” (लीरेंस) । ऐसी अतटस्थ सेवा तटस्थ जहाजों द्वारा युद्धस्थित को वास्तविक सहायता देकर की जाती है । अन्य युद्धस्थित राज्य को यह अधिकार है कि वह उनको अतटस्थ कार्य की गम्भीरता के अनुरूप कम व अधिक दण्ड दे । उदा-

हरण के लिये यदि किसी तटस्थ राज्य का कोई व्यक्तिगत जहाज किसी युद्धस्थित के सैनिक दलों को ले जावे अथवा रेडियो द्वारा सैनिक समाचार उसके उपयोग के लिए भेजे तो यह अतटस्थ सेवा कर रहा है तथा दृष्टिपात होते ही विनष्ट किए जाने योग्य है। इसी प्रकार यदि कोई तटस्थ जहाज सुरण बिछाये अथवा किसी युद्धस्थित के हित में व्यापारिक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाय तो वह प्रथम दशा में दृष्टिपात होते ही डुबाये जाने की अथवा दूसरी दशा में नौजितमाल के रूप में अभिग्रहीत तथा अपराधी प्रमाणित किये जाने का दायित्व रखता है।

लंदन की घोषणा (Declaration of London) — लंदन की घोषणा (१९०६) में जो सत्यापन के अभाव में प्रवृत्त नहीं हो सकी अतटस्थ सेवा पर एक सम्बद्ध विधि को सर्वप्रथम घोषित किया गया। अनुच्छेद ४५ में यह व्यवस्था की गई कि यदि कोई तटस्थ जहाज ऐसी यात्रा कर रहा हो जो विशिष्ट रूप से या तो (प्र) व्यक्तिगत यात्रियों के वहन करने की दृष्टि से जो शत्रु के सैनिक दलों में समावेशित हो या (प्रा) शत्रु के हित में समाचार भेजने की दृष्टि से की जा रही हो तो जहाज दण्डित किया जा सकता है यदि सेवा जान-बूझ कर की गई हो, यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि यह सेवा अवश्यमेव अनन्य (केवल उसी प्रयोजन के लिये) रही हो। जहाज तथा उस पर लदा हुआ माल जो एक ही स्वामी की सम्पत्ति हो दण्डित किये जा सकते हैं यदि स्वामी, चार्टर देने वाले अथवा मालिक के ज्ञान में जहाज शत्रु की सेना के किसी अंश को अथवा एक या अधिक व्यक्तियों को वहन कर रहा हो जो याना के बीच शत्रु की क्रियाशीलता को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देते हो। लेकिन यदि युद्ध छिड़ने की अनभिज्ञता में अथवा ज्ञान होने के उपरान्त यात्रियों को उतारने का अवसर न मिलने पर जहाज दण्डित किया जा सकता है। अनु ४७ में यह व्यवस्था की गई कि युद्धस्थित का गस्ती जहाज यदि शत्रु के सैन्यदल में समावेशित किसी व्यक्ति को तटस्थ व्यापारिक जहाज में प्राप्त हो तो वह उसके प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है, चाहे जहाज को पकड़ने के लिए कोई आधार न हो, तथा जहाज को अपने मार्ग पर जाने दिया जा सकता है। अनुच्छेद ४६ में यह व्यवस्था की गई कि अधिक गम्भीर तथा भयकर प्रकार की अतटस्थ सेवाओं के कारण जहाज तथा उसके स्वामी का उस पर लदा हुआ माल उसे शत्रु के अभिग्रहीत व्यापारिक जहाज की स्थिति में रख कर जप्त किये जा सकते हैं। ऐसे मामले उम समय उत्पन्न होते हैं जब कोई जहाज शत्रुता के कार्यों में प्रत्यक्ष भाग लेता हो अथवा शत्रु की सरकार द्वारा जहाज पर रक्षे हुये किसी अभिवर्त्ता के आदेशों अथवा नियन्त्रण के अधीन हो अथवा जब तटस्थ जहाज शत्रु का सरकार के अनन्य कार्य में सहा हो अथवा जब जहाज अनन्य रूप से शत्रु के हित में सैनिक दलों को परिवहन करने में अथवा सूचना देने में सहा हो।

सन्धन की असत्यापित घोषणा के अनुच्छेद ४७ में यह व्यवस्था की गई है कि तटस्थ जहाज से केवल वे ही व्यक्ति हटाये जायें जो शत्रु के सैन्य दलों में समावेशित हो अर्थात् जहाज पर के सिपाही अथवा नाविकगण, किन्तु यह नियम प्रथम तथा द्वितीय दोनों विश्वयुद्धों में नहीं स्वीकार किया गया। नवम्बर सन् १९१४ में ब्रिटिश सरकार ने प्रतिकार के उपाय के रूप में यह आदेश किया कि तटस्थ जहाजों पर के शत्रु के प्रारक्षितक (reservists) युद्धबन्दी बना लिए जायें जिसका प्रभाव शत्रु के सेना में भर्तों होने योग्य अवस्था प्राप्त सब प्रजाजनों पर पड़ा। पुनः जनवरी सन् १९४० में ब्रिटेन के एक गश्ती जहाज ने सेना के लिये वयस्क जर्मन नागरिकों को जापानी जहाज 'मासमा मारु' से उतार लिया।

**अटस्थ सेवा तथा विनिषेध .—**अतटस्थ सेवा वास्तव में विनिषेध से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। प्रथम तो जैसा लोरेस ने व्यक्त किया है "कार्यों के लक्षणों में ही स्वयं विभेद है। जो कुछ विनिषेध के मामलों में होता है वह केवल व्यापारिक विषय के रूप में ही किया जाता है। इसके विषय पदार्थ हैं तथा इसका उद्देश्य लाभ है। अतटस्थ सेवा में कार्य साधारण व्यापार के कार्य नहीं होते। उनकी विशिष्ट उदाधियाँ युद्धसदृश हैं न कि व्यापारिक, अर्थात् असैनिक व्यक्तियों को शत्रु की सेवा में ले जाना, राजनैतिक सन्देशों को भेजना, इत्यादि। अन्य शब्दों में विनिषेध में केवल कुछ माल रहता है किन्तु अतटस्थ सेवा में व्यक्तियों को ले जाना तथा शत्रु के लिए सन्देश भेजना भी सम्मिलित है। दूसरे यह कि विनिषिद्ध व्यापारिक माल को वैधरूप से जब्त करने के लिये शत्रु लक्ष्य क्षेत्र आवश्यक है, किन्तु अतटस्थ सेवा में लक्ष्य क्षेत्र अनावश्यक है। अतटस्थ सेवा में नियोग (mission) का स्वरूप महत्व रखता है। हाइड का भी कथन है कि शत्रु लक्ष्य की विद्यमानता जिसका प्रमाणित होना विनिषेध के सम्बन्ध में विचार करने में इतना महत्व रखती है शत्रु के सैनिक जनों को ले जाने का औचित्य दर्शाने के लिए सर्वदा ही आवश्यक नहीं है क्योंकि उनको बीच में ही रोकने का अधिकार उस विशेष दशा में उनके नियोग के स्वरूप पर अथवा ले जाये जाने के मध्य में उनके वास्तविक आचरण पर आश्रित रह सकता है। तीसरे यह कि दण्ड में भी भेद है। विनिषेध के असदृश अतटस्थ सेवा की दशा में लदा हुआ माल केवल बिरले ही मामलों में जब्त किया जाता है। विनिषेध की दशा में अहितकारी माल आरम्भ में ही राज्य-सात् कर लिया जाता है तथा भागे बड़े हुए मामलों में जहाज भी दंडित कर दिया जाता है। अतटस्थ सेवा की दशा में जहाज को उन अवैध वस्तुओं सहित जो वह ले जा रहा हो आरम्भ में ही जब्त कर लिया जाता है किन्तु सामान्यतः माल को गम्भीर मामलों को छोड़कर और किसी अन्य दशाओं में जब्त नहीं किया जाता।



भ्रत मे भ्रोपेनहेम भेद वो इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि विनिषिद्ध वस्तुभो का पार-  
वहन भ्रवश्य तथा बहुत सी दशाभो मे व्यवहार मे भी शत्रु की प्रत्यक्ष सेवा मे नही  
होता किन्तु भ्रतटस्थ सेवा मे शत्रु के लिये व्यक्तियो वा परिवहन तथा सन्देशो का ले  
जाना सामान्यतः शत्रु की प्रत्यक्ष सेवा मे होता है । भ्रतः यह विनिषिद्ध वस्तुभो को  
वहन करने से कही अधिक सहायता का द्योतक है ।

भ्रतटस्थ सेवा तथा शत्रुतापूर्ण सेवा :—भ्रतटस्थ सेवा को शत्रुतापूर्ण  
सेवा से भी पृथक् किया जा सकता है । जिस दशा मे सेवा केवल प्राशिक हो वह  
भ्रतटस्थ सेवा होगी, उदाहरणार्थ यदि कोई जहाज प्राशिक रूप से निर्दोष सेवा में  
लगे रहने के साथ ही साथ सैनिक व्यक्तियो भ्रयवा सन्देशो को ले जाने मे लगा हो ।  
लन्दन की भ्रतस्थापित घोषणा (१९०६) के अनुच्छेद ४६ में शत्रुतापूर्ण सेवा क  
चार उदाहरण परिगणित किये गए हैं जिनमे तटस्थ जहाज शत्रु के लक्षण प्राप्त कर  
लेता है तथा उससे वैसा ही व्यवहार किया जा सकता है । वे हैं (१) जब कोई  
तटस्थ जहाज लडाई में प्रत्यक्ष भाग ले, (२) जब वह शत्रु की सरकार द्वारा  
जहाज पर रक्खे गए किसी अभिकर्ता के आदेशो भ्रयवा नियन्त्रण के भ्रतगंत हो,  
(३) जब वह भ्रनन्य रूप से शत्रु के सरकार के अधीन कार्य कर रहा हो तथा (४)  
जब वह शत्रु के सैन्यदलो को परिवहन करने में भ्रयवा उसके हित मे सन्देश भेजने में  
लगा हो । प्रत्येक दशा मे भार भ्रनन्य रूप से लगने मे है । ऐसी भ्रतटस्थ सेवाये  
अधिक गम्भीर तथा भ्रयंकर प्रकार की हैं तथा जहाज और उस पर लदे हुये उसके  
स्वामी के माल को ज्वन किए जाने योग्य बना देती हैं और उसको शत्रु के पकडे  
गए व्यापारिक जहाज की स्थिति मे रख देती हैं ।

'भ्रतलाएटा' (Atlanta) का बाद एक दृढगन्त सामने प्रस्तुत करता है  
कि पासूचना (intelligence) को शत्रुपक्ष की ओर दे दिया जाय । यह (ब्रेमन का  
पोत) एक तटस्थ पोत था । आइल-डी-फ्रान्स (Isle de France) की सरकार से  
गुप्त रखकर इस पोत की सैनिक सामग्रियां वेरिस स्थित सपुद्री-मन्त्री के पास जा  
रही थी । तटस्थ पोत के कप्तान को इस तथ्य की जानकारी थी । पोत ब्रिटिश-  
सरकार द्वारा बन्दी कर लिया गया । ब्रिटिश 'प्राइज-न्यायालय' द्वारा पोत और  
कार्गो दोनों को मर्त्सना की गई । यह कहा गया कि पोत द्वारा सैनिक महत्व के  
सामानो को इस प्रकार ले जाना भ्रत्यधिक शत्रुतापूर्ण काम था भ्रत । वह यान,  
जिसमे कि सामान ले जाया जा रहा था, भी ज्व्त कर लिया जाना चाहिए ।  
'ट्रेण्ट' (Trent) के मामले में, घटना यह थी कि १८६१ में अमेरिकी  
प्रजूर 'सेन-फासिएटो' (San Fancinto) ने ब्रिटिश गेल स्टोमर 'ट्रेण्ट' को उ

समय रोक दिया, जबकि वह हबाना से सेण्ट टॉमस की ओर जा रहा था। वह समय अमेरिकी गृह-युद्ध का समय था। उसके दो यात्री मैसन और स्लीडेल, जो कि दक्षिणी-कॉन्फेडरेसी की ओर से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के लिए राजदूतों के रूप में जा रहे थे, पोत से अपने सचिवों सहित बलान् निवाल दिये गए। संयुक्त राज्य अमेरिका की अवधारणा थी कि, चूंकि पोत में स्पष्ट विनिषिद्ध सामग्रियों का प्रेषण किया जा रहा था, उन्हें ले जाने वाले भी उसी वर्ग में आते हैं। दूसरी ओर, ग्रेट ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका की इस अवधारणा का यह कहकर खंडन किया कि जो व्यक्ति पकड़े गये, उनका शील और उनके पद उन्हें विनिषिद्ध नहीं बनाता क्योंकि वे तटस्थ राष्ट्रों को राजदूतों के रूप में भेजे जा रहे थे। अतः ग्रेट ब्रिटेन ने तर्क दिया कि इस प्रकार का जब्ज किया जाना सर्वथा न्याय-प्रतिकूल था, क्योंकि एक तटस्थ राष्ट्र को निरपेक्ष अधिकार है कि वह युद्ध-संलग्न राष्ट्र से राजनयिक संबंध बनाए रखे। ग्रेट ब्रिटेन ने तर्क दिया कि अमेरिकी कुरम ब्रिटिश ध्वज एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सम्मान के प्रतिकूल था। निरन्तर की मध्यस्थताओं के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने बन्दि्यों को मुक्त कर दिया और इस वाद में विनिषिद्धता की विधि की व्यवहृति न हो सकी।

एस० एस० चीना (S. S. China), जो कि अमेरिकी मेल और यात्रियों का जहाज था और जो संघाई से अमेरिकी बन्दरगाहों तक आता-जाता था, के प्रसिद्ध वाद में प्रसंग यह था कि १९१६ में जहाज पर अनेक जर्मनवासी, आस्ट्रिया-वासी, और तुर्क यात्री थे और जो कि मनीला जा रहे थे। एक ब्रिटिश-क्रूजर 'लॉरेंटिक' (Laurentic) ने निरीक्षण के समय इन यात्रियों को जहाज से बाहर निकाल दिया। वॉशिंगटन की सरकार ने इस कृत्य का सबल प्रतिरोध इस आधार पर किया कि ये व्यक्ति सन्दन-डिवलेयरेशन के अनुच्छेद ४७ के अन्तर्गत नहीं आते, जो कि यह अनुमति देता है कि केवल सेना और नौसेना के व्यक्तियों को बन्दी बनाया जा सकता है। ब्रिटिश-सरकार ने उन व्यक्तियों पर शस्त्रों को चोर-बाजारी का आरोप लगाया। यह मत-भिन्नता का निर्धारण होने के पूर्व ही संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में प्रवेश कर गया और बन्दी छोड़ दिए गए।

आसमा-मारु (Asama Maru), जो कि एक जापानी पोत था, और अमेरिकी बन्दरगाह होनुलुलु से चलकर योकोहामा नामक जापानी बन्दरगाह तक की समुद्री यात्रा कर रहा था उसमें कुछ जर्मन नागरिक भी थे। घटना द्वितीय विश्व-युद्ध के समय १९४० में उस समय घटी, जबकि जापान एक तटस्थ राष्ट्र था। जब कि आसमा-मारु जापानी क्षेत्रीय जल में प्रवेश करने जा रहा था, एक ब्रिटिश क्रूजर द्वारा पकड़ लिया गया। उस क्रूजर ने २१ जर्मन-नागरिकों को उस पर से उतार

दिया। नागरिकों के परिरोधण पर जापान द्वारा विरोध किए जाने पर ब्रिटिश सरकार ने तर्क दिया कि 'जर्मन-सेना संहिता' (German Army Code) के अन्तर्गत प्रत्येक जर्मन पुरुष के लिए १८ वर्ष से ४५ वर्ष तक की आयु तक शस्त्र धारण करना आवश्यक है, और इसलिए ये २१ जर्मन-नागरिक, जो कि अधिकांश सैनिक-उम्र के हैं, विनिषिद्ध की स्थिति में थे, क्योंकि यदि वे जर्मनी को पहुँच जाते हैं, तो उन्हें जर्मन-सेना में सेवा करना पड़ेगा। चैम्बरलेन-सरकार ने परिणामतः २१ जर्मन बन्दिनों में से ६ को इस आधार पर मुक्त कर दिया कि वे अपेक्षाकृत सैनिक उम्र के नहीं थे, अतः उनसे सैनिक-सेवा की भांशा नहीं की जाती थी।

### अध्याय ५१

## निरीक्षण तथा तलाशी लेने का अधिकार (The Right of Visit and Search)

इसका तात्पर्य — निरीक्षण का अधिकार युद्धस्थितियों का तटस्थ व्यापारिक जहाजों को यह निश्चित रूप से ज्ञात करने के प्रयोजन से निरीक्षण करने तथा यदि आवश्यक हो तो तलाशी लेने का अधिकार है कि क्या वे जहाज वास्तव में तटस्थों के व्यापारिक जहाजों के बेटे के हैं तथा यदि ऐसी दशा हो तो क्या वे नाकाबन्दी तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा यदि विनिषिद्ध वस्तुओं को ले जा रहे हैं अथवा शत्रु की भ्रतटस्थ सेवाएँ कर रहे हैं। इस विषय का हेतु इतना स्पष्ट है कि यह विरकाल से व्यवहार में सार्वभौमिक रूप से माना जा रहा है। वास्तव में यह ही केवल एक रीति है जिसके द्वारा युद्धस्थित यह निश्चित रूप से ज्ञात करने में समर्थ होते हैं कि क्या तटस्थ व्यापारिक जहाजों का भाग्य शत्रु की सहायता पहुँचाना तथा उसकी भ्रतटस्थ सेवा करना है। (प्रोपेनहेम)।

उद्देश्य — हाइड का कथन है कि सिद्धान्त में "निरीक्षण तथा तलाशी लेने का उद्देश्य यह है कि युद्धस्थित की सूचना मुख्यतः तटस्थ जहाजों के सम्बन्ध में जिसके (युध्यमान के) युद्धपोतों से उसकी मुठभेड़ हो मिलती रहे जिससे कि वह इस प्रकार पता लगाई गई सूचना की सहायता से अपने अधिकारों का युद्धस्थित के रूप में पूर्ण रूप से प्रयोग करें।"

**युद्धस्थित के अधिकार (Rights of Belligerents)** —“समुद्र में तटस्थ जहाजों का निरीक्षण करने तथा तलाशी लेने का अधिकार युद्धस्थित का एक अधिकार है जो शत्रु की सम्पत्ति, युद्ध विनिर्दिष्ट वस्तुओं तथा नाकाबन्दी भङ्ग करने वाले जहाजों के अभिग्रहण के अधिकार को प्रयोग करने के लिये आवश्यक है।” यह अधिकार व्यक्तिगत जहाजों पर केवल या तो खुले समुद्र में अथवा युद्धस्थित के जलभागों में किया जा सकता है किन्तु तटस्थ जलभागों में कभी नहीं। यह अधिकार युद्ध छिड़ने के उपरान्त तथा युद्ध समाप्त होने के पूर्व युद्धस्थित के सब युद्धपोता तथा सैनिक वायुमानों द्वारा प्रत्येक युद्धस्थित के समुद्रोप अथवा क्षत्रीय पेट्री में प्रयोग किया जा सकता है। ओटन का कथन है कि यदि कभी शत्रु की सम्पत्ति को अभिग्रहण करने का अधिकार कठोरता से सीमित कर दिया जाय तथा स्वतन्त्र जहाज स्वतन्त्र माल का नियम अगोचर कर लिया जाय उस समय भी निरीक्षण तथा तलाशी का अधिकार इस बात को निश्चित करने के लिये आवश्यक है कि क्या राज्य की विधि तथा संधियों के अनुसार जहाज स्वयं तटस्थ हैं तथा प्रलेखों से ऐसे सिद्ध होने हैं क्योंकि जैसा विकरशीक का कथन है ‘इस बात के केवल भङ्गे ही से नहीं जो घोड़े से भी लगा दिया जा सकता है वरन् जहाज पर के लेशा से भी निश्चित रूप से ज्ञात करने के लिये कि क्या वह वास्तव में तटस्थ है, तटस्थ जहाज को रोक लेना वैध है।’

**निरीक्षण**—रोके जाने के उपरान्त जहाज युद्धस्थित युद्धपोत के एक या दो पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण का प्रयोजन जहाज की राष्ट्रीयता, उस पर लदे हुए माल तथा यात्रियों का लक्षण अथवा चरित्र तथा वह बन्दरगाह जिससे तथा वह लक्ष्य क्षेत्र जिसको वह जा रहा हो निश्चित रूप से ज्ञात करना होता है। यह सामान्यतः जहाज के कागजा अर्थात् पासपोर्ट, मस्टर रोल, लागबुकबिल आफ लेडिंग इत्यादि जो कि या तो जहाज पर पाये जाय अथवा व्यापारिक जहाज के स्वामी को अपने कागज पत्रों सहित युद्धस्थित युद्धपोत पर बुलाकर परीक्षण करके किया जाता है।

**तलाशी** —यदि जहाज के कागज पत्रों को देखकर यह प्रकट हो कि जहाज विनिर्दिष्ट वस्तु ले जा रहा है अथवा अतटस्थ सेवा कर रहा है तो वह तत्काल पकड़ लिया जाता है। लेकिन यदि केवल सदेह हो उत्पन्न होता हो तो युद्धस्थित जहाज के एक या दो पदाधिकारियों द्वारा जहाज के स्वामी की उपस्थिति में तलाशी ली जाती है। जहाज अथवा उस पर लदे हुए माल का कोई क्षति नहीं पहुँचानी चाहिये। यदि तलाशी से सदेह दूर हो जाय तो उसे अपनी यात्रा जारी

रखने दिया जाता है। लेकिन यदि उससे जहाज में विनिषिद्ध वस्तुओं की उत्पत्ति अथवा जहाज का अतटस्थ मेवा में लगा रहना पुष्ट हो जाता है तो जहाज को पकड़ लिया जाता है। यदि जहाज बन्दरगाह पर तलाशी के लिये लाया जाय और अन्त में वह निर्दोष प्रमाणित हो तो समय की हानि इत्यादि के लिये पूर्ण क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिये।

तलाशी करने में तलाशी किये जाने वाले जहाज के लिये कोई अनुचित विलम्ब अथवा असुविधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिये तथा उसके साथ हर प्रकार का विनम्रता तथा सम्मान का व्यवहार करना चाहिये।

तलाशी में बाधा — सन् १९०६ की लन्दन की घोषणा के अनुच्छेद ६३ में यह व्यवस्था की गई है कि युद्धस्थिति को रोकने, तलाशी लेने तथा पकड़ने के अधिकार का प्रबल विरोध सब दशाओं में जहाज को दण्ड का भागी बना देती है।

पथरक्षक जहाज :— पथरक्षक जहाज वे युद्धपोत हैं जो व्यापारिक जहाजों की रक्षा के लिये उनके साथ जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन को छोड़कर प्रायः और सब स्थानों में मतैव्य है कि रक्षित जहाजों की तटस्थता की सम्भावना में विश्वास रखकर तलाशी नहीं लेनी चाहिये क्योंकि वे उन जहाजों को अपने सार्वजनिक जहाजों की सुरक्षा में रख कर एक अर्थ में इस बात की प्रतिभूति देते हैं कि वे किसी भी व्यापार में नहीं लगे हैं जो उनकी तटस्थता से असंगत हो। यह मत लन्दन की घोषणा (१९०६) के अनुच्छेद ६१ द्वारा और पुष्ट किया गया है जिसमें यह निर्धारित हुआ है कि तटस्थ जहाज तलाशी से उन्मुक्त हैं जो अपने राज्य के युद्धपोतों की सुरक्षा के अधीन हो। किन्तु शर्त यह है कि सुरक्षित जहाजों का समादेशक, युद्ध स्थित युद्धपोत के समादेशक द्वारा भविष्य पर जहाज तथा उस पर लदे हुये माल के लक्षण के सम्बन्ध में लिखित सूचना उपलब्ध करे। यदि पथरक्षक जहाज के समादेशक द्वारा दी गई सूचना से युद्धस्थित युद्धपोत का समादेशक संतुष्ट न हो तथा उसके विचार में यह धावे कि तटस्थ युद्धपोत पर किये गये विश्वास का दुरुपयोग किया जा रहा है तो वह अपना सदेह तटस्थ समादेशक को प्रकट कर सकता है जिसे उस विषय का स्वयं अनुसंधान करना चाहिये तथा अपने तथ्यों को युद्धस्थित समादेशक को प्रतिवेदित करना चाहिये। यदि पथरक्षक जहाज का समादेशक अनुसंधान के उपरान्त इस परिणाम पर पहुँचे कि जहाज कुछ विनिषिद्ध वस्तुएँ ले जा रहा है अथवा अनुसंधान से जहाज का अभिग्रहण किसी अन्य प्रकार से उपयुक्त जान पड़े तो पथरक्षक जहाज को अपना संरक्षण हटा लेना चाहिये तथा उसे अभिग्रहीत करने दना चाहिये। यदि पथरक्षक समादेशक द्वारा किये गये अनुसंधान का परिणाम युद्ध-

स्थित युद्धपोत के समादेशक को संतोषपूर्ण न प्रतीत हो तो उस विषय का केवल राजनयिक सम्पर्क से ही निर्णय हो सकता है ।

केवल राष्ट्रीय पथरक्षक युद्धपोत ही अपने व्यापारिक जहाजों को उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है तथा अन्य तटस्थ राज्य का पथरक्षक युद्धपोत व्यापारिक जहाज को तलाशी से उन्मुक्ति नहीं प्रदान करता । जब कोई तटस्थ व्यापारिक जहाज किसी युद्धस्थित के पथरक्षक को स्वीकृत करे तो वह अनुतापूर्ण सम्बन्ध तथा उससे उपलब्ध निरीक्षण तथा तलाशी का विरोध करने के आशय के आधार पर दंड का भागी हो जाता है ।

सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जहाज ( Public and Private Vessels ) :—निरीक्षण तथा तलाशी के विषय में भी सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जहाजों में भेद है । सार्वजनिक जहाजों के सम्बन्ध में इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि ऐसे जहाज के ऊपर खुले समुद्र में न तो निरीक्षण अथवा तलाशी के अधिकार न कोई अन्य युद्धस्थित के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है । कोई सार्वजनिक जहाज जो किसी स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता का हो अन्य राज्य के क्षेत्रिक अधिकार क्षेत्र के भीतर निरीक्षण तथा तलाशी से उन्मुक्त है । अतः निरीक्षण तथा तलाशी के अधिकार का उपयोग केवल व्यक्तिगत जहाजों के सम्बन्ध में ही किया जाता है जो तटस्थ व्यापारिक जहाज हो किन्तु सार्वजनिक जहाजों के सम्बन्ध में इस अधिकार का प्रयोग नहीं होता है ।

लौरेंस निरीक्षण तथा तलाशी के नियम के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए यह व्यक्त करते हैं कि सब न्याय विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि तलाशी का अधिकार युद्धस्थित को तथा केवल युद्धस्थित को ही है तथा जैसा न्यायाधीन स्टोरी ने Marianna Flora ( Wheaton : Reports of the Supreme Court, Vol. XI, p. 1 ) में कहा है कि यह अधिकार राज्यों की सामान्य सहमति से युद्ध के समय में ही दिया जाता है तथा उन्हीं अवसरों के लिये सीमित है; इस अधिकार का प्रयोग केवल व्यापारिक जहाजों पर ही किया जा सकता है जो युद्धस्थित के वैधरूप से आयुक्त गश्ती जहाज को अपनी तलाशी लेने के लिये प्रत्यर्पण करने को बाध्य हैं, यद्यपि तटस्थ व्यापारिक जहाजों को तलाशी के लिये युद्धस्थित को अपने को प्रत्यर्पण करना आवश्यक है तथापि तटस्थ युद्धपोत इससे उन्मुक्त हैं; तथा यह कि युद्ध में सगे हुए जहाज भूटा भूटा लगा बर भयवा बिना किसी प्रकार के भंडा लगाये अनुसरण कर सकता है किन्तु निरीक्षण तथा तलाशी

के कार्य को वास्तविक रूप से आरम्भ करने के पूर्व इसे अपने देश का झंडा फहरा लेना चाहिये ।

विवाचन क स्थायी न्यायालय द्वारा कैथेज ( Carthage ) वाले मामले ( 1913, XIII, p 216 ) में निरीक्षण तथा तलाशी का अधिकार स्वीकृत किया गया जिसमें यह कहा गया कि "सार्वजनिक रूप से स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुसार युद्धस्थित युद्धपोत को विशेष परिस्थितियों का छोड़ कर तटस्थ व्यापारिक जहाज का खुले समुद्र में रोकने तथा इस बात को पना लगाने के लिये कि क्या वह तटस्थता के नियमों का विशेषतः प्रतिषिद्ध वस्तुओं के सम्बन्ध में पालन कर रहा है कि नहीं उसकी तलाशी लेने का अधिकार है ।"

इस विषय में प्रमुख मामला मैरिया (Maria) [(1799) 1 C. Rob. 340] का है जिसमें निरीक्षण तथा तलाशी के अधिकार के विरोध का प्रतिरोध स्वीडन के युद्धपोतों के पथरक्षक दल के अन्तरास्थापन ( interposition ) द्वारा किया गया । मैरिया स्वीडन का एक व्यापारिक जहाज था जो स्वीडन के युद्धपोत के संरक्षण में जा रहा था । ब्रिटेन की फ़ास से लड़ाई हो रही थी । अतः ब्रिटेन के नौ सेना विभाग के एक स्वर्षाडून ने निरीक्षण तथा तलाशी के अधिकार का प्रयोग करना चाहा जिसका पथरक्षक जहाज द्वारा बलपूर्वक विरोध किया गया । उसे ब्रिटेन के नौजितमाल न्यायालय ने इस आधार पर दंडित किया कि उसने उपलक्षित रीति से शक्तिशाली युद्धपोत द्वारा किये गये विरोध में भाग लिया है । नौसेना विभाग के उच्च न्यायालय का निर्णय देने में लार्ड स्टोवेल ने विधि के निम्नलिखित तीन सिद्धान्तों को निर्धारित किया :—

१. यह कि खुले समुद्र में व्यापारिक जहाजों का निरीक्षण तथा उनकी तलाशी लेने का अधिकार चाहे जहाज, उन पर लदा हुआ माल और उनका लक्ष्य-क्षेत्र कुछ भी हो युद्धस्थित राज्य के वैधरूप से अधिकृत ( कमीशन दिये गये ) युद्धपोतों का एक निर्विवाद अधिकार है । "जहाज, उन पर लदा हुआ माल तथा लक्ष्य-क्षेत्र चाहे जो कुछ हो, मैं इसलिये कहता हूँ कि जब तक उनका निरीक्षण तथा उनकी तलाशी न ली जाय यह प्रकट नहीं होता कि जहाज तथा उनका लक्ष्य-क्षेत्र क्या है तथा इन्हीं विषयों को निश्चित रूप से ज्ञात करने के प्रयोजनों से हो निरीक्षण तथा तलाशी के अधिकार की आवश्यकता विद्यमान रहती है ।"

२. यह कि तटस्थ सार्वभौम सत्ता का प्राधिकार बीच में घाता है, यह बात वैध रूप से आयुक्त युद्धस्थित युद्धपोत के अधिकारों को वैधरूप से परिवर्तित नहीं कर सकती ।

३. इस अधिकार के बलपूर्वक विरोध किये जाने के लिये दंड, निरीक्षण तथा तलाशी से रोकी गई सम्पत्ति का जब्न किया जाना है ।

इस मामले में दिये गये दंड के निर्णय के अनुसार सन् १८०० में बाल्टिक शक्तियों के बीच सशस्त्र तटस्थता की संधि हुई तथा विवादपूर्ण विषयों की व्यवस्था ५ जून सन् १८०१ की प्रतिज्ञा द्वारा की गई जिसके अनुसार तटस्थ सरक्षण में यात्रा करने वाले व्यापारिक जहाजों की तलाशी सम्बन्धी अधिकार का उसे युद्धमान पक्षकार के सार्वजनिक युद्धपोतो तक सीमित कर दिया गया तथा व्यक्तिगत सशस्त्र जहाजों को अलग कर दिया गया । एक सौ वर्ष के थोड़े ही अधिक उपरान्त यह विचार-विमर्श सन् १९०६ की लन्दन की घोषणा द्वारा समाप्त कर दिया गया जिसमें ब्रिटेन के दावे के विरुद्ध निर्णय दिया गया । लन्दन की घोषणा में यह निर्धारित किया गया कि तटस्थ जहाज अपने राष्ट्रीय पथसरक्षक के रक्षण में तलाशी से उन्मुक्त है ।

सर विलियम स्कॉट ने *The Catharina Elizabeth* (1 C. Rob. 232) में यह कथन किया कि “यदि कोई तटस्थ कप्तान छुड़ाने प्रयत्न करने को तलाशी से हटा लेने का प्रयत्न करे तो वह एक कर्तव्य का उत्पन्न करता है जो उस पर राष्ट्रों की विधि द्वारा डाला गया है अर्थात् अपने को तलाशी के लिये प्रत्यार्ण करना तथा जहाज प्रयत्न उस पर लदे हुए माल की सम्पत्ति के सम्बन्ध में जाँच कराने के लिये आना तथा यदि वह इस कर्तव्य का बलप्रयोग द्वारा उत्पन्न करे तो इसमें सन्देह नहीं कि परिणाम उसके स्वामी की सम्पत्ति पर पहुँच गया मेरे विचार में वे परिणाम उसकी रक्षा में सौंपी गई सम्पूर्ण सम्पत्ति पर पड़ेगी जिसका इस प्रकार धोखा देकर युद्ध के अधिकारों के प्रभाव में हटाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है । यदि स्वामी शत्रु हो तो मामला पूर्णतः से ही भिन्न होता है क्योंकि ऐसे कार्य में उसकी ओर से किसी कार्य का उत्पन्न नहीं होता तथा यदि वह अपने को हटा सब तो उसे ऐसा करने का अधिकार है ।”

जहाज तथा उस पर लदा हुआ माल कब दंड के भागी होते हैं:—यदि तटस्थ शक्ति का जहाज निरीक्षण तथा तलाशी का विरोध करे प्रयत्न यदि निरीक्षण तथा तलाशी से यह प्रकट हो कि तटस्थ जहाज शत्रु को महायन्त्र देने के प्रयत्न में लगा है प्रयत्न यदि कागज-पत्रों की अनुपस्थिति में जहाज का असली लक्षण जान न हो सके तो तटस्थ जहाज उस पर लदे हुए माल सहित नौजिनमाल न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने पर अभिग्रहीत करने तथा दंडित करने के योग्य हो जाता है । तटस्थ नौजिनमाल को जब तक अनाधार पर परिस्थितियाँ न हों, विनष्ट नहीं करना



चाहिये तथा यदि उन्हें विनष्ट किया जाय तो पीडित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिये । विनष्ट करने की स्वीकृत होने पर भी उन शत्रु व्यक्तियों को जो जहाज पर हो सुरक्षित स्थान में रख देना चाहिये ।

विश्व-युद्धों के मध्य व्यवहार की गई रीति:—प्रारम्भ में निरोक्षण तथा तलाशी के अधिकार को बड़े अवरोध लगा कर घेर दिया गया जिससे तटस्था को बहुत कम असुविधा हा लेकिन दो विश्वयुद्धों ने इन कल्याणकर शर्तों को उड़ा दिया । विश्वव्यापी युद्ध की आवश्यकताओं के कारण युध्यस्थित, तटस्थ जहाजों का खुल समुद्र में प्रारम्भिक के बिना रोक सक, तथा जहाज के कागज पत्रों के प्रारम्भिक परीक्षण के बिना भी पूर्ण परीक्षण के लिये बन्दरगाह को भेज दिये जाते थे जिससे तटस्थ जहाजों को अत्यधिक बिलम्ब तथा असुविधा होती थी । तटस्थ जहाजों का खुल समुद्र के स्थान पर बन्दरगाह में तलाशी लेने की ब्रिटिश रीति के विरुद्ध न्याय विचारों तथा इस विषय पर अन्य स्वतंत्र लेखकों ने कड़ी आलोचना की किन्तु ब्रिटेन ने उसे जारी रखने का औचित्य इस आधार पर स्थापित किया कि तलाशी के बीच पनडुब्बियों का भय रहता है तथा माल ले जाने वाले जहाजों की संख्या में वृद्धि हो गई है और यह कि निरंतर ही आशातीत ढंग से यह वृद्धि होती ही जा रही है ।

---





